

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE

भारत की शासन प्रणाली

(Indian Political System)

राजस्थान विश्वविद्यालय के नये कोस के अनुसार

डॉ० दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी

एम ए पी एच डी

अध्ययन राजनीतिशास्त्र विभाग

जे डी कालिज बडोत ।

(मराठ विश्वविद्यालय)

SYLLABUS

Paper II Indian Political System

The syllabus would cover in the main the following items

- 1 Landmarks in India's National Movement 1885-1947
- 2 The Constituent Assembly—its structure and approach
- 3 Outline of Indian Constitution—Federalism , The Indian Presidency, Office of Prime Minister , Parliament, Office of Governor , Supreme Court and Judicial Review
- 4 The Nature and determinants of Indian Politics
- 5 The Party System and Pressure Groups
- 6 Elections
- 7 India's Foreign Policy

प्रस्तावना

किसी भी देश के साविधानि तंत्र तथा उसकी राजनीति का उसके ऐतिहासिक सम्बन्धों से अलग करके नहीं समझा जा सकता। भारत इस मामला में नियम का अपवाद नहीं है। जिन लोगों ने भारत की औपनिवेशिक दमना के विरुद्ध संघर्ष में नेतृत्व प्रदान किया था उन्होंने लोगों को स्वाधीन भारत के संविधान की रचना की थी तथा वही लोग एक नवम्बर 1946 तक स्वतंत्रता के लिए भारतीय राजनीति पर छाये रहें थे। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न पाठ्य सामग्री यथाथ में एक प्रकार की अवयवा एकता की रचना करनी है।

पुस्तक का प्रणयन सामान्यतः निम्नलिखित तथ्यों के दो एक नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर किया गया है। पुस्तक दो खण्डों में विभाजित है। पहले खण्ड में राष्ट्रीय आन्दोलन की विवेचना है और उस समय के महत्वपूर्ण घटनाओं के राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। दूसरे खण्ड में जहाँ सामाजिक ढाँचे की विवेचना है वहाँ उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि इस ढाँचे में पाए जाने वाली समस्याएँ न केवल की जाती हैं बल्कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित किया है अथवा वे स्वयं उनसे प्रभावित होकर अपने आपको बनाने के लिए विवश हुई हैं।

पुस्तक के सम्बन्ध में एक निवेदन और है। घटनाओं और समस्याओं का सभी अंगों से अन्वेषण में देखते हैं। यद्यपि इस पुस्तक में विभिन्न सामग्रियों को यथासम्भव वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत किया गया है तथापि लेखक ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर उनकी विवेचना करने के अपने मूल अधिकार को निराजित नहीं किया है। फलतः बन्त सम्भव है कि इसके कारण इस पुस्तक में कुछ ऐसी स्थापनाएँ हों जिनमें पाठक सहमत न हो सकें। परन्तु यह कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि लेखक का विश्वास है कि वैचारिक प्रगति की प्रक्रिया द्विधात्मक होती है। चार्ज और प्रतिवादा के टकराव के परिणामस्वरूप ही सच्चाई की रचना होती है। पुस्तक के विषय में भेजे जाने वाले सभी मुद्दों का स्वागत है।

दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी

विषय-सूची

1

राष्ट्रीय आन्दोलन के ऐतिहासिक चरण

1	राष्ट्रीय चेतना का अभ्युदय ✓	1
2	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ✓	12
3	राष्ट्रीयता का प्रारम्भिक युग	28
4	उग्र राष्ट्रीयता का अभ्युदय ✓	47
5	क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन	69
6	मुस्लिम साम्प्रदायिकता का अभ्युदय	78
7	प्रथम विश्व-युद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन ✓	84
8	असहयोग आन्दोलन ✓	95
9	स्वराज्य दल ✓	107
10	पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पृष्ठभूमि	113
11	सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोल मेज सम्मेलन	125
12	भारतीय शासन अधिनियम 1935 कार्यान्विति	158
13	द्वितीय विश्व-युद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन	148
14	ब्रिटिश शासन का अवनति काल	183
15	मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा देश का विभाजन	195

2

भारत की शासन व्यवस्था की रूपरेखा

1	संविधान सभा संरचना तथा उपागम ✓	1
2	संविधान के स्रोत ✓	17
3	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ	21
4	संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त	29
5	मध्यम कार्यपालिका ✓	49
6	संघीय व्यवस्थापिका	67
7	मध्यम न्यायपालिका ✓	89
8	राज्यों और मध्यम क्षेत्रों का शासन	100
9	भारतीय संघवाद का स्वरूप ✓	119
10	सांविधानिक मनोबल और उसकी प्रक्रिया	141
11	संस्थापिकाएँ एवं निर्वाचन	149
12	राजनीति का दृष्टिकोण ✓	156
13	द्वितीय मंच ✓	187
14	भारतीय शासन की समस्याएँ	194
15	भारतीय राजनीति के निर्धारक तन्त्र ✓	202
16	भारत की विदेश नीति ✓	209

1857 से पहले

भारत में एकछत्र साम्राज्य का अन्त—1707 में मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु का ज्ञान पर भारत में एकछत्र मुगल साम्राज्य का भी अन्त होने लगा। देश के विभिन्न भागों के प्रांतीय भूजगत् या नवाब स्वतंत्र होने लगे। कुछ भागों में हिंदू राजाओं ने अपनी स्वतंत्र गिरासतें बना लीं। उधर मराठा भी स्वतंत्र हो गए। पंजाब में सिक्खों ने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। यह क्रम जारी रहा और भारत के दक्षिणी राजा तथा नवाबों की स्वाधीन गिरासतें स्थापित करने की ऐसी प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि उनमें पारस्परिक युद्ध होने लगे और राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास को कोई अवसर नहीं मिला।

यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों की गतिविधियाँ—उन बीच यूरोप की फ्रांसीसी डच पुर्तगाल तथा ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनियाँ मनुनी भाग में भारत में व्यापार करने आ रही थीं। उन्होंने दक्षिण भारत के विभिन्न नगरों में दक्षिणी राजा तथा नवाबों की आज्ञा प्राप्त करके अपनी व्यापारिक कोठियाँ निर्मित की और उनकी सुरक्षा के निमित्त अपनी छोटी छोटी सेनाएँ भी रख लीं। प्रारम्भ में इन कम्पनियों के मध्य पारस्परिक युद्ध हुए और अन्त में उनके मध्य के युद्धों तथा मधियाँ का परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही सबसे प्रबल सिद्ध हुई। फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियाँ पाटीचरी गोवा दमन दीव में ही अन्त तक बनी रहीं और डच कम्पनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपनी इस विजय का न केवल आर्थिक लाभ ही उठाया अपितु वह भारत में राजनीतिक गतिविधियाँ भी बढ़ाते गयीं।

यूरोपीय साम्राज्यवादी उद्देश्य—यह युग यूरोपीय साम्राज्यवाद का युग था जिसमें अंग्रेज साम्राज्यवादी देशों का सिरमौर बनता जा रहा था। उस युग के साम्राज्यवाद का प्रमुख उद्देश्य एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था ताकि उन साम्राज्यवादी देशों के पूँजीपति व्यापारी तथा उद्योगपति अपने साम्राज्य के उपनिवेशों का अधिक शोषण कर सकें। इन देशों से कच्चा मान प्राप्त करके अपने देशों के कारखानों को चलाते उनमें उत्पादित मान का उपनिवेशों में बिक्री तथा उन उपनिवेशों में अपनी अनिश्चित पूँजी को लगा कर उनका शोषण करने में सफल हो सकें। यह सभी सम्भव था जबकि उपनिवेशों में उनका निश्चित शासन स्थापित हो जाता।

अतः यद्यपि ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी मूल रूप से केवल एक व्यापारिक कम्पनी थी तथापि उसके भारत स्थित अधिकारियों तथा कमचारियों ने अपने देश की सरकार तथा इंग्लैंड स्थित कम्पनी के अधिकारियों को यह समाधान करने में सफलता प्राप्त कर ली कि कम्पनी के मानिकों तथा समूचे रूप में इंग्लैंड का हित इसी बात पर निर्भर करता है कि भारत में इंग्लैंड का साम्राज्य स्थापित हो जाये कम्पनी के भारत स्थित शासकों तथा अधिकारियों ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त भारतीय राजा तथा नवाबों के पारस्परिक युद्धों तथा कलहों का पूर्ण लाभ उठाने में कोई कमी नहीं रख छोटी। इन्होंने युद्धरत पक्षों में से यथावसर एक का पक्ष लेकर उसे जिताया और पुरस्कार-स्वरूप अपने व्यापार क्षेत्र का विकास किया। 1600 में उनके दसों वर्ष

की अवधि में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापार क्षेत्र भारत के सम्पूर्ण समुद्रतटीय प्रदेशों से लेकर पर्याप्त दूर तक आन्तरिक क्षेत्रों में फैल गया।

1757 से लेकर 1857 तक की शताब्दी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विकास तथा विस्तार का काल है। 1757 के प्लासी के युद्ध में कम्पनी के अधिकारियों ने जो महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका प्रस्तुत की वह भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना का श्रीगणेश सिद्ध हुई। इसके फलस्वरूप कम्पनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् 1772 तक कम्पनी की यह अधिकार सीमा बिहार, उड़ीसा तथा अवध के प्रान्तों तक विस्तृत हो गयी। जब यह स्पष्ट हो गया कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में केवल व्यापार करने वाली कम्पनी मात्र नहीं है, अतः उसके हाथ में भारत के पर्याप्त बड़े क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार भी आ गया है। इंग्लैण्ड की तत्कालीन सरकार ने यह अनुभव किया कि जब तक कम्पनी के ऊपर सदन का पर्याप्त नियन्त्रण नहीं रहेगा तब तक वह भारत में शासन-कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं कर सकेगी। अतः कम्पनी के कार्य-कलापों का नियमन करने के हेतु 1773 में ब्रिटिश सदन ने रेग्युलैटिंग एक्ट पास किया। इसके अनुसार कम्पनी के अधिकार-क्षेत्र में आ गये भारतीय प्रदेशों की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में कानून बनाया गया। यहाँ से ब्रिटिश भारत के साविधानिक विकास का श्रीगणेश हुआ।

1773 से लेकर 1853 तक प्रति 20 वर्ष के उपरान्त कम्पनी के चार्टर कानूनों में परिवर्तन तथा परिवर्धन होता गया। साथ ही भारत स्थित कम्पनी के शासकों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता तथा प्रेरणा लेकर देश में साम्राज्य विस्तार का क्रम जारी रखा। 1857 तक समूचा भारत ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता के अधीन हो गया। थोड़े से देशी राजा तथा नवाब अभी तक स्वतन्त्र थे, परन्तु भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी की नीति ऐसी थी जिसके अनुसार सम्भवतः थोड़े ही समय में इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता।

1857 का विद्रोह तथा भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति के कारण

1857 की घटना ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लिया। यो कहना चाहिए कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासकों की साम्राज्य विस्तार तथा शोषण की नीति ने भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति करने का अवसर प्रदान किया। निम्नांकित परिच्छेदों में उन तथ्यों का विवेचन किया गया है जो ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल की प्रमुख नीतियों को प्रदर्शित करते हैं और जिनके फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति होने लगी।

(1) अंग्रेजों की साम्राज्य लिप्ता—कुछ लोगों की धारणा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का कोई निश्चित तथा नियोजित उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह बात 'अवसरवशात् तथा अकस्मात्' हो गयी, परन्तु इस धारणा में कोई सत्याश नहीं है। निम्नान्वेष्ट, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आये थे। परन्तु यदि उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना ही होता तो कम्पनी के शासकों को भारतीय नरेशों के पारस्परिक युद्धों में किसी एक का पक्ष लेने का कोई औचित्य नहीं था। इसके उपरान्त बंगाल में पहले दीवानी का अधिकार प्राप्त करके द्वैत शासन की नीति अपनाना और बाद में शनैः शनैः वास्तविक शासक हो जाना, उनकी सुनियोजित साम्राज्यवादी राजनीतिक गतिविधियों का ज्वलन्त प्रमाण है। यदि इंग्लैण्ड की सरकार भारत में साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा न होती तो उसे क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग्स के कार्य-कलापों को अन्वीक्षार कर देना चाहिए था, जबकि स्वयं इंग्लैण्ड में भी अनेक राजनेताओं ने इनका कड़ा विरोध किया था। वास्तविकता यह थी कि इंग्लैण्ड उस युग में साम्राज्य विस्तार के कार्य में लीन था जो इंग्लैण्ड का राजनीतिक तथा आर्थिक हित इसी में था कि वह एशियाई देशों में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करके वहाँ शोषण नीति अपनाकर लाभान्वित हो सके। अतः भारत में कम्पनी के अधिकारियों ने इंग्लैण्ड की उस साम्राज्य लिप्ता को मफन करने में यहाँ की परि-

स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया और इंग्लैंड की सरकार ने निरंतर इस नीति का अपना पूरा समर्थन प्रदान किया। उस प्राप्ति के लिए मरणाति नहीं रमो तथा इस काय में पूरा सहायता प्रदान की और अन्त कम्पनी की अनुमति दगाकर भारत का शासन अपने हाथ में लिया। जब भारतवासी इस नीति को अपनी समझ में नग गये तो उनमें ब्रिटिश साम्राज्य को ममाप्त करने की भावना जाग्रत हान गयी।

(2) ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शासन नीति—साम्राज्यवाद के औचित्य को 'वैत नाग क दायित्व' (white man's burden) की सना देकर यक्त किया जाना रहा है। अने ही किमी अत्यन्त निष्ठ तथा अमम्य क्षेत्र क सम्बन्ध में यह धारणा सही सिद्ध हुई है परन्तु भारत सहित देश के सम्बन्ध में जो शिक्षा सभृति एवं राजनीति क क्षम में अग्रज जाति की अपेक्षा अति प्राचीन काल में ही अधिक निरक्षित अव था म था यह धारणा कोई अव नहीं रमती। यह ता तत्कालीन भारत की राजनीतिक अस्तव्यस्तता का कुप्रभाव था कि यहाँ का आर्थिक विकास पाश्चात्य देश के समान नर रहा चन रहा था जिसक कारण यूरोप के पूजीवादी देश को यहाँ अपनी श्रष्टर स्थिति प्रर्णित करने का बहाना मिन गया। अन्त राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर नेन पर अग्रज को यहाँ रन तार ठाक की व्यवस्था तथा थोड़े स कारखाना का स्थापित करना पडा। परन्तु यह नर उहाने भारत की जनता के हिताय नहा वकि अपन शासननत्र को सुदृढ बनाने की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ही किया। सम्भवत यदि भारत का राजनीतिक तन्त्र सुदृढ होता और यहा का शासन भारतीय क हाथ में होता ता औद्योगिक विकास में भारत पश्चिम के देश की तुलना में अधिक उत्तमिनी हो गया होता। वास्तव में इस काल में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शासन नीति भारत का हर दृष्टि में नोपन कर नेने पर आधारित रही।

(3) भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास—अग्रज की आर्थिक नीति का प्रमुख नश्य भारतीय उद्योग धन्दा गिर कनाया आदि का नष्ट करना यहा के कच्च मान का इंग्लैंड के कारखाना में पहुँचाना तथा अन्त क नया तयार मान स यहा के बाजारा को भर दना था परिणाम यह हुआ कि भारत के गिर जीविका को मुतमरी का सामना करना पन्ना। भारत में जमींदारी प्रथा लागू करक ब्रिटिश शासक चन् जमींदारा के हिनपी बन गये और वेचारे किसानों की दगा नोवनीय हानी गयी। दृष्टि ही एकमात्र जीविका साधन थी। परन्तु इस पर दबाव नना वन् गया कि भूमि की उवरा शक्ति नष्ट भी हानी गयी। इस प्रकार भारतीय जनता अग्रज की आर्थिक दासता क नीच कुचन गया।

ब्रिटिश शासक ने भारतीय शिक्षा सभृति साहित्य कला आदि क विकास का थोड़ा तनिक भी ध्यान नहीं लिया। जो याता सी शिक्षा सभ्याएँ स्थापित की उनका उद्देश्य थोड़े स गसे भारतीयों को इतनी हा शिक्षा दना था जिसमें कि ब्रिटिश शासन क अतगत छाने छाने कनों के रूप में उह नियुक्त कर लिया जा सन। इसलिये शिक्षा का मायम अग्रजों भाषा को बनाया गया भारतीय भाषाया सभृति साहित्य तथा शिक्षा-मद्धतिया को पूर्णतया उपशित रखा गया। यद्यपि मुगल शासन काल में भी इस शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं दिया गया था तथापि मुगल क नीति भारतीय सभृति को नष्ट करक अपने निजी स्वार्थों के हित में उसके स्थान पर अपनी सभृति थोपना नहा रन था। प्रत्युत उस काल में हिंदू तथा मुस्लिम सभृतिया परस्पर एक से मित्रने गयी था क्पाकि भारत में आकर मुगल नाग भारत को ही अपनी भूमि मानने गये थे। अग्रज की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि भारतवासियों को शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर नहा मिला। अग्रज यह भी नहीं चाहते थ कि भारतीयों को शासन के उच्च पदा पर रखा जाये। इसलिये भी शिक्षा के विकास का उपेक्षित रखा गया।

(4) शासन व्यवस्था में स्वेच्छाचारितावाद तथा उसका विदेशीकरण—ब्रिटिश शासन की नीति पूनया के गीकृत स्वच्छाचारितावाद की थी। भारत में अति प्राचीन काल से ग्राम पचायतो की व्यवस्था थी ये पचायतें ग्रामीण स्वायत्त शासन का काय करती थी। यद्यपि मुस्लिम शासन

काल में उन्हें विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया तथापि मुस्लिम शासकों की नीति उन्हें समाप्त करने की भी नहीं रही। मुसलमान शासकों ने ग्रामीण शासन-व्यवस्था में कर वसूली तक ही अपने कार्य-कलापों को सीमित रखा था, न कि वहाँ अपनी किसी व्यवस्था को थोपकर परम्परागत व्यवस्था का अन्त करने का उद्देश्य रखा। परन्तु ब्रिटिश शासकों ने ग्रामीण स्वायत्त शासन की पचायत प्रणाली का अन्त करके उसके स्थान पर उच्चोच्च व्यय की नौकरशाही व्यवस्था को स्थानापन्न किया। इसका उद्देश्य यही था कि भारतवासियों में स्वायत्त शासन की चेतना किसी भी स्तर पर विद्यमान न रह सके। धीरे-धीरे उन लोगों ने भारत में विदेशी न्याय तथा कानून पद्धति को लागू किया। इस प्रकार भारत की समूची राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का विदेशीकरण हो गया।

(5) ईसाई धर्म-प्रचार और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव—ब्रिटिश शासन की नीति ने जहाँ भारतवासियों को आर्थिक, साम्प्रतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से दास बनाया, वहाँ इन शासकों के संरक्षण में ईसाई मिशनरियों को भी धर्म-प्रचार के कार्य में प्रोत्साहित किया गया। दरिद्रता की शिकार जनता को विविध प्रकार के प्रलोभन देकर मिशनरियों ने बहुत बड़ी सत्ता में भारत के हिन्दुओं को ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण करने में मदद दी। इस प्रकार भारत की जनता के ऊपर पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता तथा साहित्य का गहन प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप भारत-वासियों को 'विदेशी शासन तथा सभ्यता का उपासक' बना लेने में अंग्रेज शासकों को सफलता मिली। यद्यपि ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य भारतीय जनता को अपनी ऐसी नीति के द्वारा पूर्णतया दासत्व की स्थिति में रखना था, तथापि इसका प्रभाव उनकी इच्छा के विरुद्ध सिद्ध हुआ। तत्कालीन भारतीय शिक्षित लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा वहाँ के विद्वानों के विचारों का अध्ययन किया। वहाँ की राजनीतिक परम्पराओं, प्रणालियों, इतिहास, दर्शन तथा चिन्तन के अध्ययन के द्वारा उन्हें ब्रिटिश शासकों की कूटनीतिक चालों तथा भारत की दासता का ज्ञान हुआ। अतएव भारत में पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्यता का प्रसार होने से भारतीय शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना की जागृति होने लगी।

(6) लार्ड डलहौजी की शासन नीति तथा सेना में रोक—ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासकों के अत्याचारों तथा कार्य-कलापों का चरमोत्कर्ष भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी की नीतियों द्वारा स्पष्ट तथा प्रकट हो गया। लार्ड डलहौजी ने निस्सन्तान देशी राजा तथा नवाबों को गोद लेने की प्रथा अपनाने से रोक दिया और उनकी रियासतों को ब्रिटिश भारत में मिलाना शुरू किया। कुछ रियासतों के शासकों के ऊपर अकुशल शासन का आरोप लगाकर उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना प्रारम्भ किया। इस नीति में मताररा, भ्रासी, अवध, बीदर, बरार, नागपुर, आदि के शासकों में भीषण विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गयी, जमीन बीच सेना में ऐसे कारतूत प्रचलित किये गये जिन्हें प्रयुक्त करने से पूर्व बात से काटना पड़ना था। सैनिकों में यह भावना उत्पन्न हो गयी कि इन कारतूतों में गाय और सुअर की चर्ची लगी है और अंग्रेज लोग भारतीय हिन्दू तथा मुसलमानों का धम-भ्रष्ट करने के लिए यह सब कार्य कर रहे हैं।

1857 का विद्रोह

विद्रोह का भड़कना—ब्रिटिश शासकों की राजनीतिक तथा आर्थिक थोपण एवं अत्याचारों की नीतियों अधिक समय तक भारतीय जन-मानस में छिपी नहीं रह सकी। यदि ब्रिटिश शासक भारतीय जनता को अपनी प्रजा सम्भूत जनता के हित में जनता की परम्पराओं के अनुसार शासन करने में सम्भवतः उनकी शोचप्रियता बटती और भाग्य का इतिहास 1857 के पश्चात् होता होता, उसमें भिन्न प्रवृत्ति न होता। परन्तु ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य तो कुछ और था। भारत में स्वेच्छाशासी शासन तो नाश होना था, उसका नाश था भारत का स्वाधीन शोषण। ऐसा करना यों ही समय नष्ट करने समान था। लार्ड डलहौजी ने चने जाने पर भारतीय जनता का

गेष तथा अमन्ताप जनन धेना म पूतन गगा । अव यह प्रकट होन गग गया कि अग्रजा का साम्राज्यवादा नीति श्वेत योगा का दायित्व नहा अपितु कान जोगा का दायित्व थी अर्थात् कान नागा का शोषण करके हा श्वेत योगा को इच्छा पूण हा सकनी थी । इसलिये अग्रज सम्पूर्ण भारत म अपना स्वच्छाचारो निरकुण गसन कायम करना चाहत थ । 1857 म ब्रिटिश गामन का नीतिया व विरुद्ध विस्फाट की जाग मना म प्रारम्भ हुइ । मरठ छावनी के मनिका न कारतूस व प्रदन को नकर विवाह प्रारम्भ किया । गाध ही यह जवाता स्थान-स्थान पर भडक उठी । बटखन राजा-नवाबा न भी अपना स्वाधानता प्राप्त करने का अवसर दया । निनी म एक प्रकार म उदो के रूप म पडे हुए अंतिम मुगन सम्राट बहादुरशाह न भी अपने को स्वतन्त्र घोषित कर लिया । विवाह गाध ही हिंसात्मक हा गया । ब्रिटिश गामन न इस कुचनत म कोई कमी नहा रखी । दूसरी जाग भारतीय देशभक्ता न भी दमनकारी अग्रजा को नष्ट करने म पूरी गति लगायी । भोसो की रानी जम्हाबाट तात्या टोप मगन पाड जाति न स्वतन्त्रता क नाम पर ब्रिटिशो गामन का विरुद्ध उठत हुए अपने प्राणा की आहुति दकर अपना नाम जमर कर दिया । यद्यपि कुछ इतिहासकार 1857 व विवाह को सनिक विरोह की और कुछ गटर की सना दते है तथापि यह विवाह असल कुछ और था । पट्टाभि सीतारामयान न से प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता मगम कहा है । यह वान दूसरी है कि यह क्रान्ति सुमगठिन तथा सुनियोजित नही थी परन्तु वतना स्पष्ट है कि हमका विस्तार यही सिद्ध करता है कि हमका मनानी ब्रिटिश गामन की नीति म प्रद हाने व कारण उमम मुक्ति चाहत थ । उस समय ब्रिटिश गामन का नाव वतनी सुदृढ हा चुकी थी कि क्रान्तिकारिया का एक छोटा-सा वग जावयन मनिक सजा तथा सुमगठिन युद्ध की नयारी व बिना ब्रिटिश गामन म गोहा नही न सकता था । अत अग्रजा ने विवाह का दबा दिया और इसका दमन करने म भा उहाने पूण नेगसता का आचरण किया । विवाह को दवान म ब्रिटिश गामन न बटना लेने की नाति अपनायी जिसन गामन को जातकनादी रना दिया ।

विवाह की प्रतिक्रिया

(अ) साविधानिक परिवर्तन—1773 म इंग्लंड की संसद न भारत म इन्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा संचालित गामन व ऊपर अपना नियन्त्रण आरम्भ कर दिया था । तब से कम्पनी संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा चाटरा व अनुमार गामन करने लगी थी । 1857 तक लगभग सम्पूर्ण भारत म ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हा चुका था । भारत का प्रधान गामक गवर्नर जनरल था जो अपना परिषद् की सलाह म अधिगामन का काय करता था । प्राता व गवर्नर अथवा नफोनट गवर्नर असक अधान थ । इंग्लंड की सरकार न 1853 म कम्पनी के लिए अंतिम चाटर (ग्रान्चा-यत्र) पारित किया था । इंग्लंड की सरकार को यह अनुभव होन गगा था कि वतन उडे दग का गामन कम्पनी व ऊपर छाडना उचित नही है । 1857 व विरोह ने इंग्लंड की सरकार की अस धारणा का पुष्ट कर लिया । अभी तक बाड आफ कंटान भारतीय गामन का नियन्त्रण निदेशन तथा निरीक्षण करना था और कोट आफ डाइरेक्टस केवन परामगवादी निकाय व रूप म थी । गवर्नर जनरल की परिषद् म 12 सदस्य थे उहा व परामग स बहु विधि निर्माण तथा प्रगामन का काय करता था । उसकी गति वतनी अतुल थी कि वह अपनी परिषद् का अवल्लन कर सकता था । इन वारह संस्था म स्वय गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति चार साधारण अधिगामनिक परिषद् व सदस्य दा कनक्ता की सुप्रीम कोट के व्यापधीग तथा नथ चार सदस्य वगान मद्रास बम्बई एव आगरा व अवध (वतमान उत्तर प्रदेश) प्राता की सरकारा द्वारा नियुक्त सरकारी कमचारी हाते थ । 1853 व अधिनियम के द्वारा भारत म प्रगामकीय अधिकारियों की नियुक्ति एव सावजनिक भारतीय सिविन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा व अनुसा हाने लगी । एक विधि आयोग का निर्माण किया गया था जिसका उद्देश्य भारतीय विधि का महिाकरण करने का संस्तुति रना था । भारतीय सीमा के अंतगत जो क्षेत्र कम्पनी के गामन व

जन्तर्गत थे, परन्तु ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों के अन्दर नहीं थे उनके प्रशासन के हेतु सपरिषद् गवर्नर-जनरल को चीफ कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार भारत के शासन के संचालन में विधायिका का प्रयोग करने की प्रथा का श्रीगणेश हो चुका था।

परन्तु विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को कम्पनी के हाथ से शासन सत्ता छीन लेने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हो गया। उसने यह अनुभव किया कि इस घटना के पश्चात् कम्पनी के ऊपर कुछ नियन्त्रण लगा देना मात्र पर्याप्त नहीं है। अतः कम्पनी के ऊपर अकुशलता तथा अक्षमता का दोष मढ़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली और कम्पनी के शासन का अन्त कर दिया। इसी के साथ-साथ 1784 के 'पिट का इण्डिया एक्ट' से चले हुए भारत के ट्वेन शासन का भी अन्त हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार तथा कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स दोनों का नियन्त्रण बना हुआ था। 1858 में संसद ने भारतीय शासन के हेतु जो अधिनियम बनाया, उसके अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन के विकास का तृतीय चरण प्रारम्भ हुआ—प्रथम चरण में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वे गतिविधियाँ थीं जिनके अनुसार उसने एक व्यापारिक कम्पनी के रूप में यद्वाँ की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर प्लासी का युद्ध जीतने और दीवानी का अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। दूसरा चरण या 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट का पास किया जाना जिसके अनुसार कम्पनी तथा ब्रिटिश सरकार की मिली-भगत से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण प्रसार हो गया। इस बीच विभिन्न चार्टरों द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का विकास होता रहा। तृतीय चरण 1858 से प्रारम्भ होकर 1947 तक रहा। इस अवधि में भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन था और इसी अवधि में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन छिड़ा।

जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रश्न है, उक्त प्रथम चरण में उसका अस्तित्व नहीं के बराबर था। उस युग में भारतीय नरेशों तथा सम्राटों की दुर्बलता एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव भारत की राजनीतिक पराधीनता के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश राज के दूसरे चरण में भी यह कमी बनी रही। परन्तु इस काल के अन्तिम वर्षों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी। 1857 की क्रान्ति वास्तव में केवल एक सैनिक विद्रोह अथवा थोड़े से राजा नवाबों की ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध वगावत नहीं थी। इस विद्रोह के पूर्व, विद्रोह की अवधि में तथा विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश शासकों की नीति भारतवासियों को यह चेतावनी देती सिद्ध हुई कि अंग्रेज लोग भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सर्वाङ्गीण शोषण करना चाहते हैं। 1857 की क्रान्ति सुनियोजित तथा सुसंगठित नहीं थी, अन्यथा यदि यह सफल हो जाती तो 1857 से ही भारत का राजनीतिक इतिहास बदल जाता। परन्तु इस क्रान्ति तथा इसके पश्चात् की ब्रिटिश शासकों की गतिविधियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना का निरन्तर विकास किया, अतः 1858 के उपरान्त के सांविधानिक विकास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अध्ययन में भारत के सांविधानिक विकास का समानान्तर अध्ययन करना आवश्यक है।

(आ) सेना का पुनर्गठन—ब्रिटिश सरकार ने 1858 में पील आयोग की स्थापना की और उसकी समितियों के आधार पर 1861 में भारत की सेना का पुनर्गठन किया। चूँकि 1857 की घटना सैनिक विद्रोह के रूप में प्रकट हुई थी, अतः अब अंग्रेजों ने भारतीय सेना पर विश्वास करना छोड़ दिया। सेना में उच्च पद तो अंग्रेजों को दिये ही जाते थे, साथ ही अब गोरों की सेना को जविक सुदृढ़ किया जाने लगा। सेना के डिवीजनों का संगठन जातीयता तथा प्रान्तीयता के आधार पर किया गया, यथा मिर्ख, जाट, मराठा, गोरखा, राजपूत आदि के रेजीमेन्ट। समस्त उद्देश्य विभिन्न जातियों तथा प्रान्तों के सैनिकों की टुकड़ियों को आवश्यकता पटने पर एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर लेना था। यह कदम भारतवासियों में अंग्रेजों की 'फूट डालो' की नीति का प्रारम्भ था। भारतीय सेनाओं के ऊपर ब्रिटिश अधिकारियों का नियन्त्रण

कठोरतम बनाया गया। सना म मुसलमानों को 'यूनतम स्थान दिया गया। क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों की यही धारणा थी कि भारत में उनका पूर्ववर्ती 'गामक' मुसलमान थे और वे पुनः अपना भूत प्राप्ति करना चाहते थे।

(इ) विदेशी सत्कृति का विकास—अंग्रेजों ने भारतीयों को वैदेशिक दासता का गिकार बना बना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यन्त समझ और 'स दृष्टि से उ'हान पाश्चात्य पद्धतियाँ को अधिक 'गोमप्रिय बनाने का प्रयास किया। भारत में ब्रिटिश 'ग की 'याय पद्धति लागू की गयी। मसदीय प्रणाली का लागू करने का उद्देश्य से 1861 में भारतीय परिषद् अधिनियम (Indian Councils Act 1861) लागू किया। अंग्रेजों ने तथा सत्कृति का प्रसार के लिए 1858 में कानून 'मन्त्र तथा बम्बई में वि'वविद्यालयों की स्थापना का गयी। स प्रकार अंग्रेजों का उद्देश्य अब भारतीयों पर वैदेशिक विजय प्राप्त करना हा गया ताकि भारतवासियों अपनी भारतीय परम्पराओं सत्कृति आदि की भूतकर राष्ट्रीय प्रगति न कर सकें और अंग्रेजियत के दास बन जाय।

(ई) जातीय भेदभाव का शीघ्रण—1857 का विद्रोह से अंग्रेजों ने यह निष्कर्ष निकाला कि 'सके लिए हिंदुओं की 'पेक्षा मुसलमानों अधिक उत्तरदायी थे क्योंकि भारत में अंग्रेजों का पूर्ववर्ती शासक होने का नाते वे अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त कर लेना चाहते थे। अतः अंग्रेजों ने मुसलमानों पर अविश्वास करना प्रारम्भ किया। या ता अब अंग्रेज सभी भारतीयों को शका का दृष्टि से देखने लग गये थे तथापि 1857 का पदचान् मुसलमानों को उच्च पदों से वचित रखा गया। सना में उ'ह कोई प्रोत्साहन नहीं लिया गया। यद्यपि महाराजों की विलोपना (1858) में कहा गया था कि जातिपाति घम रग आदि का भेदभाव किये बिना सभी भारतवासियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जायगा तथापि 'स नीति पर अत्यन्त सावधानी के साथ आचरण किया जाने लगा। 'ससे पूर्व अंग्रेज लोग भारतवासियों से बहुत अधिक सामाजिक सम्पर्क रखते थे परन्तु अब वे उसे भी समाप्त करने लगे और भारतवासियों को अपने से हीन मानकर घणा की दृष्टि से देखने लगे।

(उ) देशी राजा तथा नवाबों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन—यद्यपि 1857 तक अंग्रेजों ने भारत की अधिकांश भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और 'समें उनका स्वेच्छा चारी शासन स्थापित हो चुका था तथापि अभी भी देश के अन्तर अनेक गियामतें ऐसी थी जो 'गों राजा या नवाबों के द्वारा शासित थी परन्तु वे ब्रिटिश शासन से पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं थी। उनके साथ ब्रिटिश सरकार ने विविध संधियाँ की थी जिनके अन्तर्गत वे राजा या नवाब ब्रिटिश सरकार के दबाव में ही थे। अंग्रेजों ने अब भारतीय जनता के रोप का विरुद्ध उ'ह ऐसे प्रतिक्रियावादी तत्वों का रूप में खड़ा करना प्रारम्भ किया जिनकी सहायता से वे अपनी स्थिति का और अधिक सुदृढ़ कर सकें। अतः महाराजों का घोषणा में उ'ह यह आवासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार उनके अधिकारों सम्मान तथा स्थिति को अपना हा समझा और उनके साथ हुई संधियों का पूर्ण रूप से मानेगी। ये देशी राजा तथा नवाबों के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में भारतवासियों के भाग में प्रतिक्रियावादी रोंडे सिद्ध हुए और 1947 तक उनका कायभाग स्वतन्त्रता आन्दोलन में देश के नेतृत्व के विरुद्ध ब्रिटिश राजभक्ति प्रदर्शित करने का बना रहा।

1857 के विद्रोह की समाप्ति पर भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के अधिकार का अन्त करने तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वयं भारतीय शासन अपने हाथ में ले लेने का सम्बन्ध में 1858 में जो कानून ब्रिटिश संसद ने पास किया था वह एक प्रकार से अन्तरिम कानूनी व्यवस्था थी, 'सका वास्तविक रूप 1861 के इण्डिया कोडिफिकेशन एक्ट में मत्त हुआ।

1861 से 1885 तक की अवधि में राष्ट्रीयता का विकास

राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव—1857 के विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लग गयी थी। मासायत मासायवाद का तथा

विशेष रूप से भारत के सदर्थ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उद्देश्य उपनिवेश की जनता का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शोषण रहा था। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जाता कि विदेशी राजनीतिक दासता के पत्रों में जकड़ी किसी पराधीन देश की जनता में राष्ट्रवादी भावना का संचार शोषक देश ही करता है। यद्यपि 1857 की क्रान्ति को विदेशी सरकार ने तलवार तथा शस्त्र बल से दबा लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी, तथापि जिस म्वेच्छाचारितावाद की नीति से इसके पश्चात् ब्रिटिश सरकार भारत में अपना साम्राज्य सुदृढ़ करने में तुल गयी, उसकी प्रतिक्रिया यही हुई कि भारत में राष्ट्रवादी तत्त्व विकसित होने लगे और उनका मुख्य उद्देश्य देश को पराधीनता से मुक्त कराना था। परन्तु आवश्यकता इस बात की थी कि भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को सुमगठित किया जाये। ब्रिटिश शासन भारत में इतनी सुदृढता से स्थापित हो चुका था कि उसे उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय एकता तथा संगठन में युक्त देशव्यापी आन्दोलन को भी उतना ही अधिक सुदृढ तथा शक्तिशाली बनाया जाये। भारत की आम जनता का विशाल भाग ऐसी राष्ट्रीय तथा राजनीतिक चेतना से युक्त नहीं था। अतः 1857 के पश्चात् जहाँ राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास के कार्य-कलाप देश में विकसित होने लगे, वहाँ ब्रिटिश शासन के अत्याचार भी उसी गति से बढ़ने लगे। ब्रिटिश शासकों ने राष्ट्रीय चेतना तथा आन्दोलन को दबाने में अपनी दमनकारी नीतियों को किसी प्रकार कम नहीं किया। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास को भी सामग्री प्राप्त होती गयी। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय चेतना में विकास होने लगा त्यों-त्यों ब्रिटिश शासकों ने देश की राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ की जनता में भेदभाव तथा विघटन उत्पन्न करने के माधनों को प्रोत्साहन देना शुरू किया, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। 1885 तक भारतीय राष्ट्रीय चेतना को बलशाली बनाने में ब्रिटिश शासकों के निम्नांकित कार्य-कलापों का योगदान था

(1) अकाल तथा दरबार—जब 1876 में लार्ड लिटन भारत का गवर्नर-जनरल बनकर आया तो उसने भारत में अनेक दमनकारी तथा समय के प्रतिकूल व्यवहार प्रारम्भ किये। वह पक्का साम्राज्यवादी था। उस काल में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ रहा था। परन्तु उसने 1877 में देहली में एक शानदार दरबार आयोजित किया जिसका उद्देश्य महारानी विक्टोरिया को कैसर-हिन्द की उपाधि से सम्मानित करना था। इसमें लाखों रुपया व्यय किया गया जबकि अकाल पीड़ित जनता को राहत देने के कार्यों की उपेक्षा की गयी। भारतवासियों में ब्रिटिश शासकों की इस उपेक्षा-नीति से शोषण असन्तोष होने लगा। विद्वानों ने लिटन के इस आचरण की तुलना प्राचीन रोम की इस कहावत से की है कि 'जब रोम जल रहा था तो नीरो बाँसुरी बजा रहा था' (Nero was fiddling while Rome was burning)।

(2) वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट—लार्ड लिटन ने अनुभव किया कि भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस समय तक भारत में 400 से भी अधिक देशी भाषाओं के पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इनके द्वारा लार्ड लिटन की दमनकारी शासन नीति का विरोध किया जाने लगा था। ब्रिटिश नौकरशाही इस विकास को सहन नहीं कर सकती थी। लार्ड लिटन को विश्वास हो गया कि भारतवासियों को समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता प्रदान करना ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हानि पहुँचाना है। अतः 1878 में उसने व्यवस्थापिका से तुरन्त वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास करवाकर भारतवासियों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार में वंचित कर दिया। इस कानून के अन्तर्गत जिलाधीशों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे समाचार-पत्रों के प्रकाशकों तथा प्रेसों में जमानते माग सकते थे ताकि वे शासन की नीतियों के विरुद्ध कोई विचार व्यक्त न करने की प्रतिज्ञा करें। उनकी अवज्ञा करने पर जमानत जप्त कर ली जाती थी और ग़ामन के ऐसे कार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में अपील न करने की जा सकती थी। यह कानून भारतीय प्रेस ने विरुद्ध एक तीव्र

प्रतिगामी कदम था। इस कानून को लागू करने में भी गायन के अधिकारियों ने कोई कमी बाकी नहीं रखी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता में भीषण असंतोष फैला और इस कानून के विरोध में एक दशवर्षी आन्दोलन उमड़ पड़ा। इंग्लैंड में उदार दलीय नेता मंडस्टन ने भी इसकी निंदा की और भारत का वात्सराय होने से पूर्व ना रिपन ने भी इसे अनावश्यक तथा अवाञ्छनीय कहा।¹ यह आन्दोलन पर्याप्त सुदृढ़ हो गया और पांच वर्ष तक लगातार चलता रहा। इस कानून को सरकार ने तभी निरस्त किया जबकि नाड रिपन जो भारतवासियों के सबसे बड़े हिन्दी गवर्नर जनरल माने गए हैं ने इस कानून की बुराई को देखते हुए इसे रद्द करने का प्रस्ताव किया। इस कानून ने भारत में देशवादी राष्ट्रीयता की गहराई फटाने का कार्य किया।

(3) कपास आयात-कर का उन्मूलन—नाड रिपन ने भारत में राष्ट्रीयता की गहराई को और अधिक सुदृढ़ बनाने में अपनी साम्राज्यवादी नीति का एक और दृष्टान्त प्रस्तुत किया। उसका उद्देश्य इंग्लैंड के नागापूर तथा मान्चेस्टर के कपास के कारखानों के भागियों को लाभान्वित करने के निमित्त भारत में नव-स्थापित देशी कपास कारखानों को नष्ट करना था। यद्यपि भारत के नव-स्थापित कपास कारखानों अनेक असुविधाओं के होते हुए तथा समुचित प्रोत्साहन के अभाव में भी पर्याप्त प्रगति कर रहे थे तथापि साम्राज्यवादी शासक उनकी ऐसी उन्नति को सहन नहीं कर सकते थे। उन्हें नुस्खाना पहचान के उद्देश्य से नाड रिपन ने इंग्लैंड के कारखानों से तयार कपास के मान से आयात-कर हटा दिया ताकि उन कारखानों का मान भारत में और अधिक सस्ता बिक सके। इस कानून का विरोध स्वयं वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद् में किया गया था परन्तु नाड रिपन ने उसकी परवाह न करके इसे पास कर दिया। भारत के व्यापारियों के तीव्र विरोध के बावजूद इस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इससे भारतवासियों को महान् क्षोभ व असंतोष हुआ। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि ब्रिटिश शासन भारत का हर प्रकार से शोषण करने पर तुले हैं। स्वाभाविक था कि इसके कारण राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा।

(4) नाड रिपन के अन्य कार्य कलाप—नाड रिपन ने कानून के ऊपर अनावश्यक चढ़ाई करके अफगान युद्ध का खतरा मोटा लिया और उसके निमित्त सेना सचय में बहुत धन व्यय किया। उसने देश की गरीबी अज्ञान तथा भुलसूरी की उपेक्षा करके ऐसी युद्ध-नीति अपनाकर भारत की जनता में और अधिक असंतोष फैलाया। 1857 के विद्रोह के पश्चात् अग्रज लोग भारतवासियों को न्याय की दृष्टि से देखने लग गये थे। नाड रिपन सच्ची प्रतिगामी वात्सराय के लिए यह बात अस्वाभाविक नहीं थी कि वह भारतवासियों को अगस्त बनाने में कोई कमी करता। उसने अपने शासन काल में गम्भीर विधेयक पास करके ऐसा कानून बनाया जिसके अनुसार भारतवासियों को बिना सरकार की आज्ञा प्राप्त किया गन्ना रखने का अधिकार नहीं रहा। परन्तु भारत में रहने वाले यूरोपीय व्यक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होता था। इस प्रकार रिपन ने भारतवासियों को निराश कर दिया। साथ ही इससे सम्बद्ध जातीय भेदभाव की नीति के कारण भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिनिधित्व दर्जाना स्वाभाविक था। भारतीय नेताओं की दृष्टि में यह कानून भारतीयों का महान् अपमान था क्योंकि इसके द्वारा भारतीय जनता को स्वयं अपने ही देश में हीनतर स्तर का नागरिक बना दिया गया था।

(5) भारतीय सिविल सेवा—जबमें भारतीय सिविल सेवा का आरम्भ हुआ था तभी से शिक्षित भारतीय नवयुवक इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड जानागे और अनेक प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में इंग्लैंड के अभ्यर्थियों से उच्च प्रतिभा प्रदर्शित करनी शुरू की। ब्रिटिश शासन इसे सहन नहीं कर सके। अतः भारत के नवयुवकों को इसमें वंचित रखने के उद्देश्य से इस परीक्षा की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष

¹ स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी रामकृष्ण परमहंस 'मक' अपनाते हैं।

कर दी गयी, ताकि इस अल्पायु मे भारत का कोई भी नवयुवक इस परीक्षा का लाभ न उठा सके। इस नियम के विरुद्ध भारतीय शिक्षित वर्ग ने व्यापक आन्दोलन छेड़ा और इंग्लैण्ड की मसद के समक्ष इसके विरोध मे स्मरण-पत्र भी प्रस्तुत किये गये। इस आन्दोलन को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इण्डियन एसोसियेशन के माध्यम से सुनियोजित ढंग से सम्पन्न किया गया।¹ परिणामस्वरूप कालान्तर मे ब्रिटिश सरकार को पुन इण्डियन सिविल सर्विस की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष करने को विवश होना पड़ा। परन्तु इसके कारण राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक बल मिला।

(6) इलवर्ट विल विवाद—लार्ड लिटन के पश्चात् लार्ड रिपन भारत के गवर्नर-जनरल बनकर आये। वह अत्यन्त उदार व्यक्ति थे। उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पूर्ववर्ती वाइसराय की नीतियो तथा कार्य-कलापो से भारतवासियो मे महान् असन्तोष फैला है। साथ ही यह भी कि लार्ड लिटन की अनेक नीतियाँ अत्यन्त अवाछनीय थी। लार्ड लिटन के काल तक भारत मे यूरोपियनो के विवादो की सुनवाई भारतीय सेशन जज या जिलाधीश नहीं कर सकते थे। अत न्याय कार्य मे भी जातीय भेदभाव की नीति प्रचलित थी। लार्ड रिपन की कार्यकारिणी के एक सदस्य सर इलवर्ट कोर्टनी ने भारतीय व्यवस्थापिका परिपद् मे एक विधेयक इस उद्देश्य का रखा कि न्यायिक क्षेत्र मे इस भेदभाव को समाप्त कर दिया जाये। इलवर्ट विल के द्वारा भारतीय जिलाधीशो तथा सेशन जजो को यूरोपियनो के विवादो को तय करने का भी अधिकार दिया गया, परन्तु इससे यूरोपियनो को बड़ा क्षोभ हुआ। उन लोगो ने इस कानून का घोर विरोध किया। वे रिपन की उदार नीति से असन्तुष्ट तो थे ही क्योंकि रिपन ने अपने शासन काल मे बर्नाक्विलर प्रेस ऐक्ट को रद्द कर दिया था, अफगानिस्तान के साथ भी एक सम्माननीय सधि करके सैनिक व्यय को कम किया था और भारतवासियो के प्रति उनका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। परन्तु इलवर्ट विल का विरोध उन्होंने जी-जान से किया। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि इस कानून का भारतीय न्यायाधीश अनुचित लाभ उठायेगे। वे यूरोपियनो के मामलो को निर्णीत करने के लिए अक्षम है। इन लोगो ने लार्ड रिपन के विरुद्ध अनेक अपमानजनक व्यवहार भी किये। इस विवाद का अन्त तभी हुआ जबकि यह समझौता किया गया कि यूरोपियनो के विवादो की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन ज्यूरी की सहायता से कर सकेंगे। परन्तु इन सारे काण्ड ने भारतवासियो के हृदय मे अंग्रेजो के प्रति विरोध उत्पन्न कर दिया। अब भारतवासियो को स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज उन्हें हर तरह से हीनता की स्थिति मे रखना चाहते हैं।

(7) इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना—1857 के विद्रोह के पश्चात् और विशेष रूप से लार्ड लिटन की दमनकारी नीतियो के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न प्रांतो मे अनेक प्रकार के समुदायो की स्थापना होने लगी थी। परन्तु ये समुदाय विशुद्ध रूप से स्थानीय अथवा क्षेत्रीय प्रकृति के थे और इनका क्षेत्र भी सीमित था इन्ही मे से सुरेन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 मे स्थापित इण्डियन एसोसियेशन भी एक था। परन्तु इसकी विशेषता यह थी कि इसे 'इण्डियन' कहा गया था, जिसके कारण इसका क्षेत्र तथा स्वरूप राष्ट्रीय था। तत्कालीन सरकार की दमन नीतियो के कारण भारत मे जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी उसको संगठित तथा एकीकृत करने के उद्देश्य से सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत का भ्रमण किया, ताकि वे ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियो के विरुद्ध देश-व्यापी जनमत का निर्माण कर सके। जब इण्डियन सिविल सर्विस के लिए न्यूनतम आयु कम कर दी गयी और इलवर्ट विल के विरोध मे यूरोपीय लोगो ने 150000 रुपया एकत्र करके यूरोपीय प्रतिरक्षा संगठन (European Defence Association) स्थापित किया और अपने पक्ष मे इस कानून को पास करा लिया तो भारत मे भी इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राष्ट्रीय कोष एकत्र किया गया जिसका उपयोग

¹ ताराचन्द, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास (2), 379।

अन्य विन विवाह में भारत के पक्ष का प्रस्तुत करने में हानि वान व्यय के लिए किया जाना था। जून 1883 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कानूनी में तीन विधायी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन को जाह्न किया। इसमें विभिन्न प्रान्ता के प्रतिनिधियां ने भाग लिया। यह सम्मेलन यद्यपि उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ। इससे यह स्पष्टतया प्रकट हो गया कि भारत में राष्ट्रीय चेतना सक्रिय रूप से जागृत हो चुकी है और उसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों का विरोध करना है क्योंकि ब्रिटिश शासन हर प्रकार से भागनवाशियों का दवान व नीचा लिखान के प्रयत्न में लग है।

नाइ रिपन के चले जाने पर नाइ रिपन (1880-84) के वाइसरायत्व काल में उसकी शासन नीतियों में जो उदारता दिखायी गयी उसके कारण भी भारत के जनक निमित्त वर्गों में यह धारणा उत्पन्न हुई कि अत्याय तथा अत्याचारपूर्ण शासन का संगठित विरोध उस समाप्त कर देने में सहायक सिद्ध होता है अतएव यन्त्रि भारतीय राष्ट्र भावना का संगठित करके विरमित किया जायगा तो भारत में ब्रिटिश सरकार की अत्यायपूर्ण तथा शापणवागी नीतियों के ऊपर प्रतिरोध लग सकेगा। नाइ रिपन ने रिपन के जनक अत्याय कदमों का समाप्त किया था। साथ ही उसके शासनकाल में भारत में स्वायत्त के निमित्त स्थानीय स्वायत्त शासन का संगठन हुआ। इससे भी भारतीय राष्ट्रीय भावना का विकसित होने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला। रिपन के चले जाने पर नाइ रिपन के शासन काल में निश्चित रूप में भारतीय राष्ट्रीयता का संगठित स्वरूप प्रस्फुटित हो गया।

प्रश्न

- 1 उन्नावी सता 1 के अन्तिम चरण में भारत में राष्ट्रीय जागरण के क्या कारण थे ?
- 2 नाइ रिपन के शासनकाल में कौनसे काम हुए जिन्होंने भागनवासियों में राष्ट्रीय चेतना का जन्म दिया ?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

(INDIAN NATIONAL CONGRESS EARLY PHASE)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति के कारण

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का अभिप्राय उस आन्दोलन से है जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यशाही की दासता से भारत को मुक्त करना था। बहुधा यह माना जाता है कि इस आन्दोलन का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885 में स्थापित) के समानान्तर है। परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति का एकमात्र श्रेय कांग्रेस को ही प्रदान करना पूर्ण सत्य नहीं है। जैसा गत अध्यायो में दर्शाया गया है, भारत की राष्ट्रीयता अति पुरातन है। मध्य युग में अफगानों तथा मुगलों के राजनीतिक प्रभुत्व तथा उसके पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्यशाही के प्रभुत्व ने भारत की जनता की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना को दबाए रखा था। ब्रिटिश शासन की कूटनीतियों ने इस भावना को प्रकट में ला दिया। उस युग में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अभ्युदय में विविध तत्वों का योगदान रहा है—

(1) अठ्ठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदियों के सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलन—भारत में अत्यन्त दीर्घकाल से विधर्मियों के शासन के कारण हिन्दू धर्म को भीषण क्षति पहुँची थी। हिन्दू समाज अपनी सस्कृति को भूलने लग गया था। मुसलमानों तथा अंग्रेजों के शासन काल में इस्लाम तथा ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिन्दू समाज की इस हीनावस्था का लाभ उठाने का प्रयास किया। फलस्वरूप हिन्दू समाज की राष्ट्रीयता की भावना कुण्ठित होने लगी। 1828 में बंगाल में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिन्दू समाज को अपनी प्राचीन सस्कृति की महानता को समझने का अवसर प्रदान किया। उनके इस कार्य को देवेन्द्र नाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके हिन्दू समाज को अपनी वैदिक सभ्यता को समझने में मदद की। इन समाज-सेवकों तथा धर्म-सुधारकों ने हिन्दू धर्म की व्याख्या करके उसमें प्रचलित अन्धविश्वास तथा नैराश्य भाव को दूर करने का प्रयास किया और समाज को हिन्दू धर्म की महत्ता तथा उसकी वास्तविकता से परिचित कराया। राजा राममोहन राय ने बाल-विवाह, सती-प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दू धर्म तथा हिन्दू सस्कृति की महत्ता से न केवल हिन्दू समाज को ही प्रभावित किया, अपितु विदेशों तक में उन्होंने हिन्दू धर्म तथा सस्कृति की श्रेष्ठता का प्रबल प्रचार किया। श्रीमती ऐनी बेसेंट ने स्वयं हिन्दू धर्म को ग्रहण कर लिया और उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के कारण धार्मिक जागृति को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। उत्तरी भारत में आर्य समाज का व्यापक प्रचार स्वामी दयानन्द के अन्य प्रभावशाली शिष्यों, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपत राय आदि ने किया। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे ने ब्रह्म समाज के सहज प्रार्थना समाज की स्थापना की। उमका उद्देश्य भी हिन्दू समाज में आ गयी बुराइयों, सकीर्णताओं तथा कुप्रथाओं को दूर करना था। इन आन्दोलनों ने हिन्दू समाज की एकता बढ़ाने, अन्धविश्वास का त्याग करने तथा धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का अन्त करने में बहुत मदद की। इनके परिणामस्वरूप देश के सभी

भागा म भारत म राष्ट्रीयता की भावना क विकास को भी पर्याप्त बन मिला । इन धार्मिक ममाजा ने अनेक बड़ी-बड़ी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करवायी । इन धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण आन्दोलनों का प्रभाव राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन पर भी पड़ा । दूसरी ओर मुसलमानों का अन्दर भी सरसय अहमद खान सद्गुरु नेताओं ने सुधार आन्दोलन जारी किया और मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने पर प्रोत्साहित किया तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयत्न प्रोत्साहित किया । जहाँ धियोसाफिकन सासाब्दी ने हिंदू सद्गुरु स्कूल बनारस की स्थापना की वहाँ सर सयद अहमद ने अलीगढ़ जामिया बनारस अलीगढ़ म मुहमदन ऐंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना करवायी । इस प्रकार इन आन्दोलनों तथा उनके नेताओं का विचारानुसार भारतीय जनता म भारतीय संस्कृति का प्रति प्रेम तथा श्रद्धा की भावना को जाग्रत करके देश प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम को प्रोत्साहित किया । भागा म यह धारणा बनवती होने लगी कि अपने धर्म तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखने तथा उनका विकास करने के लिए यह बात आवश्यक है कि देश म विदेशी शासन न रहे । राष्ट्रीय स्वाधीनता इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है । साथ ही इन सुधार आन्दोलनों ने भारतीय जनता को अनेक सामाजिक कुरीतियों का समाप्त करके अधविद्यमानों को त्यागने की प्रेरणा भी दी ।

इन आन्दोलनों का कुछ प्रवर्तकों पर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी पर्याप्त था ।¹ पाश्चात्य शिक्षा ने उन्हें उन देशों के सुधार आन्दोलनों की प्रेरणा दी और विवेक तथा विज्ञान का आधार पर अपनी संस्कृति का सुधारने का प्रोत्साहन दिया । यद्यपि ये धर्म-सुधारक राष्ट्रवादी थे तथापि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता की कामना करत हुए पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा तथा व्यवस्थाओं की भनाइयाँ का भी स्वीकार किया । उनकी शिक्षाओं के प्रभाव से भारतवासियों म नयी चेतना जाग्रत हुई । यद्यपि हिंदू तथा मुस्लिम समाज एवं धर्म सुधार आन्दोलनों की समानान्तर प्रगति ने बाद के काल म साम्प्रदायिक भावना के विकास म मदद दी तथापि साम्प्रदायिक गतिविधियों के गतिमानों विचारों के हातों हुए भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध म राष्ट्रीयता का पौधा घटना चला गया ।²

✓(2) ब्रिटिश शासन तथा भारतीय एकता—भारत की राष्ट्रीय एकता से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । ऐतिहासिक भौगोलिक सांस्कृतिक धार्मिक आदि विविध दृष्टियों से भारत सदैव एक राष्ट्र रहा है । यद्यपि भारत की राजनीतिक एकता के माग म ब्रिटिश शासन के पूर्व अनेक बाधाएँ रही तथापि अनेक शासन कालों म समूचा भारत एक राजनीतिक इकाई भी रहा था । अंग्रेजों ने 1857 तक लगभग समूचा भारत को एक शासनिक इकाई के रूप म परिणत कर दिया था । इसका परिणाम यह हुआ कि सार देश की प्रशासनिक व्यवस्था राजकीय कानून एवं न्याय पद्धति समरूप हो गयी । इसके कारण समस्त भारतवासियों का हित तथा कष्ट एक से हो गए । यह बात भारतवासियों के लिए बड़े गौरव की है कि उनमें विधर्मियों का साथ राष्ट्रीय सह-अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रही है । भारत म हिंदू तथा मुसलमान अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदि मामलों म परस्पर भिन्न जुनकर रहे रहे थे । ब्रिटिश शासन से उत्पन्न कष्ट दोनों सम्प्रदायों के लिए समान होने के कारण उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना का उदय होने लगा । यह तो बाद म ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की चान रही कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए फूट डालना और राय करों की नीति अपनाकर इन दोनों सम्प्रदायों का मध्य फूट उत्पन्न कराने का अभियान चलाया । ब्रिटिश शासन ने भारत म रेल तार डाक आदि की व्यवस्था की । यद्यपि ऐसा उन्होंने केवल अपने शासन की सुविधाओं तथा अंग्रेज व्यापारी तथा व्यवसायियों के हितों को ध्यान म रखकर ही किया तथापि इन साधनों ने भारतीय राष्ट्रीय एकता का विस्तार करने म भी मदद पहुँचाई । अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्थाओं म अंग्रेजी भाषा को

शिक्षा का माध्यम बनाने का परिणाम यह हुआ कि देश के विभिन्न भागों के शिक्षित भारतीयों को परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्राप्त हो गयी। उन्हें अपनी सामूहिक समस्याओं पर एक साथ विचार करने के लिए आसानी से एकत्र होने की सुविधा प्राप्त हुई और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विविध भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोग एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार-विनिमय करने लगे। इससे उनमें एकता की भावना बढ़ने लगी।

(3) पाश्चात्य शिक्षा तथा सस्कृति—भारत में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली (Western system of education) के फलस्वरूप उच्च शिक्षा प्राप्त भारतवासियों को पाश्चात्य देशों के दर्शन, राजनीतिक समस्याओं तथा आन्दोलनों, इतिहास, साहित्य आदि का अध्ययन करने का अवसर मिला। इन शिक्षित वर्गों के ऊपर मैजनी, रूसो, वाल्टेयर आदि के क्रान्तिकारी विचारों तथा लॉक, बर्क, मिल, माटेस्व्यू, मैकॉले आदि की रचनाओं का प्रभाव पड़ा। साथ ही फ्रांस की क्रान्ति अमरीकी स्वातन्त्र्य संग्राम, इंग्लैंड की जनता के स्वतन्त्रता-प्रेम आदि के अध्ययनों ने भी उन्हें अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की आकांक्षा रखने की प्रेरणा दी। इस समूचे साहित्य के अध्ययन ने भारतीय शिक्षित वर्ग के मनोबल को उन्नत किया। साथ ही उन्हें पाश्चात्य साहित्य तथा दर्शन के प्रति अगाध प्रेम रखने की प्रेरणा दी। इस प्रकार यद्यपि भारत में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली लागू करने का ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य भारतीय शिक्षित वर्ग को केवल छोटे-छोटे शासकीय पदों पर नियुक्त करना तथा भारतवासियों में पाश्चात्य ढंग की शासन तथा न्याय-व्यवस्था के प्रति आस्था रखने की भावना का प्रचार करना था, जिससे कि वे भारत में अपने ढंग की शासन-व्यवस्था को लोकप्रिय बना ले और भारतवासियों में यूरोपीय शिक्षा, सभ्यता तथा सस्कृति के प्रति निष्ठा जाग्रत करके उन्हें सदा अपनी दासता में बनाए रखे, तथापि उनकी इच्छा के प्रतिकूल यह प्रणाली भारतवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने के निमित्त वरदान सिद्ध हुई। शिक्षित भारतवासियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि विदेशी शासकों का उद्देश्य भारत का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखना तथा भारतवासियों को सदैव दामता की स्थिति में रखना मात्र है, साथ ही यह भी कि कोई राष्ट्र या जाति पराधीन रहकर उन्नति नहीं कर सकती। पाश्चात्य देशों के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों के अध्ययन ने भारतवासियों को भी यह पाठ पढ़ाया कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन प्रारम्भ करके वह भी स्वतन्त्र राष्ट्र बन सकते हैं। यह भी एक कारण था कि प्रारम्भ के भारतीय देश-भक्त राष्ट्रीय नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली का स्वागत किया ताकि अधिकतम भारतवासी पाश्चात्य देशों के साहित्य तथा इतिहास के अध्ययन द्वारा अपनी राष्ट्रीय चेतना को विकसित कर सकें। अतएव पाश्चात्य शिक्षा भारत में राष्ट्रीय जागरण के लिए वरदान सिद्ध हुई। दादा भाई नौरोजी के विचार से पाश्चात्य शिक्षा से हमें एक नूतन प्रकाश मिला है और उसने बताया कि 'राजा प्रजा के लिए होता है, न कि प्रजा राजा के लिए', राजा राममोहन राय ने भी पाश्चात्य शिक्षा को भारत के लिए वाछनीय माना था। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेतागणों ने (आरम्भ से अन्त तक) पाश्चात्य शिक्षा के कारण ही प्रेरणा प्राप्त की थी। इस दृष्टि से पाश्चात्य शिक्षा तथा सस्कृति के प्रसार का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान है।

(4) भारतीय प्रेस का योगदान—भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने में भारतीय समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में प्रेस का विकास यूरोपियनों ने प्रारम्भ में ईसाई धर्म प्रचार के साहित्य का प्रसार करने के उद्देश्य से किया था। आन्तरिक में प्रारम्भ के कुछ उदार गवर्नर जनरलों ने भारत में प्रेस के विकास तथा उसकी स्वतन्त्रता को प्रोत्साहित किया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रेस को ऐसा प्रोत्साहन ईमानदारी की नीयत से दिया गया था, क्योंकि ऐसा करने में भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी के कई निहित स्वार्थ भी थे। उनमें विद्यालय देश का शासन संचालित करने के लिए उन्हें जनमत का ज्ञान करना

आवश्यक था। जन प्रतिनिधि-सभा का अभाव में प्रस ही एकमात्र ऐसा साधन था जो आमका को जनता की समस्याओं का ज्ञान करा सकता था यदि शासक यह सुविधा भी न दें तो उन्हें दिए शासन चलाना कठिन हो जाता परन्तु भारत में प्रस का विकास पर्याप्त गति में हुआ। गीघ ही अग्रजी तथा विविध भागतीय भाषाओं में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन होने लगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात् भारतीय समाचार-पत्रों में शासन की दुर्व्यवस्था तथा गिरावट की निर्भीकता के साथ प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। साथ ही प्रांतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों में जागृत भारतीय पत्रों के शासन के प्रति पत्रपातपूर्ण विचारों की भी खूब रूप में आलोचना की। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के जनसाधारण में शासन की नीतियों के विरुद्ध जनमत का निर्माण करने तथा जनता को शासन की व्यवस्था से अवगत कराने में भारतीय समाचार-पत्रों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। इसके कारण जनता में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करने में बहुत सहायता मिली। यद्यपि ब्रिटिश शासक विद्रोह भूमि में पत्रों में एक दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध लगातार जान बूझ विचारों को प्रोत्साहन देने लगे थे तथापि अग्रजी और देशी भाषाओं के पत्र मिलकर भारत की एकता के सूत्र में बांधते चले जा रहे थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के सभी भारतीय नेताओं (गंगा राममाहन राय से लेकर श्री जवाहरलाल नेहरू तक) का जनता तक अपनी राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रसार करने में प्रस से बहुत अधिक सहायता मिली। समाचारपत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त आगम तथा भारतीय भाषाओं में नये साहित्य का सृजन होने लगा। भारत के राष्ट्रप्रेमी विद्वानों की राष्ट्रवादी विचारधाराएं प्रस के विकास के परिणामस्वरूप जनता में गति से प्रसारित होने लगीं। बकिमचन्द्र चटर्जी का जानपद मठ उनका गीत वदे मातरम् रवीन्द्र बाबू का जन गण मन मथिनीकरण गुप्त की भारत भारती तिलक का गीता रहस्य आदि विविध साहित्यों का सृजन प्रसार तथा प्रचार प्रस के विकास का ही फल था। पान्चात्य मान्यता के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन होने लगा। अतएव 1857 के पश्चात् भारतीय प्रस की तीव्र प्रगति ने राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने में बहुत मदद पहुँचाई।

(5) भारत की आर्थिक स्थिति—साम्राज्यवाद का प्रमुख उद्देश्य उपनिवेशों की जनता का आर्थिक शोषण होना है। राजनीतिक प्रभुत्व तो इस उद्देश्य का साधन है। अग्रज लोग भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे और अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें सभी संभवता मिलतीं जबकि उनका यह राजनीतिक आधिपत्य कायम हो जाता। सम्भवतः उन्हें यह आभास रहा कि वे भारत में अधिक दीर्घ अवधि तक शासन नहीं कर सकेंगे क्योंकि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लहर भारत में फैल बिना नहीं रह सकती और अथ उपनिवेशों की भाँति उन्हें भी भारत के राजनीतिक प्रभुत्व से हाथ धोना ही पड़ेगा। अतएव उनका प्रमुख उद्देश्य भारत में शासन करना भारत में निवासित हाकर यहाँ की जनता से मिल जुल जाना कभी नहीं रहा। उनमें जातीय श्रेष्ठता का दम इतना अधिक था कि वे कभी भी अपने को भारतीयों के साथ समानता की स्थिति में रखना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने मुर्गी के सब जणों एक साथ निकाल देने की नीति का अवलम्बन किया। पान्चात्य देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन निर्मित उत्पादों में मान का बढाने उस अधिकाधिक मान में बेचकर लाभ कमाने की प्रतियोगिता दिन-दूनी रात चौगुनी चल रही थी। इंग्लैंड में मचिस्टर निवासी जॉन डेविडसन का कारखाना की सख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी। इन कारखानों का पनपना विदेशों (उपनिवेशों) से प्राप्त कच्चे मान पर निर्भर था। अतः भारत के अग्रज शासकों ने भारत में केवल नए औद्योगिक कारखाने ही नहीं खोले अपितु यहाँ से कपास आदि कच्चे मान को इंग्लैंड पहुँचाकर वहाँ का मशीन द्वारा निर्मित तयार मान से भारत के बाजारों का भरना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत के करोड़ों गिल्स जीविया तथा कुटीर उद्योगों का भोषण आघात पहुँचा। यहाँ के जुताई लुहार चमार आदि गिल्स-जीविया के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो

गया। उद्योग-धन्यो में ऐसा भीषण अवरोध आ जाने के परिणामस्वरूप जनता का शहरीकरण रुक गया और करोड़ों शिल्प-जीवी ग्रामों की ओर बढ़ने लगे। कृषि-भूमि पर भार बढ़ गया। परन्तु अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा लागू करने का परिणाम यह हुआ कि कृषकों की स्थिति भी जमींदारों के अत्याचारों के कारण दयनीय हो गयी। कृषि भूमि पर भार बढ़ने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गयी और कृषि उत्पादन में कमी आने लगी। इस प्रकार भारत की जनता को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विदेशी शासकों की यह नीति कभी भी नहीं रही कि वे भारत में किसी भी प्रकार से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। इन सबके परिणाम-स्वरूप भारतवासियों में विदेशी शासन के प्रति रोष उत्पन्न होने लगा और वे यह प्रतीत करने लगे कि देश के आर्थिक पतन को बचाने का एकमात्र उपाय विदेशी शासन-सत्ता से देश को मुक्त कराना है।

1857 के विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश शासकों का दमन चक्र—1857 के विद्रोह के पश्चात् भारत में ब्रिटिश शासकों ने कठोर दमन की नीति अपनायी थी। इस सन्दर्भ में लार्ड लिटन की दमन नीतियों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अकाल पड़ने पर राहत कार्यों का उपेक्षा करना, सेना पर अनावश्यक व्यय, दरबारों में फिजूल खर्ची, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतवासियों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का दमन, भारतीय शस्त्र विधेयक, कपास आयात-कर का उन्मूलन आदि ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में आग के ऊपर तेल डालने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास के निमित्त इलवर्ट बिल विवाद ने तो विस्फोट का कार्य किया। इस घटना ने भारत की जनता को स्पष्टतया बता दिया कि अंग्रेज जाति भारतीयों के ऊपर श्रेष्ठता का दावा करती है। अतः यह एक आत्म-सम्मान का प्रश्न था जिसे कोई भी सम्माननीय भारतीय सहन नहीं कर सकता था। ब्रिटिश शासकों के इन कुचक्रों से भारत-वासियों को यह समाधान हो गया कि जब तक भारतवासी अंग्रेजों की राजनीतिक दासता में रहेंगे, तब तक उनको आत्म-सम्मान, आर्थिक विकास एवं उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसके ऊपर भारतीय सिविल सेवा के सम्बन्ध में भारतवासियों के समक्ष रोड़ा अटकाने के हेतु न्यूनतम आयु सीमा को कम कर देना भी इस बात का प्रमाण था कि ब्रिटिश शासक स्वयं अपनी प्रतिज्ञाओं को भी ताक में रख देते हैं। अतः ऐसा शासन भारतवासियों को सहनीय नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म

राष्ट्रीय चेतना की जागृति—ऊपर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के जिन कारणों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसके अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जहाँ ब्रिटिश शासक यह विश्वास कर रहे थे कि अब भारत में उनका साम्राज्यशाही शासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है और उन्होंने विरोधियों को भली-भाँति दबा लिया है, वहाँ दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध भारतवासियों में एक नई चेतना भी जाग्रत हो चुकी थी। यद्यपि अभी यह अकुरित ही हो रही थी, तथापि यह एक ऐसा बीज था जिसे नष्ट कर सकना ब्रिटिश शासकों के लिए असम्भव था। वह कहीं न कहीं से फिर अकुरित होता जाता। भारत में ऐसी राष्ट्रीय चेतना जाग्रत होने के बहुमुखी कारण थे, इनमें से लगभग सभी कारण ब्रिटिश शासन की ही देन कहे जा सकते हैं, यदि अंग्रेज लोग ईमानदारी की भावना से भारतीय प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर शासन की नीतियाँ अपनाते तो सम्भव था कि उनका साम्राज्य भारत में और जाने तथा यहाँ शासन करने का उद्देश्य रखते और अपने को भारतीयता के रंग में रंगना चाहते तो भारत का राजनीतिक इतिहास कुछ और होता, जिस प्रकार भारत में हिन्दू तथा मुसलमान साथ-

मात्र एक भारतीयता की भावना सह रह रहे हैं उमा प्रकार वे भी रह सकते थे परन्तु अग्रज भारत में भारतीय जनता के लिए कभी नहीं आये थे। उनका जातीय अभिमान शोषण नीति तथा दमनकारी शासन एक दुधारी तनाव के रूप में सिद्ध हुआ।

राष्ट्रीय चेतना को सक्रिय रूप में मिलना—19वाँ सदी के अन्त तक भारत में राष्ट्रीयता की चेतना जागृत हो चुकी थी परन्तु अभी उसमें सक्रियता का अभाव था जिस जागरण का रूप प्राप्त नहीं हो पाया था। कोई भी आन्दोलन बिना सुसंगठित प्रयास के सफल नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्रीय चेतना को सुसंगठित करने के प्रयासों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित एंग्लो-इण्डियन एसोसियेशन तथा उम्वई और मनास के प्रांतीय संगठन प्रथम कदम थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के द्वारा आहूत एंग्लो-इण्डियन कांग्रेस (1883) के अधिवेशन ने भारतीय राष्ट्रीय जागरण का सुसंगठित रूप में संचालित करने की प्रेरणा दी। अतः इंग्लो-इण्डियन एसोसियेशन का यह भारतीय राष्ट्रीय जागरण का प्रथम सक्रिय प्रयास कहा जाये तो यह सवथा उपयुक्त होगा। नाइलिटन के अत्याचारी कृत्या में भारत में पर्याप्त रोष उत्पन्न हो चुका था। परन्तु उसमें उत्तराधिकारी नाइलिटन की उदार नीतियाँ ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाने में सहायता दी। नाइलिटन के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रयोग किया जाना तथा नाइलिटन द्वारा की गई अनेक भूतों का सुधार किया जाना राष्ट्रीय आन्दोलन को उत्तार रूप में विवर्धित करने में सहायक सिद्ध हुआ। नाइलिटन के पश्चात् 1884 में नाइलिटन भारत के गवर्नर जनरल हुए। उसके शासन काल में भारतीय राष्ट्रीय जागरण की सशक्त महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना थी।

कांग्रेस की स्थापना—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मनाम मजबूत कोई भारतीय नहीं अतः भारतीय सिविल सेवा से अवकाश प्राप्त एक अग्रज व्यक्ति था। या तो ऐसी एक राष्ट्रीय समस्या की स्थापना आवश्यक हो चुकी थी और उसके लिए पर्याप्त भूमिका निर्मित हो चुकी थी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का एंग्लो-इण्डियन एसोसियेशन उसका स्थान ले सकता था। परन्तु एक अवकाश प्राप्त अग्रज आई. सी. एस. के मस्तिष्क में एक विचार का उत्पन्न होना एक महत्वपूर्ण बात है। वह व्यक्ति था सर एडमंड आस्टेवियन ह्यूम साहब का भारतीय प्रशासन का अनुभव तो था ही मात्र यह कि भारत में विकसित हो रही राष्ट्रीय जागृति के प्रति भी जागरूक था। अतः उन्होंने अनुभव किया कि यदि राष्ट्रीयता का यह नहर उग्र हो उठी और शासन के विरुद्ध जनता के असंतोष का क्रांतिकारी हान से रोक नहीं गया तो उसमें भयंकर परिणाम हो सकता है। अतः उन्होंने मार्च 1883 में कानूनी विद्वानों के स्नातकों को एक हस्तक्षेपपूर्ण पत्र लिखकर कुछ निष्ठा तथा स्वतन्त्रता प्रेमी व्यक्तियों को गण की जा सत्यनिष्ठा कायकता है। उन्होंने तत्कालीन वामराय नाइलिटन के समक्ष अपनी योजना रखी और यह विचार व्यक्त किया कि भारत के प्रमुख राजनयिका का मान में एक बार एक साथ एकत्र होकर अपने सामाजिक विषयों के सम्बन्ध में विचार विनिमय करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यद्यपि ह्यूम साहब इस राजनीतिक प्रवृत्ति का सम्मान नहीं बनाना चाहते थे तथापि नाइलिटन ने इस राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना चाहा। उनका मत था कि ऐसा सम्मान भारत में शासन के विरोध में मत व्यक्त करने वाला सिद्ध हो तो वह इंग्लैंड के विरुद्ध पक्ष की भाँति प्रभावकारि सिद्ध हो सकता है। अतः एक सम्मान के द्वारा सरकार का ध्यान उसकी कमियाँ तथा त्रुटियों की ओर आकर्षित करके उसमें सुधार के सुभाव देना भी होना चाहिए। इसके पश्चात् ह्यूम साहब ने इंग्लैंड जाकर वहाँ के प्रमुख राजनयिका में भी परामर्श किया और अपनी योजना में उनकी अभिरक्षि उत्पन्न की। भारत लौटकर उन्होंने ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रकार ह्यूम साहब की योजना का न केवल भारत के गवर्नर जनरल ने ही स्वीकार किया अतः अनेक ब्रिटिश राजनेताओं ने भी उसका स्वागत किया।

ह्यूम साहब के प्रयासों से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन नवम्बर 1885 में पूना में बुलाया

का आयोजन किया गया। परन्तु इस अवधि में पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसका स्थान बम्बई में निर्धारित किया गया। फलस्वरूप 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म तथा प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भविष्य में राष्ट्रीय आन्दोलन की संचालक, निदेशक तथा सर्वस्व रही। इसी के अथक प्रयासों ने भारत को राजनीतिक दासता से मुक्त कराया। इतना ही नहीं, अपने वर्तमान स्वरूप में आज भी यह स्वतन्त्र भारत के केन्द्रीय शासन की वागडोर अपने ही हाथों में लिये हुए है, यद्यपि अब इसका स्वरूप बहुत बदल चुका है।

कांग्रेस का प्रारम्भिक रूप—कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् उसके विकास, कार्य-कलापों एवं उपलब्धियों का इतिहास ही वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास है। इसकी स्थापना का श्रेय अवश्यमेव एक अंग्रेज व्यक्ति को प्राप्त है और यह भी स्पष्ट है कि इसकी स्थापना को ब्रिटिश शासकों से प्रोत्साहन मिला था, जिनके विचार में कांग्रेस 'देशी पार्लियामेंट का अकुर' थी। स्वयं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वाइसरॉय ने इसे ऐसा स्वरूप प्रदान किया था। यह संस्था विशुद्ध रूप से राजनीतिक थी और इसीलिए इसकी सदस्यता सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए निषिद्ध की गई थी। साथ ही कांग्रेस की स्थापना उसे ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय जनमत के अनुसार एक मित्र के रूप में परामर्शदात्री संस्था के रूप में की गई थी, न कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करके उसे अपदस्थ करने के उद्देश्य से कार्य करने वाली संस्था के रूप में। परन्तु यह बात तो स्पष्ट है कि जिस चीज का निर्माण ईमानदारी की भावना से न किया जायेगा वह अपने निर्माणकर्ता के लिए मित्र के रूप में नहीं रह सकती, इसलिए कांग्रेस भविष्य में ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध सिद्ध हुई। अतः यदि कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ब्रिटिश शासकों को दिया जाता है, तो यह भी स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासकों ने इसकी स्थापना तथा विकास को शुद्ध भावना से नहीं लिया, परिणामस्वरूप वह स्वयं ब्रिटिश शासन की शत्रु तथा विनाशकारी सिद्ध हुई। कूपलैण्ड के मत से 'भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज्य की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसका पालन-पोषण किया,' यदि यह बात सही है तो इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि ब्रिटिश राज्य तथा ब्रिटिश अधिकारियों को या तो शिशु का पालन करना ही नहीं आता था अथवा उन्होंने शैशव अवस्था से ही उस शिशु को सन्देश की दृष्टि से देखकर उसे अपना शत्रु बना लिया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यशाही शुरू से अन्त तक कभी भी भारत के प्रति ईमानदार नहीं रही।

कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों की समीक्षा

ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षक—भारत में अपने साम्राज्य की नींव सुदृढ़ कर लेने के उपरान्त ब्रिटिश शासक अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में इतने मदोन्मत्त हो गये थे कि वे भारत में जागृत राष्ट्रीयता की लहर के औचित्य तथा स्वरूप को या तो समझ नहीं पाये या उनकी यह धारणा बनी रही कि वे इस उमड़ती हुई राष्ट्रीय भावना को बल-प्रयोग से विनष्ट कर देंगे और जहाँ पर बल-प्रयोग सफल सिद्ध नहीं होगा, वहाँ पर अपनी कूटनीतिक चालों का अवलम्बन करके उसे रोकने में समर्थ हो जायेंगे, परन्तु कांग्रेस की गतिविधियाँ ब्रिटिश शासकों की इच्छाओं पर तुल्यपात करने वाली सिद्ध हुईं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि कांग्रेस का जन्म 'ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा' के लिए हुआ था। यह एक ऐसी धारणा है जिसे स्पष्ट रूप से न स्वीकार किया जा सकता है और न जिसका पूर्ण विरोध ही किया जा सकता है।

साम्राज्यशाही श्रृंखला के विरुद्ध एक श्रमय दीप के रूप में—निःसन्देह कांग्रेस की स्थापना के पीछे मर ए० ओ० ह्यूम का लक्ष्य यह था कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता से जो तीव्र रोष उत्पन्न हो गया है उसे यदि यों ही छोड़ दिया जायेगा तो वह जल्दी ही क्षण उग्र रूप धारण कर लेगा और 1857 की क्रान्ति की भाँति फिर कोई नवीन क्रान्ति

अपना सिर उठा नेगी यह तो स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता कि ह्यूम साहब ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बने रहने देना नहीं चाहते थे। इसलिए उसका विरोध करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किया होगा। इसी भावना तो किसी भारतीय नेता के मन में हो उठती है परन्तु जैसी गांधी राजपण राय की भी धारणा रही है ह्यूम साहब स्वयं स्तन उतार गति थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी द्वारा भारत में किये जा रहे अमानुषिक अत्याचारों को पसन्द नहीं करने थे। उनका मत यह था कि ब्रिटिश शासन के अत्यायपूर्ण कार्यों के प्रति भारत में फल रहे असंतोष के विरुद्ध एक अभय दीप (safety valve) की आवश्यकता है। वह अभय दीप कांग्रेस थी। ह्यूम साहब जैसा कि कांग्रेस के एक अत्यंत आरम्भिक अग्रज नेता विनियम बरखन ने भी माना है कांग्रेस को एक ऐसी संस्था के रूप में देखना चाहते थे जो भारतीयवासियों के असंतोष को बहानित रूप से व्यक्त करने का साधन बने ताकि उग्र क्रान्ति के सतरा संचाल हो सकें। कांग्रेस की स्थापना ने ह्यूम साहब के इस मतव्य को पूर्ण किया और वह प्रबुद्ध भारतीय नेता का जाकपण बंद बन गई। इस संगठन की संस्थाना प्राप्त करके उन नेताओं ने भारतीय जनता का असंतोष इस संस्था के माध्यम से बहानित एवं शांतिपूर्ण तरीका से व्यक्त करना प्रारम्भ किया। परन्तु हमका यह अर्थ नाना भी उचित नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना केवल मान ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। यदि ऐसा ही होता तो जिन ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस की स्थापना को प्रोत्साहन दिया था वे इस संस्था का ब्रिटिश साम्राज्यवादी के हितों में विकसित होने के प्रयास करते। प्रारम्भ के तीन अधिवर्षा वम्बर् (1885) तकता (1886) तथा मास (1887) में बहा के गवर्नर ने कांग्रेस के प्रति निधिया का यथाचित सम्मान किया परन्तु नीचे ही ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना प्रारम्भ कर दिया। लाड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्ण प्रोत्साहन देकर उस राजनीतिक स्वरूप तक प्रदान किया था। परन्तु उसी लाड डफरिन ने 1887 में यह विचार व्यक्त किया कि कांग्रेस केवल एक अत्यंत सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है (represents a microscopic minority of the people) और वह अपने उद्देश्य का भी अनुद्ध प्रतिनिधित्व करती है। 1888 में जब कांग्रेस का अधिवर्षा वतावाद में हुआ तो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को बर भावना की दृष्टि से देखने लग गई थी। हम दृष्टि से यह मानना उचित नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का पोषण करना था।

कांग्रेस विमुद्धतया एक राष्ट्रीय संस्था है—यदि कांग्रेस के स्वरूप को देखा जाय तो भी यह बात पुष्ट हो जाती है कि कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पोषण करना नहीं था। प्रारम्भ से ही हम संस्था का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। यह किसी वर्ग विशेष या किसी जाति धर्म सम्प्रदाय आदि की प्रतिनिधि संस्था मात्र नहीं थी अपितु उसकी सदस्यता अग्रज हिंदू मुसलमान पारसी आदि सभी वर्गों के व्यक्तियों ने ग्रहण की जा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले तथा भारतीय सामाजिक जीवन के सावजनिक सुमाय नेता थे। इनमें से किसी का भी उद्देश्य केवल मात्र ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना नहीं था। ह्यूम बरखन फिरोजगह महता दादाभाई नोरोजी गुरेदनाथ बनर्जी बदरहीन तयवजी उमाच बनर्जी आदि किसी भी आरम्भिक नेता को राष्ट्रीय न मानकर किसी वर्ग विशेष या साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। कानांतर में श्रीमती एनी बेसेट तथा सरोजिनी नायडू महता महिताग्रा ने इसमें भाग लेकर महिताग्रा का प्रतिनिधित्व किया। वास्तव में जब ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हमारे राष्ट्रीय स्वरूप को विनसित होने देखा तो उन्हें इससे अपने साम्राज्यवाद को खतरा ही मालूम पड़ने लगा। परिणामस्वरूप उन्होंने हमें साम्प्रदायिकता के विषय को पनाया और सर समयद अहमद खां महता एक प्रबुद्ध राष्ट्रीय नेता के ऊपर मुस्लिम सम्प्रदायिकता का जाद करके फूट डालो और राय करो की नीति का अवलम्बन करके कांग्रेस की एकता को नष्ट करने का प्रयास किया।

प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस की नीति

कांग्रेस के उद्देश्य—कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन (1885) की अध्यक्षता करते हुए उमेश चन्द्र बनर्जी ने कांग्रेस के निम्नांकित चार उद्देश्य घोषित किये थे—

(1) देश के भिन्न-भिन्न भागों से आने वाले देश-प्रेमी कार्यकर्ताओं के मध्य वैयक्तिक घनिष्ठता तथा मैत्री की अभिवृद्धि करना,

(2) भारत के मित्र लार्ड रिपन के शासन काल में देश में जिस राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई है, उसका सुदृढीकरण करने के निमित्त मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा जातिगत, धर्मगत तथा प्रान्तीय भेदभावों का अन्त करना,

(3) पूर्ण विचार-विनिमय कर लेने के उपरान्त देश की निवर्तमान ज्वलन्त सामाजिक समस्याओं पर देश के शिक्षित वर्ग की परिपक्व राय का अधिकृत रिकार्ड निर्मित करना, तथा

(4) उन साधनों तथा विधियों का निर्धारण करना जिसके अनुसार आगामी 12 मासों में देश के राजनीतिज्ञों को सार्वजनिक हित में परिश्रम करना है।

प्रथम अधिवेशन के प्रस्ताव (राजनीतिक स्वरूप)—उक्त उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में कांग्रेस का उद्देश्य मुरयतया अपने सगठन को सुदृढ करना तथा उसके सदस्यों में राष्ट्र प्रेम, एकता, लगन तथा समाज सेवा की भावना का विकास करना था। इन उद्देश्यों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य की चर्चा नहीं है। परन्तु इस प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस ने देश के हित में तत्कालीन सरकार के समक्ष अपनी माँगें प्रस्तावों के रूप में रखी थी। उनके अनुसार यह माँग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन की जाँच के लिए एक गाँधी आयोग नियुक्त करना चाहिए, इंग्लैण्ड की भारत परिषद् को समाप्त किया जाय, आई० सी० एस० परीक्षा इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों स्थानों पर साथ-साथ हो और उसके लिए प्रत्याशियों को न्यूनतम आयु-सीमा में वृद्धि की जाय, भारत सरकार का सैनिक व्यय कम किया जाये, बरमा की भारत में न मिलाया जाय तथा भारतीय व्यवस्थापिका परिषद् के दोषों को दूर किया जाये। इस अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और वे सही अर्थ में भले ही जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, प्रत्युत स्वेच्छापूर्वक देश-प्रेम की भावना से प्रेरित होकर आये थे। परन्तु जिन उद्देश्यों, भावनाओं तथा उत्साह को लेकर एक शान्त वातावरण में यह छोटा-सा अधिवेशन सम्पन्न हुआ वह भविष्य में कांग्रेस की महानता तथा उसकी कार्यविधि का सही-सही रूप था। कांग्रेस की भावी प्रगति को हम चार युगों में विभक्त कर सकते हैं—

(अ) प्रारम्भिक युग, जब इसकी स्थापना हुई थी और उदार विचार वाले बुद्धिजीवियों ने इसका पोषण किया था।

(ब) कांग्रेस के सकट का युग, जब इसमें नरम तथा उग्र दो दल हो गये और जब मुस्लिम मन्त्रदायवाद ने इसके ऊपर आघात किया।

(स) गांधी युग, जबकि गांधी जी के नेतृत्व में इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सघर्ष करके भारत को स्वतन्त्र किया।

(द) स्वतन्त्रता के पश्चात् की कांग्रेस जबकि वह भारत के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में देश के शासन की वागडोर सभाले हुए है।

कांग्रेस की लोकप्रियता का विकास—कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से आरम्भ होकर 1907 तक के काल का है। इन दो दशकव्दियों में कांग्रेस अपने शौशव काल में थी। इस अवधि में देश के सार्वजनिक जीवन से सम्बद्ध समस्त भारतीय शिक्षित वर्ग तथा जन-नेता इसके सक्रिय सदस्य रहे। इन लोगों के निस्वार्थ त्याग तथा लगन से कार्य करने के कारण कांग्रेस बड़ी तीव्र गति से अत्यन्त लोकप्रिय सम्था बन गयी। 1885 में केवल 72 प्रतिनिधियों ने इसके अधिवेशन में भाग लिया था, 1886 में यह संख्या 406, 1887 में 600 तथा 1888 में 1248

हो गयी। यही प्रगति भविष्य में जारी रही और 1906 तक कांग्रेस भारत में भारी बहुमत की प्रतिनिधि संस्था मानी जान का दावा कर सकती थी।

प्रारम्भिक नेता—यस अवधि में कांग्रेस का कार्यक्रम तथा कार्यविधियाँ पूर्णतया उदारवादी थीं। इस अवधि में इसका कार्यक्रम का एक शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग का आन्दोलन माना जाता है जो सांविधानिक तरीके से ब्रिटिश शासकों के समक्ष जाबजबाबी की संस्था के रूप में कार्य करती थी। इसका प्रारम्भिक युग में सबसे उत्साही नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी¹ तक ऐसी नीति का समर्थक थे जबकि उन्हें कठोर हाना चाहिए था क्योंकि ब्रिटिश शासन की घण्टापूँण नीति का मजमूदा महान् पहार उन्हीं को सहन करना पड़ा था उस युग के नेताओं में से कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो ह्यम विनियम बडरवन उमेरा चन्द्र बनर्जी दादाभाई नौरोजी दीनानाथा वाचा फीरोजशाह महता गोपान कृष्ण गाखने बदरहीन तयबजी रानाडे सुरेन्द्रनाथ अय्यर जानद माहन प्रेम सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि। केवल सर समय अहमद खा सद्गुण नेता यसस बाहर रह। कांग्रेस के द्वितीय युग के सधप की अवधि के प्रमुख नेता बान गगाधर तिलक विपिन चन्द्र पान नाता राजपत राय एनी बसन्त आदि थे। यह वर्गीकरण वास्तव में बानगत न हाकर नीतिगत है क्योंकि उक्त अधिकांश नेता समकालीन हैं प्रारम्भ में कांग्रेस की नीतियाँ उदारवादी रहा कालान्तर में वे उग्रवादी हो गयी। गोखले उक्त दोनों युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे मूलरूप से प्रथम युग के उदारदलीय नेता थे। 1907 में कांग्रेस के नरम तथा गरम दलीय नेताओं के मध्य फूट पडने पर वे 1915 तक उदार नीतियों पर विश्वास करने के साथ साथ उग्रवादियों को पुन कांग्रेस में लाने के लिए प्रयत्नशील रह।

प्रारम्भिक नीतियाँ—प्रथम युग के कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियाँ ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय शासन व्यवस्था के सम्बंध में विविध प्रकार की मांगों को रखने की रही। यद्यपि इन नेताओं द्वारा रखी गयी मांग पर्याप्त बनगानी थी और यह कहना अनुचित भी नहीं होगा कि इनमें से अनेक की पूर्ति तो आज स्वतंत्रता के 26 वर्ष बाद तक भी नहीं हो पायी है यथा अनिवार्य निष्कर्ष निम्नलिखित तथापि इन मांगों को हमारे प्रारम्भिक कांग्रेसी नेता सर्वाधिक महत्त्व देने थे। कांग्रेस की महत्ता तथा लोकप्रियता ऐसी विभूतियों के द्वारा इसे स्थापित किया जाना तथा गतिमान बनाना उसका पोषण करने के कारण ही बनी। इन मांगों के अन्तर्गत सांविधानिक सुधार प्रशासनिक सुधार आर्थिक सुधार अवाञ्छनीय करों का हटाना जाना अवाञ्छनीय तथा प्रशासनिक एवं सैनिक प्रथम में व्यापक कटौती भारत के गतिमान वर्ग को उच्च सवाओं में समुचित स्थान देना नागरिकों की स्वतंत्रताओं तथा अधिकारों की स्वीकारोक्ति तथा उनका संरक्षण आदि शामिल हैं। यद्यपि ये मांगें बड़ी दीर्घ अवधि तक अपूर्ण ही रहीं तथापि इन मांगों ने ब्रिटिश शासन का भारतीय जनमत के प्रति सजग रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनमें से अनेक मांगों को आंशिक रूप में ही सही पूर्ण करने के लिए शासन को कदम उठाने के लिए विवश भा होना पड़ा। प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस की नीतियों को निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—

क्रमिक सुधारों में विश्वास—यद्यपि कांग्रेस की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को लेकर हुई थी तथापि कांग्रेस संगठन का नेतृत्व प्रारम्भ में ऐसे उदार व्यक्तियों के हाथ में रहा जो एक सशक्त साम्राज्यवादी के विरुद्ध क्रांतिकारी आन्दोलन द्वारा सफलता पर विश्वास नहीं करते थे। इन्हें यह विश्वास था कि भारतीय प्रशासन में क्रमिक सुधार लाकर यदि भारतवासियों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता रहे तो वह स्वाशासन की शिक्षा के लिए अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है क्योंकि बिना ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त

¹ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आर् सी एम. परीक्षा पास करने वाले सबसे पहले भारतीय थे। अग्रज शामक उनकी इस प्रतिभा को सम्मान देते रहते थे। भारत में ऐसे उच्च पद पर नियुक्त हो जाने के एक या दो वर्षों के भीतर ही सरकार ने उनका ऊपर कुछ आरोप लगाकर उन्हें पदभुक्त कर लिया।

किये स्वायत्त शासन या स्वाधीनता की माँग सफल नहीं हो सकेगी। कांग्रेस के आरम्भिक नेता क्रान्तिकारी आदर्शवादी न होकर व्यावहारिक सुधारवादी अथवा उदारवादी थे। उनका विश्वास शासन-सुधारों में अधिक था और वे इसी बात से सन्तुष्ट थे कि यदि भारतीय शासन परिपदों में भारतवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाय, सेना एवं सिविल सेवाओं में उन्हें अधिक अवसर दिया जाय और स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रभावशाली ढंग से विस्तृत किया जाय, तो वह भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के मार्ग में सन्तोषजनक कदम सिद्ध होगा। अतएव कांग्रेस के प्रारम्भिक अधिवेशनों में इन्हीं उदार माँगों के प्रस्ताव पारित किये जाते रहे और शासन के विरुद्ध कोई क्रान्तिकारी प्रतिरोध नहीं उठाया गया।

(2) ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा—कांग्रेस के आरम्भिक नेताओं के ऊपर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव था। वे यह विश्वास करते थे कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में ब्रिटिश शासन का पर्याप्त योगदान है। अंग्रेजों ने भारत में अपना एकछत्र राज्य स्थापित करके छिन्न-भिन्न भारत का राजनीतिक एकीकरण किया है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव ने भारतवासियों को एक साथ मिलने-जुलने तथा पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान करने में मदद दी है। भारत में प्रशासनिक एकता लाने के उद्देश्य से अंग्रेजों के प्रयास भारतीय राष्ट्रीय एकता की स्थापना लाने के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में 'इंग्लैंड हमारा पथप्रदर्शक रहा है।' ब्रिटिश शासन ने भारत को नयी जागृति प्रदान करके उसे मध्य युग के अवनति के गर्त से ऊपर उठाया है। ब्रिटिश शासन के कारण ही भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति का ज्ञान कर सके हैं और उस ज्ञान ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को एक नयी दिशा प्रदान की है। इन समस्त धारणाओं की पृष्ठभूमि में आरम्भिक राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन को भारत का शत्रु न समझकर उसके प्रति निष्ठा की भावना रखते थे। गोखले का मत था कि 'अंग्रेज जाति की न्यायप्रियता तथा उदारता में हमारी अबाध निष्ठा है।'¹ भारत के आरम्भिक राष्ट्रीय नेताओं में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति की भावना दादाभाई नौरोजी के इन शब्दों से ज्ञात होती है, 'हमें पुरुषों की तरह यह घोषणा करनी चाहिए कि हम पूर्णरूपेण राजभक्त हैं।'²

इसका यह अर्थ भी नहीं लेना चाहिए कि ये भारतीय नेता ब्रिटिश राज के प्रति अन्धभक्ति रखते थे या अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही ब्रिटिश शासकों के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा रखते थे और ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कृत्यों को नजरान्दाज करते थे। सही बात तो यह थी कि ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण तथा दमनकारी नीतियों ने ही कांग्रेस संगठन को निर्मित करने की प्रेरणा दी थी, ताकि उनका विरोध संगठित रूप से किया जा सके और यह भी इन नेताओं को ज्ञात था कि यदि भारतवासी किसी प्रकार के उग्र साधनों का अनुसरण करके विरोध करेंगे तो ब्रिटिश शासन उनका उसी रूप से दमन कर देगा और यह हिसावृत्ति भारतीय राष्ट्रीय चेतना को कुचल देगी। साथ ही ब्रिटिश शासक भी भारतीय नेताओं की भावनाओं से अनभिज्ञ अथवा उदासीन नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी अनुभव किया कि भारत के शासन में भारतीयों का महयोग आवश्यक है। अतः ऐसा सहयोग लेने में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ही चुना। उनमें से अनेक को उपाधियों में अलंकृत किया तथा शासन-परिपदों में स्थान दिया। इन नेताओं ने ऐसे पदों को प्राप्त करने में पदलोपता की भावना नहीं दर्शायी प्रत्युत उनका यह आचरण ब्रिटिश शासन तथा भारतीय राष्ट्रीयता दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। दूसरी ओर भारत के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए भी यह व्यवस्था प्रेरणास्पद सिद्ध हुई।

(3) साविधानिक साधनों के प्रयोग पर विश्वास—कांग्रेस के आरम्भिक नेता उदारवादी थे। उनकी धारणा यह नहीं रही कि वे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी तथा निरकुशतावादी

¹ 'We have abounding faith in the justice and generosity of English people'

² 'Let us stand up like men and proclaim that we are loyal to the backbone'

नीतियाँ एवं आचरणा का हिंसात्मक तथा क्रांतिकारी साधना से विरोध करें। वे न तो ऐसे साधना का उचित समझते थे और न ही ऐसी साधना का अवलम्बन करने में सफलता सम्भव थी। अतः इन नेताओं ने वधानिक साधना के द्वारा अपनी माँग सरकार के सामुग्न रखना अपना नय्य बनाया। जवाहरलाल नेहरू का विरोध स्मरण-पत्रा प्रस्तावों, निष्प्रभणों अथवा आवेदन पत्रों के द्वारा करना उनका मुख्य साधन था। बहुधा उनकी ऐसी पद्धति को राजनीतिक भ्रान्ति की संज्ञा दी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि वे अपनी राजनीतिक माँगों को भारत तथा इंग्लैंड स्थित ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रार्थना-पत्रों आवेदन तथा प्रत्यावेदन (prayer petitions protests) के रूप में रखते थे। उनका उद्देश्य सरकार से मध्य करना नहीं था। उस काल में कांग्रेस की प्रमुख माँग मूल स्वराज प्राप्त करने की भी नहीं थी। अपितु वह यही चाहती थी कि जिस प्रकार इंग्लैंड की जनता अपने दंग में स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकारों का उपभोग करता थी वसा सुविधा भारतवासियों को भी अपने दंग में मिलनी चाहिए। केंद्राय तथा प्रांतीय स्तरों पर कांग्रेस तथा गवर्नरों की परिषदों में भारत के नागरिकों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उन्हें कांग्रेसियों के सन्तुष्टि से प्रश्न पूछने वजह पर वाद विवाद करने आदि का अवसर मिलना चाहिए। सुयोग्य भारतीयों को सरकार में उच्च पदा पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कभी कभी अपने प्रतिनिधियों का धारा-सभा में निर्वाचित करने के अधिकार की माँग भी रखी जाती थी। साथ ही प्रारम्भिक नेताओं ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यपालिका में जादमनकारी तथा गोपनीयकारी कानून बनाये थे और जो भारत के अहित की नीतियाँ अपनायी थी उन्हें समाप्त करने की माँग भी की जाती रहा। इन नेताओं का विश्वास था कि सरकार उनकी उचित माँगों पर विचार करगी न करने पर उसने समक्ष बारम्बार आवेदन किया जायेगा। इस दृष्टि से उस युग के नेताओं के ये साधन सम्योचित तथा व्यावहारिक थे।

(4) ब्रिटिश शासन की ईमानदारी पर विश्वास—उस युग के भारतीय नेताओं की ऐसी शिक्षावृत्ति की नीति अपनाने का कारण कदापि नहीं था कि वे उग्र तथा क्रांतिकारी साधना को अपनाने में अपने का अन्त समझते रहे। साथ ही यह बात भी नहीं थी कि वे ब्रिटिश शासन के अनेक दमनकारी रवियों को सामान्य रूप से ही नेते रहे। वास्तविकता यह थी कि उन नेताओं को अग्रज जाति की श्रद्धाप्रियता तथा ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। वे पश्चात्त्य शिक्षा तथा ब्रिटेन में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के प्रभाव से यह विश्वास करते थे कि अंग्रेज लोग स्वभावतः स्वतंत्रता प्रेमी हैं अतः वे अपनी भारतीय प्रजा का भी ऐसी सुविधा देंगे। साथ ही इन नेताओं की यह भी धारणा थी कि जमीन भारत स्वशासन के लिए भूमि तैयार नहीं हो पाया है अतः श्रद्धा-प्रिय अग्रज शासक यह अनुभव करने लगेंगे कि अब भारतवासी सभी क्षमता रखने लगेंगे हैं तथा वे अपने अपने शासन भारतवासियों को ऐसी राजनीतिक अधिकार देना प्रारम्भ कर देंगे। अतएव इंग्लैंड में भी इस जनमत को जाग्रत करना उन नेताओं ने अपना नय्य बनाया। चूँकि इंग्लैंड के भारत स्थित शासन यहाँ मनमाना व्यवहार करते थे क्योंकि वे इंग्लैंड से अत्यन्त दूर भारत में नौकरग्राही शासन का स्वाद चख चुके थे अतः भारतीय नेताओं ने उनकी ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध इंग्लैंड की जनता के मध्य जनमत का निर्माण करना अपना नय्य बनाया क्योंकि भारतीय नेताओं को इंग्लैंड की जनता की स्वाभाविक ईमानदारी तथा श्रद्धाप्रियता पर विश्वास था। ये भावनाएँ कांग्रेस के उस युग के नेता समय-समय पर व्यक्त भी करते रहे और सावजनिक रूप से अग्रजों का गुणगान करते रहे। उन्हें यह विश्वास था कि जिस प्रकार अग्रजों ने अग्र उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान की है उसी प्रकार वे भारत का भी अपने अपने यह अधिकार देंगे।

प्रारम्भिक नीतियों की आलोचना—मैंने ही तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में उस युग के भारतीय उदारवादी नेताओं का ये नीतियाँ तथा धारणाएँ व्यावहारिक दृष्टि में ठीक रही

हो, तथापि यह मानना उचित नहीं है कि उनकी धारणाएँ ठीक ही थी। वास्तव में वे नेता ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के कुचक्रों का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। उन्होंने भारत के सन्दर्भ में अंग्रेज जाति की जनतन्त्रप्रियता तथा न्यायप्रियता का गलत अर्थ समझा। अंग्रेजों के हृदय में ऐसी धारणा अपने देश में भले ही विद्यमान रही है, परन्तु भारत में वे साम्राज्यवादियों के रूप में आये थे। उन्हें भारत का आर्थिक शोषण करना था और यदि वे भारतवासियों की स्वशासन की माँग को थोड़ा भी प्रोत्साहन देकर पूर्ण करने लगते तो उनकी सब आकाक्षाएँ ममाप्त हो जाती। भारत का आर्थिक शोषण उनके लिए तभी सम्भव था जबकि वे यहाँ पूर्ण स्वेच्छाचारी शासन कायम रखते। अतः उदारवादी नेता यह न समझ सके कि ब्रिटिश शासक भारतीयों को न तो स्वशासन की दिशा में शिक्षित करना चाहते थे और न उनका कभी यह उद्देश्य था कि योग्यता प्राप्त कर लेने पर वे धीरे-धीरे भारतवासियों की किसी भी ऐसी माँग को पूर्ण करेंगे। यदि थोड़े से शिक्षित वर्ग को उन्होंने कभी शासन की सेवाओं में रखा तो उसका उद्देश्य राजनीतिक चेतना प्राप्त व्यक्तियों को आन्दोलन करने से रोकने का प्रलोभन देना मात्र था। वे इन व्यक्तियों से ब्रिटिश राज के प्रति अन्ध-निष्ठा रखने की ही कामना करते थे। यदि अंग्रेज सचमुच लोकतन्त्रप्रिय, स्वतन्त्रताप्रेमी तथा न्यायप्रिय थे तो जैसी स्वतन्त्रता इंग्लैंड की जनता को प्राप्त थी, वैसी भारत में भारतवासियों को देने में निरन्तर आना-कानी करना क्या उनकी ऐसी उक्त भावनाओं से सगति रखता था? एक स्वेच्छाचारी साम्राज्यवादी सत्ता से स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता की उपलब्धि 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' का साधन अपनाकर नहीं हो सकती थी। अतएव आरम्भिक उदारवादी कांग्रेसी नेताओं की नीति बहुत प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकी।

मूल्यांकन—परन्तु जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत कांग्रेस का शैशव काल बीता, उनके अन्तर्गत सम्भवतः उदारवादियों की नीतियाँ ही व्यावहारिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त थी। उस समय तक भारतीय राष्ट्रीयता इतनी सगठित नहीं थी कि वह कठोर साधन अपनाकर स्वाधीनता प्राप्त कर सकती। ऐसी क्रान्ति को अंग्रेज शासक आसानी से दबा देते। ऐसी स्थिति में पुनः 1857 के विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो जाता। न मालूम उसके क्या परिणाम होते। अतएव उदारवादी राष्ट्रवाद का भारतीय राष्ट्रीयता के सगठन को विकसित करने में महत्वपूर्ण हाथ रहा। इन नेताओं ने एक ओर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी राजनीतिक माँगें रखकर उसे यह चेतावनी देने का कार्य किया कि उसके अत्याचारी एवं स्वेच्छाचारी शासनिक कृत्य शासितों को ज्ञात हैं और भारतीय जनता उनके सम्बन्ध में जागरूक है। अतः उसे ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए। दूसरी ओर इन राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय जनता को विदेशी शासकों की अन्यायपूर्ण नीतियों से परिचित कराके भारतीय जनमत को प्रबल बनाने में योगदान किया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता को सही दिशा प्रदान करके उसका निर्देशन किया। यह बात भी बहुत कुछ मान्य है कि 1892 का भारतीय कौन्सिल अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं उदारवादियों की माँगों से प्रभावित होकर पास किया।

प्रभाव—इस दृष्टि से उदार राष्ट्रवादी नीति समयोचित थी। भले ही उन नेताओं ने साम्राज्यवादी विदेशी शासकों की कूटनीतिक चालों का सही उत्तर अपने कार्यक्रमों द्वारा न दिया हो, तथापि उनका महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उनके कार्यक्रमों ने भारतीय जनमत को राष्ट्रीय एकता की दिशा में मोड़ा और भारतवासियों में अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न की। इस दृष्टि से उदार राष्ट्रवादियों को भारतीय राष्ट्रीयता के प्रणेता कहना सर्वथा उचित है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन रूपी भव्य भवन की सुदृढ़ नींव का निर्माण इन राष्ट्रवादियों की नीति थी, जो डा० मीतारामैया के शब्दों में, 'पहले उपनिवेशों के डग के स्वयामन, फिर साम्राज्य के अन्दर होम रूल और उसके पश्चात् स्वराज्य तथा अन्त में

पूरा स्वाधीनता की मांग के रूप में निर्मित हुआ। यद्यपि कूपनड के मत से भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की गिगु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पालन में 'जागीरदार दिया' तथापि वास्तविकता कुछ और है। यदि राज रिपन सदृश वाइसरॉय सचमुच में भारतवासियों को राजनीतिक एवं नैतिक नीति देने के उद्देश्य से स्थानात्मक स्वायत्तता तथा शासन की स्थापना कर गये और राज डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना को भारत के शासन संचालन में भारतीय जनमत प्राप्त करने का साधन मानकर उसे प्राप्ताह्न किया तो यह नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रीयता का पालन-पापण किया क्योंकि बाद में स्वयं राज डफरिन को कांग्रेस के ऊपर काफी सन्नेह होने लग गया था और चाहे ही क्यों के बाद राज कजन सदृश वाइसरॉय तो भारतीय राष्ट्रीय मांगों का कट्टर गत सिद्ध हुआ था।

क्या ब्रिटिश शासक भारतीय राष्ट्रीयता के पोषक थे?—कांग्रेस की स्थापना होने पर यदि आंग्लिक कांग्रेसी नेताओं ने ब्रिटिश शासन की चुनौती का तीव्र तथा क्रांतिकारी विरोध करने की अपेक्षा उससे सहयोग करने, आवेदन करने तथा भिक्षावृत्ति के द्वारा ही सही भारतीय राष्ट्रीय मांगों का पूरा करने की नीति अपनायी तो उसका यह अर्थ नहीं था कि ब्रिटिश शासक भारतीय राष्ट्रीयता के पोषक थे। कांग्रेस की उत्पत्ति के दो या तीन वर्षों में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेसी नेताओं का स्वागत किया। परंतु जसा पहले कहा जा चुका है वही राज डफरिन जिन्होंने इस राजनीतिक स्वरूप देने का प्रस्ताव किया था दो ही वर्ष बाद इस सन्नेह की दृष्टि से दृष्टि करने और राजनेत्री मन्त्रियों से मानने लगे। कई प्रांतों के गवर्नरों ने अपने अधीन प्रशासनिक अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों को आज्ञा देने दिये थे कि यदि वे कांग्रेस के अधिवक्ता या सभा में उपस्थित होंगे तो उस प्रशासनिक भ्रम का अपराध माना जायेगा। कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता का दमन करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के द्वारा शासनविरोधी भाषण देने या ऐसे कार्य-कलापों का दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीयता को कुचलने के उद्देश्य से जब ब्रिटिश शासकों ने जो नई नीति अपनायी वह तब से उकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही नहीं अपितु आज तक भी भारतीय राष्ट्रीयता के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। उस समय तक अग्रज मुसलमानों को ब्रिटिश राज्य का गत मानते थे। उनके मत से 1857 के विद्रोह में मुसलमानों का प्रमुख हाथ था और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता यूरोपीय सभ्यता की विरोधी थी। अतः 19वां सदी के अंतिम वर्षों तक ब्रिटिश शासकों ने भारतीय मुसलमानों को गिना राजनीतिक जीवन सामाजिक सेवाओं सेना आदि में प्राप्ताह्न करने की नीति अपनाकर उन्हें उपेक्षित रखा। राष्ट्रीयता के विकास में जनस्वरूप अनेक निर्मित मुसलमान कांग्रेस में शामिल हो गये और चूंकि कांग्रेस प्रारम्भ से ही एक राष्ट्रीय तथा धर्म निरपेक्ष संस्था के रूप में विकसित हो रही थी अतः ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस में फूट डालने तथा भारतीय राष्ट्रीय एकता को अवरोध करने के उद्देश्य से साम्प्रदायिकता को भड़काने की नीति अपनायी। उन्होंने अब मुसलमानों को प्रोत्साहित करना शुरू किया और उनमें हिन्दू सम्प्रदाय के विरुद्ध घणा करने की भावना उत्पन्न की। अंग्रेजों की यह फूट डालो और राय करो की नीति भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में निरन्तर एक विषय बाट की भांति चुभती रही। कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म के पचास वर्षों ही ब्रिटिश शासकों का रुख इनके विरुद्ध हो गया। वास्तविकता यह थी कि भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म के उपरान्त जहां भारतीय उदारवादी राष्ट्र नेता ब्रिटिश शासकों के समक्ष सहयोग और मददगारों की धारणा रखते हुए अपनी कुछ न्यायसम्मत मांगों का रखने की नीति अपना रहे थे वहां ब्रिटिश शासक कांग्रेस की ऐसी नीति का सहन नहीं कर सके और उसने विकास का निरन्तर सन्दर्भ की दृष्टि से देखने लगे। 1892 के सुधार ब्रिटिश सरकार ने किसी स्मान्तकारी की भावना से ग्राह्य नहीं किया अपितु कुछ विवर्तनाओं के कारण किये।

1892 का भारतीय कौन्सिल अधिनियम पृष्ठभूमि तथा प्रभाव

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारत के सामाजिक विकास

का क्रम समानान्तर विकसित हुआ है। इसका कारण स्पष्ट है—

(1) कांग्रेस की भारत में यूरोपीय सस्थायें स्थापित करने की धारणा—भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का श्रीगणेश ऐसे समय में तथा ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत हुआ था जिसे दबा सकना किसी भी सत्ता के लिए सम्भव नहीं था। भारतीय राष्ट्रीयता की माँग इतनी न्यायपूर्ण तथा वास्तविक थी कि प्रारम्भिक राष्ट्रीय उदार नेताओं की भिक्षावृत्ति की नीति में भी उतना ही बल था जितना कि किसी कानूनी न्यायिक माँग में हो सकता है, इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व में विकसित हुई राष्ट्रीयता ने कांग्रेस के द्रुत विकास को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। यद्यपि मैकाले सहित यूरोपीय राजनेता भारत में पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति एवं सस्थाओं को शनैः शनैः इस रूप में ला देना चाहते थे कि भारतवासी उनसे इतना साम्य स्थापित कर ले कि वे फिर अपनी समस्त सस्थाओं तथा संस्कृति को ही भूल जायें। इस प्रकार भारत का ही नहीं अपितु समूचे एशियाई देशों का, जहाँ यूरोपीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था, यूरोपीयकरण हो जायें। भारत में राष्ट्रीयता का विकास भले ही यूरोपीय सम्पर्क के प्रभाव से हुआ, किन्तु वह अपना स्वतन्त्र तथा स्वदेशी दिशा में ही बढ़ रहा था। अतः इस विकास के सन्दर्भ में अब ब्रिटिश शासकों के लिए यह बात आवश्यक हो गयी थी कि वे शीघ्रातिशीघ्र भारतीय शासन में ब्रिटेन के नमूने की सस्थाओं की स्थापना करें।

(2) कांग्रेस की भारत में ससदीय सस्थायें स्थापित करने की माँग—1892 के अधिनियम को पारित करने का एक प्रधान कारण यह भी था कि कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही यह प्रस्ताव पास कर लिया था कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका में अधिक से अधिक निर्वाचित सदस्य बढ़ाये जायें और व्यवस्थापिका सभाओं के विस्तार द्वारा सदस्यों को कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने तथा आय-व्यय पर विचार-विनिमय करने का अवसर दिया जायें अर्थात् कांग्रेस की माँग भी भारत में ससदीय शासन-प्रणाली को प्रारम्भ करने की हो गयी थी। ब्रिटिश शासकों को यह अनुभव होने लग गया था कि देश का शासन संचालित करने में जनमत का ज्ञान करना आवश्यक है और इसके हेतु व्यवस्थापिकाओं का विस्तार करके उनमें जनमत को व्यक्त करने वाले जन-नेताओं को लेने से ही समस्या का समाधान हो सकता है।

(3) ब्रिटिश नौकरशाही की गृह सरकार के नियन्त्रण से मुक्त रहने की अभिलाषा—भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के अधिकारी यहाँ के शासन को अधिकाधिक मात्रा में गृह सरकार (ब्रिटेन स्थित सरकार) के नियन्त्रण तथा निर्देशन से स्वतन्त्र रखना चाहते थे। इसलिए वे सीमित शक्तियों से युक्त भारतीय सदस्यों से निर्मित व्यवस्थापिकाओं की स्थापना में अभिरुचि रखने लगे।

1892 के अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीय शासन में व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में निर्वाचन के सिद्धान्त को अपनाया गया। इस दृष्टि से इस अधिनियम को यदि किसी अर्थ में सुधार कहा जायें तो वह यही है कि इसने शासन में जनता के नेताओं को अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने का अवसर दिया और शासन की परिपदों में उनकी सत्ता में विस्तार किया। साथ ही कार्यपालिका से प्रश्न पूछने तथा वजह पर वाद-विवाद करने का अवसर दिया। परन्तु गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरों को इतने अधिक अधिकार प्राप्त थे और इन परिपदों में शासन द्वारा नियुक्त तथा नामांकित सदस्यों की सत्ता इतनी अधिक थी कि गैर-सरकारी सदस्यों की आवाज को वे प्रभावशून्य समझते थे। शासन सम्बन्धी नीतियाँ, निर्णय तथा कानून पहले ही अन्तिम रूप से निर्णीत हो जाते थे और परिपदों के ये तथाकथित निर्वाचित सदस्य केवल उन पर अपने विचार रख सकते थे। जो बहुधा अस्वीकृत हो जाते थे। स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन की ऐसी नीति का विरोध अब उदार नीति से प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकता था।

प्रश्न

- 1 क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय पश्चात्तय शिक्षा प्रणाली से अनुप्राणित था ?
- 2 उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में भारत में वे कौनसी परिस्थितियाँ काम कर रही थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को सम्भव बनाया ?
- 3 क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कांग्रेस का स्थापना अंग्रेजों ने इसलिए करवाया था ताकि देश में बन्ते हुए अमतोष को रोका जा सके ?
- 4 अपने आरम्भिक वर्षों में कांग्रेस का क्या उद्देश्य था ? उनको प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी रीतियाँ अपनाई गईं ?
- 5 कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की सद्भावितक निष्ठाओं पर प्रकाश डालिए ।

राष्ट्रीयता का प्रारम्भिक युग (NATIONALISM . EARLY PHASE)

आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी का द्वितीय उत्तरार्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। इस युग में भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपना पूर्ण राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा, परम्पराओं आदि के बनाये रखने में कोई अभिरुचि नहीं थी। वे भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण में ही अपना हित समझते रहे थे। इसलिए भारत में पाश्चात्य शिक्षा, संस्थाओं एवं शासन पद्धतियों को लागू करने में उनकी अभिरुचि बनी रही। मैकाले सदृश राजनेता भारतीय संस्कृति को समाप्त करके यहाँ पूर्णतया यूरोपीय संस्कृति थोप देना चाहते थे। परन्तु जब 19वीं शताब्दी के अनेक भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पाश्चात्य देशों में जाने, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने तथा उन देशों की प्रगति का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें अपने देश की सांस्कृतिक अवनीति को देखकर अत्यन्त दुःख हुआ। इनमें से अनेक महापुरुषों ने यह अनुभव किया कि भारत की प्राचीन संस्कृति पाश्चात्य देशों की तुलना में महानतर थी। परन्तु ऐसी महान् संस्कृति का महान् देश विदेशी आधिपत्य के प्रभाव में आकर पतित-वस्था में चला जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यही है कि भारतीय हिन्दू समाज में कतिपय बुराइयाँ घर कर चुकी हैं। धार्मिक अन्ध-विश्वासिता, सकीर्णताये, छुआछूत की भावना, बाल-विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की समस्या, अशिक्षा आदि ने हिन्दू समाज को विल्कुल गिरा दिया है। ऐसी स्थिति में जब तक हिन्दू समाज को इन बुराइयों से मुक्त न किया जाये, तब तक भारत का उत्थान सम्भव नहीं है। उक्त सामाजिक तथा धार्मिक बुराइयों से हिन्दू समाज को मुक्त कराके उनमें आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास तथा देश-प्रेम की भावना का संचार कराना अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत के कुछ बुद्धिवादी महापुरुषों में भारत के धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रति तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इन महापुरुषों में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे तथा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम अग्रणी है। ये नेता विशुद्ध रूप में राष्ट्रवादी तो नहीं माने जा सकते, क्योंकि ये न तो राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावना रखने वाले आन्दोलनकारी नेता थे और न ही इनमें से कोई ऐसे राजनीतिक चिंतक की श्रेणी में आता है जैसे कि पाश्चात्य देशों के चिंतक रूसो, कांट, ग्रीन, हीगल, मार्क्स आदि थे। परन्तु इन्होंने जिन समाज-सुधार तथा धर्म-प्रचार आन्दोलनों का सूत्रपात किया, वे परोक्ष रूप में भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने वाले सिद्ध हुए। उन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों को राजनीतिक धारणाओं, विचारों एवं सक्रिय राजनीति से पृथक् समझा जा सकता है। इन आन्दोलनों ने अन्ततोगत्वा भारतवासियों में यह भावना जागृत करने में सहायता प्रदान की कि भारत का सांस्कृतिक पतन मुख्यतया राजनीतिक पराधीनता का फल है। अतः भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। प्रारम्भ में इन पुनर्जागरण आन्दोलनों के नेताओं में यह धारणा रही कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पूर्व शर्तें हैं। परन्तु धीरे-धीरे जब राष्ट्र भावना अधिक विकसित हो गयी तो आगामी आन्दोलनों में यह विचार व्यक्त किये जाने लगे कि पहले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी आवश्यक है और राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर सामाजिक तथा धार्मिक सुधार

संश्लिष्ट ढंग से सम्पन्न किया जा सके।

इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक युग के नेताओं को हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं। प्रथम के अंतर्गत पुनर्जागरण के सुधारवादी नेता आते हैं। इनमें राजा राममोहन राय तथा उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज कार्यक्रम को वक्ता मान सकते हैं। उनका अनुयायी नेता श्री १। श्री १णी म स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के नेता महादेव गांधीद्वारा स्थापित प्रायः समाज के नेता स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द और जनक धियामाफिरान समाज की प्रमुख ननी श्रीमती एनी बेसेंट के नाम प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में हम कांग्रेस की स्थापना हो जाने पर कांग्रेस के आरम्भिक युग के उन नेताओं का रखते हैं जिन्हें उदारवाद (moderates) कहा जाता है। इनके अंतर्गत दायभाज और राजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी फागजगाह महता गामानकृष्ण गोपबन आमगचन बनर्जी गुरहृष्ण अय्यर दानगा वाचा ए जा ह्य म विनियम वगैरान आदि प्रमुख हैं। ये लोग सक्रिय राष्ट्रीय नेता थे और उनके कार्यक्रमों तथा विचारों में राजनीतिक तथा यद्यपि पूर्व के समाज सुधार तथा धर्म सुधार आन्दोलनों के विचारों का भी एक ऊपर पड़ान प्रभाव था। ये नेता उदारवादी इस अर्थ में थे कि ये ब्रिटिश शासन का सहयोग लेकर सामाजिक धार्मिक एक राजनीतिक सुधारों का सम्पन्न कराना तथा वैधानिक तरीकों से राजन भारतवासियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराना चाहते थे। परन्तु 20वीं सदी के आरम्भ में भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ उग्रवादी धारणायें उत्पन्न होने लगीं। परिणामस्वरूप उदारवादियों की नीतियों के विरोध में बान गगाधर तिवर जखिद धाप नाना तातपतराय विपिनचन पान श्रीमती एना बेसेंट आदि ने उग्र राष्ट्रीयता के विचार रखे। ये नेता भारत का विदेशी सत्ता में स्वतंत्र कराना प्रथम कार्य मानते थे। ये समाज सुधार तथा धार्मिक सुधार के कार्यों के विरोध नहीं थे। परन्तु इनका विश्वास था कि विदेशी राजनीतिक सत्ता का सहायता लेकर ऐसे सुधारों का करवाया जाना कोई औचित्य नहीं रख सकता और न वह प्रभावकारी हो सके है।

इस दृष्टि से हम राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व का निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत करके राजनीतिक विनाम क्रम के अंतर्गत उनके विचारों तथा कार्यक्रमों का विश्लेषण करके

- (1) सुधार आन्दोलनों के नेता
- (2) कांग्रेस के आरम्भिक उदारवादी नेता
- (3) पूर्व गांधी युग के उग्रवादी नेता
- (4) गांधी युग के नेता

सुधार आन्दोलनों के नेता

(क) राजा राममोहन राय (1772-1833)

राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही उन्हें बंगाल भाषा के अतिरिक्त फारसी तथा अरबी भाषाएँ सिखायी गयीं। तत्पश्चात् उन्होंने मस्जिद भाषा का अध्ययन किया। इन भाषाओं के अध्ययन का प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने अल्लामा में ही उनके माध्यम से इस्लाम तथा हिंदू धर्मों के मूल ग्रंथों कुरान वद उपनिषद् आदि का अध्ययन किया और यह हिंदू धर्म के अंतर्गत जा गए जनक अधविश्वासों से घणा होने लगी। ये मूर्ति पूजा तथा अनन्तरवाद का हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं मानने लगे। कुछ बड़े होने पर ये तिब्बत गये। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म में जो बुराईयाँ आ गयी थी उनमें भी उन्हें घणा हो गया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदू समाज में आ गया अनेक कुरीतियों का भी बहुत अनुभव किया यथा सती प्रथा दान विधवाओं का समस्या बहुत विवाह प्रथा महिलाओं की दामनी की स्थिति आदि। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये समस्त

सामाजिक कलक धर्म पर आधारित कुप्रथाओं के विकास का फल है, न कि किसी धर्म विशेष के मौलिक मिथ्यान्त । वाइस वर्प की उम्र से इन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया और उसमें भी दक्षता प्राप्त की । इसके कारण उन्हें ईसाई धर्म ग्रन्थों, पाश्चात्य देश के दार्शनिकों के विचारों तथा पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करने का अवसर मिला । इससे उन्होंने ईसाई धर्म की भलाइयों तथा बुराइयों का भी अनुभव किया । ये पाश्चात्य शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए जिसके अन्तर्गत अनेक विज्ञानों, सामाजिक शास्त्रों तथा दर्शन का अध्ययन कराया जाता था ।

भारतीय समाज के अन्तर्गत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्यों का आन्दोलन चलाने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में जागृत हुई । उनके विचारों से उनके अनेक साथी बहुत प्रभावित हुए । उन सबके सहयोग से 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की । ब्रह्म समाज तत्कालीन भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के अन्तर्गत सुधार आन्दोलन की एक प्रमुख संस्था थी, इसके अनुसार अनेकेश्वरवाद, समस्त मानव जाति के एक धर्म, मूर्ति पूजा का विरोध, एक निराकार ब्रह्म की सत्ता के ऊपर विश्वास, साम्प्रदायिक भेद-भाव की समाप्ति आदि के प्रचार आन्दोलन चलाए गए । ब्रह्म समाज के अनुसार जिस एकमात्र मानव धर्म को महत्त्व दिया गया उससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि राजा राममोहन राय हिन्दू होते हुए भी किसी प्रचलित ऐसे धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे जिसमें साम्प्रदायिकता की भावना रहती हो । भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में जहाँ कि धार्मिक भेदभावों ने समाज की एकता तथा प्रगति को अवरुद्ध करने में महत्त्वपूर्ण कार्य भाग सम्पन्न किया था, राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज आन्दोलन में भारतीय राष्ट्रीय एकता का भारी समर्थन मिलता है ।

राजा राममोहन राय का कार्य क्षेत्र हिन्दू समाज में प्रचलित विभिन्न बुराइयों का अन्त कराने में अधिक था । उन्होंने सती प्रथा को कानून द्वारा बन्द करवाने में तत्कालीन रूढ़िवादी हिन्दुओं के विरोध का डटकर सामना किया और इस बर्बर प्रथा के विरुद्ध भारी जनमत तैयार किया । महिलाओं के उत्थान में उनकी भारी अभिरुचि थी । बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह, बाल विवाह की समाप्ति, बहु-विवाह की समाप्ति, स्त्री-शिक्षा, आदि का उन्होंने तीव्र प्रचार किया । हिन्दुओं में जाति-प्रथा से उत्पन्न हुए सामाजिक दोषों का भी उन्होंने तीव्र विरोध किया । हिन्दू समाज सुधार के निमित्त उन्होंने विभिन्न हिन्दू धर्मशास्त्रों, स्मृतियों आदि से प्रमाण देकर बुराइयों का निवारण कराने का प्रचार किया ।

यद्यपि राजा राममोहन राय को न तो एक राजनीतिक चिंतक की श्रेणी प्राप्त होती है और न ही वे एक राजनेता की श्रेणी में आते हैं, तथापि उनके अनेक विचार तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत महत्त्व रखते हैं । वे 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के आदि प्रणेताओं में से थे । यह पुनर्जागरण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जीवन के समस्त क्षेत्रों से सम्बद्ध था । यद्यपि इसमें पाश्चात्य संस्कृति, दर्शन तथा राजनीति के प्रभाव को अमान्य नहीं किया जा सकता, तथापि इसके अन्तर्गत राजा राममोहन राय ने जिन विचारों को रखा वे कोरे पाश्चात्य विवेकवाद, बुद्धिवाद, आधिभौतिकतावाद से प्रभावित न होकर हिन्दू संस्कृति, धर्म तथा शास्त्रों के विवेकपूर्ण निर्वचन पर भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में व्यक्त विचारों पर आधारित थे । चूँकि भारत में उस समय विदेशी निरकुश शासन कायम था, अतः भारतीयों की नागरिक, वैयक्तिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताओं पर भारी अकुश लगे थे । अतः राजा राममोहन राय ने अनुभव किया कि जब तक भारतवासी इन स्वतन्त्रताओं से वंचित रहेंगे तब तक समाज-सुधार या धर्म-सुधार कार्य सम्भव नहीं होंगे । पाश्चात्य देशों की परिस्थितियों के अध्ययन ने उन्हें यह नमादान कर दिया था कि पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंग्लैण्ड, में जनता ने उन्नति इसीलिए की है कि वहाँ नागरिक स्वतन्त्रताओं का उपभोग करते हैं । भारत में समाज सुधार एवं धर्म-सुधार के निमित्त प्रेस की स्वतन्त्रता अपरिहार्य थी । किन्तु भारत की सरकार ने प्रेस की स्वतन्त्रता पर भारी प्रतिबन्ध लगा दिये थे । अतः राजा जी ने इसके विरुद्ध साविधानिक तरीके से आन्दोलन प्रारम्भ

कर दिया। उन्होंने कानूनी सुप्रीम कोर्ट के समान जनता की नागरिक स्वतन्त्रताओं पर लग गवर्नर जनरल के अध्यादेश के विरुद्ध स्मरण पत्र पत्र किया। वहाँ उस अस्वीकार कर दान पर प्रिवी काउंसिल में भी स्मरण पत्र भेजा। यद्यपि वहाँ भाव बह अस्वीकृत हो गया तथापि उन्होंने सावधानिक तरीका से इस यायाचिनमाग की पूर्ति के लिए आन्दोलन जारी रखा। अतः उनकी मृत्यु के दो वर्ष पश्चात् 1835 में सर चार्ल्स मन्काऊ जब गवर्नर जनरल होकर आया तो उसने भारतीय प्रस की स्वतन्त्रता का मान्यता दी।

भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित याय व्यवस्था के अंतर्गत न तो भारतवासियों को सच्ची याय मिल सकती थी और न यहाँ यायपात्रिका कायपात्रिका से स्वतन्त्र थी। राजा जानें तक विरुद्ध आवाज उठायी। उन्होंने सरकार के समान प्रस्ताव रखे कि यायानया में ज्यूरा प्रथा लागू की जाय यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट के पद पृथक् किये जाय कम्पनी की नागरिक सेवा में भारतीय नागरिकों की अधिक से अधिक सहायता में नियुक्ति की जाय और विधि निमाण के निमित्त भारतीय जनमत का ज्ञान किया जाए। उन्होंने किमाना के ऊपर जमीनारों के अत्याचारों के विरुद्ध भी कानून बनाने की माग की।

राजा राममोहन राय सबसे पहले वह नता थे जिन्होंने भारतीय जनता की राजनीतिक एवं नागरिक स्वतन्त्रताओं के सम्बन्ध में वैधानिक तरीकों से सरकार के समक्ष माग रखी। व्यक्ति स्वतन्त्रता की उपनिधि कराना उनसे राजनीतिक विचारों का केन्द्र था। नागरिक अधिकारों के निमित्त वे विधि के शासन को लागू करने के हिमायती थे। उन्होंने पाश्चात्य देशों की राजनीतिक धारणाओं का सत्य भारतवासियों को दिया और अतः 1830 में जब वे इंग्लैंड गए तो वे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। वहाँ के स्वतन्त्रता प्रेमी तथा मानवता प्रेमी महान् विभूतियों ने उनका हृदय से स्वागत किया। राजा जी ने इंग्लैंड की जनता को भारत की स्थिति से अवगत कराया और इंग्लैंड में भारतीय जनता की मागों के समर्थन में जनमत जुटाने का कार्य किया। कुछ काल तक वहाँ रहने के पश्चात् 1833 में वहाँ उनकी मृत्यु हो गयी।

भारतीय पुनर्जागरण की प्रेरणा देने वाले समाज-सुधार एवं धर्म-सुधार के कार्य का एक नवीन निष्ठा में संचालित करने वाले पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति के साथ समन्वय करने वाले तथा भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करने वाले और भारतवासियों को नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता के महत्व का सत्य दान देने वाले वे प्रथम भारतीय थे। उनके अथक प्रयासों का ही यह फल हुआ कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग समाज-सुधार धर्म सुधार एवं राजनीतिक मागों के प्रति जागरूक हुआ। उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन में एक नई नहर पैदा की। उनका मृत्यु के पश्चात् उनके ब्रह्म समाज के कार्य को उनके शिष्य महर्षि देवदत्ताय ठाकुर तथा कान्धकार सन ने जारी रखा और कालांतर में आय समाज प्राथना समाज तथा अन्य सुधार संगठनों को उनसे प्रेरणा मिली। जब भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रीक्षण हुआ तो राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्भव सभी आरम्भिक नेता जिन्हें हम उदारवादी कहते हैं राजा राममोहन राय के विचारों से प्रभावित थे और उन्हीं की नींव पर उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का आग बढाया। मुरद्वनाथ बनर्जी ने उन्हें भारत में सावधानिक आन्दोलन का जनक करके सम्बोधित किया है। राजा राममोहन राय ने जो सदेश भारत को दिया था उससे कारण भारत का नव जागरण तथा राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

(ख) स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883)

राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज आन्दोलन की ही भांति उन्नासवा गतानी के अन्तिमाध में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आय समाज ने हिंदू धर्म सुधार भारतीय समाज के सुधार तथा भारत में नव राष्ट्रवादी निष्ठा का प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान किया

है। यह भी एक महत्त्वपूर्ण बात है कि ब्रह्म समाज का महत्त्व धीरे-धीरे घटता गया, परन्तु आर्य समाज आज तक अपने विकसित रूप में न केवल विद्यमान है, अपितु भारतीय हिन्दू समाज के अन्तर्गत उसे व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशकर था, 1824 में गुजरात के एक कट्टर हिन्दू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक कट्टर शिव उपासक थे। अतः मूल शकर को बाल्य काल में शिव भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी गयी। बाल्यवस्था से ही मूल शकर एक प्रतिभाशाली तथा विवेकपूर्ण चिन्तन करने वाले व्यक्ति सिद्ध हुए। शिवरात्रि के पर्व पर एक दिन रात्रि को शिव मन्दिर में जागरण करते हुए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाये गये प्रसाद को खा गया और शिवजी की मूर्ति जो इतनी महान् शक्तिशाली मानी जाती रही, वह स्वयं चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकी। उन्होंने अपने आपसे प्रश्न किया और अपने पिता से भी, कि आखिर यह क्या रहस्य था। कुछ काल पश्चात् उनके घर में विशुचिका से दो मृत्युएं हो गयीं। उन्होंने तब भी यही प्रश्न किया कि जो परम शक्तिशाली शिव-मूर्ति निरन्तर पूजी जा रही है, वह ऐसा चाण नहीं दे सकती तो उस मूर्ति की पूजा पर विश्वास रखना कौन-सा धर्म है? वस यही से वे सत्य ईश्वर की खोज में लीन हो गये। वे राजा राममोहन राय की तरह मूर्ति पूजा के विरोधी तो हो ही गये। साथ ही सत्य की खोज में लग गये। पिता ने उनका मन बहलाने के लिए उनकी शादी का प्रस्ताव किया तो वे घर छोड़कर ही चले गये और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तर भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने लगे। उन्हें ऐसे गुरु की तलाश थी, जो उन्हें सत्य का दर्शन करा सके। अनेक मठों में जाकर उन्होंने दर्शन का अध्ययन किया, योगाभ्यास भी किया, साथ ही वेदों का भी अध्ययन किया। उन्हें कोई सच्चा साधु नहीं मिला जो उनकी निष्ठा का भाजन बन सके। अन्ततः 24 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वामी पूर्णानन्द से दीक्षा लेकर सन्यास ले लिया और स्वामी पूर्णानन्द ने उनका नाम दयानन्द सरस्वती रखा। बाद में वे मथुरा में स्वामी विरजानन्द के कठोर अनुशासन में उनके शिष्य रहे। उन्होंने दयानन्द को उपदेश दिया कि वे इस विश्व में फैले अनाचार आदि से विरक्त रहे और वेदों में वर्णित धर्म को अपनाये तथा विश्व को इसका सन्देश दे।

यद्यपि स्वामी दयानन्द ने सन्यास धारण कर लिया था, तथापि वे सासारिक जीवन से विरक्त नहीं हुए। उन्होंने सन्यास सत् की खोज के लिए धारण किया था। उन्हें ब्रह्म के दर्शन वेदों में हुए। सनातन हिन्दू-धर्म में प्रचलित अनेकेश्वरवाद कर्म-काण्ड, मूर्ति-पूजा आदि को उन्होंने धार्मिक आडम्बर तथा पाखण्ड समझा। राजा राममोहन राय की मूर्ति-पूजा विरोधी तथा एकेश्वरवादी ब्रह्म समाज की शिक्षाओं का आधार उनका उपनिषदों का ज्ञान था, जबकि स्वामी दयानन्द ने वेदों तथा वैदिक धर्म का अवलम्बन किया और यह उपदेश दिया कि वास्तविक धर्म वैदिक धर्म है जो आधुनिक विज्ञान, विवेक, तर्क आदि सबका मूल है। वेदों में वह समूचा ज्ञान भरा पड़ा है जो कि आधुनिक विकास के अन्तर्गत व्यक्त हुआ है। पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि की सत्यता सद्विध है। वेदों में निहित ज्ञान वास्तव में ईश्वर की वाणी है। इस प्रकार स्वामी दयानन्द ने वैदिक धर्म को ही वास्तविक धर्म माना और उसी का उपदेश जनता को दिया। स्पष्टतया उनके विचार जाति-पातिगत भेदभाव, छुआछूत की भावना, ऊँच-नीच आदि के कट्टर विरोधी थे। इस दृष्टि में उन्होंने सनातन हिन्दू धर्म के अन्तर्गत आ गयीं बुराइयों का कट्टर विरोध किया।

अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। फिर उसका प्रसार लाहौर तथा उत्तरी भारत के अन्य स्थानों में भी किया। स्वामी जी द्वारा स्थापित आर्य समाज एक ऐसी संस्था थी जिसके उपदेश सरल, मानवतावादी एवं गुणमतापूर्वक ग्राह्य सिद्ध हुए। इनमें हिन्दू धर्म के अन्तर्गत मान्य संस्कारों, कर्मकाण्ड, परिपाटियों आदि की जटिलता नहीं थी। आर्य समाज ने शुद्धिकरण की योजना अपनाकर विधियों को भी, ○ राष्ट्रीय आन्दोलन/4

हिंदू धर्म में जान का भाग प्राप्त किया। मनातन हिंदू धर्म के अतगत धर्म बहिष्कृत जाया तथा विधर्मिया का अपन में मना करने की व्यवस्था नहीं थी। आज समाज ने इस कठोर नियम का मर्यादित किया और नए प्रकार के मन भागीय राष्ट्रीयता के निमाण में महत्वपूर्ण योगदान किया। ब्रह्म समाज के अतगत पारचात्य मर्यादित तथा ईसायित का भी प्रभाव बना रहने से वह अविश्व नोकप्रिय नया नया पाया जाकि आज समाज प्रियुद्ध तथा हिन्दुत्व तथा वैदिक मर्यादित पर आधारित हान के कारण वन जनप्रिय सिद्ध हुआ।

स्वामी न्यायन ने तत्कालीन हिंदू समाज में अतगत जिन बुराया का दया उन् समाप्त करने का अभियान भा प्रारम्भ किया। वान विवाह बहु विवाह विप्रवाज की समस्या शिक्षा प्रसार आदि के सम्प्रध में भी स्वामी जान पुगत्या का निराकरण करने के जागान चलाय। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में आज समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभा की सभा में छोटी छोटी जने शिक्षा में मर्यादें आज समाज के द्वारा मर्यापित का गयी हैं। स्वामी जी ने अनिवार्य निगुत शिक्षा का आवश्यकता का बहुत महत्व दिया। उनका मत था कि 18 वर्ष का उम्र तक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चा की बौद्धिक गतिया का विकास उनमें मर्यादित साधन की दव उत्पन्न करना ब्रह्मचर्य पानन गारीरिक विमर्श तथा आत्मनुशासन की प्रवृत्ति जाशुत करना होना चाहिए। वे गुरुकुल मर्यादित शिक्षा मर्यादा की मर्यापना पर बन दन थे। सह शिक्षा का व उचित छो मानन थे।

स्वामी जी की शिक्षा याजना राष्ट्रीय शिक्षा की धानक थी। उनके द्वारा मर्यापित आज समाज की शिक्षा धर्म निरपक्षता की एनी याजनाए है जिनके अतगत साम्प्रदायिक भेदभाव जातिगत भेदभाव या धर्मगत धना का कार्य मर्यान प्राप्त नहा है। व विभिन्न धर्मों के अतगत अधविश्वासा के विगोधी थे। उनका आज समाज एना हिंदू धर्म था जा एक मानवतावादी धर्म की शिक्षा दता है और जिसमें प्रत्येक यक्ति का गामिन करने का प्राविधान है। भारत मर्यादित विविध धर्मों का मानन बानी जनता के निमित्त राष्ट्रीय एकता की धारणा का बनवनी बनान के लिए आज समाज से उत्तम और वया व्यवस्था हा मकनी थी? स्वामी जी की अध शिक्षाया के अतगत उनका मर्यादी के प्रति प्रेम वन व्यवस्था मर्या उत्पन्न मर्यादितता का वितन करना हिंदी का राष्ट्र भाषा के रूप में मानना महिना उद्धार सत्य के प्रति निष्ठा धार्मिक सहिष्णुता तथा गामाजिक कुप्रथाया का तीव्र विराध गामिन है। इस प्रकार नव जागरण के युग में समाज तथा धर्म के क्षेत्र में जा सुधार की याजनायें तथा प्रचार उहान सम्पन्न किया उहाने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने तथा एन प्रबुद्ध चेतना उत्पन्न करने की शिक्षा में महान् योगदान किया।

स्वामी दयानंद के विचारा का क्षेत्र धर्म तथा समाज सुधार तक हा सीमित नहीं है। गजनीतिक क्षेत्र में भी उनका विचार महत्वपूर्ण है। व एक यथाय नाकतंत्रवादी थे। यद्यपि व समाज को एक सावयव के रूप में मानते थे तथापि उसके अतगत यक्ति की गरिमा का बनाय रखने के लिए यक्तिगत स्वतंत्रता समानता तथा बहुलता का धारणा पर बल दत थे। राज्य के काय तंत्र के सम्बन्ध में उहान जपन युग में यूरोपीय मर्या में विकसित यद्भाव्यम् (laissez faire) नीति का विराध करके नाकतंत्रवाणकारा राज्य के जाग को भाय किया। व गामन सत्ता के कनीकरण की प्रवृत्ति के विरोधी थे और प्रतिनिध्यात्मक मर्याया द्वारा गामन सत्तान नियं तान की आवश्यकता पर उहाने बन दिया। उम काल में भारत की गामन सत्ता ब्रिटिश नौकरशाही के स्वेच्छाचारी गामन के अन्तगत थी। एस समय में स्वामी दयानंद ने प्राचीन भारतीय लाजतन्त्री पद्धतिया का जागु किया जान की आवश्यकता पर नन दिया। उनका मत था

1 स्वामी दयानंद स्वयं गुजराना थे। उनको रचनाएँ जिनमें सत्याय प्रकाश प्रमुख है हिन्दी में लिखा गयी थी।

कि देय की प्रतिनिध्यात्मक मस्था मे तीन प्रकार की सभाये होनी चाहिए, राज्य सभा (राजनीतिक कार्यों के लिए), धर्म सभा (धर्म सम्बन्धी व्यवस्था के लिए) और विद्या सभा (सामाजिक एवं साम्प्रतिक कार्यों के लिए)। वे प्रबुद्ध प्रतिनिधियों के हाथ मे शासन सत्ता रखने की नीति के समर्थक थे। उनके राजनीतिक विचार प्राचीन भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं की शिक्षाओं पर आधारित थे, मुख्यतया वेदों तथा स्मृतिकारों के विचारों पर।

स्वामी दयानन्द के विचारों तथा उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के कार्य-कलापों ने 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के विकास मे महान् योगदान किया। उन्होंने हिन्दू समाज को अन्धविश्वासों, सामाजिक कुप्रथाओं के गर्त तथा विविध प्रकार के भेदभावों मे फँस जाने से बचाया, साथ ही ईसाई मिशनरियों तथा मुस्लिम धर्म के अत्याचारों से भी बचाया। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के अधिकांश नेता पाश्चात्य सस्कृति के प्रशंसक थे। उनके कार्यकलापों मे पाश्चात्य रंग था। स्वामी दयानन्द ने भारतवासियों को विशुद्ध भारतीय सस्कृति की गरिमा का उपदेश देकर भारतीय राष्ट्रीय भावना के संचार का बीज वपन किया। यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन मे पाश्चात्य प्रेमी उदारवादियों की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रीयता का अभ्युदय हुआ। तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल, महात्मा अरविन्द, विवेकानन्द आदि सभी ने विशुद्ध भारतीय सस्कृति का सन्देश दिया। इनके विचारों मे स्वामी दयानन्द के प्रभाव को विशिष्ट स्थिति प्राप्त होती है। दयानन्द को एक विशुद्ध राजनीतिक विचारक की श्रेणी तो प्राप्त नहीं होती, और न ही वे अपने युग के अन्य कई नेताओं की भाँति के राजनेता के रूप मे थे जिन्होंने किसी प्रकार के साविधानिक आन्दोलन मे सक्रिय भाग लिया हो। परन्तु समाज तथा धर्म सुधार कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ उन्होंने जिन राजनीतिक आदर्शों की व्याख्या की थी, उनके कारण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को बहुत प्रेरणा मिली और उनके अनुयायी बाद मे सक्रिय राष्ट्रीय राजनीतिक नेता बने।

(ग) स्वामी विवेकानन्द (1863-1900)

19वीं शताब्दी के धर्म-सुधार तथा समाज-सुधार आन्दोलनों मे राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती के आर्य समाज ने भारत की हिन्दू जनता मे जिस नव-चेतना का संचार किया था, उसे और अधिक भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्त करके भारतीय धर्म को मार्वाभौम रूप प्रदान करने का कार्य स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने किया। स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त पर आधारित हिन्दू धर्म तथा हिन्दू सस्कृति की महानता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करके उसके मानवतावादी स्वरूप का भारत मे ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे प्रचार करने मे सफलता प्राप्त की। उनकी शिक्षाओं तथा विचारों का भारत के कोने-कोने मे प्रचार होने मे बाद के राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर गांधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि मे राजनीति तथा आध्यात्मिकता के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने मे अवलम्बन किया और उस युग मे पाश्चात्य की भौतिकतावादी प्रवृत्ति मे राजनीतिक विचारों तथा व्यवहार को मुक्त करने की प्रेरणा विश्व को दी।

सही अर्थ मे दयानन्द सरस्वती की भाँति स्वामी विवेकानन्द भी न तो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक चिंतक थे और न ही उन्हें एक राष्ट्रीय नेता मानना उपयुक्त है। परन्तु उस युग के धार्मिक, सामाजिक तथा साम्प्रतिक पुनर्जागरण मे उन्होंने भारत की राजनीतिक एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की थी। स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस अर्थ मे वे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक नेताओं की श्रेणी मे आते हैं। स्वामी दयानन्द, जो कि आर्य भाषा मे बिल्कुल अपरिचित थे, ने प्रेसों को अपने विचारों का जवाब बनाकर वैदिक धर्म तथा वैदिक सस्कृति का व्यापक प्रचार किया, स्वामी विवेकानन्द एक प्रतिभाशाली ग्रेजुएट थे, उन्होंने पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन

किया था। व जमराजा तथा यूरोप के अनेक देशों में भी गये थे। इसलिए अग्रजी साहित्य पाश्चात्य दान एवं सस्कृत ग्रंथों का गहन अध्ययन का आधार पर उन्होंने भारतीय सस्कृति का गरिमा को पाश्चात्य ज्ञान की तुलना में उत्कृष्ट सिद्ध करने का सफल प्रयास किया।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म बंगाल के एक सम्भ्रात कथस्थ परिवार में हुआ था। व प्रचपन से ही एक प्रतिभाशाली तथा प्रसर बुद्धि वाल व्यक्ति सिद्ध हुए। उनकी माता हिंदू धर्म ग्रंथों का विगद नान रखती थी। उनसे बालक विवेकानन्द¹ (जिनका प्रारम्भ का नाम नरनाथ था) को भारी प्रेरणा मिली। उनकी विनम्र बुद्धि तथा स्मरण शक्ति की प्रशंसा उनके अध्यापकों ने निरन्तर की है। विद्यार्थी जीवन से ही वे दान तथा अध्यात्म ज्ञान में रुचि रखते थे। उनका ज्ञान भारत की दीन तथा दरिद्र जनता का दुःखा की ओर गया। उन्होंने अपने जीवन का नित्य दरिद्र जनता के कष्टों का निवारण करना बनाया और इस उद्देश्य से वे परमात्मा की खोज करने लगे। उन्हें इस उद्देश्य की सफलता के लिए एक गुरु की आवश्यकता थी और ऐसे गुरु उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले। यद्यपि रामकृष्ण ने विवेकानन्द में गिण्यत्व के पूरे गुण पाए तथापि विवेकानन्द सहस्र त्रिवक्शोन् व्यक्ति ने उनका गुरुत्व स्वीकार करने में पूर्व बहुत जम्हा अवधि तक उनकी सेवा की और उनके स्वरूप को पहचानने का प्रयास किया। अंत में उन्होंने गुरु को राम तथा कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार किया और गुरु तथा गिण्य की आत्मा का मिलन गुरु के शरीरान्त के समय ही हुआ। उनके पश्चात् विवेकानन्द ने अपने गुरु के सत्य का प्रचार प्रारम्भ किया।

उन्होंने कनकता के समीप जारानगर में 1886 में रामकृष्ण के नाम से एक मठ स्थापित किया जहाँ पर उनके सहचारी योग अध्यात्म का अध्ययन करते थे। उसके पश्चात् वे भ्रमण के लिए चले गए। सारे भारत का भ्रमण करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमात्मा का निवास प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में है। भारत की दरिद्र जनता के कष्टों का निवारण ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। व भारत की जनता के मध्य अमीर गरीब के भेदभाव से दुरी हुए। जाति प्रथा के लोप को त्यक् कर उन्हें बड़ा आघात पहुँचा। अंत में व कयाकुमांगी के पास ममुन् स्थित एक बन्दर पर बैठकर विचार करने लगे कि उनका क्या कस्य है? उन्हें बोध हुआ कि मानव मान की आत्मा में परमात्मा का वास है। अतः मानव मात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। उन्होंने यह अनुभव किया कि मानव आत्मा में जो दिव्य तत्त्व है उस प्रकार में जाकर उसकी आत्मा का विस्तृत करने वाले तत्त्वों—काम क्रोध मोह मायामोह आदि से मुक्त कराना चाहिए। एसा दिव्य संदेश हिंदू धर्म की शिक्षाओं में विद्यमान है। उन्होंने समूचे भारत का एक राष्ट्र के रूप में लिया। इस राष्ट्राय महानता तथा एकता को बनाए रखने में हिंदू धर्म की शिक्षाय योगदान करती हैं। राष्ट्र का जनता का कष्ट तथा दरिद्रता से नाश देने का युक्ति यहाँ है कि राष्ट्र का जीवन सम्पूर्ण के लिए त्याग तपस्या तथा सेवा का भावना से निर्मित किया जाय। यही वास्तविक मानव धर्म है जिसकी शिक्षा हिंदू धर्मशास्त्रों के अंतर्गत दी गयी है। यही भारतीय राष्ट्र सस्कृति तथा हिंदू धर्म की महानता है। यही का प्रचार एवं उनकी सही कार्यविधि मानव का उनके कष्टों से त्राण दे सकती है।

1893 में अमरीका के चिकागो नगर में विश्व भर के धर्मों का महासम्मेलन हुआ था। विवेकानन्द का उद्देश्य आमंत्रित होकर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने की सहाह कुछ भारतीयों ने दी। उन्हें यह प्रस्ताव उचित लगा। परन्तु तत्काल निमित्त उन्होंने अमीर योगों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अस्वीकार कर दी और निधन जनता द्वारा एकत्र धन ही स्वीकार किया क्योंकि वे उसी निधन हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने जाने वाले थे। उनके कष्ट सहन करते

¹ यह नाम उन्हें सेतडी के राजा ने उस समय दिया जबकि वे अमरीका की यात्रा पर जाने वाले थे और उनके पश्चात् इसी नाम से प्रसिद्ध हो गये। परन्तु पूर्व उन्होंने अपने कई नाम रखे और अपना वास्तविक नाम चुन रखा।

हुए वे अमरीका पहुँचे। वहाँ सम्मेलन के प्रतिनिधियों की सूची में उनका नाम अंकित कराने की तिथि दीत चुकी थी। उनकी कोई पूर्व योजना भी नहीं थी, न उन्हें सम्मेलन की कार्य-विधियों की जानकारी थी। परन्तु वहाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों से अकस्मात् उनका परिचय हो गया जिन्होंने धर्म-सम्मेलन के अधिकारियों के समक्ष उनकी प्रतिभा का परिचय कराया और उन्हें धर्म-सम्मेलन में आमंत्रित करा दिया। इस महासम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व के विविध वर्गों के प्रतिनिधियों में से विवेकानन्द ही ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र के थे। उन्होंने देखा कि सभी लोग अपने निखित भाषण दे रहे थे, परन्तु उनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। परन्तु उनका आशु व्याख्यान सुनकर श्रोता लोग चकित हो गए। उनके व्याख्यान ने सम्पूर्ण श्रोताओं को हिन्दू धर्म की महानता के प्रति आकृष्ट किया। यह पहला अवसर था जबकि इतनी विशाल सस्था के समक्ष किसी भारतीय ने हिन्दू धर्म की महानता का सन्देश देकर विश्व के विविध धर्मावलम्बियों के ऊपर अपनी छाप छोड़ी। राष्ट्रीय गरिमा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का यह महान् कार्य विवेकानन्द ने पूर्ण किया। उनके प्रभाव में अनेक अमरीकी लोग आ गए। फिर वे इंग्लैंड गए। वहाँ भी उनका इसी प्रकार सम्मान हुआ। जब वे भारत वापस आए तो फिर देश भर में भ्रमण किया। अल्मोडा जिले में चम्पावत के पास मायावती नामक स्थान पर स्वामी रामकृष्ण व विवेकानन्द की स्मृति में अद्वैत आश्रम की स्थापना उनके कुछ शिष्यों ने की है। यहाँ पर अध्यात्म चिन्तन के साथ-साथ गरीब लोगों को बीमारियों की निशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने की सुविधा भी दी जाती है। वेलूर मठ की स्थापना भी 1898 में की गयी थी। यह मिशन का प्रमुख केन्द्र है। अमरीका के न्यूयार्क नगर में उन्होंने वेदान्त सोसाइटी की स्थापना की जिसका उद्देश्य अमरीका वासियों को वेदान्त का ज्ञान कराना था। यूरोप में मैक्समूलर को उनसे मिलकर बड़ा सुख तथा मन्तोष हुआ। इसी प्रकार इंग्लैंड के अनेक दार्शनिक भी उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए।

भारत में उभरती हुई राष्ट्रीयता के युग में स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं ने राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का आदर्श प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने बताया कि राष्ट्र का वास्तविक जीवन केवल धर्म है। उन्होंने भारतवासियों को चेतावनी दी कि पाश्चात्य देशों की भौतिकतावादी सत्कृति भारतीय राष्ट्र के उत्थान में कभी सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। उन्होंने हिन्दू धर्म की रूढ़िवादी परम्पराओं को अमान्य किया जिनके अन्तर्गत जाति-प्रथा, छुआछूत आदि बुराईयाँ आ गयी थी। उन्होंने ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा भक्तियोग तीनों को सही परिपेक्ष में रखा और हिन्दू धर्म के मानवतावादी तथा आध्यात्मिक स्वरूप को यथार्थ के सन्दर्भ में व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि धर्माचरण दरिद्रता में सम्भव नहीं है, दरिद्रता निवारण सच्चा मानव धर्म है। विवेकानन्द मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, प्रत्युत वे मूर्ति पूजा को एक साधन के रूप में मानते थे। जाति-पाति के भेदभाव, छुआछूत की प्रथा के निवारण तथा अन्य ऐसी कुप्रथाओं का अन्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। यद्यपि विवेकानन्द न एक राजनेता थे और न वे राजनीति में महानुभूति रखते थे, तथापि उनके विचारों में देशभक्ति तथा राष्ट्रप्रेम की भावनाएँ भरी पड़ी थी। अतः आध्यात्मिक आधार पर राष्ट्रवाद के विकास में उनकी शिक्षाओं का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जिसे बाद में तिलक, अरविंद तथा गांधी जी ने अपनाया। उनका अध्यात्मवाद हठधर्मों या विरक्ति का नहीं है। वह कर्म की शिक्षा पर बल देता है। वे एक अर्थ में समन्वयवादी थे। भारतीय अध्यात्म का पाश्चात्य के भौतिकवाद के साथ, तथा भारतीय वेदान्त का पाश्चात्य के विज्ञान के साथ समन्वय करके वे ऐसे मानव समाज की स्थापना पर जोर देने थे जिसमें असमानता, अन्याय, शोषण, निरकुशता आदि को समाप्त किया जाय और मानवता एवं पारस्परिक भ्रातृत्व की भावना में जीवन-यापन करे। इस प्रकार स्वामी जी ने भारत को ही नहीं अपितु विश्व को मानवधर्म की महत्ता सिनायी जिसका श्रोत उन्होंने वेदान्त तथा भारतीय सत्कृति में देना। परिणाम यह हुआ कि स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं ने भारतवासियों को राष्ट्रीयता की नेतृता की ओर वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के महत्त्व को समझने लगे। इस दृष्टि में भारतीय

राष्ट्रीय जातिवाद का प्रभावित करने में स्वामी विवेकानन्द का नाम विस्मृत नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय उदारवादी नेता

(क) दादाभाई नौरोजी (1825-1917)

भारतीय राष्ट्रीय जातिवाद का प्रारम्भिक अग्रगण्य नेताओं में दादाभाई नौरोजी का समाधि का विस्मृत नहीं किया जा सकता। उन्हें कभी-कभी राष्ट्रीय जातिवाद के भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है। कांग्रेस की स्थापना एवं उसका विराम में वर्ष 1885 में 1917 तक राजम अपना सक्रिय सहयोग देते रहे। वे अपनी पीढ़ी के एक समस्या के व्योमूढ नेता थे। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के आरम्भिक युग के उत्तरवादी नेताओं में थे। उनका राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रप्रेम उन्हीं की तरह उच्च स्तर का था। दादाभाई नौरोजी का कांग्रेस के साथ सम्बन्ध निरन्तर प्रारम्भ में ही हो चुका था और उसके पश्चात् अपनी पर्याप्त वृद्धावस्था तक वह कांग्रेस की सेवा करते रहे। उत्तरवादी की परम्परा के अनुरूप नौरोजी भी अंग्रेजी शिक्षा तथा संस्थाओं की प्रवृत्ति पर विश्वास रखते थे। उन आरम्भिक उत्तरवादी नेताओं की श्रेणी में दादाभाई नौरोजी राजनीतिक भिन्नता की नीति के अनुयायी रहे। उन्हें 1886-1893 तथा 1906 में तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने इस नायित्व का पूर्ण निष्ठा के साथ सम्पन्न किया। उनके नेतृत्व में वे पट्टाभि भीतारामों के शासन में कांग्रेस का स्वरूप प्रणामनिक कठिनायियों को दूर करने की योजना करने वाले नेता के एक युग में एक ऐसी राष्ट्रीय सभा के रूप में विकसित हुआ जिसका उद्देश्य निश्चित रूप में स्वराज्य प्राप्ति हो गया।

कांग्रेस की स्थापना के कुछ ही वर्षों के पश्चात् ब्रिटिश सरकार कांग्रेस पर सख्त करने लग गया थी और उस समान करने देने के प्रयास भी किए गए। परन्तु दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी यही नीति घोषित की कि वह स्वतंत्रता की याचिका पर विश्वास रखता है। ब्रिटेन के प्रति उनकी असीम निष्ठा के कारण उन्हें पार्लियामेंट की कामन सभा के लिए भी निर्वाचित किया गया। स्वयं दादाभाई एक महान् संस्था में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का मात्र अभिप्राय रखते थे। वे इस संस्था में चुने जाने का प्रथम भारतीय थे। वे इस संस्था में जाकर ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनता का भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहते थे। वहाँ उन्होंने पार्लियामेंट की जनता का बताया कि कांग्रेस भारत की शिक्षित जनता का संस्था है जो ब्रिटिश संस्थाओं तथा परम्पराओं के प्रति निष्ठावान है। जब 1905 में लार्ड कर्जन की प्रशासन नीतियाँ विचारकर प्रगति के नये दृष्टिकोण में धारित असातुप छा गया था और प्रशासन में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी थी तो 1906 में कांग्रेस के वक्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। उस समय देश में उग्रवादी राष्ट्रीयता का विकास होने लग गया था। ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध बढ़ता जा रहा था। देश में स्वतन्त्र आन्दोलन तीव्र गति में बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने भी घुससमाज में साम्प्रदायिक भावना बढ़ाने की नीति अपनाकर कांग्रेस की राष्ट्रीय एकता को जवरुद्ध करने का कुचक्र फेला दिया था। उनके परिणामस्वरूप शासन की नीतियों के विरुद्ध जनता के असंतोष का दवाने के लिए शासन ने जो दमन की नीति अपनाई थी उसकी प्रतिक्रिया अब अधिक स्वायत्त शासन की माँग (स्वराज्य) प्रतिष्ठा के स्वतन्त्र तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के रूप में बढ़ गयी। यही सब प्रस्ताव 1906 के वक्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व तथा अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा पास किए गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का स्वतन्त्राचारि प्रणामनिक तथा आर्थिक नीतियों का परीक्षण किया। उनकी रचना (British Unrulers India) में उन्होंने तथ्यगत जोड़े के ब्रिटिश शासन की आर्थिक तथा प्रशासनिक शासन की नीतियों की बहुत आलोचना

की उनके शान्त तथा उदार नेतृत्व में कांग्रेस की एकता तथा प्रतिष्ठा बनी रही। यद्यपि कांग्रेस के अन्दर उग्रवादी तत्त्व पर्याप्त अधिक विकसित हो चुके थे तथापि उनके प्रभाव से कम से कम 1906 में कांग्रेस में विभाजन रुक गया।

दादाभाई नौरोजी की देश भक्ति, राष्ट्रसेवा, सौजन्यता तथा ओजस्विता के कारण उन्हें 'राष्ट्रीय आन्दोलन का पितामह' कहना सर्वथा सत्य है। यही कारण है कि उनके सफल नेतृत्व में 1906 तक कांग्रेस की उदारवादी नीतियाँ बनी रहीं। साथ ही ब्रिटिश सरकार के समक्ष कांग्रेस को नीति वीस वर्ष के अन्दर ही 'भिक्षावृत्ति' से कही अधिक आगे बढ़ गई और नौरोजी के काल में ही 'स्वराज्य' की माँग तक पहुँच गई। यद्यपि उस काल की स्वराज्य की माँग 1929 की पूर्ण स्वाधीनता की माँग के सदृश नहीं थी, तथापि वह औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग के रूप में थी। ब्रिटिश नौकरशाही का विरोध बढ़ने लग गया था। इस विकास-क्रम में दादाभाई नौरोजी का सक्रिय भाग रहा।

(ख) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (1848-1925)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का संगठित सूत्रपात करने वाले अग्रगण्य नेता, अपने युग के महान्तम व्याख्यानदाता, ब्रिटिश शासनकाल में इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सर्वप्रथम भारतीय एवं ब्रिटिश शासन तथा ब्रिटिश संस्कृति के सच्चे पुजारी होते हुए भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना को सक्रिय रूप प्रदान करने वाले महापुरुषों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का नाम सर्वप्रथम आता है। उस युग में भारतीयों के लिए इंग्लैंड में जाकर सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना अत्यन्त दुस्तर कार्य था, परन्तु सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इसमें सफल हुए। 1871 में वह मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त हुए परन्तु दो वर्ष के बाद उनके ऊपर सरकारी आचरण में दोष लगाकर उन्हें पदच्युत कर दिया गया। यह तत्कालीन शासकों का अन्यायपूर्ण व्यवहार था। बनर्जी ने इसके विरुद्ध इंग्लैंड की सरकार के समक्ष अपील भी की परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके उपरान्त श्री बनर्जी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। कुछ समय तक मेट्रोपोलिटन कालेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे, फिर पत्रकारिता का कार्य करने लगे। सरकार की आलोचना करने पर उन्हें एक बार कारावास का दण्ड भी मिला।

राष्ट्रीय आन्दोलन के एक प्रारम्भिक नेता के रूप में बनर्जी का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना (1876) करना था, जो कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी और कांग्रेस की स्थापना हो जाने पर उसमें विलीन हो गई। इसके उपरान्त बनर्जी आजन्म कांग्रेस की सेवा करते रहे। वह दो बार (1895 तथा 1902 में) कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंग-विच्छेद कर दिया, तो बनर्जी ने उसके विरोध में एक प्रभावशाली आन्दोलन का नेतृत्व किया। इससे पूर्व वह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उदारवादी नेता थे। जब कांग्रेस में उग्रवादी दल उत्पन्न हो गया तो बनर्जी अपनी उदारवादी नीति पर हट बने रहे। वह जहाँ एक सच्चे राष्ट्रभक्त तथा देशभक्त नेता थे, वहाँ वह ब्रिटिश शासन तथा ब्रिटिश संस्थाओं के भी भक्त बने रहे। वह मदैव यही प्रयत्न करते रहे कि अंग्रेजों से भारतीय मांगें पूर्ण कराने में राति का नहीं अपितु शांति तथा सहयोग का मार्ग अपनाया जाये और अपनी कठिनाइयाँ वैधानिक तरीकों से रजि जाँ। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि 'भारत अपनी स्वतन्त्रता यथासमय प्राप्त करेगा जिसका मूल अंग्रेजी, चरित्र अंग्रेजी तथा संस्थाएँ भी अंग्रेजी होंगी।'⁵ वह इंग्लैंड को भारत का राजनीतिक मार्गदर्शक मानते थे। वह अपने को ब्रिटिश प्रजा कहने में नहीं हिचकते थे। ब्रिटिश संविधान तथा मन्त्रियों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी। परन्तु वह यह मानते थे कि अंग्रेज भान्तवानियों को अपनी प्रजा समझ कर उन्हें वह मुविवाएँ नहीं देते हैं, जिन्हें वह स्वयं अपने के प्रजाजनों के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इन पर भी लार्ड मिंटो के शासन काल में बनर्जी माहव को लाठी चार्ज में पुलिस के डण्डों की चोट खानी पड़ी।

द्वीमवा सदी के आरम्भिक वर्षों में जब कांग्रेस के अंदर उग्रवाणियों का प्रभाव बढ़ने लगा तो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का प्रभाव कम होने लगा। परंतु व 1925 तक जर्नल अमनी मृत्यु पत्रिका कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का मतत्व यथापूर्व अपना उदारवादी नीतियाँ के अनुसार ही करती रह। उनकी वाक्पटुता विनोद विमर्श तथा व्याख्यान कला जिसमें देशप्रेम की भावना बूझ-बूझ कर मरी थी और उनकी शान्तिप्रियता उनके नेताओं का मुख बनने की शक्ति रखती थी। यही कारण है कि कांग्रेस के आरम्भिक युग में वे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के एक महान् जनप्रिय नेता बने रह।

(ग) महादेव गोविंद रानाडे (1842-1901)

उन्नीसवीं सदी के मित्तीयाद्य में भारतीय राष्ट्रीय चेतना का तत्कालीन परिस्थितियों के जन्मगत जाग्रत तथा विकसित करने में राजा राममोहन राय की भाँति के समर समाज-सुधारक महात्त्व गोविन्द रानाडे थे। बम्बई के एक सभ्रांत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न इस विभूति का अग्रजी शिक्षा में एक अन्तर्तीय दक्षता प्राप्त हुई। अपने पिता की धार्मिक रुढ़िवाण्डिता के विरुद्ध विचार रखने हुए भी रानाडे उनके आनाकारों पुत्र थे जिसके कारण उन्हें अपनी रुढ़िवाण्डिता के विरुद्ध 31 वर्ष की अवस्था में विधुर हो जाना पड़ा पर एक ग्यारह वर्ष की कथा के साथ विवाह करना पड़ा परंतु जीवन भर उन्होंने वान विवाह विधवा विवाह निषेध जाति-पाति के भेदभाव आदि कुप्रथाओं का तीव्र विरोध किया। उनकी विद्वता सावजनिक जीवन में अभिरुचि व्यापकप्रियता अग्रजी शिक्षा तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रति निष्ठा की भावना का दमककर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शासन के उच्च न्यायिक पदा पर नियुक्त किया। वह भारत में अग्रजी शासन काल में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। आज्ञा सरकारी सेवा में रहते हुए भी रानाडे ने सावजनिक राजनीतिक जीवन में कार्य किया और भारत में राष्ट्रीयता के बीजा को अंकुरित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

उस काल का भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन का विरोधी नहीं था अपितु आवश्यकता के बात की थी कि भारतीय जनता में देशप्रेम आत्म सम्मान आत्म विश्वास राष्ट्रीय एकता महान भावनाओं को जाग्रत किया जाय। यह तभी सम्भव था जबकि भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक बुराईयाँ का जत हो और जनता रुढ़िवादी विचारों का परित्याग कर। राजा राममोहन राय ने समाज-सुधार की दिशा में जो कार्य किया था उस रानाडे ने और आगे बढ़ाया। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की भाँति ही रानाडे ने प्राथमिक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य जनता में रुढ़िवादी सामाजिक बुराईयाँ को समाप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न करना था। रानाडे ब्रिटिश शासन या पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्यता के विरोधी नहीं थे अपितु वे भारत की सामाजिक बुराईयाँ का जत करने के लिए उन्हें बरदान मानते थे इसका यह अर्थ नहीं कि रानाडे भारत की राजनीतिक पराधीनता का उचित समझते थे प्रत्युत धारणा यह थी कि ब्रिटिश शासन भारतवासियों का पाश्चात्य राजनीतिक सभ्यता तथा आदर्शों का ज्ञान करायेगा और उसके द्वारा भारतवासी पाश्चात्य नाकतनी सभ्यता तथा आदर्शों का ज्ञान करके अपने देश में उनके कार्याचयन का काम प्राप्त कर सकेंगे। इस दृष्टि से रानाडे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की आरम्भिक विचारधारा के नेताओं के मागदमा थे। रानाडे का विश्वास था कि मानव जीवन के विभिन्न पक्षों (सामाजिक धार्मिक आर्थिक तथा राजनीतिक) में सावयविक एकता है। इनमें से एक की कमी दूसरे को प्रभावित करती है। अतः समस्त सुधार अनग-अनग नहीं हो सकते। राजनीतिक स्वाधीनता तभी साकार हो सकती है जबकि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मानव स्वाधीन हो। अतः रानाडे ने तत्कालीन हिंदू समाज में प्रचलित रुढ़िवादी बुराईयाँ को समाप्त करना सबसे प्रथम कार्य समझा। राजा राममोहन राय के प्रयासों में सती प्रथा बत हो चुकी थी। रानाडे ने वान विवाह तथा बहु विवाह की प्रथाओं का समाप्त

करने तथा विधवा-विवाह को प्रोत्साहन देने के विचारों का समर्थन किया। जाति-पाँति के भेद-भाव को नष्ट करके सामाजिक एकता लाना उनकी दृष्टि में हिन्दू समाज की प्रथम आवश्यकता थी। रानाडे को देश की अधिकांश जनता की आर्थिक दरिद्रता के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने इनके कारणों पर भी प्रकाश डाला था। अतः उन्होंने औद्योगिक विकास, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण नीति का अन्त किया जाना, पूँजी का समुचित विनियोजन आदि द्वारा इन दोषों को दूर करने के विचार रखे।

समाज-सुधार के निमित्त उस युग में जो सस्थाएँ तथा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे थे उनके कार्य-कलापों में रानाडे ने सक्रिय भाग लिया और उनमें समय-समय पर उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, वे समाज-सुधारकों के प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुए। रानाडे पाश्चात्य लोकतन्त्री मन्थारों तथा आदर्शों के प्रति निष्ठा रखते थे। उन्होंने भारत के देशी नरेशों को भी शासन-व्यवस्था में लोकतन्त्री सुधार लाने के सुझाव दिये। रानाडे उदार विचारों वाले राजनीतिज्ञ थे। उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य विचारों का प्रभाव तत्कालीन भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं पर प्रचुर मात्रा में पड़ा। कांग्रेस के जन्मदाता ए० ओ० ह्यूम रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। रानाडे के विचारों ने गोखले, तिलक तथा महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित किया था। आरम्भ काल के सभी राष्ट्रीय नेताओं के विचारों पर रानाडे का प्रभाव था। 1883 में जब लार्ड रिपन के शासन काल में स्थानीय स्वायत्त शासन सन्स्थाओं की स्थापना की गयी तो रानाडे ने उनका स्वागत किया और उनके विचार से ऐसा प्रयास भारत में स्वशासन की शिक्षा के निमित्त आवश्यक कदम था। रानाडे की सच्ची तथा उदार राष्ट्रसेवा की भावना से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें बम्बई की प्रांतीय परिषद् में विधिसदस्य बनाया था।

राष्ट्रीयता की भावना के विकास में रानाडे की सेवाओं को भारत कभी नहीं भूल सकता। उनका वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम, समाज-सुधार के निमित्त ठोस सुझाव, राष्ट्रीयता की जागृति के निमित्त सामाजिक सन्स्थाओं में कार्य करना, तत्कालीन शासन के अनौचित्यपूर्ण कानूनों का विरोध तथा पूर्ण लगन से अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना आदि गुणों ने भविष्य के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष अनुकरणीय दृष्टान्त प्रस्तुत किये। जीवन के विविध क्षेत्रों में उनके कार्य-कलापों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक नेताओं के मध्य एक सम्माननीय स्थान दिया है।

(घ) गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक उदारवादी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम स्वर्णशरो में अंकित किया जाता है। गोखले का जन्म महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण कुल में रत्नगिरी जिले के एक ग्राम में हुआ था। अल्पायु में ही उनके पिता का देहावसान हो जाने के कारण उनके भाई ने, जो स्वयं भी आर्थिक दृष्टि में बहुत हीन स्थिति में थे, गोखले की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की। अठारह वर्ष की उम्र में उन्होंने बम्बई के ऐल्फिन्स्टन कालेज में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। इनके पश्चात् वह दक्षिण शिक्षा समाज (Deccan Education Society) के सदस्य बने। वह गणित के उच्च कोटि के विद्वान् थे। साथ ही उन्हें साहित्य में विशेष रुचि थी। जब तथा देश के विचारों का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। इसके कारण उनमें रूढ़िवादिता की छाप जा गयी। कालान्तर में वे फर्ग्युसन कालेज में शिक्षक नियुक्त हुए। वहाँ इनका सम्पर्क जोहन्मान्य वान गगाधर तिलक के साथ हुआ, जिन्हें गोखले बड़े सम्मान की दृष्टि में देखते थे। परन्तु दोनों के विचारों में साम्य नहीं था। गोखले के भावी जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बात उनका रानाडे के साथ सम्पर्क होना था। गोखले रानाडे को आजन्म अपना गुरु मानते रहे। उन्हीं के साथ गोखले ने राजनीतिक एवं नावजनिक जीवन में कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त

किया। रानाडे ने उह पूना की सावजनिक सभा का सचिव बनाया। उस सभा का कार्य सावजनिक समस्याओं का अध्ययन करके उनके सम्बन्ध में स्मरण पत्र बनाकर सरकार के पास भेजना था। साथ ही ग्रामिण शिक्षा समाज के नायक-नायिका का सम्पादन करना भी गायन का दायित्व था। जून अन्तर्गत शिक्षा समस्याओं की सेवा करने का दायित्व भी गायन ने अपनाया था। इन सब कार्यों के परिणामस्वरूप गायन का परिचय जनमाधारण के साथ एक सुधारक के रूप में बहुत अधिक हो गया। उस जीव गायन पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भी अपने विचारों को प्रकाशित कराने लगा। उस समय राष्ट्रीय नृत्तत्व में उग्र तथा उत्तार पथी दो वर्ग हो गए थे। रानाडे के निष्पत्ति के कारण गायन उत्तारपथी वर्ग का नृत्तत्व करते रहे।

सावजनिक जीवन—गायन के सावजनिक जीवन के कार्यों का कइ भाग में विभक्त किया जा सकता है यथा राष्ट्रीय कार्य में एक नेता के रूप में भारत सरकार सर्वोच्च परिषद् के सदस्य के रूप में भारत की समस्याओं के सम्बन्ध में जनरल दार एन्गलैंड से की गयी यात्राओं के रूप में तथा समाज-सुधार सम्बन्धी कार्यों के रूप में उनके द्वारा की गयी राष्ट्रीय सेवाएँ।

यद्यपि गायन काग्रस 1889 में प्रारम्भ हुआ था तथापि काग्रस में उनका सक्रिय भाग 1901 में प्रारम्भ हुआ जबकि उह बम्बई प्रांतीय काग्रस का सचिव बनाया गया। 1903 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रस में मंत्री हुए। 1905 में उह काग्रस का अध्यक्ष चुना गया। काग्रस के इतिहास में यह युग सङ्गत का वन था क्योंकि उस समय काग्रस में उत्तार तथा उग्रपथी नेता स्पष्ट दो वर्गों में विभाजित होन लगे थे। 1906 में किसी तरह के विभाजन का टान दिया गया था जबकि वयावृद्ध नेता नौगजी का अध्यक्ष चुना गया। परन्तु 1907 में जब निरंक साजपतराय तथा रिपिन चन्द्र पाठ जा कि उग्रपथी नेता थे काग्रस में जलन हो गई तो गायन को बलुन टुल हुआ। यद्यपि वे आजम उत्तारवानी नेता बने रहे तथापि उहान दाना गुण में एकता पान का निरन्तर प्रयास किया। 1914 में एनी बमर के काग्रस में प्रवेश करने पर उनके सन्धान से गायन ने दाना गुण के मध्य एतना पान का असफल प्रयास किया। यद्यपि उनके जीवन रहते हुए यह बात न हो सकी तथापि 1916 में उनकी मृत्यु के अगले तीन वर्ष तखनऊ काग्रस अधिवेशन में उन काग्रस एक हो गयी। 1905 में उगान विभाजन के परिणामस्वरूप भारत में अग्रजी शासन नाति तथा विपक्ष रूप में तत्कालीन वात्सराय नाट कजन के दमनचक्र के विरुद्ध लश में काफी असन्तोष फैल गया था। यद्यपि गायन के विचार प्रारम्भ के उन राष्ट्रीय नेताओं से मिलते जुलते थे जो ब्रिटिश शासन के प्रतिक के और उस भारत के लिए बरतान मानते थे साथ ही राष्ट्रीय मागा के सम्बन्ध में प्राथमता पना जावदना तथा प्रत्यावदना की नीति अपनाते थे तथापि 1905 में काग्रस के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए गायन ने दाड कजन की शासन नीति की कट आलोचना की। साथ ही उहान तत्कालीन काग्रस के स्वन्धी जागानन का समर्थन भी किया भन ही वे बहिष्कार नीति का विरोध करते रहे।

गायन एक अद्भुत प्रतिभा वान जयवास्त्री थे। उनकी सावजनिक सेवाओं ने उह इतना प्रसिद्ध बना दिया था कि वे बम्बई प्रांतीय धारा-सभा के सदस्य निर्वाचित हो गये। 1902 में उह वात्सराय की सर्वोच्च विधान परिषद् का सदस्य भी निर्विरोध चुन दिया गया। इन विधान परिषद् में गायन के भाषण अत्यधिक प्रभावशाली होते थे। यद्यपि उनके अवसरा पर इन विधानसभाओं में सरकारी सदस्या का बहुमत होने के कारण सरकार मनचाह कानून पास करा ली थी तथापि गायन के वचनिक तर्कों द्वारा यत्त विरोधा की उपक्षा करने का पूरा साहस सरकार को नहा होता था। एक प्रकाण्ड जयशास्त्र नाता तथा वित्तीय मामलों का विवेचन होने के नाते सरकार के बजट पर गायन के जानाचनात्मक भाषण अत्यन्त प्रभावशाली हुआ करते थे। बहुधा उनके सुभावा का सरकारी पक्ष भी मानने को तयार हो जाता था। गायन ने दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत अग्रजी का आर्थिक नीति का बुरावना को विधान-परिषद् के बजट अधिवेशन में दास सुभावा का खनन टुल यत्त किया। नाट कजन के शासन काल में जिन प्रतिगामी कानूनों,

के विधेयक विधानसभा में रखे गये थे (यथा, भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक, प्रेस विधेयक, प्रशासकीय गोपनीय तथ्य विधेयक, आदि) इनका गोखले ने तीव्र विरोध किया। इस प्रकार विधान-परिषद् में रहते हुये गोखले निरन्तर राष्ट्र की सेवा करते रहे।

जब दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैण्ड तथा भारत के मध्य वित्तीय सम्बन्धों के बारे में ब्रिटिश शासन की शोषण नीति का तथ्यो द्वारा तीव्र विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त सेलवाड आयोग के समक्ष साक्ष्य देने हेतु दक्षिण सभा ने गोखले को इंग्लैण्ड भेजा। वहाँ गोखले ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह सिद्ध किया कि भारत सदृश गरीब देश को अत्यधिक कर-भार सहन करना पड़ रहा है और भारत सरकार का सैनिक व्यय ससार के महानतम देशों की अपेक्षा उच्चतर है। उन्होंने भारत में सिविल सेवा के भारतीयकरण के भी मुभाव रखे। दूसरी बार गोखले 1905 में कांग्रेस द्वारा भेजे गये शिष्ट-मण्डल के साथ इंग्लैण्ड गये। वहाँ उन्होंने अनेक सभाओं में भाषण दिये और उदारपथी भारतीय नेताओं की नीति के अनुरूप अपीलों द्वारा भारत की मांगों के प्रति ब्रिटिश जनता तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इन माँगों में भारतीय विधान-परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या तथा परिषदों के अधिकारों के विस्तार, इंग्लैण्ड की कामन सभा में भारतीय सदस्यों के निर्वाचन, इंग्लैण्ड में भारत मन्त्री की परिषद् में भारतीयों की संख्या में वृद्धि आदि शामिल थी। गोखले ने भारतवासियों के लिए और अधिक स्वायत्त शासन के अधिकारों की मांगें रखी। पुन 1906 में वे इंग्लैण्ड गये। उस समय वे भारत-मन्त्री मार्ले से मिले, जो भारत में शासन-सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों का मसविदा तैयार कर रहे थे। उन्होंने मिस्टर मार्ले को भारतीय राष्ट्रीय माँगों से भली-भाँति अवगत कराया, परन्तु जब वर्ग-विच्छेद के परिणामस्वरूप भारत में उग्रवादी राष्ट्रीयता ने जोर पकड़ा और लाजपतराय तथा वाद में लोकमान्य तिलक को बन्दी कर लिया गया, तो गोखले को यह दुःख हुआ कि कि कहीं ब्रिटिश सरकार क्रुद्ध होकर जो कुछ देना चाहती थी, उसे भी देने से इनकार न कर दे। अत 1908 में वे पुन इंग्लैण्ड गये। उन्होंने तिलक को मुक्त कराने का भरसक प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में भी यह सब गोखले के प्रयासों का ही फल था कि ब्रिटिश सरकार ने 1909 का शासन सुधार कानून पास किया। गोखले की नीति सदैव ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही के साथ सहयोग करने व अपील तथा आवेदनो द्वारा राष्ट्रीय माँगों को रखने की रही। ब्रिटिश शासक भी गोखले की माँगों का आदर करते थे, परन्तु अपनी शासन नीति के कुचक्रों में फँसे अधिकारी इन माँगों को पूर्ण करने में उदासीन रहते थे। गोखले का विचार था कि तत्कालीन परिस्थितियों में वैधानिक तरीका ही उपयुक्त था, न कि हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा भारत की माँगों को पूर्ण कराने का। अत भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध के बावजूद गोखले इन माँगों को रखने के लिए इंग्लैण्ड भागते रहते थे। उन्होंने छ सात बार ऐसी यात्राएँ की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सी० आई० ई० की उपाधि भी दी। भारतीय सिविल सेवाओं के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा निमित्त (1912) इस्लिंग्टन आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस कमीशन के समक्ष उन्होंने यथार्थवादी सुझाव कमीशन को दिये। गोखले ने इन सब सुविधाओं को इसीलिए स्वीकार किया कि वे इनके माध्यम से भारत की राष्ट्रीय माँगों के प्रति ब्रिटिश सरकार को और अधिक सजग रख सकें, इसलिए नहीं कि वे अवसरवादी थे, या निजी स्वार्थ-साधन से प्रेरित होकर ऐसी नाति अपनाते थे।

जब दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की सरकार के भारतीयों के प्रति रंग-भेद के अत्याचारों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आन्दोलन छेड़ा, तो गोखले ने गांधी जी को भरपूर सहयोग दिया और अपने अचूक प्रयत्नों से भारतीयों पर लगाये गये पॉल टैक्स तथा सविदावद्ध श्रम के कानूनों को समाप्त करवाने में सफलता प्राप्त की। गोखले ने 1905 में भारत सेवक संघ की स्थापना करके भारत के युवा वर्ग में मार्गजनिक सेवा की भावना उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। स्वयं गांधी जी को भी उन्होंने इनका नमूना बनाया। संघ के मुख्य उद्देश्य जनता में देश-प्रेम तथा नमोज-सेवा की भावना

को उत्पन्न करना जनता में सक्रिय राजनीतिक चेतना जागृत करना स्त्री शिक्षा नस्लिन वर्गों का उत्थान देश के औद्योगिक विकास में सहायता देना आदि थे।

गांधी के राजनैतिक विचारों का आधार उनकी व्यक्तिगत भावनाएँ, रानाडे का शिष्यत्व तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ व अतःगत उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाता था। राष्ट्रीय नेताओं—तीराजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, पीराजशाह महता आदि उत्तरवाणियों की भाँति गोखले ने भी शान्तिपूर्ण साधना द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद का विकसित करने का प्रयास किया। वे ब्रिटिश शासन का भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के निमित्त बरदान मानते थे और ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही के साथ सहयोग करके राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन को बढ़ाना चाहते थे। हिंसात्मक तथा असावधानीपूर्ण साधना में उनका विश्वास नहीं था न वे ब्रिटिश सरकार के भाग में राडा अटवान की नीति को उपयुक्त समझते थे। इस प्रकार उन्होंने राजनीति का आदर्शिकरण करने की नीति अपनायी। जब मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विकास होने लगा तो गोखले ने इस भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के निमित्त एक अभिग्राह्य समझा और मदद हिन्दू मुस्लिम एकता तथा कांग्रेस में फूट हान पर दाना गुटों में एकता लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनका विचार था कि जब तक समाज में अतर्निहित बुराईयाँ का दूर करके उसमें सुधार नहीं लाया जायगा और जब तक भारत वासियों में शान्ति, शान्ति राजनीतिक चेतना की अभिवृद्धि नहीं हो पायेगी तब तक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा। अतः गोखले शासन तथा समाज में क्रमिक सुधार के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन नून हृदयहीन नहीं है कि वे भारतवासियों को स्वायत्त शासन के लिए सक्षम देखने पर उन्हें स्वायत्त शासन के अधिकार नहीं देंगे। उनके राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक ढंग के स्वराज्य की प्राप्ति करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु गोखले भारत के शिक्षित वर्ग को कार्यशील रखना चाहते थे। साथ ही भारत में सर्व-समर्थ द्वारा वे जनता की राष्ट्रीय चेतना का विकसित करने का उद्देश्य भी रखते थे।

यद्यपि गोखले का कार्य-भार सावधानीपूर्ण साधना, शिक्षित वर्ग तथा परिपक्व तक ही सीमित रहा और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को भारत की आम जनता का आन्दोलन बनाने का कभी स्वप्न नहीं देखा तथापि यह कहना भूल हागी कि गोखले जनसाधारण के प्रति उदासीन थे। बन्तुत आम जनता के कष्टों के प्रति उनके हृदय में जगाध सहानुभूति थी। उनका एक प्रेम अनन्य था। देश की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जीवन भर उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया कि उसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ा और 1915 में 49 वर्ष की आयु में ही उनका देहावसान हो गया। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में जब राष्ट्रीय चेतना में पर्याप्त वृद्धि होने लगी तो ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रीय स्वायत्त शासन की माँग के समक्ष झुकना पड़ा। 1909 तथा 1919 के शासन सुधार अधिनियमों के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने जो भी प्रस्ताव रखे उनके निमित्त उसने यदि किसी भारतीय मतदाता की माँग सुनी तो यह गांधी के ही विचार थे। भले ही स्वेच्छा धारी साम्राज्यवादियों ने उन्हें पूर्णतया स्वीकार नहीं किया तथापि यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासक गोखले के परामर्श पर सर्वाधिक विश्वास रखते थे।

राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् भी भारत का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भारत हिंसात्मक क्रान्ति के मार्गों का अनुसरण करके अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकता था। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समय-समय पर भारत में ऐसी महान् विभूतियाँ न जन्म लीं हैं जिनकी राष्ट्रीय सेवाएँ तथा बलिदान उच्च कीर्ति के थे और जिन्होंने शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक तरीकों में विश्वास न रखकर उग्रवादी मार्ग को अपनाया। तिलक, राजपतराय, त्रिपुनित, पाल, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, मानवेन्द्रनाथ राय आदि ऐसे विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। आज भी देश के मतदाता में अनेक उग्रपथी हैं। परन्तु हम यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत अपने उग्रवादी तरीकों से अपने उद्देश्य पूर्ण करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। गोखले के बाद गांधी जी ने उनकी नीतियों का अनुसरण किया और देश को विदेशी शासन से

मुक्त कराने का श्रेय प्राप्त किया। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। स्वतन्त्रता के पूर्व तथा पश्चात् भी देश का नेतृत्व जिन विभूतियों ने सफलतापूर्वक किया है, उन्हें हम गोखले का ही शिष्य मान सकते हैं। संक्षेप में, हमें यह मानना पड़ेगा कि गोखले ने अपने युग के साथ बढ़ते हुए अपने समय की परिस्थितियों को पहचाना और राष्ट्रीय आन्दोलन को वह रूप दिया जो उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम था। साथ ही उन्होंने भविष्य के नेतृत्व को भी यह शिक्षा दी कि भारत का राजनीतिक हित शान्तिपूर्ण तरीके से राजनीति का संचालन करने में है। इस दृष्टि से गोखले देश के युग-युग के नेता सिद्ध होते हैं। क्रान्तिकारिता का जोश क्षणिक सफलता दे सकता है और अत्याचारी शासन के विरुद्ध जन-मानस को किंचित सान्त्वना देने में अच्छा प्रतीत हो सकता है, किन्तु शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक क्रान्ति में स्थायित्व होता है यह बात हमें गोखले के विचारों तथा सेवाओं से स्पष्ट होती है।

(च) फीरोजशाह मेहता (1845-1915)

कांग्रेस के संस्थापकों में सर फीरोजशाह मेहता का नाम भी प्रमुख व्यक्तियों में से है। इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी, जहाँ वे दादाभाई नौरोजी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए थे। साथ ही उनके ऊपर रानाडे के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। मेहता का सार्वजनिक जीवन बम्बई कारपोरेशन की सदस्यता तथा अध्यक्षता एवं बम्बई विधान-परिषद् की सदस्यता से अधिक सम्बद्ध रहा है। वे 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे। उसके पश्चात् कांग्रेस संगठन में वे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे। यद्यपि 1910 में भी उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था, तथापि पद-ग्रहण से पूर्व ही कुछ कारणवश वे इसे स्वीकार नहीं कर सके।

मेहता कांग्रेस के उदारवादी गुट के एक प्रमुख नेता थे। परन्तु 1907 में कांग्रेस विभाजन में गोखले की भाँति उन्हें भी बहुत दुःख हुआ और वे भी गोखले की भाँति ही निरन्तर एकता का प्रयास करते रहे। कांग्रेस के कार्य-कलापों में मेहता ने दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का समर्थन करके देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ब्रिटिश शासन के समक्ष भारत के पक्ष को रखा। वह एक सुयोग्य दार्शनिक चिन्तक भी थे। उन्होंने पाश्चात्य देशों के अनेक विद्वानों, यथा ग्रीन, कोल्टेयर, मिल आदि के विचारों का अध्ययन किया था। वे इस तथ्य को नहीं मानते थे कि 'इतिहास की स्वयं पुनरावृत्ति' होती है, उनका तो विश्वास था कि हर युग तथा हर देश में प्रगति के विकास का क्रम तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदारवादियों की भाँति मेहता भी देश के क्रमिक राजनीतिक उत्थान पर विश्वास रखते थे। उन्हें पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति की महानता पर अधिक विश्वास था। वे अंग्रेजों की भारतीय शासन नीति का विरोध अपने वैचारिक तर्कों के द्वारा करते थे। उनके मत से ब्रिटेन शक्ति के बल पर भारत में अपनी सत्ता को बनाये रखने में सफल नहीं होगा। ब्रिटिश शासकों की स्वेच्छाचारिता अंग्रेज जाति के चरित्र के प्रतिकूल है। शक्ति पर आधारित राजनीति के संचालन से ब्रिटेन को बहुत सेना संचय करना पड़ेगा जो भारतवासियों पर कर-भार बढ़ायेगा। फिर भी वे ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखने की बात करते थे। वे भारतीयों के स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकार तथा शिक्षा में प्रगति के कट्टर हिमायती थे। परन्तु यह एक आश्चर्य की बात थी कि वे भारत में संस्कृति की शिक्षा को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते थे। मेहता ने अनेक समितियों तथा शिष्ट-मण्डलों में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया। वे व्यवहारवादी थे, न कि कोरे सिद्धान्तवादी। परन्तु भारत में उग्रवाद के विकास के साथ मेहता के विचारों का महत्व भी कम होता गया। फिर भी वे आजन्म कांग्रेस के उदार तथा सच्चे मेवक बने रहे और उदारवादियों की भाँति ब्रिटिश शासन की ईमानदारी पर निष्ठा रखते हुए उसके समक्ष भारत की स्वायत्तता की अविकावधिक माँगों को रखते रहे।

(छ) अन्य प्रारम्भिक नेता

ए० ओ० ह्यूम (1829-1912)—ए० ओ० ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो भारत

सरकार की सेवा में एक दृष्टियन्त मित्रित मकर थ। अपन सेवा-काल में उन्होंने जन शिवा पुत्रिस में सुधार मध्य निषध बनाकर प्रमत्त निगोर अपगधी-सुधार तथा अन्य घरतु आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रयत्न किया। सेवा में जबतक प्राप्त करने पर (1882) उनकी अभिरुचि भारत के सामाजिक जीवन में दृष्टि गयी। भारत में किसिम राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत के सही जनमत का जानने के लिए भारत के विभिन्न भागों के राजनवाशाओं का प्रतिवर्ष एक सभा के रूप में एक साथ सम्मिलित होना का अवसर मिलना चाहिए। यह बताने मात्र एक सामाजिक या धार्मिक सभा ही नहीं है। अपितु राजनीतिक भी है। उन्होंने अपने इस विचार का तत्कालीन वामराय नाथ डफरिन के समक्ष रखा जिसने उनके प्रस्ताव का न बताने स्वागत ही किया कि उन्हें प्रस्ताव भी दिया। ह्य में साहज्य इस सभा के राजनीतिक स्वरूप को सीमित रखना चाहते थे परन्तु नाथ डफरिन का विचार था कि वह सभा 'इंग्लैंड' की सभा के विरोधी दल की भाँति गृह्य से शासन की आलोचना का कार्य कर ता जायदा होगा। उसने उससे ह्यूम माहोन अपने इस प्रस्ताव को लेकर इंग्लैंड गये और वहाँ उन्होंने मंत्रिमण्डल में भी प्रस्ताव किया। भारत 'गोल्ड' उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख योगदान किया। इसलिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। बाद में भी वे जब तक भारत में रहे निरन्तर कांग्रेस के कार्यों में भाग लेते रहे। ए. जी. ह्यूम के साथ-साथ सर विनियम वेल्शलेन का नाम भी देना आवश्यक है। वह कांग्रेस के दो अधिवक्ता (1886 तथा 1910) में अध्यक्ष रहे।

ओमेश चन्द्र बनर्जी—ह्यूम की भाँति ओमेश चन्द्र बनर्जी का नाम भी कांग्रेस के आदि स्थापका की श्रेणी में आता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम (1885) तथा आठवें (1892) अधिवक्ता में अध्यक्षता की थी। उनके प्रथम अध्यक्ष पद के भाषण में कांग्रेस के उद्देश्यों की घोषणा की गयी थी। बनर्जी के मत से कांग्रेस को सामाजिक समस्याओं में उतना ही उलझना चाहिए जितना राजनीतिक मामलों में। वे अंग्रेजों को इस धारणा के विरोधी थे कि कांग्रेस की जावान भारत की जनता की आवाज नहीं है। वे स निराग यूरोपीय भाषा की या थोड़े से भारतीय बुद्धिजीवियों की आवाज है। वे 1890 में एक दिग्विस्तृत मण्डल के साथ इंग्लैंड भी गये। उन्होंने भारत की 'याय' पद्धति में 'यूरो प्रथा' का लागू करने के सम्बन्ध में जोरदार तर्क दिये। उनका मत था कि यूरोपीय 'याय' की जा भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं रखते 'याय' प्रक्रिया में वाणी प्रतिभा या साक्षी के बतौर का विदेशी भाषा में अनुवाद करके विवाद के सम्बन्ध में सही तथ्यों का पता नहीं लगा सकते। अतः 'यूरो प्रथा' आवश्यक है।

दीनशा वाचा—कांग्रेस के प्राग्भिक वर्षों से ही दीनशा वाचा का सम्पर्क कांग्रेस से रहा और उन्होंने कांग्रेस के अधिवक्ता में ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति अपनायी जाने वाली अनुचित नीतियों का तथ्यों के आधार पर विरोध किया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सन्निक नीतियों का विरोध किया था। द्वितीय अधिवेशन में उन्होंने भारत की आर्थिक हीनता के सम्बन्ध में तथ्यों का दस्त यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस प्रकार अंग्रेज 'नाग' इंग्लैंड का धनी बनाने तथा भारत का आर्थिक शोषण करने में लगे हैं। गोलन की भाँति दीनशा वाचा भी वित्तीय मामलों में विशेष दक्षता रखते थे और उन्होंने सरकार की वित्तीय नीतियों का तीव्र विरोध करते हुए कांग्रेस के अधिवक्ता में विविध प्रस्ताव रखे। 1901 में उन्होंने कांग्रेस अधिवक्ता की अध्यक्षता की। उसमें पचास भी वह कांग्रेस के महामंत्री या अध्यक्ष महत्वपूर्ण पद पर बने रहे। वे ब्रिटिश सरकार की अवाञ्छनीय शासन नीतियों विशेष रूप से आर्थिक नीतियों के कट्टर आलोचक थे। पट्टाभि सीतारामय्य के शासन में दीनशा वाचा का समता रखने वाले तो नाथ थोड़े से व्यक्ति रहे हाँ परन्तु उनसे अष्टनर को भी नहीं था। उनके ब्रिटिश शासन विरोधी शासन के आधार पर उन्हें उदारवादी नेताओं की श्रेणी प्राप्त नहीं होनी। परन्तु सीतारामय्य के शासन में यह भी आश्चर्य की बात है कि एक युग का उग्रवादी दूसरे युग का उदारवादी बन

गया। उन्हें बाद में नाइट की उपाधि दी गयी और केन्द्रीय विधान-परिषद् का सदस्य बनाया गया।

उपर्युक्त विभूतियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक नेताओं में सुब्रह्मण्य अय्यर, वदरुददीन तैयबजी आदि का नाम भी उल्लेखनीय है। इसी अवधि में कांग्रेस के नेताओं के मध्य ऐसी विभूतियाँ भी प्रविष्ट हुईं जो प्रार्थना, आवेदनो तथा प्रत्यावेदनो द्वारा सरकार के समक्ष राष्ट्रीय माँगों को प्रस्तुत करने की नीतियों पर विश्वास नहीं रखती थी, अपितु उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन विरोधी था। प्रारम्भ में इनकी आवाज दबी रही, परन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में गतिविधियाँ तीव्र हो गयीं और उनका उद्देश्य तथा उनके साधन उग्र प्रकृति के हो गये। अगले अध्याय में हम उग्रवादी आन्दोलन का विवेचन करते हुए इन उग्रवादी नेताओं का परिचय देंगे।

उदारवादी राष्ट्रीयता का मूल्यांकन

विगत पृष्ठों में दिया गया विवरण ही वास्तव में उदारवादी राष्ट्रीयता के मूल्यांकन की विषय-वस्तु है। अतएव यहाँ पर केवल संक्षेप में कुछ बातों का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के अभ्युदय में मुख्यतया समाज तथा धर्म सुधार आन्दोलनों का प्रभाव था। इन सुधारकों में से अधिकांश नेता पश्चात्य शिक्षा, संस्थाओं एवं साहित्य और दर्शन से प्रभावित थे। उस युग में इंग्लैण्ड में भी उदारवादी विचारधारा बढ रही थी जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र के निमित्त वैधानिकतावाद पर विश्वास रखती थी। भारत का तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग इन विचारों से प्रभावित हुआ और इसी बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व रहा। ये लोग ब्रिटिश शासन पद्धति तथा अंग्रेज जाति के लोकतन्त्र प्रेम एवं न्याय भावना से प्रभावित होने के कारण ब्रिटिश सरकार की सदस्यता पर विश्वास रखते थे। इसलिए इन्होंने उसके साथ सहयोग की नीति अपनाकर भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की माँग रखना उपादेय समझा। विद्रोह तथा क्रान्ति द्वारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की उपलब्धि के लिए न तो देश तैयार था, न ऐसा संगठन सम्भव था। सुदृढ ब्रिटिश शासन ऐसे विद्रोह को शीघ्र ही दमनकारी साधनों से कुचल देता। अतः उदारवादी नेता समय के साथ चले और उन्होंने यथार्थवादी रुख अपनाकर राष्ट्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने की नीति अपनायी। इसके निमित्त उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करवाने, शिक्षा प्रसार एवं शान्ति शान्ति भारतीयों के शासन में अधिकाधिक भाग को सुनिश्चित कराने की माँगें रखना ठीक समझा। यदि ब्रिटिश शासन इन देशभक्त तथा राष्ट्र-प्रेमी नेताओं के उद्देश्यों को ईमानदारी की भावना से समझते तो उग्रवादी या क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता के अभ्युदय की समस्या ही नहीं आती। इस दृष्टि में उदारवादी राष्ट्रीयता ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की, और देश को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए माँग करने, आन्दोलन करने तथा संघर्ष करने के लिए शिक्षित किया।

प्रश्न

- 1 राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक क्यों कहा जाता है ?
- 2 राष्ट्रीय जागरण में स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगदान पर प्रकाश डालिए।
- 3 निम्न नेताओं के राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए—
(क) दादाभाई नौरोजी,
(ख) महादेव गाँधी रानाडे,
(ग) गोपाल कृष्ण गोखले।

उग्र राष्ट्रीयता का अभ्युदय (NATIONALISM THE EXTREMIST PHASE)

उग्र राष्ट्रीयता का ग्रन्थ ✓

यद्यपि भारत में राष्ट्रीयता के अभ्युदय का एक प्रमुख कारण देश में विदेशी राजनीतिक सत्ता का शोषणकारी तथा स्व-आचारी होना था तथापि प्रारम्भिक युग के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्पष्टतया विदेशी शासन का समाप्त करना नहीं था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नृत्व करने वाली विभूतियाँ में अंग्रेजी शासन के प्रति पूर्ण निष्ठा तथा विश्वास की भावना प्रती रही। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए बरतान सिद्ध हुआ है। वे नती भारत में पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता तथा राजनीतिक संस्थाओं के प्रचलन को भारतवासियों के हित की वस्तु मानते थे। साथ ही उन्हें अग्रज जाति के राजनीतिक आचरण तथा चरित्र में पूर्ण विश्वास था। यद्यपि प्रारम्भिक राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन तथा नौकरशाही के अवांछनीय कार्य-नापा तथा नीतियों की आलोचना भी की तथापि उनका विश्वास था कि अग्रज हृदयहान नहीं हैं। उनके ममक्ष यदि भारत की परिस्थितियों मांगा तथा कठिनाइयों को दूर से रखा जाय तो वे अपनी शासन-नीति में सुधार करके क्रमशः भारतीय राष्ट्रीय मांगों को स्वीकार करग और नती भारतवासियों का शासन में अधिकारिक भाग लेने का अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार का दान्तर से भारत में स्वायत्त शासन लागू हो जायेगा। परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस के अभ्युदय के पश्चात् के 15 वर्षों की अवधि में इस निष्ठा में काफी प्रगति नहीं आई। प्रत्युत ब्रिटिश सरकार का खयाल प्रतिक्रियावादी मिथ्य हाने लगा। 1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम के अंतर्गत भी बहुत रखाई दर्शाई गयी। नौकरशाही का व्यवहार भी प्रतिक्रियावादी होना लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व के अंतर्गत नयी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने लगी। युवा पीढ़ी के अनेक नेता कांग्रेस की आवेष्टता तथा प्रार्थनाओं में विश्वास करने की नाति का विरोध करने लगे। उन्हें यह विश्वास नहीं रहा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का स्थिति में सुधार हो सकेगा। अतः इनका उद्देश्य पहले स्वराज प्राप्त करना था जिससे बाद में भारतीय स्वयं अपनी समस्याएँ हल कर सकें। इन लोगों ने ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग तथा सहकारिता की नाति का विरोध किया और शासन के अयोग्यपूर्ण कृत्यों की अवता तथा बहिष्कार की नीति का समर्थन किया। यद्यपि इन लोगों ने हिंसात्मक साधना का नहीं अपनाया तथापि विरोध तथा असहयोग की नाति अवनताना तथा देशवासियों में स्वदेशी सभ्यता के प्रति प्रेम विगुद्ध भारतीय राष्ट्र भावना देश भक्ति तथा देश-सेवा का भावना को भरना और राष्ट्र के प्रति कष्ट सहने का आह्वान करना इनका उद्देश्य था। इनके कार्य-नापा नीतियाँ तथा गतिविधियाँ ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उस नयी प्रवृत्ति को जन्म दिया उग्र उग्रवाद (extremism) या उग्र राष्ट्रीयता का नाम दिया जाता है।

उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण

जिन आगाओं तथा विश्वासों का लेकर कांग्रेस का जन्म हुआ था और जिन साधनों के द्वारा कांग्रेस संगठन के प्रारम्भिक नेता राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन कर रहे थे उनके प्रति

ब्रिटिश शासन का रवैया न केवल उदासीनतापूर्ण ही रहा अपितु प्रतिगामी भी होने लगा। राष्ट्रीय चेतना को दबाना तथा शासन-नीतियों में और अधिक कठोरता तथा स्वेच्छाचारिता लाना ब्रिटिश शासकों की नीति का अंग होता गया। परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएँ तथा परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनके कारण निम्नांकित थे—

(1) हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान—यद्यपि धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति में महान् योगदान किया था, तथापि राष्ट्रीयता के विकास में पाश्चात्य सस्कृति, शिक्षा तथा साहित्य का प्रभाव बढ़ने लगा था क्योंकि आरम्भ के कतिपय राष्ट्रीय नेता-गण पाश्चात्य सस्थाओं को अपेक्षाकृत उच्चतर समझने लगे थे। परन्तु इसी अवधि में भारत में ऐसी विभूतियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिन्दू धर्म तथा सस्कृति का अध्ययन करके उसकी श्रेष्ठता की बात का प्रचार न केवल भारत में ही अपितु पाश्चात्य देशों में भी किया। इस वर्ग के नेताओं ने आरम्भ के नेताओं की पाश्चात्य सभ्यता की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति का विरोध किया। स्वामी विवेकानन्द ने 1893 में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में हिन्दू धर्म की महानता सिद्ध करके ससार को मोहित कर लिया था। वाल गंगाधर तिलक ने अपने माडला जेल की अवधि में 'गीता रहस्य' लिखकर कर्मयोग की महानता बतायी। स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के विकास द्वारा वेदों की महत्ता को दर्शाया। विपिन चन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष ने भी हिन्दू दर्शन की महानता को दर्शाया। इन सभी नेताओं ने न केवल हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान तक ही अपने प्रचार-कार्य को सीमित रखा, अपितु उन्होंने यह प्रचार किया कि राष्ट्र का हित इसी बात पर निर्भर करता है कि वह राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो क्योंकि तभी उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्यान्य सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति सम्भव है। विदेशी शासकों के समक्ष भिक्षावृत्ति की नीति अपनाकर देश का उत्थान नहीं हो सकता। अतः किसी भी जाति का पहले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार है। इन नेताओं ने अपने युग के उदारवादी नेताओं की इस धारणा से पूर्ण असहमति व्यक्त की कि राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता की पूर्ण शर्त सामाजिक सुधार है। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि जब राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायेगा तो वह अपनी इच्छानुसार वांछित दिशा में समाज सुधार के कार्यों को अधिक उत्तम ढंग से कर सकेगा। विदेशी शासकों से धार्मिक या सामाजिक सुधारों की मांग करना हास्यास्पद है।

(2) राष्ट्रीय मांगों के प्रति शासन की रुखाई—यद्यपि आरम्भ के कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रीय असन्तोष के निराकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना तथा आवेदनो की नीति अपनायी थी और ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा तथा विश्वास व्यक्त किया था, तथापि ब्रिटिश शासन तथा नौकरशाही ने इन मांगों के सम्बन्ध में प्रतिगामी नीतियाँ अपनायीं। कांग्रेस के जन्म के 7 वर्ष बाद 1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम ने भारतवासियों को शासन में भाग लेने का कोई भी वांछित अवसर नहीं दिया। यहाँ तक कि उदारवादी नेता भी ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीति से असन्तुष्ट हो गये थे, और वैधानिक साधनों से अपनी मांगें मनवाने के तरीके पर से उनका विश्वास हटने लगा था। ब्रिटिश नौकरशाही ने दमन की नीति अपनाना शुरू किया। 1897 में तिलक को राजद्रोह के अपराध में जेल का दण्ड दिया गया। उन्हें प्रिवी कोसिल में जपील करने की आज्ञा तक नहीं दी गयी। तिलक का केवल यही अपराध था कि उन्होंने बम्बई में प्लेग फैलने पर उसे रोकने में सरकार की दुर्गुण नीति के विरुद्ध 'केसरी' पत्रिका में लेख लिखा था। ब्रिटिश नौकरशाही की दमनकारी नीतियाँ सर्वत्र फैल रही थी, अतः भारतीय नेताओं में असन्तोष बढ़ता गया और उनके आन्दोलन में उग्रता की मात्रा बढ़ती गयी।

(3) प्लेग तथा अकाल फैलना—1896-97 में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल फैला। उनके निवारण के सम्बन्ध में सरकार ने कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं दिखायी। 1899-1900 में

वर्षों की कमी के कारण पुनः अकान पना। सरकार ने हम बार भी वहाँ रखा अपनाया। भारतीय जनता का अब यह प्रतीति हो गयी कि ब्रिटिश शासक अनावश्यक कार्यों में अत्यधिक व्यय करते हैं परन्तु अनहित के आवश्यक कार्यों का उपक्षित रहते हैं। यदि अपनी सरकार हानी तो वह हम सत्ता का सामना स्वयं अधिक कुशलता से कर लेती। अतएव भारत का विन्मो गामन में मुक्त कराना भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ अकान में नागा व्यक्ति पीड़ित थे अथवा कानग्रस्त हो चुके थे वहाँ हमी अवधि में पूना में भयंकर पंग फन गया। उसमें नागा व्यक्ति मर गये। यद्यपि सरकार ने इसकी राक्षसता के लिए भरन प्रयत्न किया तथापि प्यंग जायुक्त मिस्टर रड के तीरतरीका से जनता में भारी असन्तोष पन गया। उसके प्तु मन्त्रि दम्ता की मन्द में वामारा का उनके घरा में जाकर निकलवाया गया। उस समय में बहुत घमपयिया का असन्तोष हुआ। किसी युवक ने मिस्टर रड तथा उसके साथियों की हत्या तन कर डाली। फन उस फासी का लण लिया गया। सरकार के गनन रखे का प्रकाशित करने के अपराध में तिनके को जेल की सजा दी गयी। इस सबका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय असन्तोष और अधिक उग्र होना गया क्योंकि तिनके की लोकमायता बहुत बर चुनी थी।

(4) लाड कजन की डमन नीति— ब्रिटिश शासन के रखे के विरुद्ध भारत में असन्तोष बढ़ता जा रहा था। एम समय (1898-1905) में नाग कजन का भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। वह एक कुशल प्रशासक अवश्य था परन्तु जन हित का उपक्षित रहने वाला कुशल प्रशासन उत्तम शासन नहीं हो सकता। कजन भारतीयों से घणा करता था वह उन्हें किसी भी रूप में स्वशासन के योग्य नहीं समझता था। उसने धापणा की थी भारतवासी एक जनसमूह नहीं हैं न उनकी एक भाषा है न एक जाति न एक धर्म वे एक महाद्वीप या एक साम्राज्य तक नहीं है एक विन्वता दूर रहा। साथ ही वह यूरोपीय नागों का भारतवासियों से हट्ट दृष्टि में उच्च मानता था। हम आधार पर उसने ब्रिटेन के भारत के ऊपर शासन करने के औचित्य का ल्पि। अपने शासनकाल में उसने अनन्य एम कारनाम किये कि कोई भी स्वाभिमान की देभक्त महन नहीं कर सकता। उनमें से प्रथम था कनकता कापिंग्टन एक्ट 1899 जिसके अनुसार कलकत्ता निगम के सन्स्या की मग्या 50 में घटाकर 25 कर दी गयी। इसका उद्देश्य भारतवासियों के स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकार का कम करना था। वहना यह जनाया गया कि अधिन सदस्या के होने में कवन वाद विवात्त में समय नष्ट होना है और कुशलता नहीं रहती। दूसरा काय था भारतीय विन्वविद्यालय अधिनियम 1904 जिसके अनुसार भारतीय विन्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम करके उनके ऊपर सरकारी नियन्त्रण की मात्रा बढ़ा दी गयी। तथाकथित सुधार याजना विन्वविद्यालय में अध्ययन तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार का थी परन्तु उसके नाम पर विन्वविद्यालयों के ऊपर कर्तीय सरकार तथा शिक्षा सचिव के नियन्त्रण बढ़ा दिया गया। भारतीय शिक्षा ने कजन के भारतीयों के प्रति घणित विचारों का प्रतिरोध किया तो उसने भारतीय गिनिन वग को और अधिक असम्मानजनक उत्तर दिया। उसने स्पष्टतः कहा कि मेरा विश्वास है कि काग्रम अपने पनन की आर जा रही है और मेरी भी आकाशा यही है कि मैं काग्रम की गतिपूण मत्यु के निमित्त सहायता दे सकूँ। नामरा कानून सरकारी गोपनीय विषया सम्बन्धी कानून 1904 (Official Secrets Act 1904) का उसके अनुसार सरकारी कमचारियों के ऊपर सरकारी काय-कनापा को गोपनीय रहने के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया और समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को भी मर्यान्त कर दिया गया। उन्हें सरकार की नानिया तथा काय-कनापा की आनाचना करने या उन्हें प्रकाशित करने की छूट नहीं दी गयी। सरकार का विरोध राजद्रोह माना गया। इसमें उपरान्त नाड

कर्जन की सीमान्त नीति तथा सैनिक अभियान, जिनके अनुसार तिब्बत, फारस की खाड़ी, चीन आदि में सैनिक दमते भेजे जाना शामिल थे, भारतीय जनमत को बहुत अनुचित प्रतीत हुए। वगान में लार्ड कार्नवालिस के द्वारा भूमि के स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था के विरुद्ध जो मत व्यक्त किया जा रहा था, कर्जन ने उसकी भी उपेक्षा की और उसमें सुधार लाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये। इससे ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीति तथा स्वेच्छाचरिता स्पष्ट हो गयी। डा० ताराचन्द के अनुसार 'कर्जन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था कुशलता उसका मौलिक मिद्धान्त था, परन्तु उसमें आचरण की अनेक कमियाँ थी। अब वह असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी, हठी, दूसरों की राय की उपेक्षा करने वाला, विरोधियों के प्रति प्रतिशोधी, आत्माभिमानी तुनुक मिजाजी आदि था। उसमें कल्पना शक्ति तथा सहानुभूति का नितान्त अभाव था, वह सूझबूझ तिरस्कार करने वाला तथा अपने अधीनस्थों तक पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति था।'¹

लार्ड कर्जन भारतीयों से घृणा करता था। वह उन्हें हर प्रकार से, हर क्षेत्र में अक्षम, अयोग्य तथा अकुशल मानता था। यह धारणा उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण में व्यक्त की थी। वह 'भारत राष्ट्र' सट्टा किसी धारणा के अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं करता था। उसकी धारणा थी कि कांग्रेस जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई वास्तविक संस्था नहीं है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी। लार्ड कर्जन द्वारा कांग्रेस की ऐसी निन्दा करने पर तत्कालीन भारतमन्त्री हैमिल्टन ने कर्जन को शावाशी दी और कहा कि यदि कांग्रेस एक या दो वर्ष में समाप्त हो जाये तो उसकी समाप्ति का पूर्ण श्रेय आपको मिलेगा।² कर्जन के विधि-मन्त्री रैले की भी यही धारणा रही थी कि कांग्रेस द्वारा अपनी महत्ता का दावा करना अयथार्थ था। वह जिस जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपने को समझती थी उसमें से 99% ने तो उसका नाम तक नहीं सुना था। लार्ड कर्जन के इन समस्त कार्यकलापों ने भारतीय शिक्षित वर्ग में भीषण असन्तोष उत्पन्न कर दिया। इसके विरोध में भारत के उग्र तत्त्वों ने ही नहीं, अपितु उदारवादियों ने भी पूरा भाग लिया। गोखले तथा लाला लाजपत राय एक शिष्ट-मण्डल लेकर इंग्लैंड गये। परन्तु वहाँ भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लाला लाजपत राय को पूरा विश्वास हो गया कि ब्रिटिश शासन-नीति के अत्याचारों से भारत को छुटकारा देने का एकमात्र साधन देश को स्वतन्त्र कराना है, तभी भारतवासी स्वयं अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भिक्षावृत्ति की उदार नीति से भारतवासियों के कष्टों तथा उनके ऊपर किये गये अपमानों का निराकरण नहीं हो सकता। भारत के सामने सबसे ज्वलन्त समस्या स्वराज्य प्राप्त करने की है।

(5) विदेशों में भारतीयों के ऊपर अत्याचार—इसी अवधि में दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले भारतीयों तथा एशियाई मूल के निवासियों के ऊपर वहाँ की गोरी सरकार की रंग-भेद की नीति जोर पकड़ रही थी। उन्हें कुछ विशेष स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता था, रेल में वे उच्च श्रेणी में नहीं बैठ सकते थे। 1907 में ट्रान्सवाल की सरकार ने एशियाई पजीयन कानून पास करके उनके कष्टों को और अधिक बढ़ाया तथा उनके ऊपर नागरिकता के लिए पजीकरण की शर्तें लगा दी। उस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में वकालत करने गये थे। उनसे यह अपमान सहा नहीं गया। उन्होंने अकेले इसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह का साधन प्रयुक्त किया। भारत में इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष इसका विरोध करने की माँग रखी गयी। परन्तु यहाँ की सरकार ने मौन धारण किया। परिणामस्वरूप भारतीय नेतागणों में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध उग्रता आ गई।

(6) वग-विच्छेद—ब्रिटिश शासन नीति के विरुद्ध असन्तोष के उपर्युक्त कारण स्वयं ही

¹ *Ibid*, 294-95

² *Ibid*, 296

किसी भीति कम महत्व के नहीं थे। गाँव वजन की नीतियाँ न उस असंतोष को और अधिक गम्भीर रूप दिला। उसके अत्याचारी कृत्यों को इतने भर में सन्तोष नहीं हुआ। उसकी सबसे महान् तथा अनिष्टकारी नीति उसके वगान विभाजन सम्बन्धी कानून से स्पष्ट हो गयी। वास्तव में वगान विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की वह नीति काय कर रही थी जो भविष्य में लगभग 50 वर्ष तक भारत में ब्रिटिश शासन का बनाया रखने में सफल हुई। यह थी मुस्लिम साम्प्रदायिकता की नीति जिसकी वतनीन अग्रजों ने भारत में अपना सिक्का मजबूत करने का सुअवसर प्राप्त किया।¹ गाँव वजन ने यह दावे का प्रयत्न किया कि प्रशासन की कुशलता तथा सुविधा के लिए वगान प्रांत का पूर्वी तथा पश्चिमी वगान नाम के दो प्रांतों में बांटना आवश्यक है क्योंकि उस समय वगान प्रांत में बिहार उन्नीसवाँ भी शामिल था। परंतु वास्तविकता यह थी कि वगान में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता का दबाव के लिए यह नीति अपनायी गयी थी। पूर्वी वगान में मुस्लिम-बहुल जनता रहती थी। उस यह आश्वासन दिया गया कि प्रांत के विभाजन से मुमकिनमान तब दूसरे सम्प्रदाय के दबाव से मुक्त रहकर अपनी समृद्धि कर सकेंगे। वग विच्छेद ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करा (Divide and Rule) की नीति का सबसे प्रथम सक्रिय कदम था।

वग विच्छेद कानून गाँव वजन के शामिल-कानून की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उसने न केवल भारत के राष्ट्रीय नतत्न को ही घार असंतुष्ट किया अपितु अनेक ब्रिटिश अधिकारी भी इससे असंतुष्ट थे। गान्धिकरण जो स्वयं वात्सराय की कार्यकारिणी का सदस्य था उसके विरुद्ध था। उसने कहा था कि सरकार का तब तक न चन मिलना और न किसी प्रकार का समझौता सफल होगा जब तक कि संयुक्त वगान के निर्माण की दिशा में कोई कदम न उठाया जाय। ब्रिटिश पक्ष ने भी वग विच्छेद योजना की आलोचना की थी। उनका मत था कि इस विभाजन के कारण वगान की जनता में भारी असंतोष फैलना स्वाभाविक है। भारत के समाचार पत्रों ने इसकी तीव्र आलोचना की। उनका मत था कि प्रांत में विभिन्न जातियाँ तथा भाषाओं की समस्या का समाधान विभाजन के अनिर्दिष्ट अथ किसी विवेकपूर्ण तथा ईमानदार तरीके से किया जाना चाहिए था। वग विच्छेद कानून के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में और बिनापक्ष में वगान के राष्ट्रीय नेताओं में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में वगान विच्छेद की घोषणा एक बम के रूप में गिरी। हम ऐसा प्रतीत हुआ कि उससे हमारा घोर अपमान किया गया है। हम ऐसा तर्क कि यह वगान की भाषी जनता की आत्मचेतना तथा एकता के ऊपर एक भीषण प्रहार था। उसका विरुद्ध प्रतिक्रिया न केवल वगान में ही हुई अपितु सारे भारत में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध फैल हुए असंतोष की अनन्त में उसने भी डालने का कार्य किया। यही तर्क कि नम दल के नेता मोरोजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी मोलने आदि भी उससे बहुत असन्तुष्ट हो गये। उसका परिणाम यह हुआ कि देशव्यापी स्वदेशी आन्दोलन छेड़ा गया। विद्वानों मान का बहिष्कार किया जाना लगा। देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में उसका कारण उग्रता का आ जाना स्वाभाविक था। वगान की युवा पक्षी के अनेक नेताओं ने तो यह प्रतिज्ञा कर ली कि वग विच्छेद का अन्त करने के लिए जो भी साधन उचित समझे जायेंगे उन्हें प्रयुक्त किया जायेगा। कांग्रेस ने मोलने को धन्यवाद भेजा ताकि वे वहाँ इसका विरोध करें, परंतु मोलने को खाली हाथ निराशा लौटना पड़ा। इससे राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्र तत्त्वा का विकास हो गया। अनेक विद्वानों की धारणा है कि कांग्रेस में उग्रवाद तथा आतंकवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण वग विच्छेद ही है। यद्यपि 1905 में किया गया यह विभाजन केवल छ वर्ष तक कार्योचित रहा और उस बीच राष्ट्रीय आन्दोलन में पर्याप्त उग्रता आ गयी थी तथापि 1911 में

¹ इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जायेगा (अध्याय 6)।

इसकी समाप्ति हो जाने पर भी उग्रवाद का अन्त नहीं हुआ। इस राष्ट्रव्यापी माँग को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार को बाध्य होना पड़ा था, परन्तु इसके पश्चात् उसने भारत में साम्प्रदायिकतावाद को और अधिक उग्र बना दिया। अतः भारतीय राष्ट्रीयता में अब आरम्भ के नेताओं की उदारवादी नीतियों पर से विश्वास हट गया।

(7) अन्य कारण—इनके अतिरिक्त अन्य कई घटनाएँ इस बीच घटी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को उग्र बनाने में योगदान किया। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एशियाई देश यूरोपीय देशों से सैनिक बल में कम नहीं हैं। इटली की अवीसीनिया से तथा रूस की जापान से हार इसके प्रमाण थे। मध्य एशिया के अनेक राष्ट्र भी राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में अग्रसर हो रहे थे। इनका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। इनसे भारतवासियों में भी आत्म-विश्वास बढ़ा और भारतीय राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए उग्र होता गया। इस दृष्टिकोण के नेताओं ने उदारवादियों की नीतियों तथा साधनों का विरोध किया। उनका विश्वास याचना, प्रार्थना तथा वैधानिकतावाद से हट गया। इन सबका परिणाम यह हुआ कि बीसवीं सदी के आरम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्रवाद की नयी प्रवृत्ति आ गई।

उग्र राष्ट्रीयता का स्वरूप

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उग्रवादी नेताओं की त्रयी में बाल, लाल, पाल (बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चन्द्र पाल) का नाम प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासकों की प्रतिगामी तथा अत्याचार-पूर्ण शासन-नीतियों के विरोध में इस वर्ग के राष्ट्रीय नेताओं का उदारवादियों की 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' तथा आवेदनो और प्रार्थनाओं द्वारा वैधानिक तरीकों से राष्ट्रीय माँगों को पूर्ण कराने की नीति पर से विश्वास हट गया। देश को आर्थिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्पीड़नों से मुक्त कराने के निमित्त उग्रवादियों ने राष्ट्रीय माँगों के सम्बन्ध में स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा इन चार सिद्धान्तों को अपना लक्ष्य बनाया। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन को अपना यह चिरस्मरणीय नारा प्रदान किया कि 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा।' उनकी यह धारणा थी कि भारत के उत्थान का एकमात्र साधन स्वराज्य की प्राप्ति है। स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर ही भारतवासी अपनी अन्य समस्याओं को हल करने में समर्थ हो सकेंगे। अतः राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य विदेशी शासन को किसी भी तरीके से निकाल बाहर करना होना चाहिए। इस साध्य की प्राप्ति के साधन स्वदेशी, बहिष्कार अथवा निष्क्रिय प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन थे। विदेशी सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय उद्योगों को घक्का पहुँच रहा था। भारतीय बाजारों में विदेशों में बनी वस्तुएँ आ रही थीं। अतः इन आन्दोलनकारियों ने स्वदेशी आन्दोलन का प्रचार किया और जनता से माँग की कि वह अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करे तथा विदेशी माल का बहिष्कार करे। साथ ही विदेशी सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्थाओं के बहिष्कार की भी माँग की गयी। इन नेताओं ने स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षालय खुलवाये और उनमें शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया।

यह आन्दोलन प्रारम्भिक उदारवादी आन्दोलन से पूर्णतया भिन्न प्रकृति का था। इसका क्षेत्र केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, अपितु इसका उद्देश्य जन-जागृति था। जनता में स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करके उसे देश में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए तैयार करने का आह्वान किया जाने लगा। इन आन्दोलनकारियों ने उदारपथियों की विधान परिषदों के माध्यम से शासन-सुधार करवाने की धारणाओं को भ्रान्तिपूर्ण ठहराया, क्योंकि विदेशी शासकों के अत्याचार तथा दमनचक्र निरन्तर घटते जा रहे थे। अतः 1905 के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन में एक पूर्णतया नवीन प्रवृत्ति आ गई, जो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय बनी रही। इस उग्रवाद ने कांग्रेस

की गतिविधिया का भी नया रूप प्रदान किया।

बंगाल में उग्रवादी आन्दोलन—उग्रवादी राष्ट्रीय आन्दोलन की गतिविधिया का तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है बंगाल महाराष्ट्र तथा समग्र रूप में समूचे देश में। उग्रवाद की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बंग विच्छेद होने से बंगाल का जनता में क्षाभ का वर्णन स्वाभाविक था। अतः बंग विच्छेद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आन्दोलन की तीव्रता बंगाल में सर्वाधिक रही। उग्रवादी नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तक न तो राज कर्जनों की नीति की घोषणा की। एन. एम. समय का मत था कि आज बंग तथा गरिब जाति हानि तो राज कर्जनों की नीतियों के कारण उसके ऊपर भी महाभयानक गिरावट है।¹ बंगाल में विभाजन के विरुद्ध जनसंख्या निकलने लगी प्रत्यक्ष क्रियाएँ की गईं तथा जनसंख्या सभाएं आयोजित की गईं। सरकार ने इन सबका दमन करने में कोई कमी नहीं रखी। हत्याएँ हत्याएँ तथा विधायिका तथा जनता सदन भाग लिया उन्हें सरकार ने दमन भी किया। बंगाल में आन्दोलन का दवाने के लिए गारखा सेना बुलाई गई। परंतु जहाँ सरकार ने बंग आन्दोलनकारियों का दमन दिया वहाँ आन्दोलनकारियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। पूर्वी बंगाल के गवर्नर बी. फ्रेंच ने अग्रजों की बंग विच्छेद की नीति का स्पष्ट कर दिया। उसका कथन था कि मरी दो पत्नियाँ हैं—हिंदू तथा मुस्लिम और मैं मुस्लिम पत्नी का अधिक प्यार करता हूँ। स्पष्ट था कि बंग विभाजन का उद्देश्य भारत में साम्प्रदायिक विप्लव का फैलाना था जिसका जाड़ में अग्रजों कासन पनपता रहता।

आन्दोलन का तीव्र करने के लिए स्वतंत्र तथा वृद्धि के नीति अपनायी गई। विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में तथा उनके द्वारा विविध पत्र-पत्रिकाओं में लिखे गए लेखों के द्वारा बंग मातृभूमि गीत का जारदार प्रचार हुआ। घर-घर में जाकर नानाओं ने जनता से अपील की तथा प्रतिज्ञा करवायी कि वे विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। विदेशी भाषा की पुस्तकें पर धरना दिया गया और स्थान-स्थान पर विदेशी भाषा की हानि जनायी गई। विद्यार्थी समाज ने इस आन्दोलन की प्रगति में विविध रीति-रिवाज दिखायी। विपिन चंद्र पाल अरविंद घोष सुरेन्द्रनाथ बनर्जी प्रमत्ति अनेक नेताओं ने आन्दोलन का नेतृत्व किया। विपिन चंद्र पाल ने मद्रास का दौरा किया वहाँ भी बंग विच्छेद के विरुद्ध प्रचार करवाया। अतः सरकार ने उन्हें मद्रास छोड़ने का विवश किया। स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना की गई। 5 मई 1905 का घोषित बंग विच्छेद का आदेश 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया और इस बीच हुए भारी विरोध की सरकार ने तनिक भी परवाह नहीं की बल्कि उसका दमन किया। अतः 16 अक्टूबर 1905 का दिन भारत में एक महान् शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ब्रिटिश नौकरशाहों की दमन-नीति के बावजूद आन्दोलन शांत नहीं हुआ और आन्दोलन ने बंग उग्र हुआ अपितु क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी भी होने लगा।

आन्दोलन के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रिया—बंग भाग के विरुद्ध जो उग्रवादी आन्दोलन छिड़ा था उस दवाने के लिए राज कर्जनों तथा पूर्वी बंगाल के आमाम के 10 गवर्नर फ्रेंच ने शक्ति का प्रयोग किया। इसी बीच इंग्लैंड में उदार दल की सरकार बन गई। राज मार्वे भारत मंत्री बने और राज मिंटो ने कर्जनों का स्थान लिया। उन्होंने अपनी नीति को किंचित बदला। मिंटो की धारणा थी कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले बंग शासन का नेतृत्व नहीं कर सकेंगे। परंतु साथ ही वह कांग्रेस का पूणतया उपनिर्दिष्ट रखना भी उचित नहीं समझता था। अतः उसने कांग्रेस के उदार नेताओं बनर्जी गांधी तथा मोतीलाल घोष के साथ सम्पर्क स्थापित किया। दूसरी ओर ब्रिटिश राज के प्रति मुसलमानों की निष्ठा का बनाये रखने के उद्देश्य से उसने बंग विभाजन का विरोध करने वाले राष्ट्रवादी तत्त्वा से मुसलमानों का सहानुभूति हानि की नीति की आवश्यक समझा। परंतु विभाजन का निरस्त करने के सम्बन्ध में उसने स्पष्ट पत्रकारी प्रकट की। स्वायत्त शासन की मांग के सम्बन्ध में उसने ऐसी सुधार योजना निमित्त

करने की सोची जिसे कार्यान्वित करने में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक भेदभाव स्पष्ट हो जाय और शासन सुधार योजना कार्यान्वित न हो सके। डा० ताराचन्द के अनुसार 'मिटो की योजना की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह भी आवश्यक था कि भारत के राष्ट्रवादी तत्त्वों में भी फूट हो जाय, ताकि मुसलमानों के प्रति उसकी नीति के वावजूद उदारवादियों के विरोध को रोका जा सके। साथ ही, राजनीतिक सुधारों का जो अस्पष्ट या दुष्टिकारक रूप उनके समक्ष रखा जाने वाला था, वह आन्दोलनकारियों का ध्यान बटाने मात्र को एक कदम था।¹ पूर्वी बंगाल में फुलर का आतंक तीव्र होता जा रहा था और यह मांग तीव्र हो रही थी कि उसे वापिस किया जाय। स्वयं लार्ड मिंटो उससे सन्तुष्ट नहीं था। भारतमन्त्री ने भी लार्ड मिंटो से सहमति व्यक्त की। अतः मिंटो ने फुलर को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया। परन्तु आन्दोलनकारी इतने भर से सन्तुष्ट नहीं थे।

बंगाल में उग्रवादी आन्दोलन जोर पकड़ता गया। दूसरी ओर ब्रिटिश नौकरशाही हिन्दू जनता के विरुद्ध मुसलमानों को उकसाती रही। परिणामस्वरूप पूर्वी बंगाल में भीषण साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। बंगाल की एकता के निमित्त जो आन्दोलन चलाया गया था, उसकी अनेक रस्में हिंदू धर्म-परम्पराओं के अनुसार चलाई गईं, यथा राखी बाधना, चूल्हों में आग न जलाना, बन्दे मातरम् का गीत गाना, काली की पूजा आदि। यह रस्में इस्लाम धर्म-विरोधी मानी जाने लगी। जब मुसलमानों को सरकार का प्रोत्साहन मिला तो दंगों में हिंदुओं के ऊपर किये गये जुल्मों को नौकरशाही ने अनदेखा किया। संक्षेप में, ब्रिटिश सरकार निरन्तर कांग्रेस के अन्दर तथा हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों के मध्य फूट उत्पन्न कराने के सभी तरीके अपनाने में व्यस्त रही और अधिकारीगण इन सब अत्याचारों के लिए सरकार के कार्य-कलापों का औचित्य प्रदर्शित करते रहे। परिणाम-स्वरूप उग्रवादी आन्दोलन क्रांतिकारी तथा आतंकवादी दिशा में बढ़ने लगा। सरकार के भीषण दमन के वावजूद आन्दोलन में गिरियलता नहीं आ सकी। यद्यपि सरकार ने प्रमुख नेताओं को लम्बी कारावास की सजाये दी और तिलक, लाजपत राय, अरविंद घोष आदि प्रमुख के नेता बन्दी हो गये, तथापि आन्दोलन 1911 में बंगाल विभाजन आदेश के निरस्तीकरण हो जाने पर भी शान्त नहीं हुआ। उग्रवादी आन्दोलन का स्वरूप राष्ट्रव्यापी हो गया और क्रांतिकारियों तथा आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियाँ तीव्र करना आरम्भ कर दिया।

महाराष्ट्र में उग्रवादी आन्दोलन—महाराष्ट्र ने दो महान् राष्ट्रीय नेताओं गोखले तथा तिलक को जन्म दिया था। गोखले उदारवादी नेता थे और ब्रिटिश शासन की ईमानदारी पर विश्वास रखते थे। परन्तु 1900-1905 की अवधि में ब्रिटिश शासन के दमनकारी कारनामों में गोखले भी बहुत असन्तुष्ट हो गए थे। यद्यपि उन्होंने उग्रवादी नीतियों तथा गतिविधियों का अनुसरण नहीं किया, तथापि ब्रिटिश शासन की नीतियों की उन्होंने भी भर्त्सना की। तिलक उग्रवादी राष्ट्रीयता के सबसे महान् प्रवर्तक थे। सच्चे अर्थों में उनको उग्रवाद का जनक कहा जाना चाहिए। यद्यपि वे उदारवादी नेताओं का आदर करते थे, तथापि वे उनकी राजनीतिक भिन्नता तथा अग्रजों की ईमानदारी पर विश्वास रखने की नीति के विरोधी थे। उनका लक्ष्य औपनिवेशिक ढंग का स्वराज्य प्राप्त करना नहीं था, बल्कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था जिसे वे प्रत्येक भारतवासी का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। अतः स्वराज्य-प्राप्ति के निमित्त वे किसी भी प्रकार का बलिदान करने की धारणा रखते थे। उन्होंने 'केसरी', 'मराठा' आदि पत्रों के द्वारा जनता तथा नवयुवकों को आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास तथा आत्म-बलिदान की शिक्षा दी। तिलक पाश्चात्य सभ्यता की गरिमा के विरोधी थे। उनकी भारतीयता की धारणा असंदिग्ध थी। उन्होंने स्वयं भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यों में कष्ट सहें और लम्बी अवधि का कारावास भोगा। अतः वे जनता के 'लोकमान्य' नेता बने। भारत में विदेशी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने जनता को संगठित करने तथा उसमें आत्म-त्याग और आत्म-विश्वास

की भावना जागृत करने व निमित्त महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव सहित सगठना का आयोजन किया। इनके द्वारा जनता को सहभाग अनुभासन तथा दंग प्रभ की शिक्षा दी। राष्ट्रीय चेतना की जागृति करने में इन सगठना का महान् योगदान है।

अग्रज उग्रवाद का प्रभाव—ब्रिटिश शासन व विरुद्ध असंतोष केवल वगान तथा महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा। शासन की दमनकारी नीतियाँ न सारे देश में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। पंजाब में नाना राजपत राय भी इससे बहुत रुष्ट हो गए थे। वे एक शिक्षा-सुधारक समाज सुधारक तथा धर्म सुधारक थे। उन्होंने आय समाज की उन्नति में विभिन्न योगदान किया। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली थे। ब्रिटिश शासन व अत्याचारपूर्ण रवये तथा अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों को हर दृष्टि से हीन मानने की धारणा ने उनका रोष को उभारा। वे गोमने के साथ शिष्ट मन्त्रों में सम्मिलित भी गए थे। जब उन्हें निराशा पीटना पड़ा तो उन्होंने देशवासियों को बताया कि अब आन्दोलन तथा प्राथनाओं से काम नहीं चलेगा। भारतवासियों को स्वतन्त्रता की लड़ाई में आत्म विश्वास तथा आत्म बल काय करना पड़ेगा। इस प्रकार वे भी तिनक के अनुगामी बन गए। सरकार ने उन्हें देश निकाले का दण्ड दिया।

उग्रवाद तथा कांग्रेस—जुनि 1905 अवधि में कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय संस्था थी जो राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करती आ रही थी अतः सभी राष्ट्रीय नेता या तो कांग्रेस के सदस्य थे या किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कांग्रेस पर निर्भर रहते थे। निःसन्देह अंग्रेजों की फूट डाना की नीति ने थोड़े से शिक्षित मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस विरोधी बनाकर साम्प्रदायिकता को जागृत करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस श्रेणी में सर सयद अहमद शाह का नाम उत्तमोत्तम है परन्तु स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व में भी सिद्धान्त तथा साधनों के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न होने लग गया था। दादाभाई नौरोजी गोखले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि उदारवादी नेता अपनी पुरानी ब्रिटिश राज भक्ति की नीति पर विश्वास करते थे। परन्तु बान नान पान की नयी इस नीति की कट्टर विरोधी हो गयी थी। बंग विच्छेद के उपरान्त 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस में दो दल (उदारवादी तथा उग्रवादी) बन गए हैं और इन दोनों के नेता कांग्रेस के भावी कार्यक्रम की समरूप नीति का निमाण नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके साधन एक दूसरे के विरुद्ध थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले ने की थी उस वक प्रिंस आफ वेल्स भारत पधारें थे। उदारवादी उनके स्वागत का समर्थन करने लगे परन्तु उग्रवादी इससे विरुद्ध थे। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किये गये उन्हें सर्वसम्मति नहीं माना जा सकता। परन्तु 1906 में उग्रवाद जोर पकड़ चुका था। इस (कानकता) अधिवेशन में उग्रवादी नेता तिनक को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना चाहते थे जो उदारवादियों को सहनीय नहीं था। अतः वयावृद्ध नेता नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर सफट टान दिया गया। परन्तु उग्रवादी इस अधिवेशन में स्वराज्य बहिष्कार स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रस्ताव पास कराने में सफल हो गये और प्रथम बार कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीयता का उद्देश्य स्मरण तथा उपनिवेशों की भाँति का स्वायत्त शासन प्राप्त करना घोषित कर दिया।

परन्तु 1906 का अधिवेशन कांग्रेस के अंदर उमड़ती हुई फूट का निराकरण करने का उपचार सिद्ध नहीं हुआ। वगान में राष्ट्रीयता की भावना उग्र होती जा रही थी। तिनक सहित उग्रवादी नेता उदारवादियों की ब्रिटिश शासकों से मिनी भगत करने व प्रयासों को सहन नहीं कर सके। परिणामस्वरूप कांग्रेस के अन्दर फूट की नाना अंदर ही अन्दर सुलग रही थी और 1907 के मूरत के कांग्रेस अधिवेशन में यह स्पष्टतया बाहर फूट पड़ी। कांग्रेस के इतिहास में 1907 की फूट की घटना की पुनरावृत्ति 1969-70 में हुई। परन्तु दोनों के स्वरूप में भिन्नता है। उस समय दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित था न कि सत्ता प्राप्ति या नेतृत्व प्राप्ति की व्यक्ति-

गत आकाक्षा । नेतृत्व प्राप्त करने की आकाक्षा इस उद्देश्य से निर्देशित थी कि कांग्रेस के कार्यक्रम में अपने साधनों का समावेश किया जा सके । अतः उदारवादी नेताओं ने रासबिहारी घोष का नाम अध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित किया । उग्रवादी लाला लाजपतराय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे । उग्रवादी उस समय बहुसरयक नहीं थे । अतः रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित होने पर उन्होंने विरोध किया । ऐसी स्थिति में बैठक को स्थगित कर दिया गया । परन्तु दूसरे दिन फिर यही दृश्य उत्पन्न हुआ । पुलिस ने हस्तक्षेप करके बैठक को नहीं होने दिया । इस पर उग्रवादी कांग्रेस से पृथक् हो गए । वे पूरे आठ वर्ष तक कांग्रेस से अलग रहे । इस बीच कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन करके अपना उद्देश्य सांविधानिक तरीके से कार्य करना स्वीकार कर लिया । उग्रवादियों के लिये यह भी एक बड़ा धक्का था । कांग्रेस के प्रमुख नेता गोखले, फीरोजशाह मेहता आदि एकता लाने का प्रयास करते रहे, परन्तु उनके स्वप्न उनकी मृत्यु के पश्चात् ही साकार हो पाए ।

इस बीच ब्रिटिश शासकों ने उग्रवादियों का दमन करना प्रारम्भ कर दिया । जिन समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करते थे उन पर प्रतिबन्ध लगाए गए । अरविन्द घोष के ऊपर अभियोग चलाने का निष्फल प्रयास भी सरकार ने किया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने ब्रिटिश भारत छोड़कर फ्रांसीसी बस्ती पाण्डीचेरी में अपना निवास स्थान बना लिया । कर्जन के उत्तराधिकारी लार्ड मिंटो ने गोखले तक की भर्त्सना की, बंगाल के अनेक नेताओं को देश निकाले का दण्ड दिया गया । ब्रिटिश शासकों के दमनचक्र का विरोध करने पर राजद्रोह के अपराध में तिलक को 6 वर्ष का कारावास देकर माडला जेल भेज दिया गया । उनके साथ जेल तक में मानवोचित व्यवहार करने की चिन्ता ब्रिटिश नौकरशाही ने नहीं की । इसका परिणाम यह हुआ कि युवा पीढ़ी के नेता हिंसात्मक क्रान्ति तथा आतंकपूर्ण भूमिगत साधनों का प्रयोग करने लगे । यद्यपि इस बीच मार्ले-मिंटो सुधार (1909) पास किए गए थे, तथापि उनके फलस्वरूप सन्तोष तो अनग रहा, राष्ट्रीय नेतृत्व में और अधिक असन्तोष फैल गया । 1911 में बग-विच्छेद को निरस्त करने पर भी विरोध शान्त नहीं हुआ । 1911 में लार्ड हार्डिज (वाइसराय) के ऊपर किसी आतंकवादी ने बम फेंका । यद्यपि वाइसराय बच गया तथापि इससे शासकों का रोष और अधिक उग्र हो गया । प्रेस पर और अधिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया, उनसे जमानते माँगी गयी । इस अवधि में तिलक जेल में थे जहाँ उन्होंने 'गीता-रहस्य' तथा 'दि आर्किटिक होम ऑफ दि वेदाज' नामक ग्रन्थ लिखे । ये ग्रन्थ उनकी विद्वता तथा विचार व चिन्तन शक्ति की महानता के द्योतक हैं । साथ ही इनका अध्ययन किसी भी हिन्दू मानस में कर्तव्यपरायणता भरने में समर्थ हो सकता है । गीता-रहस्य में तिलक ने कर्मयोग की महत्ता को दर्शाया है । जेल से छूटने पर तिलक ने 'होम रूल' आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । इस समय श्रीमती ऐनी बेसेन्ट जो एक आइरिश महिला थी हिन्दू धर्म तथा भारतीय राष्ट्रीयता से बहुत प्रभावित हो गयी थी । उन्होंने हिन्दू धर्म को अपना लिया था । थियोसाफिकल सोसाइटी का कार्य उन्होंने बड़ी लगन के साथ किया था । वह 1914 में कांग्रेस में प्रविष्ट हुई और होम रूल आन्दोलन में सतत कार्य करती रही । 1915 की अवधि तक उदारवादी नेताओं गोखले तथा मेहता का अवसान हो चुका था, नौरोजी 90 वर्ष के हो चुके थे । अतः ऐसा प्रतीत होने लगा कि राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालने वालों की कमी होने लगी है । भाग्यवश इसी अवधि में महात्मा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिये उपलब्ध हो गए । 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया था । इंग्लैंड युद्ध में एक पक्ष था । अतः कांग्रेस के समक्ष समस्या आई कि भारतीयों को युद्ध में इंग्लैंड की महायुक्तता करनी चाहिए या नहीं । कांग्रेस के दो दलों में एकता हुए बिना आन्दोलन का सफलता मद्दिग्य प्रतीत होने लगी । 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादी पुनः कांग्रेस में आ गए और 11 वर्ष पुरानी फूट का अन्त हो गया ।

उग्रवादिया के साधन तथा मिद्धान्त ✓

उग्रवादी आन्दोलन के नेताओं ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी तथा सुधारों के सम्बन्ध में जनमुन की नीति से असंतुष्ट होकर उग्रवादी नेताओं की सांविधानिकतावादी तथा राजनीतिक शिक्षावृत्ति की नीति का विरोध किया था। उग्रवादी नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को अपना न्याय घोषित किया और उसकी प्राप्ति के लिये स्वतन्त्र बहिष्कार तथा राष्ट्रीय गिराव की प्रगति के साधन अपनाये। स्पष्ट है कि उग्रवादी आन्दोलन के सिद्धांत तथा साधन भी उग्र प्रवृत्ति के थे।

(1) उग्रवादी क्रमिक सुधारों के पक्ष में नहीं थे। वे यह नहीं चाहते थे कि पहले सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक सुधार किए जायें तब राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। उनकी धारणा तो यह थी कि पहले स्वराज्य प्राप्त होना चाहिए अर्थात् सुधार तभी मिलेंगे जब तक सम्पन्न हो सकते हैं जबकि राजनीतिक सत्ता अपने दंगलामिया के हाथ में रहे।

(2) उग्रवादी ब्रिटिश सरकार से याचना करके अपनी मांगें मनवाना पसन्द नहीं करते थे। वे जनता में आत्म विश्वास की भावना भरना चाहते थे। वे जनता की क्रांतिकारी शक्ति पर विश्वास रखते थे न कि सांविधानिक साधनों पर। साथ ही वे थोड़े से निर्मित वर्गों के महयोग पर निर्भर न रहकर आम जनता की राजनीतिक शक्तों पर विश्वास करते थे।

(3) उग्रवादियों के साधन स्वतन्त्रता का आम प्रचार विन्ती मान का बहिष्कार शासन के अयायपूर्ण कृत्या के साथ असहयोग सविनय अवज्ञा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध थे। उनके द्वारा वे जनता में रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा भरकर भारतीयों के गैरशान्ति एवं नैतिक उत्थान का अपना लक्ष्य मानते थे।

(4) यद्यपि उग्रवादी प्रथम चरण में अहिंसात्मक आन्दोलन को ही मान्यता देने थे लेकिन उनकी अक्षमता में कुछ उग्रवादी हिंसात्मक साधनों का भी उपाय सम्मिलित रहे। यद्यपि स्वयं महात्मा गांधी ने बाद में उग्रवादियों के अहिंसात्मक साधनों को अपना न्याय बनाया तथापि उग्रवादी महात्मा गांधी के सम्मिलित से कि साधनों की पवित्रता पर साध्य की पवित्रता निर्भर रहती है मतभेद रखते थे। वे मक्याविनी के इस सिद्धांत को मानते थे कि साधनों का औचित्य साध्य पर निर्भर रहता है (end justifies the means)। उनका साध्य स्वराज्य प्राप्ति था उस किसी भी प्रकार प्राप्त करना ही वे अपना प्रमुख न्याय मानते थे।

(5) उग्रवादी ब्रिटिश शासन की अयायप्रियता तथा इमानदारी पर विश्वास नहीं रखते थे। उनका मत था अंग्रेजों ने अयायपूर्वक भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया है और वे अयाय की नीति का अनुसरण करते ही अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। अतः उनसे भारत वामों अपनी स्वायत्तता की मांग वधानिक तरीकों या शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं मनवा सकते। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों ने भारत में जो भी थोड़े से सुधार किये हैं वे भारतीयों के हिंसा का ध्यान में रखकर नहीं किये हैं बल्कि अपने निजी स्वार्थों को मिट्टी करने की नीयत से किये हैं। उनके पीछे भारत का आर्थिक शोषण सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पतन निहित है। पश्चात्त्य शक्ति में रगकर भारत का उत्थान नहीं हो सकता। अतः स्वतन्त्रता का प्रचार आवश्यक है। पश्चात्त्य शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा की योजना कार्यान्वित करनी चाहिए।

(6) उग्रवादियों ने अपने आन्दोलन का प्रचार करने के निमित्त प्रस का पर्याप्त प्रयोग किया। समाचारपत्रों में तब तक राजपतराय विपिन चन्द्र पाल स्वामी विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त जॉन्स ने जनता में राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देने वाले लेख लिखे। इसी के साथ स्वयं नेताओं ने हिन्दू धर्म-दंगल तथा मस्त्रुति की महानता का प्रचार भी किया। ये सभी नेता धार्मिक दृष्टि से कठोर हिन्दू थे। अतः हिन्दू धर्म की शिक्षाओं के द्वारा भी वे जनता को भारत में राष्ट्रवाद का उग्र बनाने का प्रयास किया ताकि धर्म के नाम पर हिन्दू जनता अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार हो सके।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (1856-1920)

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियो मे बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे प्रमुख महारथियो की श्रेणी मे आता है। महाराष्ट्र की इस महान् विभूति का जन्म 1856 मे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम से एक वर्ष पूर्व उसी चितपावन ब्राह्मण परिवार मे हुआ था, जिसमे गोखले इनके दस वर्ष पश्चात् उत्पन्न हुए थे। तिलक महाराष्ट्र के उस वीर स्वातन्त्र्य-प्रेमी महारथी शिवाजी की प्रतिमूर्ति थे जिसने शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब के दाँत खट्टे किये थे। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी मुगल सम्राट औरंगजेब के मार्ग मे सदा एक काँटे की तरह बने रहे उसी प्रकार तिलक भी भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यशाही के शरीर मे निरन्तर चुभने वाले काँटे की भाँति बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ उन उदारवादी नेताओ के द्वारा किया गया था जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना रखते थे, जो पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता तथा संस्कृति के उपासक थे, जो भारतीय राष्ट्रीय माँगो के सम्बन्ध मे प्रार्थना, आवेदन आदि की नीति पर चलकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष भिक्षावृत्ति के मार्ग का अनुसरण करते थे और जिन्हे अंग्रेजो की सत्यता तथा न्यायप्रियता पर विश्वास था।

परन्तु ऐसे युग मे तिलक एक उच्च कोटि के उग्रवादी नेता के रूप मे उत्पन्न हुए, जिन्हे उदारपथियो की उपर्युक्त किसी भी नीति पर सन्तोष या विश्वास नहीं था। वे सच्चे अर्थ मे भारतीय ही नहीं अपितु सच्चे हिन्दू थे। उन्हें भारत मे ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कृत्यो से तीव्र घृणा थी। उनका विचार था कि भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए अंग्रेजो ने भारत को राजनीतिक दासता की स्थिति मे रखा है। तिलक की सुप्रसिद्ध घोषणा थी कि 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा।' यहाँ पर 'मेरा' शब्द से तिलक का अभिप्राय भारतवासियो से था, और जहाँ तक 'स्वराज्य लेकर रहूँगा', पदावली का सम्बन्ध है, तिलक कौटिल्य तथा मैकियाविली की विचारधारा के अनुसार साध्य की पवित्रता पर किसी भी साधन को को अपनाने के पक्ष मे था। तिलक का राष्ट्र-प्रेम तथा राष्ट्रवाद अनन्य था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के हित मे वे किसी भी प्रकार के बलिदान से नहीं घबडाते थे।

पत्रकारिता उनके जीवन का प्रमुख व्यवसाय रहा था। उन्होंने मराठी भाषा के दैनिक पत्र 'केसरी' का तथा अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक पत्र 'मराठा' का सम्पादन करके इनके द्वारा ब्रिटिश शासन तथा नौकरशाही के कुचक्रो का विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद 1889 मे वे कांग्रेस मे प्रविष्ट हुए। तभी से उनकी उग्र विचारधारा के कारण तत्कालीन उदारवादी नेता उनसे घबडाने लगे। 1881 मे जब कोल्हापुर के राज्य की अव्यवस्था के सम्बन्ध मे कुछ लेख उनके पत्रो मे प्रकाशित हुए तो उसके लिए तिलक को तीन मास का कारावास भी सहना पडा। तभी से तिलक की लोकप्रियता बढ गई थी। तिलक का उद्देश्य भारत के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। उसके लिए उन्होंने जहाँ पत्रो के द्वारा विदेशी शासन-नीति का विरोध किया, वहाँ गणपति तथा शिवाजी उत्सवो का संगठन करके जनता मे ऐसे प्रशिक्षित वीरो को उत्पन्न करने का उद्देश्य रखा जो राष्ट्र के हित मे सहयोग तथा अनुशासन से कार्य करते हुए अपना सब कुछ उत्सर्ग करने को तत्पर रहे।

जब महाराष्ट्र मे अकाल तथा प्लेग फैला और प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेंड की हत्या करने वाले अभियोगी को फासी की सजा दी गयी तो तिलक ने अपने पत्रो द्वारा सरकार की प्लेग निवारक नीति तथा उसके सम्बन्ध मे प्रशासनिक अधिकारियो की दमनकारी गतिविधियो की तीव्र आलोचना की थी। परन्तु तत्कालीन सरकार ने, जो तिलक को सदैव अपना प्रथम कोटि का शत्रु मानती थी, तिलक के विरुद्ध रेंड की हत्या के पड्यन्ना का आरोप लगाया। यद्यपि तिलक ने अपने पत्रो द्वारा तथा न्यायालय मे भी इस हत्या मे अपने किसी भी प्रकार के सम्बन्ध न होने की सफाई

नी तथापि 1897 में सरकार ने उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी। सरकार के इस अयायपूर्ण कृत्य के कारण तिनक की प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु सारे देश में फल गयी। यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि गोखले ने इस अवसर पर दण्ड में भारत के ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध कई वार्ता कही थी। परन्तु भारत लौटने पर उन्होंने अपने उन वार्ता को वापिस ले लिया जबकि तिनक ने जेल जाना पसंद किया। तिनक को केवल एक वर्ष बाद ही मुक्त कर दिया गया। परन्तु यह शर्त लगा दी गयी कि यदि वह ऐसे राजनीतिक द्रोह में पुनः भाग लेंगे तो 6 माह की गैर अवधि उनके आग के दण्ड में जोड़ दी जायगी।

1899 में निरन्तर तिलक काग्रेस के ऊपर यह दबाव पड़ता रहता कि वह अपनी नरम नीति का छोड़ें। परन्तु काग्रेसी नेता तिनक से सहमत नहीं हुए। 1899 के काग्रेस अधिवेशन में तिनक ने नाना सण्स्टे के अयायपूर्ण प्रशासनिक रव्य के विरुद्ध प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया परन्तु काग्रेस राजी नहीं हुई। काग्रेस के अंतर्गत तिनक के प्रमुख साथी बिपिनवद्र पाने तथा नाना राजपतराय के अनिरीक्त बहुत थोड़े भे व्यक्ति का गुट था। नाड कजन की शासन नीति तथा वग विच्छेद के कारण जो देशव्यापी असंतोष उत्पन्न हुआ उसका कारण तिनक के साथियों की सन्या में वृद्धि हुई। 1906 के काग्रेस अधिवेशन में उग्रवाणियों की वर्तनी हुई शक्ति को देखकर काग्रेस ने उन्हें दवाने के उद्देश्य से दादाभाई नौरोजी का काग्रेस अध्यक्ष चुना क्योंकि नौरोजी सहज बयोवृद्ध नेता के विरोध में कोई भी उग्रवादी उम्मादवार खड़ा नहीं होता। परन्तु 1907 में मूरत अधिवेशन में तिनक तथा उनके दल की शक्ति बहुत बढ़ गयी थी। परिणामस्वरूप वड़े हंगामे तथा विरोह के वातावरण में वह अधिवेशन उग्र तथा उदार दल के मध्य सघर्ष का व्यक्त कर देने के लिए ही हुआ। 1907 में काग्रेस ने अपने संविधान में जो संशोधन किया उसके अनुसार तिनक के उग्र दल के नेताओं के लिए काग्रेस की सदस्यता का द्वार बंद हो गया। यद्यपि 1906 में तिनक का दल काग्रेस सभापतित्व को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ था। तथापि यह सब तिनक का ही प्रभाव था कि उस अधिवेशन में काग्रेस को स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी अपने उद्देश्यों की घोषणा करनी पड़ी।

काग्रेस से अलग हो जाने पर भी तिनक का उग्रवादी जादोवन कम नहीं हुआ। इस अवधि में वग विच्छेद तथा मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण साम्प्रदायिकता का उकसाना और शासन सुधार के मतविषय पर विचार करना ब्रिटिश शासन की नीति के प्रमुख तत्त्व रहे। इन मामलों में ब्रिटिश शासन के रव्य की तिनक निन्दा करते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार तिनक से प्रवचना चाहती थी। काग्रेस से वह पृथक् हो चुके थे। अतः 1908 में ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया जिसके साथ साथ पिछले 6 माह की कारावास की गैर अवधि भी जोड़ दी गयी। उन्हें वरमा स्थित माडला जेल भेज दिया गया। उन्हें प्रीवी कांसिस में अपील करने की अनुमति तक नहीं दी गयी। बाद में उनके कारावास का कठोर न करके साधारण कर दिया गया। परन्तु माडला जेल में जेल-अधिकारी तिनक के ऊपर कड़ी नजर रखते थे। तिनक के इस प्रवास से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का बड़ा धक्का लगा। परन्तु उनका यह प्रवास एक दृष्टि से बरदान सिद्ध हुआ। भन ही उन्हें आययन काय के निमित्त वाछित माधन उपलब्ध नहीं कराये गये तथापि उनके जीवन की एक महान् अभिनाया पूर्ण हुई जिसमें सक्रिय सावजनिक जीवन में रहते हुए पूर्ण नशा कर सकते थे। वहाँ उन्होंने अपने दो प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की। प्रथम था दी आकटिक होम आफ दी वेदाज और दूसरा था गीता रहस्य। इन ग्रन्थों की रचना से यह सिद्ध हो गया कि तिलक भारतीय सभ्यता तथा वेद शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित भी थे। इसी अवधि में उनकी धर्मपत्नी का देहावसान भी हुआ परन्तु तिनक अपनी व्यक्तिक तथा गृह-परिस्थितियों की परेगानिया के बावजूद सरकार के सम्मम नहीं भुके। 1914 में जब महायुद्ध छिड़ गया और राजनीतिक वातावरण भी कुछ बदल गया तो कारावास की अवधि पूर्ण होने में कुछ समय पूर्व तिलक को छोड़ दिया गया।

परन्तु इस कारावास ने तिलक को राष्ट्रसेवा के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया। जेल में मुक्त होते ही उन्होंने पुनः अपने को स्वराज्य आन्दोलन में डाल दिया। 1915 में राष्ट्रीय नेतृत्व का अवसान प्रारम्भ होने लगा था। गोखले की मृत्यु होने पर उनकी विचारधारा से तीव्र विरोध रखते हुए भी तिलक ने उन्हें भाव-भीनी श्रद्धाजलि अर्पित की और उनकी राष्ट्रसेवा के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 1916 में कांग्रेस दलों के मध्य एकता हो जाने पर पुनः तिलक कांग्रेस में आ गये। इस बार तिलक को श्रीमती ऐनी बेसेट के होम रूल आन्दोलन से पर्याप्त प्रेरणा मिली। दोनों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की गयी। इस आन्दोलन का नेतृत्व करने तथा आजीवन राष्ट्र की सेवाओं में रत रहने के कारण सारे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ गयी थी और इसीलिए भारतवासी उन्हें 'लोकमान्य' तिलक के नाम से जानते हैं। होम रूल आन्दोलन की अवधि में तिलक को महाराष्ट्र का ही नहीं, अपितु समूचे भारत का 'वेताज का राजा' माना जाता था। इसके बाद की अवधि में भी तिलक अपने मिशन में कार्य करते रहे और जीवन के अन्तिम क्षणों तक देश-सेवा, देश-प्रेम, तथा स्वाधीनता के लिए प्राण-पण से कार्य करते रहे। 1 अगस्त 1920 को भारतमाता की पचास वर्ष तक सेवा करने के बाद भारत का यह प्यारा नेता इस ससार से विदा हो गया।

तिलक तथा गोखले की तुलना—तिलक के बाद उनके दल के जो नेता शेष रह गये थे उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। लाला लाजपत राय इस श्रेणी में आते हैं। परन्तु 1920 के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व गांधीजी के हाथ में आ गया। गांधी गोखले के शिष्य थे अथवा तिलक के, यह स्पष्टतया बताना कठिन है, क्योंकि उनकी विचारधारा तथा कार्यप्रणाली में दोनों की छाप बनी रही। गोखले तथा तिलक के सम्बन्ध में स्वयं गांधी जी के शब्दों में ही उनकी धारणा व्यक्त की जा सकती है। गांधी जी ने कहा था 'लोकमान्य तिलक मुझे एक महासागर की तरह प्रतीत हुए जिसमें किसी का भी प्रविष्ट हो सकना कठिन है। परन्तु गोखले गंगा की भाँति थे, जिसमें सुगमतापूर्वक गोता लगाया जा सकता है।' तिलक की विशालहृदयता, तथा निर्भीकता के समक्ष शायद ही कोई राष्ट्रीय नेता ठहर सकेगा। सी० वाई० चिन्तामणि के अनुसार माण्टेग्यू ने एक बार कहा था कि 'भारत में केवल एक ही वास्तविक उग्र राष्ट्रवादी थे और वह थे तिलक। सचमुच वे 'महाराष्ट्र केसरी' ही नहीं अपितु 'भारत केसरी' थे। वह सही माने में एक लौह-पुरुष थे और जिस कार्य में हाथ डालते थे उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की खोज करना उनके लिए कठिन कार्य नहीं था। गोखले तथा तिलक दोनों राष्ट्रीय आन्दोलन के महाराष्ट्रीय नेता थे, दोनों के अन्तिम उद्देश्यों में समानता होने के साथ-साथ साधनों में इतनी भिन्नता थी कि बहुधा दोनों को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। परन्तु वास्तव में दोनों एक-दूसरे के पूरक थे। इस समानता तथा अन्तर को पट्टाभि सीतारामैया के शब्दों में व्यक्त करना अधिक उपयुक्त होगा 'तिलक तथा गोखले दोनों महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, दोनों एक ही चितपावन वंश के थे। दोनों प्रथम श्रेणी के देशभक्त थे। दोनों ने अपने जीवन में महान् बलिदान किया। परन्तु दोनों के स्वभाव एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। यदि हम उस युग की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करें तो हमें गोखले को 'उदारवादी' तथा तिलक को 'उग्रवादी' कहना पड़ेगा। गोखले की योजना निर्वर्तमान सविधान को सुधारने की थी, तिलक उसका पुनर्निर्माण करना चाहते थे। गोखले आवश्यक रूप से नौकर-शाही के साथ सहचार करना चाहते थे, तिलक आवश्यक रूप से उससे लड़ना चाहते थे। गोखले का उद्देश्य या जहाँ सम्भव हो, सहयोग से कार्य किया जाये और जहाँ आवश्यक हो, विरोध किया जाये, तिलक का भुकाव प्रतिरोध की नीति पर था। गोखले का सम्बन्ध मुख्यतः प्रशासन तथा उसके सुधार के साथ था, तिलक की सर्वोच्च धारणा राष्ट्र तथा उसका निर्माण करना था। गोखले का आदर्श प्रेम तथा त्याग था, तिलक का आदर्श सेवा तथा कष्ट सहन करना था। गोखले विदेशियों पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे, तिलक उन्हें हटाना चाहते थे। गोखले इसरी की महायता में निभर होते थे, तिलक आत्म-निर्भरता पर जोर देते थे। गोखले की दृष्टि

विशिष्ट बग या शिनिन बग पर थी तिनक आम जनता तथा कराडा भारतीय पर दृष्टि रखत थ। गांधी का कार्य उन विधान परिषद थी तिनक का विचार स्थान गांव का मण्डप था। गांधी का माध्यम अग्रजी भाषा थी तिनक का माध्यम मराठी भाषा। गांधी का उद्देश्य ऐसा स्वायत्त गामन प्राप्त करना था जिसे तिनक ने जनता का अग्रजा द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अपने योग्य मित्र बनाना पड़ेगा तिनक का उद्देश्य स्वराज्य था जिसे वह प्रत्यक्ष भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार कहत थे तिनका प्राप्त उद्देश्य किमी प्रकार के विदेशी दबाव या अवरोध के करनी पड़ेगी। गांधी अपने युग के साथ थे तिनक अपने युग से आगे बढ़ चुके थे।¹

इन दोनों महान् नेताओं का तुलना का उपयुक्त विवरण देना स्पष्ट है कि इससे आम और कुछ कहना ठीक नहीं रह जाता। निम्नलिखित तिनक अपने युग से आगे बढ़ गये थे। यदि व 1920 के उपरान्त की अवधि में जीवित रहते तो निम्नलिखित राष्ट्रीय आन्दोलन में उनका प्रभाव कहा अधिक महान् हो जाता। उन अपने युग में उनकी नीतियों का समर्थन स्वयं राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा नहीं किया गया। साथ ही उस समय ब्रिटिश सत्ता शक्ती सुदृढ़ थी कि उसने तिनक के आन्दोलन को दबाने में तथा उन्हें दीर्घ अवधि तक प्रवास में रक्कड़ आन्दोलन को तीव्र तथा उग्र बनाने में सफल किया। परन्तु तिनक ने राष्ट्रीय आन्दोलन में वह जान भर दी जिसने ब्रिटिश नौकरशाही का निरन्तर मंचत रखा और भविष्य के नेताओं को ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध मंचन करने की प्रेरणा देकर देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नया जीवन भर दिया। यद्यपि जिस अवधि में तिनक राष्ट्रीय आन्दोलन का वास्तविक स्वरूप प्रदान करते उस अवधि में सरकार ने उन्हें नम्बी कारावास की स्थिति में रख दिया था तथापि उन्होंने उस अवधि का सदुपयोग करके राष्ट्र की बहुमूल्य सेवा की। साथ ही उनके कारावास दण्ड के कारण उनकी लोकप्रियता बनी और राष्ट्र के जनमानस की चेतना का भी विकास हुआ।

2 लाला लाजपत राय (1865-1928)

यदि लोकमान्य तिनक का महाराष्ट्र के सरा कहल गया है तो उनके समकालीन तथा समकालीन लाला लाजपत राय को पंजाब कसरी कहा जाता है। तिनक की भाँति ही लाला लाजपत राय भी स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख उग्रवादी राष्ट्रीय नेता थे। वे न केवल एक राजनीतिक नेता थे अपितु एक उच्च कोटि के शिक्षा प्रेमी हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक परन्तु साम्प्रदायिक सहिष्णुतावादी अपने युग के महान् व्याख्यानदाता देशभक्त तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के अनन्य पुजारी थे। वे 1888 में काग्रस में प्रविष्ट हुए थे। तिनक की भाँति वे भी उदारवादीयों की राजनीति शिक्षावृत्ति की नीति के विरोधी थे। अतएव तिनक तथा त्रिपिन चर्च पाल के साथ उन्होंने काग्रस के अंदर राष्ट्रवादी दल की स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भाग लिया। काग्रस में प्रवेश करते ही उन्होंने उठू में जा भाषण दिया था उसने उन्हें अपने युग के सर्वोत्तम सांख्यिक वक्ता के रूप में सिद्ध कर दिया। सी. वाई. चित्तामणि का मत है कि एक सांख्यिक वक्ता के रूप में लाला लाजपत राय लायड जाज के समकालीन थे उनमें ज्ञान-जनता के मध्य अपने विचारों के प्रति जागृति उत्पन्न करने की अतीव प्रतिभा थी।

लाला लाजपत राय एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। परन्तु साथ ही वे हिंदू मूल्यमय एकता के भा समर्थक थे। उनके ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रभाव था अतः आय समाज के प्रचार में उन्होंने बहुत अधिक अभिरुचि दर्शायी। वे महान् शिक्षाप्रेमी थे। उन्होंने लाला लाला ए. बी. कानेज की स्थापना की और 1888 के काग्रस जवियन में यह प्रस्ताव रखा कि

Staramayya p cit 99

² डा. ए. बी. का पूरा रूप दयानंद एगो वैदिक है। हम नाम से स्पष्ट होता है कि स्वामी दयानंद तथा उनके शिष्य आनंद भाषा के विरोधी नहीं थे। परन्तु वे शिक्षा को राष्ट्रीय रूप देना चाहते थे जो बहिष्कार परम्पराओं पर निर्मित हो।

कांग्रेस को कम से कम आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग-धन्धों की समस्या पर विचार करने में लगाना चाहिए। लालाजी पाञ्चात्य सस्कृति की अपेक्षा भारतीय सस्कृति की श्रेष्ठता के समर्थक थे। इन गुणों के अतिरिक्त वे एक उच्च कोटि के पत्रकार भी थे। उन्होंने पञ्जाबी, वन्देमातरम् तथा जनता (The People) पत्रों का प्रकाशन तथा सम्पादन किया।

1906 में लाला जी को गोखले के साथ कांग्रेस ने एक शिष्ट-मण्डल के सदस्य के रूप में इंग्लैण्ड भेजा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय दृष्टिकोण को रखना था। परन्तु जब इस मिशन में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा तो लाला जी ने अपने देशवासियों को बताया कि उदारवादियों की नीति का अनुमरण करके देश का कोई हित नहीं हो सकेगा। अतः देशवासियों को आत्म-विश्वास तथा आत्म-निर्भरता की नीति अपनाकर देश की स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष करना पड़ेगा। मातृभूमि के हित में हमें किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 1907 में, जब उग्रवादी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था तो पञ्जाब में भूमि सुधार सम्बन्धी शासन नीति का घोर विरोध करने के आरोप में लाला जी को सरदार अजीतसिंह के साथ देश निकाले की सजा दी गयी। परन्तु छ मास पञ्चात् उन्हें मुक्त कर दिया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में जब उग्र तथा नरम दल का सघर्ष चरम सीमा पर पहुँच गया, तो तिलक ने लाला जी का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। इस अवसर पर गोखले ने यह चेतावनी दी कि 'यदि आप सरकार की अवज्ञा करेंगे तो सरकार आपको और अधिक दबायेगी।' ¹ यद्यपि लाला जी इस दृष्टिकोण की परवाह नहीं करते थे, तथापि उन्होंने अपना नाम इसलिए वापिस ले लिया कि कहीं दोनों दलों के मध्य कटुता बहुत न बढ़ जाय। 1908 में तिलक के कारावास के उपरान्त लाला जी को भी निर्वासित कर दिया गया। जहाँ वे वापिस आये तो उनके पीछे खुफिया दल इस प्रकार घूमने लगा कि लाला जी ने भारत से बाहर चला जाना पसन्द किया। 1914-16 की अवधि में वे अमरीका में रहे। वहाँ उन्होंने अपनी पुस्तक 'यंग इण्डिया' लिखी, जिसका भारत तथा इंग्लैण्ड में प्रसारण वन्द कर दिया गया था। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में लाला जी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया।

लाला लाजपतराय असहयोग आन्दोलन के समर्थक नहीं थे। सीतारामैया के शब्दों में 'वह एक सत्याग्रही नहीं अपितु एक योद्धा थे। उनकी दृष्टि में सविनय अवज्ञा निष्क्रिय प्रतिरोध से पृथक् अन्य कोई अर्थ नहीं रखती।' लाला जी भारतवासियों के विधान परिषदों में प्रविष्ट होने की नीति के समर्थक थे। 1920 में उन्हें केन्द्रीय विधान-परिषद् के लिए चुना गया था। वहाँ वे स्वराज्य दल के उपनेता रहे। परन्तु बाद में वे इस दल से अलग हो गये और मदनमोहन मालवीय जी के सहयोग से उन्होंने राष्ट्रवादी दल की स्थापना की।

1928 में जब भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन चल रहा था तो लाला जी ने भी इसमें भाग लिया। इसे दवाने में पुलिस ने जो दानवीय रवैया अपनाया उसमें लाला जी को भीषण लाठी-प्रहार का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। जिन दिन डम गोरे मार्लेट ने उनके ऊपर लाठी चलायी थी, उस दिन सायंकाल अपने भाषण में लाला जी ने जो शब्द कहे थे वे चिरस्मरणीय हैं। उन्होंने कहा था 'मेरे ऊपर किया गया नाडी का एक-एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थी की एक-एक कील के रूप में सिद्ध होगा।' भारत को अपने स्वतन्त्रता संग्राम के इस महान् योद्धा, देशभक्त, शिक्षाशास्त्री, वक्ता, समाज सुधारक तथा त्यागी नेता पर गर्व करके, उनके जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए।

3 विपिन चन्द्र पाल (1859-1932)

उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की त्रयी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय

¹ 'If you flout the government, Government will throttle you' Gokhale

तथा विभिन्न चन्द्र पान को वात न न पान के नाम से सम्भावित करने की परम्परा बनी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के त्रिकोण में पंजाब में गान्धी राजपन राय महाराष्ट्र में बाबू गंगाधर तिलक तथा बंगाल में विभिन्न चन्द्र पान तीन कोण त्रिभुजा का स्थान लेने वाले हैं। बंगाल ने राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में जहाँ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सहज उदारवादिता को जन्म दिया है वहाँ विभिन्न चन्द्र पान अरविन्द घोष मानवराय सुभाष चन्द्र बोस सहज क्रांतिकारियों का भी पालन किया है। वास्तव में जिनने क्रांतिकारी नता बंगाल ने पदा किया है उतने गायन ही देश के किमी अन्य भागों में उत्पन्न हुए होंगे। विभिन्न चन्द्र पान तिलक गुट के राष्ट्रवादी नेता थे।

विभिन्न बाबू न केवल एक राष्ट्रवादी नेता ही थे अपितु एक दार्शनिक तथा पत्रकार भी थे। उन्होंने राष्ट्रवाद की व्याख्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में की है। वे एक अन्तर्राष्ट्रीयतावादी विचारक थे। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से अपना सम्बन्ध रखा और उनके माध्यम से अपने राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक विचारों का व्यक्त किया। प्रारम्भ में वे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की भाँति उदारवादी नेता थे। परन्तु उनके राष्ट्रवादी विचार उतने अधिक समय तक उदारवादी नहीं रह सके। कांग्रेस से उनका सम्पर्क प्रारम्भ में ही बने गया था। बाद में वे महात्मा अरविन्द घोष के पत्र बन्धेमातरम् से सम्पर्क हो गये। उन पर अरविन्द के क्रांतिकारी विचारों का भी प्रभाव पड़ा। वे यू. इण्डिया पत्र का भी सम्पादन कुछ दिनों तक हाँ करते रहे।

1902 के उपरांत उनके विचारों में उग्रवादिता आने लगी। उन्होंने बंग विद्रोह के मरकरी निणय का घोर विरोध किया और जब कांग्रेसियाँ ने 1906 में स्वराय का अपना उद्देश्य घोषित कर दिया तो विभिन्न बाबू ने स्वतन्त्र बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए बंगाल का यात्रा दौरा किया। 1907 में जब मद्रास में जाकर उन्होंने अपना राष्ट्रीय आन्दोलन जारी किया तो उनके प्रभाव में नूतन नया चेतना उत्पन्न होने लगी। तत्कालीन मद्रास की सरकार इस सहन नहीं कर सकी और उसने विभिन्न बाबू के मद्रास में निवास पर पाबंदी लगा दी। एक बार जब अरविन्द घोष के ऊपर उनके पत्र बन्धेमातरम् में प्रकाशित लेखों के सम्बन्ध में अभियोग चलाया गया तो विभिन्न बाबू को उसमें गवाही देने के लिए बुलाया गया। विभिन्न बाबू जानते थे कि उनकी गवाही से अरविन्द पर आरोप सिद्ध हो जायगा। जहाँ उन्होंने न्यायालय में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। इस पर न्यायालय की मानहानि के आरोप में उन्हें छ माह का कठोर कारावास दे दिया गया। 1908 में वे ब्रिटेन में रहे रहे कुछ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के आमन्त्रण पर इंग्लैंड गये। वहाँ से लौटने पर उनके एक लेख के सम्बन्ध में उन पर अभियोग चलाया गया। परन्तु इस अवसर पर उन्होंने क्षमायाचना कर ली। सीतारामय्या के मत से उनके वात विभिन्न चन्द्र पाल की लोकप्रियता कम हो गयी क्योंकि उनका दृष्टिकोण यत्तिवादी हो चला था।

1907 से 1916 तक वे भी कांग्रेस से पृथक् रहे। उसके उपरान्त कुछ वर्ष तक कांग्रेस में रहने पर 1921 में फिर उससे अलग हो गये क्योंकि वे गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के समर्थक नहीं थे। वे विधान परिषद् के बहिष्कार तथा विदेशी वस्त्रों की होनी जतान की नीति में भी संतुष्ट नहीं थे। बाद के 11 वर्षों में उनका राजनीतिक जीवन लगभग निष्क्रिय रहा। 1932 में उनकी मृत्यु हो गयी।

4/ थोमस एनी बेसेंट

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं में आइरिश महिला श्रीमता एना बेसेंट का नाम चिरस्मरणीय है। वे 1893 में थियोसोफिकल सोसाइटी की एक सदस्या के रूप में भारत आया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सामाजिक तथा शैक्षिक विकास था। 20 वर्ष तक श्रीमती एनी बेसेंट भारत में श्रीमती धर्म में कार्य करती रही और थियोसोफिकल सोसाइटी की भारतीय शाखा की अध्यक्ष रही। उन्होंने भारतीय धर्म ग्रन्थों वद उपनिषद् तथा श्रीमद्भगवद्गीता का

अध्ययन किया। अन्त में उन्होंने यह घोषित किया कि हिन्दू धर्म पाश्चात्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठतम है। उन्होंने स्वयं भी हिन्दू धर्म को अपनाया वे एक विदुषी सार्वजनिक वक्ता तथा कर्मठ महिला थी। उन्होंने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया और अपने को लोकप्रिय बनाया। उनके द्वारा किया गया श्रीमद्भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद इस रूप की सर्वप्रथम तथा जनप्रिय रचना सिद्ध हुई थी। इस प्रकार ऐनी बेसेट ने हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान में स्वामी दयानन्द, तिलक, स्वामी विवेकानन्द तथा अरविन्द घोष के समान कार्य किया।

श्रीमती बेसेट ने सामाजिक सुधार कार्यों में भी अतीव रुचि दर्शायी। वे बाल-विवाह की कटू विरोधी थी, साथ ही महिलाओं को विधवा जीवन व्यतीत करने को विवश करने की प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। वे महिलाओं को पुरुषों के तुल्य सामाजिक स्थिति प्रदान करने की समर्थक थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी वे राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की समर्थक थी। उन्होंने बनारस में मेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना करवायी, जो कालान्तर में मदनमोहन मालवीय जी के अध्यक्ष परिश्रम तथा प्रयासों से हिन्दू विश्वविद्यालय बन गया।

1908 से 1913 की अवधि में वे इंग्लैंड गयी। वहाँ उस समय आयरलैंड में होम रूल आन्दोलन चला हुआ था। चूँकि बेसेट इस अवधि में भारतीयता के रंग में रंग चुकी थी, और यद्यपि वे भारतीय राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से प्रविष्ट नहीं हुई थी, तथापि यहाँ के राष्ट्रीय आन्दोलन का उन्हें अच्छा ज्ञान हो चुका था। उन्हें लगा कि राजनीतिक पराधीनता भारतवासियों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अवनति का मुख्य कारण है। अतः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भारत में भी होम रूल आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। इंग्लैंड में भारत लौटने पर 1914 में उन्होंने अपना जीवन क्रम थियोसॉफी से राजनीति में बदल लिया। उस समय तिलक भी जेल से छूट चुके थे। भारत में स्वराज्य तथा स्वदेशी आन्दोलन चला हुआ था। कांग्रेस के दो दलों के संघर्ष के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति मन्द हो चुकी थी। बेसेट ने 1915 में दोनों दलों के मध्य एकता लाने का अथक् प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें यह सफलता 1916 में मिली। उसी वर्ष तिलक के सहयोग में ऐनी बेसेट ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। यद्यपि यह आन्दोलन बहुत अधिक नहीं चल सका, क्योंकि 20 अगस्त 1917 की माटेग्यू की घोषणा के बाद यह आन्दोलन मन्द पड़ गया था, तथापि बेसेट के प्रयासों से राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नयी जागृति उत्पन्न हुई।

श्रीमती ऐनी बेसेट ने उग्रवादियों को क्रान्तिकारियों के पथ पर जाने में रोकने, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहकर ही स्वराज्य प्राप्त करने की प्रेरणा देने तथा उन्हें उदारवादियों के और अधिक समीप लाने में सफलता प्राप्त की। मद्रास के दैनिक पत्र 'न्यू इण्डिया' का आरम्भ उन्हीं के प्रयासों में हुआ। 1914-17 की अवधि में वे भारत की एक उच्च कोटि की राष्ट्रीय नेता बन गयी और उनकी इन सेवाओं के परिणामस्वरूप 1917 में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुना गया। श्रीमती बेसेट ने स्वदेशी वहिष्कार आन्दोलन को नरम बनाया। वे स्वदेशी आन्दोलन की विरोधी नहीं थी, परन्तु वे इसे एक राजनीतिक अस्त्र नहीं बनाना चाहती थी। वे ब्रिटिश माल का वहिष्कार करने की नीति को भी उचित नहीं समझती थी। 1916 में उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में आने पर सरकार ने उन्हें उनके दो साथियों वाडिया तथा अरुण्डेल के साथ निर्वासित कर दिया। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गयी। जब माटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कानून पार हुआ तो बेसेट ने यह कहकर कि 'यह सुधार इंग्लैंड के हक में अयोग्य तथा भारत-वासियों के हक में अस्वीकृत करने योग्य' है उनकी भर्त्सना की। 1920 में जब कांग्रेस ने अमहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया, तो श्रीमती बेसेट ने कांग्रेस छोड़ दी।

कांग्रेस में अलग हो जाने के पश्चात् वे जाजन्म भारत की सेवा करती रहीं। उन्होंने ब्रिटिश मन्द के एक सदस्य मि० लैमबर्ग के माध्यम से 'कामनवेल्थ ऑफ इण्डिया' बिल संसद

म पेग बरवाया यद्यपि यह विवेक गिर गया तथापि इससे यह प्रकट होता है कि श्रीमती वेसेंट भारत की सच्ची मित्र थी।

5 महर्षि अरविंद घोष (1872-1950)

मनुष्य कुछ साधना है परंतु होता वही है जो परमात्मा का स्वीकार्य है। इस नय्य पर विश्वास करने वाले आधुनिक भारत के महान् दार्शनिक तथा योगिराज महर्षि अरविंद थे जिनके जीवन में उक्त तथ्य साकार हुआ। अरविंद घोष का पिता डा. कृष्णधन बगान के एक उच्च काटि के चिकित्सागास्त्री थे। वे कुछ वर्षों तक इंग्लैंड में रहे और वहाँ के योग के जीवन क्रम विचारों तथा आदर्शों के महान् प्रामाण्य बन गए। भारत लौटने पर उन्होंने यही च्छा रखी कि वे अपने बच्चा की शिक्षा पूणतया विनायत के वातावरण में करेंगे और उन्हें पक्का अग्रज बनाकर उच्च पदा पर नियुक्त हुआ देखेंगे। उन्होंने यही किया जब अरविंद केवल 7 वर्ष के थे तो उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्हें भारतीयता से बिल्कुल पृथक् रखा गया। वही अरविंद जब ब्रिटिश वातावरण में पढ़ाई कर रहे थे एक उद्भट विद्वान् सिद्ध हुए तो 21 वर्ष का उम्र में भारत लौटने पर उन्होंने अपना जीवन क्रम उलट डाला और आज में भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन तथा समग्र रूप में न केवल विमुक्त भारतीयता को अपनाया अपितु भारत को भाग्य के रूप में देखने तथा पूजने वाले कट्टर भारतीय बने और भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के महान्तम गणितिका का श्रेणी प्राप्त की।

अठारह वर्ष की जल्पायु में ही उन्होंने भारतीय सिविन सेवा (I C S) की परीक्षा पास की। परंतु इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पाश्चात्य देशों के कुछ महान् राष्ट्रवाद्या मजिनी प्रभति की रचनाएं पढ़ी थीं। भारत में हो रही राष्ट्रीय प्रगति का भी उन्हें पान प्राप्त होता रहा था। अतएव कहा जाता है कि वे भारतीय सिविन सेवा के अधिकारी बनना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके मन में भारत माता की सेवा करने की भावना जागृत हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने केवल घुड़सवार की परीक्षा में अपने को असफल मिद्ध करवा लिया। स्वयं इंग्लैंड में अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मातृभूमि का सेवा का सर्वप्रथम साधन उस राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन करवाना है। उन्होंने भारत की स्वायत्तता के लिए अपने जीवन का अर्पण कर देने का प्रण कर लिया। उस समय जब वे भारत लौट तो उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति निम्न हो चुकी थी। अतः उन्हें आजीविका का कोई साधन नूना था। वे बंगाल नरेश की सेवा में पविष्ट हुए। 1893 से 1906 तक वे वहाँ विविध प्रामाणिक एवं शक्षणिक संस्थाओं में कार्य करते रहे। यह 13 वर्ष का जीवन उन्होंने मुख्यतया भारत के महान्तम ग्रथा तथा भारत की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन में लगाया और उसके प्रभाव से वे पक्के भारतीय बन गये। सभी अवधि में भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता के आदानकारी संगठन काग्रम के साथ उन्होंने अपना सम्पर्क बनाया। वे उनके कई अधिवक्ता में शामिल हुए। 1906 में उन्होंने बडोदा नरेश की सेवा छोड़ दी।

राष्ट्रीय आंदोलन के तत्कालीन उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिरावृत्ति की नाति से अरविंद बहुत चिंतनमय। वे तिनक तथा बिपिन चंद्र पाल की धारणाओं को उचित समझते थे। बडोदा रहते हुए उन्होंने योगाभ्यास भी किया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्त किया और राजनीति एवं अध्यात्मवाद के मध्य घनिष्ठ सम्बंध दर्शाया। उनके राजनीतिक विचार सर्वप्रथम बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'नूदु प्रकाश' में एक लेखमाला के रूप में 'New Lamps for Old' शीर्षक से प्रकाशित हुए। इनमें उन्होंने उदारवादी नीतियों की कटु आलोचना करने ब्रान्तिकारी वाय-वक्ताओं के महत्त्व को स्वाधीनता सघप के निमित्त उचित ठहराया और इसके लिए तयार रहने के निमित्त जनता का आह्वान किया। वे सांस्त्र विगाह द्वारा देश का स्वतंत्र कराने के समर्थक थे। उन्होंने ब्रान्तिकारियों के गुण संगठना

को भी सगठित करने का प्रोत्साहन दिया। इस कार्य में उन्हें उनके भाई वारीन्द्र घोष का भी सहचार प्राप्त था। वस्तुतः बीसवीं सदी के क्रान्तिकारी आतंकवादी आन्दोलन का सूत्रपात अरविंद के कार्यकलापों से ही हुआ माना जाना चाहिए।¹

बीसवीं सदी का प्रथम दशक भारतीय राजनीति के अन्तर्गत भारतवासियों में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारी असन्तोष का काल था। बंगाल इस आन्दोलन का मुख्य केन्द्र था। लार्ड कर्जन की नीतियों ने इस असन्तोष में आग के ऊपर घी डालने का कार्य कर दिया था। तिलक, विपिन चन्द्र पाल तथा लाला लाजपत राय इस उग्र राष्ट्रीयता के सक्रिय नेता थे। बग-विच्छेद की घटना ने इस आक्रोश को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था। स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति को राष्ट्रीय आन्दोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। अरविंद सहस्र क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति को अब बड़ौदा नरेश की सेवा से कोई अभिर्वाच नहीं रह गयी, अतः 1906 में वे वहाँ से नौकरी छोड़कर स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल हो गये। अरविंद ने अपने जीवन का लक्ष्य देश-सेवा, देश की स्वतन्त्रता के लिए कार्य करना तथा जन-सेवा में अपने जीवन को लगाना बना लिया। वे देश को माता के तुल्य मानने लगे। उसकी सेवा में ही वे परमात्मा की प्राप्ति सम्भव समझते थे। उनकी यह धारणा थी कि उन्हें जो भी शक्ति अथवा क्षमता प्राप्त है वह परमात्मा ने उन्हें देश-सेवा के लिये प्रदान की है। उसे भारत माता की सेवा में लगाकर तन-मन से कार्य करके उन्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन रूपी दैत्य भारत माता का रक्त चूस रहा है। उस दैत्य के मुँह से माता को मुक्त करना उसकी सन्तान का कर्त्तव्य है। अरविंद ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्र (भारत माता) को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए शस्त्र बल सम्भव नहीं है, अतः ज्ञान के बल से उसे मुक्त कराया जा सकता है। अरविंद के विचारों से तत्कालीन उदारवादी नेता बहुत व्यग्र हुए। बाल-लाल-पाल तो उनके विरोधी थे ही इसलिए अरविंद उनके कट्टर सहयोगी बन गये। राष्ट्रीय शिक्षा के निमित्त उन्होंने एक छोटे से वेतन पर 'नए राष्ट्रीय स्कूल' के प्रधानाचार्य का पद ग्रहण किया। राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए उन्होंने 'वन्देमातरम्' पत्रिका का सह-सम्पादक बनना स्वीकार कर लिया। अपने लेखों तथा भाषणों में उन्होंने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक रूप प्रदान करके जनता में राष्ट्रभक्ति का प्रचार किया। उन्होंने राष्ट्रवाद को ईश्वर के रूप में विकसित किया।

अलीपुर बम-काण्ड में उन्हें तथा उनके भाई वारीन्द्र को बन्दी बनाया गया। 1 वर्ष तक वे बन्दी बने रहे। परन्तु उनके ऊपर सन्देह का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। अतः उन्हें छोड़ दिया गया। परन्तु उनकी क्रान्तिकारी गतिविधियों के प्रति सरकार निरन्तर शकालु बनी रही। जेल से निकलने पर अरविंद ने अनुभव किया कि सरकार ने सभी राष्ट्रवादी नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को बन्दी बना लिया था। जेल में भी वे निरन्तर योगाभ्यास तथा गहन चिन्तन में लीन रहते थे। वहाँ उन्होंने गीता का विशेष अध्ययन किया था। अब भी वे स्वतन्त्रता सघर्ष को जारी रखने के लिए कृत-संकल्प थे। अतः उन्होंने जनशिक्षा के लिए 'कर्मयोग' तथा 'धर्म' नाम के दो पत्र निकाले। सरकार भी उनके पीछे पड़ गयी। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि अब उनके लिए ब्रिटिश प्रभुत्व के आधीन वाली भूमि में रहना सम्भव नहीं है। 1910 में वे ब्रिटिश भारत छोड़ कर फ्रांसीसी बस्ती पाण्डीचेरी चले गये और राजनीति से विरक्त होकर सन्यास धारण कर लिया। अब उन्होंने अपना क्षेत्र आध्यात्म चिन्तन बना लिया। इस प्रकार 1910 से 1950 तक पूरे 40 वर्ष उन्होंने पाण्डीचेरी के आश्रम में आध्यात्म चिन्तन में बिताए और राजनीति से पृथक् रहे। दिसम्बर 1950 में उनका शरीरान्त हो गया। स्वतन्त्रता के बाद भी वे पाण्डीचेरी में ही बने रहे।

यद्यपि सक्रिय राजनीति में उन्होंने मुख्यतया केवल 4 वर्ष तक कार्य किया और इससे पूर्व भी राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत उग्र तथा क्रान्तिकारी विचारों का समर्थन करते रहे, तथापि

¹ इस आन्दोलन का वर्णन आगामी पृष्ठा में पृथक् किया जायेगा।

उनके राजनीतिक जीवन की इस छोटी-सी अवधि में उनके विचारों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नव-सृष्टि लाने का कार्य किया। उग्र राष्ट्रवाद के वंश में महान् समर्थक तथा जातिवादी राष्ट्रीयता के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक रूप प्रदान करके उस पर दृष्टांत्य प्रभाव से मुक्त कराया और उदारवादियों की पाश्चात्य-परमर्त नीतियों का अन्त करने में योगदान किया।

उग्र राष्ट्रीयता का मूल्यांकन ✓

जिस प्रकार कांग्रेस की उत्पत्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में उदारवादी नेताओं के विचारों पर पाश्चात्य सभ्यता एवं सस्कृति के प्रगति तथा भारतीय पुनर्जागरण के नेताओं—राजा राममोहन राय एवं महात्मा गोविन्द रानाडे के विचारों का प्रभाव था। उसी प्रकार 20वीं सदी के आरम्भिक वर्षों में उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के ऊपर स्वामी दयानन्द स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा अरविन्द के विचारों का प्रभाव पड़ा। ये मनीषी भारतीय सभ्यता सस्कृति एवं हिन्दू धर्म ग्रन्थों का मूल्य को समझे और उन्हें उनके आधार पर उन्होंने हिन्दू धर्म तथा आध्यात्मिकता को भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख अंग स्वीकार किया। स्वामी विवेकानन्द तथा अरविन्द भारत के ही नहीं अपितु विश्वभर के आध्यात्मिक शिक्षक सिद्ध हुए। उदारवादी नेताओं को भारत की महानता पर विश्वास नहीं था क्योंकि उनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अधीन ही भारत के कल्याण की कामना बनी रही। परन्तु उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत में भारतीय धर्म भारतीय सस्कृति एवं भारत की जनशक्ति पर विश्वास किया और वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही का भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाय रखने की नीति को सहन नहीं कर सके। निम्नलिखित उदारवादी नेताओं की शक्ति तथा जनकल्याण का भावना का चुनौती नहीं दे जा सकती। परन्तु उनके विचारों का राष्ट्रवाद बौद्धिक अधिक था धार्मिक कम। उग्रवादियों ने राष्ट्रवाद को धर्म का रूप प्रदान किया और यही कारण था कि उनके विचारों ने राष्ट्रीय चेतना का जनसाधारण के मध्य प्रसारित करने में सफलता प्राप्त की।

राष्ट्रवाद का एक प्रमुख तत्त्व किसी जनसमूह के मध्य राजनीतिक स्वतन्त्रता की धारणा का होना है। उग्रवादी राष्ट्रीयता के समर्थकों ने इस तत्त्व का भारतीय राष्ट्रीयता का अभिन्न अंग बनाया। उनकी स्वराज्य की माँग तथा आकांक्षा उनका माध्य थी इसके निमित्त उन्होंने विदेशी सरकार के साथ संधि करके इस प्राप्त करना भारतवासियों का प्रथम कर्तव्य बताया और स्वतंत्र साधन के रूप में स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरोध का कार्य क्रम बनाया। महात्मा अरविन्द ने भारतीय राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक एवं सस्कृतिक एकता के रूप में चित्रित किया। उग्र राष्ट्रीयता के सभी नेता धर्म का संकुचित साम्प्रदायिकता के रूप के नहीं बल्कि अभिन्न उद्देश्य के हिन्दू धर्म को व्यापक मानवीय धर्म के रूप में चित्रित किया और उसे एक वैश्व धर्म के रूप में व्यक्त किया। भारत सृष्टि देने में जहाँ विभिन्न जातियाँ भाषाओं तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अस्तित्व रहा है राष्ट्रवाद की उस व्यापक धारणा बहुत प्रभावी तथा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।

यद्यपि गांधी जी ने घोषित किया था कि वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तथापि गांधी जी के ऊपर विवेकानन्द के आध्यात्मवाद तत्त्वों की कार्य प्रणाली तथा अथर्व उग्रवादियों के प्रभाव का अभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने अहिंसा को अपना सर्वोत्कृष्ट साधन बनाया परन्तु उनका राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राजनीति धर्म-सापेक्ष तथा स्वतन्त्री व निष्क्रिय प्रतिरोध की नीतियाँ उग्र राष्ट्रीयता से प्रेरित थीं। जब कांग्रेस का पूर्ण नवतुल्य उनके हाथ में आ गया तो समय-समय पर उनके द्वारा संचालित आन्दोलन उग्रवादियों की नीतियों में अग्रगण्य रखने का सिद्ध हुए। निम्नलिखित राष्ट्रवाद को धर्म में समीचीन करने की उग्र राष्ट्रवादियों की नीति का विदेशी शासकों ने अपने हित-साधन में प्रयोग किया और भारत की हिन्दू तथा मुस्लिम जनता के

मध्य कटुता उत्पन्न करके भारतीय राष्ट्रवाद में साम्प्रदायिकता का विष फैला दिया, तथापि यह भी स्मरणीय है कि उग्र राष्ट्रवादी कभी भी साम्प्रदायिक भेदभाव को वाछनीय नहीं मानते थे।

ऐसे समय में जबकि उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त करके तथा अंग्रेज जाति की न्यायप्रियता पर विश्वास करते हुए ब्रिटिश शासन के आधीन ही भारत-वासियों के कल्याण तथा राजनीतिक अधिकारों एवं सुधारों की मांगें रखी, साथ ही पाश्चात्य मस्कृति तथा सस्थाओं की महानता का प्रचार किया, ब्रिटिश साम्राज्यशाही तथा नौकरशाही भारत की जनता को सुख-समृद्धि एवं स्वायत्त शासन की मांगों को न केवल उपेक्षित रखने लगी, अपितु अन्याय, अत्याचार एवं निरकुशतावाद से भरी शासन नीतियों को संचालित करने पर तुली रही। इन परिस्थितियों में उग्र राष्ट्रीयता का विकास न केवल स्वाभाविक था, अपितु उग्रवादी नेताओं से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक नये उत्साह का संचार किया और उसे केवल थोड़े से बुद्धिवादी वर्ग तक सीमित न रखके एक जन-आन्दोलन में परिणत करने का कार्य किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भीख माँगकर किसी भी देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कभी प्राप्त नहीं हुई। जो राष्ट्र अपनी परम्परागत संस्कृति, धर्म, आदर्शों तथा मूल्यों को भूलकर विदेशी तत्वों पर विश्वास करता है, वह कभी महान् नहीं बन सकता। यही सब बातें उग्र राष्ट्रीयता के नेताओं ने भारत के जन-मानस में भरी और देश को स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए प्रेरित किया।

बीसवीं सदी के आरम्भिक वर्षों में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्तर्गत उदारवादी नेताओं की पाश्चात्य-परस्त नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में जहाँ एक ओर उग्र राष्ट्रीयता विकसित हुई, वहाँ इस उग्र राष्ट्रवाद को दवाने के ब्रिटिश शासकों के प्रयासों के विरुद्ध और अधिक गम्भीर प्रतिक्रिया के रूप में क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन का सूत्रपात होने लगा। क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं के ऊपर उग्र राष्ट्रीयता का ही-प्रभाव था। इस वर्ग में उन भावुक युवकों का कार्यभाग था जो ब्रिटिश शासकों के अन्यायों को सहने में अपने विवेक को तब खो बैठे। इस आन्दोलन का विवरण हम आगामी पृष्ठों में करेंगे। इस प्रकार उग्र राष्ट्रीयता ने एक ओर क्रान्तिकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर गांधी जी सहज सत्य, अहिंसा, धर्म, आध्यात्मिकता आदि के साधनों पर विश्वास करके राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन करने में उग्रवादियों से अधिक प्रभावित हुए। संक्षेप में, उग्र राष्ट्रीयता ने स्वतन्त्रता आन्दोलन को वह प्रेरणा दी, जिसे लेकर भविष्य में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्तर्गत नये जीवन का संचार हुआ। यह दूसरी बात है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावनाओं को अपने स्वार्थ में गलत निर्वचन करके उसके आधार पर साम्प्रदायिक फूट का प्रचार करने में सफलता प्राप्त कर ली और इसी कारण वे भारत में अपना प्रभुत्व अधिक लम्बी अवधि तक बनाये रखने में सफल हो गये। साथ ही, अन्त में उन्होंने राष्ट्र के टुकड़े कराके ही अपना प्रभुत्व छोड़ा, तथापि वे इसे नष्ट नहीं कर सके।

प्रश्न

- 1 उग्र राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय समझते हैं? वह उदार राष्ट्रवाद से कहाँ और कैसे भिन्न है?
- 2 यह कहना कहाँ तक उचित है कि 'उग्रवाद न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति था वरन् वह उदारवादी नेताओं की कार्य-पद्धति के विरुद्ध या विद्रोह की घोषणा था।'
- 3 उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिन्होंने भारत में उग्रवादी राजनीति को पनपाया।
- 4 तिसरे और चौथे के राष्ट्रीय आन्दोलन को योगदान की तुलना कीजिए।
- 5 उग्रवादी राजनीति ने देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया?

क्रान्तिकारी तथा आतंकवाद (NATIONALISM THE REVOLUTION TERROR)

३५E)

भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की अवधि में 19वां शताब्दी के अन्तिम वर्षों में उदारवादी तथा 20वां शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में उग्रवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुए थे। उदारवादियों की राजनीतिक भिरावृत्ति की नीति तथा साविधानिक साधना द्वारा जन राजनीतिक अधिकारों की माँगें तथा सुधार चाहने की प्रवृत्ति उग्रवादियों का पसन्द नहल रही। स्वयं उग्रवादी भी हिंसात्मक साधना द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति पर विश्वास नहल रखत थे। उन्होंने स्वशासन स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा को अपने आन्दोलन का नश्य बनाया था। ये नीतियाँ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध की द्योतक थी। परन्तु 19वां शताब्दी के अन्तिम वर्षों में भारत के विभिन्न भागों विद्रोह (महाराष्ट्र बगान तथा पंजाब) में युवा पाने के कुछ भावक व्यक्ति भारत में ब्रिटिश सरकार की अयायपूर्ण नीतियों से इतने असन्तुष्ट हो गये थे कि उन् उदारवादियों तथा उग्रवादियों की गतिवादी तथा अहिंसात्मक साधना से स्वशासन या स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकने की नीतियों पर तनिक भी विश्वास नहल रहा। इन भावक युवकों का विचार था कि पनु बन पर निर्मित तथा आधारित साम्राज्यवाद का एमे साधना से समाप्त कर सकना असम्भव है। यनाग यूरॉप की विभिन्न क्रातियों से प्रभावित थे। हम में जारगाही के विरुद्ध मडक रही क्राति फ्रांस की प्रसिद्ध क्राति एवं अमरीकी स्वतन्त्रता की क्राति आदि न्तक प्ररणा स्रोत थे। इनका मुख्य नश्य दशकामियों का एवं व्यापक क्राति के निय प्रगति तथा सक्रिय करक तुरन्त ब्रिटिश शासन को भारत की भूमि से उताड फेंकना था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन केवल 19वां सदी के अन्तिम वर्षों या 20वीं सदी के आरम्भिक वर्षों में संचालित भावक युवा वर्ग की गतिविधियों को नहल माना जाना चाहिए। वस्तुतः ऐसे आन्दोलन की जड़ें भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ-साथ जन्म चुकी थी और उनका प्रभाव समय-समय पर प्रकट होता रहा था। जिसकी परिणति 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर हो गई। पनासी का युद्ध मसूर में हैदरअली तथा टीपू सुल्तान के फाय मराठाओं के अग्रजों के साथ सधप पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का अग्रजों के साथ सधप आदि को हम पृथक् नहल माना जा सकता है। यद्यपि ये सधप क्रान्तिकारी आन्दोलन न हाकर प्रतिरक्षात्मक युद्ध थे परन्तु ये क्रान्तिकारियों के लिए प्ररणा स्रोत सिद्ध हुए। 1857 की प्रसिद्ध स्वतन्त्रता क्राति हम आन्दोलन का ज्वलन्त प्रमाण थी। इस क्राति का भन ही ब्रिटिश सरकार ने नश्य बन से दवा लिया तथापि इसक बड़े दूरगामी प्रभाव हुए। हमन ब्रिटिश शासन को पनु बन द्वारा स्वतन्त्रता सम्बन्धी माँगों को दवाने और अपने साम्राज्य का सुदृढ़ बनाय रखने के लिए अधिक अयायपूर्ण तथा दमनकारी नीतियों का अपना को प्ररणा दे तो भारत के भावक युवकों का भी हमन क्रान्तिकारी प्रतिरोध करने का प्रोत्साहन लिया। ये शठे शाठ्यम समाचरेत के सिद्धांत पर चलने लगे।

20वां सदी के आरम्भ से भारत में क्रान्तिकारी या आतंकवादी आन्दोलन का श्रीगणन महाराष्ट्र से आरम्भ होता है जयकि क्रान्तिकारियों ने 1899 में मि रण की हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत उग्रवादियों का राय बनने लगा और

उन्हे कुचलने में भी कोई कमी नहीं रखी। परिणामस्वरूप क्रान्तिकारियों ने भी अपनी मध्य कट-विधियाँ तीव्र करनी आरम्भ कर दी। इनके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आम-क्रान्ति करने के लिए प्रेरित करना, भारतीय सैनिकों में क्रान्तिकारी भावना का संचार करना, आवश्यकता पड़ने पर छापामार युद्धों की तैयारी करना, क्रान्तिकारियों को सशस्त्र करना और इस उद्देश्य के लिए देश तथा विदेशों से भी शस्त्र संग्रह करना (विशेष रूप से उन देशों से जो ब्रिटेन के शत्रु थे), विदेशों में जाकर वहाँ से क्रान्ति का प्रसार तथा प्रचार करना, आदि थे। भारत में ही रहकर ऐसा प्रचार सम्भव नहीं होता, क्योंकि इसे यहाँ की सरकार पशुबल से कुचल सकती थी। यहाँ के क्रान्तिकारी भूमिगत कार्य-कलाप करते रहे और जनता में क्रान्ति का आवाहन करने के साधन अपनाते रहे।

महाराष्ट्र में रैण्ड की हत्या के सम्बन्ध में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाथ माना जाता है। इस घटना के पश्चात् वे इंग्लैण्ड चले गये और वही उन्होंने अपनी गति-विधियों का केन्द्र बनाया। उनके बाद महाराष्ट्र के क्रान्तिकारी नेताओं में विनायक दामोदर सावरकर तथा उनके भाई गणेश सावरकर का नाम मुख्य है। चाफेकर बन्धु (दामोदर, बालकृष्ण तथा वासुदेव) भी प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता थे जिन्हें बलवन्त फडके से प्रेरणा मिली थी। रैण्ड हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में फडके को फासी दी गयी थी। चाफेकर बन्धुओं का नारा था 'प्राण देने में पूर्व प्राण ले लो।' महाराष्ट्र के इन क्रान्तिकारियों ने अपने आन्दोलन को प्रभावी बनाने के लिए 'अभिनव भारत समिति' की स्थापना की थी।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का दूसरा केन्द्र बंगाल था, जहाँ लार्ड कर्जन के शासन काल में प्रान्त का विभाजन कर दिया गया था। इस विभाजन के फलस्वरूप देशव्यापी अन्ततोष फैला था, यहाँ तक कि उदारवादी नेता भी इससे बहुत रुष्ट हो गये थे। भावुक युवकों के लिए यह घटना असहनीय थी। लार्ड कर्जन की अन्य प्रतिगामी नीतियों ने क्रान्तिकारियों के असन्तोष को और अधिक उग्र बना दिया था। बंगाल के उस युग के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी युवक अरविन्द घोष, उनके भाई वारीन्द्र घोष तथा स्वामी विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त थे। इन्होंने तत्कालीन पत्रों 'युगान्तर' तथा 'सध्या' के माध्यम से सरकार के विरुद्ध क्रान्तिकारी विचार व्यक्त करने आरम्भ किये। इन क्रान्तिकारियों ने घोषणा की कि 'समूचे भारत में अंग्रेजों की कुल सख्या डेढ़ लाख से अधिक नहीं है, यदि आप दृढ़ सकल्प हो तो भारत से ब्रिटिश सत्ता को एक दिन में उखाड़-फेंक दिया जा सकता है।' मराठा क्रान्तिकारियों की भाँति इन्होंने भी यही नारा दिया कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप प्राण दे देने को तैयार रहे, परन्तु अपने प्राण देने से पूर्व शत्रु के प्राण ले लें। उक्त क्रान्तिकारियों तथा उनके सहयोगियों के प्रयासों से बंगाल में अनेक गुप्त क्रान्तिकारी संस्थाओं की स्थापना की गयी। बंगाल के क्रान्तिकारियों ने 1907 में उस रेलगाड़ी पर बम फेंका जिसमें वहाँ का गवर्नर यात्रा कर रहा था। कुछ काल बाद ढाका के जिला मजिस्ट्रेट को गोली से मारने का भी असफल प्रयास किया गया।

क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन की आग पंजाब में भड़की। वहाँ के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता हरदयाल, सरदार अजीतसिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, भाई परमानन्द तथा उनके भाई बालमुकुन्द आदि थे, जिन्होंने क्रान्तिकारियों को संगठित करने का प्रयास किया। इनसे से अनेक अमरीका गये। वहाँ इन्होंने 'गदर' नामक पत्रिका निकाली और वहाँ रहने वाले भारतीयों में 'गदर आन्दोलन' का प्रचार किया। जब ये लोग भारत वापस आये तो यहाँ उन्होंने सक्रिय रूप से क्रान्तिकारी गतिविधियाँ आरम्भ कीं। यह भी उल्लेखनीय है कि उग्रवादी आन्दोलन के नहर नेताओं की त्रयी बाल-बाल-पाल क्रमशः महाराष्ट्र, पंजाब तथा बंगाल में उत्पन्न हुई थी, तो क्रान्तिकारी भी इन्हीं प्रान्तों की उपज थे।

इसके पश्चात् यह आन्दोलन लगभग भारत के सभी प्रान्तों में फैला और इसका प्रसार 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त होने तक किसी न किमी रूप में चलता रहा। उग्रवाद को ब्रिटिश

सरकार ने दबा दिया था। निरंक को नम्बी अवधि तक कारावास में रखा गया। पंजाब में तारा राजपतराय अपने जीवन के अंत तक उग्रवादी गतिविधियां में जीन रहते हुए गहरी हुए। विपिन चन्द्र पात्र के स्थान पर बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। परन्तु क्रांतिकारियों तथा जातकवादी कार्य-कलाप निरंतर चलते रहे। इनका सबसे महद् रूप चम्पारण आजाद सरदार भगत सिंह सहित क्रांतिकारियों की गतिविधियों में प्रकट होत होते जनत नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के अभियानों तक चलता रहा। यद्यपि महात्मा गांधी ने मध्य और अहिंसा का राजनीति अपनाकर 1920 से निरंतर स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया और हिंसात्मक तथा जातकवादी कार्य-कलापों की भत्सना की थी तथापि उनके प्रमुख आन्दोलन भा क्रांतिकारी हा थे। असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन उग्रवाद के ही गांधीवादी रूप में तो उनके द्वारा निदेशित 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन क्रांतिकारी आन्दोलन के ही रूप में विकसित हुआ। नेताजी सुभाष बोस ने द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में भारत से भागकर जापान से जिस आजाद इन्डिया फौज का संचालन किया था उससे सम्पन्न उनका अभियान क्रांतिकारी एवं जातकवादी आन्दोलन का चरमात्मक रूप था।

भारत में क्रांतिकारी तथा जातकवादी आन्दोलन का प्रथम चरण उग्रवाद ही है जिसका अभ्युत्थ उत्तराखण्डियों की सामाजिक भिन्नावृत्ति की नीतियां व विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। क्रांतिकारी नेता उग्रवाद से एक कदम आगे बढ़ गये थे तो जातकवादी भी क्रांतिकारियों से जगती मजिद पर पहुँच गये। इन सभी आन्दोलनों के उत्पन्न होने के कारण समान थे। अन्तर केवल माधनता तथा मान्यता का था। ज्यादा उग्रवाद तीव्र होने लगा तथा त्यागिता ग्रासका के अत्याचार तथा अत्याचार बढ़ने लगे परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आन्दोलन में भा तात्पर्य जानें लगा। क्रांतिकारी आन्दोलन का शीर्षक महाराष्ट्र बंगाल तथा पंजाब में हुआ परन्तु धीरे धीरे वह भारत के अन्य प्रांतों में भी फैल गया। स्थान स्थान पर अनेक घटनाएँ होने लगी और क्रांतिकारी युवक जिनके संगठित होने लगे। बिन्नी में भी उनके संगठन कार्य करने लगे। वहाँ से वे पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रचार कार्य करने लगे। इस प्रकार 20वीं सदी के अन्तिम दशक से क्रांतिकारियों की गतिविधियां भारत के विभिन्न भागों में बहुत तीव्र हो गयीं।

उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आन्दोलन का आरम्भ 1907 से हुआ जबकि इनाहावाद से स्वराय नामक पत्रिका निकली। 1909 में दूसरी पत्रिका कमयोगी प्रकाशित होने लगी। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में स्थान स्थान पर क्रांतिकारियों के ऊपर सरकार द्वारा किये जाने वाले जुर्माना का जनता में प्रचार करना तथा सरकार की जांचोचना करना था। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रसार बंगाल से हुआ था। रास बिहारी तथा गांधी सायान ने बनारस में विद्रोह की तयारी करनी शुरू की। ये लोग पंजाब के क्रांतिकारियों के साथ भा सम्पर्क बनाए रखने की कोशिश करते रहे। बम बनाना उन्हें यत्न-तन्त्र पहुँचाना सैनिकों में विद्रोह का बीज बोना जानि इनकी गतिविधियां थी। बनारस में इन लोगों ने बिनाह का एक पत्र-पत्रिका रचा। परन्तु यह सफल नहीं हो पाया। इससे सम्पन्न अन्य क्रांतिकारी विनायकराय कापूर हरनाम सिंह सुनील गाहड़ो आदि थे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना बनपुरी पत्रिका की थी जिसके प्रमुख गहरी प. गेदानीय थे। क्रांतिकारी युवकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या धन की थी जिसके बिना वे लोग अपने कार्यक्रम तथा गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकते थे। अतः आरम्भ में उन्होंने उनके धनो योगों के यहाँ डाका चालकर रुपया प्राप्त किया कही-कही चारिया भी की परन्तु उनकी ईमानदारी के उत्पन्न नमून भी मिले हैं। कभी-कभी ये चोरी किये गये धन की पूरा राशि (आना पाइ तक में) का समाद लिख जाते थे और यह प्रतिपाद कर जाते कि सम्बद्ध राशि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर मध्य व्याज के चुका दी जावेगा। बाद में उन्होंने सरकारी खजाने लूटने की योजनाएँ भी बनायीं। उत्तर प्रदेश में तत्काल के पास 1925 के काकरी पड़वत्र में इन्होंने इन का खजाना लूटा। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना थी। इनके सचानक नेताजी

मे से स्वनाम धन्य चन्द्रशेखर आजाद बन्दी नहीं किये जा सके थे । मन्मथनाथ गुप्त¹ भी फासी से बच गये । किन्तु रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशनसिंह तथा अशफाकउद्दौला को फासी हुई । 27 फरवरी 1931 को चन्द्रशेखर आजाद इलाहाबाद के ऐल्फ्रेड पार्क में अपने शत्रु पुलिस अधिकारियों के साथ गोली-युद्ध करते-करते शहीद हुए ।

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम की अवधि में प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् सांविधानिक सुधारों की वार्ता की अवधि में कुछ काल तक क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियाँ मन्द कर दी थी । माण्टफोर्ड सुधारों ने भारत में भारी असन्तोष उत्पन्न कर दिया था । इसके विरुद्ध गांधी जी के सम्पूर्ण नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन छिड़ा । क्रान्तिकारी लोगो में से कुछ इसमें भी शामिल हो गये । परन्तु वे गांधी जी की सत्य व अहिंसा की नीति को क्रान्तिवाद से सगतिपूर्ण नहीं मानते थे । जब असहयोग आन्दोलन काफी उग्र होने लगा तो गोरखपुर के निकट चौरीचौरा में क्रान्तिकारियों ने जो पुलिस याने में हत्याकांड किया (1922), में उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया । इस पर क्रान्तिकारियों को भारी निराशा हुई । दूसरी ओर स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व का एक वर्ग कांग्रेस से पृथक् स्वराज्य दल के रूप में सगठित हुआ, तो क्रान्तिकारियों ने भी पृथक् से अपनी गतिविधियाँ तीव्र कर दी । जो स्वराज्यवादी कौंसिलो में प्रविष्ट हुए उन्होंने सांविधानिक तरीको से माण्टफोर्ड सुधार योजना को सुधारने या समाप्त करने (To mend or to end) की योजना बनायी । परन्तु उनकी योजना सफल नहीं हो सकी । ब्रिटिश सरकार ने भावी सांविधानिक सुधारों के निमित्त साइमन कमीशन नियुक्त किया, जिसका स्वागत भारतवासियों ने काले झंडे से किया । एक बार पुनः सरकार का दमन-चक्र शुरू हुआ । लाहौर में लाला लाजपतराय को पुलिस ने इतना मारा कि कुछ ही समय बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी । 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड तथा उसके समकालीन सरकार के अत्याचारों को न केवल पंजाब अपितु सारा भारत नहीं भूला था । पंजाब तो अब आग-बबूला हो चुका था । वहाँ के प्रमुख तथा चिरस्मरणीय क्रान्तिकारी नेता सरदार भगतसिंह, सुखदेव तथा बटुकेश्वर दत्त एवं साथियों ने एक क्रान्तिकारी दल की स्थापना की । चन्द्रशेखर आजाद भी इस दल में थे । इससे पूर्व क्रान्तिकारियों का दल 'हिन्दुस्तानी गणतन्त्रात्मक सघ' कहलाता था । अब इस दल का नाम 'हिन्दुस्तानी समाजवादी गणतन्त्रात्मक सघ' रख दिया गया । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में समाजवाद शब्द भगतसिंह के मस्तिष्क की उपज था । इससे स्पष्ट हो गया कि यह दल गरीब तथा मजदूर वर्ग का हितैषी था और भारत में साम्राज्यवाद को उखाड़कर समाजवादी अधिनायकवाद कायम करना चाहता था । इस दल के प्रमुख नेताओं ने लाला लाजपतराय की हत्या का बदला लेने की योजना बनायी । बहुत विचार-विनिमय करके अन्त में यह तय हुआ कि पहले लाला जी पर डंडे चलाने वाले गोरे अधिकारियों स्काट तथा सैंडर्स को मारा जाये । इस षड्यन्त्र में सैंडर्स ही मारा गया, स्काट बच गया । इसके बाद केन्द्रीय एसेम्बली में बम फेंकने की योजना बनायी गयी । भगतसिंह व बटुकेश्वर दत्त इसके लिए चुने गये । इन्होंने तय किया कि बम फेंककर भागा नहीं जायेगा, बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा ताकि सारा भारत तथा दुनिया जान जाये कि क्रान्तिकारी कैसे साहसी वीर हैं । 8 अप्रैल 1929 को यह षड्यन्त्र किया गया । भारत की तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा में जब दर्शक दीर्घा से भारत माता के इन दोनों लालों ने बम फेंका तो सभा भवन धमाके से गूँज उठा । लोग सन्न व त्रस्त थे, उधर से दोनों क्रान्तिकारियों ने 'इक्लाव जिन्दावाद' तथा 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाये और जो परचे फेंके उनमें साम्राज्यशाही के विनाश के लिए जनता से अपील की गयी थी । दोनों युवक फासी के लिए तैयार हो गये थे । मामला चला और बाद में सुखदेव भी बन्दी कर लिया गया ।

¹ विगद् वृत्तान्त के लिए देखिए, मन्मथनाथ गुप्त, 'भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास', 1966 ।

मुकद्दम की मुनवाई के बाद तीना को फासी की सजा सुनायी गयी। सारे भारत के नेताओं ने फासी की सजा रद्दवाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हो रहा था तो कुछ नेता चाहते थे कि उसके बाद फासी दी जाये। परन्तु यह कुछ न हुआ। 23 मार्च 1931 को गुप्त रूप से इन तीन युवकों को फासी दी गयी और उनकी लाशें तक सरकार ने गुप्त रूप से जता दी और भस्मी सतवज नगी में फेंकवा दी। परन्तु उनकी अत्यन्त तो भारत की करोड़ों जनता ने हृदय से की और उनके रक्त की एक एक बूँद भारत की मिट्टी में ममा चुका है और आत्मा अमर हो चुकी है।

आजाद और भगतसिंह सहश क्रांतिकारियों की विदार्थ का वष भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की अवधि में गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आन्दोलन का वष था। परन्तु इन दोनों घटनाओं के मध्य परस्पर सम्बन्ध वास्तविक नहीं हो पाया। कांग्रेस आन्दोलन मूल रूप से साविधानिक सुधारों की दिशा में निर्दिष्ट रहा। साविधानिक मांगों की अपूर्णता तथा उपेक्षा होने पर आन्दोलन तीव्र हो जाना था। फिर वार्तान्ता का सिनसिना बनता था। उधर क्रांतिकारियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र उन्हें फासी या गम्भी अवधि के कारावास दंड दिये जाने पर देश भर में भावात्मक सहानुभूति दर्शायी जाती थी। परन्तु क्रांतिकारी लोगों का रक्त उमरना रहता था। वे इन घटनाओं से दुःखी या निराश नहीं होते थे। प्रत्युत शहीदों के वनिदान उन्हें और अधिक प्रोत्साहन देते थे। भूमिगत पड़यंत्रों व निर्माण शास्त्र संग्रह आदि के कार्य में करते रहते थे। सरकार उनके प्रति पर्याप्त सजग रहती थी। इस पर भी विनाश रूप में वगान के अतन्त अन्त क्रांतिकारियों ने अनेक अग्रज अपसरा की हत्यायें कीं। 1931 के बाद कुछ वर्षों तक वगान में आतंकवाद का रूप बहुत उग्र हो चुका था। वगान में अनन महिला क्रांतिकारिणियाँ भी सक्रिय रूप से क्रांति में भाग लिया और गम्भी गम्भी जन की सजायें भुगती। जनियावाना वाग हत्याकाण्ड का प्रमुख पात्र जनरल डायर तथा उस हत्याकाण्ड का आदेश देने वाला गवर्नर ओ डायर पञ्जाबिया के आख में खटकते रहे। इसका बदला ऊधम सिंह ने लिया। वह पन्ने के लिए गन्त गया था। वहाँ उसने जनरल डायर को गाली से मारकर वृष्टि की सास ली। उसे इन्गण्ड की जेल में खूब सताया गया और जेल में फासी दी गयी।

उनके उत्तिरिक्त देश के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी युवक सक्रिय बन रहे। भारत में 1935 के शासन अधिनियम के अन्तगत प्रांतीय स्वायत्तगसी सरकारें बनीं। अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमंडल थे। ये सरकारें लगभग 2 वर्ष चलीं। सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। अक्टूबर में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की इच्छा के विरुद्ध भारत को युद्ध का एक पक्ष घोषित कर दिया तो कांग्रेस इससे रफ्त हो गयी। उसने प्रांतीय मन्त्रिमंडलों को त्याग पत्र देने का आह्वान किया। 1940 में गांधी जी का यत्तिगत सत्याग्रह आरम्भ हुआ। अब क्रांतिकारी भी और अधिक सक्रिय हो गये। 1941 में जापान भी घुरी राष्ट्रा के साथ युद्ध में साभीदार बन गया। उसने वर्मा तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्देशित भारतीय सेना के जिन सैनिकों ने दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में जापान के समक्ष समपण कर लिया था उन्हें रासविहारी घोष ने आजाद हिन्द फौज के नाम से संगठित किया। इसी बीच नेताजी सुभाष चन्द्र वास जा उस समय तक कांग्रेस दल के वामपंथी नेता थे ने फारवांड ताक दल की स्थापना की। वे सरकार द्वारा नजरबन्द कदी बनाये गये थे। एक दिन वे बड़े रहस्यमय ढंग से पुनिस के चगुन से निकल भागे। वंश बदलकर अनेक मुसीबतें सहत हुए वे काबूल के रास्ते जमनी पहुँच। वहाँ उन्होंने आजाद हिंद सेना संगठित की। 1943 के जून मास में वे जापान पहुँच गये। राम विहारी के नेतृत्व में आजाद हिन्द सेना नियत सिद्ध हान गयी थी। नेताजी के जापान पहुँचने पर यह सेना पूर्णतया उनके नियन्त्रण में रख दी गयी। उन्होंने

¹ यद्यपि यह घटना स्वतन्त्रता प्राप्ति हो जाने के बाद हुई तथापि इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रांति कारियों की भावुकता कितनी तीव्र थी।

इस सेना में नई जान फूँक दी। यद्यपि यह कार्य-कलाप जापान व जर्मनी में चले, तथापि यह धारणा मिथ्या है कि सुभाष बाबू भारत में जापानी साम्राज्यवाद चाहते थे। वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही का अन्त चाहते थे और भारत को किसी भी विदेशी आधिपत्य से मुक्त कराना वे अपना परम कर्तव्य मानते थे। निस्सन्देह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे जापान व जर्मनी की सहायता चाहते थे। जर्मनी व जापान की पराजय के साथ-साथ नेताजी की भी 1945 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। आजाद हिन्द फौज के अफसरो के ऊपर मुकदमा चलाया गया। परन्तु चूँकि अब भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता की बातें काफी प्रगति से बढ़ रही थी, अतः इन प्रमुख अधिकारियों को कठोर दंड नहीं मिला, बल्कि कालान्तर में वे मुक्त हो गये। उन्हीं के साथ आजाद हिन्द फौज के सभी बन्दी सैनिक भी छूट गये।

दूसरी ओर 1942 में जब गांधी जी ने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का सूत्रपात किया तो कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता बन्दी कर लिए गये। नेतृत्वहीन जनता आग-बबूला हो गयी। सचमुच 1942 में समूचा भारत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रान्तिकारी हो गया था। अहिंसा की नीति लगभग समाप्त हो गयी। अब कांग्रेस के नेता, युवक एवं पूर्व के क्रान्तिकारी भी सभी क्रान्तिकारी हो गये। सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करना, तार काटना, इमारतों को जलाना आदि का सिलसिला प्रारम्भ हो गया। सरकार ने दमन के कोई साधन नहीं छोड़े। परन्तु क्रान्ति नहीं रुकी। कई स्थानों पर क्रान्तिकारियों ने समानान्तर सरकारें तक अस्थायी रूप से स्थापित भी कर लीं। सारा देश क्रान्ति की लपटों के साथ प्रज्वलित हो रहा था। दूसरी ओर सरकार का दमन-चक्र भी उसी गति से बढ़ रहा था। इस दृष्टि से 1942 के आन्दोलन ने एक बार पुनः क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहित किया। अनेक कांग्रेसी युवक भी क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी कार्य-कलापों में सक्रिय हो गये। भूमिगत पड्यत्र भी हुए। उद्देश्य यह था कि सारे प्रशासनतंत्र को क्षत-विक्षत कर दिया जाये और अंग्रेजों को दरअसल भारत से अपना आधिपत्य छोड़कर चले जाने को विवश किया जाये। अनेक क्रान्तिकारी नेताओं को बन्दी करने के लिए बड़े-बड़े पुरस्कार घोषित किये गये थे, परन्तु सरकार सफल नहीं हो पाई। ब्रिटिश शासन के आधीन भारत की नौकरशाही का द्विविध कार्य भाग रहा। कुछ तो पूर्णरूप से अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहे। कुछ को आन्दोलन के साथ सहानुभूति थी किन्तु अपनी रोजी बनाये रखने के लिए उन्होंने बड़ी सावधानी से ही सरकार का साथ दिया। विश्व-युद्ध की तीव्रता के बावजूद सरकार ने आन्दोलन के क्रान्तिकारी स्वरूप पर नियंत्रण पा लिया और उसे दवाने में पशु-बल का भी पूरा प्रयोग किया। सचमुच यह एक प्रकार का देशव्यापी क्रान्तिकारी आन्दोलन था। विश्व-युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार पर विजयी मित्र-राष्ट्रों का दबाव पड़ा, इंग्लैंड की अपनी स्थिति भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसी के साथ वहाँ के निर्वाचनों में श्रमिक दल की सरकार बनी। भारत का रोष किसी भाँति कम नहीं हो गया था। अतः 1945 में इंग्लैंड ने भारत के कांग्रेसी नेताओं को जेलों से रिहा किया और स्वतन्त्रता के लिए बातों का सिलसिला चलाया। अन्ततः अंग्रेजों को भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा था। अतः उन्हें तभी चैन मिला जबकि वे भारत को खंडित करके यहाँ से गये। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो निस्सन्देह इसकी प्राप्ति का सेहरा कांग्रेस के सिर पर बसा। परन्तु भले ही क्रान्तिकारी आन्दोलन को यह श्रेय नहीं मिला, इसलिए उसे असफल ही कहा जाता है।

क्रान्तिकारी आन्दोलन की असफलता के कारण

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में एक ओर राष्ट्रीय कांग्रेस वैधानिक ढंग से अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन चलाकर भारतीय स्वतन्त्रता के लिए सघष करती रही, तो दूसरी ओर देश के भावुक युवा वर्ग ने जिन्हें क्रान्तिकारी कहा जाता है, अपना आन्दोलन तथा गतिविधियाँ जारी रखीं। उनका आन्दोलन बीसवीं सदी के आरम्भ से स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने तक विभिन्न

चरणा में तथा विविध तरीका से चेतना रहा। इसमें दा राय नहीं हो सकती कि जितना त्याग तथा उत्साह का प्रयोग इन क्रांतिकारियों ने देश का साम्राज्यवाद के अत्याचार तथा तमन के शासन से मुक्त कराने के लिए किया उनका आतिवादी तथा माविधानिक तरीका पर विश्वास रखने वाले कांग्रेस के बन्त कम नेता कर पाये। 1947 में देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय महात्मा गांधी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुआ। क्रांतिकारी गहिरा नेता तथा युवक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये। सम्भवतः यदि उनके ही कार्य के साथ ही शासन को भारत से हटाना पड़ता तो आज भी भारत की राय व्यवस्था कुछ उसी ही भाँति की होती। वह वही साम्यवादी अधिनायकत्व की तरह की होता या फासावादी तग की यह विवेचन करना यहाँ पर अप्रासांगिक तथा निरवयव है। हम यहाँ केवल उन कारणों तथा स्थितियों का विवेचन करते हैं जो क्रांतिकारी आन्दोलन की असफलता के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

पहला त्रिमी भी स्वतंत्रता आन्दोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए सघन संगठन बानी संस्था का सुसंगठित तथा दयायी होना चाहिए। उसका एक निश्चित कार्यक्रम ही नहीं अपितु उसके मिशना तथा नीतियों के पीछे एक क्रमबद्ध विचारधारा भी होनी चाहिए। भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन में इन दोनों बातों की कमी मन्द प्रती रही।

दूसरा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन तभी सफल हो सकता है जबकि आन्दोलनकारी संगठन की सम्पूर्ण या अधिकांश जनता का समर्थन तथा महानुभूति प्राप्त हो। परन्तु क्रांतिकारी आन्दोलनकारियों को ऐसा समर्थन का लाभ प्राप्त नहीं था। क्रांतिकारी स्वयं में अद्भुत साहस व त्याग की भावना रखते थे उनके प्रचार साधन गुप्त तथा भूमिगत थे। उन्हें न तो निश्चित वग का समर्थन मिला न धनी वग का। कमठ क्रांतिकारियों में अधिकांश नेता अनिश्चित तथा गरीब वग के थे। उन्हें अपने कार्य-कलापों के लिए धन नहीं मिलता था अतः वे दूर पाठ का कार्य करते थे। इसलिए भी उनकी गतिविधियाँ का नाम समर्थन नहीं मिल पाया।

तीसरा भाग्न की जनता का विगत जग क्रांतिकारी माधना की बुद्धिमत्ता पर विश्वास नहीं रखता था। भाग्न का जनता स्वभाव गति प्रमी है। दूसरी ओर कांग्रेस की अहिंसात्मक मत्याग्रह की नीतियाँ पर्याप्त लोकप्रिय होती जा रहीं थी। कांग्रेस का नवतत्व दंग के धनी विद्वान् तथा निश्चित वग कर रहे थे। उनका प्रचार भी जनता में व्यापक हो चुका था। स्वयं कांग्रेस के नवतत्व को क्रांतिकारियों से बहुत महानुभूति नहीं थी। इसलिए क्रांतिकारी आन्दोलन छुट्ट पड़ निमात्मक घटनाओं तक ही सीमित रहा।

चौथा क्रांतिकारियों के साधन हिंसात्मक थे। परन्तु हिंसात्मक क्रान्ति के लिए उनके पास न तो बतने गस्त्र थे न ऐसी प्रशिक्षित सेना जो कि सुदृढ़ साम्राज्यवादी पुलिस के सत्ता का सामना कर सकती। अतएव सरकार ने जहाँ तहाँ उन लोगों को पकड़ लिया और भारी से भारी मजबूत दी।

पाँचवाँ क्रांतिकारियों के अन्तर्गत भी सभी लोग ऐसे साहसी तथा कमठ व्यक्ति नहीं थे जो कठिन से कठिन परीक्षा में भी खर उतरते। बन्धा हुआ यह कि जब वे लोग पड़यंत्र में पड़े जाते तो उनमें से कुछ मुखरित बन जाते और गुप्त भन्ने का भंडाभाँ कर देते थे।

अंतिम महानवम क्रांतिकारी सुभाष चन्द्र बोस ने निताय विश्वयुद्ध की अवधि में आजाद फिज फौज संगठित कर ली थी। उनकी लोकप्रियता भी जनता में काफी बढ़ चुकी थी। किन्तु उनकी असामाजिक मृत्यु ने एक बार पुनः क्रान्तिकारी आन्दोलन की कब्र गहो दी। इसके पश्चात् स्वतंत्रता आन्दोलन पुनः कांग्रेस के एकमात्र नवतत्व में सफल हुआ।

मूल्यांकन

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की सफलता का मुख्य श्रेय कांग्रेस दल तथा उसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ है परन्तु इस आन्दोलन में क्रान्तिकारियों तथा आतंकवादियों

के योगदान की उपेक्षा करना उन महान् देशभक्त युवकों के प्रति घोर अन्याय होगा जिन्होंने भावुकता वश ही सही, अन्याय, दमन तथा अत्याचारपूर्ण विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने में किंचित मात्र भी सकोच नहीं किया। देश तथा जनता की निस्स्वार्थ सेवा करने का जो प्रबल उत्कठा इन वीर शहीदों के हृदय में बनी रही और जिस अदम्य उत्साह से इन लोगों ने जीवन समस्त सुखों एवं अपने प्राणों तक को देश की आजादी के समक्ष तुच्छ समझ कर उन्हें आजादी प्राप्त करने के साधनों में ही लगा दिया, इसके प्रमाण इतिहास में बहुत कम मिलेंगे। इन भावुक देश के लालों ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता भिक्षा की भाँति माँगी नहीं जाती बल्कि उसे सघर्ष करके प्राप्त किया जा सकता है। विश्व की अधिकांश स्वतन्त्रता क्रान्तियाँ ऐसे ही सघर्षों द्वारा सफल हुई हैं। नेताजी सुभाष बोस का नारा था 'तुम मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊँगा।' इसका सार यही था कि आजादी बिना रक्तमय क्रान्ति के नहीं मिल सकती।

इसका यह अभिप्राय तो नहीं है कि गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के साधनों पर चलने वाले तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने त्याग नहीं किया था, अथवा गांधीवादी आन्दोलन देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के निमित्त बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। परन्तु यह कहा जा सकता है कि एक मुट्ठ तथा शक्तिशाली विदेशी साम्राज्यशाही के चंगुल से देश को आजाद कराने के गांधीवादी साधनों की सफलता कूर्मगति की सिद्ध होती। ब्रिटिश सरकार निरन्तर वैधानिक मागों को स्वीकार करने में ढुल-मुल की नीति अपना रही थी, वह कभी भी भारत को स्वतन्त्रता नहीं देना चाहती थी। यही कारण था कि 1942 की गांधीवादी क्रान्ति तक क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन में परिणत होने लगी। इस बात में भी सन्देह है कि यदि द्वितीय विश्वयुद्ध न होता और उसमें इंग्लैंड की स्थिति इतनी अधिक निर्बल नहीं हो जाती तो ब्रिटिश सरकार 1947 में भी भारत को स्वतन्त्र नहीं करती। यह तो परिस्थितियों की बेवशी थी कि अंग्रेजों को भारत को स्वतन्त्रता देनी पड़ी, परन्तु स्वतन्त्रता देते हुए भी वे अपनी कूटनीतिक चालों से बाज नहीं आये और देश का विभाजन करके यहाँ की शान्ति को हमेशा के लिए खतरे में डाल गये। गांधीवादी अहिंसात्मक आन्दोलन की दूरदर्शिता इसी तथ्य से सगति रखती है कि भारत सदृश निर्धन तथा निःशस्त्र जनता वाले देश की जनता यदि हिंसात्मक क्रान्ति का मार्ग अपनाती तो भारी रक्तपात होता और उसके पश्चात् भारी अव्यवस्था का वातावरण बन जाता इसलिए शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक आन्दोलन द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य बना रहा।

जहाँ तक क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलनकारियों की महत्ता का प्रश्न है, उनका उद्देश्य भी देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना था, और वाद में जैसा कि सरदार भगतसिंह सदृश नेताओं के विचारों से प्रकट होता है, वे देश में सर्वहारावर्गीय अधिनायकवादी समाजवाद की स्थापना चाहते थे। देश-प्रेम उनके रक्त की एक-एक बूँद में भरा था, अन्याय तथा अपमान के समक्ष घुटने टेकना तो उनके लिए मौत के मुह में जाने के सदृश था। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी कि आजादी प्राप्त हो जाने पर देश की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का क्या विधान होगा। वे किसी राजनीतिक विचारधारा के अनुगामी नहीं थे, प्रत्युत् उनका प्रथम उद्देश्य विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना था और सम्भवतः इसमें सफलता प्राप्त हो जाने पर ही वे भविष्य में शासन-प्रणाली के स्वरूप का सम्योचित समाधान हो जाने का विश्वास रखते थे।

क्रान्तिकारियों को भले ही अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिली, तथापि उन्होंने दो महान् योगदान किये। पहला, उन्होंने विदेशी शासकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अन्यायपूर्ण तथा पशुबल पर आधारित साम्राज्यवाद कभी भी टिक नहीं सकेगा। किसी न किसी दिन उसे एक देशव्यापी विद्रोह के समक्ष घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि शासित जनता की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। यही कारण था कि शासक लोग कांग्रेस की वैधानिक मागों के समक्ष धीरे-धीरे झुकने लगे थे। दूसरा, क्रान्तिकारियों का और अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान यह था कि

उन्होंने देश की जनता में क्रांतिकारी चेतना उत्पन्न करने में मदद दी। स्वयं गांधी जी तथा उनके अन्य काग्रमा अनुयायी तक क्रातिवाद की गंगा में प्ररित होना नग। काग्रस का वामपथ क्रांतिकारी आन्दोलन का ही उपज माना जा सकता है। असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन से सम्बद्ध हिंसात्मक घटनायें क्रांतिकारी आन्दोलन से प्रभावित थी 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में करा या मरो का नारा बुनद हो गया था और गांधी जी के अहिंसा पर जोर देने के बावजूद यह आन्दोलन बहुत अधिक मात्रा में क्रान्तिवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित रहा। यदि गांधीवादी आन्दोलन ऐसे क्रातिवाद का सहारा न लेता तो सम्भवतः भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता कुछ और अनिश्चित अवधि के लिए टन जाती।

जहाँ तर त्याग तथा आत्म बलिदान का प्रश्न है वसम् दो राय नहीं हो सकती कि क्रांतिकारियों के त्याग तथा आत्म बलिदान की समता में अन्य लोग नहीं ठहर सकते। इनके साधन उग्र या समयोचित भन ही न ठहरे हों परन्तु उहान जेकेय कनाप किय उहें अनतिक नहा माना जा सकता यदि जयाय और अत्याचार का बन्ना हिंसा द्वारा किया गया तो इमे अनतिक नहा कहा जा सकता। यदि कोई अधिकारी अपनी क्षमता का अनुचित लाभ उठाकर इरादतन अयाय अत्याचार करे और उसे दड देने के लिए सभी जयायपूण तथा वधानिक तरीका को सीन मुहर कर दिया जाय और उस आतंकपूण गग में कोई भावुक व्यक्ति दड दे तो क्या इस भी अनतिक कहा जायगा? यहाँ काय आतंकवातिया न किय परन्तु व्यक्तिगत स्वाथसिद्धि के लिए नहीं बल्कि देश सेवा की भावना से प्ररित हाकर और साहसपूण तथा वीरोचित ढग से। ऐसे साहसपूण कायों का अनतिक अराजनीतिक या जयायपण काय कहा जाय तो फिर नतिक राजनीतिक या जयायपूण काय और क्या हो सकत हैं?

मसार कमक्षण है। मनुष्य जम नेता है कुछ काय करता है और मर जाता है या गहीद हो जाता है। वह भावा पीठिया के लिए इतिहास की वस्तु बन जाता है। भावी पीठिया को उसके कायों से कुछ भनी या बुरी गिक्षायें प्राप्त हाती है। यह भावी पीठी का कतव्य है कि वह प्रत्यक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति के काय-कनापा का सही मूल्याकन करे। भावा पीठिया को कवन कुछ आदर्शों के भावावग में नहीं जा जाना चाहिए बल्कि ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वा का सही मूल्याकन करके उह समुचित सम्मान तथा श्रद्धाजलि अर्पित करनी चाहिए। हम महान् गहीदा की स्मृति को और अधिक अमर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इनके काय-कनापा के सम्बध में प्रचुर साहित्य का निमाण मग्रहानया की यवस्था ममोरियन उनके परिवारा की पीठिया के लिए समुचित सहायता आदि की भरपूर व्यवस्था करना भारत की वतमान पीठी का परम कतव्य है। यही इन गहादा के प्रति देश की सच्ची श्रद्धाजलि होगी। इनके जीवन वृत्त सही पंगिपेश में भावी युवा पीठी के समक्ष पाठ्य विषया के रूप में प्रस्तुत किये जान चाहिए ताकि उनके जीवन तथा काय नये भारत का निर्माण करने वाले युवका के लिए प्ररणास्पद बने रहें। -

प्रश्न

- 1 भारत में क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आन्दोलन में सन्निहित मायनाओं पर प्रकाश हालिए।
- 2 भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का विकास कैसे हुआ? और उसमें बंगाल उत्तर प्रन्थ और पंजाब के नवयुवका का क्या योगदान रन?
- 3 हम परिस्थितिया की विवेचना कीलिए जिनके परिणामस्वरूप भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन की सफलता प्राप्त नन हो सकी।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता का अभ्युदय (RISE OF MUSLIM COMMUNALISM)

धर्म की दृष्टि से भारत एक बहुल-सम्प्रदायी देश है, किन्तु भारतीय राष्ट्रीयता में हिन्दू तथा मुस्लिम सम्प्रदायवाद का महत्त्वपूर्ण कार्यभाग रहा है। 13वीं शताब्दी से भारत में मुसलमानों का राजनीतिक आधिपत्य स्थापित हुआ था और अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक उनका प्रभुत्व बना रहा यद्यपि राजपूतों तथा मराठों ने समय-समय पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए मुसलमान शासकों से लोहा लिया तथापि वे मुसलमान शासकों को निकाल भगाने या पराजित कर देने में सफल नहीं हुए। 18वीं शताब्दी तक यह स्थिति थी कि मुसलमान लोग पर्याप्त अधिक सत्ता में भारत में बस गये थे और कुछ शासकों के काल में बहुत से हिन्दुओं को भी उन्होंने इस्लाम धर्म मानने को विवश किया था। भारत के मुसलमान अपने को विदेशी नहीं अपितु भारतीय ही समझते रहे। उनका उद्देश्य यहाँ की शासन-सत्ता अपने हाथ में रखना तथा भारतीय भूमि में स्थायी रूप से निवसित हो जाना था। अतः यूरोपीय लोगों की भाँति उनमें भारत का आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण करने की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का कोई विचार नहीं रहा। वास्तविकता यह थी कि भारत के विभिन्न भागों में हिन्दू तथा मुसलमान परस्पर मिल-जुलकर रहते थे। यद्यपि धर्म के नाम पर कभी-कभी उनके मध्य संघर्ष हो जाते थे, तथापि राष्ट्रीय जीवन में साम्प्रदायिक पार्थक्य की भावना का प्रायः अभाव था।

अंग्रेज लोगों ने जब भारत में अपना शासन तथा प्रभुत्व स्थापित किया तो वे मुसलमान शासकों के ही उत्तराधिकारी बने थे। अतः वे मुस्लिम सम्प्रदाय को सदैव शका की दृष्टि से देखते थे। 1857 की क्रान्ति ने उनके मुस्लिम विरोध को और अधिक पुष्ट कर दिया था। उन्हें मुसलमानों से हमेशा यह भय बना रहा कि कहीं वे अपनी खोयी हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सक्रिय न हो उठें। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में टर्की के ऊपर यूरोपीय राष्ट्रीय कुचक्रों की नीति के परिणामस्वरूप अरब में जो बहावी आन्दोलन छिड़ा था उसका प्रभाव भारत के मुसलमानों के ऊपर भी पड़ा था। भारतीय मुसलमानों पर इस्लाम धर्म की रक्षा के हित में भी बहावी आन्दोलन का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यद्यपि बहावी आन्दोलन मुरयत धार्मिक प्रवृत्ति का था, तथापि इसने भारतीय मुसलमानों में आर्थिक दृष्टि से एक दलित वर्ग होने की भावना विकसित की। उन्होंने बगल में कई सर्वहारा आन्दोलनों में भाग लेकर अपनी आर्थिक कठिनाइयों की माँग व्यक्त की। परन्तु ब्रिटिश शासकों ने इन आन्दोलनों को कुचलने में कोई कमी नहीं रखी। इसके कारण अंग्रेज शासकों का भारतीय मुस्लिमों के विरुद्ध सन्देह और अधिक बढ़ गया। 1857 की क्रान्ति में अंग्रेज लोगों ने हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों को ही अपना वास्तविक शत्रु माना। इस कारण ब्रिटिश शासकों ने भारतीय मुसलमानों को शिक्षा, नौकरी तथा आर्थिक क्षेत्रों में भी उपेक्षित ही रखा। हिन्दुओं ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने में काफी प्रगति की, परन्तु मुसलमानों ने इस दिशा में कोई अभिरुचि नहीं दर्शायी। मुसलमानों को सेना तथा अन्य असैनिक (civil) सेवाओं से वंचित रखा गया। बहुत से मुसलमान अनेक कुटीर उद्योग-धन्धों पर निर्भर रहकर अपनी आजीविका कमाते थे। परन्तु अंग्रेजों की भारत में कुटीर उद्योगों को नष्ट करने तथा भारत का आर्थिक शोषण करने की नीति ने इन गरीब मुस्लिम वर्गों को बड़ा धक्का पहुँचाया। संक्षेप में, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरम्भिक वर्षों में ब्रिटिश शासकों की नीति भारतीय मुसलमानों

को गिना प्रशासन आर्थिक यावसायिक आदि सभी क्षेत्रों में उपनिवेश रणन तथा दबाये रक्ता की बनी रही। यद्यपि 1858 में महाराना विकारिया को घोषणा में कहा गया था कि सावजनिक पत्र पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार घम जाति जाति का भेदभाव नहीं करेगी तथा कि भारतीय मुसलमानों के सम्बन्ध में इस घोषणा का पूर्णतया उपयोग का गढ़। इस प्रकार भारत का मुस्लिम जनता में एक उपनिवेशवादी जनसमूह हान की चेतना उत्पन्न हाना स्वाभाविक था।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति में अंग्रेजों का हाथ

यह कथन मबया मत्य कि यदि भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति का एक प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की नीति थी तो भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास का पूर्ण दायित्व भी ब्रिटिश शासन पर था। उनकी यह नीति समय-समय पर जगमगाता हुआ म प्रयुक्त हाना रही।

(1) उपेक्षा की नीति द्वारा साम्प्रदायिकता की भावना का विकास—प्रारम्भ में अंग्रेजों ने मुसलमानों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रवर्तन राजा के रूप में मानकर उन्हें हर दृष्टि से उपलब्ध रखा (इसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं)। उसका यह परिणाम यह कि भारतीय मुसलमानों में एक असंतुष्ट तथा उपनिवेशवादी जनसमूह बग हान की चेतना उत्पन्न हाने लगी। उन्होंने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन नीति के कारण हिन्दू बहुसंख्यक बग उत्पन्न कर रहा है परन्तु मुस्लिम सम्प्रदाय की उपेक्षा की जा रही है। यद्यपि इसका दाप हिन्दू बग पर नहीं मड़ा जा सकता था तथापि मुस्लिम बग में हिन्दुओं के प्रति न्य तथा ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। जा हिन्दू मुसलमान परस्पर मित्र जुगुन रहते थे और यहा तक कि 1857 के विद्रोह में जिहाद परस्पर मित्र अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रान्ति की थी उनमें परस्परिक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करने का दायित्व ब्रिटिश शासन नीति पर ही जाना है क्योंकि इस क्रान्ति के पश्चात् ब्रिटिश शासन ने एक बग को प्रोत्साहन देकर दूसरे की उपेक्षा की। इसके कारण मुसलमानों में साम्प्रदायिकता की भावना उत्पन्न हान लगी।

(2) विलियम हटर का काव—1871 में सर विलियम हटर की पुस्तक *The Indian Musalmans* में व्यक्त विचारों ने भारतीय मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश नीति में आमूल परिवर्तन करने की नीति व्यक्त की। इस अवधि में भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृति हा रही थी। अंग्रेजों को ऐसा आभास हुआ कि पश्चात्य गिना के प्रभाव से भारत की हिन्दू जनता के गिनिन बग का राष्ट्रीय चेतना विकसित होती जा रही है। यदि यन्ने प्रगति जारी रही और मुस्लिम जाति भी इसमें शामिल हो गई तो भारत की समस्त जनता की संगठित राष्ट्रीय भावना ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर कुठाराघात करने में सफल हो जायेगी। ब्रिटिश शासन की नौकरगानी के जनक अय बग भी ऐसा अनुभव करने लग था। जत विलियम हटर ने यह दशाया कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का जवरुद्ध करने के हेतु आग मुस्लिम सहयोग आवश्यक है। इसका प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश नौकरगानी जो पहले भारतीय मुसलमानों को गका की दृष्टि से देखती थी अब मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वचन हो गई।

(3) सर सयद अहमद खा तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता—भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का जनक सर सयद अहमद खा को माना जाता है। परन्तु यह बात विचारणीय है कि सर सयद कहां तक इसका लिए उत्तरदायी हैं। उनका नाम एक सम्प्रदाय मुस्लिम परिवार में हुआ था और उन्होंने पश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति का गहन अध्ययन किया था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वे अनेक उच्च पत्र पर नियुक्त हुए थे। भारत के अय आरम्भिक काग्रेस नेताओं का भाति वे पश्चात्य शिक्षा संस्कृति एवं ब्रिटिश राज के भक्त थे। साथ ही उनमें राष्ट्रवाद भावनाएं भी बूट-बूटकर भरी हुई थी। वे भारतीय जनता के मध्य राष्ट्रीय एकता नाने तथा भारतवासियों के पिछड़पन को दूर करने की तीव्र आकांक्षा रखत थे। उन्होंने यह अनुभव किया

कि भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण उनकी पुरातनपन्थी सकीर्णता तथा रुढ़िवादिता थी। अतः मुस्लिम जनसमाज को पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् उनका एकमात्र मिशन मुस्लिम जन-समुदाय की सेवा करना तथा उन्हें पिछड़ेपन के गर्त से उठाना हो गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अलीगढ़ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। उनके प्रयासों से अलीगढ़ में मुहम्मदन ऐंग्लो ओरियन्टल कालेज की स्थापना की गई जो बाद में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की भाँति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका उद्देश्य मुस्लिम जनता में पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना था। सर सैयद ने ब्रिटिश नौकरशाही के अत्याचारों की घोर निन्दा की। कांग्रेसी नेताओं की भाँति वे भारतीयों को विधान परिषदों में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दलील देते थे। यह कहना भी गलत है कि उन्हें हिन्दुओं के साथ द्वेष था। उनकी धारणा यह थी कि 'हिन्दू तथा मुसलमान भारत की दो आँखें हैं।' हिन्दू शब्द साम्प्रदायिकता का प्रतीक नहीं है अपितु हिन्दू के अन्तर्गत प्रत्येक भारतवासी (मुसलमान भी) शामिल है। अतः राष्ट्रीय उत्थान के हित में हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा सहयोग आवश्यक है। कांग्रेस की स्थापना के काल तक सर सैयद अहमद खॉं एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता बने रहे। साथ ही मुस्लिम दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया। परन्तु कांग्रेस की स्थापना होने पर जहाँ जहाँ सर सैयद की विचारधारा परिवर्तित होने लगी और कालान्तर में वे एक कट्टर हिन्दू विरोधी अथवा साम्प्रदायिकतावादी बन गये। अकस्मात् ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? क्या हिन्दू सम्प्रदाय के किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष ने उन्हें कोई आघात पहुँचाया था? अथवा क्या हिन्दू सम्प्रदाय के नेताओं ने मुसलमानों के विरुद्ध किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भेदभाव की नीति अपनायी थी? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए भी ब्रिटिश शासन की नीति उत्तरदायी है।

(4) मि० वेक तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता—मुहम्मदन ऐंग्लो ओरियन्टल कालेज के प्रिंसिपल पद पर मिस्टर वेक को नियुक्त किया गया था। वेक ब्रिटिश साम्राज्यशाही का सच्चा भक्त था। वह विलियम हटर की नीति का समर्थक था। यदि सर सैयद के दिमाग को पलटने में उसे सफलता न मिली होती तो राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप ही बदल जाता। सर सैयद वास्तव में हिन्दू विरोधी नहीं, अपितु ब्रिटिश विरोधी थे। सचमुच में उनके जीवन का मिशन मुसलमानों को अपनी अधोगति से ऊपर उठाना था। परन्तु वेक ने उनके इस मिशन की सफलता के साधन के रूप में उनके ऊपर ऐसा जादू डाला कि वे हिन्दू-विरोधी हो गये। उसने सर सैयद को यह समाधान कराया कि मुसलमानों का उत्थान आंग्ल-मुस्लिम सहयोग से ही हो सकता है। मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हैं। राष्ट्रीय कार्यकलापों में कांग्रेस एक हिन्दू सत्स्था के रूप में विकसित हो रही है जिसका उद्देश्य भारत में हिन्दू-राज स्थापित करना है। भारतीय राष्ट्रवाद के अन्तर्गत मुसलमानों के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा सर सैयद को इस धारणा पर विश्वास दिलाना तथ्यों के विल्कुल विपरीत था, क्योंकि प्रारम्भ से ही कांग्रेस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बना रहा और कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव में हिन्दू राज या मुस्लिम विरोध की तनिष्ठा गन्ध नहीं थी, तथापि अंग्रेज लोगों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों को भड़काने में सर सैयद के ऊपर प्रभाव डालने में सफलता प्राप्त कर ली। यही से अंग्रेजों की भारतीय राष्ट्रीयता के अन्दर 'फूट डालो और शासन करो' की नीति का सफल श्रीगणेश हुआ।

यहाँ पर यह कहना असंगत नहीं होगा कि यदि ब्रिटिश नौकरशाही तथा मि० वेक सर सैयद के ऊपर अपना जादू चला देने में सफल न होते तो सर सैयद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के एक महान् नेतानी मित्र होते। वे मुस्लिम जन-समुदाय का उत्थान करने वाले जनमेवक ही नहीं रहते अपितु समस्त भारत के राष्ट्रीय नेता बनते। परन्तु उन्हें यह समाधान करा दिया गया कि

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में जिस रूप की प्रतिनिध्यात्मक शासन संस्थाओं की मांग करती आ रही है यदि उसे मान लिया जायगा तो भारतीय विधान सभाओं में हिंदूओं का न केवल बहुमत हा रहेगा अपितु चूंकि मुसलमान लोग सभी जगहों पर अल्पसंख्यक हैं अतः उनके प्रति निधिया को वहां से भी चुना जा सकना सम्भव नहीं होगा। इस त्रिनि कुचान का प्रभाव यह हुआ कि कांग्रेस के निर्याम के साथ साथ सर मयल ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। जब इंग्लैंड की संसद में भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में 1889 में प्रिन पन किया जाना लगा तो मि वक ने उसके विरोध में भारतीय मुसलमानों का समर्थन किया और मुस्लिम रक्षा परिषद् की स्थापना करायी। स्वयं वक इसका सचिव था यद्यपि इस परिषद् का उद्देश्य मुसलमानों के हितों का रक्षा करना था तथापि इसका वास्तविक उद्देश्य तो यह था कि मुसलमान कांग्रेस से पृथक् रहें। मि वक ने अनेक पत्रिकाओं में इस जाग्य के तत्त्व प्रकाशित करवाये कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। कांग्रेस मूल रूप से एक हिन्दू संस्था है और मुसलमानों की उसके प्रति कोई जाय्था नहीं है न व कांग्रेस की प्रतिनिध्यात्मक शासन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी मांग के समर्थक है क्योंकि उनसे मुसलमानों का हिंदू वर्गसंख्यका के अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। अतः मुसलमानों तथा यूरोपियनों का परस्पर संयुक्त होकर कांग्रेस का विरोध करना चाहिए। इसमें मुस्लिम अपसंग्यता का हित निहित है। इस प्रकार भारत में मुसलमानों की राष्ट्रीय जादौन के विरुद्ध साम्प्रदायिक भाव में संगठित करने का प्रयत्न मि वक का जाना है। भन हा सर मयल अग्रजों के इस जादू मंत्र के निकार देने और उन्हें मुस्लिम साम्प्रदायिकता का जन्म देने के लिए बदनाम किया जाता है तथापि उन्होंने जो कुछ भी किया वह मुस्लिम जनता के उत्थान की भावना में प्रेरित था।

(5) लाड कजन की नीति—भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का साकार करने में लाड कजन ने सक्रिय कदम उठाया। उसके शासन काल तक यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में राष्ट्रवादों आंदोलन काफी विकसित हो गया है। अग्रजों की फूट पगों की नीति इस राष्ट्रवादों का दवान तथा उसके मांग में राग्य अटकाने का एक उत्तम साधन थी। लाड कजन ने इस नीति का साकार करने के लिए वगान प्रांत का हिंदू तथा मुस्लिम बहुसंख्यक दो भागों में बांट दिया। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का कांग्रेस से दूर रखने का और प्रवृत्त करना था। यदि केवल प्रशासन का सुविधा के लिए हा वगान का विभाजन किया जाना जमा कि लाड कजन ने इसमें औचित्य का सिद्ध करने के लिए तक किया था तो विभाजन रखा दूसरे रूप का हानी भारतीय राष्ट्रवादी नेता कजन की इस चाल में अनभिज्ञ नहीं थे। अमीरों ने वग विभाजन का धार विरोध किया गया। परन्तु यह हमें वात का प्रमाण था कि अग्रज भारतीय मुसलमानों का भारतीय राष्ट्रीय संस्था के विरुद्ध एक प्रतिरोधी तथा समतोलन शक्ति के रूप में संगठित करना चाहते थे और साम्प्रदायिक फूट हा इस उद्देश्य की सफलता का एकमात्र साधन था।

(6) लाड मिटो तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता—कजन के उत्तराधिकारी लाड मिटो ने साम्प्रदायिक भेदभाव को मुहट तथा संस्थापित करने में जो कार्य किया वह राष्ट्रीय जादौन के सम्पूर्ण प्रतिग्राम में एक प्रभावकारी अवरोध सिद्ध हुआ। कजन की नीतियां के विरुद्ध राष्ट्रीय जादौन ने जो उग्रवादी दल बना था उसके अधिकांश नेता हिन्दू संस्कृति के प्रबल समर्थक थे यथा निरंक राजपुतराय अरविन्द आदि। यद्यपि उनके पाले प्रतिग्राम घम या मुस्लिम साम्प्रदायिक विरोधों का भा धारणा स्पष्ट था जस्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं की गई थी तथापि मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उत्तजित करने वाला न इसका भग्नूर उपयोग किया। कांग्रेस का स्वराज्य की मांग को त्रिनि सरकार अधिक न देना सकी। अतः उसने भारत में शासन सुधार सम्बन्धी कानून के अंतर्गत प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना का विचार किया। इस समय लाड माल भारतमें था। परन्तु भारत में शासन सुधार के सम्बन्ध में उन्हें बालमग्य लाड मिटो का बातें मानने का विरोध जाना पड़ा। लाड मिटो के पास आगा खा के नरुत्व में एक मुस्लिम

शिष्ट-मण्डल पहुँचा। उसने प्रतिनिध्यात्मक सस्थाओं के सम्बन्ध में मुसलमानों के पृथक् निर्वाचन तथा सुरक्षित स्थानों की माँग रखी। साथ ही सामान्य सीटों पर भी मुसलमानों के लिए मतदान में गुरुत्व (weightage) की माँग की। लार्ड मिंटो ने इस शिष्ट-मण्डल की बातों को स्वीकार किया, और उनकी माँग का स्वागत करते हुए उसे प्रोत्साहन भी दिया। इस शिष्ट-मण्डल ने ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों की ओर से पूर्ण राजभक्ति का आश्वासन दिया, साथ ही विधान सभाओं के अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में भी सुरक्षित स्थानों की माँग की। इस शिष्ट-मण्डल का संगठन करने में अंग्रेजों का सक्रिय हाथ था। मि० वेक के उत्तराधिकारी मि० आर्चीबोल्ड ने जो उस समय मुहम्मदन ऐंग्लो ओरन्टियल कालेज अलीगढ़ का प्रिंसिपल था, वाइसराय के वैयक्तिक मंचिव में इस सम्बन्ध में पूर्ण विचार-विनिमय कर लिया था।

साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली—1909 के शासन सुधार अधिनियम के अन्तर्गत लार्ड मिंटो के सुझावों के फलस्वरूप प्रथम बार भारत में अंग्रेजों ने साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया और यह प्रथा भारतीय राजनीति में निरन्तर बनी रही। मुसलमानों को न केवल निर्वाचन में ही गुरुत्व प्रदान किया गया अपितु उनके लिए निर्वाचन में उम्मीदवारों की योग्यता भी गिनिल की गई। यदि आम सीट के लिए 3 लाख रु० पर आयकर देने की शर्त थी तो मुस्लिम सीट के लिए 3 हजार रु० पर आयकर देने की शर्त रखी गई। आम सीट के लिए तथा मुस्लिम सीट के लिए जो शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गई थी उनमें भी काफी अन्तर था। मुसलमान मतदाता पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र में अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को मतदान करने के साथ-साथ आम सीट के लिए खड़े उम्मीदवारों के लिए भी मतदान कर सकते थे। यद्यपि साम्प्रदायिक निर्वाचनों का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रामजे मैकडोनेल्ड तथा भारतमन्त्री लार्ड मॉर्ले ने भी विरोध किया था, तथापि भारत स्थित ब्रिटिश नौकरशाही के कुचक्रों ने इसे मान्य करा लिया। इस दृष्टि से भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरम्भ करने का श्रेय लार्ड मिंटो को जाता है। समूचे अर्थ में, भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति तथा उसके विकास के लिए भारत के मुसलमानों को दोष देना न्यायसंगत नहीं है, अपितु इसका पूरा दोष ब्रिटिश नौकरशाही का था। वे ही इसके जन्मदाता, पोषक तथा फलभोगी बने रहे। वे फलभोगी इस अर्थ में रहे कि इसके कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद काफी लम्बे समय तक भारत में बना रह सका।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा राजनीति—भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उत्पन्न करना ब्रिटिश शासकों का राजनीतिक पड़्यन्त्र था। अंग्रेजों ने भारत में कांग्रेस को स्थापना को एक ऐसे अभयद्वीप (safety valve) के रूप में देखना चाहा था, जो ब्रिटिश शासन के विरोधी नस्लों को दबाने में सहायक सिद्ध हो सके। परन्तु अपनी स्थापना के तीन या चार वर्षों के अन्दर ही कांग्रेस ने जिन राष्ट्रीय माँगों को रखना शुरू किया, उनके कारण ब्रिटिश शासकों को कांग्रेस की गतिविधियाँ अपनी स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध प्रतीत होने लगी। अतः कांग्रेस का विरोध करने के लिए उन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया। 1906 में जब शासन सुधारों के सम्बन्ध में प्रतिनिध्यात्मक सस्थाओं की माँग बटने लगी और मुसलमानों की ओर से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग की गयी, तो भारतीय मुसलमानों ने कांग्रेस के समक्ष एक राजनीतिक संगठन निमित्त करने की योजना बनायी। मुहम्मद शफी ने 1901 में ही मुस्लिम लीग बनाने की धारणा व्यक्त की थी, परन्तु मुस्लिम लीग की स्थापना वास्तव में 30 दिसम्बर 1906 को हुई जबकि मुसलमानों को लार्ड मिंटो की कृपा में अपनी माँगें पूर्ण कराने में पूरी सफलता प्राप्त हो गयी थी।

लीग के उद्देश्य—मुस्लिम लीग के मुख्य उद्देश्य ये थे—

- (1) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा उत्पन्न कराना
- (2) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों तथा हितों का संरक्षण कराना और

उनके सम्बन्ध में शासन से निष्ठापूर्वक प्रार्थना करना तथा

(3) भारतीय मुसलमानों में उपयुक्त उद्देश्यों से विरोध न रखने की स्थिति में जय मस्जिदों का विस्तृत वरभाव रखने की धारणा का रोकना ।

इस बात पर सन्देह करने की कोई गजाल नहीं रह जाती कि स्वयं ब्रिटिश शासकों ने ही कांग्रेस के विरुद्ध एक मुस्लिम राजनीतिक संगठन निर्मित करने का प्रोत्साहन मुसलमान नेताओं को दिया था । वास्तव में मुस्लिम लीग के उपयुक्त उद्देश्य किसी भी रूप में उसके राष्ट्रीय या राजनीतिक स्वभाव के परिचायक नहीं हैं । परन्तु कानून में लीग के कार्य-कलाप राजनीतिक प्रवृत्ति के हात में गये । 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग अल्प अवधि के लिए एक साथ आये जबकि खिलफत आन्दोलन चला था । परन्तु यह सन्धि स्थायी नहीं रह सकी और मुस्लिम लीग को तब तक चला नहीं गया जब तक कि भारत का विभाजन नहीं हुआ (इसका विवरण आगे किया जायेगा) ।

प्रश्न

- 1 भारत में मुस्लिम से प्रभावित ब्रिटिश शासन को दन था । इस रचना की समीक्षा कीजिए ।
- 2 1857 के बाद भारत में वे कौन-सी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ काम कर रही थी जिनके फलस्वरूप मुस्लिम सम्प्रदायवाद का विकास हुआ ।
- 3 भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना एवं उद्देश्यों पर लिखी लिखिए ।

प्रथम विश्वयुद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन (NATIONAL MOVEMENT AND WORLD WAR I)

1906 से 1915 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्धकार का काल कहना अत्युक्ति नहीं होगी। इस काल में कांग्रेस की वागडोर उदारवादियों के हाथ में रही। उग्रवादी राष्ट्रीय नेता तिलक 1908 से 1914 तक जेल में पड़े रहे। क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन को सरकार ने दबा दिया था। क्रान्तिकारी आन्दोलन के सूत्रधार तथा प्रेरणा-स्रोत महर्षि अरविन्द ने राजनीति से ही सन्यास ले लिया था और 1910 में वे ब्रिटिश भारत को छोड़कर पाण्डिचेरी चले गए थे। लार्ड मिण्टो ने मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक् कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी। 1909 का शासन सुधार अधिनियम भी लागू हो गया था। परन्तु कांग्रेस की फूट तथा मुस्लिम लीग की स्थापना ने राष्ट्रीय आन्दोलन को सशक्त होने से रोक लिया। कांग्रेस की स्वराज्य की माँग पर 1909 के सुधार अधिनियम ने पानी फेर दिया था। अतः राष्ट्रीय नेताओं में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध असन्तोष बढ़ता जा रहा था। इस तथ्य से ब्रिटिश शासक अनभिज्ञ नहीं थे। कर्जन तथा मिण्टो की प्रतिगामी नीतियों के उपरान्त ब्रिटिश सरकार ने भारतीय असन्तोष को शान्त करने की नीयत से लार्ड हार्डिंज को वाइसराय बनाकर भेजा। निस्सन्देह तत्कालीन भारतमन्त्री क्र्यू (Crewe) तथा वाइसराय हार्डिंज दोनों अपने पूर्ववर्ती पदाधिकारियों की तुलना में बहुत निर्बल थे, तथापि हार्डिंज को भारतीय परिस्थितियों का समुचित ज्ञान था। वे मन्त्रिमण्डल में एक स्थायी अपर सचिव तथा विदेश कार्यालय के प्रधान थे। साथ ही रिपन के पश्चात् शायद वही एक ऐसे वाइसराय थे, जिन्हें भारतवासियों के प्रति सहानुभूति थी। इस समय यूरोप में महायुद्ध के बादल मँडरा रहे थे। लार्ड हार्डिंज ने भारतीय असन्तोष को दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाया। उनके शासन-काल में अनेक ऐसी घटनाएँ हुईं जिनके कारण राष्ट्रीय आन्दोलन ने 1919 तक एक नया मोड़ लिया।

वग-विच्छेद का निरसीकरण—1911 में सम्राट् जार्ज पंचम भारत की यात्रा पर आये। उस अवसर पर लार्ड हार्डिंज के वाइसरायत्व में दो महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित किये गये। प्रथम के अनुसार वग-विच्छेद का अन्त करके वगाली भाषी-क्षेत्रों से युक्त वगाल को पुनः एक प्रान्त बना दिया गया और पश्चिमी वगाल से बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर के भाग निकालकर उन्हें एक पृथक् प्रान्त के रूप में निर्मित कर दिया गया। इस प्रकार छह वर्ष तक चला आया एक महान् असन्तोष समाप्त हो गया। दूसरी घोषणा के अनुसार भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दी गयी। वगाल प्रान्त का शासन अब एक अलग गवर्नर के अधीन रखा गया। आसाम को चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया। इस प्रकार लार्ड हार्डिंज ने लार्ड कर्जन की एक महान् भूल का निराकरण करके भारतवासियों के मध्य लोकप्रियता प्राप्त की। परन्तु दुर्भाग्यवश आतंकवादियों के एक वर्ग ने लार्ड हार्डिंज के ऊपर बम फेंककर, जिसमें वह बाल-बाल बच गये, ब्रिटिश शासकों को पुनः स्मृत कर दिया। यह घटना वास्तव में अवाञ्छनीय थी, विशेष रूप से लार्ड हार्डिंज सदैव वाइसराय के विरुद्ध ऐसा कार्य उचित नहीं था। परन्तु यह घटना इस बात की द्योतक थी कि ब्रिटिश सरकार की विविध शासन नीतियों के विरुद्ध भारत में भारी असन्तोष व्याप्त था और भावुक युवा-वर्ग क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोदना चाह रहा था।

एक कान व काग्रस व कणधार उदारवादी नेताओं ने पुनः ब्रिटिश शासन की नीति प्रियता तथा सत्यता पर आस्था व्यक्त करनी शुरू कर दी। मुरन्नाथ वनर्जी महता गांधी नौरोती पण्डित मदनमोहन मालवीय तजबहादुर सप्रू जति सभी एक कान के उदारवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा में हाथ बढ़ाया। परंतु ऐसा यह अर्थ नहीं था कि ये उदारवादी नेता 1909 के मुबारक तथा बग विच्छेद के निरसीकरण से संतुष्ट हो गए थे। जसी उदारवादियों की प्रारम्भ से ही नीति बनती रही उहान पुन सरकार के समक्ष विधान-परिषद के मुबारक की मांग रखी। काग्रस ने स्वराज्य (स्वायत्त शासन) प्राप्ति को अपना उद्देश्य बना लिया था परंतु 1909 के मुबारक से उस नीति में कोई सतान नहीं मिला था। पृथक् साम्प्रदायिक निवाचित प्रणाली के दोष स्पष्ट हो चुके थे। अतः जब 1913 के काग्रस अधिवेशन में यह मांग रखी गयी कि कर्तीय विधान परिषद में गर सरकारी सदस्या का वामत होना चाहिए और प्रातीय परिषद में निवाचित सदस्या का। ब्रिटिश सरकार ने अभी तक उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था। अतः स्पष्टतया अब काग्रस का नया मार्चा एक मांग के समवन में खाना जाना था। 1914 के काग्रस अधिवेशन में यह मांग रखी गयी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तशासी सरकार निर्माण का जाना चाहिए।

श्रीमती ऐनी बेसट तथा तिलक का काग्रस में प्रवेश—1914 में काग्रस के नेतृत्व में परिवर्तन जाना गया। श्रीमती ऐनी बेसट जो एक जाइरिंग महता थी थियोसाफिकल सासायटी का सचान करती थी। उस समय आयरलण्ड में होमरूल जागेवन चल रहा था। भारत जान पर उह भारतीय ससृति के प्रति निष्ठा उत्पन्न हुई। साथ ही भारतीय जनता के कष्टों में वह बल चितित हई। उह गया कि यह सब भारत की राजनीतिक पराधीनता के कारण है। अतः उहाने थियोसाफी का काय छाडकर राजनीति में प्रवर्ग किया और आयरलण्ड के नमूने पर भारत में भी हामरूल आंदोलन छान का प्रण कर लिया। एक समय भारत का भावुक युवा बग ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए प्रचल था। उग विच्छेद की घटना से पूर्व ई पी पी को अपन अन्तक नमठ नताओं के विचार सुनने को मिले थे। परंतु 1908-1914 की अवधि में ये सभी महान् नता भारत के राजनीतिक पद से पृथक् हो गये थे। तिनक जन में थे। राजनाराय व रिपिन चत्पात विदगा में थे। उदारवादियों की भिभावृत्ति की नीति से युवा पागे ऊन गयी थी। उसमें सक्षय का उत्साह था परंतु नेतृत्व का अभाव खल रहा था। श्रीमती बेसट के राजनीति में प्रवर्ग ने एक बग की जाशाओं में नया उत्साह उत्पन्न किया। भाग्यवत इसी बग 6 सान की कारावास की अवधि पूण हान के कुछ ही कान पूर्व सरकार ने तिनक को मुक्त कर दिया था।¹ यद्यपि तिनक नारीरिक दृष्टि में बहुत अस्वस्थ थे तथापि उनका राष्ट्र प्रेम उह राजनीति में प्रविष्ट हान से नहा राक सका। श्रीमती बेसट ने अनुभव किया कि जब तक उग्रवादी नेता काग्रस में पुन न जा जायें तब तक हामरूल जागेवन प्रभावगाना नहा हो सकता। अतः वे तिनक से मिली। तिनक काग्रस में आना तो चाहते थे परंतु वे उदारवादियों के कार्यक्रम से समझौता नहा कर सकते थे। उदारवादी नेता भी काग्रस के दाना दाना में एकरा के लिए व्यग्र थे। 1915 में जब गोखल तथा महता की मृत्यु हो गयी तो इसमें तिनक का काग्रस में प्रवर्ग सुविधाजनक हो गया। उहान ने कवन हामरूल जागेवन की विचारधारा को आग बनाया प्रत्युत अपन दम से एक जागेवन को अपन प्रात में बनाया और अपन जनक अनुयायियों का सहचार भी प्राप्त किया। 1916 में उनकी अवस्था 60 बप की हो चुकी थी अतः जनता ने उनकी 60वीं बप-गाठ पर उह 1 लाख रुपए का धनी भेंट की। जिस उहान राष्ट्रीय कार्यों के लिए दान कर दिया। उनकी लोकप्रियता निम्न बनी जा रही थी। निस्सन्देह गोखल तथा फीराजगां महता की मृत्यु हो जाने से काग्रस का बग धक्का गया। स्वयं तिनक जो गांधी की नीतियों के प्रवर्ग विरोधी थे गांधी की मृत्यु से सबसे

अधिक दुःखी हुए। 1915 में कांग्रेस ने अपने सविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जिसके कारण उग्र राष्ट्रवादी नेता पुनः कांग्रेस में आ सकें। परन्तु संशोधन के अनुसार जो अवधि सम्बन्धी प्राविधान रखा गया था, उसके अनुसार 1916 से पूर्व तिलक कांग्रेस में नहीं आ सकते थे। श्रीमती ऐनी बेसेट ने कांग्रेस के दोनों दलों में एकता लाने के पूर्ण प्रयास किये। अन्ततः 1916 में उनका मिशन सफल हो गया। इसके पश्चात् के पाँच वर्षों तक तिलक तथा बेसेट ने कांग्रेस का नेतृत्व किया।

महायुद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन—1914 में यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में मित्र-राष्ट्रों ने (जिनमें इंग्लैंड भी शामिल था) जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा की थी, उसका उद्देश्य 'लोकतन्त्र की रक्षा' घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में लार्ड हार्डिज के प्रयासों से यह धारणा जाग्रत हुई कि युद्ध में इंग्लैंड की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। चूँकि युद्ध का उद्देश्य लोकतन्त्र की रक्षा करना है, अतः युद्ध में विजय हो जाने पर इंग्लैंड भारत में भी लोकतन्त्री व्यवस्था कायम करेगा। भारतीय नेताओं ने तन, मन, धन से इंग्लैंड की सहायता की। स्वयं महात्मा गांधी ने जो उस समय तक कांग्रेस के प्रमुख नेता नहीं बने थे, युद्ध के लिए भारतवासियों की ओर से यथासम्भव इंग्लैंड की सहायता करने के प्रयास किये। यदि भारतीय नेता इस अवसर पर ब्रिटिश सरकार से कोई आशा करते थे तो वह यही कि सरकार युद्ध के पश्चात् भारत में स्वायत्त शासन स्थापित करने की घोषणा कर दे। परन्तु सरकार मौन ही रही। उग्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार की नेक-नीयती पर अब भी आश्वस्त नहीं थे। भारत के सैनिक यूरोप में इंग्लैंड की ओर से युद्ध में लड़े और उन्होंने इंग्लैंड को विजयी बनाने का श्रेय तो लिया ही, साथ ही उन्होंने यह भी अनुभव किया कि किसी देश की सहायता तथा प्रतिष्ठा के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता का सबसे अधिक महत्त्व है।

कांग्रेस के दो दलों में सन्धि—1914 में श्रीमती बेसेट के कांग्रेस में प्रविष्ट होने पर राष्ट्रीय आन्दोलन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। श्रीमती बेसेट ने राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नई जान फूँकने का कार्य किया, उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और देश की वास्तविक परिस्थितियों का जायजा लिया। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उदारवादी नीतियों से राष्ट्र का हित सम्भव नहीं है। देश की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में वे तिलक की भाषा में बोलती थीं। उनका मत था कि यद्यपि युद्ध काल में इंग्लैंड की सहायता करते हुए भारत अपनी स्वतन्त्रता की माँग कर रहा था तथापि भारत अपनी स्वतन्त्रता की माँग अपनी इस राजभक्ति के प्रत्युपकार के रूप में नहीं चाहता। 'भारत स्वतन्त्रता की माँग युद्ध-काल में कर रहा है, वह युद्ध के पश्चात् भी इसकी माँग करता रहेगा, परन्तु एक पुरस्कार के रूप में नहीं, अपितु अपने अधिकार के रूप में करेगा।'¹ 1915 में गोखले तथा मेहता की मृत्यु के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में शून्यता आ गई थी। स्वयं बेसेट तथा तिलक भी कांग्रेस के दोनों दलों के मध्य एकता लाने के लिए व्यग्र थे। दोनों का उद्देश्य होमरूल आन्दोलन को तीव्र करना तथा राष्ट्रवादी दल को मजबूत बनाना था।

1915 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नेताओं ने पर्याप्त उत्साह के साथ बहुत बड़ी सरया में भाग लिया। साथ ही इस अधिवेशन में बहुत से प्रस्ताव पारित किये गये जिनमें से अधिकांश प्रस्ताव पिछले प्रस्तावों की पुनरावृत्ति एवं पुष्टिकरण के रूप में थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस सविधान के अन्तर्गत एक संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया कि 'कोई भी व्यक्ति इस शर्त पर कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना जा सकता है कि 31 दिसम्बर 1915 को वह लगातार 2 वर्ष की अवधि तक किसी ऐसे सङ्गठन में चुना गया हो जिसका उद्देश्य वैधानिक तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त शासन प्राप्त करना रहा हो।' इस संशोधन ने राष्ट्रवादी नेताओं के कांग्रेस में प्रवेश के द्वार खोल दिये। परन्तु तिलक का ऐसा कार्यकाल अभी पूर्ण नहीं हो पाया था। अतः अप्रैल 1916

मं निरक ने अपने प्रान्त में हामरून आंदोलन छेड़ दिया सरकार ने उसका दमन किया तथा उनमें बहुत ऊँची धनराशि की जमानत मांगी ताकि वे अपने एस जाचरण में पृथक् रहें। हाई कोर्ट ने सरकार की इस मांग का ग़र कानूनी घोषित कर दिया। सस तिनक का प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। वसक 6 मास पश्चात् श्रीमती वमन ने मन्स में अखिर भारतीय होम रून नीग की स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति 1916 में वस रूप में चन रही थी कि वसका वास्तविक नतत्व अब उदारवातिया के हाथ में निकलता जा रहा था और तिनक तथा वसट हा वमने वास्तविक नेता रह गये थे। 1916 के नवनऊ के काग्रस अधिवेशन में तिलक तथा उनके जनक साथी काग्रस में प्रविष्ट हो गये। वस प्रकार नगभग एक दशात् की काग्रस की फूट का अंत हो गया और काग्रस के दाना दन एक में मिल गये।

काग्रस-नीग समझौता (Lucknow Pact 1916)—काग्रस की बन्ती हुई लोकप्रियता तथा शक्ति से व्यग्र हाकर ब्रिटिश नौकरशाही ने फूट डालने और शासन करा की नानि का अवलम्बन करके भारत के मुसलमान सम्प्रदाय को काग्रस के विरुद्ध संगठित किया था। मुस्लिम नीग की स्थापना में स्पष्टतया नौकरशाही का हाथ था। यद्यपि 1909 के सुधारा के अनगत विधान परिषद् में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को गुन्ता देकर तथा पृथक् निर्वाचन प्रणाली का अपनाकर भारत के मुसलमानों का प्रसन्न करने का प्रयास सरकार की प्रमुख नीति रही थी तथापि इस बीच कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिनके कारण भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश शासन की नीतियाँ में असंतुष्ट हो गये थे। गान् हाडिगज ने हिंदू मुस्लिम समस्या पर अपने पूर्ववर्ती वात्सराया के प्रति तत्परता की नानि का अवलम्बन किया। नग विद्वत् की समाप्ति ने साम्प्रदायिकतावादी मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर दिया। अभी तक अनीगढ़ मुस्लिम नीग तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद का गत था। परन्तु अब नीग का प्रधान कार्यालय नवनऊ में बना दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय शत्रु में टर्की जो कि भारतीय मुसलमानों की निष्ठा का केन्द्र था नवनऊ की कृपा पर आश्रित रहता था। परन्तु वस बीच टर्की तथा व्टनी के युद्ध में इंग्लैण्ड ने टर्की का साथ नहा दिया। इससे भारतीय मुसलमान अग्रजा से असंतुष्ट हो गये। इसी अवधि में मुस्लिम नीग के कुछ प्रमुख नेता यथा मुहम्मद अली जिन्ना तथा अनी बघु (मौलाना मौक़्त अनी तथा मौलाना मुहम्मद अनी) जो कि राष्ट्रवादी विचारों के थे मुस्लिम नीग की अग्रज भक्ति से असंतुष्ट हो गये। उह मुसलमानों की ऐसी दासता पसन्द नहीं थी अन वे भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा स्वायत्त शासन की मांग करने लगे। इस प्रकार मुस्लिम नीग की विचारधारा के प्रारम्भिक स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता जा गई।

1913 के नीग के नवनऊ अधिवेशन में नीग ने ब्रिटिश शासन के अनगत वधानिक शासना द्वारा तथा नय सम्प्रदायों के साथ सहयोग करत हुए स्वायत्त शासन का प्राप्ति करना अपना उद्देश्य घोषित किया। यह उद्देश्य नगभग वही था जा कि काग्रस के उदारवादी नेता पूर्व ही घोषित कर चुके थे। अंत मद्भातिक दृष्टि से नीग काग्रस के सन्निकट आन लगी। 1913 के कराची अधिवेशन में काग्रस ने नीग के इस उद्देश्य का स्वागत किया। जिन्ना जा उस समय एक पक्के राष्ट्रवादी नेता थे काग्रस की इस प्रतिब्रिया से बहुत प्रभावित हुए। 1915 में काग्रस का अधिवेशन बम्बई में हुआ ता नीग ने भी अपना अधिवेशन नगभग उसी अवधि में बम्बई में ही किया। परिणामस्वरूप दाना संगठनों के नेताओं का परस्पर विचार विनिमय करने का अवसर मिला। दोनों दलों की एक मयुक्त सम्मेलन समिति गठी गई और उसकी सस्तुतियाँ के आधार पर नाना दलों के मध्य समझौता सम्भव हो गया। 1916 में दोनों संगठनों के अधिवेशन नवनऊ में हुए। वहा दन दनों ने ऐतिहासिक काग्रस-नीग समझौते का स्वीकार किया।

काग्रस नीग समझौता हो ता गया परन्तु यह मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विषय को हटाने का उपचार सिद्ध नहा हुआ अपितु अपनी इच्छा के विरुद्ध काग्रस का नीग का गते माननी पना ताकि नीग का सहयोग ब्रिटिश शासन की अनिवादिता के विरुद्ध राष्ट्रीय जागृता के संचालन में

प्राप्त हो सके और राष्ट्रीय ऐक्य का विकास हो। इस समझौते के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन को स्वीकार किया गया। साथ ही प्रतिनिधित्व के निमित्त अल्पसंख्यकों के लिए गुस्ता के मिद्धान्त को भी माना गया। इस प्रकार भविष्य में विधान परिषदों में मुसलमानों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक सीटें प्राप्त हो सकती थीं। यह भी स्वीकार कर लिया गया कि अल्पसंख्यकों के हितों पर प्रभाव डालने वाले विधायनों में यदि सम्बद्ध जन-समुदाय के तीन-चौथाई प्रतिनिधि विरोध करें तो ऐसा विधायन विधान परिषदों में आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। लीग की इन माँगों को स्वीकार करने में कांग्रेस के नेताओं की आशा सही सिद्ध नहीं हुई। वे यह व्याल करते रहे कि कालान्तर में हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायवाद क्षीण पड़ जायेगा तो मुसलमान स्वयं ही पृथक् निर्वाचन प्रणाली का विरोध करेंगे, परन्तु कांग्रेस के नेताओं की ऐसी धारणा का भविष्य में उल्टा प्रभाव पड़ा। सरकार ने 1919 के सुधार-कानून के अन्तर्गत इन शर्तों को स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस-लीग समझौते के अन्तर्गत भविष्य में भारत की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेक माविधानिक सुधारों की मांगें भी रखी गईं। इनमें से प्रमुख माँगों के अन्तर्गत प्रान्तीय शासन को केन्द्र के नियन्त्रण में मुक्त रखने, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों में व्यापक मताधिकार के आधार पर 80% निर्वाचित सदस्यों को रखने, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कार्यकारी परिषदों में कम से कम आधे सदस्यों को सम्बन्धित विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों में से लिए जाने, तथा विधान परिषदों के अधिकार-क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करने की शर्तें थीं। प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्धों, युद्ध, शान्ति आदि के मामलों को केन्द्रीय सरकार के हाथ में रखने की बात भी इस समझौते के द्वारा मानी गई। अन्ततः, इस समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार के मामलों में भारत-मन्त्री के नियन्त्रण को कम करके उसकी स्थिति अन्य स्वायत्तशासी उपनिवेशों के उपनिवेश मन्त्री की भाँति रखने की माँग भी की गई थी। इसका अभिप्राय यह है कि कांग्रेस-लीग समझौते ने भारत के लिये एक प्रकार के औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग रखी और यह आशा व्यक्त की कि जोध ही सम्राट् की सरकार यह घोषित करे कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में स्वायत्त शासन तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का है। ये माँगें इतनी प्रगतिशील थीं कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार जो भारत में स्वेच्छाचारी साम्राज्यवाद की नीति पर डटी हुई थी, इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती थी। यद्यपि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने 1919 में शासन सुधार अधिनियम पास किया तथापि इन साविधानिक सुधारों को उन्होंने पूर्णतया उपेक्षित रखा।

कांग्रेस तथा लीग की एकता भी अस्थायी सिद्ध हुई। यह खिलाफत आन्दोलन¹ तक ही बनी रही। ज्योंही वह समाप्त हुआ, त्योंही लीग ने साम्प्रदायिक हठ-वर्षिता अंगीकार कर ली और 1922-23 से मुस्लिम लीग कांग्रेस की असली शत्रु बन गई।

होम-रूल आन्दोलन—महायुद्ध काल में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत श्रीमती ऐनी बेसेट तथा तिलक के द्वारा संचालित होम-रूल आन्दोलन एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध हुआ। होम-रूल का आशय है स्वायत्त-शासन। इस अवधि में आयरलैण्ड में ऐसा आन्दोलन चला हुआ था। 1918 में जब श्रीमती ऐनी बेसेट इंग्लैण्ड गई तो उन्हें यह प्रेरणा मिली कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत भी ऐसा ही आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय। वैसे होम-रूल आन्दोलन भारत के लिए कोई नया कार्यक्रम नहीं था। 1906 में कांग्रेस अपना उद्देश्य 'स्वराज्य प्राप्ति' घोषित कर चुकी थी। तिलक ने यह आन्दोलन चला लिया था। 1914 में जब वे जेल से छूटे तो पुनः इसके लिए कार्य करने लग गये थे। श्रीमती बेसेट ने भारत लौटने पर दैनिक पत्र 'न्यू इण्डिया' तथा मासिक पत्र 'कॉमन वील' के द्वारा इस आन्दोलन का प्रचार किया। मारे देश का दौरा करके उन्होंने जनता को यह प्रेरणा दी कि भारत में स्वराज्य की प्राप्ति करना प्रत्येक

¹ उदा। विवेचन आगामी अध्याय में लिया गया है।

भारतवासी का जन्म सिद्ध अधिकार है। तिनक पहन ही ऐसी घोषणा कर चुके थे। अप्रैल 1916 में तिनक ने महागण मन्म आन्दोलन का प्रीक्षण कर लिया था। उन्होंने भी कैमरी तथा मराठा पत्रों के द्वारा मन्म आन्दोलन को अधिक व्यापक ढंग से प्रचारित करने का प्रयास किया। प्रीमता एनी वसेंट ने 1916 में मन्मस में होम रूल प्रीग की स्थापना की। उस समय महायुद्ध छिन्न हुआ था। मन्म आन्दोलन का उद्देश्य यह नहीं था कि सरकार का परगान किया जाय और उसके युद्ध सम्प्र की प्रयत्ना में गेरा अन्काया जाय। प्रत्युत तिनक तथा वसेंट दोनों ने युद्ध-कार्यों में सरकार की यथासम्भन्न सहायता करने की सलाह जनता को दी। साथ ही होम रूल प्रीग के माध्यम से उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक भारतवासी राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सहायता उचित रूप में नहीं कर पायेंगे। अन्तःस्थापित शासन प्राप्त करना प्रत्यक्ष भारतवासी का जन्म अधिकार है। यह आन्दोलन मूल रूप में प्रचारात्मक था। वसेंट तथा तिनक दोनों ने व्यापक रूप से पत्रिकाएँ (Pamphlets) के द्वारा जनता में स्वायत्त शासन की मांग का प्रचार किया। वसेंट ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गन्त नहीं थी अपितु वे अन्तःस्थापित तथा भारत की समान राष्ट्रीय रूप में मानती थी। उनका उद्देश्य यह था कि स्वायत्तशासी भारत तथा इंग्लैण्ड के मध्य मित्र राष्ट्रीय का सा सम्बन्ध हो न कि शासित तथा शासक राष्ट्रीय का सा। इसी में दोनों का मन्ति है। वसेंट मन्म बात को मानने के लिए भी राजी नहीं थी कि भारतवासी इंग्लैण्ड के प्रति राजभक्ति रखें और उसके वदन में अन्तःस्थापित से स्वायत्त शासन की भीख मांगें अपितु स्वायत्त शासन भारतवासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस सधष करके प्राप्त करना चाहिए। निवर्तमान सरकार निरकुश हानी जा रही है। प्रीमता वसेंट के मत से होम रूल का अभिप्राय यह है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम परिषदा जिना दोनों नगरपालिकाया तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाया से होत हुए राष्ट्रीय समद तक अपन लिए पूण स्वायत्त शासन की स्थापना करना अपना नक्ष्य मानते हैं जिनकी शक्तियाँ साम्राज्य के अन्तगत स्वाशासित उपनिवेशा की विधान सभाया के तुल्य हा। इस प्रकार वसेंट का होम रूल आन्दोलन 1906 में काग्रस द्वारा घोषित स्वतन्त्री आन्दोलन की भांति ही ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना करना था।

परन्तु तत्कालीन भारत के ब्रिटिश शासक ने इस गानिपूण आन्दोलन का दवाने में कोई कमी नहीं रखी। मन्मस के गवर्नर पेंटनड ने प्रीमती वसेंट तथा उनके दो सहायगी कार्यकर्ताया बाबिया तथा अन्तःस्थापित को नजरबन्ध कर लिया। वसेंट के पत्रों में अन्तःस्थापित तथा कामन वीन पर प्रतिबन्ध लगाकर उनसे बीस हजार रूपय की जमानत मांगी जा बाद में जप्त कर ली गई। विद्यार्थियों का भी मन्म आन्दोलन में भाग लेने में रोका गया। बम्बई में तिनक में भी सदाचरण सम्प्र की 40 हजार रूपय का बाण्ड मांगा गया और दस हजार रूपय की जमानत भी मांगी गई परन्तु अफीन करने पर हार्ड काट ने मन्म सरकारी आन्त को अवध घोषित कर दिया।

सरकार के इस मन्मन चक्र का प्रभाव यह हुआ कि होम रूल आन्दोलन अन्तः प्रीग नाकप्रिय हो गया। सरकार की मन्मनकारी नीति के विरुद्ध अनेक प्रतगना तथा सभाया का आयोजन हान लगा। दंग के अधिकाधिक व्यक्ति मन्म प्रीग के सन्तस्य वनन गे। इसी वष काग्रस के दाना दना में एकता हा जाने तथा एनी वसेंट और तिनक के हाथ में राष्ट्रीय आन्दोलन का नन्तव आ जान का परिणाम यह हुआ कि काग्रस पुन उग्रवादी नन्ताया की नीति का अनुमरण करने लगी। यद्यपि अभी तक महात्मा गांधी काग्रस के प्रमुख नन्ताया की स्थिति में नहीं आ पाय थे तथापि वे काग्रस में प्रविष्ट हा गय थे और उन्त निस्वाय भाव से युद्ध में अग्रजा की सहायता करने के लिए भारतवासियों का आह्वान किया। तिनक तथा वसेंट ने यह नीति अपनायी कि युद्ध काज में ब्रिटिश सरकार के समर्थन स्वरूप का आन्दोलन तीव्र करने का नाम उठाना चाहिए ताकि ब्रिटेन को युद्ध प्रयास में सहायता कर उह भारतीय राष्ट्रीय मांगा के समर्थन करने के लिए विवग

किया जा सके, न कि राजभक्ति दर्शाकर ब्रिटेन से पुरस्कार के रूप में स्वराज्य की याचना की जाय।

होम-रूल आन्दोलन लगभग उसी प्रगति से बढ़ने लगा जिस प्रकार 1906-07 में स्वदेशी आन्दोलन बढ़ा था। इसके अन्तर्गत भी स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार को महत्त्व दिया गया। आन्दोलन की प्रगति तथा प्रभाव के बारे में वाइसराय के गृह सचिव (Home Member) रेजीनल्ड क्रेडोक ने लिखा था, 'स्थिति अत्यन्त कठिन है। जनसाधारण के मध्य उदारवादी नेताओं को कोई समर्थन नहीं मिलता, जो कि अब तिलक तथा बेसेट के प्रभाव में हैं। स्वायत्त शासन (होम-रूल) पर जोर दिया जा रहा है जिसे भारत की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार अनगिनत गलतियों तथा दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय माना जा रहा है। वैधानिक आन्दोलन की आड़ में समाचार पत्रों को पढ़ने वाली जनता के मनो में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विष भरा जा रहा है।'¹ जब सरकार ने आन्दोलन को बलात् दबाया और बेसेट तथा तिलक के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगाये तो इससे भारत का प्रबुद्ध जनमत और अधिक रुष्ट हो गया। 1916 में कांग्रेस-लीग एकता निर्मित हो चुकी थी। जिन्ना ने जो इस समय लीग के प्रमुख नेता थे, बेसेट की नजरबन्दी की तीव्र भर्त्सना की। उनके मत से इस व्यवहार का अर्थ है 'कांग्रेस तथा लीग द्वारा लखनऊ में एक साथ स्वीकार कर ली गयी स्वायत्त शासन या होम-रूल योजना को ही नजरबन्द कर लेना।'² गांधी जी तथा तेजबहादुर सप्रू ने भी सरकार की इस नीति का विरोध किया।

जब इतने दबाव पड़े तो 20 अगस्त 1917 को भारत मन्त्री ने भारत को स्वायत्तशासी अधिकार प्रदान करने की घोषणा की। इसी अवसर पर श्रीमती बेसेट को मुक्त भी कर दिया गया था। बेसेट की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। उसी वर्ष उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित चुन लिया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषणा की 'भारत को स्वतन्त्र देखना, उसे राष्ट्रो के मध्य ऊँचा सिर किये हुए देखना, भारत माता के पुत्रों-पुत्रियों को सर्वत्र सम्मान प्राप्त करते हुए देखना, भारत को अपने शक्तिशाली अतीत के अनुरूप देखना, जो कि और अधिक शक्तिशाली भविष्य के निर्माण में लगा हुआ है—क्या इस सबके लिए कार्य करना, इसके लिए यातना भोगना, जीवित रहना तथा मरना कोई मूल्य नहीं रखता ?'³

20 अगस्त 1917 की घोषणा तथा होम-रूल आन्दोलन का अन्त—20 अगस्त 1917 को भारत मन्त्री मिस्टर माटेयू ने इंग्लैंड की सदन में भारत की शासन प्रणाली के भविष्य के बारे में जो घोषणा की थी, उसका भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं साविधानिक विकास के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक महत्त्व है। इस घोषणा का विवेचन करने से पूर्व इसके कारणों पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार आज तक भारतीय राष्ट्रीय माँगों को निरन्तर उपेक्षा की दृष्टि में लेती रही तथा आन्दोलन को सदा दमन के द्वारा दबाती रही और यही धारणा व्यक्त करती रही कि भारतवासी स्वायत्त शासन के लिए सर्वथा अयोग्य है, उसी सरकार ने स्वयं भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की।

घोषणा के कारण—(1) इस बीच राजनीतिक घटनाक्रमों की प्रगति इस रूप में होती जा रही थी कि ब्रिटिश नौकरशाही के लिए अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने की नीति अपनाना सम्भव नहीं रह गया था। ब्रिटिश शासन ने भारत में राष्ट्रीय शक्तियों के दवाने के लिए साम्प्रदायिक भेदभाव को प्रोत्साहित करके कांग्रेस की प्रतिगामी स्स्थिति मुस्लिम लीग स्थापित करवा ली थी। परन्तु 1916 में कांग्रेस-लीग समझौते ने ब्रिटिश नौकरशाही के इस कुचक्र पर पानी फेर दिया था।

(2) कांग्रेस के दोनो दल 1907 में पृथक् हो गये थे और उग्रवादी नेता न केवल कांग्रेस में जनग ही हो गये थे, अपितु उनके नेतृत्व को सरकार ने कुचल डाला था। तिलक छ वर्ष तक जेल में रहे। परन्तु 1916 में पुन कांग्रेस के दोनो दलों में एकता स्थापित हो गयी थी। नर्म दल

¹ Quoted in Tara Chand, *op cit*, 450

² *Ibid*, 451

³ *Ibid*

का नतत्व समाप्त होकर काग्रेस का नतत्व पुन उग्र देने के हाथ में जा गया था और तिनक तथा वसंट का हाम रून आत्मान अत्यधिक नाकप्रिय होने लगा था ।

(3) महायुद्ध में भारत के राष्ट्रीय नेताओं में सविता न भी ब्रिटिश व युद्ध प्रयासों में अवरोध उत्पन्न नहीं किया था । प्रत्युत इस आशा से कि यह युद्ध लोकतन्त्र की रक्षा के लिए किया जा रहा है ब्रिटिश की भरपूर सहायता करने का भारत की जनता में प्रचार किया । 1917 के मध्य युद्ध ऐसी स्थिति में पहुँच चुका था कि ब्रिटिश का भारत की सहायता के बिना विजय की आशा नहीं रह गयी थी अतः उस भारत की राष्ट्रीय मांगों को उपक्षिप्त रखकर भारत से सहयोग तथा सहायता की आशा रखना सम्भव नहीं था ।

(4) 1914 में जब ब्रिटिश ने टर्की के विरुद्ध युद्ध छेड़ा तो इस युद्ध का सञ्चालन भारत सरकार के ऊपर छाड़ दिया गया था । 1916 में ब्रिटिश सरकार के भारतीय युद्ध कार्यालय ने यह दायित्व अपने ऊपर लिया । इस युद्ध में जो अकुशलता दर्शायी गयी तथा सैनिकों को खाली मामूली चिकित्सा-साधन आदि प्रदान करने में जसी असावधानी बरती गयी उसके भीषण दुष्परिणाम सामने आये । अतः ब्रिटिश सरकार ने इस अकुशलपूर्ण युद्ध-सञ्चालन की जाँच के निमित्त एक महापद्मविद्या आयोग नियुक्त किया । इस आयोग के प्रतिवेदन ने भारत की नौकरशाही सरकार की ज़रूरतों तथा अकुशलता की तीव्र भत्सना की और इस कमी का सारा दायित्व उस पर थोपा । उस समय मिस्टर चम्बरलैन भारत मंत्री थे । मिस्टर माट्यू ने जो पहल भारत मंत्री के मसदोय अवसरसचिव रह चुके थे मसद में भारत सरकार की इस अकुशलता की घोर निंदा की । उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि ब्रिटिश भारत में युद्ध कार्य में सहायता की जावाशा करता है तो उस यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अब वह समय जा गया है जबकि भारतवासियों का अपना देश का सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने तथा अपने भविष्य का निर्धारण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए । माट्यू की इस तीव्र आलोचना का परिणाम यह हुआ कि मिस्टर चम्बरलैन ने भारत मंत्री पद में त्याग पत्र दे दिया और माट्यू का भारत मंत्री बनाया गया । माट्यू की 1912 में भारत में आ चुके थे । उन्हें भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की मांगों के प्रति सहानुभूति थी अतः उनके भारत मंत्री पद प्राप्त करने से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं के हृदय में आशा की नहर फली ।

1916 में नाड चम्बरलैन को भारत का वाइसरॉय नियुक्त किया गया । उन्होंने भी भारत में जाते ही यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति शीघ्रानिशीघ्र भारत का स्वाशासन प्रदान करने की है । इस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विविध वर्गों तथा गुण के नेताओं में एकता हो जाने का फल यह हुआ कि कानूनी विधान परिषद् के 19 घर सरकारों निर्वाचित सन्ध्या¹ ने एक आवेदन पत्र तैयार किया । यह 19 का स्मरण-पत्र भी नाविधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रलेख है । इसके प्रमुख नतीजा दोनो वाचा मन्त्रमोहन मातवीय तजबहादुर सप्र मुहम्मदअली जिन्ना ब्राह्मी रहीमतुल्ला आदि थे । इस आवेदन का भागें लगभग उसी प्रकृति की थी जो काग्रेस नाग सम्मेलनों के ध्वनित रखी गयी थी (उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है) । इन मांगों के अंतर्गत इण्डिया कोडिफिकेशन की समाप्ति प्रान्तीय स्वशासन विधान परिषद तथा वायकारी परिषदों में निर्वाचित सन्ध्या के बहुमत केनीय एवं प्रान्तीय सरकारों में उत्तरदायी शासन स्थायी स्वायत्त शासन के विकास एवं सना में भारतीय सैनिकों को अग्रज सैनिकों के तुल्य सुविधा देने की गतें रखी गयी थी ।

घोषणा—20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री मिस्टर माट्यू ने भारत में ब्रिटिश सरकार की उत्तरदायी शासन स्थापित करने की नीति को ससम्भ घोषित किया । घोषणा इस प्रकार थी

1 इस देश के सन्ध्या की कुल सन्ध्या 27 थी जिनमें से तीन सन्ध्या अनुपस्थित थे तीन सन्ध्या ने इस योजना पर हस्ताक्षर नहीं किये और दो अग्रज भारतीय सन्ध्या में स्पष्टतः (उनके विरोध का आभास करने हुए) कोई परामर्श नहीं दिया गया ।

‘सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्णतया सहमत है, प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों के अधिकाधिक सहचार को बनाये रखने, तथा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग मानते हुए वहाँ उत्तरदायी शासन की प्रगति के निम्न स्वायत्तशासी सस्थाओं के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने की है। अतः सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस दिशा में जितनी जल्दी सम्भव हो वास्तविक कदम उठाये जाने चाहिए।’

इस घोषणा के साथ-साथ भारत मन्त्री ने यह मत भी व्यक्त किया कि इस नीति का कार्यान्वयन सीढ़ी-दर-सीढ़ी सम्पन्न होगा और ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार इन विकासक्रमों का जायजा लेते हुए निश्चित करेगी कि कब कौनसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर भारत की जनता के कल्याण का दायित्व है।

श्रालोचना—राष्ट्रीय आन्दोलन के उपर्युक्त घटनाचक्र तथा ब्रिटेन के महायुद्ध में ग्रस्त होने की अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शासन की नीति के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा करना जहाँ एक महत्त्वपूर्ण विकास था, वहाँ उसकी ईमानदारी पर सन्देह करना भी निर्मूल नहीं था। ब्रिटिश सरकार 1833 से निरन्तर ऐसे आश्वासन देती आयी थी, परन्तु उन पर अमल करना तो दूर रहा, उनकी वस्तुतः पूर्ण उपेक्षा की गयी थी। निस्सन्देह राष्ट्रीय माँगों के सन्दर्भ में भारत में ‘उत्तरदायी शासन स्थापित करने के’ ब्रिटिश सरकार के वायदे में एक नवीनता थी, जिसके बारे में घोषणा में ही यह कहा गया था कि यथाशीघ्र वास्तविक कदम उठाये जायेंगे।’ परन्तु इस घोषणा में भी कई बातें ब्रिटिश साम्राज्यवादी की पुरानी नीतियों से भरी पड़ी थी। घोषणा में कहा गया था कि भारतवासियों के कल्याण का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर है, यह नहीं कि भारतवासी स्वयं अपने भाग्य-निर्माता हैं। साथ ही उत्तरदायी शासन की दिशा में कब कौनसे कदम उठाये जायेंगे उनका निर्धारण ब्रिटिश सरकार करेगी, अर्थात् भारतीयों के लिए कब कौनसी चीज वाछनीय है उसका निर्धारण इंग्लैंड की ससद करेगी। यह धारणा राष्ट्रीय आन्दोलन की उन समस्त घोषणाओं के प्रतिकूल थी, जो स्वराज्य को भारतवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार कहती थी। फिर भी यदि ब्रिटिश सरकार ईमानदारी की नीयत से इस घोषणा पर अमल करती तो इसे पुरानी नीतियों के ऊपर एक सुधार माना जा सकता था। इसी आशा पर इस घोषणा का भारत में स्वागत किया गया था।

माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट—20 अगस्त 1917 को घोषणा के उपरान्त मिस्टर माटेग्यू भारत आये और भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के साथ भविष्य में भारतीय साविधानिक सुधारों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया। भले ही माटेग्यू के हृदय में भारत के प्रति सहानुभूति तथा उत्साह रहा हो, परन्तु शासन नीति के निर्धारण में एकमात्र उन्हीं का हाथ नहीं था। अतः जिन आशाओं तथा उत्साह को लेकर वे भारत में पवारे थे, वे कालान्तर में क्षीण भी होती गयी, क्योंकि उन्हें भारत के भविष्य की साविधानिक योजना को तैयार करने में ब्रिटिश नौकरशाही पर भी निर्भर रहना पड़ा। फिर भी उनकी भारत-यात्रा का प्रभाव यह हुआ कि भारत में ऐनी बेसेट की नजरबन्दी से जो असन्तोष उत्पन्न हुआ था, वह कम हो गया। उनकी नजरबन्दी समाप्त कर दी गयी। साथ ही स्वयं उनके विचारों में भी परिवर्तन आ गया उन्होंने आन्दोलन की उग्रता को कम कर दिया और सत्याग्रह का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार महायुद्ध के काल में माटेग्यू को भारत में व्याप्त असन्तोष को कम करने में कुछ सफलता प्राप्त हुई।

1919 के शासन सुधार अधिनियम की पृष्ठभूमि

20 अगस्त की घोषणा को कार्यरूप में परिणत करने के उद्देश्य से भारत की शासन-व्यवस्था में भविष्य में सुधार करने के निमित्त मिस्टर माटेग्यू ने भारत के वाइसरॉय लार्ड चेम्सफोर्ड के महवार में एक योजना निर्मित की जिसे माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। 1919 के

भारतीय शासन सुधार अधिनियम का आधार यही रिपोर्ट थी। परन्तु 1919 के शासन सुधारों की याजना का एकमात्र आधार यही रिपोर्ट नहीं है प्रत्युत इस याजना की स्वरूपा पहचान ही निर्मित हो चुकी थी जिसमें एक शासन की राजनीतिक टेम्पलेट कहलाती है। 1915 में वेम्बई के गवर्नर लार्ड विनिंग्टन ने शासन में भारत के भावी सांविधानिक सुधारों के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करने की मांग की थी। यद्यपि शासन अस्वस्थ था तथापि उन्होंने एक योजना की स्वरूपा तैयार की थी और जकारिया के शासन में यही याजना माट्यू चम्सफोर्ड सुधारों का सारांश थी। दूसरे काग्रस नीति याजना को जब सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के 19 सन्स्था द्वारा निर्मित स्मरण पत्र के प्रस्ताव भी उक्त सुधार योजना के निर्देशक तत्त्व सिद्ध हुए यद्यपि उसमें की गयी मांगें बहुत सावधानी के साथ ही अपनायी गयीं। तीसरे 1919 के सुधार कानून की जो मुख्य विशेषता प्राप्ति में अधिशासन प्रणाली को अपनाने की थी उसका स्रोत 'ड्यूक' आवेदन-पत्र था। सर चार्ल्स ड्यूक बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर थे और 1915 में वे एशिया की सभ्यता के सन्स्था बने। इंग्लैण्ड में एक गौन मजदूर थे जो भारतीय मामलों में बहुत अभिप्रेत रहता था। उनके एक सदस्य मिस्टर कर्न्स ने चार्ल्स ड्यूक से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करने की मांग की थी। ड्यूक की योजना में स्पष्टतया यह बताया गया था कि जब भारत में उत्तरदायी शासन की याजना को कार्यान्वित करने का समय आ गया है परन्तु इसका कार्यान्वयन गतिमान होना चाहिए। सर्वप्रथम प्रांतीय शासन में कुछ प्रशासनिक विषया (यथा गिरा स्वास्थ्य म्यानीय स्वाशासन आदि) पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए परन्तु पुनिस सामान्य प्रशासन सहित महत्वपूर्ण विषया को संगठित रखा जाना आवश्यक है। उक्त जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के नियन्त्रण में रखने का समय अभी नहीं आया है। उनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका के सन्स्था के परामर्श से करे। हस्ताक्षरित विषया का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में सौंप दिया गया मन्त्रियों के हाथ में रहे और वे मन्त्रा प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों। जब लार्ड चम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल बनकर आये तो उन्होंने मिस्टर कर्न्स से ड्यूक योजना की मांग की। वास्तव में 1919 के शासन सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय अधिशासन प्रणाली का आधार यही याजना थी।

माट्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिश—भारत में शासन सुधारों की भावी याजना के सम्बन्ध में माट्यू तथा चम्सफोर्ड ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसका आधार उपर्युक्त सामग्री थी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत मुख्यतया निम्नलिखित सिफारिशें की गयीं थी जिनके आधार पर सन्स्था में 1919 का भारतीय शासन सुधार कानून पास किया गया।

(1) यथासम्भव म्यानीय स्वाशासन सन्स्थाओं में पूर्णतया जन नियन्त्रण होना चाहिए और उन्हें बाहरी नियन्त्रण से अधिकारों के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए।

(2) उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास की प्रथम मंजूर प्रांतीय सरकार होनी चाहिए। उसमें सर्वप्रथम थोड़ा बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का प्रयोग शुरू कर दिया जाना चाहिए और व्यापक परिस्थितियाँ अनुकूल होती जायें तब तब पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का उद्देश्य रहना चाहिए ताकि प्रांतीय विधायी प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन लागू करने का लक्ष्य मध्यम उठाया जा सके।

(3) जहाँ तक केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है माट्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट में बतलाया यही सिफारिश की गयी थी कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का और अधिक प्रतिनिध्यात्मक तथा विस्तृत बनाया जाय और उसमें अधिकारों में ऐसा विस्तार किया जाय जिससे वह शासन को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रभावित कर सके। इस उद्देश्य से केन्द्रीय विधानमण्डल के लिए दो सन्स्था की स्थापना की सिफारिश की गयी। परन्तु केन्द्रीय सरकार की कार्यकारी परिषद् के अधिकारों में किसी प्रकार के परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई। सन्स्था में केन्द्रीय सरकार को पूर्णतया

ब्रिटिश समद के प्रति उत्तरदायी रखा गया ।

(4) यह भी सिफारिश की गयी कि उपर्युक्त शासन-सुधारों के सन्दर्भ में भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के ऊपर समद तथा भारत मन्त्री के नियन्त्रण को उसी अनुपात में शिथिल किया जाये, जितना अनुपात में उन्हें उत्तरदायी शासन प्रदान किया जायेगा ।

आलोचना—माटैग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन से भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को घोर अनन्तोष हुआ । प्रांतीय द्वैध-शासन की योजना ने भारतीय नेताओं की उत्तरदायी शासन की माँगों पर पानी फेर दिया । केन्द्रीय शासन को अनुत्तरदायी रखने की सिफारिश ने उनकी निराशा को और अधिक बढ़ा दिया । यद्यपि साम्प्रदायिक निर्वाचनों की प्रणाली को बनाये रखने की सिफारिश की गयी थी तथापि मुस्लिम लीग भी मन्तुष्ट नहीं हुई । राष्ट्रीय तत्त्वों के विकास को जबरदस्त करने के हेतु नरेन्द्र-मण्डल महान् प्रतिगामी व्यक्ति का सृजन करने की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गयी थी । इस प्रकार इस रिपोर्ट ने भारतीय जनमत को बड़ा धक्का पहुँचाया । भारतवासी ने जिन उत्साह तथा सद्भावना से युद्ध काल में अंग्रेजों की सहायता की थी, उसके बदले में राष्ट्रीय माँगों को नितान्त उपेक्षित रखने की ब्रिटिश साम्राज्यशाही नीति भारत के लिए न केवल असन्तोषजनक ही थी, अपितु अपमानजनक भी थी । चूँकि यही रिपोर्ट 1919 के शासन सुधार कानून का आधार बनी, अतः 1919 के वैधानिक सुधारों से भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में नया मोड़ आना स्वाभाविक था ।

प्रश्न

- 1 प्रथम महायुद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर प्रभाव आँकिये ।
- 2 होम-रूल आन्दोलन पर टिप्पणी लिखिये ।
- 3 नवतन्त्र पैक्ट (1961) की विवेचना कीजिए ।

असहयोग आन्दोलन (NON COOPERATION MOVEMENT)

असहयोग आन्दोलन का अभिप्राय

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन व प्रतिहाम म 1920 का वष एक नय चरण का गिनायाम करना ॥ 1905 म काग्रस म अन्तर उदार तथा उग्र दा दना क मजन तथा बीसवा सदी क प्रथम दो दशका के जनगत राष्ट्रीय आन्दोलन क विकास एवं ब्रिटिश शासन की दमनकारी और उपक्षायपूर्ण नीतिया न यत् सिद्ध कर लिया था कि उन्नावानी गुप्त ब्रिटिश सरकार से सहयोग करत एण ब्रिटिश शासन के अतगत ही स्वायत्त शासन क अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करने की नितात असफल चप्या करता रहा था। इसीनिण उग्रवादिया का स्व असहयोग की नीति पर तुना था। साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलन का एक वग क्रान्तिकारी तथा जातकवाणी कार्यक्रम द्वारा दन का ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहता था। महायुद्ध (1914-1919) की अवधि म राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ नीमा पड गया था। उनक नेतृत्व म भी अंतर आ गया था। पुराने उन्नावदिया म सुरक्षाथ वनजी हा प्रमुख नता थप रह गय थ। काग्रस का नतृत्व तिनक क हाथ आ चुका था अत उग्रवानिया का प्रभाव प्रदना जा रहा था। बाल नातमान की जाती जीविन थी। युद्ध की अवधि म महात्मा गांधी भी काग्रस के प्रमुख नताआ की श्रणी म आ चुक थ। युद्ध काल म उहाने भारत की ओर म अग्रजा की हर तरह से सहायता की थी। अत उह कमर हित की उपायि दी गय थी। गांधी जा पर गोखले का प्रभाव वन्त अधिक था। जन व भा उदारवादिया की भाति ब्रिटिश सरकार क साथ सहयोग करने का नीति क समर्थक थ। युद्धकाल म भारत न जिस भावना तथा तनन से अग्रजा की सहायता की थी तथा अग्रजा न गा आश्वामन भारतवासिया का दिय थ उनके प्रतिफल तथा पूर्ति की भारतवासामा वणी उत्पुक्ता के साथ प्रताशा कर रह थे।

पन्तु 1919 म जा घटनाए घना उन्तान यह सिद्ध कर लिया कि अग्रज लोग म न श्रमानदारी ॥ न सह्यता ॥ प्रत्युन्व राष्ट्रवादी गतिया को अमानवीय ढग म कुचनने पर तुन है। अत महात्मा गांधी न तुरन्त अपना स्व वन्त दिया और उनक नेतृत्व म काग्रस ने ब्रिटिश सरकार क साथ असहयोग करने क हनु अहिमात्मक सत्याग्रह तथा प्रत्ये क कायवाही का कार्यक्रम अपनाया। इस प्रकार काग्रस जो गन 35 वष तक राजनीतिक मिश्रावृत्ति तथा ब्रिटिश सरकार म सहयोग करने की नीति अपनाती रही थी सन्व के लिए वन नीतिया का त्याग कर अहिमात्मक राजनीतिक सघप तथा असहयोगपूर्ण अवका का नीति पर आ गयी। 1920 म तिनक की मृत्यु हा चुकी थी। अत इसके पन्चात् भारतीय राष्ट्रीय काग्रस का यथाय नतृत्व पूणतया गांधी जी क हाथ म आ गया। राष्ट्रीय आन्दोलन का नतृत्व सम्भालन पर गांधी जी का प्रथम कार्यक्रम असहयोग आन्दोलन था। इसके पन्चात् स्वतन्त्रता प्राप्ति तक अर्थात् पूर 28 वष तक गांधी जी काग्रस क सर्वोच्च नता वन रन्। अत असहयोग आन्दोलन स नरर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक का पूरा काल राष्ट्रीय आन्दोलन क प्रतिहाम म गांधी युग के नाम म जाना जाता है।

असहयोग आन्दोलन छेन्न क कारण

जिन परिस्थितिया तथा कारण म 1920 म महात्मा गांधी क नेतृत्व म असहयोग

आन्दोलन प्रारम्भ किया गया वह संक्षेप में निम्नलिखित थे—

(1) कांग्रेस में पुनः विभाजन—1919 के सुधार कानून की भारत में विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हुईं। नेताओं का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सुरेन्द्रनाथ बनर्जी करते थे, सुधार योजना से सन्तुष्ट था और तत्कालीन परिस्थितियों में जो स्वायत्तता के अधिकार दिये गये थे उन्हें भारतीयों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त समझता था। यह वर्ग ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके इन सुधारों के कार्यान्वयन में भाग लेने का इच्छुक था। स्वयं गांधी जी भी गोखले के शिष्य होने के नाते सुधारों के कार्यान्वयन में सरकार के साथ सहयोग करने की नीति के समर्थक थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय उदार संघ (National Liberal Federation) की स्थापना की गयी और यह दल सुधारों के अन्तर्गत सरकार से सहयोग की नीति पर चला। परन्तु 1919 के प्रारम्भ में ब्रिटिश शासकों ने जिन दमनकारी अमानुषिक व्यवहारों का प्रदर्शन किया (विशेष रूप से जलियावाला बाग हत्याकाण्ड तथा रौलेट एक्ट का पारित किया जाना) उन्होंने गांधी जी के विचारों में परिवर्तन कर दिया और वे एकाएक सहयोग की अपेक्षा असहयोग की नीति पर तुल गये और चूँकि 1920 में तिलक की मृत्यु हो जाने पर कांग्रेस का नेतृत्व पूर्णतया गांधी जी पर आ गया था, अतः गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रहे-सहे उदारवादी पुनः कांग्रेस से पृथक् हो गये।

(2) रौलेट एक्ट के विरुद्ध प्रतिक्रिया—यद्यपि भारत में ब्रिटिश शासकों ने अतीत में राष्ट्रवादी तथा क्रान्तिकारी तत्त्वों को दबाने के लिए समय-समय पर अनेक दमनकारी कानून पास किये थे, तथापि 1919 के रौलेट एक्ट तथा इस वर्ष के दमनकृत्य नितान्त अवाञ्छनीय एवं अमानुषिक थे। युद्ध काल में सरकार ने विरोधी तत्त्वों को दबाने के लिए भारत रक्षा कानून पास किया था। युद्ध की समाप्ति पर इसे समाप्त हो जाना था। परन्तु देश में विकसित हो रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रान्तिकारिता को पुनः दबाने की नीति सरकार ने अपनायी। अतः न्यायाधीश रौलेट की अव्यक्तता में ऐसा कानून बनाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। उसकी सिफारिशों के आधार पर रौलेट के नाम से दो विधेयकों का प्रस्ताव रखा गया था। इनमें से एक को केन्द्रीय विधान-सभा ने पास कर दिया था, जिसके अनुसार सरकार को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह राजनीतिक विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोहियों को बिना न्यायिक सुनवाई किये अनिश्चित काल तक कारावास में रख सकती थी। विधानसभा के भारतीय सदस्यों ने इसका तीव्र विरोध किया परन्तु फिर भी 17 मार्च 1919 को यह कानून पास हो गया। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल को देशव्यापी अहिंसात्मक हड़ताल का आह्वान किया। अतएव दूसरा विधेयक पास होने से रोक लिया गया। दिल्ली में यह हड़ताल 13 अप्रैल को मनायी गयी। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी गयी। हड़ताल शान्तिपूर्ण रही, परन्तु दो एक स्थानों पर साधारण सघर्ष हुए। जब गांधी जी को दिल्ली व पंजाब में प्रवेश करने से रोककर बन्दी बनाया गया तो इससे देशव्यापी रोष फैला और कई स्थानों पर आन्दोलन की तीव्रता को सरकार ने कठोरता से दबाया।

(3) जलियावाला बाग का हत्याकाण्ड—इस अवधि में क्रान्तिकारी आन्दोलन का स्थल पंजाब बन रहा था। सरकार को पंजाब की अधिक चिन्ता थी, क्योंकि वह अफगानिस्तान तथा रुम से निकट था, जिनका खतरा अंग्रेजों को मदा रहा था। रौलेट एक्ट के विरोध में आन्दोलन करने वाले दो पंजाबी जनप्रिय नेताओं डा० किचलू तथा डा० सत्यपाल को जब सरकार ने बन्दी कर लिया तो जनता में रोष की आग भड़क उठी। आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र अमृतसर था। पंजाब के उप-राज्यपाल माइकल जो० डायर के आदेश पर ये बन्दिyaँ 10 अप्रैल को मारी गयी थीं। इन बन्दि्यों के विरुद्ध प्रदग्गनकारी तत्त्वों को बल-प्रयोग द्वारा दबाया गया। गोलियाँ भी चलीं, जिनमें कई व्यक्ति मरे। जनता का रोष अधिक बढ़ा। मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि के पश्चात् अमृतसर की जनता की एक भीड़ ने कुछ यूरोपियों पर गोली चलायी। उप-गवर्नर ने जालन्धर

○ राष्ट्रीय आन्दोलन/12

सैनिक निराजन के कमाण्डो जनरल डायर से विवाह का दवान में मदद मांगी वह तुरन्त सैनिक टुकड़ी सहित अमृतसर पहुँचा। 13 अप्रैल को अमृतसर की जनता सरकार के मंत्री-काण्ड के विरुद्ध सभा करने के लिए अनियावाना बाग नामक स्थान पर एकत्र हो रहा थी। जनरल डायर ने इस सभा की मनाही की। परन्तु जनता को इसकी सूचना नहीं मिल पायी। जिन्हें मिनी भा उहान परवाह नहीं थी। जब जनरल डायर को सूचना मिली कि जनता सभा में इकट्ठी हो गई है तो वह 150 मण्डल ट्रिनिंग तथा भारतीय सैनिकों सहित सभा-स्थल पर पहुँचा। यह स्थान नगर के केंद्र में चारों ओर इमारतों से घिरा है। कबन एक मांग जान का था। रात तीन भाग बंद थे। यह सभा पूर्णतया शांतिपूर्वक हो रही थी। जनता निराश्रय थी। हजारों की संख्या में लोग स्त्रियाँ बच्चा सहित वहाँ एकत्र थे। रात तथा दानव डायर ने सैनिकों का सभा में एकत्र व्यक्तियों पर गोला चरानों का आगोश दिया। कहा जाता है कि 1650 तक बंदूक के फायर किया गया और तब तक गोलीयों की शक्ति रही जब तक कि गोलियाँ समाप्त नहीं हो गईं। नगरमातृपूर्वक निरीह जनता पर गोला चलाने की निंदयता का ऐसा दृष्टान्त विश्व के इतिहास में सम्भवतः कहीं नहीं मिलेगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे तथा 1137 घायल हुए थे। परन्तु वास्तव में यह संख्या कहाँ अधिक आती है। हत्याकाण्ड के अर्थ विवरणों का वर्णन करते हुए किसी का भी चिन्ता नहीं होती है। हत्याकाण्ड के उपरान्त डायर मृतकों की रागा की छाँट कर चला गया। अमृतसर में मांग का नून नाम किया गया। यहाँ के वास्तविक समाचार दश के अर्थ भाग में पहुँचने में रोकें गए। किसी भी प्रकार के राय को उसी नगरसेता के साथ दबाया गया।

परन्तु जब यह खबर दश में पड़ी तो जनता का रोष तथा दुःख बढ़ता स्वाभाविक था दश की महान् विभूतियों की आर से सश्रम महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के विवरण खी न्नाथ टगार की हुई जिहान ट्रिनिंग शासका के दम कर कृत्य का देखकर गवर्नर जनरल का निश्चय एक पत्र के साथ अपनी नाइटहुड (Knighthood) की पदवी वापिस कर दी। सर गवर्नर नाथर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया।

सरकार ने इस क्रूर हत्याकाण्ड का निरूपण भी गम्भीरता से नहीं लिया। दशव्यापी असंतोष का दंगल हुए 6 मास पश्चात् अक्टूबर में हटर कमीशन का निर्माण किया गया। मार्च 1920 में इसकी रिपोर्ट निकली जिसमें जनरल डायर का बचान का प्रयास किया गया और उसके कृत्य को निणय नत की भूत कहा गया। उसे सेवा से निवृत्त तो कर दिया गया परन्तु साथ ही ब्रिटिश संसद में कुछ सदस्यों ने उसकी प्रशंसा सम्बन्धी भाषण तक दिये। उसे सम्मान का तनवार तथा 2000 पौंड की धनराशि भेंट की गई। इंग्लैंड स्थित शासका ने उसके कृत्य को सम्मानकारी से पूर्ण परन्तु भ्रामक निणय कहा। स्वयं जनरल डायर ने स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य भविष्य में एक विवाह को रोकने के हेतु आतंक उत्पन्न करना था।

परन्तु भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इस हत्याकाण्ड को बहुत गम्भीरता के साथ लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस घटना का जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट में जनरल डायर के कृत्य की घोर भत्सना की गई। समिति के विचार से मृतकों की संख्या सरकारी रिपोर्ट की अपेक्षा कहाँ अधिक थी। कांग्रेस ने माँग की कि मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों का पर्याप्त अधिक सहयोग दी जाय और इस हत्याकाण्ड के दोषी अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जाय। परन्तु इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अग्रा के दश स्वयं से गांधी जी बहुत अमन्युष्ट हो गए। नवम्बर 1919 तक उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने का बना रहा था। परन्तु अब वे असहयोग हो गए और नवम्बर 1920 में वे पक्के असहयोगी बन गए।

✓ (4) खिलाफत आन्दोलन—लार्ड मिण्टो ने भारतीय राजनैतिक में साम्प्रदायिकता का विप फनाकर भारतीय मुसलमानों का कांग्रेस का विरोधी बना लिया था। परन्तु घटनाक्रम ने 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को बहुत कुछ समाप्त हो दिया था। यद्यपि मुसलमानों का राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक् रहने के निमित्त साम्प्रदायिक निर्वाचित पद्धति बनो रही स्वयं कांग्रेस-लीग

समझते थे भी इसे स्वीकार कर लिया था, और 1911 के सुधार कानून में भी इसे मान्य किया गया था, तथापि युद्ध की अवधि में भारत के मुसलमान अंग्रेजों से असन्तुष्ट रहे। राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने के निमित्त भावी कार्यक्रम में कांग्रेस को मुसलमानों का सहयोग प्राप्त होने का यह सर्वोत्तम अवसर था। अतः मुसलमानों के अमन्तोष में खिलाफत आन्दोलन के साथ कांग्रेस ने भी मुसलमानों का साथ दिया।

खिलाफत आन्दोलन

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों में सर सैयद जहमद खाँ के विचारों तथा प्रचारों ने भारतीय मुसलमानों के मानस में पृथकतावादी भावना भर दी थी। इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और स्वतन्त्रता आन्दोलन में कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से एक प्रतिगामी संगठन मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया। 1909 के शासन सुधार कानून ने साम्प्रदायिक निर्वाचन रूपी विष फैलाकर भारत की राष्ट्रीय शक्तियों को भारी धक्का पहुँचाया। परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि में मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने एक नया मोड़ लिया, जो कम से कम थोड़े से समय तक ही सही, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता के मार्ग में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। 1916 में जहाँ एक ओर कांग्रेस के उग्र तथा उदार गुटों में एकता आ गयी, वहाँ कांग्रेस तथा लीग के मध्य भी लखनऊ के समझौते ने एकता का संचार किया। इस समय ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रथम विश्व युद्ध में उनभे हुए थे, और वे इस साम्प्रदायिक एकता को देखकर बहुत ध्रुब्ध होते हुए भी इसे तोड़ने की दिशा में कुछ न कर सके। उन्हें युद्ध-प्रयासों के लिए भारतवासियों के सहयोग की अधिक चिन्ता थी जो उन्हें प्राप्त होता आ रहा था।

परन्तु युद्ध में टर्की का प्रवेश भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग के लिए चिन्ता का विषय बन गया था। वे टर्की के सुलतान को अपना खलीफा मानते थे और समस्त अरब क्षेत्र में मुस्लिम तीर्थ स्थानों में टर्की के ओटोमन साम्राज्य की सम्प्रभुता बनाये रखना और उन तीर्थ स्थानों की सुरक्षा की गारन्टी चाहते थे। जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध में टर्की जर्मनी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेगा तो यह भय था कि भारत के मुसलमान अंग्रेज सरकार का साथ दे या टर्की के प्रति निष्ठावान बने रहे। भारत का 'मुस्लिम जनमत इस विषय पर विभाजित था कि कुछ लोग सरकार के प्रति निष्ठावान रहकर उसे युद्ध में मदद देना चाहते थे। कुछ ओटोमन खलीफा के भविष्य के बारे में चिन्तित थे।'¹ प्रथम वर्ग में जिन्ना प्रमुख थे और द्वितीय में अब्दुलवारी, डा० अन्सारी, अजमल खा, अबुल कलाम आजाद आदि थे। ये उलेमा वर्ग के थे। इन्होंने अफगानिस्तान, सीमा प्रान्त तथा अरब देशों में अपने अभिकर्ता इस उद्देश्य से भेजे कि वे टर्की को जर्मनी की सहायता से भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि भारत से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ा जा सके।² कांग्रेस लीग एकता भी अंग्रेजों के लिए चिन्ता का विषय बन गयी थी। अतः अंग्रेजों ने मुस्लिम उलेमा की विश्वास दिया कि युद्ध में अरब के मुस्लिम तीर्थों तथा मेसोपोटामिया को पूर्णतः सुरक्षित रखा जायेगा।

अक्टूबर-नवम्बर 1918 में मित्र-राष्ट्रों के समक्ष जर्मनी तथा टर्की की पराजय हो गयी। नेवर्स में टर्की के साथ अंग्रेजों ने सन्धि की। इसके अनुसार टर्की के साथ अंग्रेजों का व्यवहार अत्याचारपूर्ण सिद्ध हुआ। मुस्तफा कमाल पाशा टर्की शासक बना, उसने किसी तरह टर्की को और अधिक बरवाद होने से तो बचा लिया, परन्तु अरब क्षेत्रों में स्थित मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर टर्की की सम्प्रभुता नहीं रही। इस प्रकार मुस्लिम जगत में टर्की के सुलतान की खिलाफत समाप्त हो गयी। खलीफा पद की ऐसी प्रतिष्ठा-भंगता से उनके प्रति निष्ठावान भारतीय मुस्लिम वर्ग को भारी आघात पहुँचा। 1918 के मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए

¹ Tara Chand *History of the Freedom Movement in India*, Vol III, 415

² *Ibid*

फज्जुन हू न घोषणा की कि हम घटना में भारत में इस्लाम का भविष्य अधिकारमय नगता है। विश्व में कहा भी मुस्लिम शक्ति का हल्ला होगा उसका कुप्रभाव भारत में मुस्लिम सम्प्रदाय के राजनीतिक जीवन पर अवश्य पड़ेगा। उनमें के अग्र प्रमुख नेताओं की भी ऐसा ही भावनाएँ थी। हम प्रकार भारत में मुस्लिम सम्प्रदाय के धर्म प्रेरित वर्ग के मन में टर्की के खलीफा के प्रति त्रिटेन के व्यवहार के कारण भारत में त्रिनि गायन के प्रति भी राय उत्पन्न हो गया। कांग्रेस काग ममभौत के फनस्वरूप होम स्न कार्यक्रम में नीग गामिन हो चुकी था। धर गिनाफन आन्दोलन का वातावरण तयार हो चुका था।

नितम्बर 1919 में नखनऊ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें एक अखिल भारतीय गिनाफन समिति का निमाण किया गया जिसके अध्यक्ष मठ छात्रानी और मंत्री मोताना गौततत्रनी नियुक्त किये गये। नवम्बर 1919 में दिन्नी में हमारा सम्मेलन हुआ जिसमें फज्जुन हू न सभापित्व किया। हम सम्मेलन में गांधी जी मोताना नहू तथा मन्तमाहन माननीय जी भा उपस्थित थे। अगले दिन स्वयं गांधी जी को सम्मेलन का सभापति चुना गया। गिनाफन आन्दोलन के मुस्लिम वर्ग के साथ गांधी जी तथा कांग्रेस के सभी उच्चतम नेताओं की पूर्ण सहानुभूति बना रही। यहाँ तक कि निनक मानवीय जी तथा नाना राजपतराय सहू कट्टरपथी हिंदू नेता भी गिनाफन आन्दोलन के समर्थक बन गये। इस प्रकार कांग्रेस के नतत्व में मुस्लिम धर्म प्रेरित गिनाफन आन्दोलन का हिन्दू मुस्लिम एकता का एक राजनीतिक अस्त्र बनाया। हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन को पर्याप्त शक्ति प्राप्त होने की आशा की गयी थी। कांग्रेस तथा गिनाफन समिति पर्याप्त भातत्व के वातावरण में कार्य करने लगी। गिनाफन समिति ने त्रिनि प्रदानमन्त्री तथा वास्मराय के पाम प्रतिनिधि मण्डल भेज और भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का टर्की के खलीफा के साथ किये गये अत्याचारों के विरुद्ध पहुँचाकर उन्हें ठीक करने की माँग की परन्तु उन्हें निराश होना पड़ा।

धर महारमा गांधी ने त्रिनि सरकार के भारत स्वायत्त गायन की माँग के प्रति उपक्षा पूर्ण खयाल जपाना तथा गतिपूर्ण एवं सरकार के साथ निरंतर सहयोग करने वाली जनता को रोने एकट जतियावाता वाग हत्यानाट्र गति दमनकारी तरीका से व्यवहार करने की नीतियाँ के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम बना लिया था। जब गिनाफन समिति का भी त्रिनि गायन में उपेक्षित ग्या ता गिनाफन आन्दोलन के नेता भी गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के समर्थक बन गये। दाता संगठना न असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर लिया।

कार्यक्रम—कांग्रेस तथा गिनाफन समिति के सह नतत्व में गांधीजी के असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम साथ साथ चला। गांधी जी का कहना था कि यदि हिंदू जनता मुसलमानों के साथ शाश्वत मित्रता चाहती है तो उसे भी इस्लाम के सम्मान की रक्षा के लिए मर मिटना चाहिए। इस प्रकार दाता संगठना ने जो कार्यक्रम अपनाया उसे गिनाफन कार्यक्रम ने अपने कराँची अधिवेशन में जुलाई 1921 में निम्नांकित रूप दिया

- (1) गिनाफन माँगों की पूर्ति की उपनिधि करना
- (2) टर्की की सम्प्रभुता पर किसी भी मर्यादा की अस्वीकृति
- (3) अरब अम्मा में स्थित मुस्लिम ताथ स्थानों के ऊपर किसी भी घर मुस्लिम नियन्त्रण का अस्वाकाराति
- (4) त्रिनि सना में किसी भी मुसलमान द्वारा भर्ती का इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानना और
- (5) भारत में त्रिनि गायन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा कार्यक्रम में कांग्रेस के साथ सहकार करना तथा यदि त्रिनि सरकार टर्की में कोई सैनिक वायवाहक कर तो भारत में गणतन्त्र की स्थापना के निमित्त पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करना।

गिनाफन आन्दोलन के नेताओं ने असहयोग आन्दोलन में निष्ठापूर्वक भाग लिया। त्रिनि सरकार का दमन चक्र भी तीव्र हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रयासधारिया में सरकार से

कोई अनुदान न प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। जब उन्होंने इस माग को न माना तो आन्दोलनकारियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। उलेमा के नेताओं को बन्दी किया गया। इस प्रकार खिलाफत आन्दोलन ने अमहयोग आन्दोलन को तीव्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया।

आन्दोलन की दुर्बलतायें तथा प्रभाव—यह एक आश्चर्य की बात थी कि भारत के एक धर्म-प्रेरित मुस्लिम वर्ग की अभिरुचि टर्की के सुलतान की मुस्लिम जगत में खलीफा के रूप में सम्प्रभुता बनाये रखने के प्रति इतनी अधिक थी। डा० ताराचन्द के अनुसार 'अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया के मुस्लिम देशों के साथ भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति पूर्णतः आदर्शवादी अथवा पूर्णतया अव्यावहारिक थी।'¹ अन्य मुस्लिम देशों के मध्य इस्लामी एकता का आधार अनेक प्रकार के राजनीतिक सम्बन्धों का होना था। जहाँ भारतीय मुसलमान अन्य सम्पूर्ण इस्लामी देशों के मध्य एकता की कामना करते थे, और टर्की के सुलतान को सम्पूर्ण मुस्लिम जगत की धार्मिक सम्प्रभुता (खलीफा) देना चाहते थे, वहाँ यह भी सन्देह है कि विरुद्ध के अन्य मुस्लिम देश भारत के अपने मुस्लिम भाइयों को ऐसी ही दृष्टि से देखते हों। दूसरी ओर स्वयं पश्चिम एशिया तथा अरब के अनेक मुस्लिम देश अपने ऊपर ओटोमन सुलतान के राजनीतिक या धार्मिक प्रभुत्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे। स्वयं भारत में सर सैयद सदृश मुस्लिम नेता टर्की के सुलतान को खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार भारतीय मुसलमानों का खिलाफत आन्दोलन कोरा धार्मिक आदर्शवाद था। आन्दोलन को राजनीतिक स्वतन्त्रता आन्दोलन का रूप देना और स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इसके माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम एकता का स्वप्न देखना भ्रामक था। फिर भी गांधी जी का मत था कि राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्रम में खिलाफत आन्दोलन का सहयोग प्राप्त करना मानवीय तथा नैतिक दृष्टि से उचित था। यह सर्कीर्ण अर्थ में राजनीतिक नहीं था, भले ही राष्ट्रीय हितों के स्थायी संरक्षण के निमित्त इसका उपयोग किया गया था।²

भारतीय मुसलमानों का यह आन्दोलन विजयी मित्र-राष्ट्रों, जिनमें इंग्लैंड प्रमुख था, को खलीफा की सम्प्रभुता तथा मुस्लिम तीर्थ स्थानों में उसके नियन्त्रण को बनाये रखने को विवश नहीं कर सकता था। परिणाम यह हुआ कि जिन मुसलमानों ने युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़कर टर्की में अंग्रेजों को विजयी बनाया उनके नेताओं को अंग्रेजों ने खलीफा के बारे में जो आश्वासन दिये थे, वे पूर्ण नहीं हो पाये। अरब देशों के ऊपर इंग्लैंड, फ्रांस आदि मित्र-राष्ट्रों का प्रभुत्व कायम हो गया। खिलाफत आन्दोलनकारी अंग्रेजों को अपनी नीति बदलने को बाध्य नहीं कर सके।

केरल में जब मोपला विद्रोह खड़ा हुआ तो धर्मान्ध मोपला विद्रोहियों को सरकार द्वारा दमनात्मक तरीकों से कुचलने के प्रयास में उल्टे मोपलों ने वहाँ के हिन्दुओं के ऊपर ही अत्याचार कर दिया। इसके कारण लाला लाजपतराय तथा मालवीय जी को तथाकथित हिन्दू-मुस्लिम एकता में सदेह हो गया। जब चौराचौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया तो खिलाफत आन्दोलन के अनेक नेताओं को गांधी जी के ऐसे रवैये पर ही अमनोत्पत्ति होने लगा। स्वयं कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी से रूढ़ हो गया। पंडित मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी तथा सी० आर० दास ने उदारवादी स्वराजिस्ट दल का निर्माण किया और उन्होंने 1919 के सुधार कानून में सरकार को सहयोग देकर उक्त कानून की खामियों को प्रकट में लाने का कार्यक्रम बनाया। अक्टूबर 1922 में कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की में गणतन्त्र की स्थापना कर दी गयी। सुलतान को नामधारी खलीफा बनाया गया जिसके हाथ से लौकिक सत्ता छिन गयी। कालान्तर में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार भारतीय मुसलमान खिलाफत नेताओं को घोर असन्तोष तथा निराशा का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार खिलाफत आन्दोलनकारियों को एक ओर तो ब्रिटिश सरकार के दमनचक्रों

का सामना करना पड़ा तो दूसरी ओर असहयोग आन्दोलन की वापसी न उनका उत्साह को ठण्डा कर दिया और तीसरी ओर स्वयं टर्की में हुए विकास क्रम ने उनकी आगाआ पर पानी फेर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में खिलाफत आन्दोलन की घटना आन्दोलन की सफलता के मांग में एक बड़वा घट मिट्टी हुई। प्रारम्भ में जो हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण इसके कारण बना था वह इस आन्दोलन की असफलता के कारण सत्ता के लिए समाप्त हो गया। डा. नारायण के गान्धी में यह स्वाभाविक था कि अत्यधिक भावुक तथा धर्मांध खिलाफतियों ने अपने उद्देश्य की असफलता के लिए गांधी जी का दाप लिया और जब वे एम. सम्प्रदाय से जो उनका राय में उनकी असफलता का कारण था अपने को पृथक् रखने का विचार करने लगे। भारतीय मुसलमानों के लिए तत्कालीन मजहब में खिलाफत की समस्या मुख्य थी स्वायत्त शासन की माँग गौण। वास्तव में धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यों का सफल नहीं बना सकता था। गांधी जी की राजनाति धर्म नतिकता तथा मानवतावादी सभा कुछ हो सकती थी परन्तु यह उनकी भूल थी कि उन्होंने एक धर्मांध आन्दोलन को राजनाति का अस्त बनाया जो भावी कायनेम के निमित्त पूजनया विराधी मिट्टी हुआ। खिलाफत आन्दोलन की असफलता ने भारतीय मुसलमानों के एक बग के पृथक् राष्ट्रीयता की भावना से भर दिया और बाद में अवधि में एक बार पुनः ब्रिटिश शासक का साम्प्रदायिक पापकथ का उकसाने तथा उसका लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।

कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन की स्वीकृति

स्पष्ट है कि 1919 के सुधार कानून से उत्पन्न असन्तोष रौलेट एक्ट जिनियावाना बाग हत्याकाण्ड तथा खिलाफत आन्दोलन ने कांग्रेस के उग्रवादी तथा प्रगतिवादी बग के ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने की नीति अपनाने के लिए विवश कर दिया था। उस समय कांग्रेस का नतत्व उग्रवादी नेताओं के हाथ में था। जगस्त 1920 में निरंकुश की मृत्यु का ज्ञान पर कांग्रेस का पूरा नतत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। मिनम्बर 1920 में कन्नडा में कांग्रेस का विभाज्य अधिवेशन हुआ। यद्यपि इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के विभाज्य बन्धन का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सी. आर. दास राजपत राय मानवीय जी विपिन चन्द्र पान जिन्ना तथा एनी बेसेन्ट इसके समर्थन में नहीं थे। तथापि धार्मिक बहुमत से यह पार हो गया। बाद में मिनम्बर 1920 के कांग्रेस के नियमित नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक विभाज्य बहुमत से इसकी पुष्टि कर दी।

इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का नागपुर अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पश्चात् कांग्रेस की राजनातिक भिन्नवृत्ति की नीति सत्ता के लिए समाप्त हो गई और उसका स्थान अहिंसात्मक सधष न दिया। इस पूर्व कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत स्वायत्त शासन प्राप्त करना था। अब उसका उद्देश्य एम. स्वराज्य की प्राप्ति करना हो गया जो यदि सम्भव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर लिया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो उससे बाहर रहकर। अब कांग्रेस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल बधानिक साधना के अवलम्बन करने तक सीमित नहीं रही। मन्त्रालय गांधी मत्याग्रह का सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे अब सत्य तथा अहिंसा पर उनका अद्वैत विश्वास हो चुका था। उनके नतृत्व में कांग्रेस की कायविधि अहिंसात्मक मत्याग्रह की धापिन की गया। इस हेतु कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ममम्न शान्तिपूण तथा औचित्यपूण साधना को

प्रयुक्त करने का सकल्प किया। कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसे अपने उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मात्र वैधानिक साधनों से सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि अतीत में ऐसे साधनों से उसे कोई लाभ नहीं हुआ था।

असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम

कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पास करने के साथ-साथ अपने कार्यकर्ताओं तथा जनता से निम्नांकित कार्यवाही करने का आह्वान किया, जो असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम की सूचक है—

- (1) समस्त पदवियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग करना,
- (2) स्थानीय स्वशासन सस्थाओं के नामांकित पदों से त्याग-पत्र देना,
- (3) सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित तथा उनके सम्मान में किये गये उत्सवों का बहिष्कार,
- (4) सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को रोकना,
- (5) वकीलों तथा वादी-प्रतिवादियों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार,
- (6) मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिक सेवाओं की प्रविष्टि का विरोध,
- (7) 1919 के कानून द्वारा सगठित की जाने वाली परिषदों के लिए उम्मीदवारी तथा मतदान करने का बहिष्कार।
- (8) विदेशी माल का बहिष्कार,
- (9) राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाओं की स्थापना तथा उनका अधिकाधिक उपयोग,
- (10) लोक न्यायालयों की स्थापना से उनमें पचायती निर्णयों से विवादों को हल कराना,
- (11) हथ-करघा तथा कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा स्वदेशी माल का उपयोग,
- (12) साम्प्रदायिक एकता का विकास,
- (13) छुआछूत के भेदभाव का अन्त करना, तथा
- (14) सर्वत्र अहिंसात्मक ढंग से आचरण करते हुए उक्त कार्यक्रम को सम्पन्न करना।

गांधी जी का विश्वास था कि यदि यह कार्यक्रम ईमानदारी तथा सच्ची भावना से कार्यान्वित किया जाय तो भारत एक वर्ष की अवधि में स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। असहयोग आन्दोलन का यह कार्यक्रम पहले के स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन का ही विकसित रूप था। इसके दो पक्ष थे। एक ओर यह ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने के तरीकों को बताता है, और दूसरी ओर यह उन रचनात्मक कार्यों पर जोर देता है जो बहिष्कार तथा असहयोग के फल-स्वरूप होने वाली रिक्तता को भरने में सहायक सिद्ध हों।

आन्दोलन

असहयोग आन्दोलन कैसे प्रारम्भ किया जाय, यह बात नयी नहीं थी। 1919 में रौलेट एक्ट तथा जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के विरुद्ध जनता विरोध कर चुकी थी। कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन की घोषणा करते ही 1919 के सुधार कानून के अनुसार होने वाले चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवार अलग-हो गये। 1921 के प्रारम्भ से ही आन्दोलन के कार्यक्रम पर अमल होने लगा। मतदाताओं तक ने बहुत बड़ी संख्या में मतदान का बहिष्कार किया। गांधी जी तथा अन्य नेताओं ने अपनी कैमरे-हिन्द की पदवियाँ वापिस कर दी थीं। बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना बन्द कर दिया। अनेक महान् नेताओं, यथा सी० आर० दास, मोतीलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल, वल्लभभाई पटेल आदि ने बकालत करना छोड़ दिया। विदेशी माल का बहिष्कार बड़ी द्रुत गति से होने लगा। न्यायालयों का भी बहिष्कार किया जाने लगा। यह सब शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक ढंग से हुआ। दूसरी ओर देश के अनेक

धनी व्यक्तियां न (सठ जमनाल वजाज प्रभृति) बहिष्कार के फलस्वरूप हानि भोगने वाला को सहायता दी। दश म केरवा उद्योग द्रतगति स फता अतक राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाआ (कान्वा विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ तिनक महाराष्ट्र विद्यापीठ राष्ट्रीय कानज नाहौर जामिया मिनिआ दिल्ली असोसिड राष्ट्रीय मुस्लिम वि विविद्यालय जादि) की स्थापना की गयी। सिटि मुस्लिम एकता जिम रूप म एस बाच विकसित हुई बसी कभा नहा हो पायी। छुआछत की बुराई का नान भी जनता को होने लगा।

इस आन्दोलन की एक सबसे महत्वपूर्ण विषयना यह थी कि यह आन्दोलन प्रारम्भ क राष्ट्रीय आन्दोलन की भांति था—से शिक्षित वग तक सीमित नहा रहा अपितु यह आम जनता का आन्दोलन बन गया सिद्ध मुस्लिम एकता न एस जोर अविन प्रभावगानी बना दिया। थाप्ते स ब्रिटिश राजभक्त उदारवादी तथा निहित स्वाय वान वग इसके विरुद्ध रन। परंतु जहा तक इसके असह्यागत्यक भाग का सम्बन्ध था उसके प्रचार तथा संचालन म पूर्ण शांति तथा अहिंसा सम्भव नहीं थी। सरकार इस दंगल पर चुन्ती थी। अतः छुट्ट पट्ट हिंसात्मक घटनाआ का हा जाना भी अस्वाभाविक नहीं था। दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा असह्याग का परिणाम यह हुआ कि उदार वां या की चन पनी। विधानमभाजा म उह पर्याप्त स्थान प्राप्त हा गये। सरकारी-यन क विपन्न या डावाडोन होन की स्थिति नहीं आ पाई। परंतु सरकार की ययता बहुत बढ गयी।

सरकार द्वारा दमन—यद्यपि आन्दोलन शांतिपूर्ण ढंग स विशाल पमान म चल रहा था तथापि सरकार का इसकी नाकप्रियता तथा सफलता चिंतित बाने लगी। निम्नदह आन्दोलन का प्रचार कर्न से नताजा को सरकार विरोधी धारणाए व्यक्त करनी पडा। अतः सरकार न यह तय किया कि आन्दोलन को कुचना जाय। क्रांतिकारी सभाजा क ऊपर कानून द्वारा रोक लगा दी गयी। सरकार ने वन प्रयाग द्वारा आन्दोलन को दवाना प्रारम्भ किया। इस निण उमका प्रथम चरण अनी उधुआ को बंदी करने स आरम्भ हुआ। उनके ऊपर यह आरोप था कि उहान सरकार विरोधी प्रचार कर्के जनता को हिंसात्मक कायवाहा करन के निए प्रोत्साहित किया है।

नवम्बर 1921 म प्रिंस आफ वेल्स की भारत यात्रा हान वाली थी। सरकार चाहती थी कि राजकुमार के प्रति भारतवासी पूर्ण राजभक्ति व्यक्त करें। परंतु कांग्रेस न राजकुमार के स्वागत का भी बहिष्कार किया क्योंकि सरकार की दमन नीति तथा अनी उधुआ का मुक्त न करने की हठधर्मिता कांग्रेस का माय नहीं थी। इससे सरकार का रोप और अधिक बढा। इस बाच मनवावर म मापाया विद्रोह ने सरकार को खिनाफत आन्दोलन क प्रति भी स्पष्ट कर दिया था। मापाया विद्रोह म अनेक यूरोपीय तथा हिंदू भी मार गये थ। सरकार न इसका आरोप अनी-य धुआ पर लगाया और उह बंदी बनाय रही। सरकार के दमनचक्र के कारण कांग्रेस काय समिति न यह तय किया कि जिस दिन राजकुमार बम्बई पहुच उस दिन नगर म पूर्ण हड़ताल रखी जाय। सरकार न बहिष्कार करन वाला तथा हड़तालिया का दंगल की काशिग की। परंतु स्वयंसबक सभा के विकास को बह नहीं रोक सकी। कई स्थान पर हिंसात्मक दमन भी किया। जनता की ओर से हिंसात्मक कार्यों के करने की गांधी जी न निंदा की। सरकार न कांग्रेस तथा खिनाफत समिति सहित अनेक स्वयंसेवी सगठना को जबघ घोषित कर दिया। पुलिस न भी आन्दोलनकारिया को दवाने म हिंसा का प्रयाग किया। आन्दोलन तीव्र हाता गया और 1 सितम्बर 1921 तक सरकार न सी आर दास मोतीलाल नेहरू राजपतराय मौनाना जाजाद आदि प्रमुख नेताआ को बंदी कर लिया। हजारों की सख्या म अय सत्याग्रही भी बन्दी कर निय गये।

दिसम्बर 1921 म प्रिंस आफ वेल्स का कक्षा पधारन वान थ। सरकार न पुन कांग्रेस म सह्याग चाहा। परन्तु कांग्रेस राजी नहा हुई उसन अना बधुआ को मुक्त करन की गत रखी जो सरकार का अमाय थी। अधिकांश उच्च नता जनता म थ। गांधी जी का ही सरकार न समिने सुना रखा कि उह बंदी करन पर आन्दोलन और अधिक तीव्र हो जायगा। कांग्रेस न भी उहा क ऊपर आन्दोलन क संचालन का पूरा भार हाट दिया था।

आन्दोलन का स्थगित किया जाना—असहयोग आन्दोलन अपने कार्यक्रम के अनुसार अधिकांशतः सफलतापूर्वक तथा पर्याप्त प्रभावशाली ढंग से चल रहा था। इससे ब्रिटिश शासकों की चिन्ता बढ़ती गयी। अतः उन्होंने इसे अधिक लोकप्रिय बनने से रोकने में कोई कमी नहीं रखी। आन्दोलन का एक भाग क्रान्तिकारी अवश्य था, परन्तु कार्यक्रम का उद्देश्य अहिंसात्मक था। परन्तु ऐसी सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था कि एक जन-आन्दोलन जिसे सरकार बल-प्रयोग द्वारा दबाने पर तुली हुई थी, पूर्णतः अहिंसात्मक ही चल पायेगा। सरकार ने इसे दबाने में जिस उग्र दमन की नीति को अपनाया था, उससे आन्दोलनकारियों के उग्र वर्ग में थोड़ी-बहुत हिंसा की प्रवृत्ति उत्पन्न होना स्वाभाविक था। गांधी जी को छोड़कर गेप सभी बड़े-बड़े नेता जेलों में थे। अतः दिसम्बर 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में आन्दोलन को और अधिक तीव्र करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके साथ सविनय अवज्ञा को भी जोड़ा गया। गांधी जी ने फरवरी 1922 में गवर्नर-जनरल को एक पत्र लिखकर उसमें सरकार को 7 दिन का समय यह विचार करने के लिए दिया कि वह दमन की नीति को छोड़े, अन्यथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। परन्तु इसी बीच गोरखपुर जिले के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक काण्ड हो गया। एक क्रुद्ध आन्दोलनकारी भीड़ ने एक थानेदार तथा 21 पुलिस के सिपाहियों को बलात् थाने में बन्द करके उन्हें जीवित जला दिया। इस घटना में महात्मा गांधी को बड़ा दुःख हुआ। उनके अहिंसा के सिद्धान्त से आन्दोलन सर्वथा प्रतिकूल था। अतः तुरन्त उन्होंने असहयोग आन्दोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी।

स्थगन की प्रक्रिया—असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने के गांधी जी के आदेश का कांग्रेस तथा मुसलमानों दोनों ने विरोध किया। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं के मत से जब आन्दोलन अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका था, तो उस समय एकाएक उसे वापिस ले लेना बुद्धिमानी नहीं थी। यद्यपि आन्दोलन की अवधि में खिलाफत प्रश्न को लेकर हिन्दू-मुस्लिम एकता सुहृद हो चुकी थी और मुसलमान भी आन्दोलन में शामिल थे, तथापि वे राजनीति में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त से सहमत नहीं थे। अतः आन्दोलन के स्थगन से वे रुष्ट हो गये। यद्यपि उस समय आन्दोलन के स्थगन का विरोध किया गया था तथापि गांधी जी का निर्णय सर्वथा अयुक्तिपूर्ण नहीं माना जा सकता। ज़ौरीचौरा काण्ड की सी घटनाएँ अन्यत्र भी घट सकती थीं। जो सरकार अहिंसात्मक आन्दोलन को बल-प्रयोग से दबाने पर तुली थी, वह हिंसात्मक घटनाओं को और अधिक रफ्तार से कुचलती। इसका परिणाम यह होता कि क्रान्ति भी हिंसात्मक होती जाती। उच्च नेताओं के कारावास में होने के कारण आन्दोलन का सही नेतृत्व नहीं हो पाता। अतः इस सबका परिणाम भयावह होता। परन्तु तत्काल गांधी जी के ऐसे निर्णय का बहुत विरोध हुआ। जेलों में बन्दी नेताओं ने भी इसे अनुचित माना। साथ ही कांग्रेस के उग्र तथा प्रगतिशील तत्त्व तो स्थगन से बहुत रुष्ट हुए।

दूसरी ओर सरकार इससे बहुत लाभान्वित हुई। सरकार का प्रथम कदम यह रहा कि उसने गांधी जी के विरुद्ध उत्पन्न राष्ट्रवादी रोष का लाभ उठाकर मार्च 1922 में उन्हें बन्दी करके उनके ऊपर अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी। अभी तक सरकार ऐसा साहस नहीं कर सकती थी। अभियोग में गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने शासन विरोधी अभियान शुरु किया था। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक स्वतन्त्र नागरिक के रूप में जेल से छूटने पर वह अपने तथा भारत की जनता के न्यायोचित अधिकारों की माँग के समर्थन में पुनः यही कार्य करेंगे। उनकी यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक थी। गांधी जी को न्यायालय ने छ वर्ष के कारावास का दण्ड दिया। परन्तु दो वर्ष पश्चात् 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया। सम्भवतः अब सरकार के समक्ष बहुत गम्भीर समस्या नहीं थी। आन्दोलन शान्त हो चुका था गांधी जी का विरोध भी बहुत हो रहा था। उनके कारावास

कास की अवधि में परिस्थितियाँ भी बर्तन चुकी थी। खिलाफ आन्दोलन समाप्ति पर था काग्रस ने कौमिन प्रवेश की नीति अपनायी थी। इसलिए भी सरकार को उह जेन से मुक्त कर देने में कोई हानि प्रतीत नहीं हुई।

असहयोग आन्दोलन का प्रभाव

कई परिस्थितियाँ के कारण असहयोग आन्दोलन वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। गांधी जी का आशावाद समयाचित नहीं था। जसा नेताजी मुभापचन का मत है गांधी जी नारा एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने की घोषणा करना न केवल अविवक्षणीय था अपितु उल्हा का मा आशावाद था।¹ आन्दोलन का सघर्षात्मक पक्ष अहिंसापूर्ण ढंग में संचालित हो सकना सम्भव नहीं था। जो सरकार जदियावाता वाग जमी अमानवाय घटनाओं के लिए उत्तरदायी अधिकारी जनरल गायर के हृदय को एक मामूली भूत बनाकर उस सम्मान प्रदान कर सकती थी उससे यह आशा करना कि वह अहिंसात्मक आन्दोलन के समक्ष मुक्त जायगी या सामाज्य रूप के विरोध तक का कुचनन में हिंसा का अवलम्बन नहीं करेगी एक भूत थी। हिंसा प्रतिहिंसा को उत्पन्न करती है। जग सरकार ने आन्दोलनकारियों के विरुद्ध दमन की नीति अपनायी, बहा आन्दोलन कारियों का हिंसा की ओर भुनाव हो जाना अवाभाविक नहीं हो सकता था। ऐसा स्थिति में आन्दोलन का स्वरूप ही बर्तन जाता और वह अहिंसात्मक नहीं रह जाता। इस आन्दोलन की एक बहुत बड़ी श्रुतता यह थी कि इसके साथ खिलाफ आन्दोलन का संयुक्त किया गया था। असहयोग आन्दोलन पूणतया राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन था जबकि खिलाफ आन्दोलन भारतीय मुसलमानों का टर्की के सुतान के समर्थन में एक विरुद्ध रूप में धार्मिक आन्दोलन था जिसका भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता से कोई सम्बन्ध नहीं था। टर्की की खत्रीफा सम्बन्धी समस्या दूसरे ढंग से हल हुई। बहा कमान पाशा के नतृत्व में घमनिरपक्ष गणतन्त्र राज्य कायम हुआ। परिणामस्वरूप भारतीय धर्म प्रेरित मुसलमानों का खिलाफ आन्दोलन स्वयं ठण्डा पड़ गया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि स्वयं टर्की की जनता भारतीय मुसलमानों के खिलाफ आन्दोलन को एक मजान समझती रही थी। अतः याही खिलाफ आन्दोलन समाप्ति की ओर आया क्योंकि मुसलमान असहयोग आन्दोलन अथवा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से ही असहयोग करने लग गये। उनकी साम्प्रदायिकता की भावना पुन बर्त गयी। स्वयं अनेक मुसलमान भी राजनीति तथा अहिंसा के मन्त्र को साम्य नहीं देखते थे। परिणाम यह हुआ कि गन पाँच या छ वर्षों की अवधि में काग्रस तथा नीग में जो ऐक्य का वातावरण बनने लगा था वह पुन सन् के लिए समाप्त हो गया। 1921 में मनावार के मोपना विरोध न हिन्दू मुस्लिम में भाव का और अधिक बढ़ा दिया और असहयोग आन्दोलन की समाप्ति पर पुन कई स्थानों में हिन्दू मुस्लिम दंगे प्रारम्भ होने लगे। इस दृष्टि में भी असहयोग आन्दोलन की सफलता मिट्ट नहीं हो पायी।

परन्तु इन कमियाँ के हान हुए भी इस आन्दोलन का पूणतया असफल नहीं बल जा सकता। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में इस आन्दोलन के प्रभाव का अमाय नहीं कहा जा सकता। यद्यपि गांधी जी से पूर्व निम्न में राष्ट्रीय आन्दोलन को जनता ने आन्दोलन बनाने का प्रयास किया था तथापि गांधी जी के इस आन्दोलन ने जिस विद्यत् प्रवाह से हम तुरन्त दंग की आम जनता का आन्दोलन बनाने में सफलता प्राप्त की वह श्रय तो निम्न तक की कभी गलत नहीं हो सकता था। निम्न की स्वराज्य की धारणा को दंग के कोन कान में फेरान का काय हम आन्दोलन में किया। बहिष्कार तथा स्वतन्त्र आन्दोलन को हमने व्यापक रूप में रचनात्मक बनाया। विशाल सत्याग्रह चरखा तथा हथकरघा का निमाण हुआ। दंग भक्त बनाया तथा जनता ने गान्धी का उपयोग करने का सक्ल न किया। इस प्रकार इस आन्दोलन ने जनता

को आत्मनिर्भर तथा स्वदेशी का पाठ पढ़ाया। इसने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नयी दिशा प्रदान की। अब मे राष्ट्रीय नेताओं को यह विश्वास हो गया कि केवल वैधानिकतावाद का अवलम्बन करके स्वतन्त्रता तथा शासन सुधारों की माँग पूर्ण नहीं हो सकती। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब जनता में यह विश्वास बढ़ने लगा कि शासन की बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाना तथा अन्यायपूर्ण शासकीय कानूनों एवं आदेशों का विरोध करना अनुचित नहीं है।

असहयोग आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को इतना जनप्रिय बना दिया कि अब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा शासन सुधारों की माँग करना केवल थोड़े से शिक्षित वर्गों का विशेष हित नहीं रह गया। अर्थात् अब जनसाधारण भी निर्भयता के साथ सरकार के दमनकारी कार्य-कलापों का सामना करने के लिए तत्पर हो गये। सरकार की बुराइयों को खुले रूप से व्यक्त करने का साहस जनता में बढ़ने लगा। राजनीतिक कारणों पर जेल जाना जनता के लिए एक प्रकार की तीर्थ यात्रा सी हो गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय नेताओं का उत्साह भी बढ़ने लगा। अब उन्हें आन्दोलन के लिए जन-सहयोग प्राप्त होने का पूरा आश्वासन मिलने लगा। देश के स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता के लिए यह चीज सबसे अधिक वाछनीय थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में यह सबसे पहला अवसर था जबकि आन्दोलन राजनीतिक भिक्षावृत्ति तथा वैधानिकतावादी तरीकों को छोड़कर एक क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा अनुभव कांग्रेस के नेता तभी करने लग गये थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी के आन्दोलन को स्थगित करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण माना था। परन्तु सम्भवतः गांधी जी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। भले ही आन्दोलन छोड़ने के सम्बन्ध में उनके कुछ साधन समयोचित अथवा पूर्णतया सही न रहे हों, तथापि आन्दोलन में हिंसा का तत्त्व आ जाने पर उसे स्थगित करना उनका युक्तिपूर्ण निर्णय ही कहा जा सकता है। यदि सरकार भी हिंसापूर्ण दमन की नीति अपनाती और हिंसा-प्रतिहिंसा का वातावरण फैल जाता, तो भारत की जनता उस समय उन समस्त साधनों तथा क्षमताओं से युक्त नहीं थी कि वह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो जाती। 1942 के पश्चात् की घटनाएँ तक इस तथ्य की साक्षी हैं कि उस समय जब ब्रिटेन बहुत अधिक निर्बल हो चुका था, तब उसने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को दबा लेने में पूरी सफलता प्राप्त कर ली थी, 1921-22 में तो वह और अधिक सुदृढ़ थी, इसलिए इस आन्दोलन को दबाना उसके लिए बहुत कठिन बात नहीं होती।

आन्दोलन स्थगन के उपरान्त गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य रखा। वह सफल होता या न होता, परन्तु इसी बीच उन्हें बन्दी कर लिया गया। उधर उदारवादियों ने पुनः कौन्सिल प्रवेश की नीति अपनाकर असहयोग आन्दोलन को दुर्बल बना दिया। 1921-24 की अवधि में उनके सहयोग से 1919 के अधिनियम को कार्यान्वित करने में सरकार सफल हो गयी। इस अवधि में उदारवादियों ने कई नये कानूनों को पारित कराने में सफलता प्राप्त कर ली। साथ ही सरकार भी उनकी माँगों के फलस्वरूप 1919 के शासन-सुधार कानून की कमियों को दूर करने की दिशा में प्रवृत्त हो चुकी थी। अतः इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में अब कांग्रेस को राष्ट्रीय आन्दोलन के भावी कार्यक्रम को नये ढंग से निर्मित करने की आवश्यकता थी।

प्रश्न

1. उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए जिन्होंने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन को जन्म दिया।
2. खिलाफत आन्दोलन से आप क्या समझते हैं? क्या आपकी राय में खिलाफत के साम्प्रदायिक प्रश्न को राष्ट्रीय आन्दोलन की माँगों में स्थान देना उचित था?
3. असहयोग आन्दोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा?

स्वराज्य दल का स्थापना

हिन्दी भी जन-संगठन का उद्देश्य एक हाते हुए भी उसके सदस्यों के मध्य साधना तथा कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में मतभेद होता ही है। एक निम्न देश-यापी राजनीतिक दल के सम्बन्ध में यह बात और अधिक तथ्यपूर्ण है। प्रारम्भ से ही कांग्रेस के अन्तर्गत नेताओं के मध्य ऐसे मतभेद चल रहे थे। 1905 में इन मतभेदों के कारण कांग्रेस के दो दल बन गये थे। दोनों में 1916 में सम्मेलन हुआ जाने पर भी 1919 में पुनः कई नए कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने उदारवादी संगठन का निर्माण करके 1919 के सुधार कानून के अन्तर्गत कौन्सिल प्रवेश का कार्यक्रम अपनाया था। जो नेता कांग्रेस में बने रहें उनके मध्य भी मतभेदों की प्रक्रिया एक अनोखे ढंग की सिद्ध हुई। प्रारम्भ में गांधी जी सरकार के साथ सहयोग की नीति चाहते थे और चित्तरंजन दास इसके विरोधी थे। शीघ्र ही धारणा विकृत होती ही गयी। गांधी जी के असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव सितम्बर 1920 के विधि अधिवेशन में यों से बहुमत से ही प्राप्त हो सका था। 1922 में असहयोग आन्दोलन के स्थगन के परिणामस्वरूप कांग्रेस कार्यक्रम में पुनः रूढ़िवादी आ गयी। गांधी जी के कारावास के कारण वह रूढ़िवादी और अधिक दृढ़ गया। अब जो नेता दूर गये थे उन्हें गांधी कार्यक्रम तैयार करना था। इनके अन्तर्गत प्रमुख चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू राजगोपालाचारी अबुलकलाम आजाद जवाहरलाल नेहरू आदि थे। निराशा आन्दोलन की समाप्ति हो जाने पर अनेक मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस कार्यक्रम से हाथ खींच दिया और वे पुनः साम्प्रदायिकता की नीति का अनुसरण करने लगे थे।

1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन में सी. आर. दास मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस कार्यक्रम का विरोध किया। परन्तु राजगोपालाचारी सहित नए गांधीवादी कार्यक्रम में परिवर्तन के विरोधी बन रहे। अतः चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर एक नये स्वराज्य-दल का निर्माण किया। 1923 के जन में 1919 के शासन सुधार अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीय आम चुनाव होने वाले थे। अतः स्वराज्य दल के नेताओं ने इन निर्वाचनों में भाग लेकर कौन्सिल प्रवेश द्वारा अन्तर्गत 1919 के शासन सुधार कानून के कार्यान्वयन को अवरोध करना अपना उद्देश्य बनाया। 1923 के नवम्बर मास में मोतीलाल अबुलकलाम आजाद को अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विधि अधिवेशन हिन्दी में हुआ जिसमें कौन्सिल प्रवेश के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अधिभूत रूप से स्वीकार कर लिया। फरवरी 1924 में जब महात्मा गांधी जन से दूर ना रहे स्वराज्य दल की कौन्सिल प्रवेश की नीति संशयान्वित हुई। साथ ही उन्हें यह भी समझाना हुआ था कि पुनः असहयोग आन्दोलन की नीति में प्रत्यावर्तन भा सफल कार्यक्रम सिद्ध नहीं हो सकेगा।

इस स्थिति में एक नया स्पष्टतया दृष्टिकोण बन गया था कि एक बार पुनः कांग्रेस में विभाजन हो जाने वाला है। परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार सम्मेलन करें अथवा कांग्रेस विभाजित जायगी यह समस्या गांधी जी के सामने थी। स्वराज्य दल ने कौन्सिल प्रवेश में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली थी। अतः 1925 में गांधी जी

ने कांग्रेस के सदस्यों को यह छूट दे दी कि वे 'कौन्सिल-प्रवेश' अथवा 'रचनात्मक कार्यक्रम' में से जिसे ठीक समझे उसे अपनाये। इस प्रकार कांग्रेस विभाजित होने से बच गयी। कौन्सिल प्रवेश के कार्यक्रम के समर्थक 'स्वराज्यवादी' कहलाये।

स्वराज्यवादियों के उद्देश्य तथा साधन

स्वराज्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य गांधीवादियों की भाँति ही देश के लिए स्वराज्य (स्वशासन) की प्राप्ति करना था। चूँकि 1919 के सुधार कानून में स्वराज्य की उपेक्षा की गयी थी, अतः यह दल कम से कम ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता था। परन्तु इनमें तथा गांधीवादियों में साधनों की भिन्नता थी। स्वराज्य दल सविनय अवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलन की नीति न अपनाकर कौन्सिल प्रवेश द्वारा वहाँ से साविधानिक सुधारों की उपलब्धि करना चाहता था। कौन्सिल प्रवेश के कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि निर्वाचनों में भाग लेकर आम जनता में राष्ट्रीयता के विचार भरे जायें।

स्वराज्यवादियों की कौन्सिल प्रवेश की नीति का दूसरा लक्ष्य यह था कि कौन्सिलों में जाकर वे अपनी राष्ट्रीय स्वायत्तता की माँगों के प्रति जनमत का निर्माण करें। साथ ही कौन्सिलों में वे ऐसे प्रतिनिधियों के बहुमत का निर्माण करें जो वास्तव में जनता के प्रतिनिधि अथवा जनमत की अभिव्यक्ति करने वाले सिद्ध हों।

कौन्सिल प्रवेश का एक लक्ष्य यह भी था कि उनमें जाकर वे सरकार की हों में हों मिलाने की नीति न अपनाकर सरकार तथा नौकरशाही के अवाछनीय कार्यक्रमों का विरोध करें। इस प्रकार वे शासन के अन्तर्गत रहकर प्रतिरोध की नीति द्वारा 1919 के शासन सुधार कानून की कार्यान्विति के मार्ग में बाधा डालें, जिससे कि सरकार को इस सुधार कानून को सशोधित करने के लिए विवश होना पड़े।

सरकार के कार्यों में रोड़ा अटकाना, बजट का विरोध, सरकार द्वारा प्रस्तावित अवाछनीय विधेयकों का विरोध, प्रशासन की बुराइयों की निन्दा आदि स्वराज्य दल के विध्वसात्मक कार्यक्रम के अंग थे। यह एक प्रकार से असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के ही रूप थे। अन्तर यही था कि इनकी कार्यान्विति सरकार के अन्तर्गत रहकर 'अन्दर से' होती थी। दूसरी ओर स्वराज्य-वादियों के कार्यक्रम का रचनात्मक उद्देश्य भी था। वे कौन्सिलों में रहकर ऐसे प्रस्ताव पास कराना चाहते थे, या ऐसे कानूनों का निर्माण कराना चाहते थे जिनके द्वारा सरकार को वैधानिक सुधार लाने तथा लोक-कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए बाध्य किया जा सके।

अन्ततः, स्वराज्यवादी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम तथा सत्याग्रह कार्यक्रम के विरुद्ध भी नहीं थे। 1923 के चुनाव घोषणा-पत्र में उन्होंने स्पष्टतया इस नीति की घोषणा कर दी थी कि दल का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों को अपनी सरकार स्वयं चलाने तथा नियन्त्रित करने के अधिकार को उपलब्ध कराना होगा। यदि सरकार जनता की इस माँग को ठुकराने पर तुलेगी, तो दल भी यथाशक्ति सरकार के संचालन को असम्भव बनाने की कोशिश करेगा। यह कार्य प्रथमतः व्यवस्थापिकाओं के भीतर रहकर किया जायेगा, परन्तु यदि आवश्यकता पड़ी तो दल गांधी जी के सत्याग्रह कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग देकर कार्यान्वित करने में भी सकोच नहीं करेगा।

इस दृष्टि से स्वराज्य दल का उद्देश्य वही था, जो समूचे रूप में कांग्रेस का था। अन्तर केवल कार्यविधि तथा साधनों का था।

स्वराज्य दल की उपलब्धियाँ

स्वराज्य दल की कौन्सिल-प्रवेश नीति को पर्याप्त लोक-समर्थन प्राप्त हुआ। असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् भारत के मतदाताओं के समक्ष स्वराज्य दल के कार्यक्रम को

स्वीकृति दन के सिवाय और कोई प्रस्ताव भी नहीं रह गया था। 1923 के निर्वाचनों में उदारवादियों का कौंसिल से जगमग सफाया हो गया। स्पष्ट था कि अब दश प्रमी जनता उदारवादियों की ब्रिटिश राज परस्ति नाति से उठ गयी थी। इस निर्वाचन में स्वराजवादियों का केन्द्रीय व्यवस्थापिका में 145 में से 47 स्थान प्राप्त हुए और यही तब तक सबसे बड़ा दल बना। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन में 145 कुल स्थान थे जिनमें से 105 निर्वाचित सदस्यों के लिए थे। इनमें से 47 स्थान स्वराज्य दल को प्राप्त हो जाना दल का एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मध्य प्रदेश की विधान परिषद् में इस दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। बंगाल में भी इस पर्याप्त अधिक बहुमत प्राप्त रहा। अजयप्रान्त का विधानपरिषद् में भी उनकी संख्या पर्याप्त अधिक थी।

केन्द्रीय विधानसभा में भी मोतीलाल नेहरू स्वराज्य दल के नेता थे। उह विधानसभा के अजय राष्ट्रवादी तथा स्वतन्त्र सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने में सफलता मिल गयी। मोतीलाल जी के अजय कमठ साधियों में बिटठनभाषण पटन रामास्वामी आयगर मदनमोहन मानवीय विपिन चण पात्र आदि थे। परिणामस्वरूप उनके प्रयासों में फरवरी 1924 में विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास कर लिया कि शासन सुधार कानून 1919 में ऐसा संशोधन किया जाए कि जिससे भारत में पूर्ण स्वायत्त शासन से युक्त उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके और अपसत्त्वता के संरक्षण हेतु एक गान मज सम्मेलन बुलाया जाए जिसकी सन्तुति का आधार पर भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। केन्द्रीय विधानसभा को भगकरके नव निर्वाचित विधानसभा के समक्ष उस संविधान को पारित करने तथा ब्रिटिश संसद द्वारा उस कानूनी रूप प्रदान करने के हेतु भेजने की व्यवस्था की जाए। यह प्रस्ताव सांविधानिक विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही स्वराज्य दल के कौंसिल प्रवेश के उपायों में उसका पारित होना तब की एक महान् उपलब्धि थी।

1924 में अजय भारतीय सिविल सेवा के सम्बन्ध में जब तीव्र कमीशन की रिपोर्ट व्यवस्थापिका के सामने रखी गयी तो मोतीलाल जी के नेतृत्व में सभा ने उस अस्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट में यद्यपि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश का अनुपात 50/ सन्तुन किया गया था तथापि सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए इतने अधिक संरक्षणों यूरोपीय अधिकारियों के लिए इतने भत्ता तथा सुविधाओं की तथा सिविल सेवा को लोकप्रिय सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने की सन्तुनिया थी कि उनका पूरा नाम यूरोपीय सिविल सेवा के अधिकारियों को प्राप्त होता।¹ बाद में उच्च सदन (कौंसिल आफ स्टेट) ने इस विना संशोधन के पास कर लिया। वित्त विभागों तथा वित्तीय माँगों सम्बन्धी प्रस्तावों को अस्वीकार करने में सभा ने यह मिहान्न अपनाया कि *No supplies till the grievances are removed* अर्थात् जब तक कमियाँ का दूर नहीं किया जाता तब तक कोई वित्तीय माँग स्वीकार नहीं की जायेगी।

यद्यपि इस बीच लण्डन में मजदूर दल की सरकार बन गयी थी जिसने भारतवासियों का अंतर आगाएँ थी तथापि ब्रिटिश सरकार ने उक्त प्रस्ताव का ठुकरा दिया परिणामस्वरूप स्वराज्य दल ने अजय राष्ट्रवादी संस्था के सहयोग में विधानसभा में अपनी प्रतिराय की वापवाहियों तीव्र कर दी। आगामी तीन वर्षों तक वे जगनार बजट का अस्वीकार करते रहे और जनर जनरल को अपन प्रमाणिवरण के अधिकारों का महारा नसर विभिन्न बजट प्रस्तावों तथा अनुदानों को स्वीकृति नहीं पड़ी। समय-समय पर विधानसभा सरकार की वापवाहियाँ के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने लगा। कई अवसरों पर स्वराज्य दल ने सरकार के हठीन व्यवहार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए सदन में बहिष्करण भी किया। सरकार द्वारा आयाजित उत्सवों में निमंत्रणों को उपेक्षा की गयी। प्रस्तावों द्वारा राजनीतिक बर्तियों की रिहाई की माँग की गयी। सतत में स्वराज्य दल ने

अपने प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से अपनाया ।

प्रान्तीय विधान परिषदों में भी उनका कार्य भाग पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ । मध्य प्रदेश, में जहाँ वे पूर्ण बहुमत में थे, उन्होंने मन्त्रिपद ग्रहण न करके द्वैध-शासन का संचालन अवरुद्ध कर दिया और गवर्नर को स्वयं हस्तान्तरित विभागों के शासन का कार्य संचालित करना पड़ा । बंगाल में सी० आर० दास के नेतृत्व में भी स्वराज्य दल ने यही कार्य भाग सम्पन्न किया । अन्य प्रान्तों में स्वराज्य दल की ओर से साविधानिक सुधारों की निरन्तर माँग रखी गयी और शासन-नीतियों की घोर आलोचनाएँ की जाती रही ।

स्वराज्य दल के फरवरी 1924 के प्रस्ताव का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने सर एलेक्जेंडर मूडीमैन की अध्यक्षता में द्वैध-शासन की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक समिति नियुक्त की । मोतीलाल नेहरू ने तो उसकी सदस्यता तक स्वीकार नहीं की । समिति के बहुसंख्यक सदस्य सरकार समर्थक थे । अतः बहुसंख्यक सदस्यों की राय थी कि द्वैध-शासन प्रणाली सिद्धान्ततः उचित सिद्ध हुई है । इसमें कुछ थोड़े से सामान्य परिवर्तनों का ही उन्होंने सुझाव दिया । परन्तु अल्पसंख्यक सदस्यों ने, जिनमें सर तेजबहादुर सप्रू भी शामिल थे, इसके मूलभूत सिद्धान्त को ही गन्त बनाकर उसमें विशाल परिवर्तन करने का सुझाव दिया । सितम्बर 1925 में जब यह रिपोर्ट केन्द्रीय विधानसभा के समक्ष रखी गयी तो प० मोतीलाल नेहरू ने द्वैध-शासन-प्रणाली की कठोरतम आलोचना की, और फरवरी 1924 के प्रस्ताव की भाँति ही मूडीमैन समिति की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विशाल बहुमत से विरोध किया गया और सरकारी प्रस्ताव पर 14 के विरुद्ध 45 मतों से सशोधन पारित किया गया । सशोधन जो मोतीलाल जी के द्वारा रखा था, उसमें यह माँग की गयी थी कि ब्रिटिश संसद भारत की उत्तरदायी शासन की माँग को मान्य करे और तुरन्त भारत के विभिन्न दलों का गोल मेज सम्मेलन आहूत करे जो संविधान को तैयार करेगा और उसे संसद अधिनियमित करे ।

नीति परिवर्तन

स्वराज्य दल के कार्य-कलापो तथा उद्देश्यों में कालान्तर की परिस्थितियों ने परिवर्तन कर दिया । दल का व्यवस्थापिकाओं में जाकर सरकार की गलत नीति का विरोध करने का कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाया । बंगाल तथा मध्य प्रदेश में द्वैध-शासन की स्थापना के अभाव में गवर्नर हस्तान्तरित विषयों का शासन स्वयं चलाने लगे थे । अन्य प्रान्तों में स्वराज्य दल के अल्पसंख्यक होने के कारण उनके विरोध निष्प्रभावी सिद्ध हुए । स्वयं केन्द्र तक में प० मदनमोहन मालवीय तथा लाला लाजपत राय यह अनुभव करने लगे कि सरकार-विरोधी नीति हिन्दू जनता के हित में वाछनीय नहीं है । स्वराज्य दल की अडगा लगाने की नीति इस अर्थ में सफल नहीं हो पायी उनके कार्य-कलापो से शासन को कोई क्षति नहीं हो सकती थी । गवर्नर जनरल के पास इतनी अधिक शक्तियाँ थी और उच्च सदन में सरकार का इतना अधिक समर्थन था कि सरकार मनचाहे कानून बना लेती थी । 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के कारण स्वराज्य दल में भारी रिक्तता आ गयी । अब शासन में रहकर निरन्तर विरोध तथा असहयोग सम्भव नहीं था । अतः दल के अनेक प्रमुख नेताओं ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया । राष्ट्रवादियों तथा उदारवादियों ने स्वराज्यवादियों की बजट सम्बन्धी माँगों को अस्वीकार कर देने की नीति से सहमति व्यक्त करना उचित नहीं समझा । इस प्रकार सरकार का विरोधी पक्ष समान नीतियों तथा विचारधाराओं से आवद्ध नहीं रह पाया । स्वयं स्वराज्य दल के अन्तर्गत भी एकता नहीं रह सकी । केन्द्र में 1925 में प्रमुख नेता वी० जे० पटेल को केन्द्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया । मध्य प्रदेश में एम० वी० टैम्बुन गवर्नर के कार्यकारी पार्षद बन गये । मोतीलाल नेहरू ने उन सदस्यों पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगाया जो दल की घोषित नीतियों के विरुद्ध आचरण कर रहे थे । परन्तु इसका परिणाम यही हुआ कि दल में और

अधिक विघटन हानि लगा। अतः स्वराज्य दल के कुछ सदस्यों जयकर बलकर आदि ने अपनी गतिन विरागी नीतियाँ का निश्चित कर लिया। जब इनका मित्रात उत्तराधारी सहयोग का हो गया। अनेक मदस्यों ने कई शासकीय समितियाँ की सदस्यता ग्रहण कर ली। स्वयं पन्ति नहरे भी स्क्रीन समिति के सदस्य बन गये थे। दल का जनता के मध्य संगठनात्मक कार्यक्रम भी सत्तापजनक नहीं था। कौंसिल के कार्य-कलाप मात्र से दल जनता को प्रभावित नहीं कर सकता था। उत्तराधरिया (responsivists) तथा कट्टर स्वराज्यवादियों के मध्य एकता जाने के प्रयास भी निष्फल सिद्ध हो गये।

स्वराज्य दल का मूल्यांकन

जिस प्रकार असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में अनेक आतिशूण धारणाओं ने आन्दोलन को सफलता की सहायता बना दिया था और यतत उसे स्थगित करना पड़ा था। उसी प्रकार स्वराज्य दल का प्रतिरोध का कार्यक्रम भी युक्तिपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ। यह धारणा कि कौंसिल में जाकर विरोध के द्वारा गामन सुधार अधिनियम की याजना के संचालन को जबरदस्त कर दिया जायगा एक मिथ्या धारणा थी क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को जिन शक्तियों से विभूषित किया गया था उनके अन्तर्गत विधानसभाओं की निरन्तर उपेक्षा करके गामन को संचालित कर सकते थे। केवल विरोध के लिए विरोध कोई वास्तविक नीति नहीं है। इसमें विरागी पक्ष की प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। स्वराज्य दल का संगठन पक्ष निरक्षर था। उसके सदस्य जनता में अपनी योग्यता बनाने में सफल नहीं हो पाये। दूसरी ओर कार्यक्रम के माधोवादी नेता जायनात्मक कार्यक्रम में नये स्वराज्य दल की नीति से विनय सहानुभूति नहीं रखते। जब अपने तीन चार साल के कार्यक्रम में इस दल की वाछिन सफलता के आसार निरक्षर हो गये।

परन्तु इन असफलताओं के बावजूद स्वराज्य दल के कार्यक्रमों तथा उपनिधियों ने उनके उद्देश्य को बहुत कुछ अंश में सफल बनाया। मूलीमन समिति की नियुक्ति साइमन कमिशन का निश्चित तिथि से दो वर्ष पूर्व नियुक्ति तथा गान मेज परिषद् की व्यवस्था स्वराज्य दल के कार्य-कलाप के ही परिणाम थे। असहयोग आन्दोलन के स्थगन के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन में जो रक्तिता आ जाती उस स्वराज्य दल ने पूरा किया और राष्ट्रवादी धारणाओं को जनता के मध्य जीवित रखा।

इस दल के कार्य-कलाप ने न केवल देशवासियों को ही अपितु गामन को भी यह समाधान कराया कि 1919 की सुधार योजना दोषपूर्ण है। कौंसिल में जाकर सरकार के स्व-आचारी कार्य-कलाप का विरोध करके दल ने जनता को स्व-आचारी शासन के विरुद्ध सचेत बनाय रखा। साथ ही इस दल ने जनता की इस धारणा को भी दूर प्रदान किया कि विदेशी गामन के अत्याचारों का विरोध किया जाना चाहिए। इस दल ने उत्तरवादी दल का अन्त करा दिया और सरकार को भी यह आभास हो गया कि जनता के प्रतिनिधि सदस्य गामन के साथ सहयोग की नीति का अधानुमरण नहीं करेंगे।

परन्तु 1926-27 का वान राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अचरार का वान मिद्ध हुआ। उस अवधि में देश में जनक म्याना पर साम्प्रदायिक दंग छिड़े। या तो इन दलों का सितसितना पहन ही प्रारम्भ हो गया था। परन्तु 1926-27 के दंगाने गामनीय आन्दोलन का बहुत प्रभावित किया। अब यह स्पष्ट हो गया कि हिंदू मुस्लिम एकता का पुनर्जीवित किया जाना सम्भव नहीं है। स्वराज्य दल की शक्ति भी क्षीण होनी जा रही थी। राष्ट्रीय आन्दोलन भागनिगूय हो गया था। अतः इस सजीव करने के लिए नई परिस्थितियाँ तथा याजनाओं की आवश्यकता थी।

स्वराज्य दल की नीतियाँ तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति के काम

मे जो भी कमियाँ रही हो, यह श्रेय तो स्वराज्य दल को मिलता ही है कि उसने भारत सरकार को यह ममाधान कर दिया कि 'औपनिवेशिक नमूने की सत्ता का हस्तान्तरण एक ऐमा मामला था जिमे किसी निश्चित अवधि के भीतर अव्यावहारिक तथा अप्राप्त समझकर एक किनारे पर रख दिया जाये।' स्वयं वाइसराय के गृह सदस्य मेनकम हैली ने इसे एक जीवित मामला कहा था। स्वराज्य दल ने यह मिद्ध कर दिया कि भारत के राष्ट्रीय नेताओं में कितनी उच्च कोटि की सासदीय क्षमता थी और ससद में एक प्रभावशाली विरोध प्रस्तुत करने की तथा निर्वाचनों के निमित्त सगठनात्मक क्षमता भारत के राष्ट्रीय नेताओं में कितनी श्रेष्ठ थी। इस दल को सबसे बड़ा श्रेय इस बात का प्राप्त होता है कि इसने 1919 के शासन सुधार कानून की निरर्थकता को स्पष्ट कर दिया जो न तो ब्रिटिश नमूने की ससदीय शासन प्रणाली का द्योतक था और न ही अमरीकी अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का। अतएव उसका कार्यान्वयन अव्यावहारिक सिद्ध हुआ। स्वयं लार्ड रीडिंग की धारणा थी कि यदि स्वराज्य दल, राष्ट्रवादी तथा स्वतन्त्र सदस्य एक जुट होकर सरकार का विरोध करते रहते, तो सरकार के लिए शाही आयोग को और अधिक जल्दी नियुक्त करने की माँग को ठुकराना कठिन हो जाता। इस दृष्टि से स्वराज्य दल ने वैधानिक एवं सहयोगपूर्ण ढंग से सरकार की अवाञ्छनीय नीतियों का प्रतिरोध करने का एक नया तरीका निकाल सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि भारतवासी अपनी स्वायत्त शासन की माँग को पूर्णतया सही परिपेक्ष में रख रहे थे। शासकों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भारतवासी स्वशासन की क्षमता नहीं रखते।

प्रश्न

- 1 स्वराज्य दल का क्या उद्देश्य था ? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में उसे कहा तक सफलता मिली ?
- 2 स्वराज्य दल की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए।

पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पृष्ठभूमि

(AIM OF POORNA SWARAJ BACKGROUND)

साइमन कमीशन

भारतीय शासन सुधार अधिनियम 1919 के अनुच्छेद 84 में यह प्राविधान किया गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष पश्चात् इस कानून के अन्तर्गत स्थापित शासन व्यवस्था प्रतिनिध्यात्मक मन्थाना आदि के सम्बन्ध में जांच करने तथा उनमें सुधार परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में रिपोर्ट्स के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जायगी। इसके अनुसार ऐसा कमीशन 1929 में नियुक्त किया जाना था। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसकी नियुक्ति करने का निश्चय विवाचित समय से दो वर्ष पूर्व ही (अर्थात् 1927 में) कर दिया और नवम्बर 1927 में इसकी नियुक्ति की घोषणा कर दी। ऐसा क्या किया गया इसके अनेक कारणों का अनुमान लगाया जाता है। एक धारणा यह है कि इस सुधार कानून का भारतवासियों ने प्रारम्भ में ही तीव्र विरोध किया था और निरन्तर इसकी समाप्ति तथा इसके स्थान पर नये कानून के निर्माण की मांग प्रबल होती जा रही थी। स्वराज्य के विधान सभाओं में जो प्रतिरोध का स्वभाव अपनाया था उसका अनुसार भी भारत की सांविधानिक सुधारों की मांग को लम्बे समय तक रोक रखना ब्रिटिश सरकार के हित में न होता। यद्यपि इंग्लैंड के विभिन्न राजनयिकों तथा प्रमुख नेता विचार रूप में दौरी तथा उदार दलों के राजनयिक कार्यक्रम तथा उसके अन्तर्गत नवाग्राह और स्वराज्य के गतिविधियों का जवाबदेही कानिकारी तथा अनुत्तरदायित्व गूण मानते रहे और भारत की स्वायत्त शासन की मांग को ठुकराते रहे तथापि वास्तव में सगरे तान्त्रिकों को बड़ी बचनी का अनुभव हो रहा था। व्यवस्थापिका में प्रायः दिन सरकारों प्रस्तावों का विरोध उसके लिए असह्य हो रहा था। अतः इस कमीशन की नियुक्ति करने में गीघ्रता की गयी। दूसरी धारणा यह है कि 1926 में भारत में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया था अतः ब्रिटिश सरकार इस घटनाक्रम का नाश उठाना चाहती थी। उस समय पर कमीशन को यह सिफारिश के अन्तर्गत मिल जाता कि भारत में साम्प्रदायिक मनोभाव इतने बढ़ चुके हैं कि पूर्ण उत्तरदायी शासन संचालित करने की क्षमता भारतवासियों में नहीं है। एक तीसरा दृष्टिकोण यह है कि भारतीय धर्म का भावनात्मक अनुसार देश के शासन का यह आभास हुआ कि 1929 में इंग्लैंड के आम चुनावों में मजदूर दल के जीतने का आसार था। अतः यदि 1929 में कमीशन नियुक्त किया जायगा तो उसकी रिपोर्ट आदि के सम्बन्ध में मजदूर दल की सरकार ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को उचित रूप में सम्पन्न नहीं करेगी। दौरी नेताओं को यह भय था कि श्रमिक दल की भारतीय स्वायत्त शासन की मांग के साथ सहानुभूति है। अतः यदि 1929 में ऐसा आयोग नियुक्त किया जायगा तो श्रमिक दल इस समस्या का उसमें स्थान लगा जा भारतीय स्वायत्त शासन की मांग का पूरा करने की सिफारिश करेगा और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन अहित होगा। दौरी नेता यह महत्त्व करने को भी तैयार न थे कि आयोग की नियुक्ति की घोषणा से पूर्व भारत का राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में राष्ट्रवादी तत्त्वा के बहुमत में फिर ऐसा मांग का प्रस्ताव पाम हो जाय क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इन तत्त्वा का ऐसा प्रचार करने का लाभ मिलेगा कि उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को इस आयोग की नियुक्ति के लिए विवश कर दिया था। इसमें व्यवस्थापिका के

अगले चुनावों में उनकी लोकप्रियता बढ़ जायेगी।¹ अतः शीघ्र ही कमीशन की नियुक्ति कर दी गयी। भारत में इस अवधि में युवक सगठन तथा वामपंथी सगठन जोर पकड़ रहे थे। इनके ऊपर रूसी क्रांति तथा समाजवादी विचारधाराओं का प्रभाव था।² इसलिए भी ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत के लिए नये वैधानिक सुधारों को लाने की चिन्ता में थी, ताकि युवक सगठनों की गति-विधियों को दूसरी ओर मोड़ा जा सके। इस प्रकार अनेक परिस्थितियों तथा कारणों से ब्रिटिश सरकार को ऐसा कमीशन तुरन्त नियुक्त करने के लिए विवश होना पड़ा।

साइमन कमीशन की नियुक्ति

1919 के सुधार अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये इस ससदीय आयोग को साइमन कमीशन इसलिए कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था। इस कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्य थे। ये सभी अंग्रेज थे। इस कमीशन की सबसे बड़ी कमी यही थी। इसी के कारण भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग ने इसकी नियुक्ति को देश का सबसे महान् अपमान समझा और विविध स्थानों द्वारा इसके प्रति विरोध प्रकट किया जाने लगा। जब इसके निर्माण पर भारत में आपत्ति तथा विरोध प्रारम्भ हुआ, तो ब्रिटिश सरकार की ओर से ऐसे तकनीकी तर्क दिये गये कि कमीशन में केवल ब्रिटिश सदस्य ही इसलिए नियुक्त किये गये थे कि उन्हीं को समझ के समक्ष प्रतिवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके विरुद्ध जब यह तर्क रखा गया कि लार्ड सिन्हा जो एक भारतीय थे और ब्रिटिश सदस्य भी थे, उन्हें क्यों नहीं लिया गया, तो प्रति-तर्क यह था कि यदि उन्हें लिया जाता तो भारतीय जनता के विविध स्वार्थों से युक्त अन्य वर्गों को उनकी नियुक्ति पर आपत्ति होती। साथ ही यदि विविध वर्गों के भारतीय प्रतिनिधि कमीशन में नियुक्त किये भी जाते तो उसमें कमीशन का आकार बहुत बड़ा हो जाता और उसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती। इस प्रकार जो भी तर्क इस सम्बन्ध में दिये गये, वे सब अपूर्ण एवं सारहीन थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में किसी भी सांविधानिक सुधार योजना के लिए ब्रिटिश सरकार भारतवासियों का सहयोग नहीं लेना चाहती थी, अपितु उसके निर्णय का दायित्व केवल ब्रिटिश संसद पर छोड़ना चाहती थी। कमीशन की नियुक्ति की घोषणा भी ऐसे नाटकीय ढंग से की गयी कि जिससे भारतवासियों को अपमानित ही होना पड़ा। 5 नवम्बर 1927 को गवर्नर-जनरल ने गांधी जी तथा अन्य भारतीय नेताओं को दिल्ली आने का निमन्त्रण दिया, और जब वे वहाँ पहुँचे तो गवर्नर-जनरल ने उन्हें वह कागज यमा दिया, जिसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति की सूचना थी। गांधी जी ने व्यग्र करते हुए कहा कि जब गवर्नर-जनरल इस पत्र को एक आने के लिफाफे में भेज सकते थे, तो उन्हें हजारों मील की यात्रा करते हुए इतने नेताओं को इस छोटी-सी बात के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। परन्तु साइमन कमीशन की नियुक्ति से सम्बन्धित यह घटना राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अत्यन्त महत्त्व की घटना सिद्ध होने की थी।

कमीशन का बहिष्कार

साइमन कमीशन में जिन सात सदस्यों को नियुक्त किया गया था उनमें से 3 रुढ़िवादी दल के, अध्यक्ष सहित 2 उदार दल के तथा 2 श्रमिक दल के सदस्य थे। इनमें से साइमन को छोड़कर शेष कोई भी सदस्य उच्च कोटि के राजनेता नहीं थे, भले ही वे सांविधानिक विधि नेता रहे हों। इसमें किसी भी भारतीय नेता को सदस्य के रूप में न लेना ब्रिटिश साम्राज्यशाही नीतियों का स्पष्ट प्रमाण था। उन्हें केवल साक्ष्य के रूप में कमीशन के समक्ष उपस्थित होने का

¹ Tara Chand, *op cit*, 60

² इनका उत्तम क्रांतिकारी आन्दोलन के अध्याय में पहले किया जा चुका है। मुद्रमिद क्रांतिकारी नेता सरदार भगतसिंह ऐसे विचार रखते थे।

प्राविधान किया गया था। कमीशन का रिपोर्ट तयार हो जाने पर भारतीय विधानमण्डल की एक प्रवर समिति उस पर अपने विचार रखती और कमीशन तथा प्रवर समिति की रिपोर्ट ब्रिटिश समन्त की संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती। इस प्रकार जसा डा. ताराचन्द ने लिखा है ब्रिटिश समन्त के साथ समस्या की इस पूर्णतः प्रबुद्ध ज्यूरी (exceptionally intelligent jury) से यह आशा की गयी थी कि वह मसद का एक ऐसी समस्या पर सनाह दे जो अत्यधिक जटिल तथा ऐतिहासिक दृष्टि से विषयव्यापी महत्त्व की थी।¹

स्वयं भारत मंत्री वर्नेन्ड तथा वामराय नाड इरविन का भय था कि भारत के भावी सांविधानिक ढांच के सम्बन्ध में सनाह देने के लिए विबुद्धनया अग्रज सदस्य द्वारा निर्मित आयोग को भारत में भेजने की प्रतिक्रिया भारतीय नेताओं द्वारा उसका बहिष्कार करने के रूप में व्यक्त होगी। ये ब्रिटिश नेता भारतीय स्वायत्त शासन का मांग का ठुकराने का धारणा में जिनके अधिन प्ररित थे उनका ही अधिन उन्हें इस वास्तविकता का ज्ञान हो चुका था कि जब भारतीय नेतृत्व काफी प्रबुद्ध तथा जागरूक हो चुका है। अतएव उन्होंने भारतीय नेताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा इस आयोग का विरोध किया जाना तथा बहिष्कार किया जाना की भावनाओं पर कूटनीतिक विचार आरम्भ कर लिया। भारतीय विधान सभा के अध्यक्ष विल्लिन्गडोन्स ने जो उस समय अध्यक्ष की धारा पर गये हुए थे नाड वर्नेन्ड का स्पष्टनया बता दिया था कि इस आयोग का भारत में पूर्ण बहिष्कार किया जायेगा। नाड इरविन ने भारत मंत्री को सूचित किया था कि वह भारत के मुसलमानों, उत्तरवातियों तथा राजा-महाराजाओं की महायता से विरोधी (हिन्दु) काग्रस से निरन्तर होगा। उसने बताया कि मुसलमान अग्रजों के मिन हैं और वे कमीशन का बहिष्कार नहीं करेंगे। राजा व नयाव ता पूर्णतया अग्रजों के साथ हैं। इस प्रकार ब्रिटिश शासक आयोग का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया जाना की सम्भावनाओं से पूर्व परिचित थे। साथ ही भारत में कमीशन का बहिष्कार किया जाना की स्थिति में सम्भावित आन्दोलन का घन प्रयोग द्वारा कुचनन के लिए भी सरकार सतर्क थी।

कमीशन के निर्माण में जो दाव था वे तो भारत के लिए ग्रपमानजनन से ही साथ हो उसके उद्देश्य भी भारतीय जनमत का भाव नहीं थे। कमीशन यह जांच करने के लिए नहीं आ रहा था कि भारत में उत्तरवाती शासन का संचालन करने को थापना किस प्रकार की जा सकती है अतितु उसे मूलरूप में यह बताया था कि भारतवासी उत्तरवाती शासन का संचालन करने की क्षमता रखते हैं या नहीं। जत यह स्वाभाविक था कि ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्णतया अग्रजों से निर्मित आयोग की संस्तुति केवल भारत के सांविधानिक भविष्य का निर्धारण किया जाना भारतीय जनता के आत्म-सम्मान का भारी चुनौती थी। इसलिए सार्वभौमिक राजनैतिक दाना ने कमीशन का विरोध तथा बहिष्कार करने का संकल्प लिया। अन्तर्मुनिम लोग का एक वर्ग हमेशा समयन था। जिन्ना के सहयोगी मुस्लिम लोग के नेता भी इस कमीशन के बहिष्कार के समयन में थे। स्वयं जिन्ना ने मग्न शिवस्वाधी अध्यक्ष एनी बेसेन्ट अन्तर् रहीम अली इमाम चिमन नाथ सोनववाल जाति के साथ उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया था जिसमें यह मांग की गयी थी कि भारतवासी इस आयोग के साथ कार्य करने में भाग न लेंगे और न उस कोई सहयोग देंगे। भारतीय जनता ने सकी नियुक्ति का एक राजनैतिक धूतना अथवा भारत का घोर अपमान माना।

काग्रस कर्म में सकी नियुक्ति की प्रतिक्रिया यह हुई कि नवम्बर 1927 का मंगल अधिवेशन में काग्रस ने हमेशा पूर्ण बहिष्कार करने का संकल्प लिया। उत्तरवाती मध महम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मस्लिम लोग के एक वर्ग हिन्दू महासभा जाति ने भी हमेशा बहिष्कार करने का निश्चय किया। इस प्रकार कमीशन का व्यापक बहिष्कार होना था। परन्तु

1928 में जब प्रथम बार कमीशन बम्बई में पहुँचा तो देशव्यापी हड़ताल के द्वारा उसका स्वागत किया गया। 16 फरवरी 1928 को केन्द्रीय विधान सभा में लाला लाजपतराय ने कमीशन के विरुद्ध यह प्रस्ताव रखा कि 'विधान सभा सपरिषद् गवर्नर-जनरल को सन्तुति देती है कि वे कृपा कर सम्राट की सरकार को ससदीय आयोग के प्रति जिसे कि भारत के विधान का पुनरवलोकन करने के निमित्त नियुक्त किया गया है, विधान सभा के पूर्ण अविश्वास से अवगत करा दे।' सरकार के गृह सदस्य ने भी इसका विरोध किया। वाद-विवाद के उपरान्त उक्त प्रस्ताव 62 के विरुद्ध 68 मतों से पास हो गया। जहाँ कहीं भी कमीशन पहुँचा, वहाँ हड़ताल वाले भण्डों, प्रदर्शनों तथा 'साइमन वापिस जाओ' के नारों से उसका विरोध किया गया। सबसे अप्रिय घटना लाहौर में हुई। लाला लाजपतराय, जो स्वयं हृदय-रोग के मरीज थे, साइमन कमीशन विरोधी जलूम का नेतृत्व कर रहे थे। इस समय सरकार ऐसे प्रदर्शनों, विरोधों आदि का हिंसात्मक ढंग से दमन कर रही थी। पुलिस ने लाला जी के ऊपर इतनी निर्दयता से प्रहार किया कि दो सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत के ऊपर भी ऐसे ही लाठी प्रहार किये गये। सर्वत्र कमीशन का काम पुलिस की कठोर देख-रेख में किया जाने लगा। प्रथम बार यह 3 फरवरी 1928 से 31 मार्च 1928 तक और दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत में रहा। इसे अवकाश साक्ष्य केन्द्रीय व्यवस्थापिका की केन्द्रीय समिति तथा प्रान्तीय परिषदों की समितियों से प्राप्त हुआ। कमीशन तथा समितियों के प्रतिवेदन पृथक्-पृथक् दिये गये। मई 1930 में ये प्रतिवेदन ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किये गये। उस समय इंग्लैंड में रामजे मैकडोनेल्ड के नेतृत्व में श्रमिक दल की सरकार बन चुकी थी और कमीशन की रिपोर्ट मिलने से पूर्व ही प्रधानमंत्री से परामर्श करके वाइसराय ने कुछ घोषणाएँ कर दी थी जिनमें गोल मेज सम्मेलन की स्थापना तथा भारत को औपनिवेशिक स्थिति प्रदान करने के आश्वासन थे। ठोरी तथा उदार दल के नेताओं ने इस घोषणा का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे श्रमिक दल की सरकार की भारत के प्रति किसी भी सहानुभूतिपूर्ण नीति के विरोधी थे।

कमीशन का प्रतिवेदन

भारत की भावी साविधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका क्षेत्र कुछ दृष्टियों से व्यापक था, परन्तु कुछ मौलिक बातों के सम्बन्ध में उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों को जान-बूझकर बचाया। इससे पूर्व राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता निरन्तर औपनिवेशिक स्वराज्य सहस्य व्यवस्था की माँग करने आये थे। परन्तु दिसम्बर 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में औपनिवेशिक के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की माँग का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। इसके विपरीत साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारत की औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थिति तक को पूणतया उपेक्षित रखा गया। रिपोर्ट का ऐसा व्यवहार भारत की जनता के लिए सबसे अधिक असन्तोष का कारण सिद्ध हुआ। अन्य सुभाव निम्नांकित थे

(अ) प्रान्तीय शासन—कमीशन ने प्रान्तों की द्वैध-शासन-प्रणाली को सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों दृष्टियों से दोषपूर्ण बताकर वहाँ पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की सन्तुति दी। उसके मत से प्रत्येक प्रान्त को इतनी स्वायत्तता प्रदान की जाये कि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन सके। प्रान्तों के प्रशासन में केन्द्रीय सरकार तथा भारत मन्त्री के हस्तक्षेप का अवसर न दिया जाये। परन्तु प्रान्त में शान्ति तथा व्यवस्था एवं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए कुछ रक्षा-कवच (safeguards) होने आवश्यक ह। अतः गवर्नरों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करके इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ब) केन्द्रीय सरकार—साइमन कमीशन सिद्धान्ततः द्वैध-शासन-प्रणाली का समर्थक नहीं था। अतः उसने केन्द्र के लिए अनुत्तरदायी स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था का समर्थन किया।

कमीशन के मत से एक मुद्दा तथा शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की नितांत आवश्यकता थी। परन्तु केंद्रीय सरकार का यह रूप अनिश्चित काल तक नहीं बना रहना चाहिए। इसका यह अभिप्राय है कि कमीशन का मतानुसार केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना कक्ष में था परन्तु उसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं कर सका कि उसकी स्थापना कब से की जाय। चूंकि कमीशन का यह सघटन शासन की सम्भावना का अपरिहार्य मान रहा था जिसके अन्तर्गत ब्रिटिश प्रांतों के अनिश्चित दली रियासतों भी शामिल हो जायगी अतः उसकी दृष्टि में तभी केंद्रीय सरकार के रूप में भी परिवर्तन लाया जा सकेगा जबकि सघटन व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम हो जाय। सम्पूर्ण भारत सघटन का निर्माण करने वाला था या के दो भागों (प्रांतों तथा रियासतों) को अलग अलग प्रकार की शासन प्रणितियाँ के अंतर्गत रहना जवाबदायी एवं असंगतिपूर्ण लगता है। अतः कमीशन की दृष्टि में इन दोनों भागों को एक ही सघटन व्यवस्था के अंतर्गत समरूप शासन प्रणाली के अनुसार शासन के प्रयास किए जान चाहिए। इस हेतु कमीशन ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के ऐसे विस्तार की सत्तुति दी जिसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा दश रियासतों दोनों का प्रतिनिधित्व हो। यह दोनों तत्त्वों के सामूहिक मामलों पर विचार करेंगे। इस हेतु संविधान में एक सामूहिक विषयों की सूची भी निर्मित कर दी जानी चाहिए।

(स) मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व—मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कमीशन ब्रिटिश शासन की नीति से जाग नहीं गया। क्योंकि मताधिकार की बात का उसने जव्यावहारिक एवं अव्यावहारिक बतौर दुसरा दिया। परन्तु मताधिकार के क्षेत्र का और अधिक बढान की सिफारिश की गयी। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को न बढा उसने समर्थन ही दिया अतः उस और अधिक बढा चलाकर जटिल प्रणाली का प्रयास किया केंद्रीय व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की सत्तुति देकर केंद्रीय शासन के सम्बन्ध में लोकतंत्र की पूर्ण उपेक्षा की गयी। इन सभाओं के प्रतिनिधियों को प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित करने की व्यवस्था सुझायी गयी।

(द) सांविधानिक परिवर्तन—भविष्य में सांविधानिक परिवर्तनों के बारे में कमीशन को अपने प्रति दर्शाया गया राष्ट्रव्यापी असंतोष का बड़ा अनुभव हुआ। अतः उसने यह सत्तुति दी कि भविष्य में सांविधानिक परिवर्तनों के बारे में प्रतिबन्ध देने के लिए विशेष आयोगों द्वारा जांच करने की व्यवस्था न रखी जाय। अतः संविधान का ही स्तना जाचपूर्ण बना दिया जाय कि उसमें सांविधानिक संशोधन करने का अधिकार परिवर्तन लाय जा सकें।

सुझावन

संघर्ष कमीशन की रिपोर्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। जहाँ कृपण्ड सदेश लेखकों के मत में इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश राजनीतिशास्त्र के पुस्तकालय में एक नया प्रारंभ रचना की वृद्धि की वहीं भारतीय विचारकों व राजनयिकों के मत में यह रिपोर्ट रूढ़ी की टाकरी में फटने लायक श्रुति थी। इस रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार ने ताम्र पत्र भी कायवाही न करके अगले साल मज सम्मेलन के लिए इसके ऊपर विचार विनिमय करने का दरवाजा खोल दिया। निम्न 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की अनेक बातें से रिपोर्ट पर आधारित थी परन्तु आचार्य की बात यह है कि इस रिपोर्ट में जो थोड़ी-सी अछाहियाँ थी उनकी उपेक्षा करके 1935 के कानून में उन्हें और अधिक गुरुत्व से रखा गया।

जिस दृष्टि में यह कमीशन की नियुक्ति की गयी थी और इसके प्रति जो दण्डव्यापी अमनोपेक्षा थी उन मन्त्रियों में भारतीय जनमन द्वारा यह रिपोर्ट का स्वागत तो सम्भव नहीं था परन्तु रिपोर्ट ने भारतीय माँग की मूलभूत बातों को उपरान्त रखकर भारतीय परिस्थितियों की कमियों का और अधिक जलिल बताने पर जोर दिया। इसके कारण यह रिपोर्ट की अछाहियाँ भी समाप्त हो गयी। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि भारतवर्ष में यह रिपोर्ट का विरोध न करता तो सम्भव

प्रान्तीय स्वायत्त शासन की स्थापना 1937 में होने की अपेक्षा और जल्दी हो जाती। इस रिपोर्ट में प्रान्तों में रक्षा कवचों से युक्त पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो सिफारिशें की थीं वे 1935 के अधिनियम द्वारा प्राविधित प्रान्तीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था से अधिक खराब नहीं थी। साइमन कमीशन से जो कि पूर्णतया अंग्रेज सदस्यों से निर्मित था, यह आशा करना भ्रान्तिपूर्ण था कि वह भारत की औपनिवेशिक स्वराज्य, वयस्क मताधिकार तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांगों को किंचित मात्र भी प्रोत्साहन देता। उससे यह आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वह साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या को सुलझाने में कोई ईमानदार प्रयत्न करता क्योंकि एक ऐसी यही दवा थी जिसके प्रयोग से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत में अस्तित्व बना हुआ था। इसके समर्थन में ये तर्क दिये गये थे कि स्वयं कांग्रेस तथा लीग ने 1916 में इसे स्वीकार कर लिया था। परन्तु इस तथ्य की उपेक्षा की गयी थी कि उक्त समझौता एक अस्थायी व्यवस्था थी और स्वयं जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1927 में पृथक् निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट ने भी इसका विरोध किया था।¹ जहाँ तक केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उसका दृष्टिकोण प्रतिक्रियावादी बना रहा। एक अनुत्तरदायी केन्द्रीय सरकार की स्थापना की सिफारिश करना, वह भी उस समय जबकि राष्ट्रीय आन्दोलन पूरे जोर के साथ पूर्ण स्वराज्य की मांग पर तुला था, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण सुभाव था। कमीशन को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने सर्वप्रथम भारत के लिए एक अखिल भारतीय सघ-व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में सघात्मक शासन-प्रणाली नितान्त आवश्यक थी। परन्तु सघ-व्यवस्था की स्थापना के निमित्त व्यवस्थापिका सभाओं में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करना 'घोड़े के आगे बघी को खड़ा करने' के सदृश था। 1919 के सुधार कानून तक ने सीमित मताधिकार के आधार पर ही सही, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की थी। परन्तु कमीशन द्वारा 1930 में यह सिफारिश करना कि केन्द्रीय व्यवस्थापिकाएँ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हों, कमीशन के सदस्यों के किस तर्क तथा सविधानवाद के किस अनुभव पर आधारित थी, वही लोग जाने। इस प्रकार मझूचे रूप में तत्कालीन राष्ट्रवादी शक्तियों के विकास की गति के सन्दर्भ में साइमन रिपोर्ट किसी भी अर्थ में सन्तोषजनक नहीं थी और भारतीय जनमत द्वारा ठुकराना पूर्णतया एक सम्मानजनक निर्णय था।

नेहरू रिपोर्ट

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में जातीय अभिमान अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। भारत में अपने साम्राज्यवाद को बनाये रखने तथा भारतवासियों की स्वायत्त शासन की मांगों को ठुकराने में अंग्रेज भारतवासियों की अयोग्यता तथा अक्षमता को व्यक्त करने में जरा भी नहीं सकुचाते थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति करते समय अनुदार दलीय भारत मन्त्री लार्ड वर्कनहेड ने लार्ड सभा में भारतवासियों को यह चुनौती दी कि भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता इस सीमा तक बढी हुई है कि कोई भी भारतवासी समस्त साम्प्रदायिक वर्गों को मान्य सविधान बना सकने में अक्षम है। ऐसी स्थिति में भारतवासियों द्वारा साइमन कमीशन का वहिष्कार करने में कोई बुद्धिमत्ता व्यक्त नहीं होती। भारत मन्त्री की इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को कांग्रेस ने दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें लगभग 29 सगठनों ने भाग लिया। इसके पश्चात् 19 मई 1928 को इस सम्मेलन की वर्म्बर्ड में पुन बैठक हुई। इस बैठक में पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया गया।² इसका कार्य भारत के लिए एक उपयुक्त सविधान का प्राप्त रूप तैयार करना था।

¹ Ibid, 76

² ये सदस्य थे तेजबहादुर सप्रू, अली इमाम, प्रधान, शोयब कुरेशी, सुभाषचन्द्र बोस, अणे, जयकर, एन० एम० जोशी तथा मंगलमिह जो विभिन्न राजनीतिक गुटों से लिए गए थे।

समिति के अध्यक्ष पण्डित नरहरी के नाम से जा रिपोर्ट तयार की गयी उसी का नरहरी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस समिति ने 25 बैठकें करके एक सवर्माय सविधान का प्रारूप तयार किया। यद्यपि यह एक पर्याप्त द्रुततर काय था तथापि ब्रिटिश भारत मन्त्री की चुनाता का यह सर्वोत्तम उत्तर था। नरहरी रिपोर्ट तयार हो जाने पर अगस्त 1928 में सवदनाय सम्मेलन की पुनः व्यवस्था में डा. अमारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें नरहरी रिपोर्ट को सम्मेलन ने अपना अनुमोदन प्रदान किया। 22 दिसम्बर 1928 से 1 नवम्बर 1929 तक का अवकाश में सवर्माय सम्मेलन के समक्ष मातीनाम जी ने समिति की इस रिपोर्ट का प्रस्तुत किया। उस सम्मेलन में गांधी जी जिता प्रभु देश के विभिन्न वर्गों के प्रमुख नेता उपस्थित थे। ये अमारा सम्मेलन के अध्यक्ष थे।

रिपोर्ट के प्राविधान

यह बात स्मरणीय है कि साविधानिक सुधारों के तार में सामान्य कामाशन को अपनी रिपोर्ट तयार करने में 2 वर्ष का समय लगा जबकि नरहरी समिति ने चार महीने में सविधान की व्यापक रूपरेखा तयार कर दी। कारण स्पष्ट है सामान्य कामाशन का ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का संरक्षण करना था जिसमें तथ्या को तोड़ मरोड़ कर रखने में समय लगा स्वाभाविक था। दूसरी बात यह थी कि सामान्य कामाशन के सभी सदस्य अज्ञ थे जिन्हें भारत की स्थिति का सही ज्ञान नहीं था। उनकी खोज भौण तथा अज्ञानपूर्ण साधना पर आधारित थी। अतः विपरीत नरहरी समिति भारतीय सविधान की व्यवस्था के बारे में स्वयं स्पष्ट थी और जिस सविधान को तयार कर रही थी वह अपने देश तथा आवश्यकताओं के लिए था। यही कारण है कि नरहरी समिति की रिपोर्ट भविष्य में स्वतन्त्र भारत के सविधान की पूर्वगामी सिद्ध है और सामान्य कामाशन की रिपोर्ट गाने में परिणत हो चुकने की जगह पर जाकर 1935 के नामन सुधार अधिनियम का माग-अंग बनने जा पहुँचता है तब तक नहीं हो पायी। नरहरी रिपोर्ट की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) सुदूर भविष्य में भारत राज्य का स्वरूप सघातमक शासन-व्यवस्था बना ही हो सकता है जिसमें एक तथा प्रान्त पूर्ण स्वायत्तगामी है। ज्ञान के मध्य गति विनश्यत सघीय आधार पर किया जाना चाहिए और अवशिष्ट विषय केन्द्र के हाथ में रहें।

(2) कर्तीय तथा प्रातीय सरकारें समन्वय नामन प्रणाली के आधार पर निर्मित की जानी चाहिए और मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व सामूहिक होना चाहिए।

(3) रिपोर्ट में यह मांग की गयी थी कि भारत का गान्धानिरीक्ष जीपनिवशिक स्वराज्य की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए जमी की कनाता आदि दशा की थी।

(4) कर्तीय व्यवस्थापिका के दो सदन होंगे। लोक मन्त्र (निम्न मन्त्र) वयम्भ मनाधिकार के आधार पर प्रत्येक रूप में चुन गये मन्त्रियों का तथा उच्च मन्त्र प्रातीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित मन्त्रियों का होगा। प्रान्त में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी जिनके मन्त्र वयम्भ मनाधिकार द्वारा चुन जायेंगे। इन मन्त्रियों का कार्यकाल पांच वर्ष का होना चाहिए। मन्त्रिमण्डल उनके प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा। परन्तु सरकारों के स्थायित्व के हित में यह व्यवस्था भी बनाई गयी थी कि प्रथम तीन वर्ष तक केवल अध्याचार मन्त्र जागता पर ही मन्त्रिमण्डल अधिनियम द्वारा नियमित जा सकेंगे। पांच वर्षों में उन्हें व्यवस्थापिका के विराम पयन हो पाने पर बन रहने का हक होगा।

(5) नरहरी रिपोर्ट ने प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में यह संस्तुति दी थी कि प्रधानमन्त्री प्रतिस्थापन मन्त्री विराम मन्त्री तथा सम्मेलन मन्त्रियों का एक ही विधान मन्त्रियों का एक समिति हो जा सकेगा मामला में मनाह किया करण।

(6) नरहरी रिपोर्ट का एक विधान यह भी था कि उभय सविधान द्वारा नामनिका के

मौलिक अधिकारों की घोषणा करने तथा लोकप्रभुसत्ता के सिद्धान्त को अपनाने का सुझाव दिया था।

(7) अल्पसंख्यकों के संरक्षण तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्हें स्वतन्त्रता देने की व्यवस्था भी बतायी गयी थी। साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया था। केवल मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुझाई गयी थी, परन्तु सयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाने का सुझाव था।

(8) सिन्ध के पृथक् प्रान्त के निर्माण तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को पूर्ण प्रान्त की श्रेणी देने की भी सिफारिश की गयी थी।

(9) न्यायपालिका के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया था कि भारत के लिए एक सर्वोच्च तथा अन्तिम अपील की न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए और प्रीवी कौन्सिल में भारत की कोई अपील ले जाने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

(10) देशी राज्यों के बारे में भी कहा गया कि उनसे अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का आग्रह किया जाये, ताकि वे सध में शामिल होने के लिए तैयार हो सकें। परन्तु उनके विशेषाधिकारों का संरक्षण किया जायेगा। अर्थात् सर्वोच्च सत्ता (paramountcy) का अन्त नहीं होगा। वह ब्रिटिश शासन के हाथ से भारत की नई सरकार के पास आ जायेगी।

रिपोर्ट के ऊपर प्रतिक्रिया

भारतीय साविधानिक विकास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रलेख है। परन्तु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के विकास-क्रम के सन्दर्भ में इस रिपोर्ट को वांछित समर्थन तथा प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो पाया। ब्रिटिश शासकों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाना अप्रत्याशित नहीं था। वे तो साइमन कमीशन पर आशा लगाये बैठे थे। औपनिवेशिक स्वराज्य, पूर्ण उत्तरदायी शासन, वयस्क मताधिकार, मूल अधिकारों की प्रत्याभूति आदि की ब्रिटिश शासकों में आशा करना कोरा स्वप्न था। साथ ही साविधानिक सुधारों की जो व्यापक रूपरेखा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी थी, उसे मानना उसके लिए एक अपमान की बात होगी, क्योंकि वे भारतवासियों को ऐसा कर सकने में सर्वथा अक्षम मानते हैं।

दूसरी ओर भारतीय राजनीति के विविध वर्गों ने भी अनेक आधारों पर इसे स्वीकार नहीं किया। स्वयं कांग्रेस का युवा तत्त्व इसका विरोध करने लगा। पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस युवा वर्ग के नेता थे। दोनों ने इस आधार पर रिपोर्ट का विरोध किया कि रिपोर्ट भारत के लिए औपनिवेशिक स्थिति मात्र से सन्तुष्ट है। इस वर्ग ने दिसम्बर 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य की माँग पर जोर दिया। 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पण्डित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष होने वाले थे। अतः उन्हें इस विरोध का सामना करना था। वे इसके लिए गांधी जी की सहायता पर निर्भर थे। अधिवेशन में विरोध का उत्तर देते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि 'मैं ब्रिटेन के साथ सम्बन्धों को तोड़ लेने में राजी हूँ यदि उसका हमारे साथ आज का सा व्यवहार बना रहता है। परन्तु मैं उसके ऐसे आचरण के विरुद्ध नहीं हूँ जैसा वह उपनिवेशों के साथ करता है।' परन्तु जवाहरलाल तथा नेताजी सुभाष इससे सन्तुष्ट नहीं थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस में पुनः विभाजन की स्थिति आने लगी है। अतः गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और यह बात स्वीकार कर ली गयी कि यदि ब्रिटिश सरकार नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसम्बर 1929 तक स्वीकार कर लेती है तो कांग्रेस इस रिपोर्ट को ज्यों का ज्यों स्वीकार कर लेगी। अन्यथा असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ा जायेगा जिसके अन्तर्गत करों को न देना भी शामिल है।

अतः कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सशर्त स्वीकार किया। परन्तु जब सर्वदलीय सम्मेलन की स्वीकृति के बाद विभिन्न दलों ने पृथक् से इस पर विचार किया तो अनेक वर्ग भी इसे स्वीकार

करन म हिचकें। सिकन्दो के एक वग न बस बसलिए अमाय किया कि इसमे केवन मुसलमाना के लिए स्थान सुराति रखने की व्यवस्था की गया थी। सिकन्द भी अपन लिए वसो हा सुरक्षा चाहन नग। स्वय मुसलमाना के एक वग ने जिसके नेता मुहम्मद अनी जिन्ना ये इस स्वीकार नहा किया। जिन्ना अपनी 14 मूत्री मांगा पर डटे रह।¹ राष्ट्रवादी मुसलमाना न बसका स्वीकार कर लिया। कुछ हरिजन भी बस सन्तुष्ट नही हुए। मौलाना मुहम्मद अनी न भी बसका विरोध किया।

जब 28 दिसम्बर 1928 का सबदतीय सम्मेलन म नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा था तो जिन्ना न साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध म कुछ सगाधन रखे। उनका मांग थी कि केन्द्रीय विधान सभा म एक तिहाई स्थान मुसलमाना के लिए सुराति रखन की व्यवस्था की जाय और पञ्जाब तथा बंगाल की प्रांतीय सभाओं म जनसंख्या के आधार पर उनके लिए स्थान सुराति रखे जायें। सिक को तुरन्त जवाब प्राप्त कर दिया जाय न कि संविधान लागू हान पर। अवशिष्ट गतिविधि प्राप्ता की गी जायें। संविधान सगाधन का अधिकार प्रत्येक सदन के 4/5 बहुमत द्वारा तथा दोनों सदन के संयुक्त रूप स मतदान के आधार पर लिया जाय। सत्र न जिन्ना के सगाधन को 'यावहारिकता की दृष्टि स उचित बनाया परन्तु हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि जयकर न बसका तीव्र विरोध किया। मतदान पर जिन्ना का सगाधन गिर गया। यह एक बनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसन साम्प्रदायिक समस्या को भविष्य म निरन्तर जटिलतर बना दिया। सत्र के मत स जनसंख्या के आधार पर जब 27/ स्थान मुसलमाना को स्वयमेव मिलन ये और यदि 6 1/2/ उह और द निय जात तो कार्य आसमान तो नहा गिर जाता। एक भारी समस्या का समाधान हा जाता। यदि यह माना गया था कि उत्तरदायी शासन स युक्त विमुक्त लोकतन्त्र म स्थाना का सुराति रखा जाना असमंज है तो स्वय नेहरू रिपोर्ट सुराति स्थाना की व्यवस्था के सिद्धांत का मान चुकी थी। वास्तविकता की उप ना करके आत्मवादिता का जवनम्बन करना उचित नहा था। यह भी जान्चय की वान थी कि स्वय गांधी जी न बस अवसर पर बाल विवाद म भाग नहा लिया और समाधान के लिए कोई हस्तक्षेप किय बिना रिपोर्ट को यथावत् स्वीकार कर उन का प्रस्ताव रखा। सम्मेलन के इस व्यवहार न जिन्ना सहृदय राष्ट्रवादी तथा मुहम्मद अनी महान गांधीवादी एवं दाना प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं को रष्ट कर लिया। यद्यपि रिपोर्ट का सरकार न भी कतई स्वीकार नही किया तथापि बसन भारतीय मुसलमाना की एकता विरोधी भावनाओं को प्रजन कर लिया। जिन्ना न अपना मत व्यक्त करत हुए कहा कि यह तरीका विन्यास का है (This is the parting of ways)। मौलाना मौहम्मद अनी के गाना म हमम (मुसलमाना म) तथा उनम (काप्रनिया म) अब एक एसी गानी आ गयी है जिसके ऊपर पुन का निमाण नहा हा सकता। य मतभेद बन्त गय और ब्रिटिश गामना का बस घटना स अताव हय तथा उमाद् मिला। इसकी सूचना गान्धर्विन न बडे उत्साह के साथ भारत मन्त्री को भेजते हुए दिया कि जब मुसलमान लोग हिन्दुओं के साथ एसी प्रतिपादिता करें ना सन्तुलन बनाय रखन के निमित्त हम भयंकर काय करेंगे।²

पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग

बीसवा सती के प्रारम्भिक वर्षों म हा काग्रम के उपबाना दन न काग्रम का राजनान्त्रिक भिन्नावृत्ति की नीति का विरोध करना प्रारम्भ कर लिया था और 1906 के कानूनता अधिनियम म नागरमाय निनक के प्रभाव स काग्रम न अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज का मांग स्वीकार कर

¹ इनका उत्तर म 'मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा देश का विभाजन' वान अध्याय म आ किया गाना।

T. Chaudhary, vol IV 113-15

When it is a case of Moslems competing with Hindus we do not try to hold the balance even. 16/4/1916

लिया था। परन्तु पूर्ण स्वराज्य का अर्थ पर्याप्त लम्बी अवधि तक ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य ही बना रहा। सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों के कांग्रेस से पृथक् हो जाने पर तथा तिलक के दीर्घ अवधि के कारावास के कारण पूर्ण स्वराज्य की माँग दबी पड़ी रह गयी। अन्य उग्रवादी नेताओं के ऊपर भी भारी प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। बाद में होम रूल आन्दोलन का लक्ष्य भी औपनिवेशिक ढंग से स्वराज्य की प्राप्ति का ही बना रहा। 1920 के लगभग जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया तो उन्होंने भी पूर्ण स्वराज्य की माँग जैसी स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं की। वे भी औपनिवेशिक स्वराज्य सदृश धारणा को ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का लक्ष्य मानते रहे। 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय करते समय पुनः कांग्रेस के युवा नेतृत्व के प्रभाव से कांग्रेस ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति घोषित किया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का बहुत स्वागत नहीं किया। इसका अर्थ यह था कि भारतवासी अपने देश में ऐसी स्वायत्त शासन-प्रणाली अपनाना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत भारत ब्रिटेन से अपना किसी प्रकार का साविधानिक सम्बन्ध नहीं रखेगा। परन्तु गांधी जी ब्रिटेन के साथ ऐसे सम्बन्ध-विच्छेद को उचित नहीं समझते थे।

1928 के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस को प्रस्ताव पास करना था। सितम्बर 1928 में जब कांग्रेस कार्य समिति ने इस रिपोर्ट को अपनी स्वीकृति प्रदान की तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने हट्ट होकर कांग्रेस सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्थिति को स्वीकार किया गया था, जबकि जवाहरलाल जी कांग्रेस के 1927 के प्रस्ताव 'पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति' के उद्देश्य पर अड़े रहे। उनके समर्थक सुभाष बाबू, आदि थे। स्पष्ट था कि इस प्रश्न पर पुनः कांग्रेस में विभाजन हो जायेगा। जब गांधी जी ने नेहरू रिपोर्ट को समर्थन देने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर सशोधन प्रस्ताव रख दिया और सुभाष बाबू ने उसका समर्थन किया। इस पर गांधी जी ने हस्तक्षेप करते हुए 31 दिसम्बर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा मानने की तथा उसकी अनुपस्थिति में कांग्रेस द्वारा पुनः असहयोग व सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ने की शर्त रखी। यद्यपि पण्डित जवाहरलाल तथा उनके साथी इससे भी सन्तुष्ट नहीं थे, तथापि गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार कर लिया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने स्पष्ट किया कि 'स्वतन्त्रता शब्द को यदि इस रूप में व्यक्त किया जाये जिस रूप में श्रद्धा तथा विश्वास की भावना से मुसलमान अल्लाह शब्द तथा हिन्दू राम या कृष्ण शब्द उच्चारित करता है तो यह एक कोरा ढकोसला होगा। स्वतन्त्रता शब्द कोरा शब्द-जाल मात्र नहीं है, अपितु यह एक बहुत बड़ी चीज है।'¹ गांधी जी का अभिप्राय यह था कि पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग तथा एक वास्तविक औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग केवल भावावेश की द्योतक है।

कांग्रेस के इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया ब्रिटिश कैम्प में एक-दूसरे ही ढंग से व्यक्त हुई। 1929 के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड के आम चुनावों में मजदूर दल के नेता रामजे मेकडोनेल्ड को मन्त्रिमण्डल बनाना पड़ा। इस समय मजदूर दल पूर्ण बहुमत में नहीं था। भारत को मजदूर दल की सरकार से बहुत आशाएँ थी। मजदूर दल को अपने देश में अनुदार तथा उदार दोनों दलों से समर्थन प्राप्त करना था, अतः वह भारत की स्वतन्त्रता की माँग को मानने की स्थिति में नहीं था।

अक्टूबर 1929 में वाइसराय ने यह घोषणा की कि 'भारत की साविधानिक प्रगति का स्वाभाविक मामला जैसा विचार किया जा रहा है यही है कि उसे औपनिवेशिक स्थिति (dominion status) प्राप्त हो। इस घोषणा का भारत में बहुत स्वागत हुआ। इस दिशा में ब्रिटिश मित्रों के भारत को सहायता देने सम्बन्धी श्रमिक दल की सरकार के प्रयासों के प्रत्युत्तर में गांधी जी ने कहा 'मैं तो सहयोग के लिए मर रहा हूँ।' साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि

¹ Quoted in P. Sitaramayya, *op cit*, 331

यदि वास्तव में औपनिवेशिक स्थिति मुझे प्राप्त होती है तो मैं इस सविधान की प्रतीक्षा में रह सकता हूँ। इसका अभिप्राय यह था कि वे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित 31 दिसम्बर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने की गत को डीना करने को भी तयार थे। परन्तु वात्सराय की इस घोषणा की प्रतिक्रिया इंग्लैंड में उठनी हुई। अनुत्तरदायी नया चर्चित वर्नेनहेड (भूतपूर्व भारत मंत्री) लाड रीनिंग आदि तो भारत को औपनिवेशिक स्थिति देना पाप समझते थे। उत्तरदायी नया लायड जाज न भी इसका विरोध किया। फनस्वम्प तत्कालीन भारत मंत्री वंजवुन वन ने अपनी प्रतिरक्षात्मक धारणा व्यक्त करते हुए इस घोषणा की पुनर्प्राप्ति की कि जिस रूप में उत्तरदायी शासन भारत में चल रहा है वह औपनिवेशिक स्थिति का ही रूप है। उमम वही मिद्वान्त है और यह जब भारत के अधिकारों का भंग बन चुका है।¹ वन का यह कथन भारतीय जनमत के निम्न एक निराशाजनक वात थी। गांधी जी जो अभी तक औपनिवेशिक स्वराज्य के कट्टर समर्थक थे अब पूर्ण स्वराज्यवादी होन लग गये। बाद में 1 मिनम्बर 1931 को यह इंग्लैंड में उठाने लिखा था कि कांग्रेस की दृष्टि में औपनिवेशिक स्थिति के मान ही पूर्ण स्वराज्य है जिसमें जहाँ तक सम्भव हो इंग्लैंड के साथ ऐच्छिक सहचार भी शामिल था जो दाता श्रेणी की पारस्परिक भनाई का धोतक है।

दिसम्बर 1929 में ताहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था। इस अधिवेशन में पण्डित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले थे। 31 दिसम्बर 1929 की तिथि कांग्रेस मन्त्रियों को भनी भाँति याद थी। जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की नेतावनी की उपता की तो ताहौर कांग्रेस ने कांग्रेस सविधान में सम्मोहन करके स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अपना ध्येय घोषित कर लिया। 31 दिसम्बर 1929 की जाही रात को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का निरगा भण्ण फहराते हुए पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति के कांग्रेस के उद्देश्य की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 से निम्नतर रमा तिथि को स्वतन्त्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। भारत के इतिहास में 26 जनवरी की तिथि एक महान् राष्ट्रीय पर्व बन गया है। जब पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर नये सविधान को पारित किया गया तो उस लागू करने के लिए भी यही तिथि भाग्य की गयी थी। पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा के ठीक बीस वर्ष पश्चात् स्वतन्त्र भारत ने 26 जनवरी 1950 को प्रभुत्वसम्पन्न गणराज्य का सविधान लागू किया। तब से यह दिन गणतन्त्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व बन चुका है।

प्रश्न

- 1 साइमन कमिशन के आपमन की भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?
- 2 टिप्पणी लिखिए—
 - (अ) साइमन कमिशन को रिपोर्ट।
 - (ब) नेहरू रिपोर्ट।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोल मेज सम्मेलन

(CIVIL DISOBEDIENCE AND THE R T C)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता संग्राम का पूर्ण नेतृत्व अपने हाथ में लेने के पश्चात् गांधी जी का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला संघर्ष 1920 का अमहयोग आन्दोलन था। इस आन्दोलन में वांछित सफलता न मिलने के पश्चात् गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया। यह कार्यक्रम स्वदेशी आन्दोलन का गतिपूर्ण विस्तार था। सावरमती तथा वर्धा आश्रम इसके केन्द्र थे। गांधी जी के अनुयायी समूचे देश में इसका प्रचार-कार्य करते रहे। जब 1920-30 के दशक में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की वदती हुई मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया बना रहा, तो यह निश्चित था कि अब गांधी जी को दूसरा अभियान प्रारम्भ करना पड़ेगा। यही अभियान 1930 का सविनय अवज्ञा आन्दोलन था जो प्रथम चरण में मार्च 1930 से मार्च 1931 तक चला। परन्तु इसकी पुनरावृत्ति 1932 से 1934 तक की गयी।

आन्दोलन की पृष्ठभूमि

(1) सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का मुख्य कारण देश की गिरती हुई राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ थीं जिसके लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी थी। इस बात को गांधी जी ने तत्कालीन वाइमराय लार्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में स्पष्टतया व्यक्त किया था। 26 जनवरी 1930 के कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार ने देश का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक शोषण करके देश को वरवाद कर दिया है। अतः जब तक देश राजनीतिक दृष्टि में पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हो जाता तब तक जनता के कष्टों का अन्त नहीं हो सकता। ब्रिटिश शासक अपनी शोषण नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे थे। अतः ऐसे शासन को समाप्त करना जनता का प्रमुख कर्तव्य है। दमनकारी शासन की समाप्ति के लिए निःशस्त्र जनता सविनय अवज्ञा तथा अहिंसात्मक सत्याग्रह का ही सहारा ले सकती है। गांधी जी को अपने इस कार्यक्रम की सफलता पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वे इसका सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे।

(2) ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत का रोप साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण बढ़ गया था क्योंकि भारत के लिए सांविधानिक सुधार-व्यवस्था पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए भारतवासियों की उपेक्षा करके पूर्णरूपेण अंग्रेज सदस्यों से निर्मित आयोग की रचना करना भारत का घोर अपमान था। इसमें यह भी स्पष्ट हो गया था कि ऐसे आयोग द्वारा जिस रूप की शासन-व्यवस्था सुझाई जायेगी वह कभी भी भारत के हित में नहीं हो सकती।

(3) जब कांग्रेस ने ब्रिटिश शासकों की चुनौती स्वीकार करते हुए सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार कराके उसका सभी दलों के सम्मेलन में अनुसमर्थन करा लेने में सफलता प्राप्त कर दी, तो ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को उपेक्षित तो रखा ही, जैसा कि उससे आना की जाती थी, साथ ही स्वयं कांग्रेस के एक वर्ग द्वारा उस रिपोर्ट में एक कदम आगे बढ़कर औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करके ब्रिटिश सरकार को 31 दिसम्बर 1929 तक इसे स्वीकार कर लेने का समय दिया था। इसी तर्क पर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया था, अन्यथा उसने यह प्रण कर लिया था कि

एसा न हान पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायगा। अन्तर्गत यही था। अन्त 31 दिसम्बर 1929 का कार्यक्रम न औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना अपना नया घोषित कर दिया। स उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब कार्यक्रम के पाम सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं रह गया था। अन्त कार्यक्रम कार्यकारिणी ने 11 फरवरी 1930 का महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार दे दिया।

(4) 1928 तथा 1929 की अवधि में देश में कुछ नये प्रकार के आर्थिक संगठन बनने लगे थे और कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। इनमें से प्रथम घटना 1928 का वास्तोनी सत्याग्रह थी। मूलतः जिन के वास्तोनी नामक ग्राम के किसानों के ऊपर जब भू राजस्व 25% बढ़ा दिया गया जिसका कि कोई तालिम या कानूनी आधार नहीं था ता किसानों ने बढ़ा हुआ नगान देश में स्वीकार कर दिया। मन्तर बन्धुमर्त्य पटन के मतत्व में यह सत्याग्रह और अधिक गतिशील सिद्ध हुआ। यह पूर्णतया गान्धीय एव जाहमात्मक था। परन्तु इनकी नीति पर चर्चा बाना ब्रिटिश सरकार ने इन दान के लिए पठाना की सनिक टकनी बनी भेजी। किसान उस से मत नहीं हुए। इस पर केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष विन्स्टन चर्च पटन ने वास्तोनी का पन निवकर अपना 'यागपत्र' इन की स्वीकृत की। अन्त समझौता हा गया और एक 'यायिक समिति' की नियुक्ति का गयी जिसने 6 1/2% वृद्धि का मुभाव दिया। किसान उसमें लिए राजा हा गये। वास्तविकता यह थी कि इन आन्दोलन में किसान नगान नना नहीं चाहते थे। उनकी यहा माग थी कि मनमाने रूप में 25% वृद्धि का 'यायिक' जाच की जानी चाहिए। दूसरी बात यह था कि कार्यक्रम इन आन्दोलन में अलग रहा। उनमें इन राजनीति आदान का रूप नहीं दिया। अन्त यह स्पष्ट हा गया था कि जब अत्याचारी गामन के विरुद्ध आन्दोलन का सत्याग्रह मफत हा सनता नना दायव्यापी संगठित सत्याग्रह नया नहीं सफत हा सनगा।

(5) दूसरी ओर इन में कुछ समाजवादी गतियाँ भी विकसित हो रही थी। इसी माध्यम वाली गति का प्रभाव भारत में भी आन लगा था क्योंकि भारत का आर्थिक शापण एक गतिशील पूँजीवादी साम्राज्य द्वारा मनमाने रूप से किया जा रहा था। भारत के माध्यमवादी का मरठ जन में जिना आगवा की 'यायिक मुनवा' किय बन् कर दिया गया था। भारत में भी अन्तिम भारतवादी दूत गनियन कार्यक्रम की स्थापना का जा चुकी थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू इनमें सम्भाषित थे। पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा में भारत का एक समाजवादी गणनत्र निमित्त करने की भा घोषणा की गयी थी। अन्त आर्थिक शापण करने पर नना साम्राज्यवादी के विरुद्ध क्रान्ति का सम्भाषन बन्ती जा रहा थी। उस बचन नतृत्व की आवश्यकता थी।

(6) ब्रिटिश सरकार भारत की भावी गामन यव था के सम्बन्ध में भारतवासियों में जिमा प्रसार का सहयोग प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त नना थी। उन्टे वन् साम्राज्य में प्रतिगध पर नी दमन की नानि अपना रहा थी। गान मज सम्पन्न की बात स्वाकार करके ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य जमा कि वास्तोनी न घोषित किया था यह था कि वह साम्राज्य का सरकार के मागानन के निमित्त जिसमें ऊपर समद के विचारार्थ प्रस्ताव का 'परत' प्रस्तुत करने का दायित्व था राय के व्यक्त करगी और उम सम्पत्ता प्रदान करगा।¹ इन दृष्टि में वास्तोनी ने ब्रिटिश गामन नीति का स्पष्ट कर दिया कि वह भारतवासियों के आमनिष्य के अधिकार का उपहास कर रही थी। भीतागमया के गाना में यह पूर्णतया स्पष्ट था कि भारत का नना आत्मनिष्य करने का न मयुक्त रूप में निषय करने की आगा रचना चाहिए यदि उर दूसरा के निषय पन् निभर रहना चाहिए। गमा कि पति में सविनय अवज्ञा आन्दोलन और अधिक आवश्यक प्रतीत हा गया।

इस प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर्याप्त सुदृढ़ थी और उसके कारण भी सुस्पष्ट थे। परन्तु इस बार गांधी जी ने पर्याप्त समय वरता। आन्दोलन छेड़ने से पूर्व उन्होंने न केवल सरकार को ही स्पष्ट चेतावनी दी, अपितु उसे विचार करने का पूरा अवसर भी दिया। साथ ही आन्दोलनकारियों को पूर्णतया तैयार कर लिया ताकि आन्दोलन किसी भी रूप में हिंसात्मक न होने पाये और सरकार द्वारा उसका दमन करने में खून-खराबी से बचा जाये।

आन्दोलन से पूर्व गांधी जी की शर्तें

यद्यपि सविनय अवज्ञा आन्दोलन की स्वीकृति कांग्रेस कार्यकारिणी ने फरवरी 1930 में दे दी थी और उसके पश्चात् भी गांधी जी ने अन्तिम क्षण तक वाइसराय को सोच-विचार करने का अवसर दिया था, जो कि उनके वाइसराय को लिखे गये 2 मार्च 1930 के पत्र के द्वारा स्पष्ट है,¹ तथापि गांधी जी ने जनवरी मास में ही बोमन जी को अपनी प्रसिद्ध 11 शर्तें बता दी थी और बोमन जी ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से समझौता वार्ता करने की योजना रखी थी। गांधी जी की 11 शर्तें संक्षेप में इस प्रकार थी पूर्ण नशाबन्दी, भारतीय रुपये का मूल्य डेढ़ शिलिंग की अपेक्षा 1½ शि० निर्धारित करना, भू-राजस्व को 50% कम करना, नमक कर की समाप्ति, सैनिक व्यय में कम से कम 50% की कमी करना, उच्च अधिकारियों के वेतन को आधा करना, विदेशी कपड़े पर रक्षात्मक प्रशुल्क लगाना, समुद्र तटीय प्रशुल्क सुरक्षा विधेयक को पारित करना, अहिंसात्मक ढंग से कार्य करने वाले समस्त राजनीतिक बन्धियों को मुक्त करना, गुप्तचर पुलिस का अन्त करना या उसे जन-नियन्त्रण के अन्तर्गत रखना, तथा जन-नियन्त्रण के अन्तर्गत आत्मरक्षा हेतु बन्दूकों को रखने के लाइसेंस प्रदान करना।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र—सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने से पूर्व केन्द्रीय व्यवस्थापिका के बजट अधिवेशन में सरकार की वित्तीय नीति के विरोध में पण्डित मदनमोहन मालवीय, दीवान चमनलाल आदि अनेक नेताओं ने त्याग-पत्र दे दिया था। यद्यपि इनका सम्बन्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ नहीं था, तथापि कांग्रेस के घोषित आदेशों के अन्तर्गत फरवरी 1930 में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के 172 सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिये थे। कांग्रेस ने अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का अनुरोध जारी रखा। इस प्रकार अवज्ञा आन्दोलन के पूर्व असहयोग का वातावरण बन चुका था। दूसरी ओर सरकार भी दमन की नीति पर दृढ़ होती जा रही थी।

गांधी जी का वाइसराय को पत्र—इन सब परिस्थितियों के सन्दर्भ में गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को स्पष्ट शब्दों में तथा निर्भय होकर जो पत्र वाइसराय लार्ड इरविन को लिखा था वह वास्तव में राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण प्रलेख है। इस पत्र में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक अभिशाप बताया, परन्तु अंग्रेजों को अपना मित्र कहा। 1930 में आयोजित गोल मेज सम्मेलन के उद्देश्य की भी उन्होंने भर्त्सना की, क्योंकि वाइसराय उसके अन्तिम परिणामों के बारे में कोई भी आश्वासन देने में असमर्थ रहे थे। भारत में ब्रिटिश शासन नीति की समस्त बुराइयों का स्पष्टीकरण करते हुए गांधी जी ने तथ्यों द्वारा वाइसराय को बताया कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक शोषण कर रही है। उन्होंने सरकार की कर-नीति, उद्योग तथा वाणिज्य की नीति, प्रशासन में अत्यधिक व्ययशीलता, सेना में अत्यधिक व्यय, भारत की जनता को राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों से वंचित रखने तथा हर प्रकार में उन्हें दासता की स्थिति में बनाये रखने की प्रवृत्ति और न्यायोचित मांगों के लिए किये जाने वाले अहिंसात्मक तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों पर दमन की नीति अपनाने की नीतियों का पर्दाफाश किया, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि वाइसराय को ब्रिटिश

¹ इस पत्र का सारांश मात्र आगे दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री की तुलना में लगभग चौगुना वतन मिलता है जिसका भार निधन भारतीय जनता को उठाना पड़ता है और उस पर कर भार बढाया जाता है। इसी प्रकार सार प्रशासन का व्यय बढाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एस गासन को भारत में विद्यमान रहने का कोई नतिक तथा वापसित अधिकार नहीं है। भारतवासियों के इन कष्टों का निवारण तभी हो सकता है जबकि उन्हें स्वयं अपना सामा करने का अधिकार प्राप्त हो जाये। ब्रिटिश सरकार इस दिशा में कोई ईमानदार कदम उठाने का प्रस्तुत नहीं है। अतः जनता के पास अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा करके अपने इन पवित्र अधिकारों का प्राप्त करने का अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। गांधी जी ने इस हेतु 11 मार्च 1930 तक की तिथि वात्सराय को विचार करने के लिए दी और लिखा कि यदि वह अब भी समस्या पर उनसे विचार विनिमय करने का अच्छा रखे तो पत्र प्राप्त करते ही तार द्वारा उन्हें सूचित करे। इस स्थिति में वे (गांधी जी) सविनय अवज्ञा के अपने प्रस्तावित आंदोलन को स्वर्गित कर सकते हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो 12 मार्च को वे नमक कानून तोड़कर अपने अभियान का प्रारम्भ कर देंगे।

ऐतिहासिक डांडी यात्रा का प्रस्ताव—जसी कि आत्मा श्री वात्सराय ने इस पत्र का तुरन्त उत्तर तो दिया परंतु गांधी जी की स्पष्ट घोषणा के बावजूद वात्सराय ने यह कहा कि जिस मांग का अनुसरण गांधी जी कर रहे हैं उससे निश्चय ही अति व्यवस्था तथा कानून का उल्लंघन करने में हिंसा का तत्त्व आ जायेगा। इस उत्तर में गांधी जी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं रोनी मांग रहा था उत्तर में मुझे पत्थर मिला है। ऐसी स्थिति में गांधी जी का अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करने से प्रारम्भ होता था अवश्यभावी हो गया। 12 मार्च को गांधी जी ने सावरमली आश्रम से डांडी तक 200 मील की पद यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। उनका साथ आश्रम के अहिंसा में प्रशिक्षित गिप्स दत्त। डांडी जाकर पहले स्वयं गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन करने के प्रतीक रूप में नमक खेनात और बिना कर दिए उस जनता को प्रयाण के हेतु वितरित करते। उसके पश्चात् तब उनके अनुयायी सविनय अवज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य कार्य-कलाप करते। इसकी सूचना वात्सराय का पत्र ही दे दी गई थी। अतः 12 मार्च को इस अभियान का आरम्भ निश्चित हो गया। गांधी जी के पूर्व खयाल को देखते हुए यह भी निश्चित हो गया कि वात्सराय गांधी जी द्वारा रखी गई सब समस्याओं पर विचार विनिमय करने के प्रस्ताव को स्वाकार नहीं करेगा और अन्तर्गत सविनय अवज्ञा आन्दोलन अवश्य आरम्भ करना पड़ेगा।

गांधी जी द्वारा सत्याग्रहियों को चेतावनी—जहाँ एक ओर गांधी जी ने वात्सराय का ऐसी चेतावनी दी और सोच विचार करने का अंतिम क्षण में एक और अवसर दिया वहाँ उन्होंने स्वयंसेवकों को बाल दण्डियों का भी अहिंसा के माध्यम का अनुसरण करने तथा पूजनमा अनुसरण रहने और समय से कार्य करने का आह्वान किया। प्रत्येक सत्याग्रही का यह शपथ रही थी कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेना चाहता है वह सभी शान्तिपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण तरीके से भारत के लिए कांग्रेस द्वारा निर्धारित पूरे स्वराज्य की प्राप्ति के सिद्धान्त को अपनाता है। इस अभियान में वह जन या अन्य किसी प्रकार के दण्ड को सहन करने के लिए तैयार है यदि वह जान गया तो उस अवधि में अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक गृहायना की कांग्रेस में माँग नहीं करेगा और वह पूर्णरूपेण उन नेताओं की आज्ञा का पालन करेगा जिनके ऊपर आन्दोलन का भार सौंपा गया है।

आन्दोलन का प्रारम्भ (डांडी यात्रा)

पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सविनय अवज्ञा का आगमन स्वयं गांधी जी के द्वारा डांडा नामक स्थान पर समुद्र तट से बिना कर न्यून नमक उठाकर किया जाता था। अतः सावर मनी आश्रम से डांडा तक की लगभग 240 मील की पदयात्रा में गांधी जी ने 12 मार्च की प्रातः

काल को अपने 78 प्रशिक्षित साथियों के साथ प्रस्थान किया। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। प्रातः काल जब गांधी जी के साथ सत्याग्रहियों का दल प्रस्थान करने लगा तो अहमदाबाद की सारी गलियाँ हजारों दर्शकों की भीड़ से भर गई। 'गांधी जी की जय' के शब्द घोष से आकाश गूँज उठा। जनता में अतीव श्रद्धा, उत्साह तथा ओज था। लेखकों ने इस यात्रा को रामचन्द्र जी की लका पर चढ़ाई करने की यात्रा से तुलना की है, जो वास्तविक है। गांधी जी का दल मार्ग में जिन ग्रामों से होकर गुजरा, सब जगह नर-नारी भारी हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत करने लगे। गांधी जी सबको यही उपदेश देते गए कि कहीं पर भी अनुशासनहीनता तथा हिंसा नहीं होनी चाहिए। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपने पदों से त्याग-पत्र दे दिये। जिन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिये उनका बहिष्कार किये जाने की योजना रखी गई। परन्तु गांधी जी ने चेतावनी दी कि इस कार्य में तनिक भी हिंसा न आने पाये। सामाजिक बहिष्कार का क्षेत्र केवल उनके पद से सम्बद्ध कार्यों तक सीमित रहे। अन्यत्र ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रवत् व्यवहार बना रहे। मार्ग में कहीं पर भी सत्याग्रही दल के व्यक्तियों के लिए इससे अधिक सुख-सुविधा की व्यवस्था न की जाय जितनी कि भारत के एक साधारण व्यक्ति को प्राप्त होती है। 24 दिन की पैदल यात्रा पूरी करके दल अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा। 6 अप्रैल की प्रातः काल की वेला में गांधी जी ने अपने साथियों सहित अपना सविनय अवज्ञा का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर बिना कर दिये उसे लोगों में बाँटा। सत्याग्रह दल के साथ अनेक पत्रकार, चित्र लेने वाले तथा फिल्म-निर्माता भी थे। सारा विश्व भारत के इस महान् दृश्य को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। कुछ विदेशी पत्रकारों का मत था कि भारत में स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में महान् क्रान्ति हो चुकी है, ज्यों ही गांधी जी के सफल अभियान की सूचना देश में फैली, त्यों ही हजारों लोगों ने डांडी को प्रस्थान किया। शेष उनके आदेशों के अनुसार आन्दोलन के अन्य कार्यक्रमों को सम्पन्न करने की बाट देख रहे थे।

गांधी जी के आदेशानुसार देश-भर में प्रत्येक सत्याग्रही को नमक कानून का उल्लंघन करना था। नमक तैयार करना, उसे स्वतन्त्रतापूर्वक बिना कर चुकाये बेचना या लोगों में वितरित करना इस अभियान के अंग थे। गांधी जी को पूरा विश्वास था कि सरकार ऐसे सत्याग्रहियों का दमन करने में पुलिस का सहारा लेगी। परन्तु सत्याग्रहियों को गांधी जी के कठोर आदेश थे कि कहीं पर भी हिंसा का अवलम्बन न किया जाये। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी माल एवं विशेषकर कपड़े का बहिष्कार तथा खादी का प्रयोग, सरकारी पदों से त्याग-पत्र देना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, शराब की दूकानों पर धरना देना (इस कार्य में गांधी जी ने महिलाओं के विशेष योगदान पर जोर दिया था), घर पर चरखे का प्रयोग छुआछूत का विरोध, साम्प्रदायिक सद्व्यवहार, आदि रचनात्मक कार्य शामिल थे।

सभी को विश्वास था कि नमक कानून तोड़ते ही गांधी जी को बन्दी बना लिया जायेगा। परन्तु सरकार को ऐसा खतरा मोल लेने का साहस नहीं हुआ। जब अवज्ञा आन्दोलन की लहर सारे देश में फैल गई, तो अन्यत्र सरकार का दमन शुरू हुआ। ऐसा अनुमान है कि लगभग एक लाख की सत्याग्रहियों को बन्दी बना लिये गये थे और सरकारी जेलों में स्थानाभाव हो जाने के कारण सरकार को बन्दीयों के लिए अन्य इमारतों की व्यवस्था करनी पड़ी। स्थान-स्थान पर शान्तिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने वालों के ऊपर पुलिस ने लाठी प्रहार, गोली चलाने आदि हिंसात्मक कार्यों की भी कमी नहीं की। गांधी जी को सारी सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। उन्होंने सरकार की दमनकारी नीति की भर्त्सना करते हुए वाइसराय को पुनः पत्र लिखा। परन्तु सरकार ने परवाह नहीं की, प्रेम पर प्रतिवन्द्य और कड़ा कर दिया गया। मिनेमा गृहों को कटे आदेश दिये गये कि वे गांधी जी की टाटी यात्रा के फिल्मों का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। संक्षेप

प्रथम गोल मेज सम्मेलन

सम्मेलन की पृष्ठभूमि—जैसा पहले कहा जा चुका है, भारत की साविधानिक सुधारों की समस्या प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद तीव्र गति से जटिल होती जा रही थी, साटफोर्ड सुधारों ने इसे और अधिक जटिल बना दिया था। 1924 में स्वराज्य दल ने केन्द्रीय विधानसभा में साविधानिक समस्या के हल के लिए गोल मेज सम्मेलन बुलाने की माँग का प्रस्ताव पास किया था। परन्तु 1920 से 1930 की अवधि में ब्रिटेन के उदार तथा अनुदार दलीय नेता, भारत मन्त्री एव वाइसराय, सभी ने वास्तविकताओं की उपेक्षा की और साटफोर्ड योजना में प्राविधित 10 वर्ष तक कोई नया कदम न उठाने की नीति पर अड़े रहे। उन्होंने न तो विश्व में हो रहे विकासों के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर ध्यान दिया और न स्वयं भारत में विकसित हो रही राजनीतिक जागृति की परवाह की। वे अपने साम्राज्यवादी स्वप्नों को ही दमनकारी तथा बल प्रवर्ती साधनों द्वारा साकार करने में व्यस्त रहे। परन्तु समय की माँग ने उन्हें साइमन कमीशन को निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व नियुक्त करने को विवश किया, तो उसके सम्बन्ध में जो नीति अपनायी वह भी उनके शरारतपूर्ण रवैये की ही द्योतक सिद्ध हुई जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों को हट करने का ही श्रेय प्राप्त किया। वाइसराय लार्ड इरविन जो भारत की वास्तविक स्थिति के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क में था, अब वास्तविकता को कुछ समझने लगा था। परन्तु इंग्लैंड में सत्ताधारी नेता तथा विरोधी दलों के नेता उससे सहमत नहीं होते थे। भारत में स्वायत्त शासन की माँग निरन्तर प्रत्येक वर्ग की ओर से बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में लार्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व ही 31 अक्टूबर 1929 को यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक ढंग के स्वशासन की स्थापना करने तथा भावी संविधान के मसविदे पर विचार करने के लिए गोल मेज सम्मेलन बुलाने का है।

इधर साइमन कमीशन की प्रतिद्वन्द्वी नेहरू समिति की रिपोर्ट निकल चुकी थी जिसका भारतीय जनमत ने पर्याप्त स्वागत किया था, भले ही मुस्लिम लीग इससे हट हो गयी थी। परन्तु साइमन कमीशन की रिपोर्ट की तुलना में यह मुस्लिम हितों के लिए अधिक उपयुक्त थी। लीग ने कमीशन की रिपोर्ट को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि उसमें औपनिवेशिक स्थिति का उल्लेख तक नहीं था। लीग इससे कम किसी शर्त को मानने को राजी न थी। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि कांग्रेस अब औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना चुकी थी और शासकों के राष्ट्रीय माँगों के विरुद्ध हठीले तथा उपेक्षापूर्ण रुख के कारण सविनय अवज्ञा आन्दोलन भीषण रूप धारण कर चुका था। यद्यपि सरकार ने इस शान्तिपूर्ण आन्दोलन को कुचलने में दमन का कोई साधन शेष नहीं छोड़ा था, तथापि अब वाइसराय भी बहुत परेशानी अनुभव करने लगा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जहाँ भारतवासियों को सर्वथा अमान्य थी, वहाँ इरविन ने भी अनुभव किया कि यह भारत की वास्तविकताओं से दूर होने के कारण निरर्थक थी। अतः इरविन ने गृह सरकार के अधिकारियों के समक्ष गोल मेज सम्मेलन बुलाने का आग्रह किया, ताकि इसके कारण भारत का वातावरण कुछ शान्त किया जा सके। परन्तु उस समय इंग्लैंड स्थित मजदूर सरकार इतनी निर्बल थी कि प्रधानमन्त्री तथा भारत मन्त्री दोनों बिना विरोधी दलों से परामर्श किये कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। परन्तु उदार तथा अनुदारदलीय नेता ऐसे सम्मेलन के पक्ष में नहीं थे। इस पर इरविन ने त्याग-पत्र की धमकी दी। अन्ततः ब्रिटेन के नेताओं को इसे स्वीकार करना पड़ा।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि गोल मेज सम्मेलन की घोषणा भारतीय समस्या का समाधान मिट्टी होती। वास्तविकता यह थी कि स्वयं वाइसराय भारतीय जनमत को अवज्ञा आन्दोलन से विमुख करने का जम्हारी उपचार ढूँढ रहा था। उसे यह स्पष्ट ज्ञात था कि

एमा गाँव मज सम्मनन जा भाग्यीय राजनाति क विभिन्न वगा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता काग्रम क प्रतिनिधित्व क अभाव म निश्चयक हा हागा । यदि काग्रम को सम्य गामिन हात का कहा जाता ता वात्सराय का काग्रम की भाग न सामन भुक्ता पन्ता । इसके लिए त्रिनिग्द सरकार तयार नहा थी । जत काग्रम क प्रतिनिधित्व का प्रश्न हा नती था जाकि सम समय उग्र रूप म आ । नन म उतभी ह् था और उमक सभी प्रमुख नेता जना म थ ।

वात्सराय क समक्ष सम्मनन क निमित्त भारत क विभिन्न वगा क प्रतिनिधिया क चयन तथा सम्मनन म वात् विवात् क मुख्य विषया क आधारभूत सिद्धान्त का निर्धारण करने का समस्या थी । प्रथम क निमित्त काग्रम क अभाव म उमन मप्र तथा जयकर का छाँटा । लोग त्रि महासभा मिक्क र्माई अनुसूचिन जात्रिया एगो शिष्यन बर्मी लगी नरगा जमातगा आति क प्रतिनिधिया का भी छाँटा गया । तन्तु म 8 मज्जर दन क 4 उत्तर तन क 4 अनुतर तन क प्रतिनिधि निये गये । भाग्यीय राष्ट्रवादी प्रतिनिधिया म एस यन्त्रिया को दन की सावधानी बरती गया जा उदार समझौतापरस्त तथा वन्पिफार विरोधा हा । सम प्रकार कुन 89 प्रतिनिधि सम गाँव मज सम्मनन न लिए चुन गये । मुख्य विचारणीय विषय थ— (1) औपनिवर्गिक स्थिति की मायता (2) मात्मन कमीशन की रिपोर्ट का अंतिम गान न मानता । त्रिनिग्द अधिकागिया क साथ दम्पी परामर्शाना तथा विचार विनिमय कर नन क उपरान्त स्वयं वात्सराय न सम्मनन की घोषणा 9 जुलाई 1930 को कानीय व्यवस्थापिका म का और 12 नवम्बर 1930 सम्मनन की तिथि घोषित की गयी ।

निर्धारित नियि को सम्मनन आयोजित किया गया । मप्र तथा जयकर तन्तु जान म पर नहल् तथा गाँव जा म जना म मित । काग्रम नेताआ न स्पष्टन उता दिया कि काग्रम पण स्वराय म कम सिमा माँग म सहमत नन लगी । निम्नह् काग्रम क प्रतिनिधित्व क अभाव म एत सम्मनन एत लोग ली था कशकि तन की भावी साविधानिक समस्या पर काग्रम क अभाव म उपयन तन का प्रतिनिधित्व निरवक ली माना जा सकता है ।

वर्कें—12 नवम्बर 1930 स प्रथम गाँव मज सम्मनन का वरक प्रारम्भ त् । सम 57 प्रतिनिधि भारत क 16 दली गियासता क तथा 13 यकि तन्तु क विभिन्न राजनातिक दता क प्रवक्ताआ क रूप म गामिन थ । इसकी वर्कें समय समय पर हाता रहा । सम्मनन म औपनिवर्गिक स्वराय की माँग उग्रमग सभी न रही । तगा नरणा क प्रतिनिधि सघामन व्यवस्था क समर्थक थ । त्रिनिग्द प्रधानमन्त्री का मन था कि प्रस्तावित सविधान का व्यवहृत नियि जाने योग्य तथा विरामणीत प्रवृत्ति का हाता चाहिए । वात् म अनक उममितिषाँ यथा प्रनिग्दशा मताधिकार सघाना अपनव्यर । ताक सवाला प्राणीय विषया जाकि न सम्मनन म रिपोर्ट नन क रिपोर्ट निम्न त् 11 दनर 1931 क सघाना सघमनन क अतिरिक्त दूज निम्न दन सम्मनन किया गया कि जा रिपोर्ट तथा विचार व्यक्त निये गये हैं क सविधान निर्माण क तन्तु प्रचुर सामग्री प्रदान करत है और एत काय जागा रन्ता चाहिए ।

भावी साविधानिक व्यवस्था क अन्तगन भारत का राजनातिक स्थितिक सम्बन्ध म सम्मनन क अधिकाग सम्य औपनिवर्गिक स्थिति म मन्तु थ । व यह भूत गये कि काग्रम जा कि तबमात्र दन का जनता की प्रतिनिधि सम्म है और जा जनता का पण समर्थन नन तन तन का पण स्यनप्रता की माँग पर नती ह् है और जिनम औपनिवर्गिक स्थिति की माँग का टुंग रिपोर्ट है व किम प्रकार सम प्रस्ताव म राजा हा जायगा ? कश तगा एत म सम्मनन का सफलता प्राप्त हा जायगा ? एतनु आन्वय की गन यत् है कि त्रिनिग्द प्रधानमन्त्री ता सम्य भा एक कटम और नीर त् । उताय घोषणा की रि मध्यव्यवस्था क अन्तगन ता सरकार बनगा वह मघाय व्यवस्थापिका क ला गन्ता क प्रति उमरगाया जागा । एतनु साथ न य रिपोर्ट सम्बन्ध तथा प्रनिग्दशा क निमित्त साधारणतया न अधिकाग का मूर्तिगत गनता पन्ता और स्वतन्त्र जनरन का गान्य का गानि तथा रिताय स्थितता न निमित्त कुन विषय साविक मौन पन्ने । गान्ता म

यह बात अवश्य थी कि ऐसे रक्षा-कवच केवल अन्तरिम काल के लिए होंगे और कालान्तर में भारतवासियों को अपने लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन-व्यवस्था स्थापित रखने का अवसर दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सत्याग्रहियों के साथ वाइसराय की समझौता-वार्ता चल रही है ताकि उनका सहयोग भी प्राप्त किया जा सके।

प्रथम गोल मेज सम्मेलन की आलोचना—जिन उद्देश्यों से निदेशित होकर तथा जिस प्रकार गोल मेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों को चुना गया था। उससे स्पष्ट था कि सम्मेलन निरर्थक सिद्ध होगा। दिखाने के लिए सम्मेलन को भारत की भावी साविधानिक संरचना पर विचार विनिमय करना था, परन्तु जिन विविधतापूर्ण निहित स्वार्थों से युक्त व्यक्तियों का चयन इसके लिए किया गया था वे अपने व्यक्तिगत या वर्गगत हितों तथा प्रतिक्रियावादी विचारों को रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते थे। समस्या थी एकता की परन्तु उसके समाधान के निमित्त पृथक्तावादी तत्त्वों का साधन अपनाया गया था। कूपलैण्ड ने उचित ही कहा है कि 'अब यह कहना चाहिए कि लन्दन के पट में उनकी आँखों के समक्ष भारत की समस्या का सम्पूर्ण जाल जीवित किया गया। परन्तु वह वास्तव में पूर्ण नहीं था। इस समूह में एक बड़ी खाई थी। भारतीय राजनीति के सबसे विनाश तथा शक्तिशाली सङ्गठन का, जो कि भारत के युवा वर्ग को सर्वाधिक लोकप्रिय था। इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। कांग्रेस का व्यवहार अभी भी पूर्णतया शत्रुतापूर्ण था।¹ कांग्रेस ही वास्तव में ऐसा सङ्गठन था जिसे भारतीय राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि कहा जा सकता है, उसके अभाव में शेष वर्गों के प्रतिनिधियों से यह आशा करना भ्रामक था कि वे भारत की स्वायत्त शासन की माँग को महत्त्व देते। उन्हें तो अपने विशेष हितों के संरक्षण की चिन्ता मात्र थी। मुसलमानों के प्रतिनिधियों का चयन भी प्रतिक्रियावादी वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य फजलीहुसैन की सलाह से किया गया था। अतः कोई भी राष्ट्रवादी मुसलमान उसमें नहीं छाँटा गया था।

जहाँ तक सम्मेलन की कार्यवाहियों तथा निर्णयों का सम्बन्ध है, ऐसे सम्मेलन से कोई सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं थी। मूल प्रश्न थे भारत को औपनिवेशिक स्थिति के स्वायत्त शासन का प्रदान किया जाना, भारत की सघातक या एकात्मक संरचना का निर्धारण तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों (विशेष रूप से मुसलमानों) के हितों का संरक्षण। औपनिवेशिक स्थिति की धारणा ब्रिटिश नेताओं ने भ्रामक बनाकर समाप्त कर दी। वे केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन देने के पक्ष में नहीं थे। संघवाद के बारे में सभी सहमत थे। परन्तु संघ की संरचना के बारे में अनेक मतभेद बने रहे। देशी नरेश भी संघ के बारे में सहमत थे, परन्तु इन सब प्रस्तावों के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या मुस्लिम साम्प्रदायिकता की थी। इसके सम्बन्ध में यदि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा स्थान सुरक्षित रखने की बात मान ली जाती तो समस्या सुलभ सकती थी। परन्तु कट्टरपंथी साम्प्रदायिक तत्त्वों ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया। मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादियों को ऐसी संघ व्यवस्था जिसमें देशी नरेश शामिल हों अमान्य थी। उन्हें यह भय था कि देशी रियासतें हिन्दुओं के बहुमत वाली होने से संघ सरकार में मुसलमानों के स्थानों की संख्या कम हो जायेगी। परोक्ष में वे पृथक् स्वतन्त्र मुस्लिम भारत की कामना करते थे। मु० इकवाल तो पृथक् मुस्लिम राज्य की धारणा व्यक्त करने में लगे थे और वे मुस्लिम बहुल जनता वाले प्रान्तों के संघ में शामिल होने के विरोधी थे। इस प्रकार प्रथम गोल मेज सम्मेलन साम्प्रदायिक मतभेदों के जाल में फँसा रहा और कोई ठोस निर्णय लेने में असफल रहा। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के अभाव में इसकी सफलता की आशा करना मृग मरीचिका के तुल्य थी।

¹ Coupland, *The Indian Problem*, Part I, 113

भारत में प्रतिक्रिया

काग्रस काय समिति का प्रस्ताव—21 जनवरी 1931 का राजन प्रस्ताव के मभावित्व में काग्रस काय समिति का बैठक आगगाद में हुई। काय समिति के प्रमुख नेताओं का अनुपस्थिति में जाति जनामथ काय समिति ने ब्रिटिश सरकार के स्वयं की भूमिका करने का कया कि जय का म सरकार गतिपूण का म सत्याग्रह करने का का जनाम ठस रही है उन पर नाटी चाज गानी चवान तथा जय प्रकार के जत्याचारपूण कृत्य किये जा रहे है ता एम अवसर पर था म निहित स्वार्थी तत्वा का आमश्रित करक तथाकथित गान मज सम्भवन के जायाजन म कायम का का म मध्य नहा है। ब्रिटिश गामन नाति की जा घोषणा प्रधानमन्त्री के का की गया है व म तनी अस्पष्ट है कि उमर द्वारा काग्रस अपनी नीति में परिवर्तन करना उचित नहा समझती हन परिस्थिति का म काय समिति सविनय आदान का स्थगित करने का जान नहा मात्र मकती प्रत्युत व म वासिया म मघष को तीव्रतर बनान की माग करती है। काग्रस उन समस्त सत्याग्रहियों का ध्येय तथा वर्धा दनी है जिहान मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए गतिपूण तथा अनुगमित का म सत्याग्रह किया है और ब्रिटिश सरकार के जत्याचार पूण तम का खुली स म है या प्राणा का म म कर चुक है। काय समिति के अनुमान में 75000 यति जनामथ है।¹ जन म कायकारिणी न कावासिया में 26 जनवरी 1931 को पववत् और अधि उस्माह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनान का आह्वान किया।

काय समिति का प्रस्ताव समाचार-पत्रों के प्रकाशनाथ दिया जाय या नहा इस बात पर वाद विवाद था कि दूसरे ही दिन काग्रस में सप्र जयकर तथा गांधी जी का तार मिला कि काय समिति तक भारत पहुँचने में पूर्व प्रधानमन्त्री की घोषणा पर कार्य निणय न न। अन उक्त निणय का प्रकाशित करने में रोक दिया गया।

काय समिति के सदस्यों की रिहाई—25 जनवरी का वात्सराय नाड त्रविन न एक वक्तव्य दिया जिसमें ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की 19 जनवरी 1931 की घोषणा के सद्भ म यह घोषणा की गई कि भारत सरकार काग्रस काय समिति के 1 जनवरी 1930 में आज तक के मन्त्रियों का स्वतंत्र रूप में का राजनानिक समस्या पर विचार करने का अवसर देना चाहता है। इस उद्देश्य से काय समिति के उक्त मन्त्रियों के उपर लगाय गय मभा प्रतिग्रह जिनमें कारावास दण्ड भां शामिल था हटा दिया जायग। यह मुक्ति गतहीन है हमका उद्देश्य प्रधानमन्त्री की घोषणा का साकार करने के लिए वातावरण बनान का है। वात्सराय की इस घोषणा का कार्याविधि के रूप में 26 जनवरी 1931 का महात्मा गांधी सहित काग्रस काय समिति के 19 सदस्य जनामथ मिला कर दिया गया। 9 जय यति वात्सल म गिरा कर दिया गया।

आधा इंग्लिश ममभाना

जन म मुन हान ही कायकार समिति के समस्त मन्त्र्य आगगाद पहुँच जहाँ पण्डित मातीरान नेहरू तगभग मृयु गय्या पर थ। गांधी जी ने गण्ट के नाम एक मन्त्र्य दिया कि जिसमें उहान सविनय अवका आन्तान सरकार के दमन चक्र तथा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की का के सन्ध म स 19 म भावा कायक्रम के धार में बनाया कि वह जन म एक स्वच्छ मन्त्रिण तथा हय सकर बाहर आय हैं और ममम्या का हम बीच पटी घटनाओं के परिपत्र में अध्ययन करेंगे तथा अन माधिया एक मन्त्र्य म आन थान माधिया म वातावरण करक भावी कायक्रम तयार करेंगे। इनाहावात पहुँचने पर काय समिति के सभी मन्त्र्य प भावाजन के स्वागत के धार में चिन्तित हा गय। 7 फरवरी 1931 का दिन के हित में मय कुछ घोषावर करक मातृभूमि की निरन्तर सेवा करने रहने के उपरान्त व हन का का कहने हुए कि अब म अपना अन्तिम ना

लेता हूँ, परन्तु मेरी यही इच्छा है कि मैं एक पराधीन देश में नहीं, अपितु स्वतन्त्र देश में इस चिर-निद्रा का काल विताऊँ, ससार से विदा हो गये। मोतीलाल जी की अन्तिम इच्छा के अनुसार भारत के भविष्य का निर्धारण स्वराज्य भवन इलाहाबाद में किया जाना था। उनकी मृत्यु से सारा राष्ट्र शोकाकुल हो गया। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि उस समय वे अपनी स्थिति एक विधवा के तुल्य समझ रहे हैं। इसी बीच सप्रू, शाम्भू, जयकर आदि नेता भारत पहुँचते ही सीधे इलाहाबाद गए और गांधी जी तथा अन्य नेताओं से मिले। यह तय किया गया कि अब सरकार के साथ वार्ता का कार्यक्रम बनाया जाय। 14 फरवरी को गांधी जी ने वाइसराय को पत्र लिखा और 16 फरवरी को तार द्वारा वाइसराय का उत्तर मिला। तुरन्त गांधी जी तथा अन्य नेताओं ने दिल्ली को प्रस्थान किया। गांधी-इरविन वार्ता का प्रथम दौर 17 फरवरी को प्रारम्भ हुआ।

प्रथम तीन दिनों की वार्ता में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन म्यगित करने के सम्बन्ध में सत्याग्रहियों की विना शर्त रिहाई, छीनी गयी सम्पत्ति की वापसी, त्यागपत्र देने वाले सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, पुलिस के अत्याचारों की जाँच, धरना देने के अधिकार, नमक कानून की समाप्ति तथा आन्दोलन दवाने के सम्बन्ध में जारी किये गये अध्यादेशों की वापसी, आदि पर जोर दिया ताकि इसके परिणामस्वरूप वार्ता का वातावरण तैयार हो सके। इनमें से कई शर्तें ऐसी थीं जिनके सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए सरकार को समय चाहिए था। वाइसराय ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कुछ निर्देश चाहे थे। उनके पहुँचने में समय लगा। अतः 27 फरवरी से पुनः वार्ता प्रारम्भ हुई और 4 मार्च तक चली। नित्य गांधी जी वार्ता के पश्चात् जब वापिस आते थे तो डा० अन्सारी के मकान में कार्यकारिणी के सदस्य उनकी प्रतीक्षा में रहते थे और रात को लम्बे समय तक समिति उन पर विचार करती थी। गांधी जी ने वाइसराय को स्पष्ट कर दिया था कि वह जो भी वाते करते हैं या निर्णय लेते हैं उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कांग्रेस कार्यकारी समिति करेगी। स्वभावतः विभिन्न समस्याओं पर मतभेद होना अस्वाभाविक नहीं था। यह भी सम्भव नहीं था कि जो भी माँग गांधी जी की ओर से रखी जाय उसे वाइसराय मान लेगा या जो भी वह कहे उसे कांग्रेस मान लेगी। 5 मार्च 1931 को समझौता वार्ता को अन्तिम रूप दिया गया और 5 मार्च को ही वह प्रकाशित कर दी गयी। यह वह तिथि थी जिस दिन एक वर्ष पूर्व गांधी जी ने वाइसराय को सविनय अवज्ञा आन्दोलन की घोषणा का पत्र दिया था।

गांधी-इरविन समझौते की शर्तें—‘सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त किया जाय तथा सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करे साविधानिक सुधारों के सम्बन्ध में सही सिद्धान्त तथा प्रतिरक्षा, विदेशी मालों, अल्पसंख्यकों, भारत की वित्तीय व्यवस्था आदि के बारे में कुछ रक्षा-कवचों की अपरिहार्यता को जैसा कि गोल मेज परिषद् में स्वीकार किया गया था अनुसमर्थित किया गया, प्रधानमंत्री की घोषणा से अनुसार कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी साविधानिक सुधार योजना पर आगे विचार करने के लिए गोल मेज सम्मेलन में आमन्त्रित किये जाने पर निर्णय हुआ, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सत्याग्रही कानून उल्लंघन, कर न देने, आन्दोलन का प्रचार करने तथा नागरिक एवं सैनिक सेवा के कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करने के कार्यकलाप नहीं करेंगे, भारतीय माल के उपयोग का प्रचार करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु ब्रिटिश माल के बहिष्कार करने का प्रचार समझौता वार्ता के हित में नहीं है, विदेशी माल तथा शराब विरोधी धरने सामान्य कानून के अन्तर्गत ही किये जा सकेंगे, आन्दोलन की अवधि में पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध सार्वजनिक जाँच को शान्ति स्थापना के हित में उचित न समझते हुए गांधी जी उस पर जोर न देने को राजी हो गये, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विरुद्ध जारी किये गये अध्यादेशों को सरकार वापिस ले लेगी, इस आन्दोलन के मध्य कांग्रेस तथा अन्य जिन मगठनों को अवैध घोषित करने के अध्यादेश जारी किये गये थे उन्हें सरकार वापिस ले लेगी, आन्दोलन में बन्दी किये गए जिन व्यक्तियों के ऊपर अभियोग नहीं चलाये जा सके ह

उह वापिस न लिया जाएगा परन्तु उसम मना तथा पुनिस क कमचारिया क ऊपर अभियाग गामिन नही ह । मविद्य जवना आन्दान क फत्स्वरूप अहिमात्मक कृत्या के लिए कारावास की मजा प्राप्त की गिहा कर लिए आयग ना जय न्ह वसून नहा किय गण ह उह राव निया जाएगा परन्तु वसून हो गए दण्ड तथा जत हा गयी जमानत वापिस नही का जायगी जनता क यय पर नियुक्त अतिरिक्त पुनिस हटा नी जाएगा आन्दान क मध्य किसी व्यक्ति म जवन की गयी जवन सम्पत्ति जा सरकार क पास सुरक्षित ह सम्पत्ति पथ का वापिस कर दी जाएगी सरकार क पास सुरक्षित जवन सम्पत्ति भी वापिस कर दी जाएगी परन्तु उहा उस उम समय नामू अध्यापक क जतगत निजता लिया गया न वहा पर सरकार कुछ नहा कर सकगी परन्तु यदि कोई व्यक्ति यह समझ कि सम्पत्ति का निवन्तारा गर-वानूनी दण्ड से हुआ न वहा वायिक वाधवाहा कर सक्ता न सत्याग्रह म त्यागपत्र दन वान एम कमचारिया को पुन सेवा म न लिया जाएगा जितन रिक्त स्थाना पर म्याया नियुक्तिया नन की गयी है और नन मामना म सरकार उत्तर नीति अपनाएगी सरकार नमन कानून समाप्त करन की स्थिति म नहा है परन्तु एम स्थाना म जहा नमक बनाया या एकत्र किया जाता है वहा की जनता अपन घरेलू उपयोग क लिए हा यह सुविधा प्राप्त कर सकगा परन्तु व्यापार व्यवसाय क लिए नहा ।

गांधी सरविन पक्क 1931 की उपयुक्त प्रमुख बात उस बात क स्पष्ट प्रमाण है कि ननक अनुसार सरकार विसा भी वान पर वास्तविक रूप स नहा भुनी अपितु काग्रम का ही भुजना पडा । सविनय अवज्ञा आन्दान की प्रमुख गतों तथा उस अवधि म सत्याग्रहिया क ऊपर किय गण जत्याचार तथा उनन द्वारा मही गयी हानिया क बार म भी सरकार गांधी जी की गतों का पूणतया न मान सकी । साविधानि मुधारा क सम्प्रथम भी काग्रम का पूण स्वतन्त्रता की मांग औपनिवेशिक स्थिति की मांग म भी हानतर रखी गयी । जत समझौते का किसी भी रूप म भागन क लिए सन्तापजनक नहा कहा जा सकता । परन्तु उस पूणतया निम्सार तथा महत्त्वहीन भी नहा माना जा सकता । नमकी मजस नी विपत्ता यह है कि राष्ट्रीय आन्दान क इतिहास म सब प्रथम वात्सराय न काग्रम जथच भारत क एकमात्र मुमाय नना क माय मन्त्रीपूण दण्ड से मीहान तथा सभावनामय वातावरण म भारत की राजनीतिक समस्याओं पर विचार विनिमय किया । यह भेंट एक गामन तथा अधीन प्रजाजन क बीच की न हाकर दा राप्ता क प्रमुख प्रतिनिधिया क मध्य की वार्ता क रूप म मिट्टी न् । उसम गांधी ज्ञान जिम स्पष्टचान्ति सहयोग तथा माननारी का परिचय लिया उह नमर स्वच्छाचारा तथा निरकुतावाद का सर्वोत्तम प्रतीक भारतम वात्सराय भाजिन गया और वह गांधी जी की प्रशंसा करन म जरा भर भी न मकुचाया । दूसरी ओर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिया को न्यत हूण सहयोग तथा समझौते क माननारी ककु गांधी ज्ञान ने अपना व्यक्तिगत तथा वाग्रस क ननाश्र क । अनेक धारणाओं पर जनावयन नन म जार कर वाता न जमफन बनाता का नीति नहा अपनाया । अर प्रश्न यथा कि ब्रिटिश शासक प्रत्युत्तर ग कहीं तक उस समझौते पर माननारी म अग्रिम कायवाहा करग । 5 मार्च 1931 का समझौता गतों क प्रकाशन क पश्चात् गांधी ज्ञान एक भारतीय तथा विन्ता पत्रकार सम्मेलन म एक वक्तव्य देकर अपना स्थिति का व्यापक रूप स स्पष्ट किया । दूसरी ओर राड इरविन न पतिस प्रज्ञामक बग तथा ब्रान्तिचारिया म भा न्नी प्रकार की अपान की । दाना नताओं क वक्तव्य का अभिप्राय यथा था कि नन म गान्धिपूण वातावरण बनाया जाय ताकि भावा प्रगति का महा माग प्रशस्त न सक ।

राजका अधिपशन

भारत क राष्ट्रीय आन्दान तथा साविधानिक विराम क इतिहास म 1931 क बराधी अधिवेशन का अत्यधिक महत्व है । प्रथम बात ना यह है कि ताहीर अधिवेशन जिमम काग्रम न जना उद्देश्य पूण स्वतन्त्रता की प्राप्ति म्ना था क उपरान्त काग्रम ब्रिटिश सरकार क माय

सघर्ष की स्थिति में पहुँच गयी थी। 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कांग्रेस का रुख पूर्णतया क्रान्तिकारी रहा और बड़े-बड़े नेता जेलों में डाल दिये गये थे। गांधी-इरविन समझौते के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की जेल से रिहाई होने के ठीक एक माह बाद इस अधिवेशन का होना आवश्यक समझा गया ताकि सम्पूर्ण कांग्रेस उक्त समझौते तथा प्रधानमंत्री की घोषणा पर विचार करते हुए देश की निवर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपना भावी कार्यक्रम तथा नीति तय कर ले। अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों को छाँटने की भी समस्या थी। अनेक नेता अभी जेलों में ही थे। कुछ नया नेतृत्व प्रस्फुटित हो गया था, जिससे 1930 में आन्दोलन में महान् त्याग किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया था। परन्तु स्वयंसेवकों के द्वारा अत्यन्त नियन्त्रित, समयित एवं अनुशासित ढङ्ग से शराबबन्दी तथा ब्रिटिश व विदेशी कपड़े के बहिष्कार आन्दोलन में धरना देने के कार्यक्रम को नहीं छोड़ा था। विविध प्रकार के प्रदर्शनों को न करने की भी सलाह दी गयी थी। गांधी जी ने पुनः अहिंसा के सिद्धान्त पर चलने के सिद्धान्त को और अधिक कठोर बना दिया था।

इस अधिवेशन के लिए सरदार पटेल को अध्यक्ष चुना गया और यह निश्चित किया गया कि अधिवेशन खुले स्थल पर होगा। दर्शकों में से प्रत्येक को चार आना प्रवेश शुल्क देना था। लगभग 10000 रुपये इससे एकत्र हुआ। इस अधिवेशन के मध्य देश में दो घटनाएँ ऐसी घटीं जिनके कारण अधिवेशन का वातावरण विषादपूर्ण रहा। प्रथम घटना थी 23 मार्च 1931 को सरदार भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को मृत्युदण्ड दिया जाना। इनके ऊपर साण्डर्स हत्याकाण्ड का आरोप था। गांधी जी ने वाइसराय से इन नवयुवकों की मृत्युदण्ड की सजा को कम करने की माँग रखी थी, जिसे वाइसराय ने अपनी असमर्थता पर ठुकरा दिया। परन्तु ये वीर युवक स्वतन्त्रता संग्राम के अमर शहीद बन चुके हैं। दूसरी घटना थी अधिवेशन काल में कानपुर में साम्प्रदायिक दंगों के छिड़ने की, जिसमें मुसलमान अल्पसंख्यकों को बचाने के प्रयास में गणेशशंकर विद्यार्थी की हत्या कर दी गई थी। विद्यार्थी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा सद्भाव के महान् समर्थक थे। इसी कार्य में उनकी हत्या ने इन्हें भी अमर शहीद बना दिया है। कराची कांग्रेस में इन दो घटनाओं ने शोक का वातावरण बना दिया था।

इस अधिवेशन में अधिकांश प्रस्ताव आन्दोलन की अवधि में सक्रिय सहयोग देने वालों की वहाँ देने, उसमें शहीद हुए व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने (जिसमें पं० मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे) तथा कष्ट भोग रहे कार्यकर्त्ताओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के सम्बन्ध में थे। अन्य प्रस्तावों में कुछ गांधी-इरविन समझौते की शर्तों को सरकार द्वारा ईमानदारी के साथ पालन करने के सम्बन्ध में थे, यथा बन्दीयों की रिहाई, करो की माफी आदि। सांविधानिक समस्या पर विचार करने के हेतु प्रस्तावित द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावित किया। साथ ही कार्य समिति को अन्य प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दे दिया।

इस कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश के भावी संविधान में मूल अधिकारों का समावेश करने के सम्बन्ध में था। यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक इन्हें उपेक्षित ही रखा गया, तथापि स्वतन्त्र भारत के संविधान में जिन मूल अधिकारों तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का किया गया है वे सभी कराची कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किये गए थे। इसके अन्तर्गत धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, व्यवसाय आदि की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत कानूनों तथा राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों के संरक्षण की गारंटी की माँग की गयी थी। साथ ही वयस्क मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली एवं विभिन्न संघीय इकाइयों तथा केन्द्र में स्थानों की सुरक्षा के प्राविधानों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण देने का प्रस्ताव भी था। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग द्वारा नरकारी नौकरियों में नियुक्ति अवसर की समानता तथा साम्प्रदायिक वर्गों के लिए नौकरियों में

समुचित स्थान सुरक्षित किया जाना चाहिए तथा प्राजापति के प्रतिनिधित्व तथा भाग्य में एक सच के निमाण का व्यवस्था के प्रस्ताव थे जिसके अंतर्गत प्राजापति का हाथ में अवशिष्ट गतिविधि रहे। इस अविवर्धन में कांग्रेस ने पश्चिमात्तर सीमा प्रांत तथा सिंध का पूर्ण प्रांत की स्थिति प्रदान किया जाना तथा बसा के वहां का जनता की इच्छा के अनुसार भारत में पृथक किया जाना के प्रस्ताव भी पास किया। अथ विवादास्पद प्रश्नों की जांच के लिए समितियां प्रस्ताव दी गया जिनका रिपोर्ट के आधार पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा कार्यकारी समिति का निर्णय लेना का अधिकार लिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का कर्गचा अविवर्धन जनक दृष्टियां से महत्वपूर्ण तथा सफल मित्र हुआ। कराची कांग्रेस के प्रस्ताव जिता के 14-मूनी प्रस्तावों से मने नहीं रखते थे। 1928 के कांग्रेस महासम्मेलन में महारि रिपोर्ट की स्वीकृति के अवसर पर जिता न जा सगाधन रखे थे यदि कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर लेता तो साम्प्रदायिक समस्या जल्दी जितनी नहीं हानी जितनी तब तक कर 1931 तक हाती गयी। जब कांग्रेस ने जिता का कुछ मांगें स्वीकार करती तो उनमें यह था कि इस समय तक लोग का स्व बहुत हठीता हो चुका था। साथ ही जब जिता की मांग 14 में भी अति हो चुका था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का मांग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अधिकांश मुमनमानों का पूर्णतः पृथक्तावादी बना लिया था।

गांधी इंग्लैंड में समझौते के द्वारा

गांधी हरिविन अपना वात्सराय पद का कार्यकाल समाप्त करके 18 अप्रैल 1931 को इंग्लैंड को रवाना हो गए। 17 अप्रैल को लंडन विमान में उनका उत्तराधिकार प्राप्त किया। देश की स्थिति यह थी कि कांग्रेसी मयाग्रही जनता में रहे थे और उनका जज्जुमा में स्वागत हो रहा था। राष्ट्रीय गान उसाह में गाय जाते थे। कांग्रेस कार्यकर्ता तथा कांग्रेसी नेताओं के निवास स्थानों में तिरंगा भण्डा पहरोन लग थे। उस समय कांग्रेस का तिरंगा भण्डा ही राष्ट्रीय भण्डा माना जाता था। पूर्ण उत्साह के साथ सत्याग्रही शराव तथा विरक्षा बण्डों की दुकानों में धरना दे रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से न चाहते थे बहिष्कार की मांगें कर रहे थे। समझौते के अन्तर्गत राजनीतिक विद्वानों का रिहाई छाननी के सम्पत्ति का वापस आने का मांग की जाना था।

परन्तु दूसरी ओर गांधी हरिविन समझौते में माना नौरंगाही का सारी आजादों पर तुषारापान कर लिया था। एक छात्रों में पुनिम के मिपाहा में नरक बने में बने भारतीय मित्रों सेवा के कमचारी तक सभा यह साचन थे कि उनका वास्तविक शक्ति गेना जा रहा है। वे अपने कृत्या पर किसी भी प्रकार का वाद्व हस्तक्षेप सहन करने की कामना नहीं करते थे। वास्तव में भारत के नासत तो नौरंगाही ही थे और यहां सारे राग की जन्म थी। प्राजापति गवर्नर भी गांधी हरिविन समझौते में सन्तुष्ट नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि गांधी हरिविन समझौते का विवरणात्मक वाता के वायावयन में नौरंगाही अपना मनमाना करने का हस्त सेट में मने नहीं रहे। वह जन्म ही तरीके में समझौते का अर्थ गगन गेना। प्राजापति गवर्नर अपना अधिकार सीमा में का हस्त सेट वरगान करने के इच्छु नहीं थे। इस सबके कारण समझौते की विवरणात्मक वाता में नौरंगाही तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मध्य विवाद उत्पन्न हुए। राजनीतिक विद्वानों का रिहाई कर वसूला पिकनिंग जयन्टों की वापिस आने के सम्बन्ध में नौरंगाही का खयाल बटार हाता गया। पुनिम का वापसिया में कोई काम नहीं जा रही था। राजस्व तथा प्राजापति अधिकारी किसी भी भाषण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पिकनिंग ममाओं का आयोजन करने तथा राष्ट्रीयता के प्रचार-कार्यों का सहन नहीं कर पा रहे थे। इन सबके बावजूद नौरंगाही का मोन समझौते के प्राप्ताहित कर रहा था। वास्तव में पुन कर-वसूली में

अत्याचार प्रारम्भ हुए। यह सिलसिला लगभग मर्वत्र फेला। कांग्रेसी कार्यकर्त्ता समझौते की बातों पर जोर देकर विरोध करने लगे तो नौकरशाही उसकी उपेक्षा करने लगी।

अतः गांधी जी ने वाइसराय के सचिव को इन सब बातों से अवगत कराते हुए यह माँग की कि समझौते की शर्तों पर सरकार तथा कांग्रेस के मध्य विवाद खड़ा होने पर उनका निर्वचन निष्पक्ष न्यायाधिकरण या जाँच बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए। गांधी जी ने सचिव का ध्यान अन्य कई बातों की ओर भी आकृष्ट किया। वाइसराय से भेट भी की। परन्तु ऐसा आभास हुआ कि मग्नो वाइसराय को समझौते का कोई ज्ञान ही न था। नये वाइसराय के रवैये में एकाएक ऐसे परिवर्तन का मुख्य कारण इंग्लैण्ड में सत्ता-परिवर्तन था। श्रमिक दल की सरकार अब त्याग-पत्र दे चुकी थी। नई सरकार में मेकडोनेल्ड प्रधानमन्त्री अवश्य थे। परन्तु वे पूर्णतया रूढ़िवादी दल के हाथ की कठपुतली थे। वेन भारत मंत्री पद से त्याग-पत्र दे चुका था। उसका स्थान कट्टरपथी रूढ़िवादी सेमुअल होर ने लिया था। अतः कांग्रेस के साथ ब्रिटिश सरकार की शत्रुता की नीति अधिक कड़ी होनी जा रही थी। स्वयं वाइसराय इसी विचारधारा का समर्थक था। वाइसराय के सचिव ने भी गांधी जी को निराशापूर्ण तथा टालमटोल का उत्तर दिया। बम्बई तथा सयुक्त प्रान्त के गवर्नरों ने गांधी जी के पत्रों का उत्तर इसी प्रकार दिया। अन्ततः गांधी जी को यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि वे प्रस्तावित द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने में असमर्थ हूँ। निर्धारित तिथि (15 अगस्त) को जब सप्रू, जयकर आदि इंग्लैण्ड को रवाना हुए तो गांधी जी ने अपने प्रस्थान का विचार छोड़ दिया। सरकार की टालमटोल की नीति तथा नौकरशाहों के दमन-चक्र में पूर्ववत् स्थिति को देखते हुए कई स्थलों में हिंसात्मक घटनाएँ भी हुईं। पूना में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक विद्यार्थी ने बम्बई के गवर्नर पर गोली चलाने तक का प्रयास किया। कांग्रेस तथा गांधी जी ने इस घटना पर बहुत दुःख प्रकट किया।

सरकार ने पुनः साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देने की चाल चलना प्रारम्भ कर दिया। गोल मेज परिषद् के लिए प्रारम्भ में लार्ड इरविन ने पण्डित मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा डाक्टर अन्सारी को नामांकित करने का वचन दिया था। परन्तु फजली हुसैन के सकेत पर डा० अन्सारी को न भेजने के वाद के सरकारी फैसले से गांधी जी असन्तुष्ट हो गये। सरकार की नीति यह थी कि वह राष्ट्रवादी मुसलमानों को भेजने में हिचकने लगी, क्योंकि उनकी उपस्थिति से मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बल नहीं मिल पाता और इसके परिणामस्वरूप सरकार का उद्देश्य पूर्ण न हो पाता। इसलिए भी गांधी जी ने इंग्लैण्ड जाने का विचार रोक दिया। इसके पश्चात् वाइसराय तथा गांधी जी के मध्य पत्र-व्यवहार चलता रहा। अन्ततः दोनों में परस्पर वार्ता भी हुई और गांधी जी ने 29 अगस्त को गोल मेज परिषद् में भाग लेने का निर्णय कर लिया विशेषतः वे गांधी-इरविन समझौते में की गई इस शर्त को मानना अपना नैतिक दायित्व समझते रहे।

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, 1931

गांधी जी अपनी नित्य की वेशभूषा में इंग्लैण्ड पहुँचे और ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यवस्थित प्रसादों या होटलों में रहने की अपेक्षा पूर्वी लन्दन के किंग्सले हॉल में कुमारी लीस्टर के मेहमान बने। अपनी उसी वेशभूषा में वे मग्राट सहित सभी अधिकारियों से मिलते थे। इंग्लैण्ड के वच्चे-वच्चे गांधी जी की इस विचित्र वेशभूषा में बड़े प्रभावित हुए। अनेक सस्याओं तथा व्यक्तियों की ओर से उन्हें आमन्त्रण मिले और स्थान-स्थान पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस सबका यह निष्कर्ष है कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा, राष्ट्र-प्रेम तथा देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के सम्बन्ध में उनकी सत्यनिष्ठा के प्रति चाहे निहित स्वार्थों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादी कितने ही रूष्ट रहें हों, तथापि उक्त गुणों से युक्त इस फकीर राजनेता के प्रति लोगों में अतीव श्रद्धा उत्पन्न हो गयी।

द्वितीय गांधी मंत्र सम्मेलन का बटका मंजूर जाय तब 3 मंत्रों का अवधि तक समय समय पर चर्चा की जाती थी प्रमुख बतलावने रहे । यद्यपि इस समय कांग्रेस का विरोध करने के लिए 31 और प्रतिनिधि प्रतिनिधि छोड़े गये जो विविध विरोधी तथा प्रतिप्रियावादी वर्गों में मंत्रित गये थे तथापि इस सम्मेलन में उनका अस्तित्व काई महत्व नहीं रखता था । निम्न यह भाग की 85 प्रतिशत में भी अधिक जनता के वास्तविक प्रतिनिधित्व के रूप में देश की भावना राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में उनका विचारों में अतिरिक्त उनकी सब विचारों को शान्त जाना जा सका निम्न स्वार्थों में भरपूर हान के कारण वास्तव में महत्वहीन थे । परन्तु उही विचारों को ताड़ मराठकर रचना और गांधी जी के विचारों का मया उमर प्रमाण में प्रमाण रूप अर्थ तत्त्वा का मुख्य उद्देश्य बना रहा ।

प्रथम सम्मेलन में व्यक्त तथा निर्धारित नीतियों का गांधी जी ने सम्मेलन की बैठक में एक एक करके उत्तर दिया । सब व्यवस्था तथा उनमें अन्तर्गत सरकार का स्थापना के युक्त करने और प्रतिस्थापन प्रतिनिधि सम्मेलन तथा विचारों नीति का सर्वांगीण विचारों के अंतर्गत रखने का नीति का तथ्यगत विरोध करने हुए गांधी जी ने भारत की गरिमा प्रतिष्ठा तथा आत्म सम्मान का ऊंचा उठाया । उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अपने देश को प्रतिस्थापन का नायब भारत की मनाय स्वयं भारत की नीतियों के अनुसार पूर्ण रूप से ममान्य करती है कि विदेशी साम्राज्यवादी सरकार तथा उसकी मनाय । भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग का व्याख्या करने हुए उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज का अपना पूर्ण स्वराज का भारत तथा स्वराज के मध्य भेद की हित में और अधिक स्पष्ट हाना मिद्ध किया । गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत स्वराज के एक अधीन देश के रूप में यह बातों नहीं कर रहा है अपितु यह बातों को समान स्थिति के रूप में मध्य की है । कांग्रेस की स्थिति का स्पष्टकरण करने हुए गांधी जी ने बताया कि यह जय शान की भाँति एक राजनीतिक न माननी है । अपितु वह समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सभी रियासतें शामिल हैं । फ्रांस जिसा भी मान में जिसा सम्प्रदाय विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती । वह हमें जानि देता है कि आधार पर किसी देश विचारों की स्थापना होकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय मन्त्रालय और गांधी जी स्वयं अपना व्यक्तिगत श्रमता में इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं अपितु वह उमा मन्त्रालय मन्त्रालय के प्रतिनिधि एक मंत्र है और उमा मन्त्रालय के आत्ममानुसार कार्य करते हैं ।

साम्प्रदायिक स्थिति के सम्मेलन में जा कि भारतीय राष्ट्रीयता का भावना का बुझने के लिए अग्रजों का समय महान् माधन या गांधी जी ने कांग्रेस की नीति का स्पष्टतया व्यक्त किया । नई साविधानिक व्यवस्था में सम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था के बारे में गांधी जी स्पष्ट थे । परन्तु चूंकि एक सम्प्रदाय इस पर जोर देता था अतः गांधी जी ने मुस्लिम तथा सिक्ख सम्प्रदाय के लिए ता बुद्धि सामा नेव इस मन्त्रीय माना । परन्तु जिन लोगों ने हरिजनों का भाँ साम्प्रदायिक आत्मसंयम मानने का स्वीकार किया उन गांधी जी ने महत्त्व उत्तर दिया । गांधी जी ने तब के साथ कहा कि हमारा भूभावनपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने वाला तथा हमी व्यवस्था का मायना हमें नीति का उद्देश्य विरोध करण । भारत में ब्रिटिश शासन के स्वतंत्राचारानुसार स्वयं का भी गांधी जी ने इस सम्मेलन में उल्लेख किया और हमें करने में उन्होंने अपने मायाना स्वयं का ही अपनाया । उन्होंने स्पष्टतया बताया कि प्रधानमन्त्री का पदना गांधी मंत्र पद के बाद की गयी धारणा में भारत की नीतिक सम्मेलना की उपयोग की गयी थी । गांधी जी ने इस सम्मेलन में इस गये विचारों के समय समय पर लिख गये महत्वपूर्ण व्याख्याना का सारित्व माने जाते हैं । भारताय स्वतंत्रता का माँग के प्रति पूर्णतया उत्साहीन ब्रिटिश नेता हर जगह पर साम्प्रदायिक भूभाव का भावना का हाँ पार मराठ कर या उदात्तवादी व्यवस्था के तब और साम्प्रदायिक समतमाना का भावना का उद्वेगना सभी ब्रिटिश अधिकारियों का उद्देश्य बना रहा ताकि कोई समतमान न निकलने पाय । 1 नवम्बर 1931 का सम्मेलन का समाप्ति के पश्चात्

पर उन्होंने प्रधानमन्त्री को सम्मेलन आयोजित करने तथा उन्हें उसमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया।

इस सम्मेलन में प्रो० लास्की ने अपने पत्र-व्यवहार में अमरीकी न्यायाधीश ह्यूम को जो विचार व्यक्त किये थे वे तथ्यों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। लास्की सैंकी को महायत्ना दे रहे थे, सैंकी इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे। लास्की के मत से 'ऐसे व्यक्तियों के साथ जो यह विश्वास करें कि वे ही वास्तविक सत्य के धारक हैं, बात करना असम्भव है' मुसलमानों की धार्मिक हठमति भयानक है। मेरा अनुमान है कि पूरब में इस्लाम भक्ति एक ऐसी शक्ति है और इसके समर्थकों की माँगे इतनी अस्पष्ट तथा भयावह हैं कि उनको पूर्ण किया जा सकता असम्भव है।

टोरी साम्राज्यवाद तथा भारतीय उग्रवाद से युक्त पक्षों के द्वारा साम्प्रदायिक समस्या के हल की आशा नहीं की जा सकती। अशक्त मैकडोनेल्ड को दोष देता हूँ, क्योंकि यदि वे दुर्बल, निरर्थक तथा निर्णयरहित होने की अपेक्षा दृढ-मन के होते तो मेरा विचार है कि वे किसी न किसी समझौते से सम्बद्ध पक्षों को वाध्य कर लेते।¹ लास्की ने सर्वाधिक दोष संयुक्त होर को दिया जो कि अपने टोरी स्वभाव की पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। अन्यथा लास्की के मत से गांधी तथा सैंकी किसी निर्णय पर पहुँच जाते।

जब गांधी जी भारत लौटे तो मम्बई में जनता ने उनका जो शानदार स्वागत किया, वह किसी राजा तक को कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। परन्तु भारत में ब्रिटिश शासकों का दमन-चक्र पूर्ववत् पूर्ण गति से चल रहा था। संयुक्त प्रान्त, बंगाल, बारदोली इस दमन के केन्द्र थे। किसानों के ऊपर अप्रत्याशित ज्यादतियाँ की जा रही थी। संयुक्त प्रान्त में सरकार की इन ज्यादतियों के विरुद्ध लगान विरोधी अभियान चलाने के आरोप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा निसारअहमद शेरवानी को बन्दी कर लिया गया था। बंगाल में चिटगाँव के छापेखाने में जो गुण्डागर्दी की गयी थी उसमें कुछ यूरोपियों का हाथ था, परन्तु पुलिस ने उसमें कोई कार्यवाही नहीं की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में खान बन्धुओं (सीमान्त गांधी अब्दुलगफ्फार खाँ तथा डाक्टर खान) के नेतृत्व में स्वातन्त्र्य आन्दोलन चल रहा था और पठानों का सगठन खुदाई खिदमतगारों के नाम से निर्मित हो चुका था। इस सगठन की कांग्रेस के प्रति पूर्ण निष्ठा थी।

संक्षेप में, जब गांधी जी इंग्लैण्ड से वापिस आये तो उन्होंने यह अनुभव किया कि सरकार गांधी-इरविन समझौते की शर्तों से हर क्षेत्र में मुक्त नहीं है। सत्याग्रह आन्दोलन पूर्ववत् हिंसात्मक दमन की नीति से कुचला जा रहा है। नौकरशाही किसी भी रूप में जनता के प्रति सहानुभूति पूर्ण अथवा उत्तरापेक्षी रख नहीं अपनाता चाहती। ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतन्त्रता की माँग के सम्बन्ध में जरा-भर भी झुकने की इच्छुक नहीं है, अपितु इसे ठुकराने के वहाने देश में साम्प्रदायिक तथा अन्य निहित स्वार्थ वाले तत्त्वों, यथा राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों आदि को प्रोत्साहन दे रही है। कांग्रेस के उच्चतम नेताओं को किसी न किसी रूप में बन्दी कर लेने का अवसर ढूँढा जा रहा है। ऐसी स्थिति में गांधी-इरविन समझौते अथवा कांग्रेस द्वारा गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के कोई सन्तोषजनक परिणामों की आशा व्यर्थ थी। अतः कांग्रेस के लिए पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी करना अपरिहार्य हो चुका था।

आन्दोलन का दूसरा दौर

28 दिसम्बर 1931 को जब गांधी जी इंग्लैण्ड से भारत लौटे तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को गोल मेज परिपद तथा ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराया। साथ ही देश में चल रही ब्रिटिश शासन की करतूतों का ज्ञान भी उन्होंने

किया। काग्रस तथा गांधी जी न अनुभव किया कि बान्सराय नाथ विनिम्न तथा नीकरगाही गांधी रविन समभौत का ध्यानकारी स अमन म नान का परवाह नहा कर रह है न उनकी एमा नीति है। एमी स्थिति म काग्रस कायकारा समिति न पुन सविनय अवता आत्मान प्रारम्भ करने का निणय किया। मम पूव गांधी जी न नाथ विनिम्न का 29 डिसेम्बर 1931 क दिन एक तार भजा जिमम उहान सरकार की धमनकारी अध्यात्मा को जारी करके शासन करने की नानि का विरोध किया और बान्सराय म वाता करने की ष्टा प्रकट की। म तार का तुरन् निराशाजनक उत्तर बान्सराय की आर म प्राप्त आ। तत्पश्चात् 6 दिन तक तम्ब चौथे तारा का गिरमिता चता जिनम एक-मर के ऊपर (काग्रस तथा सरकार) आरोप प्रत्यारोप गमाय गया। जतन काग्रस काय समिति का सताप हा गया कि टिनी समभौता (गांधी रविन समभौता) सरकार का आर म भग कर दिया गया है। जत समिति न राष्ट्र स पुन सविनय अवता आत्मान को पूण उत्साह अहिंसा तथा मत्यनिष्ठा म चतान का आह्वान किया। 3 जनवरी 1932 का गांधी जी न अंतिम तार का मगाय का भजत हुए नाचारी यन की कि उन् सरकार के अमह्यागपूण तथा स्पष्टाचारी और जयाचारी स्वय का त्तर सविनय अवता आत्मान छान्त का आह्वान करना पड रहा है।

सरकार आत्मान का वन प्रयाग द्वारा कुचनन के लिए पहन स नीतयार थी। कहा जाता है कि टिनी समभौत की अवधि म सरकार आत्मान का कुचनन क माधना का जुनन म मतन रही। चूकि विनिम्न की सरकार तथा नीकरगाही गांधी रविन समभौत म असंतुष्ट था जत अनक अध्यात्मा तो पहन ही नामू कर न्यि गय थ। आत्मान पुन प्रारम्भ हात हा जय भा जारी कर न्यि गय। काग्रस मगठन का अवध धापित कर दिया गया। मोनारामया के गन्त म 1930 के आत्मान म पुनिम नाठी चाज का मन्त्रा बहुत वाट म रिया गया था परन्तु 1932 क आदातन का कुचनन के लिए एमी माधन स गुम्नात की गयी। गांधी जी सरदार पटन नन्त गान अन्तगपफार खां जानि का तुरन् वनी बना रिया गया। म्मक नाथ अय काग्रमा नताआ तथा कायवताआ की गिरफ्तारी म न गनि स प्रारम्भ हई कि जहाँ 1930 क सम्पूण आत्मान म नगभग। नाथ व्यक्ति वनी किय गय थ वहाँ 1932 म था ही समय म एक नाथ बाग हजार क नगभग मत्याग्रहा वनी बना रिय गय। मभाआ म नाग चाज गाता चताना जता म वन्ध्या के साथ जयाचार म्मी-यचा तक का मताना स्कूना म बिद्याधिया के ऊपर जुम करना जानि सय बातें दमन पर तन नामका के लिए माधारण मां जान थी। अन अतिरिक्त मनमान अयन्ण दना नागा का जतन मम्पनि गेतना मनमान ग म कर तथा अयन्ण वसूत राना आनि का गिरमिता उग्रतर हाता गया। आत्मान का धमन करने के लिए मनमान तथा अत्याचारी अध्यात्मा जारी करना सरकार के लिए मतना हा गया था। वास्तव म क्या जाता है कि नाथ विनिम्न का नावा था कि वह आत्मान का 6 मप्ता म कुचन त्या। परन्तु यत् म्मरणीय है कि िमा तथा दमन म एमा राष्ट्रीय आेन नन कम समय म नहा कुचना जा मरता था। धमन की नीशता के साथ मत्याग्रहिया के मनारन भी ऊँच होत गय और आत्मान अधिउ उग्र हाता गया। एमा प्रतात हाता था कि माना भारत म विधि के नामन का निरा जो गयी थी। म जातक तथा अध्यात्मा म पूण ब्रिटिश नीकरगाहा कन्ता रचित नागा। समाचार पत्रा पर कठारतम प्रतिरोध गमा रिय गय थ। उनम न्मना वना धनराशि का नन्त जमानन मोगी गया कि कर् ममाचारग्रत ता वन्त हा हा गय। अध्यात्मा का म्म न्मना स्वाध्याचार तथा उनका मत्या न्मना अधिक था कि नान मभा मर समुग्रत हाज जा कि न्म आत्मान का धमन करने की नीति के बठोर समयक थ का भा म्म स्वाकार करना पडा कि के वन्त बन्त थ परन्तु सरकार उह नामू करने का विवग थी। पण्डित मन्मन्त मानवाय का म्मर गियन सरकार के नाम नन्त विरुद्ध एक म्मवा तार भजना पडा ता तार विभाग न उम भजत म न्मकार रिया कि न्मना म्मवा तार नन्त भजा ता मरता। जता का जावन जत्यन कल्मय था। म्मरन्त के

साम्राज्यवादी टोरी दल के नेताओं की नीतियों पर आधारित भारत में ऐसा अत्याचारी अविनायकवादी शासन चलाने वाले अंग्रेज शासकों के दमन-चक्र का यह सक्षिप्त विवरण ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि जो अंग्रेज अपने देश में स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र के इतने कट्टर हिमायती हैं वे साम्राज्य-लिप्सा के प्रभाव में अधीन बना लिए गये देशों की जनता की ऐसी ही अहिंसापूर्ण ढंग से की जाने वाली माँग को किस निर्दयता से कुचलते थे। यह बात अंग्रेज जाति के सामान्य चरित्र को कितना कलुषित करती है, इसे वे साम्राज्यवाद के नशे में बिल्कुल ही भूल गये थे। दूसरी ओर ब्रिटिश राज्य के उन राजभक्त भारतवासियों की मनोवृत्ति को देखकर भी दुःख ही होता है जिन्होंने ब्रिटिश शासकों के आदेशों का इतनी अन्ध श्रद्धा से पालन किया कि अपने ही देशवासियों तथा बन्धुओं के ऊपर जो कि अपनी ही नहीं बल्कि उनकी स्वतन्त्रता के लिए भी लड़ रहे थे, अत्याचारपूर्ण कृत्य करने में सकुचाहट नहीं दर्शायी। अन्यथा जिस जोग से सविनय अवज्ञा आन्दोलन चला था, उसके अन्तर्गत ब्रिटिश शासकों को 1932 में ही भारत छोड़कर चले जाने को विवश होना पड़ता। सम्भवतः अभी ब्रिटिश राज्य के पापों का घड़ा पूर्णतया नहीं भरा था।

कम्यूनल ऐवार्ड तथा पूना पैक्ट

बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में लार्ड कर्जन तथा लार्ड मिण्टो के वाइसरायत्व काल में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारत की राष्ट्रीयता के सफल विकास को अवरुद्ध करने के लिए साम्प्रदायिकता का विष फैलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तब से लेकर ब्रिटिश शासकों का निरन्तर यही प्रयास रहा कि भारत में साम्प्रदायिकतावादी तत्त्वों को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीयता की शक्तियों को नष्ट-भ्रष्ट करे और स्वाधीनता की माँग के समक्ष साम्प्रदायिक भेदभाव की समस्या को रखकर मामले को जटिलतर बनाते जायें। साइमन कमीशन ने इसे और अधिक उभार दिया था, यद्यपि गोल मेज परिषद् के समक्ष गांधी जी द्वारा साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में स्थिति का पूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट पर जिन्ना ने अपनी चौदह सूत्री माँगें रखकर ब्रिटिश सरकार की टालमटोल की नीति को और अधिक बढ़ावा दे दिया। अंग्रेज लोग केवल मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद से ही सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने सिक्खों तथा ईसाइयों को तो इसमें शामिल कर ही लिया था। परन्तु अब इस समस्या के विष को और अधिक तीव्र बनाने के लिए उन्होंने हिन्दू समाज के दलित (अछूत) वर्ग को भी अलग सम्प्रदाय घोषित करके उसे भी एक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय में वर्गीकृत करना चाहा, ताकि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्थिति और निर्दल पड़ जाय।

साम्प्रदायिक पचाट (Communal Award)—द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के अवसर पर जब भारत की भावी सांविधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विविध सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के मध्य मतैक्य नहीं हो पाया, तो प्रधानमंत्री मेकडोनेल्ड ने कहा कि ब्रिटिश सरकार स्वयं इस समस्या के समाधान पर निर्णय लेगी। 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री ने इस सम्बन्ध में जो अपनी नीति बताई उसे साम्प्रदायिक पचाट कहा जाता है। इस निर्णय को ऐसा नाम देना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि सम्बद्ध पक्षों ने प्रधानमंत्री को ऐसा निर्णय स्वयं लेने की अधिकृत महमति कभी नहीं दी थी। फिर भी यह एक ऐसा निर्णय था जिससे ब्रिटिश सरकार की साम्प्रदायिकता को उकसाने की नीति स्पष्ट हो गयी।

इसके अनुसार नई सांविधानिक व्यवस्था में भारत की प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित करने तथा उनके लिए पृथक् निर्वाचन की प्रणालियों को मान्यता दी गयी। इस प्रकार मुसलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों तथा महिलाओं के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र होते। वम्बई में सात स्थान मराठाओं के लिए सुरक्षित किये गये। जो अहं मतदाता उक्त सम्प्रदायों के नहीं थे वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही मतदान करते। अनुसूचित जाति के मतदाताओं को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार

होगा। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों व्यवस्थापिकाओं के लिए यह पद्धति अपनायी जायेगी। केन्द्रीय व्यवस्थापिका में भारे भारत के लिए निर्धारित स्थानों के 18 प्रतिशत स्थान दलित वर्ग के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे। उम्मीदवारों के चयन की उपर्युक्त पद्धति केवल दस वर्ष तक चलेगी। यह योजना गांधी जी के सामने रखी गयी और साथ ही सरकार के सामने भी और दोनों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस समझौते के उपरान्त गांधी जी ने 26 सितम्बर को अनशन तोड़ दिया। इस समझौते को 'पूना पैक्ट' कहा जाता है, क्योंकि इसकी योजना पूना में बनी थी, जहाँ गांधी जी अनशन कर रहे। इस समझौते में हरिजनो के प्रतिनिधियों के रूप में उनके नेता अम्बेदेकर तथा राजा जे। समझौते से गांधी जी को यह सन्तोष था कि दलित वर्ग के लिए पृथक् निर्वाचन की विषैली प्रथा नहीं रह पायेगी, सरकार को यह सन्तोष था कि आखिर दलित वर्ग को एक विशिष्ट सम्प्रदाय माना ही गया है जिसका लाभ वह कभी न कभी उठा सकेगी, दलित वर्ग को प्रतिनिधियों को यह सन्तोष था कि उन्हें पहले की अपेक्षा और अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है।

इसके उपरान्त गांधी जी ने छुआछूत के भेदभाव को नष्ट करने के लिए तुरन्त और अधिक प्रभावशाली कदम उठाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनो का हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश तथा किसी भी रूप में छुआछूत का भेदभाव न बरतना शामिल थे। उस समय अधिकांश प्रमुख नेता जेलों में थे। जो बाहर थे, उन्हें सविनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ-साथ अद्वैतोद्धार का कार्य करना था। गांधी जी जेल में बहुत नियन्त्रणकारी प्रतिबन्ध में थे। कोई उनसे नहीं मिल सकता था। अतः गांधी जी ने सरकार से आग्रह किया कि हरिजनोद्धार कार्य में उन्हें सुविधा न देना पूना पैक्ट के विरुद्ध है। अन्ततः उन्हें इस कार्य के लिए कुछ छूट दी गयी। कुछ नेताओं को उनसे मिलने दिया गया। हरिजनोद्धार का कार्य धीमी गति से चलने लगा।

गांधी जी का उपवास तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्थगन

सरकार की दमन नीति तथा अव्यादेशों के शासन में कोई कमी नहीं आयी थी। जिस प्रकार 1932 में सरकार द्वारा रोक तथा प्रतिबन्ध की स्थिति में कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसी प्रकार मार्च 1933 में कलकत्ता में भी इसका आयोजन किया गया। पण्डित मालवीय जी इसके अध्यक्ष होने वाले थे। परन्तु सरकार इसे न होने देने की पूर्ण तैयारी कर चुकी थी। कलकत्ता पहुँचने से पूर्व ही मालवीय जी सहित बड़े-बड़े नेताओं को बन्दी कर लिया गया। महिला नेताओं तक को नहीं छोड़ा गया, यथा श्रीमती मोतीलाल नेहरू, श्रीमती अणे आदि। किसी भी तरह विशाल सख्या में प्रतिनिधि अधिवेशन स्थल में पहुँच गये। पुलिस लाठी चार्ज तथा प्रतिरोध के बावजूद एम० एस० अणे की अध्यक्षता में कांग्रेस ने सात प्रस्ताव पास कर लिए। बाद में अधिवेशन के सिलसिले में बन्दी किये गये नेताओं को छोड़ दिया गया। पण्डित मालवीय जी ने सरकार के इस रवैये की घोर निन्दा की, इसके पश्चात् 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के हेतु 21 दिन का उपवास रखने का सकल्प किया। इनका मुख्य उद्देश्य हरिजनोद्धार के पवित्र कार्य का संचालन करने हेतु आध्यात्मिक बल तथा शान्ति प्राप्त करना था। गांधी जी के मत से ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने यह सकल्प किया था, अतः उन्होंने अन्य साथियों को अपना अनुसरण न करने की सलाह दी, जब तक कि उन्हें भी ऐसी भगवत्प्रेरणा प्राप्त न हो गयी हो।

जब सरकार ने देखा कि इस उपवास का उद्देश्य राजनीतिक नहीं, अपितु सामाजिक व धार्मिक है, तो उसने गांधी जी को तुरन्त मुक्त कर दिया। गांधी जी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को छ सप्ताह तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर देने की सलाह दी। 21 दिन का उपवास सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेने पर गांधी जी को अनुभव हुआ कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन से कोई वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं हुई है वल्कि सरकार की दमनकारी नीति बटी है, जिसके कारण सत्याग्रहियों तथा जनता को कष्ट ही हुआ है। अतः 12 जुलाई को पूना में कांग्रेस का

एक अनौपचारिक सम्मेलन हुआ जिसमें सामूहिक सत्याग्रह का स्थगित कर देना का निश्चय किया गया परंतु व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस अध्यक्ष को जाना नकरा कार्यकर्त्ताओं को सविनय अवज्ञा करने की छूट दे दी गयी। गांधी जी ने इस बीच वाइसराय से मिलने की च्छेदा व्यक्त की ताकि वातावरण द्वारा समस्याओं का समाधान ढूँढा जा सके। परंतु वाइसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। इसीनिये व्यक्तिगत सत्याग्रह का कदम उठाना पड़ा। जब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ तो फिर प्रमुख नेतागण जिनमें गांधी जी भी शामिल थे बंदी कर लिए गए। 16 अगस्त को गांधी जी ने पुनः उपवास शुरू कर दिया। इस बीच गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा तो सरकार ने 23 अगस्त को उन्हें छोड़ दिया। 30 अगस्त को पण्डित नेहरू का भी इस आधार पर छूट दिया कि उनकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा था। परंतु सामूहिक आंदोलन का समाप्त कर देने की घाबराहट के बावजूद सरकार ने अनेक शीपस्थ नेताओं तक का मुक्त नही किया उदाहरणार्थ सरदार पटेल के कारावास को कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गयी थी। उन्हें छान्ना था न छोड़ना सरकार की स्वच्छता पर निर्भर था।

कौमिल प्रवेश का कार्यक्रम

सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी का अधिकांश समय तथा ध्यान हरिजनोद्धार के कार्य में लगा रहा। आंदोलन का अवधि में बंदी किये गए जा कार्यकर्त्ता छूट गए उनमें उत्साह की कमी जान गयी। सरकार ने अपने की नीति में कोई कमी नहीं की थी। एसी स्थिति में कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग यह अनुभव करने लगा कि आगामी व्यवस्थापिकाओं के चुनावों में भाग लेना तथा कौमिल प्रवेश द्वारा अध्यादेशों से भर गायन का विरोध करना और वहाँ से भावी संविधान के बारे में नये मुद्दे रखना अधिक प्रयत्न होगा प्रजापक्षक कि व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा अपना माँग का मनवान का असफल प्रयास किया जाय। इस कार्यक्रम के हेतु डा. जमनालाल तथा मालवीय जी का प्रमुखता देकर एक नये भारतीय स्वराज्य दल का निमित्त करने की योजना बनायी गयी। इसी बीच 16 जनवरी 1934 को बिहार में भयंकर भूकम्प की घटना हो जाने से गांधी नेहरू जीने प्रमुख नेताओं का ध्यान भूकम्प पीड़ित जनता के राहत देने के लिए रचनात्मक कार्य करने की ओर बँट गया। डा. जमनालाल के नेतृत्व में एक निष्पक्षपूर्ण उम्र समर्थ विहार में भूकम्प-प्रांति धन में घूम रहे गांधी जी में मिला। गांधी जी ने कौमिल प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। मई 1934 में कांग्रेस कार्य समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने भी इस स्वीकार कर दिया। 20 मई 1934 को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का पुनर्नया समाप्त कर दिया। गैर-शस्त्री अवधि में भारतीय राजनयिकों के अंदर एक नयी घटना हुई। वह थी पटना में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना जो आचार्य नरेश दत्त के नेतृत्व में संगठित हुई। जुलाई में कांग्रेस कार्य समिति का बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित मामलों में कांग्रेस संगठन का व्यवस्थापक भाषा माविधानिक व्यवस्थाओं की पर विचार करना था।

सांविधानिक विकास क्रम तथा तृतीय गोल मेज सम्मेलन—पूना पक्ष के उपरान्त सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा कांग्रेस की गतिविधियाँ मंजूर हो गई थी। सरकार के दमन के कारण भी यह निश्चितता स्वाभाविक थी। कांग्रेस संगठन पर प्रतिबंध लगा था। एसी स्थिति में टारो के प्रभाव में संचालित ब्रिटिश सरकार विधायक रूप में तत्कालीन मायायवादी भारत सरकार मंगुलन द्वारा यह महन करने का तयार न था कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधीन यत्न भारत के लोग का मान मेज परिपक्व में समानता की स्थिति में आमंत्रण मिले। अतः नवम्बर-दिसम्बर 1932 में तत्कालीन गोल मेज सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डा. नारायण के द्वारा यह कथन किया गया था (it was just a piece of window dressing)। दली नरेशा का स्वयं का अभिमान नहीं था। ब्रिटिश भाष्य में शामिल नहीं किया गया था। सभी प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार का ही नहीं ही मिलान मान थे या कुछ आन्दोलन व्यक्त

थे। इंग्लैण्ड के मजदूर दल ने इसका वहिष्कार कर दिया था। भूतपूर्व भारत मन्त्री वेन के विरोध के कारण प्रथम दो अधिवेशनो में साइमन को नहीं बुलाया गया था। परन्तु तृतीय में उसे आमन्त्रित किया गया। यह ठीक भी था क्योंकि अब नई टोरी सरकार पुनः साइमन रिपोर्ट को ही नये साविधानिक सुधारों का आधार बनाने पर तुली हुई थी। अधिवेशन 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक चला। अतः प्रथम तथा द्वितीय गोल मेज परिषदों के प्रस्तावों तथा उनकी समितियों की रिपोर्टों को इसमें अन्तिम रूप दिया गया। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं था। अतः साम्प्रदायिक तथा प्रतिगामी तत्त्वों से युक्त इस परिषद् ने साम्राज्यवादियों की नीतियों को भावी भारतीय साविधानिक व्यवस्था के लिए स्वीकृति दे दी। कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने जो भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखे, उन्हें अमान्य कर दिया गया। अन्त में तेजबहादुर सप्रू ने अपने भाषण में कहा कि सरकार जिस सविधान को बनाने जा रही है उसे ऐसा होना चाहिए कि जो भारत की जनता को मान्य हो। उन्होंने सम्मेलन को याद दिलाया कि भले ही गांधी जी से उनके कुछ बातों में मतभेद है तथापि गांधी जी का व्यक्तित्व भारत की जनता में अतीव सम्मान प्राप्त करता है। साथ ही उनकी देशभक्ति सर्वोत्कृष्ट है। अतः जब तक उन्हें (सप्रू को) समाधान न हो जाये कि वे कांग्रेस-जनो को सन्तुष्ट कर सकते हैं तब तक देशवासियों को सन्तोष दिलाने के कोई अवसर नहीं रहेगे। संमुअल होर ने सप्रू को आश्वासन दिया कि वे सप्रू की माँगों पर पूर्णतः विचार करेंगे।

श्वेत-पत्र तथा सयुक्त ससदीय प्रवर समिति—मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी साविधानिक स्वरूप के सम्बन्ध में श्वेत-पत्र जारी किया। इसमें जो प्रस्ताव रखे गये थे, वह तीन गोल मेज सम्मेलनों में रखे गये विचारों पर आधारित बताये गये थे। परन्तु यह भी स्मरणीय है कि श्वेत-पत्र में उन अनेक प्रस्तावों की उपेक्षा की गयी थी जिन्हें गोल मेज सम्मेलन में समर्थन मिला था क्योंकि वे टोरी सरकार को मान्य नहीं थे। इसी श्वेत-पत्र के आधार पर अप्रैल 1933 में ब्रिटिश सदन के दोनों सदनों की एक सयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की गयी जिसे नयी साविधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में श्वेत-पत्र के आधार पर रिपोर्ट देनी थी। सयुक्त प्रवर समिति ने नवम्बर 1934 को अपनी रिपोर्ट सदन को दी।

जहाँ तक इन विविध सम्मेलनों, प्रलेखों, समितियों तथा स्वयं ब्रिटिश सदन के हाथों भारतीय साविधानिक व्यवस्था में सुधारों का प्रश्न है, उनके आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण स्वराज्य या स्वायत्तता तथा-उत्तरदायी शासन की माँगों की स्वीकारोक्ति तो दूर रही, इन सबने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हितों को और अधिक सुदृढ़ बनाया। गोल मेज परिषदें ढकोसला-मात्र रह गयीं, साम्प्रदायिक पचाट यद्यपि विभिन्न सम्प्रदायों को सन्तुष्ट करने में असफल रहा, तथापि उसने भारतीय राजनीति में इस जहर को और अधिक तेज बनाया, श्वेत-पत्र ने गोल मेज परिषद् की थोड़ी सी अच्छाईयों को भी समाप्त कर दिया था, सयुक्त प्रवर समिति एक कदम और आगे बढ़ गयी। जहाँ पिछली व्यवस्थाओं में केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली रखी गयी थी, वहाँ इस समिति ने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की सिफारिश की, ताकि उनमें किसी प्रकार के लोकतन्त्रीय तत्त्व विद्यमान न रह सके। इस समिति के अध्यक्ष लार्ड लिनलियथो तथा प्रमुख प्रवक्ता संमुअल होर थे। यही लिनलियथो वाद में भारत के गवर्नर-जनरल भी नियुक्त किये गये थे जो एक सच्चे टोरी थे। इनसे यही आशा की जा सकती थी। सयुक्त प्रवर समिति की अन्य प्रतिगामी सत्तुतियों के अन्तर्गत निम्नांकित वाते महत्वपूर्ण थीं प्रस्तावित सध-व्यवस्था में केन्द्रीय व्यवस्थापिका के लिए देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को वहाँ के नरेशों के द्वारा नामांकित करके भेजा जाना, न कि जनता द्वारा निर्वाचित किया जाना, पृथक् निर्वाचन के क्षेत्र को बढ़ाना, प्रान्तों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदनों को समाप्त करने की शक्ति ब्रिटिश सदन को देना (श्वेत-पत्र ने यह शक्ति केन्द्रीय व्यवस्थापिका को दी थी), सदीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करना, ताकि ब्रिटिश प्रीवी कौंसिल अन्तिम अपील न्यायालय बना रहे। सयुक्त प्रवर समिति की सत्तुतियों के आधार पर ब्रिटिश सदन में पेश किये जाने के निमित्त

1935 क प्रारम्भ म एक विनियम तयार किया गया ता जगन्त 1935 म भारतीय गान्त अग्रिनियम (Government of India Act 1935) क रूप म पास किया गया ।

गांधी जा का काग्रम म अलग हाना

भारतीय गणाय आन्तान्तन म 1934 म एक आर ता ममानवाता न्त का अम्भुत्य हा चुना ता और न्तम आर गय । एम आर तथा मानवाय जा भा काग्रम मगन्त क प्रमुत्त पना म पृथक् ता गन्त थ । ब्रिटिश सरकार न मगन्त पन्त न्हन् खान अन्तुगणकार खाँ आन्ति अनक क्ता नताजा का काग्रवाम म मुक्त नन्ता किया था । न्मा वाच मिनम्बर 1934 म गांधी जा न एकाणक एक वक्तव्य न्कर अपन का काग्रम म अलग नान का घोषणा कर ता । गांधी जा का एमा आनाम हान गगा था कि काग्रम म ग्हत हुए व अय नागा का न्तका न्ता क विम्ब जपना वाता का मानन क लिए विवग करत थै । अन्धा काग्रम क अय क्ता नताजा म उनक विचार न्हो मितन थ । यद्यपि गांधी जा न काग्रम म अलग हान का घोषणा कर ता और क्ता चार आन क मन्म्य भा नन्ता र्ता तथापि यन् मान नन्ता महा न्हो थै कि गांधी जा का काग्रम म सम्बन्ध न्ता गया । भन्ता व काग्रम मगन्त म किमा पन् पन् नन्ता र्ता तथापि नन्त तक वह जावित र्ता काग्रम का राष्ट्रीय आन्तान्तन न्हो क परगमन तथा उन्ता का मरलता म चरता र्हा । नन्ता नाग निरन्तर उनम हा मन्ताह नन्त र्ता ।

प्रश्न

- 1 सविनय अवज्ञा आन्तान्तन की वृत्तभूमि टिण्णता निविण ।
- 2 सविनय अवज्ञा आन्तान्तन क कायक्रम पर प्रकाश हानिण ।
- 3 गांधी अरविन समझौत पर टिण्णता निविण । म समझौत को पूरा तरन्त बना लागू नन्ता किया जा सका ?
- 4 विनाय गान मन्त सम्मन्तन क माधन जा मन्तयाएँ था न्तक विनय म काग्रम क दृष्टिकान का बन्ताप ।
- 5 टिण्णता निविण—
 - (i) साम्प्रदायिक पचा
 - (ii) पूना पैक
 - (iii) डांडा बाध ।

भारतीय शासन अधिनियम 1935 : कार्यान्विति

(GOVERNMENT OF INDIA ACT 1935 . AT WORK)

प्रमुख विशेषताएँ

भारतीय सावधानिक विकास के इतिहास में 1935 का भारतीय शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे विशाल कानून था। कुछ दृष्टियों से इसका विशेष महत्त्व भी है। मुख्यतया इसलिए कि स्वतन्त्र भारत के संविधान-निर्माताओं ने इस कानून से बहुत बातें ग्रहण की हैं और कुछ दृष्टियों से भारतीय संविधान इसी कानून की अनुकृति माना जाता है। यद्यपि इस कानून के अनुसार दस वर्ष तक भारत में ब्रिटिश सरकार शासन करती रही, तथापि वास्तव में इस कानून को केवल आंशिक रूप से ही लागू करने की स्थिति आई थी और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए। इस शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है

(1) भारत की पराधीनता पूर्ववत् बनी रही—यद्यपि यह अधिनियम एक विस्तृत सावधानिक प्रलेख के रूप में है, तथापि इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, जो कि भारत-राज्य की स्थिति का स्पष्टीकरण करती। यदि प्रस्तावना दी जाती तो उसमें भारत की औपनिवेशिक स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए था, जिसके लिए भारतीय नेतृत्व वर्षों से संघर्ष कर रहा था और ब्रिटिश सरकार इसका आश्वासन भी देती आ रही थी। परन्तु तत्कालीन टोरी शासक ऐसी घोषणा संविधान द्वारा करने तक को तैयार नहीं हुए। इस कानून ने 1919 के शासन सुधार कानून को निरस्त नहीं किया। अतएव 1919 के कानून में उल्लिखित प्रस्तावना ही इसके लिए भी लागू होती रही। इस दृष्टि से पूर्ण स्वराज्य तो दूर रहा, औपनिवेशिक स्वराज्य तक भारत के लिए स्वीकार नहीं किया गया और उत्तरदायी शासन की स्थापना भी पूर्व की भाँति शनैः शनैः लागू करने की नीति बनी रही, जिसका अन्तिम निर्णय ब्रिटिश संसद के हाथ में रहा। इस प्रकार इस कानून के अन्तर्गत भी ब्रिटिश समद की सर्वोच्चता बनी रही।

जिस समय ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को पारित किया था, उस समय टोरी नेता वाल्डविन ने घोषणा की थी कि 'यह मेरा विचारपूर्ण निर्णय है कि आज की इस विशाल दुनिया में समस्त परिवर्तनों तथा अवसरों के अन्तर्गत आपके पास भारत के उस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए साम्राज्य के अन्तर्गत रखने के उत्तम अवसर है।'¹ साथ ही चर्चिल तथा लायड जार्ज ने भी समद को बताया कि भारत स्वायत्त शासन के लिए अयोग्य है और केवल इसी आधार पर कि वहाँ के शिक्षित वर्ग के एक महत्त्वहीन अंग की आवाज पर इस दिशा में कोई विकास खतरे से खाली नहीं होगा। इसके विपरीत श्रमिक नेता ऐटली ने स्पष्ट किया कि 'भारत के उत्तमतर शासन के लिए कोई भी विधायन तब तक मन्तोपजनक नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय जनता की मदभावना तथा सहयोग को प्राप्त नहीं करेगा और जिसमें भारत की औपनिवेशिक स्थिति को मान्य नहीं किया जाता और उसमें इसकी प्राप्ति के प्राविधान नहीं किये जाते।'² ऐटली का तर्क था कि 1935 के शासन सुधार अधिनियम का आधारभूत सिद्धान्त अविश्वास है (The keynote of the Bill is mistrust)। इसके अनुसार जो रक्षा-कवचों की व्यवस्था कर दी गयी है वह

¹ Quoted by Tara Chand *op cit* 209

² *Ibid*

विवाद भी उत्पन्न हो सकते थे। अन्य सघो मे इन विवादो का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करने की परम्परा सबसे अधिक लोकतन्त्री मानी गयी है। परन्तु इस कानून के अन्तर्गत भारत के सघीय न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं थी। ऐसे विवादो तथा अवशिष्ट विषयो के अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवादो का निर्णय करने की शक्ति गवर्नर-जनरल को दी गयी थी।

(4) केन्द्र मे द्वैध-शासन-प्रणाली का आरम्भ—1935 के अधिनियम ने 1919 के सुधार कानून पर यही विकास किया कि प्रान्तीय द्वैध-शासन की व्यवस्था केन्द्र मे लागू कर दी गयी। प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, धार्मिक विषय तथा आदिवासी क्षेत्र सरक्षित विषयो के अन्तर्गत रखे गये। शेष विषय हस्तान्तरित माने गये। गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका मे पार्षद्गण उक्त सरक्षित विषयो के प्रभारी रहते और शेष विषयो का प्रशासन केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मन्त्रियो के हाथ मे रहता। परन्तु गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व इतने अधिक थे कि उनका अवलम्बन करते हुए वह सरक्षित एव हस्तान्तरित दोनो के शासन मे पूर्णतया हस्तक्षेप कर सकता था।

(5) प्रान्तीय स्वायत्तता—जैसा पहले कहा जा चुका है, 1935 का शासन अधिनियम आंशिक रूप से ही लागू हुआ था। इसकी सघ-व्यवस्था तथा केन्द्रीय शासन केवल अधिनियम तक ही सीमित रहे। व्यवहार मे उनका प्रयोग कभी नहीं हो पाया। 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता उसके द्वारा प्रान्तो मे द्वैध-शासन का अन्त करके स्वायत्त शासन की स्थापना करना थी। इस अधिनियम का यह भाग लागू हो गया। केन्द्रीय शासन अगस्त 1946 तक 1919 के कानून के अन्तर्गत ही चलता रहा। प्रान्तीय स्वायत्तता के अन्तर्गत भी गवर्नरो को इतनी विशाल तथा विशिष्ट शक्तियाँ दे दी गयी थी कि प्रान्तो मे उत्तरदायी शासन तथा स्वायत्तता नाममात्र की रह जाती। वास्तव मे इस कानून के निर्माता गवर्नरो को किसी भी रूप मे केवलमात्र वैधानिक प्रधान नहीं बनाना चाहते थे। अतएव प्रान्तीय शासन व्यवस्था न तो विशुद्ध रूप मे ससदात्मक हो पायी और न ही उसे सही माने मे उत्तरदायी कहा जा सकता है।

(6) रक्षा-कवचो की व्यवस्था—1935 के शासन अधिनियम की यह सबसे बड़ी विशेषता ह। इस अधिनियम को अन्तिम रूप देने से पूर्व ब्रिटिश अधिकारियो ने जिन सावधानियो को बरता उनका उल्लेख गत अध्याय मे किया जा चुका है। साइमन कमीशन, गोल मेज सम्मेलन, श्वेत-पत्र तथा सयुक्त ससदीय प्रवर समिति सभी ने ब्रिटिश साम्राज्यशाही, नौकरशाही, साम्प्रदायिकता (विशेष रूप से मुस्लिम साम्प्रदायिकता) तथा देशी नरेशो की प्रतिक्रियावादिता आदि का पूर्ण लाभ उठाकर भारतीय राष्ट्रीयता तथा स्वाधीनता की माँगो को ठुकराने मे कोई कमी नहीं रख छोडी थी। इसलिए इस कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सरचना इस रूप मे निर्मित करने की योजना रखी गयी थी कि जो कभी व्यवहृत ही न हो सके, और यदि हो भी जाय तो उसके अन्तर्गत गवर्नर-जनरल, भारत मन्त्री तथा ब्रिटिश ससद के अधिकारो को इतना सुदृढ बना दिया गया था कि राष्ट्रीय तत्त्व प्रभावहीन बने रहे। इसी प्रकार प्रान्तीय स्वायत्तता को प्रभावहीन करने के लिए गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल दोनो को ऐसे रक्षा-कवचो से युक्त कर दिया था कि प्रान्तीय स्वराज्य केवल नाम-मात्र की चीज रह जाती। इन रक्षा-कवचो के अन्तर्गत केन्द्रीय सरक्षित विषयो पर गवर्नर-जनरल की स्वविवेकी शक्ति, मन्त्रियो के अधीन (केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनो स्तरों मे) विषयो के सम्बन्ध मे गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरो के विशेष उत्तरदायित्व, अल्पसंख्यको, देशी नरेशो, लोक सेवाओ तथा ब्रिटेन के आर्थिक हितो के सम्बन्ध मे गवर्नरो तथा गवर्नर-जनरल को अपने 'व्यक्तिगत निर्णय पर' या अपने 'स्वविवेक पर' कार्य करने और भारत मन्त्री के आदेशो का पालन करने के लिए विवश रहने के प्राविधान इन रक्षा-कवचो के दृष्टान्त है। इनके अतिरिक्त शासन के दैनिक संचालन मे भी गवर्नरो तथा गवर्नर-जनरल को इतनी अधिक अविश्वसनीय, वितीय, विधायी तथा प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान कर गयी थी कि वे इन्हे मनचाहे ढंग से प्रयुक्त करके लोकतन्त्र के सीमित क्षेत्र को भी अवरुद्ध कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा

जो थोड़ी बहुत स्वायत्तता भारतवासियों को एक हाथ में दे दी गयी थी वह रक्षा-क्वच एपी डूमर हाथ में छान जा गयी।

(7) कुछ विशिष्ट संस्थाओं का सृजन—यहां अधिनियम के साथ भारत में रिजर्व बैंक, मंत्रालय, योजनाय तथा रेलवे स्टचुटरी आयोगों की स्थापना भी की गयी। यह संस्थाएँ हमें पूर्व विद्यमान नहीं थी।

निर्वाचन—यद्यपि कांग्रेस 1935 के अधिनियम में विस्तृत भी मत्तु नहीं थी तथापि उसमें यह अधिनियम का बहिष्कार तथा सरकार के साथ असहयोग करने की नीति नहीं अपनायी प्रत्युत यह निश्चय लिया कि हमें अंतर्गत निर्वाचना में भाग लेकर प्रांतीय स्वायत्त शासन की योजना को विफल नहीं किया जाय। अतः 1937 में जब निर्वाचन हुए तो उसमें कांग्रेस सहित अन्य सभी तथा वर्गों ने पूर्ण उत्साह के साथ भाग लिया। निर्वाचना के फलस्वरूप 6 प्रांत (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा) में कांग्रेस विधान बहुमत से विजयी हुई। बंगाल, असम तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में उस पूर्ण बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ किंतु वहाँ सबसे बड़ा बहुसंख्यक बन था। मिथुन में कांग्रेस की स्थिति अप्रसन्न थी। पंजाब में हिंदू मित्र तथा मुस्लिम संस्था की संयुक्त सरकार बनी।

कांग्रेस द्वारा पद ग्रहण—यद्यपि छ प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था तथापि कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार नहीं किया क्योंकि गवर्नर की विधि शक्तियों का दुरुपयोग कांग्रेस को यह भय था कि उत्तरदायी शासन तथा स्वायत्तता का गवर्नर अपनी शक्तियों के दुरुपयोग पर अंत कर देगे। गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि गवर्नर लोग यह आशय रखें कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग विधान प्रदान करने में करेंगे तो कांग्रेस मंत्रिमण्डल बन सकती है। परंतु गवर्नर हमें निराशा नहीं थे। अतः तीन माह तक प्रतिरोध बना रहा। हम बीच-बीच कांग्रेस बहुमत वाले प्रांतों में अंतर्गत बनाने का मंत्रिमण्डल बनाने का वार्ता किया। कांग्रेस का मत था कि ऐसी व्यवस्था अवधानिक है। या तो अपनी शक्तियों का आश्रय लेते हुए गवर्नर शासन बना सकते थे परंतु निश्चय ही वह नावधानिक भावना के विरुद्ध है और वह गवर्नरों को दिया गया आदेश पत्रों में भी संगति नहीं रखता। अतः जुलाई 1937 में गवर्नर जनरल लॉड रिजनिथम ने भारत मंत्री की अनुमति में एक वक्तव्य दिया जिसमें उक्त कहा कि गवर्नरों से यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि प्रांतीय शासन के अनिवार्य मामलों में वे अनावश्यक हस्तक्षेप करके प्रांतीय स्वायत्त शासन को अवरोध करेंगे। गवर्नरों के विधि शक्ति असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही हैं।

कांग्रेस हमें वक्तव्य में मत्तु हुआ गयी। वास्तव में हमें हमें कांग्रेस असहयोगी नहीं बनाना चाहती थी। वह प्रांतीय स्वायत्त शासन का वास्तविक स्वरूप जनता के अपने कार्यों से मत्तु करना चाहती थी। अतः जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार कर लिया। अंतर्गत बनाने मंत्रिमण्डल ने 'योगदान' दिया। छ प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बन गयीं। बांग्लादेश में असम तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में भी कांग्रेस के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल बन गये। मिथुन तथा पंजाब में कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनने का प्रयत्न नहीं था। मिथुन में मुस्लिम लीग का बहुमत था। बंगाल में विभिन्न वर्गों की शक्ति समान थी।

मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया—कांग्रेस की इस विजय में मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा घटना लगा। लीग के नेता जिन्ना का बड़ा निराशा था। यद्यपि मुसलमानों के लिए सुरक्षा के स्थानों की संख्या पर्याप्त अधिक थी और उनका निर्वाचन पृथक् निर्वाचन प्रणाली में हुआ था तथापि मुस्लिम स्थानों में लीग को बहुत कम स्थान मिले थे। कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने मुसलमानों का मंत्रिमण्डल में वितरित प्रतिनिधित्व दिया था। परंतु हमें मुस्लिम लीग का अंतर्गत नहीं हुआ। जिन्ना ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लीग का मिश्रित मंत्रिमण्डल बनाने की बातें प्रारम्भ कीं। लीग ने इन बातों स्वरूप पर ध्यान दिया। कांग्रेस केवल एक बात पर राजी थी कि मुस्लिम लीग विधानमंडल

मे पृथक् गुट के रूप में विद्यमान न रहे और न भविष्य में उसकी संसदीय बोर्ड किसी उप-चुनाव में पृथक् रूप से अपने उम्मीदवार खड़ा करे। लीग इसके लिए राजी न थी, न कांग्रेस ही किसी रूप में लीग के ऐसे रवैये से दबने की स्थिति में थी, क्योंकि उसे स्वयं ही पूर्ण बहुमत प्राप्त था। परिणाम यह हुआ कि फिर अन्य प्रान्तों में भी लीग के ऐसे प्रयास करने का प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि कांग्रेस की नीति स्पष्ट ही चुकी थी। इसलिए अब जिन्ना ने यह प्रचार आरम्भ किया कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है, कांग्रेस हिन्दुओं का दल है, कांग्रेस राज्य में मुसलमानों के हितों को संरक्षण नहीं मिल सकता, कांग्रेस मन्त्रिमण्डल वाले प्रान्तों में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, आदि। कांग्रेस ने इन सब आरोपों का न केवल खण्डन ही किया, बल्कि उसने लीग को स्पष्टतया कह दिया कि वह सभी न्यायालय द्वारा ऐसे आरोपों की जाँच कराये। संयुक्त प्रान्त के गवर्नर तक ने ऐसे आरोपों को निराधार बताया। लीग के पास चिल्लाने तथा झूठा प्रचार करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। स्पष्टतः लीग की इस निराशा के अन्तर्गत पाकिस्तान की माँग के अकुर विकसित हो रहे थे।

प्रान्तीय स्वायत्त शासन का मूल्यांकन

यह तो निश्चित था कि यदि गवर्नर लोग अपने विशेष अधिकारों का अवोचित प्रयोग करने लगते तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन काठ की हाडी मात्र रह जाता। यह भी निश्चित था कि गवर्नर-जनरल के आश्वामन के बावजूद सभी प्रान्तीय गवर्नर तदनुसार कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आश्वामन के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं थी, अपितु उसका उद्देश्य संसदीय अभिसमयों को विकसित होने का अवसर देना मात्र था। इसके विपरीत गवर्नरों की शक्तियों के पीछे सावधानिक शक्ति थी। यह भी निश्चित था कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल जब भी यह अनुभव करेंगे कि गवर्नर गवर्नर-जनरल के आश्वामन को ठुकरा रहे हैं, तो वे त्यागपत्र देंगे। परन्तु जब तक गवर्नर संसदीय शासन की सुमान्य परम्पराओं को अपनाते रहेंगे तब तक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल भी प्रान्तीय स्वायत्त शासन को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। इन विविध परस्पर विरोधी धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में छोटे-बड़े सफटों का उपस्थित होना स्वाभाविक बात थी। जहाँ कहीं गवर्नरों ने स्वविवेक शक्तियों का मनमाना प्रयोग किया, वहाँ कांग्रेस क्षेत्रों में असन्तोष होने लगा। उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में गवर्नर ने व्यवस्थापिका के एक विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। मध्य प्रान्त के गवर्नर ने एक मन्त्रिमण्डल को भग कर दिया था। परन्तु सबसे बड़ा असन्तोष तब उत्पन्न हुआ जबकि संयुक्त प्रान्त तथा बिहार के मन्त्रिमण्डलों ने राजनीतिक बन्धियों की रिहाई का प्रश्न उठाया। गवर्नर-जनरल के आदेशानुसार गवर्नरों ने उसे स्वीकार नहीं किया, कारण यह बताया कि ऐसा करना प्रान्त में शान्ति तथा व्यवस्था को बनाये रखने के गवर्नर के विशेष दायित्व के मार्ग में बाधक होगा। गवर्नर-जनरल का तर्क था कि एक प्रान्त का ऐसा निर्णय सभी प्रान्तों को प्रभावित करेगा। अतः इन दोनों प्रान्तों के गवर्नरों ने इसी आधार पर मन्त्रिमण्डलों के इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस हस्तक्षेप को देखकर इन मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसकी प्रतिक्रिया सभी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों वाले प्रान्तों में होती, परिणामस्वरूप प्रान्तीय स्वायत्त शासन ठप्प हो जाता। ब्रिटिश सरकार भी इससे कुछ व्यग्र हुई। अन्त में दोनों पक्षों के मध्य समझौता वार्ता द्वारा समस्या का हल निकाला गया और यह तय हुआ कि राजनीतिक बन्धियों की रिहाई प्रत्येक वैयक्तिक मामले के गुणावगुणों के आधार पर की जायेगी। इसी प्रकार उड़ीसा में एक अधीनस्थ अधिकारी को गवर्नर के पद पर नियुक्त कर दिये जाने से भी समस्या उत्पन्न हुई। परन्तु इसने स्थायी गतिरोध का रूप नहीं लिया।

संक्षेप में, कांग्रेस मन्त्रिमण्डल वाले प्रान्तों में जब भी गवर्नरों ने कहीं पर अवोचित रूप से हस्तक्षेप करना शुरू किया तो गतिरोध उत्पन्न हुए। परन्तु समग्र रूप में इन प्रान्तों के गवर्नरों ने

मनमाना हस्त पर वरुन का साहम नहा किया। उनकी स्थिति 'यूनाघिन' मात्रा में वधानिच प्रभाना का सी रहा। परन्तु सर ग्राग्रसा मन्त्रिमण्डला के प्राप्ता में गवर्नर का हस्त पर अधिक र्णा। पञ्जाब के गवर्नर न राजनानिक वदिया की रिहाई के प्रश्न पर बिना मुख्यमन्त्री की मनाह लिए अपनी दृष्टिकाण गवर्नर अनरर का भज लिया। 1939 में 'त्रि' काग्रम मन्त्रिमण्डला न त्रिटि गवर्नर की विश्व-युद्ध की नाति के विरोध में त्यागपत्र दे दिया तो गवर्नर न अधिनियम की धारा 93 के अंतगत वधानिकतन्त्र की विफलता धापित करते हुए 'गामन' अपने हाथों में ले लिया। अग्रे प्राप्ता के गवर्नर न मुर्ति नमस्ती के मन्त्रिमण्डला को बनाय रखा। यद्यपि के अन्तर्मुख्य दन थे तथापि अधिकांश काग्रमी मन्त्रियों के बदले किए जाने पर वे मन्त्रिमण्डल बन रहे मक्। 'म' दृष्टि न प्राप्तीय स्वायत्त 'गामन' के कार्यालयन में काग्रम मन्त्रिमण्डला के प्राप्ता में गवर्नर न अनावश्यक स्मरण की प्रवृत्ति छोड़कर उम सफर बनाने में बहुत योग दिया।

जहाँ तक जनप्रिय मन्त्रिमण्डला द्वारा प्राप्तीय स्वायत्त 'गामन' के कार्यालयन का सम्बन्ध था मन्त्रिमण्डला न उत्तरदायी समन्वय 'गामन' की सुमाय परम्पराओं का कार्यालयन में कोई कमी नहा था। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का बनाय रखा गया। मन्त्रिमण्डला के निर्माण में अन्तर्मुख्य का प्रतिनिधित्व दन का भी विचार ध्यान रखा गया। यद्यपि समान 'गामन' का परम्परा के विरुद्ध मन्त्रिमण्डला की प्रवृत्ति में गवर्नर सभापतित्व करते हैं और उनकी उपस्थिति राम नीतिशा के निर्माण में बाधक सिद्ध होती थी तथापि मुख्यमन्त्रियों की अनौपचारिक बैठकों का बुलाकर ठाम नियम न तत थे।

प्रान्तीय स्वायत्त 'गामन' की सफर कार्यावधि के निमित्त प्राप्ता में निम्नित सवा के उच्च पदाधिकारियों का महभाग जत्यत आवश्यक था। चूंकि गवर्नर को निम्नित सवा के अधिकारियों के निम्न का संरक्षण करने का विचार लायित्व दिया गया था जिसमें वे मन्त्रिमण्डल की सलाह को ठुकरा सकते थे जब यन्त्रि 'गमा' खयाल चरता रहता तो प्राप्तीय स्वायत्त 'गामन' असम्भव हो जाता। उत्तरदायी 'गामन' के अंतर्गत निम्नित सवा के 'गामन-मन्त्रियों' तथा विभागीय अधिकारियों को मन्त्रियों के अधीन कार्य करना आवश्यक था। त्रिटि 'गामन' के अंतर्गत स्वच्छाचारिता स कार्य करने वाली नौकरगाही को जनप्रिय मन्त्रिमण्डला के अधीन कार्य करने में बड़ा सहायक बन गया था। यद्यपि साविधानि अधिनियम में उनका हिता का पर्याप्त संरक्षण प्राप्त था तथापि वे 'गमी' 'गामन-व्यवस्था' के प्रचलन का सहन नहा कर पाय। कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने काग्रसी नताओं के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में अनुचित व्यवहार किया था। अब जब उन्हें उहा नताओं के अधीन कार्य करना था तो उन्हें सहायक तथा भय दाता थे। 'म' कुछ अधिकारियों ने तो त्यागपत्र दे दिए थे। कुछ 'म' भी तत्त्व थे तो प्राप्ताय स्वायत्त 'गामन' की सफलता का अवरोध करने के लक्ष्य से अजन्तयोग तथा सक्ता की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही शासनिक पदा पर बन रहे। समुक्त प्राप्ता में 'गमी' स्थिति उत्पन्न हुई 'त्रि' 'गामन' के मुख्य सचिव न अधीनस्थ अधिकारियों के नाम पर प्रपत्र भेजकर यह मांग की कि वे शासन सचिवों के प्रति-हस्ता र्ण से विहात जिम्मा आग्रह का कार्यालयन न करें। मुख्यमन्त्री पण्डित साविन्वन्तभ पत को जब यह पान हुआ तो उन्होंने मुख्य सचिव में आग्रह मांगा और उमके आग्रह की तीव्र भस्मना की। परिणामस्वरूप वे आग्रह निरस्त कर दिया गया। इस घटना न समुक्त प्राप्ता में हा नहा अतितु अन्य सभी प्राप्ता के लिए एक घातक प्रवृत्ति किया। अविष्य में नौकरगाही न 'गमा' खयाल छोड़कर मन्त्रियों के साथ महभाग में कार्य करना प्रारम्भ कर लिया।

यद्यपि प्राप्तीय स्वायत्त 'गामन' कबन 'मगभग' रूप के अवधि तक हा चला क्योंकि मिनस्वर 1939 में काग्रम मन्त्रिमण्डला न प्रान्तीय विरुद्ध छिन्न पर त्रिटि गवर्नर 'मग' युद्ध में भारत का भी एक पण धापित करने की नाति के विरोध में त्यागपत्र दे दिए थे तथापि इस अन्तर्मुख्य में काग्रम मन्त्रिमण्डला न प्राप्तागति तथा सातकन्त्यापारा कृत्या के क्षत्र में जो उपनिषदा के उनका गराहना त्रिटि अधिकारियों तथा आशाचर नक न की है। मगभग मनी

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो वाले प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा, ग्राम-विकास, पंचायतो के विकास, उद्योग, नशाबन्दी, कृषि, भूमि-सुधार, श्रम, दलित वर्गों के सुधार आदि के सम्बन्ध में ठोस कार्य किये गये। राजनीतिक दन्दियों की रिहाई पर भी कदम उठाये जाने लगे। बम्बई तथा मद्रास की सरकारों ने भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के मध्य लोगों से छीनी गयी सम्पत्ति की वापसी के सम्बन्ध में कानून बनाये। सयुक्त प्रान्त तथा बिहार की सरकारों ने ग्राम-सुधार योजना को बहुत व्यापक बनाया और ग्रामोत्थान के कार्यों से जनता के मध्य पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की। अक्टूबर 1939 में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलियगो ने भी इन प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों के कार्यों की बहुत सराहना की थी। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने गैर-कांग्रेसी प्रान्तों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इन मन्त्रिमण्डलों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय नेता स्वराज्य के लिए केवल चिल्लाते ही नहीं हैं, जवितु भारतवासी ही स्वयं अपने देश की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने की पूर्ण प्रगासनिक क्षमता रखते हैं, जो कि विदेशी शासकों की क्षमता से परे की चीज है। इन मन्त्रिमण्डलों ने एक और उत्तम उदाहरण यह प्रस्तुत किया कि मन्त्रिगण उतना ही वेतन लेंगे जितना कि भारत सदृश गरीब देश के लिए उचित है। सयुक्त प्रान्त में मन्त्रियों का वेतन केवल 500 रुपए मासिक तय किया गया था। इस अल्प अवधि में भारतीय नेताओं को प्रशासन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिला। इससे कांग्रेस की लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। अंग्रेज भले ही स्पष्टतया कहने में हिचके, परन्तु उन्हें यह समाधान पूर्णतया हो गया कि भारतवासी स्वशासन की पूरी क्षमता रखते हैं।

प्रान्तीय स्वायत्त शासन तथा मुस्लिम लीग—यद्यपि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अन्तर्गत अप्रैल 1937 से प्रान्तीय स्वायत्त शासन लागू हो गया था और जुलाई 1937 से छह प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल कार्य करने लग गये थे, तथापि भारतीय राजनीति और स्वतन्त्रता आन्दोलन में जहाँ एक ओर कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने सराहनीय ढंग से शासन-कार्य सम्भालकर ब्रिटिश शासकों की इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया था कि भारतवासी स्वायत्त शासन के अयोग्य हैं, वहाँ कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों की इस प्रतिष्ठा ने साम्प्रदायिक मुसलमानों तथा अंग्रेज शासकों दोनों को भारी आघात पहुँचाया। इसके अत्यन्त दूरगामी प्रभाव हुए। अब ब्रिटिश शासक कांग्रेस की लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए पुनः साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करने लगे। जैसा पहले कहा जा चुका है, मुस्लिम लीग को 1936-37 के चुनावों में जो निराशा हुई थी, उसके बावजूद उसके नेता जिन्ना ने यह प्रयास किया कि लीग के निर्वाचित सदस्यों को प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों में स्थान मिलना चाहिए। विशेष रूप से सयुक्त प्रान्त में लीग ने इस दिशा में भरसक प्रयास किया था। निर्वाचन अभियान की अवधि में कांग्रेस तथा लीग के मध्य भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य दिशाओं में कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं था। कांग्रेस ने भी लीग के उम्मीदवारों के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किये थे और लीग के विरोध न करने में कांग्रेस को भी अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को विजयी बनाने में सफलता मिली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने लीग को यह आश्वासन दिया था कि यदि उसे बहुमत प्राप्त हो गया तो वह लीग के दो सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में लेगी। परन्तु जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया और जिन्ना ने कांग्रेस से सयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने की पेशकश की तो कांग्रेस का दृष्टिकोण बदल गया। वह अबिक से अधिक केवल एक सदस्य खालिकुज्जामन को लेने को राजी थी।¹ बाद में जिन्ना व खालिकुज्जामन के बहुत आग्रह करने पर जो शर्तें लीग को लेने की रखी गयी, उनका स्पष्ट जर्ज्य यही था कि सयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग अपना अस्तित्व ही खो देती। जिन्ना ऐसे जोखिम के लिए तैयार नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुलकलाम अजाद तथा सयुक्त प्रान्त के मुख्यमन्त्री पंडित गोविन्दवल्लभ पंत ने जिन्ना तथा खालिकुज्जामन ने अनेक तक-विनर्क

मुस्लिम सदस्यों का समर्थन मिलने लगा। यही स्थिति पंजाब में रह गयी जहाँ सरकार का विरोध हिन्दू सदस्यों तक सीमित रह गया। अन्यत्र भी मुसलमान सदस्य कांग्रेस-विरोधी होने लग गये। ब्रिटिश सरकार तो ऐसी प्रतीक्षा कर ही रही थी। आज तक एकमात्र प्रबुद्ध तथा सुयोग्य मुस्लिम नेता जिन्ना ब्रिटिश शासकों के अन्ध-समर्थकों में से नहीं थे। अब वही एकमात्र वास्तविक मुस्लिम नेता थे और वे भी ब्रिटिश शासकों के हित में कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो चुके थे। इसका लाभ अन्त तक अंग्रेजों ने भरपूर उठाया। इस प्रकार 'यह राजनीतिक अदूरदर्शिता तथा ब्रिटिश शासकों की कांग्रेस के प्रति घृणा जिन्ना के भारत के भविष्य का एकाएक निर्णायक बन जाने के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुए।'।

कांग्रेस दल में दरार—1937-39 की अवधि में यद्यपि कांग्रेस दल को प्रान्तीय स्वायत्त शासन का संचालन करने के फलस्वरूप पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, तथापि दो घटनाएँ ऐसी हुईं जिनके कारण कांग्रेस को भारी हानि हुई और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के संचालन में उनके दूरगामी प्रभाव हुए। इनमें से एक घटना, जिसका संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, मुस्लिम लीग का कांग्रेस-विरोधी हो जाना था, और दूसरी घटना स्वयं कांग्रेस दल के अन्दर नेतृत्व में फूट का आ जाना था।

कांग्रेस के नेतृत्व के अन्तर्गत युवा-वर्ग कुछ वामपंथी विचारों का था। यह वर्ग गांधी जी की अहिंसा की राजनीति पर विश्वास नहीं करता था। साथ ही यह गांधी जी की प्राचीन भारतीय आदर्शवादी परम्पराओं को भी उपयुक्त नहीं मानता था। इसके ऊपर पाश्चात्य देशों के क्रान्तिकारी नेताओं तथा उनके आदर्शों का प्रभाव अधिक था। ब्रिटिश साम्राज्यशाही की पराधीनता से देश को मुक्त कराने के निमित्त वह कड़े संघर्ष पर अधिक विश्वास रखता था। उसमें रूसी क्रान्ति का भी प्रभाव था। पंडित नेहरू तथा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस इस वर्ग के प्रमुख नेता थे। परन्तु नेहरू जी गांधी जी के प्रभाव में बहुत अधिक आ चुके थे, जबकि बोस गांधी जी के प्रभाव से लगभग मुक्त थे। नेहरू व बोस दोनों असहयोग आन्दोलन की अवधि में कांग्रेस में आये थे। बोस ने आई० सी० एस० से त्यागपत्र दे दिया था। वे प्रारम्भ से ही क्रान्तिकारी विचारों के थे। जब गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित किया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन की अवधि में वे वियना में अपनी बीमारी का इलाज कराने गए हुए थे। जब उन्होंने सुना कि गांधी जी ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया है तो वे बहुत क्रुद्ध हुए। उस समय केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल भी वही थे। दोनों ने गांधी जी के इस निर्णय की भर्त्सना की और गांधी जी को असफल राजनीतिज्ञ कहा। सुभाष बोस संघर्ष की राजनीति पर विश्वास करते थे। उनका मत था कि भारत की 35 करोड़ जनता संघर्ष द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। 1935 में अपने प्रवास में उन्होंने *The Indian Struggle* लिखी जिसे भारत सरकार ने जप्त कर दिया। 1936 में जब वे भारत लौटे तो उन्हें तुरन्त नजर-बंद करके अपने भाई के घर पर ही रख दिया गया। परन्तु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

सुभाष बोस कांग्रेस को पुनर्गठित करके उसमें नवीन नेतृत्व भरना चाहते थे जो संघर्ष की राजनीति अपनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो सके। 1937 में जब कांग्रेस ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन के अन्तर्गत पद ग्रहण कर लिया तो गांधी जी की इच्छा हुई कि युवा नेता बम को किसी ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाय जहाँ पद के दायित्वों से ढक जाने के कारण उनके उग्र विचारों को उद्धार बनाने का अवसर मिल सके। अतः 1938 में सुभाष बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। पद ग्रहण करते ही सुभाष बोस ने घोषणा की कि वे कांग्रेस का निदेशन इस रूप में करेंगे जिससे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गयी संघ-व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया जायेगा। इसमें सभी शान्तिपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण साधन अपनाये जायेंगे, आवश्यकतानुसार अहिंसात्मक असहयोग भी काम में लाया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन, एकता तथा जनता को संघर्ष के लिए तैयार करने की योजनाओं पर बल दिया। वे भारी औद्योगीकरण की

नीति के समर्थक थे। ब्रिटिश शासक उनकी नीतियाँ सन्तुष्ट होकर हान नग क्याकि सरकार के प्रति उनका विरोध रखा तात्पर्य हान नगा था। वास यूरोपीय राजनीति को भली भाँति समझते थे। उन्हें पूर्ण आभास हो गया था कि गांधी ही यूरोप में भारी युद्ध छिड़ेगा। अतः उस समय भारतवासियों का भी अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का तयार रहना पड़ेगा। उनकी न नीतियाँ में कांग्रेस का पुराना नतत्व जो गांधी जी की शिक्षा का प्रति निष्ठावान था परणाना में पड़ गया। 1939 में जब नये कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न आया तो गांधी जी ने पद्मभि सोनारामया को उम्मीदवार चुना। दूसरी ओर सुभाष दास को पुनः निर्वाचित करने के समर्थक भी थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वाम के मुत्सद्दिन सोनारामया का पणजय का सामना करना पड़ा। उसमें गांधी जी उन्ने विजय हुए। वास के नतत्व में 10 मार्च 1939 को कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को अटीमटम भेजने का प्रस्ताव दिया कि वह 6 मास के अन्दर भारत का पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर अन्यथा राष्ट्रीय संघर्ष की तयारी का जाय। उस पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों में उन्नी खतराती मच गयी।

वाल् में सुन अधिवेशन में गांधी जी के समर्थक यह प्रस्ताव पाम करा जतन में सफल हो गया कि कांग्रेस अपने जावन की नन्ही अवधि में अपनाय गये साधना का ही प्रयोग करेगी। साथ ही प्रस्ताव दिया गया कि कांग्रेस कार्यकारिणी का भविष्य में गांधी जी का निम्न स्वीकार करना चाहिए और अध्यक्ष का तदनुसार कार्यकारिणी का चयन करना चाहिए। सुभाष दास के लिए यह एक भारी चुनौती थी। स्पष्टतः कांग्रेस के नतत्व में दरार पड़ गया। समझौते के सभी प्रयास निष्फल हुए क्योंकि गांधी जी तथा वाम में से कोई भी अपने निश्चया में झुक्ने को तयार न थे। परिणामस्वरूप वाम ने अध्यक्ष पद में त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर डा. राजेन्द्र प्रसाद का कांग्रेस का अध्यक्ष चुन दिया गया। सुभाष वाम ने कांग्रेस से त्यागपत्र दकर नया दल पार्लामेन्ट में बना दिया। यद्यपि डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कार्यकारिणी का निर्माण किया तथापि ऐसे अवसर पर जबकि विश्व के समस्त एक मन्तव्य विपत्ति आन गाने थी और कांग्रेस के अन्दर एकता एक भारी आवश्यकता थी वाम का कांग्रेस से पृथक् हो जाना भारी दुर्भाग्य की बात थी। 1939 के वाल् के घटना चक्र में कांग्रेस में सुभाष बोम का अनुपस्थिति के कारण सादालन में भारी रिकतना आ गयी जसा कि राष्ट्रीय आन्दोलन की भावी घटनाओं में स्पष्ट होगा।

प्रश्न

- 1 1937 के उपरांत प्राला में लागू किए गए स्वायत्त शासन का अन्वयन कीजिए।
- 2 प्रांतीय स्वायत्त शासन प्रणाली के प्रति मुस्लिम लीग का क्या रुख था? आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
- 3 लगे मन्तव्य के आरम्भ पर कांग्रेस मंत्रिमहस में क्या त्यागपत्र दिया? उनके त्यागपत्र की क्या प्रतिक्रिया हुई और उसमें उत्पन्न अनिश्चय को दूर करने के लिए क्या किया गया?

द्वितीय विश्वयुद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन (NATIONAL MOVEMENT AND WORLD WAR II)

द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ—जब भारत में प्रान्तीय स्वायत्त शासन का प्रयोग चल रहा था तो यूरोप द्वितीय विश्वयुद्ध की तैयारी में था। जर्मनी में नाजीवादी तथा इटली में फासीवादी अविनायकतन्त्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुके थे। 1935 में इटली ने अवीमीनिया पर आक्रमण करके विश्व को चेतावनी दे दी थी। इससे पूर्व जब 1937 में जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण किया था तो भारत सरकार ने चीन में भारतीय सेनाएँ भेज दी थी। इस पर कांग्रेस ने यद्यपि जापान के चीन पर आक्रमण की निन्दा की, तथापि भारत सरकार को भी चेतावनी दे दी थी कि विना भारतवासियों के परामर्श के सरकार यदि भारतीय मानव-शक्ति का इस प्रकार अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोषण करेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने एकाएक पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया। 3 सितम्बर 1939 को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड, फ्रांस आदि मित्र-राष्ट्रों का दावा था कि वे लोकतन्त्र की फासीवादी अधिनायकवाद से रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहे हैं। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भारत को भी एक पक्ष घोषित करके भारतीय सैनिक टुकड़ियों को पश्चिमी एशिया के देशों में भेजना शुरू कर दिया। साथ ही भारतीय शासन अधिनियम में संशोधन करके भारत-स्थित ब्रिटिश नौकरशाही को युद्ध-प्रयागों के हेतु विशाल आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान कर दी। सध-व्यवस्था को लागू करने का प्राविधान स्थगित कर दिया गया था।

युद्ध के प्रति कांग्रेस का रुख—यद्यपि कांग्रेस फासीवादी साम्राज्य तथा अन्य सभी प्रकार की सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के विरुद्ध थी, तथापि वह लोकतन्त्री साम्राज्यवाद के भी विरुद्ध थी। ब्रिटिश सरकार एक ओर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का उद्देश्य लोकतन्त्र की रक्षा कहती थी, दूसरी ओर भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में किसी भी प्रकार के लोकतन्त्री अधिकार देने में निरन्तर उदासीन बनी रही थी। भारत के ब्रिटिश शासक युद्ध छिड़ने से पूर्व युद्धकाल में कांग्रेस के सम्भावित रुख के बारे में विचार करने लग गए थे। युद्ध छिड़ते ही भारत रक्षा कानूनों के अन्तर्गत कांग्रेस के विरुद्ध रणनीति की भूमिका बना चुके थे। कांग्रेस भी स्पष्टतया घोषित कर चुकी थी कि उसकी राय लिए बिना भारत को युद्ध में एक पक्ष घोषित करना अनुचित होगा। परन्तु कांग्रेस की शक्ति को कुचल देने पर तुली हुई सरकार ने कांग्रेस के नेताओं की एक न सुनी। 8 अक्टूबर 1939 को वाडमराय ने कुछ सुविधाओं की घोषणा की। सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वह केन्द्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करेगी, सरकार को युद्ध-कार्यों में सलाह देने के लिए एक युद्ध-परिषद् का निर्माण करेगी, और युद्ध समाप्त होते ही नए संविधान का ढाँचा तैयार करने के लिए एक निकाय की स्थापना करेगी। 17 अक्टूबर 1939 को यह देखते हुए कि कांग्रेस को उपर्युक्त सुविधाएँ जमान्य हैं यह आश्वासन दिया गया कि सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि वह 1935 के कानून में भारत के दलों तथा हितों से परामर्श करके युद्ध समाप्त होने पर संशोधन पर विचार करेगी। कांग्रेस या लीग कोई भी ऐसे आश्वासनों से सन्तुष्ट नहीं थी। अतः ब्रिटेन द्वारा युद्ध की घोषणा करते ही कांग्रेस कार्य समिति ने ब्रिटिश सरकार से यह माँग की कि यदि वह फासीवाद के विरुद्ध तथा लोकतन्त्र की रक्षा के निमित्त युद्ध में भागत्वामियों के

मन्थान तथा मन्थयता का रूप । करता है ता उस स्पष्ट पन्ना में यह घोषणा करना चाहिए कि हमका भारत के प्रति दायित्व तथा साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में क्या उद्देश्य है । 15 सितम्बर 1939 तक कांग्रेस मन्थनमिति ने समस्या पर विचार करके त्रिनिदाद सरकार से यह मांग की कि वह स्पष्टतः यह घोषणा करे कि युद्ध के दाम्निविक उद्देश्य क्या है और त्रिनिदाद भारत का भविष्य क्या होगा क्यारि यदि युद्ध का उद्देश्य भारत में यथस्थिति बनाये रखना है ता भारत का युद्ध में क्या प्रयोजन होगा ? यदि त्रिनिदाद सरकार सच्चे भाव से तथा स्पष्ट पन्ना में ऐसा दायित्वमान है तब ता कांग्रेस चाहता कि वह अधिनायकता के सिद्ध मित राष्ट्रा का युद्ध में भारत की शान्त में यह प्रकार मन्थयता है कि कार्य में लग जाता जसा कि उसने प्रथम विश्वयुद्ध का अवधि में किया था । परन्तु त्रिनिदाद सरकार ऐसा करने में उत्तम सक्षमता ।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डली का त्यागपत्र—कांग्रेस की इन मांगों के उत्तर में गवर्नर जनरल ने भारतवासी नतामणों से जाना कि और यह वक्तव्य दिया कि भारत के विभिन्न वर्गों में एक के भावों साविधानिक स्वरूप के बारे में मतभेद नहीं है त्रिनिदाद सरकार भारत का जीवनविविध स्वतन्त्रता देना अपना नय मानती है । इन युद्ध समाप्ति के पश्चात् भारत के विविध वर्गों तथा सम्प्रदायों में परामर्श करने के उपरान्त 1935 के अधिनियम की परिखर्तित करने के निमित्त उत्तम प्रयास जायेंगे । युद्ध समाप्ति के पश्चात् गवर्नर जनरल विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों का परामर्शान्त्री युद्ध निमित्त करने का तयार है । गवर्नर जनरल ने इस वक्तव्य में कांग्रेस का धारा में पूर्ण निराशा व्यक्त की । इस पूर्व गांधी जी का राजपत्र प्रसार तथा पत्र नम्बर का मरायम मित 4 । परन्तु 17 अक्टूबर 1939 की रात्रमराय की उत्त घोषणा पर प्रतिप्रिया व्यक्त करते हुए गांधी जी ने कहा कि यह श्रवण निराशाजनक था इसका अर्थ युद्ध के बाद पुनः एक ऐसा राज मज सम्भवतः न बुलाना होगा जो निश्चय ही असफल होगा । यह प्रसार न भी यही निष्कर्ष निराना कि त्रिनिदाद सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । हम ही विचार नम्बर जा तथा मद्रास जा न भी थे । इसी स्थिति में कांग्रेस का प्रतीत हुआ कि उसकी मांगों के उत्तर में त्रिनिदाद सरकार दाम्निव में कुछ भी नहीं देना चाहती अपितु भारत में पुनः फूट पड़ना और शासन करी की नीति अपना रही है । कांग्रेस का त्रिनिदाद शासन का प्रथम विश्वयुद्ध के बाद का नाति का बहुत अनुभव न हुआ था । इस पर 22 अक्टूबर 1939 का कांग्रेस कार्य समिति ने प्रान्तीय कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र देने का आदेश दिया । तत्पश्चात् तब कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र देने की गवर्नर ने 1935 के शासन अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत साविधानिक विफलता का घोषणा करके प्रान्तों के शासन का अपने हाथों में ले लिया । इस प्रकार प्रान्तीय स्वायत्त शासन का अन्त होकर पुनः स्वतन्त्राचारितावादी शासन शुरू हो गया ।

गवर्नर जनरल के उत्त वक्तव्य तथा कांग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र देने का तात्पर्य मुख्यतः नीति उठाने की थी । जिन्ना ने घोषणा की कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र में मुख्यतः मांगों के ऊपर हिन्दूओं के अत्याचारों का शासन का अन्त हो गया है । इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने राजपत्र प्रसार न जिन्ना का चुनौती दी कि न भारत के मध्याय यायाय के मुख्य यायाधीश से यह और कहा कि कांग्रेस शासन समुत्तमानों के लिए क्या तब अत्याचार था । परन्तु जिन्ना का ऐसा माहम कहा था ? जब से वह कांग्रेस में स्पष्ट होकर तथा अपने पक्ष के विचारों जान्ते तथा उद्देश्यों का भूतकर पक्के मुख्यतः सम्प्रदायवादी बन चुके थे तब से वह त्रिनिदाद शासन के अत्याचार पर कांग्रेस के विरुद्ध नाहन लग थे । परन्तु त्रिनिदाद सरकार भी जब जिन्ना का मांग को भारत की सम्पूर्ण मुस्लिम जनता की मांगों का बर्णना मानकर भारत की किमा भा स्वतन्त्रता या स्वायत्तता की मांग को ठकुरा नगा था । इस समय समस्या यही थी कि त्रिनिदाद सरकार युद्ध प्रयासों में कांग्रेस तथा उसके माध्यम से सम्पूर्ण भारत का जनता का मन्थान चाहते कि लिए वजाय अध्यात्मों द्वारा शासन चरान के कांग्रेस का जीवनविविध स्वतन्त्रता की मांग का स्वाकार पर नही और भारतवासी शासन में कानून में सम्मिलित गणमान्य करके भारतीय स्वायत्तता के सम्बन्ध

मे एक कदम आगे बढ़ जाती। ब्रिटिश शासको की यह धारणा निर्मूल थी कि ऐसा करने से मुस्लिम वर्ग को असन्तोष होगा। यह तो केवल टालने का बहाना था। वास्तव में स्थिति यह थी कि जिन्ना को छोड़कर अन्य कोई भी मुस्लिम नेता (फजलुल हक, सिकन्दर हयात खाँ या सिन्ध तथा असम के मुख्यमंत्री) सरकार के विरुद्ध नहीं होते। जमायत-उल उलेमा भी जिन्ना के विरुद्ध थी। 1939 में भारतीय मुसलमान खिलाफत जैसी किसी प्रेरणा में अंग्रेज विरोधी नहीं थे। मिस्र, ईराक तथा टर्की सदृश मुस्लिम देश अंग्रेजों की ओर थे। अतः भारत के मुसलमान अंग्रेजों का साथ देते।¹ परन्तु ब्रिटिश शासको ने हठधर्मिता से ही काम किया।

यद्यपि कांग्रेस मन्त्रिमण्डली ने त्यागपत्र दे दिया था, तथापि कांग्रेस ने युद्धकाल के लिए अपना कार्यक्रम निश्चित नहीं किया था। वह अब भी सरकार के साथ समझौता-वार्ता करती रही। स्वयं भारतीय नेतृत्व युद्ध की अवधि में ब्रिटिश रवैये तथा युद्ध सम्बन्धी विषयों पर अपनी नीति सुनिश्चित करने में एकमत नहीं था। सुभाष बोस का मत था कि भारत का एकमात्र उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्त करना तथा अंग्रेजों की साम्राज्यशाही को समाप्त करना था। अतः भारत को इस अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की परेशानी का लाभ उठाकर किसी भी साधन से स्वतन्त्रता प्राप्त करनी चाहिए। इसके विपरीत प० नेहरू जहाँ भारत की स्वतन्त्रता के लिए चिंतित थे, वहाँ वे मित्र-राष्ट्रों के युद्ध के आदर्शों स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र तथा मानवतावाद के साथ भी सहानुभूति रखते थे। इसलिए वे चाहते थे कि मित्र-राष्ट्र होने के नाते इंग्लैंड भारत के सन्दर्भ में भी युद्ध के उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करे। गांधी जी किसी प्रकार की सौदेबाजी के पक्ष में तो नहीं थे, प्रत्युत वे फासी तथा नाजी नीतियों से घृणा करते थे और ब्रिटेन के साथ समझौता करके समस्या के समाधान के लिए उत्सुक थे। उधर मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने अपनी माँगों का जो हठीला रुख अपना लिया था, उसी को ब्रिटिश शासको ने प्रमुखता दी और कांग्रेस के साथ भारत की साविधानिक स्थिति के बारे में कोई भी निश्चित घोषणा करने के मार्ग में बाधा डालने के निमित्त लीग की माँगों पर अड़े रहे। इंग्लैंड का रवैया यही बना रहा कि मानो भारत की साविधानिक समस्या के हल के ठेकेदार वे अंग्रेज ही हैं। इसके विपरीत गांधी जी का मत था कि इंग्लैंड भारत को स्वतन्त्र कर दे और भारतवासी अपनी साविधानिक समस्याओं से स्वयं निवट लेंगे। परन्तु ब्रिटिश अधिकारी अपने साम्राज्यवादी को भारत में बनाये रखने के इच्छुक होने के कारण भारत की स्वायत्त शासन की किसी भी माँग के निमित्त मुस्लिम साम्प्रदायिकता, देशी नरेशों के हितों आदि को तूल देकर उसे अस्वीकार करते गये और सारा दोष कांग्रेस को देते रहे। अतः कांग्रेस तथा सरकार के मध्य किसी समझौते के सभी द्वार बन्द थे।

युद्ध का प्रसार तथा भारत की समस्या—ब्रिटिश सरकार को दो युद्धों का सामना करना पड़ रहा था—भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा यूरोप में नाजीवाद के विरुद्ध। प्रथम को वह टालमटोल तथा शक्ति के बल पर दबा लेने की स्थिति में थी, परन्तु यूरोप में हिटलर की बढ़ती हुई शक्ति उनके लिए भारी चिन्ता का विषय थी। 1940 में यूरोपीय युद्ध तीव्रता से बढ़ रहा था। हिटलर ने यूरोप के एक के बाद दूसरे राष्ट्र को हड़पना प्रारम्भ कर दिया था। जब उसने नार्वे, स्वीडन को झुगड़ लिया और फ्रांस को भी दबा लिया तो मई 1940 में ब्रिटिश संसद में टोरी नेता ऐमरी ने प्रधानमंत्री चैम्बरलेन से इंग्लैंड की इन राष्ट्रों को बचा सकने में असमर्थता के लिए त्यागपत्र की माँग की। परिणामस्वरूप चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया और उसका स्थान कट्टर तथा दृढ़प्रतिज्ञ टोरी नेता चर्चिल ने लिया। चर्चिल के प्रधानमंत्री बनने पर जेटलैंड के स्थान पर ऐमरी ने भारत मन्त्री का पद सम्भाला। पिछले टोरी नेताओं की तुलना में ये दोनों नेता भारत की स्वतन्त्रता की माँग के कट्टरतम शत्रु थे और किसी भी कीमत पर भारत की ऐमी

¹ Tara Chand, *op cit* 295-96

भाग क निमित्त जरा भर भा मुकन का जाणा इनम नहा थी ।

युद्ध की गति साब्र हाना गया जमना न आ बोच हम व साथ युद्ध-वजन सवि कर ना थी । यह ब्रिटेन के लिए और अधिक मतलबी सी बात था । धुरी शक्तिया उत्तर अफ्रीका मध्य एशिया तथा पश्चिम यूरोप क दबा म द्या गयी था स्वयं एंग्लो म नाजी बमबारा गुरू हा गया थी । 1941 का वर्ष युद्ध म इंग्लैंड क लिए महायुद्ध सिद्ध हाना गया । जमनी न विजय क नग म चूर हाकर हम क ऊपर भी आक्रमण कर लिया । जमनाका एंग्लैंड का सहायता दन क लिए आगे आया । मुद्दू पूर्व म जापान भा धुरी राष्ट्र क प म युद्ध म कूट पन और शीघ्र ही दक्षिण पूर्व एशिया क दशा का अपना निगाना बनाकर वह भारत की साम्राज्य का आरंभ गया था । जमनीका तथा ब्रिटेन न एतनाटिक चाटर पर हस्ताक्षर करके युद्ध म नाजी शक्ति क विरुद्ध मार्च बना लिया था । हम भी जय मित्र गण्टा म मिन गया था । जमनीका का जब एतनाटिक व प्रगति मन्तासागर स हाकर जमना तथा जापान दोनों स मुकाबिला करना था । यदि यूरोप म नाजी व फासी शक्तिया नष्ट न जाता तो जापान अकन पन जाता और उस नष्ट करना मित्र गण्टा क लिए बठिन न हाना एसा ब्रिटेन का अनुमान था । परन्तु जब जापान पूर्व स भारत क द्वार सटखटाना गया और भारत म राष्ट्रीय नेताजा का ब्रिटिश सरकार क साथ असहयोगपूर्ण खया बना आ था साथ ही भारत क प्रसिद्ध आतिशारी नना मुभाष वाम धुरी राष्ट्र म मिनकर अग्रजा क विरुद्ध माचा नन की याजना बना चुके थे । ना अत्र ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत की प्रतिरक्षा क निमित्त भारतीय नेताजा क साथ सहयोग करने की आर गया । यद्यपि यह प्रयास दिखाव का हा था और ब्रिटिश शासक न उसके प्रति कोई ईमानदारी नही दिखायी तथापि इसक दूरगामी प्रभाव हुए जिनका अपना ब्रिटिश नामक नहा करने थे । डा नारायण क गान्धी म युद्ध का यह असर चरण ब्रिटिश सरकार क मिर क ऊपर आकराज का तनवार की भांति नटक रहा था जा भारत क सम्मुख विभाजन का धमकी क रूप म था ।

अगस्त 1940 का प्रस्ताव

कारण—जमा ऊपर कहा जा चुका है जब नाजी विजया न परिणामस्वरूप एंग्लैंड भाग सक्त म पडन गया तो एंग्लैंड म यह अनुभव किया गया कि युद्ध प्रताप का मुहूर्त करने क लिए सरकार म नृत्व बचनन की आवश्यकता है । अतः चम्बरलैन क स्थान पर चर्चिन का प्रधानमन्त्रा बनाया गया और नय मन्त्रिमण्डल म एमरा का भारत मन्त्री का पद मिला । य दोनों व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद क पक्क समर्थन तथा भारत का स्वतंत्रता क बटूर विरोध था । एतनाटिक चाटर क एक प्रमुख हस्ताक्षरकता क रूप म भी चर्चिन ने कहा कि यह चाटर (जा कि स्पष्टतया किन्ही नामन तथा आक्रमण क विरुद्ध गण्टा का स्वायत्त शासन प्रदान करने की घोषणा करता था) भारत या ब्रिटिश साम्राज्य क अधिन आ पर लागू नहा हाना । एसा स्थिति म ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का किमा भा प्रकार का आरंभोत्त शोधकनान या अन्तर्निष्कानान स्वायत्त शासन की भांग की पूर्ति का जाणा करना निरर्थक था । परन्तु वायस की निरन्तर बढ़ना भाग का भा ब्रिटिश सरकार या हा ठुकरा नन का माहम भा नया कर सकता थी वराकि ब्रिटेन क ऊपर युद्ध-सक्त प्रहता जा रहा था । अतः अगस्त 1940 म भारतीय माविधानिक प्रतिपाद को पूर करने क लिए गवर्नर जनरल ने एक प्रस्ताव रखा जिस अगस्त 1940 का प्रस्ताव कहा जाता है ।

प्रस्ताव—यह प्रस्ताव क अनुसार गवर्नर जनरल ने य घोषणा की

1 इन पन्नाओं का दिक्कत नही है।

Thu the co-isting f w t Ji with the wo d f D mo d h s s
r th he d of th G rnm t i B t Ju with the t f p t t conf s
1.1.1 11.1.1 308

(1) युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार भारत के भावी सविधान का निर्माण करने के निमित्त एक सविधान सभा का आयोजन करेगी, जिसमें भारत के सभी प्रमुख राष्ट्रीय तत्त्वों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

(2) गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को रखा जायेगा और ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से युक्त एक युद्ध परामर्शदात्री समिति बनायी जायेगी।

(3) ब्रिटिश सरकार भारत की शान्ति तथा सुरक्षा के वर्तमान दायित्व को किसी ऐसी सरकार को नहीं दे सकती जिसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय जीवन का एक विशाल वर्ग करता हो।

(4) ब्रिटिश सरकार युद्धोत्तर काल में भारत की औपनिवेशिक स्थिति की माँग को मान्यता देगी और यथासम्भव युद्धकाल में उसके सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया जायेगा।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया—यद्यपि अगस्त 1940 के प्रस्ताव में स्पष्टतया औपनिवेशिक स्वराज्य, सविधान सभा की स्थापना तथा अन्तरिम काल में भारत के शासन में भारतीयों को शामिल करने की घोषणा थी, तथापि इसकी शब्दावली इतनी अस्पष्ट थी कि वह केवल 'फूट डालो और शासन करो' की नीति पर आधारित थी। इसमें तुरन्त उत्तरदायी लोकतन्त्री शासन की स्थापना को पूर्णतया उपेक्षित किया गया था। मुस्लिम लीग को अवश्य इससे सन्तोष हुआ क्योंकि इस योजना के माध्यम से वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों का बहाना लेकर इस योजना को सफल न होने देने में समर्थ हो जाती। वास्तव में अब लीग का उद्देश्य भारत की एकता तथा स्वतन्त्रता नहीं था, प्रत्युत वह स्वतन्त्र मुस्लिम भारत का ही स्वप्न देखने लगी थी। अतः कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना—सरकार के ऐसे असहयोगी रुख तथा चालों को देखकर कांग्रेस ने महात्मा गांधी को पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार दे दिया। गांधी जी के समक्ष कई ऐसी समस्याएँ थीं जिन पर बहुत सोच-विचार करके सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने का निर्णय करना था। युद्ध की तीव्रता का प्रभाव भारत की आम जनता पर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि देश का शासन वह राष्ट्र कर रहा था जो युद्ध में निर्बल पक्ष बनता जा रहा था, शासकों का देश की न्यायोचित माँगों के सम्बन्ध में हठी रुख तथा टालमटोल से भरा व्यवहार राष्ट्रीय नेताओं के लिए असह्य हो रहा था, सविनय अवज्ञा आन्दोलन को ग्राम जनता का आन्दोलन बनाना ऐसी सकटमय स्थिति में अनुचित होता। यद्यपि कांग्रेस युद्ध में इंग्लैंड की हर प्रकार से सहायता करने को तैयार थी, क्योंकि वह फासीवादी आक्रमण को कदापि सहन नहीं करती थी और गांधी जी ने हिटलर तथा मुसोलिनी तक को उनकी समर नीति के विरुद्ध पत्र लिखे थे, तथापि अंग्रेजों की भारत में साम्राज्यवाद कायम किये रखने तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की न्यायोचित माँगों के प्रति हठधर्मिता तथा उदासीनता दर्शाने की नीति को देखकर कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना भी अनुचित प्रतीत हुआ। इन सब बातों को ध्यान में रखकर गांधी जी ने 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' की योजना बनायी, क्योंकि आम सत्याग्रह के हिंसा में परिवर्तित हो जाने का भय था और ब्रिटिश शासक उसे दवाने के लिए हिंसात्मक साधन अपनाते। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूर्णतया अहिंसात्मक होता। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अहिंसा पर पूर्ण विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का चयन किया गया। सत्याग्रही पहले जिला अधिकारियों की अपने इरादों की सूचना देते। उसके बाद वे शान्तिपूर्ण तरीके से जनता से माँग करते कि वे युद्ध के निमित्त सरकार को किसी प्रकार की सहायता न दें क्योंकि युद्ध भारत की जनता की स्वतन्त्रता तथा उनके लोकतन्त्री अधिकारों की सुरक्षा में लिए नहीं, बल्कि उसे निरन्तर ब्रिटिश दाम्ना के अन्तर्गत बनाये रखने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों के संरक्षण के लिए लड़ा जा रहा था।

सत्याग्रह का आरम्भ—व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ करने के लिए गांधी जी ने सबसे प्रथम आचार्य विनोबा भावे को चुना। अक्टूबर 1940 में आन्दोलन का श्रीगणेश विनोबा जी ने

किया। उन्नीस जनता के समय एक मरिष्ठ भाषण दिया तभी उन्नीस बढ़ी कर दिया गया। हमके पचास आन्दोलन तीव्रतापूर्वक फटा। एक मास की अवधि में सहसा सत्याग्रही बढ़ी कर दिए गए। कुछा को नोर्त्सि प्राप्त हात हा बढ़ा बना दिया गया। कुछा को नौ चार बात जनता से वन्दन का अवसर मिला। कानातर में काग्रस के तगभग सभी उच्चस्तरीय नेता बढ़ी हा गए। कवन गांधी जा तथा कुछ अन्य नेता जा सत्याग्रह आन्दोलन का निन्धन कर रहे थे और त्रिहान व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग नही लिया वही बच रहे। ऐसा अनुमान है कि जकहूर 1940 से अप्रैल 1941 तक की अवधि में तगभग 20000 सत्याग्रही बन्दी कर लिए गए थे। आन्दोलन का निन्धन पयाप्त सावधानी तथा अनुशासनपूर्ण ढङ्ग से किया गया। किसी भी सत्याग्रही की ओर से हिंसा की एक भी कायबाहा नही की गयी। बिहार तथा पनाब में एक दो घटनाएँ हुए जिनमें सत्याग्रहियों का गिरफ्तारी के विरुद्ध जनता में प्रदग्गन किया और पुलिस ने गाँधी चाज दिया। हम आन्दोलन का जनता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। हम जनता की राष्ट्रीय चेतना को मुहूर्त करने में सहायता पहुँचाया। जनता का यह विश्वास बन गया कि युद्ध भारत के हित में न होकर ब्रिटेन के हित में हो रहा है। जन सरकार की सहायता करना भारत के हित में नही है। सरकार का ऐसा आन्दोलन उचित नही होगा क्योंकि हम सरकार का स्थिति निम्न हो जानी। हम पर भी ब्रिटिश अधिकारी अपना पुराना राग जतापते रहे कि भुमसमान तथा देनी नरग काग्रस की नीतियाँ का अपन अहित में मानकर किसी भावी साविधानिक प्रगति में भाग लेने का शूर नही है। गांधी जा न भारत मन्त्री की ऐसा प्रतिक्रिया का भारत के आन्तरिक मामला में अवाछनाय हमें तब क्या जाए मार भतिगव का तब ब्रिटिश सरकार की पूर डाता का नीति पर मत।

सरकार की प्रतिक्रिया—यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन का जो कि पूर्णरूप में पान्तिपूर्ण तथा अस्मिन्मक ढङ्ग में चल रहा था तबान के लिए सरकार का उग्र कर्म उगन की आवश्यकता नही पती तथापि जनता पर हमल पडन बात प्रभाव का सरकार सहन नही कर सकी। दूसरी ओर जापान भी धुग गछा का ओर में मित्र राष्ट्रा के विरुद्ध युद्ध का घोषणा करने की तयारी में था। हमरा कुप्रभाव सीधे भारत पर पछता। भारतवासियों द्वारा ब्रिटेन के युद्ध प्रयासा का विरोध ब्रिटिश नागन के लिए अस्मिन्मक था। जन जनार् 1941 में गवनर जनरल ने अपना तायकारी परिषद् के सन्ध्या का सन्धा जात में बहतर तरह के त ओर उमम पाँच भागताय सन्ध्या निधुन कर दिए। परन्तु काग्रस या मुनिम तग में से किसी भी तब न जन प्रतिनिधि नही भजे। स्पष्टतया पाँच नय सन्ध्या हम व्यक्ति के जा ब्रिटिश सरकार का तब में तब नरन बात थे। परिषद् के सन्ध्या के फन्सन्स भा बिन्हा राजनानिक प्रतिक्रिया वित्त पूर जाति सन्ध्यापूर्ण विभाग यूगातीर पापता के हाथ में बने रहे। भागताय सन्धिया का गर सन्ध्या के विभाग गौर गये। ब्रिटिश सरकार का बचा का फूमतान का सी हम नाति का भागताय गच्छा नताभा पर का प्रभाव नही पडा।

सत्याग्रह आन्दोलन का स्थगन—कायपानिका के विस्तार के बाद दूसरा मा वपूर्ण निधय त्रि ब्रिटिश सरकार ने दिया वह था सत्याग्रहियों का मुक्त करने का। सम्भवतः जमना तग हम पर जाग्रमण कर तब का तयारा तथा जापान तारा युद्ध में प्रविष्ट हो जान के भय में ब्रिटिश सरकार भारत के गच्छा नताजा का बनी तिय स्थगन का माहम करने में घबरा गया था। यद्यपि प्रमुख नतागन हात लिए गये थे तथापि हमके कारण काग्रस की नाति में कोई परिवर्तन नही हुआ। सरकार का नाति में भा कोई ऐसा परिवर्तन नही आया जिसके आधार पर यह माना जाता कि वह गच्छा स्वतन्त्रता का माँग के सन्ध्या में का हमानतार प्रयास कर रहा है। अगस्त 1940 के सन्ध्या के अनुसार गवनर जनरल ने एक युद्ध पगमण त्रि परिषद् भा बना मा था परन्तु ये सन्ध्या काय बहतर में गाव के थे। वास्तविक मता गवनर जनरल तथा उमम कायकारण परिषद् के सन्ध्या सन्ध्या के हाथ में बनी रहा। परन्तु तब सन्ध्या 1941 में

जापान युद्ध में प्रविष्ट हो गया तो उसके कारण भारत के समक्ष आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया। अतः कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी के पूर्ण अहिंसात्मक सिद्धान्त को एक विदेशी आक्रामक के विरुद्ध भी प्रयुक्त किये जाने की नीति का विरोध किया। इस पर गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह माँग की कि जनता को युद्ध के खतरे में चिन्तित न होने दे और देशवासियों को अपने आप अपने देश की रक्षा करने को प्रोत्साहित करे।

लीग का रुख—जैसी कि आशा की जाती थी, युद्ध प्रारम्भ होने पर जब कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दिये तो लीग की मन्त्रिमण्डल मनाने की पेशकश सफल न होने पर जिन्ना ने निरन्तर कांग्रेस तथा ब्रिटिश शासकों के मध्य सघर्ष का लाभ उठाने का प्रयास किया और वे मुसलमानों तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अविक मेत्री स्थापित करने के प्रयासों में लगे रहे। भारत की वास्तविक स्थितियों के सम्पर्क में रहने के कारण वाइसराय यहाँ के अन्य मुस्लिम नेताओं के विचारों से परिचित था। जिन्ना की लीग के साथ वगाल, पंजाब, सिंध तथा पं० मीमा प्रान्त के मुख्य मन्त्री सहमत नहीं थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा सरकार के भावी साविधानिक अनिरोध को दूर करने के प्रयासों में भी सहमत थे। परन्तु ब्रिटेन स्थित भारत मन्त्री जिन्ना की जिद को ही हिन्दू-मुस्लिम समस्या का वहाना बनाये रखकर भारत की माँगों को टालना चाहते थे। अगस्त 1940 के प्रस्ताव के अन्तर्गत जब वाइसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया तो कांग्रेस ने पद स्वीकार नहीं किये। वह पूर्ण उत्तरदायी शासक की माँग कर रही थी। मुस्लिम लीग इसलिए शामिल नहीं हुई कि वह कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की मर्यादा में लीग का गैर-मुस्लिम सदस्यों के साथ समान प्रतिनिधित्व चाहती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा-परिपद् में जब वगाल व पंजाब के मुसलमान मुख्य मन्त्री शामिल हुए तो जिन्ना उनके विरुद्ध इसलिए बौखलाये कि वे जिन्ना की अनुमति लिए बिना क्यों शामिल हो गये। संक्षेप में, भले ही जिन्ना अपने को समस्त भारतीय मुसलमानों के हितों का संरक्षक, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि मानते रहे और ब्रिटिश साम्राज्यवादी उनके इस दावे को न केवल स्वीकार करते रहे, अपितु तदनुसार कांग्रेस की स्वतन्त्रता की माँग को ठुकराने के निमित्त उसे ताश की तुरुपचाल बनाते रहे, तथापि जिन्ना का यह दावा भ्रामक तथा झूठा था। परन्तु ब्रिटिश अधिकारी तो अपने साम्राज्यवादी हितों को बनाये रखने में पूर्णतः मैकियाविलीवाद का अवलम्बन कर रहे थे। उनकी इस नीति के कारण जहाँ एक ओर 1940 में युद्ध की प्रगति को देखते हुए कांग्रेसी नेता धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लोकतन्त्री मित्र-राष्ट्रों तथा भारत की रक्षा के लिए आतुर होकर ब्रिटिश सरकार में भारत की स्वायत्त शासन की माँग मनवाने तथा उसको हर प्रकार से युद्ध में सहायता देना चाहते थे, वहाँ लीग के नेता जिन्ना के लिए ये सब बातें गौण थी। वे परिस्थितियों का लाभ उठाकर पाकिस्तान की माँग को पुष्ट करने की सौदेबाजी में लगे थे। 1940 में तो पाकिस्तान का विचार स्पष्टतया सामने आ गया था।

क्रिप्स प्रस्ताव 1942

परिस्थितियाँ—1941 के अन्त तक महायुद्ध की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो चुकी थी। जापान ने पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में आतंक फैला दिया था। बर्मा में उमफा प्रवेश निश्चित था। भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरा आ चुका था। अतः अब इंग्लैंड को भारत के सहयोग की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। मर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंग्लैंड के एक उच्च कोटि के ब्रूटनीतिज्ञ थे। उनके प्रयासों में रूस जर्मनी के विरुद्ध मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। क्रिप्स पहले भी भारत में रह चुके थे और उनके यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं, नेहरू आदि, के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। इस समय वे इंग्लैंड के युद्ध मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे। जापान के युद्ध प्रवेश ने भारत की प्रतिकक्षा को भीषण स्वरूप उत्पन्न कर दिया था। अतः 1942

क प्रारम्भ में ट्रिनि की सरकार ने ट्रिनि का भारतीय सांविधानिक गतिराय का दूर करने के निमित्त कुछ प्रस्ताव लेकर ममझौता बार्ता के त्तु भारत में भेजने की घोषणा की। जिन प्रस्तावों का ट्रिनि ने रखा उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन एवं सांविधानिक विकास के इतिहास में ट्रिनि याजना के नाम से जाना जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास हम तथ्य का द्योतक है कि अग्रज किसी कीमत पर भारत का स्वतंत्रता या स्वायत्त नामने देने के पक्ष में नहीं रहे। युद्धकालीन संकट तक वे देश को राष्ट्रीय नेताओं के एडिक्ट मन्थन के समक्ष नहीं भुके थे। जय भी उन्हीं काई नयी याजना बनायी उसमें पीछे ऐसा नहीं जाया जा सके था। उनमें से सांप्रदायिकता का प्रास्ताविक देने के लिए उन्हें मुस्लिम लीग तथा अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ का महयाग मिलता रहा। संकट की हम घड़ी ने हमें अग्रजों ने इन साधना का यथाशक्ति उपयोग किया और राष्ट्रवादी तत्त्वा की उभार की।

ट्रिनि में जन भजन का प्रमुख कारण यही था कि ट्रिनि किसी ने किया रूप में राष्ट्रीय नेताओं का अपनी याजना में सम्मिलित करने में सफल हो जायगा। इस प्रकार राष्ट्रीय नेताओं की रूप की प्रतिस्थापन स्थिति में अमर्यादी प्रवृत्ति देख जायगा। परन्तु कुछ अन्य कारण भी थे जिनके कारण ट्रिनि सरकार का हम याजना के लिए विवश होना पड़ा। नवम्बर 1941 में स्वयं काग्रम ने एक प्रस्ताव पारित करके रूप का रक्षा के निमित्त सरकार के साथ सशस्त्र महयाग की इच्छा प्रकट की थी। जय यह सरकार के हित में था कि वह उस शक्त का स्वाकार करे। तावहालुर मूल में चर्चित हो तार भेजकर कुछ मांग तुरन्त स्वाकार करने की मांग की थी। फरवरी 1942 में राष्ट्रवादी चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शेंग भारत पर्यटन थे। उन्होंने ट्रिनि सरकार का मतार्थ ही की कि लीग पूर्वोक्त एशिया में जापान के वल्ले हुए आक्रमण का भारत में न वल्ले देने के लिए यह आवश्यक है कि ट्रिनि सरकार भारतीय स्वाधीनता का मांग के स्वाकार करे। भारतवासी ही भारत की रक्षा उचित प्रकार से कर सकेंगे। अमरीका ने मर्यादी राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी ट्रिनि पर भारत का स्वतंत्रता देने के बारे में दबाव डाल रहे थे। उन्होंने ट्रिनि प्रधानमन्त्री चर्चित के इस वक्तव्य के विरुद्ध कि एशियाई चारों ओर भारत के लिए नागू बना होना वक्तव्य किया कि यह राष्ट्र समूचा अनिया के लिए नागू होना है जिसमें भारत तथा पर्मा भी शामिल है। आशय का मत यह है कि चर्चित ने अमरीकावासियों तक से सफल भूत शानकर भुमसह किया। उन्होंने बताया कि भारतीय मता में 75 प्रतिशतमान है जे अग्रजों का महय साथ रहे। तब से वे बचने की काग्रम के प्रभाव में लगे। वास्तविकता यह थी कि वल्ले 35 प्रतिशत भुमसमान का था। मता पर काग्रम या नाम के प्रभाव से बचने का मतार्थ अमर्यादीपूरा था। परन्तु चर्चित उमा पुराने गंग (टिड्ड मुस्लिम सम्भाव) का अनाप रहे थे ताकि स्वतंत्रता देने का बात का लोका जा सके। एसा भी अनुमान लगाया जाता है कि मित्र राष्ट्रों की आर में युद्ध में प्रविष्ट होने पर हमें न भी भारत की स्वतंत्रता के बारे में चर्च पर स्वायत्त होना होगा। आशय भी एसा दबाव डाल रहा था। इस प्रकार ट्रिनि के ऊपर भारतीय स्वतंत्रता की मांग का गलतबूझ में वल्ले वल्ले अन्तर्गतिय स्वायत्त पड़ रहा था जिसका अवलोकन करने का माहम चर्च का नहीं था क्योंकि लीग विश्वयुद्ध का अवधि में चर्च अपना पूर्व का स्थिति में एसा निदान हो चुका था। स्वयं प्रधानमन्त्री चर्चित ने स्वाकार किया था कि भारत की प्रतिस्थापन के लिए चर्च के स्वयं के मापने अपाय है। दूसरे ओर भारतीय मन्त्रि जो दल में पूर्व एशिया में जायाना नेताओं के अधीन हो चुके थे आजाद हिन्द फौज में संगठित किए जा चुके थे। उनका उद्देश्य जापान का महायना में भारत का ट्रिनि माध्याय में मुक्त कराना था। एसा स्थिति में चर्च का विवश होकर ट्रिनि मिशन का विचार विनिमय के त्तु भारत भेजने का प्रस्ताव करना पड़ा ताकि वह भारत में गलतबूझ में वल्ले वल्ले मित्र राष्ट्रों का गंग कर सके और भारत के नेताओं का ध्यान बने उन में समझ हो सके।

क्या क्रिप्स मिशन की योजना एक ईमानदार कदम थी ?—इंग्लैण्ड के टोरी नेता किसी भी रूप में युद्ध की तीव्रता की अवधि में भारत की स्वतन्त्रता या भारत के नेताओं द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारत के सदर्थ में युद्ध के उद्देश्यों को घोषित करने के प्रश्न को नहीं उभारना चाहते थे। परन्तु मित्र-राष्ट्रों तथा स्वयं इंग्लैण्ड के तत्कालीन सम्मिलित मन्त्रिमण्डल में उप-प्रधानमन्त्री ऐटली एवं भारत तथा इंग्लैण्ड में जनमत के ऐसे दबाव को टालना भी टोरी नेताओं के लिए सम्भव नहीं रह गया था। अतः प्रधानमन्त्री चर्चिल ने भारत मन्त्री ऐमरी तथा भारत के वाइसराय लार्ड लिनलिथगो से परामर्श करके युद्धोत्तर काल में तथा तत्काल भारतीय समस्या के सम्बन्ध में एक घोषणा का मसविदा बनाया। परन्तु इसे घोषित करने से पूर्व यह निश्चय किया गया कि पहले केबिनेट के एक मन्त्री को इसके सम्बन्ध में भारतीय नेताओं के साथ विचार-विनिमय के लिए भारत भेजा जाय। वस्तुतः घोषणा की रूपरेखा 8 अगस्त 1940 के प्रस्ताव से अधिक कुछ नहीं थी जिसे कांग्रेस अस्वीकार कर चुकी थी। वाइसराय ने पुनः मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या को तूल देकर घोषणा के सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए अपने त्याग-पत्र की धमकी तक दे दी थी। क्रिप्स को भारत भेजने के निर्णय की पूर्ण सूचना भी उसे नहीं दी गयी थी। इसलिए भी वह असन्तुष्ट था। भारत में घोषणा के सम्बन्ध में क्रिप्स के अधिकार-क्षेत्र को भी अस्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। क्रिप्स के एक जीवनी लेखक के अनुसार 'वह किसी समझौते की शर्तों के बारे में समझौता वार्ता करने के लिए एक कृति-सम्पन्न प्रतिनिधि के रूप में नहीं गया था, वरन् वह एक ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के मन्त्री के रूप में नीति-सम्बन्धी एक ऐसे वक्तव्य की शर्तों को समझाने तथा स्पष्ट करने के लिए गया था जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था।'¹ क्रिप्स का निष्कर्ष था कि वह आवश्यकतानुसार घोषणा की शर्तों पर समझौता वार्ता के मध्य आवश्यक परिवर्तन कर सकता था। मिशन के वाइसराय के साथ सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं थे। साधारणतया उसे वाइसराय के साथ सहयोग करके अपना कार्य करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु वाइसराय तथा मिशन के सदस्य के मध्य पर्याप्त मतभेद थे। वस्तु-स्थिति यह थी कि प्रधानमन्त्री तथा भारत मन्त्री वाइसराय पर अधिक विश्वास रखते थे। दूसरी ओर मिशन का सदस्य इन तीनों से पृथक् दृष्टिकोण रखता था। वह सचमुच भारतीय समस्या का एक विवेकपूर्ण तथा व्यावहारिक समाधान ढूँढना चाहता था, जबकि प्रधानमन्त्री तथा कम्पनी इसे टालना चाहते थे। अतएव स्पष्टतः क्रिप्स मिशन से कोई सफल आशा नहीं की जा सकती थी। यह तो केवल मित्र-राष्ट्रों के दबाव तथा भारतीय जनमत को भूल-भुलैया में डालने का एक गैर-ईमानदार षड्यन्त्र मात्र था।

क्रिप्स प्रस्ताव—23 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत पहुँचे। भारतीय नेता उनसे बहुत आशाएँ लगाये बैठे थे, क्योंकि एक तो उन्हें भारत के माथ सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति समझा जाता था और दूसरे वे समाजवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। भारत पहुँचते ही उन्होंने गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् के सदस्यों से वार्ता प्रारम्भ की। उसके बाद वे भारतीय नेताओं से मिले। वार्ता के पश्चान् जो प्रस्ताव उन्हें ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल द्वारा दिए गये थे उन्हें उन्होंने भारत के नेताओं के समक्ष रखा इन्हे दो भागों में रखा जा सकता है।

(क) दीर्घकालीन—(1) ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को यथाशीघ्र स्वायत्त शासन प्रदान करना है।

(2) इस उद्देश्य की उपलब्धि के निमित्त ब्रिटिश सरकार भारत को राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत एक प्रभुत्व सम्पन्न मध्य-राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है।

(3) युद्ध समाप्ति के तुरन्त पश्चान् एक सविधान सभा का निर्माण किया जायेगा जो भारत के लिए नया सविधान तैयार करेगी। इस सभा का निर्माण करने में पूर्व प्रांतीय

¹ Colincooke, *The Life of Richard Stafford Cripps*, quoted in Tara Chand, *op cit*,

व्यवस्थापिकाओं व निवाचन हॉल जीर प्रांतीय विधानसभाएँ अपना कुन सन्म्य-सन्म्या व सन्म्य समानुपाती प्रतिनिधित्व का प्रथम सविधान सभा व निग चुनेंगी। चकि सघ म देशा गियामते भा गामिन हागी अत प्रत्येक रियासत व नरग जनमग्या के अनुपात म अपन प्रति निविद्या की सविधान सभा व निग नामाकित करेंग।

(4) एम सविधान सभा द्वारा निमित्त सविधान का ब्रिटिश सरकार न्न गतों व अन्तगत नागू करगा कि (अ) कार्त्त भी प्रात यन् नय सविधान का स्वाकार न कर ता वन् अपना वतमान स्थिति बताय रग सकगा जीर अपना नया सविधान बना सकगा। वन् भा एक उपनिवग की भाति रह सकगा। यन् उसकी विधानसभा 60/ म अधिन बहुमत व द्वारा सघ प्रवग का निणय न कर सक ता एसा निणय जनमत मग्न द्वारा कराया जायगा। एसा प्रकार कोई दगा राय भी यन् सघ म प्रविष्ट न हाता चायगा ता एसा कर सकगा और ब्रिटिश सरकार उसक साथ नया समझौता कर सकगी। (ब) सविधान निर्माण व पञ्चात् ब्रिटिश सरकार भारतीय सविधान सभा व साथ सत्ता व हम्तातरण व सम्बन्ध म सन्धि करगी जिमम ब्रिटिश सरकार नारा अतीत म जातीय एक धार्मिक अस्मयका व संरक्षण व दायित्व म सम्पूर्ण प्राविधान किय जायेंग। (ग) भविष्य म ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल व एसा व साथ अपन सम्बन्ध ना निधारण करने का पूर्ण दृष्ट भारतीय सघ की प्रा त गयी।

(ख) अन्धकालीन—उपयुक्त प्रस्ताव युद्ध का समाप्ति व पञ्चात् की व्यवस्था व प्रार म थ। एसा याजनाएँ ब्रिटिश सरकार किता न किसी रूप म पन्न भी रगती जा रही थी। भारतीय मांग तुरन्त उत्तरदायी सरकार की स्थापना व सम्बन्ध की थी। एम सम्बन्ध म ब्रिटिश प्रस्ताव म बना गया था कि युद्ध-काल म विश्वयुद्ध व प्रयासा व रूप म भारत की प्रतिरक्षा व नियन्त्रण नया निष्पन्न का दायित्व ब्रिटिश सरकार व साथ म रहना आवश्यक थ परन्तु भारत व मनिन नतिव तथा भीतिर साधना का पूण उपयोग करने म भारतवासियों व सहयोग की उपनधि करने का दायित्व भारत सरकार का हागा।

ब्रिटिश प्रस्तावों की झालोचना—ब्रिटिश मिशन म भारतवासियों वही आनाएँ लगाय हुए थ। परन्तु ब्रिटिश की भाता जादूगर की सी पिटारी मिद्ध हुई। जिम रूप म ब्रिटिश याजना व प्रस्ताव रग गय थ वन् कार्त्त नई बात नया थी। एम आन्वागत विभिन्न अवसर पर परिस्थिति की गरिमा का दयन एम ब्रिटिश सरकार किसी न किसी रूप म रग न्न का अय्यासा हा चुकी था जिन परिस्थितियाँ व सम्बन्ध म ब्रिटिश मिशन भारत आया था व पूर्व की अप ता अधिक गम्भीर थी अत ब्रिटिश याजना का रगन म एक-ना नय आन्वागत न्य गय परन्तु जिम रूप म उन् ताता मराया गया उमन आधार पर भारत का कार्त्त भा दन या वग उन् मानन का राजा नया हुआ। भारत का युद्ध व पञ्चात् एक स्वायत्तशासता उपनिवग का स्थिति प्रगन करने की घोषणा कार्त्त नई बात नही थी। ब्रिटिश प्रस्ताव म सविधान सभा नारा भारत व नय सविधान का बुनान की घोषणा करता आवश्यक एक स्पष्टाति थी। परन्तु सविधान सभा का अन्ति तथा प्रभाव था जिम रूप म रगा गया था वन् किता भी दन का माय नया था। पहला सविधान सभा म एक आर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं नारा निवाचन सन्म्य हात और दूसरा आर न्यो-नरगा नारा नामाकित एम सन्म्य हात जा अपन प्रतिनिधियों केव नारा एक नारन-ना सविधान निर्माण व काय म साधन मिद्ध हात। दूसर एम सभा जिम सविधान का निर्माण करता उम स्वाकार या सम्वाकार करने का पूर्ण गति पराण रूप म न कवन दगा रा-या का हो हो गया था अन्तिनु प्रान्ता का भा प्राप्ता हा जाता। तागर एम प्रस्ताव भारत का दनन रा-या म विभाजित करने का स्पष्ट याजना रगत थ। चौथ ब्रिटिश सरकार न आरगन्धर्व का सम्बन्ध न्न व सम्बन्ध म सविधान सभा व साथ सन्धि करने की गत रगा था जो हर तरह भ्रामक तथा अस्पष्ट थी। अन्ति पन्थिम काय म भारतीयों का उत्तरदायी शासन न्न व सम्बन्ध म ब्रिटिश राजा नहा थ। आरम्भ म एम इम यात पर राजा हात दीमत थ कि ब्रिटिश का रगदकर घाय विषय का शासन

भारतीय मन्त्रियों के हाथ में दिया जाय और उनके सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल की स्थिति वैधानिक प्रधान की सी रहे, परन्तु बाद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल के निदेशन पर क्रिप्स इसके लिए भी राजी नहीं हुए।

अन्तरिमकालीन योजना के सम्बन्ध में जो बातें आमक थीं उनमें से एक तो यह थी कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिपद् का भारतीयकरण किये जाने पर वाइसराय की स्थिति क्या होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बातें करते हुए क्रिप्स ने बताया कि वाइसराय इंग्लैण्ड के राजा की भाँति वैधानिक प्रधान रहेगा। यद्यपि यह धारणा अभिसमय पर ही आधारित होती क्योंकि 1935 के कानून में सशोधन किये बिना इसके व्यवहार में आ सकने की कोई आशा नहीं थी, तथापि स्वयं वाइसराय क्रिप्स की ऐसी धारणा से रुष्ट हो गया। दूसरी समस्या वाइसराय की कार्यकारी परिपद् को 'राष्ट्रीय सरकार' का नाम देने की थी। प्रस्ताव में ऐसी किसी पदावली का प्रयोग नहीं था। क्रिप्स द्वारा इस पदावली का प्रयोग किया जाना भी टोरी नेताओं को अच्छा नहीं लगा। परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रतिरक्षा-मन्त्री के सम्बन्ध में था। मूल प्रस्ताव में यही बात थी कि युद्ध काल में प्रतिरक्षा-मन्त्री प्रधान सेनापति ही रहेगा। कांग्रेस की धारणा यह थी कि जब सम्पूर्ण शासन पर राष्ट्रीय नियन्त्रण की बात मानी जाती है, तो प्रतिरक्षा का दायित्व प्रधान सेनापति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के हाथों में रखना एक असंगति ही होगा। कांग्रेस इसके लिए तो राजी थी कि सरकार में प्रधान सेनापति एक सदस्य के रूप में रहे क्योंकि युद्ध-काल में वह एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। परन्तु उसका दायित्व युद्ध के कार्य-कलापों के संचालन तक ही सीमित रहना चाहिए। जब देश को युद्ध अपनी रक्षा के लिए लड़ना है तो युद्ध से सम्बद्ध अन्य कई बातें ऐसी होती हैं जिनके सम्बन्ध में प्रतिरक्षा-मन्त्री अधिक प्रभावशाली ढंग से निर्णय ले सकता है। जनता में मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना, युद्ध के बारे में राजनीतिक निर्णय आदि के लिए प्रतिरक्षा-मन्त्री भी भारतीय को होना चाहिए। परन्तु वाइसराय इसके लिए सहमत नहीं था। इंग्लैण्ड स्थित मन्त्रिमण्डल से इस सम्बन्ध में क्रिप्स ने परामर्श किया तो वहाँ से स्पष्टतया ऐसी माँग का विरोध किया गया। वाइसराय की कार्यकारिणी के अन्य अंग्रेज सदस्य भी कार्यकारिणी के भारतीयकरण से रुष्ट थे। वाइसराय यह कभी नहीं चाहता था कि 1935 के द्वारा दी गयी उसकी शक्तियों को कम करके उसे केवल वैधानिक प्रधान बनाया जाय।

अतः जैसा पहले कहा जा चुका है, क्रिप्स मिशन केवल एक भ्रम जाल था। ब्रिटिश शासक भारत सरकार के संचालन का दायित्व जरा भर भी भारतीयों को देना नहीं चाहते थे। अतः क्रिप्स के ईमानदार प्रयासों के बावजूद पग-पग पर उसकी समझौता-वार्ताओं में वाइसराय उसके अंग्रेज पार्षद, लीग, नरेश और सबसे ऊपर चर्चिल तथा ऐमरी रोडे अटकाते रहे। यहाँ तक की उस समय अमरीकी प्रतिनिधि लुई जानसन भारत में आया था। क्रिप्स ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में समस्या के समाधान के लिए उसमें परामर्श किया। जो सूत्र दोनों ने निकाला वह भी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को अमान्य ही सिद्ध हुआ। इसके अनुसार प्रतिरक्षा-मन्त्री एक भारतीय को बनाने की बात थी जो प्रधान सेनापति को युद्ध-संचालन की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करता। क्रिप्स इन सबसे इतना परेशान हो गये कि एक बार तो उन्होंने मिशन से त्याग-पत्र देने का ही निर्णय कर लिया था। परन्तु चूँकि वे भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे, अतः उन्होंने ऐसा करने का साहम नहीं किया। अन्ततः उन्हें निराशा का ही सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने तो 1935 के कानून को डम दिया में मशोबित करना चाहती थी और न डम कानून में दिये गये अपने दायित्वों को छोड़कर भारतीयों को सौंपना चाहती थी। अतः युद्ध-काल में भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की यह वार्ता असफल ही सिद्ध हो सकनी थी।¹

योजना की विफलता—क्रिप्स याजना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक वर्ग का मजबूत करना था और प्रस्तावों में ऐसा बात स्पष्ट थी। कांग्रेस का यह मन्ताप लिया गया कि भारत का भावी संविधान स्वयं भारत की प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा बनायगी और भारत राज्य का भावी स्वरूप संघात्मक होगा। मुस्लिम लीग का यह मन्ताप लिया गया कि मुस्लिम प्रमुख प्रांत संविधान निर्माण के पश्चात् भी भारतीय संघ में पृथक् स्वतंत्र राज्य बना सकेंगे अर्थात् परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने से गंभीरता से नाराज था कि उसका हिता का संरक्षण करने के लिए ब्रिटिश सरकार संविधान सभा के साथ गठबंधन करेगी। लीग ने कहा कि यह मन्ताप था कि वह संविधान निर्माण में अपने नामांकित प्रतिनिधियों का भेज सकें और संविधान बन जाने पर उन्हें उस स्वीकार या अस्वीकार करने तथा संघ में शामिल होने या न होने का भी अधिकार प्राप्त होगा। परंतु जिसे भी दान न देकर स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस लीगका लीग के बीच समस्या से तो असंतुष्ट थी कि क्योंकि उसमें लीग विभाजन की स्पष्ट उक्ति थी परंतु कांग्रेस का अंतरिम-कालीन व्यवस्था का उपक्षेप रखने में भी असंतुष्ट था। मुस्लिम लीग का यह मांग था कि संघ में शामिल होने या न होने के सम्बन्ध में जो जनमत संग्रह किया जाय उसमें स्वयं मुसलमानों का मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। मिर्जापुर में राजा ने यह कि इस योजना के आधार पर पत्रों में यथा मुसलमानों के राज्य में मित्रता या उसका विभाजन हो जायगा किन्तु हमें वचन के लिए प्राण पण से तैयार हैं। हिन्दू महासभा ने इसीलिए इस अस्वीकार किया कि यह पाकिस्तान की मांग का स्वीकार करने की योजना थी। इस प्रकार यद्यपि क्रिप्स योजना सफल बनाने का उद्देश्य रखती थी तथापि वह किसी का भी असंतुष्ट नहीं कर सकी। लीग अवश्य हमें काफी असंतुष्ट थी। परंतु कांग्रेस का कार्य भाग तो वह अंग्रेजों का ही था।

अन्ततः 11 अप्रैल 1942 का दिन प्रस्तावों का वापस ले लिया गया। ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग का जिसे भी कामना पर स्वीकार करने को राजा नहीं था। उसका उद्देश्य भारतीय एक अंतरांगीय दवावा का मन्ताप देना मात्र था ताकि वह युद्ध प्रयासों में उनके विरोध में बची रह सके। क्रिप्स योजना का विफलता का ताप कांग्रेस के ऊपर गिरा कि ब्रिटिश शासकों ने उनके समक्ष यही प्रचार कर दिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन

क्रिप्स मिशन की विफलता का प्रभाव—जून अप्रैल 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिए गए तो भारतीय नेताओं में घोर निराशा फैल गयी। लीग का विरोधी जाग्रमण में वृद्धि हुई। इस कार्य के लिए न तो ब्रिटिश सरकार तैयार थी और न वह भारतवासियों से समझौता कर रही थी। उनकी हठमति का चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। भारतीय स्वतंत्रता की मांग के प्रति उसका दृष्टिकोण की नीति स्पष्ट हो चुकी थी। क्रिप्स प्रस्तावों में यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज लोग भारत का बड़े राष्ट्रीय स्वायत्तता से दान देना चाहते हैं और उनके साथ पारस्परिक सम्बन्धों का उत्साहक अनिश्चित काल तक लगे में अपनी साम्राज्यवादी कायम रखना चाहते हैं। वायसराय एरविन ने स्पष्ट कह दिया था कि भारत में स्वायत्तता प्राप्त तथा भारतीय एकता में बाधा नहीं पड़ेगी। अंग्रेजों में इरविन ने भारत में जान समय कहा था कि भारत का अगले 50 वर्ष तक स्वतंत्र होने का आकांक्षा नहीं करना चाहिए।

गांधी जी तथा कांग्रेस के नेताओं के इस विचारों का अन्तिम भाव जितने बने कि भारत में इरविन के जाने के पश्चात् क्रिप्स ने अंग्रेजों से विनाश के समय में भारत का समस्या के बारे में अपने मिशन के अक्षमता के बारे में तथा का तात्पर्य कर जा भूत वयान

दिये और सारा दोष गांधी जी तथा कांग्रेस के ऊपर मढ़ दिया, ये बातें किसी भी देशभक्त तथा आत्म-सम्मान रखने वाले व्यक्ति को सहन नहीं हो सकती थीं। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जो क्रिप्स भारत रहते हुए वाड्सराय तथा ब्रिटिश स्थित युद्ध-मन्त्रिमण्डल की इच्छाओं के विरुद्ध भारतीय नेताओं से समझौता वार्ताओं में बहुत अधिक मात्रा में भारत की मांगों को मानने लगे थे और टोरी नेताओं के व्यवहार से झुल्ला तक उठे। वही क्रिप्स इंग्लैंड जाकर फिर उन्हीं टोरी नेताओं के शब्दों में गांधी जी तथा कांग्रेस की तीव्र भर्त्सना करने लगे थे। वास्तविकता यह थी कि कांग्रेस क्रिप्स योजना के सदर्थ में न तो मुस्लिम जनता के ऊपर अपनी सत्ता थोपना चाहती थी और न ही वह प्रस्तावित योजना में किसी जनसमूह को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय मध्य में बलपूर्वक मिलाना चाहती थी जैसा कि 10 अप्रैल के उसके प्रस्ताव से स्पष्ट था। डा० सीतारामैया ने गांधी जी के विचारों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि गांधी जी ने यहाँ तक घोषित किया था कि यदि अंग्रेज भारत की शासन-सत्ता सम्पूर्ण भारत की सत्ता के नाम पर मुस्लिम लीग को सौंप दे जिसमें कि तथाकथित भारतीय भारत शामिल है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा हो जाने पर भारत की स्वतन्त्र सरकार के रूप में लीग के साथ कांग्रेस हर प्रकार से सहयोग करेगी। गांधी जी को क्रिप्स प्रस्तावों से जरा भर भी सन्तोष नहीं था। वे वास्तव में क्रिप्स के साथ वार्ता करने को राजी ही नहीं थे। परन्तु भारतीय नेताओं के आग्रह पर जब वे प्रथम बार क्रिप्स से मिले और क्रिप्स ने उन्हें अपने प्रस्तावों का प्रारूप दिखाया तो उन्होंने तुरन्त उन्हें अस्वीकार कर दिया। उनके बाद वे फिर क्रिप्स मिशन से कभी नहीं मिले। अन्य नेता ही उसमें बातें करते रहे। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो अंग्रेज हिटलर, मुसोलिनी या तोजो को साम्राज्यवादी कहकर दोष देते हैं वे स्वयं उनसे भी निकृष्ट रूप के साम्राज्यवादी हैं। क्रिप्स तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासक गांधी जी के इन विचारों में रुष्ट हो गये थे और झूठ-झूठ ढग से तोड़-मरोड़ कर उन्होंने मित्र-राष्ट्रों विशेषतः अमरीका को सन्तोष दिलाने के लिए उल्टा प्रचार प्रारम्भ किया। गांधी जी ने कहा कि 'आज जिस वनावटी आलोचना को मैं देख रहा हूँ वह पूर्णतः भ्रष्टता से भरा है, इसका उद्देश्य मुझे डराना तथा कांग्रेस की निन्दा करना मात्र है। यह एक ऐसा झूठा खेल है कि वे यह भूल जाते हैं कि इसके कारण मेरे हृदय में कैसी आग लग रही है।

क्रिप्स के चले जाने पर उनके मिशन की असफलता तथा युद्ध की प्रगति एवं मिशन की प्रतिक्रिया आदि ने भारतीय राजनीति के वातावरण को अत्यन्त अन्धकारमय तथा अनिश्चित बना दिया था। गांधी जी ने इस मारी स्थिति पर गम्भीरतम विचार करना प्रारम्भ किया। साथ ही कांग्रेस का सम्पूर्ण नेतृत्व भी भावी कार्यक्रम के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में था। कांग्रेस क्रिप्स प्रस्तावों को तो अमान्य कर ही चुकी थी। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक इलाहाबाद में हुई। उसने कार्य समिति के उक्त निर्णय को स्वीकार किया और यह प्रस्ताव किया कि भारत के ऊपर घुरी शक्तियों (जापान) के आक्रमण की स्थिति में कांग्रेस आक्रमणकारी के साथ अहिंसात्मक असहयोग करेगी। गांधी जी इस बैठक में नहीं गये थे, परन्तु उन्होंने अपने कुछ विचार इसके समक्ष भेजे थे। उनके मत से स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मित्र है जिसने भारत को बलपूर्वक दबा रखा है, अतः ब्रिटिश तथा उसके मित्रों का युद्ध में कोई नैतिक आधार नहीं है। अतः ब्रिटिश को भारत में अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। राजगोपालाचारी ने यह मत व्यक्त किया था कि तत्कालीन परिस्थितियों के सदर्थ में मुस्लिम लीग की मांगों को स्वीकार कर लेना व्यावहारिक होगा। कांग्रेस ने अपने पूर्व मिद्धान्तों के अन्तर्गत इसे नहीं माना। अतः राजगोपालाचारी ने कार्य समिति में त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में बताया कि जब कांग्रेस विभिन्न प्रान्तों के मध्य में प्रवेश के निमित्त आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को मान चुकी है तो लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकराना अव्यावहारिक होगा। वस्तुतः नैतिक दृष्टि में राजा जी सही कहते थे, परन्तु भावात्मक दृष्टि में कांग्रेस भारत की एकता के हित में इसे अनुचित समझती थी। दुर्भाग्य में कांग्रेस ने तत्कालीन परिस्थितियों के सदर्थ

म दश व किमा भाग की जनता की इस स्वतन्त्रता या अमाय कर दिया कि वह भारत में जनगृह मन्त्री ।

अब समस्या यह थी कि इन प्रस्तावों को सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम अपनाया जाय । कांग्रेस ने इसका समाधान गांधी जी पर छोड़ दिया । गांधी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की प्रतिरक्षा तथा ब्रिटन की सुरक्षा इसा बात पर निर्भर करती है कि अंग्रेज लोग तुरन्त भारत में अपनी सत्ता हटा दें । उनका मत था कि जाक्रमणकारी जापान का उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करना है । गांधी जी यह भी नहीं चाहते थे कि जापान का मदद से अंग्रेजों का भारत से निर्यात जाय क्योंकि जापान के डगला क्लार्क में भी गांधी जी का नाथु था । उन्हें यह भी चिन्ता नहीं थी कि अंग्रेज सत्ता किस सीमा पर उठान कर दिया कि वह भगवान् के हाथ में सत्ता सीप भारत में चढ़ जायें । गांधी जी का अंग्रेजवर्ग की स्थिति में जान की भाँति चिन्ता नहीं थी । उनका मत था कि समता की स्थिति में तो अंग्रेजवर्ग की स्थिति अच्छी है । युद्ध के परिणामों के बाद उनका कर्तव्य था कि जनता जीत या न जान साम्राज्यवाद का नष्ट हो जाना निश्चित है । अंग्रेजों ने शक्ति के रूप पर भारत में साम्राज्य प्रथम किया है अतः भारत में उनकी सत्ता घटाना या भारत की रक्षा के अधिकारों का अंग्रेजों के हाथ में न रहने का उनका कोई धायपूण या नैतिक दावा नहीं हो सकता । गांधी जी ने समस्त पञ्चतन्त्र पर विचार करके भारत छोड़ो आन्दोलन के कार्यक्रम का निश्चय लिया । उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत छोड़ो का अभिप्राय यह नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज लोग भारतभूमि में न रह जायें । इसका अर्थ यही था कि अंग्रेज भारत के ऊपर अपनी शासन सत्ता का छोड़ दें । उन्होंने चीन के राष्ट्रपति च्यांग काइ शेक तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का भी अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था । वे यह भी नहीं चाहते थे कि भारत से जापानी आक्रमणकारियों को रोकने वाली मित्र राष्ट्रों की सहायता चली जायें । उनका धारणा यह थी कि जब भारत में अंग्रेज सत्ता नष्ट जाएगी और भारत स्वतन्त्र हो जायगा तो भारतवासी मित्र राष्ट्रों का सत्ता का और अधिक सहायता में योगदान करेंगे ।

14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और इस स्वीकृति दी । 7 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मुख इस पर विचार करने का पुनर्निर्देश किया ।

भारत छोड़ो प्रस्ताव—कांग्रेस समिति ने उक्त प्रस्ताव के अनुसार यह घोषणा की गयी थी कि भारत एक संयुक्त राष्ट्र के हित में अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक सत्ता का परित्याग सबसे प्रथम आवश्यकता है । वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का टर करने तथा महायुद्ध में विन्ता आक्रमण से भारत की रक्षा करने के अलावा उक्त प्रस्ताव को मानने का ब्रिटिश सत्ता हट जाय । सभी भारतवासी आत्म विश्वास तथा आम-सम्मान की भावना से अंग्रेजों को अपना समस्याओं का स्वयं हल करेंगे । अविध्य के सम्बन्ध में कुछ प्रतिपादित करने मात्र में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में निर्यात एक भार एक अभिभार है ।

इस प्रस्ताव में आगे कहा गया था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पश्चात् तुरन्त एक अन्तरिम सरकार की स्थापना करनी जायगी जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता के सत्य प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व होगा और वह सरकार समस्त राष्ट्र में सभी सम्बन्ध स्थापित करेगी । कानून तथा वह सरकार सविधान सभा की स्थापना करके भारत के भावी सविधान का निमाण करा देगा । इस अनुसार भारत एक ऐसा मध्यम मार्ग जिसमें घटना का अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी और अवशिष्ट शक्तियाँ उन्हीं को प्राप्त होंगी ।

इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए पुनः जनता का आह्वान किया गया कि वह अपने स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता के अधिकारों का प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक अमर्याद आन्दोलन प्रारम्भ करे । कांग्रेस ने पुनः गांधी जी का नए आन्दोलन का निश्चय करने तथा राष्ट्र का माग्यमान करने का

अधिकार दे दिया। यद्यपि गांधी जी ने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को प्रारम्भ करने में जनता से 'करो या मरो' की भावना से कार्य करने की प्रेरणा दी थी, तथापि गांधी जी तथा कांग्रेस दोनों ने यह चेतावनी दी कि आन्दोलन में हिंसा की भावना कदापि नहीं आनी चाहिए। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को भारतीय स्वतन्त्रता की तुरन्त घोषणा कर देने के लिए विवश करना था।

आन्दोलन का आरम्भ तथा सरकार द्वारा दमन—वास्तव में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन कांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव तक ही सीमित रहा। चूँकि यह आन्दोलन आम जनता के आन्दोलन के रूप में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के रूप का होता और यदि यह अपने मूल प्रवर्तक गांधी जी के निदेशन में संचालित होता तो इसका रूप कुछ और होता। परन्तु जिस रूप में यह आन्दोलन एक क्रान्तिकारी संघर्ष के रूप में परिणत हो गया उसका दायित्व पूर्णतया तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर था। निम्नलिखित यह आन्दोलन जितना उग्र तथा हिंसात्मक हुआ उसके लिए सरकार उत्तरदायी थी अथवा यह कहना असंगत न होगा कि स्वयं सरकार ने उसे हिंसात्मक बना दिया।

महाममिति की 7 अगस्त 1942 की बैठक से पूर्व ही सरकार सजग हो चुकी थी। 17 जुलाई 1942 को भारत सरकार के सूचना महानिदेशक ने सभी प्रांतीय सरकारों को एक गम्भीर पत्र भेजकर कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने का आदेश दे दिया था और भारत सरकार ने 8 अगस्त तक विविध आदेशों के द्वारा प्रांतीय सरकारों को सम्भावित आन्दोलन को कुचल देने की सभी तैयारियाँ करने के लिए सजग कर दिया था। 7 अगस्त के महासमिति के प्रस्ताव में आन्दोलन के कार्यक्रम पर गांधी जी ने ये विचार व्यक्त किये थे—'इस आन्दोलन में जनता हिन्दू-मुस्लिम के भेदभाव को भुलाकर अपने को भारतीय समझे, हमारा भगडा अंग्रेज लोगों के साथ नहीं है न उनमें हमें घृणा है, प्रत्युत हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, सत्याग्रह में किसी प्रकार की भूठ या वैदमानी को स्थान नहीं होता, करो या मरो, या तो भारत स्वतन्त्र होगा या इस प्रयास में मर मिटो।' इसी के साथ गांधी जी ने पत्रकारों, देशी नरेशों, सरकारी कर्मचारियों, विचारियों, सेनिकों आदि सभी के निमित्त उनके आन्दोलन के सम्बन्ध में कर्तव्यों का उल्लेख किया। प्रस्ताव का उद्देश्य यह नहीं था कि आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था। गांधी जी बाइसराय में मिलकर उसे समूची स्थिति से अवगत करा देना चाहते थे, और यदि सरकार न मानती तो सभी आन्दोलन का श्रीगणेश होता। गांधी जी ने राष्ट्र के विविध वर्गों के निमित्त कार्यवाही करने का व्यापक कार्यक्रम बना लिया था, उसमें सविनय अवज्ञा सम्बन्धी व्यापक निर्देश थे। आन्दोलन 24 घंटे की एक गान्धिपूर्ण हड़ताल में प्रारम्भ होता। 8 अगस्त 1942 को इस कार्यक्रम पर महाममिति ने विचार किया और 9 अगस्त को इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाना था। परन्तु सरकार इसे कुचलने के लिए इतनी तत्पर थी कि उसके प्रयासों के अन्तर्गत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को बन्दी बना दिया गया। गांधी जी को पूना में तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को अहमदनगर किले की जेलों में रख दिया गया। कांग्रेस को गैर-कानूनी मर्यादा घोषित किया गया और उसके कार्यालयों को तहस-नहस कर दिया गया। राष्ट्र के महानतम नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना दावानल की लपटों की भाँति देश के कोने-कोने में फैल गयी। एक सप्ताह में भी कम की अवधि में देश के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता, प्रांतीय, जिला तथा मण्डल समितियों के सभी सदस्य जेलों में बन्द कर दिये गये। सूचना महानिदेशक पकल (Puckle) के गम्भीर पत्र ने जनुमार नैतिक मिट्टान्तों का कोई प्रश्न नहीं था, प्रत्युत व्यावहारिकता नेतृत्वविहीन जनता में हड़ताल, जलूस, सार्वजनिक बैठकों आदि का महारा लिया। सरकार ने इन्हे दवाने में नाड़ी जाज, गोली चलाता, बलात् लोगों को रोकना जादि हिंसात्मक साधन अपनाये। जेलों में सत्याग्रहियों के साथ अमानुषिक, निन्द्यतापूर्ण तथा श्रममानजनक व्यवहार किया गया। शान-शान में आन्दोलन को दवाने के लिए पुलिस को सेना की मदद पहुँचायी गयी। महिलाओं ने सारा भी सत्याग्रह किया गया। लगभग सारे देश में सर्वत्र सप्ताह 14-4 लगा दी गयी। इनमें

आन्दोलन नष्ट हो जायेगा और आन्दोलनकारी भी अनेक स्थान पर हिंसात्मक कार्य करने का विवश हो जायेंगे। कृष्ण स्थाना पर भूमिगत पन्थान भी हुए। सरकार सम्पत्ति का नष्ट करना अमान्यता को जताना खोजाना का तूटना रत तार का तानना का कानना पुनिस थाना पर आक्रमण आदि ऐसी अनेक घटनाएँ हुई। सरकार ने सावधानिक सम्पत्ति के नष्ट होने पर समापवर्ती जनता से सामूहिक प्रति प्रति करवाना शुरू किया। समाचार-पत्रों पर भारी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस प्रकार एक एक मनुष्य का सा वातावरण बन गया जिसमें सरकार तथा जनता दोनों का जन तथा धन का हानि उठानी पड़ी।¹ त्रिनिदाद तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन अधिक उग्र रहा। उत्तर प्रदेश के वनियारा जिले में तो एक दिन तो प्रशासन ठप्प हो गया और आन्दोलनकारियों ने अपनी सरकार स्थापित कर ली। तीन या चार महाना तक आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया परन्तु जन में सरकार से नियन्त्रित करने में सफल हो गयी। देश की अधिकांश जनता तो एक भ्रम में पड़ गयी थी कि त्रिनिदाद सरकार ने गांधी जी तथा अन्य उच्च नेताओं का देश से बाहर जाना था पर पहुँचा दिया।² कुछ लोग तो सरकार के दमनकारी स्वयं से डरने भयभीत हो गये थे कि उन्हें यह सन्देश मिलेगा कि अग्रज गान्धिका ने गांधी जी की प्रति प्रमुख नेताओं का मार डाला है। समाचार-पत्रों पर प्रतिबन्ध था देश में पूजनया जनता का राज्य था ऐसी स्थिति में कांग्रेसी नेताओं का बर्तन करने तथा आन्दोलन में भाग लेने वाला का न्यायतापूर्वक दमन करने की त्रिनिदाद गान्धिका का नाति के कारण जनता आतङ्कपूर्ण शासन का गिहार बनी हुई थी। कृष्ण स्थाना पर हिंसा तूट मार तथा सरकारों सम्पत्ति का नष्ट करने में गुप्त। तथा वन्दना का भी हाथ लगा परन्तु उसके दुष्परिणाम आन पास की निर्दोष जनता का भागने पड़े।

यद्यपि सक्रिय आन्दोलन का दवान में सरकार सफल हो गया थी तथापि अनेक कार्यकर्ता विविध रूप से समाजवादी दल के अनेक प्रमुख नेता (जयप्रकाश नारायण राममनोहर लाल आदि) अरुणा आम्बे जेता आदि) त्रिनिदाद सरकार का पकड़ में नहीं आये। दाल में जयप्रकाश जी का पुत्र पकड़ लिया गया। ये लोग भूमिगत प्रयास करने रहे और त्रिनिदाद गान्धिका काय करते रहे। इस प्रकार कांग्रेस तथा समाजवादी दल ने भारत छोड़ो आन्दोलन का पर्याप्त तीव्र कर दिया। भले ही सरकार ने हिंसा तार नसका करने किया तथापि इस आन्दोलन ने भारत की जनता की राजनीतिक चेतना को पर्याप्त मात्रा में जागृत कर दिया। इसमें पूर्व के आन्दोलनों में जनमाधारण का जो बग स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रति उत्पन्न रत्ता था वह भी अब नतता जागृत हो गया कि वह उस दिन का प्रतीक्षा करने लगा जब देश अग्रजी गान्धिका से मुक्त हो जाय। आन्दोलन का अग्रवि में स्वतन्त्रता के द्वार में जनमाधारण में आगा तथा निगगा नाना था परन्तु ऐसा विश्वास लाग करने लग था कि अतिरिक्त कान तो अग्रज भाग्य का न्यायता की स्थिति में बनाय रखने का माहम नहीं करेगा।

परन्तु भात के साम्यवादिता ने इस आन्दोलन में कां के अधिकृतपूर्ण रूप नहीं रखा। अब तक हम युद्ध में अग्रजा की जार से प्रविष्ट नहीं जाया था तब तक के युद्ध का साम्राज्यवादी रत्त था। परन्तु ऐसा ही इस युद्ध में बूना था उसे जन-युद्ध कहने लग। चूँकि उस समय हम नया चरण मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत भारत के साम्यवादी लोग स्वतन्त्रता आन्दोलन से बाहर रहे। सम्भवतः उन्हें अग्रजा का न्यायता की अपेक्षा हम के दामन ग्रहण करने की अभिप्राय देग का स्वतन्त्रता से अधिक प्रिय था। मुस्लिम लोग ने आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार करने पर अच्छा अवसर प्राप्त किया। उसने यह प्रचार किया कि भारत छोड़ो आन्दोलन का उद्देश्य कांग्रेसी लोग त्रिनिदाद सरकार से अपनी मार्गें बनवाना तथा उसके बाद मुसलमानों के उपर हिंसा का निरकुण शासन स्थापित करना था।

गांधी जी का उपासक—आन्दोलन पर नियंत्रण पाने के पन्चानु त्रिनिदाद गान्धिका ने

महात्मा गांधी तथा कांग्रेस पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि उन्हीं की प्रेरणा से यह हिंसात्मक आन्दोलन छिड़ा है। गांधी जी इस आरोप को सहन नहीं कर सके। वास्तव में स्वयं गांधी जी अनेक स्थानों पर जनता द्वारा हिंसात्मक कार्य-कलापों को अपनाने के समाचारों से अत्यन्त खिन्न थे। शासन द्वारा उनके ऊपर हिंसा को प्रोत्साहन देने के आरोप लगाये जाने पर उन्होंने यह माँग की कि या तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाय या उनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाय। परन्तु सरकार किसी भी विकल्प के लिए राजी नहीं थी। उसकी एकमात्र शर्त यह थी गांधी जी आन्दोलन को वापिस ले। परन्तु बिना कार्य-समिति के सदस्यों से परामर्श किये यह सम्भव नहीं था। अन्ततः, अपने स्वभावानुकूल उन्होंने 10 फरवरी 1943 से 21 दिन का उपवास करनी की घोषणा की। इस उपवास की अवधि में वे जेल में थे जहाँ 13 दिन के बाद उनकी स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई। डाक्टरों ने भी यह घोषित कर दिया कि यदि उन्हें मुक्त नहीं किया गया तो उनका जीवन खतरे में है। गवर्नर-जनरल ने अपनी कार्यकारी परिषद् की आपात बैठक बुलाई जिसके अधिकांश सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि गांधी जी की रिहाई से शान्ति-व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। अतः गांधी जी को मुक्त नहीं किया गया।

गवर्नर-जनरल की परिषद् के बहुसंख्य सदस्यों की ऐसी राय के विरोध में तीन भारतीय सदस्यों (सर्वश्री एच० पी० मोदी, एम० एस० अणे तथा एन० आर० सरकार) ने परिषद् से त्याग-पत्र दे दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि गवर्नर-जनरल ने भारतीय सदस्यों के बहुमत वाली परिषद् बना ली थी, तथापि अधिकांश भारतीय सदस्य ब्रिटिश सरकार के भक्त थे। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश शासकों को गांधी जी के प्राणों की चिन्ता नहीं थी। वे गांधी जी की मृत्यु हो जाने की आकांक्षा रखते थे। सम्भवतः ऐसी स्थिति आ जाने पर उसका सामना करने के लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली थी। परन्तु गांधी जी का उपवास मरुतता-पूर्वक पूरा हो गया।

सरकार का मिथ्या प्रचार—1942-43 की अवधि में यूरोप में महायुद्ध की गति मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में बढ़ने लगी थी। हिटलर तथा मुसोलिनी की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। इसका कारण यह था कि यूरोपीय मित्र-राष्ट्रों को रूस तथा अमरीका की सक्रिय सहायता मिलने लगी थी। परन्तु सुदूर पूर्व में जापान की गतिविधियों का विस्तार होने लगा था, और जिन भारतीय फौजों ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था उन्हें नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा उनके क्रांतिकारी साथियों ने आजाद हिंद फौज के रूप में संगठित करके भारतीय स्वतन्त्रता के निमित्त जापान के सहयोग से भारत की ओर यान करने की योजना बना ली थी। अतः बड़े-बड़े मित्र-राष्ट्रों की अभिरुचि भारत की समस्या की ओर होने लगी थी। अमरीका का जनमत भारत में ब्रिटिश नीति के बारे में निश्चित नहीं था। भारत-स्थित अमरीकी पर्यवेक्षक तथा पत्र-भारत की स्वाधीनता की माँग के प्रति सहानुभूति रख रहे थे। ऐसी स्थिति में अमरीकी जनता का ध्यान वास्तविकता से हटाने के लिए और ब्रिटिश नीतियों के पक्ष में जाने के लिए ब्रिटिश शासकों ने ब्रिटिश मसद तथा भारत में भ्रामक प्रचार अभियान प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने युद्ध की समाप्ति पर भारत की स्वतन्त्रता की माँग जैसी क्रिप्स प्रस्तावों में भी, को मृत नहीं माना। परन्तु तुरन्त मत्ता त्यागने के वाग़े में अपनी पुगानी नीतियों को ही डुहराने लगे कि भारत में सत्ता किसे सौंपी जा सकती थी। साम्प्रदायिक वर्गों तथा गुटों के हितों की बात को ही वे सर्वोच्च महत्त्व देने लगे। यहाँ तक कि ऐटली तक ने जो भाग्य की स्वायत्त शासन की माँग के समर्थक थे ऐसे ही वक्तव्य दिए। भारत में वाडमराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी थी। परन्तु उसमें न कांग्रेस शामिल थी न लोग। भाग्य सरकार ने क्रांति को शान्ति-व्यवस्था तथा देश की मुक्ति के अहित में हिंसात्मक बनाने का दोष कांग्रेस तथा गांधी जी पर लगाने का पुरजोर अभियान चलाया जो जनता की मुक्ति के दिन में अपने दमनात्मक रवैये का औचित्य प्रदर्शित करने की

काग्रेस का। उस प्रचार में उस नाग का सक्रिय महयाग मिला। मरकार न नीग की निष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य में उस उमक उद्देश्य का प्राप्ति के लिए पूरा आश्रयसत दिया और महायता भी पहुँचा। मरकार न वामनविक्रम का रूप में करने में अपन प्रचार कार्य के अंतर्गत कोई कमर नहा नहीं।

काग्रस विरोधी दलों के प्रोत्साहन—उस महान् स्वतंत्रता प्राप्ति में एक ओर काग्रस तथा जनता सरकार के भारी आस्थाचार तथा मन का मामला नग रहो था तो दूसरी ओर ब्रिटिश शासन की प्रेरणा तथा महयाग में मुस्लिम नीग जनता साम्प्रदायिक कुचारा का सुहा करने में नगा थी। जिन्ना के प्रयासों से वगान में यद्यपि नीग की मरकार नहा बन पायी तथापि फजनुन नक न नीग के मिद्वानता के प्रति पूण आस्था व्यक्त करती। परंतु उमक सम्मिलित मन्त्रिमण्डल में जिसमें सुभाष दाम का फारग नता भी शामिल था गवर्नर जमनुन था। उसने एक का त्यागपत्र दान को विवग किया और नीग के नेता नाजिमुद्दीन का मुख्य मंत्री बनाया। पञ्जाब में दिसम्बर 1942 में मिस्तर हयातखा का मृत्यु का जान पर गिज हयात खा का मन्त्रिमण्डल बना। परंतु अविनाशिया न उम भी नीग के प्रभाव में आ जान का वाध्य किया। सिंध में अन्नावग अग्रजा का दमन नाति से जमनुन हा गया था अतः गवर्नर ने उसे पदच्युत करके नीगा नेता गुलाम हुसैन का मुख्य मंत्री बना दिया। पश्चिमात्तर सीमा प्रांत में डा खान साहब त्यागपत्र चुन द। जन वहा भी नीगा नेता आरगजब खा का मुख्य मंत्री बना दिया गया। जम्मू में नीगी नेता माल्लन न सरकार बना नी। उस प्रकार दश के पांच मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों की सरकारों में नाग का पूरा प्रभाव हा गया और जिन्ना के निम्नान में न प्राता का भाग में प्रथम हान का अभियान मुनिश्चित हा गया। यन् भी अग्रजा की काग्रस विरोधी नीति की एक भारी उपनति थी।

लाड बवेल का गवर्नर जनरल बनना तथा ब्रिटिश नीति में परिवर्तन—अक्टूबर 1943 में लाड तिनतिथगा का गवर्नर जनरल का कार्यभार समाप्त हान पर कमन्वेल्थ चीफ लाड बवेल का भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सम्भवत यह व्यवस्था नसलिए की गई कि बवेल का भारत की प्रतिस्थापक व्यवस्था की पूण जानकारी पूर्व में ही हान के कारण वह गवर्नर जनरल के पद पर उचित सिद्ध हाग। उस बीच जापान की युद्ध सम्प्रती गतिविधिया नीत्रता में बन रही थी। दक्षिण पूर्वो एशिया में आजान हिंद फौज का मगानन नेताजी सुभाषचन् बोस कर रन् थ। यन् सना भारत की आन्तरिक सीमा में पूर्व का ओर में प्रविष्ट हो चुकी थी। उसको जापान का सहयोग प्राप्त था। अतः ब्रिटिश मरकार भारत की एमी स्थिति में बन्त चिन्तित थी। मई 1944 में नान बवेल ने गांधी जी का जन में रिक्त कर लिया। परंतु गांधी जी के आग्रह के बावजूद काग्रस के अथ प्रमुख नेताओं का रिहा नहीं किया गया। गांधी जी के लिए स्वयं काई नियम बना सम्भव नहा था। जन भारत छोडा आन्दोलन समाप्त नहा हुआ। राजनीतिक गतिरोध बना रन् स्वयं मरकार भी उम दूर करने के लिए चिन्तित थी।

सी० आर० सूत्र (गजाजी फामूना)

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1942 तक काग्रस के प्रमुख नेताओं में मथे। वह गांधी जी के अनन्य समर्थक में मथे। 1942 में जब ब्रिप्स वार्ता चल रही थी तो उन्होंने यह अनुभव किया था कि मुस्लिम नीग पाकिस्तान की मांग में किता भा रूप में डिगने वाली नहीं है। स्वयं ब्रिटिश सरकार निरन्तर नीग का एमी माँग के लिए आत्माहित करती जा रही है। ऐसी स्थिति में दान की स्वतंत्रता तथा भावी सांविधानिक व्यवस्था के समाधान के लिए पाकिस्तान के सजन की माँग का न मानना उचित नहा है। काग्रस ऐसा माँग का पूण विरोध कर रही थी। एमी स्थिति में ब्रिप्स वार्ता की विफलता के पश्चात् भी राजगोपालाचारी काग्रस से अलग हो गये और पाकिस्तान के सजन के सम्बन्ध में विचार करने लगे। चकि भारत छोडा आन्दोलन की

अबत्रि मे वे काग्रेस से पृथक् थे, अतः उन्हें बन्दी नहीं बनाया गया था। मई 1944 मे जब गांधी जी जेल से छूटे तो राजाजी गांधी जी से मिले और उनसे अपने प्रस्ताव के बारे मे वार्ता की। बाद मे उन्होंने यह घोषणा की कि उनके प्रस्ताव को गांधी जी का अनुसमर्थन प्राप्त है। इसी प्रस्ताव को मी० आर० सूत्र कहा जाता है।

सूत्र—यह प्रस्ताव गांधी जी तथा जिन्ना दोनों के द्वारा एक सन्धि के रूप मे अनुसमर्थित किया जाता था। इसकी शर्तें अग्राहित थी—

(1) भारतीय स्वतन्त्रता की माँग से सहमत होते हुए मुस्लिम लीग सक्रमण काल मे काग्रेस के सहयोग से एक अन्तरिम सरकार की स्थापना से सहमत है।

(2) युद्ध की समाप्ति पर एक आयोग की नियुक्ति की जायेगी तो भारत के उत्तर-पश्चिम तथा पूर्वी क्षेत्रों के मुस्लिम बहुसंख्यक जनता वाले क्षेत्रों का निर्धारण करेगा और उन क्षेत्रों की समस्त जनता निर्धारित मतदान प्रणाली से हिन्दुस्तान मे रहने या पृथक् रहने के बारे मे अपना निर्णय करेगी। यदि बहुसंख्यक मनदाता भारत से पृथक् होने की माग करेगे तो उसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

(3) ऐसा विभाजन हो जाने पर दोनों देशों की पारस्परिक सहमति द्वारा प्रतिरक्षा, यातायात, व्यापार, आदि की व्यवस्था की जायेगी।

(4) दो प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्रों के बन जाने पर उनकी जनता के पारस्परिक स्थानान्तरण की पूर्णतया ऐच्छिक आधार पर स्वीकृति दी जायेगी।

(5) यह शर्तें तभी लागू होंगी जबकि इंग्लैण्ड भारत को पूर्णतया राजसत्ता का हस्तान्तरण कर देगा।

(6) गांधी जी तथा जिन्ना इन शर्तों से सहमत हैं और वे क्रमशः काग्रेस तथा लीग मे इसे मनवाने के लिए प्रयास करेंगे।

श्रालोचना तथा प्रभाव—यद्यपि तत्काल राजाजी के इस प्रस्ताव के सम्बन्ध मे कांग्रेसी क्षेत्रों एवं देश मे बड़ी निराशा तथा आश्चर्य की स्थिति जा गई और बहुत कम लोग राजाजी की पाकिस्तान निर्माण की स्वीकारोक्ति से सहमत हुए, तथापि यह मानना पड़ेगा कि राजाजी का निष्कर्ष उनकी राजनीतिक दूरदृष्टिता का प्रमाण था, क्योंकि अन्ततः पाकिस्तान बनकर रहा और देश की स्वाधीनता-प्राप्ति के हेतु इसे स्वीकार करना पड़ा। परन्तु तत्काल स्वयं जिन्ना ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर ठुकरा दिया कि जैसा पाकिस्तान राजाजी के सूत्र द्वारा प्रस्तावित किया गया था वह 'लुज-पुज तथा दोमको द्वारा खाया गया' (maimed, mutilated and moth-eaten) पाकिस्तान है। वास्तव मे जिन्ना तो सम्भवतः समूचे देश को पाकिस्तान बना देना चाहते थे जिसमे मुस्लिम लीग ही एकमात्र शासक रहे। कम से कम उनकी व्यक्ति वारणा का पाकिस्तान सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान, समूचे वगाल, असम एवं पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के मध्य एक लम्बी गैलरी वाला पाकिस्तान था। यदि पाकिस्तान का निर्माण होना ही था और राजाजी के सूत्र की जिन्ना स्वीकार कर लेते तो सम्भवतः देश विभाजन के समय बाद मे जो कटुता का वातावरण फैला और जिसके कारण इतनी खून-खराबी हुई वह न होती। कुछ विद्वानों का मत है राजाजी के सूत्र के अनुसार जिस रूप मे पाकिस्तान की योजना थी, वह 1947 मे निर्मित पाकिस्तान की तुलना मे कहीं अधिक अच्छी थी।¹

आजाद हिन्द फौज (I N A)

मुभापचन्द्र वोन द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण—जब 1939 मे मुभापचन्द्र वोन

¹ See R. N. Agarwal, *op cit*, 239

राष्ट्रम ठान चुकता उहान भारत का स्वतन्त्रता का निमित्त गांधी जी की अहिंसात्मक सत्याग्रह या नानिया पर विश्वास करना दान दिया और चूक काग्रस का दक्षिणपथा नेता गांधीवादी हा य अत राम न वामपथी फाग्व नाक दन की रचना की। इस दन म भारत क क्रांतिकारा नेता तथा युवा पीठा क वामपथी कायकता गामिन हा गय। उहान भारत म ब्रिटिश राज का उपाड फवन क निमित्त तो फाट तथा विवस की कायवाहिया का ठाक ममभा। प्रारम्भ म जयप्रकाश जी भी एमी कायवादा का उचित समझत थ। प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि स भारत म मेस तत्त्व सन्निय र्थ और व सगठित दना क द्वारा क्रांति करन क पड्यन रचत र्थ। द्वितीय विश्वयुद्ध म पूव सुभाषचन्द्र बोस भा क्रांतिकारी हात जा रह थ। उहान 1935 म The Indian Struggle नामक रचना प्रकाशित की था जिस भारत सरकार न प्रतिवाधत कर दिया ना। युद्ध म पूव जब क काग्रस स अलग हा गय तो उहान युद्ध का नाम उठाकर अग्रता की सत्ता का भारत म उठा केंद्रन क उद्देश्य स नय र्थ की रचना की। उहान अपनी उक्त रचना म लिखा है कि भारतवामिया का अहिंसा क गांधीवादी दानतिक विचार या नहरु जा की धुरी गण्टा का विराधी वणिक नीति की भावनामूकता क द्वारा अवरुद्ध नहा किया जाना चाहिए।¹ काग्रस का अध्यक्षाता छान्त ही उहान सम्पण भारत का तूफाना दौरा किया और मरवा जन-समाज म आपण दकर त्रिणि साम्राज्याती का विराध करत हुए भारत की जनता का आन्दान लिया कि व युद्ध म ब्रिटेन की जरा भी मन्गयता न करें।

य अग्रन 1940 म ही सन्निय अवता आन्दान चना चुक थे। उन्हाने काग्रस क सहज अग्रज सरकार क साथ वार्ता करा की काई योजना नहा रखी। उनका निष्कप था कि युद्ध म ब्रिटेन की पराजय स त्रिणि साम्राज्य नष्ट हो जाणगा अत व भारत स सत्ता नही हटायेग तो जनता को बनात उ न निकानता पड़ेगा। त्रिणि भारतवामिया को ब्रिटेन क साथ युद्ध छड दना चाहिए और उसक गजरा क साथ सहयोग करना चाहिए। जुलाई 1940 का उह सरकार न जन म राज दिया। उनके न क अग्र कायकर्ता भी जनी कर गिए गय थ। जब म बोस न अनिश्चित बान का भूख ह्मतान प्रारम्भ कर दी ता सरकार न उह छाकर नजर कद म रखा। जनवरी 1941 म वाम र्थस्यमय र्थ स निकन भाग और वग बन्दकर काबुल मास्को हात हुए जमनी पहुँच गय। वहाँ म उहान अपने अश्वामिया को र्थ या द्वारा सन्ध भजना आरम्भ किया। वहा न फासा तथा नाजी नेताज म मिन और उनम जाग्रह करते र्थ कि व भारत की स्वतन्त्रता का गाय कर। मास्को म भी उहान एसा प्रयाम लिया किनु जब वहा उनके र्थ जाग्रह का उपात र्था गया ता वहा स उहान जापान जान की याजना बना।

समय युद्ध म जापान की मित्र राष्ठा न ऊपर भारी विजय जाता जा र्थी थी। अत सुभाषचन्द्र वाम र्थन की नीतिया पर विश्वास रखन वाना भारतीय जनमत एशिया र्थेशा का एसा प्रिज्या म अत प्रभावित र्था था और जापान क सन्धयोग म भारत का स्वतन्त्रता की आशा करने लगा था। जापान म रामविहारी वाम न भारताय स्वाधीनता लीग की स्थापना कर ली थी। र्थ लीग का उद्देश्य एक भारतीय मुक्ति मना का मगठन करना था। 22 जून 1942 का र्थका सम्मेलन वका म र्था जना सुभाषचन्द्र वाम का र्थकी अध्यक्षता करने का आमन्त्रण दिया गया।

आजाद हिन्द फौज का सजन—भारताय स्वाधीनता लीग न भारताय मुक्ति मना तथा जापाना मना क सन्धार न मन्ध म एक कायवाही परिषद् (Council of Action) क निर्माण या प्रस्ताव भी किया। प न जापाना मनिव अधिकागी इन विवरणा स सहमत नहा थ। जब जापान न मनाया म त्रिणि मनाथा का पराजित कर दिया ता त्रिणि मना क भारतीय सत्ता न जापान न समक्ष आत्मसमपण कर दिया था। र्थ मना क कप्तान मोहनमित्र का मना सन्नि

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में शामिल होने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार कैप्टन मोहनसिंह के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज का सृजन हुआ। वे इस सेना के प्रधान सेनापति बने। अगस्त के मध्य तक लगभग 16000 जवान इस सेना में हो गये थे। वे समस्त भारतीय युद्धबन्दियों को इसमें लेकर 40000 तक की सेना बनाना चाहते थे। परन्तु जापानी सैनिक अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं थे। कालान्तर में आजाद हिन्द फौज तथा स्वाधीनता लीग में कुछ आन्तरिक कलह भी उत्पन्न हो गये और मोहनसिंह ने त्यागपत्र दे दिया। इससे फौज में रिक्तता आ गयी। रासबिहारी बोस भी इस संगठन से अलग हो गये। परन्तु सुभाषचन्द्र बोस ने नेतृत्व करने का आश्वासन दे दिया था। प्रश्न यह था कि वे जर्मनी से जापान कैसे पहुँचें। किसी तरह 1943 के आरम्भ में वे एक जर्मन पनडुब्बी से होकर जापान पहुँच गये।

टोकियो पहुँचते ही सुभाषचन्द्र बोस ने पहला अभियान यह चलाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री तोजो को भारतीय स्वाधीनता को मान्यता देने के लिए राजी कर लिया। तत्पश्चात् सिंगापुर पहुँचकर उन्होंने भारतीय स्वाधीनता लीग तथा आजाद हिन्द फौज में आ गयी दरार को पाटा और दोनों का नेतृत्व स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की जिसके वे प्रधान, प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेनापति बने। उन्होंने एक मन्त्रिमण्डल भी बनाया। पदाधिकारियों ने विधिवत् पद-ग्रहण की शपथ ली। बाद में जापान, जर्मनी, इटली तथा छह अन्य देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। अब सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज के समक्ष अपना ओजस्वी भाषण देकर 'दिल्ली चलो' अभियान आरम्भ किया। एक आई० सी० एस० पद को लात मारने वाला देश-भक्त, क्रान्तिकारी नेता, कांग्रेस का चोटी का नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक का सृष्टा जब भारत की आजादी के निमित्त भारी से भारी जोखिम सहकर जापान पहुँचा तो आजाद हिन्द फौज तथा स्वतन्त्र भारत की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का प्रधान बन गया। उन्होंने सैनिक पोषाक पहन ली। आजाद हिन्द फौज ने उन्हें 'नेताजी' का प्रिय नाम दिया। आज वे इसी प्रिय नाम से भारत की स्वतन्त्रता के शहीदों के शिरोमणि के रूप में भारतवासियों के प्रिय हो चुके हैं।

स्वतन्त्र भारत की क्रान्तिकारी अस्थायी सरकार के प्रधान के रूप में उन्होंने इंग्लैंड तथा अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने अण्डमान निकोबार के भारतीय द्वीप जिन्हें उसने जीत लिया था, इस सरकार के हवाले कर दिये। इसके पश्चात् नेताजी ने आजाद हिन्द फौज को बर्मा होते हुए भारत की ओर कूच का आदेश दिया।

आजाद हिन्द फौज की समस्याएँ तथा असफलता—नेताजी ने फौज की कमान सम्भाल ली थी और सैनिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर ली गयी थी। फौज के जवानों का मनोबल उच्च था। परन्तु उसके समक्ष सबसे बड़ी समस्या अम्ब्रो-गस्त्रो तथा युद्ध की साज-सज्जा की थी। बर्मा तथा आसाम की जंगली से भरी पहाड़ियों से फौज को भारत की ओर कूच करना था। उसके पास रसद, शस्त्रास्त्र आदि नहीं रह गये थे। उधर युद्ध की प्रगति भी मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में बढ़ रही थी। अमरीका ने जापान की सेनाओं को दवाना आरम्भ कर दिया था। अतः जापानी सेनायें बर्मा से प्रशान्त महासागर के दक्षिणी भागों की बढ़ने लगी थी अतः आजाद हिन्द फौज को भी वापिस लौटने के लिए विवश होना पड़ा। जापानी सेना उसे शस्त्रास्त्रों तथा रसद से विहीन छोड़ती गयी। ऐसी स्थिति में आजाद हिन्द फौज को भारी परेशानियों में रहना पड़ा। जब नेताजी ने सेना की ऐसी स्थिति देखी तो वे भी बहुत परेशान हो गये। वे टोकियो में जापानी प्रधानमंत्री से सहायता के लिए पहुँचे, तो स्वयं जापान उस समय अमरीका के आक्रमणों से परेशान था। स्वयं फौज में एकता, मनोबल तथा अनुशासन भग होने लगा था। ओडे से निष्ठावान सैनिकों में काम नहीं चल सकता था। नतीजा यह हुआ कि 1945 के मध्य तक आजाद हिन्द फौज की दशा बहुत वृन्त वृन्त हो गयी। नेताजी रगून, बेंकाक, सिंगापुर टोकियो के चक्कर काटने में व्यस्त रहते थे। परन्तु जब अगस्त 1945 में जापान ने अमरीका

के अणुबम प्रयोग करने के फलस्वरूप आत्मसमर्पण कर लिया ता आजाद हिन्द फौज के रह सहे भाग का भविष्य भी अधकार में पड़ गया। नेताजी मिंगापुर बकाक तथा संगीन में ही अपना गतिविधियाँ जारी रख रहे थे।

18 अगस्त 1945 का जब वे हनीबुरहमान के माथ संगीन से टाकिया का एक हवाई जहाज में जा रहे थे तो फारमूसा के हवाई जड्ड पर जहाज में आग लग गयी। नेताजी इसमें बहन जन गये। उन्हें वहाँ से अस्पताल में जाया गया। इसके पश्चात् क्या हुआ यह कहानी आज तक भी रहस्यपूर्ण बनी हुई है। जा भी हो तब से नेताजी प्रकट नहीं हो पाये हैं। डा. ताराचंद का कहना है भारत के इस बहादुर सपूत की कहानी जिसने निरंतर भारत की स्वतंत्रता के स्वप्न देखे जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर दिया और जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नई दिशा प्रदान की समाप्त हो गयी।¹ इसी के साथ आजाद हिन्द फौज की कहानी भी समाप्त हो गयी।

योगदान—भने ही फौज का अभियान सफल नहीं हुआ और युद्ध की समाप्ति पर इसके अधिकारिया तथा सैनिकों को पकड़ लिया गया और बाद में इसके प्रमुख नेताओं के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया जिसमें देश के उच्चतम कार्गि के भारतीय वकीलों ने उनके पक्ष में दलील दी। बाद में उन्हें मृत्यु-दण्ड भी सुनाया गया और फिर उन्हें मुक्त भी कर दिया गया तथापि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिन्द फौज की निष्ठा को भुनाया नहीं जा सका। नेताजी तथा उनके साथियों ने इस फौज तथा भारतीय स्वाधीनता संग्राम के माध्यम से जो कार्य बनाये किये उनका पर्याप्त अंतराष्ट्रीय महत्त्व है। इन संगठनों ने भारतीय आंतरिक परिस्थितियों (माम्प्रदायिकता तथा बंधानिकतावाद) को उपेक्षा करके सद्यपय ब्रिटिश की याजना बनाकर भारत को ब्रिटिश साम्राज्यशाही से मुक्त करने का प्रयास किया। युद्धकाल में महानक्तिया के साथ युद्ध की घोषणा करना और भी युद्ध के साधनों का अभाव में यह दगाना है कि युद्ध के पश्चात् महानक्तिया (अमरीका तथा रूस) भारत की स्वतंत्रता के महत्व को नहीं भना सकी। आजाद हिन्द फौज ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सना भाडे के सैनिकों की सना नहीं है अपितु वह अपनी मातृभूमि के सच्चे सैनिकों की सना है। इन वीरों ने अपने अन्ध उत्साह का परिचय कर घोर से घोर सक्क में भी आत्मविश्वास तथा उत्साह से कष्ट सहन कर देने का ह्मत्त प्रस्तुत किया। यह कहना असंगतिपूर्ण नहीं होगा कि इस फौज की बहादुरी ने साम्राज्यवादियों की जंठें हिला दी। अब यह आगा नहीं रख सकत थे कि किराये के सैनिकों की सना द्वारा विद्व को साम्राज्यवाद की दास्ना के अन्तगत रखा जा सकता है। आजाद हिन्द फौज को भारत को सबसे बड़ी देन उनका जयहिन्द का नारा है जो आज स्वतंत्र भारत का प्रसिद्ध तथा लोक प्रिय नारा हो चुका है।

बबल याजना तथा शिमला सम्मेलन

राजनीतिक घातावरण—भारतीय राजनीति के अंतगत 1944 में गांधी जी की रिहाई तथा राजगपालाचारी जी के प्रस्ताव की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण घाते नहीं हुए। काप्रसी नेता जेला में थे। परंतु 1945 के प्रारम्भ के कई अंतराष्ट्रीय परिस्थितियाँ ने भारतीय राजनीति को पुनः सक्रिय हान का अवसर दिया। यूरोप में मित्र राष्ट्रों की जमनी तथा इटली के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त हो गई थी। अब जापान ही मित्र राष्ट्रों का एकमात्र शत्रु रह गया था। जापानी सनाओं के सहयोग में अस्त्र-सजा विहीन परंतु दग भक्ति के मनोबल से प्रेरित आजाद हिन्द फौज की शक्ति भी धीरे धीरे जा रही थी। यूरोप को युद्ध से राहत मिलने पर मित्र राष्ट्रों का ध्यान जापान को परास्त करने पर केन्द्रित हो गया था। आजाद हिन्द फौज

के अनेक प्रमुख नेता तथा सैनिक मित्र-राष्ट्रों की सेना द्वारा बन्दी बना लिए गये थे। जापान का पतन भी शीघ्र हो जाना लगभग निश्चित था।

भारत में साविधानिक गतिरोध बना हुआ था। मित्र-राष्ट्रों का इंग्लैण्ड के ऊपर इसे दूर करने के सम्बन्ध में दबाव जारी था। युद्ध ने इंग्लैण्ड को हर दृष्टि से निर्बल बना दिया था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अब वह अपनी पुरानी सर्वोच्चता की स्थिति खो चुका था। उसके साम्राज्यवाद को बनाये रखने के स्वप्न धूमिल पड़ चुके थे। अतः अब वह इस स्थिति में नहीं रह गया था कि भारत की स्वतन्त्रता की माँग को ठुकरा सके। इंग्लैण्ड में नये आम निर्वाचनों की तैयारी होने लगी थी। चर्चिल के नेतृत्व की रूढ़िवादी दल की सरकार भारतीय स्वतन्त्रता की माँग को टालती जा रही थी। मजदूर दल ने चुनाव अभियान में इसका लाभ उठाया और चर्चिल सरकार की इस बात के लिए निन्दा की कि वह भारतीय साविधानिक गतिरोध को दूर करने में पूर्णतया असफल रही है। इसी कारण भारत की प्रतिरक्षात्मक गतिविधियाँ निर्बल पड़ी हैं। चर्चिल की सरकार मजदूर दल के इस आरोप को निर्मूल करने के लिए चिन्तित थी, अन्यथा उसे निर्वाचनों में हानि उठानी पड़ती। अतः वह भी भारतीय समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाने के लिए प्रयत्न करने लगी।

भारत में लार्ड वैवेल को प्रधान सेनापति रह चुकने तथा लगभग डेढ़ वर्ष से गवर्नर-जनरल रह चुकने के कारण यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों की पर्याप्त जानकारी हो चुकी थी। वह क्रिप्स मिशन के साथ भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर चुके थे। अतः वह चर्चिल सरकार से सलाह-मशविरा करने मार्च 1945 में इंग्लैण्ड गये। जून में वहाँ से वापिस आते ही वह भारत के साविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना लाये जो वैवेल योजना के नाम से प्रसिद्ध है।

वैवेल योजना—चूँकि क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता का एक मुख्य कारण अन्तरिम काल की योजना का कोई सन्तोषजनक समाधान प्रस्तुत न कर सकना था, अतः वैवेल योजना ने इसी बात को लिया। अन्तरिम योजना का अभिप्राय तुरन्त केन्द्र में राष्ट्रीय तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। अतएव वैवेल योजना के अन्तर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय साविधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार तुरन्त गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् का पुनः सगठन करना चाहती है। इसके अनुसार गवर्नर-जनरल तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त अन्य सभी पार्षद भारतीय होंगे और गवर्नर-जनरल तथा प्रधान सेनापति के ऊपर देश की प्रतिरक्षा का दायित्व रहेगा। शासन के अन्य सभी विषय जिनमें वैदेशिक सम्बन्ध भी शामिल हों, भारतीय पार्षदों के हाथ में रहेंगे। ब्रिटेन के वाणिज्य सम्बन्धी हितों की देख-रेख के लिए भारत में एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जायेगी। गवर्नर-जनरल की परिषद् में हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बराबर सख्या में स्थान प्राप्त होंगे। गवर्नर-जनरल को कार्यकारी परिषद् के बहुमत के निर्णयों पर निषेधाधिकार प्रयुक्त करने की शक्ति प्राप्त रहेगी। भारत के शासन में भारत मन्त्री के नियन्त्रण को अधिकाधिक मात्रा में कम कर दिया जायेगा। यह योजना किसी भी भाँति भारतवासियों के भविष्य में अपने सविधान को निर्मित करने के अधिकार के विरुद्ध नहीं है। भविष्य में ऐसी वार्ता चलती रहेगी।

शिमला सम्मेलन—इस प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप देने के लिए यह आवश्यक था कि समुचित वातावरण बनाया जाय। अतः कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गृह कर दिया गया। 9 जुलाई 1945 से गवर्नर-जनरल ने शिमला में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं गांधी जी एवं जिन्ना को एक सम्मेलन में आमन्त्रित किया। सम्मेलन का कार्य लगभग 2 सप्ताह तक चला। परन्तु अन्त में 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता घोषित कर दी गई।

सम्मेलन के विफल होने के कारण स्पष्ट है। यद्यपि प्रस्तावित कार्यकारी परिषद् में हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बराबर स्थान देना किसी भी रूप में जीवित्यपूर्ण नहीं था, क्योंकि

भारत की जनसंख्या में हिंदु मुस्लिम अनुपात 7 : 3 का था तथापि कांग्रेस ने इसका विचार नहीं किया। वह भारत की स्वाधीनता सम्प्रदायी वाता में ऐसा जबरान उत्पन्न करना नहीं चाहता था। परन्तु कांग्रेस उस बात पर राजी नहीं था कि मुसलमान पापदा को नामांकन करने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग का लिया जाय। जितना उसी बात पर अखिर हिंदु मुसलमान पापदा लीग के द्वारा ही नामांकित किया जायेंगे। सचमुच कांग्रेस के लिए समझौते के निमित्त इतना उच्च कीमत देना कदापि उचित नहीं था। कांग्रेस कबल मात्र हिंदु जनता की सस्था नहीं थी बल्कि उसमें बहुत बड़ी संस्था में गण्टवादी मुसलमान भी प्रारम्भ में भी रहने जाय थे। 1945 में स्वयं मोताना जयुनकरनाम आज्ञा कांग्रेस अध्यक्ष थे। सम्मेलन वाता के मध्य गवर्नर जनरल ने उन्हें आवासन दिया था कि वे वाता में किसी एक दल द्वारा अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करने देंगे। पंजाब के संयुक्तवादी दल (unionists) ने मुसलमानों के नामांकन में अपने अधिकार का भी दावा किया। जितना ने याजना को मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि यदि उस स्वीकार कर लिया जायगा तो सरकार में लीग का प्रतिनिधित्व एक तिहाई रह जायगा और उसका जय हागा पाकिस्तान की मांग की अस्वीकृति उस प्रकार कबल जिद्दा की हठधर्मिता से निम्नता सम्मेलन विफल हो गया और राजनीतिक गतिराव बना रहा।

सूयाकन—यद्यपि वक्त्र योजना भी त्रिप्स प्रस्तावों की भांति विफल हो गई तथापि यह प्रभावहीन मिथ नहीं हुई। उसका कारण कांग्रेस के नेतागण जेता में दूट गये और जो नहीं दूट थे उनकी रिहायश का तार भी खुन गया। जिद्दा की हठधर्मिता ने जो निम्नता सम्मेलन की विफलता का एकमात्र कारण थी यह मिथ कर लिया कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का मांग पूर्ण हान से कम किसी भी प्रस्ताव में नहीं मानगी। उसकी इस मांग के पीछे त्रिप्स सरकार का पूरा सहयोग था। राष्ट्रीय नेताओं की रिहायश ने जनता में एक नये जीवन का संचार करने में सफल दा। जेता में निकलने के बाद नेहरू पटेन जाति नेताओं ने जनता के भ्रमा का निवारण किया कि भारत को दो आदावन निरसक नहीं था। जनता का पुन स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त पूर्ण आजादी चाहिए। वास्तव में वक्त्र याजना किसी सच्च भाव से नहीं रखी गई थी। वक्त्र ता कबल गण्टवादी दल के निवाचन अभियान का प्रचार करने की चीज थी क्योंकि मजदूर दल ने उसका ऊपर यह आरोप लगाया था कि वह भारत का समस्या हल करने में असफल रहा है। चर्च की सरकार से मंत्री में प्रतिक्रिया जेता हुआ चुक था। जुलाई में त्रिप्स में नये जाम चुनाव हान वाता में। चर्च तथा हमारे ने स्पष्ट घोषणा की थी कि वक्त्र याजना का भारत के नेताओं के समक्ष रखने तथा उसे उस पर विचार करने का मौका देने में हम किसी भी चीज का नहीं दे रहे हैं (we aren't giving away anything)। यह बात विस्तृत मन्त्र था। भारतवासियों स्वतंत्रता चाहते थे और कांग्रेस को उसका निराकरण करने वाला प्रमुख दल था भारत का एकमात्र दल यह था। यह याजना भारत का ने स्वाधीनता दल का लक्ष्य रखनी थी जो न भारत की एकता बनाये रखने का इसमें प्रस्ताव था। त्रिप्स सरकार उसकी असफलता के कारण में पहल में ही आश्रयस्थ थी।

यदि वक्त्र याजना की शर्तों पर विचार किया जाय तो वह त्रिप्स लीग में गये 1942 के प्रस्तावों से भी निरुत्पन्न थी। इसमें न तो औपनिवेशिक स्थिति का चर्चा था न स्वाधीनता की और न ही भविष्य में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण करने वाला संविधान सभा के निर्माण का याजना थी। अतएव यह आश्चर्य का बात है कि कांग्रेस इस स्वाकार करने का क्या राजा हा गया। 1945 में हम याजना का स्वाकार करने की कांग्रेस का धारणा उतना हा गत था जितना 1942 में त्रिप्स याजना का अमाय करने की। जेता अवसर पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का भूयावन महा नहीं किया। लगभग दो तान वर्षों की अवधि में जिद्दा ने मुस्लिम लीग की स्थिति का अधिक सुहृद कर लिया था। वे नये निवाचन के लिए अधिक उत्सुक थे ताकि वे उसमें लीग का सफलता के लीग अपने हम भाव का पट्ट कर सकें कि

लीग ही भारत के समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके द्वारा वे मुस्लिम बहुल जनता वाले प्रान्तों में लीग का बहुमत हो जाने पर यह दर्शाना चाहते थे कि वहाँ की जनता आत्म निर्णय के द्वारा पाकिस्तान की माँग को सही करती है। अतएव उन्हें केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बनाने की चिन्ता नहीं थी। कांग्रेस यह सोचती थी कि वह स्वतन्त्रता संघर्ष से ऊब चुकी है अतएव वह सरकार के साथ इस दिशा में कोई समझौता कर लेने के बाद अग्रिम कार्यवाही के लिए उत्सुक थी। जो भी हो, शिमला सम्मेलन की विफलता के लिए जिन्ना की हठधर्मिता जिसे प्रोत्साहित करने में ब्रिटिश नेताओं का पूरा हाथ था, जिम्मेदार थी। परन्तु इसने युद्धोत्तर काल में साविधानिक गतिरोध दूर करने के प्रयासों का मार्ग अवश्य खोल दिया।

प्रश्न

- 1 युद्ध के प्रति कांग्रेस का क्या रुख था ?
- 2 टिप्पणी लिखिए—

(अ) अगस्त प्रस्ताव 1940,	(द) आजाद हिन्द फौज (I N A),
(ब) व्यक्तिगत सत्याग्रह,	(घ) देसाई-अली पैक्ट,
(स) सी० आर० फार्मुला,	(र) वैवेल योजना।
- 3 क्रिप्स प्रस्तावों में भारतीय लोकमत को संतुष्ट करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए थे ? इन प्रस्तावों का भारतीय लोकमत ने क्यों अस्वीकार किया ?
- 4 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन पर टिप्पणी लिखिए।

ब्रिटिश शासन का अवसान काल (LAST DAYS OF BRITISH RAJ)

राजनीतिक घटना चक्र

विश्वयुद्ध का अन्त—1945 के प्रारम्भ में मित्र राष्ट्रों ने यूरोप की फासीवादी शक्तियाँ पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। अब युद्ध में कबन जापान उतरा गिर रहा था। अगस्त 1945 में जब अमरीका ने जापान में दो अणु बम छोड़े तो जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार पूरे छह वर्षों से चल रहा विश्वयुद्ध का अन्त हो गया और मित्र राष्ट्रों के हाथ विजय मिली। अब विजयता राष्ट्रों के समक्ष पुनः विश्व का युत्ताग्नि से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने का समस्या थी। इस लिये एक सम्मेलन भी उठाया जा रहा था। उनमें फरवरी 1945 में संयुक्त राष्ट्र सभ की स्थापना हुई। वास्तव में विश्वयुद्ध का एक कारण साम्राज्यवाद था। इस यद्यपि विश्वयुद्ध में इंग्लैंड की ओर था तथापि वह ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का समयक नहीं था। युद्ध में इंग्लैंड की शक्ति बहुत निम्न हो चुकी थी। अतः अब वह अपने पुराने साम्राज्यवादी स्वप्न का साकार किया रखने का शक्ति नहीं रख सकता था। उसके ऊपर इस तथा अमरीका का दबाव बढ़ रहा था कि वह भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग का पूरा करे। अप्रैल 1945 में जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र सभ के निमण पर विचार विनिमय हो रहा था तो इस के विरुद्ध मंत्री माताजेव ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सम्मेलन में हमारे समक्ष एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल है परन्तु भारत एक स्वाधीन राष्ट्र नहीं है। हम सब जानते हैं कि वह समय जायगा जबकि एक स्वाधीन भारत की आवाज भी सुनाई देगी।¹ इस अवसर पर उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि संयुक्त राष्ट्र का प्रयास होगा कि वह विश्व के पराधीन राष्ट्रों को स्वाधीनता प्रदान करेगा और प्रयास करेंगे।

इंग्लैंड के आम चुनाव—यद्यपि बर्चिन के नवतंत्र की सत्तावादी दल की सरकार ने विरुद्ध युद्ध का संचालन करके इंग्लैंड का विजयी बनाने का श्रेय प्राप्त किया था तथापि इंग्लैंड की जनता सत्तावादी दल में उतरा गयी थी। युद्ध समाप्त होत ही जुलाई 1945 में इंग्लैंड के निर्वाचन परिणामों ने मजदूर दल के नेता एटना को ब्रिटिश सरकार के संचालन का भार सौंप दिया। इंग्लैंड में जब कभी मजदूर दल की सरकारें बनीं भारत हमेशा उनसे कुछ न कुछ आशा लगाया रखता था। इस समय मजदूर दल ने अपने चुनाव अभियान में ही भारत के साविधान्त्रिक गतिराज्य का दूर करने की घोषणा की थी। साथ ही परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मजदूर दल का इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाना आवश्यक भाँसा हुआ गया था।

भारत की स्थिति—वाग्रसा नेताओं की जवाब से रिहाई से जनता का उत्साह बढ़ गया था। इन नेताओं ने पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय जागरण की पट्टी में मदद गिनिया के कारण जनता में छापी हुई निराशा का दूर किया। यद्यपि अगस्त 1945 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता सुभाषचन्द्र बोस का एक हवाई दुर्घटना में कथित मृत्यु के समाचारों से भारतवासियों का मन दुखी था क्योंकि आजाद हिन्द फौज का जिस उत्साह के साथ उन्होंने संचालन किया था उसमें फरवरी 1945 में उनका प्रति महान् निष्ठा उत्पन्न हो गयी थी। आजाद हिन्द

फौज के संचालन के कारण उन्हें भारतवासी 'नेताजी' के नाम में पुकारते हैं। इस फौज का अग्रेजों ने दमन कर दिया और इसके तीन प्रमुख नेताओं शाहनवाज, डिल्लन तथा सहगल के विरुद्ध फौजी न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। दिल्ली के लालकिले में यह ऐतिहासिक मुकदमा चला जिसमें स्वयं नेहरू सहित अनेक कांग्रेसी नेता उन नेताओं के वचाव पक्ष में वकील के रूप में खड़े हुए। न्यायालय ने उन्हें फाँसी की सजा सुना दी। उनके विरुद्ध आरोप था कि वे ब्रिटिश सरकार की फौज में भागकर उसी के विरुद्ध सशस्त्र करने लगे थे। सारा भारत इस मुकदमे के निर्णय की बड़ी उत्सुकता में प्रतीक्षा कर रहा था। गवर्नर-जनरल लार्ड वैवेल ने परिस्थिति का बड़े विवेक से अध्ययन किया और अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके इन नेताओं के मृत्युदण्ड को समाप्त कर दिया। आजाद हिन्द फौज का नारा 'जयहिन्द' आज भी भारत का राष्ट्रीय नारा हो चुका है। उक्त निर्णय से तथा आजाद हिन्द फौज के कार्यभाग से जनता में एक नये उत्साह का संचार होने लगा था।

भारत के निर्वाचन—इंग्लैंड में मजदूर दल ने सत्ता प्राप्त करते ही सितम्बर 1945 में गवर्नर-जनरल लार्ड वैवेल को परामर्श के लिए इंग्लैंड बुलाया। वहाँ से आते ही गवर्नर-जनरल ने भारतीय राजनीतिक तथा साविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1935 के शासन अधिनियम के अन्तर्गत नये निर्वाचनों की घोषणा की। समय के राजनीतिक विकास-क्रम के सन्दर्भ में कांग्रेस ने पुनः चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। उसने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के औचित्य को पुनः दोहराकर अपने चुनाव घोषणा-पत्र में उसे शामिल किया। निर्वाचनों में पुनः कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई। सामान्य स्थानों में ने लगभग सभी स्थान कांग्रेस ने प्राप्त कर लिए। मुस्लिम स्थानों में से भी अनेक स्थान कांग्रेस के हाथ लगे। परन्तु अधिकांश स्थान मुस्लिम लीग ने जीत लिए। पंजाब में संयुक्तवादियों को लीग के साथ पराजय का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में खुदाई खिदमतगारों का सामना लीग नहीं कर पायी, क्योंकि वहाँ सीमान्त गांधी का प्रभाव बहुत ऊँचा था। परन्तु निर्वाचन-परिणाम इस बात के द्योतक सिद्ध हुए कि भारत के अधिकांश मुसलमान लीग के समर्थक हैं, अतः लीग की पाकिस्तान की माँग को ठुकराना सम्भव नहीं रह गया। इन निर्वाचनों के परिणामस्वरूप सात प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बने, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में कांग्रेस समर्थक खुदाई खिदमतगारों की सरकार बनी। सिन्ध तथा बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकारें स्थापित हुईं। पंजाब में संयुक्तवादियों ने अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई परन्तु लीग ने इस पर बहुत रोष व्यक्त किया।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की घोषणा—भारत के उक्त आधार आम निर्वाचनों के परिणामों के आधार पर जनता के रुख को देखकर तथा भारत की सम्पूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन करने के उपरान्त 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि 'भारतवासियों के आत्मनिर्णय तथा स्वतन्त्र भारत का संविधान स्वयं निर्मित करने के अधिकार को हमें मान्यता देनी चाहिए। यदि स्वतन्त्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक् रहना चाहे तो हमें भारत को इसके विरुद्ध बाध्य करने का भी कोई अधिकार नहीं है। निःसन्देह हमें अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे बहुसंख्यकों के भय में मुक्त रह सकें। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के निर्णय पर निपेधाधिकार प्रयुक्त करके साविधानिक प्रगति में बाधा डालने की छूट मिल जाये।' स्पष्टतः कांग्रेस के लिए यह घोषणा बहुत आशाप्रद मित्र हुई। परन्तु मुस्लिम लीग ने अन्ततः अपने निपेधाधिकार की शक्ति का पुर्ण प्रयोग किया जो पाकिस्तान लेकर ही उसे जैत पड़ा। इस सम्बन्ध में रुढ़िवादी तथा श्रमिक दल की नीतियों में जहाँ एक अन्तर था, वहाँ समानता भी थी। रुढ़िवादी सिद्धान्त था 'फूट डालो और शासन करो', श्रमिक दल की नीति थी 'फूट डालो और छोड़ो'।¹ दोनों दल

¹ Tara Chand, *op cit*, 455

मुस्लिम लीग की पृथक् स्वतन्त्र राष्ट्र का भाग में महानुभूति रखते थे। उक्त घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री ने मंत्रिमण्डल के एक मंत्रिमण्डल का भारत की स्थिति का अध्ययन करने तथा सुझाव देने के निमित्त भारत में भोजन की घोषणा भी की। उसका उद्देश्य बताते हुए भारत मंत्री ने कहा था कि वह भारत के नये परिणाम निमाण का व्यवस्था पर भारत की व्यवस्थापिकाओं में चुने गये प्रतिनिधियों तथा देशी नरेशों के साथ विचार करेगा। संविधान निर्मात्री संस्था की स्थापना तथा पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना की व्यवस्था करायेगा। काश्रम के नेताओं ने इन घोषणाओं का स्वागत किया परन्तु मुस्लिम लीग अपने विरुद्ध भी क्याही उनके अन्तर्गत पाकिस्तान की स्थापना का काम करने नहीं था।

केबिनेट मिशन याजना

उक्त घोषणा के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने तान सम्मेलन परियोजनाओं (भारत मंत्री) सर स्पाइड रिप्प तथा ए. बी. गनकजण्डर केबिनेट मिशिमण्डल के रूप में 23 मार्च 1946 को भारत पहुँचे। भारत पहुँचते ही मिशन के सम्मेलन में भारत सरकार के अधिकारियों तथा के विभिन्न वर्गों के नेताओं का सम्पर्क रूप में काश्रम तथा मुस्लिम लीग के नेताओं तथा देशी नरेशों से साविधानिक प्रगति के सम्बन्ध में बातें प्रारम्भ की। उस दौरे के बाद में उक्त मन्त्रिमण्डल में साधारणतः रिया और एक मासम्मत लीग का खोज की। परन्तु मुस्लिम लीग का हस्तक्षेप मिशन के कार्य में भी बाधक सिद्ध हो। अतः जहाँ बातों में कोई सम्मेलन हो नही निकलता तो मिशन ने ब्रिटिश सरकार के परामर्श से स्वयं एक याजना प्रस्तुत की जिस केबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan) कहा जाता है। उसकी घोषणा 16 मई 1946 को की गयी थी।

योजना—केबिनेट मिशन ने भारतीय स्वतन्त्रता तथा साविधानिक समस्या के हल के लिए निम्नांकित प्रस्ताव रखे—

(1) सम्पूर्ण भारत का एक सघ—मिशन का दृष्टि में भारत का साम्प्रदायिक समस्या का लीग पाकिस्तान का निमाण नहीं हो सकता था क्योंकि वह व्यवहार में सम्भव नहीं हो सकता था। अतः समूचे भारत का जिसमें देशी रियासतें भी शामिल हों एक सघात्मक राज्य के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। प्रस्तावित सघ में देशी रियासतों के शामिल होने पर उनकी साविधानिक स्थिति को विस्तार से नहीं समझाया गया था। परन्तु ब्रिटिश प्रान्तों के बाद में उनके समूह बनाकर उन्हें सघ के घटक (प्रान्त) तथा सघ की मध्यवर्ती शक्तों के रूप में रखने का प्रस्ताव था। ये मध्यवर्ती प्रान्तों में समूह तीन भागों में बाँटे गये—(क) दक्षिण मराठा मध्यप्रदेश विहार उड़ीसा तथा संयुक्त प्रान्त (ख) असम तथा बंगाल और (ग) पंजाब सिंध तथा पश्चिमाञ्चल सीमा प्रान्त।

(2) संविधान निर्माण—प्रस्तावित सघ व्यवस्था के अन्तर्गत संविधान निमाण के लिये मिशन ने भारतीय प्रतिनिधियों का संविधान सभा निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा के प्रतिनिधि प्रान्तों की व्यवस्थापिकाओं के सम्मेलन के द्वारा समानुपातों प्रतिनिधित्व के एकत्र सत्र मण्डलीय मन्त्रालय के पद्धति से चुने जाते थे। प्रत्येक प्रान्त से चुने जाते सन्धियों की संख्या प्रति लीग लीग की जनसंख्या पर एक मन्त्रिमण्डल के लिये निर्धारित का गया थी। निम्नलिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में तीन प्रकार के निर्वाचन मण्डल माय विद्ये गये थे (सामान्य मुस्लिम तथा पंजाब के लिए मिस्र भी)। उस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सम्मेलन होते जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रान्तों में 93 देशी रियासतों से तथा 4 चाफ कमिशनरों के प्रान्तों से लिए जाते। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनने के बाद में उनमें परामर्श करके विधि का निर्धारण करने का प्रस्ताव था। प्रान्तीय 292 प्रतिनिधियों में से 210 स्थान सामान्य 78 मुसलमानों के तथा 4 मिस्रों के लिए तय किए गये थे।

(3) **सघ सरकार**—प्रस्तावित सघ में केन्द्रीय सरकार को प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों तथा संचार यातायात के विषय दिये जाने थे। अवशिष्ट विषय प्रान्तों को दिये जाने का सुझाव रखा गया था। केन्द्रीय (सघीय) सरकार में एक कार्यपालिका तथा एक व्यवस्थापिका होती जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि होते। व्यवस्थापिका में किसी भी साम्प्रदायिक मामले का निर्णय व्यवस्थापिका में उपस्थित सदस्यों के एवं दोनों प्रमुख सम्प्रदायों (हिन्दू तथा मुस्लिम) के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता।

(4) **सविधान निर्माण प्रक्रिया तथा विषयों के वितरण में प्रान्तों की स्थिति**—कैबिनेट मिशन योजना ने सविधान निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये थे। सविधान सभा की प्राथमिक बैठक के उपरान्त विविध वर्गों में बाँटे गये प्रान्तों के प्रतिनिधि पृथक्-पृथक् बैठकर अपने वर्गों के प्रान्तों के लिये सविधान बनाते। वह अपने प्रान्त-मण्डल तथा उसमें शामिल प्रान्तों के मध्य भी विषयों का विभाजन करते। अन्त में समूची सविधान सभा केन्द्रीय तथा प्रान्तों के वितरण पर पुन विचार करके सविधान का अन्तिम रूप देती। ब्रिटेन के द्वारा भारत को सत्ता हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य तक सन्धि किये जाने का प्रस्ताव था। यह बात भारतीय सविधान सभा की इच्छा पर छोड़ दी गयी थी कि वह ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल में रहे या न रहे। नये सविधान के लागू हो जाने पर किसी प्रान्त की व्यवस्थापिका निर्धारित प्रान्त-मण्डल में रहने या न रहने का निर्णय भी कर सकती थी। उसे बहुमत द्वारा प्रति दस वर्ष पश्चात् सविधान में पुन संशोधन सम्बन्धी विचार करने की माँग रखने का भी अधिकार दिया गया था।

(5) **सविधान सभा की सर्वोच्चता**—इस प्रकार निर्मित भारत की सविधान सभा जिस सविधान को तैयार करती उसे लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य रहती।

(6) **अन्तरिम सरकार का गठन**—कैबिनेट मिशन योजना में उपर्युक्त बातें दीर्घकालीन योजना के रूप में थी। परन्तु ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वतन्त्र कर देना चाहती थी। अतः इस योजना में यह भी प्रस्तावित था कि यथाशीघ्र भारत में एक अन्तरिम सरकार की स्थापना की जायेगी जिसमें शासन के सम्पूर्ण विषय भारतीय मन्त्रियों को दे दिये जायेंगे। यह सरकार भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करेगी। ब्रिटिश सरकार इस अन्तरिम सरकार को शासन-संचालन के सम्बन्ध में पूरा सहयोग प्रदान करेगी, ताकि मत्ता का हस्तान्तरण द्रुत गति से तथा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।

मूल्यांकन—इसमें कोई सन्देह नहीं कि कैबिनेट मिशन योजना पिछली अन्य योजनाओं तथा आश्रयमानों से कहीं अधिक स्पष्ट थी। साथ ही इसमें ब्रिटेन की भारत को शीघ्रातिशीघ्र स्वाधीन कर देने की आतुरता भी प्रकट होती थी। पाकिस्तान के निर्माण की मुस्लिम लीग की माँग को उस योजना के निर्माताओं ने व्यावहारिक, राजनीतिक, प्रशासकीय, भौगोलिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टिकोणों से अवाञ्छनीय मानकर अस्वीकार किया था। अतः यह स्पष्ट था कि पाकिस्तान का ही एकमात्र स्वप्न देखने वाली मुस्लिम लीग कदापि इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती। इस योजना ने अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में जिन प्रस्तावों को रखा था वे भी उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त में मेल नहीं खाते थे।

इतना होने के बावजूद इस योजना में कई बातें अस्पष्ट तथा भ्रामक थी। विशेष रूप से प्रान्तों को तीन मण्डलों में बाँटने की योजना ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को अलग-अलग अथवा निकालने का अवसर दिया। कांग्रेस ने यह अर्थ लगाया कि कोई भी प्रान्त निर्धारित मण्डल में शामिल होने या न होने तथा मण्डल का सविधान बन जाने पर उसे स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतन्त्र है। इसके विपरीत लीग की धारणा यह थी कि निर्धारित मण्डल में रहे गये प्रान्त के लिए उसी में बने रहना अनिवार्य है तथा किसी वर्ग-विशेष द्वारा दिये जाने वाले निर्णय उस वर्ग के प्रतिनिधियों के माध्याम्य बहुमत से किये जायेंगे। 25 मई 1946 को मिशन ने इस विवादामय मामले की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि प्रान्त-मण्डलों का निर्माण सुविधित है

जोर उमम राना या न राना प्रात की वृद्धा पर नहा है। मण्डन के सविधान को स्वीकार करन या न करन के अधिकार का प्रयोग नये सविधान के आधार पर निर्मित यशस्वापिका की कर सकती है। इस प्रकार मिशन ने लीग की धारणा का समर्थन दिया। यद्यपि मिशन ने लीग की पाकिस्तान का मांग का टुकरा दिया था तथापि जिस प्रकार से प्रांतों के मण्डन बनाये गए थे उमम यह स्पष्ट था कि उनका आधार साम्प्रदायिक था और वे पाकिस्तान निमाण में सहायक सिद्ध नए। काग्रम ने आर्थिक रूप में ही याजना का स्वागत किया। वह अंतरिम सरकार की स्थिति तथा गतिविधि भावित सत्रिनिध सनिता न अस्तित्व तथा उस सघ की स्थापना और सविधान सभा में लगी गियामता के प्रतिनिधित्व की याजनाओं से संतुष्ट नहीं थी। परंतु लीग इस याजना में सिरकुन अमंतुष्ट था क्योंकि इस याजना ने पाकिस्तान निमाण की धारणा का अमाय किया था न पृथक सविधान सभाओं की स्थापना का उल्लेख इसमें था। कर्तीय कायपातिका में भी मुमनमाना तथा गर मुमनमाना का समान प्रतिनिधित्व दन की बात इसमें नहीं थी।

योजना पर अमल

(1) सविधान सभा—याजना पर अमल करन के लिए ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत जुलाई 1946 में सविधान सभा के निवाचन कराये गए जिसमें काग्रम को 205 तथा लीग का 73 स्थान प्राप्त हुए। इस लीग का बड़ी निराशा हुई। यद्यपि मुस्लिम लीग 6 जून 1946 का इस याजना को स्वीकार कर चुकी थी तथापि निवाचन के पश्चात् लीग ने इस अस्वीकार कर दिया। इसी बीच अंतरिम सरकार निर्मित की जा रही थी। लीग की निराशा बदन में उमम भाषण लगा तथा रक्तपात का प्राप्तात्मन द दिया था। अंतरिम सरकार भी बन चुकी थी। 6 दिसम्बर 1946 का ब्रिटिश अधिकारियों ने पुनः प्रांत मण्डन सम्बन्धी विवाद की याजना की जिसमें मुस्लिम लीग के निवाचन का माय किया गया था। 9 दिसम्बर 1946 का सविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। परंतु लीग ने इसका बहिष्कार किया। सविधान सभा का कार्य चलता गया। यद्यपि काग्रम ने याजना का 25 जून 1946 का स्वीकार कर दिया था तथापि वह प्रांत मण्डन के सम्बन्ध में अपने ही निवाचन पर निश्चय रखा। जब 6 दिसम्बर का ब्रिटिश सरकार ने पुनः इसकी याजना की और काग्रम के बहिष्कोण का समर्थन नए मिना ता तब भी काग्रम ने अमन्यागी रूप में अपनाया और 7 जनवरी 1947 का काग्रम ने 6 दिसम्बर 1946 के यक्तव्य का भी इस बात पर स्वीकार कर दिया कि प्रांत मण्डन सम्बन्धी व्यवस्था निम्न प्रांत पर अनुचित दबाव न पड़े और पञ्जाब में मिश्रण के हिता का संरक्षण किया जाय। लीग ने यह बहाना बनाकर कि काग्रम ने 16 मई 1946 के प्रस्ताव का पूनर्नया स्वीकार नहा किया है सविधान सभा का बहिष्कार जारी रखा। वह कभी भी सविधान सभा में शामिल नहीं हुई।

(2) अंतरिम सरकार की स्थापना—कनिट मिशन ने नाइ ववन (गवर्नर जनरल) का अंतरिम सरकार की स्थापना के आग्रह द दिया था। परंतु जब नाइ ववन ने राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष यह प्रस्ताव रखा तो अंतरिम सरकार का निर्माण करन के सम्बन्ध में यह कठिनाई उत्पन्न हुई कि किन किन प्रांतों का प्रतिमण्डन में लिया जाय। काग्रम इस बात का मानन के लिए राजी नहीं थी कि प्रतिमण्डन में काग्रम का मय अनुमूचित जाति के प्रतिनिधियों के मुस्लिम लीग के भी बराबर स्थान मिले। मुस्लिम लीग यह अवसर देख रहा थी कि काग्रम इस पृथक रण ता वह अन्य बुद्धि तथा वर्गों से मिलकर प्रतिमण्डन बना लगी। परंतु गवर्नर जनरल ने ऐसी व्यवस्था का स्वीकार नहा किया। अतः 29 जून को एक 7 मन्त्राय मरक्षक (care taker) सरकार बना ला गया। परंतु यह याजना का समाधान नहीं था। अतः 22 जुलाई का गवर्नर जनरल ने एक 14 मन्त्राय प्रतिमण्डन का प्रस्ताव रखा जिसमें 6 काग्रम के 5 लीग के तथा 3 अन्य मन्त्रय हए। काग्रम का अपन बात में एक अनुमूचित जाति के मन्त्रय तथा एक राष्ट्रवादी मुमनमान का भी नामांकन करन का अधिकार दिया गया। लीग इसमें भी संतुष्ट नहा

हुई। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। 24 अगस्त 1946 को गवर्नर-जनरल ने प० जवाहरलाल नेहरू को सरकार का निर्माण करने का आमन्त्रण दिया। इस पर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के दोनों पक्षों (दीर्घकालीन तथा अन्तरिमकालीन) को अस्वीकार कर दिया। अतः 2 सितम्बर 1946 को प० नेहरू की उपाध्यक्षता में अन्तरिम सरकार की स्थापना हो गयी। 12 सप्तम्भीय मन्त्रिमण्डल में कांग्रेसी हिन्दू, राष्ट्रवादी मुसलमान, सिक्ख, ईसाई तथा अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये।¹ दो मुस्लिम स्थान रिक्त छोड़े गये। मुस्लिम लीग को इससे और अधिक धक्का लगा।

लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा सरकार में प्रवेश—लीग की हठधर्मिता के कारण गर्वनर-जनरल को अन्तरिम सरकार की स्थापना के कार्य में बड़ी अड़चनो का सामना करना पड़ रहा था। लीग द्वारा कैबिनेट योजना को अस्वीकृत कर देने पर जब 6 अगस्त 1946 को गर्वनर-जनरल ने कांग्रेस को अन्तरिम सरकार के निर्माण हेतु सहयोग देने को कहा तो लीग ने अवाछनीय रवैया अपनाया। उसके आह्वान पर 16 अगस्त 1946 का दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए तय किया गया। उस दिन कलकत्ता, ढाका तथा सिलहट में भीषण उत्पात हुए। नोआखाली के अत्याचारों की कहानी वर्णनातीत है। साम्प्रदायिक दंगों में नर-संहार, बलात्कार, बलात् धर्म परिवर्तन-बलात् विवाह आदि की घटनाएँ मानवता की सीमा का उल्लंघन करके दानवता में परिणत हो गईं। अनुमान है कि इन उत्पातों में हजारों नर-नारियों की बलि दी गई। बंगाल को ऐसी क्षोभपूर्ण स्थिति 1943 के भीषण अकाल में भी नहीं देखनी पड़ी थी। प० नेहरू ने भारत की व्यवस्थापिका सभा में इन उत्पातों के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए इनके लिए लीग को दोषी ठहराया। इतना सब कर चुकने पर भी लीग को चैन नहीं था, क्योंकि अन्तरिम सरकार में अपनी अनुपस्थिति से वह बेचैन हो उठी थी। गर्वनर-जनरल भी लीग को सरकार में लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। पण्डित नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार ने अनेक मुन्दर परम्पराएँ स्थापित कर ली थीं। समूचा मन्त्रिमण्डल नेहरू के नेतृत्व पर विश्वास करता था और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करने के लिए वचनबद्ध हो चुका था।

अक्टूबर 1946 में गवर्नर-जनरल ने वार्ता करने के बाद मुस्लिम लीग ने अन्तरिम सरकार में प्रविष्ट होने की कामना व्यक्त की। लार्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग को उसके लिए निर्धारित पाँचों म्यानों में अपने प्रतिनिधि भेजकर सरकार के प्रविष्ट होने की स्वीकृति दे दी, परन्तु लीग ने यह आश्वासन नहीं लिया कि वह सविधान सभा में भाग लेगी। सरकार में शामिल राष्ट्रवादी मुसलमानों ने त्याग-पत्र देकर लीग के लिए स्थान रिक्त कर दिये।¹² सरकार में शामिल होने पर लीग ने पुनः असहयोगपूर्ण रवैया अपनाया। वह सरकार में एक पृथक् गुट के रूप में कार्य करने लगी। उसने नेहरू जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और बहुधा मन्त्रिमण्डल की नीतियों का विरोध करना शुरू किया। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 तक मुस्लिम लीग भारत की अन्तरिम सरकार में बनी रही, और असहयोगपूर्ण रवैये से कार्य करती रही।

पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर—भारत की राजनीतिक स्थिति विगड़ती जा रही थी। मुस्लिम लीग के कार्य-कलापो, विरोध तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही, मे जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसके बड़े भयकर परिणाम होने नजर आ रहे थे। दंगों के कारण देश में गृह-युद्ध का सा वातावरण बन गया था। द्वि-दलीय सरकार होने के कारण स्वयं उसके लिए भी दंगों का सामना करना कठिन था। ब्रिटिश सरकार भी आशंकित थी कि वह इस स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। अतः

¹ मी प्रमण्डल मे नदग्य-प० जवाहलाल नहर, मग्दार पटेन, डा० राजेन्द्र प्रमाद, चन्वर्ती राजगापालाचारी, मी लाफअली, परदार वलद्वामिह, श्री जाजीवन राम, मैयदप्रती जहीर, श्री शरत् चद्र वोग, जीन मधार्ई, मी० ए३० बाभा तथा मफात अहमद पा व ।

² लीग के पांच सदस्य नियासुल हनी झा, चुन्नीशर, अदुरव निम्तर, गजनफार अली खा तथा जोगेन्द्रनाथ मण्डल थे।

ब्रिटिश सरकार यथानीघ्न भारत का सत्ता सौंप देने के लिए व्यग्र थी।

20 फरवरी 1947 की घोषणा—ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऐटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि सम्राट की सरकार निश्चित रूप से जून 1948 तक भारतवर्ष में भारत की शासन सत्ता सौंप देने का फैसला करेगा। इसी के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि भारतवासी विवाद तथा युद्ध का भाग अपनाकर ऐसा बर्तन बनाना जिससे कि वह ब्रिटिश से अपने देश की सत्ता प्राप्त करने तथा उसका समुचित संचालन करने में समर्थ हो सके। यदि जून 1948 तक संविधान सभा संविधान तैयार नहीं कर सकी तो ब्रिटिश सरकार उस समय तक निर्मित केन्द्रीय या प्रांतीय सरकारों का सत्ता हस्तांतरित कर देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

लाह माउण्टबेटन का गवर्नर-जनरल बनना—उपरोक्त घोषणा से सम्बद्ध ब्रिटिश सरकार का एक निर्णय यह भी था कि लाह बंदर के स्थान पर लाह माउण्टबेटन को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त कर लिया गया।

माउण्टबेटन योजना—गवर्नर जनरल का पद सम्भालते ही लाह माउण्टबेटन ने भारत की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देश की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुस्लिम लीग जिस भाँति भारत का व्यवस्था का स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार का भारत में बने रहना वांछनीय नहीं होगा। उनका निष्कर्ष यही था कि देश का विभाजन ही समस्या का एकमात्र समाधान हो सकता है। अतः उन्होंने भारत विभाजन की एक योजना बनाई। उसके सम्बन्ध में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं के विचार प्राप्त करने तथा उस पर उनकी सहमति के बारे में भी आश्वस्त होना का प्रयास किया। पाकिस्तान निर्माण के सम्बन्ध में उन्होंने यह अनुभव किया कि कुछ बातों पर लाना देना के लिये सहमत है। यद्यपि कांग्रेस ने भारत विभाजन के प्रस्ताव का मद्देब विरोध किया था तथापि अब उसे ऐसा आभास हो गया था कि पाकिस्तान का निर्माण अपरिहार्य हो चुका है अतः मुस्लिम लीग स्वतन्त्रता के भाग में बाधक बनी रहने लगी।

माउण्टबेटन योजना बनाते समय योजना—लाह माउण्टबेटन ने जिस योजना का 2 जून 1947 को ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए अपने प्रमुख अग्रज सहायकारों के द्वारा प्रस्तुत किया था उसके निमाण में उसके सांविधानिक सहायकारों के पाँच मंत्रियों की उपस्थिति में हुआ था कि एक भारतीय अधिकारी साथ ही रहेंगे। मंत्रियों की सरदार पटेल के साथ अच्छी मंत्री थी। वे स्वयं एक चतुर कुशल तथा प्रतिभाशाली राजनयिक अधिकारी थे। 1946-47 में भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जो बर्तन बन चुका था उसके विभिन्न पहलुओं के गुणावगुणा का उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया था। वे भी पाकिस्तान के निर्माण का अपरिहार्यता पर आश्वस्त हो चुके थे। अतः उनकी जल्दी ही एक योजना या जिसके बारे में वे सरदार पटेल से विचार विमर्श कर चुके थे और सम्भवतः पटेल उस स्वीकार कर चुके थे। परन्तु मंत्रियों का इस न वाइसराय का बताना का अवसर मिला था और न नेहरू जी का। माउण्टबेटन ने अपनी योजना के बारे में मंत्रियों को भी अधिकार मिला था। माउण्टबेटन की योजना ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की योजना का ही एक रूप थी जिसमें पार्टी के नेताओं की सहमति के बिना ही एकतरफा तौर पर प्रस्ताव का सत्ता हस्तांतरित कर देना चाहिए और ब्रिटिश मजबूत केन्द्रीय सरकार के बंद एक फड्डे में जाना चाहिए।¹ माउण्टबेटन ने कांग्रेस तथा भाग दाना देना द्वारा योजना में बाधा डालने की सम्भावित बातों को भी साँच दिया था और उनके समाधान के तरीकों का भी हल निकाल दिया था। भारत के विभाजन की समस्याओं पर उसने गांधी जी का बताना का जायज कर लिया था। परन्तु वास्तविक योजना किसी पक्ष का नहीं बताया गई थी।

इसके तुरन्त बाद वाइसराय शिमला पहुँचे। मेनन भी साथ में गये थे। वहाँ वाइसराय ने मेनन से भारत की भावी स्थिति (राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनकर या अलग रहकर) के सवाल को छोड़ा तो मेनन ने कहा 'मैंने तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक योजना बना रखी है क्या आपको किसी ने नहीं बताया। मैंने लार्ड वैवेल को इसके बारे में बताया था और इण्डिया आफिस को भी इसकी सूचना दी थी।' इसके बाद मेनन ने इसके सम्बन्ध में पटेल से हुई अपनी वार्ता का भी उल्लेख किया। मेनन ने उपनिवेश के आधार पर सत्ता हस्तान्तरित करने तथा पटेल के माध्यम से कांग्रेस द्वारा उसकी स्वीकृति कराये जाने की बात भी बताई। जिन्ना तथा लीग तो उपनिवेश के आधार पर राष्ट्र-मण्डल में रहते हुए सत्ता प्राप्त करने को इच्छुक थे ही। मेनन की योजना से वाइसराय अत्यन्त प्रभावित हुआ। वाइसराय द्वारा अपनी योजना के बारे में मेनन से पूछने पर मेनन ने कहा कि 'आपने मुझ से पूछा ही कब था'।

17 मई को वाइसराय ने सभी भारतीय प्रमुख नेताओं की बैठक शिमला में बुलाई थी। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने माउण्टबेटन योजना को कुछ चन्द सशोधनो सहित स्वीकृति दे दी थी और वह पहुँच चुकी थी। 10 मई की शाम वाइसराय ने मूड में आकर नेहरू जी को यह दिखाई तो नेहरू भल्ला उठे और इसे मानने को कतई इनकार कर दिया और उसी नाराजगी की मुद्रा में चले गये। दूसरे दिन उन्होंने इस योजना के खतरों से आगाह करते हुए वाइसराय को एक स्मरण-पत्र भेजा। वाइसराय परेशान थे। तुरन्त मेनन को बुलाया गया और अपनी योजना शाम तक दे देने को कहा, क्योंकि शाम तक नेहरू जी चले जाने वाले थे फिर उन्हें पकड़ सकना कठिन होता। इतनी महान् योजना जिसे अंग्रेज सरकार इतने वर्षों तक न तैयार कर सकी, मेनन को तीन चार घण्टे में तैयार करनी थी। मेनन इससे भी परेशान थे कि वे नेहरू जी से वाइसराय के सकेत पर कुछ बातें पहले भी कर चुके थे और नेहरू को ऐसा आभास हो गया था कि मेनन पटेल से इसके बारे में पहले ही विचार कर चुके हैं। अन्ततोगत्वा मेनन ने किसी तरह इसे तैयार किया। मोसले ने लिखा है कि 'जिस योजना से हिन्दुस्तान और दुनिया की शक्ति बदलने वाली थी उसे तैयार करने में एक आदमी को सिर्फ चार घण्टे लगे थे'।¹ इन परिस्थितियों में वाइसराय ने 17 मई वाली बैठक को स्थगित करवा दिया और इंग्लैंड को तार भेजा कि पहली योजना में कुछ कमियाँ रह गयी हैं, दूसरी तुरन्त भेजी जा रही है। इंग्लैंड से तार आया कि वाइसराय स्वयं आवे और विचार-विनिमय करें। 18 मई को लार्ड माउण्टबेटन मेनन वाली योजना लेकर इंग्लैंड को रवाना हुए। मेनन भी साथ में थे। वाइसराय के अंग्रेज सलाहकार भल्लाये हुए थे कि उनकी योजना को स्वीकार नहीं किया गया। इंग्लैंड में प्रधानमन्त्री के भवन में इस योजना को स्वीकृति देने में केवल 5 मिनट लगे।² वाइसराय ने मेनन की इस असाधारण प्रतिभा के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिये, उनकी प्रशंसा की और आभार प्रकट किया।

3 जून 1947 को गांधी जी तथा जिन्ना से सलाह कर लेने के उपरान्त माउण्टबेटन ने मेनन द्वारा तैयार की गई तथा ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कर दी गई इस योजना की घोषणा कर दी। इसके अनुसार अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता को छोड़ देने का विचार व्यक्त किया। दूसरे, भारत तथा पाकिस्तान के दो पृथक् उपनिवेश बनेंगे जिन्हें ब्रिटिश सरकार सत्ता का हस्तान्तरण करेगी। देश विभाजन के निमित्त योजना में कहा गया था कि बंगाल तथा पंजाब विधानमण्डलों के मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रतिनिधि पृथक् मतदान द्वारा भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय करेंगे। सिन्ध की विधान सभा समूचे रूप में भारत या पाकिस्तान के विकल्प पर मतदान करेगी। त्रिलोचिस्तान में स्वायत्त-नामी मन्थानों के प्रतिनिधि मयुक्त रूप में ऐसा विकल्प देंगे। पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जनता वाले मिलहट जिले के क्षेत्र लोकनिर्णय द्वारा भारत या

¹ वही, 100।

² वही, 101।

पाकिस्तान में रहने का विकल्प होगा। तीसरे यदि पंजाब तथा उ्गान में एम निणया के परिणाम स्वरूप प्रांतों का विभाजन करना आवश्यक होगा तो उसमें निम्नलिखित सीमा आयागा की नियुक्ति की जायेगी जो प्रांतों का विभाजन स्वयं का निर्धारण करेगा। चौथे दाना दगा के मध्य विभाजन के परिणामस्वरूप नए नए के मामलों की भांति व्यवस्था की जायेगी।

चूँकि ब्रिटिश सरकार ने नाना उपनिवेगा का 15 अगस्त 1947 का सत्ता हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया था और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने विभाजन का स्वाकार कर लिया था अतः अतः आवश्यकता इस बात की थी कि माउण्टबटन याजना का कार्यावलि किया जाय। याजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों के प्रतिनिधियाँ या जनता का भाग या पाकिस्तान के सम्बन्ध में विकल्प दता था उसमें परिणाम पूर्व निश्चित थे। न माउण्टबटन याजना के पाकिस्तान में सिंध, त्रिबोक्मिस्तान, पश्चिमात्तर सीमा प्रांत, पश्चिमा पंजाब, पूर्वी उ्गान तथा सिन्ध जिन के मुस्लिम बहुसंख्यक जनता वाले क्षेत्र शामिल हुए। पूर्वी पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के जिन न भारत में शामिल होने का निश्चय किया। जिता का एस ही भन पाकिस्तान का ग्रहण करना पडा। यह उनके स्वप्न के उम पाकिस्तान में कहा अतिरिक्त बुरा था जिस सा जार सूत्र में प्रस्तावित किया गया था जोर जिम जिता न राजपज तथा दामका तारा तप्ट किया गया पाकिस्तान कहकर ठुकरा दिया था। पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य का गंदरी की माग ता कारा स्वप्न ही सिद्ध है।

तमरा वाय एम याजना को कार्यावलि करने के सम्बन्ध में विधि निर्माण का था। जत जुलाई 1947 में ब्रिटिश समर के द्वारा मजदूर न के सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का पारित कराया। साथ ही भारत में नाना उपनिवेगा के निमाण के निमित्त सीमा आयागा तथा नए नए की व्यवस्था सम्बन्धों कायवाल्या प्रारम्भ है।

सेना की समस्या—3 जुलाई 1947 की घोषणा के सम्बन्ध में कांग्रेस लीग तथा सिक्ख तीनों क्षेत्रों से थोड़े बहुत सैनिकों या विगत व्यक्तियों को भेजा गया परन्तु नाना पर किसी न किसी आधार पर यह मानने का विचार हुआ कि या उह मनवाया गया। लीग का पाकिस्तान का पृथक् उपनिवेग भिन्न गया। कांग्रेस का भी स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य परा हा गया भन ही उपनिवेग के रूप में जिम के आसानी से प्राप्त समाप्त कर सकती थी। सिक्खों के नेता वल्लभभिमह राजनीति में नए नए पटु नए थे कि पंजाब के विभाजन का अस्वीकार करने में सफल हों।

परन्तु जत न समझाया था प्रथम यह कि नाना उपनिवेगा के गवर्नर जनरल कीन हू ? नाना नए उपनिवेगा के मध्य बटवारा तथा सम्भावना के वातावरण का उनाय करने के लिए मध्यस्थ के रूप में माउण्टबटन का ही कुछ समय तक नाना का गवर्नर जनरल उनाय करने उचित समझा जा रहा था। यह वन भारतीय सना में काम कर रहे ब्रिटिश नागरिक एवं सैनिक अधिकारियों के तिन में आया। जिता में टाउत न जोर जन में स्वयं न पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने के चक्रे हाँ गया। कांग्रेस ने माउण्टबटन को स्वीकार कर दिया। युद्ध समाप्त हुए अभी अधिक समय नहा बीता था। तम समय भारत का प्रधान मन्त्री अचिननक था वह कुन नाना के अवश्य था परन्तु कुन राजनितिन नहा था। राजा हिन्दू फौज के अफमरा पर मुकदमा चलाय जान की उसकी जिन् न उम भारतीयों के मध्य अतीव प्रिय दाना दिया था। वह नहा चाहता था कि तनी शीघ्र सना का भांति नए न मध्य विभाजन के किया जाय। वह कम से कम अगस्त 1948 तक सयुक्त सना का ब्रिटिश कमान के अधीन हा रहना चाहता था। परन्तु जिना सना के राष्ट्रीय स्वतंत्रता का दाना नाना के नए अपण तथा ग्रव्यावहारिक मानने थे। अचिननक ब्रिटिश अधिकारियों की नाना के लिए भी ब्रिटिश कमान को उनाय करने ठीक समझना था साथ ही विभाजन के परिणामस्वरूप हान वान दगा को नवान के लिए भी। उसकी धारणा माउण्टबटन का स्वीकार नहा न। जत 15 अगस्त 1947 में पूर्व सना के उन्वार की भांति व्यवस्था करना थी।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947

भारतीय शासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश संसद का यह अधिनियम सबसे अन्तिम कानूनी प्रलेख है। इसके प्राविधान निम्नांकित थे—

(1) 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार भारत के शासन की सम्पूर्ण सत्ता भारत तथा पाकिस्तान के दो उपनिवेशों को हस्तान्तरित कर देगी।

(2) भारतीय संघ में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब, मुस्लिम बहुल जनता वाले सिलहट जिले के क्षेत्रों को छोड़कर शेष असम, दिल्ली, अजमेर तथा कुर्ग के प्रान्त सम्मिलित होंगे।

(3) पाकिस्तान के उपनिवेश में सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल तथा सिलहट के मुस्लिम बहुल जनता वाले क्षेत्र शामिल होंगे।

(4) बंगाल तथा पंजाब प्रान्तों के विभाजन के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त किया जायेगा जिसमें प्रत्येक उपनिवेश से एक न्यायाधीश रहेगा और सर सिरिल रैंडविल्फ को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

(5) ब्रिटेन भारत की शासन-सत्ता प्रत्येक उपनिवेश की प्रभुत्व-सम्पन्न सविधान सभा को हस्तान्तरित करेगा। यह सभाएँ अपना सविधान निर्मित करने में पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होंगी और ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के साथ रहने या न रहने का निर्णय करने का इन्हें पूरा अधिकार प्राप्त रहेगा।

(6) 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक उपनिवेश के लिए गवर्नर-जनरल की नियुक्ति वहाँ के मन्त्रिमण्डलों की सलाह से की जायेगी। इसके परिणामस्वरूप भारत ने लार्ड माउण्टबेटन को तथा पाकिस्तान ने मिस्टर जिन्ना को अपना गवर्नर-जनरल नियुक्त किया जाना स्वीकार किया, जिनकी शक्ति वैधानिक प्रधानों की सी रह गई।

(7) सविधान निर्माण की अवधि तक दोनों उपनिवेशों का शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा, परन्तु उसमें आवश्यक परिवर्तन हो जायेगे, यथा प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति उपनिवेशों के मन्त्रिमण्डलों की सलाह पर की जायेगी और गवर्नर भी अपने प्रांतों के वैधानिक प्रधान रहेंगे।

(8) 15 अगस्त 1947 में भारत मन्त्री का पद समाप्त हो जायेगा और वेस्ट मिनिस्टर सचिव 1931 के अनुसार ब्रिटिश सरकार इन नये उपनिवेशों के साथ अपने सम्बन्धों का नियमन करेगी। इसका यह अर्थ था कि भारत तथा पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का निर्धारण राष्ट्र-मण्डलीय सचिव करेगा।

(9) सविधान निर्माण हो जाने तथा उसे लागू होने की तिथि तक प्रत्येक उपनिवेश की सविधान सभाएँ वहाँ की केन्द्रीय व्यवस्थापिका के रूप में भी कार्य करेगी। इन सभाओं द्वारा पारित कानूनों पर ब्रिटिश सरकार की कोई निषेधाधिकारी या स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति नहीं रहेगी, न ब्रिटिश संसद इन उपनिवेशों के लिए कोई कानून बना सकेगी।

(10) 15 अगस्त 1947 में भारतीय देशी रियासतों के नरेशों के ऊपर ब्रिटेन की मार्वाभौमिक सत्ता समाप्त हो जायेगी। इसका यह अर्थ था कि भारत की देशी रियासतों को भी पूर्णतया स्वतन्त्र कर दिया गया था। परन्तु इस अधिनियम ने यह प्राविधान किया था कि देशी नरेश स्वेच्छा में भारत या पाकिस्तान में से किसी भी उपनिवेश में शामिल हो जाने अथवा पूर्णतया स्वाधीन बने रहने के लिए स्वतन्त्र ह।

अधिनियम का कार्यान्वयन

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तथा उसे लागू करने के बीच की

अपधि वन्न ही सूत्र थी। अग्रज नासका को भारत की विगन्ती हुई परिस्थिति में वन्न चिन्ता हा गयी थी। यह विद्वान हो चुका था कि उस स्थिति का सामना वन्न का साहम तथा क्षमता उनमें नहीं रह गई है। व शीघ्रानिर्णय उस दायित्व में मुक्त होना चाहते थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में ही प्रत्येक कायदाही का मांग अपनाकर देश में साम्प्रदायिक दंगा की आग सुनगा दी थी। यह बहुतना दिना दिन बढ़ाई जा रही थी। अन्न देश विभाजन का समय आया तो साम्प्रदायिक दंगा में भीषणतम रूप धारण कर लिया। जाकि पाकिस्तान का मित्रन था उनमें निवास करने वाले गर मुस्लिम सम्प्रदाया को अपनी जान मान का भागी रखता था। पाकिस्तान मांगत वाले मुसलमान यह नहीं चाहते कि प्रस्तावित पाकिस्तान की सीमा के अन्दर काइ भी गर मुस्लिम रहे। अत पाकिस्तान की गर मुस्लिम जनता के साथ वहां के मुसलमानों न दानवीय नीता प्रारम्भ करे। उनकी सम्पत्ति को लूटना उनका नरसहार महिनाओं के साथ अत्याचार जाति सभी अमानुषिक कृत्य प्रारम्भ हुए। उन लोगो को अपनी मां की सम्पत्ति का माह छोड़कर भारत में शरण लेने के अनिर्दिष्ट और कानून काग नही था। परंतु पाकिस्तान के मुसलमान उन्हें जीवित भारत में जान देना तन नहीं चाहते थे। पञ्जाब तथा बंगाल में भीषण रक्तपात के स्थान बन गये थे। उसकी प्रतिक्रिया भागत में हाता भी अस्वाभाविक बात नहीं थी। यद्यपि भारत ने धर्म निरपेक्षा का मिद्धात अनाया तथापि यहां भी कई स्थानों पर दंगे हुए। परंतु भारत सरकार ने उन्हें देश की पूण चष्मा ही नही की अस्तितु भारत में बस रहने के इच्छुक मुसलमानों का यथाशक्ति परा शरण प्रदान किया और पाकिस्तान जान के अन्तर्गत मुसलमानों को सुरक्षा के साथ वहां जान की व्यवस्था की। साथ ही पाकिस्तान प्रदेश में भागत में आये शरणार्थियों का वमान उनकी सुख सुविधा जादि का भार अपन कंधा पर लिया।

इन हृदय विदारक घटनाओं का ज्विर उत्पन्न करना यहां पर प्रामाणिक नहीं है। दुनिया के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के 26 वर्षों का इतिहास अभी ताजा है। यह तथ्य भी सूच के प्रमाण की भांति स्पष्ट है कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में गर मुस्लिम जनता जिना दिन घटती जा रही है और वहां से हिन्दी का शरणार्थियों के रूप में भारत को निष्क्रमण जारी है। पाकिस्तानी सरकार तथा जनता दोनों में अन्तर्गत दे रहे हैं जबकि भारत में लगभग 6 करोड़ मुसलमान पूण अमन चत से स्वतंत्र नागरिका की भांति रह रहे हैं। उन्हें सरकार के उच्चतम पदा को प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होनी रही है। गत 26 वर्षों की अवधि में भारत में भी कुछ अवसरों पर साम्प्रदायिक दंगे अवश्य हुए हैं परंतु इन दंगों का मुख्य कारण पाकिस्तानी प्रचार हा है। पाकिस्तान के एजेंट भारत में ऐसी बहुतना उत्पन्न करत रहते हैं और अपने देश में हिन्दी के ऊपर निय जान वान अत्याचारों को छिपाने के लिए भारत में एमी गडबडी उत्पन्न करने में लग रहते हैं।

जब 15 अगस्त 1947 का ब्रिटिश साम्राज्यवाणिया ने सत्ता से त्याग किया और अपने नि राष्ट्र मिद्धात तथा पूरा आजा और नामन करो की नीति में सफल हा गये तो भारत को गजनीति स्वतंत्रता की प्राप्ति ऐसी खून मरावी के बातावरण में प्राप्त हुई। समार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए रक्तमय ब्रान्तिया के अनन्त इच्छात मित्रत हैं। उनमें सत्ताधारी नासका तथा स्वतंत्रता की इच्छुक जनता के मध्य युद्ध तथा ब्रान्तिया के उत्पादन मित्रत हैं जबकि भारत में सत्ताधारी अग्रज भवन मनुष्या का तरह सम्मानपूर्वक भागत की जनता को सत्ता हस्तान्तरित करके गये परंतु देश का विभाजन करके दोना राष्ट्रा को बनाकर तथा जनता के मध्य रक्तपात करार गत्ता छोड़ गये। 15 अगस्त 1947 के पूर्व भी जब दंग हात रहे ता ब्रिटिश शासकों ने उन्हें उपेक्षित रखा। पण्डित नेहरू ने केनीय विधान सभा में एक बार कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने मविनय प्रवृत्ता आंदोलन को हिमात्मक ढंग में बुचबन में कोई बमो गयी क्या वह इन लोगों को नहीं दया सकती थी? वास्तव में अन्क ब्रिटिश अधिकारिया ने यहाँ तक प्रयास किया कि भारत में न दंगा को अधिकाधिक प्राप्ताहित किया जाय और सत्ता छोड़ने समय एमी

अराजकता का वातावरण बना दिया जाये कि जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि भारतवासी अपने देश का शासन स्वयं चला सकने की क्षमता नहीं रखते। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद का मूलन साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासकों ने किया था और उसे इस प्रकार बढ़ावा देते रहे कि जब तक उनके लिए सम्भव था तब तक उन्होंने भारत में अपना साम्राज्यवाद बनाये रखने के लिए साम्प्रदायिकतावाद का पूरा लाभ उठाया। अन्त में देश का विभाजन करके सत्ता का त्याग किया और आज देश की स्वतन्त्रता के 26 वर्ष पश्चात् तक भी यह विषय भारतीय राजनीति की नसों से नहीं उतरा है क्योंकि अंग्रेजों द्वारा सृजित साम्प्रदायिक विषय का प्रतीक सर्प पाकिस्तान भारत की पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों सीमाओं में निरन्तर डक मारता रहा है। पाकिस्तान बनते ही पहले उसने काश्मीर पर आक्रमण किया था और आज तक वह काश्मीर का एक-तिहाई भाग जबरदस्ती हथियाए हुए है। उसके पश्चात् 1965 तथा 1971 में उसने पुनः भारत पर आक्रमण किया। यद्यपि दोनों बार उसे बुरी परास्त होना पड़ा था, तथापि वह अब भी अपने ऐसे नापाक इरादों को नहीं भूला है। 1971 के युद्ध में उसे पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा था जो अब पाकिस्तानी अत्याचारों से मुक्त होकर स्वतन्त्र व प्रभुत्व-सम्पन्न बंगला देश बन चुका है। यह सब पाकिस्तान की साम्प्रदायिक धर्मान्धता तथा आत्माभिमान की घृणा भरी राजनीति का फल है।

15 अगस्त 1947 को भारत ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, अंग्रेज चले गये। यहाँ तक कि सभी उच्चतम सेवाओं में नियुक्त अंग्रेज पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिये। लार्ड माउण्टबेटन स्वतन्त्रता के पश्चात् कुछ समय तक भारत के गवर्नर-जनरल बने रहे। उनके चले जाने पर भारत के वरिष्ठतम राजनेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम तथा अन्तिम भारतीय गवर्नर-जनरल बने। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का नया संविधान लागू हुआ तो यह पद समाप्त हो गया और नये प्रभुत्व-सम्पन्न गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति पद पर डा० राजेन्द्र प्रसाद आसीन हुए। इस प्रकार भारत को स्वतन्त्र कराने का श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है जिसने 62 वर्ष के अथक् परिश्रम में यह सफलता प्राप्त की। यो तो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय विगत 27 वर्षों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का संचालन करते आ रहे थे और उनके सफल तथा लोकप्रिय नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन सफल हुआ, तथापि हमें राष्ट्रीय आन्दोलन के उन सेनानियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने समय-समय पर कांग्रेस तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया।

प्रश्न

- 1 टिप्पणियाँ लिखिए—
(क) कैबिनेट मिशन योजना,
(ग) माउण्टबेटन योजना।
- 2 भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अधिनियम के कार्यान्वयन में क्या परिवर्तन हुए ?

मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा देश का विभाजन

(MUSLIM COMMUNALISM AND PARTITION OF INDIA)

हिंदू मुस्लिम एकता के माग से दूर—बीमवा गान्धी के प्रथम दो दंगानों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के माग में मुस्लिम साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति उमर विराम जालि पर हम पुस्तक के गत अध्यायों में प्रकाश डाला जा चुका है। 1916 के काग्रस रोग समझौते के बाद जेठ काग्रस में भारतीय मुसलमानों द्वारा संचालित खिलाफत आन्दोलन का समयन किया था यह जाणा बनन लगा था कि राष्ट्रीय एकता मुट्ठा हा जायगी और अग्रजों का फूट डाना और नामन रंग का नीति नष्ट भ्रष्ट हा जायगी। 1919 के गासन सुधारों के अंतर्गत मुसलमानों का व्यवस्थापिका में पर्याप्त अधिक प्रतिनिधित्व मिल गया था। परंतु खिलाफत आन्दोलन का असफलता ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता समर्थक तत्त्वों का पुन काग्रस में पृथक् हा जान में सहायता दी। अग्रज भी इस बात के लिए तैयार थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का बनाव मिलाता उनकी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में तुषारापात करना होगा। जब 1920 में गांधी जी ने अमृत साग आंदोलन आरम्भ किया तो मुस्लिम लोग ने इस आन्दोलन में मत् करना शुरू कर दिया था। उसी बीच कुछ घटनाएँ और घटी जिनके कारण हिंदू मुस्लिम पृथक्तावाद की धारणा और अधिक बलवती हानी गया और तब से मुस्लिम साम्प्रदायिकता निरंतर बढ़ती गया।

अफगान आक्रमण तथा सोपला विद्रोह में मुस्लिम साम्प्रदायिकता—1919 में जब अफगानिस्तान ने भारत पर चला का तो भारत के मुसलमानों ने धर्म के नाम पर अफगानिस्तान के मुजाहिदों का सहायता देने की नाति अपनाया यद्यपि वहना भारत का विरुद्ध सरकार का जिनमें भारत में गैर-एक सहन दमनात्मक कानून लागू कर दिए थे सहायता देने का था। हमारे विपरीत गांधी जी का मत था कि ऐसा सरकार के साथ मेल्याग करना उचित नहीं है जो राष्ट्र का विश्वास का चुरी है। हममें यह स्पष्ट हा गया कि हिंदूओं में मुसलमानों की असफलता नीति में यह भय उत्पन्न हुआ था कि वे भारत में पुन मुस्लिम साम्राज्य का थापना चाहते हैं। अफगान आक्रमणकारों भगा लिया गया था। परंतु हमें मुस्लिम साम्प्रदायिकता पुन प्रभुत्व में लगी। इस बीच मलाबार में खिलाफत आन्दोलन का लेकर जा मापना खिलान हुआ था उसमें मुसलमानों के द्वारा हिंदूओं सहित अन्य धर्मावलम्बियों का नामस बंध किया जाना भी मुस्लिम साम्प्रदायिकता का स्पष्ट प्रमाण था। राष्ट्रवादी मुसलमानों तक ने मापना के हम कृत्य की स्पष्ट मिला नही की प्रत्युत यह धारणा व्यक्त की कि जब हिंदूओं ने मापना का देवान में विरुद्ध सरकार की मदद की है तो मापना द्वारा हिंदूओं का भी अपना नश्य पनाना अस्वाभाविक नया था। मुसलिम आयसमाजी मना स्वामी अद्वानत ने राष्ट्रीय मुसलमानों के इस दृष्टिकोण का उत्तर 1926 में अपने एक लेख में किया था। हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिकता भट हम प्रकार बतलन रंग है कि 1921 से 1924 तक का अवधि में हमें के विभिन्न भागों में अनेक बार दंगल। ब्रिटिश सरकार की नाति सता हा हमें दंगा का प्राप्तापन हमें का रंग। पश्चिम में उकमान में विषय सागलान करती थी। हमें बात का लोग के नना जिज्ञा तक ने स्वीकार किया था।

आय समाज की प्रतिनिधिता—फरवरी 1924 में जब गांधी जी जेल में छूट ता उत्पान

हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थन में 21 दिन का उपवास किया। परन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकता के पीछे जो धर्मान्विता थी, उसका उपचार उपवास या सम्मेलन नहीं हो सकते थे। भारत में मुसलमान तथा ईसाई दलित एवं पिछड़े वर्ग के हिन्दूओं का धर्म-परिवर्तन करने के कार्य में लगे थे। अतएव इस प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया यह हुई कि आर्यसमाजी नेताओं ने भी शुद्धि आन्दोलन चलाया और छुआछूत के भेदभाव को नष्ट करने, हरिजनो के उद्धार एवं शुद्धि द्वारा अन्य धर्मावलम्बियों को, विशेष रूप से उन्हें, जो धर्म-परिवर्तन द्वारा मुसलमान बना दिये गये थे, पुनः हिन्दू धर्म में लाने का कार्यक्रम अपनाया। परन्तु अनेक मुसलमानों ने इस नीति की आलोचना की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार के साम्प्रदायिक भावना से भरे कार्य-कलाप तथा क्रिया-प्रतिक्रिया स्वस्थ राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक थी। परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा करने की छूट किसी एक ही सम्प्रदाय विशेष का हित नहीं हो सकती थी।

लीग की साम्प्रदायिक गतिविधियों का विकास—1924 तक मुस्लिम लीग की गतिविधियाँ निर्वल पड़ी रही परन्तु 1924 के लीग अविवेशन में पुनः लीग में जान आने लगी। यद्यपि इस अविवेशन में भाषण करते हुए जिन्ना ने साम्प्रदायिकतावाद तथा हिन्दू-मुस्लिम दंगों की तीव्र भर्त्सना की और हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए अपने को पूर्णतया एक राष्ट्रवादी मुसलमान घोषित किया, तथापि उस समय के प्रमुख मुस्लिम नेताओं, डा० किचलू, रजा अली, जिन्ना एवं मौलाना मुहम्मद अली सभी ने यह धारणा व्यक्त की कि मुसलमान अल्पसंख्यकों को विधानसभाओं तथा सरकारों में नौकरियों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, आदि, जबकि वास्तव में इसके विपरीत थी। विधानसभाओं में उन्हें पर्याप्त अधिक स्थान प्राप्त हुए थे। साम्प्रदायिक निर्वाचन तथा पृथक् निर्वाचन प्रणाली ने उन्हें आवश्यकता से अधिक संरक्षण प्रदान किया था। लाला लाजपत राय, जो हृदय से हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे, मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद के खतरो में भली-भाँति परिचित थे। उन्होंने अपनी चिन्ता कांग्रेसी नेता चित्तरजनदास को लिखे गये एक पत्र में व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय मुसलमान भले ही राष्ट्रवादी होने का दावा करें, परन्तु यह कुरानवादी पहले हैं और राष्ट्रवादी बाद में। इसका यह अभिप्राय है कि मुसलमान धर्म के नाम पर राष्ट्र-प्रेम, देश-प्रेम आदि सबको ताक पर रख देता है। गांधी जी तक इस तथ्य को जानते थे। भले ही उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए आज्ञा प्रयास किया और उसी खातिर अपने प्राण दिये, तथापि मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद को निर्मूल करना उनके लिए सम्भव नहीं हो पाया।

लीग का कांग्रेस-विरोधी रवैया—1923-24 में जब टर्की का प्रश्न हल होकर वहाँ धर्म-निरपेक्ष राज्य स्थापित हो गया, तो भारत में खिलाफत आन्दोलन चलाने वाले मुसलमानों तथा सगठनों को बड़ा धक्का लगा। भारत में साम्प्रदायिकता की भावना बढने लगी थी। लीग के सदस्य अब कांग्रेस को एक हिन्दू सत्ता के रूप में देखने लगे थे, दूसरी ओर हिन्दू महासभा के नेतागण भी मुसलमानों को शका की दृष्टि से देखने लगे थे। परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियों में साम्प्रदायिकता की भावना आ जाने के कारण उसने कांग्रेस में सहयोग करना छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि फिर वही पुराने झगड़े शुरू हो गये, जो बीसवीं सदी के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए थे। लीगी नेताओं को 1919 के सुधारों से बहुत अधिक असन्तोष हो गया था। यद्यपि हिन्दू बहुल प्रान्तों में मुसलमानों को मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, तथापि मुस्लिम-बहुल प्रान्तों में पंजाब तथा बंगाल में उन्हें इस अनुपात बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। पंजाब में तो हस्तान्तरित विषयों के शासन में कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं बन पाया था। सीमित मतधिकार के कारण बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत कम थी। यद्यपि इन सब परिस्थितियों का कारण उक्त अधिनियम को लागू करने सम्बन्धी नियम थे, तथापि असन्तुष्ट मुसलमानों ने इसका रोप कांग्रेस पर निकालना शुरू किया और दुश्मनी प्रकट करने का नाचन साम्प्रदायिक कलहों को बनाया। धीरे-धीरे यह गतिविधियाँ

तनी अधिक बढ़ने लगी कि अनेक राष्ट्रवादी मुसलमानों ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय उद्देश्यों पर साम्प्रदायिकता का रंग देकर उनका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया।

साइमन कमीशन—1926-27 में यह भावना तनी उग्र हो गयी कि भारत के विभिन्न भागों में जनक साम्प्रदायिक दंग हुए। ब्रिटिश सरकार का यह स्वप्न जबलूर प्राप्त हुआ। कांग्रेस लोग समझौता समाप्त हो गया था। हिंदू मुस्लिम एकता के मर्म में ऐसा दरार पड़ गयी थी जिस भर सकना असम्भव हो गया था। 1919 के एक्ट में इस पारित होने के दस वर्ष बाद एक आयोग की रचना करने तथा उसका सन्तुष्टियाँ के आधार पर भावी सुधार करने का प्राविधान था। जब 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय जीवन के अन्तर् इतना भीषण साम्प्रदायिक भेदभाव उत्पन्न हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्देश्यों का पूर्ति के नियम निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की घोषणा कर दो ताकि कमीशन साम्प्रदायिक तनाव की स्थितियों में प्राविधानिक सुधारों की भावी योजनाओं के सम्बंध में साम्प्रदायिक भेदभाव का सहारा नकर राष्ट्रीय मांगों को ठुकराने का बहाना आमानों से प्राप्त करने। यद्यपि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने में मुसलमान भी शामिल थे तथापि मुस्लिम सम्प्रदायवादी या की साम्प्रदायिकता की भावना साइमन कमीशन को नाभर मिट्टे हुई। 1927-28 की अवधि में लोग ने साम्प्रदायिकता के आधार पर पृथक् सिद्ध प्राप्त की मांग की। इसी प्रकार पश्चिमात्तर सीमा प्रांत को एक पूर्ण प्रांत की शर्तों प्रदान करने की मांग जोर पकड़ रही थी। इन गतिविधियों के कारण हिंदू महासभा की गतिविधियाँ भी बढ़ने लगी। जहाँ हिंदू मतासभा राष्ट्रीय आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता जान तथा अपसरयक के द्विधा का आरम्भ द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान करने का बात कहती थी वहाँ साम्प्रदायिक मुस्लिम नती पृथक्तावादी प्रवृत्तियाँ अपनाते गये। इन पृथक्तावादीयों की गतिविधियों को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से बहुत प्रेरणा मिल रही थी। लोग के अन्तर् जो राष्ट्रवादी तत्त्व विद्यमान थे उन्होंने भी कांग्रेस के साथ सहयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप साइमन कमीशन ने भी पृथक् निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया। 1928 की नहरू रिपोर्ट को साम्प्रदायिकतावादी मुसलमानों ने अस्वाकार कर दिया। यद्यपि सर्वदलीय सम्मेलन ने उसे अपना समर्थन दिया था तथापि लोग ने उस ठुकरा दिया क्योंकि नहरू रिपोर्ट में पृथक् निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया था।

मुसलमानों की झूलत घण में अग्रिमचि—मई पश्चात् मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादी तत्त्वा ने हरिजनों में दिनचर्या नती प्रारम्भ किया। यह एक ऐसा वर्ग था जिस हिंदू अज्ञान मानते थे। विधायिका (मुसलमान तथा ईसाइयों) ने यह अपने धर्म में नती का आह्वान किया और यह प्रचार किया कि हिंदू धर्म तथा समाज के अंतर्गत ये दिनचर्या करने रहेंगे जत उनका भविष्य हिंदुओं पर दयालु नज़र नहीं है। उनके दृष्टिकोण यह था कि हरिजनों का हिंदुओं में न मिलने के परिणाम यह होगा कि विधानसभाओं में हिंदुओं का बहुमत कम हो जायगा। अतः हरिजनों के लिए भी पृथक् निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखने की नीति का प्रचार किया जाना लगा। परन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादीयों की इस चान का परिणाम यह हुआ कि उन्हें भी अपना उद्देश्य पूर्ण करने में सफलता नहीं मिली प्रत्युत हिंदू समाज तथा सगठनों में अज्ञानाधार की प्रवृत्ति उत्पन्न लगी। हिंदू महासभा तथा जाय समाज की दिनचर्या अज्ञानाधार काय में बनी और गांधी ने इस काय का बाड़ा उठाया। उन्होंने आज्ञा जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काय किया उसी प्रकार अज्ञानाधार के नियम भी अपनी सारी शक्ति लगा दी। 1920 के पश्चात् मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में जा विकास हुए उनका पत्रस्वरूप 1928 में नहरू रिपोर्ट को अस्वाकार करने पर जिम्मा ने अपनी धोखे शर्तें रखा जो अन्त तक लागू की नाति के निर्देशक तत्त्व बनी रहा। यह गति स 1930 में निम्नांकित थी—

सघातमक मविधान के अन्तर्गत अवशिष्ट विषय प्रान्ता के अधीन हो प्रांतीय स्वायत्तता अपसरयक का प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाना तथा प्रान्ता के बहुमध्यक वर्ग का बहुमत

सुरक्षित रखा जाना, केन्द्र में मुस्लिम सीटों की सत्या कम में कम एक-तिहाई हो, पृथक् निर्वाचन पद्धति, पंजाब, बंगाल तथा पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में मुसलमानों के बहुमत को विधानसभा में सुरक्षित रखना, साम्प्रदायिक आधार पर धार्मिक स्वतन्त्रता की गारण्टी, किसी भी विधानसभा द्वारा किसी सम्प्रदाय विशेष के सम्बन्ध में ऐम विधायन को पारित करने की शक्ति को उस सम्प्रदाय के मदम्यों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा मर्यादित रखना, सिन्ध को बम्बई प्रान्त से पृथक् करना, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त तथा विलोचिस्तान को अन्य प्रान्तों के साथ समान स्थिति में रखना, अखिल भारतीय सेवाओं तथा स्वायत्त शासन निकायों में मुसलमानों को उचित अंश प्रदान करना, मुसलमानों को अपने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्यान्य कायकलाओं के हेतु शासन-संस्थाओं द्वारा समुचित अनुदान दिया जाना, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कम से कम एक-तिहाई सुनिश्चित करना, तथा सांविधानिक सशोधन का अधिकार केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका को ही न प्राप्त हो, अपितु उसे प्रान्तीय विधानमण्डलों का भी अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में मुस्लिम साम्प्रदायिकता इस प्रकार भड़कने लगी थी कि अब उसके राष्ट्रवादी तत्वों के साथ ऐक्य स्थापित करने के अवसर समाप्त हो गये। थोड़े से राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता अवश्य कांग्रेस के साथ रहे और धर्मनिरपेक्ष नीति को मानते रहे, परन्तु अधिकांश मुस्लिम नेता यद्यपि विभिन्न सगठनों में¹ विभक्त थे, तथापि उनका दृष्टिकोण साम्प्रदायिकतावादी बना रहा। इन सगठनों में से सीमा-प्रान्त के मुदाई खिदमतगारों के अतिरिक्त शेष सब कांग्रेस-विरोधी रहे और कांग्रेस को हिन्दू संस्था मानते रहे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम के प्रति उदासीनता तथा प्रतिक्रियावादिता दर्शाना आरम्भ कर दिया। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उसका उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य था, जबकि कांग्रेस का युवा वर्ग पण्डित नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग पर आ गया। इसके बाद जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया तो मुस्लिम सगठन इसे हिंसात्मक कहने लगे और उन्होंने इसका बहिष्कार किया। ये सभी साम्प्रदायिक आधार पर सांविधानिक माँगें करने लगे। इन्होंने सर सैयद अहमद खॉ की ब्रिटिश राजभक्ति की नीति का भी बहिष्कार कर दिया और अब वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की 'फूट डालो और शासन करो' की नीति के शिकार बनकर भारतीय स्वतन्त्रता की तुरन्त प्राप्ति के मार्ग में सबसे भयानक कटक मिद्ध होने लगे।

गोल मेज सम्मेलनों में मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद का कार्य-भाग—गोल मेज सम्मेलनों में भारतीय मुसलमान सगठनों का कार्य-भाग पूर्णतया पृथक्वादी बना रहा, जिसमें साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को महत्त्व प्रदान करने की माँगों ने सम्मेलन के आयोजकों को भावी शासन सुधारों में अपने मन की करने में अच्छी सफलता प्राप्त कर ली। परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री ने 'कम्प्यूनल एवार्ड' की घोषणा की जिसने साम्प्रदायिकता के विपक्ष में भारतीय राजनीति के अन्दर और अधिक तीव्र बनाया। जब 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को ब्रिटिश मसद ने पास कर दिया, तो भारत की जनता की सबसे बड़ी प्रतिनिधि मध्या कांग्रेस के तीव्र विरोध के बावजूद साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और अधिक प्रसार किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत जब निर्वाचन हुए तो कांग्रेस व लीग दोनों ने पूरे जोर से निर्वाचनों में मधर्ष किया। परन्तु लीग को अपनी आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली। केवल सिन्ध प्रान्त में उसे सर्वाधिक बहुमत मिला। बंगाल में भी वह फॉरवर्ड ब्लाक के सहचार में मन्त्रिमण्डल बना मरने की स्थिति में आ गई। पंजाब में उसे विभिन्न दलों के मयुक्त मोर्चे के

¹ लीग के दो बड़े (जिन्हा लीग तथा शफी लीग) बन गये थे। अन्य सगठन थे अहमद, गिलाफन बार्कन, 'मामन उल-उलेमा, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त के मुदाई खिदमतगार, आदि।

मम न विग्राधिया क रूप म रहता पना । कम् म भी गीग का अधिग सफतना नता मिनी । जब 6 प्राता म जता काग्रस पूण वम्मत म था काग्रम न पदग्रहण नहा किया तो वनम स कुछ प्राता (यथा मयुन प्रात आदि) म गीग न अपना सरकार बनान का पनाकन की । परतु उम सफतना नहा मिनी । काग्रम नारा पदग्रहण स्वाकार कर वन पर गीग न सरकार की गति प्राप्त करन का वाग्य नता छोडा । मयुन प्रात म गीग क आवन पर काग्रम मुनिम गीग का नम गत पर मन्त्रिमण्य म कुछ स्थान न को राजा हा ग कि गीग विधानसभा म पृथक दन क रूप म गता वठगा जीर उप निवाचना म पुन स अपन उम्मीदवार खन नहा करगी । काग्रम न तिए जा पूण वम्मत म थी गीग क न्ति म नना त्याग करना यहन अगि न पानु गीग का रवथा नना हठी था कि माना वह म कुठ प्राप्त कर नना चाहनी थी चा उसका काड जीवित्य न या नहा । एसा स्थिति म गीग की यह मनाकामना सफ नहा हु । यद्यपि 1935 क एक न अनुसार काग्रम मन्त्रिमण्य वाव प्राता म सरकार न अत्यन मगहनीय काय करक महान् नाप्रियता प्राप्त की तथापि मुस्लिम सम्प्रदायवातिया की काग्रम की नम नाप्रियता स उम स्थिा हान गता । अन मुनिम गीग न अत न सरकारा का हि अविनायकवा कहकर उदनाम करन का प्रचार आरम्भ किया । यह स्थिति अधि न्ति नहा न सकी क्याकि सितम्बर 1939 म तिया महायुद्ध न्ति जान क फनम्बर त्रिग सरकार की युद्ध नीति स काग्रम रन न ग और जकूजर 1939 म काग्रस मन्त्रिमण्य न त्यागपन न न्य । मुस्लिम गीग अव भी यह प्रयास करन गगी कि उम न प्रात म सरकार बनान म सफतता मित जाय । परतु यह सम्भव नता था । एक पश्चात् काग्रम म याग्रह जागेन की अवधि म गीग न काग्रम की नीति का विरोध जारी रता

पाकिस्तान का विचार

गीग का राष्ट्रीयता विराधी हल—भारतीय राष्ट्रीय आन्दान क जनगन वीमवा सगी न आरम्भ म नकर पूर चार टाका तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता न जिस न्ठर्धमता का रूप अपनाकर आन्दान क माग म गन जनवान का मनन प्रयास किया उमक पीठ स्पष्टत त्रिग साम्प्रदायिकता का हाय था । उान न्ति मुस्लिम पृथक्तावा का यथामम्भव वावा न्या था । मुस्लिम साम्प्रदायिक मगता क न वायनतावा की प्रतिक्रिया क फनम्बर न्ति महामभा क नारा भा नका विरोध करना का जम्वाभाविक बान नहा थी । परतु साम्प्रदायिकतावा मुमनमान चातन य कि व ता म कुछ कर तथा व मरन न क्याकि व नमन्यक है साथ ही उतरी गतिविधिया का तत्कालीन सरकार का समथन भी प्राप्त रहता था । परतु व म महन नता कर सकत य कि न्ति मनामभा महा का नय मगन वन जा कि मुनिम साम्प्रदायिकता नाद का विगध र । काग्रम आरम्भ म न नर धमनिगता की नीति पर चनता रही । यहाँ तक कि जनर वे-वे गणवाती मुस्लिम नता न्मे मन्म वन न । कुछ गणवाती मुमनमान नता भी जो कभी काग्रम क समक थ धीर गीग साम्प्रदायिकतावा क चकर म फमत गग य । यन तक कि गीग क प्रमुग नता जिता भा वन नम्वा अवधि तक गणवाती थी थ ।

मुस्लिम नेताग्रा द्वारा भारत को एक राष्ट्र न मानना—जय मुनिम साम्प्रदायिकतावा प्रतुनिया क विकास न 1916 क काग्रम-गीग समभौन का जन कर न्या ता य निश्चि हा गया था कि जय हिू मुमनमान एवता क नारा गणाय न्तिनता प्राप्ति क प्रयास जमम्भव न । वीमवा मी क वीमर नारा की जन्म अवधि नर जनक मुस्लिम नता मावजनिग रूप म य न्तिन न न गग थ कि भारत एक राष्ट्र नता है । न विभिन्न गणायताग्रा को एक स्वतय राष्ट्र क जनगन वनात् गगता न्ति नहा है । यद्यपि नम धारणा क नाद्र वास्तविक न्या का जभाव था क्याकि भारत म मुस्लिम समुदाय क व्यक्ति समूह न म फन नथ गीर धार्मिक

विश्वास के अतिरिक्त जीवन के विविध क्षेत्रों में उनकी समस्याएँ अन्य भारतीयों से घुल-मिल गई थी। यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है कि धर्म ही एकमात्र राष्ट्रीयता का निर्धारक तत्त्व होता है। इस दृष्टि से मुसलमानों की पृथक् राष्ट्रीयता की कल्पना केवल साम्प्रदायिकता की द्योतक थी। इसके आधार पर पृथक् राष्ट्रीय राज्य की धारणा भारत सहश देश में कोरी भ्रान्ति थी। फिर भी मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादी नेता मुस्लिम राष्ट्रीयता के आधार पर पृथक् स्वतन्त्र राज्य का स्वप्न देखने लग गये थे। उनका यही स्वप्न पाकिस्तान के रूप में नाकार हुआ।

पाकिस्तान के विचार का आविर्भाव—पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम सर मुहम्मद इकबाल के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ था। 1930 के लीग के अधिवेशन में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि 'यदि भारत के मुसलमान मुस्लिम-भारत के निर्माण की माँग करते हैं तो ऐसी माँग पूर्णतया न्यायसंगत है। पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, सिन्ध तथा विलोचिस्तान को मिलाकर एक राज्य के रूप में देखना मेरी कामना है।' दस वर्ष पश्चात् 1940 के लीग के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया, वह 'पाकिस्तान प्रस्ताव' ही कहलाया। इसमें कहा गया था कि देश की किसी भी साविधानिक योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्वी भाग का एक प्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र राज्य बनाया जाये। इस प्रकार स्पष्ट हो गया था कि लीग का उद्देश्य भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों का एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बनाना था।

पाकिस्तान के विचार का जन्मदाता—परन्तु पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम 1940 में केम्ब्रिज के चार मुस्लिम विद्यार्थियों के द्वारा प्रकाशित किया गया। इनका नेता चौ० रहमत अली था। चार पृष्ठ की एक पुस्तिका में चौ० रहमत अली की अध्यक्षता में यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के हित में पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, काश्मीर, सिन्ध और विलोचिस्तान में रहने वाले तीन करोड़ मुसलमानों की इच्छा एक पृथक् सभ में संगठित स्वतन्त्र 'पाकिस्तान' (पवित्र स्थान) के निर्माण की है। वाद में रहमत अली ने पाकिस्तान का जो नक्शा खींचा उसको तीन नाम दिये—(1) पाकिस्तान जो पूर्वोक्त उत्तर-पश्चिमी भारत के प्रदेशों का बनता, (2) बंग-ए-इस्लाम, अर्थात् बंगाल तथा असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और (3) उस्मानिस्तान अर्थात् हैदराबाद के निजाम की रियासत। उसका यह स्वप्न भारत में इस्लामिस्तान स्थापित करने का था। यद्यपि मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्दर पृथक् मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धान्त को पर्याप्त उग्र बना दिया था, तथापि अब भी मुस्लिम रवैये में एकता तथा स्पष्टता का अभाव था। युद्धकाल में साविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए विविध प्रस्ताव रखे जाने लगे। लीग का असहयोगपूर्ण रुख बना रहा। ऐसा लगता था कि लीग सब कुछ चाहती है या कुछ नहीं चाहती है। स्वयं भारतीय मुस्लिम नेतृत्व समूचे रूप में किसी एक माँग का समर्थक नहीं था। लीग किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं थी जिसमें उसे अपनी भागी के रस्ती भर अंश का उत्सर्ग करना पड़े। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार जो भी प्रस्ताव रखती उसमें लीग के विरोध के कारण, किसी भी पक्ष का राजी होना असम्भव था।

राजगोपालाचारी प्रस्ताव में पाकिस्तान—इन सब परिस्थितियों के आधार पर अप्रैल 1942 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह राय व्यक्त की कि भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान बिना पाकिस्तान की माँग को पूरा किये सम्भव नहीं है, क्योंकि मुस्लिम साम्प्रदायिकता की हठमिता बिना पाकिस्तान का पृथक् राज्य स्वीकार किये किसी भी साविधानिक योजना को सफल नहीं होने देगी। उनकी इन धारणा का कांग्रेस महासभा ने विरोध किया, अतः राजाजी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में जनमत ज्ञात करने का विचार करने लगे। 1942 के क्रिप्प प्रस्ताव की असफलता पर गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए

जब भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ किया तो मुस्लिम लीग ने इस आन्दोलन का भत्सना की। 1944 में राजाजी जंगल में गांधी जी से मिले और उनके समक्ष अपना प्रस्ताव तथा दंग विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। गांधी जी ने राजाजी के प्रस्ताव को युक्तिमय मान लिया। युद्ध की समाप्ति पर जब पुनः भारत के सांविधानिक गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास ब्रिटिश सरकार ने प्रारम्भ किये तो मुस्लिम लीग का खयाल पूनवत् बना रहा। इस अवधि में लीग की अपनी पाकिस्तान की माँग तीव्र करने में अधिक प्रोत्साहन मिलने लगा गया था। विशेष रूप से जब लीग ने देगा कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता राजाजी तक इसका समर्थन करने लगे थे।

युद्ध के पश्चात् लीग का कार्यक्रम—1945 के गिमरा सम्मेलन तथा कैबिनेट मिशन योजना की पुनः लीग ने नाटकीय ढंग में असफल कर देने में पूर्ण ताकत लगायी। 1946 का वर्ष मुस्लिम साम्प्रदायिकता का चरमोत्कर्ष था। ब्रिटिश सरकार ने अंतिम रूप में भारतवर्ष को देग की राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित करने का सकल्प करके कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। इस मिशन की राय में पाकिस्तान का निर्माण अव्यवहार्य था। परन्तु लीग ने प्रत्येक पायवाही तथा साम्प्रदायिक दंगे छेड़ने का मार्ग अपनाकर देश का वातावरण गंदा कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान निर्माण मंभा तथा अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का सकल्प कर दिया था। जब अन्तरिम सरकार की स्थापना पण्डित नेहरू के नेतृत्व में की गई तो लीग प्रारम्भ में इसमें शामिल नहीं हुई। बाद में जब वह शामिल हुई तो उसने अन्तरिम सरकार की सफल कार्यविधि के मार्ग में बाधक बनने का कार्य मार्ग सम्पन्न करना प्रारम्भ किया। दिसम्बर 1946 में जब संविधान मंभा का उद्घाटन हुआ तो लीग ने इसका बहिष्कार किया और कभी भी इसमें शामिल नहीं हुई।

स्वतंत्रता की ओर—भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त नाजुक हो रही थी। साम्प्रदायिक तनाव का जमा वातावरण यहां तक चुका था उसमें निवटना ब्रिटिश सरकार के लिए कठिन था। ऐसी स्थिति में फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत से सत्ता छीनने की तिथि 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी। गार्ड माउण्टबेटन को गवर्नर-जनरल बनाकर भारत भेजा गया और उद्देश्य यह कार्य सौंपा गया कि वह ब्रिटिश सरकार के इरादों को अंतिम रूप दें।

माउण्टबेटन योजना में पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति—गार्ड माउण्टबेटन ने भारत में आते ही अपनी याजना बनाई और उसमें अंतिम रूप में भारत विभाजन को स्वीकार कर दिया गया। अब कांग्रेस के समक्ष भारत विभाजन स्वीकार करके देग की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनिवार्य अर्थ को स्वीकार करना पड़ा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करने में तैयारी नहीं लगायी। परन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद का यही पराजय नहीं हुआ। लीग द्वारा 1946 में प्रारम्भ की गई प्रत्येक कार्यवाही ने साम्प्रदायिक देग को भड़काया था। जब माउण्टबेटन याजना तथा स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार पंजाब तथा बंगाल में सीमा आयोग ने कार्य प्रारम्भ किया और जनसंख्या का भारत-पाकिस्तान में आवागमन शुरू होने लगा तो पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में गर मुस्लिम जनता को निकालने में जा अत्याचार-अत्याचार किये गए उन्हीं मानों मानवता को दानवता में परिणत कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया दूसरे क्षेत्र में होना भी कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद ने एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म दिया।

क्या विभाजन अनिवार्य था ?

स्पष्ट है विभाजन के लिए अग्रजों की फूल डाना और शासन करा की नीति उत्तरदायी थी। यह भी स्पष्ट है कि विभाजन के लिए मुस्लिम लीग तथा उसके कार्यकर्ताओं का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। परन्तु प्रश्न है कि क्या विभाजन के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं को भी उत्तरदायी बताया जा सकता है ? पिछले दिनों में यह विषय पर अनेक विद्वानों ने नूतन प्रकाश

डाला है। मौलाना आजाद ने इसके लिए मुख्य रूप से नेहरू जी को उत्तरदायी घोषित किया है। प्रत्येक लेखक इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ है। यदि इस प्रकार किसी को उत्तरदायी ठहराना है तो कांग्रेस के एक या दो नेताओं को उत्तरदायी ठहराने के स्थान पर समूची कांग्रेस को उत्तरदायी ठहराना अधिक उचित होगा। वस्तुतः साम्प्रदायिक समस्या के समाधान की दिशा में कांग्रेस ने जो कदम उठाये, वे प्रभावहीन और गलत थे। उदाहरण के लिए, 1916 में जब लखनऊ सम्मेलन के द्वारा कांग्रेस ने पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार किया, तो उसने एक भयंकर भूल की थी। वस्तुतः लखनऊ सम्मेलन में ही विभाजन के बीज अवलोकित किये जा सकते थे। कांग्रेस ने मुस्लिम सम्प्रदायवाद को सन्तुष्ट करने के लिए खिलाफत के साम्प्रदायिक प्रश्न को राष्ट्रीय आन्दोलन में स्थान देकर एक दूसरी भूल की। इस विषय में श्रीप्रकाश जी का निम्न कथन बहुत सारगुप्त है

‘हमारे नेताओं ने विभाजन क्यों स्वीकार किया ? यह तो स्पष्ट ही है कि महात्मा गांधी इसके घोर विरोधी थे। उनका स्पष्ट कहना था कि हम देश को एक बनाये रखना चाहते हैं। हमें शासनाधिकार से कोई प्रयोजन नहीं। परन्तु गांधी जी को अपने निकटतम सहयोगियों को अपना विरोध करते देख अपनी हार माननी पड़ी—कांग्रेस के नेता एक बार शासन के अधिकार प्राप्त करके उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वे उसकी कुछ भी कीमत देने को तैयार थे। मेरा विचार है कि अधिकार के मोह और देश की दुर्व्यवस्था के भय ने हमारे नेताओं के मन में ऐसा प्रभाव किया कि उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। कौन भाव अधिक तीव्र था यह मैं नहीं कह सकता। यदि कांग्रेस के नेता शासनाधिकार छोड़कर विभाजन को अस्वीकार कर देते तो हो सकता है अंग्रेज कुछ दिन और बने रहते। अधिक से अधिक वे मुस्लिम लीग को पूरे देश का राज्य सुपुर्द कर जाते। मुस्लिम लीग अकेले राज नहीं कर सकती थी। तब कोई ऐसा सम्मेलन हो सकता था जिसमें देश का विभाजन भी न होता और शासन भी सुव्यवस्थित हो जाता। पर अब यह सब कल्पनामात्र है।’

बहुत से लेखकों का विश्वास है कि पाकिस्तान की रचना के लिए केवल मि० जिन्ना को उत्तरदायी समझा जाना चाहिए। यह सही है कि देश के विभाजन में जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ था, परन्तु इसके लिए उन्हें एकमात्र उत्तरदायी ठहराना अनुचित होगा। यथार्थ में यदि देश की मुस्लिम जनता में साम्प्रदायिकता की भावना न होती और उसमें इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए उत्साह न पाया जाता तो मि० जिन्ना को अपने इस उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिल सकती थी।

प्रश्न

- 1 उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके अन्तर्गत भारत का विभाजन हुआ। क्या विभाजन अनिवार्य था ?

सविधान सभा • सरचना तथा उपागम

(CONSTITUENT ASSEMBLY STRUCTURE AND APPROACH)

सविधान सभा की रचना

भारत की आधुनिक शासन संस्थाओं का विकास का क्रम ब्रिटिश शासन-काल में शुरू हुआ। 1858 से 1935 तक ब्रिटिश शासकों का देख रखा कि हमारे देश में ससदीय नमूने की संस्थाओं का क्रमिक विकास हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की आँधी भी माथ-साथ चरती रही और ज्यों-या दंग स्वराज्य की डयाली का नजदीक पहुँचता गया स्वभावतः दश में अपनी सविधान सभा की मांग जोर पकड़ती गई। 1936 में कांग्रेस ने घोषणा की भारतीय केवल एस सविधानिक ढाँचे को माँगता है सकते हैं जिसका निर्माण वे स्वयं करें। पुन 1939 में कांग्रेस ने कहा सविधान सभा ही एकमात्र शासनात्मक उपाय है जिसका द्वारा एक दश के सविधान का निश्चय हो सकता है। अन्ततोगत्वा क्विंट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में सविधान सभा का निर्णय चुनाव कराया गया।

385 की कुल सदस्यता में से ब्रिटिश भारत के 292 सदस्यों के लिए तो चुनाव हुये पर भारतीय रियासतों के लिए 93 सीटों के लिए चुनाव नहीं हुए। सविधान सभा की 212 सीटें कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीता मुस्लिम लीग को 73 सीटें पर सफलता मिली 117 सीटें अन्य दलों के पास रही। सविधान सभा में कांग्रेस की सबल स्थिति देखकर मुस्लिम लीग के नेताओं में निराशा की लहर दौड़ गई। फलतः उन्होंने सविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया तथा साथ ही में उन्होंने यह भी मांग की कि पाकिस्तान का सविधान बनाने के लिए एक पृथक् सविधान सभा की रचना की जाय।

सविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रबल बहुमत प्राप्त हुआ था तथापि इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि उस एक गतिशीली अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था। स्पष्टतः मुस्लिम लीग के सम्बन्धों की अनुपस्थिति में सविधान रचना का काम सुचारु रूप में नहीं चल सकता था। मुस्लिम लीग इस तथ्य से भली भाँति अवगत थी। ब्रिटिश सरकार के रवये से मुस्लिम लीग को प्रत्याह्वान प्राप्त हुआ था। कांग्रेस ने लीग को विधान सभा में लाने का प्रयास भी किया था परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सविधान सभा की बैठकें मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के बावजूद भी 9 दिसम्बर 1946 में आरम्भ हो गई थी और स्वतंत्रता के पूर्व उसने अपना अध्यक्ष व विभिन्न समितियाँ चुन ली थी तथा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया था। यह अवश्य है कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व तक सविधान सभा का काम अत्यधिक मंद गति से चला था। परन्तु स्वतंत्रता के साथ सविधान सभा के मांग से समस्त कठिनायियों का निराकरण हो गया और वह एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्य कर सकती थी।

सविधान सभा के कार्य में 15 अगस्त के पूर्व 211 सदस्यों ने भाग लिया इनमें 155 हिंदू थे 30 अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि थे 5 सिख थे 6 भारतीय ईसाई थे 5 प्रतिनिधि निछाड़ी जातियों के थे 3 एंग्लो इंडियन थे 3 पारसी थे तथा चार मुसलमान। यह मंजूर है कि कुल मुस्लिम सीटें 80 थी और उनमें में केवल 4 सविधान सभा में उपस्थित हुए थे परन्तु यह

आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें भाग लेने वाले केवल हिन्दू थे ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् सविधान सभा का नवगठन किया गया, ऐसा करना इसलिये आवश्यक था क्योंकि देश का विभाजन हो चुका था और उसके साथ में पंजाब, बंगाल और आसाम के प्रान्तों के भी हिस्से किये जा चुके थे । नवगठित सविधान सभा में 298 सदस्य थे । बाद में जब जम्मू-कश्मीर का राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ तो उसके भी 4 सदस्यों को सविधान सभा में शामिल कर लिया गया । हैदराबाद ने भारतीय संघ की सदस्यता बहुत बाद में स्वीकार की थी, अतः सविधान सभा में उसका कोई भी सदस्य नहीं था । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में सविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से विधान-मण्डलों के के द्वारा निर्वाचन हुआ था, वहाँ देशी राज्यों के 40 प्रतिशत प्रतिनिधियों को वहाँ के नरेशों ने मनोनीत किया था ।

यहाँ सविधान सभा के सदस्यों का राजनीतिक एवं व्यावसायिक आधार पर विश्लेषण करना भी अप्रासंगिक न होगा । जैसा कहा जा चुका है कि सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित हुये थे । परन्तु कांग्रेस को यथार्थ में कोई राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता था । फलतः उसमें सैद्धान्तिक एकता का अभाव था । कांग्रेस में जहाँ घोर रूढ़िवादी थे, वहाँ दूसरी तरफ उसमें ऐसे भी व्यक्ति थे जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उतावले थे । इस प्रकार उसमें एक छोर पर सरदार पटेल और के० एम० मुन्शी थे जिनके अनुसार यथास्थिति में किसी भी प्रकार के मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ दूसरे छोर पर उसमें प्रोफेसर के० टी० शाह और दामोदर स्वरूप सेठ भी थे जिन्हें समाजवादी व्यवस्था में अपनी आस्था को छिपाने में अरुचि थी । यह सही है कि दोनों छोरों के बीच में ऐसे बहुत से सदस्य थे जिन्होंने सैद्धान्तिक विवाद में कभी कोई निश्चित स्थिति ग्रहण नहीं की । वस्तुतः कांग्रेस में ऐसे ही सदस्यों का बहुमत था । कांग्रेस टिकट पर जो लोग चुने गये थे उनमें देश के लघु-प्रतिष्ठित विधिशास्त्री तथा बुद्धि-जीवी भी थे । प्रतिष्ठित वकीलों एवं विधिशास्त्रियों में उल्लेखनीय नाम सर अल्लादी कृष्णस्वामी ऐयर का है, जिन्हें विश्व के सभी सविधानों का पूर्ण ज्ञान था और जो सदस्यों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ और जिन्होंने एक अध्यापकीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सिखाया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा । सदस्यों में बकशी टेकचन्द और पी० के० सेन जैसे अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश भी थे और सर एन० गोपालस्वामी आयरगर तथा एच० बी० कामथ जैसे अवकाश-प्राप्त सिविल सर्विस के सदस्य भी । सविधान सभा अध्यापन के व्यवसाय के प्रतिनिधित्व से भी अछूती नहीं बची थी, उसे डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, डा० एच० सी० मुखर्जी तथा प्रोफेसर के० टी० शाह जैसे व्याति-प्राप्त अध्यापकों का अपने कार्य में सक्रिय सहयोग प्राप्त था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभा में देश के बुद्धिजीवी वर्ग की विविधता को भली प्रकार प्रतिध्वनित थी ।

सविधान सभा की रचना के सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य दूसरी बात यह है कि उसका गठन प्रान्तीय विधानमण्डलों के उन सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने किया था जो 1935 के सविधान के अनुसार पृथक् निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत चुने गये थे । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि सभा में साम्प्रदायिक तत्त्वों का भी प्रतिनिधित्व होता । यह सही है कि पाकिस्तान की रचना के उपरान्त, इन तत्त्वों का प्रभाव सविधान सभा में कम हुआ था, तथापि यह दावा नहीं किया जा सकता कि सभा उनके प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो गई थी । वस्तुतः उसमें सभी प्रकार के सम्प्रदायवादी उपस्थित थे, यद्यपि उनकी सत्ता बहुत अधिक नहीं थी । इस प्रकार उनके सदस्यों में मौहम्मद इस्माइल जैसे मुस्लिम सम्प्रदायवादी भी थे । सविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का सम्बन्ध व्यावसायिक मध्यम वर्ग के साथ था और उसमें सबसे अधिक मन्त्रा-वकीलों की थी । इनके अतिरिक्त सदस्यों की सूची में बड़े जमींदारों तथा उद्योगपतियों के नाम भी देने जा सकते थे ।

उपर्युक्त विवेचना में स्पष्ट है कि सभा में किसानों और श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों को

छाड़कर अन्य सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। कुछ समय के लिए उसमें अविभाजित बंगाल से सामनाथ नाहिडो के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक प्रतिनिधि प्राप्त था परंतु विभाजन के उपरांत जब पश्चिमी बंगाल में दोसरा चुनाव हुए तो नाहिडो अपने को दासरा चुनाव में असफल रहे। संविधान सभा में कांग्रेस का बानवाना था और इस बात की अभियक्ति सभा के विवादों में जल्द ही अवलोकित की जा सकती थी। कांग्रेस का दावा था कि वह समूचे देश का प्रतिनिधित्व करती है।

संविधान के निर्माण का प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण

संविधान की रचना देश के विभाजन तथा साम्प्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को बुलाई गयी। साम्प्रदायिक आधार पर देश का विभाजन सन्निकट था। कांग्रेस के नेता विभाजन को रोकने में लगे थे। अतः वे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे मुस्लिम लोग के साथ समझौते की सम्भावनाएँ विनष्ट हो जायें। इसलिए 15 अगस्त 1947 के पूर्व संविधान सभा में जा ममीने प्रस्तुत किया गया उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया था। किंतु जब पाकिस्तान की रचना हो गई तो भारत के लिए एक नया गति और एक नया खतरा उत्पन्न हो गया। संविधानका एक दृष्टिकोण का इस वस्तु स्थिति ने एक बड़ा सीमा तक प्रभावित किया था। आदमवाद न यथावत् का जन्म दे दिया इसलिए सरकार की निरंकुशता में व्यक्ति की रक्षा करने के स्थान पर उनकी चिन्ता और यह होने लगा कि खतरनाक यत्तियाँ तथा समाज विरोधी तत्त्वों से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाय। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रांतीय स्वायत्तता के आदर्श पीछे धकेल दिए गए तथा पीछे के दरवाजे से एकता को स्थापित करने के प्रयत्नों का ध्यान केन्द्र को गतिशाली बनाने के प्रयत्न में न दिया। यत्तियों के अधिकार से राज्य के अधिकार अधिक महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए। वास्तव में संविधान सभा के विवादों में उभरते दृष्टिकोण सभी स्थानों पर देखा जा सकता है।

संविधानकारों के दृष्टिकोण का प्रभावित करने वाला दूसरा कारण वह अनुभव था जिस उन्नि ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान प्राप्त किया था। जीव निवेदित सत्ता न भारतीयों के ऊपर अनेक आयोगनायें नादी थी। अतः यह स्वाभाविक ही था कि नये संविधान की रचना करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता कि भविष्य में उन अयोग्यताओं का निराकरण हो सके।

भारत के सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ न भी संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण का प्रभावित किया था। इन कुरीतियों के परिणामस्वरूप देश की जनता का एक प्रधान अंग अछूत माना जाता था। स्वाधीन भारत के लिए यह स्थिति अवाछनीय थी। इसलिए यह अनिवार्य था कि संविधान में देश के सामाजिक जीवन के इस कलक का धा होने का प्रयास किया जाता।

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन घम निरपेक्ष आदर्शन था। कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमान समावे। इसलिए कांग्रेस के नवृत्त में निर्मित हानि बाद संविधान में घमनिरपेक्षता की अपेक्षा का जा सकती था। संविधान के इस पहलू का सम्बन्ध संविधान निर्माताओं के बल घमनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ ही नहीं था उसका सम्बन्ध वस्तु स्थिति के साथ भी था। देश में अनेक धार्मिक भाषायी तथा जातीय असमन्वय पाये जाते थे और उनके मासृतिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता थी। वस्तुतः वैदिक मंगल योजना का स्वीकार करके राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार का ऐसा करने का आश्वासन भी दिया था।

जता कहा जा चुका है कि संविधान सभा के अधिकांश समस्या का सम्बन्ध धार्मिक मध्यम वर्ग के साथ था। इन लोगों का धार्मिक विकास ब्रिटन को उत्तरदायी परम्पराओं में अनुप्राणित था। फलतः भारतीय संविधान का मुख्य दार्शनिक धारा उत्तरदायी थी।

सविधान के प्राविधानो मे सन्निहित दृष्टिकोण

उपर्युक्त पृष्ठभूमि मे सविधान के मुख्य प्राविधानो मे सन्निहित दृष्टिकोणो की विवेचना की जा सकती है ।

1 प्रस्तावना

सविधान सभा ने सविधान मे अग्रलिखित प्रस्तावना निहित की—

‘हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न-लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब मे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता मे वृद्धि करने के लिए दृढ़ सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा मे आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ईसवी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, सम्वत् दो हजार छ विक्रमी) को एतद् द्वारा इस सविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है ।’

प्रस्तावना मे अभिव्यक्त विचारो को सविधान सभा ने अपने पहले अधिवेशन मे ही नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करके स्वीकार कर लिया था । प्रस्तावना के आरम्भिक शब्दो मे यह भाव निहित है कि अन्तिम सत्ता जनता मे निवास करती है और जनता की इच्छा से ही सविधान का उद्भव हुआ है । इस सम्बन्ध मे सविधान सभा मे यह मत व्यक्त किया गया कि सभा की रचना सीमित मताधिकार पर आधारित प्रान्तीय विधानमण्डलो के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुई है, अतः उसे भारतीय जनता की इच्छा का प्रतिबिम्ब नहीं कहा जा सकता । इस तर्क के आधार पर यह विचार भी व्यक्त किया गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नवीन सविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए । परन्तु जैसा स्वाभाविक था इस विचार को सविधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका ।

प्रस्तावना मे एक सशोधन के द्वारा यह सुझाव रखा गया था कि उसमे भारत को ‘प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतान्त्रिक समाजवादी गणराज्य’ बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए । परन्तु इस सशोधन को सविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया । इसके विरोध मे डा० अम्बेदेकर का यह तर्क था कि हमे आने वाली पीढियो को किसी एक प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बाँध देना चाहिए । हमे यह काम बाद मे चुनकर आने वाली ससदो के लिए छोड़ देना चाहिए ।

प्रस्तावना मे ‘ईश्वर’ शब्द की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी । एच० बी० कामथ ने यह सशोधन प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना के आरम्भ मे ‘ईश्वर के नाम पर’ शब्द जोड़े जाये । परन्तु सभा ने इस सुझाव से असहमति प्रकट की, उसने हृदय नाथ कुंजरु के इस मत को स्वीकार किया कि यह सशोधन प्रस्तावना की मूल भावना के प्रतिकूल है क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति की विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतन्त्रता स्वीकार करती है ।

2 मूल अधिकार

परतन्त्रता की स्थिति मे मध्यम वर्ग ने निरकुश शासको के हाथो जो अन्याय सहे थे उनमे मुख्य थे निरकुश कर-प्रणाली, निरकुश शिरफ्तारी, भाषण और विचार-अभिव्यक्ति के ऊपर निरकुश नियन्त्रण तथा धार्मिक स्वतन्त्रता का हनन । यही नहीं, उस काल मे समाज का सगठन पद-सोपान पर आधारित था, जिसमे सबसे ऊँचा स्थान सामन्तो को प्राप्त था, फलतः इस सामाजिक सगठन मे उदीयमान मध्यम वर्ग समानता के अधिकार से वंचित था । संक्षेप मे ये अन्याय थे जिनका उपचार होना था । इनमे मे प्रत्येक उपचार को मूल अधिकार की सज्ञा प्रदान की गई । राजाओ द्वारा थोपे गये निरकुश करो का उपचार करने के लिए सम्पत्ति

क अधिकार का प्रतिपादन किया गया निरकुण गिरफ्तारी की सम्भावनाओं का निराकरण करने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की मांग की गई तथा सामाजी व्यवस्था में सन्निहित असमानता से उत्पन्न जाया का उपचार समानता के अधिकार में खाजा गया।

भारत में भी पश्चिम की भांति अधिकारों को अयाय के उपचार के रूप में स्वीकार किया गया। इन अयाय का मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार के अयाय वे थे जिन्हें भारतवासियों के ऊपर ब्रिटिश शासन ने थोपा था और जिनका थोड़ा या बहुत अनुभव विधान सभा के अधिकार सन्स्था को था। दूसरे प्रकार के अयाय वे थे जिनकी जड़ें स्वयं भारत के सामाजिक जीवन में सन्निहित थीं। स्पष्टतः स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए यह परमावश्यक था कि इन अयायों का निराकरण होता।

मूल अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान निर्माताओं को जिस समस्या का सबसे पहला सामना करना पड़ा वह समस्या यह थी कि किन अधिकारों को मूल अधिकार माना जाय। प्राधुनिक लोक-कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि में काम और शिक्षा के अधिकार जीवन स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। यथायथ आज इन अधिकारों का महत्व उदारवादी दृष्टि में प्रतिपादित अधिकारों की अपेक्षा कहाँ अधिक है क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में अच्छे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परन्तु संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को वाद-योग्य (justiciable) मूल अधिकारों की सूची में नहीं रखा। उन्होंने उन्हें अवाद-योग्य (non justiciable) नीति निर्देशक तत्त्वों में स्थान दिया। इस प्रकार के अधिकार जिन्हें मायता प्रदान करके श्रमिक वर्ग तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के जीवन में मौलिक परिवर्तन लाये जा सकते थे उन्हें अवाद-योग्य बना लिया गया। किन्तु मध्यम वर्ग के हितों पर आधारित अधिकारों को मूल अधिकारों की सम्मानित श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया गया जिनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायालयों द्वारा दण्ड की व्यवस्था थी।

उत्तरवर्तीय है कि इस दृष्टिकोण को संविधान सभा में चुनौती दी गयी। यथायथ इस दृष्टिकोण की आलोचना सदन में पाय जान जाने सभी राजनीतिक मता को मानने वालों ने की थी जिनके एक छोर पर उदारवादी सदस्य हूय नाथ कुजूरू थे और दूसरे छोर पर सदन के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ नाहिडी थे। कुजूरू का कहना था कि वाद-योग्य तथा अवाद-योग्य अधिकारों के बीच में विभाजन रेखा खींचना मुश्किल है। प्रभाव रजन ठाकुर का कहना था कि मूल अधिकारों की सूची में आर्थिक अधिकारों को स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए। नाहिडी ने कुजूरू के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। जपन तक की यात्रा करते हुए उन्होंने कहा उदाहरण के लिये जब हम यह व्यवस्था करते हैं कि योगा के पास काम का अधिकार होना चाहिए यानी देश से बेरोजगारी का उन्मूलन होना चाहिए तो वह एक सामाजिक अधिकार है। यदि आप उसे मूल अधिकारों के अन्तर्गत शामिल कर देते हैं तो वह स्वाभाविक रूप में वाद-योग्य बन जाता है। इसी प्रकार भूमि का प्रश्न लिया जा सकता है। यदि हम यह कहना चाहते हैं कि भूमि पर जनता का स्वामित्व है और किसी का नहीं तो वह निश्चिन्त एक सामाजिक और मूल अधिकार होगा परन्तु यदि उस अधिकार की कार्याविति अपेक्षित है तो यह एक वाद-योग्य अधिकार भी होगा। जहाँ वाद-योग्य तथा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के बीच विभेद निरकुणतापूर्ण है। आर के सिधवा ने यह मत व्यक्त किया कि मूल अधिकारों की सूची उद्देश्य प्रस्ताव के साथ तथा उस पर क्रिय गय नहरू जी के भाषण के साथ मेल नहीं खाती। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक साथ उपलब्ध होगा। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय नहरू जी ने कहा था कि वे समाजवाद में विश्वास करते हैं और उन्हें विश्वास है कि भारत समाजवादी राज्य के संविधान को निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सिधवा ने उस वक्त के लिए कुछ व्यक्त किया कि इन आदर्शों को मूल अधिकारों की सूची में स्थान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवाद-योग्य

अधिकार केवल सविधान के पृष्ठों को सजाने तथा केवल थोड़ा सा सन्तोष प्रदान करने के लिए है, परन्तु मैं चाहता हूँ कि उन्हें सविधान का अभिन्न अंग बनाया जाय ताकि प्रत्येक नागरिक गर्व पूर्वक यह कह सके कि 'अब समानता एवं सम्पत्ति के उपभोग करने का मेरा समय आ गया है ताकि मैं हमेशा के लिए दरिद्र न रह सकूँ।' मूल अधिकारों के मसौदे में आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विशम्भर दयाल त्रिपाठी ने कहा था कि 'भूत अधिकार को छोड़कर सविधान के अन्तर्गत गरीब आदमी को कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नहीं हुआ है।'

सामान्य विवेचन के समय मूल अधिकारों के मसौदे में कुछ कमियों की ओर भी इशारा किया गया। इस सम्बन्ध में जो पहली बात कही गयी वह यह थी कि अस्पृश्यता के निवारण के लिए जो प्राविधान किये गये हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमें जातिव्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। समस्या के इस पहलू को प्रस्तुत करते हुए प्रमोद रजन ठाकुर ने कहा कि 'मेरी समझ में नहीं आता कि आप जाति-व्यवस्था का उन्मूलन किये बिना अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं? छुआछूत जाति-व्यवस्था की बीमारी का केवल लक्षण है।' इस दृष्टिकोण का समर्थन डा० एस० सी० बनर्जी तथा धीरेन्द्रनाथ दत्त ने भी किया था।

आलोचकों ने अधिकारों के मसौदे में उल्लिखित सीमाओं के औचित्य को भी चुनौती दी। हृदय नाथ कुजूर ने कहा कि इन सीमाओं के कारण 'अधिकार व्यवहार में बाध-योग्य भी नहीं रहेंगे।' मसौदे के इन प्राविधानों की शिकायत करते हुए सोमनाथ लाहिडी ने कहा—'प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ प्रतिबन्ध जुड़े हुए हैं, जिससे अधिकार का पूर्ण रूप से हनन हो जाता है, क्योंकि सभी जगह यह कहा गया है कि गम्भीर संकट के समय इन अधिकारों को ले लिया जायेगा।' मूल अधिकारों के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी की व्यवस्थाएँ भी आलोचकों की दृष्टि से अछूती नहीं बची। वास्तव में यह आश्चर्य की बात थी कि जिन लोगों ने औपनिवेशिक शासन में निवारक नजरबन्दी के कटु अनुभव प्राप्त किये थे, उन्हीं लोगों ने सविधान में उन प्राविधानों को स्थान दिया जिनसे वैयक्तिक स्वाधीनता का संरक्षण नहीं हो सकता था। यह बात निस्सन्देह सही है कि सविधान की रचना के समय देश ऐसी असाधारण परिस्थितियों के बीच में से होकर गुजर रहा था जिनसे राज्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो गया था। इन परिस्थितियों का प्रभावपूर्ण तरीके से मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक था कि राज्य के पास असाधारण शक्ति हो। परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति तो माधारण कानून के द्वारा भी हो सकती थी, इसलिए इस सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों का यह मत था कि सविधान में इस प्रकार के प्राविधान नितान्त अनावश्यक हैं। इन सदस्यों में सबसे अधिक मुखर सोमनाथ लाहिडी थे, जिन्होंने यह घोषणा की कि 'इन मूल अधिकारों की रचना पुलिस कास्टविल के दृष्टिकोण से की गई है, स्वतन्त्र एवं सघर्षरत राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं।'

सविधान सभा में जिस धारा ने बहुत लम्बे विवाद को जन्म दिया, उसका सम्बन्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ है। सदन के विधिवेत्ता सदस्यों ने इस सन्दर्भ में राज्य के मुख्य अभिकरणों—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका—की भूमिका की विवेचना की। यथार्थ में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए खतरा कार्यपालिका की ओर से उत्पन्न होता है, ऐसा उस समय विशेष रूप से होता है जबकि उसके पास सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए केवल सन्देह के आधार पर किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने का अधिकार हो। संकटकाल में इस प्रकार की शक्ति का औचित्य समझा जा सकता है, परन्तु इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि कार्यपालिका इस शक्ति का प्रयोग साधारण स्थिति में भी करे तो यह उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार है। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाना चाहिये—विधानमण्डल को या न्यायपालिका को। इस प्रकार, अन्तिम विचारण में, विवाद ने व्यवस्थापिका बनाम न्यायपालिका का रूप धारण कर लिया।

यहाँ यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि सविधान के तीसरे अध्याय की रचना एक

निश्चित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुई थी। स्वतंत्रता के पूर्व सभा ने 15वां धारा में जिस वाक्य में 21वीं धारा के रूप में स्थान दिया गया 'अमरीकी संविधान की कानून की प्रक्रिया' शब्दों का प्रयोग किया गया था। उस समय यह विश्वास किया जाता था कि इस सम्बन्ध में भारतीय कानून अमरीकी ढाँचे के अनुरूप होगा। परन्तु पाकिस्तान की रचना के उपरान्त जब देश में विभाजन पमाने पर साम्प्रदायिक दंग आरम्भ हो गये तो समस्या के ऊपर पुनर्विचार आवश्यक हो गया। उस समय यह महसूस किया गया कि अधिकारों का उनकी प्रागम्भिक पवित्रता के वातावरण में अस्तित्व सम्भव नहीं था। सत्ता के अर्थ में स्वतंत्रता के अधिकारों का उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिस रूप में उस अमरीकी संविधान में मायता प्रदान की गई थी। इस पृष्ठभूमि में जो समस्या प्रस्तुत हुई वह यह थी कि सामाजिक नियंत्रण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच जिसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाये। वस्तुतः 'मानव' का साथवता के दानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में है। परन्तु विभाजन से उत्पन्न नव द घटनाओं के वातावरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदेश को वांछित महत्व प्रदान नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभा के अधिकांश सदस्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की अपेक्षा सामाजिक नियंत्रण का स्थापित करने के लिए अधिक चिन्तित थे। इस प्रकार कानून की प्रक्रिया (Due Process of Law) शब्दों के स्थान पर जापानी संविधान की 21वीं धारा में प्रयुक्त कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का छाड़कर (except in accordance with the procedure established by law) शब्दों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार 'मायल' का एक जटिलपूर्ण कानून के मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस प्राविधान के समर्थन में तब प्रस्तुत करते हुए 13वीं धारा (19वीं धारा) पर हुए विचार के समय में हनुमंतया ने कहा था— 'मायल' की प्रकृति ऐसी नहीं है कि वे विधायी कार्यों का निष्पन्न कर सकें वे बस उनकी व्याख्या कर सकते हैं। अब आने वाले समय में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ कायम हो पायें उसी के अनुसार कानून भी जपने जायें वन्त जायें इस सम्भव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भूत अधिकारों को मर्यादित करने की शक्ति व्यवस्थापिका को सौंपी जाय। परन्तु इस दृष्टिकोण का विरोध लगभग आठ वक्ताओं ने किया जिनमें डाकिंग कमिटी के सदस्य के एस. मुन्ना भी शामिल थे। मुन्ना ने कहा कि सम्भवतः राजकन चल रही सन्देहातीन अवस्था के कारण हम यह भूल गये हैं कि यदि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दूर नहीं दते तथा उस 'मायल' की सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो हम उस परम्परा का जन्म देंगे जो देश में रही सभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। इस दृष्टिकोण का समर्थन जहाँ एक तरफ ने भी किया। उनका कहना था— हम यह अनुभव करें कि हम अपने यहाँ मसलीय सरकार की व्यवस्था करा जा रहे हैं यानि ऐसी सरकार की जहाँ विधानमण्डल को कार्यपालिका नियंत्रित करती है। हमारे यहाँ अध्यात्म की भाँव व्यवस्था है जिसका अर्थ है कि आठ या दस व्यक्तियों की एक समिति विमा बात को तय करेगी उस अध्यात्म के रूप में लागू करेगी और व्यवस्थापिका उस अपनी स्वोक्ति प्रदान कर देगी अथवा उसका जय होगा कार्यपालिका में अविश्वास का प्रस्ताव। इसलिए अन्तिम विचारण में व्यवस्थापिका का अर्थ है कवित्व या कार्यपालिका। इसलिए प्रश्न है कि क्या आप कार्यपालिका का इस प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करने का तयार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुनिपाली अधिकारों का हनन कर सकती हैं या आप कार्यपालिका पर कुछ नियंत्रण लगाना चाहते हैं।

परन्तु इन तर्कों को संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। यदि इस प्राविधान पर हुई चर्चा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो हम यह अनुभव करेंगे कि संविधान निर्माताओं ने इस निष्पत्ति को दो कारणों से स्वीकार किया था। प्रथम यह कानून की प्रक्रिया शब्दों के माध्यम से जुरी हुई अपराधों का भारतीय संविधान में स्थान नहीं देना चाहते थे। दूसरे वे नहीं चाहते थे कि कार्यपालिका विधानमण्डल का तीसरा सदन बन जाय।

सविधान सभा में 22वीं धारा ने भी अत्यधिक गरम वहस को जन्म दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सविधान के मसौदे में इस प्रकार की कोई धारा नहीं थी। वस्तुतः उसे सभा के अन्तिम दिनों में प्रस्तुत किया गया था। डा० अम्बेदेकर ने उसका औचित्य प्रमाणित करते हुए यह कहा था कि इस व्यवस्था के माध्यम से 'कानून की पद्धति' शब्दावली के समस्त लाभ जन-साधारण को उपलब्ध हो सकेंगे।

इस प्राविधान में निम्न व्यवस्थाएँ की गई थी—

- (1) गिरफ्तार किये हुए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताये जायेंगे।
- (2) उन्हें न्यायालय में अपने बचाव के लिए अपनी इच्छा का वकील रखने का अधिकार होगा।

(3) गिरफ्तार किये गये अथवा नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा और यदि उसकी हिरासत की अवधि को बढ़ाया जायेगा तो ऐसा मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जायेगा।

परन्तु इन अधिकारों के दो अपवाद थे। प्रथम, ये अधिकार उन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे जिनका सम्बन्ध किसी शत्रु राष्ट्र के साथ है। दूसरे, ये अधिकार उन व्यक्तियों को भी नहीं दिये जायेंगे जिन्हें निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

जहाँ तक पहले अपवाद का प्रश्न था, उसका सविधान सभा में कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वह एक उचित सिद्धान्त पर आधारित था। परन्तु दूसरे अपवाद के विरोध में पर्याप्त मात्रा में गरमा-गरमी हुई। उदाहरण के लिए महावीर त्यागी ने इस अवसर पर भाषण करते हुए यह कहा था कि यह धारा 'मूल अधिकारों का निषेध' है और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी 'काश कि डा० अम्बेदेकर तथा ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को जेल में नजरबन्दी का अनुभव होता।' अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश वरही टेकचन्द ने अपने शक्तिशाली भाषण में इस प्राविधान की कटु आलोचना की। उन्होंने पूछा कि क्या ससार में कोई ऐसा लिखित सविधान है जिसमें साधारण स्थिति में बिना मुकदमा चलाये लोगों की नजरबन्दी की व्यवस्था की गई हो।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधान में इस व्यवस्था को इस समझ के आधार पर उचित ठहराया गया था कि देश में सकटकालीन अवस्था हमेशा कायम रहेगी तथा सविधान विवेकपूर्ण एवं कानून मानने वाले लोगों के लिए नहीं है, अपितु उन असामान्य विगड़े हुए लोगों के लिए है जो समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

यद्यपि सविधान सभा में समानता के अधिकार से सम्बद्ध प्राविधानों का कोई विरोध नहीं हुआ, तथापि लोक सेवाओं में पिछड़े हुए वर्गों को दी जाने वाली रियायतों ने कुछ विवाद की अवश्य जन्म दिया। इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियुक्तियों में स्थान सुरक्षित रखने का अर्थ है पिछड़ेपन तथा अयोग्यता को प्रोत्साहन देना। इसके समर्थन में केवल एक ही बात कही जा सकती है और वह यह है कि यह व्यवस्था उदार है, 'परन्तु इस उदारता के फलस्वरूप उन लोगों का पतन होगा जिनके प्रति इसे व्यवहार में लाया जाएगा।' परन्तु सदन ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अधिकांश सदस्यों की यह मान्यता थी कि पिछड़े हुए वर्गों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकें, यह आवश्यक है कि उनके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाए।

धार्मिक अधिकारों से सम्बद्ध प्राविधानों के कारण भी सविधान सभा में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ। वह उन धाराओं को लेकर हुई जिनके अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता के नाम पर धर्मत्व अथवा न्याय के अधीन धार्मिक नामों पर शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनके धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करने की वान कही गई थी। आलोचकों का कहना था कि धर्म-निरपेक्ष राज्य में धर्म के जाघार पर अल्पमत्त्वों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, यदि ऐसा

किया गया तो उसके परिणामस्वरूप धर्म निरपेक्षता का आधार ही नष्ट हो जाएगा। यही नहीं धर्म का आधार पर शिक्षा मस्याआ की स्थापना से राष्ट्रीय एकता का भाग ही अवरुद्ध नही होगा जो भाग्य जैसे विभिन्न मतावलम्बी द्रव्य में परमावश्यक है अपितु उससे साम्प्रदायिकता तथा समाज राष्ट्रविरोधी दृष्टिकोण का बढावा मिलेगा जसा कि अब तक होता आया है और जिसके घातक परिणामों से हम अवगत हैं। वस्तुतः हम आगम्य का एक संगोपन प्रोपेसर के टी ग्राहक ने 6 दिसम्बर 1948 का प्रस्तुत भी किया था। परन्तु डा अम्बेदेकर ने इस संगोपन को अस्वीकार कर दिया।

जिम अधिकार को निमित्त करने में संविधान सभा को सबसे अधिक कठिनाई हुई उसका सम्बन्ध 31वीं धारा में निहित सम्पत्ति के अधिकार से था। इस धारा का प्रस्तुतीकरण स्वयं नेहरू जी ने किया था। अपने भाषण में नेहरू जी ने कहा कि इस प्रश्न के प्रति दा दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण का सम्बन्ध 'यक्ति के अधिकार' के साथ है जबकि दूसरा दृष्टिकोण उस सम्पत्ति में समाज की रचि का ध्यान में रखकर चलता है। नेहरू जी ने दावा किया कि उनका प्रस्ताव इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक संविधान का प्रश्न है सम्पत्ति पर बल पूर्वक अधिकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्य की प्रगति व सुरक्षा के लिए किसी वस्तु का आवश्यक समझते हैं तो व्यक्ति उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता। परन्तु सम्पत्ति पर अधिकार करते समय विधान मण्डल के लिए यह आवश्यक है कि वह उचित एवं वायवपूर्ण मुआवजे की व्यवस्था करे। परन्तु ध्यान में रखने की बात यह है कि 'याय' का सिद्धांत केवल व्यक्ति पर लागू नहीं होता समाज पर भी लागू होता है। निम्नान्तर्ह समाज अन्तर्गतत्वा व्यक्ति के अधिकारों का उत्पन्न कर सकता है परन्तु कोई भी राज्य व्यक्ति के अधिकारों का उस समय तक चोरा नहीं पहुँचाया जावे तक ऐसा करना बहुत अधिक आवश्यक न हो। तब प्रश्न है कि उनका बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाय। उत्तरान क्या कि संतुलन बानूनी तरीके में स्थापित किया जा सकता है परन्तु अन्तिम विश्लेषण में संतुलन स्थापित करने बानी सत्ता का निवास प्रभुत्वपूर्ण विधान मण्डल में ही होना चाहिए।

नेहरू जी ने कहा कि सदन को यह अधिकार हागा कि वह मुआवजे का अथवा उसके सिद्धान्त को निर्धारित करे और इसको केवल एक स्थिति में चुनौती दी जा सकती है और वह यह है कि सदन संविधान के साथ कोई छोटा न करे। साधारणतः समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन संविधान को छोड़ा नहीं देगी। अथ उपधाराओं की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को केवल इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह यह देखे कि उतावनेपन में विधानमण्डल कोई गति नहीं कर ले। कोई 'यायधीन' कार्य सर्वोच्च 'यायालय' सम्प्रभुता-सम्पन्न विधानमण्डल के नियमों ऊपर नियम नहीं दे सकता। नेहरू जी की राय थी कि इस सम्बन्ध में 'यायपालिका' का काम केवल सदन के कामों की प्रतियाँ को दूर करना था।

इस विषय पर जा बहस हुई उसमें एक जान पहचान समाजवादी विचारों वाले सन्स ने यह निष्कर्ष की इस धारा को संविधान में स्थान देने से समाजवाद की उपलब्धि असम्भव हो जायेगा। दूसरे उपधारा की सन्स ने मुआवजा देने के प्रश्न पर प्रधानमंत्री से असहमति व्यक्त की। तीसरे में इस सम्बन्ध में 'यायपालिका' का किसी भी प्रकार की शक्ति प्रदान करने का अवाञ्छनायक बताया। सदन में कुछ एम भी सन्स थे जिनका मन उपर्युक्त मता से संवत्ता भिन्न था। उनका कहना था कि मुआवजा उचित और पर्याप्त होना चाहिए तथा अन्तिम रूप से उसका निर्धारण 'यायपालिका' के द्वारा होना चाहिए।

यहाँ अन्त में सांविधानिक उपधारा के अधिकार का स्थगित करने के प्राविधान पर हई बहस का उत्तर आवश्यक है। इस व्यवस्था की आवश्यकता बरतते हुए तज्जम्मुन हुसैन ने कहा था कि राष्ट्रपति को इस अधिकार के स्थगन की शक्ति प्रदान करना अनिवार्य होगा। उन्होंने संविधान सभा द्वारा इस प्रकार के प्राविधान का निमित्त करने की शक्ति का भी चुनौती दी। उत्तरान

कहा, 'हमारा स्वतन्त्र देश है। यदि लोग क्रान्ति चाहते हैं, तो उन्हें क्रान्ति करने की छूट होनी चाहिए। हमें उसे रोकने का क्या अधिकार है? इसलिए मैं कहता हूँ इस सविधान के अन्तर्गत जिन अधिकारों का आश्वासन दिया गया है, उनके स्थगन का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो।' इसी प्रकार के तर्क सदस्यों ने सकटकालीन प्राविधानों पर बहस के समय व्यक्त किये थे। परन्तु डा० अम्बेदकर ने इस अलोकतान्त्रिक व्यवस्था का समर्थन किया था और कहा था कि 'इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य को व्यक्ति को आश्वासन देना चाहिए ताकि उसके पास अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता हो, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि कुछ अवसरों पर, जैसे जब राज्य का अस्तित्व सकट में हो, उस समय इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबन्ध होने चाहिए। सकट के समय स्वयं व्यक्ति को यह लगेगा कि उसका अस्तित्व ही मिट रहा है।'।

3 नीति निर्देशक सिद्धान्त

सविधान सभा में चौथे अध्याय में सन्निहित धाराओं पर बहस शीर्षक को लेकर शुरू हुई। करीमुद्दीन ने इस आशय का एक सशोधन प्रस्तुत किया कि शीर्षक में से 'निर्देशक' शब्द हटाकर 'मौलिक' (Fundamental) शब्द का प्रयोग किया जाये। इसी आशय का एक सशोधन एच० बी० कामथ ने प्रस्तुत किया। इन लोगों का कहना था कि इन सिद्धान्तों का कार्यान्वयन राज्य के लिए अनिवार्य होता चाहिए। अन्यथा इनको सविधान में स्थान देने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। डा० अम्बेदकर ने इन सशोधनों का विरोध करते हुए दो तर्क प्रस्तुत किये प्रथम, इन सिद्धान्तों को मौलिक सिद्धान्तों के रूप में 29वीं धारा के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए शीर्षक में 'मौलिक' शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। दूसरे, इन सिद्धान्तों का प्रयोजन यथार्थ में आने वाली व्यवस्थापिकाओं एवं कार्यपालिकाओं को इस सम्बन्ध में निर्देशन देना है कि उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। यदि 'निर्देशक' शब्द को हटा दिया गया तो इस अध्याय की रचना का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। डा० अम्बेदकर के भाषण के उपरान्त सभा ने समस्त सशोधनों को अस्वीकार कर दिया।

परन्तु कुछ सदस्य ऐसे थे जो डा० अम्बेदकर के तर्कों से सन्तुष्ट नहीं थे। वे इन सिद्धान्तों को प्रभावशाली बनाना चाहते थे। उन्हें अपने मत को व्यक्त करने का अवसर उस समय प्राप्त हो गया जबकि सदन के सम्मुख 29वीं धारा विचारार्थ प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर के० टी० शाह ने एक सशोधन प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि 29वीं धारा के स्थान पर निम्न धारा को सविधान में स्थान दिया जाये—

'राज्य का अपने नागरिकों के प्रति यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अध्याय में निहित प्राविधानों की कार्यान्विति को अपना कर्त्तव्य माने। इन अधिकारों का कार्यान्वयन उस अधिकारी के द्वारा होगा और उस प्रकार होगा जो कानून के अनुसार उस समय इस काम को संचालित करने का अधिकारी होगा। राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन सिद्धान्तों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाये।'।

उन्होंने कहा कि 29वीं धारा जिस रूप में प्रस्तावित की गई है उसके कारण इस अध्याय की समस्त धाराएँ अप्रभावशाली हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस अध्याय के प्राविधानों की तुलना अग्रिम तारीख के उस चैक के साथ की जा सकती है जिसका भुगतान केवल उस समय हो जबकि बैंक ऐना करने में समर्थ हो। प्रोफेसर शाह का मत था कि 'प्रत्येक व्यक्ति को इन उत्तरदायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य को विवश करने का अधिकार होना चाहिए।'। परन्तु सदन को उक्त सशोधन मान्य नहीं था और उसने 29वीं धारा को उन्ही रूप में पारित कर दिया जिनमें उसे प्रस्तावित किया गया था।

चौथे अध्याय की अन्य धाराओं के प्रस्तुतीकरण के समय समाजवादी, गांधीवादी, नम्प्रदाय-

वाना और उत्तरवाणी नगमन सभी प्रकार के दृष्टिकाणा को व्यक्त किया गया। उदाहरण के लिए 30वां धारा पर जब सविधान सभा विचार विमर्श कर रही थी तो उस समय दामोदर स्वरूप सठ न एक सभाधन प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को निर्मित करने की बात कहा गया थी। सठ जी का कहना था कि धारा जिस रूप में प्रस्तावित की गई है वह अत्यंत अस्पष्ट है। परन्तु वह अनुमतियां न धारा की इस अस्पष्टता की प्रशंसा की और कहा उनकी गहराई रचना अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है। यदि कम्युनिस्ट पार्टी भी सत्तारूढ़ हो जाय तो वह 30वां और 31वां धारा के अंतर्गत अपने कार्यक्रम का लागू कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि इन धाराओं के अंतर्गत किसी भी देश पर अपने कार्यक्रम को लागू करने में प्रतिबंध नहीं होगा। समाप्रसार 31वां धारा पर विचार करते समय प्राफेसर के टी. गाहन ने यह भाग की कि प्रत्यक्ष नागरिक को एक पर्याप्त जीवन-स्तर का प्राप्ति करने का अधिकार होना चाहिए। देश के प्राकृतिक प्रसाधना पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए तथा देश में एकाधिकारी पंजी के विनाश का रोपने के प्रयत्न किए जान चाहिए।

चौथासवा धारा पर विचार करते समय महावीर यागी ने यह भाग की था कि राज्य का स्वस्थी वस्तुओं का प्राप्ताह देना चाहिए तथा कुत्तर उद्योग धंधा को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उस मुझाव को इजाजत कमिटी के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तथा उस चौतीसवीं धारा के एक भाग के रूप में मान्यता दे दी गई।

पतीमवी धारा में समूच देश के लिए एक में सिविल कोड की स्थापना की बात कही गई। परन्तु सविधान के इस प्राविधान की भी मदन के कुदृष्ट मुस्लिम सदन्या ने इस आधार पर आनाचना की कि उससे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर चोट पहुंचती है। मुस्लिम सदन्या की आलोचनाओं का उत्तर देते हुए के एम. मुंशी ने कहा सविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को पहन से ही मान्यता दे रखी है। अतः धर्म के आधार पर किसी के ऊपर अत्याचार करने का प्रयत्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि जब आप किसी समाज का सुदृढ़ बनाता चान्त हैं तो आपका उस बात को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें समूच समाज का नाम पहुँचें उसमें किसी एक भाग को नहीं। प्रश्न यह है कि क्या हम अपने निजी कानून को इस प्रकार गुप्त और एक बनाना चाहते हैं जिसमें समूच देश में कानून के एकता स्थापित हो सके तथा उस धर्मनिरपेक्ष बनाया जा सके। हम धर्म को निजी कानून से जिस सामाजिक सम्बंध बनाया जा सकता है प्रत्येक जिन्हें विभिन्न पक्षों के उत्तराधिकार के अधिकारों के नाम से भी पुकारा जा सकता है अलग रखना चाहते हैं। मरी समझ में नहीं आता कि इन बातों का धर्म से क्या सम्बंध है।

सदन में वायपानिका और यायपानिका का एक-दूसरे से अलग रखने का प्रस्ताव भी विवाद का विषय रहा। डा. जम्बदकर ने यह प्रस्तावित किया था कि सविधान की कार्यविधि के तीन वर्ष के भीतर वायपानिका और यायपानिका के बीच पृथक्करण कर दिया जायगा। सदन्या को तीन वर्ष की यह समय-सीमा पसंद नहीं थी। इस सम्बंध में टी. टी. कृष्णामाचारी ने यह मत व्यक्त किया कि पृथक्करण के विचार की अभिवृत्ति मात्र ही पर्याप्त है। विन्वनाथ नास का कहना था कि राज्य पृथक्करण के व्यवस्था करने में असमर्थ है और तीन वर्ष की अवधि में वह इतना समझ हो सकेगा यह बात महामन्द है। तबहार तब नहरे का मत था कि तीन वर्ष की अवधि में पृथक्करण की व्यवस्था करने से सविधान में कटारता आ जायगा। वस्तुतः इस काम को हम विधानमण्डल के सुपुर्ण कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून भा सरकार इस निर्णय की वृत्ति तब तक उपेक्षा नहीं कर सकेंगी।

चौथे अध्याय के प्राविधानों के प्राप्ति में सविधानकारों ने जो परिवर्तन किए उनमें दो विशेष रूप से उत्तरेखनीय हैं। प्राप्ति में बना गया था कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है कि उस प्राथमिक शिक्षा मुक्त प्राप्त हो। सविधानकारों ने इस व्यवस्था का वृत्ति दिया और उनमें स्थान पर यह लिखा कि राज्य इस शिक्षा में प्रयत्न करेगा। दूसरे अन्तर्गच्छीय नागरिक

एव मुश्किल की अभिवृद्धि से सम्बद्ध प्राविधानों में एक नवीन उपधारा जोड़ी गई जिसमें इस बात पर वन दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण करने के लिए 'पंच-फैसले' का महान किया जाये। वस्तुतः इसमें नवीन गणराज्य की शान्तिपूर्ण विदेश नीति की अभिव्यक्ति होती थी।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि नीति निर्देशक मिट्टान्तो को सविधान में स्थान देकर सविधानकारों ने जनता के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की और इस प्रकार उन्होंने समाजवादी आदर्शों में अपनी आस्था व्यक्त की। सविधान के प्राप्ति में गाँधीवादी आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। सविधान के निर्माताओं ने ग्राम पंचायती, कुटीर उद्योग-धन्धे, नशाबन्दी, तथा कृषि एवं पशु-पालन को प्रोत्साहन की व्यवस्था करके इस कमी को पूरा किया। सभा के समाजवादी सदस्य चाहते थे कि इन प्राविधानों को वाद-योग्य बनाया जाय अथवा इन आदर्शों को कार्यान्वित करने में राज्य की भूमिका को अधिक स्वीकारात्मक बनाया जाय। परन्तु इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया।

4 सघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं मन्त्रि-परिषद्

सविधान सभा के समक्ष एक बड़ी समस्या यह थी कि देश में जिस कार्यपालिका की स्थापना की जाय उसका स्वरूप और प्रकार क्या हो। कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्हें अमरीकी प्रकार की कार्यपालिका पसन्द थी। इन सदस्यों का कहना था कि भारत को एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता है और यह केवल अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका के अन्तर्गत ही सम्भव है। दूसरे, स्वतन्त्र भारत को एक नवीन प्रकार की कार्यपालिका में अपनी जीवन-यात्रा आरम्भ करनी चाहिये और उसे दामता की समूची परम्पराओं से अपने सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने चाहिये। किन्तु सविधान सभा के अधिकांश सदस्य समघीय कार्यपालिका के पक्ष में थे। इस निर्णय तक पहुँचने में जिस कारण ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसका सम्बन्ध उस अनुभव से था जिसे देश ने ब्रिटिश काल के साविधानिक विकास के दौरान प्राप्त किया था। इस सम्बन्ध में नेहरू जी का यह कथन उल्लेखनीय है—'हम उसकी प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते।' किसी को स्थायी सरकार की वाञ्छनीयता में सन्देह नहीं था। इस स्वायत्त के लिये वे कार्यपालिका एवं विधान मण्डल के बीच अच्छे सम्बन्धों को आवश्यक समझते थे। डा० अम्बेदकर का कहना था कि हमें एक निश्चित अवधि के बाद सरकार के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करने की पद्धति की तुलना में वह पद्धति अधिक पसन्द है जिसमें 'उत्तरदायित्व का दैनिक मूल्यांकन' होता है। इसके अलावा यह भी अनुभव किया गया कि यदि केन्द्र में अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका की स्थापना की गई तो उसके फलस्वरूप यह भी आवश्यक होगा कि राज्यों में भी उसी प्रकार की कार्यपालिकाएँ स्थापित की जायें। उनके परिणामस्वरूप देशी राज्यों में राजतान्त्रिक भावनाओं में अभिवृद्धि हो सकती है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह निश्चय हुआ कि सघीय कार्यपालिका के दो अंग होंगे, प्रथम, राष्ट्रपति जो ब्रिटिश राजा की भाँति राज्य का साविधानिक अध्यक्ष होगा, और दूसरे, मन्त्रि-परिषद् जो देश के शासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देगी तथा जो अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप में समद के प्रति उत्तरदायी होगी।

राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार हो, यह विषय सविधान सभा का अत्यधिक विवादग्रस्त विषय था। इस विषय पर सविधान के निर्माताओं में दो दृष्टिकोण पाये जाते थे। कुछ सदस्यों का मत था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यापक मताधिकार के आधार पर होना चाहिये। जबकि कुछ अन्य सदस्य उसका निर्वाचन समद के दोनों सदनों द्वारा निमित्त निर्वाचक-मण्डल के द्वारा चाहते थे। अन्त में इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक समझौता हो गया जिसके अनुसार निर्वाचन मण्डल में केन्द्रीय समद के दोनों सदनों के अतिरिक्त राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों को भी शामिल कर दिया गया।

जिन सदस्यों का यह कहना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना

चाहिये उनका तब या कि राज्य के अध्यक्ष को जनता की सामूहिक श्रमता एवं प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिये। उसी स्थिति में वह ब्रिटिश राजा की भाँति राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन सकेगा। विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति कबन एक जन का प्रतिनिधि होगा और वह बहुमत वाले दल के हाथ में कठपुतली होगा। यही नही भारतवर्षा नताशा की पूजा करने वाले हात में जन उद्देश्य सत्तुष्ट करने के लिये वह आवश्यक है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन बयस्क मताधिकार के आधार पर हो। परन्तु राष्ट्रपति के निर्वाचन की इस पद्धति को संविधान सभा के प्रारम्भ में अस्वीकार कर दिया। बहुमत न इस सम्बन्ध में तब तक प्रस्तुत किये प्रथम भारत में निर्वाचका का आकार इतना बड़ा है कि यह व्यावहारिक नहीं है। दूसरे इतने बड़े चुनाव को सम्पन्न कराने के लिये बहुत अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी। तीसरे इस प्रकार का निर्वाचन संविधान में निहित राष्ट्रपति की स्थिति में मन नग्न खाना। नेहरू जी ने कहा कि हम सरकार के मंत्रिपरिषद् के स्वरूप पर बल देना चाहते हैं सत्ता यथायथ मन्त्रिमण्डल और विधानमण्डल में निवास करती है राष्ट्रपति में नहीं। यह बात कुछ अस्पष्टी सा होगी कि राष्ट्रपति को यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाय और फिर उस को वास्तविक शक्ति न दी जाय।

सानुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोगिता में भी सन्देह व्यक्त किया गया। यह कहा गया कि सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रयोग कबन उस समय होता है जब एक से अधिक मन्त्रियों के लिये निर्वाचन होता है तब एक पद के निर्वाचन में उसका काम में तब से बचने से कठिनाइयाँ और उन्नत पदा होगी। उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी निर्वाचित होकर जा सकता है जो वास्तव में केवल अप्रभुत्व का प्रतिनिधि हो। परन्तु प्रारूप तयार करने वाली समिति ने इस दृष्टिकोण का स्वीकार नहीं किया। डा. अम्बेडकर का कहना था कि चकि संविधान में पृथक् निर्वाचन पद्धति को स्थान नहीं दिया गया है इसलिये सभी मत मतान्तरों को प्रतिनिधित्व देने के लिये कबन एक ही प्रभावशाली तरीका है और वह है सानुपातिक प्रतिनिधित्व।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ—राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों संविधान सभा में एक उग्र विवाद का आधार बनी। एवं ही कामधे ने कहा कि मसार के अन्तर्गत संविधानों में प्रविधानों का समानान्तर मिलना कठिन है इनसे मिलता जुलता प्रवस्था जमनी के वायमर संविधान में की गई थी और उन्हा का नाभ उठाकर हटाने में जमनी में वाक्ताव्र की हत्या कर दी। प्रविधानों के विरुद्ध मर्यादों का आपत्तियाँ थी—प्रथम व अतन्त्राधिक हैं और दूसरे व संघवाद के मिद्वान्त के प्रतिकूल हैं। परन्तु ए के अन्तर में इन व्यवस्थाओं का इस आधार पर समर्थन किया कि मध्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह जन में संविधान को वायमर रखे। उन्हां ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्थाएँ अमरीकी और आस्ट्रेलियन संविधानों में भी की गई हैं तथा यह मोचना गलत है कि हम ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को न दें। वस्तुतः ये शक्तियाँ सत्ता के प्रति उत्तरदायी कर्तव्य मन्त्रिमण्डल को दी जा रही हैं। इस अवसर पर डा. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया कि इन प्रवस्थाओं के उपयोग की सम्भावनाओं में इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु दुष्प्रयोग की सम्भावनाएँ तो संविधान के अन्तर्गत प्रविधानों के द्वार में भी लागू होती हैं। उन्हां ने आगे व्यक्त की कि इन व्यवस्थाओं को कभी भी वायमर रूप में परिणित नहीं किया जायगा।

संविधान सभा ने ससनीय वायपानिका के मिद्वान्त को पन्ना से ही मायना प्रदान कर दी थी। मन्त्रिमण्डल में मन्त्रियों की योग्यता-सम्बन्धी प्रविधान भी पर्याप्त विवाद का आधार बन। कुछ मन्त्रियों का मत था कि अपना नियुक्ति के समय मन्त्री को मन्त्र का सम्बन्ध जानना चाहिए कुछ दूसरे मन्त्रियों का कहना था कि उस उम्र के मन्त्र का सम्बन्ध जानना चाहिए जिसे जो सभा में बहुमत प्राप्त है। परन्तु इन गुमावा को घस्वाकार कर दिया गया। महावीर त्यागी का मत था कि मन्त्री के लिये कुछ शक्ति यापनाएँ निर्धारित कर देनी चाहियें परन्तु मन्त्रियों को

यह सुभाव भी मान्य नहीं था। प्रशासन में शुद्धता कायम रखने के लिए प्रोफेसर के० टी० शाह और एच० बी० कामय चाहते थे कि अपनी नियुक्ति के समय मन्त्री अपनी आर्थिक स्थिति का व्यौरा प्रस्तुत करें। परन्तु डा० अम्बेदकर को 'इस सुभाव की उपादेयता में सन्देह था।'

5 सघीय ससद

सविधान सभा ने देश के लिए ससदीय कार्यपालिका की व्यवस्था की थी, अतः एक प्रकार से देश के प्रशासन में ससद का स्थान निश्चित हो चुका था। परन्तु ससद के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न और ये जिनका समाधान आवश्यक था। पहला प्रश्न था कि ससद एकसदनात्मक हो अथवा द्विसदनात्मक। साविधानिक परामर्शदाता ने अपने स्मरण-पत्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की सिफारिश की थी। परन्तु सविधान सभा में कुछ सदस्यों ने द्विसदनात्मक विधानमण्डल के सिद्धान्त की आलोचना की और कहा कि 'द्वितीय सदन प्रगति के पहिये में अवरोधक' है। फलतः उन्होंने एकसदनात्मक विधानमण्डल के लिए सशोधन प्रस्तुत किये। एन० गोपालस्वामी आयरगर ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया तथा द्विसदनात्मक विधान मण्डल के औचित्य का प्रतिपादन किया। उनका कहना था कि 'ससार में जहाँ कभी भी कुछ महत्त्व के सघीय राज्य पाये जाते हैं, वहाँ सभी जगह द्वितीय सदन की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। हम द्वितीय सदन से यह अपेक्षा करते हैं कि वह महत्त्वपूर्ण विषयों पर सम्मानपूर्ण तरीके से विवाद करे तथा ऐसे कानूनों के पारित होने में उस समय तक देरी लगाये जिन्हें परिस्थितियों से उत्पन्न भावावेशों में सोचा गया हो तथा उन्हें उस समय तक पारित न होने दें जब तक कि भावावेशों में शीतलता न आ जाये तथा उन पर शान्त वातावरण में पुनर्विचार न हो सके, और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सविधान में इस बात की व्यवस्था की जाये कि जब भी किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर, विशेषतः वित्तीय विषयों पर लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न हो, तो लोकसभा का दृष्टिकोण हावी हो।'।

सविधान सभा ने बहुमत से इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। एन० गोपालस्वामी आयरगर के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सविधानकारों की दृष्टि में द्वितीय सदन की केवल एक सीमित भूमिका हो सकती थी, वह सम्मानित तरीके से महत्त्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद कर सकता था ताकि कोई विधेयक जल्दी में कानून न बन सके तथा उसका प्रयोजन ऐसे योग्य व्यक्तियों को विधायी कार्य में भाग दिलाना था जो किसी अन्य प्रकार से सम्भव नहीं था।

जहाँ तक दोनों सदनों की रचना का प्रश्न है, सविधानकारों ने 1935 के सविधान में निहित प्राविधानों से बहुत सहायता ली थी। परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था की वह दो अर्थों में 1935 की व्यवस्था से भिन्न थी। 1935 में सीटों का वटवारा इस प्रकार किया गया था जिसमें देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की अपेक्षा अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। सविधानकारों ने इस अन्यायपूर्ण स्थिति का अन्त कर दिया। दूसरे, 1935 के सविधान में सघीय विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन अत्यधिक समिति मताधिकार के आधार पर होता था। सविधान सभा ने इस असंगति को भी दूर कर दिया।

आरम्भ से ही यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि राज्यसभा में कुछ व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाय। परन्तु सविधान में इस प्रश्न पर मतैक्य का अभाव था कि इस प्रकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो तथा उनके चुनाव की पद्धति क्या हो। सघ सविधान समिति ने सिफारिश की थी कि इन सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक दस हो जिन्हें राष्ट्रपति विश्व-विद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के परामर्श में मनोनीत करे। गोपालस्वामी आयरगर ने प्रस्तावित किया कि यह संख्या 25 होनी चाहिए तथा उनका निर्वाचन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए।

प्राष्ट्र समिति ने 15 सदस्यों का प्रस्ताव दिया जिसकी सदन में काफी आलोचना

ई। एन मन्स्य न कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने की व्यवस्था हमारे विधानमण्डल की रचना की एकरूपता के प्रतिबन्ध है। यही नही हम प्रकार की व्यवस्था में यह खतरा निहित है कि राष्ट्रपति अनुचित ढंग से की जाने वाली आवाजना का गिकार बन। नमोनीरायण साहू ने कहा कि यदि हम राष्ट्रपति को 12 मन्स्य को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान करेंगे तो उसके ऊपर पक्षपात करने के बट आरोप लगाये जायेंगे और यह बात अवांछनीय होगी। परन्तु इस विरोध के बावजूद संविधान सभा ने यह व्यवस्था का कि राज्यसभा में गारह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।

जहाँ तक राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य का प्रश्न है संविधानकारों के सम्मुख एक बड़ी समस्या यह थी कि क्या उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका की भांति न्याय को दूसरे सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए। वस्तुतः इस प्रकार की समानता का अंतरा के बावजूद कृत्रिम समझी जाना चाहिए। अतः संविधानकार जनसंख्या के आधार पर न्यायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहते थे यद्यपि प्रत्येक स्थिति में इस नियम का पालन सम्भव नहीं था। मध्य संविधान समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए एक समझौता प्रस्तावित किया जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को प्रति दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा यह क्रम 50 लाख की जनसंख्या तक चलेगा और उसके बाद प्रत्येक 20 लाख की जनसंख्या पर उन्हें एक प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार होगा इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि किसी भी राज्य का 20 प्रतिनिधि से अधिक निर्वाचित करने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार जहाँ जनसंख्या को प्रतिनिधित्व का आधार माना गया वहाँ इस बात की सावधानी बरती गई कि बड़ी जनसंख्या वाले राज्य छोटे छोटे राज्यों पर हावी न हों पायें।

राज्यसभा की रचना के समय में सांविधानिक परामर्शदाता न जेफरसन ने यह सुझाव दिया था कि उसमें प्रांतों तथा देशों के प्रतिनिधियों को हम प्रकार स्थान दिया जाय जिसमें प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर कम से कम एक प्रतिनिधि निर्वाचित हो तथा प्रत्येक साठे सात लाख की जनसंख्या पर अधिक से अधिक एक प्रतिनिधि चुना जाय। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व को सम्भव बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि समूचे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाय और प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के उपरान्त इन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर पुनर्रचना की जाय।

संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति ने इस सुझाव का कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया। पहले संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 500 होगी इससे अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की गई कि साठे सात लाख की जनसंख्या पर कम से कम एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा तथा पचास लाख की जनसंख्या पर अधिक से अधिक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। संविधान सभा ने अधिकतम संख्या 520 निर्धारित की तथा संविधान के प्रारूप की अन्य व्यवस्थाएँ स्वीकार कर लीं।

प्रारूप समिति ने लोकसभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार की सिफारिश की। इस प्राविधान का सदन में सामान्यतः स्वागत किया गया। प्रोफेसर गिन्जन नाम संसद में उस संविधान का सबसे बड़ा गुण बताया। परन्तु इस प्राविधान के अंतर्गत में डा. राजेंद्र प्रसाद और हृदयनाथ कजरू जैसे व्यक्तियों ने सख्त विरोध किया। उन्हें वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त में विरोध नहीं था अपितु उन्हें उम्र तरीके में विरोध था जिसमें हम पद्धति का स्थान दिया जा रहा था। कजरू का कहना था कि हम इस विचार में धीरे धीरे काम बढ़ाना चाहिए। डाक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह व्यवस्था बचने एवं परामर्श है जिसका प्रयोग यदि उचित ढंग में नहीं किया गया तो उम्र के परिणाम भयंकर होंगे।

संविधान सभा में अल्पमंड्यकों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर भी काफी बहस विवाद हुआ। प्रारूप समिति ने अल्पमंड्यकों के लिए सांगों का गुरांति रखने की सिफारिश की थी। परन्तु

इस व्यवस्था के विरुद्ध दो प्रकार की आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी। सरदार हुकुम सिंह ने कहा कि 'यदि पृथक् निर्वाचन प्रणाली ने सम्प्रदायवाद को बल पहुँचाया है, तो सीटों को सुरक्षित रखने की पद्धति से उसे कुछ कम बल नहीं मिलेगा।' करीमुद्दीन की आपत्ति इससे बिल्कुल भिन्न थी। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचन साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं तो सीटों को सुरक्षित रखने से अल्पसंख्यकों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। अतः कुछ सदस्यों ने सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया। परन्तु प्रारूप समिति को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था। संविधान सभा ने इस मामले में प्रारूप समिति के दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया।

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के ऊपर भी बल दिया। परन्तु संविधान सभा ने डा० राजेन्द्र प्रसाद के इस दृष्टिकोण को मानने से इनकार कर दिया।

6 सघीय न्यायापालिका

1935 के संविधान में प्रस्तावित भारतीय सघ के लिए समन्वित (Integrated) न्यायापालिका की व्यवस्था की गई थी, उसमें सघ में शामिल होने वाली समस्त इकाइयों के उच्च न्यायालयों के ऊपर एक सघीय न्यायालय का प्राविधान था। परन्तु उस संविधान में भी सघीय न्यायालय अपील का अन्तिम न्यायालय नहीं था। परन्तु स्वतन्त्र भारत के संविधान में उसे सिविल तथा फौजदारी मुकदमों की अपीलों का अन्तिम न्यायालय बनाकर न्यायपालिका के समन्वयन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया।

संविधानकारों का मत था कि न्यायपालिका को सरकार की विधायी नीति पर निर्णय देने का अधिकार न दिया जाये। परन्तु साथ ही न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान की जाये ताकि वह कार्यपालिका के भय अथवा पक्षपात के बिना काम कर सके। एक सदस्य ने कहा न्यायपालिका की भूमिका 'लोकतन्त्र की रखवाली करने वाले' की होनी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक माना गया कि उसे राजनीतिक प्रभावों से स्वतन्त्र होना चाहिए। न्यायाधीशों को भ्रष्ट करने वाले प्रभावों से मुक्त रखने के लिए संविधानकारों को अत्यधिक चिन्ता थी। इसी चिन्ता से प्रेरित होकर पी० के० सेन ने यह सुझाव पेश किया कि 'वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के पद पर है, अथवा जो उस पद पर रह चुका है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त होने का अधिकारी नहीं होगा', यद्यपि मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से उसे अल्पकाल के लिए कुछ और दायित्व सौंपे जा सकते थे अथवा राष्ट्रीय हित में सतत्कालीन अवस्था में उसे अन्यत्र काम पर लाया जा सकता था। प्रो० के० टी० शाह का सुझाव था कि हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में किसी कार्यपालिका पद पर नियुक्त न किया जाये।

डा० अम्बेदेकर ने अपने उत्तर में सेवारत न्यायाधीश और सेवा-निवृत्त न्यायाधीश के बीच विभेद किया। उन्होंने इस मत से सहमति व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को गैर-न्यायिक उत्तरदायित्व उस स्थिति में नहीं सौंपने चाहिये, यदि उसे सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा काम करने जाना है। परन्तु उनका कहना था कि सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उस प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार की न्यायिक क्षमता से सम्पन्न व्यक्ति की नियुक्ति बहुत आवश्यक होती है। उनके परामर्श पर संविधान सभा ने समस्त सशोधनों को अस्वीकार कर दिया।

प्रश्न

- 1 भारतीय संविधान सभा की संरचना की महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालिए।
 - 2 संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर हुई बहस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए।
- © सामान्य प्रणाली/2

सविधान के स्रोत (SOURCES OF CONSTITUTION)

माविधानिक सिद्धांत के सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान् जयसामी ने एक स्थान पर लिखा है मविधान की तुलना उम देगी पौधे के साथ की जा सकती है जो विन्गी भूमि पर नहीं उगता । परन्तु डायमी का यह मत भारतीय मविधान के ऊपर भी लागू होना है ऐसा दावा नहीं किया जा सकता । मच बात यह है कि उसके निमाण में नया जोर विन्गी अनेक प्रकार के प्रभावा का योगदान रहा है । नवीन भारत का जन्म म विरासत के रूप में सघातमक शासन-व्यवस्था प्राप्त था उसकी उपायेयता औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध सशप में प्रमाणित हो चुकी थी । स्वतंत्र भारत का यथाय म एक म माविधानिक ढांच की आवश्यकता थी जो जनकता के मन्त्र में भा विधनकारी तत्वा का नियंत्रित करने में उसकी सहायता कर सके । मविधानकार साम्प्रदायिक समस्या में भी भाति जवगत थे । राष्ट्रीय भुक्ति मघप के काल में प्राप्त अनुभव से वे नम निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि नम समस्या का जटिल रूप प्रदान करने में पृथक निर्वाचन प्रणाली का एक विशिष्ट भूमिका रनी था । स्पष्टतः ऐसा स्थिति में नवान मविधान में उस पुनः स्थान दिया जायगा इसकी उपाय नया की जा सकती था । मविधान की रचना में विन्गी सविधाना का प्रभाव भी पड़ा था । वस्तुतः ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि मविधानकारों का उद्देश्य किसी मौनिक ममविद की रचना करना न था बकि एक जात्य नामन व्यवस्था का स्थापित करना था । जत उन् जिम किसी भी देश की नामन प्रणाली में ज-उ नव दिखार प उनका उद्धान मविधान में स्थान देने का प्रयास किया । यही मविधान के न खाना की विवचना आवश्यक है ।

1. 1935 के अधिनियम का प्रभाव

1935 का मविधान भारतीय सविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है । वस्तुतः सविधान का आकार उसकी विषय-सूची भाषा जाति मभा पर नम अधिनियम का प्रभाव अवलोकित किया जा सकता है । अधिनियम की उपभग 200 धाराएँ मी हैं जिन्हें जरण या वाक्य रचना में माधारण परिवर्तन करके मविधान में स्थान दिया गया है । नमारा मविधान रूपरखा और भाषा में 1935 के अधिनियम का कितना जाभागी है नमका स्पष्टीकरण निम्न उदाहरणों में दिया जा सकता है—

(1) भारताय मविधान की 256वाँ धारा में यह वन गया है कि प्रत्येक राज्य की वायकारा गति इस प्रकार प्रयुक्त होगी जिससे मविधान द्वारा बनाय गय कानूना का निश्चित रूप में पानन हो और मघ की वायकारी गति का नम मन्वध में राज्य का उचित निर्णय देने का अधिकार हो । मविधान की म भाषा तथा 1935 के अधिनियम की 126वीं धारा में प्रयुक्त भाषा एक-दूसरे से वन मिलनी जुनती है ।

(2) सविधान की 36वाँ धारा में राष्ट्रपति का मकतकारात गतिया के उल्लेख है 1935 के अधिनियम में नम जाय का मग 102 में व्यक्त किया गया था न नाना धाराभा में महत माम्य है ।

(3) मविधान की 251वाँ धारा में उस स्थिति का उल्लेख है जिसमें मघ एक राज्य सरकार के कानून परस्पर विरोधी हो नम द्वारा की 1935 के अधिनियम की 107वाँ धारा में वन मत है ।

(4) सविधान की 356वाँ धारा में राज्य में माविधानिक मन्त्र के विपन हो पानन गलत

सकट का उल्लेख किया गया है। यह धारा अधिनियम की 92वीं धारा से मिलती-जुलती है।

(5) सविधान में सन्निहित सिद्धान्त भी अधिनियम के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। निम्न उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

(अ) अधिनियम में भारत के लिए जिस प्रकार की सघीय व्यवस्था की कल्पना की गई थी, वह ससार के अन्य सघों से बहुत अर्थों में भिन्न थी। भारतीय सविधान ने भी जिस सघ को देश में स्थापित किया है, वह विश्व के अन्य सघ-राज्यों से मेल नहीं खाता। यदि उसकी अनुरूपता किसी से है तो उस सघ से है जिसे 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित किया गया था।

(ब) अधिनियम में शक्ति-विभाजन का काम तीन सूचियों—सघ सूची, समवर्ती सूची और प्रान्तीय सूची—के द्वारा सम्पन्न किया गया था। वर्तमान सविधान में भी इसी विभाजन को स्वीकार किया गया है।

(स) अधिनियम में गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया था और वह आपात् काल में सघ शासन को एकात्मक शासन का रूप दे सकता था। आधुनिक सविधान में राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(द) अधिनियम की भाँति आधुनिक सविधान में भी सरक्षणों (safeguards) की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषा-सम्बन्धी अधिकारों के सरक्षण की व्यवस्था सविधान में है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को निम्न स्तर के न्यायानुयों को अपने नियन्त्रण में रखने का अधिकार है और केन्द्रीय सरकार का किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में राज्य के शासन को अपने नियन्त्रण में लेने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1935 के अधिनियम को भारतीय सविधान का एक प्रमुख स्रोत घोषित किया जा सकता है। वस्तुतः सविधान-निर्माता देश में उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसकी कार्यान्विति से देशवासी परिचित थे। ऐसी स्थिति में यह होना अत्यन्त स्वाभाविक था। इस सम्बन्ध में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा० अम्बेदेकर का यह कथन उल्लेखनीय है—‘मैं इस बात में किसी प्रकार की लज्जा अनुभव नहीं करता कि हमने नवीन सविधान का निर्माण करते समय अधिनियम की बहुत सी बातों को अपनाया है। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में सकोच नहीं होना चाहिए, दूसरे साविधानिक सिद्धान्त किसी व्यक्ति अथवा देश-विशेष का एकमात्र अधिकार नहीं होते। मुझे तो खेद इस बात का है कि 1935 के अधिनियम की जिन धाराओं को अपनाया गया है उनमें से अधिक का सम्बन्ध शासन की वारीकियों से है।’

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत का आधुनिक सविधान 1935 के अधिनियम की केवल नकल मात्र है। वस्तुतः इन दोनों में बहुत अधिक भिन्नता भी है।

2 विश्व के विभिन्न सविधानों का प्रभाव

भारतीय सविधान की रचना को समार के विभिन्न देशों की शासन-प्रणालियों का एक निश्चित योगदान रहा है। इस योगदान को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है—

सविधान अपने समदीय स्वरूप के लिए ब्रिटिश सविधान का ऋणी है। यथार्थ में औपनिवेशिक शासन के काल में ही भारत को समदीय प्रणाली से जानकारी प्राप्त हो गई थी, अतः यह स्वाभाविक ही था कि जब भारत ने अपने सविधान की रचना की तो वह समदीय शासन पद्धति को उसमें स्थान देना। समदीय शासन प्रणाली के अनुरूप सविधान में राष्ट्रपति की स्थिति नामान्यत ब्रिटिश राजा जैसी रही तथा प्रथम सदन को द्वितीय सदन की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। ब्रिटिश सविधान में सविधानकारों ने ‘कानून के शासन’ का विचार ग्रहण किया था, यद्यपि ब्रिटिश सविधान की पृष्ठभूमि में उसका महत्त्व वह नहीं हो सकता था जो उसे अनिश्चित सविधान के अन्तर्गत प्राप्त है।

संविधान पर अमराकी प्रभाव का मूल अधिकारों के प्राविधानों में सर्वोच्च प्राधान्य की व्यवस्था में उप राष्ट्रपति के पद तथा उस मीप गये कार्यों की सूची में संविधान का समाधान प्रक्रिया जानि मन्त्रा जा सकता है। यद्यपि अमराका का भाति भारत में टुंगी नागरिकता का व्यवस्था नग है फिर भी वह अमराकी संविधान का तरह प्राधान्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत का स्वीकार करता है तथा प्राधान्य का पदस्थित करने के लिए भी वह उस प्रक्रिया की व्यवस्था करता है जो संयुक्त राज्य अमराका के संविधान में उल्लिखित है।

भारतीय संविधान के कुछ प्राविधानों आधारभूत के संविधान का व्यवस्थाओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए संविधान में मन्त्रिंहित नानि निर्देश सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था तथा राज्य सभा में कला साहित्य विज्ञान जानि स सम्बद्ध विभिन्न गतिविधियों के मनानयन का प्रणाली प्राधान्य के संविधान में मन्त्रा जुगती है।

भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप में कला के संघात के साथ वन अधिक साम्य है। कला में मध के लिए यूनिन गत प्रयुक्त है भारत में भी हम मध का यूनिन के नाम में ही पुकारते हैं। कला के स में अवगति गतिविधियों का मीपी गयी है गतिविधियों के विभाजन के सम्बन्ध में भारत में भी उस नियम का अनुसरण किया है।

भारतीय संविधान की कुछ व्यवस्थाओं आस्ट्रेलियन संविधान में मिलती हैं। संविधान का प्रस्तावना में निहित भावनाएं समवर्ती सूची तथा स सूचा में उल्लिखित विषयों पर मध और कला के बीच संघर्ष का निराकरण के लिए बनाये गये उपाय आस्ट्रेलिया के संविधान के अनुरूप है।

भारत के संविधान में राष्ट्रपति का सकल काल में संविधान का स्थगित करने की शक्ति प्रदान की गयी है यह व्यवस्था जर्मनी के मी रूप में वायमर संविधान में पायी जाती थी। संविधान की 21वां धारा में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छाँटकर गतवर्ती का प्रयोग किया गया है वस्तुतः यही शक्तवर्ती जापान के संविधान की 31वीं धारा में प्रयुक्त है।

उपयुक्त विवेचना में स्पष्ट है कि नवीन संविधान का रचना में विभिन्न दशा के संविधानों का भूमिका रहा है। इस आधार पर कुछ नागा न उस अनुमति का पिटारा बताया है। कुछ दूसरे लोग न उस उपार की धारा के नाम में प्रकार है। परन्तु इस प्रकार की गताचनाएं भारतीय संविधान के साथ प्राधान्य नहीं करता। यह सत्य है कि संविधान के स्थात विन्द के प्रमुख संविधान हैं। परन्तु संविधानकारा न अथ नशा स कवन उन वाता का ग्रहण किया है जिनका उपयोगिता इस दग में या ता पहन स हा प्रमाणित हा चुकी थी या विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति में उनकी उपयोगिता की कपना की जा सकता थी। मध धान यह है कि संविधानकारा न अथ होकर नवन नहा की था। संविधान के इस पहन के सम्बन्ध में एक उल्लेखनाय बात यह है कि विभिन्न संविधानों के सम्मिश्रण से भारत के संविधान में एक नयी मौलिकता आ गयी है जो स्वयं भारत की है।

संविधानकारा न इस नग के लिए संविधान का रचना का थी जिसमें न ता नाकतांत्रिक विकास हा उचित दग में था था और न जिसके अधिक विकास का ही समीचीन धापित किया सकता था। फलतः उक्त संविधान में प्रत्येक बात का निम्न का प्रयास किया। इस प्रकार संविधान का उत्तरागतापूर्वक विस्तृत होन लिया गया और उसमें अभिममया के विकास के लिए प्राधान्यभाव कम स कम गजाता छाडा गया है। फलस्वरूप भारत की प्राधान्यकीय समस्याओं और यों के राजनानिक अनुभवा का भी संविधान का एक स्थात बताया जा सकता है क्योंकि संविधान के वन मा व्यवस्थाओं का नग समस्याओं के समाधान के लिए संविधान में स्थान दिया गया है।

3 अभिममय

जगा कला जा चुका है कि भारतीय संविधान समार के समस्त संविधानों में मन्त्रा अधिक विस्तृत एवं स्पष्ट संविधान है फलतः उसमें अभिममया के विकास का सम्भावना वन कम है।

परन्तु इसके बावजूद भी अभिसमयों के लिए कुछ क्षेत्र सविधान में ही रह गया तथा कालान्तर में कुछ अभिसमय विकसित हो गये। वस्तुतः ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि कोई भी सविधान चाहे वह कितना ही विस्तृत क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ बात ऐसी रह जाती है जो स्पष्ट नहीं हो पाती। इस प्रकार की स्थिति अभिसमय के विकास के लिए एक समुचित पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है। भारत के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है।

नये सविधान के कार्यान्वित होने के उपरान्त हमारे देश में जो अभिसमय विकसित हुए हैं उन्हें सविधान का स्रोत बताया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप कुछ अभिसमय निम्नलिखित हैं—

(i) सर्वप्रथम अभिसमय मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में है। यद्यपि हमारे देश में ममदीय कार्यपालिका स्थापित है, तथापि सविधान का यह भाग मुख्यतः अलिखित अथवा अस्पष्ट है। सविधान में जहाँ कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गयी हैं, वही उसमें मन्त्रि-परिषद् की भी व्यवस्था है और इस मन्त्रि-परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री को बनाया गया है तथा उसे ससद के प्रति उत्तरदायी भी बनाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सविधान की व्यवस्थाओं में अस्पष्टता पायी जाती है। परन्तु इस अस्पष्टता के होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की कार्यपालिका ससदात्मक है, अध्यक्षतात्मक नहीं। सविधान की यह विशेषता एक बड़ी सीमा तक उस अभिसमय पर आधारित है जिसका आरम्भ नेहरू जी के प्रधानमन्त्रित्व के समय में हुआ था। चूँकि नेहरू जी के स्तर का नेता प्रधानमन्त्री था इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रधानमन्त्री का पद अधिक गौरवपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता। यह परम्परा कालान्तर में सविधान का एक अंग बन गयी।

(ii) राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति करते समय केन्द्रीय सरकार सामान्यतः सम्बद्ध राज्य की सरकार से परामर्श करती है, यद्यपि इस प्रकार की कोई व्यवस्था सविधान में नहीं है।

(iii) लोकसभा तथा राज्यों की विधानमण्डलों के अध्यक्ष निर्दलीय अथवा निष्पक्ष होने चाहिए, यह बात भी अभिसमय पर आधारित है।

(iv) राज्यों के मुख्यमन्त्रियों तथा प्रधानमन्त्री को विधानमण्डल में बहुमत वाले दल में से लिया जाता है। सविधान की यह विशेषता भी अभिसमय पर ही आधारित है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सविधान का अलिखित भाग जिसमें सविधान के अभिसमयों की रचना होनी है, उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि लिखित भाग। दोनों भागों का सह-अस्तित्व कभी-कभी गम्भीर संघर्ष को जन्म दे सकता है। चौथे आम चुनावों के पश्चात् राज्यों में इस संकट के स्पष्ट संकेत दृष्टिगोचर होने लगे थे। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसकी विवेचना अलग से होनी चाहिए।

सम्पूर्ण विवेचन से यह प्रमाणित है कि भारतीय सविधान के अनेक स्रोत हैं। यद्यपि यह एक विस्तृत आलेख है जिसमें प्रत्येक बात का समावेश करने का प्रयास किया गया है तथापि उसमें अभिसमयों का विकास हुआ है और उन्हें सविधान में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

प्रश्न

- 1 1935 के सविधान का नवीन सविधान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या आप इस मन में सहमत हैं कि स्वतंत्र भारत का सविधान 1935 के अधिनियम की नकल मात्र है?
- 2 इस कथन का परीक्षण कीजिए कि भारत का सविधान एक 'उधार की वेली' है। उदाहरणों में अपने उत्तरों को स्पष्ट कीजिए।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

(SALIENT FEATURES OF THE INDIAN CONSTITUTION)

भारत के संविधान न केवल सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणतन्त्र की स्थापना का है। अतः यह उचित ही है कि इस संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन का आरम्भ उसकी विनिष्पत्तियों के साथ करें।

1. लिखित एवं सर्वोच्च अधिक व्यापक संविधान

भारतीय गणतन्त्र का संविधान एक लिखित (written) संविधान है। आखिर जर्मनी के संविधान में वह विषय में सर्वोच्च अधिक विस्तृत एवं सर्वोच्च अधिक विस्तृत (detailed) संविधान है। इसमें 397 धाराएँ हैं जो 22 अध्यायों में विभक्त हैं तथा इनके अतिरिक्त इसमें 9 सूचियाँ हैं। भारतीय संविधान का आकार किना विशाल है इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से पाँच गुना और फ्रांस के चतुर्थ गणतन्त्र के संविधान से सात गुना अधिक बड़ा है। यहाँ तक कि वह ग्रीस के संविधान से भी (जो फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी पाँच गुना अधिक विस्तृत हैं) अधिक बड़ा है।

प्रश्न है कि भारतीय संविधान का इतना अधिक विस्तृत क्यों बनाया गया है? सम्भवतः इसका एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय संविधान महात्मक है तथा उस संयुक्त राज्य अमेरिका के महात्मक ढाँचे के आधार पर निर्मित न करके कनाडा के महात्मक ढाँचे के आधार पर निर्मित किया गया है। अमेरिकी संविधान में केवल राष्ट्रीय सरकार के संगठन का वर्णन किया गया है। यही बात स्विट्जरलैंड, जापानिया तथा सोवियत संघ के संविधानों के सम्बंध में कही जा सकती है। परन्तु कनाडा के संविधान की भाँति ही भारतीय संविधान में जहाँ राष्ट्रीय सरकार के संगठन का उल्लेख है वहाँ उसमें संघ में सम्मिलित स्वायत्तता के संगठन का भी वर्णन पाया जाता है। यहाँ इस सम्बंध में ध्यान में रखने योग्य बात यह भी है कि आरम्भ में भारतीय संघ की स्वायत्तता का चार प्रणियाँ में विभाजित किया गया था। अतः यह आवश्यक था कि इन चार प्रकार के संघों के संगठन का संविधान में अलग अलग उल्लेख किया जाता।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संघीय स्वरूप ने संविधान के विस्तृत हान में एक अन्य प्रभाव से भी अपना योगदान दिया है। संविधान में संघ और संघों के पारम्परिक सम्बंधों का भी वर्णन है। संविधान के ग्यारहवें अध्याय में केवल और संघों के बीच पाये जाने वाले विधायी सम्बंधों का उल्लेख है। इस अध्याय में 19 अनुच्छेद हैं तथा इसके अतिरिक्त संविधान की मानव सूची में भी इन सम्बंधों का वर्णन किया गया है। संघ और संघों के बीच पाये जाने वाले वित्तीय सम्बंधों का उल्लेख संविधान के बारहवें अध्याय में किया गया है और इसमें 99 धाराएँ हैं। इसके अतिरिक्त 263वाँ धारा में अंतर-संघीय निर्णयों का प्राविधान किया गया है तथा 262वाँ धारा में नदियों के जल तथा नदी घाटियों में मत्स्य निकास के समायोजन की व्यवस्था की गयी है।

संविधान के आकार के बड़े हान का एक दूसरा कारण यह है कि उसमें न केवल केवल एक संघों की संरचना के संगठन का वर्णन किया गया है। अपितु उसमें प्रशासकीय स्तरों की भी संरचना है। विषय के अन्य संविधानों में इस स्तरों का सामायोजन इन के माध्यम से कानून के द्वारा

निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार संविधान की 24 धाराओं में संघीय न्याय-पालिका के गठन का वर्णन किया गया है तथा 4 धाराओं में राज्यों की न्यायपालिका के गठन का उल्लेख है।

संविधान के विस्तृत होने का एक तीसरा कारण यह है कि उसमें जहाँ मूल अधिकारों का विशद वर्णन है, वहाँ उसमें उन अधिकारों के ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धों का भी व्यापक उल्लेख है। इसके अतिरिक्त उसके चौथे अध्याय में ऐसे निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है जिन्हें न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता परन्तु जिन्हें देश के शासन-तन्त्र की आधारभूत अवधारणा घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान का कलेवर इसलिए और अधिक बट गया है क्योंकि उसमें कुछ समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया है जो भारत की अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं तथा जिनके निराकरण की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार की समस्याओं में अल्पसंख्यकों की समस्या, पिछड़ी हुई तथा अनुसूचित जातियों की समस्या, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं की समस्याएँ प्रमुख हैं। इनका उल्लेख संविधान के सत्रहवें अध्याय (9 अनुच्छेदों) में तथा पाँचवीं और छठी सूची में हुआ है। संविधान में सन्निहित संकटकालीन प्राविधानों के कारण भी उसके आकार में वृद्धि हुई है।

कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधानकारों को इतने लम्बे संविधान को निर्मित करने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आइवर जेनिंस ने कहा है कि भारतीय संविधान की यह विशेषता मुख्यतः भूतकाल की देन है। ब्रिटिश सरकार ने 1919 और 1935 में भारत के लिए अत्यधिक विशद संविधानों की रचना की थी। इस सम्बन्ध में एन० श्रीनिवासन् का यह कथन उल्लेखनीय है कि 1935 के ही अधिनियम की ही भाँति भारत का नवीन संविधान 'केवल संविधान ही नहीं है अपितु एक विस्तृत कानूनी संहिता भी है जिसमें देश की समूची सांविधानिक एवं प्रशासकीय पद्धति से सम्बद्ध समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख है।' इसका एक दूसरा उत्तर भी हो सकता है। जिस समय संविधान की रचना हो रही थी, उस समय देश में राजनीतिक परिपक्वता इतनी अधिक नहीं थी कि किसी भी बात को अभिसमयों के विकसित होने के लिए छोड़ा जाता। अतः संविधानकार यह जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे कि संविधान से सम्बद्ध किसी भी पहलू को अपरिभाषित छोड़ा जाये।

भारतीय संविधान के इस लम्बे आकार ने दो दुष्परिणामों को जन्म दिया है। सर्वप्रथम इसके फलस्वरूप संविधान की दुःसहोध्यता में वृद्धि हुई है। यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि संविधान के सन्दर्भ में 'दुःसहोध्यता' शब्द का अर्थ सदैव सापेक्ष होता है और उसका सम्बन्ध केवल इस बात से होता है कि संविधान को सहोध्य करने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, उसका सम्बन्ध इस बात के साथ भी होता है कि संविधान के प्राविधान क्या हैं। यदि संविधान का आकार अत्यधिक विशाल है तो उस स्थिति में उसमें सहोध्यन की सम्भावना कम रहेगी। इसके अतिरिक्त संविधान की वृहत्ता ने उसे इतना अधिक जटिल बना दिया है कि वह जनसाधारण की समझ से परे हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान को माध्यमिक स्कुलों के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, किन्तु भारत में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यथार्थ में भारतीय संविधान के अध्ययन के उपरान्त इस निष्कर्ष से वचना कठिन है कि 'वह एक ऐसा प्रलेख है जिसे वकीलों ने वकीलों के लिए निर्मित किया है।' संविधान के कार्यान्वित होने के बाद जितने सांविधानिक मुकदमों सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, उनसे इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है।

2 विश्व की अनेक सांविधानिक प्रणालियों के आधार पर निर्मित संविधान

भारतीय संविधान के ऊपर नामान्यतः यह आरोप लगाया जाता है कि उसमें मौलिकता का निम्न अभाव है तथा उसकी रचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त असंगत तत्त्वों के द्वारा हुई है।

उस प्रकार के आलोचक सविधानों के सम्बन्ध में तयसी के उस मत का उद्धरण करते हैं कि सविधान उस देशी पौध के समान है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता तथा वह कहते हैं कि भारतीय सविधान में भारतीय परम्पराओं का ध्यान में नहीं रखा गया है तथा उसका निर्माण समार के विभिन्न सविधानों से उधार लिया गया तथा के द्वारा किया गया है। उदाहरण के तौर पर 1953 में सागर में स्थित पोनिटिकल माउन्स एसोसिएशन के हुए वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष पद से भाषण देने पर प्राथमिक बोधराज तर्मा ने सविधान की स्वर विधान समितियों तथा समन्वय तालिकाओं की यह कटकर आलोचना की कि यह देशी पौध के समान उधार लिया गया है तथा उद्देश्य से बात पर धन प्रकट किया था कि नये भारत के आसनन में प्रणामन एवं सरकार से सम्बद्ध हमारे देशी मिद्वान्तों को स्थान देने का कार्य प्रयत्न नहीं किया गया। कुछ आलोचकों ने सविधान की यह कहकर भी आलोचना की है कि उसमें शाही जी के मिद्वान्तों का भी स्थान देने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यहाँ हमें जरापा पर विचार करने की आवश्यकता है।

यह सच है कि भारतीय सविधान की रचना में विदेशी सविधानों का प्रभाव अत्यधिक स्पष्ट है। वस्तुतः ऐसा जाना स्वाभाविक भी था। ब्रिटेन के साथ भारत का दीर्घकाल से सम्बन्ध रहा था। अतः यदि भारतीय सविधानकारों ने ब्रिटेन की साविधानिक परम्पराओं का अनुकरण किया तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। उस प्रकार सविधानकारों ने समुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक आन्दोलन, दक्षिण अफ्रीका तथा आयरलैंड आदि देशों के सविधानों से भी बहुत कुछ सामग्री ग्रहण की है। परन्तु उसका जाण्य यह कदापि नहीं है कि सविधान में काँच मौलिकता नहीं है। किसी भी सविधान की रचना में रचना नहीं होती। सविधानों की रचना किसी निश्चित सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि में होती है जहाँ काँच भी सविधान उस पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं कर सकता। भारतीय सविधान की रचना ब्रामबा गान्धी के मध्य में हुई थी अतः सविधानकारों के समक्ष जो समस्याएँ प्रस्तुत थी वे आधुनिक युग की समस्याएँ थी और उनका समाधान आधुनिक तरीकों से ही हो सकता था। उनका मूलभूत में भारत के परम्परावादी मिद्वान्त प्रभावगामी नहीं हो सकते थे। उससे अनिश्चित यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि सविधानकारों ने देशी परम्पराओं का अवगणन करने करने की है तो यह स्पष्ट प्रस्तुत होता है कि उन्हें भारत की कौनसी परम्परा का अनुगमन करना चाहिए था। भारत में कदाँ एक राजनीतिक परम्परा नहीं रही है जिसका प्रत्यक्ष युग में तथा देश के प्रत्यक्ष भाग में पानन हुआ हो। इसी स्थिति में यदि किसी एक परम्परा का अनुगमन किया भी जाता तो उसका नाम भी उस विचार के लिए गड़ा जा सकता कि क्या उस परम्परा का पानन किया जाना उचित था। वस्तुतः उस प्रकार की आलोचना करने वाले यह भूल जाते हैं कि साविधानिक मिद्वान्त एक स्वरूप काँच कापीराष्ट्र सामग्री नहीं है जिनका जय गया के द्वारा प्रयोग वामून् के द्वारा वजित कर लिया गया था। उस सम्बन्ध में तो हमें पता होगा कि यह उद्घरणार्थ है—हमारे सविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक मौलिक अथवा अनायास सविधान बनाना नहीं था। वे चाहते थे कि व्यावहारिक दृष्टि में एक अलग व समस्त सविधान बनाया जाय। तन्नुसार उन्होंने विदेशी सविधानों में स्वतन्त्रतापूर्वक एक प्राविधान लिये हैं जो वहाँ मूल्य मिद्वान्तों और जो अपने देश की आशा के लिए उपयुक्त समझे गए।

3 नावनामिक सविधान

वे भी स्वीकार न भारतिय सविधान का उद्देश्य सविधान बनाया है। वस्तुतः सविधानकारों ने नावनामिक प्रणाली को स्थापित करने के अपने निश्चय की अभिव्यक्ति 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) के द्वारा कर दी थी। मूल प्रणाली सविधान की प्रस्तावना में भी उद्देश्य अपने उस मकसद को दर्शाया था कि वे देश में नावनामिक व्यवस्था का जन्म देना चाहते हैं। यदि प्रस्तावना के अनुसार ही ध्यानपूर्वक पढ़ा

जाये तो उममे यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत मे लोकतन्त्र केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही मर्यादित नहीं है, अपितु उसका सामाजिक एव आर्थिक क्षेत्र मे भी विस्तार करने की प्रतिज्ञा की गई है। सक्षेप मे भारतीय मविधान उदारवाद एव समाजवाद के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कृतमकल्प है।

सविधान मे सन्निहित लोकतान्त्रिक तत्त्वों को यथार्थ मे सविधान के सभी अध्यायों मे अवलोकित किया जा सकता है, परन्तु मूल अधिकारों के अध्याय मे इन तत्त्वों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। सविधान ने केन्द्र और राज्यों मे विधायी एव कार्यपालिका शक्तियों को जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों मे सौपा है। सविधान मे यह व्यवस्था भी की गई है कि इन प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के उपरान्त वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा। वस्तुतः 21 वर्ष की आयु के सभी स्त्री-पुरुषों को मताधिकार प्रदान करने के परिणामस्वरूप आज भारत ससार का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश बन गया है, जितने मतदाता आज भारत मे पाये जाते हैं, उतने विश्व के किसी अन्य देश मे नहीं पाये जाते। इस बात का महत्त्व उस समय और भी अधिक बढ़ जाता है जबकि हम इस बात को भी ध्यान मे रखे कि स्वाधीनता से पूर्व भारत मे अत्यधिक सीमित मताधिकार था तथा निर्वाचन-क्षेत्र साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित थे। नवीन सविधान ने जहाँ मताधिकार को व्यापक बनाया है, वहाँ उसने साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों का भी अन्त किया है। मूल अधिकारों के माध्यम से उसने भारत के ममस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता का भी आश्वासन दिया है। सविधान की यह व्यवस्था देश मे सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करती है। भारतीय लोकतन्त्र के सम्बन्ध मे ध्यान मे रखने योग्य बात यह है कि वह केवल बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर शासन मात्र नहीं है, अपितु वह अल्पसंख्यकों के न्यायोचित अधिकारों की सुरक्षा की भी व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त उसमे समाज के पिछड़े हुए वर्गों के हितों की अभिवृद्धि के लिए विशेष प्राविधानों को स्थान दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधानकारों ने लोकतन्त्र की स्थापना करते समय इस बात को ध्यान मे रखा है कि देश को इन बुराइयों से दूर रखा जा सके जो अविकसित देशों मे लोकतन्त्र के साथ सामान्य रूप मे उत्पन्न होती है।

4 मसदीय कार्यपालिका

भारतीय सविधान ने केन्द्र और राज्यों मे मसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था की है। सविधान सभा मे वस्तुतः इस प्रश्न के ऊपर पर्याप्त मात्रा मे विचार-विमर्श हुआ था कि नवीन भारत की कार्यपालिका की स्थापना ब्रिटेन की मसदीय कार्यपालिका के अनुरूप की जाय अथवा संयुक्त राज्य अमरीका की कार्यपालिका के अनुरूप अध्यक्षीय कार्यपालिका का निर्माण किया जाये। लम्बे विवाद के उपरान्त सविधान सभा ने मसदीय कार्यपालिका को स्थापित करने का निर्णय लिया। यथार्थ मे इस प्रकार का निर्णय स्वाभाविक भी था क्योंकि 1919 और 1935 के अधिनियमों के अन्तर्गत भारतीय जनता को एक सीमा तक मसदीय कार्यपालिका के परिचालन का अनुभव प्राप्त हो चुका था, बाद मे 1947 मे देश स्वाधीन होने के बाद उत्तरदायी शासन के ऊपर ब्रिटेन द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध उठ जाने के पश्चात् देश की जनता ने मसदीय लोकतन्त्र का पूर्ण अनुभव भी प्राप्त कर लिया था। यही नहीं, सविधानकारों का यह विश्वास था कि अध्यक्षीय कार्यपालिका की अपेक्षा मसदीय कार्यपालिका इसलिये अधिक अच्छी होती है क्योंकि उममे कार्यपालिका के लिये विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उन सम्बन्ध मे सविधान सभा मे डा० अम्बेदकर ने कहा था कि इस पद्धति मे कार्यपालिका के उत्तरदायित्व या दैनिक एव एक निश्चित अवधि के उपरान्त मूल्यांकन होता रहता है।' कार्यपालिका का निश्चित अवधि के उपरान्त मूल्यांकन ग्राम चुनाव के समय निर्वाचकों के द्वारा होता

है अतः तोगत्वा निवाचक हा कायपात्रिका द्वारा निष्पादिन कार्यो क औचित्य अथवा अनीचित्य पर अपना अन्तिम निणय लन है। कायपात्रिका क कार्यो तथा नातिया का दनिक मूयाकन निवाचका तारा निवाचिन प्रतिनिधिया के द्वारा विधानमण्डन म हाता है। एम प्रकार स्पष्ट है कि सविधान सभा न समदाय कायपात्रिका का निणय जान-बूझकर लिया था। इस प्रकार की कायपात्रिका म गतिया क पृथक्करण क मिद्धात का कोई स्थान नहा लिया जाता। अत भारतीय मन्निधान म राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राजा की स्थिति जसी हाती है अमरीकी राष्ट्रपति जसी नहा। डा जम्बदकर क गत्ता म वह गष्ट का प्रतीक है उसका गसक नहा। सघ की कायपात्रिका गक्ति का परिधानन उमके नाम म हाता है परन्तु उमका वास्तविक प्रयाग मन्त्रि मण्डन तारा हाता है जिसस सविधान क तारा यह अपभा की जाती है कि वह 'नासभा क प्रति उत्तरदायी हागा। यहा उत्तरदायीय है कि सविधान का व्यवस्थाआ स यह बात स्पष्ट नही है कि भारत की कायपात्रिका समन्वीय ही है अध्यात्मिक नहा है। वस्तुन सविधान म जहा यह लिखा है कि कायपात्रिका तानमभा क प्रति उत्तरदायी होगी वहा उसम यह भी लिखा है कि मन्त्री राष्ट्रपति क प्रसाद कान म ही अपन पद पर काय कर सकेंग। सविधान म एक स्थान पर लिखा है कि राष्ट्रपति का उमक कार्यो म महायता एव परामग देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् हागी जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हागा। परन्तु सविधान म कहा भी यह नहा लिखा कि राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डन द्वारा दिया गया परामग प्रत्यक स्थिति म स्वीकार करना पड़ेगा। अत यह कहा जा सकता है कि भारतीय सविधान म कायपात्रिका का वास्तविक स्वरूप अभिममया क द्वारा निर्धारित हुआ है।

5 धमनिरपक्ष राज्य

यद्यपि सविधान म स्पष्ट गत्ता म यह कहा नहा लिया है कि भारत एक धमनिरपक्ष राज्य (Secular State) है तथापि नस तथ्य की अवगतता नहा की जा सकती कि सविधानकार दग म एक धमनिरपक्ष राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहत थ। वस्तुन सविधान सभा म हुए विवादा स एम सत्य की अभिव्यक्ति भनी प्रकार हा जाती है। धमनिरपक्ष राज्य म स्वीकारात्मक एव निपधात्मक दोना प्रकार क पहलू पाय जात हैं। निपधात्मक रूप म वह साम्प्रदायिक अथवा धमसापक्ष (Theocratic) राज्य क मवधा विपरीत है क्याकि उसम राज्य किसी भी धम विगप त साथ अपना सम्बन्ध स्थापित नहा करता तथा किसी भी धम क मिद्धाता को अपना पथप्रणक नहा मानता। वेस्टारमन न लिया है कि धमनिरपक्ष राज्य न ता धार्मिक होता है न अधार्मिक और न धम विराधी परन्तु वह धार्मिक क्रियाआ एव अधविश्वासा म अपन आपका पूर्णत पृथक् रखता है और एम प्रकार उस धार्मिक मामला म तन्मय कहा जा सकता है। अत नस मायता क अनुकूल एम राज्य म नागरिका पर एम कर आरापित नहा क्रिय जात जिनम प्राप्त आय का किसी धम विगप क प्रचार म व्यय किया जाय।

स्वीकारात्मक रूप म धमनिरपक्ष राज्य अपन समस्त नागरिका का समान दृष्टि म दखता है तथा धम क आधार पर किसी भी प्रकार क भेदभाव को स्वीकार नहा करता। फलम एम राज्य म सभी नागरिका को चाह उनका धम कुछ भी क्या न हा उन्नति करन क समान अवसर प्राप्त हात हैं।

उपपक्त ताना बनीलिया क जाघार पर भारत का धमनिरपक्ष ताना अमन्त्रिय घोषित का जा सकता थ। भारत म सभी नागरिका का समान अधिकार प्रदान क्रिय गय है तथा क्रिया भा नागरिक का उसक धम के आधार पर उसक अधिकारा म बचिन नया रखा जा सकता। भारत का धमनिरपक्ष ताना की अभिव्यक्ति एम तथ्य क द्वारा ना ताना है कि हमारा यहाँ साम्प्रदायिक निवाचा नेत्रा का अन्त कर लिया गया है तथा उनका स्थान पर समुक्त निवाचन तत्र स्थापित क्रिय गय है। भारतीय सविधान न प्रत्यक्ष भारतीय नागरिक का किसी भी धम का मानन एमक अनुमार आचरण करन तथा उमका प्रचारित करन का अधिकार प्रदान क्रिया है तथा साथ हा म

उन्हें किसी भी धर्म को न मानने की भी छूट है। सविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को यह आश्वामन भी प्राप्त है कि लोक-सेवाओं में नियुक्ति के समय किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायगा।

कुछ लोगो ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त की यह कहकर आलोचना की है कि वह अनैतिक एवं अभारतीय है। वस्तुतः यह आलोचना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के साथ न्याय नहीं करती। नैतिकता का सम्बन्ध आवश्यक रूप से धर्म के साथ नहीं है। विश्व का इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ धर्म के नाम पर भयंकर अनैतिक काम किये जा चुके हैं। इसी प्रकार उसे अभारतीय बताना भी केवल सकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है। सच बात यह है कि दर्शन अथवा सिद्धान्त किसी भी प्रकार के भौगोलिक अथवा राजनीतिक सीमान्तों को स्वीकार नहीं करता तथा किसी भी सिद्धान्त पर किसी राज्य विशेष का पेटेन्ट अधिकार भी नहीं होता। कोई भी राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी सिद्धान्त को अपनी सावधानिक प्रणाली में स्थान दे सकता है।

6 प्रभुसत्ता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य

सविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य (Sovereign Democratic Republic) घोषित किया गया है। यहाँ इस सदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 16 मई 1949 को सविधान सभा ने एक प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्र-मण्डल में शामिल होने का निर्णय किया था। यद्यपि इस अवसर पर भाषण करते हुए नेहरू जी ने सविधान सभा में यह कहा था कि 'यह एक ऐसा समझौता है जिसे स्वतन्त्र इच्छा के द्वारा किया गया है तथा जिसे स्वतन्त्र इच्छा के द्वारा तोड़ा भी जा सकता है।' बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता भारत के गणतान्त्रिक स्वरूप के साथ मेल खाती है? आखिर राष्ट्र-मण्डल ब्रिटिश क्राउन के प्रति भक्ति पर आधारित है, स्पष्टतः इस बात का किसी भी गणतन्त्र के साथ मेल नहीं हो सकता। निम्नन्वेद इस तर्क में निहित शक्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसके साथ में ध्यान में रखने की बात यह भी है कि अप्रैल 1949 में राष्ट्र-मण्डल के प्रधानमन्त्रियों का एक सम्मेलन लन्दन में हुआ था जिसमें इस दुविधा का निवारण करने के लिए एक फार्मूला निकाला गया। इस फार्मूले के अनुसार एक गणतान्त्रिक राज्य को भी राष्ट्रमण्डल की सदस्यता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि देश के बहुत से राजनीतिक दलों ने भारत की राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता को देश की स्वतन्त्रता के लिए असंगत बताया है तथापि इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उससे भारत के स्वतन्त्र आचरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

7 सुसशोध्यता एवं दुस्सशोध्यता का समन्वय

बहुधा सविधानों को सुसशोध्य (flexible) तथा दुस्सशोध्य (rigid) सविधानों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। परन्तु यथार्थ में इस प्रकार की वर्गीकरण बहुत अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि कोई भी सविधान न तो पूर्ण रूप से सुसशोध्य होता है तथा न पूर्ण रूप से दुस्सशोध्य। इस दृष्टि से सविधानों में जो भी अन्तर पाया जाता है, वह केवल मात्रा का होता है गुण का नहीं। भारतीय सविधानकार देश के लिए एक ऐसा सविधान निमित्त करना चाहते थे जिसमें उपर्युक्त दोनों प्रकार के सविधानों का समन्वय पाया जाता। वस्तुतः उनके लिए ऐसा करना आवश्यक भी था क्योंकि जहाँ सविधान को राजनीतिक दलों के हाथ में खिलौना बनने से रोकना था वहाँ यह भी आवश्यक था कि उसके विकास के मार्ग को अवरोध न किया जाये। इस सम्बन्ध में सविधान सभा में नेहरू जी ने भाषण था यह अज उद्बुद्ध्य है—'जहाँ हम चाहते हैं कि यह सविधान बनना ठोस और स्थायी होना चाहिए, जितना वह हो सकता है, वहाँ हमें यह भी समझना चाहिए कि सविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता। उसमें एक मात्रा में लचीलापन भी होना चाहिए। यदि आप सभी जानें

को बठार और स्थायी बना देंगे ता आप राष्ट्र की जीवित क्रियाशील एवं अव्यवा जनता का विश्राम राक देंगे। हम बिना भी स्थिति में हम मविधान का इतना बठार नही बनाना चाहिए कि वह बदलती हुई परिस्थितियाँ के अनुसार अपने आपको न ढाँच सकें। फलतः यह स्वाभाविक हो या कि संविधानकार जिसे मविधान की रचना करने उसमें मुमंशाध्यता एवं दुस्संगाध्यता का एक अपूर्व मिश्रण पाया जाता।

मघीय संविधान तान के कारण यह आवश्यक था कि उसमें एक सीमा के अन्तर्गत दुस्संगाध्यता के तत्त्व पाये जाते। जाँवर जनिम में भारतीय संविधान में दुस्संगाध्यता के तत्त्वा का ही अवतारित किया है। अपने इस मन के समर्थन में जनिम ने दा तब प्रस्तुत किया है प्रथम संविधान के संशोधन की विधि साधारण कानून बनाने की विधि की अपेक्षा कुछ अधिक उन्नत है तथा द्वितीय संविधान का आकार उन्नत बना है। परंतु कुछ अन्य बातों ने इस मन के साथ अपनी असहमति व्यक्त की है। एलेक्जेंड्रोविक (Alexandrowics) ने निम्ना है कि इस बात के आवश्यक भी कि भारतीय संविधान का आकार बहुत बड़ा है तथा उसमें संशोधन केवल एक विधिगत प्रक्रिया के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है उस पर दुस्संगाध्यता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सब बात यह है कि भारतीय संविधान में दुस्संगाध्यता के दापा को कम करने की कोशिश की गई है। परन्तु संविधान में यह व्यवस्था है कि आपातकाल में जिना किसी संशोधन के सहायक राज्य में एकात्मक राज्य की व्यवस्था स्थापित हो सकें। इस प्रकार की व्यवस्था बिना अन्य मघीय राज्य में नहीं पाई जाती।

संविधान की 368वीं धारा में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संसद विधायक के रूप में संविधान में संशोधन का प्रस्तावित कर सकती है और यह विधायक उससे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधायक के पारित होने के सम्बन्ध में संविधान में विधि व्यवस्था है। सबसे प्रथम उसमें पारित होना के लिए यह आवश्यक माना गया है कि संसद के दोनों सदन उस अवधि में एक ही रूप में अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत में स्वीकार कर तथा इस विधायक पर मतदान करने वालों का संख्या प्रत्येक सदन में उसकी कानूनी संख्या के बहुमत होना चाहिए। इसका अर्थ यह था कि संशोधन के पारित होना के लिए नौकमभा के कम से कम 263 सदस्यों तथा राज्य सभा के 119 सदस्यों का समर्थन अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय सदन द्वारा उपयुक्त विधि में पारित होना के उपरान्त विधायक को राष्ट्रपति के समक्ष उसका स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी कार्यवाही केवल उसी समय में होगी जबकि उस राष्ट्रपति भी स्वीकार करेगा। सामान्यतः संशोधन के सम्बन्ध में इसी प्रक्रिया का व्यवहार में लाया जाता है परन्तु संविधान में कुछ भागों का संशोधन करने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि उस समय में कम से कम राज्य के विधानमण्डल का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार जिन संशोधनों के लिए राज्यों के स्वाकृति आवश्यक है उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें राज्यों के विधानमण्डल द्वारा स्वीकार नहीं कर लें।

संविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें संशोधित करने के लिए केवल संसद द्वारा साधारण कानून की आवश्यकता माना गई है। इस प्रकार के संशोधनों में नये राज्य का रचना प्रवर्तित राज्यों का पुनर्गठन तथा राज्यों के द्वितीय सदन का उद्घाटन (अनुच्छेद 4, 169 और 240) आदि शामिल हैं।

संविधान में संशोधन की उपयुक्त प्रक्रियाओं का एक विभिन्न श्रेणी में जानाघना का गई है। आलोचकों का पहला आपत्ति यह है कि हमारा देश में संशोधन के माध्यम में जनता की चला जानने का प्रयास नहीं किया गया है तथा उस पर केवल संसद का अधिकार स्थापित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संसद राज्य जमशेका स्वतंत्रराज्य तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों में संशोधन के पारित करने में जनमत-संग्रह का व्यवस्था पाई जाता है। भारत में इस

व्यवस्था का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आलोचना का औचित्य इसलिए और भी है क्योंकि हमारे देश में सत्ता मुख्यतः एक ही दल के हाथों में रही है, इसी दल ने देश के संविधान की रचना भी की थी। अतः आलोचकों के इस कथन में एक बड़ी मात्रा में सत्य पाया जाता है कि आधुनिक संविधान कांग्रेस दल का संविधान है।

8 संविधान की अन्य विशेषताएँ (Other Features)

मूल अधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त—उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त संविधान की कुछ अन्य विशेषताएँ भी हैं जिनमें मूल अधिकार तथा नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की व्यवस्था को प्रमुख समझा जाना चाहिए। ब्रिटिश शासनकाल में भारतवासियों के लिए मूल अधिकारों जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। परन्तु हमारे आधुनिक संविधान में इस कमी को दूर किया गया है तथा उसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान में जिन अधिकारों को मान्यता दी गयी है, उन्हें सात शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित हैं—

- (1) समानता का अधिकार,
- (2) स्वतन्त्रता का अधिकार,
- (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार,
- (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार,
- (5) सस्कृति और शिक्षा का अधिकार,
- (6) सम्पत्ति का अधिकार, तथा
- (7) सांविधानिक उपचारों का अधिकार।

संविधान के एक प्राविधान के अनुसार राज्य को किसी ऐसे कानून को बनाने के अधिकार में वंचित रखा गया है जिससे नागरिकों के उपर्युक्त मूल अधिकारों पर आघात पहुँचता हो। इन अधिकारों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उनका सम्बन्ध सामान्यतः पश्चिम के उदारवादी लोकतान्त्रिक दर्शन के साथ है, फलतः वे उन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं जो आज के युग में केवल हमारे देश के सम्मुख ही नहीं अपितु प्राचीन व्यवस्था में रहने वाले सभी देशों के समक्ष गम्भीर रूप से प्रस्तुत हैं। संविधानकार इस तथ्य से अवगत थे, अतः उन्होंने कुछ अन्य अधिकारों की भी व्यवस्था की, परन्तु उनके सम्बन्ध में यह कहा गया कि उनकी कार्यान्विति के न होने पर किसी न्यायालय में शिकायत नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार के अधिकारों को राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। वस्तुतः नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को हमें भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता समझनी चाहिए। इन सिद्धान्तों के माध्यम से संविधान-निर्माताओं ने भारतीय गणराज्य के लक्ष्यों एवं आदर्शों की घोषणा की है।

प्रश्न

- 1 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

सविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त

(PREAMBLE FUNDAMENTAL RIGHTS
AND THE DIRECTIVE PRINCIPLES)

सविधान की प्रस्तावना

प्रत्येक सविधान का आरम्भ एक प्रस्तावना के साथ होता है जिसमें उसके मूल उद्देश्य सन्निहित होते हैं। इस व्यापक नियम का अभी तक केवल एक ही उपयोग रहा है और वह था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1935 का अधिनियम। अंग्रेजों ने इस अधिनियम की रचना करते समय इस नीति का पुरानी परम्परा का पालन क्या नहीं किया जिसके कारण की खोज करना कोई कठिन कार्य नहीं है। स्पष्टतः अंग्रेजों ने इस दश के सदैव में जो उद्देश्य निश्चित किये थे वे ऐसे नहीं थे जिनकी खुलकर घोषणा की जा सकती। यदि वे भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने उद्देश्य घोषित करते तो इससे इंग्लैंड की जनता के असन्तुष्ट हान की आशंका थी और यदि इंग्लैंड के लोगों की इच्छा को ही ध्यान में रखकर कोई घोषणा की जाती तो उससे भारतीय जनता के अप्रसन्न होने का भय था। परन्तु नवीन भारत के निर्माताओं के समक्ष इस प्रकार का कोई धर्म नहीं था। वस्तुतः प्रस्तावना की रचना के रूप में उन्हें एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था जिसके माध्यम से वे इस देश में स्थापित होने वाली नई व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने स्वयं की अभिव्यक्ति कर सकते थे जिन्हें यह देश गतात्म्या से सजाया जाता आ रहा था।

नवतः भारतीय सविधान का आरम्भ उस प्रस्तावना के साथ होता है जिसके द्वारा उनमें देश में एक ऐसे युग का आरम्भ करने का संकल्प किया है जिसमें देश की जनता के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को उच्चतम मानव गरिमा एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप निमित्त किया जायगा। अपनी अंतिम पुस्तक *Principles of Social and Political Theory* में अन्तर्गत वाक्य में हमारे सविधान की प्रस्तावना को विषय-सूची के दाल के पृष्ठ पर उद्धृत किया है तथा उसके सम्बन्ध में लिखा है कि जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे यह लगता है कि उसमें मैं पुस्तक का अधिकांश तक सत्य में वर्णित है और उसमें उसकी कमी माना जा सकता है। मैं उस उद्धृत करने के लिए संतुष्ट और सन्तुष्ट हूँ क्योंकि मुझे इस बात पर गर्व है कि भाग्य के योग अपने स्वतंत्र जीवन का आरम्भ राजनीतिक परम्परा के उन सिद्धान्तों के साथ कर रहे हैं जिन्हें हम पश्चिम के लोग पश्चात्त्य कहकर पुकारते हैं परन्तु जो अब पश्चात्त्य में कहा अधिक है।

सविधान की प्रस्तावना से सम्बद्ध कोई भी विवेचना उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक कि उसमें नहों जो द्वारा सविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 का प्रस्तावित प्रस्ताव का उद्देश्य न किया जाय। इस प्रस्ताव में भारतीय जनता के उच्च आत्माओं की अत्यधिक सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रस्ताव में अंग्रेजों के साथ यह भी कहा गया है कि जिसमें भारत के समस्त लोगों के लिए अधिकार प्राप्त किये जायेंगे और प्रत्याभूत हों—न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पर अवसर तथा धन का समान समानता विचार अभिव्यक्ति विचार पूजा व्यवसाय संपत्ति और कार्य का स्वतंत्रता कानून एवं नतिकता के अधीन तथा जिसमें अन्य गण्यता विद्यमान हों तथा जनजातीय तथा और दलित तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण।

की व्यवस्था की जायेगी।'

प्रस्तावना का कानूनी महत्त्व—मेक्सवेल ने लिखा है कि किसी भी 'सविधान की प्रस्तावना' उसके अर्थ को समझने का अच्छा साधन है, वह उसके समझने की कुजी है।' अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश स्टोरी ने इसके सम्बन्ध में लिखा है कि 'सविधान की प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुजी है, कि वे उसके द्वारा किन बुराइयों को दूर करना चाहते थे तथा सविधान की व्यवस्थाओं के द्वारा वे किन उद्देश्यों की प्राप्ति चाहते थे।' भारतीय सविधान की प्रस्तावना के महत्त्व को सविधान सभा के एक सदस्य पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—'प्रस्तावना सविधान का सबसे अधिक मूल्यवान भाग है। वह सविधान की आत्मा है। वह सविधान की कुजी है। वह वस्तुतः मापक है जिसकी सहायता से सविधान के मूल्यों को आँका जा सकता है।' संक्षेप में, प्रस्तावना में सविधान के उद्देश्य तथा उसकी नीतियों का उल्लेख है। सविधान के वास्तविक भाग में उन नीतियों को व्योरे सहित स्पष्ट भाषा में लिखा होता है। अतः जहाँ सविधान की भाषा स्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों के आधार पर सविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न नहीं उठता। परन्तु जैसा डा० डी० वी० वसु ने लिखा है कि 'जहाँ सविधान का कानूनी भाग अस्पष्ट है, वहाँ उसकी व्याख्या करने के लिए तथा उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है।' इसी प्रकार का मत सर्वोच्च न्यायालय ने 'ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य' नामक मुकदमे में व्यक्त किया था। इस मुकदमे में जस्टिस पतजलि शास्त्री ने अपना निर्णय देते हुए कहा था कि यद्यपि सविधान ने नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिये हैं, 'परन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि उसके प्राविधानों की भाषा की इस प्रकार खीच-तान की जाए कि कानून की व्याख्या के सभी नियमों का उल्लंघन करके उसका ताल-मेल किसी न किसी साविधानिक सिद्धान्त के साथ बैठा दिया जाय।' किन्तु जब भी व्यवस्थापिका ने किसी साविधानिक नीति की स्थापना की है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखने का प्रयत्न किया है कि उस नीति को प्रस्तावना के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है अथवा नहीं।

प्रस्तावना की व्याख्या

प्रस्तावना की व्याख्या के पूर्व उसकी जान लेना आवश्यक है। प्रस्तावना निम्नलिखित है—
हम भारत के लोग, भारत को एक 'सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य' बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता' को उपलब्ध कराने लिए, तथा उन सबमें 'व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बन्धुत्व' की अभिवृद्धि करने के लिए, दृढसंकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को एतद् द्वारा इस सविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म-समर्पित करते हैं।'

उपर्युक्त प्रस्तावना से निष्कर्ष रूप में जो पहली बात निकलती है कि वह यह है कि भारत में प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। यद्यपि सविधान में इस आशय की कोई धारा नहीं है, तथापि प्रस्तावना में कहा गया है कि देश के लोगों ने इस सर्वोच्च कानून को अंगीकृत अधिनियमित, तथा आत्मसमर्पित किया है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि सविधान सभा को भारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी रचना केविनेट मिशन योजना के अन्तर्गत सीमित एवं पृथक् निर्वाचन की प्रणाली पर आधारित प्रान्तीय विधानमण्डलों के द्वारा हुई थी। उसके अतिरिक्त वह प्रभुसत्तासम्पन्न संस्था भी नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ केविनेट मिशन योजना के प्रावधानों के द्वारा मर्यादित थीं। यही नहीं, उसमें देशी राज्यों के 93 प्रतिनिधि भी मौजूद थे और वे वहाँ की जनता अथवा वहाँ के विधानमण्डलों द्वारा निर्वाचित न होकर वहाँ

के नरणा द्वारा मनोनीत किया गया था। अतः संविधान सभा का यह नामाकरण वा कीर्ति अधिकार नहीं था कि जिन भारत के लोगो की ओर से संविधान की रचना की है। उससे तर्कों में निहित मूल्य से इनकार न करने हुए भी यह स्वीकार करना पड़ा कि 1946 में जब संविधान सभा का निर्णय निवाचन हुए थे उस समय चाहे जिस प्रकार के मतानुसार के आधार पर चुनाव कराये जाते संविधान सभा के स्वरूप में जो विषय अन्तर्गत नहीं पड़ सकते थे। 1952 में हुए प्रथम आम चुनावों के परिणामों से यह बात भी निश्चित प्रमाणित है। जहाँ तक संविधान सभा की प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में उगाई गई आपत्ति का प्रश्न है क्या यह कहना गलत होगा कि संविधान सभा विदेशी मोक्षार्थ के अंतर्गत नाम कर रहीं थी।

प्रस्तावना में प्रयुक्त नामों का स्पष्ट है कि भारत की जनता ने स्वयं अपने आपका संविधान लिया है। इसका अर्थ यह भी है कि जिस राज्य का अपना राज्या के किसी समूह को संविधान का अंत करने का अधिकार उनके द्वारा निर्मित मध्य में प्रत्येक हानि का अधिकार नहीं है। संविधान के मुख्य भाग में भी देश की एकता पर बल दिया गया है। यद्यपि प्रणामनीय मुविद्या की प्रति में देश को विभिन्न राज्यों में बाँटा गया है तथापि देश की एकता अखण्ड माना गई है उसकी जनता एक है और उसी में प्रभुसत्ता निवास करती है।

यहाँ भारतीय संविधान में निहित प्रभुसत्ता के स्वरूप की विवेचना अप्रामाणिक न होगी। जमा कहा जा चुका है कि भारत में प्रभुसत्ता जनता की एकता में निवास करती है। यद्यपि संविधान में विषयों का ज्ञान सूचिया में विभाजित किया गया है तथापि इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत में प्रभुसत्ता विभाजित है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शक्तियों का मध्य की कर्तव्य सत्ता में केंद्रित किया जा सकता है। यह सही है कि विदेशी दृष्टि में मध्य प्रणाली में प्रभुसत्ता के निवासस्थान का पता लगाना असम्भव होता है परन्तु भारतीय संविधान में हम यहाँ का पता लगा लिया गया है।

प्रस्तावना में प्रयुक्त राजनीतिक गणनायक नामकी कुछ भ्रमास्पद है। हम सम्मेलन में भी इन जनताओं ने लिया है कि राजनीतिक गणनायक नामकी में एमी प्लुरल (tanology) है जिस हटायी जा सकती है और राजनीतिक प्रति से गणनायक नाम के कुछ राजनीतिक विगणन का प्रयोग करके किसी विषय नाम की प्राप्ति भी नहीं हो सकती थी।

परन्तु सम्भवतः संविधानसभा ने राजनीतिक नाम का प्रयोग जानबूझ कर अनियमित किया था क्योंकि वह उसके द्वारा राजनीतिक के विचार में मूलभूत सामाजिक आर्थिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का अभिव्यक्त करना चाहते थे। संविधानकारों की यह जाका था उन उच्च जातियों में स्पष्ट नहीं जानती है जिनका उद्देश्य प्रस्ताव में था। वस्तुतः हम जानें कि यह अस्पष्टता भी संविधान सभा में लिया गया एक भाषण में व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि हम संविधान की रचना करते समय वास्तव में हमारे दो उद्देश्य थे—(1) राजनीतिक राजनीतिक के स्वरूप से निश्चित करना तथा (2) यह प्रतिपादित करना कि हमारा आत्म आर्थिक राजनीतिक है। यहाँ प्राप्ति राजनीति का यह कथन उद्घरणाय है कि राजनीतिक समानता तब तक वास्तविक नहीं है। हम जानते हैं कि उनके साथ वास्तविक आर्थिक समानता भी नहीं है। हम अर्थ में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना ने वस्तु गृहस्थ में इन दोनों जातियों का संविधान में मनुष्यत्व दिया है।

प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय गणराज्य भागनाय जनता को चार जातियों की उपनिधि परगन का मकसद करना है। इनमें से पहला जाति है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जाति। जाति नाम की परिभाषा के सम्बन्ध में सचिवका में मन्थन हो सकता है परन्तु हम मध्य में इनकार नहीं किया जा सकता कि जाति में जाति अतिशय व्यक्तित्व होता एक सामाजिक जाति के बीच समन्वय स्थापित करने में है। संविधान ने जाति में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की है। हम प्रसार का नाम प्रणाली में यह बताना सम्भव है कि जो सरकार निर्मित है वह बहुमत का अधिपत्य नाम कायम करेगा। परन्तु प्रस्तावना हम प्रसार के अधिपत्य नाम का अनुचित

ठहराता है क्योंकि वह भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय की उपलब्धि कराने का वचन देती है। वस्तुतः मन्चे लोकतन्त्र की यही आधार-जिला है। यदि स्वतन्त्रता के पूर्व के भारतीय सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता मधर्ष और तनाव थे तो नवीन संविधान के अन्तर्गत स्वतन्त्र भारत का सामाजिक जीवन एकता और भाईचारे पर आधारित होगा। सामाजिक न्याय के विचार में यह भावना भी निहित है कि समाज में सभी प्रकार की असमानताओं का अन्त होना चाहिए। आर्थिक न्याय के विचार में आर्थिक समानता का विचार शामिल है, यथार्थ में अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक अमीरी के वातावरण में आर्थिक न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रस्तावना देश में समाजवाद की स्थापना का आश्वासन देती है। राजनीतिक न्याय इस बात का आश्वासन देता है कि देश की जनता के साथ राज्य लोकतान्त्रिक व्यवहार करेगा।

20वीं शताब्दी में स्वतन्त्रता के निषेधात्मक अर्थ को स्वीकार नहीं किया जाता, भारतीय संविधानकारों ने 'स्वतन्त्रता' शब्द का प्रयोग स्वीकारात्मक अर्थ में किया है। उन्होंने स्वतन्त्रता को इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि उनके माध्यम से व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वतन्त्रता उच्छ्वलता का नाम नहीं है, वस्तुतः वह उन अनुकूल परिस्थितियों का नाम है, जिनके अन्तर्गत व्यक्ति सामाजिक हितों को क्षति पहुँचाये बिना अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। हमारा संविधान इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का आश्वासन देता है।

संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पद तथा अवसर की समानता को उपलब्ध कराने का वचन देती है। वस्तुतः हमारे संविधान में समानता का वही अर्थ है जिसमें कि उसे फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा घोषित मानवीय अधिकारों के घोषणापत्र में प्रयुक्त किया गया था—'मनुष्य अधिकारों में स्वतन्त्र एवं समान पैदा हुए हैं।' सामाजिक विभेदों का औचित्य केवल सार्वजनिक उपयोगिता के आधार पर ही किया जा सकता है।

प्रस्तावना में 'बन्धुत्व' शब्द का प्रयोग दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। सर्वप्रथम संविधानकार उनके द्वारा मानव की गरिमा को स्थापित करना चाहते थे, दूसरे, वे उसके द्वारा राष्ट्र की एकता को कायम करना चाहते थे। भारत को एक लम्बे समय तक साम्प्रदायिक घृणा के वातावरण में होकर गुजरना पड़ा था। यदि उसे एक राष्ट्र की भाँति जीवित रहना था तो यह परमावश्यक था, कि सभी प्रकार के साम्प्रदायिक एवं समाज-विरोधी भावनाओं का उन्मूलन किया जाय। प्रस्तावना में बन्धुत्व का सिद्धान्त इसी पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया है।

मूल अधिकार

व्यक्ति एवं राज्य के बीच का मधर्ष कोई नूतन असामान्य घटना नहीं है, वस्तुतः यह मधर्ष उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास। फलतः राजनीतिक विचारकों एवं संविधानकारों के समक्ष जो एक समस्या हर युग में प्रस्तुत रही है, वह यह है कि इस मधर्ष का निराकरण कैसे किया जाय। इसके लिए सामान्यतः दो उपाय सुझाये गये हैं प्रथम, राज्य की शक्तियों को विभाजित करके उन्हें तीन विभिन्न अभिकर्णों में इस प्रकार बाँट दिया जाये, जिसमें कोई भी अभिकर्ण इतना अधिक शक्तिशाली न होने पाये जिसमें वह दूसरों के लिये खतरा बन जाये। द्वितीय, राज्य के नागरिकों को कुछ ऐसे मूल अधिकारों का आश्वासन दिया जाये, जिनका उल्लंघन स्वयं राज्य भी न कर सके। यहाँ मूल अधिकारों में तथा माधारण कानूनी अधिकारों के बीच भेद करने की आवश्यकता है। माधारण कानूनी अधिकारों से भिन्न मूल अधिकारों की मुद्धा का आश्वासन देश के संविधान के द्वारा दिया जाता है। इन अधिकारों को 'मूल' इसलिए कहा गया है कि क्योंकि माधारण अधिकारों की भाँति उन्हें व्यवस्थापिका माधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के द्वारा नहीं बदल सकती, उन्हें बदलने के लिए स्वयं संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको केवल संविधानिक संशोधन के द्वारा ही बदला जा सकता है।

है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भाँसे व सविधान में कबल उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जा सकता है जिन्हें उस देश के सर्वोच्च कानून में निहित किया गया हो तथा जिनकी पवित्रता एवं अनुसूधनीयता का कायपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों स्वीकार करते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मूल अधिकारों के विचार के मूल में सीमित सरकार का स्थापित करने की भावना मजिहिन है। सीमित सरकार में हमारा अभिप्राय उस सरकार में है जिसमें राज्य के किसी भी अंग का सत्ता पर एकाधिकार नहीं होने दिया जाता। वस्तुतः इस प्रकार की सरकार का परिचयन कानून के द्वारा होता है व्यक्तियों की सनक के द्वारा नहीं। सरकार के इस स्वरूप को समुक्त राज्य अमेरिका के सविधान में मायता प्रदान की गई है परन्तु ब्रिटिश सविधान में इस प्रकार के विचार के नियमों का स्थान नहीं है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भारतीय सविधानकारों ने सविधान में मूल अधिकारों का स्थान देकर अमेरिकी साविधानिक परम्परा को क्या स्वीकार किया ब्रिटन की परम्पराओं का क्या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर पान के लिए हमें दोनों परम्पराओं की मजिहिन विवेचना आवश्यक है।

ब्रिटन में आधुनिक लोकतन्त्र का जन्म निरकुश कायपालिका के विरुद्ध जनता के समक्ष सघष के परिणामस्वरूप हुआ है और इस सघष का वहाँ की संसद ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि ब्रिटन के नाम निरकुश राजतन्त्र द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समाधान संसदीय प्रभुमत्ता में पाते। फलतः ब्रिटन की राजनैतिक प्रणाली जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास के ऊपर आधारित है। ब्रिटन के जनमानस में यह दान कभी स्वीकार नहीं की कि विधानमण्डल भाँसे आत्तायी बन सकता है तथा जनसाधारण की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उसकी शक्तियाँ को भी मर्यादित करने की आवश्यकता है। यहाँ कारण है कि ब्रिटन में जिन मसौदों का अधिकारों का घोषणा-पत्र कहा जाता है वे कबल कायपालिका की शक्तियों पर सीमाएँ आरोपित करते हैं व्यवस्थापिका की शक्तियों पर नहीं।

अमेरिकी स्थिति इससे मर्यादा भिन्न थी। अमेरिका का जनता का न कबल निरकुश कायपालिका का अनुभव था अपितु उसने निरकुश व्यवस्थापिका का भी अनुभव किया था। उसने ऐसा था कि ब्रिटिश संसद जैसी प्रतिनिधि संस्था भी उपनिवेशों के साथ धूरतापूर्वक पेश आती थी। यह निष्कर्ष एक कठ उपहाम था कि ब्रिटन की संसद ने निरकुश राजतन्त्र के विरुद्ध सघषों की अपनी शौरवपूर्ण परम्पराओं का परित्याग करके उपनिवेशों की जनता पर निरकुश शासन का शासन का प्रयास किया था। इस पृष्ठभूमि में यह स्वाभाविक ही था कि अमेरिकी सविधानकारों का जहाँ कायपालिका के प्रति अविश्वाम था वहाँ उन्हें अविश्वाम व्यवस्थापिका के प्रति भी था। इसलिए वे कायपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों के विरुद्ध व्यक्तिक अधिकारों की रक्षा को आवश्यक मानते थे।

भारतीय स्थिति समुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति से भिन्नता जुनता थी। हमारे एक व राष्ट्रीय आन्दोलन का भी ब्रिटन का कायपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों के अत्याचार का अनुभव था। फलतः 1927 के मसौदों में हुए वायस अधिकारों ने माँग की कि भारत के लिए जा भाँसे सविधान बनाया जाए उस मूल अधिकारों पर आधारित होना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में नहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। सविधान में इनके उल्लेख का औचित्य प्रतिपादित करते हुए उसमें यह कहा गया था कि हमारा पहला काम अपने मूल अधिकारों की व्यवस्था करना होना चाहिए जिनका आन्तर्गमन इस प्रकार किया जाए जिनमें कि उन्हें किसी भी स्थिति में बाधित न किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था का नहरू रिपोर्ट के लेखकों ने हमारे आवश्यक माना क्योंकि हमें विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मतभेद पाय जान थे। फलतः उन मामलों में जो एक दूसरे के मध्य एक अविश्वाम का दृष्टि में आते थे विश्वाम एवं मर्यादा की भावना का पालन करने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें सविधान के द्वारा यह आन्तर्गमन दिया जाए कि उन्हें अनेक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक अधिकारों के उपभोग करने का मूल अधिकार होगा।

मूल अधिकारों के विचार की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य एक बात यह है कि उसका जन्म उन अयोग्यताओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जिन्हें सरकार ने जनता के ऊपर लादा था। यह बात संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अतः अमरीका की हो भौति भारत में भी यह कहा गया कि अधिकार अपने अन्तिम विश्लेषण में उन अन्यायों का उपचार है जिन्हें निरकुश शासकों ने जनता के ऊपर वरता है। अतः अधिकार भी सख्या में उतने ही होने चाहिए जितने अन्याय हैं और जिनका उपचार होना है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह भी है कि फ्रांस के क्रान्तिकारियों का भी इस सम्बन्ध में यही निष्कर्ष था। अमरीका और फ्रांस में निरकुश शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा मध्यम वर्ग के लोगों ने बुलन्द किया था, फलतः उन्होंने जिन अधिकारों को अपने अपने देशों के संविधानों में स्थान दिया, वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के हितों पर ही आधारित थे। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को भी मध्यम वर्ग का ही नेतृत्व प्राप्त था और संविधान सभा में भी मध्यम वर्ग के सदस्यों की ही भरमार थी। अतः उन्होंने संविधान में जिन अधिकारों को स्थान दिया है, उनका सम्बन्ध भी प्रधानतः मध्यम वर्ग के हितों के साथ है। भारतीय संविधानकार इस तथ्य से अवगत थे कि अब इस व्यक्तिवादी पृष्ठभूमि का सदैव के लिए अन्त हो चुका था जिसने अमरीकी फ्रेंच अधिकारों के विचार को जन्म दिया था और उसका स्थान कल्याणकारी राज्य के विचार ने ले लिया था। भारतीय संविधानकार इस तथ्य की भी अवहेलना नहीं कर सकते थे कि उन्हें उस देश के लिए अधिकारों की रचना करनी है जिसकी अपनी दार्शनिक एवं सामाजिक परम्पराएँ हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों में उपर्युक्त सभी प्रकार के प्रभाव उपस्थित हैं।

मूल अधिकारों की प्रकृति

ससार के किसी भी देश के संविधान में मूल अधिकारों का इतना विशद उल्लेख नहीं हुआ है जितना भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान का एक समूचा अध्याय (तीसरा अध्याय) जिसमें कुल 24 धाराएँ हैं (12 से 35 तक)—मूल अधिकारों के वर्णन के साथ सम्बद्ध है। इन अधिकारों को सात शीर्षकों में बाँटा गया है—(1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, (6) सम्पत्ति का अधिकार, तथा (7) सांविधानिक उपचारों का अधिकार। मोटे तौर पर अधिकारों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के अधिकार वे हैं जिन्हें कार्यान्वित करना राज्य के लिए बाध्यकारी है और यदि राज्य का कोई कानून उनका उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। दूसरी श्रेणी में वे अधिकार आते हैं जिनके ऊपर राज्य कुछ सीमाएँ आरोपित कर सकता है। इस प्रकार के अधिकारों पर निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण करके प्रतिबन्ध नहीं लगाये जा सकते। अतः यदि कोई कानून इन सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की प्रकृति के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि वे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त पर आधारित नहीं हैं। फलतः कोई भारतीय नागरिक किसी ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकता जिसे संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि भारतीय संविधान में यह बात स्वीकार नहीं की गई कि अधिकारों की कोई सीमा नहीं होती, वस्तुतः भारतीय संविधान अधिकारों को सीमित मानता है। कुछ मामलों में तो अधिकारों पर सीमाएँ स्वयं संविधान ने आरोपित की हैं, कुछ मामलों में सीमाओं को आरोपित करने का दायित्व संसद को सौंपा गया है। परन्तु इस प्रकार के अधिकारों के सम्बन्ध में भी ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उनमें भी अधिकारों को मूल माना गया है, प्रतिबन्धों को नहीं। उपर्युक्त विवेचना में स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में निहित अधिकारों

को इसलिए मूल अधिकार नष्ट बनाया गया क्योंकि व असौमित्र है तथा व प्राकृतिक अधिकारों के मिट्टा व पर आधारित हैं इनमें सबसे अधिक उच्च मौलिक अधिकारों की मना इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि उच्च दण्ड व मूल कानून में स्थान दिया गया है तथा उच्च कार्यवित्त करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर केंद्रीय सरकार तक सभी प्रशासनिक अधिकारों काय है। उच्च मौलिक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा भारत का मूल एकता की अभिवृद्धि होती है। भारत के सभी नागरिकों का चार व दण्ड के किसी भाग में क्या न रहता है एक से अधिकारों का आवश्यकता दिया गया है। मूल अधिकारों में जर्मन पतञ्जलि शास्त्रों का यह निष्कर्ष उल्लेखनीय है कि 368वीं द्वारा व प्राविशान सामाज्य है तथा व समस्त का प्रिना किसी अपवाद के सविधान को सहायित करने की शक्ति प्रदान करने है। वार्षिक 1964 में सर्वोच्च न्यायालय ने गावकनाथ बनाम पञ्जाब नामक मुकदमे में अपने इस निष्कर्ष को व्यक्त किया और कहा कि समस्त का तीसरा अध्याय में निहित अधिकारों को सहायित करने का वार्षिक अधिकार नहीं है। यहाँ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दण्ड के जनमत ने इस स्थिति का कभी स्वीकार नहीं किया। 1971 के मध्यावधि चुनावों के परिणामों में तथ्य को प्रमाणित करते हैं। फलतः दण्ड में समस्त का 1964 से पूर्व का गतिविधि का वापिस दिनांक के लिए मांग पाई जाती है। 24वाँ और 25वाँ संशोधन संसद की इस शक्ति को वापिस दिवाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। इन संशोधनों को कानूनन भारत का मुकदमे में चुनौती दी गई थी परन्तु इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया उससे द्वारा उनकी वधना स्वीकार कर लेता है।

मूल अधिकारों में सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है

उपरोक्त विवेचना में स्पष्ट है कि अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। समस्त उच्च संविधान में निहित अपवादों का ध्यान में रखकर निम्नलिखित बताने सकती है—वस्तुतः अधिकारों की व्यवस्था करते समय दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—प्रथम जनता का हित और द्वितीय राज्य की सुरक्षा। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न है कि इस बात का निष्कर्ष कौन करेगा कि किसी नागरिक ने अपने अधिकारों का लालच करते समय उक्त सीमाओं का अतिक्रमण किया है अथवा नहीं। यह प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं—प्रथम न्यायपालिका और द्वितीय संसद।

यहाँ यह तक प्रस्तुत किया जा सकता है कि व्यवस्थापिका का निर्वाचन वाणिज्य मताधिकार के आधार पर होता है और वह देश की समूचा जनता का प्रतिनिधित्व करती है अतः उस देश के नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व सीमा तक सकता है। इसलिए किसी भी न्यायाधीश को अथवा किसी भी न्यायालय का तामरा सदन बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। संविधान में इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये। एक दृष्टिकोण यह है कि मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाये तथा विधानमण्डल को उच्च मर्यादित करने की वार्षिक शक्ति प्रदान की जाय। समय आने पर न्यायपालिका इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठा लेगी। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि कुछ देशों की अवस्थाओं के कारण सामाजिक ढाँचा सामन्ती युग का अवशेष है राज्य नवजात शिशु के समान है तथा वाणिज्य मताधिकार पर आधारित मर्यादित शासन प्रणाली नया अनुभव है अतः राज्य को निर्वाचन में मतदान के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार व्यवस्थापिका का दिया जाए। भारतीय संविधान में इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच समन्वय स्थापित करने हुए मूल अधिकारों का गिनाया गया है इस सूची में उन अधिकारों का सम्मिलित किया गया है जिन्हें संविधानद्वारा व्यक्त व निरूपित आवश्यक मानते हैं। परन्तु जब भी माय हो उसमें उनका ऊपर कुछ नाम प्रविष्ट है लगाय गया है जिसमें राज्य तथा संविधान का परिचय बिना दिया गया है। वस्तुतः इस विषय में

अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना जा सकता जिससे सामाजिक हित पर आंच आती हो।

व्यवहार में अधिकारों की व्याख्या के क्षेत्र में हमारे देश में न्यायपालिका की शक्तियों का विकास हुआ है। न्यायपालिका के निर्णयों के द्वारा, जहाँ निवारक नजरबन्दी कानूनों के बहुत से भाग अवैध घोषित किये जा चुके हैं वहाँ ऐसे अनेक प्रगतिशील कानूनों को भी गैर-कानूनी बताया जा चुका है जिनकी रचना सामाजिक तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर की गई थी। कुछ मामलों में सदन को अपनी आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये सविधान को सशोधित करने के लिये बाध्य होना पड़ा है। उदाहरण के लिये 1951 और 1955 के सशोधनों को लिया जा सकता है। वस्तुतः भारतीय सविधान में न्यायपालिका को अत्यधिक सीमित भूमिका सौंपी गई है। इस बात को समझने के लिये 21वीं धारा का उदाहरण लिया जा सकता है। इस धारा में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी अन्य तरीके से उसके जीवन तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय सविधान ने प्राकृतिक कानून के विचार को स्वीकार नहीं किया। भारत के सविधान के अनुसार कानून वह है जिसकी रचना सदन के द्वारा होती है। स्पष्टतः ऐसी स्थिति में न्यायपालिका केवल यह देख सकती है कि व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करते समय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है अथवा नहीं। भारतीय सविधान में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, यथार्थ से अमरीकी सविधान से भिन्न जहाँ न्यायिक समीक्षा केवल एक न्यायिक निर्णय पर आधारित है भारत में इसकी व्यवस्था स्पष्ट शब्दों में स्वयं सविधान में की गई है। सविधान की 13वीं धारा में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्रत्येक कानून की वैधता की इस आधार पर जाँच करे कि उसमें तीसरे अध्याय में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं होता। यहाँ न्यायपालिका किसी कानून को केवल इस आधार पर गैर-कानूनी घोषित कर सकती है कि उसकी रचना से राज्य ने सविधान द्वारा आरोपित सीमाओं का उल्लंघन किया है। इसी सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मूल अधिकारों के संरक्षक की भूमिका अदा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की इस भूमिका पर प्रकाश डालते हुए 'रामसिंह बनाम दिल्ली राज्य' नामक मुकदमे में अपना निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति बोस ने यह कहा था—

'यह देखना हमारा कर्तव्य और अधिकार है कि वे अधिकार जिन्हें मौलिक बनाया गया था, वे मौलिक ही रहे और हम यह भी देखें कि वह सदन और कार्यपालिका इन स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबन्ध लगाते समय उन सीमाओं का उल्लंघन न करें जिन्हें सविधान ने उन पर आरोपित किया है तथा कार्यपालिका के सम्बन्ध में हम यह देखें कि वह सदन द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर विचरने न पाये। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि भारतीय जनता को वे सब स्वतन्त्रताएँ उपलब्ध होतीं रहे जिनका उन्हें आश्वासन दिया गया है तथा सदन द्वारा पारित कानूनों अथवा कार्यपालिका के कार्यकलापों के द्वारा उनका महत्त्व कम न होने पाये।'

भारतीय सविधान में निहित विशिष्ट अधिकार

जैसा कहा जा चुका है कि भारतीय सविधान में मूल अधिकारों को निम्न सात शीर्षकों में बाँटा गया है—(1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) वार्षिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, (6) सम्पत्ति का अधिकार, तथा (7) साविधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ उपर्युक्त सातों प्रकार के अधिकारों की विवेचना आवश्यक है।

(1) समानता का अधिकार (Right to Equality)—समानता का अधिकार सविधान की 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं धाराओं में निहित है। 14वीं धारा नागरिकों तथा गैर-नागरिकों दोनों को 'कानून के समक्ष समानता' (Equality before laws) तथा 'कानूनों का

समान मरक्षण (Equal protection of laws) का आश्वामन होती है। कानून के समान समानता का अर्थ मूल रूप से प्रजासत्ताकीय यायावस्था का अभाव है तथा प्रत्येक नागरिक को चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्या न हो एक ही कानून के द्वारा शासित मानना है। कानूना का समान मरक्षण गणराज्यीय सत्ता के सब नागरिकों को अपने सुख को प्राप्त करने का तथा सम्पत्ति का प्राप्त करने और उसका उपभोग करने का समान अधिकार होना चाहिए तथा उन्हें अपने अधिकार तथा सम्पत्ति के मरक्षण के लिए अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए तथा कानून के कायाबयन के लिए यायावस्था के पालन का समान अधिकार है किसी के कायबयन पर ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए जो समान परिस्थितियों में अन्य नागरिकों पर न लगाया जाये एक व्यवस्था तथा परिस्थिति में किसी के ऊपर अन्य नागरिकों पर आरोपित बाध से अधिक बाध आरोपित न हो किया जाना चाहिए जो ज़रूरी याय के प्रशासन में किसी व्यक्ति पर समान अपराधों के लिए दूसरों से भिन्न अथवा दूसरों से अधिक दण्ड न दिया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित न निषेधात्मक एवं स्वीकारात्मक दोनों अर्थों में समानता का आश्वामन किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि 14वां धारा की व्याख्या करते समय हमारे मन की याय पानिका न कानून के समान समानता गणराज्यीय की गणभंग उपस्था की है और उसके स्थान पर उसने कानूना के समान मरक्षण गणराज्यीय को ही मुख्य ध्यान में रखा है। 14वीं धारा की यायिक यायका में यह स्पष्ट है कि उसमें निहित समानता का अधिकार असीमित नहीं है। वह कब तक एक ही स्थिति में रहने वाला एक ही नागरिक के बीच में समानता का आश्वामन होती है उससे उम समानता का आश्वामन प्राप्त नहीं होता जो सब नागरिकों का चाहें उनका सामाजिक स्थिति कभी भी क्या न हो एक ही बर्तव्य की गारंटी दे सकें।

इस नीति के अन्तर्गत आने वाली अन्य धाराएँ भी उन्हीं मायताओं पर आधारित हैं। 15वां धारा में कहा गया है कि राज्य केवल घरेलू रंग जाति निग जन्म-स्थान अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक का किसी दुकान अथवा सावजनिक जगह में रहने से अथवा कुछ जलायवा नती के घाटा मड़रा तथा ऐसे सावजनिक प्रयोग के स्थानों में न जाने रोका जा सकता जिनका कायम रखने का व्यय या तो पूणतः अथवा आंशिक रूप में राज्य के द्वारा होता है अथवा जिन्हें सावजनिक प्रयोग के लिए समर्पित कर दिया गया है। परन्तु इस धारा में इस अधिकार के दो अपवाद भी गिनाये गये हैं। प्रथम वह राज्य का म्रिया तथा बच्चा के लिए विनाय ध्वस्त्य कर को अनुमति होती है और द्वितीय वह राज्य का इस बात की भी पूरा देती है कि वह सामाजिक तथा नागरिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों अथवा परिगणित जातियों तथा परिगणित क्षेत्रों के विकास के लिए विनाय प्रावधानों की रचना कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस धारा में ये आधार परिगणित हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वीकारात्मक दृष्टि में राज्य इन आधारों का छोड़कर अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। उदाहरणार्थ वह भेदभाव का भाषा राष्ट्रीयता परिवार व्यवसाय आदि पर अथवा उनमें से किसी एक पर आधारित कर सकता है। इसमें होने वाले भी इस धारा का अर्थ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि वह घरेलू रंग जाति अथवा निग के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करके वह राज्य एकता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

16वां धारा के द्वारा प्रत्येक नागरिक को नौकरों पान अथवा राज्य के अधीन किसी पर नियुक्ति हान के मामले में समान अवसर का आश्वामन किया गया है तथा उममें यह भी कहा गया है कि इस मामले में केवल घरेलू रंग जाति निग का परम्परा जन्म-स्थान निवास स्थान अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। इस धारा में

आगे इसके तीन अपवाद बताये गये हैं—पहले अपवाद के अनुसार राज्य को कुछ विशिष्ट पदों के लिए निवास योग्यताएँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। द्वितीय अपवाद के अनुसार राज्य को पिछड़े हुए वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखने की अनुमति दी गई है और अन्तिम अपवाद के अनुसार किसी भी धार्मिक संस्था के प्रबन्ध को इस धारा की परिधि से बाहर रखा गया है।

17वीं धारा के अनुसार छुआछूत का अन्त करने की घोषणा की गई है तथा कहा गया है कि वह कानून द्वारा दण्डनीय अपराध है। संविधान की यह व्यवस्था निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा युगों से चली आ रही एक सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया गया है। जैनिंग्स ने लिखा है कि छुआछूत का खात्मा कोई अधिकार नहीं है, उससे तो केवल एक सामाजिक अयोग्यता दूर होती है। परन्तु इसके होते हुए भी यह एक मूल अधिकार है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि अधिकार उन अन्यायों के उपचार हैं जिनका व्यक्तियों पर आगोपण या तो राज्य के द्वारा हुआ है और या समाज के द्वारा।

18वीं धारा के द्वारा राज्य के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वह सैनिक अथवा शैक्षिक खिताबों के अतिरिक्त किसी अन्य खिताब से अपने नागरिकों को अलङ्कृत नहीं करेगा। कुछ लोगों का विश्वास है कि भारत-रत्न, पद्मविभूषण आदि खिताबों की परम्परा को चालू करके सरकार ने 18वीं धारा की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वस्तुतः 1 मई 1969 को आचार्य जे० वी० कृपलानी ने लोकसभा में इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा गया कि राज्य द्वारा व्यक्तियों को इस प्रकार अलङ्कृत करने की परम्परा का अन्त किया जाये। इस विधेयक पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वतन्त्रता के पूर्व जो काम अंग्रेज करते थे उस काम को उसने 'पिछले दरवाजे' से फिर अपने शासन-तन्त्र में स्थान दे दिया है।

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)—स्वतन्त्रता का अधिकार संविधान की चार धाराओं—19, 20, 21 और 22—में निहित है।

19वीं धारा उदार लोकतन्त्र में सन्निहित परम्परागत वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं का आश्वासन देती है ये स्वतन्त्रताएँ अग्रलिखित हैं—भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण ढंग में तथा बिना हथियारों के एक स्थान पर एकत्रित होने की स्वतन्त्रता, समुदाय अथवा सघ बनाने की स्वतन्त्रता, समस्त भारत में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरने की स्वतन्त्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने अथवा बस जाने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा देवने की स्वतन्त्रता तथा कोई भी व्यवसाय करने अथवा कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतन्त्रता। इन स्वतन्त्रताओं का महत्त्व स्वयंसिद्ध है। वस्तुतः उनकी अनुपस्थिति में किसी भी लोकतांत्रिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान-निर्माता इस तथ्य में अवगत थे, परन्तु वे इस बात से भी अपरिचित नहीं थे कि व्यक्ति को दी जाने वाली अनियन्त्रित स्वतन्त्रता समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। इसलिए 19वीं धारा में न केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है, अपितु उसमें इन स्वतन्त्रताओं के अपवादों का भी उल्लेख किया गया है।

भाषण और विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की सात सीमाएँ इस धारा में बताई गई हैं। मूल संविधान में सीमाएँ केवल चार थीं। परन्तु 1951 में 'रमेश यापर बनाम मद्रास राज्य' नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त उसमें सशोषण करना आवश्यक हो गया। अतः पहले सशोषण (1951) के अनुसार उसमें तीन सीमाएँ और जोड़ी गईं। इस प्रकार 11वीं धारा में जैसी वह आज है, भाषण और विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सात प्रतिबन्ध, आगोपित करती हैं। ये प्रतिबन्ध हैं—राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के प्रतिकूल कोई जाचरण, न्यायालय का अपमान, किसी को बदनाम करने की चेष्टा, अथवा हिसात्मक कार्यवाहियों के लिए उकसाना। यही यह बात विशेष रूप में उल्लेखनीय है कि विचार-अभिव्यक्ति में प्रेम की स्वतन्त्रता भी

सम्मिलित है। शान्तिपूर्ण तरीके से तथा बिना हथियारों के एक स्थान पर एकत्रित होने का स्वतन्त्रता वास्तव में विचार अभिव्यक्ति तथा भाषण की स्वतन्त्रता का पूरक है। इस स्वतन्त्रता पर मात्र जनिक व्यवस्था तथा नतिकता के हित में याय-मगन प्रतिरोध लगाया जा सकता है।

समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता की यायावरी न दो प्रकार से व्याख्या की है। एक पक्ष अथ म्बीमात्मक है जिसका अभिप्राय है कि कोई भी नागरिक स्वच्छा में चाह जिस समुदाय अथवा संगठन का सम्पन्न बन सकता है। दूसरा पक्ष जय निषिद्धात्मक है जिसका अभिप्राय यह है कि किसी भी नागरिक का उसका च्छा के प्रतिरूप किसी समुदाय अथवा संगठन का सम्पन्न बनने के लिए बाध्य न हो किया जा सकता है। इस स्वतन्त्रता का भी मात्रजनिक व्यवस्था तथा नतिकता के हित में म्वाप्ति किया जा सकता है। अपने एक मन्त्वपूर्ण निषय में सर्वोच्च यायावरी न यह मन प्त किया है कि इस अधिकार पर का भी प्रतिरोध तब तक न हो लाया जा सकता जब तक कि उस प्रतिरोध के आधारा की किसी यायिक अधिकार के द्वारा समुचित जाँच न हो जाय।¹

19वां धारा न द्वारा प्रत्यक्ष भारतीय नागरिक के समूह देश में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरने तथा किसी भाग में निवास करने तथा वहाँ स्थायी रूप में वस जान तथा सम्पत्ति प्राप्त करने उस रखने तथा उस वचन के अधिकार का मायता न है। इन स्वतन्त्रताओं को सामान्य जनता के हित में जयवा किसी अनुमूचित कवीन के हितों की रक्षा के लिए म्वाप्ति किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय का करने की स्वतन्त्रता पर राज्य मात्रजनिक हित में कुछ प्रतिरोध लगा सकता है तथा कुछ व्यवसायों को करने के लिए कुछ नातिक यायताएँ भी निर्धारित कर सकता है।

संविधान का 20 में लेकर 22वां धारा तक व्यक्ति के जीवन तथा वयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 20वां धारा में उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है जिस पर किसी अपराध का करने का आरोप लगाया गया है। इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक दण्डित न हो किया जा सकता जब तक कि अपराध करने के समय उसने किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और न वह उसमें जिरफ रूप का पात्र लगा जा उस अपराध का करने के समय उस प्रचलित कानून के अधीन लिया जा सकता था। इसके अनुरित्त (1) का पत्ति एक ही अपराध के लिए एक बार में अधिक अभियोगित और दण्डित न हो किया जा सकता तथा (2) किसी अपराध में अभियुक्त का स्वयं अपने विरुद्ध शवाही देने के लिए बाध्य न हो किया जा सकता। उपर्युक्त धारा के प्रथम भाग का प्रभाव यह लाता कि राज्य का कानून न हो बना सकता जा किमा घीती हूँ घटना पर लागू हो सक।

21वां अनुच्छेद में कहा गया है कि किमा भी व्यक्ति न अपने जीवन जयवा न्हिक स्वतन्त्रता में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) को छाँवर किसी अन्य प्रकार में वचिन न हो किया जायगा। इस अनुच्छेद में मुख्य रूप कानून (law) है। यथा कानून से अभिप्राय समस्त जयवा रायों के विधानमण्डल द्वारा निमित्त कानून में है। न के मागलन बनाम मन्म राय नामक मुकदमे में सर्वोच्च यायावरी न कानून शब्द की यथा व्याख्या की है। इस प्रकार भारतीय संविधान में यायिक समीक्षा का त्र पयाप्त रूप से सीमित कर दिया गया है। इस यथ भी स्पष्ट है कि जावन तथा नातिक स्वतन्त्रता के अधिकारों का भारतीय संविधान असीमित न हो मानता है कि विपरीत उसमें इस अधिकार के त्र का मागिन कर दिया है।

22वां धारा में गिरफ्तार व्यक्तियों का तान अधिकारों का जायवामन दिया गया है प्रथम उक्त इस धारा का आशयमान किया गया कि उक्त उनकी गिरफ्तारी के कारणों में सूचित

किया जायगा, द्वितीय, उन्हें इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी इच्छा के वकील से परामर्श करे तथा उससे अपना बचाव कराये तथा अन्तिम उन्हें इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि उनकी गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा तथा उन्हें हिरासत में केवल उसके आदेश के आधार पर ही आगे रखा जा सकेगा। यह अधिकार उन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हो सकता जिनका विदेशी शत्रु-राष्ट्र के साथ सम्बन्ध है तथा द्वितीय, इस अधिकार का दावा वे लोग नहीं कर सकते जिन्हें किसी निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। अनुच्छेद की अन्य उपधाराओं (4 से 7 तक) में यह व्यवस्था की गई है कि साधारणतः किसी व्यक्ति को तीन महीने की अवधि से अधिक बिना मुकदमा चलाये जेल में नहीं रखा जायगा, परन्तु यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से निर्मित परामर्शदात्री मण्डल अपने प्रतिवेदन में उनकी नजरबन्दी की अवधि को बढ़ाने की सिफारिश करे, तो ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद ससद को भी परामर्शदात्री मण्डल की सलाह के बिना किसी व्यक्ति को निवारक नजरबन्दी में रखने के लिए कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। यही नहीं, यह अनुच्छेद नजरबन्द करने वाले अधिकारी को सार्वजनिक हित में उन आधारों को न बताने की अनुमति देता है जिनके कारण उसने किसी व्यक्ति को निवारक नजरबन्दी में रखा है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में जिस अधिकार के साथ सबसे अधिक अन्याय किया गया है, वह वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार है। यह सही है कि राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी ग्रहस्तक्षेप के सिद्धान्त के लुप्त हो जाने तथा लोक-कल्याणकारी राज्य के उदय के परिणामस्वरूप व्यक्ति को असीमित स्वतन्त्रता का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। 21वीं धारा ने व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक संरक्षण से लगभग वंचित कर दिया है। स्पष्टतः संविधान की इस व्यवस्था को भारतीय गणराज्य के लोकतान्त्रिक आधारों के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में नजरबन्द करने वाला अधिकारी सार्वजनिक हित में यह बताने से भी इनकार कर सकता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इस स्थिति में नजरबन्द व्यक्ति बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी प्रस्तुत नहीं कर सकता तथा न्यायालय उसकी सहायता करने से विवश है। स्पष्टतः इन अन्यायपूर्ण प्रावधानों को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सम्भवतः भारत में निहित स्वार्थों ने जिन्हें प्रोफेसर के० टी० शाह के शब्दों में संविधान सभा में 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था' ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें।

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Rights against Exploitation)—यह अधिकार संविधान के 23वें और 24वें अनुच्छेदों में सन्निहित है। 23वाँ अनुच्छेद मानव के क्रय-विक्रय, और बेगार और जबरदस्ती काम करने के अन्य स्वरूपों का निषेध करता है तथा यह घोषणा करता है कि इस प्रावधान का उल्लंघन कानून द्वारा दण्डनीय अपराध है। परन्तु इसी अनुच्छेद की दूसरी उपधारा में इस अधिकार का एक अपवाद बताया गया है और वह यह है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकेगा। यद्यपि 'सार्वजनिक प्रयोजन' शब्दावली की कहीं व्याख्या नहीं की गई, तथापि उसका उद्देश्य स्पष्ट है। उसके अन्तर्गत समूची जाति का हित आता है उसमें किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों के समुदाय के हित को शामिल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष में कम की आयु के किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान अथवा किसी अन्य सकट-युक्त नौकरी में काम पर नहीं लगाया जा सकता।

उपर्युक्त दोनों अनुच्छेद लोक-कल्याणकारी राज्य की आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। 24वीं धारा तो एक प्रकार से संविधान के चौथे अध्याय के 39(c) तथा 45 अनुच्छेदों के

कायाचयन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि नयार करती है। 45वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य युद्ध के हितों पर विचार ध्यान देगा तथा उनका शिक्षा का प्राप्ताधिकार करेगा। 39(e) द्वारा मंजूर है कि राज्य वंचना की दृष्टि से आयु का दुस्प्रयोग नहीं होना देगा तथा उन्हें आर्थिक आवश्यकता से विरक्त होकर एक व्यवसायी में नहीं बदल देगा जो उनके लिए आयु तथा शक्ति के लिए अनुपयुक्त है। इन अनुच्छेदों के बीच पाये जाने वाले सामान्य को अंगीकृत किया जा सकता है।

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Religious Rights)—धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान की चार धाराओं में—25, 26, 27 और 28 में उल्लेख हुआ है। पहले बताया जा चुका है कि कांग्रेस कंसिडरेशन मिशन के सामने इस बात के लिए बचनबद्ध थी कि भविष्य में भारत के लिए जा भी संविधान निर्मित होगा उसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जायेगी। यथाथ 14वीं धारा के द्वारा संविधान में कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण का आश्वासन दिया जा चुका था तथा इसी अनुच्छेद में यह बात स्पष्ट रूप से मंजूर की गई थी कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। परन्तु बहुत से अल्पसंख्यकों को आश्वासन का अपर्याप्त मानते थे कि इसके अतिरिक्त कुछ और संरक्षण चाहते थे। अतः उक्त संविधान में जो अन्य व्यवस्थाएँ दी गई हैं वे निम्न प्रकार हैं—

अनुच्छेद 25—सांख्यिक व्यवस्था, सत्ताचार एवं स्वास्थ्य तथा इस अर्थों के अन्य प्राविधानों के रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति का अन्तर्करण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अन्तर्गत रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार है। परन्तु इस अधिकार से किसी एक वर्तमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव न पड़ेगा अथवा राज्य द्वारा एक कानून में धार्मिक हानि—(अ) जो धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की नीतिगत क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्वहन करनी हो अथवा हिंसा की सांख्यिक धर्म समस्याओं को हिंसा के संभावित वर्गों और विभागों के नियंत्रणता है।

व्याख्या—(1) कृपाण धारण करना के त्वर चरना मित्र धर्म का अंग समझा जायेगा। (2) उपर्युक्त मन्दिर में हिंसा में सिकन्दर धर्म जन अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी सम्मिलित समझा जायेगा।

अनुच्छेद 26—सभी व्यक्तियों का सांख्यिक व्यवस्था, सत्ताचार और स्वास्थ्य के अधिन रहते हुए अपने धार्मिक सम्प्रदाय या किसी विभाग की (अ) धार्मिक समस्याओं की स्थापना (आ) धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबंध (इ) जगम तथा यावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व तथा (ई) एका सम्पत्ति के कानून द्वारा प्रशासन करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 27—किसी भी व्यक्ति का एक बरतन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी धर्म विषय अथवा धार्मिक सम्प्रदाय का उत्पत्ति अथवा पोषण में व्यय करने के लिए विशिष्ट रूप से विनियुक्त कर देना है।

अनुच्छेद 28—राज्य निम्नलिखित पूर्णरूप से पात किन्हीं गिना समस्याओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे जायेगा। परन्तु यह व्यवस्था किसी एकी शिक्षा समस्या पर लागू न होगी जिनका प्रशासन तत्काल करता है परन्तु जिसकी स्थापना किसी एक धर्म के अथवा धर्मों के आश्रित हुई है। जिनके अनुसार उस समस्या में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्य में अभिजात अथवा राज्य से आर्थिक सहायता पाने वाली शिक्षा समस्या में पहले वाले किसी व्यक्ति को एकी समस्या में दाखिल करने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अथवा उसमें या उसमें लग स्थान में दाखिल करने वाली धार्मिक उपस्थिति में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत में यह बात स्पष्ट है कि उनमें कोई भारतीय संविधान में राजनानि के धर्म से अलग रहने का प्रयास किया है। परन्तु संविधान की इन व्यवस्थाओं का संविधानसभा के धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की नीति का आवश्यक परिणाम बनाया जा सकता है।

(5) सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)—सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सविधान की 29वीं और 30वीं धाराओं में उल्लिखित हैं। यथार्थ में इन प्राविधानों का उद्देश्य धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करना है। 29वाँ अनुच्छेद प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा उसकी अपनी संस्कृति को कायम रखने तथा उसका संवर्धन करने के आधार का आश्वासन देता है तथा साथ में ही वह यह व्यवस्था भी करता है कि किसी भी नागरिक को किसी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूलवश, जाति तथा उनमें से से किसी एक के आधार पर प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकता। 30वाँ अनुच्छेद समस्त अल्पसंख्यकों को चाहे उनकी रचना धर्म के आधार पर हुई हो या भाषा के आधार पर, यह अधिकार उपलब्ध कराता है कि वे अपनी शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करें तथा उन्हें यह आश्वासन दिलाता है कि अनुदान देते समय राज्य किसी संस्था के विरुद्ध धर्म अथवा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

सविधान की उपर्युक्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि ये निर्दोष नहीं हैं। वस्तुतः वे संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों को उन अधिकारों के उपभोग की भी अनुमति नहीं देती जिनका आश्वासन उन्हें सविधान की 15वीं धारा के द्वारा दिया गया था। 15वीं धारा में कहा गया था कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति जन्म-स्थान अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा, परन्तु 29वीं धारा में 'जन्म-स्थान' शब्द छोड़ दिया गया है। इस सम्बन्ध में के० वी० राव का यह कथन उल्लेखनीय है—'29वीं धारा शिक्षा के अधिकारों पर घातक प्रहार करती है—उसको छोड़ देने से हमें 14वीं, 15वीं और 19वीं धाराओं के अन्तर्गत अधिक अच्छे अधिकार उपलब्ध हो सकते हैं।'¹ 29वीं धारा के सम्बन्ध में एक और कठिनाई है और वह कठिनाई यह है कि 'संस्कृति' शब्द से क्या अभिप्राय है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे देश में संस्कृति शब्द का प्रयोग सामान्यतः उन मूल्यों के लिये होता है जो हमारे जीवन के सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक पहलुओं के साथ सम्बद्ध हैं। और यदि 29वीं धारा हमारी उस संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करती है जिनसे हमारे देश की सामाजिक रूढ़ियों का प्रतिनिधित्व होता है, तो निस्सन्देह वह प्रतिगामी है। सम्भवतः सविधानकारों का यह उद्देश्य कदापि नहीं था, और उनसे यह भूल अनजाने में हो गई हो। परन्तु इतना होते हुए भी इस भूल की गम्भीरता से इनकार नहीं किया जा सकता।

यहाँ 30वीं धारा के सम्बन्ध में भी यह कहने की आवश्यकता है कि उसकी व्यवस्थाएँ भी पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं हैं। उसने सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे उनकी रचना भाषा के आधार पर हुई हो अथवा धर्म के आधार पर अपनी शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा उन्हें चलाने का अधिकार दिया है। भाषावार अल्पसंख्यकों की बात समझ में आ सकती है, परन्तु धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देना निश्चय ही गलत है। अनुभव साक्षी है कि इस प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ हर सम्भव प्रकार के सम्प्रदायवाद और जातिवाद को जन्म देती हैं। वस्तुतः राज्य की धर्मनिरपेक्षता के लिये इस प्रकार की संस्थाएँ सबसे बड़ी चुनौती हैं।

(6) सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)—सविधान में सम्पत्ति के अधिकार का उल्लेख दो स्थानों पर हुआ है—धारा 19(f) में तथा धारा 31 में। इस सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है वह यह है कि सविधान में सम्पत्ति के अधिकार की व्यवस्था दो स्थानों पर क्यों हुई, अन्य अधिकारों की भाँति एक ही स्थान पर क्यों नहीं, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें दोनों धाराओं की पृष्ठभूमि ध्यान में रखनी चाहिये। 19वीं धारा एक प्रकार की स्वतन्त्रता की व्यवस्था करती है जिसका उपभोग भारतीय नागरिक कर सकते हैं, जबकि

31वा धारा उस स्वतन्त्रता में व्यक्ति को वंचित करने का अधिकार राज्य का सौंपती है तथा वह यह भी बताता है कि राज्य अपने अधिकार का प्रयोग किस प्रकार करेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 31वा धारा में जब तक चार संशोधन हो चुके हैं और प्रत्यक्ष संशोधन की रचना सर्वोच्च न्यायालय की ही समझ में शक्ति का कम बल के उद्देश्य से है। वस्तुतः इस अनुच्छेद के ऊपर जितना विचार किया गया है, तन्ना सविधान के किसी अन्य प्राविधान पर नहीं पाया जाता। इस अनुच्छेद में सम्बद्ध मुक्तम भी सबसे अधिक सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचे हैं। साथ ही इस अनुच्छेद की जा याथा सर्वोच्च न्यायालय ने की है वह हमारा एकमात्र नहीं रहती है। जब ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में व्यापक रूप भ्रम पाये जायें। यहाँ हमको विस्तृत विवरण आवश्यक है।

भारत में सम्पत्ति में सम्बन्ध सविधानिक प्राविधानों की रचना एक निश्चित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुई है। सविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था तथा कांग्रेस बहुत दिनों से आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए बहुत से कानूनी सुधारों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी शामिल था। अपने 1945 के चुनाव घोषणा पत्र के द्वारा उसने देश की जनता के समक्ष अपने इस मत को दुहराया था कि वह जमींदारी का उन्मूलन करेगा परन्तु उसके लिए वह जमींदारों का उचित मुआवजा देगी। जब सविधान की रचना हुई तो उसमें मुआवज का ता उल्लेख किया गया परन्तु मुआवजा का वह उचित जयवा यायपूर्ण रूप का प्रयोग नहीं किया गया तथा यह कहा गया कि मुआवज की राशि अथवा उस राशि को निर्धारित करने वाले मिट्टाता का निर्धारण व्यवस्थापिका के द्वारा होगा। इसमें यह भी कहा गया कि यदि इस प्रकार का कानून किसी राज्य विधानमण्डल के द्वारा निर्मित हुआ है तो उसका कार्यविधि उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि उस राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जायगी। अनुच्छेद में उचित अथवा यायपूर्ण रूप का प्रयोग जान-बूझकर नहीं किया गया था क्योंकि इनके प्रयोग में मुक्तमराजों को बढ़ावा मिल सकता था। कोई भी व्यक्ति उस कानून को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दे सकता था कि उसमें जो मुआवज की राशि निश्चित की गयी है वह पर्याप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में शायद देश के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए गांधीदेव ने यह पत्र लिखा था— हम हर एक को उचित मुआवजा देना चाहते हैं परन्तु हम किसी मामले में मुक्तमराजों में नहीं उलझना चाहते। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधानकारों का यह दृष्टिकोण था कि मुआवज की राशि के निर्धारण में अन्तिम रूप व्यवस्थापिका का होना चाहिए न्यायपालिका का नहीं।

परन्तु यह दृष्टिकोण न्यायपालिका का नहीं था। रामेश्वर सिंह यनाम बिहार राज्य मुक्तम में पटना उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि न्यायालय मुआवज के प्रश्न की जाँच करने में सक्षम है कि तब तक यह तब तक कि उस कानून में शायद मूल अधिकारों से सम्बद्ध प्राविधानों—उल्लेख के लिए 14वा धारा—का उल्लंघन न हो रहा हो। इस दृष्टिकोण का अपनाकर पटना उच्च न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार कानून 1950 का अवध घोषित कर दिया। बाद में पटना उच्च न्यायालय के इस निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन कर दिया तथा उसने उन धाराओं का भी स्वीकार कर दिया जिनके ऊपर पटना उच्च न्यायालय ने इस कानून का अवध उल्लेख था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधान की व्यवस्थाओं का भूमि सुधार कानून का न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बाहर रहने में सफलता नहीं मिल सकी। इस स्थिति का निराकरण करने के लिए 31वा धारा में संशोधन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। पहले सविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम 1951 पारित किया गया जिसके अनुसार 31वा धारा में दो अर्थ धाराएँ—31 A तथा 31 B—जोड़ी गयी तथा उसके साथ ही सविधान में एक नई सूची (9वा) जोड़ी गयी। अनुच्छेद 31 A में यह कहा गया कि कोई कानून जिसमें राज्य किसी सम्पत्ति की प्राप्ति सम्पत्ति अथवा उक्त अधिकार का संशोधन अथवा भावजनिक हित में उक्त

प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेने को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उसके द्वारा अनुच्छेद 14, 19, अथवा 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन होता है। अनुच्छेद 31B के द्वारा 9वीं सूची को जोड़ने की व्यवस्था की गयी, जिसमें 13 जमींदारी उन्मूलन कानूनों का उल्लेख था तथा जिनकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

थोड़े ही दिनों में यह अनुभव किया गया कि 31वें अनुच्छेद में जो सशोधन किये गये थे, उनसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर राज्य द्वारा अधिकार स्थापित करने वाले अधिनियमों को न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र से दूर नहीं रखा जा सकता था। 1953 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'द्वारिकादास श्रीनिवास बनाम शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी' नामक मुकदमे में बम्बई उच्च न्यायालय को उलट कर शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी (एमरजेन्सी प्रोवीजन्स) ऑर्डिनेन्स 1950 को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि उसमें कम्पनी को समुचित मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं की गयी थी। राज्य की तरफ से इस मुकदमे में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि उसने कम्पनी की सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं किया है, उसने तो केवल उसके प्रबन्ध को अपने हाथ में इसलिए लिया है क्योंकि उसका प्रबन्धक-मण्डल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था तथा अगस्त 1949 में उसने बिना किसी पूर्व सूचना के मिल को यकायक बन्द करके अपने 13000 मजदूरों को बेरोजगार कर दिया था तथा राष्ट्र को 25 लाख गज कपड़ा और 15 लाख गज सूत की क्षति पहुँचाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में जो दृष्टिकोण अपनाया, उसने 31वीं धारा में दूसरे सशोधन को आवश्यक बना दिया। फलतः सविधान (चतुर्थ सशोधन) अधिनियम 1955 की रचना हुई, जिसने 31वीं धारा में एक नवीन उपधारा (2 A) को जोड़ा। इनमें यह व्यवस्था की गई कि मुआवजे के किसी प्रश्न को किसी ऐसे कानून को अवैध ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के स्वामित्व को राज्य अथवा राज्य के अधीन अथवा राज्य द्वारा नियन्त्रित किसी निगम को हस्तान्तरित किया गया हो।

कुछ क्षेत्रों में इन सशोधनों की आलोचना की गयी है और कहा गया है कि इनके कारण सम्पत्ति के अधिकार की वादयोग्यता (justiciability) नष्ट हो गयी है। यह प्रश्न जब 1967 में 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत हुआ तो इसने 6-5 के बहुमत से 17वें सशोधन को यह कहकर अवैध घोषित कर दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के द्वारा समद को तीसरे अघ्याय के प्राविधानों को सशोधित करने का अधिकार नहीं है। यह स्वाभाविक था कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की देश में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती। कुछ विधिवेत्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी सविधान की इस व्याख्या को अनुचित ठहराया है।

यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से समद की शक्ति कम हुई है तथा न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। वस्तुतः यह स्थिति सविधानकारों की इच्छा के सर्वथा प्रतिकूल है। जैसा कहा जा चुका है श्री नेहरू ने सविधान सभा में यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई भी न्यायालय समद के कामों पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। अतः स्वाभाविक रूप से इस निर्णय ने समद में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति पहले नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत विधेयक में हुई और बाद में उनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 25वाँ सशोधन पारित किया गया। इस सशोधन के द्वारा समद को वह शक्ति वापिस दिलायी गयी जो उसे गोलकनाथ के मुकदमे में दिये गये निर्णय के पूर्व प्राप्त थी। इन सशोधन में निम्न व्यवस्थाएँ की गयी हैं—

(1) राज्य जिस सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित करेगा, उसके लिए समद अथवा राज्य के विधानमण्डलों को बाजार की दर पर मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। जो मुआवजा वे निश्चित कर देंगे वही अन्तिम होगा। वह राशि जो व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण है तथा राष्ट्र के लिए अन्यायपूर्ण है, उसे न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह बात विधायक ही निश्चित कर सकते हैं कि

गण्ट म उस सम्पत्ति क लिए दन की क्या क्षमता है जिस उसने अपन हित म प्राप्त किया है।

(2) 14 19 और 31 अनुच्छेद म जिन अधिकार का आश्वासन दिया गया है उन्हें एम सामाजिक तथा आर्थिक कानूनों को रद्द करने के लिए माध्यम नहीं बनाया जा सकता जिनका उद्देश्य सम्पत्ति की एकाधिकारी प्रवृत्तियों का रोकना है।

(3) इस प्रकार के कानूनों को निर्मित करने के बाद मसद अथवा रायों के विधानमण्डल के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दें कि उन्होंने उस कानून की रचना किसी नीति निर्देशक सिद्धांत का कार्यान्वित करने के लिए की है। यदि उस कानून के साथ म इस प्रकार का प्रमाण-पत्र मेलन है तो 'यायानय' 14 19 और 31 अनुच्छेद के प्राविधानों का प्रयोग म 'दाकर' इस कानून का अवध घोषित नहीं कर सकते।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संविधान में सन्निहित सम्पत्ति का अधिकार अभी भी विवाद प्रस्त है। 31वां भाग के प्राविधान सामाजिक प्रगति की ओर दृष्टि के अभियान को रोकने के लिए ही अभी तक प्रयुक्त हुए हैं। 1969 में जबकि के राष्ट्रीयकरण के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि मुआवजे की राशि बाजार की दर पर आधारित होना चाहिए तथा उसके साथ में सम्पत्ति के स्वामियों को उनकी सद्भावना (Goodwill) के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि हम स्वीकार कर लिया गया तब तो का भी प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक कानून बन ही नहीं सकता। 25वां संशोधन इसी दुरन्तता का दूर करने का प्रयास करता है।

(7) सांविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)—संविधान की 32वां भाग भारत के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार प्रदान करती है कि वे अपने अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। इस अधिकार का मौखिक अधिकार घोषित करके संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की यथायथा रक्षा हा जाती है और यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार कबन पवित्र नहीं हैं। साथ ही इन अधिकारों का कार्यान्वित करने के लिए कृत-संकल्प है। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका का मौखिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करके भारतीय संविधान निमाताओं ने राजनैतिक दायित्व की धारणा को पुष्ट किया है। इस प्राविधान के अनुसार यदि किसी नागरिक के किसी मूल अधिकार का अनिष्टमण किसी शासक या आदेश अधिनियम या विनियम के द्वारा होने की शिकायत हो तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में निवेदन करके उनका निराकरण करा सकता है। इस हेतु न्यायालय के नीचे प्रत्येकीकरण (Habeas Corpus) परमादेश (Mandamus) प्रतिषेध (Prohibition) अधिकार-पट्टा (Quo Warranto) तथा उत्प्रेषण (Certiorari) द्वारा सम्बद्ध पक्षों का यायानय द्वारा अंतिम निर्णय देने तक सरकारी आदेशों का प्रभाव होने से रोक सकता है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय एम किसी आदेश या अधिनियम का संविधान के प्राविधानों के प्रतिपक्ष या उनमें असंगत होने पर अवध घोषित कर सकता है।

राय के नीति निर्देशक सिद्धांत

ऊपर कहा जा चुका है कि संविधानकारों ने मूल अधिकारों का 14 भाग में विभाजित कर दिया था। वे अधिकार जिनका प्रतिनिधि निषेधात्मक था तथा जो 18वां और 19वां भागों के आश्वासनों परम्परागत में मेल गान थे उन्हें मूल अधिकारों के नाम से पुकारा गया। परन्तु जिन अधिकारों का प्रतिनिधि स्वायत्तात्मक था तथा जिनका अनुपस्थिति में नाक-बन्धनकाराण राय तथा समाजवादी समाज के रचना का कल्पना भी नहीं हो सकती थी उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों का मर्यादा प्रदान की गई तथा यह कहा गया कि वे उन रायों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका प्राप्त करने का आशय नागरिकों के हितों में होगा।

नीति-निर्देशक मिहान्तो को कार्यान्वित करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है अतः उनके उत्पन्न की स्थिति में कोई भी भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। संविधान मन्त्रालय में डा० अम्बेदेकर ने यह मत व्यक्त किया था कि उनकी तुलना 1935 के अधिनियम में निहित उन निर्देशनों से की जा सकती है जो प्रांतों के गवर्नरों को उनकी नियुक्ति के समय दिए जाते थे। इन दोनों में केवल एक ही अंतर है—1935 के अधिनियम में निर्देश केवल कार्यपालिका को दिए जाने की व्यवस्था थी तबहीं मन्त्रिपरिषद् ने उन्हें व्यवस्थापिका को भी दिया जाता है। 25वें संशोधन के पारित होने पर कार्यपालिका में भी उनके पालन की अपेक्षा की जाती है।

नीति-निर्देशक मिहान्त केवल भारतीय मन्त्रिपरिषद् की अंतर्हीन विशेषता नहीं है उनकी व्यवस्था इसके पूर्व आयरलैंड के संविधान में की जा चुकी थी। 1947 में वहाँ के संविधान में भी इन्हें स्थान दिया गया था। 1951 में विभिन्न नेपाल के संविधान में तथा 1952 में आईरलैंड के संविधान में भी इन मिहान्तों को मनाविष्ट किया गया था।

मूल अधिकार बनाम निर्देशक सिद्धान्त

अनुभव साक्षी है कि संविधान में निहित नीति निर्देशक सिद्धान्तों एवं मूल अधिकारों के बीच कभी-कभी विरोध की स्थिति पाई जाती है। उदाहरण के लिए 47 और 48 अनुच्छेदों को निजा ले सकता है। 47वें अनुच्छेद में राज्य को यह शक्ति सौंपा गया है कि वह मनु-निषेध की दिशा में कदम उठाये तथा अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य गो-हत्या को रोकने का प्रयत्न करे। उक्त दोनों अनुच्छेदों का संविधान की 19 (f) (g) धारा में कोई मेल नहीं है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य छोड़े में स्थानियों के पक्ष में उनके समर्थन को रोकने का प्रयत्न करेगा। स्पष्टतः इन अनुच्छेदों की और 31वीं धारा की व्यवस्थाओं में कोई मेल नहीं है। मूल अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तों के बीच पाये जाने वाले विरोध की परिस्थिति मन्त्रालय सरकार के मान्यशासिक आदेश (Communal order) में हुई। इस मुकदमे की उत्पत्ति मन्त्रालय सरकार के मान्यशासिक आदेश (Communal order) में हुई। इस आदेश के अनुसार मन्त्रालय बोरोराजन्त का मैजिस्ट्रेट कालिज में एवम् इस आदेश पर नहीं दिया जा था क्योंकि वह मर्का बाह्य थी और कालिज में सीटें अभावों के लिए सुरक्षित थी। अपनी याचिका में बोरोराजन्त ने मर्कारी आदेश को अनुच्छेद 15 (1) तथा 29 (2) में मरिहित मूल अधिकारों पर आघात लगाया था। सरकार ने इसके विरुद्ध यह तर्क दिया कि उसका आदेश अनुच्छेद 46 के प्रावधानों में मेल खाता है जिन्में यह कहा गया है कि राज्य समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा-मन्त्रालय तथा आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देगा। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि निर्देशक सिद्धान्त जिनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट व्यवस्था कि उन्हें न्यायपालिका के द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। नीचे अज्ञात के प्रावधानों का अन्वित नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में यह स्पष्ट है कि इन सिद्धान्तों की अपेक्षा मूल अधिकारों का मानविक मूल्य कहीं अधिक है।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों का विश्लेषण

निर्देशक सिद्धान्तों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—मानव सिद्धान्त, आर्थिक सिद्धान्त तथा सामाजिक सिद्धान्त।

(1) सामाजिक सिद्धान्त—इन श्रेणियों में छोटे अंशों की 36, 37, 48 और 49वीं धाराएँ पानी हैं। 36वें अनुच्छेद में राज्य मनु की व्यवस्था की गई है। 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि इन सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के द्वारा नहीं कर दी जा सकती। मन्त्रालय सरकार ने इन सिद्धान्तों को मौखिक सम्झौता बनाया चाहिए तथा राज्य को यह तर्क होना चाहिए कि वह कानूनों की रचना करने में इन सिद्धान्तों का ध्यान करे। 48वें अनुच्छेद में

कहा गया है कि राज्य का वित्तनिर्वाह आधार पर वृष्टि एवं वसुपात्रन से विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उस से हत्या का रोकने की भी वागदानी करनी चाहिए। 49व अनुच्छेद में राज्य का यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह कृषि-विकास तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों की रक्षा करे।

(2) आर्थिक मिशन—इस नीति के अंतर्गत अनुच्छेद 38 39 41 42 43 45 46 और 47 का रखा जा सकता है। इनका उद्देश्य उन जातियों को प्राप्त करना है जिनका उत्थान विधान की प्रस्तावना में किया गया था तथा जो नाक-कल्याणकारी राज्य के मुख्य आधार हैं। 38वें अनुच्छेद में दिया है कि राज्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करने का प्रयत्न करेगा जिसमें सामाजिक राजनीति तथा आर्थिक वायु राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं को अनुप्राणित करे। अनुच्छेद 39 में कुछ विषय निर्दिष्ट किए गए हैं। राज्य अपनी शक्ति का संचालन इस प्रकार करेगा कि (अ) सभी नागरिकों का समान रूप से विकास के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों (आ) दश के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार होगा कि जिसमें सामूहिक हित प्राप्त हो सकें (इ) आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी वर्णन न हो (ई) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का ही समान कार्य के लिए समान वेतन मिले (उ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति और मानसिक अवस्था का दुरुपयोग न हो (ऊ) श्रम और किसानों की अवस्था का सुधारण के भौतिक और आर्थिक परिचायक न हों।

अनुच्छेद 41 में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह अपनी क्षमता के अन्तर्गत लोगों को काम मिलाने के लिए बराबर के वेतन, बीमा तथा शारीरिक और मानसिक अवस्था की स्थिति सामाजिक समता प्राप्त करने के अधिकारों की व्यवस्था करे।

अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की पर्याप्त एवं मानवीय परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयत्न करे।

अनुच्छेद 43 में राज्य का यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह वृष्टि तथा उद्योग में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक का गुजर-पार कर सज्जगी अर्द्धा जीवन स्तर तथा अवकाश उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे।

अनुच्छेद 45 में राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि विधान के कार्यावली के 10 वर्ष के भीतर उस 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

अनुच्छेद 46 में राज्य की यह जिम्मेदारी बताई गई है कि उस समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामर्थ्य तथा जातिगत अन्धकारों की अभिवृद्धि का प्रयत्न करना चाहिए।

अनुच्छेद 47 में राज्य का यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह लोगों के जीवन स्तर तथा पोषण के स्तर का ऊंचा उठान का प्रयास करना चाहिए।

उपरोक्त विवेचना में स्पष्ट है कि इन मिशनों की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचारों का कोई संतुलन नहीं हो सकता। वस्तुतः इनका आधार पर देश में एक नया समाज की रचना हो सकती है जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन सभी भारतीय नागरिकों का उपलब्ध हो सकेगा।

(3) कानूनी मिशन—कानूनी मिशन चार अध्यायों की 44वां और 50वां प्रांगण में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य का सम्बन्ध नागरिकों के लिए एक ही अन्तर्गत कानून (Civil Code) की रचना करना चाहिए। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक-दूसरे में घुसकर चलने पर रोक दिया गया है।

विधान का उपयोग इन व्यवस्थाओं का सर्वोत्तम स्वयं मिश्र है। 44वां प्रांगण का सम्बन्ध सम्मेलन के लिए यह है कि राज्य को अपने अधिकारों में अन्तर्गत कानून का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए।

धर्म का एक अंग माना गया है तो अधिक उपयोगी होगा। चूँकि भारत में अनेक मतावलम्बी पाये जाते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि यहाँ बहुत सी आचार संहिताएँ भी पायी जाती हैं। इस प्रकार मुसलमानों की अपनी आचार संहिता है जिसे वे 'व्यक्तिगत कानून' (Personal Law) के नाम से पुकारते हैं तथा हिन्दुओं में कम से कम तीन आचार संहिताएँ पायी जाती हैं—मयूख, मिताक्षर और दयाभाग। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि धर्मान्ध लोगो ने सदैव से इन संहिताओं को ईश्वर प्रदत्त बताया है तथा उनकी पवित्रता को अनुलघनीय प्रमाणित करने का प्रयास किया है। परन्तु देश की राष्ट्रीय एकता के लिए आचार संहिताओं की इस बहुलता का अन्त किया जाना परमावश्यक था। अतः संविधान की इस व्यवस्था को शुभ समझा जाना चाहिए।

निर्देशक सिद्धान्तों का मूल्यांकन

आरम्भ से ही इन सिद्धान्तों की विविध प्रकार से आलोचना की गई है। संविधान सभा में इनके सम्बन्ध में प्रो० के० टी० शाह ने कहा था कि ये 'उस चैंक के समान हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।' कुछ अन्य आलोचकों ने इन सिद्धान्तों को पवित्र आकांक्षाओं का सग्रह-मात्र कहा है। परन्तु इतना होते हुए भी इनके महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता।

वस्तुतः इन सिद्धान्तों को राज्य की आचार संहिता बताया जा सकता है। राज्य में चाहे जो दल सत्तारूढ हो, उसके लिए यह वाञ्छनीय है कि वह इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करे। इस सम्बन्ध में पायली ने यह ठीक ही लिखा है कि 'निर्देशक सिद्धान्तों का महत्त्व इस बात में है कि वे नागरिक के प्रति राज्य के दायित्व के द्योतक हैं। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये दायित्व महत्त्वहीन हैं और इसकी पूर्ति होने पर भारत की सामाजिक व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आयेगा। वस्तुतः ये क्रान्तिकारी गुणों से ओतप्रोत हैं। यही कारण है कि निर्देशक सिद्धान्तों को संविधान का अभिन्न अंग बनाया गया है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धान्तों द्वारा भारतीय संविधान व्यक्ति स्वातन्त्र्य की घातक, भेदभाव वर्गों की तानाशाही, तथा जनसाधारण की सुरक्षा में बाधक होने वाले पूँजीवादी अल्पतन्त्र की दोनों चरम सीमाओं में सन्तुलन स्थापित करता है।'

प्रश्न

- 1 भारतीय संविधान में प्रस्तावना के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
- 2 संविधान में सन्निहित समानता के अधिकार पर एक निबन्ध लिखिए।
- 3 संविधान में स्वतन्त्रता के अधिकार के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध किये गये हैं? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
- 4 भारतीय संविधान में सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? अभी तक इस अधिकार के क्षेत्र में जितने संशोधन हुए हैं, उन्हें ध्यान में रखकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
- 5 'राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों से सम्बद्ध अध्याय में उच्च कोटि की भ्रान्तियाँ, अनेक पवित्र आकांक्षाएँ तथा कुछ ऐसे अधिकार वर्णित हैं, जिनकी संविधान द्वारा गारण्टी की जा सकती थी।' विवेचना कीजिए।

संघीय कार्यपालिका (THE UNION EXECUTIVE)

संघ जयवा राया की कार्यपालिका का अध्ययन करते समय यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि उनकी रचना ब्रिटेन की संसदीय पद्धति के अनुरूप की गई है जिसके दो मुख्य तथ्य हैं—पहला तथ्य कि कार्यपालिकाएं होती हैं एक औपचारिक और दूसरी वास्तविक दूसरा तथ्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निरुद्ध का सम्बन्ध होता है। यद्यपि भारतीय संघ का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति आनुवंशिक न होकर निर्वाचित अधिकारी है तथापि भारतीय मंत्रिमण्डल ब्रिटिश कबिनेट की ही भांति शक्तिमान है। वह तब तक अपना काम करती है जब तक कि उस संसद के प्रथम सदन का विश्वास प्राप्त है। कुछ विद्वान् इस तथ्य से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें अध्यक्षीय प्रणाली के तत्त्व विद्यमान हैं। उनका कहना है कि संविधान के कुछ प्राविधानों ने राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से अधिकार प्रदान किये हैं। आगे बोलें पृष्ठा में हम इस मत की विवेचना करेंगे।

1. राष्ट्रपति ✓

भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं और वह उनका प्रयोग या तो स्वयं प्रत्यक्ष या फिर जयवा संविधान के प्राविधानों के अनुरूप अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है।

निर्वाचन

किसी भी नागरिक कार्यपालिका की रचना करने समय जो समस्याएँ सबसे पहले प्रस्तुत होती हैं वह यह है कि राज्य के राज्य के निर्वाचन किस प्रकार किया जाय। संविधान की 54वाँ और 55वाँ धाराओं में इस समस्या को सुनिश्चाने की विधि बताई गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से मानवप्रातिक प्रतिनिधित्व की एक नम्रमणीय पद्धति के आधार पर एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मण्डल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में दो बातें मुख्य हैं—पहली उसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकत्रितता कायम रखने के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। दूसरी उसमें इस बात का भी मान्यता दी गई है कि संघ एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व के साथ समता कायम रखी जाय। फलतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में परिणाम मतों का माधारेण गणना से निर्धारित नहीं होता बल्कि मतों का निम्न फलान से मान निर्धारित जाना है—

किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य

राज्य की जनसंख्या

विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या — 1000

इस प्रकार समस्त के सदस्य के मत का मूल्य

राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल योग
संसद के दोनों सभों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या

1962 तक कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रत्याशी पहली ही गिनती में बहुत अधिक मत से निर्वाचित हो जाया करता था। परन्तु 1967 के चौथे आम चुनाव में अनेक राज्यों के विधान-मण्डलो में कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रही तथा सदन में भी उसका पहले की भाँति बहुमत नहीं रहा। फलतः मई 1967 में जब राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हुआ तो उस समय कांग्रेसी उम्मीदवार डा० जाकिर हुसैन को विरोधी दलों द्वारा मनोनीत प्रत्याशी के० सुब्बाराव के साथ कड़ा मुकाबिला करना पड़ा। यद्यपि डा० जाकिर हुसैन पहली ही गिनती के उपरान्त निर्वाचित घोषित कर दिये गये थे, तथापि उन्हें वह बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था जो इससे पूर्व तीन चुनावों में कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ था। डा० जाकिर हुसैन का देहान्त उनके कार्यकाल में ही हो गया, अतः 1969 में राष्ट्रपति के पद के लिए पाँचवीं बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में परिस्थिति में इसलिए और जटिलता उत्पन्न हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अधिकांश कांग्रेसी सदस्यों ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम सजीव रेड्डी का विरोध करने का निर्णय किया था। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बी० बी० गिरि निर्वाचित घोषित हुए, परन्तु ऐसा तभी हो सका जबकि दूसरी पसन्द के मतों की भी गणना कर ली गई। इस प्रकार पहली बार एक पद के लिए निर्वाचन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का महत्त्व स्पष्ट हुआ। इस पद्धति के अन्तर्गत एक उम्मीदवार प्रथम गणना में अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त करने के उपरान्त भी चुनाव में हार सकता है। उसके लिए चुनाव जीतने के लिए केवल यह आवश्यक नहीं है कि उसे अपने प्रतिद्वन्दी की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त हों, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह विजयी घोषित होने के लिए निर्धारित मतों को भी प्राप्त करने में सफल हो। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि उसे वैध मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए संविधान में यह व्यवस्था है कि निर्वाचित प्रत्याशी को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान में निर्वाचन की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें प्रत्येक मतदाता को अपनी पहली, दूसरी, तीसरी आदि पसन्द बताने का अवसर दिया गया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि किसी निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को प्रथम पसन्द के आधे से अधिक मत प्राप्त न हो तो उस स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को जिसे सबसे कम मत मिले हो विलोपित कर दिया जायेगा तथा उसकी दूसरी पसन्द के मतों को अन्य उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। यह विलोपन की प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ, वैध मतों की कुल संख्या 15000 है और मधुर में 4 प्रत्याशी हैं, चुने जाने के लिए प्रत्याशी को 7501 मत प्राप्त करने चाहिए। परन्तु 4 उम्मीदवारों को मत इस प्रकार प्राप्त होते हैं—(अ) 5250, (ब) 4800, (न) 2700, तथा (द) 2250। चूंकि द को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं इसलिए उसे विलोपित कर दिया जायेगा। उसके 2250 मतपत्रों पर दूसरी पसन्द इस प्रकार है—(अ) के पक्ष में 300, (ब) के पक्ष में 1050, और (स) के पक्ष में 900। दूसरी पसन्द की गणना के उपरान्त स्थिति यह हो जाती है—(अ) $5250 + 300 = 5550$, (ब) $4800 + 1050 = 5850$ और (न) $2700 + 900 = 3600$ । इस गणना में ब के मत अ के मतों में घट जाते हैं। परन्तु न विलोपित हो जाना है। उसके 3600 मतपत्रों पर तीसरी पसन्द के मत इस प्रकार हैं—(अ) 1700 और (ब) 1900। जब उन्हें हस्तान्तरित किया जाता है तो उम्मीदवार ब के कुल मत 7750 हो जाते हैं और उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

विधान निर्वाचन में 17 प्रत्याशियों ने भाग लिया था, किन्तु इनमें से 9 तो कोई भी मत प्राप्त नहीं हुआ। यथायथ में बाल्मिकि मधुर बी० बी० गिरि और सजीव रेड्डी के बीच था, उनके अतिरिक्त एक तीसरे उम्मेदवारी प्रत्याशी डा० नी० टी० देशमुख थे जिन्हें जनमध, स्वतन्त्र पार्टी तथा भारतीय रान्ति दल ने समुक्त रूप में वोट दिया था। दोनों प्रमुख उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या इस प्रकार थी—गिरि 420676 और रेड्डी 405427। डा० देशमुख को केवल

है—(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ, (ब) विधायी शक्तियाँ, (स) वित्तीय शक्तियाँ, तथा (द) सकट-कालीन शक्तियाँ । यहाँ इन शक्तियों की विस्तारपूर्वक विवेचना की आवश्यकता है ।

✓(अ) राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ—सविधान ने भारतीय सघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित बतायी हैं । कार्यपालिका शक्तियों के अन्तर्गत प्रशासकीय, राजनयिक, सैनिक, न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक और यहाँ तक कि एक सीमा तक विधायी सभी प्रकार की शक्तियाँ शामिल हैं । सविधान में लिखा है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिका सम्बन्धी काम राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित होंगे । वही सरकार के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन के लिये नियम बनायेगा । वह प्रशासन का औपचारिक अध्यक्ष है तथा सभी सघीय अधिकारी, चाहे उनका सम्बन्ध सैनिक सेवा के साथ हो या असैनिक सेवाओं के साथ, वे सब उसके अधीन हैं ।

राष्ट्रपति को सघीय अधिकारियों को नियुक्त करने की व्यापक शक्ति प्रदान की गई है । जिन अधिकारियों की नियुक्ति उसके द्वारा होती है उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—प्रधानमन्त्री तथा अन्य सघीय मन्त्री, महाधिवक्ता, नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के गवर्नर, राजदूत तथा अन्य राजनयिक अधिकारी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और अनुसूचित वर्गों के लिये विशेष अधिकारी । इनके अतिरिक्त वह विभिन्न आयोगों को भी नियुक्त करता है, जैसे वित्त आयोग, भाषा आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग आदि । उसे मन्त्रियों, राज्यों के गवर्नरों, महाधिवक्ता, तथा सेना के उच्च अधिकारियों को पदच्युत करने का भी अधिकार है ।

राष्ट्रपति देश की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है । राज्य के अध्यक्ष होने के नाते वह सभी प्रकार के राजनयिक विशेषाधिकारों का अधिकारी है । वह अपने देश के सभी राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तथा बाहर से आने वाले सभी विदेशी राजदूत उसी को अपने पद के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं । यही नहीं, सभी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों और समझौतों उसी के नाम से किये जाते हैं ।

ब्रिटिश राजा की भाँति, भारतीय राष्ट्रपति भी न्याय एवं सम्मान का स्रोत है । उसे अपराधियों को क्षमा करने, उनको दिये गये दण्ड को कम करने तथा उसमें छूट देने का अधिकार है । यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उसका यह अधिकार निम्नलिखित तीन स्थितियों में लागू होता है—(1) जहाँ कोई व्यक्ति किसी सैनिक न्यायालय के द्वारा दण्डित हुआ हो, (2) जहाँ दण्ड किसी सघीय कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया हो, (3) ऐसे सभी मामलों में जहाँ अपराधी को मृत्यु-दण्ड दिया गया हो । राष्ट्रपति विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित भी करता है, भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण तथा पद्मश्री आदि उपाधियों के माध्यम से वह उन्हें उनकी सेवाओं के लिए अलंकृत करता है ।

जैसा कहा जा चुका है, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है तथा प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा होती है । परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चाहे जिसको प्रधानमन्त्री नियुक्त कर सकता है । वस्तुतः इस सम्बन्ध में उसकी शक्तियाँ अत्यधिक सीमित हैं क्योंकि दलगत राजनीति की विवशताओं के कारण वह लोकसभा में बहुमत के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है । इस सम्बन्ध में सविधान की व्यवस्था यह है कि प्रधानमन्त्री तथा उसके मन्त्रिमण्डल को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए । प्रधानमन्त्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए, परन्तु साधारणतः यह आशा की जाती है कि वह लोकसभा का सदस्य होगा । 1966 में लालबहादुर शास्त्री के देहान्त के उपरान्त श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था, यद्यपि उस समय वे राज्य सभा की सदस्य थीं, लोकसभा की नहीं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री को नियुक्त करने की शक्ति नावैधानिक औपचारिकता में अधिक कुछ नहीं है । परन्तु यह औपचारिक शक्ति उन समय

कालान्तर में ससद की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। राष्ट्रपति को समय-समय पर वित्त आयोग को नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त है तथा इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर वह आयकर से प्राप्त होने वाली आय में से विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली राशि को निर्धारित करता है। इसी प्रकार वह यह भी निश्चित करता है कि पटसन के निर्यातकर की आय में से कुछ राज्यों को बदले में क्या धनराशि मिलनी चाहिए। अन्त में, राष्ट्रपति भूतपूर्व राजाओं को दी जाने वाली प्रिवीपर्स में विभिन्न राज्यों को कितना योगदान है, यह निर्धारित करता है।

(द) सकटकालीन शक्तियाँ—भारतीय संविधान में सकटकालीन प्राविधान उसके 18वें अध्याय में सन्निहित है। वस्तुतः ससार के अन्य लोकतान्त्रिक संविधानों में इन प्राविधानों का समानान्तर खोजना कठिन है। संविधान सभा में इन आशकाओं को व्यक्त भी किया गया था। इस मत को व्यक्त करते हुए एच० वी० कामथ ने कहा था कि संविधान के उल्लंघन की सम्भावना केवल आन्दोलनकारियों, विद्रोहियों एवं क्रान्तिकारियों के द्वारा ही नहीं है, अपितु उन लोगों के द्वारा भी है जो सत्तारूढ हैं। डा० पंजावराम देशमुख ने इस आशका को व्यक्त किया था कि 'मन्त्री राष्ट्रपति में निहित शक्तियों को चुनाव के उद्देश्य के लिए काम में ला सकते हैं तथा वे चुनाव के विलकुल पूर्व सकटकाल की घोषणा कर सकते हैं और इस प्रकार वे दूसरे दल का दमन कर सकते हैं और वे राष्ट्रपति को सौंपी गई शक्तियों का दलगत हितों के लिए प्रयोग कर सकते हैं।'।

संविधान में तीन प्रकार की सकटकालीन अवस्थाओं का उल्लेख है जो निम्नलिखित हैं—

(अ) भारत की अथवा उसके किसी एक भाग की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न होने पर (352वीं धारा)।

(ब) राज्यों में सांविधानिक यन्त्र के असफल होने की स्थिति में (356वीं धारा)।

(स) भारत अथवा उसके किसी एक भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख के लिए खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में (360वीं धारा)।

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त तीनों प्रकार की सकटकालीन अवस्थाओं के घोषित होने पर राज्यों की स्वायत्तता का अतिक्रमण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सकट की घोषणा 352वीं धारा के अन्तर्गत हुई है तो उस स्थिति में केन्द्र को शक्तियों के सघीय विभाजन की अवहेलना करके राज्यों की सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 352वीं धारा के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि संविधान में उसकी अवधि की कोई सीमा नहीं बताई गई है, उसकी सीमा निर्धारित करने का काम केवल कार्यपालिका को सौंपा गया है। वस्तुतः ऐसा होना उचित भी है क्योंकि कार्यपालिका अधिकारी ही इस बात को समझता है कि सकट की घोषणा को कब वापिस लिया जाये। यथार्थ में 352वीं धारा में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आपत्ति की जा सके। परन्तु यह बात 356वीं धारा के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसे राज्यों में अपना शासन स्थापित कर सकता है, 'जहाँ राज्य का शासन इस संविधान के प्राविधानों के अनुसार निष्पादित नहीं किया जा सकता।' राष्ट्रपति को इस धारा ने यह शक्ति प्रदान की है कि वह या तो राज्य के गवर्नर से इस आज्ञा का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा उनके बिना ही इस आज्ञा की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति को गवर्नर के प्रतिवेदन की अनुपस्थिति में इस प्रकार की घोषणा करने के अधिकार का औचित्य बताते हुए डाक्टर जम्बेदकर ने संविधान सभा में यह तर्क प्रस्तुत किया था कि 355वें अनुच्छेद में सघ की सरकार को जो दायित्व सौंपे गये हैं, उनका पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की जाये। 355वें अनुच्छेद में लिखा है—'सघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य

है कि राष्ट्रपति के पास 'वास्तविक' शक्तियाँ हैं तथा वह उनका प्रयोग अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। उदाहरण के लिए एलन ग्लैडहिल (Alan Gladhill) ने लिखा है कि 'राष्ट्रपति सविधान का उल्लंघन किये बिना सत्तावादी सरकार की स्थापना कर सकता है।' इस प्रकार के ० एम० मुन्शी ने राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसकी कुछ शक्तियाँ मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण से परे (Supra-ministerial) हैं तथा उनके निष्पादन के लिए वह मन्त्रिमण्डल के परामर्श का सहारा नहीं ले सकता। मुन्शी ने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि सविधानकार राष्ट्रपति को ब्रिटिश राजा के सदृश नहीं बनाना चाहते थे। ब्रिटिश परम्परा में राजा सदैव मन्त्रियों के परामर्श पर काम करता है, परन्तु सविधान में इस प्रकार की व्यवस्था कही भी नहीं की गई। मुन्शी ने आगे कहा है कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ से बंधा हुआ है, शपथ में कहा गया है कि वह निष्ठापूर्वक सविधान को कायम रखने तथा उसकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति के पद से सम्बद्ध कार्यों का निष्पादन करेगा तथा वह देश की जनता के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए उनकी सेवा में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस आधार पर सविधान ने राष्ट्रपति को सविधान एवं देश की जनता दोनों के ही संरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा है। मुन्शी का तीसरा तर्क यह है कि राष्ट्रपति संसद का आत्मज नहीं है और न उसका मनोनयन केन्द्र में स्थित सत्ताखंड दल के द्वारा होता है। इसके विपरीत वह समूचे राज्य का एक स्वतन्त्र अभिकरण है तथा उसे स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी शक्तियों को संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यपालिका अधिकारी नहीं है, वह सघीय मन्त्रियों से भिन्न जो केवल संसद के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, समूचे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मुन्शी का यह भी तर्क है कि यदि राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रधानमंत्री को हस्तान्तरित कर दिया जायगा तो उससे भारतीय सविधान के सघात्मक स्वरूप का पूर्णरूप से हनन हो जायेगा।

यथार्थ में मुन्शी के उपर्युक्त दृष्टिकोण से सहमत होना कठिन है। यदि इस सम्बन्ध में सविधानकारों की इच्छा को जानने का प्रयास किया जाए, तो सविधान सभा में इस प्रश्न पर हुई बहस के समय अनेक सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत में राष्ट्रपति को केवल औपचारिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सविधान सभा में किसी भी सदस्य ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया कि राष्ट्रपति को सत्ता का एक स्वतन्त्र अभिकरण होना चाहिए। सच बात तो यह है कि सभा के अधिकांश सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की थी सविधान की व्यवस्थाएँ कहीं उनकी इच्छाओं की पूर्णरूप से कार्यान्विति में कहीं असफल तो नहीं होंगी। अतः यह स्पष्ट है कि सविधान सभा की बहस के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा के सदृश वास्तविक शक्ति से वंचित नहीं है।

सविधान में राष्ट्रपति की स्थिति को समझने के लिए एक ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उसने मन्त्रिमण्डल को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि लोकतान्त्रिक प्रणाली में वास्तविक शक्ति उस अभिकरण को सौंपी जाती है जिसको उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए अपने स्वतन्त्र विवेक का प्रयोग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तथा मन्त्रिमण्डल के परामर्श की अवहेलना करता है तो मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे सकता है। चूंकि संसद में वैकल्पिक सरकार की रचना की सम्भावनाएँ बहुत कम हैं, अतः यह आवश्यक ही है कि लोकसभा भंग कर दी जाए तथा दुबारा चुनाव कराये जायें। यदि नये निर्वाचन में केबिनेट द्वारा पर्याप्त शक्ति से सत्ताखंड हो जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना सुनिश्चित है। यह सोचना गलत है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल सविधान के उल्लंघन की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, तथा मन्त्रिमण्डल के परामर्श को नवीकार न करना सविधान का उल्लंघन नहीं है। वस्तुतः सविधान का उल्लंघन कोई नाविधानिक प्रश्न नहीं है, वह एक राजनीतिक प्रश्न है और उसका निर्णय किन्हीं

भी सदन का अथवा किसी भी राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं रह सकता। अतः यदि कोई सदन अथवा किसी राज्य विधानमण्डल का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसके लिए व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्यागपत्र देना आवश्यक है।

उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और इस अवधि में या तो वह स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकता है, अथवा उसे राज्य सभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, हटाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि उसका नोटिस कम से कम 14 दिन पूर्व दिया जाए।

कार्य—सविधान ने उपराष्ट्रपति को कोई विशेष काम नहीं सौंपे है, उसे केवल एक औपचारिक काम सौंपा गया है, और वह है राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। राज्य सभा के अध्यक्ष की हैसियत से ही उसको 2250 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इस दृष्टि से भारतीय उपराष्ट्रपति अमरीकी उपराष्ट्रपति के सदृश है। परन्तु दोनों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण अन्तर है। यदि संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो वहाँ उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति के पद का भार सम्भालता है। किन्तु यह व्यवस्था भारत में नहीं पाई जाती। हमारे देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद से सम्बद्ध कार्यों का संचालन केवल उस समय तक कर सकता है जब तक कि नये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका के एक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति ने यह कहा था—‘मैं कुछ भी नहीं हूँ, परन्तु मैं सब कुछ बन सकता हूँ।’ भारत का उपराष्ट्रपति केवल एक लम्बी साँस लेकर यह कह सकता है—‘मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हो सकता।’

हरि मोहन जैन ने उपराष्ट्रपति के पद को भारत के लिए अनावश्यक बताया है। उनका कहना है कि संयुक्त राज्य अमरीका जैसी अध्यक्षतात्मक शासन-प्रणाली में इसका औचित्य हो सकता है, किन्तु भारत में उसका कोई औचित्य नहीं है। अतः उन्होंने कहा है कि या तो इस पद का अन्त कर देना चाहिए और या उसका सुधार होना चाहिये। जैन ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने की व्यवस्था सविधान में की जानी चाहिए। जैन का यह भी सुझाव है कि उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव की वही पद्धति अपनायी जानी चाहिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयोग में लायी जाती है।

3 प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रि-परिषद्

जैसा कहा जा चुका है राष्ट्रपति कार्यपालिका का साविधानिक अध्यक्ष है, अतः वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मन्त्रि-परिषद् में निवास करती हैं। सत्य यह है कि मन्त्रि-परिषद् ही उन समस्त शक्तियों का निष्पादन करता है जिन्हें सैद्धान्तिक रूप से राष्ट्रपति में निहित माना गया है। यहाँ ‘मन्त्रि-परिषद्’ एवं ‘केबिनेट’ के बीच भेद करने की आवश्यकता है। सविधान में केवल ‘मन्त्रि-परिषद्’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। ‘केबिनेट’ एक अनौपचारिक संस्था है और उसमें सभी मन्त्री शामिल नहीं माने जाते। वस्तुतः वह मन्त्रि-परिषद् का ही एक भाग है, दूसरे शब्दों में वह चक्र के भीतर एक चक्र है। मन्त्रि-परिषद् में तीन कनिष्ठ मन्त्री भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य-मन्त्री तथा उप-मन्त्री के नामों से पुकारा जाता है। ये मन्त्री केबिनेट स्तर के नहीं होते, अतः मन्त्रि-परिषद् की नीति के निर्माण में इनका कोई विशेष योगदान नहीं होता। इनके अतिरिक्त कुछ ससदीय सचिव (Parliamentary Secretaries) भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती अपितु जिन्हें प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। अतः स्पष्ट है कि इन मन्त्रियों में सबसे ऊँची श्रेणी केबिनेट मन्त्रियों की होती है। केबिनेट में दल के वरिष्ठ सदस्यों को स्थान दिया जाता है, सरकार की नीतियों का निर्धारण उन्हीं के द्वारा होता है। केबिनेट के सदस्यों की सत्या निश्चित नहीं है, परन्तु वह अभी तक 19 से ऊपर नहीं गयी है।

रहती। नेहरू जी के प्रधानमन्त्रित्व काल के आरम्भिक दिनों में राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्य नेता भी भारत के राजनीतिक रणमंच पर उपस्थित थे। इन नेताओं में सरदार पटेल, मोलाना आजाद और गोविन्दवल्लभ पन्त के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्पष्टतः स्वाधीनता संग्राम के इन वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसलिए सविधान के व्यवहार में आने के बाद यदि नेहरू जी देश के प्रधानमन्त्री बने तो उन्हें सरदार पटेल को उप-प्रधानमन्त्री बनाने के लिए विवश होना पड़ा, यद्यपि दोनों के बीच में वैचारिक साम्य न के बराबर था। पटेल के देहान्त के उपरान्त उप-प्रधानमन्त्री का पद समाप्त कर दिया गया। अतः कहा जा सकता है कि सरदार पटेल के निधन के बाद ही भारत में प्रधानमन्त्री के पद के महत्त्व में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सरदार पटेल के जीवन काल में प्रधानमन्त्री के पद का महत्त्व ही नहीं था, महत्त्व तो था, किन्तु यह महत्त्व 'समान व्यक्तियों में प्रथम' से कुछ ही अधिक था। बाद में नेहरू जी का अपने मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण नियन्त्रण था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में नेहरू जी की अपने मन्त्रिमण्डल में स्थिति 'छोटे नक्षत्रों के बीच चाँद' की थी।

नेहरू जी के निधन के बाद 1971 के मध्यावधि चुनावों तक प्रधानमन्त्री की स्थिति 'समान लोगों में प्रथम' (First among the equals) से अधिक की नहीं थी। परन्तु 1971 के चुनावों के परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में निखार आया है और अब वह निस्सन्देह अपने मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण रूप से हावी है।

साधारणतया भारत जैसी कार्यपालिका को ससदीय कार्यपालिका की सज्ञा प्रदान की जाती है। जैसा कहा जा चुका है ससदीय कार्यपालिका उस कार्यपालिका को कहते हैं जिसकी रचना और जिसका विघटन ससद भवन में हो। परन्तु यह केवल सैद्धान्तिक बात है और यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसका राजनीतिक यथार्थ में कोई सम्बन्ध नहीं है। आज लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त है उसको देखते हुए इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि वर्तमान कैबिनेट को कभी ससद के द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। अतः आज के सन्दर्भ में यदि यह कहा जाय कि 'ससदीय कार्यपालिका' शब्दावली सार्थक नहीं है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में प्रधानमन्त्री की शक्तियों का विकास हुआ है तथा जिस अनुपात में प्रधानमन्त्री की शक्तियों में वृद्धि हुई है, उसी अनुपात में ससद एवं कैबिनेट की शक्तियों का पराभव हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि आधुनिक कार्यपालिका को 'प्रधानमन्त्रीय प्रणाली की सरकार' घोषित किया जाय तो वह अनुपयुक्त नहीं होगा।

कुछ लोगों ने प्रधानमन्त्री की इस बटती हुई प्रतिष्ठा को देश में लोकतन्त्र के विकास के लिए अशुभ बताया है। इस प्रकार के दृष्टिकोण को मानने वालों का कहना है कि भारत में राजनीतिक सत्ता पर केवल एक राजनीतिक दल का एकाधिकार है और उस दल में सम्पूची शक्तियाँ एक व्यक्ति यानी प्रधानमन्त्री में केन्द्रित हैं। इस प्रकार की परिस्थितियाँ लोकतान्त्रिक प्रवृत्तियों को बड़ावा देने के स्थान पर अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बड़ावा देगी। भारतीय प्रधानमन्त्री के विरुद्ध इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। वस्तुतः यह स्वाभाविक बात है कि विकानशील देशों में इस प्रकार के नेतृत्व का उदय हो जो अपने यहाँ की जनता को मन्त्रमुग्ध रख सके। देश तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, प्रधानमन्त्री ने जनता को यह आश्वासन दिया है कि वह देश को शीघ्रातिशीघ्र विकसित करेगी और वे देश में एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगी। यदि सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने में सफल नहीं होती तो जिस जनता ने उसे अपना समर्थन दिया है, उसे पदच्युत भी कर सकती है। इसलिए प्रधानमन्त्री की आधुनिक स्थिति में अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को खोजना बुद्धिसंगत नहीं है।

भारतीय कैबिनेट की कुछ मुख्य विशेषताएँ

यद्यपि भारत में कार्यपालिका का संगठन ब्रिटेन के ढाँचे पर आधारित है तथापि उनकी

उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने लिए 6 महीने के भीतर सदन के किसी भी सदन में सीट तलाश कर ले अन्यथा उसे मन्त्री पद से त्याग-पत्र देना होता है। संविधान में कहीं दोनों सदनों में से लिये जाने वाले मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, यथार्थ में यह काम प्रधान-मन्त्री के लिए छोड़ दिया गया है, इस सम्बन्ध में भारत में कोई निश्चित अभिसमय भी नहीं है। फलतः दोनों सदनों में से नियुक्त होने वाले मन्त्रियों की संख्या हमेशा बढ़ती-घटती रही है। 1966 में लालबहादुर शास्त्री के निधन के उपरान्त तो प्रधानमन्त्री की नियुक्ति भी राज्य सभा के सदस्यों में से हुई।

उपर्युक्त विवरण से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि भारतीय मन्त्री जनता से दूर रह कर सरकारी पदों पर बने रहना चाहते हैं। वस्तुतः राज्य सभा में से लिये गये मन्त्रियों ने लोक-सभा के लिए चुनाव लड़ा है और यदि चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपने मन्त्री पद से भी त्याग-पत्र दे दिया है। हाफिज मौहम्मद इब्राहीम केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे तथा उन्हें राज्य सभा में से नियुक्त किया गया था। परन्तु जब वे अमरोहा में हुए लोकसभा के उप-चुनाव में पराजित हो गये तो उन्होंने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कैबिनेट की रचना के सम्बन्ध में भारत ने उच्च लोकतांत्रिक परम्पराओं का परिचय दिया है।

(5) आन्तरिक कैबिनेट—ब्रिटेन की ही भाँति भारत में भी कैबिनेट के भीतर कैबिनेट पद्धति का विकास हुआ है। वस्तुतः यह कोई नयी बात नहीं है। 1947 में जब स्वार्थीन भारत का पहला मन्त्रिमण्डल बना था, उस समय समस्त महत्त्वपूर्ण निर्णय नेहरू और पटेल के द्वारा लिये जाते थे। फलतः इन दो व्यक्तियों को कुछ लोगों ने 'सुपर कैबिनेट' की संज्ञा प्रदान की थी। पटेल की मृत्यु के उपरान्त नेहरू अपनी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श लेते थे, यथार्थ में उन्हीं की सलाह से महत्त्वपूर्ण फैसले लिये जाते थे। आरम्भ में इन सदस्यों में आजाद, आयरगर, किदवई और देशमुख की गणना होती थी। 1958 में कृष्णमाचारी ने त्यागपत्र दे दिया और इसी वर्ष मौलाना का देहान्त हो गया। पन्त जी की 1960 में मृत्यु हो गई। इस बीच में शास्त्री जी का कुशल गृह-मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री के सहायक के रूप में उदय हुआ। कृष्ण मेनन का पर-राष्ट्र विषयक मामलों में सबसे अधिक प्रभाव था। अतः इस काल की आन्तरिक कैबिनेट में प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त शास्त्री, नन्दा और मेनन शामिल थे।

1964 में जब शास्त्री जी प्रधानमन्त्री बने तो उन्होंने भी नेहरू जी द्वारा स्थापित आन्तरिक कैबिनेट की प्रणाली को जीवित रखा। वस्तुतः उस काल में प्रधानमन्त्री की स्थिति बराबर वालों में पहले नम्बर के व्यक्ति की थी। परन्तु इसके बावजूद भी कैबिनेट के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों की अपेक्षा प्रधानमन्त्री के अधिक निकट थे। इनमें स्वर्ण सिंह, नन्दा, कृष्णमाचारी, चव्हाण और पाटिल के नाम लिये जा सकते हैं। शास्त्री जी के समय में इन्हीं मन्त्रियों के द्वारा आन्तरिक कैबिनेट की रचना हुई थी।

1966 में श्रीमती गांधी प्रधानमन्त्री बनीं। आरम्भ में चव्हाण, अशोक मेहता, सुब्रह्मण्यम और दिनेशसिंह उनके मुख्य सलाहकार थे। 1969 में कांग्रेस की फूट के समय जगजीवन राम और फखरुद्दीन अली अहमद प्रधानमन्त्री के मुख्य सलाहकार थे।

(6) प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चता—कैबिनेट प्रणाली की सरकार प्रधानमन्त्री सर्वोच्चता के सिद्धान्त पर आधारित है। प्रधानमन्त्री संसदीय दल का निर्वाचित नेता है। दल की नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में उसकी भूमिका सबसे अधिक प्रमुख है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि मन्त्रिमण्डल में अपने सहयोगियों का चयन करने में उसका हाथ सबसे अधिक हो। यथार्थ में मन्त्री अपने पदों पर केवल उसी समय तक बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें प्रधानमन्त्री का विश्वास प्राप्त है। इसी प्रकार जब नवम्बर 1966 में गुलजारीलाल नन्दा ने मन्त्रिमण्डल

नीतियों का अनुसरण किया है, वे यथार्थ में सरकार की नीतियाँ हैं।' परन्तु एक दूसरे अवसर पर स्वयं नेहरू जी इस बात को भूल गये कि सरकार की नीतियों की असफलता के लिए किसी एक मन्त्री को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए यदि किसी एक मन्त्री को उत्तरदायी ठहराना है तो वह मन्त्री केवल प्रधानमन्त्री हो सकता है। 1962 में चीन के विरुद्ध लड़े गये युद्ध में असफलता के लिए विरोधी दलों के सदस्यों ने कृष्णा मेनन को उत्तरदायी घोषित किया। यह सही है कि नेहरू जी ने सदन और जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि उत्तरी सीमान्तों पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मेनन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नेहरू जी जानते थे कि मेनन के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार के मून में निहित स्वार्थों का हाथ था, जो प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मेनन की समाजवादी नीतियों से असन्तुष्ट थे। परन्तु इसके बावजूद भी नेहरू जी मेनन की विरोधी दलों की आलोचनाओं से रक्षा करने में असमर्थ रहे। निस्सन्देह मन्त्रि-परिषद् से मेनन का त्यागपत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उल्लंघन था।

नवम्बर 1966 में जब नन्दा ने गृह-मन्त्री के पद से त्यागपत्र दिया तो उन्होंने भी इसी प्रकार की शिकायत की। इस अवसर पर प्रधानमन्त्री को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने लिखा था—'नीति-सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आप से तथा कैबिनेट के अन्य सहयोगियों से अच्छी प्रकार परामर्श लिया गया। इन नीतियों की कमियों और दोषों के लिए तथा उनकी कार्यान्विति के तरीकों में हुई गलतियों के लिए मुझे उत्तरदायी ठहराना झूठे अभियोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।' उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जो कुछ हुआ है उसके लिए वे उत्तरदायी हैं। इसी पत्र में उन्होंने प्रधानमन्त्री से पूछा कि 'क्या अवास्तविकता की राजनीति इससे आगे भी कही जा सकती है?'

सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के उल्लंघन के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। स्पष्ट है कि सरकार के मन्त्रियों ने भी अनेक अवसरों पर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है। निस्सन्देह इस स्थिति को कैबिनेट प्रणाली के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न

- 1 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? इस निर्वाचन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या महत्व है?
- 2 भारत के संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति की विवेचना कीजिये।
- 3 राष्ट्रपति की आपात्कालीन शक्तियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिये।
- 4 'प्रधानमन्त्री कैबिनेट-रूपी मेहराब की आधारशिला है'—भारतीय प्रधानमन्त्री के सदन में इस कथन की समीक्षा कीजिये।
- 5 भारतीय कैबिनेट प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ बताइये।

लिये छोड़ दे। भारतीय संविधान में इस सबकी इस रूप में व्यवस्था नहीं की गई है। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान में इस सम्बन्ध में जो भी प्राविधान पाये जाते हैं उनका अभिप्राय इसी बात के साथ है। 52वें अनुच्छेद में लिखा है कि कार्यपालिका गतिविधि राष्ट्रपति में निवास करेगी, 74वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मन्त्रि-परिषद् की व्यवस्था की गई है, 75वें अनुच्छेद में मन्त्रि-परिषद् को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। वास्तव में कार्यपालिका का चयन तथा उसको नियन्त्रित करने का काम संसद को इसी 75वीं धारा के अन्तर्गत सौंपा गया है।

संसद का दूसरा काम देश के लिए कानूनों की रचना करना है। संसद का अधिकांश समय इसी काम को सम्पादित करने में लगता है।

संसद का तीसरा काम राष्ट्र की नैतिकता को नियन्त्रित करना है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि करो का आरोपण एवं सग्रह संसद की अनुमति से ही हो सकता है (अनुच्छेद 265) तथा संसद ही सब सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि की स्वीकृति दे सकती है (अनुच्छेद 113 और 114)।

संसद का चौथा काम है प्रशासन के कार्यों की जाँच करना तथा प्रशासन को नियन्त्रित करना। वह समूचे प्रशासन की देखरेख करती है, वह मन्त्रियों से प्रशासन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछती है तथा प्रशासकीय नीतियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करती है। अतः यदि यह कहा जाये कि समूची संसदीय प्रक्रिया एक प्रकार से सरकार एवं प्रशासन को नियन्त्रित करने का एक साधन है तो यह अनुचित न होगा।

संसद का पांचवाँ काम आवश्यकता पड़ने पर संविधान सभा की भूमिका अदा करना है। संविधान के 368वें अनुच्छेद में लिखा है कि एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संसद संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है।

संसद का छठा काम राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक-मण्डल की हैसियत से काम करना है [अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 66 (1)]।

संसद का सातवाँ और अन्तिम काम आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की भूमिका निष्पादित करना है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है। इसी प्रकार वह एक प्रस्ताव के द्वारा अथवा एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उप-राष्ट्रपति को (धारा 67), लोकसभा स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर को [धारा 94 (6)], सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को [धारा 124 (4)] और महालेखा निदेशक को (धारा 148) पदच्युत कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर उसे सदन का अपमान करने पर किसी को भी दण्ड देने का अधिकार है।

उपर्युक्त विवेचना का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि संसद उक्त सभी कार्यों का सम्पादन स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करती है। वस्तुतः कैबिनेट प्रणाली की सरकार में यह सम्भव भी नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से वे काम जो संसद में अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, उनका निष्पादन यथार्थ में कैबिनेट के द्वारा होता है। उदाहरण के लिये नीतियों को निर्धारित करने का काम लिया जा सकता है। सैद्धान्तिक रूप से इसका सम्बन्ध संसद के अधिकार-क्षेत्र से है। परन्तु आधुनिक युग में यह काम इतना जटिल हो गया है कि उसको सम्पादित करने के लिये हमें विशेष योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। स्पष्टतः संसद की रचना ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नहीं होती। ऐसी स्थिति में यदि यह काम संसद के हाथों से निकल कर कैबिनेट के हाथों में चला गया तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? कुछ वर्ष पूर्व ब्रिटेन में सर एडवर्ड फेलोस (Sir Edward Fellows) की अध्यक्षता में प्रोफेसरों तथा संसद के दोनों सदनों के अधिकारियों के एक अध्ययन मण्डल ने इस समस्या का अध्ययन किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि संसदीय नियन्त्रण का अर्थ है 'प्रभाव न कि प्रत्यक्ष रूप से शक्ति, आलोचना न कि अडगा डानना, परामर्श न कि आदेश, जांच न कि पहल, विज्ञापन न कि गोपनीयता।' कैबिनेट प्रणाली

1	የ ታሪክ	91	የሀገሪ ልማት	18	የሀገሪ ልማት
1	ሥራ	95	ሥራ ልማት	91	ሥራ ልማት
1	ሥራ	01	ሥራ ልማት	6	ሥራ
2	ሥራ ልማት	11	ሥራ	11	ሥራ
3	ሥራ	10	ሥራ	2	ሥራ
1	ሥራ ልማት	1	ሥራ	7	ሥራ
4	ሥራ ልማት	19	ሥራ	18	ሥራ ልማት

✓ 1914 14 14 14 14 14 14

[illegible]

1412 142 222

१. अन्तर्गत मन्त्र की स्थिति की तम शक्ति प्रभावशीली थी मन्त्र का प्रयोग किया जा सकता है।

उसे किसी भी स्थिति में भग नहीं किया जा सकता। राज्य सभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं तथा उनमें से एक तिहाई प्रति दो वर्ष के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। भारत का उप-राष्ट्रपति पदेन उसका अध्यक्ष होता है, सदन को अपने में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है।

राज्य सभा की शक्तियाँ तथा लोकसभा के साथ उसकी तुलना—संविधान ने विधिनिरमाण के कार्य में दोनों सदनों के भाग लेने की व्यवस्था की है। वास्तव में उनके पारस्परिक सहयोग की अनुपस्थिति में विधायी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रगति सम्भव नहीं हो सकती। परन्तु इसके होते हुए भी संविधान ने कुछ मामलों में राज्य सभा की अपेक्षा लोकसभा की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। सम्भवतः इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात सदन और मन्त्रि-परिषद् के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों के साथ सम्बद्ध है। राज्य सभा को मन्त्रि-परिषद् को नियन्त्रित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि यह अधिकार लोकसभा को मिला हुआ है। राज्य सभा को मन्त्रि-परिषद् से सरकार की नीतियों और प्रशासन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, परन्तु वह मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। सदन के विश्वास का अर्थ है लोकसभा का विश्वास तथा कार्यपालिका का सदन के प्रति उत्तरदायित्व का अर्थ है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व।

द्वितीय, धन विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य सभा की शक्तियाँ नहीं के बराबर हैं। धन विधेयक का आरम्भ केवल लोकसभा में ही हो सकता है, परन्तु राज्य सभा को इन विधेयकों की जाँच करने का अधिकार अवश्य प्राप्त है। परन्तु इस सम्बन्ध में संविधान ने उसे केवल परामर्श देने की शक्ति प्रदान की है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के उपरान्त राज्य सभा के पास उसके विचार के लिये भेजा जायेगा, राज्य सभा के लिये यह आवश्यक है कि उसके ऊपर अपना निर्णय उसके प्रस्तुत होने के 14 दिन के भीतर ले ले। यदि वह उस विधेयक को पारित कर देती है तो वह मीमांसा राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए चला जाता है, यदि वह उसे अस्वीकार करती है अथवा उसे संशोधित करती है तो उस स्थिति में वह विधेयक लोकसभा के पास पुनर्विचार के लिए आ जाता है। लोकसभा उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धन विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य सभा को केवल परामर्श देने का अधिकार दिया गया है।

जहाँ तक अन्य विधायी विषयों का सम्बन्ध है, संविधान ने दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्रदान की हैं। यह बात केवल साधारण कानूनों पर ही लागू नहीं होती, संविधानिक संशोधनों पर भी लागू होती है। संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार कोई भी विधेयक किसी भी सदन में जन्म ले सकता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत करने अथवा उसे संशोधित करने का अधिकार राज्य सभा को प्राप्त है। यदि लोकसभा किसी भी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से असहमत है तो उस स्थिति में संविधान ने दोनों सदनों की एक सम्मिलित बैठक की व्यवस्था की है। चूँकि राज्य सभा की अपेक्षा लोकसभा की सदस्य-संख्या अधिक है, इसलिये दोनों सदनों के बीच संघर्ष की स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि लोकसभा राज्य सभा के ऊपर हावी हो। संयुक्त बैठक में पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की राज्य सभा जर्मनी की सीनेट की भाँति शक्तिशाली नहीं है। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि वह ब्रिटिश लार्ड सभा की भाँति शक्तिहीन है। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि लोकसभा और राज्य सभा के बीच में तीन शक्तियाँ ऐसी हैं जिन पर दोनों का समान अधिकार है। ये शक्तियाँ हैं—(1) राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसके महानियोग में भाग लेना, उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उसकी पदच्युति, और

ने प्रस्तुत किया था। इन 101 विधेयको में से 4 विधेयक वे थे जिनका सम्बन्ध हिन्दुओं के सामाजिक सुधार के साथ था, वे विधेयक थे हिन्दू विवाह कानून (Hindu Marriage Act), हिन्दू अल्प-वयस्क एवं अभिभावक कानून (Hindu Minority and Guardianship Act), हिन्दू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Act), तथा हिन्दू गोद तथा पोषण कानून (Hindu Adoptions and Maintenance Act)। इस प्रकार जैसा पी० विजयराघवन ने लिखा है— 'राज्य सभा को ऐसे कानूनों को निर्मित करने का श्रेय जाता है जिनके बारे में यह दावा उचित रूप से किया जा सकता है कि उनके द्वारा भारत के बहुसंख्यक लोगों को प्रभावित करने वाले सामाजिक सुधारों का समारम्भ हुआ है।' इसी काल में राज्य सभा में 12733 प्रश्नों की पूछने की अनुमति दी गयी, 65722 प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया, इनसे सम्बद्ध 34839 पूरक प्रश्नों के उत्तर दिये गये। 1967 तक राज्य सभा ने 26 ऐसे विधेयकों को सशोधित किया था जिनका आरम्भ लोक सभा में हुआ था। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि इन समस्त सशोधनों को लोकसभा ने स्वीकार कर लिया था।

लोकसभा और राज्य सभा के बीच पारस्परिक सम्बन्ध—मौरिस-जोन्स ने लिखा है कि 'संस्था का स्वभाव अपने सदस्यों में अपने प्रति भक्ति पैदा करना होता है और जब दो संस्थाओं की रचना एक-दूसरे के साथ-साथ की जाय तो यह स्वाभाविक है कि दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो तथा भावनाएँ उत्तेजित हों।' यह बात राज्य सभा और लोकसभा के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में भी कही जा सकती है। राज्य सभा की रचना 1952 के आम चुनाव के बाद हुई थी, तब से लेकर अभी तक बराबर केन्द्र में कांग्रेस दल का शासन रहा है और दोनों सदनों में कांग्रेस ही बहुसंख्यक दल रहा है परन्तु यह तथ्य दोनों सदनों के बीच प्रतिस्पर्धा के उदय को रोकने में असमर्थ रहा है।

राज्य सभा एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, परन्तु दोनों सदनों की शक्तियाँ अनेक अर्थों में एक-दूसरे के समान हैं, यद्यपि लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोनों सदनों की दलगत रचना भी एक-दूसरे से मिलती-जुलती है, यहाँ तक कि दोनों सदनों की वर्ग-रचना भी ऐसी नहीं है जिसके आधार पर दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभेद किया जा सके। यदि दोनों सदनों के सदस्यों की औसत आयु को ध्यान में रखा जाये तो यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सभा में लोकसभा की अपेक्षा अधिक आयु के सदस्य पाये जाते हैं। इसी प्रकार अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से भी दोनों सदनों के बीच कोई अन्तर नहीं किया जा सकता। दोनों सदनों के बीच पायी जाने वाली इस लगभग समानता ने तथा इसके साथ मिले इस तथ्य ने कि लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त है, राज्य सभा के सदस्यों में हीनता एवं निराशा की भावना को जन्म दिया है। फलतः यदि लोकसभा में राज्य सभा की स्थिति एवं शक्तियों के सम्बन्ध में ऐसा कुछ कहा गया है जिससे यह भासित हो कि राज्य सभा की स्थिति लोकसभा की समकक्ष नहीं है तो इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया राज्य सभा में अवश्य हुई है और यह नेहरू जी के इस आश्वासन के वावजूद है कि 'संविधान दोनों सदनों को समान मानता है' अथवा डा० जाकिर हुसैन के इस वयान के कि 'दोनों सदनों का अस्तित्व एक-दूसरे के साथ-साथ है तथा एक सदन दूसरे की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ नहीं है।' राज्य सभा के इस दृष्टिकोण ने लोकसभा के भीतर भी उत्तेजित भावनाओं को जन्म दिया है। इस प्रकार दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों में अपेक्षित सौहार्द की बहुधा कमी पायी गयी है।

2 लोकसभा का गठन ✓

भारतीय संसद के लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। उसका गठन एवं उसकी शक्तियाँ ब्रिटिश लोकसभा के साथ बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। उसकी सदस्य-संख्या 523

है जिसमें 521 का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 1971 के चुनाव में विभिन्न राज्यों की संघीय सभा में 521 स्थानों की अग्रिम प्रक्रिया से चयन किया गया था—

राज्य		राज्य		संघीय क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	41	महाराष्ट्र	45	मिजोरम	7
असम	14	मसूर	47	हिमाचल प्रदेश	6
बिहार	53	नामा	0	मणिपुर	2
गुजरात	24	पंजाब	13	त्रिपुरा	2
हरियाणा	9	राजस्थान	3	चंडीगढ़	1
जम्मू और कश्मीर	6	उत्तर प्रदेश	85	पाकिस्तान	1
कराच	19	पश्चिमी बंगाल	40	गदर और नागर हस्ता	1
मध्य प्रदेश	37	नागालैण्ड	1	अन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	1
तमिलनाडु	39			उत्तराखण्ड	1
				गोवा, दमन और दीव	2
				नया	1

संविधान में साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है परन्तु उन परिणामित जातियाँ एक परिणामित क्षेत्रों के नियम सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था का है। उन अधिकार अधिकारों को प्राप्त भारतीयों के मनोनीयन के नियम भी राष्ट्रपति का अधिकार प्राप्त किया है। नागरिकों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होता है। नागरिकों का संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों के नियम अर्थात् आवश्यक माना गया है—

- (1) वह भारत का नागरिक हो तथा उम्र 25 वर्ष की आयु पूरी करनी हो।
- (2) उम्र व सभी योग्यताएँ हो जो संसद उम्र के लिए कानून द्वारा विहित करे।

उपरोक्त अर्हताओं के अतिरिक्त भी प्रत्याशा के लिए यह भी आवश्यक है कि उम्र निम्न क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिये—

- (1) मंत्री पद तथा संसद के किसी कानून द्वारा मुक्त पदों का उत्तर भारत अर्थात् किमा राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर नहीं हो।
- (2) किसी भी अधिकाधिक यापान्य क्षेत्रों में पापन धारित न किया गया हो।
- (3) वह दिवानिया न हो।
- (4) संसद द्वारा निमित्त किसी कानून के अन्तर्गत अग्रिम न उद्घोषित किया गया हो।

साधारणतः नागरिकों पांच वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। परन्तु उस अवधि में पूर्ण होना है परन्तु उसका विघटन किया जा सकता है तथा आपात्काल के घोषणा होने पर उसका अवधि का बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में व्यवस्था यह है कि आपात्काल में उसका अवधि का एक बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है परन्तु आपात्काल के समाप्ति के उपरान्त उसकी अवधि अधिक से अधिक 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

नागरिकों में से एक व्यक्ति का निर्वाचन करना है जिस स्थान के नाम से चुनाव है। मन्त्रालय या राज्यपालों का मन्त्रालय करने उम्र में मन्त्रालय का कार्य करने तथा मन्त्रालय के अधिकारों का रक्षा करने का उत्तरदायित्व उमा का है। सामान्यतः नागरिकों के स्थानों का वहाँ के निवासी जाति के निवासी नागरिकों के स्थानों की है। वस्तुतः स्थानों के पदों में सम्मिलित जातिमय विचारों का भी विचारित हुआ है जो उसी प्रकार के है जो निम्न में स्थानों के मन्त्रालय में पाये जाते हैं। अतः भारत में भी स्थानों के स्थानों की नीति निर्वाचना की जा सकती है।

स्थानों के अधिकार नागरिकों एक स्थानों के स्थानों का भी निर्वाचन करना है जो स्थानों का अनुसूचितों में मन्त्रालय में अग्रिम का पद होता है। स्थानों के नागरिकों का अधिकार है जो मन्त्रालय में अग्रिम अग्रिम है। परन्तु निम्न क्षेत्रों में निर्वाचित

देते समय डिप्टी स्पीकर को कोई सन्देह होता है तो वह उसे स्पीकर के निर्णय के लिए छोड़ सकता है। डिप्टी स्पीकर के पद के साथ भी पिछले वर्षों में कुछ अभिममय विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए उसका निर्वाचन यदि किसी ससदीय समिति में हो जाता है तो यह आवश्यक है कि उस समिति का अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर ही हो। इसके अतिरिक्त वह चाहे जिस समिति की बैठक में उपस्थित हो सकता है, यदि ऐसा है तो उस समिति में भी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर को ही दी जायेगी। यदि किसी समय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही सदन से अनुपस्थित हैं तो उस समय मदन में अध्यक्षता करने के लिये स्पीकर सदन के सदस्यों में से 6 व्यक्तियों का एक अध्यक्ष-मण्डल मनोनीत कर देता है, इस सम्बन्ध में एक परम्परा यह है कि इस अध्यक्ष-मण्डल के कुछ सदस्य विरोधी दलों में भी हों। जिस समय इस अध्यक्ष-मण्डल का कोई सदस्य सदन में अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है, उसे स्पीकर के तुल्य ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

✓ **लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य**—लोकसभा का पहला और मुख्य कार्य देश के लिए कानूनों की रचना करना है। इस कार्य में उसकी राज्य सभा के साथ साझादारी है, केवल धन विधेयकों के क्षेत्र में लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जहाँ तक गैर-धन विधेयकों का प्रश्न है दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। परन्तु यदि दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है तथा उस मतभेद का निराकरण करने के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है तो उस स्थिति में लोकसभा अपनी अधिक सदस्य-संख्या के कारण राज्य सभा के ऊपर हावी रहेगी। जैसा कहा जा चुका है कि भारतीय सदन की विधायी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं, वह एक गैर-सम्प्रभु विधायी निकाय है। अतः उसे केवल सघ सूची और समवर्ती सूची में दिये हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, असाधारण स्थिति में यदि 249वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सभा ने उसे राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी है तो बात दूसरी है।

लोकसभा का दूसरा कार्य सघ की वित्तीय व्यवस्था को अपने नियन्त्रण में रखना है। इसलिए सदन की अनुमति के बिना सघ सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न कोई खर्चा ही कर सकती है। यहाँ सदन का वास्तविक अर्थ लोकसभा ही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सघ सरकार का कुछ खर्चा ऐसा अवश्य है जो लोकसभा के नियन्त्रण से परे है, लोकसभा उस खर्च के ऊपर बात तो कर सकती है, परन्तु उस पर मतदान नहीं कर सकती। इस प्रकार के खर्चों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा निदेशक आदि के वेतन एवं भत्ते शामिल हैं।

लोकसभा को राज्य सभा के साथ कुछ अधिकारियों को निर्वाचित करने का भी अधिकार प्राप्त है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। इस सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों सदन अलग-अलग इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति से करे, उसे दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना चाहिए तथा मतदान में प्रत्येक सदन की कुल सदस्य-संख्या की दो-तिहाई की उपस्थिति होनी चाहिए। लोकसभा को अपने सदस्यों को अथवा बाहर के किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड देने का अधिकार है।

सदन को संविधान को संशोधित करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति भारत में राज्यों के विधानमण्डलों को संशोधन के क्षेत्र में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें संशोधित करने के लिये किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें सदन के साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। परन्तु अधिकतर संशोधन के लिये दोनों सदनों का अलग-अलग पूर्ण बहुमत तथा

देते समय डिप्टी स्पीकर को कोई सन्देह होता है तो वह उसे स्पीकर के निर्णय के लिए छोड़ सकता है। डिप्टी स्पीकर के पद के साथ भी पिछले वर्षों में कुछ अभिममय विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए उसका निर्वाचन यदि किसी ससदीय समिति में हो जाता है तो यह आवश्यक है कि उस समिति का अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर ही हो। इसके अतिरिक्त वह चाहे जिस समिति की बैठक में उपस्थित हो सकता है, यदि ऐसा है तो उस समिति में भी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर को ही दी जायेगी। यदि किसी समय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही सदन से अनुपस्थित हैं तो उस समय सदन में अध्यक्षता करने के लिये स्पीकर सदन के सदस्यों में से 6 व्यक्तियों का एक अध्यक्ष-मण्डल मनोनीत कर देता है, इस सम्बन्ध में एक परम्परा यह है कि इस अध्यक्ष-मण्डल के कुछ सदस्य विरोधी दलों में भी हों। जिस समय इस अध्यक्ष-मण्डल का कोई सदस्य सदन में अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है, उसे स्पीकर के तुल्य ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

✓ **लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य**—लोकसभा का पहला और मुख्य कार्य देश के लिए कानूनों की रचना करना है। इस कार्य में उसकी राज्य सभा के साथ साझादारी है, केवल धन विधेयकों के क्षेत्र में लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जहाँ तक गैर-धन विधेयकों का प्रश्न है दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। परन्तु यदि दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है तथा उस मतभेद का निराकरण करने के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है तो उस स्थिति में लोकसभा अपनी अधिक सदस्य-संख्या के कारण राज्य सभा के ऊपर हावी रहेगी। जैसा कहा जा चुका है कि भारतीय संसद की विधायी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं, वह एक गैर-सम्प्रभु विधायी निकाय है। अतः उसे केवल संघ सूची और संघवर्ती सूची में दिये हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, असाधारण स्थिति में यदि 249वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सभा ने उसे राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी है तो बात दूसरी है।

लोकसभा का दूसरा कार्य संघ की वित्तीय व्यवस्था को अपने नियन्त्रण में रखना है। इसलिए संसद की अनुमति के बिना संघ सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न कोई खर्च ही कर सकती है। यहाँ संसद का वास्तविक अर्थ लोकसभा ही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संघ सरकार का कुछ खर्च ऐसा अवश्य है जो लोकसभा के नियन्त्रण से परे है, लोकसभा उस खर्च के ऊपर बात तो कर सकती है, परन्तु उस पर मतदान नहीं कर सकती। इस प्रकार के खर्च में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा निदेशक आदि के वेतन एवं भत्ते शामिल हैं।

लोकसभा को राज्य सभा के साथ कुछ अविकारियों को निर्वाचित करने का भी अधिकार प्राप्त है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। इस सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों सदन अलग-अलग इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति से करें, इसे दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना चाहिए तथा मतदान में प्रत्येक सदन की कुल सदस्य-संख्या की दो-तिहाई की उपस्थिति होनी चाहिए। लोकसभा को अपने सदस्यों को अथवा बाहर के किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड देने का अधिकार है।

संसद को संविधान को संशोधित करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। संयुक्त राज्य अमरीका की भाँति भारत में राज्यों के विधानमण्डलों को संशोधन के क्षेत्र में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें संशोधित करने के लिये किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें संसद के मातृकारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। परन्तु अधिकांश संशोधन के लिये दोनों सदनों का अलग-अलग पूर्ण बहुमत तथा

मतदान के समय दो निम्नलिखित मददगार की उपस्थिति आवश्यक है। मविधान के जिन प्राविधानों का सम्बन्ध सघीय शासन व्यवस्था के साथ है उसे परिवर्तित करने के लिये रायों के विज्ञान मण्डल का स्वीकृति आवश्यक है।

राज्यसभा का जन्मिष्ठ काम सघीय कायपालिका का अपन नियंत्रण में रहना है। सघीय मंत्र परिषद् अपने कामों के लिये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि वह अपन में राज्यसभा का विश्वास या दृढ़ता में उमड़ती स्थिति में उमड़कर पाम त्यागपत्र देने के अनिश्चित और कोई दमक विकल्प गेप नहीं रहता। राज्यसभा का इस शक्ति का प्रयोग करने के लिये कुछ साधन उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम वह सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। इन प्रश्नों के माध्यम से सरकार की गतिविधियों का भण्डारण किया जा सकता है। तब यह काम राका प्रस्ताव के द्वारा सरकार के नित्यक कायों को रोककर किसी मावजनिक महत्व के मामलों पर विचार कर सकता है। इस काम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा आध घण्टे का विवाद के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। राज्यसभा के सम्मुख सरकार की आलोचना करने के लिये मन्त्र म प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्त के अधिकारों के कारण कायपालिका के सम्मुख चौकन रहने के लिये इस सम्बन्ध परिणामस्वरूप एक सीमा तक शक्तियाँ का दुरुपयोग नहीं हो पाता।

लोकसभा का स्पीकर—जमा कहा जा चुका है कि राज्यसभा अपना उठका में अध्ययन का आसन ग्रहण करने के लिये एक अधिकारी का निवाचित करनी है जिस स्पाकर के नाम में जाना जाता है। उसका निवाचन राज्यसभा के सभा में होता है। हर बार प्रत्येक आम चुनाव के बाद नए निवाचित राज्यसभा स्पीकर का चयन करती है तथा पुनर्गठित राज्यसभा जब तक नये स्पीकर को चुन नहीं पाता वह अपने पद पर बना रहता है। यदि इस बात में किसी कारणवश स्पीकर का पद रिक्त हो गया तो उस स्थिति में राज्यसभा नये स्पीकर का चुनाव करती है। स्पीकर को अपने पद में त्यागपत्र देने का अधिकार है तथा राज्यसभा भी अपने सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से उसे पदच्युत कर सकता है।

वित्तीय राज्यसभा के स्पीकर की भाँति भारत में भी स्पाकर का एक विशेष अधिकार मविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर वह यह नियंत्रण करता है कि जमुके विषयक धन विषयक है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में उसका नियंत्रण अंतिम होता है तथा इस किमा भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती। स्पीकर के प्रमुख काया एवं शक्तियों का निम्न प्रकार गिनाया जा सकता है

- (1) वह सदन के नेता के परामर्श में विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है।
- (2) सदन के नेता में परामर्श करके वह सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है।
- (3) प्रश्नों को स्वाकार करना अथवा उसे निम्न विरुद्ध धारित करना उसका काम है।
- (4) यदि मावजनिक महत्व के आवश्यक मामलों पर विवाद करने के लिये कोई काम राका प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है तो उस पर स्पीकर की अनुमति के बिना कोई बहस नहीं हो सकती।
- (5) यदि उसकी आज्ञा से गजट में किसी विषय को प्रकाशित कर दिया जाता है तो उस प्रस्तुत करने के लिये किसी प्रस्ताव का आवश्यकता नहीं होती।
- (6) प्रवर समितियों के अथवा वही नियुक्त कर सकता है।
- (7) किसी विचाराधीन विषय पर विवाद रोकने का प्रस्ताव उसकी अनुमति पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (8) किसी प्रस्ताव का ग्राह्य अथवा अग्राह्य होने का नियंत्रण वही देता है।
- (9) समस्त एवं गण्यति के वाद होने वाले मारों पर व्यवहार उसी के माध्यम से संचालित होता है।
- (10) समस्त के सम्मुख का वह भाषण देने का अनुमति देना है और यह नियंत्रण करना भी उसी का काम है कि भाषणा का क्रम क्या होगा।
- (11) प्रक्रिया सम्बन्धी विवादास्पद प्रश्नों (points of order) पर नियंत्रण देना उसी का काम है।
- (12) सदन में गान्ति व व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व भी उसी का सौंपा गया है।
- (13) विभिन्न विषयों का एक प्रस्ताव पर मतदान करना भी उसी का काम है और वही उस मतदान का परिणाम

घोषित करता है। (14) उसे किसी ऐसे सदस्य को सदन से बाहर निकालने का अथवा उसे उसकी सदस्यता से निलम्बित करने का भी अधिकार है जो उसके आदेशों को न माने अथवा जिसके आचरण से सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होती हो। (15) सदन में गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की स्थिति में उसे उसका कार्य स्थगित अथवा निलम्बित करने का भी अधिकार प्राप्त है। (16) दर्शकों के प्रवेश को भी नियन्त्रित करने की उसे शक्ति प्रदान की गई है, किसी भी समय वह दर्शकों को बाहर जाने का आदेश दे सकता है। (17) यदि सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो उसकी ममता में अशिष्ट अथवा असदस्य है तो वह ऐसे शब्दों को कार्यवाही में से निकाल सकता है। (18) सदन में उसके खड़े होने पर अन्य सदस्यों के लिए यह परमावश्यक है कि वे अपने स्थान पर बैठ जायें, उस समय कोई भी सदस्य सदन छोड़कर बाहर नहीं जा सकता।

लोकसभा के स्पीकर के पद पर विचार करते समय यह उल्लेखनीय है कि भारत में उसका विकास न तो ब्रिटिश परम्पराओं के अनुसार हुआ है और न स० रा० अमरीका की परम्पराओं के अनुसार। भारत में ब्रिटेन से भिन्न स्पीकर से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देगा, परन्तु इसके साथ ही उसमें यह अपेक्षा भी नहीं की जाती कि वह अमरीकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की भाँति दलगत राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेगा।

यहाँ यह कहना भी अप्रासंगिक न होगा कि भारत में अभी तक सदन के सभी वर्गों के सदस्यों से वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा की जानी चाहिये। अपने अस्तित्व के इस अल्पसमय में ऐसे अवसर भी आये हैं जबकि सदस्यों ने स्पीकर की निष्पक्षता में सन्देह व्यक्त किया है तथा उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। एक बार स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा चुका है। यह प्रस्ताव 18 दिसम्बर 1954 को पेश किया गया था और उस समय स्पीकर जी० वी० मावलकर थे। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था—‘उन्होंने उस निष्पक्ष रव्ये को अपना बन्द कर दिया है जो सदन के सभी वर्गों के विश्वास को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।’ एक लम्बी बहस के उपरान्त जिसमें सदन के सभी महत्वपूर्ण सदस्यों ने भाग लिया था और जिसमें स्वयं प्रधानमन्त्री नेहरू भी एक थे, सदन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परन्तु इस बहस का एक अच्छा परिणाम भी निकला। इस विवाद में स्पीकर के पद से सम्बद्ध प्रतिष्ठा एवं सत्ता का उल्लेख किया गया तथा इस बात के ऊपर बल दिया गया कि स्पीकर को पूर्णरूप से निष्पक्ष होना चाहिये। सदन की इस बैठक की डिप्टी स्पीकर ने अव्यक्षता की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था—‘मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि एक सम्भावित सदस्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जाता तो उसे शिकायत हो सकती है तथा बहुत से सम्मानित सदस्य उसे अपना समर्थन दे सकते हैं।’ 9 अप्रैल 1960 को एक समाजवादी सदस्य अर्जुन सिंह भदौरिया को अव्यक्त के आदेश की अवहेलना करने के कारण सशरीर उठाकर सदन से बाहर निकाल दिया गया था। इसी प्रकार 30 अगस्त 1962 को समाजवादी पार्टी के के. ही. राममेवक यादव को सदन में निलम्बित किया गया था। इस प्रकार के उदाहरण और भी दिये जा सकते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि भारत में स्पीकर का वह सम्मान नहीं है जो उसे ब्रिटेन में प्राप्त है। निश्चय ही इस स्थिति को वांछनीय नहीं कहा जा सकता। देश में सदस्यीय लोकतन्त्र को गतिशान्ति बनाने के लिये यह परमावश्यक है कि स्पीकर के पद को राजनीतिक विवादों से ऊपर उठा जाए तथा उसे वह सम्मान प्रदान किया जाय जो उसे सदस्यीय परम्पराओं में प्राप्त है।

विवाची प्रक्रिया (अ) गैर-वित्तीय विधेयक ✓

जैसा कहा जा चुका है सदन का सबसे महत्वपूर्ण काम देश के लिये कानूनों की रचना करना है। यद्यपि सदन का अधिकांश समय इसी काम के निष्पादन में व्यय होता है। नाथानियन विधेयकों को दो श्रेणियों में रखा जाता है—वित्तीय विधेयक व गैर-वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक जिन्हें ‘ग्रन विधेयक’ भी कहते हैं, केवल लोकसभा में ही जन्म लेते हैं। वहाँ से

पारित होने के उपरान्त उक्त सभ्य सभा में विचारार्थ भज दिया जाता है। परन्तु राय सभा उनका नकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। उसमें तब यह आवश्यक है कि वह चौदह दिन के भीतर उस विधयक के सम्बन्ध में अपना नियम नोकसभा का बता दे। यदि राय सभा ने उस विधयक का उसी रूप में पारित कर दिया है जिसमें उस नोकसभा ने पारित किया था तब तो कोई कठिनाई नहीं है उस राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के नियम भज दिया जाता है। परन्तु यदि राय सभा ने उस मशायित किया है तो नोकसभा उन सगोषणा पर पुनर्विचार करेगी उसमें यह पूरा अधिकार है कि वह राय सभा द्वारा सुभाय गये सगोषणा का अस्विकार कर दे। यदि उसने ऐसा किया है तो वह धन विधयक राय सभा की अनुमति के बिना भी राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के नियम भज दिया जाता है। परन्तु यह बात गर विस्तीय विधयक पर लागू नहीं होती उहे समझ के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधयक केवल उस स्थिति में कानून बन सकते हैं जबकि समझ के दोनों सदन उन्हें पास कर दें। यदि किसी विधयक पर दाना सदन के बीच मतभेद की स्थिति पायी जाती है तो उसका निराकरण करने के नियम दोनो सदन का मयुक्त प्रत्येक का आयोजन किया जा सकता है इस प्रकार की प्रक्रिया में साधारणतः नोकसभा का स्पीकर या अन्य का आभन ग्रहण करता है।

अधिकारण समझ में विधयक का प्रस्तुतीकरण मंत्रियों के द्वारा होता है। इस प्रकार के विधयक का सरकारी विधयक के नाम से जाना जाता है। इन विधयक का जन्म यथायथ सरकार के किसी मन्त्राय में होता है। मन्त्राय के सदस्य उस विधयक का रूप देने के पूर्व इस बात पर जोर देते हैं कि उसका कानून बन जाने से राजनीतिक प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उस कानून का सम्बन्ध सरकार के अन्य मन्त्राय के साथ भी है तो उसके मसौदा का तयार करने के पहले उनसे भी परामर्श ले लिया जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो इस काम के नियम कानून मन्त्राय तथा एडोर्नी जनरल की भी सहायता ली जाती है। जैसा कि इस प्रकार प्रस्तावित विधयक की जांच कर ली जाती है तो सम्बद्ध मन्त्राय इस आयोजन का एक नामन कविन्ट का देते हैं। केविन्ट उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे सकती है परन्तु यदि प्रस्ताव का प्रकृति विवादास्पद है तो वह उस अपनी किसी स्थायी समिति को जांच के नियम दे सकती है कभी कभी इस प्रकार के प्रस्ताव पर व्यापक रूप से विचार करने के नियम स्थायी समितिया भी नियुक्त की जा सकती हैं। कभी कभी कविन्ट विधयक से सम्बद्ध सामान्य सिद्धांतों की स्वीकार करने के बाद भी उसके मसौदे को फिर से अपने पास जांच के नियम मंगा सकती है। केविन्ट में स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बद्ध मन्त्राय जांच के कागजात के साथ उस विधयक के प्रारूप का सरकारी टाफ्ट्समन के पास भज देता है। विधयक के डाफ्ट को तयार करना वास्तव में बड़ी सुगम कार्य नहीं है कभी-कभी तो उस अंतिम रूप देते समय तक उनका टाफ्ट बनते और विगड़ते हैं।

प्रथम वाचन—सदन होने के बाद विधयक का प्रस्तुतीकरण तथा प्रथम वाचन की स्थिति में लाया जा सकता है। विधयक का प्रस्तुतीकरण सदन के दाना सदन में से किसी एक में हो सकता है। हम कहना चाहें कि विधयक को नोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस स्थिति में उस विधयक की एक सत्य प्रतिनिधि नोकसभा के सचिवालय का सौंप दी जाएगी (यहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि सविधान के अंतर्गत किही विषय पर विधयक को प्रस्तुत करने के नियम राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है)। इसके उपरान्त विधयक के प्रस्तुतकर्ता के परामर्श से स्पीकर एक तिथि निश्चित कर देता है और उस दिन विधयक का विधिपूर्वक सदन में पेश कर दिया जाता है। उस निश्चित तिथि को प्रस्ताव के घण्टे के बाद प्रस्तुतकर्ता अपने स्थान पर गडा होकर स्पीकर से विधयक को पेश करने की अनुमति मागता है। इसके उपरान्त स्पीकर सदन को सम्बोधित करके कहता है—प्रस्ताव प्रस्तावित हो चुका है उस प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय और उस समय कोई विवाद नहीं होता। विधयक के पेश करने का प्रथम वाचन का नाम

दिया गया है। कभी-कभी विधेयक का उसके प्रस्तुतीकरण के समय भी विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए 23 नवम्बर 1954 को जब निवारक नजरबन्दी (मशोबन) कानून को प्रस्तुत किया गया तो उसका इस आधार पर विरोध किया गया कि वह संविधान की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है। जब विधेयक का विरोध उसके प्रस्तुतीकरण के समय किया जाता है तो उस समय स्पीकर प्रस्तुतकर्ता और विरोधी सदस्य दोनों को ही थोड़ा समय अपने-अपने दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के लिये देता है। यदि विरोध का आधार सांविधानिक है तो उस समय स्पीकर पूरे विवाद की अनुमति दे सकता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर एटोर्नी जनरल को भी भाग लेने के लिये बुलाया जा सकता है।

विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरान्त उसे भारत सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि स्पीकर से यह अनुरोध किया जाय कि विधेयक को उसके प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही गजट में प्रकाशित कर दिया जाय तो वह ऐसा करने की स्वीकृति दे सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक को औपचारिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती।

द्वितीय वाचन—विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरान्त उसकी प्रतियाँ सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती हैं। इसके उपरान्त विधेयक का द्वितीय वाचन आरम्भ होता है। साधारणतः विधेयक के प्रस्तुत होने तथा उसके वाचन में दो दिन का अन्तर होता है, परन्तु यदि स्पीकर की राय में विधेयक का शीघ्र पारित होना आवश्यक है तो इस दो दिन के अन्तर को खत्म भी किया जा सकता है। विधेयक का द्वितीय वाचन दो चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में प्रस्तुतकर्ता यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक पर विचार किया जाय, अथवा उसे किसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, अथवा किन्हीं अपवादपूर्ण स्थिति में, उसे दोनों सदनों की मयुक्त समिति को सौंप दिया जाय, अथवा उस पर जनमत को जानने का प्रयास किया जाय। यदि विधेयक पर जनमत जानने का निश्चय किया गया है तो उस स्थिति में सदन का सचिवालय राज्य सरकारों के पास एक पत्र भेजता है जिनमें उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे विधेयक को अपने-अपने राज्यों के गजटों में प्रकाशित करें तथा म्यानीय मस्थाओं एवं अन्य मान्यता-प्राप्त समुदायों और व्यक्तियों से उसके बारे में राय प्राप्त करें। यह राय एक निश्चित समय तक ही प्राप्त की जा सकती है और उस अवधि में उसे सदन के सचिवालय तक पहुँच जाना चाहिए। इन रायों का प्राप्त करने के बाद उनका साराण सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। इसके उपरान्त प्रस्तुतकर्ता सदन से यह अनुरोध करता है कि विधेयक को किसी प्रवर समिति अथवा दोनों सदनों की मयुक्त समिति को सौंप दिया जाय। इस प्रस्ताव के उपरान्त सदन में विधेयक पर सामान्य विवाद आरम्भ होता है। इसी को विधेयक का द्वितीय वाचन कहते हैं। विधेयक के इस चरण में विधेयक के सिद्धान्तों की सामान्य रूप से विवेचना की जाती है। इस चरण में विधेयक में मशोबन प्रस्तावित नहीं किया जा सकते।

जब सदन विधेयक को किसी समिति को सौंपने का निर्णय कर लेता है, तो उस समय वह विधेयक पर विचार करने के लिए एक समिति को भी नियुक्त कर देता है। वस्तुतः समिति के सदस्यों के नामों को प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में ही प्रस्तुत कर देता है तथा इसी प्रस्ताव में इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाता है कि समिति का प्रतिवेदन कितने दिन में प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रत्येक बार प्रवर समिति का अलग में गठन किया जाता है, समिति के अध्यक्ष का मनोनयन स्पीकर के द्वारा होता है। सामान्यतः वह वृद्धतः वाले दल का सदस्य होता है। परन्तु यदि डिप्टी स्पीकर समिति का सदस्य है तो उस स्थिति में कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बन सकता। इन समितियों का काम सदन के नियमों के अन्तर्गत होता है। समिति की बैठकों में एक निहाई कोरम आवश्यक माना गया है। समिति की सदस्य-संख्या सामान्यतः 20 और 30 के बीच में होती है, कभी-कभी यह संख्या 35 तक पहुँच जाती है। चूँकि विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों की विवेचना पहले ही सदन में हो चुकी होती है अतः समिति में विधेयक के व्योम्ने पर ही विचार

गता =। समिति हम काम की भय प्रकार में सम्पान्ति करने के लिए एक उप-समिति को भी नियुक्त कर सकती =। समिति का असल काम न संचालन में मन्त्र के सचिवानय तथा सरकार के द्राफ्टमन की सहायें उपबन्ध होती है।

प्रवर समिति की बैठकें निम्न भा स्थान पर हो सकती हैं य बैठकें उन निम्न भा हो सकती हैं जबकि सदन का अधिवेशन न हो रहा =। हम सम्बन्ध में बताने यह व्यवस्था है कि इन बैठक का उस समय स्थिति में दिया जायगा जबकि मदन में मत विभाजन न हो रहा हो। हम समितिया की बैठक में विधेयक के प्रस्तुतकर्ता तथा मन्त्रालय के अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बुलाया जा सकता है। कभी-कभी सरकार सावजनिक हित में कुछ सूचनाओं का हम में जनता के कर सकती =। प्रवर समिति में प्रक्रिया अनौपचारिक होता है तथा उसकी कार्यवाही का गुप्त रखा जाता है। उनमें समाचार पत्र के प्रतिनिधियों को जान की अनुमति नहीं होती। विषय का यह चरण उमके जीवन का न अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय उसी वाराकी के साथ जांच की जाता =। हम चरण में विधेयक में सहायन प्रस्तावित किया जा सकता है हम सहायता के सम्बन्ध में बताने यह है कि न विधेयक में निहित सामान्य सिद्धांतों के प्रतिकूल न हो। यदि समिति न विधेयक में आपन सहायता को जोड़ने का निणय किया = ता उस स्थिति में वह विधेयक पर दुबारा लोकमत का पता लगाने की सिफारिश कर सकती =। समिति विधेयक के सम्बन्ध में विचारना में परामर्श न सकती है और बाहर से सहाय बुला सकता है। उसका काम यह भी है कि वह विधेयक का प्रत्येक धारा और उप धारा की जांच करे। इतना सब काम जब पूरा न होता = ता समिति अपनी सिफारिशों का जितना सहायन भी नामित हो सकते है। एक रिपोर्ट के रूप में मन्त्र के समक्ष प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट—रिपोर्ट पर समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और वही उस सदन के सामने पेश करता है। यदि वह उपस्थित न हो = ता हम काम को समिति का दूसरा मन्त्र सम्पान्ति कर सकता =। समिति द्वारा सहायन विधेयक तथा समिति की रिपोर्ट छाप कर सदस्यों के बीच वांट दी जाती =। इस पत्रावृत्ति प्रस्तुतकर्ता सदन के सम्मुख निम्न तान प्रकार के प्रस्ताव पेश कर सकता है—(1) प्रवर समिति न विधेयक का जिस रूप में प्रस्तुत किया है उस पर विचार किया जाय (2) जिस रूप में विधेयक को रिपोर्ट किया गया = उसी रूप में हिदायतों के सहित अथवा हिनायतों के बिना प्रवर समिति का विचार के लिए माप लिया जाय (3) जिस रूप में समिति न उसका रिपोर्ट का = उस रूप में उस पर लोकमत जाना जाय।

यदि मदन न इस प्रस्ताव को स्वीकार किया = कि उस पर विचार आरम्भ किया जाय ता उस स्थिति में विधेयक का प्रत्येक धारा एक उप धारा पर विचार विमर्श शुरू हो जाता है। प्रत्येक धारा मन्त्र के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है उस समय मन्त्र विधेयक में सहायन प्रस्तावित कर सकता =। स्पीकर का अधिकार है कि वह किसी भा सहायन का अनुचित बताकर प्रस्तावित नो न हान दे। परन्तु व्यवहार में ऐसा कभी न हो जाता। प्रत्येक धारा पर विचार वास्तव में एक नया प्रक्रिया = और हममें बहुत समय लगता है।

तृतीय वाचन—जब प्रत्येक धारा और उप धारा पर विचार का चरण पूरा हो जाता है तब विधेयक का तीसरा वाचन आरम्भ होता है। तीसरा वाचन यथाय मन्त्र प्रस्ताव का दूसरा नाम = जिसमें प्रस्तावक यह प्रस्तावित करता है कि विधेयक को पारित कर लिया जाये। हम चरण में विवाद इस बात के उद्दिष्ट धक्कर काटता है कि विधेयक को स्वीकार किया जाय अथवा नहीं। इस स्थिति में हमें विधेयक पर बात की जाती है विधेयक के ब्यौर पर नहीं। इस चरण में सामान्यतः सहायन प्रस्तावित नहीं किया जाना फिर भा भाषा का ठीक करने के लिए यदि किसी सहायन का सुझाव दिया गया है ता उसकी अनुमति है। चूंकि विधेयक में सतिहित सिद्धांतों को पहन से ही स्वीकार कर लिया गया है तथा उसके ब्यौर की भी परीक्षा कर ली गई है इसलिए तीसरा वाचन सामान्यतः एक औपचारिकता होती है।

एक सदन में पारित होने के बाद, विधेयक दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इस सदन में भी विधेयक को उन समस्त चरणों में होकर गुजरना होता है जिनमें वह लोकसभा में से गुजर चुका है। यदि दूसरे सदन ने विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया तो उसे दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। वहाँ से भी पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। यदि दूसरे सदन ने उसे पास नहीं किया तो उसे उसी सदन को वापिस कर दिया जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। वहाँ उसके ऊपर पुनर्विचार होता है। यदि यह सदन सशोधित विधेयक को स्वीकार कर लेता है, तो उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर को भेज दिया जाता है।

विधेयक की स्वीकृति—जैसा कहा जा चुका है, जब विधेयक को दोनों सदन पास कर देते हैं तो उसके पश्चात् वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है, वह अपनी स्वीकृति रोक सकता है, अथवा यदि वह धन विधेयक नहीं है तो वह उसे अपने सदेश के साथ पुनर्विचार के लिए वापिस कर सकता है (अनुच्छेद 111)। जब राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार वापिस किया गया विधेयक पुनर्विचार के बाद भी उसी रूप में सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।

गैर-सरकारी विधेयक—ऊपर बताया जा चुका है कि गैर-धन विधेयको को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—सरकारी और गैर-सरकारी। गैर-सरकारी विधेयक उन विधेयको को कहते हैं जिनका सदन में प्रस्तुतीकरण सदन के व्यक्तिगत सदस्यों के द्वारा होता है। इन विधेयकों के सम्बन्ध में जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह लगभग वही है जिसे सरकारी विधेयको के सम्बन्ध में अपनाया जाता है। दोनों में अन्तर केवल निम्नलिखित तीन बातों में है—

- (1) गैर-सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने का नोटिस 1 महीना पूर्व देना होता है।
- (2) कोई भी सदस्य एक अधिवेशन में चार से अधिक विधेयको का नोटिस नहीं दे सकता।
- (3) किस विधेयक का प्रस्तुतीकरण पहले हो और किसका बाद में, इस बात का निश्चय बैलेट के द्वारा होता है।

इस प्रकार के विधेयको को एक समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसे व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयको की समिति (Committee on Private Members' Bills) के नाम से पुकारा जाता है। इस समिति की सबसे पहली रचना 1953 में हुई थी और इसमें अध्यक्ष को मिलाकर 15 सदस्य होते हैं।

धन विधेयक ✓

भारतीय सदन में धन विधेयको के सम्बन्ध में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसका उल्लेख सविधान की 112 से लेकर 117 धाराओं तक हुआ है। इस सम्बन्ध में पहली उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में वित्तीय प्रक्रिया उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जिन्हें ब्रिटेन में स्वीकार किया गया है। कार्यपालिका अपनी तरफ से न कोई कर लगा सकती है और न कोई धनराशि व्यय कर सकती है। ऐसा करने के लिए उसे सदन के निम्न सदन की स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु निम्न सदन अपनी पहलकदमी पर न कोई कर प्रस्तावित कर सकता है और न कोई खर्चा ही, इसी प्रकार उसे कर में वृद्धि अथवा खर्च में वृद्धि करने का भी अधिकार नहीं है। ये सभी काम कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा ही हो सकते हैं।

जैसा कहा जा चुका है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त उसे राज्य सभा के पास भेज दिया जाता है। परन्तु राज्य सभा को उसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। वह उसे चाँदह दिन के भीतर अपने मुभाव के साथ वापिस कर सकती है, किन्तु उन मुभावों को मानना या न मानना लोकसभा की

बृद्धा पर न। यदि नारसभा उम विधयन का दुपारा जन भूत म्प म ही पारित कर दे ता राय मभा की स्वीकृति क न नान पर भा वह राष्ट्रति क पाम उमकी स्नाकृति क निए भेज निया जाता है। नस सम्प्रथ म राष्ट्रति का शक्ति भी नहा क बराबर है। अत यह कहा जा सकता है कि धन विधयन क क्षेत्र म नारसभा का निणय ही अन्तिम हाता है।

वजट—मविधान म यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष म राष्ट्रपति मसद क दाना मन्ना म उम वर्ष क भारत सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण रखवायेगा। नस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा वजट क नाम स पुकारा जाता है। भारत म वजट को दो भागा म प्रस्तुत किया जाता है—रतव वजट और सामाय वजट। रतव वजट का सम्प्रथ वजन रतव की अनुमानित आय एवं व्यय क साथ हाता है तथा उस मन्त म रेन मन्त्रा क द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सामाय वजट म भारत सरकार क आय म नानया का आय एवं व्यय का उत्पन्न हाता है तथा उमका प्रस्तुतानरण वित्तमन्त्री क द्वारा किया जाता है। दाना प्रकार क वजन का स्वयं एक मा हाता है तथा समन्त म उनको पारित करने की प्रक्रिया भी एक सी हाता है। भारतीय समदीय प्रक्रिया की नस सम्प्रथ म एक उन्मनीय बात यह है कि हमार यन्त्रा क्रियेन की भाँति वजट क ऊपर विचार समूच सन्त की समिति म नहा होना परन्तु सन्त की साधारण बढका म हाता है जिनम अग्र्यभता स्वयं स्पीकर ही करता है। यद्यपि वजट को पास करने का उत्तरदायित्व लोकसभा का ह्म मोपा गया है तथापि उसे राय सभा क सम्मुख भी पेश किया जाता है और वहाँ भी उमका ऊपर बहम हाती है। वजट म अनुमानित व्यय को दो भागा म नियाया जाता है—(1) व्यय की वह राशि जा सचित निधि पर भारित होती है (Charged upon the Consolidated Fund) तथा (2) अय व्यय की रकम। प्रथम नणी म निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हात है

(1) राष्ट्रपति का वतन उसके भक्त तथा उमका प स सम्बद्ध अय खर्चें (2) ससद क दोना सन्ता क अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों क वतन और भक्त (3) ऋण चुकान क सम्प्रथ म व्यवस्था (Interest and sinking fund charges) (4) सर्वोच्च यायालय क यायाधीशों क वतन उनके भक्त और पंगन जादि (5) कोई भी वह व्यय जिसे सविधान अथवा ससद कानून द्वारा पमा घोषित कर दे तथा सर्वोच्च यायालय के सगठन का पूरा व्यय रियासता के राजाज्मा को दी जाने वाली निजी धनियाँ (Privy Purses) तथा सधीय नोन सेवा आयाग का पूरा व्यय।

उपयुक्त श्रणा म सम्मिलित खर्चों क ऊपर सदन म मतदान नहीं हाता परन्तु उन पर विवाद हो सकता है। सचित निधि पर भारित एवं अय खर्चों की अनुमानित राशिया अनुदानों की माँगा (Demands for grants) क रूप म लोकसभा म रखी जाती हैं। सभा को उनम कटौती करने का अथवा उह अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है परन्तु वह उनमे वृद्धि नहा कर सकती। जसा क्ता जा चुका है कि अनुदाना माँगें कवन राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोक सभा म रखी जा सकती है।

वजट पर साधारण घात विवाद—वजट के प्रस्तुत किए जाने के थोड़े दिना बाद ससद के दोना सदन के आय व्यय के प्रस्ताव पर साधारण वाद विवाद हाता है। इसक निए दो तीन दिन दिय जात है। यह वाद विवाद क मुख्यत आय सम्बन्धी प्रस्तावा म निहित भूत सिद्धांता अथवा उनकी नीति पर केन्द्रित होता है उसम आय व्यय सम्बन्धी विस्तार की बाता पर विचार किया जाता। नस विवाद के समय कटौती प्रस्ताव भी पेश नहीं किये जा सकत। नस अवसर पर सन्स्य प्रशासन की नीतिया का सिंगबनोकन करते हैं तथा प्रशासन स सम्बद्ध अपनी निकायता की अभियक्ति भी करत है। मारिस जोस न निखा है कि यह वह अवसर है जबकि प्रत्येक सदन अपनी मनोकगा को यक्त करता है और सरकार उमके नारा यह सोख सकती है कि आने वाले धरणा म उसके किसी विनिष्ट प्रस्ताव का किस प्रकार स्वागत किया जायेगा।

माँगों पर मतदान—अनुदानों पर सामाय विवाद के पून हा जान के बाद वजट क सम्बन्ध

में राज्य सभा की प्रभावशाली भूमिका की भी इतिश्री हो जाती है। इसके उपरान्त अनुदानों की माँगों पर मतदान होता है। इन माँगों का सम्बन्ध वजट के उस भाग में है जिसमें व्यय का उल्लेख होता है तथा उन्हें कार्यपालिका के सदस्य अनुरोध के रूप में इसलिए प्रस्तुत करते हैं ताकि प्रशासन को चलाया जा सके। प्रत्येक मन्त्रालय की माँगों को लोकसभा के समक्ष अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है तथा उन पर अलग-अलग मतदान होता है। लोकसभा के नेता के परामर्श में स्वीकर प्रत्येक मन्त्रालय की माँगों तथा समूचे वजट के व्यय वाले भाग के लिए समय निश्चित करता है। जैसे ही समय पूरा हो जाता है, विवाद बन्द कर दिया जाता है और माँग पर मतदान कराया जाता है। उसी प्रकार वजट के व्यय वाले भाग पर विवाद निश्चित दिन को शाम के पाँच बजे खत्म कर दिया जाता है और वे सभी माँगें जिन पर विवाद चाहे आरम्भ भी न हुआ हो, मतदान के लिए सदन के सम्मुख रख दी जाती हैं।

प्रतिषेध जो साधारण अनुदान देने हैं उनके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति पूरक माँगों (Supplementary grants) को भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता है। उनके सम्बन्ध में भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उसी प्रकार लोकसभा को अग्रिम (advance) अनुदान तथा अपवाद (exceptional) अनुदान देने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें लेखानुदान (vote of account) को महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उक्त अनुदान की माँग तथा आय के ऊपर समद द्वारा विचार पूर्ण होने के पूर्व ही सरकार के आवश्यक खर्चों के हेतु वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक काल के लिए एक बड़ी वनराशि पेशगी अनुदान के रूप में स्वीकार कर दी जाती है। फलस्वरूप आय-व्यय प्रक्रिया को 31 मार्च से पूर्व पूरा करना आवश्यक नहीं रहा।

करो की स्वीकृति और वित्त विधेयक—विनियोग अधिनियम (Appropriations Act) के पारित होने के उपरान्त सदन वजट के दूसरे भाग अर्थात् आय एवं कर-सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करता है। कुछ कर स्थायी होते हैं जिन पर सदन प्रतिवर्ष विचार नहीं करता। जिन कानूनों द्वारा कर आरोपित किये जाते हैं, उनके अन्तर्गत कार्यपालिका उनकी दरों को घटाने अथवा बढ़ाने-सम्बन्धी कार्यवाही करती है। कुछ कर ऐसे हैं जिनकी दरों को सदन प्रतिवर्ष निर्धारित करती है। इस प्रकार के करों में आय-कर (Income-tax), आयात-निर्यात कर (Customs Duties), उत्पादन महसूल (excise-duties) शामिल हैं। आगामी वर्ष के लिए सभी कर-सम्बन्धी प्रस्तावों को एक विधेयक के रूप में समद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यही विधेयक वास्तव में आय विधेयक होता है। इसके पारित होने के पश्चात् ही नये कर-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रभावी होते हैं। नये कर-सम्बन्धी प्रस्तावों को वर्ष में किसी भी समय लाया जा सकता है, उन्हें भी वित्तीय विधेयक के रूप में पारित होने के बाद लागू किया जाता है।

समदीय समितियाँ

आधुनिक व्यवस्थापिका में समदीय समितियों का महत्व अत्यधिक होता है। वस्तुतः सदन का वास्तविक काम समितियों के माध्यम में ही होता है। समद के पास न तो इतना समय है और न उम्मीदों का उतनी क्षमता ही है कि वह उन समस्त कार्यों का निष्पादन कर सके जो उसे सौंपे गए हैं। अतः जैसा लोकसभा के भूतपूर्व सचिव एम० एन० कॉल ने कहा है—‘समद नीति की विवेचना करती है, परन्तु जब तक सभी समितियाँ न हों जो उनके व्योम के विवेचन कर सकें, गौर जहाँ वे लोग जो प्रशासन चलाते हैं, जाकर अपनी गवाही न दे सकें, जहाँ मामलों की अच्छी तरह जाँच न हो सके, समदीय नियन्त्रण दुर्लभ रहेगा।’ जहाँ तक विधायी कार्य का सम्बन्ध है, तब तो उक्त समितियाँ के बीच काम का विभाजन अत्यन्त आवश्यक है। समद किसी भी विधेयक में सन्निहित केवल सामान्य सिद्धान्तों की जाँच कर सकती है, उसमें अधिन की वास्तव में समद में अपवाद भी नहीं हो जा सकते। समद द्वारा सामान्य विवेचना के उपरान्त विधेयक

समिति या क हवान कर न्थि जात ह जना उन पर चारीना क साथ विचार किया जाता ॥ जना म जब व समिति की सिफारिश अथवा सुभाष क साथ समझ म वापिस आत ह तो वही उन पर अन्तिम निणय रता ॥ समिति म काम सन्तन का अपक्षा अधिक प्रभाव होता ॥ समिति यथाथ म समझ का ही एक छोटा रूप ॥ क्यानि उसम सन्तन क प्रत्यक्ष वष का प्रतिनिधित्व दन का प्रयाम किया जाता ॥ समिति और सन्तन क काम करन म एक बन्ता अन्तर यत् ह कि समिति का बठना म दनगन राजनीति का वह अभिव्यक्ति नहा गता जा सन्तन का साधारण बठना म हानी ह ॥ सन्तन अतिरिक्त समिति का बठक चूनि गुप्त गता है ॥ समिति उनम मदम्या की उस प्रकार क भाषण करन की भा आदव्ययता नहा ॥ जिनका व सन्तन म बहुधा प्रवचन किया करत हैं ॥ उन समितिया गरा किया जान वाला काम निस्सन्दह रतना महत्वपूर्ण ॥ कि गान् मुखर्जी न ता यहा तन सुभाष किया ॥ कि समझ क औपचारिक कामा म कमी की जानी गणि तथा समितिया क काम का चरया जाना चाहिण ताकि समझा की प्रतिभा एक सवा का अधिक सक्रिय रूप म काम म लाया जा सक ॥

भारत की समिति प्रणाली का एक उल्लेखनीय घात यह है कि समाज में स्थायी समितियाँ का व्यवस्था नहीं की गई है। जहाँ किसी विषयक का किसी समिति के हवाला करने का नियम निया जाता है उस समय उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थायी प्रवर समिति का भी नियुक्त कर दिया जाता है। परन्तु इस व्यवस्था में कुछ नियमित समितियाँ भी हैं जिन्हें चार श्रेणियाँ में बाँटा जा सकता है—(1) सामाजिक समितियाँ (2) जाति समितियाँ (3) विधायक समितियाँ और (4) वित्तीय समितियाँ। इन समितियों की रचना के लिए सामाजिक तीन तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं। प्रवर समितियाँ तथा दो वित्तीय समितियाँ (शोक तथा समिति और अनुमान समिति) का छात्रों के रूप में सभी समितियों के सदस्यों का मतान्वयन स्वीकार करना होता है। प्रवर समितियों के सदस्यों के नामों का विधायक का प्रस्तुतपत्र पत्र करता है। अनुमान समिति तथा शोक तथा समिति के सदस्यों का सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर शोकसभा के द्वारा निर्वाचन होता है।

१ सामाज्य समितिया—एन समितिया के जनगत जा समितिया शामिल है व इस प्रकार है—नियम समिति (Rules Committee) काय सञ्चालन परामर्शदाता समिति (Business Advisory Committee) सामाज्य उद्देश्य समिति (General Purposes Committee) घृष्ट समिति (Home Committee) और सरकारी जावामता की समिति (Committee on Government Assurances) । यहा एन समितिया की सजिप्त बिबचना आव यक्त ।

नियम समिति म 15 सदस्य हात ह जिन ह स्पीकर मनोनात करता है। स्पाकर स्वयं वम समिति का अध्यक्ष होता है। वम समिति का काम सदन क काय-संचालन की प्रक्रिया पर विचार करना तथा उसका निष्पत्ति करना तथा यदि आवश्यक हो ता प्रक्रिया को सुधारन के लिए उपाया की सिफारिश करना है। वम समिति की बैठका म उसके सन्मया के अतिरिक्त अन्य सदस्या को भी आमन्त्रित किया जा सकता है। 1954 तः प्रक्रिया क नियम म स्पीकर समिति की सिफारिश पर परिवर्तन किया करता था। परन्तु अब समिति की सिफारिश सदन क सभुव प्रस्तुत की जाती हैं तथा सदन ही उह स्वीकार करता है।

सन्तन व कार्यक्रम तथा समय का निर्धारण काय सञ्चालन परामशदात्री समिति की सहायता से होता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और स्पीकर इस समिति का भी अध्यक्ष होता है। समिति की सिफारिश पर तथा नामसभा के नेता एवं विरोधी गुट के नेताओं के परामर्श से स्पीकर सन्तन व कार्यक्रम का सञ्चालन करता है। कभी कभी वह समिति अपनी पहचान पर यह सिफारिश भी करती है कि सावजनिक महत्व के कुछ विषयों का मदन के समुल्ल प्रस्तुत किया जाय तथा वह उसके लिए समय भी निश्चित करती है। समिति की सिफारिशें अभी तक सर्वसम्मति से हुई हैं परन्तु मदन ने भी उसके प्रतिवन्दन और सिफारिशों का एकमत से स्वाकार किया है।

सामान्य उद्देश्य समिति की रचना 1954 में हुई थी। उसमें 20 सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष मण्डल (Panel of Chairmen) के सदस्य, विभिन्न दलों के नेता तथा कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति का भी अध्यक्ष स्पीकर होता है। इस समिति का काम सदन के सगठन एवं उसकी कार्य-प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में स्पीकर को परामर्श देना है। इस समिति की सिफारिशों पर ही स्वचालित मतगणना प्रणाली का समारम्भ हुआ है, सदस्यों के लिए क्लब की स्थापना हुई है तथा ससदीय रिपोर्टों को जल्द छापने की व्यवस्था की गयी है।

गृह समिति में 12 सदस्य होते हैं तथा उसकी रचना प्रति वर्ष स्पीकर के द्वारा की जाती है। इस समिति का काम सदस्यों के लिए आवास की सुविधा की व्यवस्था करना है।

सरकारी आश्वासनों की समिति भारत की एक अपनी निराली सस्था है। मॉरिस-जोन्स ने उसे 'पूर्णतः भारत का अपना आधिष्ठाक' बताया है। इस समिति की स्थापना 1953 में हुई थी। उसमें 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का काम समय-समय पर मन्त्रियों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों की जाँच करना है तथा इस बात की रिपोर्ट करना है कि उन आश्वासनों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है और आश्वासनों के कार्यान्वयन में आवश्यकता से अधिक समय तो नहीं लगाया गया।

2 जाँच समितियाँ—इस श्रेणी के अन्तर्गत दो समितियाँ रखी जाती हैं—विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) तथा याचिका समिति (Committee on Petitions)।

विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और इसकी रचना सदन के गठित होने के समय होती है। इस समिति का काम सदन और उसके सदस्यों के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा करना है। विशेषाधिकार का प्रश्न अनेक प्रकार से उठ सकता है। किसी समाचार-पत्र में सदन के किसी सदस्य अथवा सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में आपत्तिजनक लेख अथवा समाचार प्रकाशित हो सकता है, कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक भाषण दे सकता है, कोई सदस्य स्पीकर के निर्णय पर आपत्तिजनक तरीके से अपने मत को व्यक्त कर सकता है—स्पष्टतः ये सभी परिस्थितियाँ विशेषाधिकार के प्रश्न को जन्म दे सकती हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को विशेषाधिकार समिति को सोप दिया जाता है। समिति इस प्रश्न की जाँच करती है, वह इसके लिए गवाह बुला सकती है, वह सम्बद्ध व्यक्तियों से सफाई माँग सकती है। इतना करने के बाद समिति का अध्यक्ष सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके उपरान्त सदन का नेता यह प्रस्तावित करता है कि उक्त मामले में क्या कार्यवाही की जाए। सदन उस प्रस्ताव के ऊपर अपना निर्णय लेता है।

याचिका समिति में भी 15 सदस्य होते हैं और उसकी रचना भी सदन के गठन के समय पर ही स्पीकर के द्वारा होती है। कोई भी मन्त्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इस समिति का काम उन याचिकाओं पर निर्णय लेना होता है जो सदन के सन्मुख व्यक्तियों अथवा सस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक याचिका की जाँच करने के लिए समिति गवाहों को बुला सकती है। अपनी जाँच पूरी करने के बाद समिति अपना प्रतिवेदन सदन के सन्मुख प्रस्तुत करती है जिसमें वह यह सुझाव देती है कि याचिका में निहित शिकायतों का कैसे निराकरण किया जाये।

3 विधायी समितियाँ—विधायी समितियों के अन्तर्गत निम्न समितियाँ आती हैं—(अ) प्रचार समितियाँ, (ब) व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों एवं प्रस्तावों की समिति, तथा (न) अधीनस्थ कानून-निर्माण की समिति (Committee on Subordinate Legislation)।

जैसा कहा जा चुका है कि प्रवर समितियों के सदस्यों का नामांकन स्वयं विधेयक के प्रस्तुतकर्ता के द्वारा किया जाता है। इन समितियों की सदस्य-संख्या निश्चित नहीं होती। समिति के सदस्यों में से किसी एक को स्पीकर उसका अध्यक्ष मनोनीत कर देता है। यह अध्यक्ष सामान्यतः शान्त दम में सम्बद्ध होता है। इन समितियों को गवाहों के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने मन्त्रुग

उपस्थित हान का आगमन का अधिकार है। कभी-कभी समितियाँ विधेय की अधिक विस्तृत जाँच के लिए उप-समितियाँ का भी गठन करती हैं। कभी-कभी दाना सन्ना की संयुक्त प्रवर समितियाँ का भी नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार का समितियाँ में जाँचमचा एवं राज्य सभा में सन्ना में 2 और 1 का अनुपात होता है।

✓ व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयों एवं संकल्पों से सम्बद्ध समिति की रचना 1953 में हुई थी। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनका मनोनीयन स्पीकर के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। विटो स्पीकर इस समिति का अध्यक्ष होता है। सरकारी विधेयों के सम्बन्ध में जो काम कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति का सौंपा गया है वह काम सरकार द्वारा विधेय के सम्बन्ध में इस समिति को सौंपा गया है। विधेयों के महत्त्व तथा उनकी आवश्यकता के आधार पर सरकार विधेयों का दो श्रेणियों में बाँटा जाता है। समिति इसी आधार पर यह निर्दिष्ट करता है कि उसमें ऊपर किन समय तक विचार किया जाय। सविधान में मशायन से सम्बद्ध सरकार विधेयों का जाँच इस समिति के द्वारा उनके प्रस्तुतीकरण के पहले का जानी है। इसी प्रकार समिति में बात की जा जाँच करता है कि कानून विधेय समान का नून बनाने की शक्ति से परे तो नहीं है।

✓ अधीनस्थ कानून रचना से सम्बद्ध समिति का काम उन नियमों की जाँच करना है जो समद द्वारा प्रस्तुत गति के अधीन सरकार की कार्यपालिका द्वारा के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस समिति की मध्यम पहल स्थापना 1953 में हुई थी और इसका काम यह था कि वह प्रत्यक्ष व्यवस्थापन (Delegated Legislation) पर समद के नियंत्रण का प्रभाव न हो सके। इस समिति के 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर मनोनीत करता है। अपन नाम के सम्पादन में समिति को निम्न बातों पर ध्यान रखना होता है—(1) क्या वह उस कानून के सामान्य सिद्धांतों के अनुकूल है जिसको कार्यान्वित करने के लिए उसका रचना हुई है (2) क्या उसमें वह सामान्य शामिल तो नहीं है जिसके ऊपर समद द्वारा पारित कानून की आवश्यकता है (3) क्या उसके द्वारा कर आरापित किए गए हैं (4) क्या वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान या क्षति संचालित करता है (5) क्या वह कानून के किसी प्राविधान का किसी पिछड़ा नियम से तो प्रभावी नहीं बनाता जिसकी कानून के अंतर्गत उस शक्ति प्रदान नहीं की गयी है (6) क्या उसमें कोई ऐसा व्यय तो सन्निहित नहीं है जो सार्वजनिक राशि अथवा संचित निधि पर भारित हो (7) क्या वह कानून के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी गति का व्यवस्था तो नहीं करता जो असाधारण अथवा अप्रत्याशित हो (8) क्या उसमें प्रकाशन अथवा समद के समान उसमें प्रस्तुतीकरण में आवश्यकता से अधिक विनियम तो नहीं आया (9) क्या किसी कारण से उसमें स्वरूप अथवा उद्देश्य में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

यह प्रदान का आवश्यकता नहीं कि इस समिति का काम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसमें पास यह उत्तरदायित्व है कि वह समद की प्रभुमत्ता तथा नागरिकों के अधिकारों की कार्यपालिका के अतिव्रमणा से रक्षा करे। इसका जाण्य यह कदापि नहीं है कि इस समिति का काम प्रशासन का विरोध करना है। वस्तुतः मन्त्रालय और समिति के बीच एक बनी सीमा तक सहयोग पाया जाता है। इस समिति के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि इससे बैठना में सदस्य दक्षता भावना से प्रेरित होकर काम नहीं करते बल्कि उनके निष्पक्ष हात हैं।

✓ वित्तीय समितियाँ—मारिस जोस ने लिखा है कि— यदि यह सत्य है कि कानून भी विधानमण्डल अपनी समितियाँ के द्वारा जाना जाता है तो यह आभास करना बुद्धिसंगत होगा कि वित्तीय समितियाँ का मुख्य रूप से विनायक मन्त्र माना जाय। वित्तीय समितियाँ के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण समितियाँ के नाम लिये जाते हैं। वे हैं—(1) अनुमान समिति (Estimates Committee) (2) नाक लेखा समिति (Public Accounts Committee) तथा (3) सार्वजनिक उद्योग धंधा की समिति (Committee on Public Undertakings)।

अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा अपने सदस्यों में से सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित करती है। इस समिति का काम मुख्यतः प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता लाना है। अतः वह बजट प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जाँच करती है। उसकी आलोचनाओं और सुझावों ने प्रशासन में अपव्यय को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समिति को निम्नलिखित काम सौंपे गये हैं—

(1) यह बताना कि बजट अनुमानों में सन्निहित नीति के अन्तर्गत सगठन में किस प्रकार मितव्ययिता और कार्य-कुशलता लाई जाय।

(2) प्रशासन में कार्य-कुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना।

(3) इस बात की जाँच करना कि अनुमानों में निहित नीतियों की सीमा के अन्तर्गत क्या बचत का विनियोजन सही हो रहा है।

(4) ससद के समक्ष अनुमानों को प्रस्तुत करने के स्वरूप के सम्बन्ध में सुझाव देना।

पिछले वर्षों में इस समिति ने सरकार के ऊपर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभाव डाला है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उसके प्रभाव में निरन्तर वृद्धि हो रही है और अब उसका प्रभाव इतना व्यापक है कि वजाय इसके कि वह फिजूलखर्चों के विरुद्ध केवल चौकीदारी का काम सम्पादित करे, वह आज 'एक प्रकार से ससद का तृतीय सदन' बन चुकी है।

लोक लेखा समिति को एक प्रकार से अनुमान समिति का पूरक समझा जाना चाहिए। अनुमान समिति का काम सार्वजनिक व्यय के अनुमानों की जाँच करना है, जबकि लोक लेखा समिति का काम यह देखना है कि क्या सार्वजनिक व्यय उन मरदों पर किया गया जिनके लिए उसे स्वीकृति दी गयी थी।

इस समिति की सदस्य-संख्या 22 है, जिसमें 15 लोकसभा में से लिए जाते हैं और 7 राज्य सभा में से। इनका निर्वाचन दोनों सदनों के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कोई भी मन्त्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा की प्रक्रिया नियम 241 [1] के अनुसार यह समिति भारत सरकार के व्यय के लिए लोकसभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और लोकसभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की जाँच करती है।

लोक लेखा समिति को निम्न कर्तव्य भी सौंपे गये हैं—(1) राजकीय निगमों, व्यापार तथा निर्माण योजनाओं एवं परियोजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की जाँच करना, जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति ने उपेक्षा की हो या जो कि किसी विशेष निगम, व्यापार संस्था अथवा परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था विनियमित करने वाले सन्निहित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हो तथा उन पर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच करना, (2) स्वायत्तशासी तथा अर्धस्वायत्तशासी निकायों का आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की जाँच करना, जिसका लेखा परीक्षण नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों के अन्तर्गत अथवा समद की किसी सविधि के अनुसार किया जा सके, तथा (3) उन मामलों में नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उससे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा करने की अथवा किसी भी अन्य प्रकार के लेखों की परीक्षा करने की उपेक्षा की हो।

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ससद की एक समिति के द्वारा सरकार के लेखों की जाँच उसकी अनियमितताओं के ऊपर निम्नसन्देह एक रोक है। इससे सरकारी विभागों को अपने काम के संचालन में अधिक मावधानी बरतने की प्रेरणा मिलती है। इसकी रिपोर्ट सदन के सन्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है और इस प्रकार सार्वजनिक लेख सम्बन्धी कमियाँ सबके सामने आती हैं।

त्रितीय समितियाँ म जायु म सत्रम अधिक छोटी सावजनिक उद्योग धंधों की समिति है। उनकी स्थापना म 1964 म हुई थी। मत्रा म म्य मस्या 15 है जिनम म 10 तारमभा म म और 5 मय मभा म म निर्वाचित किय जात म। म्य समिति का निम्न काम माप गय म—

(1) उन सावजनिक उद्योगा व प्रतिष्ठना और मत्रा की जांच करना जो म्य समिति का नियम म्य स साप गय ह (2) सावजनिक उद्योगा व मम्वय मयमि नियमक एम महानम्या परीमक का काई प्रतिवमन हा ता उनका जांच करना (3) सावजनिक उद्योगा की स्वायत्तता एव मापकृताता का ध्यान म मम्वन म्य म्य मात की जांच करना कि उनका प्रम्व ध्यापार व गिद्धाता तथा मुद्रिमगत यापामिक जाचम्या व अनुकूल हा रहा म अथवा नहा और (4) साव जनिक उद्योगा म मम्वद्ध नाक मत्रा ममिति एव अनुमान ममिति म निम्न उन कायों का मम्यामन करना ता (1) (2) और (3) व मम्वगत नहा मात तथा जिनके निम्याता का मायित्व उम म्पीकर व मत्रा मीमा गया म। माजकन दम म सरकारी क्षम म 83 उद्योग धम्व हैं और उनम 3 मत्र 50 वरम म्य का पूजी ममी दूत म। उसी काय प्रणानी का का भी पहलू ऐसा नहा म जिसकी ममिति न भना प्रमा जांच न की हा। ममिति का काम सावजनिक उद्योगा व मम्वय प्राममन का मम्व रख करना न म और न उनका काम मत्रा नातिया की जांच करना म। उमका काम कनन उनका कायममा प्रम्व मत्राय काय मचातन जादि का परी मण करना म। उन उद्योगा पर समन्वी म्य म्य का कायम कन म यह ममिति उपयोग मिद्ध दूत म।

भारतीय समम—एक म्प्याकन

उपयक्त विवेचन म पट्ट म कि भारतीय समम मेश का मवम अधिक महत्वपूर्ण निमाय म। वम्वन म्य की ममम मम्वपूर्ण ममम्याम्रा पर—चा म गम्वीय हा अथवा मम्वगतम्वीय म्य निचार ममम हाता म। म्य विचार ममम म दम व मभा मगी व मत्रा रचि मत हैं। जम ममम मीमी महत्वपूर्ण ममम्या पर विचार करती म तो उम ममय मत्रा मजारा की मस्या म दमव मारी म पहचन का प्रयत्न करत म। जनता की मिकायता का मयत करन व क्षम म भी ममद की मूमिका महत्वपूर्ण रता म। म्य मत्रा ह कि ममम म मम्वयी म्य कभी अधिक शक्तिशाली नहा म्य तथापि ममम म उमका मागमन का मम करक नहा जाँसा जा सक्ता। मच बात यह म कि ममम म मम्वयी मम्वम्या न जपनी मति म अधिक प्रभाव का प्रम्वगत मिया है।

ममम का अधिक प्रभावणाता बनान व माग म अनक माधायें ह मत्रा मापाजा की जनता का एव मडी का माग जाना चाहिय। मविधान की 120वा धारा म लिखा है कि ममम म काय म मचातन हिनी अथवा जम्वजी म हाता परन्तु उमम म्य म्यमस्था भी की गइ म कि म्पीकर मिया मम मम्वय का अमनी मान मापा म मापण करन का अधिकार प्रमात कर मवना म जा अपन मापको उपयक्त दाना मापाजा म स मिसी म जस्टी प्रमा म मयत करन म अममय हा। मम्वमम मम्वय हिनी अथवा मम्वजा म अपन मापका मयत कर सकत है परन्तु मम्वम भारत म मात वाने वदूत म मम्वय ममा करन म मममय ह। मम्वम मिया म अनुवा म सुमिधा की म्यम या की ममम पर तु यह मयम्या जभा तक मीम परक नहा हा सनी म।

भारतीय मम्वमय की अनुभवहीनता तथा बाधित मान व जभा म की एव दूसरी मात्रा माना जा सकता म। भारत म मम्वमया व मम्वय म पामर तथा मम्वर का म्य मम मय मम्वमनीय म— व कनन अनुभवहीन ही नहा व मम मम्वमि भा ह उह कम मम्वम मी मम्वता है तथा अधिमामत उह कठिन मम्व मम्वम्या म रहना होना म। उनका मम्व मम्वम्व रूप म महामया की भा मयस्था नहा है और उ म माव तथा मापमा और प्रतिवमना का मयार ममम म मीम महामया नही मम्वती। म्य मम्व वम्व स ममम्व मद य मा उा सुमिधाम्रा की भा प्रयोग म नहा मान जो उ म प्राम्त म। मम्व मिया मम्वमीर मम्वमन अथवा मम्वमन व मिय ममय अथवा अवमर मम्वमन एव मम्वर काय म मम्व मम्व का मम्वका तथा उनका मम्व व मम्व

उन्हे सुगमता से उन लोगों का शिकार बना देते हैं जो उनके इर्द-गिर्द सभी समय घूमा करते हैं। बहुधा उनका अपने निर्वाचकों से सम्बन्ध टूट जाता है, यदि निर्वाचकों की राजनीति में दिलचस्पी है तो उन्हें स्थानीय निकायों तथा राज्य के विधानमण्डल में अपने प्रतिनिधित्व में अधिक रुचि है अपेक्षाकृत सुदूर नई दिल्ली में स्थित अपने प्रतिनिधियों में।'

अतः इस पृष्ठभूमि में भारत की राजनीतिक पद्धति में सदन की भूमिका का मूल्यांकन करना कठिन काम है। यह ठीक है कि वह देश में कानून निर्मित करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकरण है, परन्तु सच बात यह है कि बुनियादी प्रश्नों का समाधान सदन के द्वारा नहीं होता। वास्तव में औसत सदन सदस्य को देखते हुए सदन में इस काम की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। फलतः ससदीय पद्धति में उससे जिस भूमिका की आशा की जानी चाहिये, उसे निवाहने में वह असमर्थ रही है। यथार्थ में यह दुर्बलता केवल भारतीय सदन की ही नहीं है, इसे ब्रिटेन में भी अवलोकित किया जा सकता है जहाँ मुख्य शक्ति अब मन्त्रिमण्डल तथा सिविल सर्विस के द्वारा परिचालित होती है। परन्तु इन सीमाओं के होते हुए भी भारत की सदन ने पिछले वर्षों में अनेक बार इस तथ्य का प्रमाण दिया है कि वह प्रशासकीय यन्त्र का एक आवश्यक हिस्सा है। देश के सभी प्रधानमन्त्रियों ने उसकी कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, वस्तुतः उनका अपने दल में नेतृत्व भी इस बात पर अवलम्बित होता है कि वे सदन के विभिन्न वर्गों में अपने लिये किस सीमा तक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। 1969 में कांग्रेस की फूट के बाद यह बात स्पष्ट रूप से व्यक्त हो गई थी।

प्रश्न

- 1 राज्य सभा और लोकसभा के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए यह बताइए कि क्या भारतीय द्वितीय सदन शक्तिहीन सदन है ?
- 2 लोकसभा की रचना कैसे होती है ?
- 3 लोकसभा के स्पीकर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
- 4 भारत में गैर-वित्तीय विधेयकों को किस प्रकार पारित किया जाता है ?
- 5 वित्तीय विधेयकों को पारित करने के सम्बन्ध में संविधान में क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं ?
- 6 ससदीय समितियों पर एक टिप्पणी लिखिये।

संघीय संविधान की बहुत सी विषयताओं में एक आवश्यक विषयता यह है कि उसमें एक स्वतंत्र एवं सुसंगठित न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए। संघीय राज्य में संघ सरकार तथा राज्यों का सरकारों के बीच शक्तियाँ का बंटवारा होता है। इस प्रकार की गामन प्रणाली में अधिकार-क्षेत्रों के प्रश्नों पर दोनों प्रकार का सरकारों के बीच अथवा राज्यों का सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यही नहीं संघीय राज्य में सरकार की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों का भी समायोजन कर दिया जाता है। अतः यदि सरकार की कोई शाखा अपना सीमाओं का अनिर्धारण करती है तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। तब भी विवादों का निवारण करने के लिये निष्पक्ष एवं शक्तिशाली न्यायपालिका की आवश्यकता है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय न केवल राज्य के संघात्मक स्वरूप की रक्षा करता है अपितु उसमें यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वह सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। वस्तुतः सभी नागरिकों में राज्य में न्यायपालिका से इस काम की अपेक्षा की जाती है। संविधान में सभी सर्वोच्च न्यायालय के इस काम पर पर्याप्त रूप में ध्यान दिया गया था। वस्तुतः एक मन्त्र्यन ता इस नागरिकों का प्रहरी (watch dog of democracy) घोषित किया था और इसी आधार पर समस्या न यह भाग का थी कि न्यायपालिका का न्यायपालिका के नियंत्रण में सुक्त होना चाहिए। संविधानकारों ने न्यायालय का स्वतंत्रता का वाक्य रखने के लिये अग्रिमस्थित आठ व्यवस्थाएँ की हैं।

1 नियुक्ति—सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों के परामर्श से होती है जिनमें राष्ट्रपति इस सम्प्रदाय में परामर्श करना चाहता है परन्तु मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है।

2 योग्यता—न्यायाधीशों की नियुक्ति का राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रहने के लिए संविधान में उनके लिये निम्नतम योग्यताएँ बहुत ऊँची रखी गयी हैं।

जो व्यक्ति न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जाए उसमें भारत के नागरिक होने का अतिरिक्त (अ) किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर पाँच वर्षों तक काम करने का अनुभव होना चाहिए अथवा (ब) वह दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में बर्तीत रह चुका हो अथवा (स) वह राष्ट्रपति की राय में कानूनशास्त्र तथा न्यायशास्त्र में प्रख्यात विद्वान हो।

योग्यताओं का सूची में इस अंतिम प्राविधान को शामिल करने का अभिप्राय केवल यह था कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक अधिक विस्तृत दायर में से की जाय। इस प्रकार इस प्राविधान के अंतर्गत एक ऐसे विधिशास्त्री का जो किसी विश्वविद्यालय में विधिशास्त्र का अध्यापन कर रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जा सकता था।

3 अवधि—संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भाँति भारतीय संविधान न्यायाधीशों की अवधि जीवन पर्यंत नहीं बनाता इस सम्प्रदाय में उसने यह व्यवस्था की है कि वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं। भारत में जोसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु निश्चय हो बहुत अधिक है।

4 सेवा-निवृत्त होने के बाद वकालत करने का निषेध—कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। परन्तु सविधान की कोई भी व्यवस्था उसे भारत सरकार के अन्तर्गत किसी ऐसे काम का उत्तरदायित्व लेने से नहीं रोकती जिसमें उसके विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। वस्तुतः सविधान सभा में इस बात की ओर इशारा भी किया गया था कि इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक ही जैसा समझा जाना चाहिए, परन्तु इस दृष्टिकोण को सविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया।

5 पदच्युति—सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल प्रमाणित कदाचार अथवा अयोग्यता के आधार पर अपने पद से च्युत किया जा सकता है। सदन को इस सम्बन्ध में यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह इस कदाचार अथवा अयोग्यता की जाँच करने के लिए प्रक्रिया निश्चित करे। परन्तु यह प्रक्रिया चाहे जो भी हो, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए यह आवश्यक है कि सदन का प्रत्येक सदन उन्मत्त एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, ये सदस्य सदन की कुल सदस्य-संख्या के आधे से अधिक होने चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव राष्ट्रपति को सम्बोधित किया जायेगा और वह उस पर अपना आदेश देगा।

6 वेतन—भारत में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को कायम रखने के उद्देश्य से न्यायाधीशों के वेतन को व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से मुक्त रखा गया है। इस सम्बन्ध में सविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक न्यायाधीश को 4000 रुपया मासिक वेतन दिया जायेगा तथा मुख्य न्यायाधीश का वेतन 5000 रुपया मासिक होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायाधीश को रहने के लिए मुफ्त मकान तथा कुछ अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी दी जायेगी। वित्तीय संकट के समय सदन द्वारा पारित कानून के द्वारा न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है।

7 सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार—सविधानकार केवल इतने से ही मन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक व्यवस्था और की जिसके अनुसार न्यायालय को अपने कार्यालय तथा सहायक कर्मचारियों के ऊपर पूरा नियन्त्रण प्रदान किया गया है। इस प्रावधान की अनुपस्थिति में न्यायालय की स्वतन्त्रता का वास्तव में कोई अर्थ नहीं हो सकता था। अतः सर्वोच्च न्यायालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। उनकी सेवा की परिस्थितियों का निर्धारण भी न्यायालय के द्वारा होता है तथा उनके वेतन, भत्ते आदि का व्यय भारत की सचिव निधि पर भारित होता है।

8 आलोचना से मुक्ति—अन्त में, न्यायालय की स्वाधीनता को सुरक्षित रखने के लिए सविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीशों द्वारा सरकारी अधिकारियों की हैसियत से लिये गये निर्णयों के लिए उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि न्यायालय के निर्णय अथवा किसी न्यायाधीश के मत का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जिन बातों का निषेध किया गया है वह केवल यह है कि निर्णयों को देने के सम्बन्ध में न्यायाधीशों की ईमानदारी में सन्देह व्यक्त नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

सविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिक से अधिक सात अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, इसके साथ ही सविधान ने सदन को न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार प्रदान किया है। सदन ने पिछले वर्षों में अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया है, फलतः आज न्यायाधीशों की संख्या मात्र में घटकर चौदह हो गयी है और इनमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। जैसा कहा जा चुका है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उन न्यायाधीशों के परामर्श में की जाती है, जिनमें वह परामर्श लेना चाहता है, और उनमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। यद्यपि सविधान के अनुसार न्यायाधीश उच्च न्यायालय

का तम वष का अनुभव प्राप्त गन्वायेन अथवा पाँच वष का अनुभव प्राप्त उच्च यायालय का यायाधीश अथवा प्रख्यात विधिशास्त्री हो सकता है तथापि आज तक जितने भी यायाधान नियुक्त हुए हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिसका उक्त याग्यताओं में से अंतिम याग्यता का आधार पर नियुक्त किया गया हो। चूंकि यायाधीशों के लिए सेवा निवृत्त होने की आयु 65 वर्ष मानी गया है इसलिए सर्वोच्च यायालय के यायाधानों में आयु निरंतर परिवर्तन होता रहता है।

सर्वोच्च यायालय का अधिकार क्षेत्र

सर्वोच्च यायालय के अधिकार क्षेत्र का तीन शीपों में विभाजित किया जा सकता है—
प्राथमिक अपीलीय तथा परामर्शदात्री। यहाँ उनकी विवेचना आवश्यक है।

(1) प्राथमिक अधिकार-क्षेत्र—सर्वोच्च यायालय को निम्नलिखित विवादों में विषय में प्राथमिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है—(1) जो विवाद भारत सरकार तथा किसी राज्य सरकार के बीच उत्पन्न (2) जिस विवाद में भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकार एक-दूसरे के साथ अथवा एक-दूसरे के अधिकारों के विषय में उत्पन्न (3) जब किसी दो अथवा अधिक राज्यों के बीच कोई ऐसा विवाद उत्पन्न जिसमें किसी कानून अथवा तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और जिसमें ऊपर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मध्यम राज्यों में एक-दूसरे के अधिकारों के विषय में उत्पन्न होने वाले विवादों में सर्वोच्च यायालय का भारतीय मध्य के विभिन्न राज्यों में रहने वाले नागरिकों के बीच पाए जाने वाले विवादों के ऊपर प्राथमिक अधिकार-क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार के विवादों में सर्वोच्च यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। परन्तु एक बात ऐसा है जिसमें सर्वोच्च यायालय को अंतर्गत कार्य भी नागरिकों की सेवा सर्वोच्च यायालय के पास जा सकता है और वह है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कार्य भी नागरिक अपनी याचिका के साथ सर्वोच्च यायालय में जा सकते हैं। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि इस क्षेत्र पर यायालय का एकमात्र अधिकार होता है इस पर राज्यों के उच्च यायालयों का भी अधिकार है।

(2) अपीलीय अधिकार क्षेत्र—सर्वोच्च यायालय को दीवानी और फौजदारी के मुकदमों में उच्च यायालयों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च यायालय के इस क्षेत्राधिकार का तीन शीपों में अंतर्गत किया जा सकता है—सांविधानिक शीपों और फौजदारी।

(अ) सांविधानिक—संविधान के 130वें अनुच्छेद के अनुसार यदि उच्च यायालय यह प्रमाणित करे कि विवाद में संविधान सम्बन्धी कोई प्रश्न निहित है तो भारत में किसी भी उच्च यायालय के निर्णयों की अपील सर्वोच्च यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च यायालय को दीवानी फौजदारी अथवा अन्य वायव्याहिकों के बारे में क्या नहीं है। यदि उच्च यायालय इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं देता और सर्वोच्च यायालय का यह विश्वास हो जाय कि विवाद में संविधान सम्बन्धी प्रश्न निहित है तो उस स्थिति में सर्वोच्च यायालय स्वयं ही ऐसा प्रमाण पत्र लेकर अपील की विधि अपना प्रदान कर सकता है। जब किसी पत्र का उच्च यायालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है या जब सर्वोच्च यायालय अपील के लिए विधि अपना प्रदान कर देता है तो विवाद प्रस्तुत कार्य भी पक्ष सर्वोच्च यायालय से उस आशय की अपील करने का अधिकारी हो जाता है कि उच्च यायालय ने संविधान की व्याख्या गलत आधार पर की है अथवा कानून के प्रश्नों का गलत अर्थ में लिया है। अपीलार्थी सर्वोच्च यायालय की आज्ञा से अन्य आधारों पर भी अपील कर सकता है। सर्वोच्च यायालय में जो अन्य अथवा नया आधार लिया जाता है या लिया जायगा उससे लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सांविधानिक आधार पर ही आधारित हो।

(ब) दीवानी—संविधान के 133वें अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च यायालय को दीवानी के मुकदमों में अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। उच्च यायालयों के निर्णय अथवा आदेशों

के विरुद्ध किसी भी ऐसे दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि—

(1) विवादग्रस्त विषय की धनराशि प्रथम न्यायालय में बीस हजार में कम नहीं थी और अपील में आये हुए विवाद में भी कम नहीं है, अथवा

(11) निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में भी इतने घन अथवा सम्पत्ति का अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उलझा हुआ है। परन्तु यदि उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न न्यायालय के निर्णय के प्रतिबन्धन नहीं है तो फिर एक और प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा जिसमें उच्च न्यायालय प्रमाणित करेगा कि अभी और भी कानून के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं। यदि कोई पक्ष ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहता है तो फिर उसे अधिकार है कि वह भाविधानिक प्रश्न पर भी विवाद उठा सके।

(म) फौजदारी—मविधान की 134वीं धारा के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में उस समय अपील की जा सकती है, जबकि—

(1) उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुक्त किये गये अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया हो, अथवा

(11) उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय में कोई मुकदमा अपने यहाँ भेगाकर किसी अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया हो, अथवा

(111) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए उपयुक्त है।

सविधान की धारा 134 (2) के अनुसार समद कानून द्वारा शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जिनका वर्णन कानून में किया जाये, सर्वोच्च न्यायालय को भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के फौजदारी विवाद में दिये निर्णय के विरुद्ध अपील लेने और मुनने की शक्ति प्रदान कर सकती है। परन्तु जब तक धारा 134 (2) के अन्तर्गत समद कानून की रचना नहीं कर सकती, मविधान के अन्तर्गत उपर्युक्त अवस्थाओं को छोड़कर अन्य मामलों में राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध फौजदारी के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। अतः यदि कभी कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र देता है कि 'मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील किये जाने योग्य है' तो ऐसा प्रमाण-पत्र काफी सोच-विचार कर दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेक में भारत राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी मामले में दिये हुए किसी निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है, परन्तु यह बात सशस्त्र सेना से सम्बद्ध किसी न्यायाधिकरण के किसी निर्णय अथवा आदेश के सम्बन्ध में लागू नहीं होती (अनुच्छेद 136)। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनर्विलोकन (review) की शक्ति भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में मान्य होगा।

(ड) परामर्शदात्री—मविधान के 143वें अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श-दात्री श्रेणी अधिकार प्राप्त हुआ है। यदि कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी कानून अथवा न्याय के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय जानना अच्छा है तो वह उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने के लिए सौंप सकता है। न्यायालय उचित सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपनी सम्मति का प्रतिवेदन देगा, परन्तु राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस सम्मति को अन्य न्यायालय भी कानूनी रूप में स्वीकार करने को बाध्य नहीं है।

अपने कार्य-काल में सर्वोच्च न्यायालय को अभी तक मुख्यतः चार बार इस प्रकार के परामर्श देने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहला अवसर 1951 में उस समय आया था जब राष्ट्रपति ने उसमें तीन कानूनों की वैधता के बारे में अपनी राय देने को कहा था। वे कानून थे—दिल्ली नॉज एक्ट, 1912 (Delhi Laws Act, 1912), अजमेर-मारवाड़ (एक्सटेन्शन ऑफ लॉज) एक्ट, 1947 [Ajmer-Marwara (Extension of Laws) Act, 1947] तथा पार्ल 'मी'

स्टेट्स (राज) एक्ट 1950 [Part C States(Laws) Act 1950]। इन कानूनों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय एकमत से काइ राय नही दे सका। परन्तु फिर भी न्यायाधीशों द्वारा यत्न विभिन्न मतों का यह कन्फ़रन्स स्वागत किया गया था कि विधायी शक्ति के हस्तांतरण के ऊपर वे अपना प्रकाश डालते हैं।

दूसरी बार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श 1957 में करन शिक्षा विधेयक की वधता के प्रश्न पर माँगा गया था। इस विधेयक के द्वारा केरल सरकार ने अपने राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। इस विधेयक में कुछ प्राविधान एम भी थे जो सरकार को एम स्कूलों का प्रबंध अपने हाथ में लाने की अनुमति देते थे जो निजी अभिकर्षण के द्वारा प्रकाशित होते थे। चूंकि इस विधेयक का सम्बंध सविधान में निहित सम्पत्ति के अधिकार के साथ था अतः उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक था। राष्ट्रपति ने इस विधेयक का सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श के लिए मौप लिया। अपने इस परामर्श में सर्वोच्च न्यायालय ने भाषायी और धार्मिक अपसम्यक्ता का सविधान द्वारा नियंत्रित किया और संस्कृति सम्बन्धी अधिकारों के आश्रयों की व्याख्या की थी। इस परामर्श का सविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है।

1964 में सर्वोच्च न्यायालय की उत्तर प्रश्न विधान सभा बनाम राज्य के उच्च न्यायालय बना विवाद में एक बार फिर एक महत्वपूर्ण सांविधानिक प्रश्न पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारत में विधानमण्डल के निर्वाह अधिकार के क्षेत्र के सम्बंध में इस मत का भी विगिष्ट भूमिका रही है।

1974 में सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रश्न पर परामर्श मांगा गया कि क्या किसी सविधान सभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है जिसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारात्मक रूप में दिया।

सविधान के मरम्मत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय का सविधान की धारणा के क्षेत्र में अंतिम शक्ति प्राप्त है अतः उस सविधान का मरम्मत बताया गया है। सविधान के 141वें अनुच्छेद में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों का माय होगा। जहाँ तक सविधान में निहित मूल अधिकारों का प्रश्न है उनकी सुरक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का ही सापा गया है। सविधान की 13वाँ धारा में दिया है कि राज्य काइ ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिनमें तात्पर्य अथवा मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सविधान की 13वाँ धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का कानून की वधता की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार एक न्यायिक निर्णय पर आधारित है परन्तु भारत में यह अधिकार स्वयं सविधान में निहित है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं होता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में अधिक शक्ति प्राप्त है। वस्तुतः हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति अनेक प्रकार से सीमित है। सविधानकारों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका को तीसरा सदन न बन जाय। इसलिए उन्होंने स्वयं सविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की है जिससे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ को मर्यादित किया जा सके।

जसा कहा जा चुका है सविधान में न्यायिक समीक्षा का प्राविधान पाया जाता है परन्तु वह एक भिन्न प्रकार का प्राविधान है। सविधान लिखित है और उसकी रचना एक संवैधानिक व्यवस्था बना राज्य के लिए हुई है जिसमें संघीय एवं राज्यों के विधानमण्डलों की विधायी क्षमता का स्पष्ट चित्रण भी उल्लेख होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून

सविधान की 7वीं सूची में उल्लिखित शक्तियों के अनुरूप होना चाहिए। सविधान के 246वें अनुच्छेद में विधायी क्षमता के क्षेत्र परिभाषित किये गये हैं, (विधानमण्डल) को अपने क्षेत्राधिकार के सदर्भ में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। अतः अपने-अपने क्षेत्र में सघ और राज्य दोनों प्रकार के विधानमण्डल सर्वोच्चता का उन्भोग करते हैं। इस सीमा तक भारत की साविधानिक प्रणाली ब्रिटेन की प्रणाली से मिलती-जुलती है। इससे भिन्न संयुक्त राज्य अमरीका में शक्तियों के विभाजन की प्रणाली ने वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं। वहाँ कांग्रेस की शक्ति सीमित एवं परिभाषित है तथा वे सभी शक्तियाँ जिनका निषेध राज्यों के लिए नहीं किया गया है तथा जो कांग्रेस की विधायी क्षमता के बाहर नहीं हैं, राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को सौंपी गयी हैं। अमरीका में शक्तियों का यह वितरण एक नीति के अधीन हुआ था और वह नीति यह थी कि सघ की सरकार की अपेक्षा राज्यों की सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान की जाये यद्यपि बाद में बहुत सी बातों के कारण वहाँ राज्यों की अपेक्षा सघ को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। वहाँ न्यायपालिका सविधान की व्याख्या करती है तथा राज्यों अथवा सघ सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, इस बात का निर्णय इस आधार पर होता है कि न्यायाधीशों ने सविधान की व्याख्या किस प्रकार की है। संयुक्त राज्य अमरीका में एक प्रचलित लोकोक्ति यह है—‘अमरीका में हम सविधान के अधीन रहते हैं और सविधान वह है जो हमें न्यायाधीश बताते हैं।’ फलतः पिछले वर्षों में अमरीका में एक चीज का उदय हुआ है जिसे वहाँ न्यायालयों का ‘बौद्धिक मापदण्ड’ (intellectual yardstick) की संज्ञा प्रदान की गई है। भारत में न्यायपालिका के लिए यह सब कुछ करना सम्भव नहीं है। यहाँ दोनों प्रकार के विधानमण्डलों का क्षेत्राधिकार बड़ी अच्छी तरह से परिभाषित है, यहाँ तक कि समवर्ती क्षेत्राधिकार में कोई अस्पष्टता नहीं है और अवशिष्ट विषय भी सघ की ससद को सुस्पष्ट शब्दों में सौंपे गये हैं। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए शक्तियों के वितरण के सम्बन्ध में कुछ भी करने की बाकी नहीं है। अतः भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह ‘निहित शक्तियों के सिद्धान्त’ (Doctrine of Implied Powers) जैसा कोई सिद्धान्त विकसित कर सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा सविधान की 246वीं धारा में सन्निहित प्राविधानों के अधीन है।

सविधान में मौलिक अधिकारों का भी एक अव्याय है और इसमें एक अनुच्छेद ऐसा भी है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को साविधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। सविधान की इन व्यवस्थाओं ने एक दूसरे क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा को आमन्त्रित किया है। सविधान की 12वीं और 13वीं धाराएँ कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के अतिक्रमणों के विरुद्ध मूल अधिकारों की उनकी सुरक्षा का आश्वासन देती हैं। फलतः न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे यह देखें कि कोई भी कानून मूल अधिकारों के प्रतिकूल तो नहीं है। न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार सविधान की 32वीं धारा के अन्तर्गत भी प्राप्त है जिसने नागरिकों के साविधानिक उपचारों के अधिकार को मान्यता प्रदान करके उन्हें यह शक्ति प्रदान की है कि वे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं और न्यायालय बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रच्छा तथा उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। इस प्रकार का अधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी प्रदान किया गया है। न्यायालयों की इस शक्ति के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कानिया ने ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य मुकदमे में अपना निर्णय देते हुए कहा था—‘सविधान में अनुच्छेद 13 (1) (2) को अत्यधिक सावधानी के कारण शामिल किया गया है। उनकी अनुपस्थिति में भी यदि किसी कानून के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता तो न्यायालय को उसे उम सीमा तक अवैध घोषित करने का अधिकार था जिन सीमा तक उसमें मूल अधिकारों का अतिक्रमण होना हो। यहाँ भी संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की शक्तियों में अन्तर अवन्तकिन तथा जा सकता है। अमरीका में सविधान के तीसरे संशोधन को छोड़कर जिसमें शक्ति काल

म नागरिका के घरा म सनिका को निमान का निपथ किया गया है अप अय प्राविधान कवन व्यवस्थापिका का गतिया का मयाप्ति करत है जोर जय भी वहा की व्यवस्थापिका काइ गमा कानून बनाती है जा उसक अधिकार तय स बाहर हो तो उम स्थिति म यति सर्वोच्च यायानय क समथ उसम सम्बद्ध काई विवाद प्रस्तुत हा ता सर्वोच्च यायानय का उस कानून का अवय प्रापित करन का अधिकार है । अमरीका म काग्रम का अधिकारा का नियमित करते की गति प्राप्त नहा है जत निमा कानून म सन्निवि नोनि अथवा उद्देश्य की यायिक बचना की जाच की जा मकता है । यी नहा अमरीका म सर्वोच्च यायानय की शक्ति समिति और प्रन गई है क्यानि उस जीवन स्वतन्त्रता जोर समाति क अधिकारा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है तथा नागरिका का न अधिकारा म कवन कानून की प्रक्रिया क नाग नी बचित किया जा मकता है । यती यह न्यतमीय है कि कानून की प्रक्रिया (Due process of law) शतावनी अत्यधिक जल्द है और समिति समी याग्रा भी प्रकता रनी ह । अनुभव साक्षी है कि यदि सविधान क प्राविधानता म अस्पष्टता पाई जाती है ता उस स्थिति म यह अनिवाय है कि उसकी या या करन बाने अभिकरण (यायपात्रिका) का शक्तिया अवन हानी चाहिय । भारताय सविधान का रम तथ्य म अवगत थ अन उहान रम बान का पूरा ध्यान रखा है कि सविधान म काई अस्पष्टता न रने ।

भारत म सर्वोच्च यायानय का किसी कानून की यायिक समीक्षा का अधिकार कवन समिति नहा दिया जा मकता क्याकि उसम किसी अधिकार का परिमामन किया गया है उसे यह अधिकार कवन समिति दिया जा मकता है कि वह रस जान की जाच कर कि कानून द्वारा जागपित सामाग सविधान म निहित उन प्राविधाना म मन खती ह अथवा नहा निनम सीमाग्रा का उन्नव किया गया है । कानून का उद्देश्य अथवा उसकी नीनि कुछ भा हो सकती ह परतु यायानय का उसकी जाच करन का काइ अधिकार नही है ।

स्पष्ट है कि भारत म यायानिका का व्यवस्थापिका का तीसरा सत्तन नहा माना गया । जत उसम यत् अप ता नता की जानी कि क कानून की रचना करगा । कानून बानता व्यवस्थापिका का काम है जोर गमा हाना उचित भी है । जाखिर व्यवस्थापिका क सदस्य जनता क निर्वाचित प्रतिनिधि हात है समिति उनरी है छा क ऊर यायपात्रिका तारा जागपित रम प्रकार का जकुन उचित नहा है । यायपात्रिका का सविधान क सरक्षक का उत्तरदायित्व दिया गया है समिति उम यायिक समीक्षा का भी अधिकार प्राप्त है ।

सर्वोच्च यायानय तथा मून अधिकारा का सशाधन

माच 1967 म एक अयधिक मन्त्रपूण निणय म सवाच यायानय न यह कहा कि समर का सविधान म निहित मून अधिकारा म कोई परिवर्तन करन का अधिकार प्राप्त नही है । दूसरे गता म समर को मून आधकारा की सूची म कित्ता भा प्रकार का सशोधन करने की गति प्राप्त नहा है । इस समय म सविधान की निम्नलिखित दो शाराग्रा की याग्या क सम्बध म मतकष नता पाया जाता

धारा 13 (2)—राय काइ ऐसा कानून नहा बनायगा जा इस भाग (भाग 3) द्वारा प्रन्त अधिकारा का छीनता या यून करता हा और रम खण्ड क उन्नधन म निमित प्रत्येक कानून उ नधन की सीमा तय अवध होगा ।

धारा 368—रस सविधान क मशाधन का मूनपात उस जाग्य क विषयक के किसी भी सदन म प्रस्तुतीकरण क द्वारा किया जा सकगा तथा तब प्रत्येक सदन तारा उस सदन की सम्पूण सन्स्य मर्या क बहुमत स तथा उम सदन म उपस्थित तथा मतदान म भाग लेन बाने सदस्यो के ता तिहाई स जयून बहुमत स वह विधायक पारित हा जाता है तब वह राष्ट्रपति क समक्ष उसकी अनुमति क लिए रखा जायगा तथा विधायक का ऐसा अनुमति प्राप्त हा जाने क उपरांत विधायक

के निबन्धनों के अनुसार सविधान सशोधित हो जायेगा ।

परन्तु यदि ऐसा सशोधन—

(अ) धारा 54, 55, 73, 162, अथवा 241 में, अथवा

(आ) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में, अथवा

(इ) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी एक में, अथवा

(ई) सदन के राज्यों के प्रतिनिधित्व में, अथवा

(उ) इस धारा के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जाने के पहले उस सशोधन के लिए उन विधानमण्डलों से पारित सकल्यों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।

मार्च 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो विवाद प्रस्तुत था वह 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' के नाम से प्रख्यात है । इस विवाद में अनुच्छेद 31 में निहित सम्पत्ति के अधिकार को सविधान (सत्रहवें सशोधन) कानून, 1964 के द्वारा न्यून करने की सदन की शक्ति को चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने उस पर अपना यह निर्णय दिया था कि सदन की सविधान को सशोधित करने की शक्ति सविधान की 248वीं धारा में निहित उसकी विधायी शक्ति का ही एक रूप है, अतः साविधानिक सशोधन कानून उस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है जिसे अनुच्छेद 13 के द्वारा पारिभाषित किया गया है, अतः यह सशोधन कानून अवैधानिक है । दूसरे शब्दों में इस निर्णय का अर्थ है कि सदन को सविधान में सशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों को न्यून अथवा खत्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि भारत सरकार मूल अधिकारों के सम्बन्ध में सविधान में सशोधन करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 248 तथा सघ सूची के 97वें विषय (Item) में निहित अवशिष्ट शक्तियों के कार्यान्वयन के अन्तर्गत नई सविधान सभा को बुलाने का आयोजन करना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने मूल अधिकारों को सदन की साविधानिक शक्ति से परे बना दिया । इसके पूर्व सदन 1951, 1955 और 1964 में प्रथम, चतुर्थ और सत्रहवें सशोधनों के द्वारा सविधान में निहित मूल अधिकारों को सशोधित कर चुकी थी । 1967 के अपने निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने इन सशोधनों को भी अवैध घोषित कर दिया । परन्तु चूंकि ये सशोधन इस निर्णय से बहुत पहले किये जा चुके थे तथा पिछली तिथि से उन्हें अवैध करने से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती थी, अतः यह कहा गया कि वे लागू रहेंगे ।

सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय निस्सन्देह अत्यधिक दूरगामी प्रभाव वाला था । इस निर्णय ने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म दिया । क्या सदन सविधान में सशोधन करने के लिये प्रभुसत्ता-सम्पन्न नहीं है ? इस निर्णय का न्यायपालिका पर सविधान के संरक्षक के रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप सविधान इतना दुस्सहोध्य बन जाएगा कि जन-इच्छा द्वारा कोई भी सुगम परिवर्तन न किया जा सके । पिछले दिनों में इन प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये हैं वे एक दूसरे के विरोधी हैं । उदाहरण के लिये यदि के० एम० मुशी ने कहा कि मूल अधिकारों को सदन की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता तो इसके विपरीत सुख्यात वकील एन० सी० चटर्जी ने राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया था कि सदन की प्रभुसत्ता के मामले को सन्देह से ऊपर उठाया जाये । यदि कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया तो देश के अधिकांश चिन्तनशील व्यक्तियों के मन में यह आशंका घर कर गई कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रगतिशील विधायन के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा ।

गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त देश के राजनीतिक जीवन में अत्यन्त द्रुतगति के साथ परिवर्तन उपस्थित हुए हैं और इन परिवर्तनों की वैधता को अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । जब-जब इन प्रकार के मामले सर्वोच्च न्यायालय

म प्रस्तुत किया गया था। यायानयन न अपना निणय यथास्थिति के पक्ष में लिया। 1969 में सरकार ने 14 वें बका का राष्ट्रियकरण करने का निर्णय किया और उमन डेम जाशय का एक विधायक समझ में पड़ा किया। इस विधायक का जहाँ दंग के प्रगतिशील जनमत का समर्थन प्राप्त था वहाँ स्वतंत्र पार्टी जनमध तथा पुगता काग्रस न उमका इस आधार पर विरोध किया कि उमम दंग की अव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वह सम्पत्ति के मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। समझ न विधायक का पारित कर लिया परंतु सर्वोच्च यायानयन उम असाविधानिक घोषित कर लिया। यायानयन का मन था कि मविधान न प्रतिकर के अधिकार की प्रत्याभूति ली है जो अजित का जान वाली सम्पत्ति के बराबर हाना चाहिए जिस तरीके से बका की सम्पत्ति का मूल्यांकन किया गया है उमम उनकी जनता के महत्वपूर्ण अंगों को सम्मिलित नहीं किया गया है फलतः बका का पूरा प्रतिकर नहीं दिया जा रहा है जो कि मविधान द्वारा दंग गारंटी के विरुद्ध है इसलिए विधायक अवध है। कुछ दिन बाद समझ न इस सम्बन्ध में सगाधित विधायक का पारित किया और वही कानून बना।

1970 में भारत सरकार ने भूतपूर्व नरगा के विभागाधिकारों तथा उनके दी जाने वाले प्रिवी पर्सों (Privy Purses) का अंत करने के लिए संविधान के मशौन हनु 24वाँ मशौधन विधेयक समझ में प्रस्तुत किया। इस विधेयक का ताकमभान आवश्यक दा तिहाइ बन्मन में पारित कर दिया परंतु गण्यमभा में वह थानी मी कमा के कारण वाछित दा तिहाइ बन्मन प्राप्त नहीं कर सका। उमके बाद सरकार ने उमा उद्भय को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति से एक अध्यात्म निकलवाया जिसमें दंग सभी नरशा में मायता छीन ना गई तथा उनके विभागाधिकारों एवं पर्सों का अंत कर लिया। इस आदेश के विरुद्ध कुछ नरगा न सर्वोच्च यायानयन में अपील की यायानयन ने राष्ट्रपति के आदेश को अवध घोषित कर लिया। यहाँ यह उलखनीय है कि अपन निणय में मुख्य यायाधिपति हिलायतुता न ता प्रिवी पर्सों का सम्पत्ति घोषित किया और कहा कि उनका अंत करने का जय है संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में हस्तक्षेप। निर्णय ही सर्वोच्च यायानयन का यह निणय एमा था जिस सामाजिक प्रगति के माग में राना माना जा सकता था। बन्मन इसी पृष्ठभूमि में 1971 के ताकमभा के मयावधि चुनावों में काग्रस की विजय के महत्व को समझा जा सकता है। इन चुनावों के परिणामों से यह स्पष्ट है कि जनता सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन चाहती है। सर्वोच्च यायानयन के निणय जनता की लोकतान्त्रिक च्छा के कायावयन में बाधक सिद्ध हुए हैं। फलतः पिछले दिनों में यायानयन की प्रतिष्ठा का आच पड़ची है। निम्नदेह यह स्थिति वाछनीय नहीं है। अतः इसका अंत करने के लिए संविधान में 25वें और 26वें सगाधना के द्वारा समझ का उसकी प्रभुसत्ता को दिनात का फिर से प्रयास किया गया है। संविधान में आवश्यक परिवर्तन और उसकी सीमा में रहन कानून बनाना मसद का अधिकार है और ऐसा जाना भी चाहिए। यायानयन काइ विभागी सदन नहीं है उमका काम तो केवल संविधान का संरक्षण करना और कानूनों का अंतिम निवचन करना है।

1972 में सर्वोच्च यायानयन के समुख कंगवान न भारती का मुकामा जाया। मुन्ता यह था कि क्या समझ न मविधान में 24 25 26 और 29वें सगाधन करके अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। इस सम्बन्ध में मुख्य यायाधीश सीकरी ने अपन निणय में कहा कि ससद को मूल अधिकारों को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। वह उन्हें सगाधित कर सकती है उनका बदलती ह न परिस्थितियाँ के साथ तात मल बठाने के लिए उनमें कुछ हेर पर कर सकती है तथा उन्हें नियमित भा कर सकती है। किंतु इस प्रक्रिया में अधिकार नष्ट नहीं हान चाहिए। संविधान के ढांचे के अंदर इन तत्त्वों को भी सन्निहित बताया गया—संविधान की मर्को चता सरकार का राजतान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक स्वरूप दंग की प्रभुसत्ता संविधान का धमनिरपेक्ष तथा सघात्मक ढांचा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद

वात 1973 की है। मूल अधिकारों से सम्बद्ध मुकदमों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने उस दिन घोषित किया था जिसके एक दिन बाद मुख्य न्यायाधीश सीकरी सेवा-निवृत्त होने वाले थे। अतः उनके स्थान पर एक नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी। राष्ट्रपति ने इस पद पर ए० एन० राय को नियुक्त किया। परन्तु ऐसा करके उन्होंने तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशों—शेल्ट, हेडगे और ग्रोवर—के इस पद पर नियुक्त होने के दावे की उपेक्षा कर दी। ए० एन० राय की इस नियुक्ति के विरोध में तीनों न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। फलतः यह विचार सामने आया कि सरकार के इस काम से देश में लोकतन्त्र की हत्या हो गई है, कानून और न्याय की समूची इमारत ढहकर नीचे गिरने लगी है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रान्ति दल के अध्यक्ष चरणसिंह ने अपने एक भाषण में कहा कि देश शनैः शनैः अधिनायकतन्त्र की ओर जा रहा है। इसी प्रकार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता ए० के० गोपालन और पी० राममूर्ति ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि 'तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से हमारे इस दृष्टिकोण को बल पहुँचा है कि सत्तावादी प्रवृत्तियाँ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं।' इसी प्रकार का मत भूतपूर्व न्यायाधीश के० एस० हेडगे ने अपने त्यागपत्र के बाद दिये गये सम्वाददाता सम्मेलन में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतन्त्र के लिए आवश्यक सभी तत्त्व एक-एक करके नष्ट किये जा रहे हैं। देश में शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव है, जागरूक लोकमत की अनुपस्थिति है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग साक्षर भी नहीं हैं, प्रेस की स्वतन्त्रता का भी धीरे-धीरे लोप हो रहा है क्योंकि आज प्रेस की स्वतन्त्रता का केवल एक ही अर्थ है और वह है सरकार की प्रशंसा करने की स्वतन्त्रता। चौथा आवश्यक तत्त्व है स्वतन्त्र न्यायपालिका, अब उसका भी सफाया कर दिया गया है।

भारत में न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच पाया जाने वाला विवाद 1973 में कोई यकायक उठकर खड़ा नहीं हो गया। वास्तव में उसका जन्म 1967 में उस समय हुआ था जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के मुकदमे में यह निर्णय दिया था कि संसद को मूल अधिकारों, विशेषतः सम्पत्ति के अधिकार को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि सरकार और विपक्ष में से किसी ने भी इस विवाद के सम्बन्ध में अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण इन शब्दों में नहीं किया है, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय से लेकर बराबर अब तक सरकार के इन दोनों अंगों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही है। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय से भी इस संघर्ष का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं हुआ है क्योंकि इस निर्णय में जहाँ मूल अधिकारों को संशोधित करने के संसद के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी है, वहाँ उसमें यह भी कहा गया है कि वह इन अधिकारों को इस प्रकार संशोधित नहीं कर सकती जिससे संविधान की आत्मा ही नष्ट हो जाये और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार अपने में सन्निहित माना है कि कोई भी संशोधन इस कसौटी पर खरा उतरता है अथवा नहीं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच पाये जाने वाले विवाद का अन्तिम समाधान हो चुका है। वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बद्ध विवाद को इसी पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए।

इस सन्दर्भ में सरकार के लिए यह उचित ही था कि वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यताओं के अतिरिक्त इस बात को भी ध्यान में रखे कि उनकी किस प्रकार के 'सामाजिक दर्शन' में जास्था है। इस सम्बन्ध में लोकसभा में सरकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए तत्कालीन उत्पात-मन्त्री मोहन कुमारमगलम ने कहा था कि न्यायाधीश के निर्णय उसके दृष्टिकोण एवं उसके दर्शन में प्रभावित होते हैं। 'हमारे लिए इसकी उपेक्षा करना भूर्वता होगा। अराजनीतिक न्यायाधीश जैसा अद्भुत व्यक्ति हमें कहीं नहीं दिखाई देता।' अपने भाषण में

कुमारमगनम न मून अधिसारा के मुकद्दम म यायाधीश के निणया का उतख किया और कहा कि य विभिन्न निणय अस बात के छानक है कि मून अधिसारा एव नीति निगक सिद्धान्त के सम्बन्ध म इन यायाधीश के दृष्टिकाण म समानता नह है । उन्हान कहा कि सरकार का यह वतव्य और अधिकार है कि व इस निणय पर पहुँचन के पूर्व कि कोई यायाधीश सर्वाच्च यायालय को किसी निश्चित समय पर नवृत्त प्रदान कर अथवा नह । उसकी यायिक निष्ठा एव कानून के ज्ञान के अतिरिक्त उसने दान एव उसके दृष्टिकाण का भी ध्यान म रख । उन्हान कहा कि सरकार प्रतिपद्ध यायाधीश नह चाहती । परन्तु एस यायाधीश अवश्य चाहती है जो जाग का ओर खत ध्यान न पोछ की ओर नह । कुमारमगनम न अपन भाषण म ब्रिटन कानून संयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रिया जस लोकतान्त्रिक दगा म राजनीतिक व्यक्तिया के यायाधीश के पद पर नियुक्त हान के उल्लेख दिये । परन्तु उन्हान कहा कि भारत म इस सम्बन्ध म स्थिति भिन्न रहा है यहा राजनीतिक पात्रिया के मदम्या का यायाधीश के पद पर नियुक्त नही किया जाता ।

भारताय सर्वोच्च यायालय का मूल्यांकन ✓

यह बात निर्विवाद है कि मधाय शासन प्रणाली म सर्वोच्च यायालय जस अमिकरण की आवश्यकता है । भारत म सर्वोच्च यायालय न इस भूमिका को अदा करने का प्रयास किया है और व त से सामना म उसकी यह भूमिका प्रगतिनाय भी रहा है । परन्तु जितना हान हुए भी इस सत्य म अनकार नही किया जा सकता कि आज के युग के मुख्य प्रश्न पर जो सम्पत्ति के अधिकार के साथ सम्बद्ध है उसका दृष्टिकोण रुढ़िवादी रहा है । ऊपर गानवनाय वकी का राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पक्षों के मुकद्दमा का उतख किया जा चुका है इन सभी मामलों म यायालय का दृष्टिकाण यथास्थिति के कायम रखने के पक्ष म था । उसका बदलने के पक्ष म नह था । अपन इस दृष्टिकाण के वावजूत भी सर्वोच्च यायालय का आज तक जनसाधारण न सामान्य रूप से सम्मान ही प्रदान किया है उस जनता जानाचना एव ब्राह्म का निष्कार नह बनाया है । वस्तुतः एसा हाना स्वाभाविक भी था क्याकि भारतीय सविधान यायशास्त्रिका को असीमित शक्ति प्रदान नह करता तथा भारत म मून अधिकारी के स्वरूप भा उतना दृष्टान्त नही है जितना कि वह संयुक्त राज्य अमरीका म पाया जाता है । सविधान की यह दुष्मन्नीयता इस बात की गारन्टी है कि भारत म यायाधीशों का सरकार कभी कायम नह हो सकेगी । परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नह है कि भारत न सार्वधानिक शासन म सर्वोच्च यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण नह हो सकता । इस सम्बन्ध म अन्तर्दी दृष्टांतास्वामी अथर का यह कथन उद्धरणाय है— भारतीय सविधान का आगामी विकास एक बन्नी सीमा तक सर्वोच्च यायालय के काम तथा इस विकास का यायालय द्वारा निष्ठा गर्ई दिशा के उपरनिभर करेगा । समय समय पर सविधान के निवचन के समय सर्वोच्च यायालय का उन परस्पर विरोधी शक्तिया का सामना करना पड़ेगा जो तत्कालीन समाज म काम कर रही हंगी । जहा उसका काम सविधान की पालन करना है वहा वह अपन कर्तव्य के निष्पादन म अपन समय की सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक प्रवृत्तिया का उपभोग नही कर सकता । उस निष्ठा पन्न वाली परस्पर विरोधी शक्तिया के वाच म सन्तुलन कायम रखना है ।

प्रश्न

- 1 यायालिकों का स्वतन्त्रता का रक्षण करने के लिए सविधान म क्या प्राविधान किए गये हैं ?
- 2 सर्वोच्च यायालय का अधिकार क्षेत्र बताइये ।
- 3 मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च यायालय का भूमिका बताइये ।

राज्य और संघीय क्षेत्रों का शासन

(GOVERNMENT OF THE STATES AND THE UNION TERRITORIES)

यद्यपि सविधानकारो ने समूचे सविधान में किसी एक भी स्थान पर 'सघवाद' (Federalism) शब्द का प्रयोग नहीं किया है तथापि इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सविधान सभा में 'सघवाद' के सारतत्त्व की विस्तारपूर्वक विवेचना की गई थी, तथा अन्त में जब सविधान बनकर सामने आया तो उसमें 'सघवाद' के तत्त्व आसानी से अवलोकित किये जा सकते थे। सविधान में भारत को राज्यों का सघ (Union of States) बताया गया है तथा इस सघ अथवा यूनियन में जो राज्य सम्मिलित हैं उनके नाम सविधान की प्रथम सूची में उल्लिखित हैं। विश्व के अन्य सविधानों से भिन्न आरम्भ में भारतीय सघ की इन इकाइयों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था—'क' श्रेणी के राज्य, 'ख' श्रेणी के राज्य तथा 'ग' श्रेणी के राज्य। सघात्मक शासन प्रणाली के इस जटिलस्वरूप की यथार्थ में उन ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर ही व्याख्या की जा सकती है जिनमें भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। परन्तु राज्यों का इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत दिन नहीं चल सकता था, उनका पुनर्गठन आवश्यक था। यथार्थ में पुनर्गठन की यह प्रक्रिया आरम्भ से ही शुरू हो गई थी। 1956 में इसका पहला परिणाम सामने आया, किन्तु उससे देश के जनमानस को पूर्णरूप से सन्तोष नहीं मिल सका। अतः यह काम बाद तक चलता रहा। फलतः भारतीय सघ में आज 21 राज्य हैं।¹ इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो वैधानिक दृष्टि से केन्द्र के आधीन हैं, इन्हें 'केन्द्र प्रशासित प्रदेश' कहा गया है।

भारतीय सघ के इन राज्यों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका के राज्यों की भाँति इनका अपना अलग सविधान नहीं है। यदि इसका कोई अपवाद है तो वह जम्मू-कश्मीर का राज्य है जिसे अपना अलग से सविधान बनाने का अधिकार दिया गया है। समूचे देश का एक ही सविधान है और इस सविधान में ही राज्य सरकारों की शासन-व्यवस्था का विवरण दिया हुआ है। केन्द्र की सरकार की ही भाँति राज्यों की शासन-प्रणाली भी ससदीय प्रकार की उत्तरदायी शासन-प्रणाली है। सविधान में इन राज्यों का कार्यक्षेत्र पहले से ही परिभाषित कर दिया गया है। साधारणतः यह वह क्षेत्र है जिसमें केन्द्र सरकार उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। यहाँ राज्यों की शासन-प्रणाली की विवेचना आवश्यक है।

राज्यों की कार्यपालिका (State Executive)

जैसा कहा जा चुका है कि राज्यों में कार्यपालिका का संगठन केन्द्र की भाँति ही किया गया है। फलतः राज्यों की कार्यपालिका को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है— औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। राज्यपाल राज्य में सामान्यतः औपचारिक

¹ इन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं—(1) आन्ध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) गुजरात, (5) हरियाणा, (6) हिमाचल प्रदेश, (7) जम्मू और कश्मीर, (8) केरल, (9) मध्य प्रदेश, (10) महाराष्ट्र, (11) पंजाब, (12) नागलैण्ड, (13) उड़ीसा, (14) पंजाब, (15) राजस्थान, (16) तमिलनाडु, (17) त्रिपुरा, (18) उत्तर प्रदेश, (19) पश्चिमी बंगाल, (20) मणिपुर, (21) मेघालय।

कायपानिका का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि एम उदाहरण है जबकि रायपाना न अपन पद की मर्यादा का उत्तरधन किया है। मन्त्रिमण्डल में राय की वास्तविक कायपानिका गतिविधि निहित है। यहाँ इन दोनों प्रकार का कायपानिका की समीक्षा अप्रसंगिक नहीं होगी।

1. राज्यपाल का पद तथा उसका उभरता हुआ स्वम्भ

संविधान के अंतर्गत राय की कायपानिका शक्तियाँ रायपान में निहित हैं। राय का शासन यथाथ में उसी के नाम में परिचालित होता है। जब संविधान सभा में राय के अध्यक्ष के पद पर विचार किया जा रहा था तब यह प्रस्तावित किया गया था कि रायपान का निर्वाचन सम्बद्ध राय की जनता के द्वारा होना चाहिए। परन्तु इस सुझाव का संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। सभा का मन था कि जनता द्वारा निर्वाचित रायपान तथा विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी मुख्य मंत्री के बीच सह-अस्तित्व सम्भव नहीं है। यही नहीं 1947 में तब 1949 तक शासन के संचालन का जो अनुभव संविधानकारों ने प्राप्त किया था उसमें वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि यदि एक में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है तो यह आवश्यक है कि रायपान के अतिरिक्त राय का जोवन वाली सांविधानिक कक्षा के रूप में काम करे। अतः यह निष्पत्ति किया गया कि रायपान की नियुक्ति मधाय कायपानिका के द्वारा होना चाहिए तथा उस पदस्थित करने का अधिकार भी उसी का होना चाहिए। व्यवहार में इसका अर्थ था कि रायपान की नियुक्ति प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय के द्वारा होगी। परन्तु इस सम्बन्ध के कानूनी म एक परम्परा विकसित हुई जिसके अनुसार रायपान का नियुक्त करने में पूर्व सच की सरकार सम्बद्ध राय के मुख्य मंत्री से परामर्श लेती थी। परन्तु इस परम्परा का सभी जगह पालन नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर सरकार ने जब श्रीप्रकाश को मन्त्रिमंडल का रायपान नियुक्त किया था तब उसने कक्षा के मुख्य मंत्री से परामर्श नहीं किया था। इस प्रकार उदाहरण में जब कुमारस्वामी राजा का रायपान नियुक्त किया था तो उस समय भी वही के मुख्य मंत्री से सलाह नहीं मांगी गयी थी। यह स्थिति उस समय थी जब श्री नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। जबकि कांग्रेस दल की सरकारें दशक के सभी रायों में स्थापित थी। स्पष्ट काश्मीरी मुख्य मंत्रियों में नेहरू जी का विरोध करने की अपेक्षा नष्ट का जा सकती थी। परन्तु श्री नेहरू के निधन के उपरान्त विपक्ष चौथे आम चुनाव के उपरान्त इस स्थिति में एक मौलिक परिवर्तन उपस्थित हुआ। इस नया पृष्ठभूमि में यदि किसी राय में मुख्य मंत्री के परामर्श के बिना रायपान की नियुक्ति की जाती तो उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी। इस सम्बन्ध में पश्चिमी जगत में मुख्य मंत्री एवं रायपान के पारस्परिक सम्बन्ध का उदाहरण दिया जा सकता है। इस राय में वसुंधरा का रायपान के पद पर राय सरकार के परामर्श के बिना नियुक्त किया गया था। मार्च 1969 में मुख्य मंत्री अजय मुखर्जी ने कक्षा में धर्मवीर को वापिस बुलाने का आग्रह किया क्योंकि वह राय के प्रशासन का मन्त्रिमण्डल के सहयोग के साथ संचालित करने में असमर्थ थे। परन्तु कक्षा ने इस माँग को यह कहकर ठुकरा दिया कि सच सरकार इस परिपाटी के विरुद्ध है कि राय सरकारों की वृत्ति के अनुसार रायपानों की नियुक्ति का आग्रह। परन्तु कक्षा सरकार को वास्तव में यह करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

रायपान की नियुक्ति से सम्बद्ध सांविधानिक व्यवस्थाएँ एवं उसके अभिसमयों की विवेचना में स्पष्ट है कि भारतीय प्रणाली मधाय शासन प्रणाली के सिद्धांत से भिन्न नहीं होती। यदि भारत में समुदायी शासन प्रणाली के अंतर्गत रायपान को औपचारिक कायपानिका बनाना अभीष्ट था तो ऐसा उस राय विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित कराकर भी किया जा सकता था। यथाथ में रायपान की नियुक्ति को प्रचलित प्रणाली उस औपचारिक कायपानिका का भूमिका अर्थ करने की अपेक्षा सच सरकार के अभिकता की भूमिका अर्थ करने के लिए विवक्षित करती है।

राज्यपाल की शक्तियाँ

सविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन शक्तियों को चार शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है (अ) कार्यपालिका शक्तियाँ, (व) विधायी शक्तियाँ (स) वित्तीय शक्तियाँ, (द) न्यायिक शक्तियाँ।

(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ—जैसा कहा जा चुका है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित की गई हैं। उसका यह अधिकार है कि मन्त्रिमण्डल उसे अपने निर्णयों से अवगत कराये तथा उसे राज्य के प्रशासन में सम्बद्ध सूचनाएँ प्रदान करे। मुख्य मन्त्री की नियुक्ति उसी के द्वारा होती है तथा मुख्य मन्त्री की सिफारिश पर वह अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मुख्य मन्त्री की अभ्यर्थना पर वह राज्य के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे, एडवोकेट जनरल तथा लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की परिधि में वे सभी विषय आते हैं जो सविधान की सातवी अनुसूची में उल्लिखित हैं और जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधानमण्डल को कानून बनाने का अधिकार है। जहाँ तक सम्बन्धी सूची में दिये हुए विषयों का सम्बन्ध है, राज्यपाल की शक्तियों को राष्ट्रपति के अधीन माना गया है।

(व) विधायी शक्तियाँ—सविधान ने राज्यपाल को राज्य विधानमण्डल का एक अंग बनाया है तथा उसकी रचना में उसे कुछ भूमिका प्रदान की है। 333वें अनुच्छेद के अन्तर्गत वह राज्य विधानसभा में आगल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को उस स्थिति में मनोनीत कर सकता है, यदि उसकी राय में इस समुदाय के लोगों का विधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। 1969 में पारित 23वें संशोधन ने राज्यपाल की इस शक्ति को थोड़ा मर्यादित कर दिया है, अब वह एक नए अधिक सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पायी जाती है, उनमें राज्यपाल को विधान परिषद् में कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, महारिक्ता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में त्यागित अर्जित की हो। सविधान की 192वीं धारा में यह व्यवस्था की गई है कि यदि विधान सभा का कोई भी सदस्य 191वें अनुच्छेद में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसके सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु निर्णय लेने के पूर्व राज्यपाल के लिये यह आवश्यक बताया गया है कि वह उसके सम्बन्ध में चुनाव आयोग की राय जान ले। राज्यपाल को विधान सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों के आकस्मिक तरीके से रिक्त हो जाने की स्थिति में यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्थायी प्रवन्ध के न होने तक सभा की बैठकों में अध्यक्षता करने के लिये किसी सदस्य को मनोनीत कर दे। इसी प्रकार वह विधान-परिषद् में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के रिक्त हो जाने पर अस्थायी अध्यक्ष को मनोनीत कर सकता है।

राज्यपाल को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को अथवा किसी एक सदन को अथवा दोनों सदनों को अलग-अलग सम्बोधित करने का अधिकार है। सामान्यतः वह विधानमण्डल के अधिवेशन के आरम्भ होते समय उसके संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण करता है, वास्तव में यह अभिभाषण उसी प्रकार का है जैसे मधीय सदन में राष्ट्रपति का होता है।

राज्य विधानमण्डल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून उस समय तक नहीं बन सकता जब तक कि उसे राज्यपाल की अनुमति प्राप्त न हो जाये। इन विधेयकों को राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे सकता है, उन्हें वह स्वीकृति देने से इनकार भी कर सकता है तथा उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए मुरक्षित रख ले। उसके अतिरिक्त सविधान ने उसे यह अधिकार भी माँपा है कि वह उन विधेयकों को अपने सुझावों के साथ व्यवस्थापिका को लौटा दे। परन्तु यदि विधानमण्डल उन्हें द्वारा उसी रूप में पारित कर दे तो उन स्थिति में राज्यपाल उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए विवश है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि

रायपान का धन विधायक का जौगान का अधिकार नहीं है। काइ भी धन विधायक विधानसभा में उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पारित करने की अभ्ययना पर रायपान के हस्ताक्षर न हों।

सविधान रायपान को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्रदान करता है। ऐसा उस समय किया जा सकता है जबकि राय के विधानमण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो। रायपान द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही बलता प्राप्त है जो विधानमण्डल द्वारा पारित कानून का मिलती हुई होती है। परंतु यह विधानमण्डल के अधिवेशन के प्रारम्भ होने के त्र्य महीने बाद केवल उस स्थिति में प्रभावशाली हो सकता है यदि उस विधानमण्डल की स्वीकृति प्राप्त हो जाय।

(स) वित्तीय शक्तियाँ—सविधान ने राय की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व रायपान को सौंपा है। इस सम्बन्ध में उस जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वे हैं (i) को भी धन विधायक रायपान की पूर्व अनुमति के बिना राय की विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। (ii) रायपान राय के बजट को विधान सभा में प्रस्तुत कराता है। (iii) राय की आकस्मिकता निधि का नियंत्रण रायपान के अधिकार में है। इस निधि में से वह राय की सरकार का आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम राशि ले सकता है परंतु इसकी बात में राय विधान सभा द्वारा पुष्टि आवश्यक है।

(द) यायिक शक्तियाँ—सविधान की 161वां शारा ने रायपान का कुछ ऐसी शक्तियाँ सौंपी हैं जिनकी प्रकृति अवस्थायिक है। इसमें कहा गया है कि रायपान उन विषयों से सम्बद्ध अपराधों में जो राय की कार्यपालिका शक्ति का परिधि में आते हैं अपराधियों को क्षमा कर सकता है तथा उनकी सजा में कमी अथवा परिवर्तन कर सकता है। यहाँ यह जानना है कि रायपान को किसा ऐसे अपराधों का क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है जिनमें सघ सरकार के कानून का उल्लंघन किया है एम अपराधों का क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति का दी गई है।

निष्कर्ष—सविधान के उपर्युक्त प्राविधानों से ऐसा लगता है कि रायपान राय की वास्तविक कार्यपालिका है तथा उसकी स्थिति ब्रिटिश नामनकान के प्रांता के गवर्नरों में मिलती जुलती है। परंतु सामान्यतः यह सत्य नहीं है। रायपान से आम तौर पर इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शक्तियों का कार्यावलीन मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर करेगा। सविधान के 163वें अनुच्छेद की पहली उपधारा में लिखा है कि— रायपान के कार्यों के निष्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होगा जो वह उस केवल उन विषयों को छोड़कर—जिनमें उससे सविधान के द्वारा अथवा सविधान के अंतर्गत अपने विवेक से काम करने का अपेक्षा की जाती है सभी अन्य विषयों में सहायता करेगा। यह बातों की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार का प्राविधान राष्ट्रपति के सम्बन्ध में नहीं पाया जाता। परंतु साधारण कानून में सविधान ने रायपान का कार्य ऐसा काय नहीं सौंपा है जिसकी कार्यक्षमता वह अपने विवेक से कर सके। इसका केवल एक अपवाद है जो वह है असम का राज्यपाल जिस केवल कदाचित् एव सीमांत क्षेत्रों के प्रशासन के संचालन में अपने विवेक का प्रयोग में आने की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त रायपान को अपने विवेक के द्वारा यह भी निश्चित करने का अधिकार है कि मुख्य मंत्री के पद पर किसका नियुक्त किया जाय विधान सभा का भंग किया जाय अथवा नहीं तथा राय में सांविधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने का प्रतिबन्धन राष्ट्रपति के पास किस प्रकार भेजा जाय। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामान्यतः रायपान से यह आशा की जाती है कि वह राय के प्रशासन में औपचारिक अर्थों की भूमिका अदा करेगा। यह ठीक है कि सविधान में वही यह नहीं लिखा है कि रायपाल का प्रत्येक स्थिति में अपने मंत्रियों का परामर्श स्वीकार करना चाहिये। परंतु संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जिस भारत में अपनाया गया है यह आवश्यक है कि कुछ अपवादपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतः रायपान को अपने मन्त्रिमण्डल के परामर्श से ही काम करना चाहिये। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत औपचारिक अध्यक्ष अपने द्वारा

निष्पादित कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं होता, उसमें उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल का ही होता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि वास्तविक शक्तियाँ उस अभिकरण में निहित हों जिसके पास उन शक्तियों के निष्पादन का उत्तरदायित्व है। चूँकि राज्यपाल के पास कोई वास्तविक उत्तरदायित्व नहीं है, अतः अपवादपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। सविधान सभा में तो डा० अम्बेदकर ने यहाँ तक कहा था कि शक्तियों की बात तो दूर है, राज्यपाल के तो कोई काम भी नहीं है, उसके तो केवल कर्तव्य है। उन्होंने राज्यपाल के दो कर्तव्य बताये थे—(1) मन्त्रिमण्डल को सत्ता में बनाये रखना और यह देखना कि वह इस सम्बन्ध में अपने विवेक को प्रयोग में कब लाये, तथा (2) मन्त्रिमण्डल को परामर्श देना, उसे चेतावनी देना, उसे विकल्प सुझाना, तथा उससे पुनर्विचार की माँग करना। के० एम० मुखर्जी ने कहा था कि 'राज्यपाल को मन्त्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध काम करने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसी ब्रिटेन में राजा अथवा रानी की है।' टी० टी० कृष्णमाचारी ने यह मत व्यक्त किया था कि राज्यपाल केवल 'सांविधानिक अध्यक्ष' हैं जिसके पास वास्तविक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।' अपने एक लेख में एच० बी० कामथ ने राज्यपाल के पद पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि वह 'उम कठपुतली' से कुछ अधिक है जिसे एक तरफ से मुख्य मन्त्री नियन्त्रित करता है तथा दूसरी तरफ से राष्ट्रपति, जिसका अर्थ है वास्तव में प्रधानमन्त्री।' वस्तुतः 1950 से लेकर 1957 तक राज्यपाल इतने शक्तिहीन थे कि कुछ राज्यपाल स्वयं अपने भाग्य को कोसने लगे थे और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि उनके पद का कोई महत्त्व नहीं है। अपने एक लेख में डा० के० बी० राव ने सरोजिनी नायडू का यह वाक्य उद्धृत किया है जिसमें उन्होंने अपने आपको 'सोने के पिण्डों में बन्द चिड़िया' बताया था। डा० राव ने अपने इस लेख में यह भी लिखा है कि मुख्य मन्त्री भी राज्यपालों को कोई विशेष महत्त्व नहीं देते थे, तथा कुछ राज्यपालों ने इसकी नेहरू जी से शिकायत भी की थी। परन्तु इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उल्टे नेहरू जी ने इन राज्यपालों से कहा कि उनकी शिकायत का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि डा० एम० के० जैसी पार्टियों ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की माँग की थी तब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह तो तम्बोर का केवल एक पहलू है। यह ठीक है कि राज्यपाल के कार्य सामान्यतः औपचारिक हैं और उनका निष्पादन भी आम तौर पर मन्त्रियों के परामर्श पर ही होता है। किन्तु जैसा कहा जा चुका है कि कुछ स्थितियों में उसे अपने विवेक के अनुसार आचरण करने की छूट भी दी गई है। ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न हो सकती है जबकि आम चुनाव के बाद राज्य विधान सभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा मत्तारुह दल में फूट पड़ गई हो। ऐसे अवसरों पर यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि मुख्य मन्त्री किमको बनाया जाये। स्पष्टतः ऐसी स्थितियों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की पूरी छूट है। चौथे आम चुनाव से पूर्व भी इस प्रकार की स्थिति कम से कम तीन बार उत्पन्न हुई थी। सर्वप्रथम 1952 में मद्रास विधान सभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। परन्तु वहाँ के राज्यपाल ने राजगोपालाचारी को मुख्य मन्त्री बनाया, यद्यपि वह विधान मण्डल के सदस्य भी नहीं थे। 1957 में यह स्थिति केरल और उड़ीसा में पैदा हुई और इन राज्यों के राज्यपालों ने अपने विवेक के आधार पर मुख्य मन्त्री का चयन किया।

राज्यपाल मध्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में

जब किसी राज्य में सांविधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है तो उस समय भी राज्यपाल की शक्ति औपचारिक न होकर वास्तविक हो जाती है। जब कोई राज्यपाल सविधान की 356वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पास इस आग्रह का प्रतिवेदन भेजता है कि राज्य का शासन सविधान

क प्राविधाना व अनुसार मवानित नहा किया जा सकता उस समय स्पष्टन वह अपन विवेक के अनुसार भी जाचरण करता है। वस्तुतः जुलाई 1959 में जब कंगन व रायपान रामकृष्ण राव न राष्ट्रपति व पास अपना प्रतिबदन भेजा था ता उन्होंने मुख्य मंत्री ई. एम. एम. नम्बूत्तिरीपाद स काई परामर्श नहीं किया था। मुख्य मंत्री न स्पष्ट गंगा में बस बात की गिवायत भी का थी। यही नहीं यदि 356व अनुच्छेद व अतगत राय व नामन का उत्तरदायित्व कंगन अपने हाथ में लेता है उस समय रायपान का स्थिति औपचारिक नामक की नहीं रहती वह तब वास्तविक नामक बन जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रायपान व अनेक उत्तरदायित्व है और उह पूरा करने समय वह मन्त्रिमण्डल व परामर्श का उपयोग भी कर सकता है। इस तथ्य का प्रमाणित करने व लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उदाहरण व लिए रायपान को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधानमण्डल द्वारा पारित किया भा विधेयक का राष्ट्रपति की स्वीकृति व लिए सुरक्षित रख सकता है। यह बात आम तौर पर कही जाती है कि करने व रायपान न कहा व गिरा विधेयक (1957) को राष्ट्रपति की अनुमति व लिए सुरक्षित करते समय अपने मन्त्रिमण्डल का परामर्श नहा किया था। फिर वान में उन्होंने जब मन्त्रिमण्डल को पदच्युत करने का प्रतिबदन राष्ट्रपति व पास भेजा था उस समय भी उन्होंने मुख्य मंत्री अथवा मन्त्रिमण्डल का अपने विश्वास में नहा किया था। उक्त दावा अवसरा पर यह कहा गया था कि रायपान न राय व साविधानिक अयक्ष की भूमिका अना न करके कंगन व अभिकर्ता की भूमिका अदा की थी।

चौथे आम चुनाव व बाद रायपाल की भूमिका—चौथे आम चुनाव व बाद दश का राजनीतिक स्थिति में मौलिक परिवर्तन उपस्थित हुए। न चुनाव व बाद कांग्रेस का राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया तथा देश के अनेक राज्यों में गरवाग्रसी मिन जुल मन्त्रिमण्डल का स्थापना हुई। इन मन्त्रिमण्डल की रचना किसी वचार्गिक साम्य व आधार पर नहीं हुई थी उनका यदि कोई आधार था ता वह था कांग्रेस विराधवा। ऐसा स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि इनमें सत्ता एवं पला के लिए मन्त्रिमण्डल में शामिल दला व बीच सघष एवं तनाव की स्थिति पायी जाती। य दल सामायन सरकार का समर्थन उस समय तक करते व जब तक कि उन सरकार स कुछ पान की जाणा हाता था और जम ही उसकी जाणा धूमित हा जाती थी व अपना समर्थन वापिस ले लेते व। इस प्रकार एक व बाद हमने सयुक्त मोर्चे व मन्त्रिमण्डल का पतन हाता गया। मार्च 1967 स लेकर मार्च 1972 तक देश व विभिन्न राज्यों में 24 बार सरकार का पतन हुआ तथा 15 बार राज्यों में राष्ट्रपति नामन नाशू किया गया। राय विधान मभाजा व 5वें आम चुनाव व पूर्व देश व मान राय राष्ट्रपति नामन के अधान व। इस वान में दल बदल मनावृत्ति अपनी चरम सीमा पर थी। जत इस स्थिति में यह अपना भी नहा की जा सकती थी कि राज्यों में कोई स्थायी मुख्य मंत्री और कोई स्थायी मन्त्रिमण्डल काम कर सकगा। स्पष्टन इस स्थिति में रायपाना स भी यह आशा नहा की जा सकती थी कि व सविधान व 163वें अनुच्छेद व अनुसार मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर ही काम करगे।

जब तक विधानमभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था और उसमें अपने दल व नेता का चुनन की क्षमता थी तब तक रायपान व लिए स मामल में अपने विवेक को प्रयोग में लाने की कोई गजाडग नहा थी। परंतु जब दो या तीन दल अथवा उनके गठबंधन बहुमत व समर्थन का दावा करते हा अथवा अपने को मन्त्रिमण्डल की रचना करने का अधिकारी बताते हा ता उस समय रायपान का यह काम हा जाता है कि वह निश्चित कर कि मुख्यमन्त्री किस बनाया जाय। चौथे आम चुनाव व उपरान्त इस प्रकार के मामल अनेक बार प्रस्तुत हुए हैं।

एक दूसरा मामला जिसमें रायपाना न अपने विवेक का प्रयोग किया है वह व्यवस्थापिका क सदन अथवा सदन के अधिवेशन का बुलाना अथवा उनका समापन करना अथवा उह भंग करने स सम्बद्ध है। जब राज्यों व नामन में स्थायित्व पाया जाता था इस गति का प्रयोग

मुख्य मन्त्री के परामर्श से होता था, परन्तु सयुक्त विधायक दलों के मन्त्रिमण्डलों के युग में जब कोई मुख्य मन्त्री विधान सभा में बहुमत का समर्थन अपने दल के सदस्यों के दल-वदल के कारण अथवा मयुक्त मोर्चे के किसी घटक के उससे हट जाने के कारण खो देता था, तो उसे यह प्रलोभन होता था कि वह कुछ दिनों अपने पद पर बना रहे ताकि विरोधी सदस्यों को लालच देकर वह अपने साथ ले सके और व्यवस्थापिका में अपने बहुमत को दुबारा कायम कर सके। यदि मुख्य मन्त्री ने बहुमत का समर्थन विधानमण्डल के अधिवेशन के समापन के फौरन बाद खोया है तो वह सविधान की 174 (1) वी धारा के अनुसार छ महीने तक विधान सभा के अधिवेशन बुलाये बिना अपने पद पर बना रह सकता है। कुछ मामलों में राज्यपालों ने मुख्य मन्त्री से कहा कि वे विधान सभा के अधिवेशन को बुलाकर यह पता लगाये कि उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यदि मुख्य मन्त्री ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो राज्यपाल ने अपने विवेक का प्रयोग करके उसे पदच्युत कर दिया। इस प्रकार की घटना सबसे पहले पश्चिमी बंगाल में घटी। वहाँ डा० पी० सी० घोष के नेतृत्व में 17 विधायकों ने अजय मुखर्जी के नेतृत्व में गठित सयुक्त मोर्चे की सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया। राज्यपाल धर्मवीर ने मुख्य मन्त्री से कहा कि 23 नवम्बर, 1967 तक विधान सभा का अधिवेशन बुलाकर अपनी स्थिति का परीक्षण करे। मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल का परामर्श यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि विधान सभा का अधिवेशन छ महीने की अवधि में कभी भी बुलाया जा सकता है तथा वह राज्यपाल के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री को पदच्युत कर दिया और उनके स्थान पर डा० पी० सी० घोष को नियुक्त कर दिया। यदि अन्य राज्यों में राज्यपालों ने समान परिस्थिति में ऐसा किया होता तो सम्भवतः पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के कार्य की आलोचना न की जाती। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। लगभग उसी समय जब धर्मवीर ने अजय मुखर्जी के मन्त्रिमण्डल को पदच्युत किया, बिहार में राज्यपाल अनन्त शयनम आगरा ने अपने राज्य के मुख्य मन्त्री से यह आग्रह नहीं किया कि उन्हें विधान सभा का अधिवेशन बुलाना चाहिए। यद्यपि वहाँ भी एक बड़ी सरया में मयुक्त मोर्चे के घटकों में से दल-वदल हुए थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्यपाल गोपाल रेड्डी ने भारतीय क्रान्ति दल के नेता चरणसिंह की विधान सभा को बुलाने की माँग को उस समय ठुकरा दिया था जबकि कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी तथा मुख्य मन्त्री चन्द्रभानु गुप्त को विधान सभा का केवल अल्पमत का समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त ऐसे मुख्य मन्त्रियों के भी उदाहरण हैं जिन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल के लिए सकट उपस्थित होने पर स्पीकर के द्वारा विधान सभा के अधिवेशन का स्थगन करवा दिया और फिर राज्यपाल के द्वारा उसका समापन करवा दिया।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राज्यपालों ने अपनी इन साविधानिक शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जिससे उनकी राजनीतिक निष्पक्षता की अभिव्यक्ति होती हो। अतः यह स्वाभाविक ही था कि गैर-कांग्रेसी दलों के नेता राज्यपालों के इन कार्यों की आलोचना करते। इस सदर्भ में देश के राजनीतिक क्षेत्रों में राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका की पर्याप्त रूप में चर्चा हुई है। नम्बूदिरिपाद ने कहा है कि सामान्यतः राज्यपाल के पद पर उन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है जो या तो कांग्रेस पार्टी के नेता रह चुके हैं अथवा जो भारतीय मिविल सर्विस के सदस्य रह चुके हैं। इन दोनों श्रेणियों में से किसी से भी निष्पक्षता के साथ काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पहली श्रेणी के लोग जो हमेशा राजनीति में रहे हैं, 'राजनीति एव दलों से ऊपर' नहीं रह सकते। दूसरी श्रेणी के राज्यपालों में 'जिन्होंने समान स्वाभिमति के माध्यम से ब्रिटिश एव कांग्रेसी शासकों की सेवा की है', इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वे राजनीतिक विवादों में तटस्थ रह सकेंगे।

उपर्युक्त वाद-विवाद के मन्दर्भ में कुछ लोगो ने यह सुझाव दिया है कि राज्यपालों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ हिदायते (Guidelines) होनी चाहिये। परन्तु इसमें समस्या का समाधान हो सकेगा, यह बात मन्देहास्पद है। कुछ समय पूर्व आयोजित एक परिचर्चा में

उप राष्ट्रपति और गांधी स्वयं पाठन में यह मत व्यक्त किया था कि बहुत सम्भव है कि हिंसायता और सविधान की व्यवस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाये उस हानत में वह 'याविक' व्याख्या की कसौटी पर खरी नहीं उतरे सक्ती। इसके अनिश्चित इस प्रकार की हिंसायता से चाहें उनमें कितना ही अधिक 'चौरा' क्या न हो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। वास्तव में ये समस्याएँ इसलिए पैदा नहीं हुई हैं क्योंकि सविधान की व्यवस्था अस्पष्ट है। सच वान यह है कि इन समस्याओं के जन्म के लिए भारत में आधुनिक युग में प्रचलित सिद्धांतहीन राजनीति ही उत्तरदायी है जिसमें प्रत्येक राजनीतिक समुदाय ने अपने तुल्य राजनीतिक स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के सम्भव अवसरवाद का परिचय दिया है। अतः यदि देश में सविधान की व्यवस्थाओं का वायावयन अपेक्षित है तो यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों के अनुशासन को एक वास्तविकता रूप दिया जाये तथा संसदीय शासन तंत्र के नियमों का पालन किया जाये।

2 मंत्रिपरिषद्

सविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य में राज्यपाल को उन विषयों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगा। मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति के लिए जापद्धति उत्तर्गई है वह निम्नलिखित है।

राज्यपाल मुख्य मंत्री को नियुक्त करता है। इस नियुक्ति का करत समय राज्यपाल को यह बात ध्यान में रखनी होती है कि जिस व्यक्ति का मुख्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा रहा है उस विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं। राज्य में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्य मंत्री की सिफारिश पर होती है। मंत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधान सभा के सदस्य हों कि तु यदि कोई मंत्री नियुक्त हान से पूर्व राज्य की व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह छ महीने के भीतर सदस्य बन जाये अथवा वह अपने पद पर नाना नहीं रह सकेगा। मंत्रियों में विभागों का वितरण मुख्य मंत्री के द्वारा किया जाता है।

सविधान में राज्य की कार्यपालिका गतिविधियों को वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद् में निहित किया है। यद्यपि शासन का परिचालन राज्यपाल के नाम से होता है तथापि यथाथ में सभी निणय मंत्रियों के द्वारा किये जाते हैं और सामान्यतः राजपाल उन निणयों को कार्याचित करने के लिए वाध्य है। मुख्य मंत्री का यह काम है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् के निणयों में अवगत कराये तथा उसने ममक्ष विधायन के प्रस्ताव प्रस्तुत करे। यदि राज्यपाल का किसी निणय में सम्बद्ध कोई अधिक जानकारी हासिल नहीं है तो वह मुख्य मंत्री से इस बात का आग्रह कर सकता है कि वह उसे पूरी जानकारी दे। राज्यपाल मंत्रिपरिषद् का परामर्श दे सकता है और वह उसे धत्तावनी भी दे सकता है। सविधान के अनुसार मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पान में ही बन रहे सकते हैं। दूसरे पान में इसका अर्थ है कि राज्यपाल यदि चाहें तो किसी मंत्री को पदच्युत कर सकता है। परंतु ऐसा इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि मंत्रिपरिषद् को सविधान में विधान सभा के प्रति उत्तरदायीता बताया है और 'रोसतंत्र' में वास्तविक गतिविधियाँ उसको सीपी जानी हैं जिसके पास उनका निष्पादन का उत्तरदायित्व है।

सविधान की 164 (2)वां धारा में लिखा है कि मंत्रिपरिषद् अपने कामों के लिए सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि मंत्री अपने पदों पर बने उम समय तक बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। उन्हें उमसी बैठना तथा उसका कार्यवाहियाँ में भाग लेने का अधिकार है। वे उसकी बैठकों में सरकारों विधेयकों का प्रस्तुत करते हैं तथा उन्हें पारित करवाने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का होता है।

राज्य के विधानमण्डल को मन्त्रियों के कार्यों की देख-रेख करने तथा उन्हें नियन्त्रित करने के लिए वे सभी साधन उपलब्ध हैं जो किसी भी ससदीय लोकतन्त्र में व्यवस्थापिका सदनों को दिये जाते हैं। ये सूचनाएँ पाने के लिए मन्त्रियों से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। सरकार के कार्यों की आलोचना करने के लिए उन्हें स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। अन्ततः उन्हें मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को पारित करने का भी अधिकार है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि मन्त्रिमण्डल की रचना में व्यवस्थापिका की भूमिका होती है तो उनकी मारने में भी उसका हाथ कुछ कम नहीं होता। परन्तु जहाँ यह सही है, वहाँ दूसरी तरफ यह भी सच है कि मन्त्रि-परिषद् के सदन विधानमण्डल में बहुसंख्यक दल अथवा दलों के गुट के नेता होते हैं। अतः उनके लिए विधान सभा के सदस्यों को प्रभावित करना कोई कठिन बात नहीं है। अपने इसी प्रभाव के आधार पर उन्हें सामान्यतः अपने सभी विधायी प्रस्तावों को पारित करवाने में सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि दलीय अनुशासन कठोर है तथा विधान सभा में सरकार का बहुमत स्पष्ट है तो मन्त्रि-परिषद् के लिए अपने अस्तित्व के लिए चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में विधान सभा को मन्त्रि-परिषद् को अपदस्थ करने का अवसर केवल तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सरकार के विधानमण्डलीय समर्थक विश्वास के योग्य नहीं है, उस स्थिति में उनसे दल-वदल करवाकर सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है।

3 मन्त्रि-परिषद् में मुख्य मन्त्री का स्थान

जैसा कहा जा चुका है कि भारत में केन्द्र और राज्यों दोनों में ससदीय प्रकार की कार्य-पालिका को अपनाया गया है। अतः मोटे तौर पर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को वही शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा उसके वही काम हैं जो सघ की सरकार में प्रधानमन्त्री को दिये गये हैं। प्रधानमन्त्री की ही भाँति मुख्य मन्त्री भी अपने मन्त्रिमण्डल के साधियों को चुनता है और वही उनके बीच विभागों का वितरण करता है। उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह यदि चाहे तो किसी मन्त्री को उसके पद से हटा सकता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर वह मन्त्रियों के विभागों में हेर-फेर कर सकता है। उसी के माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त कार्यान्वित होता है। वह मन्त्रि-परिषद् तथा राज्यपाल और व्यवस्थापिका एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी है।

परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है वह केवल औपचारिकता है। वास्तव में ऐसे मुख्य मन्त्री थोड़े हुए हैं जिन्होंने नेहरू जी अथवा शास्त्री जी अथवा इन्दिरा गांधी की जैसी शक्तियों का उपभोग किया हो। इस प्रकार के मुख्य मन्त्रियों में पश्चिमी बंगाल में बी० सी० राय और उत्तर प्रदेश में गोविन्दवल्लभ पंत के नाम लिये जा सकते हैं। परन्तु इन मुख्य मन्त्रियों को जो प्रतिष्ठा प्राप्त थी, वह संविधान की किसी व्यवस्था के कारण नहीं थी, अपितु उसका कारण उनके अपने नेतृत्व की क्षमता थी। स्पष्टतः यह प्रतिष्ठा उन मुख्य मन्त्रियों को नहीं मिल सकती थी जिनमें नेतृत्व के उन गुणों का अभाव था।

राज्य के विधानमण्डल

भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है, आठ राज्यों¹ के विधानमण्डलों में दो सदन पाये जाते हैं और शेष में केवल एक। राज्यपाल विधानमण्डल का आवश्यक अंग है। राज्यों के दूसरे सदन को 'विधान-परिषद्' का नाम दिया गया है और प्रथम सदन को 'विधान सभा' का।

¹ ये आठ राज्य हैं—बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर। पंजाब के पुनर्गठन के पूर्व वहाँ भी विधान-परिषद् की व्यवस्था थी। परन्तु बाद में वहाँ विधान-परिषद् का अन्त कर दिया गया है।

सविधान सभा में यह एक विचारग्रन्थ प्रश्न था कि रायों में दूसरे सदन का स्थापना की जाय अथवा नह। फलतः प्रत्येक राज्य में एक सदन का निर्णय उस राज्य के प्रतिनिधियों के बहुमत में लिया गया। इस प्रकार के श्रमों के ताने-बाने—असम मध्य प्रान्त और उड़ीसा—में दूसरे सदन का स्थापना का विरोध किया। सश्रमों के द्वारा रायों में निम्नतात्पर्य व्यवस्था पिका के पक्ष में मतदान किया। अतः सविधान की 168वां धारा में सदन रायों के लिए दो सदन की व्यवस्था का गठन। परन्तु 169वां धारा में यह व्यवस्था का गठन है कि किसी भी राज्य में दूसरे सदन का सच की समान उम्र स्थिति में रहने पर सकती है यदि उस राज्य का विधान सभा पण बहुमत से उस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे प्रगति कि मतदान में भाग लेने वाले मतस्य कुल मतस्य-संख्या के दो तिहाई ह। इस प्रकार सभी प्रक्रिया के द्वारा उन रायों में जहाँ कबल एक सदन पाया जाता है विधान सभा दूसरे सदन की स्थापना के पक्ष में प्रस्ताव पारित करे ता मसद उस राज्य के लिए इस जाय का एक सदन बना सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी राज्य में विधानसभानिम्नताय हा अथवा एक-सदनीय इस बात का निर्णायक उस राज्य की स्वयं विधान सभा है। पञ्जाब और पश्चिमी बंगाल में विधान-परिषद् का उद्भूतन हा चुका है। विधान सभा दूसरे सदन का रहने करने के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। विधान सभा में सदन की वषा आवाचना का गठन है। तागा न बना है कि उनमें मावजनिक घन का अपत्य्य हाता है तथा उनमें द्वारा व्यवस्थापिका में उन तागा का पिठवा में थान लिया जाता है जिह आम चुनाव में जनता ने ठुनरा लिया था।

1. विधान-परिषद् ✓

गठन—सविधान में विधान-परिषद् की रचना के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है—

(1) विधान-परिषद् की कुल मतस्य-संख्या विधान सभा की मतस्य संख्या के एक तिहाई में अधिक नह। होगी परन्तु उसकी न्यूनतम संख्या 40 हाती चाहिए। इसका कबल एक अपवाद है और वह है जम्मू और कश्मीर का राज्य जहाँ की विधान-परिषद् में कबल 36 मतस्य हैं। इसका कारण यह है कि उस राज्य का अपना अलग से सविधान है जिसमें अनुसार वहाँ की विधान सभा और विधान-परिषद् के मतस्य की संख्या निश्चित की है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सविधान में रायों का विधान-परिषद् की मतस्य-संख्या निश्चित नह। की है उसमें कबल अधिकतम और न्यूनतम संख्या का निर्धारण रखा है।

(2) इन सीमाओं के अन्तर्गत राज्य की विधान परिषद् में अग्रलिखित पांच वर्गों का प्रतिनिधित्व हागा (i) परिषद् के एक तिहाई मतस्य का निर्वाचन राज्य की स्थानाय संस्थाओं के द्वारा हागा। (ii) परिषद् के 1/12 मतस्य विधिविधानों के कम से कम तीन वर्ष पुराने स्नातकों या उनके समान योग्यता वाले राज्य के निवासियों के द्वारा हागा। (iii) कुल मतस्य के 1/12 मतस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं तथा उनमें उच्च स्तर के कम से कम तीन वर्ष पुराने शिक्षकों द्वारा चुने जायेंगे। (iv) कुल मतस्य के 1/12 मतस्य राज्य की विधान सभा के मतस्यों द्वारा उन मतस्यों में से चुने जायेंगे जो विधान सभा के मतस्य नही हैं। (v) नव मतस्य यानी कुल मतस्य-संख्या के 1/6 मतस्य का राज्य का राज्यपाल मनाना करेगा।

उपरोक्त प्रथम चार वर्गों के मतस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एवं सक्षमणीय मत द्वारा सम्पन्न हाता है। अंतिम वर्ग के मतस्यों का मनानेयन राज्यपाल उन व्यक्तियों में से करता है जिहान माहित्य के विधान महाकागिना जाते-लेते समाज सेवा आदि में विनिष्ट योगदान लिया है।

विधान परिषद् की इस रचना व्यवस्था में मसद को परिवर्तन करने का अधिकार है।

सदस्यों की योग्यता तथा अयोग्यता—विधान-परिषद् की सदस्यता के लिए अग्रलिखित

योग्यताओं का निर्धारण किया गया है—

(1) वह भारत का नागरिक हो। (11) उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। (111) उसमें वे सभी योग्यताये हो जिनका निर्धारण ससद कानून-निर्माण करके निश्चित करे।

ऐसा कोई भी सदस्य जो निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में आ जाता है विधान-परिषद् का सदस्य नहीं रह सकता—

(1) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है। (11) वह दिवालिया हो गया है। (111) उसने सघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी लाभ के पद को ग्रहण कर लिया है। (1v) उसने अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। (v) उसने किसी अन्य विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। (vi) वह ससद द्वारा निमित्त किसी कानून के अन्तर्गत विधान-परिषद् की सदस्यता के लिए अयोग्य हो। (vii) यदि वह सदन की अनुमति प्राप्त किये बिना 60 अथवा उससे अधिक दिनों तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहा है, तथा (viii) यदि वह विधानमण्डल के दोनों सदनों का सदस्य है तो उसके लिए एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना आवश्यक है।

अवधि—विधान-परिषद् एक स्थायी सदन है तथा उसे भंग नहीं किया जा सकता। उसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं तथा प्रति तीसरे वर्ष उसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं।

2 विधान सभा

गठन—विधान सभा राज्य विधानमण्डल का निचला सदन है। सविधान के अनुसार उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वालिग मताधिकार के आधार पर होना है। उसमें अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। सविधान के कार्यान्वयन के पूर्व देश में साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र कायम थे। सविधान ने निर्वाचन की इस प्रणाली का अन्त कर दिया है तथा उसने समुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थापना की है। परन्तु इसके साथ ही उसमें अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ी हुई जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए स्थानों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। सविधान की 332वीं धारा में लिखा है कि विधान सभा में निम्न वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे—

(1) अनुसूचित जातियाँ,

(11) अनुसूचित आदिम जातियाँ।

सविधान में यह भी व्यवस्था है कि यदि राज्यपाल की राय में आगल-भारतीय समुदाय को राज्य की विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह अपने विवेक से जितने सदस्यों का मनोनयन आवश्यक समझता हो मनोनीत कर सकता है। आरम्भ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा आगल-भारतीयों के लिए स्थानों को केवल दस वर्ष के लिए सुरक्षित रखा गया था, परन्तु इस अवधि को दस-दस वर्ष के लिए दो बार बढ़ाया जा चुका है। अब यह अवधि 1980 में खत्म होगी।

सदस्यों की योग्यता—विधान सभा के सदस्यों के लिए सविधान में निम्नलिखित योग्यताये निर्धारित की गई हैं—(1) वह भारत का नागरिक हो, (11) उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, (111) उसके पास वे सभी योग्यताये हो जिन्हें कानून के द्वारा राज्य के विधानमण्डल ने निर्धारित किया हो।

अवधि—विधान सभा का निर्वाचन पाँच वर्ष की अवधि के लिये होना है। सकट काल में ससद एक बार में उसकी अवधि एक वर्ष के लिए कानून के द्वारा बढ़ा सकती है, परन्तु सकट काल की समाप्ति के छ महीने के उपरान्त उसकी अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता। विधान सभा का विघटन इस अवधि के भीतर भी किया जा सकता है। ऐसा विघटन मुख्य मन्त्री के परामर्श पर

रायपान करा किया जाता है।

राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ और कार्य ✓

राय्य व विधानमण्डल को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका राय्य सूची में उल्लेख है। सामान्यतः इस क्षेत्र पर राज्य विधानमण्डल का एकमात्र अधिकार है। इससे अनिश्चित वह समस्त सूची में उल्लिखित विषयों पर भी कानून बना सकता है। परन्तु इस क्षेत्र में राय्य विधानमण्डल का एकाधिकार नहीं है। यदि स सूची में दिये हुए विषयों पर सभ की ससद और राय्य विधान सभा दोनों का कानून है तो जिस सीमा तक राय्य का कानून सभ के कानून के प्रतिकूल है तो उस सीमा तक वह कानून अवध हो जाता है। परन्तु यदि उस कानून को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है तो वह सभ के कानून के प्रतिकूल होने के बावजूद भी बंध माना जायगा।

विधानमण्डल का मुख्यतः विधान सभा को राय्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। राय्य का विधानमण्डल है सभ कर सम्बन्धी प्रस्तावों का कानूनी रूप देना है। विधान सभा खर्चों की माँगों को स्वीकार करता है और विधानमण्डल द्वारा विनियोग अधिनियम के पारित करने के बाद ही सरकार संचित निधि से व्यय के अनुबंध निष्पन्न करती है। वित्तीय क्षेत्र में विधानमण्डल की शक्तियाँ पर कानून सीमाओं नहीं हैं। सिवाय इसके कि कुछ खर्चें संचित निधि पर भारित होते हैं और उन पर विधानमण्डल को वातचीन करने का अधिकार तो होता है किन्तु उस पर मतदान का अधिकार नहीं है।

सविधान न केवल और राय्य दोनों में ही ससदीय कार्यपालिका की स्थापना की है। फलतः राय्य में वास्तविक कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधान सभा अपने बहुमत से कोई निम्न अधिनियम जयवा काम रोके प्रस्ताव पारित करे तो मंत्रिपरिषद् को त्याग पत्र देना होता है। जवा नहीं जा चुका है कि सामान्य परिस्थिति में विधान सभा के लिए मंत्रिमण्डल को अपदस्थ करना सम्भव नहीं होता। परन्तु प्रश्ना स्थागत प्रस्तावों आदि के द्वारा वह सरकार की नीतियाँ तथा उसके कार्यों का पक्षपात प्रवर्धन कर सकती है। वतान की आवश्यकता है कि शक्तिशाली में कोई भी सरकार विधान सभा की इन शक्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकती।

उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त सविधान न राय्य के विधानमण्डल को दो अन्य काम भी सौंपे हैं। वे हैं—सविधान की सहायन प्रक्रिया में भाग लेना तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना।

सविधान की उन कार्यों को जिनका सम्बन्ध राज्या की शक्तियों के साथ है सभी संशोधित किया जा सकता है जबकि सविधान संशोधन विधायक का कार्य ससद एक विशेष बहुमत से पारित कर और साथ ही अधिक राय्य के विधानमण्डल उसका अनुमोदन कर। सविधान में संशोधन के लिए राय्य विधानमण्डल के दोनों सदनों (यदि दो सदन हों तो) की स्वीकृति आवश्यक है।

राय्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ पर प्रतिबंध

राय्य विधानमण्डल की शक्तियाँ असंमित नहीं हैं। सविधान ने उनकी शक्तियों के ऊपर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाये हैं—

(1) कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें राय्य सूची में निहित किया गया है किन्तु जिन पर राय्य के विधानमण्डल तब तक कानून का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि उन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो जाय।

(2) समस्त सूची में विषयों पर राय्य विधानमण्डल कानून तो बना सकता है किन्तु यदि

वह ससद के किसी भी कानून के विरोध में है तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय कानून वैध होगा और राज्य का कानून गैर-कानूनी, यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो राज्य का कानून वैध होगा और ससद का कानून गैर-कानूनी।

(3) कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य विधानमण्डल कानूनों का निर्माण तो कर सकता है, किन्तु वे तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृति प्रदान न कर दे। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के द्वारा भेजे जाते हैं।

(4) सकट-कालीन स्थिति में सघीय ससद राज्य सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बना सकती है।

(5) यदि राज्य में साविधानिक व्यवस्था असफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति को राज्य की विधान सभा को विघटित करने का अधिकार प्राप्त है तथा वहाँ इसके बाद नये चुनावों की व्यवस्था की जाती है। इस अवधि में केन्द्रीय ससद को राज्य-सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

(6) यदि राज्य-सभा दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य-सूची में उल्लिखित किसी एक विषय पर अथवा कुछ विषयों पर सघीय ससद को कानून बनाना चाहिए, तो उस स्थिति में एक वर्ष की अवधि के लिए राज्यों के विधानमण्डलों को उन पर कानून बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(7) राज्य स्वयं राज्य-सूची के किसी भी विषय को विधि-निर्माण हेतु सघीय ससद को सौंप सकता है।

विधानमण्डल के दोनों सदनों के बीच सम्बन्ध

जिस राज्य में द्विमदनात्मक विधानमण्डल पाया जाता है, उसमें निम्न सदन अर्थात् विधान सभा को ही वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उच्च सदन अर्थात् विधान-परिषद् केवल द्वितीय सदन ही नहीं है, यथार्थ में वह गौण सदन है। वित्तीय मामलों में अन्तिम और एकमात्र शक्ति विधान सभा को ही दी गई है। धन-विधेयक का जन्म विधान सभा में ही होता है। वहाँ से पारित होने के बाद उसे विधान-परिषद् में भेज दिया जाता है। परिषद् के पास उस पर विचार करने के लिए केवल चौदह दिन होते हैं। यदि इस बीच में परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाती तो उसके वावजूद भी उसे राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर मतदान करने का अधिकार केवल विधान सभा को ही प्राप्त है।

जहाँ तक गैर-धन विधेयकों का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में भी विधान सभा की शक्तियाँ विधान-परिषद् की शक्तियों से अधिक हैं। यदि कोई विधेयक विधान सभा के द्वारा पारित होने के उपरान्त (i) परिषद् के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाय, अथवा (ii) परिषद् उसे प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर उस पर कोई कार्यवाही न करे, अथवा (iii) परिषद् उम विधेयक को ऐसे सगोचनों के साथ पारित करे जो विधान सभा को मान्य नहीं हैं, तो उम स्थिति में यदि विधान सभा उक्त विधेयक को दुबारा उसी रूप में पारित कर दे जिसमें उसने उसे पहले पारित किया था, तो वह विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जायेगा।

विधान-परिषद् के पास कार्यपालिका को नियन्त्रित करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। इस सम्बन्ध में यदि परिषद् को कोई शक्ति मिली हुई है तो वह केवल उमसे सूचनाएँ प्राप्त करने की शक्ति है। ऊपर बताया जा चुका है कि संविधान ने कार्यपालिका को नियन्त्रित करने की शक्ति केवल विधान सभा को सौंपी है।

राज्यों की 'यायपालिका'

भारतीय संघ-व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों का 'यायपालिका' का स्थिति जय विनिष्ठा मध्या म कुट्ट भिन्न प्रकार की है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में राज्यों के अपने अपने संविधान हैं और राज्यों की 'यायपालिकाएँ' उन्हीं संविधानों के अनुसार स्थापित की जाती हैं और उन्हीं से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। संघीय संविधान तथा सरकार का उनसे तब तक यही सम्बन्ध है कि संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का उल्लंघन करने वाले सदन तथा अधिकार इन का निवारण नहीं हो सकता। राज्यों में मध्या कायून का लागू करने के लिए पृथक् संघीय 'यायपालिका' स्थापित किया गया है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका के राज्यों में दो प्रकार के 'यायपालिका' स्थापित हैं जिनमें से प्रत्येक को एक सम्बन्ध नहीं है। परंतु भारत में समूचे देश के लिए एक ही संविधान है। इसका मुख्य कारण एक ही संविधान का होना है। यद्यपि 'यायपालिका' की उच्चतम परम्परा में सर्वोच्च 'यायपालिका' का उच्चतम 'यायपालिका' है तथापि प्रत्येक राज्य में 'यायपालिका' के नीचे पर उच्च 'यायपालिका' है। राज्य के समस्त निम्न तरीख 'यायपालिका' उच्च 'यायपालिका' के अधीन कार्य करती है। सर्वोच्च 'यायपालिका' 'यायपालिका' की उच्च शृंखला के नीचे में है परंतु राज्यों के उच्च 'यायपालिका' के ऊपर उनका अधिकार इन केवल अधीन है न कि नियंत्रणकारी। स्वयं उच्च 'यायपालिका' भी अभिन्न 'यायपालिका' है और उनकी मूल संविधान द्वारा की गयी है। यह व्यवस्था स्थापित की गयी है ताकि राज्यों का प्रधान 'यायपालिका' हान के नाते उनकी स्वतंत्रता बनी रहे।

उच्च 'यायपालिका' के सदन तथा अधिकारों का स्वरूप भारत का संविधान है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च 'यायपालिका' है। इस संविधान के अनुसार दो राज्यों का एक ही उच्च 'यायपालिका' भी हो सकता है। इसी व्यवस्था तभी की जाती रही है जबकि किसी राज्य के विभाजन में दो राज्यों बन जाते हैं परंतु कानून में उनमें से प्रत्येक राज्य अपना पृथक् उच्च 'यायपालिका' स्थापित करा जाता है। राज्यों के उच्च 'यायपालिका' के 'यायपालिका' का समान निश्चित नहीं की गयी है। इसका निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति का दी गयी है जो समय समय पर राज्य विभाग की आवश्यकतानुसार इसका निर्धारण करता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक उच्च 'यायपालिका' में एक मुख्य 'यायपालिका' तथा अन्य कई 'यायपालिका' होते हैं। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च 'यायपालिका' का 'यायपालिका' एक व्यक्ति का बनाया जाता है जो भारत का नागरिक न हो उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक न हो। वह राज्यों के 'यायपालिका' में कम से कम 'यायपालिका' या बकीर रहे चुका है। इस प्रकार उच्च 'यायपालिका' में राज्यों की 'यायपालिका' में काम करने वाले अनुभवी 'यायपालिका' तथा बकीरों दोनों को लिया जा सकता है। नियमित 'यायपालिका' सेवा में नियुक्त किये गये 'यायपालिका' अपने कार्यकाल के उपरांत पेंशन भी प्राप्त करते हैं। मुख्य 'यायपालिका' की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति सर्वोच्च 'यायपालिका' के मुख्य 'यायपालिका' तथा सम्बंधित राज्य के 'यायपालिका' से परामर्श करता है और अन्य 'यायपालिका' की नियुक्ति के बारे में उच्च 'यायपालिका' के मुख्य 'यायपालिका' से। मुख्य 'यायपालिका' का 4000 रु. तथा अन्य 'यायपालिका' का 3500 रु. मासिक वेतन सम्बंधित राज्य की सचिव निधि से लिया जाता है। यय की यह मद 'व्यवस्थापिका' के मताधीन नहीं है। किसी 'यायपालिका' के कार्यकाल में इस उसके अहित में कम न किया जा सकता। अवकाश ग्रहण करने पर उच्च 'यायपालिका' का 'यायपालिका' उम्मी उच्च 'यायपालिका' में बकायन नहीं कर सकता। उच्च 'यायपालिका' के 'यायपालिका' का राष्ट्रपति स्थानान्तरित कर सकता है। यह प्राविधान मावजनिक हित में उनकी योग्यता तथा अनुभव का लाभ उठाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य 'यायपालिका' की स्वतंत्रता पर अकुल गगाना नष्ट है। इस प्राविधान का मुख्य उद्देश्य उच्च 'यायपालिका' की स्वतंत्रता का बनाय रखना है।

अधिकार क्षेत्र—उच्च 'यायपालिका' के अधिकारों का व्याख्या संविधान में उस रूप में

नहीं की गयी है जिस रूप में उच्चतम न्यायालय की की गई है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की भाँति प्रारम्भिक, अपील तथा प्रशासनिक तीन प्रकार के अधिकार रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भाँति उच्च न्यायालय भी अपनी प्रादेशिक सीमा के अन्तर्गत सविधान निर्वाचन तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र का उपभोग करते हैं, और इस निमित्त वे आवेदनों की सुनवाई करके आदेश जारी करते हैं। वे अपनी प्रादेशिक अधिकार सीमा के अन्तर्गत सैनिक न्यायाधिकरणों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनते हैं। यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होने लगे कि कोई विवाद जो उसके अधीन निम्न न्यायालयों में चल रहा है, साविधानिक व्याख्या चाहता है, तो उस मामले को अपने पास मँगा सकता है और या तो स्वयं उसकी सुनवाई करके निर्णय देता है या साविधानिक व्याख्या दे देने के उपरान्त उमी न्यायालय को सुनवाई करने तथा निर्णय देने के हेतु वापिस कर सकता है। दीवानी और फौजदारी के समस्त विवादों में जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। माल के विवादों में यद्यपि राज्य का अन्तिम न्यायालय 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' है, तथापि उसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है, वशर्ते कि विवाद में कोई ऐसा मामला हो जिसमें साविधानिक निर्वाचन करने की बात अन्तर्निहित हो। उच्च न्यायालय अपने सम्पूर्ण कार्यालय तथा न्यायालय के कर्मचारी-वृन्द पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखता है। साथ ही कुछ अंश में उसका प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य के जिला न्यायालयों के ऊपर भी रहता है। यद्यपि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तथापि उनकी नियुक्ति करने में राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श लेता है। उच्च न्यायालय अपनी न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करता है, साथ ही राज्य के निम्न न्यायालयों को भी इस सम्बन्ध में आदेश देता है, वह उनके कार्यों का निरीक्षण भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय की भाँति उच्च न्यायालय को राज्य सरकार को परामर्श देने सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं है। चूँकि राज्यों में राज्यपाल पद के अस्थायी रूप से खाली होने पर 'उप-राज्यपाल' सदृश किसी पद का प्राविधान नहीं है, अतः ऐसी स्थिति आने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के कार्यकारी राज्यपाल का कार्य करता है। परन्तु उस अवधि में वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्य नहीं करता।

उच्च न्यायालयों को साविधानिक निर्वाचन तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने की शक्ति प्रदान करने का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि विशाल देश में यदि यह शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में रहती, तो नागरिकों के साविधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जा सकने में कठिनाई प्रतीत होती। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार भी बहुत बढ़ जाता। यदि केभी उच्च न्यायालयों के पास अत्यधिक कार्य बढ़ जाता है तो उसे निवटाने के लिए अस्थायी रूप से अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किये जाते हैं।

राज्यों में अधीन न्यायालय—उच्च न्यायालयों के नीचे श्रेणीबद्ध क्रम में न्यायपालिका की व्यवस्था का निर्धारण सविधान द्वारा नहीं किया गया है। यह अधिकार राज्य की विधानमण्डलों को प्रदान किया गया है कि वे अपने राज्य में इसका संगठन करने के हेतु विधि-निर्माण स्वयं कर लें। इसलिए विभिन्न राज्यों में निम्न-स्तरीय न्यायपालिका संगठन के विवरणात्मक रूपों में किञ्चित् विविधता का होना स्वाभाविक है। परन्तु कुछ आधारभूत सिद्धान्त जिनके अनुसार राज्यों में न्यायपालिका का संगठन किया गया है, सर्वत्र बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल में चलनी आयी न्यायिक व्यवस्था को स्वतन्त्र भारत में भी बनाये रखा गया है। परन्तु आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन तथा परिवर्धन किये जाते रहे हैं। जो मुख्य बातें सर्वत्र समान रूप में पायी जाती हैं, वे इस प्रकार हैं

प्रत्येक राज्य को न्यायिक दृष्टि से जिलों में विभक्त किया गया है। कुछ जिले प्रगामनिक

जिला व स्तर में हुआ और वहाँ पर यायिक सगठन के निमित्त दाया तीन जिलों का भी एक जिला के रूप में सगठित किया गया है। यायानय तीन प्रकार के हैं—दीवानों की जागीरें तथा मान।

जम्मू और कश्मीर राज्य की विधेय स्थिति

भारतीय संघ की अथेय कानूनों की भांति जम्मू और कश्मीर भी भारतीय संघ का एक अंग है। परंतु उसका आंतरिक सविधान अलग रहा है तथा केन्द्र के साथ सम्बंधों में भी उसकी विनिष्ठा स्थिति का मायना दी जाती रही है।

प्रश्न है कि सविधान न जम्मू और कश्मीर राज्य को अथेय राज्य से भिन्न पद क्या दिया है? इस प्रश्न का उत्तर हमें उन विनिष्ठा परिस्थितियों में मिल सकता है जिनमें कश्मीर न पाकिस्तानी आक्रमण के उपरान्त भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया था। ऐसा करने में वहाँ की जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। परंतु पाकिस्तान न इस समय तक अपना आक्रमण बंद नहीं किया था उत उमन धर्म के आधार पर इस समूचें राज्य पर अपना दावा जताना आरम्भ कर लिया था। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार न कश्मीर की जनता का यह आश्वासन दिया कि राज्य में सामांय स्थिति की स्थापना में वह जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ की जनता का परामर्श लेगा। अतः यह आवश्यक था कि जम्मू और कश्मीर के राज्य को सविधान में एक विनिष्ठा पद प्रदान किया जाना।

जम्मू और कश्मीर राज्य तथा भारत के माविधानिक सम्बंधों का उल्लेख भारत के सविधान में हुआ है। उसमें लिखा है कि सविधान की केवल दाधाराय जम्मू और कश्मीर के राज्य पर लागू होगी। वे हैं—धारा 1 और 370। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का राज्य भारतीय संघ का एक भाग है। अनुच्छेद 370 में इस राज्य की विनिष्ठा स्थिति का स्वीकार किया गया है तथा यह कहा गया है कि सविधान के अथेय प्राविधानों को राष्ट्रपति एस. मशोधना के साथ लागू कर सकेंगा जो राज्य की सरकार का मांय है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति न एक आदेश के द्वारा यह घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर राज्य के सदन में संघीय ससत् की विधायी शक्ति केवल संघ और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित रहेंगी जो इस राज्य के प्रवेग पत्र के प्राविधानों से मेल खाते हैं। इसका अथेय यह हुआ कि संघ सूची में 97 विषयों में से केवल 56 विषयों पर समद द्वारा बनाय गये कानून जम्मू और कश्मीर के राज्य में लागू हो सकेंगे। सविधान के 22 अध्यायों में से 9 अध्यायों में वहाँ लागू हो नए किये जा सकते हैं।

1954 के बाद की स्थिति—उपयुक्त व्यवस्था उस समय तक चलती रही जब तक कि राज्य न सविधान सभा का निर्वाचन नहीं कर लिया। सभा न फरवरी 1954 में एकमत में भारत में शामिल होने के निर्णय का सम्पुष्टि कर दी। इसका बाद धीरे धीरे राज्य के भारतीय संघ में पूर्ण विलयन के लिए कदम उठाये जाने लगे। पहला कदम 1954 में उस समय उठाया गया जब राष्ट्रपति न इस सम्बंध में एक आदेश निकाला। इस आदेश के अनुसार सविधान का पहला दूसरा तीसरा पांचवाँ ग्यारहवाँ बारहवाँ और तेहरवाँ अध्याय राज्य के ऊपर लागू माना गया। इन सबमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया।

26 फरवरी 1958 का राष्ट्रपति न एक दूसरे आदेश के द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया का एक कदम आगे बढ़ाया। इस आदेश के द्वारा भारत के महानंवा परीक्षक का जम्मू और कश्मीर के राज्य में भी नेत्राधिकार प्रदान किया गया। इसका अन्तर्गत चुनाव आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ क्षेत्र भी इस राज्य में लागू कर दिया गया। जब अथेय राज्यों की भांति जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बाद में एक आदेश के द्वारा यह व्यवस्था भी का गई कि अथेय राज्यों की भांति इस

राज्य से भी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर होगा, पहले इनका निर्वाचन राज्य की विधान सभा के द्वारा होता था ।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर कानूनी एवं साविधानिक दृष्टि से न केवल भारत का अभिन्न अंग है, अपितु शनै-शनै उसका भारत के साथ एकीकरण हुआ है तथा केन्द्र सरकार के साथ उसके सम्बन्ध अब लगभग वैसे ही हैं जैसे अन्य राज्यों के हैं । परन्तु इसके साथ में यह बात भी अवलोकित की जा सकती है कि कुछ मामलों में इस राज्य की साविधानिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है । उदाहरण के लिए सघ की ससद भारतीय सघ के अन्य राज्यों के सीमान्तों में हेर-फेर कर सकती है, परन्तु ऐसा वह जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में नहीं कर सकती । द्वितीय, अन्य राज्यों का कोई अपना अलग से संविधान नहीं है, परन्तु इस राज्य का अपना पृथक् संविधान है । तृतीय, आन्तरिक उपद्रवों के आधार पर राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के राज्य में सकट-काल की घोषणा राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता । इसी प्रकार राष्ट्रपति को इस राज्य के सन्दर्भ में यह शक्ति भी प्राप्त नहीं है कि साविधानिक व्यवस्था के असफल हो जाने की स्थिति में वह राज्य के शासन को अपने अधिकार में ले । देश के कुछ राष्ट्रवादी तत्त्वों ने यह मांग प्रस्तुत की है कि इस राज्य का भारतीय सघ के साथ पूर्ण एकीकरण होना चाहिए तथा संविधान के 370वें अनुच्छेद का अन्त कर देना चाहिए । परन्तु ऐसा राज्य की जनता की इच्छा के आधार पर ही हो सकता है । गजेन्द्रगडकर आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में यही सुझाव दिया है कि इस प्रश्न को राज्य की सरकार और जनता के निर्णय पर छोड़ दिया जाये ।

संघीय क्षेत्रों का शासन

मूल संविधान के प्राविधानों के अनुसार भारतीय सघ में आरम्भ में तीन प्रकार की इकाइयाँ थी—‘क’ श्रेणी के राज्य, ‘ख’ श्रेणी के राज्य, और ‘ग’ श्रेणी के राज्य । इनके अतिरिक्त अण्डमान और निकोबार के द्वीपों को ‘घ’ श्रेणी का राज्य कहा गया था । ‘ग’ श्रेणी के राज्यों में जो इकाइयाँ शामिल की गई थी वे इस प्रकार थी—हिमाचल प्रदेश, विलासपुर, भोपाल, कच्छ, मणीपुर, त्रिपुरा, विन्ध्य प्रदेश, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली । 1954 में विलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया ।

यद्यपि इन इकाइयों को ‘राज्य’ की संज्ञा प्रदान की गई थी तथापि अन्य दो श्रेणियों की इकाइयों और इनमें मौलिक अन्तर थे । इन इकाइयों को केन्द्र के साथ अपने सम्बन्धों में वह स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी जो पहली दो श्रेणियों से सम्बद्ध इकाइयों को प्राप्त थी । उनके ऊपर राष्ट्रपति या तो चीफ कमिश्नर के माध्यम से शासन करता था या लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार इन इकाइयों में एक प्रकार का द्वैध शासन कायम था । स्पष्टतः यह व्यवस्था अच्छी प्रकार से काम नहीं कर सकती थी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत संघर्ष तथा अनुत्तरदायित्व की भावनाओं का उदय स्वाभाविक था ।

राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganization Commission) ने इन राज्यों की समस्या पर गहराई के साथ विचार किया । आयोग का यह निष्कर्ष था कि ‘ग’ श्रेणी के राज्यों में निहित अनगतिपूर्ण यथास्थिति का अन्त किया जाना चाहिए । आयोग की सिफारिश थी कि इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा यह कहा कि इन क्षेत्रों में लोकतन्त्र को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन में जनता का परामर्श लिया जाना चाहिए, परन्तु जनता को प्रशासन को संचालित करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ।

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान का सातवाँ संशोधन पारित किया गया । इस प्रकार जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसमें ‘ग’ श्रेणी के पाँच राज्यों को समाप्त करते उन्हें पड़ोस के राज्यों के साथ मिला दिया गया । जो राज्य समाप्त किये गये, वे थे—अजमेर,

भाषान कुग वच्छ और विध्य प्रन्ग । जो काव्या सधीय क्षत्र कहनाया उनका हम दा अणिया म विभाजिन कर सकत है । पहनी अणी म व क्षत्र है जिनम विधान सभाजा तथा मन्त्रिपरिषत्ता की व्यवस्था की गई है । दूसरी अणी म व क्षत्र है जिनम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है ।

अ विधान सभाया वाले मधीय क्षत्रा का शासन

इस प्रकार के क्षत्रा म निम्नलिखित काव्या जाती है—(1) हिमाचन प्रन्ग (2) मणीपुर (3) त्रिपुरा (4) पाण्डीचरी और (5) गोआ डामन ड्यू । पहन तीन क्षत्र ता भारतीय सघ म पहन स नी शामिल थ । इनक निय 1956 म राव्या के पनगठन के उपरात सघ की समत् ने एक कानून के द्वारा एक क्षत्रीय परिषद् (Territorial Council) की स्थापना की थी । 1957 म य परिषदें अपन अस्तित्व म आयी । हिमाचन प्रन्ग म इस परिषद् की सन्म्य-मत्या 41 थी तथा मणीपुर और त्रिपुरा म 30 । इनकी गक्तिया अत्यधिक सीमित था परतु इसक बावजूद इह स्थानीय सस्याआ से अधिक गक्तिया प्राप्त था । गोआ डामन ड्यू पर 1961 तक पुतगानिया का अधिनार था परतु जब इह विन्शी दामता स मुक्ति प्राप्त हो गई तो इन क्षत्रा को भी भारतीय सघ म एकीकृत कर लिया गया । जारम्भ म यहा सनिक शासन की स्थापना की गई कागानतर म नागरिक प्रशासन न सनिक प्रशासन का स्थान न लिया और रेपटीनट गवनर उसका प्रमुख बना । 1 नवम्बर 1954 का पाण्डीचरी का प्रशासन भी भारत के हाथ म आ गया इसक प्रशासन का दायित्व एक चीफ कमिन्टर का सौंपा गया । उसको परामर्श व सहायता दन के निय छ पापन ५ और 40 निर्वाचित सदस्या की एक सभा थी ।

सितम्बर 1962 म भारत की ससद ने चौन्हा सन्ोधन पारित किया । उसके पश्चात 1 जुलाई 1963 स हिमाचन प्रदेश मणापुर और त्रिपुरा की क्षत्रीय परिषदें विधान सभाजा म परिणित हो गई और इसी प्रकार पाण्डीचरी का निर्वाचित सभा को भी विधान सभा का नाम दे दिया गया । इस सम्बन्ध म जा कानून बना उसम मुख्यत अग्रलिखित व्यवस्थाय की ग—

(1) मणीपुर त्रिपुरा हिमाचन प्रदेश गोआ डामन ड्यू एव पाण्डीचरी प्रत्येक एक के निय एक विधान सभा बनी । हिमाचन प्रदेश की विधान सभा म सन्स्या की सत्या 40 रखी गई और गप अय क्षत्रा के निय 30 । (2) विधान सभा की अवधि पाच वष निश्चित की गई परतु असाधारण स्थिति म उसे नमम पन्न भी विषटित करन का प्राविधान ह । (3) यदि किसी विधान सभा नारा पारित किसी भा कानून का कां भी प्राविधान नसद द्वारा बनाय गय किसी कानून स मन नहा खाता तो समत् नान निर्मित कानून असगति की सीमा तक अवध हा जायगा । (4) प्रत्येक नेन का प्रशासन प्रतिवष वित्तीय वष के निय आर्थिक वित्तीय विवरण विधान सभा म प्रस्तुत करवाना है परतु उन पर राष्ट्रपति की पूव अनुमति प्राप्त की जाती है । (5) प्रत्येक क्षत्र म प्रशासक का उसके कार्यों म सहायता व परामर्श के लिए एक मन्त्रिमन्ग का व्यवस्था की गई है ।

व एम सधीय क्षत्र जिनम विधान सभाय नहा है

दिन्नी—इसक प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से सधीय ससद के हाथ म है । इसका दख रख सघ सरकार के गृह मन्त्री के द्वारा होती है । 1957 के म्युनिमिपल कार्पोरेशन कानून के अनुसार समूच दिन्नी क्षत्र के निय—जिसम शहरी और ग्रामीण सभी क्षत्र शामिल हैं—एक निगम की स्थापना हुई है । निगम म 100 सदस्य और 6 एट्टरमन ह । 1966 म दिन्नी के निय समद न एक और कानून पारित किया जिस दिल्ली प्रशासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है । इस कानून के नारा दिन्नी के निय एक मेट्रोपॉलिटन कांसिल (Metropolitan Council) की रचना हुई है । इसकी कुल सदस्य सत्या 61 है इस कांसिल का कुछ विधायी काय मौप गय हैं । दिन्नी क्षेत्र के मुख्य कायपात्रिका अधिकारी को रेपटीनट गवनर का नाम दिया गया है तथा उसके कार्यों म सहायता व परामर्श के लिए चार कायकारी पापन (Executive

Councillors) तथा एक मुख्य पार्षद की व्यवस्था की गई है। इस कानून ने दिल्ली के लिये एक पृथक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह—ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। यहाँ के सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रशासन एक चीफ कमिश्नर के हाथों में है। प्रशासन की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ एक म्युनिस्पैलिटी है।

लक्कादीव, मिनीकाय और अमिनीदीव द्वीप समूह—ये द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। इनका कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत ही कम है। इनका प्रशासन एक सभ सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा संचालित होता है।

दादरा और नागर हवेली—ये क्षेत्र पहले पुर्तगाल के अधीन थे। 11 अगस्त 1961 को इन क्षेत्रों को भारतीय सभ में मिला लिया गया। अब उनका प्रशासन सभ सरकार द्वारा एक सघीय क्षेत्र के रूप में होता है।

नेफा (North East Frontier Agency—NEFA)—प्रशासन को संचालित करने के लिए नेफा को पाँच कमिश्नरियों में बाँटा गया है। प्रत्येक कमिश्नरी का कार्यभार एक राजनीतिक अधिकारी (Political Officer) है। उनके अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त अधिकारी भी हैं। प्रत्येक कमिश्नरी उप-कमिश्नरियों में विभाजित है। राजनीतिक अधिकारी की सहायता के लिए चिकित्सा अधिकारी, कृषि अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक आदि हैं।

चण्डीगढ़—पंजाब के विभाजन के पश्चात् हरियाणा और पंजाब के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि चण्डीगढ़ पर किमका अधिकार हो। चूँकि कोई भी पक्ष अपने दावे को छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए चण्डीगढ़ को केन्द्रीय-शासित सघीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। चण्डीगढ़ का लोकसभा में एक प्रतिनिधि है।

सघीय क्षेत्रों का आधुनिक स्वरूप

पिछले दिनों में कुछ सघीय क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उन क्षेत्रों के नाम हैं—हिमाचल प्रदेश (1970), मेघालय (1971), मणिपुर (1971) तथा त्रिपुरा (1971)।

पूर्वी सीमान्त पर स्थित क्षेत्रों को नये नामों के साथ सघीय क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी गई है। वे हैं—मीजोरम (1971) तथा अरुणाचल (1971)। इस प्रकार अब भारतीय सभ में 21 राज्य हैं तथा 9 केन्द्र-शासित सघीय क्षेत्र हैं—दिल्ली, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्कादीव-मिनीकाय-अमिनीदीव द्वीप समूह, दादरा-नागर हवेली, गोआ-डामन-ड्यू, पाण्डीचेरी, चण्डीगढ़, मीजोरम, तथा अरुणाचल।

प्रश्न

- 1 राज्यपाल की साविधानिक स्थिति की विवेचना करते हुए यह बताइये कि उसमें साविधानिक अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारों दोनों का किस प्रकार समन्वय हुआ है ?
- 2 चौथे आम चुनाव के बाद राज्यपालों ने अपनी भूमिका को किम प्रकार निभाया है ?
- 3 राज्यों के विधान-मण्डलों की रचना किम प्रकार होती है तथा उनके कौन-कौन से प्रमुख कार्य हैं ?
- 4 राज्यों के मन्त्रिमण्डल में मुख्य मंत्री के पद की विवेचना कीजिए।
- 5 राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के सगठन व शक्तियाँ का वर्णन कीजिए।
- 6 जम्मू-कश्मीर राज्य की साविधानिक स्थिति पर एक टिप्पणी लिखिये।
- 7 सघीय क्षेत्रों के शासन पर एक निबन्ध लिखिये।

भारतीय संघवाद का स्वरूप (NATURE OF INDIAN FEDERALISM)

प्रस्तावना

पिछले अध्याय में जमा कहा जा चुका है संविधान के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था में परंतु उसमें क्या भाषा के अन्तर्गत का प्रयोग नहीं किया गया है। वस्तुतः संविधान में भारत को राज्य की यूनिटों के रूप में पुकारा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष इस शब्दावली के प्रयोग में प्राप्त होने वाले लाभों की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था कि संघवाद का सही महत्वपूर्ण तथ्या का अभिव्यक्ति होना है—प्रथम भारत में संघवाद का अर्थ है कि किसी समझौते का परिणाम नहीं है और द्वितीय में यह सम्मिलित होने वाली इकाइयों का उसमें पृथक् होने का अधिकार नहीं है। यथायथ भारत में संघ की रचना एकात्मक राज्य के पुनर्गठन के द्वारा हुई है। संघ में अंतराकाशी भांति स्वतंत्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों के बीच का किसी संविधान के परिणामस्वरूप नहीं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि वह राज्यों का एक स्थायी संघ होना। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की शासन प्रणाली संघात्मक नहीं है। यथायथ भारत में संघवाद के लक्षणात्मक अत्यधिक स्पष्ट रूप में अवलंबित किया जा सकता है। सर्वप्रथम उसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियाँ का बंटवारा होता है। संघ तथा तीन सूचियाँ निर्धारित की गई हैं। संघ सूची में सर्वोच्च सूची तथा राज्य-सूची में सूचियाँ पर केन्द्र और राज्यों के कार्य-क्षेत्र का पहलू से ही परिभाषित कर दिया गया है। साधारणतः राज्य अपने निश्चित क्षेत्र में संघ सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त है। अतः यह कहा जा सकता है कि राज्य भारतीय संघ में स्वायत्तता प्राप्त करते हैं। इन प्रकार की सरकारें अपनी अपनी शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में संविधान से प्राप्त करती हैं। द्वितीय संविधान को राज्य का सर्वोच्च कानून माना गया है। उसके प्राविधान सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी है। न तो केन्द्र की सरकार उनका अपवाद हो सकती है और न राज्यों की सरकारें। इसका अर्थ यह भी हुआ कि उपर्युक्त दोनों प्रकार की सरकारों की संविधान में उल्लिखित शक्तियों के विभाजन को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने का अधिकार नहीं है। तृतीय संविधान निम्नलिखित है और एक सीमा तक सुसंगत भी। चतुर्थ भारत में एक स्वतंत्र नागरिकता का व्यवस्था की गई है और उस संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को संघीय समक्ष अथवा राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित किसी भी कानून को इस आधार पर अवयव घोषित करने का अधिकार है कि उसके द्वारा संविधान की किसी व्यवस्था का उल्लंघन होता है।

परंतु हमारा संविधान में संघात्मक व्यवस्था को उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिस रूप में उसमें अन्य संघ राज्यों में माना गया है। वस्तुतः उसमें अंतराकाशी व्यवस्था है कि कुछ भाग में उसमें अर्ध-संघ (Quasi federation) कहा है। वे साक्ष्यों के अनुसार भारत ऐसा संघ राज्य होने वाला जिसमें एकात्मक तत्त्व गौण रूप में पाया जा रहा है। एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक तत्त्व गौण रूप में पाया जा रहा है। ऊपर कहा जा चुका है कि संविधानकारों ने अन्तर्गत का कहा प्रयोग नहीं किया उसमें स्थान पर उन्होंने यूनिट

शब्द का प्रयोग किया है। इससे इस दृष्टिकोण को बल मिलता है कि भारतीय संविधान का केवल बाह्य स्वरूप सघात्मक है किन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है। समूचे संविधान में बल एकरूपता तथा केन्द्र की शक्ति के ऊपर है। संविधान के एकात्मक पहलू को निम्न प्रकार देखा जा सकता है।

1 संविधान के एकात्मक तत्त्व

(1) **शक्तिशाली केन्द्र की रचना**—संविधान ने एक ऐसे शक्तिशाली केन्द्र की रचना की है, जिसकी तुलना सप्तास के किसी अन्य सघीय संविधान के साथ नहीं हो सकती। सम्भवतः संविधानकारों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय भारत साम्प्रदायिक गृह-युद्ध की ज्वाला में से होकर गुजर रहा था और वे देश की स्वतन्त्र सत्ता को विघटनकारी शक्तियों की चुनौती का सामना करने के लिए समर्थ बनाना चाहते थे। इसका दूसरा कारण यह था कि संविधानकार इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में केन्द्रीय सत्ता के दुर्बल होने की स्थिति में राष्ट्र का अस्तित्व ही संकट में पड़ चुका है। फलतः तीन विषय-सूचियों में जो सबसे अधिक लम्बी सूची है, वह सघ सूची है, जिसमें 97 विषय हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची है जिसमें 47 विषय हैं और जिसके ऊपर केन्द्रीय सरकार को आवश्यकता पड़ने पर अधिकार दिया गया है तथा जिसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर केन्द्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा बनाये गये कानूनों में विरोध है तो केन्द्र का कानून चलेगा और राज्य का कानून अवैध माना जायेगा। यही नहीं, संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को भी केन्द्र को ही सौंपा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में जो शक्तियों का बँटवारा हुआ है, वह मूलतः केन्द्र को अधिक शक्ति प्रदान करने की भावना से अनुप्राणित है।

(2) **समूचे सघ के लिए एक संविधान की व्यवस्था**—भारत में अन्य सघों की भाँति इकाइयों को अपना अलग-अलग संविधान बनाने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है अपितु समूचे देश के लिए एक ही संविधान है। संविधान सभा केवल सघ की ही संविधान सभा नहीं थी, बल्कि वह राज्यों की भी संविधान सभा थी। फलतः उसने जिस संविधान की रचना की, उसमें जहाँ सघ की शासन-प्रणाली का उल्लेख है, वहाँ उसमें राज्यों की शासन-प्रणाली का भी वर्णन हुआ है। डा० अम्बेदेकर के शब्दों में 'सघ और राज्यों के संविधान का एक ही ढाँचा है जिसमें से कोई भी नहीं निकल सकता और उन्हे उसी के अन्तर्गत काम करना है।' इस नियम का केवल एक ही अपवाद है और वह है जम्मू-कश्मीर का राज्य जिसे कुछ विशिष्ट कारण-वश अपने संविधान को बनाने का अधिकार दिया गया था।

(3) **दुहरी नागरिकता का अभाव**—सभी पारस्परिक सघीय प्रणालियों में नागरिकों की दुहरी नागरिकता स्वीकार की गई है, परन्तु इस सम्बन्ध में भारतीय सघ अन्य सघों से भिन्न है। भारत में संविधान केवल एक ही प्रकार की नागरिकता स्वीकार करता है और वह है भारतीय नागरिकता। भारत में विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी पृथक् नागरिकता की व्यवस्था नहीं है।

(4) **सकटकालीन प्राविधान**—पारस्परिक सघीय संविधानों के ढाँचों में एक प्रकार की दुरुहता पायी जाती है। किसी भी परिस्थिति में उनके सघीय स्वरूप को नहीं बदला जा सकता, यदि ऐसा किया जाना आवश्यक है तो उसके लिए संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। परन्तु भारत में बिना संशोधन किये ही सघात्मक राज्य को एकात्मक राज्य में बदला जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान समय एवं परिस्थितियों के अनुसार सघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार के राज्यों की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान का यह एक ऐसा पहलू है जिसकी मिनाल किमी अन्य सघीय राज्य में नहीं मिल सकती।

(5) **साधारण स्थिति में भी केन्द्र की शक्ति में अभिवृद्धि करने की व्यवस्था**—हमारे

संविधान का एक असाधारण पहलू यह है कि उसमें साधारण स्थिति में भी केन्द्र की विधायी शक्ति में अभिवृद्धि करने का प्राविधान पाया जात है। साधारणतया राज्य के विधामण्डल का राज्य सूची में दिया हुआ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु संविधान की 249वीं धारा में लिखा है कि यदि राज्य सभा ने तिहाई बहुमत से केंद्र शासन का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय अथवा विषयों पर केंद्रीय कानून का होना राष्ट्रीय हित में है तो उस स्थिति में सद्यः उस विषय अथवा उन विषयों पर कानून बना देगी। स्पष्टता के प्रकार की व्यवस्था भी किसी अन्य सध में नहीं पायी जाती।

(6) इकाया की प्रादेशिक अखण्डता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सुनिश्चितता का न होना—अब सभा की भांति भारतीय सघ की व्याख्या की प्रादेशिक अखण्डता के सम्बन्ध में संविधान में किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई है। संघीय संस्था में उनके सीमाओं में हर फेर करने नये राज्य की रचना करने का अधिकार प्राप्त है उस यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्रों का घटा जयवा बना दे तथा उस यह अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह किसी राज्य की सामाजिक या अथवा उसके नाम को बदल सके। संविधान की तीसरी धारा में निश्चित है कि उपर्युक्त प्रकार के परिवर्तन राष्ट्रपति की सिफारिश पर केन्द्रीय मंसूब के द्वारा पारित कानून से किया जा सकते हैं जबकि सम्बन्ध में कबन एक ही बात है और वह यह है कि राष्ट्रपति अपनी सिफारिश करने के पूर्व सम्बद्ध राज्य अथवा राज्य की राय जान ले। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के लिए सम्बद्ध राज्य अथवा राज्य की उस मामल में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं माना गया है। केन्द्रीय सरकार ने संविधान के इस प्रावधान को अतन्त्र देना के राजनीतिक मानचित्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इस दिशा में एक कदम उस समय उठाया गया जबकि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई। कालांतर में असम के राज्य में एक राज्य नामाकरण निमित्त किया गया। पंजाब के दो भाग कर लिये गये—पंजाब और हरियाणा। 1970 में असम के अतन्त्र मंचान्त के एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई।

(7) राज्य सभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व का न दिया जाना—सामान्यतः पारम्परिक संघीय राज्यों में इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिये जाने की व्यवस्था पायी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा सीनेट में दो प्रतिनिधि भेजता है। ऐसा ही व्यवस्था स्विट्जरलैण्ड में पायी जाती है जहाँ प्रत्येक कanton संघ के द्वितीय सदन में दो प्रतिनिधि भेजता है और प्रत्येक अधिवेशन एक प्रतिनिधि। किंतु भारत में प्रत्येक राज्य अपनी जनसंख्या के आधार पर राज्य सभा में अपने अपने प्रतिनिधि चुनता है।

(8) राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति—भारतीय संविधान में राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश पर होती है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति को राज्य के गवर्नर की नियुक्ति और हटाने का अधिकार प्राप्त है।

(9) मूल अधिकारों में एकरूपता—सामान्यतः अथ सघीय प्रणालियाँ में कानून प्रशासन तथा न्यायिक मरम्भण के मापना में विभिन्नता पायी जाती है। किन्तु भारत में इस प्रकार की विभिन्नता को काय स्थान नहीं दिया गया है। क्योंकि संविधानकारों का आशय था कि यदि इस विभिन्नता को सीमाश्रय का अतिक्रमण करने दिया गया तो उसमें न्याय में अयवस्था फैल जायेगी। फलतः संविधान में एकरूपता पर ध्यान दिया गया और इसके लिए तीन तरीकों का अपनाना गया है—

(क) समूच देश व तिए उहाँन समन्वित मायपात्रिका (integrated judiciary) की रचना की है (ख) समूच देश के तिए उहाँन एक ही प्रकार व असन्धित एक फौजदारा कानून का

स्थापित किया है, तथा (ग) उन्होंने समूचे देश के लिए समन्वित शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था की है। वित्तीय प्रशासन को भी इस प्रकार निमित्त किया गया है जिसमें समूचे देश की वित्तीय स्थिति की देखभाल कम्पट्रोलर जनरल तथा आडीटर जनरल कर सके। यही नहीं, समूचे देश के लिए चुनावों की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है।

(10) सविधान में दुःसहोध्यता की न्यूनता—भारतीय सविधान सप्ताह के अन्य सघीय सविधानों की अपेक्षा कम दुःसहोध्य है। जैसा कहा जा चुका है कि सविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें सकट काल में बिना किसी संशोधन के बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राविधान ऐसे हैं जिन्हें केवल संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही बदला जा सकता है। कुछ अन्य प्राविधानों को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों के अलग-अलग दो-तिहाई मतों की आवश्यकता होती है, बहुत थोड़े से मामलों में संशोधन करने के लिए आठ राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सविधान में संशोधन की प्रक्रिया अन्य सघीय राज्यों की अपेक्षा कम जटिल है। फलतः सविधान में यह निश्चितता एवं अन्तिमता नहीं पायी जाती जो अन्य सघों के सविधानों में पायी जाती है।

2 सघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध ✓

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सविधान ने देश में जिस सघ की स्थापना की है, उसका रुझान निश्चयात्मक रूप से एकात्मकता की ओर है। सविधान के इन उपबन्धों की बहुत आलोचना की गई है। कुछ आलोचकों ने तो यहां तक कहा है कि सघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इस प्रकार किया गया है कि राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं के समान हो गयी है। वस्तुतः इस प्रकार की आलोचनाएँ अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, और उनसे पूर्णरूपेण सहमत होना कठिन है। किन्तु फिर भी उनमें निहित मूल्य अथवा असत्य का पता लगाने के लिए सघ एवं राज्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों की समीक्षा की जाये।

(अ) विधायी सम्बन्ध

जैसा कहा जा चुका है कि भारत में शक्तियों को तीन सूचियों में बाँटा गया है—सघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची।

(1) सघ सूची—सघ सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के 97 विषय हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, मौलिक शक्ति, गस्त्रास्त्र, युद्ध और शान्ति, आणविक शक्ति तथा उसके निर्माण के लिए आवश्यक प्राकृतिक प्रसाधन, देशीकरण, मुद्रा-निर्माण, लोक ऋण, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, विदेश व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य, नियमन तथा उनका विनियमन, आयात एवं निर्यात, तम्बाकू और अफीम आदि पर महसूल, बैंकिंग, बीमा, जेयर बाजार, नाप-तौल के प्रतिमान, उद्योग नियन्त्रण, खानों, खनिज पदार्थों तथा तेल संसाधनों का विनियमन एवं विकास, राष्ट्रीय संग्रहालयों का आरक्षण, ऐतिहासिक स्मारक, भारत का सर्वेक्षण, सघीय लोक-मेवाएँ, संसद व राष्ट्रपति के निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जनगणना, गान्तिनिकेतन, मीमांश-शुल्क तथा निर्यात-शुल्क, निगम-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, मस्यदा-शुल्क, समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय पर कर, अलीगढ़, बनारस एवं उस्मानिया विश्वविद्यालय आदि।

उपर्युक्त सूची में स्पष्ट है कि उसमें ऐसे सभी विषय सम्मिलित हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्त्व का माना गया है। परन्तु इस सूची का महत्त्व केवल उन विषयों के कारण नहीं है जिन्हें उसमें शामिल किया गया है, उसका महत्त्व इस सूची के साथ दिये गये अन्य प्राविधानों के कारण भी है। उदाहरणस्वरूप, सूची में 52वें नम्बर पर लिखा है—‘उद्योगाध्वे जिन पर संसद द्वारा पारित कानून मार्गदर्शक हित में सघ का नियन्त्रण वाछनीय घोषित करे।’ इस व्यवस्था के फलस्वरूप सघ सरकार ने लोहे और इस्पात के बहुत से उद्योगों को तथा 1971 में कोयले की खानों पर अपना

नियंत्रण स्थापित कर दिया था। सभी प्रकार के विधायन जहाँ राज्य सूची में आते हैं वहाँ विधान न समझ को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह किसी भी मन्त्रालय को राष्ट्रीय महत्व की समस्या घोषित कर सकती है और इस प्रकार वह उस मन्त्रालय के नियंत्रण में आ सकती है। संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करके जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल आफ टेक्नोलॉजी स्टडीज तथा गुप्तकृत विधिविधान के अपने नियंत्रण में ले लिया। इसमें यह प्रमाणित है कि इस सूची में मन्त्रालय संसद की पूरी शक्तियाँ का अनुमान नहीं हो सकती उसकी शक्तियाँ का सही मूल्यांकन करने के लिए विधान के अन्य प्रावधानों को भी देखना आवश्यक है।

(ii) समवर्ती सूची—इस सूची में राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के 47 विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची का व्यवस्था भारतीय मन्त्रालय की कोई अपनी विधिपता नहीं है। वस्तुतः विश्व के अन्य संघीय संविधानों में इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि शक्तियाँ दो सूचियों में वितरण से जो जटिलता उत्पन्न हो उससे बचकर ली जा सके तथा कानून की आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय मन्त्रालय के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया जा सके। जैसा बताया जा चुका है कि इस सूची में उल्लिखित विषयों पर संघ और राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है परन्तु यदि संघ और राज्य के कानूनों में कोई अतिरिक्त है तो उस स्थिति में संघ का कानून माना जायेगा राज्य का नहीं। इस सूची में वर्णित विषयों में से मुख्य निम्नलिखित हैं—पौजदारों का कानून व प्रक्रिया सिविल प्रणाली विचारक निराश विवाह और विवाह विच्छेद विधानाधिकार तथा ऋण ग्राहकता पागलपन ठग और सामेनारी मजदूर संघ श्रमिक तथा सामाजिक नियोजन सामाजिक सुरक्षा और बीमा गणनाधिकार की सहायता पुनर्वास खाद्य पदार्थों में मितिवत् राजगार और धरोजगार विधि चिकित्सा तथा व्यवसाय श्रम मरण के आकरे श्रम कल्याण सूच्य नियंत्रण कारखाने प्रजनी समाचार-पत्र पुस्तकें तथा मुद्रणालय आदि।

1954 में पारित तृतीय संशोधन के अनुसार इस सूची में एक विषय और जोड़ा गया है जो इस प्रकार है—(अ) एक किसी उद्योग या के उत्पादन जिसे संसद के कानून के द्वारा सावजनिक स्थिति में संघ के नियंत्रण के योग्य घोषित किया जा चुका है तथा उसी प्रकार के उत्पादन के आयात (ब) खाद्यान्न जिनमें तिलहन और खाने के तेल शामिल हैं (स) पशुओं का चारा जिनमें घन सम्मिलित है (द) कपास और कितोले तथा (य) कच्चा जूट। इस संशोधन द्वारा प्राप्त शक्ति के अंतर्गत ही संघ सरकार ने एक राज्य संघ संघ राज्य में तथा एक राज्य के भीतर एक स्थान में दूसरे स्थान में खाद्यान्न के खाने तथा न खाने को निर्यात किया था।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर संघ एवं राज्य के बीच संघ की स्थिति का निराकरण करने के लिए एक अभिसमय विकसित हुआ है जिसके अनुसार संघ सरकार राज्य की सरकारों को समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय पर यदि उसकी इच्छा कानून बनाने की है तो वह उसमें राज्य की सूचना भेज देती है। राज्य की सरकार इस अवसर का लाभ उठाकर संघ की सरकार को उस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण में अवगत करा सकती है। इसी प्रकार राज्य की सरकारें भी जब वह ऐसा करता होता है केन्द्र का अपने प्रस्ताव की सूचना भेज देती है और वे सामान्यतः उस समय तक कानून नहीं बनाते जब तक कि संघ का कानून मन्त्रालय उस अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर देता।

(iii) राज्य सूची—इस सूची में 66 विषय हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य का ही प्राप्त है। दूसरे शब्दों में साधारण स्थिति में इस सूची में वर्णित विषयों पर संघ की संसद का कानून बनाने का अधिकार में वंचित रखा गया है। इस सूची में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया है उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—सांख्यिक व्यवस्था पुलिस पाय प्रशासन जन तथा सुधारालय स्थानीय शासन सावजनिक स्वास्थ्य और मर्त्य भिक्षा पशु पुस्तकालय अजायबघर वृषि मिचाई पशुपालन मत्स्य व्यवसाय चिकित्सालय वन्य पशुओं की रक्षा ग्राम-सुधार सावजनिक निर्माण कार्य गस व गस निमाण मण्डियाँ और मेने

राज्यगत व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि आय-कर, भूमि-कर, मनोरजन-कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर, समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर विक्री-कर, विज्ञापन पर कर, वस्तुओं की उत्पत्ति तथा उनका वितरण, नाटक घर आदि।

उपर्युक्त सूची से स्पष्ट है कि सामान्यतः ऐसे उन सभी विषयों को राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है जिनका सम्बन्ध सामाजिक कल्याण के साथ है। इस सूची से यह भी भासित होता है कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में स्वायत्तता प्रदान की गई है। किन्तु यथार्थ में यह स्वायत्तता उतनी वास्तविक नहीं है जितनी कि वह दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सघ सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों में सविधान के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में दिये हुए विषयों के ऊपर भी कानून बनाये।

राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर केन्द्रीय ससद के हस्तक्षेप की एक अन्य स्थिति भी हो सकती है। सविधान की 253वीं धारा में लिखा है कि अपने अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों के पालन के लिए केन्द्र की ससद राज्य सूची में दिये गये ऐसे सभी विषयों पर कानून बना सकती है जिनका सम्बन्ध उन अनुबन्धों के साथ है। इस प्रकार सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्यों के विधानमण्डलों का राज्य सूची में गिनाये गये विषयों पर कोई एकाधिकार नहीं है, यद्यपि यह सही है कि सविधान के लागू होने के बाद केन्द्र ने इन प्राविधानों का दुरुपयोग करके राज्यों की स्वायत्तता के लिए कोई खतरा प्रस्तुत नहीं किया है।

(iv) **अवशिष्ट शक्तियाँ**—जो विषय उपर्युक्त तीनों सूचियों में वर्णित नहीं हैं, उनका प्रशासन सघ सरकार को सौंपा गया है। संयुक्त राज्य अमरीका में ये शक्तियाँ राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं, इस प्रकार भारतीय सविधान की यह व्यवस्था अमरीकी सविधान की व्यवस्था से भिन्न है। किन्तु यह व्यवस्था कनाडा के सविधान से मिलती-जुलती है, वहाँ भी इन शक्तियों को केन्द्र में निहित किया गया है।

सघ और राज्यों के बीच पाये जाने वाले विधायी सम्बन्धों के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सविधान ने राज्यों के विधानमण्डलों को भी यह अधिकार प्रदान किया है कि वे यदि आवश्यक समझे तो राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय अथवा विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र की ससद को समर्पित कर दें। सविधान की 252वीं धारा में यह प्राविधान है कि यदि दो अथवा दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें तो केन्द्र की ससद उनके लिए उस विषय पर कानून बना सकती है और इस प्रकार बनाये गये कानून को राज्य के कानून द्वारा सशोधित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सविधान की इस व्यवस्था को सघीय प्रणाली का उत्तलघन करने के लिए केन्द्र की सरकार के पास राज्यों की ओर से एक स्थायी निमन्त्रण की सज्ञा प्रदान की जा सकती है। बहुत सम्भव है कि अधिकांश राज्यों में तथा केन्द्र में किसी एक दल का शासन हो तथा कुछ थोड़े से राज्यों में अथवा किसी एक राज्य में किसी दूसरे दल का शासन हो। उस स्थिति में केन्द्र का शासक दल राज्यों में स्थित अपने दल की सरकारों के साथ सॉठ-गॉठ करके केन्द्र की ससद को अपरिमित विधायी शक्तियों को हड़पने का अवसर दे सकती है।

(व) प्रशासनिक सम्बन्ध

किसी भी सघीय शासन-प्रणाली की सफलता के लिए यह परमावश्यक है कि सघ तथा राज्यों की सरकारों के बीच पारस्परिक सहयोग हो। परन्तु प्रत्येक सघीय राज्य में कुछ ऐसी शक्तियाँ जवश्य पायी जाती हैं, चाहे वे हज़र हो अथवा अदृश्य, जिन्हें यदि कानून द्वारा मर्यादित न किया जाय, तो वे विवादों एवं सघर्षों को जन्म दे सकती हैं, जिनके परिणामस्वरूप राज्य के अस्तित्व को भी खतरा पहुँच सकता है। अतः प्रत्येक सघ में इस प्रकार की सम्भावना का निराकरण करने के लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध अवश्य कर लिये जाते हैं। भारतीय सविधान में भी इस

प्रसार के प्रवर्गा की व्यवस्था है। वस्तुतः इन प्रवर्गों के मूल में दा उद्देश्य निहित हैं—प्रथम सघीय मसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर सघ के नियन्त्रण का प्रभावगामी बनाना तथा द्वितीय सघ और राया के बीच सघ की स्थिति का उत्पन्न न हान देना। यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रवर्ग में केन्द्र की स्थिति का सर्वोपरि स्थान मिलता तथा राया की स्थिति को हीन रखा जाता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान में सघ और राया के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारित करत समय 1935 के अधिनियम का अनुकरण किया गया है। केन्द्रीय सरकार राया पर निम्नलिखित ढंग से अपने नियन्त्रण का प्रयोग में ला सकती है—

(1) राय सरकारों को निर्देश देना—संयुक्त राय अमरीका में सघीय सरकार द्वारा राय सरकारों के निर्देश देने का अच्छा नमूना माना जाता। किंतु भारतीय संविधान सघ का निम्न स्थिति में निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है—

(अ) संविधान का 26वाँ धारा में लिखा है कि प्रत्येक राय की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा जिसमें संसद द्वारा निर्मित कानूनों का तथा उन वर्तमान कानूनों का जो उस राय में लागू हैं पानन सुनिश्चित रहे तथा सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राय में एक निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार का उस प्रयोजन के लिए आवश्यक लिखा है।

इस प्राविधान के मूल में दो सिद्धान्त निहित हैं जिनका उल्लेख स्वयं डा अम्बेकर ने संविधान सभा में किया था। डा अम्बेकर के ही शब्दों में—प्रथम सिद्धान्त यह है कि समवर्ती सूची के बारे में कानून चाहें उस संसद में बनाया जाए या राय विधानमण्डल में उसे कार्यान्वित करने की शक्ति साधारणतया राया में निहित होगी। दूसरा यह कि समवर्ती सूची में संविधान विषय के बारे में कानून की रचना करने समय यदि संसद के विचार में केन्द्रीय सरकार को उसका परिधानन करवाना तथा कार्यान्वित करने की शक्ति होगी चाहिए तो संसद ऐसा करने में समर्थ होगी।

क्या यह वाञ्छनीय है कि केन्द्रीय सरकार के कानूनों पर कोई अमन न किया जाय और वह केवल कांग्रेस पर लिखे कानून माने जा सकें। संविधान ने केन्द्र को यह दायित्व सौंपा है कि वह छुआडूँ का उन्मूलन करे। क्या यह बात युक्तिसंगत कही जा सकती है कि केन्द्र एक विधायक पारित कर गति से बँट जाय और प्रतीक्षा करता रहे कि राज्य सरकार किस प्रकार उक्त विधायक की क्रियाविति करती है।

राय सरकार द्वारा इन आदेशों के पानन न करने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषणा कर सकता है कि राय में सांविधानिक व्यवस्था अक्षय हो गई है और वह इस घोषणा के द्वारा राय द्वारा सम्पानित हानि वाले सभी कामों को अथवा किसी एक काम को अपने हाथ में ले सकता है।

(ब) संविधान ने सघ की कार्यपालिका को यह दायित्व भी सौंपा है कि वह यह लेखे कि राय और सघ के बीच का सघ उत्पन्न न हो पाय। संविधान की 257वीं धारा में लिखा है कि राय की सीमाओं के अंदर केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति को अनुचित अथवा अव्यवस्थित न किया जाय। यदि किसी सघीय अभिकरण को किसी राय में अपने कर्तव्य का परिधानन करने में कठिनाई होनी हो तो सघों कार्यपालिका राय सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकती है।

(स) कुछ विषय ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन मामलों के ऊपर राया का सहायपरामर्श देता रहे। इस प्रकार के विषयों में राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्त्व के संचार-साधना का निमाण और पोषण राया के सीमान्तों में रहने वालों की सुरक्षा आदि शामिल हैं। संविधान ने संसद को यह शक्ति भी प्रदान की है कि वह किसी राजपथ को अथवा जनमार्गों को अथवा नौकागम्य नदियों को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर दे और

फिर उनके नियन्त्रण को केन्द्र के हाथों में सौंप दे।

यह बहुत सम्भव है कि केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट कार्यों के सम्पादन में राज्यों को अपने सामान्य व्यय से अधिक व्यय करना पड़े। अतः संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार के कार्यों के लिए जो अतिरिक्त व्यय राज्यों को करना पड़े, उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। व्यवस्था के अनुसार सघ राज्यों के साथ एक करार करेगा जिसमें यह निश्चित कर दिया जायेगा कि सघ कितनी राशि देगा। यदि सम्बद्ध पक्षों को इस सम्बन्ध में कोई समझौता करने में सफलता न मिले तो उस स्थिति में मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है और वह यह निश्चित करेगा कि राज्य ने उस कार्य के लिए कितना अतिरिक्त व्यय किया है। राज्य को उतनी ही राशि अतिरिक्त व्यय के लिए दी जाएगी।

(2) **सघीय कार्यों का राज्य सरकारों को सौंपना**—संविधान का 258वा अनुच्छेद सघीय कार्यपालिका को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने क्षेत्र में आने वाले कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य राज्य की सम्मति से राज्य सरकार अथवा उसके किसी अधिकारी को सौंप दे। संसद को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने किसी कानून द्वारा (जो राज्यों पर लागू होता है) राज्य के अधिकारियों को कोई भी शक्ति कार्य अथवा उत्तरदायित्व सौंप सके। सघ सरकार राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य के लिए किये गये व्यय की अदायगी राज्य सरकार को करेगी। यह व्यवस्था है कि इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ करेगा।

संविधान की 207वी धारा भारत सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी विदेशी राज्य की सरकार के साथ किये गये समझौते के आधार पर किसी भी राज्य-क्षेत्र में कोई भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अथवा न्यायपालिका सम्बन्धी कार्य ग्रहण कर सकती है। 260वी धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र सघ की, तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, न्यायिक कार्यवाहियों तथा अभिलेखों आदि को पूर्ण मान्यता प्रदान की जाएगी। इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने की रीति एवं शर्तों तथा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा निश्चित रीति के अनुसार होगा।

यहाँ उल्लेखनीय बात यह भी है कि संविधान की 355वी धारा ने सघ सरकार को यह कर्तव्य सौंपा है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ी से राज्य सरकार की रक्षा करे और इस बात का ध्यान रखे कि प्रत्येक राज्य में शासन का परिचालन संविधान के अनुसार हो।

(3) **अखिल भारतीय सेवाएँ**—भारतीय संविधान द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि सघ सरकार एवं राज्य सरकारों के अलग-अलग सार्वजनिक अधिकारी होंगे जिनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होगा। परन्तु साथ ही में संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि भारतीय प्रशानन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का कार्य-क्षेत्र सघ एवं राज्य दोनों में समान रूप से होगा। संविधान की 312वी धारा में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राष्ट्रीय हित में कानून द्वारा सघ एवं राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की रचना के लिए उपबन्ध कर सकती है। वस्तुतः यह प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है।

(4) **आर्थिक सहायता**—यदि किसी सघ की इकाइयों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वायत्तता को औपचारिक बनाने के स्थान पर उसे कुछ वास्तविक स्वरूप प्रदान करना अपेक्षित है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि इकाइयों को आर्थिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। परन्तु इस सिद्धान्त की कठोर क्रियान्विति सम्भव नहीं है। अतः सामान्य रूप से प्रत्येक मघात्मक संविधान में इन प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि करो में प्राप्त कुछ धनराशि का मघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विभाजन हो जाय करे। परन्तु इस व्यवस्था से भी राज्य सरकारों का काम नहीं चल पाता, फलतः उन्हें केन्द्र की आर्थिक सहायता का मुँह देखना पड़ता है। भारतीय संविधान की 275वी धारा में यह व्यवस्था की गई है कि वह राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप

म एसा रागियाँ कानून द्वारा निर्धारित कर कि उन्हें कितन धन की आवश्यकता है। एसी धारा म यह भी कहा गया है कि अनुदान के रूप म राया को दी गई धनरागिया भारत क सचित निधि प भरिन हा। सविधान न विगण रूप स दा स्थितिया म राया का क द्वारा आर्थिक सहायता निगान की व्यवस्था की है—

(अ) यदि किसी भी राय न भारत सरकार की पूव सहमति स ऐसी निकास योजनाआ के कार्याचयन का उत्तरदायित्व अपन हाया म न दिया हा अथवा जिनका उद्ग्य अनुसूचित रा के प्रगासकीय स्तर का ऊचा करना हा तो उसक निग सम्बद्ध राय को अनुदान दिया जा सकता है। पर तु यह अनुदान भारत की सचित निधि पर भारित होगा।

(ब) अमम के राया का अनुसूचित क्षता क विकास क लिए सहायक अनुदान दिया जा सकता ह।

उपयुक्त विवेचना स प्रमाणित है कि आर्थिक सहायता क माध्यम स सघ की सरकार का सहायता प्राप्त करन वान राया पर अपना नियन्त्रण स्थापित करन का अवसर मिल जाता है। आर्थिक सहायता सत्व किसी शत क साथ दी जानी है तथा वह सघीय सरकार के विनियमा के अधिन रहती है। यह स्वाभाविक भी है कि जा धन खय करता है वह अपना इच्छानुसार नीति भी निर्धारित कर।

(म) वित्तीय सम्बध

जसा कहा जा चुका ह कि मघ राय म कानूनी का वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करन के लिए आर्थिक स्वायत्तता का भी व्यवस्था की जाती ह। फनन प्रत्येक सघ म कद्र और कानूनी को उनके अपन विधायी एवं कार्यपात्रिका सम्बधी कार्यों क निष्पादन के लिए अलग अलग वित्तीय प्रसाधन सौपे जात है। परतु एम सिद्धान्त का पणरूपेण पानन किसी भी सविधान म नहा हो सका है।

एस सम्बध म भारतीय सविधान म पाइ जान वाली स्थिति बहुत अधिक असन्तोषजनक है। राया को जो प्रसाधन दिए गए ह के बहुत अधिक अपर्याप्त है। जत यह व्यवस्था की गई ह कि कुछ कर एम हाग जिह सघ की सरकार नगायगी तथा जिनका संग्रह या तो सघ की सरकार करगी और या राय की सरकार और जिसस प्राप्त जाय का या ता जागिक रूप से राय का द दिया जाएगा या पूण रूप स। एमक अनिश्चित सविधान द्वारा किया गया वित्तीय प्रसाधना का वितरण न ता अंतिम ह और न अपरिवर्तनाय। सविधान रचना के समय यह व्यवस्था की गई थी कि वित्तीय प्रसाधना का वितरण उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार 1935 के अग्नियम म किया गया था। परन्तु साथ ही म यह व्यवस्था भी की गई थी कि राष्ट्रपति प्रत्येक पाँच बष क पश्चान् एक वित्त जायगा निगुक्त किया करगा जा उसे सघ और राया क बीच वित्तीय प्रसाधना क वितरण तथा सघ द्वारा राया का रिय जान वाल अनुदान क सिन्ताता क सम्बध म परामन देगा। इस प्रकार भारतीय सविधान म सघ और राया के बीच पाय जान वान आर्थिक सम्बध म एक अनाया नचकीरापन पाया जाना है जिसकी मिसान हम किसी अन्य सघीय राय म नही टियाई पडती।

प्रसाधनों का वितरण—सघ और राया क बीच आय क वितरण का उदख सातवा सूची म दृआ है और जसा कहा जा चुका है कि उसका आधार वह वितरण है जो 1935 क अग्नियम म किया गया था। एम प्रकार सघ सरकार का व सभी प्रसाधन प्रदान किय गय हैं जो सघ सूची के अंगत आत हैं तथा राया को व प्रसाधन सौपे गय है जो राय सूची म उा नमित हैं। समकनी सूची म किसी भी प्रकार क करा का प्राविधान नग है। एस वितरण क सम्बध म एक उदखनीय वान यह है कि जग राया का अपन द्वारा नगाय गये करा स प्राप्त सम्पूण आय को अपने पास रान का अधिकार है किन्तु जिन करा को लगान का अधिकार सघ

को दिया गया है, उनमें से कुछ कर ऐसे हैं जिनसे प्राप्त आय या तो पूर्णतः राज्यों को दे दी जाती है, अथवा वह उन्हें आंशिक रूप से दी जाती है। सविधान ने इस प्रकार के करों की चार विभिन्न श्रेणियाँ बतायी हैं। प्रथम श्रेणी में वे कर आते हैं जो केन्द्र की सरकार के द्वारा लगाये जाते हैं, किन्तु जिनका संग्रह राज्यों के द्वारा होता है और जिनसे प्राप्त आय को राज्य पूर्णतः अपने पास रख लेते हैं। इस प्रकार के करों में मुद्राक शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री (toilets) पर शुल्क सम्मिलित हैं। द्वितीय श्रेणी के कर वे हैं जो सघ के द्वारा आरोपित और संग्रहीत किये जाते हैं, परन्तु जिनसे प्राप्त आय को राज्यों को दे दिया जाता है। इस प्रकार के करों में कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति के उत्तराधिकार-विषयक शुल्क, कृषि भूमि से अन्य सम्पत्ति विषयक शुल्क, रेल, समुद्र अथवा वायु द्वारा ले जाये गये माल और यात्रियों पर सीमा कर, शेयर बाजार और सट्टा बाजार के सौदों पर मुद्राक शुल्क से अन्य कर आदि। तृतीय श्रेणी में आय कर आता है जिसे सघ की सरकार आरोपित भी करती है तथा संग्रहीत भी, किन्तु जिससे प्राप्त आय को सघ और राज्य दोनों के बीच बाँट दिया जाता है। चौथी श्रेणी में वे कर आते हैं जिन्हें सघ आरोपित करता है तथा जिनके संग्रह का दायित्व भी सघ सरकार के पास ही होता है, किन्तु जिनका सघ राज्यों के पास हिस्सा बाँट कर लेता है। इस प्रकार के करों में औषधि एवं प्रसाधनिक सामग्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क शामिल हैं।

अनुदान—सविधान में सघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिये जाने का भी प्राविधान पाया जाता है। सविधान की 273वीं धारा में लिखा है कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा असम के राज्यों को जूट तथा जूट-उत्पादनों के निर्यात शुल्क के बदले में सघ अनुदान देगा तथा अनुदान की राशि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जायेगी। सविधान में सघ को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह अनुसूचित कबायली क्षेत्रों में प्रशासकीय स्तर को ऊपर उठाने के लिए तथा उनके कल्याण के कार्यों को निष्पादित करने के लिए काम करे और इस सम्बन्ध में वह राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। सविधान की 275वीं धारा में इस प्रकार के अनुदान का उल्लेख है। यह संघीय सरकार का काम है कि वह इस प्रकार दिये जाने वाले अनुदानों की राशि निर्धारित करे तथा यह भी निश्चित करे कि उस राशि को किस प्रकार खर्च किया जाना है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इन अनुदानों के माध्यम से सघ को राज्यों को अपने नियन्त्रण में रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले वित्त आयोगों की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों को हस्तान्तरित किये जाने वाले वित्तीय प्रसाधनों की राशि में, जिसमें अनुदान शामिल है, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1952 में यह राशि 60 और 65 करोड़ के बीच में थी, अब यह बढ़कर 550 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

275वीं धारा के अन्तर्गत राज्यों को जो अनुदान सघ से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक राशि उन्हें अनुदान के ही रूप में 282वीं धारा के अन्तर्गत प्राप्त होती है। यह अनुदान नियोजन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को दिया जाता है। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः राज्यों को बराबर की राशि स्वयं व्यय करनी होती है। इस अनुदान के सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य एक बात यह है कि वह राज्यों को उन विषयों के ऊपर व्यय करने के लिए दिया जाता है जिनका सम्बन्ध राज्य सूची के साथ है। उदाहरण के लिए 1959-60 के बजट में 60 विषयों पर व्यय करने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 20 करोड़ रुपये सामान्य और तकनीकी शिक्षा के लिए या, 17 करोड़ की राशि सामुदायिक विकास के लिए निर्धारित की गई थी, 8 करोड़ रुपये कृषि और मत्स्य-पालन के लिए निश्चित किया गया था तथा 7.5 करोड़ रुपये की राशि मलेरिया उन्मूलन के लिए निर्धारित की गई थी। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के अनुदान के द्वारा भी सघ सरकार को राज्यों के ऊपर नियन्त्रण रखने में बड़ी सहायता मिली है।

कद्व द्वारा रायों को दिये जान वाले ऋण—मध्य और राया के बीच वित्तीय सम्बन्धों के परिचालन में कद्व द्वारा राया का लिये जान जाने वाला ऋणों का भूमिका कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ होने के पूर्व राया को मध्य द्वारा लिये जाने वाले ऋणों का कोई विनाश महत्त्व नहीं था यद्यपि यह राशि बहुत थोड़ी होती थी। उदाहरणस्वरूप 1948 से लेकर 1951 तक कुल 50 करोड़ रुपये के ऋण मध्य ने राया को सरकारों को दिये थे। परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में यह राशि बढ़कर 900 करोड़ रुपये पर पहुँच गई। अक्टूबर 1964-65 के वर्ष में राया को 690 80 करोड़ रुपये के ऋण मध्य सरकार ने दिये थे।

यह सही है कि यह बात राया की दृष्टि पर निर्भर करती है कि वह कितने ऋणों के अधीन रहे। परन्तु काल भी रायों के ऋण लेने से सरकार केवल उस स्थिति में कर सकता है जबकि वह अपने आर्थिक विकास की भी आवश्यकता का ही परिचय कर दे। स्पष्टतः ऐसा करना किमा भी रायों के लिए सम्भव नहीं हो सकता। उन वास्तविक होकर उन्हें केवल ऋण लेने पड़ते हैं और जब वह ऋण की सरकार के पास ऋण की माँग का माध्यम है तो उन्हें उसके समक्ष अपनी वह योजना भी प्रस्तुत करनी होती है जिसकी कार्यावधि के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता है। कर्तीय सरकार उनकी माँग का केवल उस स्थिति में स्वाकार कर सकती है जबकि उस उनकी योजना भी माँग है। इस प्रकार यह प्रकट है कि कर्तीय ऋणों की राया का स्वायत्तता के क्षेत्र में मध्य सरकार में हस्तान्तरण की ही अभिव्यक्ति है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक—लेखा परीक्षण की भारतीय सविधान में मध्य सरकार के एकाधिकारी क्षेत्र में रखा गया है। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए केन्द्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की व्यवस्था है तथा राया में नया परीक्षक की। परन्तु वास्तव में ये सभी अधिकारों मध्य सरकार के अधिकार हैं। रायों सरकार का उसके स्वयं लेखा का परीक्षण करने वाले अधिकारी के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का पद अधिक आर्थिक है तथा उनकी नियुक्ति राज्य राष्ट्रपति के द्वारा होती है तथा उसके कार्य करने का परिस्थितियों का निर्धारण भी संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा होता है। यह काम इस अधिकारी का है कि वह यह बताये कि मध्य तथा राया की सरकारें अपने आय व्यय के लेखों को किस प्रकार रखती और उनका यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह उनके लेखा का परीक्षण करायें।

वित्तीय सफट और राया की स्वायत्तता—सविधान की 360वीं धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय सफट की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। इस सफट की अवधि के काल में राया का मधीय करा में उनके भाग में वित्तित किया जा सकता है राष्ट्रपति रायों को यह आदेश दे सकता है कि वे अपने वित्त विनियमों का उसकी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखें तथा मध्य सरकार को किसी भी रायों की वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रित करने का निर्देश दे सकता है। समेष में वित्तीय सफट के समय राया की वित्तीय स्वायत्तता का अलंकरण के लिए पूर्णतः स्थगित रखा जा सकता है।

3 क्या भारत एक मध्य है ?

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय सविधान में मध्य को अपनी अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनके माध्यम से वह राया के आन्तरिक मामलों में बहुत सुगमतापूर्वक हस्तक्षेप कर सकता है। मध्य सरकार की इतनी अधिक शक्तियों के कारण बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को मध्य वतान का क्या औचित्य है। वस्तुतः यह प्रश्न कोई नया नहीं है उस यद्यपि उस समय भी उठाया गया था जबकि सविधान की रचना हो रही थी और उस पर सविधान मन्त्रालय विवाद भी हुआ था। सविधान सभा के कुछ सदस्यों का यह मत था कि सविधान में संघात्मक सिद्धान्त की निमनतापूर्वक हत्या की गई है। इसके विपरीत डा. अम्बेडकर का मत था कि सविधान दुहरी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है एक केंद्र में तथा दूसरी छोर पर

राज्यों में, और प्रत्येक को अपने-अपने क्षेत्र में सविधान के द्वारा सम्प्रभु शक्तियाँ प्राप्त हैं।' उनके इस दृष्टिकोण का सविधान सभा के अनेक सदस्यों ने समर्थन किया। उदाहरण के लिए श्री नेहरू ने कहा कि 'स्पष्टतः राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है।'

परन्तु इतना होते हुए भी बहुत से राजनीतिक नेताओं तथा साविधानिक विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि भारत एक सघ नहीं है। पहले के० सी० ह्वीयर के इस मत का उल्लेख किया जा चुका है जिसमें उसने यह कहा था कि भारत एक एकात्मक राज्य है, जिसमें सघात्मक तत्त्व गौण रूप से पाये जाते हैं। इसी प्रकार के दृष्टिकोण को आइवर जेनिंग्स तथा एलन ग्लैडहिल ने व्यक्त किया है कि भारतीय सविधान में जो सघात्मक तत्त्व पाये जाते हैं वे तो यथार्थ में केवल एक नकाब हैं जिनके द्वारा उनकी एकात्मकता को छिपाने का प्रयास किया गया है। के० एम० मुशी ने भी जो स्वयं प्रारूप समिति के सदस्य थे, इस मत को व्यक्त किया है कि 'भारत फेडरेशन नहीं है, अपितु वह एक यूनियन है।' कुछ दिन हुए प्रशासकीय सुधार आयोग ने सघ-राज्य सम्बन्धों का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। इस अध्ययन दल ने भी अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है—'भारत की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप सघात्मक है, किन्तु उसमें परम्परागत सघों के सार का अधिकांशतः अभाव है।'

इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि भारत में सघात्मक शासन के सभी तत्त्व पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए के० मन्थानम का मत है कि 'इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत एक सघ है।' पॉल एच० एपलबी ने भारतीय सविधान को 'अत्याधिक सघात्मक' घोषित किया है। कुछ लोगों ने भारत में एकात्मक शासन को स्थापित करने की माँग की है। इनमें सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चन्द महाजन तथा भारतीय जनसघ शामिल हैं। एकात्मक शासन को स्थापित करने की माँग से भी यह भासित होता है कि इन लोगों के मतानुसार भारत में सघात्मक व्यवस्था कायम है जिसे वे अवांछनीय मानते हैं।

ऊपर जिस विवाद को सारांश रूप में व्यक्त किया गया है, वह केवल कोई शब्दों का झगडा नहीं है। वस्तुतः उसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत मूल्यांकन सन्निहित है। अब यह आवश्यक है कि हम उन आधारों की समीक्षा करें जिन्होंने भारतीय सविधान की सघात्मकता पर एक प्रश्न-चिन्ह खड़ा कर दिया है।

इस सन्दर्भ में जो पहली बात कही जाती है वह यह है कि सविधान में 'फेडरेशन' शब्द को जान-बूझकर प्रयुक्त नहीं किया गया है और उसके स्थान पर 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया है। डा० अन्वेदकर ने सविधान सभा में 'यूनियन' शब्द के प्रयोग को लाभकारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, परन्तु उनकी व्याख्या से स्थिति तो स्पष्ट नहीं हुई, कुछ भ्रमों में अवश्य वृद्धि हो गई। इस भ्रम का एक उदाहरण हमें राज्य सभा में गोविन्द वल्लभ पन्त के उस भाषण में देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा था, 'हम एक यूनियन में रहते हैं, एक फेडरेशन में भी नहीं' (We live in a union, not even in a federation)। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'यूनियन' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, उसे सघात्मक राज्यों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है और एकात्मक राज्यों के लिए भी। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के सविधान की प्रस्तावना में 'यूनियन' शब्द के द्वारा उस देश का वर्णन किया गया है। यह बात निर्विवाद है कि संयुक्त राज्य अमरीका एक सघ है। परन्तु दूसरे छोर पर 'यूनियन' शब्द दक्षिणी अफ्रीका के राज्य के साथ भी प्रयुक्त होता है, जो निम्नन्वेद एक एकात्मक राज्य है। वस्तुतः 'यूनियन' शब्द के प्रयोग से सविधान की सघात्मकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमें इसमें अधिक बजानदार तर्कों की विवेचना करने की आवश्यकता है।

भारत के मधीय राज्य न होने के पक्ष में जो दूसरा तर्क दिया जाता है और जो पहले तर्क की अपेक्षा निश्चय ही अधिक शक्तिशाली है, वह यह है कि हमारे यहाँ केन्द्र को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उहा तर्क कि जबकि विषयों को भी केन्द्र में ही निहित कर दिया गया है। यह

तक कोई नया तक नहा है इस अनन्य बार मरिधान मभा म भा ुनराया गया था । परन्तु इस तक सम्बन्ध म भी एक बात कही जा सक्ती है कि विश्व क मभस्त मधाय मविधाना म का भा म मरिधान एस नहा है जिनम गक्तिया का विभाजन एकसा आ हा । यहा गहा ध्यान म ग्वन का बात यह भी है कि आज ममार क सभा आ म क नियकरण का प्रवृत्ति पा जाता है । इस प्रकार जय सविधाना म क नियकरण विमम की एक नया प्रक्रिया क गग सम्पन्न हुआ है । किन्तु भारत म एस मत्र कुछ नहा हुआ यहा ना क नियकरण का प्रवृत्ति का सविधान क गरा हा मायता प्रान क दा ग । वस्तुन एस हा ना स्वाभाविक भा था क्यानि भगताय राष्ट्रीय आनन का दीध कान स गक्तिया का क का स्थापित करन का न य था । यनि उसन दुव क का व्यवस्था का स्वीकार किया था ना इमनिण था नि मुस्लिम नाग का पृथक्तावाग माग क माय किमी भी प्रकार का का समझौता हा जाय । परन्तु विभाजन क पचात् म प्रकार का का अविश्यक्ता भी नहा रह गई था । जत इस नवान पृष्ठभूमि म क मुत्ता सघ की स्थापना का जा सक्ती थी ।

भारतीय सविधान म अवशिष्ट गक्तिया क का सावा ग ह परन्तु इस आधार पर भा सविधान क मयात्मक स्वरूप का चुनौती नहा दा जा सकती । ससार का का एस अताग्य न नहा है जहा म प्रसार का व्यवस्था पाइ जाना हा । कना म भा अवशिष्ट गक्तिया क म हा निहित की ग है नि तु उसम उस सबत्मक स्वरूप पर का जतर नहा आया है । यहा इस सम्बन्ध म एक उतग्वनाय बात यह है कि सविधान क इस प्राविधान म सघ की शक्ति म जभा तक का दृष्टि नहा ह । गक्तिया क वितरण की तीना सूचिया तना विग और औरवार ह नि उनम जव किमी न गक्ति का जानन का का गाम गताग नहा है । कवन सविधान क काया वयन क गगभग 24 वष हा चुक ह और इस प्राविधान का अभी तक व्यवहार म नान का आवश्यकता गहा है ।

उपयुक्त विद्वचना म स्पष्ट है कि क का अधिक गक्ति प्रदान कर न स किसा भी सविधान क मयात्मक स्वरूप नहा हा नात । यथाय म सविधानवाद का मून सिद्धांत गक्तिया का सघ और का या क वाच विभाजन है और यह विभाजन एस हा ना चाहिए जिनम सघ का सरकार अपनी वृच्छा स इकाया की गक्ति का कम न कर सक तथा सघ गव काया का सरकार प्रत्यक्ष म सविधान म स हा जवना गक्तिया प्रदान कर । सरग म सधीय सविधान म एस या की स्वायत्तता का मायता दा नाना चाहिए । यहा महत्वपूर्ण बात यह नहा है कि स्वायत्तता का क्षेत्र कितना विग अथवा कितना सामित है महत्व की बात कवन तनी है कि काया का वायत्तता किस क्षेत्र म स्वाकार की जाय क निचन हानी चाहिए । इस सम्बन्ध म अस्वरूप का सविधान सभा म यह कथन उतग्वनाय है कि जा क्षेत्र गया क पास छोटा गया ह उसम व उसी प्रकार सम्प्रभ है निम प्रकार क उस न म सम्प्रभ है जा उस सौता गया है । यह कथन ऊपर म दखन पर अनिशयाक्तिपूर्ण प्रतीत हाता है क्याकि सविधान म एस प्राविधाना का जभाव नहा है जा के को राया क आतारिक मामला म हस्तक्षप का अधिकार प्रदान करत हैं अथवा जिनस उस सकट कान म राय की सम्पूर्ण स्वायत्तता का हृप जान की क्षमता प्राप्त होती है । यहाँ उनम स कुछ प्राविधाना का उतग्व किया जा सकता है । सर्वप्रथम सविधान की तीसरी धारा का लिया जा सकता है । इस धारा म सधीय व्यवस्थापिका का गया की सीमाआ म हर-वेर करन की तथा म प्रकार नय राया की रचना का अधिकार दिया ह । सविधान का चौथी धारा म लिखा है कि इस प्रकार जो परिवर्तन किय जायेंग उह सशोधन नहा माना जायेगा । एसलिए इस प्रकार क परिवर्तना का सस क साधारण कानून क द्वारा व्यवहार म लाया जा सकता है । यह सहा है कि इस प्रकार क परिवर्तना का सस म प्रस्ताविन करा क पूव सघ की सरकार स यह जपता की ग है कि क सम्बद्ध राय जथवा राया स इस सम्बन्ध म परामग कर । परन्तु उनका परामग सघ क निय वायकारी हागा यह

कही नहीं लिखा है। सघ की ससद ने इसी शक्ति के आधार पर 1963 में आन्ध्र के राज्य की रचना की थी और आन्ध्र की रचना की प्रक्रिया में हैदराबाद के राज्य का लोप हो गया। इसी शक्ति के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्संगठन कानून (States Reorganisation Act) निर्मित किया गया था, जिसके द्वारा भारत के राजनीतिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे। पिछले वर्षों में इसी शक्ति के आधार पर नागालैण्ड राज्य की असम राज्य के पुनर्गठन के द्वारा रचना की गई, इसी प्रकार पुराने पंजाब को बाँटकर पंजाब और हरियाणा के नये राज्यों को जन्म दिया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से सविधान की तीसरी धारा ने सघ को राज्यों के जीवन और मृत्यु का निर्णय देने का अधिकार दिया है। इस धारा पर टिप्पणी करते हुए के० पी० मुखर्जी ने लिखा है कि यदि यह एकात्मक सरकार की परिभाषा नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि वह क्या है।' इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी धारा ने सघ सरकार को वह शक्ति प्रदान की है जो विश्व के किसी भी सविधान में सघ को प्राप्त नहीं है। यथार्थ में ससार के सभी सघों में जहाँ सघ की अखण्डता को कायम रखने का वचन दिया जाता है, वहाँ उनमें इकाइयों की अखण्डता को भी कायम रखने का आश्वासन दिया जाता है। अतः यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सविधान की तीसरी धारा सघात्मक सिद्धान्त के प्रतिकूल है। परन्तु इतना मानने के बाद भी यह लिखना आवश्यक है कि सविधान में तीसरी धारा को इसलिए स्थान दिया गया था क्योंकि 1950 में भारत के राजनीतिक मानचित्र को ब्रिटिश सरकार से उत्तराधिकार में प्राप्त किया गया था और यह स्पष्ट था कि साम्राज्यवाद की यह विरासत बहुत दिन नहीं चल सकती थी। यदि सविधान की रचना के समय ही इस मानचित्र में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास किया गया होता, तो उसके फलस्वरूप देश में इतना उग्र विवाद जन्म ले लेता कि उसका प्रतिकूल प्रभाव सविधान रचना पर भी पड़ता। अतः यह उचित समझा गया कि इस कार्य को अभी स्थगित कर दिया जाये तथा उसका निष्पादन सविधान द्वारा स्थापित ससद के द्वारा हो।

तीसरी धारा के अतिरिक्त भी सविधान में ऐसे अन्य प्राविधान भी हैं जिनसे साधारणतया असाधारण दोनों प्रकार की स्थितियों में राज्यों की स्वायत्तता पर आँच पहुँचती है। इन प्राविधानों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और उनके सम्बन्ध में भी इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनसे केन्द्र को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं तथा राज्यों की स्वायत्तता पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अहाँ तक 356वीं धारा के अन्तर्गत आने वाली सकटकालीन व्यवस्थाओं का, राज्यों में साविधानिक प्रणाली के असफल हो जाने वाले प्राविधानों का, प्रश्न है, कुछ बातें ध्यान में रखी जानी आवश्यक है। यद्यपि सविधान में कहा गया है कि सघ राज्यों के प्रशासन को अपने हाथों में केवल उस समय ले जबकि राज्य में सविधान के अनुसार शासन का संचालन हो ही न सकता हो तथा इस आशय का प्रतिवेदन उसके पास राज्य के गवर्नर से आया हो। परन्तु यदि केन्द्र और राज्य में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें हैं, तो उस स्थिति में केन्द्र राज्य के गवर्नर से अपनी इच्छानुसार रिपोर्ट लिखवा लेगा तथा फिर वहाँ के शासन को अपने अधिकार में ले लेगा। यह सही है कि ऐसा अभी तक बहुत कम हुआ है, परन्तु ऐसा हुआ है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 1958 में केरल में नम्बूदिरिपाद मन्त्रिमण्डल को वरखास्त कर दिया गया तथा वहाँ राष्ट्रपति शासन स्थापित किया गया। चौथे आम चुनाव के बाद अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, जिनमें हरेक को उचित नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु इसे सविधान का दोष नहीं कहा जा सकता, यह दोष तो उनका है जिनके पास सविधान को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है। स्पष्टतः ये व्यवस्थायें भी जलपकालीन हैं तथा उनमें सविधान का सघात्मक स्वरूप आवश्यक रूप से नष्ट नहीं होना। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्राविधान भारतीय सविधान की कोई अपनी अनोखी विशेषता नहीं है, उनका अनोखापन केवल इस तथ्य में

है कि यहाँ उह अथ सविधाना की अप न अधिक विगद बनाया गया है।

उपयुक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अपनी केन्द्रीय प्रवृत्तियाँ व यावज्जुद भारतीय सविधान का स्वरूप सघातक है। वस्तुतः सनाग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उनका कहना है कि सविधान की कार्यविधि में प्रसार हो रही है जो उसकी निर्माताओं की चिन्ता व सचवा प्रतिकूल है। वदुषा यह गिनायत की जाती है कि वदत हुए केन्द्रीयकरण व परिणामस्वरूप राया की स्वायत्तता में निस्सन्देह कमी आई है। उदाहरणस्वरूप टी० एम के व स्वर्गीय नेता भी जसोदोराई न इस सम्प्रदाय में अपना मत व्यक्त करते हुए एक बार कहा था कि सघीय सविधान व कायावयन में राया की शक्तियाँ व शक्ति खतरा प्रस्तुत हो रहा है तथा राया की स्थिति अब कवन खरात पान वान निगम (dole getting corporation) की रह गई है। इसी प्रकार का मत स्वतन्त्र पार्टी व नेता सा राजगापानाचारी न भी व्यक्त किया था। उनकी गिनायत थी कि राया की स्वतन्त्रता का भुनाया जा रहा है तथा समूच भारत में मिना विचार एकात्मक राय को स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार की गिनायत का मुख्य उद्गम वास्तव में राष्ट्रीय नियोजन है तथा नियोजन का क्रियाविधि में योजना आयोग की भूमिका है। समस्या व इस पन्तू पर प्रकाश डालने हुए सरतो क सिन् न जो योजना आयोग व सदस्य भी रह चुके हैं एक बार यह लिखा था— राष्ट्रीय नियोजन न केन्द्र की भूमिका में वृद्धि की है तथा उनमें केन्द्र और राया के उत्तरदायित्व व विभे की कम करने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

यह सही है कि नियोजित अथवावस्था न राय सम्बन्धों का का मुल बनाया है परन्तु इस प्रवृत्ति को जन्म देने के लिए सविधान का उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। वस्तुतः इसके लिए दो कारण उत्तरदायी हैं और उनमें से किसी एक का सविधान का अपरिचिततीय अथवा अनिवाय अंग नहीं माना जा सकता। प्रथम राया को केन्द्र से प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हानी है और न्तीय 1967 के आम चुनावों के पूर्व तक देश के कवन एक राजनीतिक दल का राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार था। यहाँ यह कहा जा सकता है कि रायो को अपनी याजनाओं को कार्यावित करने के लिए केन्द्र का मद वसति ए ताजता पता है क्योंकि सविधान न उह पर्याप्त वित्तीय प्रसाधन प्रदान किया है। यथाय में बात एसी नहीं है। राया की आर्थिक दुर्गता का एक बड़ा कारण यह है कि राया की सरकारों न राजनीतिक कारणों से प्ररित हाकर अपन यहाँ स्थित वित्तीय प्रसाधन का पूरणपण प्रयुक्त नहीं किया है और न उनमें ऐमा करने की चिन्ता पायी जाती है। इसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि व केन्द्र पर जाग्रत रह। केन्द्र से सहायता न केन्द्र व सहायता में उत्पन्न परिणामों से वचन की आगा नहीं कर सकते।

जसा कहा जा चुका है कि 1967 तक कांग्रेस का केन्द्र एवं राया की सरकारों पर सभी जगह एकाधिकार था। सन देश में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्तियों को एक बड़ी सीमा तक बढ़ावा दिया था। एक समय में एमा हाना स्वाभाविक भी था क्योंकि उस समय देश की वाग्वार राष्ट्रीय आन्दोलन व आन-पहचाने नेताओं और विगपकर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। राया के नेता पथ प्रदान एवं परामर्श के लिए उनकी ओर लखा करते थे। परन्तु 1964 में नेहरू जी के देहान्त के उपरांत स्थिति में निश्चय ही एक परिवर्तन आया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नेहरू जी और गानवहान्तर शास्त्री व उत्तराधिकारियों के चयन में राया के मुख्यमंत्रियों ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी।

नामन ही पामर न लिखा है कि स्वतन्त्रता के उपरांत भारतीय राजनीतिक जीवन के बहुत से अतविराधों में से एक अतविरोध यह है कि यहाँ केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीयकरण दोनों की शक्तियों की प्रवृत्तियों का एक साथ विकास हुआ है। जहाँ देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वान तत्त्व पाये जाते हैं वहाँ एस तत्त्वा का भी अभाव नहीं है जो देश का विघटन का आर

ले जा सकते हैं। आज भी देश के राजनीतिक जीवन में सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा भाषावाद आदि बुराइयों को अवलोकित किया जा सकता है। इन बुराइयों को देखकर बहुधा कुछ निराशावादियों ने यह सन्देह व्यक्त किया है कि कालान्तर में भारतीय सघ का विघटन हो जायेगा। उदाहरणस्वरूप पॉल एच० एपलबी ने अपने प्रतिवेदन में यह प्रश्न पूछा है 'क्या भाषायी विभाजनों तथा अपने प्रगामन के एक बड़े भाग के लिए राज्यों के ऊपर अमावारण निर्भरता की पृष्ठभूमि में भारत अपनी राष्ट्रीय एकता एवं शक्ति को कायम रखने में समर्थ हो सकेगा ?'

यहाँ इन भविष्यवाणियों की विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए केवल इस तथ्य को मान्यता देना पर्याप्त है कि भारत में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ तथा स्थानीय भावनाएँ पायी जाती हैं और राज्य इन भावनाओं के प्रतीक हैं। पिछले दिनों में इन्हीं राज्यों में केन्द्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति हुई है। यह स्वाभाविक ही है कि भारत जैसे बड़े आकार के देश में जहाँ विभिन्न भागों की ऐतिहासिक परम्पराएँ भी न केवल एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती, अपितु उनमें एक प्रकार का टकराव भी पाया जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नताएँ विकसित हो। वस्तुतः ये विभिन्नताएँ ही इस बात की सबसे बड़ी गारन्टी हैं कि यहाँ अत्यधिक केन्द्रवाद विकसित नहीं हो सकता। यदि सीमाओं का उल्लंघन करके केन्द्रवाद को विकसित करने का प्रयत्न किया गया तो इसका परिणाम राष्ट्र की एकता के लिए घातक होगा। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केन्द्र को स्थापित करने की आकांक्षा तथा क्षेत्रीय भावनाओं की अवहेलना न करने की इच्छा के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि भारतीय संविधान में अन्य मघात्मक संविधानों की तुलना में कुछ भिन्नताएँ पायी जाती। भारतीय सघ के सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उसकी रचना संयुक्त राज्य अमरीका अथवा स्विट्जरलैण्ड के संविधानों की भाँति उस समय नहीं हुई जबकि राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में निपेधात्मक वारणा पायी जाती थी। आज राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में स्वीकारात्मक विचार पाये जाते हैं और ऐसी स्थिति में यदि सघ के कार्यक्षेत्र को संविधान में व्यापक बना दिया गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नियोजन का विचार भी वास्तव में राज्य के कार्यक्षेत्र की स्वीकारात्मक वारणा के साथ सम्बद्ध है और नियोजन के कार्य में केन्द्र और राज्य दोनों ही एक प्रकार से साझीदार हैं। यह सही है कि इसमें सघ की साझीदारी अधिक है, परन्तु इसके साथ में सही यह भी है कि राज्यों के सहयोग के बिना सघ कुछ भी न कर सकने की स्थिति में होगा। इसी आधार पर कुछ लोगों ने भारतीय सघवाद को सहकारी सघवाद की संज्ञा प्रदान की है।

4 वित्त आयोग

संविधान की 280वीं धारा में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। सघात्मक प्रणाली के मिश्रान्त एवं व्यवहार में इसे भारत का मौलिक योगदान घोषित किया जा सकता है। यद्यपि 1940 में इस प्रकार के आयोग की स्थापना की मिफारिश कनाडा में की गई थी, परन्तु उसकी कभी कार्यान्विति नहीं हुई। अतः वित्त आयोग के प्राविधान को भारतीय संविधान की अपनी विशेषता समझी जानी चाहिए।

यद्यपि संविधान में सघ और राज्य के बीच पाये जाने वाले वित्तीय सम्बन्धों का व्यौरेवार वर्णन पाया जाता है तथापि संविधानकार जानते थे कि कोई भी प्रबन्ध, चाहे उसे कितनी ही सावधानी से क्यों न बनाया जाये, हर परिस्थिति के लिए सन्तोषप्रद नहीं हो सकता। अतः यह सोचा गया कि पाँच वर्ष की अवधि के उपरान्त वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और उस आयोग का यह दायित्व होना चाहिए कि वह पिछले पाँच वर्ष में दिये वित्तीय परिवर्तनों को ध्यान में रखकर सघ और राज्यों के बीच वित्तीय प्रमाणों का पुनर्वितरण करे।

संविधान की 280वीं धारा में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान के व्यवहार में जाने के दो वर्ष बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की रचना करे, यह नाम इसके बाद हर पाँच वर्ष बाद

या उसमें पूर्व दृष्टिगत जाना चाहिए। अभी धारा 8 वित्त आयोग के गठन के सम्बन्ध में यह नियम है कि उसमें एक अध्यक्ष व अनिश्चित चार सभ्य और होंगे। 1951 के वित्त आयोग अधिनियम (1955 में संशोधित) में अध्यक्ष तथा सभ्यता की योग्यताय निर्धारित की गई है। अन्य बातें लिए यह आवश्यक माना गया है कि उस सावजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए तथा सदस्यों के लिए कहा गया है कि वे (1) या तो उच्च यायालय के यायाधीन रहे चुके हों अथवा उसमें यायाधीन बनने की योग्यता हो अथवा (2) उच्च सरकार के वित्त तथा राजस्व का विनिष्ठाज्ञान हो अथवा (3) उच्च वित्तीय मामलों एवं प्रशासन के सम्बन्ध में व्यापक अनुभव हो अथवा (4) उच्च अर्थशास्त्र का विनिष्ठाज्ञान हो। यद्यपि आयोग की स्थिति कबल परामर्श देने वाला अभिकरण की है तथापि अभी तक इसके किसी परामर्श को ठुकराया नहीं गया है।

सविधान की 280 (3) धारा में वित्त आयोग के कार्य करने की निर्धारित किया गया है। उस राष्ट्रपति का तीन प्रकार की सिफारिश करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है—प्रथम धारा में प्राप्त आय तथा मध्य और राज्य के बीच किस प्रकार वितरित किया जाय द्वितीय भारत की संचित निधि में से राजस्व का कितना सिद्धांतों के आधार पर अनुदान दिया जाय और तृतीय अन्य वित्तीय प्रशासन की स्थापना के लिए राष्ट्रपति द्वारा पेश गये मामलों पर परामर्श।

जब तक ये वित्त आयोगों की रचना की जा चुकी है। पहला 1952 में स्थापित किया गया था जिसमें 1957 में तृतीय 1961 में चौथा 1965 में और पांचवा 1968 में निर्मित हुए थे। इन आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य सरकार में प्राप्त धन में से राजस्व का दिया जाने वाला हिस्सा में निरंतर वृद्धि होना लगी है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना के पूर्व राजस्व को दो भागों में बांटा जाय की 50 प्रतिशत थी जो अब यह बल्कर 75 प्रतिशत हो गई है। वित्त आयोगों की विभिन्न सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्व का विभिन्न वस्तुओं के उत्पन्न होने में भी कुछ निम्मा मिलने लगा है।

वित्त आयोगों ने अब तक जो सिफारिशें की हैं उनकी विवेचना से यह स्पष्ट है कि इन आयोगों की भूमिका सरकारों में संचालन के संचालन करने वाली है। बहुधा यह कहा जाता है कि भारतीय सविधान में पाये जाने वाले वित्तीय उपबंधों की योजना भारतीय संचालन का सामान्य प्रवृत्ति के अनुकूल ही हुई है। मध्य सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक स्थिर और गतिशील है। परंतु ऐसा मानना आवश्यक भी था और वास्तविक भी क्योंकि इसके बिना देश का नियोजित रूप में आर्थिक विकास नहीं हो सकता था। परंतु इस सम्बन्ध में सविधानकारों ने एक बात का विशेष ध्यान दिया और वह बात यह थी कि राजस्व की स्थिति राष्ट्रीय रूप से अत्यधिक दुर्जन न रहे। वित्त आयोग के प्राविधान ने इसके साथ ही साथ मध्य और राजस्व के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्धों के अध्ययन की आवश्यकता की है। इस अध्ययन के आधार पर इन सम्बन्धों में परिवर्तन किया गया है जिनमें राजस्व की स्वायत्तता का नाम पड़ चुका है।

5 क्षेत्रीय परिषदें

क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) की स्थापना 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत हुई थी। इसके पूर्व भारत में मुख्यतः तीन प्रकार के राज्य पाये जाते थे। 1956 के अधिनियम ने जहाँ राजस्व का पुनर्गठन किया वहाँ उसमें के और छह राज्यों के राज्य के बीच में विभक्तों को भी समाप्त कर दिया। चूंकि राजस्व का पुनर्गठन मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ था इसलिए कुछ क्षेत्रों में यह आश्चर्य व्यक्त की गई कि इसके कारण देश में विघटनकारी गतिविधियों का उत्पन्न होना। यह जानकर पूर्णतः निराश्वर्य भी नहीं था क्योंकि इसके पूर्व भाषा के आधार पर बहुत अधिक उग्रता हो चुकी थी। इसी पूर्णभूमि में प्रधानमंत्री नेहरू ने 21 नवम्बर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श के समय यह मुद्दा प्रस्तुत किया कि देश को चार अथवा पांच बड़े क्षेत्रों में बांटा जाय तथा हर एक क्षेत्र को एक क्षेत्रीय

परिषद् स्थापित कर दी जाये। नेहरू जी ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से देश में सामूहिक चिन्तन की आदत विकसित होगी। गोविन्दवल्लभ पन्त ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों के मूल में जो उद्देश्य सन्निहित है वह यह है कि राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाया जाये। नेहरू जी के सुझाव को सदन ने स्वीकार कर लिया। फलतः समूचा देश निम्नलिखित पाँच क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया—

(1) उत्तरी क्षेत्र—इसमें पंजाब, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश¹ के केन्द्र-शासित प्रदेश शामिल हैं। पंजाब के विभाजन के बाद इसमें हरियाणा राज्य भी शामिल कर दिया गया है।

(2) दक्षिणी क्षेत्र—इसमें आन्ध्र प्रदेश, मद्रास (अब तमिलनाडु) और केरल के राज्य शामिल हैं तथा मैसूर (अब कर्नाटक) को इसकी बैठकों में स्थायी रूप से निमन्त्रित किया जाता है।

(3) मध्य क्षेत्र—इसमें केवल दो राज्य सम्मिलित हैं—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।

(4) पूर्वी क्षेत्र—इसमें पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, नागालैण्ड² तथा मणिपुर और त्रिपुरा के केन्द्र-शासित प्रदेश शामिल हैं।

(5) पश्चिमी क्षेत्र—इसमें महाराष्ट्र, गुजरात तथा मैसूर के राज्यों को सम्मिलित किया गया है।

क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य

23 अप्रैल 1957 को उत्तरी क्षेत्र की परिषद् का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन गृह-मन्त्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए 6 बातें बतायी थी जो अग्रलिखित हैं—

(1) देश में भावनात्मक एकता की रचना करना।

(2) स्थानीय, क्षेत्रीय, भाषायी प्रवृत्तियों के विकास को रोकना।

(3) कुछ मामलों व पृथक्करण से उत्पन्न प्रभावों को दूर करने में सहायता देना ताकि पुनर्गठन, समन्वयन और आर्थिक विकास की प्रक्रियाएँ एक दूसरे के साथ मिल सकें।

(4) सघ और राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना ताकि समान हित के लिये एक-सी नीतियों को विकसित किया सके तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(5) प्रमुख विकास योजनाओं की कार्यान्विति में एक दूसरे के साथ सहयोग करना।

(6) क्षेत्रों और देश के बीच किसी प्रकार का राजनीतिक सन्तुलन स्थापित करना।

क्षेत्रीय परिषदों का संगठन

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् की रचना निम्न अधिकारियों के द्वारा होती है—(1) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय मन्त्री, (2) क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक राज्य का मुख्य मन्त्री, (3) इन राज्यों के दो अन्य मन्त्री जिन्हें वहाँ के गवर्नर ने मनोनीत किया हो, (4) क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक केन्द्र-शासित प्रदेश का एक प्रतिनिधि जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करे। क्षेत्रीय परिषद् का अध्यक्ष केन्द्रीय मन्त्री होता है। अभी तक पाँचों क्षेत्रीय परिषदों में इस पद के उत्तरदायित्वों का निष्पादन केन्द्रीय गृह-मन्त्री ने किया है। उनकी अनुपस्थिति में यह उत्तरदायित्व राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को सौंपा जाता है और वे वारी-वारी से इस पद को ग्रहण करते हैं।

¹ 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भी पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया।

² नागालैण्ड को पूर्ण राज्य का दर्जा 1962 में प्राप्त हुआ था।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् में कुछ परामर्शदाता भी होते हैं। उनमें क्षेत्र में स्थित रायों के मुख्य सचिव विकास आयुक्त तथा योजना आयोग का एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाता है। परामर्शदाताओं को परिषद् की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है परन्तु वे उनमें मतदान नहीं कर सकते। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् का अपना सचिवान्वय होता है जिसकी रचना एक सचिव तथा एक अधिकारिया और सहायक के द्वारा होती है जिन्हें परिषद् नियुक्त करना चाहें। क्षेत्र में स्थित प्रत्येक रायों का मुख्य सचिव वारी वारी में एक वर्ष के लिये क्षेत्रीय परिषद् के सचिव के कार्यों का सम्पादन करता है। संयुक्त सचिव की नियुक्ति उन अधिकारियों में से की जाती है जिनका क्षेत्र में स्थित किसी रायों के साथ सम्बन्ध नहीं है। उसकी नियुक्ति परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा होती है। सचिवान्वय का मुख्य कार्यान्वय क्षेत्रीय परिषद् के मुख्य कार्यान्वय में होता है।

क्षेत्रीय परिषद् की बैठकें सामान्यतया तीन महीने में एक बार होती हैं। इस सम्बन्ध में परिषद् की यह है कि बैठकें वारी वारी से क्षेत्र में स्थित रायों में की जायें। बैठक में निम्न उपस्थित सदस्यों के सम्मेलन के द्वारा नियंत्रित होते हैं।

क्षेत्रीय परिषद् के कार्य

क्षेत्रीय परिषदें एक किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकती हैं जिनमें क्षेत्र में सम्मिलित रायों का तथा सचिव की रचना है। ये परिषदें केवल परामर्श देने वाली संस्थाएँ हैं तथा वे मध्य सरकार तथा सम्बद्ध रायों की सरकारों को उन मामलों में परामर्श देती हैं जिन पर उन्होंने विचार किया है। सामान्यतः इन परिषदों में निम्न विषयों पर विचार किया जाता है—

(अ) आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन से सम्बद्ध क्षेत्रीय विषय।

(ब) सामाजिक विकास, मापदण्ड, जनसंख्या तथा अंतर्राष्ट्रीय यातायात से सम्बद्ध विषय।

(ग) रायों के पुनर्गठन से सम्बद्ध कार्य-मामला।

यहां क्षेत्रीय परिषद् की अभी तक की उपस्थितियों के विषय में कुछ कहना अप्रसंगिक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि इन परिषदों का सफलता कुछ ऐसी नहीं है जिनसे उनके अस्तित्व का औचित्य प्रतिपादित होता है। इन परिषदों के माध्यम से न तो रायों के बीच अथवा रायों एवं सचिव के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है और न उन तनावों का निराकरण हुआ है जिसके लिये इन परिषदों की स्थापना हुई थी। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इन परिषदों को हम पूर्णरूप से अनुपयोगी समझना चाहिये। इन परिषदों ने क्षेत्रों की सामूहिक सुगठित पुनित वित्तीय अधिकारियों के लिये सामूहिक प्रतिनिधित्व के स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सन्तुष्टि परिवर्तन के गुणोत्कर्षण (rationalisation) आदि मामलों का तय करने में कुछ सफलता अथवा प्रगति हासिल की है। परन्तु अधिकतर मामलों में ऐसे हैं जिन्हें इन परिषदों के द्वारा सुनिश्चित नहीं जा सका है।

यदि क्षेत्रीय परिषदों ने उन आशाओं को पूरा नहीं किया है जिनकी उनमें अपेक्षा की जाती थी तो उन्होंने उन आशाओं को भी सही प्रमाणित नहीं किया है जिनके भय से उनको स्थापित किया गया था। अपने आरम्भ के दिनों से ही इन परिषदों के विरुद्ध तीन प्रकार की आपत्तियाँ उभरती थीं। चूंकि इन परिषदों के साथ क्षेत्रीय सरकारों का भी सम्बद्ध रखा गया था अतः कुछ लोगो को यह आशा थी कि इनके माध्यम से क्षेत्रीय रायों के आसन्न पर अधिकारिक नियंत्रण स्थापित करके प्रयत्न करेगा। अब यह कहा गया कि क्षेत्रीय परिषदों की रचना के नियोजन की ओर एक कदम है जिसका अर्थ है रायों का स्वायत्तता में कमी। इसी मन का जो भी भी गिरि ने भी 1956 में व्यक्त किया था तथा उन्होंने उन्हें भविष्य में स्थापित होने वाले एकमात्र रायों की ओर कन्म बताया था। 'सक' विपरीत कुछ हमारे लोगो का कहना है कि क्षेत्रीय समितियाँ न रायों के बीच सहयोग का माध्यम बनने की बजाय उनके बीच सघर्षों और तनावों को जन्म दिया है। वस्तुतः इन दोनों दृष्टिकोणों के साथ

सहमत होना कठिन है। इनके सम्बन्ध में गोविन्दवल्लभ पन्त ने सही कहा था कि वे केवल 'अन्तर्राज्यीय फोरम' हैं जिनसे न तो केन्द्र की शक्ति पर आँच आती है और न राज्यों की।

6 भारतीय सघ और चौथा आम चुनाव

ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय सघ में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को जन्म देने में दो कारणों की विशेष भूमिका रही है—केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा एक दल के हाथ में समूची राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार। मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू के देहान्त के उपरान्त स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया तथा जैसा कहा जा चुका है 1964 में नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज के काम में तथा इसी प्रकार 1966 में लालबहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी की खोज में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। वस्तुतः नेहरू के अन्तिम दिनों में ही देश के राजनीतिक जीवन में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी थी। जैसा माइकल ब्रेकर ने लिखा है—'नेहरू के अन्तिम दिनों में ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण आरम्भ हो गया था। इस सम्बन्ध में उत्तराधिकार ने तो केवल इतना किया कि उसने राज्यों के बढ़ते हुए प्रभाव की प्रवृत्ति को सामने ला खड़ा कर दिया।' यथार्थ में नेहरू के अन्तिम दिनों में अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों की ऐसी अनेक समस्याएँ थी जिनका समाधान नहीं हो सका था। अतः यह स्वाभाविक ही था नेहरू जैसे व्यक्तित्व के उठ जाने के बाद यह समस्या और भी अधिक उग्र होती। चौथे आम चुनाव के पूर्व 1966 में भूतपूर्व एटोनी जनरल एम० सी० सीतलवाड ने कहा था कि 'केन्द्र दुर्बल हो गया है। शक्ति-सन्तुलन अब खिसक कर राज्यों के पास पहुँच गया है।' ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि चौथे आम चुनाव में यह प्रवृत्ति खुलकर सामने आती। इस चुनाव में राजनीतिक सत्ता पर एक दल का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की, सामान्यतः मिली-जुली सरकारें स्थापित हुईं। स्वतन्त्रता के पश्चात् यथार्थ में यह पहला अवसर था जबकि केन्द्र को एक साथ विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों का सामना करना पड़ा था। वस्तुतः इसे भारतीय सघवाद के लिए परीक्षा का पहला अवसर घोषित किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में यह अनिवार्य था कि बल सविधान के सघात्मक पहलुओं पर दिया जाता जिनकी एकदलीय प्रभुत्व के काल में उपेक्षा की गई थी।

आरम्भ में नयी गैर-कांग्रेसी सरकारों को इस बारे में सन्देह था कि केन्द्र उन्हें वाँछित सहयोग प्रदान करेगा तथा सघ-राज्य सम्बन्धों के नये ढाँचे को विकसित करने के लिये उनके साथ निबाहने का प्रयत्न करेगा। अतः यह स्वाभाविक था कि राज्यों के नये नेता केन्द्रीयकरण का विरोध करते तथा राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता की माँग करते। सत्ता में आने के फौरन बाद मद्रास के डी० एम० के० के मुख्य मन्त्री स्वर्गीय अन्नादोराई ने केन्द्रीयकरण के विरुद्ध सघर्ष करने के अपने निश्चय की घोषणा की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्री पी० सुन्दरैया ने केन्द्र की इकाइयों पर हावी रहने की शक्तियों के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन का आह्वान किया। केरल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन दिया जिसमें यह माँग की गई कि केन्द्र-राज्य सघटन की स्थापना की जाय जो केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक सम्बन्धों के परिचालन में राष्ट्रीय फोरम की भूमिका अदा करे। इस ज्ञापन में यह सुझाव भी दिया गया कि राज्यों के वित्तीय प्रसाधनों में और वृद्धि की जाय। 'राज्यों की स्वायत्तता' विषय पर हुई एक विचार-गोष्ठी में भाषण करते हुए अन्नादोराई ने कहा कि 'केन्द्र की शक्ति राज्यों की शक्ति में निहित है और उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि उस शक्ति को राज्यों में विकेंद्रित किया जाय जिन पर आज केन्द्र का अधिकार है।' 'केन्द्र को अपने पास केवल उतनी शक्ति रखनी चाहिए जिससे कि वह राष्ट्र की अखण्डता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा कर सके, उसे जेप शक्ति राज्यों को दे देनी चाहिये।' इसी बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए सुन्दरैया ने 'राज्यों के लिये पूर्ण स्वायत्तता' की माँग की और कहा कि 'केन्द्र को केवल प्रतिरक्षा और पर-राष्ट्र विषयक मामलों

पर नियंत्रण रमना चाहिये। नवम्बर 1971 में एक प्रस्ताव के द्वारा मास्सराणी कम्युनिस्ट पार्टी के पोपिन्गूरा ने राय्या के नियंत्रण अधिकार का भी मांग की है।

यही यह उल्लेखनीय है कि राय्या के नियंत्रण अधिकार स्वायत्तता की मांग करने वालों की दृष्टि से हा नहा है उसमें अथवा दूर भी शामिल नहीं। 1967 में जो धर्म के कार्यक्रमों मुख्य मंत्री द्वारा राज्य में कहा था कि क्षेत्र और राय्या के बीच वित्तीय प्रसाधन का अधिक उचित वितरण होना चाहिये। अर्थात् नतीजा सन्त फर्दिमिह ने भी राय्या को अधिक शक्ति दिये जाने की मांग का समर्थन किया ताकि राय्या के प्रशासन में कृषि का प्रभाव हस्तगत हो जा सके। यही तर्क कि जनसमूह ने भी राय्या और क्षेत्र के बीच वित्तीय प्रसाधन के पुनर्वितरण की आवश्यकता का अनुभव किया है।

सब और राय्या के बीच तनाव की अभिव्यक्ति करने राज्य के द्वारा होकर समाप्त हो गई है ऐसा मान नहीं है। वस्तुतः चौथे चुनाव के बाद उद्घाटन रूप में भी प्रकट किया गया। उदाहरण के लिये करन के मंत्रिमण्डल ने कृषि संचालन में नियुक्त अपने यहां कृषि विभाग की पूर्व गतिविधियों के मामलों में पुनः नए जॉब करान के काम में सहयोग करने से इंकार कर दिया। अतः पश्चात् 19 सितम्बर 1968 का जब कृषि मंत्रालय के कमचारियों ने हस्तान्तरण की ताकत की सरकार ने हस्तान्तरण का सामना करने के काम में क्षेत्र के साथ सहयोग करने से इंकार कर दिया। यही नहीं उसने कुछ दिन बाद उन सभी व्यक्तियों के विनाश चलाये जाने के मुकदमों को वापिस ले लिया जिन्हें उस हस्तान्तरण के सिनसिन में गिरफ्तार किया गया था।

उपरोक्त घटनाक्रमों में तमिलनाडु की सरकार ने 1970 में पी. वी. राजमन्जार की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति उस उद्देश्य से नियुक्त की कि वह क्षेत्र और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों की जांच करे और वह यह सुझावे दे कि भारत में लोकतन्त्र का शक्तिशाली बनाने के लिए उन सम्प्रदायों में सुधार करने की आवश्यकता है। इस समिति की सिफारिश निम्नलिखित थी—

(1) प्रधानमंत्री का अध्यक्षता में समस्त राय्या के मुख्य अधिकारों की एक अन्तर्गत व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। उस परिपक्ष में स्वीकृति के बिना कार्य भी ऐसा विधायक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जिसमें राय्या के अधिकारों पर आंच आती हो।

(2) जायज योजना आयोग को विधायित्व देना चाहिए तथा उसमें स्थान पर ऐसे मण्डल की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विज्ञान तकनीक कृषि तथा अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हों। यह विधान राय्या को योजना के सम्बन्ध में परामर्श दे। प्रत्येक राय्या में भी इस प्रकार के योजनामण्डल होना चाहिए।

(3) निम्न आयोग एक स्थायी अभिकरण होना चाहिए तथा क्षेत्रों को राय्या का पर्याप्त मात्रा में वित्तीय प्रसाधन सौंपना चाहिए ताकि राय्या क्षेत्र पर अधिक आश्रित न रहे।

(4) सभी और सम्भवतः सूचना में से कुछ विषयों का राज्य सूची में स्थानांतरित कर देना चाहिए।

(5) राज्यपाल की नियुक्ति राज्य मंत्रिमण्डल के परामर्श से होनी चाहिए अथवा इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना होनी चाहिए तथा जो शक्ति एवं वास्तविकता पर काम कर चुका है उसे इसी बार किसी अन्य सम्बन्धी पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सविधान में इस आयोग का संशोधन किया जाना चाहिए जिसमें राय्याओं के लिए एक प्रकार की आचार संहिता बनाया जा सके। सविधान की 164वां धारा को जिसमें लिखा है कि मंत्री राज्यपाल के प्रस्तावों पर काम कर सकते हैं सविधान से निकाल देना चाहिए।

(6) राय्या के अधिकारों में जान बान विषयों से सम्बद्ध मुकदमों में राज्य का उच्च न्यायालय सर्वोच्च होना चाहिए। परन्तु वे विवाद जिनका सम्बन्ध सविधान के निश्चय के साथ है सर्वोच्च न्यायालय में भेज जा सकते हैं।

यदि राज्यों ने केन्द्र के विरुद्ध विरोध का भण्डा बुलन्द किया था, तो केन्द्र ने भी अनावश्यक रूप से राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। उदाहरणस्वरूप उसने वगाल और पंजाब में कानून द्वारा स्थापित सरकारों को तोड़कर अपनी कठपुतली सरकारों को कायम किया। केन्द्र से यह पाकर इन राज्यों के गवर्नरों ने जो भूमिका अदा की वह निश्चय ही वैसी नहीं थी जैसी कि राज्य के साविधानिक अध्यक्ष की होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सघ और राज्य के बीच तनाव को जन्म देने में दोनों ने अपना-अपना योगदान दिया था। कुछ क्षेत्रों में इस तनाव का अन्त करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि देश से सघीय शासन-प्रणाली को समाप्त करके एकात्मक शासन पद्धति को कायम कर देना चाहिए। इस प्रकार के मत को व्यक्त करने वालों में भारतीय जनसघ प्रमुख है। किन्तु यथार्थ में यह निराशावादी दृष्टिकोण है और यह सौभाग्य की बात है कि देश के बहुसंख्यक लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में यह दृष्टिकोण इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि भारत जैसे विशाल एवं विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों के देश में सघवाद का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। एकात्मक शासन-प्रणाली से क्षेत्रीय भावनाओं का निराकरण नहीं हो सकता। सच बात तो यह है कि भारत में राज्यों की स्वायत्तता को मानकर ही राष्ट्रीय एकता को सम्भव बनाया जा सकता है। साथ ही, राज्यों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपनी स्वायत्तता को अतिरिक्त रूप में न जताएँ। यथार्थ में केन्द्र और राज्य दोनों के नेताओं की बुद्धिमत्ता इस बात को देखने में है कि उनमें से कोई भी अपने-अपने अधिकारों का दावा इस सीमा तक न करे जिससे राष्ट्र की एकता के लिए ही खतरा उत्पन्न हो जाये।

प्रश्न

1. ह्वीयर के मत का परीक्षण कीजिये कि भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक संविधान है जिसमें सघात्मक तत्त्व गौण रूप से पाये जाते हैं।
2. भारतीय संविधान में केन्द्र और राज्यों के विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय सम्बन्धों को निर्धारित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?
3. क्षेत्रीय परिपदों पर एक निबन्ध लिखिए।

साविधानिक सशोधन और उसकी प्रक्रिया (THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT AND ITS PROCESS)

यहाँ जा चुका है कि संविधानकारों ने देश की निम्न सघीय संविधान की व्यवस्था की थी। सघीय संविधानों का एक आवश्यक गुण उनकी दृढ़ता (rigidity) को माना गया है परन्तु भारतीय संविधानकारों का यह आरम्भ से ही मत था कि उनके देश का संविधान संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का भाँति इस मध्य में होना चाहिए। यथायथ म वे ऐसा संविधान निर्मित करना चाहते थे जिसमें दृढ़ता (rigid) और सुगम (flexible) दोनों प्रकार के संविधानों का सम्मिश्रण हो। ऐसा करने का कारण यह था कि जहाँ यह आवश्यक था कि संविधान का राजनैतिक दृष्टि से होना चाहिए वहाँ भी अपेक्षा थी कि उसमें विकास का अवसर भी दिया जाय। हम मध्य में संविधान सभा में नहरेजी के भाषण का यह अंग उद्धरणिय है—जहाँ हम चाहते हैं कि यह संविधान नया ठोस और स्थायी होना चाहिए जितना वह हो सकता है वहाँ हम यह भी समझना चाहिए कि संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता। उसमें एक मात्रा में परिवर्तन भी होना चाहिए। यदि आप सच जानें तो कठोर और स्थायी बना देंगे तो आप राष्ट्र की जीवन प्रक्रियाएँ एवं अवयवों की जनता का विश्राम राक्ष देंगे। हम किसी भी स्थिति में इस संविधान का कठोर नहीं बनाना चाहिए कि वह चट्टानी हो परिस्थितियों के अनुसार अपने आपका न हो सके। वस्तुतः यह जाना जा रहा है कि यह दृष्टिकोण साविधानिक सिद्धांत की आधुनिकतम मान्यताओं में से एक माना जा रहा है। उदाहरण के लिए मुल्फोर्ड (Mulford) ने लिखा है—संशोधन न होने वाला संविधान समय का सबसे बड़ा अत्याचार है। इसी प्रकार मुनरो (W B Munro) ने भी लिखा है—संशोधन न होने वाला संविधान की उत्पत्ति असम्भव है यथायथ यह एक अतिविरोधाभासी युक्त मान्यता है। भारतीय संविधानकारों में तब से भी भाँति अलग है कि उनका यह निश्चित मत था कि संविधान की प्रक्रिया ही यथायथ संविधानों की दृढ़ता को परिस्थितियों की चर्चों का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। फलतः संविधान की 368वाँ धारा (20वाँ अध्याय) में उहाँ ने इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है।

यहाँ यह कहना अप्रासंगिक होगा कि भारतीय संविधान के इस पहलू पर विश्व में मतभेद का अभाव है। यदि कुछ विद्वानों का उसमें दुसरा मत है तो ही तत्त्व दृष्टिकोण से ही तो कुछ दूसरे विद्वानों ने उसमें सुगमता का अवलोकन किया है। उदाहरणार्थ जेनिंग्स (Ivor Jennings) का मत है कि भारतीय संविधान एक सुगम संविधान है। अपने मत के समर्थन में जेनिंग्स ने दो तर्क प्रस्तुत किए हैं। प्रथम संविधान के संशोधन की विधि साधारण कानून बनाने की विधि की अपेक्षा भिन्न है तथा द्वितीय संविधानों का आकार बतलाना है जिससे परिणामस्वरूप उसमें संशोधन की गति में ही बहुत कम देर रह गई है। परन्तु दूसरी तरफ एलेक्जेंड्रोविच (Alexandrowics) जैसा तर्क भी है कि भारतीय संविधान पर सुगमता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सच बात यह है कि भारतीय संविधान में सुगमता के दावा को कम करने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु संविधान में ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि आपातकाल में जिना किसी संशोधन के सघातक राज्य की एकात्मक राज्य में परिवर्तित कर लिया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के किसी अन्य सघीय संविधान में नहीं है।

सशोधन की प्रक्रिया

सविधान की 368वीं धारा में सशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है। इसके अनुसार ससद विधेयक के रूप में सविधान में सशोधन को प्रस्तावित कर सकती है और यह विधेयक उसके किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को पारित करने के लिए सविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम, उसके पारित होने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि ससद के दोनों सदन उसे अलग-अलग एक ही रूप में अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार करें तथा इस विधेयक पर मतदान करने वालों की सख्या प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्य-सख्या का बहुमत होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि सशोधन के पारित होने के लिए लोकसभा में कम से कम 263 सदस्यों तथा राज्य सभा के 119 सदस्यों का समर्थन अत्यन्त आवश्यक है। दूसरे, ससद द्वारा उपर्युक्त विधि से पारित होने के उपरान्त विधेयक को राष्ट्रपति के सन्मुख उसकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी कार्यान्विति केवल उसी समय हो सकेगी जबकि उसे राष्ट्रपति भी स्वीकार करले। सामान्यतः सशोधन के सम्बन्ध में इसी प्रक्रिया को व्यवहार में लाया जाता है, परन्तु सविधान में कुछ भागों को सशोधित करने के लिये यह आवश्यक माना गया है कि उसे कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जिन साविधानिक व्यवस्थाओं को सशोधित करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को आवश्यक बताया गया है, वे निम्नलिखित हैं—

- (1) राष्ट्रपति को चुनने वाला निर्वाचक मण्डल (अनुच्छेद 54)
- (2) राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 55)
- (3) सघ एवं राज्यों की कार्यशालिका सत्ता का विस्तार (अनुच्छेद 72 व 162)
- (4) सघ शामिन प्रदेश के उच्च-न्यायालय (241वाँ अनुच्छेद)
- (5) सर्वोच्च न्यायालय से सम्बद्ध अध्याय (5वें भाग का चौथा अध्याय)
- (6) राज्यों के उच्च-न्यायालय (छठे भाग का 5वाँ अध्याय)
- (7) सघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति वितरण (11वें भाग का पहला अध्याय)
- (8) सातवीं अनुसूची में उल्लिखित शक्तियों की सूची,
- (9) ससद के दोनों सदनों में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तथा
- (10) 368वाँ अनुच्छेद।

जिन सशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, उन्हें राष्ट्रपति के सन्मुख उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें राज्यों के विधानमण्डलों के द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

सविधान में सशोधन के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया के साथ ही उसकी कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें सशोधित करने के लिए केवल ससद द्वारा पारित साधारण कानून को ही पर्याप्त माना गया है। ऐसे प्राविधानों में नये राज्य की रचना, प्रचलित राज्यों का पुनर्गठन तथा राज्यों के द्वितीय सदनों का उन्मूलन आदि शामिल हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में सविधान को सशोधित करने के लिए तीन प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं। प्रथम, सविधान के ऐसे प्राविधान हैं जिन्हें सशोधित करने के लिए ससद के बहुमतयुक्त उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। द्वितीय, कुछ ऐसे प्राविधान हैं जिनमें सशोधन करने के लिए ससद के समर्थन के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। तृतीय, सविधान की कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएँ हैं जिन्हें ससद अपने साधारण बहुमत में ही बदल सकती है।

सशोधन की प्रक्रिया की आलोचना

सविधान में सशोधन की उपर्युक्त प्रक्रियाओं की देव के विभिन्न क्षेत्रों में आलोचना की

यह है। इस सम्बन्ध में पहली आपत्ति यह रही जाती है कि हमारा समाज सभाधन के मामलों में जनता की दृष्टि का जानने का प्रयत्न न करना समाजपूर्ण है तथा उस पर कबल ससद का एकाधिकार स्थापित करना जिसका भी दृष्टि में उचित नग्न है। जानाचका का यह भी कहना है कि इस सम्बन्ध में जनता का विचार में नग्न ससिण और भी अधिक आवश्यक था क्योंकि यहाँ सविधान के निमाण में समय भी जनता की दृष्टि का जानने का प्रयत्न नग्न किया गया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमरीका संविधान तथा जापानिया आदि देशों में सभाधन का पारित करने में जनमत-संग्रह को व्यवस्था की गयी। भारत में इस व्यवस्था की अनुराधित को लागू करना कहा जा सकता है। वस्तुतः हम जानाचका का औचित्य समझिए और भी अधिक है क्योंकि हमारा समाज सत्ता मुख्यतः अभी तक एक ही स्तर पर हाथा में रही है। यही दृष्टि दृष्टि के सविधान का रचना भी की थी। यथायत्न हम कबल में एक स्तर माना में सत्य पाया जाता है कि आधुनिक सविधान संग्रह में का सविधान है।

सविधान की इस व्यवस्था पर भी जानाचका ने आपत्ति व्यक्त की है कि सभाधन के विधायन का कबल उम्मीदमय कार्याचार किया जाय जबकि उसे राष्ट्रपति का भी स्वीकृति प्राप्त हो जाय। यह जानाचका सत्तान्तिक भी है और राजनीतिक भी। विचार में सम्भवतः कोई भी ऐसा ऐसा नहीं है जहाँ सांविधानिक शक्तियाँ की जनता जयवा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रतिरिक्त किसी अन्य अभिव्यक्ति में निहित किया गया है। वस्तुतः हम शक्ति का कार्याचयन उम्मीद करता है कि चाहे तब हम किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु भारत में इस सिद्धांत का यथार्थ माना में सम्मान प्रदान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ सविधान के द्वारा प्राप्त करता है तथा उस यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह सविधान के प्रस्ताव को कानूनी रूप भी प्रदान करे। निम्न यह व्यवस्था अत्यन्त अमाधारण है। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रपति सभ संस्कार का एक अधिकारी है। यद्यपि उसने निर्वाचन में रायों के विधानमण्डल के सदस्य भी भाग लेते हैं। सविधान में राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह अपने मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर काम करे। यदि रायों के विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत किसी सभाधन के प्रस्ताव का कानूनी मंत्रिमण्डल के परामर्श पर राष्ट्रपति अस्वीकार कर दे तो उस समय सभात्मक व्यवस्था तथा रायों की स्वायत्तता के लिए निम्न यह एक खतरा पैदा हो जाएगा। इस आपत्ति के विरोध में आयरलैंड तथा वर्मा के सविधानों का उदाहरण दिया जा सकता है जहाँ हम प्रसार की व्यवस्था पाते पाते हैं। इन देशों में यह प्रावधान कबल एक औपचारिकता है जो हम आचार पर कुछ नहीं है यह मत व्यक्त किया है कि भारत में भी राष्ट्रपति की इस शक्ति का औपचारिकता ही समझा जाना चाहिए। परन्तु इस दृष्टिकोण के साथ सभी विविधास्तो महसूस यह है

कतिपय विचारों ने इस बात की भी जानाचका की है कि सविधान में कुछ क्षेत्र ऐसे निश्चित कर लिये गये हैं जिनमें सभाधन करने के लिए रायों के विधानमण्डल की स्वीकृति आवश्यक मानी गयी है। स्पष्टतः इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य सविधान के मधीय स्वरूप को कायम रखना था और इसलिए जिन क्षेत्रों को सभद की एकाधिकारी शक्तियों से मुक्त रखा गया है वे हैं जिनमें रायों की अधिकतम शक्ति हो सकती है। फिर इस क्षेत्र में दृष्टि की समुची शायिक प्रणाली का स्थान दिया गया है क्योंकि शायिकता की विधायन की शायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है और इसलिए सभद द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे रायों के लिए कठिनाई अथवा परेशानी पदा हो। सिद्धांत रूप में सविधान के इस वर्गीकरण से किसी का शायिकता हो सकती है कि उसका कुछ भाग बहुत अधिक मौनिक है तथा कुछ कम मौनिक। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि सविधान के कबल उम्मीद भागों को अधिक मौनिक माना जाना चाहिए जिनका उम्मीद सविधान के सबसे भाग में हुआ है। वस्तुतः सविधान के कुछ अन्य भाग भी हैं जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सविधान के

छूटे भाग को लिया जा सकता है जिसमें राज्यों की साविधानिक व्यवस्था का उल्लेख है अथवा तेरहवें भाग को लिया जा सकता है जिसमें अन्तर्राज्यीय के व्यापार संचार आदि का उल्लेख है। इसी प्रकार सविधान के 18वें अध्याय (मकटकालीन व्यवस्थाएँ) अथवा तीसरे अध्याय (मूल-अधिकार) को भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। निम्नान्वेह सविधान की इन सभी व्यवस्थाओं में राज्यों के विधानमण्डलों की स्वाभाविक रुचि है और उनको सशोषित करने का समद का एकाधिकार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अनुभव साक्षी है कि पिछले वर्षों में सविधान की इन कमियों के कारण केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा हुआ है।

साविधानिक सशोधन

सविधान का समारम्भ 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तबसे लेकर अब तक 24 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच में 32 सशोधन पारित हो चुके हैं और कुछ समद के विचाराधीन हैं। यहाँ इन सशोधनों का सक्षिप्त उल्लेख अप्रासंगिक न होगा।

पहला सशोधन 1951 में पारित हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 10, 19 और 61 को सशोधित किया गया था, तथा सविधान में दो नये अनुच्छेद 31 (अ) और 51 (ब) तथा एक नवीन अनुसूची—नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। इन सशोधनों की आवश्यकता इसलिए हुई थी क्योंकि राज्यों के उच्च-न्यायालयों ने तथा सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिये थे जो सरकार के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते थे। इस सशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19 में स्वतन्त्रता के अधिकार के प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार के हित में अथवा न्यायालय के अपमान अथवा अपराध को उकसाने पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 31 (अ) के अनुसार, राज्य का कोई भी ऐसा कानून जो राज्य द्वारा किसी भी जमींदारी अथवा भूमि पर अधिकारों को अर्जित करने वाला हो, इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह इस भाग में वर्णित अधिकारों का उल्लंघन करता है। 31 (ब) में यह व्यवस्था की गई है कि नवी अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को अवैध नहीं ठहराया जायेगा। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी कानूनों का उल्लेख है।

दूसरा सशोधन 1952 में पारित हुआ। इसके अनुसार अनुच्छेद 81 को सशोधित किया गया। इस अनुच्छेद में लोकसभा के निर्वाचन की विधि दी गई है। चूँकि इस सशोधन का प्रभाव लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ता था, अतः उसकी पुष्टि राज्यों के द्वारा कराई गई।

तीसरा सशोधन 1954 में समवर्ती सूची के 33वें स्थान को इस प्रकार किया गया जिससे केन्द्रीय सरकार का समद द्वारा पारित कानून की स्थिति में सभी प्रकार के उद्योग-धन्वों, खाद्यान्नों, पशुओं के आहार, कपास और जूट पर नियन्त्रण स्थापित हो सके।

चौथा सशोधन 1955 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 के खण्ड 6 के स्थान पर यह खण्ड रखा गया है—‘कोई भी सम्पत्ति अनिवार्य रूप से सिवाय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित न की जायेगी और न सिवाय ऐसे कानून द्वारा जो सम्पत्ति के अर्जन के लिए प्रतिकर (Compensation) की व्यवस्था करे और जो या तो प्रतिकर की राशि नियत करे अथवा उन सिद्धान्तों तथा तरीकों को स्पष्ट करे जिनके द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया जायेगा तथा दिया जायेगा और ऐसे किसी भी कानून के विरुद्ध किसी न्यायालय में इस आधार पर कोई कार्यवाही न की जा सकेगी कि उसके द्वारा प्रतिकर की व्यवस्था अपर्याप्त है।’

पाँचवाँ सशोधन भी 1955 में ही पारित हुआ। उसके अनुसार अनुच्छेद 3 के इस उपबन्ध में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी विवेक समद के किसी भी समद में राष्ट्रपति

की पूव विचारणा के बिना प्रस्तुत न किया जा सकना और यदि ऐसा विषयक का सम्बन्ध स्वामित्वा राया की सीमाओं व नामों से हुआ है तो राष्ट्रपति को उस पर सम्बद्ध राय अथवा राया के विधानमण्डल के मन का जानना अनिवार्य होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्याय सभा के पत्रस्वरूप ही राया के पुनर्गठन का कार्य निश्चित अवधि के भीतर सम्पन्न हो सकेगा।

छठा संशोधन 1956 के द्वारा मातृसूची के 92 अंग के उपरांत 92 (अ) जाना गया है जो इस प्रकार है—समाचार-पत्रों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों की प्रिंटी और खरीद पर कर जहाँ कि ऐसी प्रिंटी और खरीद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा वाणिज्य के सम्बन्ध में है। इस संशोधन को ध्यान में रखकर राय सूची के अंग 54 में भी अपभ्रंश परिवर्तन किया गया है।

सातवा संशोधन भी 1956 में पारित किया गया तथा उससे द्वारा राया के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अनेक परिवर्तन किये गए। इस परिवर्तन को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम सविधान का प्रथम अनुसूची में परिवर्तित करके विभिन्न पुनर्गठित राया की सीमाओं का उल्लेख किया गया है तथा सघीय क्षेत्रों की सीमाओं को भी बताया गया है। द्वितीय सम्बद्ध अनुसूची में परिवर्तित करके चौथी अनुसूची में विभिन्न राया के राय सभा में प्रतिनिधियों की संख्या में आवश्यक परिवर्तन किये गए हैं। इस पुनर्वितरण के पत्रस्वरूप जब राय सभा का कुल सभ्य संख्या 220 हो गई है। तमो प्रकार लोकसभा की रचना में भी आवश्यक परिवर्तन किये गए हैं। इस ही परिवर्तन विभिन्न राया की विधान सभाओं की संस्य संख्या उनके उच्च न्यायालय के संगठन तथा अधिकार तब जादि के सम्बन्ध में हैं। भाग 7 के राया के स्थान पर सघीय क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी अनुसूची 229 एवं 240 में आवश्यक परिवर्तन किये गए हैं। इस संशोधन के द्वारा अनुसूची 258 के बाद अनुसूची 258 (अ) जोड़ा गया है जो इस प्रकार है—सविधान में अन्य व्यवस्था के रहते हुए किसी राय का गवर्नर भारत सरकार का सहमति से भारत सरकार अथवा उसके अधिकारियों को मन सहित अथवा रहित किसी भी एक मामला में कार्य सौंप सकता है जाकि राय की कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्र में जाता है। इस संशोधन के पत्रस्वरूप राय प्रमुखा की व्यवस्था का सर्व के लिए अंत कर दिया गया।

आठवा संशोधन 1959 में पारित हुआ। इसके द्वारा अनुसूची 534 को समाहित किया गया है। जिसके पत्रस्वरूप अनुसूचित जातियाँ व जनजातियाँ एवं आगम भारतीयों के लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था आगामों दस वर्षों के लिए बना दी गई।

नवा संशोधन 1960 के अनुसार सविधान की प्रथम अनुसूची में नसलिए परिवर्तन किया गया जिससे 1958 में भारत व पाकिस्तान की सरकारों के बीच जो समझौता हुआ था उसके अनुसार भारत के कुछ क्षेत्रों को मुगलतापूर्वक पाकिस्तान को हस्तांतरित किया जा सके।

दसवा संशोधन 1961 में दादरा और नागर हवेली को पुनर्गठनी अधिपत्य से मुक्त कराने की पृष्ठभूमि में पारित किया गया। इसके अनुसार इन क्षेत्रों का भारत के साथ एकीकरण किया गया और उसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा बनाय गया विनियमों के अधीन रखा गया।

ग्यारहवा संशोधन 1961 के अनुसार उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मण्डल के निर्माण हेतु समद के नाना सदनों की वरक की आवश्यकता नहीं रही। तमो संशोधन के द्वारा अनुसूची 61 में यह परिवर्तन हुआ है कि राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव का इस आधार पर चुनौती न दी जायगी कि निर्वाचन में चुनाव के समय कोई स्थान रिक्त था।

बारहवा संशोधन 1961 के द्वारा गोआ, डामन और डयू की भारतीय संघ में एक इकाई के रूप में स्थान दिया गया और उन्हें सातवा सघीय क्षेत्र बनाया गया।

सत्रहवा संशोधन 1962 के द्वारा नागालैण्ड (सोनहवा राय) की रचना हुई और उसने नागालैण्ड के लिए कुछ विशिष्ट रक्षण की व्यवस्था की। इस संशोधन के द्वारा नागालैण्ड के गवर्नर को भी कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंप गये हैं।

चौदहवाँ सशोधन 1962 के द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, गोआ, डामन और ड्यू तथा पाण्डिचेरी में 'ग' भाग के राज्यों के अनुरूप विधानमण्डलों तथा मन्त्रि-परिषदों की व्यवस्था की गई तथा इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई।

पन्द्रहवाँ सशोधन 1963 के द्वारा राज्यों के उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए केवल एक ही बार जांच की जायेगी।

सोलहवाँ सशोधन 1963 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की गई, जिसमें कि वे ऐसी सभी कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध लगा सकें जिनका उद्देश्य देश की एकता को खण्डित करना हो तथा वे राजनीतिक दलों द्वारा भारतीय संघ से पृथक् होने को चुनाव का प्रश्न बनाने की भी मनाही कर सकती हैं। इस सशोधन के द्वारा 19वें अनुच्छेद में भी इस आगम का परिवर्तन किया गया है जिससे पृथक्तावादी प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।

सत्रहवाँ सशोधन 1964 में पारित किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 31 (अ) में सम्पत्ति (estate) शब्द को और अधिक व्यापक बना दिया गया तथा नवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को स्थान दे दिया गया है।

अठारहवाँ सशोधन 1966 में पारित हुआ, और उसके अनुसार पंजाब और हरियाणा के दो राज्यों की तथा चण्डीगढ़ के संघीय क्षेत्र की रचना की व्यवस्था की गई है।

उन्नीसवाँ सशोधन 1966 में पारित हुआ। उसके अनुसार अनुच्छेद 324 (1) में से इन शब्दों को निकाल दिया गया—'संसद अथवा राज्य विधान मण्डलों के निर्वाचनों के अथवा उनसे सम्बद्ध सन्देहों एवं विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरणों (Election Tribunals) की नियुक्ति समेत।' इसके पारित होने के उपरान्त चुनाव याचिकाओं की सुनवाई सीधे उच्च-न्यायालयों में होगी तथा याचिकादाताओं को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा।

वीसवें सशोधन 1966 ने उन न्यायिक पदाधिकारियों की, जिनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित घोषित कर दी गई थी, नियुक्तियों, तैनातियों, तबादलों और उनके द्वारा रिये गये निर्णयों, आज्ञापत्रों, सजाओं एवं अन्य आदेशों को वैध कर दिया।

इक्कीसवाँ सशोधन 1966 के द्वारा सिन्धी भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

बाइसवाँ सशोधन 1966 ने निर्वाचन सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन किये जिनसे निर्वाचन अधिकरणों का अन्त।

तेईसवाँ सशोधन 1969 में पारित हुआ जिसके द्वारा अनुमोचित जातियों एवं जनजातियों के लिये लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में आरक्षण तथा लोकसभा व राज्यों की विधान सभाओं में नामजदगी द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को 10 वर्ष आगे 1980 तक के लिये बढ़ा दिया गया। इस सशोधन में इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नागालैण्ड राज्य के लिये नहीं की गई है। साथ ही में इसके प्राविधान के अनुसार किसी भी राज्य में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक से अधिक प्रतिनिधि को मनोनीत नहीं किया जायेगा।

सविधान में 24वाँ सशोधन 1970 में प्रस्तुत किया गया, परन्तु वह पारित नहीं हो सका। इस सम्बन्ध पुराने नरेशों के विशेषाधिकारों तथा उनके प्रिवी पर्सों (Privy Purses) के उन्मूलन करने के साथ था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1969 में कांग्रेस दल में फूट पड़ चुकी थी तथा कांग्रेस का वह भाग जो मिण्टीकेट के नाम से जाना जाता था इस नावधानिक सशोधन के विरुद्ध था। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि देश के अन्य सभी दक्षिणपन्थी दल इस सशोधन के विरोध में थे। फलतः वह राज्य सभा में अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत को प्राप्त

करन में अममय रखा। यही उद्देश्यहीन बात यह भी कि 1967 में गांधीजी के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसका अनुसार समस्त जो मंत्रिगण के तामर अध्याय को महाधिन करने की शक्ति में वृद्धि कर दिया गया था। फलतः न्यायिक भाषा की मर्यादा अतः समाजवादी वादों का पूरा करने में अतः जाय का अममय पा रहा था। इसीलिए उद्देश्य राष्ट्रपति को तामरभा का भंग करने तथा नव चुनाव करवाने का परामर्श दिया। ये चुनाव फरवरी 1971 में हुए। अतः चुनाव घोषणापत्र में न्यायिक भाषा के नवत्व का भी वाक्य न यह कहा कि वह अतः जाय वाक्य का तात्पर्य करने के लिए मंत्रिगण में जायक महाधिन होगी। चुनाव में वाक्य का 518 के मन्त्र में 350 स्थानों पर मर्यादा प्राप्त है। निम्नलिखित वाक्य मर्यादा का अभिव्यक्ति की शक्ति का जनता सर्वोच्च न्यायालय के विद्वत् निर्णय में सन्तुष्ट नहीं थी। इस पृष्ठभूमि में 24वें और 25वें महाधिन का पारित किया गया।

चौथीसवाँ महाधिन जिसका चुनाव 1971 में प्रस्तुत किया गया और जगत् 1971 में वह समस्त के तामर मन्त्रों के तामर जायक वृद्धि में स पारित कर दिया गया। इसका अनुसार समस्त का तामर अध्याय समस्त समूह मंत्रिगण की शक्ति प्राप्त का गई। इस उद्देश्य का शक्ति के नियम विधान को 368वाँ धारा में जायक परिवर्तन किया गया है। इस महाधिन के तामर 368वें अनुच्छेद के तामर में परिवर्तन किया गया है। सहायक तामर या मंत्रिगण का महाधिन करने का प्रक्रिया अतः समस्त स्थान पर जो तामर प्रयुक्त किया गया है वह यह है—मंत्रिगण का तथा समस्त प्रक्रिया का महाधिन करने की समस्त की शक्ति।

इस महाधिन के तामर 13वाँ धारा में भी जायक परिवर्तन किया गया है। 13वाँ धारा में समस्त प्रयोजन तामर विधानमण्डल का मंत्रिगण के तामर अध्याय के प्रतिकूल कानून न बनाने का निर्णय दिया गया था। इस महाधिन में यह व्यवस्था की गई है कि महाधिन 368वाँ धारा के अधिन निमित्त महाधिन का 13वाँ धारा के प्रतिकूल नहीं उद्देश्य जा सकता। इसका प्रतिकूल इस महाधिन के तामर 368वें अनुच्छेद में एक दूसरा व्यवस्था जायक गया जिसका अनुसार यह व्यवस्था का गत कि समस्त मंत्रिगण के तामर भाग का इस अनुच्छेद में उद्देश्य प्रक्रिया के अधिन परिवर्तन कर सकती है अतः समस्त तामर मर्यादा है। इस महाधिन में यह भी व्यवस्था की गई कि जब तक विधानमण्डल के तामर मन्त्रों के द्वारा पारित होने के उपरान्त राष्ट्रपति के समस्त स्वाधिन के लिए प्रस्तुत किया जाय ता वह उस स्वाधिन प्रदान करने के लिए वाज्य होगा।

पचौसवाँ महाधिन भी 1971 में पारित हुआ। इसका अनुसार अनुच्छेद 31 (2) में प्रयुक्त मुआवजा तामर दिया गया तथा समस्त स्थान पर राशि (amount) तामर प्रयोग किया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था का गत है कि यदि राशि किमा सावधानी उद्देश्य की शक्ति के लिए किमा सम्पत्ति का अपन अधिकार में तामर चाहता अनुच्छेद 19 (1) (F) में सम्पत्ति प्राविधान तामर का एसा करने में शक्ति तामर सहेगा। इसके अनिवार्य इस महाधिन के तामर मंत्रिगण में एक नए अनुच्छेद 31 (C) का जोड़ा गया है जिसका अनुसार यदि कोई कानून 39 (B) और (C) में निहित भावि निष्पन्न सिद्धांतों को वाक्यावृत्ति करने के लिए बनाया जाए और समस्त इस जायक का घोषणा कर दी गई हो तो समस्त कानून को तामर जायक पर जायक घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका तामर मंत्रिगण की 14 19 और 31 धाराओं का उद्देश्य होता है। यदि इस प्रकार का कानून तामर विधानमण्डल तामर बताया गया है तो समस्त का वाक्यावृत्ति तामर उस समय हा सहेगी जबकि उस राष्ट्रपति के स्वीकृति प्राप्त हो जाय।

छत्तीसवाँ महाधिन 1971 के द्वारा भूतपद नरों के प्रिबी वर्सा का समाप्त किया गया है।

सत्तासर्वे महाधिन के तामर दण्ड के पूर्वी सामाजिक तामर को पुनर्गठित किया गया है। इस प्रकार मणालुर त्रिपुरा मन्त्रालय और जलानन्द के नव तामर की रचना हुई है तथा मिजोरम का एक नया कानून गामित प्रदान वाक्य किया गया है।

अठाइसवें सशोधन 1971 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा सम्पूर्ण देश में न करके देश के किसी एक भाग में कर सकता है।

उनतीसवें सशोधन 1972 के द्वारा अनुच्छेद 31 में ऐसा प्रावधान किया गया जिसके अन्तर्गत कृषि भूमि सुधार कानूनों के अन्तर्गत जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करके सम्बन्धी राज्य सरकारों के कानूनों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक कृषि-भूमि का अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में प्रतिकर के रूप में उसकी धनराशि को बाजार भाव पर न देने की व्यवस्था थी। परन्तु केरल भूमि सुधार अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त इसे वापिस ले लिया गया।

तीसवाँ सशोधन 1972 का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी विवादों की अपील मुनने के कार्यभार को हल्का करना था। इसमें यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित धनराशि (ग्रीम हजार रुपये) से अधिक वाले विवादों में निर्णय दे दिये जाने पर उनके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का आधार केवल निर्धारित धनराशि में अधिक का विवाद होना ही नहीं होगा, अतः अपील तभी की जा सकेगी जबकि उच्च-न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है अथवा उसमें सविधान का निर्वचन अन्तर्ग्रस्त है इसलिए अपील की जा सकती है।

इकतीसवाँ सशोधन भी 1972 में पारित हुआ। इसके अनुसार अनुच्छेद 314 को निरस्त करके स्वतन्त्रता से पूर्व चले आये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को प्राप्त विशेष अधिकारों तथा सेवा गतों के सरक्षणों को समाप्त कर दिया गया।

वत्तीसवाँ सशोधन 1973 में पारित हुआ। इसके अनुसार लोकसभा की सदस्य-संख्या 525 में बढ़ाकर 545 कर दी गई, इनमें 525 सदस्य राज्यों से चुनकर आयेगे तथा सघीय क्षेत्रों से 20। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि परिमिशन आयोग (Delimitation Commission) द्वारा सीटों में किये गये हेर-फेर के फलस्वरूप राज्यों को जो अभी तक सीटें प्राप्त हैं उनमें कोई कमी नहीं आयेगी। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि उसके प्रावधान नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल तथा मिजोरम पर लागू नहीं होंगे।

तैंतीसवाँ सशोधन विधेयक तथा 34वाँ सशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। तैंतीसवें सशोधन विधेयक का उद्देश्य विधानमण्डलों में सदस्यों द्वारा दल-बदल को नियन्त्रित करना है।

चौत्तीसवाँ सशोधन विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक विधानमण्डलों के सदस्यों से त्याग-पत्र लेने को अप्रभावी बनाना है।

प्रश्न

- 1 भारतीय संविधान में उल्लिखित सशोधन की प्रक्रिया की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये।
- 2 चौत्तीसवें और पच्चीसवें सशोधन पर एक निबन्ध लिखिये।

मताधिकार एवं निर्वाचन (FRANCHISE AND ELECTION)

1. मताधिकार

समारक सभी देशों में नागरिकों की व्यवस्था के परिचालन के लिए व्यापक नागरिक मताधिकार गुण मनुष्यता तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की पद्धति को आवश्यक माना गया है। इस दृष्टि से भारत में समारक निम्नलिखित समय तक नोकराज है। सावधान की व्यवस्था है कि प्रत्येक भारतीय को चाहिए वह स्त्री हो या पुरुष यदि उसकी आयु 21 या उससे अधिक है तो वह मतदान में भाग ले सकता है बशर्त कि उन लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया है जिन्होंने किसी निर्वाचन क्षेत्र में निश्चित अवधि तक निवास न किया हो अथवा जिसका विभाग खराब हो अथवा जो किसी धर्म अथवा धर्म समुदाय में किसी प्राधान्य के द्वारा दण्डित हो चुका हो। ब्रिटिश शासन काल में मताधिकार के ऊपर अनेक प्रतिबंध थे। सविधान ने एक ही बार में इन सभी प्रतिबंधों का अंत कर दिया है। संविधान का यह कर्म कितना क्रांतिकारी था इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1935 के संविधान के अंतर्गत केवल 3 करोड़ 50 लाख भारतीयों का मताधिकार प्राप्त था आज इनकी संख्या 25 करोड़ पर पहुँच गई है। इस प्रकार देश के लगभग 50 प्रतिशत नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। यदि हम यह बात ध्यान में रखें कि भारत के अधिकांश निर्वाचन निरक्षर हैं तथा उन नागरिकों की प्रक्रियाओं का कार्य अनुभव नहीं है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि देश के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान करने का निश्चय एक क्रांतिकारी कर्म था। प्रथम आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने अपने प्रतिवेदन में संविधान सभा में कहा था कि यह निश्चय भारत के साधारण व्यक्ति में तथा उनकी पारिवारिक बुद्धि में विश्वास का परिचायक है।

जिस समय मताधिकार का प्रश्न संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत था उस समय कुछ लोग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि भारत में यह परीक्षण खतरनाक सिद्ध होगा। उनका कहना था कि राजनीतिक नेता लोगों के अज्ञान का लाभ उठावगे और इस प्रकार देश में अधिनायकत्व के नियम मान प्रवेश होगा। कुछ दूसरे लोग का कहना था कि इतने व्यापक मताधिकार का पारिवारिक रूप देने में अनेक कठिनाइयाँ प्रस्तुत होंगी। परंतु संविधान सभा ने इन आपत्तियों का जवाब देकर कहा कि इस प्रकार के लोगों की उत्तर देने में संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था— मैं इससे भयभीत नहीं हूँ। मैं गांधी के लोग को जानता हूँ जो अपने व्यापक निर्वाचन मण्डल के बहुमत की रचना करते हैं। मेरी राय में हमारे लोगों के पास विवेक एवं सामान्य बुद्धि है। उनके पास संस्कृति भी है जिसे मिथ्या सभ्यता में विश्वास करने वाले आपस में समझ नहीं सकते परंतु जो ठास है। उनमें वह क्षमता भी है जिससे वे अपने तथा देश के हितों में यदि वे उनकी समझा लिये जायें रुचि ले सकते हैं।

प्रश्न है कि क्या संविधानकारों ने भारत के निर्वाचकों में जिस विश्वास को व्यक्त किया था वह पिछले चुनावों के अनुभव से सही प्रमाणित हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर प्रायः दो प्रकार से दिया जाता है। पहला उत्तर मुख्य चुनाव आयुक्त मंत्री ने 1969 में एक भाषण में दिया था। उन्होंने कहा था— जमा मेरा अनुभव रहा है मतदाता की धन की प्रतीति लिये

जा सकता है, वह किसी प्रत्याशी के वाहनो में लाया और ले जाया जा सकता है, परन्तु इन सुविधाओं को प्रयोग में लाने के बाद भी उसे उस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने में सकोच नहीं होगा जिसे वह अच्छा समझता है।' दूसरा मत एम० सी० छागला का है, उन्होंने भी एक भाषण में अपने अनुभव के ही आधार पर यह कहा था कि वालिग मताधिकार एक ऐसी नेकी है जिसका महत्त्व अतिरिक्त करके बताया गया है। उन्होंने कहा कि उससे देश में 'सम्प्रदायवाद एवं विरादरीवाद की जड़े मजबूत हुई हैं। ऐसे औसत विधायकों का उदय हुआ है जिनमें सत्ता के लिए भूख है तथा जिन्हें केवल निजी स्वार्थों को पूरा करने की लालसा है।' वस्तुतः उपर्युक्त दोनों उत्तर सही हैं। यदि यहाँ के निर्वाचकों ने सम्प्रदायवाद एवं विरादरीवाद के दृष्टिकोणों से प्रेरित होकर मतदान किया है तो उन्होंने देश के सन्मुख प्रस्तुत राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं को समझने का भी प्रयास किया है और उन्होंने उस राजनीतिक दल को अपना मत दिया है जो उनके मतानुसार उन समस्याओं का सन्तोषजनक उत्तर दे सकता था।

व्यापक मताधिकार के साथ, हमारे सविधान ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धान्त को भी मान्यता प्रदान की है। सविधान समान निर्वाचन-क्षेत्रों की भी व्यवस्था करता है, वास्तव में सविधान के इस प्राविधान को 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धान्त का पूरक ही माना जाता चाहिए। सविधान ने साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों का अन्त करके उस आधार को नष्ट करने की तरफ एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद में पृथक्ता के तत्त्वों को पनपाया था। इसका आशय यह कदापि नहीं है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों अथवा पिछड़े हुए लोगों के प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं है। सविधान में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के लिए आम प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं परन्तु सविधान की यह व्यवस्था अल्पकालिक है। सविधान के 331वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को ऐंग्लो-इंडियनों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया है। सविधान की यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं है।

2 निर्वाचन

लोकतन्त्र के सफल परिचालन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था की जाय। अतः चुनाव के मामले में कोई भी अनुचित रूप से दबाव न डाल सके इसे सम्भव बनाने के लिए सविधान में एक स्वतन्त्र अभिकरण की व्यवस्था की गई है जिसे चुनाव आयोग का नाम दिया गया है। इस आयोग को ससद, राज्यों के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन व नियन्त्रण, निर्वाचित सूचियों को तैयार कराने और निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के निर्णय कराने आदि के उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। चुनाव आयोग को परामर्शदात्री कार्य भी सौंपे गये हैं। सविधान के 103वें अनुच्छेद के अनुसार आयोग राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को क्रमशः ससद एवं राज्य विधानमण्डलों की नियोग्यताओं से सम्बद्ध किसी भी प्रश्न पर अपना परामर्श देगा।

सविधान ने आयोग को एक स्वतन्त्र अभिकरण के रूप में स्थापित किया है। अतः उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से मुक्त रखने के लिए सविधान के 324वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को। परन्तु जबकि न्यायाधीश 64 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, मुख्य आयुक्त की नियुक्ति किसी भी सीमित अवधि के लिए की जा सकती है।

चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो उसका अध्यक्ष होता है तथा अन्य आयुक्त हो सकते हैं, जिनकी मर्यादित समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जायेगी। इन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ससद द्वारा विहित नियमों के अन्तर्गत करता है। राज्य विधानमण्डलों

क निराचना में आयाग की महायन्त्रा के लिए चुनाव आयाग के परामर्श में राष्ट्रपति प्रा निर आयुक्त (Regional Commissioner) भी नियुक्त कर सता है। इन आयुक्ता की अधिक और सेवा की गतें भी राष्ट्रपति नियम बनाकर निर्धारित करता है। परन्तु यह आवश्यक है कि वे सत्तर गारा निर्मित कानूना के अनुसार हों।

दूसरा चुनाव की व्यवस्था करने लिए समस्त राज्या कानूना का निर्मित किया है। वे हैं—जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 (People's Representation Act 1950) और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 (People's Representation Act 1951)। इन कानूना के द्वारा मतदाताओं की मायताय निश्चित की जाती है मतदान सूचिया का रचना की जाती है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जाता है समस्त राज्या विधानमण्डलों की सम्पूर्ण समस्या को निर्धारित किया जाता है निर्वाचना का प्रबंध एवं संचालन का प्रणामनिक व्यवस्था का करने होता है निर्वाचन विभाग का निर्वाह तथा उप चुनावों का व्यवस्था का जाती है। पिछले 20 वर्षों में इन कानूना तथा उनसे जनगत निर्मित नियमों में आवश्यकानुसार संशोधन किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य चुनावों का विरोधता को रचना करना है तथा चुनावों में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करना है। यदि इस भ्रष्टाचार को रोकने में हम सफलता नहीं मिलता तो उस स्थिति में हमारे चुनाव एक तमाशा मात्र रह जायेंगे। वस्तुतः चुनावों का विरोधता को रचना का समस्या ने भारतीय नागरिकों के समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया है। हमारे देश में कबल वागम मतदान के उदाहरण पाये जाते हैं परन्तु चुनावों में मतदानों का रक्षण धमकान तथा उन्हें प्रत्येक मतदान के पर रोक जान के उदाहरण भी कम नहीं हैं। इन दुर्घटनाओं का रोकने के लिए देश में उपाय किया गया है। उदाहरण के लिए वागम मतदान के अवसर समाप्त करने के लिए कुछ दिन पूर्व प्रतिपक्ष (counter foil) मन्त्रि मतदानों की एक नवीन व्यवस्था का प्रयोग आरम्भ किया गया था। मतदानों का प्रत्येक मतदान के पर जान से रोकने की प्रथा को बन्द करने के लिए चयन किरन वाग मतदान केन्द्रों (mobile polling booths) का आरम्भ किया गया है। समस्त अथवा विधानमण्डलों के लिए चुनावों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की चुनाव याचिका कानून द्वारा निर्धारित ढंग में उपयुक्त अधिकारी को दी जाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभी तक राज्या के विधानमण्डलों में निराचना के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया है। जनता की चुनाव पद्धति का पूर्ण निर्धारण समस्त राज्या निर्मित कानूना के द्वारा ही होता है।

निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन—चुनावों का निष्पक्ष एवं चयन रूप से आयोजित करने के लिये यह परमावश्यक है कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन वायव्य ढंग में किया जाय। संसिदि 377व अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त किया गया कि वह समस्त राज्या विधानमण्डलों में निर्वाचना के लिए कानून के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का व्यवस्था करे। पहले आम चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का व्यवस्था करने के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जाय के द्वारा किया गया था। यह आरम्भ समस्त के अनुमानों के बाद ही कार्यान्वित हो सकता था। जब जब उस समय के समुदाय प्रस्तुत किया गया तो उसने उसमें जनसंशोधन किया। इन संशोधनों के सम्बन्ध में यह निरायत थी कि समस्त राज्या किया गया संशोधन दत्तगत हितकोण से अनुप्राणित थे। 1952 के चुनावों के लिये की गई यह व्यवस्था सत्तापजनक प्रमाणित नहीं हुई। इस सम्बन्ध में चुनाव आयाग ने अपने प्रतिपक्ष में कहा कि यह प्रक्रिया उचित सत्तापजनक अथवा सुचारु रूप से नहीं चली। फलतः आयाग ने इस काम के निष्पक्ष के लिए एक स्वतंत्र अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की। फलतः समस्त के 1952 में सीमांकन आयाग अधिनियम 1952 (Delimitation Commission Act 1952) पारित किया। इस अधिनियम में यह प्राविधान है कि दस वर्ष के उपरान्त प्रत्येक जनगणना के साथ निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिये। इस आयाग में तीन सम्पूर्ण होते हैं जिनमें दो सर्वोच्च यायायिक अथवा उच्च यायायिक के अवकाश प्राप्त यायायिक होते हैं तथा तीसरा सम्पूर्ण मुख्य चुनाव

आयुक्त होता है। इस आयोग की सहायता के लिये प्रत्येक राज्य से दो या सात सहायक सदस्यों का प्राविधान है। ये सहायक सदस्य सम्बद्ध राज्य से लोकसभा के लिये अथवा राज्य विधान-मण्डलो के लिये निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। इस प्रकार इस आयोग की रचना में प्रत्येक राज्य तथा मुख्य राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। निर्वाचन-क्षेत्रों के सीमांकन के लिये जिस प्रक्रिया को विहित किया गया है, उसमें इस बात की व्यवस्था है कि जनता के लोग व्यक्तिगत रूप से अथवा सांगठनिक रूप से आयोग के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियाँ अथवा सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इन आपत्तियों तथा सुझावों पर सार्वजनिक बैठकों में विचार आवश्यक माना गया है। इसके उपरान्त ही आयोग सीमांकन आदेश की घोषणा करता है, जो अन्तिम होता है तथा जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

3 निर्वाचनतन्त्र और निर्वाचन प्रक्रिया

चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण काम विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है। प्रथम आम चुनाव के बाद आयोग ने इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक कसौटी तैयार की। इसके अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में केवल उस दल को मान्यता दी जा सकती थी जिसने सदन के चुनाव में कुल डाले गये मतों के कम से कम 3 प्रतिशत मत प्राप्त किये हों। इसी प्रकार राज्यीय दल के रूप में उस राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त हो सकती थी जिसको विधानसभा के लिये कुल डाले गये मतों का 3 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हों। इस प्रकार उस समय केवल 4 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। वे दल थे—कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनसंघ। इनके अतिरिक्त उसने 19 दलों को राज्यीय दलों के रूप में स्वीकार किया। तीसरे आम चुनाव के लिये चुनाव आयोग ने देश एवं राज्यों में विभिन्न दलों की स्थिति पर पुनर्विचार किया। इस प्रकार आयोग ने आरक्षित चुनाव-चिन्ह प्रदान करने के लिये लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में 16 दलों को मान्यता प्रदान की।

चुनाव आयोग को जो दूसरा काम सौंपा गया है वह है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव-चिन्ह प्रदान करना। आयोग का यह काम निस्सन्देह महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव-चिन्ह के प्रश्न पर दो राजनीतिक दलों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस स्थिति में आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से न्यायिक ढंग से विधान का निबटारा करने का प्रयास करेगा। 1971 के लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के अवसर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा संगठन कांग्रेस के बीच अविभाजित कांग्रेस के चुनाव-चिन्ह दो दलों की जोड़ी पर विवाद उत्पन्न हो गया था। चुनाव आयोग ने अपना निर्णय सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में दिया तथा अपने निर्णय के समर्थन में उन्होंने बहुमत के नियम को तर्क के रूप में प्रस्तुत किया। संगठन कांग्रेस ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णय की कार्यन्विति को रोक दिया, परन्तु बाद में जब उसने इस विवाद में अपना अन्तिम निर्णय दिया तो उसने भी चुनाव आयुक्त के फैसले को दुहराया।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त चुनाव आयोग को कुछ अन्य काम सौंपे गये हैं। वे निम्न-लिखित हैं—(1) राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव भाषणों की सुविधाये दिलवाना, (2) राजनीतिक दलों के लिये आचार संहिता को निर्मित करना, (3) प्रत्याशियों द्वारा कुल व्यय की राशि को निर्वाचित करना, (4) मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, (5) निर्वाचन याचिकाओं (Election Petitions) आदि के सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। इनके अतिरिक्त आयोग से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर सरकार को अपने कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन भेजता रहेगा तथा चुनाव-प्रक्रिया को अधिक सुचारु बनाने के लिये सुझाव देता रहेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया का जारम्भ उस सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में होना है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की 14वां धारा के अन्तर्गत जारी की जाती है तथा उस वर्तमान गणसभा की अवधि की समाप्ति पर ही जारी किया जा सकता है। विधान सभा के निर्वाचन के नियम इस आशय की अधिसूचना राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। इसके उपरान्त चुनाव आयोग मतदान की तिथियाँ की घोषणा करता है। इस घोषणा का निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जा सकता है। इस घोषणा में नामजदगी पत्रों की गणना की तिथि चुनाव संधि से नाम वापिस लेने की तिथि और मतदान की तिथि सभी का उल्लेख होता है। प्रत्यागियों को 1966 के उपरान्त चुनाव अभियान के नियम कथन 20 तिन दिख जाते हैं। आयोग का मत है कि यह कानून 15 तिन किया जा सकता है।

4 निर्वाचन-पद्धति में सुधारों की समस्या

यद्यपि भारत में चुनावों की पद्धति का यथासम्भव निर्दोष बनाने का प्रयास किया गया है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश में चुनावों की पद्धति के विरुद्ध कोई शिकायत की गजा नहीं है। वस्तुतः पिछले वर्षों में इस सम्बन्ध में मसद तथा उसके बाहर अनेक बार चर्चा की जा चुकी है। चुनाव पद्धति से सम्बन्धित पहला प्रश्न जिसने गणना का ध्यान आकर्षित किया है मतदान की आयु के साथ जुटा हुआ है। संविधान का प्राविधान है कि प्रत्येक भारतवासी जिसकी आयु 21 वर्ष है मतदान में भाग ले सकता है। इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिये। इस सुझाव का कुछ लोग न विरोध किया है। इन लोगों ने अनेक विरोध के समर्थन में मुख्यतः दो तर्क प्रस्तुत किये हैं। उनका पहला तर्क यह है कि मतदान की आयु को घटा देने का परिणामस्वरूप मतदाता सूची में लगभग 5 करोड़ लोगों की वृद्धि हो जायेगी फलतः चुनाव के व्यय में भी वृद्धि होगी। अतः प्रशासन में मित-ययिता होने के लिये यह आवश्यक है कि इस कदम को न उठाया जाय। इस सम्बन्ध में जो दूसरा तर्क दिया गया है वह यह है कि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों और नारियाँ में वांछित मानसिक परिपक्वता का अभाव होता है अतः यह मताधिकार उनको दे दिया गया तो उसके परिणाम देश के लिये भयंकर हानि।

निर्वाचन से सम्बन्धित एक दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिये? भारत के सदन में यह प्रश्न इसलिये प्रासंगिक है क्योंकि अभी तक पांच आम चुनाव जो हा चुके हैं उनमें मतदान ऐसा नहीं हुआ जिसे से नापजरू किया जा सके। जीतते अभी तक मतदान का प्रतिशत 45 और 48 के बीच में रहा है। मतदान का यह ग़ुन प्रतिगत हो जाता का द्योतक है प्रथम यह कि भारतीय मतदाता को देश में नाकतांत्रिक प्रणाली में काम करने के लिये से असन्तोष है दूसरे भारत में नाकतांत्रिक चेतना का जनमानस में अपनी जड़ों को जमान में अभी तक सफ़रता प्राप्त नहीं हो सकी है। उपर्युक्त दोनों स्थितियाँ दोस्ताने की सफ़रता के लिये ग़ुन नहीं कहा जा सकता। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि नाकतांत्रिक प्रक्रिया का परिचालन इस प्रकार हो जिससे देश के अधिकाधिक निर्वाचक उसमें भाग ले सकें। इस दृष्टिकोण में कुछ तिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस पी सेन वर्मा ने निम्नलिखित मतदान का सुझाव दिया था।

यदि चुनावों में जनता ख़ुशरू बनी सत्या में भाग लेने लगे तो उसके कुछ निश्चित एवं स्पष्ट लाभ होंगे। इससे परिणामस्वरूप नाकतंत्र की जनसाधारण की सक्रिय रूचि में गहरी जड़ जायेगी और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रतिशत भी बढ़ेगा फिर से ग़ौरव लगेगी। इसका एक दूसरा नतीजा यह भी होगा कि धूल और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के राजनीति को उस प्रकार निर्धारित नहीं कर पायेंगे जमा कि वह आज कर रहे हैं। यदि प्रत्येक मतदाता मतदान-केन्द्र पर जाने लगे तो चुनाव में भ्रष्टाचार की सम्भावना भी स्वतः मर्यादित हो जायेगी। धनी प्रयोगी घूस दानर कुछ मतदाताओं के बाट खरीद सकते हैं। परन्तु वे समूचे निर्वाचकों के मत खरीद सकें इसकी कोई सम्भावना नहीं है। इस सम्बन्ध में अंतिम बात यह है कि इससे देश में देश-वन्दन की

रोक-थाम की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाये जा सकेंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों की साझेदारी की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न है कि क्या इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मतदाता को मतदान केन्द्र पर आने के लिए विवश किया जा सकता है ?

मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस प्रकार की बाध्यता को आरोपित करने को उचित ठहराया है। अपने मन के समर्थन में उन्होंने कुछ ऐसे देशों के नाम गिनाये हैं जहाँ उन नागरिकों को दण्डित किया जाता है जो जान-बूझकर मतदान करने नहीं जाते। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मताधिकार का प्रयोग न करने वालों को जुर्माना देना होता है। चिली में ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सकता है। इन देशों का हवाला देकर सेन वर्मा ने कहा है कि भारत में भी मताधिकार के प्रयोग न करने को दण्डनीय अपराध घोषित किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि ससद को इस प्रकार के कानून को निमित्त करने की शक्ति सविधान के 327वें अनुच्छेद के अन्तर्गत प्राप्त है।

वस्तुतः यह सुझाव इस मान्यता पर आधारित है कि मताधिकार केवल अधिकार नहीं है, वह एक कर्तव्य भी है। अतः यदि कोई नागरिक अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसे इसके लिए बाध्य किया जा सकता है और इससे उसकी स्वतन्त्रता के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस तर्क में निहित सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसके साथ ही इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि मतदान को अनिवार्य बना देने से वांछित फल की प्राप्ति नहीं की जा सकती।

भारतीय निर्वाचन-पद्धति के विरुद्ध एक शिकायत यह भी की गयी है कि उसमें बहुधा उस दल को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए सम्भव हो जाता है क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से जिस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है, उसे अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा सबसे अधिक मत मिले होते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या अन्य पराजित उम्मीदवारों को प्राप्त मतों के योग से अधिक हो। 1952, 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस को प्राप्त मत क्रमशः 44 99, 47 67, 44 73 और 40 82 थे, परन्तु उसे प्रथम तीन चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए थे, जबकि चौथे चुनाव में स्थानों की संख्या घटकर 53 प्रतिशत के लगभग आ गयी थी। 1971 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने मद्रास राज्य में लोकसभा के 41 स्थानों के लिए कुल डाले गये वोटों का 45 26 प्रतिशत प्राप्त किया और उसे 30 स्थान मिले, परन्तु 1967 के चुनाव में उसे केवल तीन स्थान प्राप्त हुए, यद्यपि उसे प्राप्त मतों में केवल 4 प्रतिशत की कमी हुई।

अतः भारतीय निर्वाचन-पद्धति की इस असंगति को दूर करने के लिए पिछले वर्षों में कुछ क्षेत्रों से यह सुझाव आया कि देश में सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को शुरू किया जाना चाहिए। परन्तु यह सुझाव सामान्यतः लोगों को मान्य नहीं है। इसके विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह है कि वह विधानमण्डल में राजनीतिक दलों की बहुलता को जन्म देता है। भारत में यह बीमारी पहले से ही मौजूद है और यदि इस प्रणाली का सूत्रपात कर दिया गया तो रोग के और अधिक बढ़ने की सम्भावना है। आजकन भी चुनाव आयोग के पास 75 राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह बात बुद्धिसंगत नहीं है कि इस पद्धति को देश में अपनाया जाये।

भारतीय निर्वाचनों के सम्बन्ध में एक आम शिकायत उसमें होने वाले वॉक्ली और वेईमानी को लेकर की जाती है। स्वयं चुनाव आयोग ने इस शिकायत के औचित्य को स्वीकार किया है। 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में निर्वाचन से सम्बद्ध भ्रष्ट आचरण में निम्न बातें गिनायी गयी थी—धूस, अनुचित दवाव, धर्म, मूलवश, जाति अथवा भाषा के आधार पर किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करना, अथवा किसी प्रत्याशी को वोट न देने को अपील करना, भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच धर्म, सम्प्रदाय, विरादगी तथा भाषा के

आधार पर तनाव पना करना तथा चुनाव में निर्वाचित राशि से अधिक धन खर्च करना। वही कानून में यह व्यवस्था भी की गया है कि चुनाव याचिका में उभरे प्रमाणित हो जाने पर निर्वाचित उम्मादवार का निर्वाचन निरस्त हो जाता है।

— भारत में जाति के साथ धर्म का घना दामन का साथ रहा है। जहाँ यह स्वाभाविक ही है कि जाति एवं धर्म द्वारा थोपे गए पवाग्रहा से ग्रसित भारतीय जनता को धर्म के आधार पर मतदान करने के लिए पदोन्नत प्रत्यागी प्रभावित करे। सभी चुनावों में यह भी एक आम गिनायत रही है कि राजनीतिक दल न धार्मिक अपसंगिकों को नाना प्रकार के प्रलोभन दत्त उनसे मत प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। वन्धा यह भी देखा गया है कि इन अल्पसंख्यकों ने सामूहिक रीति में अपना मतदान किया है और इसका प्रभाव निर्णायक रूप में निर्वाचना पर पड़ा है।

उपयुक्त विवेचना में स्पष्ट है कि भारत की निर्वाचित पद्धति में सुधार की समस्या आज हमारे प्रस्तुत है क्योंकि भारतीय समाज का संगठन जहाँ तक उस आधार पर नहीं हो पाया है जिस योजनाओं के विकास के लिए समीचीन कहा जा सके। परन्तु इस सम्बन्ध में आगे बात यह है कि भारतीय समाज में गतिशीलता का अभाव नहीं है। वह निरंतर उत्तरात्तर विकास की ओर अग्रसर है। विकास के नये तत्त्वों का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर एक-सा नहीं रहा है। गतिहीनता से गतिशीलता की ओर जाने का प्रक्रिया के समय भारतीय समाज में अनिश्चित जनक अंतरों की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें एक पाठो और दूसरी पीढ़ी के बीच के अंतर स्त्री और पुरुष के अंतर ग्रामीण एवं गहरी क्षेत्रों में निवास करने वालों के अंतर विषय रूप से उल्लेखनीय है। फलतः तनाव एवं सामाजिक संघर्षों का उदय उन क्षेत्रों में भी हुआ है जिन्हें परम्परागत रूप से संतुलित माना जाता था। पहले प्रत्येक भारतीय की स्थिति समाज में निश्चित थी वस्तुतः उसका निर्धारण उसके जन्म के साथ ही हो जाता था। परन्तु अब स्थिति बदल रहा है। यह ठीक है कि अभी यह बात पूर्ण रूप से निश्चय कर हमारे सामने नहीं आयी है कि तुल्य बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ हो चुका है तथा समय के साथ हमारे चुनावों के साथ जो बहुत सी गुराहियाँ जुड़ी हैं और जिनका सम्बन्ध हमारे समाज के ढाँचे के साथ है उनका स्वन तोप हो जायेगा। उनका निराकरण कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रश्न

1. भारत में स्वतंत्र निर्वाचनों का सफल बनाने के लिए क्या व्यवस्थाओं का गठन है ?
2. क्या आपकी राय में भारतीय निर्वाचन पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन्हीं सुधारों की आवश्यकता है ? यदि हाँ तो वे किसे सुधार क्या होने चाहिए ?

1 भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताएँ

भारतीय राजनीतिक दलों के अध्ययन के आरम्भ में प्रस्तावना के रूप में भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना समीचीन होगी। बर्क के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक निकाय है जो किन्हीं मान्य सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि चाहते हैं। वे नागरिक जो एक समुदाय में राजनीतिक इकाई के रूप में काम करने को तैयार हैं उन्हें एक राजनीतिक दल का सदस्य माना जा सकता है। अतः दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह ऐसे लोगों का निकाय है जिनका सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति एक सा दृष्टिकोण है तथा जो सामूहिक क्रियाओं के द्वारा सरकार का नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये इसलिये प्रयत्न करते हैं ताकि उनके दृष्टिकोण के अनुसार ही उन प्रश्नों का समाधान किया जा सके।

भारत में राजनीतिक दलों का विकास उस तरीके से नहीं हुआ जैसे पश्चिम के देशों में हुआ था। यहाँ राजनीतिक दल का उदय किसी कुलीनतान्त्रिक सत्तारूढ़ वर्ग को अपदस्थ करने के लिये नहीं हुआ था, अपितु उसका उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष का परिचालन करना था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कांग्रेस न केवल विदेशी दासता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में संगठित हुई थी बल्कि उसका उद्देश्य भारतीय समाज में सन्निहित उन तत्त्वों का भी उन्मूलन करना था जो सामाजिक प्रगति के मार्ग में अवरोध प्रस्तुत करते थे। 1947 में स्वतन्त्रता के उपरान्त कांग्रेस संगठन का विघटन आरम्भ हो गया। वस्तुतः औपनिवेशिक शासन के अन्तिम दिनों में ही कम्युनिस्ट कांग्रेस से अलग हो गये थे। 1947 में अपने कानपुर अधिवेशन के बाद सोशलिस्टों ने भी कांग्रेस से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। 1959 में राजगोपालाचारी और के० एम० मुन्शी के नेतृत्व में घोर दक्षिणपन्थियों ने भी कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। इस प्रकार कांग्रेस के विघटन के परिणामस्वरूप देश में चार राजनीतिक दलों की स्थापना हो गई। परन्तु चूँकि इनमें कांग्रेस ही सबसे अधिक संगठित थी इसलिये शासन की वागडोर सामान्यतः उसी के हाथ में रही। स्वतन्त्रता के समय से लेकर 1967 तक देश के राजनीतिक क्षितिज पर कांग्रेस इस प्रकार छापी रही कि कुछ लेखकों ने भारत को 'एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली' (One Dominant Party System) घोषित कर दिया। यद्यपि भारत की दलीय प्रणाली का यह नामकरण सामान्यतः सभी क्षेत्रों में स्वीकार कर लिया गया तथापि 'कांग्रेस' के प्रभुत्व की चरम सीमा के समय भी वह केवल आंशिक रूप से ही सही था। उससे दलीय प्रणाली में वास्तविकता से अधिक असन्तुलन के अस्तित्व का आभास होता था। यह सही है कि कांग्रेस का लोकसभा में हमेशा पूर्ण बहुमत रहा, परन्तु इसके साथ में यह भी सही है कि 1952 से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं उनमें किसी में भी कांग्रेस को मतदाताओं के पूर्ण बहुमत का कभी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। राज्यों के मन्दर्भ में एक दल के प्रभुत्व की बात और भी अधिक भ्रमोत्पादक है क्योंकि जहाँ केरल जैसे राज्य का उदाहरण मौजूद है जिसमें कांग्रेस को कुछ समय तक विरोधी वैचारिक पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा था तो वहाँ ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जिनमें यह प्रमाणित है कि शासक दल और विरोधी दलों के बीच बहुत अधिक असन्तुलन नहीं था।

उपयुक्त विवचना की पृष्ठभूमि में भारतीय राजनीति की विगपता का व्यक्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पहली उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में राजनीति का विकास उच्च राजनैतिक क्षेत्र में हुआ है जिसका जवाब देना स्वतन्त्रता के पूर्व भी किया जा सकता था तथा जिसकी मस्यागत अभिवृद्धि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा होती थी। दूसरी बात यह है कि स्वतन्त्रता के पूर्व और उसके बाद भी कुछ समय तक राजनैतिक दलों के सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि एक सी थी जो जाति का सम्बन्ध ऊपर की तिरादरिया के अग्रजों पर निम्न वर्ग के साथ होता था। इसी वर्ग में संविधानी समुदायों का भी उल्लेख हुआ। यथाथ में स्वतन्त्रता के पूर्व भी कांग्रेस में गुट थे। स्वतन्त्रता के बाद उस गुटबन्दी में वृद्धि ही हुई है। ये गुट ही कांग्रेस में विभिन्न राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गये। जैसा कहा जा चुका है दश के विभिन्न दलों एक समय कांग्रेस के ही अंदर किसी न किसी गुट के साथ सम्बद्ध रह चुके हैं। परन्तु हमका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इन गुटों के विभिन्न राजनैतिक दलों में संगठित होने के बाद कांग्रेस के अंदर की गुटबन्दी समाप्त हो गई। वास्तव में गुटबन्दी भारत के राजनीतिक दलों की एक विगपता है। फलतः सत्तापक्ष दलों के असंतुष्ट गुट तथा विरोधी दलों के असंतुष्ट गुटों के बीच बिल्कुल स्पष्ट विभाजन रखा नहीं है। स्पष्टतः इस प्रकार के संगठनों के सत्तारूढ़ता का अनुशासन करना कोई आसान बात नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनुशासनहीनता तथा दलबद्धता भारतीय राजनीतिक दलों की एक मुख्य विगपता है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे देश में राजनीतिक दलों का संगठन मुख्यतः किसी निश्चित विचारधारा के आधार पर नहीं हुआ। इस नियम के बिना दो ही अपवाद हैं—कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ।

भारतीय राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में एक दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि उन पर नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव आवश्यकता में अधिक है। उदाहरण के लिये एक नम्बर समय तक नेहरू जी का व्यक्तित्व कांग्रेस संगठन पर आच्छादित रहा और आज यही बात श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्बन्ध में कही जा सकती है। यद्यपि राजा कांग्रेस की वास्तविक विगपता नहीं है इसका अवगतान जय राजनीतिक दलों में भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में द्रमुक का उदय जयन्तराज के व्यक्तित्व से पृथक् करके नहीं समझा जा सकता। सभी प्रकार पश्चिमी वर्गों और वर्गों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति का यद्यपि वस्तुतः ई. एम. एस. नम्बुद्रीपाद की लोकप्रियता के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है।

भारतीय राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ वे अपने विरोध का यत्न करने के लिये क्वचन सांविधानिक तरीकों का ही प्रयोग नहीं करते अपितु वे आन्दोलनों का भी मार्ग अपनाते हैं। वस्तुतः यह स्थिति हम औपनिवेशिक काल में न देखे गये राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है।

भारतीय दलों का वर्गीकरण

पिछले दो दशकों में भारत के राजनैतिक दलों में विविधता आयी है और कुछ ऐसे तत्त्वों का उल्लेख हुआ है जिनके प्रभाव से अखिल भारतीय राजनीतिक दल भी अलग नहीं रह सकते हैं। एक बार नेहरू जी ने भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति के विषय में कहा था— कांग्रेस के अतिरिक्त भारत में वर्तमान राजनीतिक दलों को चार समूहों में बाँटा जा सकता है— कुछ एम राजनीतिक दल हैं जिनके अपने आर्थिक सिद्धांत हैं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथी संगठन हैं। विभिन्न समाजों को लिये हुए अन्य साम्प्रदायिक दल हैं जो निश्चित रूप से सर्वोच्च साम्प्रदायिक विचारधारा का अनुसरण करते हैं और चौथे वर्ग में उनके स्थायी दल और समूह हैं जिनका प्रभाव प्रांतीय और क्षेत्रीय है।

इस वर्गीकरण में स्थिति के सन्दर्भ में योजना-संगठन करने से भारतीय राजनीतिक दलों का इस क्रम में रखा जा सकता है—

(1) **अखिल भारतीय स्तर के दल**—इस श्रेणी के अन्तर्गत वे राष्ट्रीय दल आते हैं जिनका सगठन समूचे देश के स्तर पर पाया जाता है। इनके अपने सिद्धान्त हैं, अपना आर्थिक कार्यक्रम है तथा उसे लागू करने की एक व्यवस्थित योजना है। इस प्रकार के दलों में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी का उल्लेख किया जा सकता है।

(2) **क्षेत्रीय अथवा राज्य-स्तरीय दल**—इस श्रेणी के अन्तर्गत उन सभी दलों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र अथवा राज्य तक ही सीमित है। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में डी० एम० के०, हरियाणा में विगल हरियाणा पार्टी, केरल में केरल कांग्रेस और बिहार में भारखण्ड पार्टी तथा उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रान्ति दल के नाम इस श्रेणी के दलों के सन्दर्भ में लिये जा सकते हैं।

भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय दलों का होना स्वाभाविक ही समझा जाना चाहिए। वस्तुतः इतने बड़े देश में जहाँ विभिन्न भाषाएँ और मस्कृतियाँ पायी जाती हैं, जहाँ भौगोलिक असमानताएँ जीवन का यथार्थ हैं, वहाँ यह अनिवार्य है कि क्षेत्रीय समस्याओं का उदय हो। स्पष्टतः इन समस्याओं के निराकरण के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय दल इसी आवश्यकता को पूरा करते हैं। 1967 के चुनावों के समय से देश की राजनीति में इन दलों का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। इस चुनाव के समय ही देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय-स्तर के दलों का सगठन हो चुका था। उदाहरण के लिए, वगल में वगला कांग्रेस, उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस जैसे दल स्थापित हो चुके थे और इन्होंने उस चुनाव में भाग भी लिया था। यह सही है कि वगला कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलयन हो चुका है तथापि इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये सगठन वगल और उड़ीसा की विशिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुए थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 1967 के बाद इनमें से कुछ का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि अखिल भारतीय स्तर के दलों को इनके साथ समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1971 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस का डी० एम० के० के साथ समझौता इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

(3) **क्षेत्रीय किन्तु जातीय अथवा वर्गीय दल**—कुछ दल ऐसे भी हैं जो किसी क्षेत्र-विशेष में ही किसी जाति अथवा वर्ग-विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के दलों में केरल में मुस्लिम लीग अथवा पंजाब में अकाली दल के नाम लिए जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी दल हो सकते हैं जिनका गठन किसी क्षेत्र-विशेष में ही निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है। इस प्रकार के दलों में गुजरात में महामुजरात परिषद्, महाराष्ट्र में सम्पूर्ण महाराष्ट्र समिति, आन्ध्र में तेलगाना प्रजा समिति के नाम लिये जा सकते हैं।

(4) **साम्प्रदायिक दल**—इस वर्ग में उन दलों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य किसी सम्प्रदाय विशेष के हितों की रक्षा करना अथवा उन्हें आगे बढ़ाना है। इन प्रकार के दलों में हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, रामराज्य परिषद्, जनसंघ आदि दलों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभी साम्प्रदायिक दलों का स्वरूप एक सा नहीं है। उदाहरण के लिए रामराज्य परिषद् का स्वरूप साम्प्रदायिक होने के साथ-साथ परम्परावादी भी है जबकि जनसंघ के स्वरूप में परम्परावादी, साम्प्रदायिक एवं आधुनिक तीनों तत्वों का समावेश हुआ है।

(5) **पूर्णतया जातीय दल**—कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिनका सगठन केवल किसी जाति विशेष तक सीमित है। इस श्रेणी के दलों में रिपब्लिकन पार्टी का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है।

2 विविध राजनीतिक दल और उनके कार्यक्रम

उपर्युक्त प्रस्तावना के मन्दर्भ में हम भारत के राजनीतिक दलों तथा उनके कार्यक्रमों की विवेचना कर सकते हैं। निम्नन्वेह भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दल भारतीय

राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। मगर हम अपने अध्ययन का आरम्भ उसी से करेंगे।

(1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (फूट से पहले और फूट के बाद)

स्वतन्त्रता से पूर्व कांग्रेस की गणना राजनीतिक दल के अन्तर्गत नहीं की जा सकती थी। यद्यपि उस समय उसका स्वरूप एक राष्ट्रीय जातिवाद था जिसमें देश के व सभी जाति जाति व जाति राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से प्यार था। उस समय कांग्रेस यन्त्र औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक व्यापक मोर्चे की रचना कर रही थी तो दूसरी तरफ वह देश के सामाजिक नित्य एक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी दशवासिया का आन्दोलन कर रही थी। फलतः जहाँ उसने विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध नए जान बान संघर्ष का रूपरेखा निश्चित का वहाँ उसने उन नातियाँ और कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जिनके माध्यम से उस देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता था। 1931 में अपने कराचा अधिवेशन में उसने एक घोषणा पत्र पारित किया था जिसमें यह बताया गया है कि स्वराज की रूपरेखा क्या होगी? द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर जब प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव हुए तो उस समय कांग्रेस ने एक 12 सूची कार्यक्रम बना कर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें से कुछ मुख्य बातें निम्न हैं—(i) भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं समान अवसर उपलब्ध कराना (ii) सामाजिक अत्याचार एवं अश्रम से पालित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना (iii) गरीबों के अभिगाथ को दूर करना तथा जनता के जीवन-स्तर का ऊपर उठाना (iv) उद्योग एवं कृषि का आधुनिकीकरण करना तथा (v) धन के सभी साधन तथा उत्पादन एवं वितरण के सभी तरीकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना।

कांग्रेस का संगठन—जब देश स्वतन्त्रता संघर्ष में से होकर गुजर रहा था तब गांधी जी तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्य नेताओं ने कांग्रेस की एकता को कायम रखने के लिए भरसक प्रयत्न किया था यद्यपि उनके इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप कांग्रेस का स्वरूप एक छतरी संगठन (Umbrella organization) का रहा वह एक गुप्त राजनीतिक दल का रूप कभी धारण नहीं कर सका। परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत गांधी जी ने यह मत व्यक्त किया था कि कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं करना चाहिए। उनका सुझाव था कि कांग्रेस को विघटित करके उस लोक-मोक्ष संघ के रूप में सड़े प्रकार से संगठित किया जाना चाहिए तथा संसदीय तंत्र में नये संगठन के लिए छेड़ना चाहिए जिसे स्पष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित किया गया हो।

गांधी जी का यह सुझाव कार्यान्वित नहीं हो सका क्योंकि कांग्रेस के नेता सत्ता प्राप्त करने के उपरांत उस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। परन्तु एक दृष्टि से उनका ऐसा करना भारतीय शासन के लिए शुभ रहा उसने उस स्थायित्व प्रदान किया। कांग्रेस का संगठन समूचे देश में फैला था यहाँ तक कि उसकी शाखाएँ प्रत्येक गाँव में पाई जाती थी। जब जब अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं के हाथों में सत्ता हस्तांतरित हुई तो कांग्रेस अपने संगठन के धनवृत्त पर भारत में नाकामात्रिक व्यवस्था का कायम रखने में समर्थ हो सका। फलतः लोकतन्त्र को भारत में तेजी से बढ़ाने में जो उस पाकिस्तान अथवा बर्मा में देखने पड़े थे।

स्वतन्त्रता के पश्चात् कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय समिन्धान में अनेक बार परिवर्तन किये हैं उसमें ऐसा करने के लिए इसीलिए विचार होना पड़ा है कि वह अपने संगठनात्मक ढाँचे का अपने नूतन तन्त्र या एव उद्देश्यों के अनुकूल बना सके। 1947 में देशी राजवादा का भारतीय संघ में विघटन हो गया 1956 में राष्ट्रीय का पहली बार पुनर्गठन हुआ उसके उपरान्त 1960 और 1966 में पुनर्गठन के काम की पुनरावृत्ति हुई। देश के संघीय ढाँचे में हुए इन परिवर्तनों का पूर्णभूमि में यह आवश्यक था कि राष्ट्रीय इकाइयों का भी पुनर्गठन किया जाय। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कांग्रेस के संघात्मक स्वरूप पर कोई आघात नहीं पड़ा है।

1948 तक कांग्रेस सगठन की सबसे छोटी इकाई कांग्रेस पंचायत थी। परन्तु यह अनुभव किया गया कि दलीय यन्त्र पर प्रभावी नियन्त्रण कायम करने की दृष्टि से ग्राम एक अत्यधिक छोटी इकाई है। फलतः जब यू० एन० देवर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस सगठन को नये प्रकार से सगठित करने का प्रयत्न किया गया। सगठन की इस नई योजना के अनुसार अब ग्राम का स्थान मण्डल ने ले लिया। प्रति 20000 की जनसंख्या पर एक मण्डल की रचना की गई और उसमें यह व्यवस्था की गई कि उसमें प्रति एक हजार पर एक प्रतिनिधि चुनकर आया करेगा। परन्तु थोड़े दिनों में यह महसूस किया गया कि मण्डल-प्रणाली के द्वारा भी कांग्रेस जन-सगठन के रूप में अपनी भूमिका कारगर रूप से अदा नहीं कर सकती। अतः एक नवीन समिति—क्षेत्रीय समिति (Block Committee) की रचना की गई। इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि इनमें प्रति 2000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आयेगा।

1967 के निर्वाचन के उपरान्त यह आवश्यकता महसूस की गई कि कांग्रेस की प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में भी एक सगठनात्मक इकाई होनी चाहिए। 1969 में अपने वगलौर अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आग्रह का एक प्रस्ताव पारित भी कर दिया था। समूचे देश में कांग्रेस की 20 प्रदेश समितियाँ हैं तथा इनके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र-शासित क्षेत्र में भी उसकी एक सगठनात्मक शाखा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का सगठन समूचे देश में व्याप्त है। वस्तुतः देश में कोई ऐसा दल नहीं है जो इस दृष्टि से कांग्रेस का मुकाबला कर सके।

कांग्रेस दल का सर्वोच्च कार्यपालिका अभिकरण वर्किंग कमेटी है। उसमें अध्यक्ष के अलावा कुल 20 सदस्य होते हैं, इनमें से दस अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा शेष सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

वर्किंग कमेटी अपने कार्यों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठके वर्किंग कमेटी के द्वारा ही बुलाई जाती हैं। दल के सगठन पर जहाँ केन्द्रीय नेताओं का नियन्त्रण स्पष्ट दिखाई पड़ता है वहाँ राज्यों के नेता भी प्रभावशाली नहीं हैं। राज्य विधान सभाओं के लिए दलीय प्रत्याशियों के नाम प्रस्तावित करना उन्हीं का काम है। यद्यपि अपने इस अधिकार का वे समुचित प्रयोग करने में आमतौर पर अपनी दलीय गुटबन्धियों के कारण असफल रहते हैं तथापि उनके इस अधिकार के महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता।

दलीय ढाँचे में सदस्यीय बोर्ड का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसमें कांग्रेस अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य होते हैं। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र के विधानमण्डलों के कांग्रेस सदस्यों को अनुशासित करना तथा उनके कामों के बीच में ताल-मेल बैठाना उसी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। सरकार की नीतियों को निर्मित करने में भी उसकी एक विशिष्ट भूमिका रही है।

कांग्रेस की आन्तरिक गुटबाजी—कांग्रेस सगठन के मुख्य अंगों का सक्षिप्त विश्लेषण भी इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकता कि यह दल किसी सुनियोजित कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत काम नहीं करता, अपितु वह अपने में सन्निहित गुटों के माध्यम से काम करता है। यथार्थ में कांग्रेस का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो किसी न किसी गुट के साथ सम्बद्ध न हो। गुटों का कांग्रेस के जीवन के साथ आज इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि हम जिस प्रकार किसी हिन्दू की उसके वर्ण के बिना कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार किसी कांग्रेसी की भी उसके गुट के बिना कल्पना नहीं की जा सकती।

किसी-दल में गुटों का अस्तित्व उसकी जीवनशक्ति के लिए शुभ नहीं होता, उसमें उसकी राजनीतिक स्थिरता पर कुप्रभाव पड़ता है। यह ठीक है कि एक लम्बे समय तक लोक सभा में कांग्रेस दल की एकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, यद्यपि गुटबाजी में वह भी मुक्त नहीं था। 1969 की घटनाओं के बाद उसके कुप्रभाव केन्द्र में भी दृष्टिगोचर होने लगे। किन्तु राज्यों

म ता गुटवाजी क बुर परिणाम आरम्भ स हा अब तो किन विय जा सकत थ । राज्या म दनीय अनुशासन हमशा म हा निम्न स्तर का रहा फनन दन राया की राजनीति म प्रभावी भूमिका भी अदा नहा कर सता । काग्रम के आ तरिक सघष म गुटा न प्रतियागी दवाव समूहा के रूप म काम किया म सघष म सिद्धान्त और विचारधारा क निण कार् स्थान नहा था जोर यत्ति था ता वह कवन नाममात्र क निण हो था । वस्तुतः सी म्यनि ने काग्रम म अनुशासनहीनता को ज म दिया म असक कारण किसी काग्रमी की अपन दल के प्रति निष्ठा क स मुख सन्व एक प्रश्न बिह नगा रहता है ।

काग्रम के इसी पराभव का रोकन क निण विगपन 1963 क तान उप चुनाव म काग्रस का पगजय क उपरान नहरू जी ने काग्रस का पुनर्गठित करने क निण 6 मुख्य मंत्रिया तथा अपन मंत्रि परिषद् क 6 सदस्या का त्याग पत्र कामराज याजना क जतगत स्वीकार किया था । इस याजना का उद्देश्य दन के वरिष्ठ नेताओ को सरकारी पता स मुक्ति तिलावर दन का भगठित करन क काम म नगाना था । क म ता अस योजना को लागू करन म काई विगप कठिनाई उपस्थित नही हई कयाकि वहां अन्तिम निणय नहरू जी जस गतिशायी नेता के हाथा म था परन्तु राया म कम योजना का लागू करन म जनक कठिनाइया प्रस्तुत हा गई । कनाय नेतृत्व उह रोकन म असमर्थ रहा । उदाहरण क निण उत्तर प्रदेश म कमभानु गुत के बाद मुच्चा कृपतानी ने मुख्य मंत्री का काय भार सम्भाना । वह मुख्य मंत्री के पद पर इमनिण आसीन हो सका कयाकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री क समर्थक अपन नेता क अपदस्थ होन स प्रसन्न नहा थ तथा व ए ए एस यत्ति को मुख्य मंत्री बनाना चाहत थे जिस नहरू जा नहा चाहत थ । कम बाट जसा हाना क लिए था उत्तर प्रदेश म काग्रस क रार की गुट स्पर्धा बट गट ।

उपयुक्त विवेचना स स्पष्ट है कि कामराज याजना अपन उद्देश्य की प्राप्ति म असफल रही । नेताओ का बटन दन मात्र स दन के पराभव को रोक नही जा सका और न उसस दन के अदर की गुटवाजा पर ही कोई वाछित प्रभाव पडा । अब दन के अतर विराधी गुट का अस्तित्व काई रम्य नहा था दन आतरिक तनाव स जकटा हुआ था दन क सन्ध्य अपनी स्वाय सिद्धि म प्रस्त थ तथा दल के हिना को जागे बताने म किसी को भी रुचि नहा थी । इस पृष्ठभूमि म यत्ति 1967 क आम चुनाव म काग्रम का मह की सानी पता ता असम आश्चर्य की बात हा क्या थी ?

सदस्यता—काग्रस की सदस्यता नो प्रकार की है—प्राथमिक और सक्रिय । काई भी ऐसा यत्ति जिसकी आयु 18 वष है तथा जो काग्रस के उद्देश्य म जास्था रहता है काग्रस का सदस्य बन सकता है बगने कि बट किसा अय दन का सदस्य न हो । वह यत्ति जो दो वर्षों तक लगातार काग्रम का प्राथमिक सदस्य रह चुका है तथा जिसकी आयु 21 वष है 25 रुपया का चन्दा देकर अथवा 25 प्राथमिक सदस्या की भरता करक काग्रम की सक्रिय सदस्यता प्राप्त कर सकता है । काग्रस सगठन अपन सदस्या स जिस आचरण की अपा करता है उसमे यह प्रतीत नही हाना कि उसम कही आधुनिकता भी है । उदाहरण क लिए काग्रस के सक्रिय सदस्या क निण यादी पहनना अनिवार्य है यद्यपि कम नियम का सम्मान सामान्यतः उसके उन्धन क द्वारा ही हाता है उमक पालन क द्वारा नही । काग्रसजना क लिए जो वक्तय बताया गय है व भी आम तोर पर अराज नीतिक है । काग्रम क सविधान म सक्रिय सदस्या क लिए यह व्यवस्था की गई ह कि व प्रतिदिन अपना कुछ समय रचनात्मक कायक्रम म नगाय । रचनात्मक कायक्रम म निम्न बातें शामिल है—साम्प्रदायिक एकता खाी और प्रामोद्योग बुनियादी शिक्षा मद्य निषध हरिजन कल्याण अधिक अय उरजाओ अन्तेन गौ सेवा प्राकृतिक विविस्था का प्रणिमण कुल निवारण प्रोत् शिक्षा आदि । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन कार्यों का काग्रस के राजनीतिक उद्देश्य क साथ कार् विगप सम्भव नही है । यहाँ यह बतान की आवश्यकता नहा है कि इस आचार सहिता का पालन भी काग्रसी हाली दिवाली विगप पर्वों पर ही करत है ।

काग्रेस का आर्थिक कार्यक्रम—स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही कांग्रेस ने देश में व्याप्त निर्धनता को दूर करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार को विकसित किया था। 1955 में अपने अवादी सम्मेलन में कांग्रेस ने यह घोषणा की कि वह देश में 'समाजवादी ढाँचे का समाज' स्थापित करना चाहती है। परन्तु यह प्रस्ताव भी इतना अधिक अस्पष्ट था कि लोगो ने उसकी भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की। रूढ़िवादियों की दृष्टि में यह प्रस्ताव देश में उग्र समाजवाद की ओर ले जाने वाला पहला कदम था, जबकि वामपन्थियों का विश्वास था कि उसके अन्तर्गत देश में पूँजीवाद और निजी पूँजी का विकास होगा।

1956 में कांग्रेस ने औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में एक नया प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। मिश्रित अर्थतन्त्र के ढाँचे में निजीक्षेत्र के पास अत्यधिक सीमित क्षेत्र होना चाहिए तथा उसके पास कृषि, लघु उद्योग-धन्धे तथा व्यापार के अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी की रचना हुई है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद से उसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। कालान्तर में कांग्रेस ने 'संसदीय लोकतन्त्र पर आधारित समाजवादी राज्य' की स्थापना को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। परन्तु इस प्रस्ताव में सन्निहित उद्देश्य का कांग्रेस की करनी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ यह लिखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस की करनी और करनी के बीच पाये जाने वाले इन अन्तर्विरोधों का अर्थव्यवस्था पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। यह ठीक है कि इन नीतियों के घोषित होने के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ है। किन्तु इस सत्य के साथ हम इस बात की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि इस पूरे काल में देश में एकाधिकारी पूँजी का भी विकास हुआ है। निश्चय ही इसे समाजवाद की सजा प्रदान नहीं की जा सकती। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का प्रश्न है, वहाँ यह स्मरणीय है कि इससे सम्बद्ध उद्योगों के बारे में यह आम शिकायत है कि न तो उनमें कार्यकुशलता पायी जाती है और न ही उनसे वाँछित मुनाफे की प्राप्ति हो रही है। वस्तुतः इन उद्योगों ने देश में समाजवादी अर्थतन्त्र को लोकप्रिय बनाने के बजाय जनमानस में उसकी उपयोगिता के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

काग्रेस ने चौथा आम चुनाव इसी पृष्ठभूमि में लड़ा था। अतः जैसा स्वाभाविक था चुनाव में उसे मुह की खानी पड़ी, देश के अधिकांश राज्यों में उसे विरोधी बेंचों पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा। यद्यपि केन्द्र में उसका बहुमत कायम रहा, तथापि यहाँ भी उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। अतः इस सन्दर्भ में उसे अपने नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़ा। मई 1967 में अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने एक दस-सूत्री कार्यक्रम को अपनाया। कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें थी—

1 वंको का राष्ट्रीयकरण, 2 आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, 3 आयात और निर्यात में राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के आधार पर प्रगति, 4 खाद्यान्न में राज्य व्यापार, 5 सहकारिता के क्षेत्र का विस्तार, 6 एकाधिकारी पूँजी का संचालित ढग से खात्मा, 7 लोगो की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, 8 नगरों की भूमि के मूल्यों में वृद्धि को रोकना, 9 ग्रामों में पुनर्निर्माण कार्य, भूमि सुधार आदि, तथा 10 भूतपूर्व राजाओं को दी जाने वाली प्रिवी पर्सों का खात्मा।

काग्रेस फूट के बाद—1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का एक भाग श्रीमती गांधी के नेतृत्व में और दूसरा सिण्डीकेट के नेताओं के प्रभाव में चला गया था। दिसम्बर 1969 के अन्त में इन दोनों कांग्रेस संगठनों के अलग-अलग अविवेदन हुए। पुरानी कांग्रेस ने अपना अविवेदन अहमदावाद में निजलिगप्पा की अध्यक्षता में किया और नयी कांग्रेस का अविवेदन बम्बई में जगजीवन राम के सभापतित्व में हुआ। इन पृथक् अविवेदनों से अविभाजित कांग्रेस के 84 वर्ष नम्बे इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। अब दो दल सामने आ गये—कांग्रेस और नगठन कांग्रेस। दोनों दलों के कार्यक्रमों और नीतियों में अन्तर है। यह बात 1971 के मध्यार्थ

चुनाव में दाना दाना जाग जागे किया गया चुनाव घोषणा-पत्रों में स्पष्ट था जायगा।

सत्तापद काग्रस दल का चुनाव घोषणा-पत्र—सत्तापद कार्यक्रम नं 24 जनवरी 1971
 का जो चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया उसमें निम्नलिखित बातें थी—

(i) सरकार का विकास विज्ञान सम्पत्ति का समायोजन करना न सिर्फ उद्योगों के लिए बल्कि अधिक लोगों में सम्पत्ति का वितरण करने के लिए प्रयत्न करना कि उचित माता र ठहर निम्न सम्पत्ति तथा आर्थिक शक्ति का वितरण करना भी न हान किया जाय क्योंकि यह आवश्यक और सामाजिक वाय का विकासकारण व प्रतिकूल है।

(ii) भारत में अविज्ञान गरीबी भूमि की और गरीब किसानों में वृद्धि का आर्थिक स्थिति का सुधारण के लिए यह आवश्यक है कि हमें समग्र कार्यक्रम का समायोजन करना होगा। हमें विज्ञान में रुचि देना है कि जागृकता के विकास के लिए प्रयोग आवश्यक है। कार्यक्रम हमें जान के लिए प्रयत्न करनी कि विज्ञान के लाभ हान और न्यून किसानों में तथा भूमिहीन वर्गों में सभी का समान रूप में प्राप्त है। हमें विज्ञान के विकास का प्रयोग आर्थिक की सुविधा भी जायगी ताकि वे भी वित्तिय नरवान में रुचि करें तथा वित्तिय भी करें। सूख पत्रों में सभी के लिए और भी अधिक जागृक कार्यक्रम बनाया जायगा।

(iii) औद्योगिक विकास में सामाजिक शक्ति व जागृक की प्रमुख भूमिका होगी। सामाजिक उद्योगों का संगठन और समायोजन हमें यह मालूम कि हमें विज्ञान और शक्ति में अधिक पैजा लगाए व साधन मिलें। अब हम उद्योगों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम न आगे बढ़ाए ता गन्तीयकरण जायान विज्ञान के व्यापार में सरकार का अधिकारिक भाग लेने और जहाँ जनता का पतन होगा व हम उद्योगों में सरकार की बढ़ती भूमिका का विज्ञान के विकास और सरकारों में मिनिया के गृहण कर सरकारों के विकास के प्रस्ताव किया है।

(iv) विज्ञान क्षेत्र का कार्य प्रणाली सभी पानी चालित जागृक का समायोजन की जागृक ता में समावेश है। अब नये उद्योग पित्त क्षेत्रों में स्थापित जागृक चालित। उद्योगों का आर्थिक तथा आर्थिक शक्ति चालित हाथों में ही न मिले जागृक हमें जान का ध्यान में रखते हम निजी उद्योगों का विकास प्रोत्साहन किया जायगा।

(v) ग्राम सभा व गांव विकास धन और भूय नीति का अभिन्न सम्पद है। कार्यक्रम हमें विज्ञान संगठित नीति प्रणाली तथा उद्योग कार्यक्रमों में।

(vi) घोषणा-पत्र में राजगार कार्यक्रम का प्रभाव हमें चेतन पर भी वत दिया गया है।

(vii) विज्ञान और जान समाधान के मध्य में भाषा घोषणा पत्र में मायना प्रदान का गयी है। पिछले दशक के विज्ञान के लिए ता हमें कार्यक्रम का समाधान आरम्भ था चुकी है।

(viii) विज्ञान और जनता के क्षेत्र में एक गन्तीय वित्तिय और समाज की योजना तयार की जायगी जिस आर्थिक योजना के साथ संगठित किया जायगा।

(ix) कार्यक्रम निम्न और मध्यम उद्योगों का विकास की आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर उद्योगों का विकास कार्यक्रम तय में होगी।

(x) अपसम्यक्ता के अधिकारों और विज्ञान की सुरक्षा का जायगा। धर्म निरपेक्षता व गिद्धांत के आधार पर सभी अपसम्यक्ता का अपनी गति में जाय मालूम था स्थापित करने और उनका प्रत्यक्ष चेतन का अधिकार होगा। भाषाओं अपसम्यक्ता के विकास का प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की व्यवस्था की जायगी।

(xi) विभिन्न भाषाओं गान्तिय गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जायगा। उद्योगों का उद्योग उद्योग स्थान विज्ञान का प्रयोग किया जायगा जिसमें उद्योग वित्तिय रखा गया है।

(xii) समाज की भर्ती में हमें जान का प्रयत्न किया जायगा कि अपसम्यक्ता के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।

(xiii) समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक राजगार तथा आर्थिक विकास का जागृक विज्ञान

रूप से ध्यान दिया जायेगा।

(xiv) विदेश नीति के क्षेत्र में कांग्रेस उसी नीति का अनुगमन करेगी जिसकी रचना नेहरू जी के समय में हुई थी। इस प्रकार कांग्रेस गुट-निरपेक्षता तथा सैनिक गठबन्धनों से अलग रहने की नीति का अनुसरण करती रहेगी। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना उसकी विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धान्त होगा। अतः कांग्रेस पाकिस्तान और चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए प्रयत्न करेगी। किन्तु कांग्रेस देश की प्रतिरक्षा की ओर उदासीनता की नीति नहीं बरतेगी, अतः वह सशस्त्र सेनाओं को अधिकाधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करेगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर कांग्रेस को लोकसभा के 515 स्थानों में से 352 पर सफलता प्राप्त हुई। कुछ लोगो ने कहा है कि कांग्रेस की यह जीत वास्तव में इन्दिरा गांधी की 'वैयक्तिक जीत' थी। किन्तु इस प्रकार का मत व्यक्त करने वाले यह भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने 1967 का चुनाव भी इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा था और उस चुनाव में कांग्रेस को धूल चाटने के लिए विवश होना पड़ा था। यदि श्रीमती गांधी 1971 का चुनाव अपने व्यक्तिगत करिश्मे से जीत सकती थी तो 1967 में वह यह करिश्मा क्यों नहीं दिखा सकी? वास्तव में यह जीत इन्दिरा गांधी की कोई निजी जीत नहीं थी, वह तो उस नारे की जीत थी जो उन्होंने विरोधी दलों के 'इन्दिरा हटाओ' नारे के जवाब में दिया था। उनका नारा था—'गरीबी हटाओ'। कांग्रेस घोषणा-पत्र में इस नारे की अभिव्यक्ति इन शब्दों में हुई थी—गरीबी हटनी चाहिये। असमानता कम होनी चाहिये। अन्याय का अन्त होना चाहिये। ये हमारे अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिये आवश्यक कदम हैं, हमारा लक्ष्य है एकताबद्ध एवं शक्तिशाली भारत—वह भारत जो अपने प्राचीन एवं स्थायी आदर्शों में आस्था रखता है, परन्तु जो अपने विचारों एवं उपलब्धियों में आधुनिक है तथा जो भविष्य का सामना कल्पना एवं विश्वास के साथ करने को तैयार है।

वस्तुतः भारतीय मतदाता ने कांग्रेस के पक्ष में जो मतदान किया था उसका आधार चुनाव घोषणा-पत्र का यही अंश था। अतः कांग्रेस की इस जीत को इन्दिरा गांधी की व्यक्तिगत विजय नहीं कहा जा सकता। चुनाव के पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके तथा राजाओं के प्रिवी पर्सों को समाप्त करके जनमानस में उन्होंने यह चेतना भी उत्पन्न की थी कि वह वास्तव में देश को समाजवाद की ओर ले जाना चाहती है। इस सन्दर्भ में यह स्वाभाविक ही था कि देश की जनता उनके 'गरीबी हटाओ' के नारे में वास्तविकता का अवलोकन करती। देश की जनता अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहती थी, वह देश की अर्थव्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण आधार पर सगठित करना चाहती थी। 'गरीबी हटाओ' के नारे में उसे अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर हो रही थी। अतः 1971 के चुनावों में कांग्रेस की विजय को इन्दिरा गांधी का चमत्कार नहीं, बल्कि इस नारे का चमत्कार समझा जाना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति पहले की अपेक्षा अधिक उग्र हुई है। दल के आन्तरिक विरोधों का निराकरण करने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया है वह भी एक नया तरीका है। अब वह दल के अन्तर्विरोधों का समाधान करने के लिए दल के सहयोगी नेताओं से बात करने की अपेक्षा जनता से सीधे बात करती है। यथार्थ में कांग्रेस के सिण्डिकेट नेताओं को अपदस्थ करने में उन्हें इस तरीके से आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी, उनका यह तरीका आज भी जारी है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि नयी कांग्रेस अब पूर्णतः बदल चुकी है। वास्तव में नयी कांग्रेस का आन्तरिक चरित्र भी वैसा ही है जैसा कि पुरानी कांग्रेस का था। यदि पुरानी कांग्रेस में विचारवारा की एकरूपता का अभाव था, तो नयी कांग्रेस भी उस बीमारी में मुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए कांग्रेस में आज भी सुब्रह्मण्यम् जैसे लोग मौजूद हैं जिन्हें टाटा के 'मयुक्त क्षेत्र' (Joint Sector) को स्थापित करने के प्रस्ताव में कोई

खराबी नहाना दीखता। वही प्रकार यदि पुराना काग्रेस में जानी सम्म्यता की बीमारी पाई जाना थी तो नयी काग्रेस में यह बीमारी पहचान की अपनाना कई गुनी अधिक है। पुरानी काग्रेस गुटबाजी में बुरी तरह ग्रसित थी। यह दृष्टि में भी नयी काग्रेस का पुरानी काग्रेस का परिमार्जित स्वरूप नहाना कहा जा सकता। जहाँ तक गरीबी हुआ कि उग्र कार्यक्रम की कार्यावधि का प्रश्न है वहाँ भी नयी काग्रेस में जो निष्क्रियता अभी तक प्रतीति की है वह भी अविभाजित काग्रेस की निष्क्रियता में भिन्न नहाना है। सच बात तो यह है कि अभी तक गरीबी हुआ कि कार्यक्रम की कार्यावधि भी आरम्भ नहाना हुआ है।

संगठन काग्रेस का चुनाव घोषणापत्र—संगठन काग्रेस में अपने चुनाव घोषणापत्र में निम्न बातों पर बल दिया था—

(i) देश में इस बात का विरोध किया कि सम्पत्ति व अधिकार को संविधान से निकाल दिया जाना चाहिये। उसने देश का राजनीतिक समाजवादी और धर्म निरपेक्ष समाज में आस्था प्रदान की ताकि देश में सामाजिक न्याय अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की स्थापना की जा सके।

(ii) देश में स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन की व्यवस्था की जायगी जहाँ-यवस्था को विकसित किया जायगा 1975 के वर्ष तक समूह देश की युनतम आवश्यकताएँ पूरी की जायगी कर प्रणाली तथा राजस्व प्रणाली का आसान बनाया जायगा मध्यम और निम्न आय के लोग के लिए एक वर्ष में 10 लाख मकान बनाये जायेंगे कृषि वस्तुओं के मूल्य में प्रकार निर्धारित किये जायेंगे जिनमें कृषकों को लाभ पहुँचे तथा 1 हजार करोड़ की ऐसी योजना चालू की जायगी जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिल सके।

(iii) देश में कहा कि प्रिवी पर्सों को उचित देन से समाप्त किया जायगा परन्तु मूलभूत अधिकारों को विनाशित सम्पत्ति व अधिकार को रद्द करने अथवा उसमें सन्शोधन व किसी भी प्रयास का विरोध किया जायगा।

(iv) घोषणापत्र में संसद् देश का इस बात के लिए आलोचना का कि उसने आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय का समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए तिकड़म की राजनीति का सहारा लिया है। उसने देश की राजनीति के लोकतांत्रिक ढाँचे को काग्रेस में फूट डानकर तथा कम्युनिस्ट और सम्प्रदायवाद्या से साठ गाँठ करके क्षति पहुँचाई है। उसने न्यायपालिका के विरुद्ध संघर्ष की स्थिति पैदा करके देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट पैदा किया है।

(v) घोषणापत्र में सरकार का इसलिए भी आलोचना की गई क्योंकि वह प्रतिगत और मावज्जिनक आचरण के मामले में नतिक मूल्यों के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। इसका भारतीय राजतंत्र के स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(vi) काग्रेस (संगठन) ने उन समस्त देश की आलोचना की जो मूल अधिकारों विनाशित सम्पत्ति व अधिकार का समाप्त करने अथवा सन्शोधित करने की बात करते हैं। घोषणापत्र में भारतीय जनता की इन लोकतांत्रिक स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। काग्रेस (संगठन) ने यह घोषणा की कि उसका नया गरीबी को दूर करना आर्थिक धन उत्पन्न करके तथा धन का समान वितरण करके जनता के रहने-सहने के स्तर को ऊपर उठाना है यह काम गरीबों को वादकर नष्ट किया जा सकता।

(vii) औद्योगिक क्षेत्र में मिश्रित व्यवस्था के ऊपर धन दिया गया जिसमें मावज्जिनक निजी और सहकारी सभी प्रकार के क्षेत्रों के लिए स्थान होगा तथा जिन्हें समाज के हित में नियंत्रित करने का सरकार का अधिकार होगा।

(viii) कृषि क्षेत्र में काग्रेस (संगठन) ने मूल्य में भूमि सुधार का उल्लंघन किया तथा कहा कि वह अपने पहले के वायदा के अनुसार उच्च मीट्रातिनीय लागू करगी। कृषि वस्तुओं के मूल्यों के

सम्बन्ध में इस घोषणा-पत्र में कहा गया था कि किसानों के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा की जायगी।

(ix) शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के ऊपर बल दिया गया तथा यह कहा गया कि शिक्षा-प्रणाली एवं संस्थाओं के संचालन में छात्रों की भी भूमिका होगी। घोषणा-पत्र में स्त्रियों के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया।

(x) मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाय ताकि देश के राजनीतिक जीवन में युवा पीढ़ी की अधिकाधिक साझेदारी हो सके।

(xi) विदेश नीति के क्षेत्र में दल ने यह इच्छा व्यक्त की कि 'भारत की विदेश नीति के सन्तुलन को फिर से कायम' किया जाना चाहिए तथा उसे 'वास्तविक गतिशील गुट-निरपेक्षता' का रूप दिया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस (संगठन) ने मध्यावधि चुनाव जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ा था। चुनाव में इस मोर्चे की तरफ से अकेले कांग्रेस (संगठन) के 239 प्रत्याशी मैदान में थे और इनमें उसे केवल 16 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। चुनाव के परिणाम इस दल के लिए निश्चय ही निराशाजनक थे। दल के नेताओं के लिए यह पराजय ऐसी थी जो उनके गले के नीचे नहीं उतर सकती थी, अतः उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने चुनावों में शासनतन्त्र का दुरुपयोग किया है। परन्तु जहाँ तक देश के लोकमत का सम्बन्ध था, उसने यह बात भलीभाँति प्रदर्शित कर दी कि वह केवल सत्तारूढ़ कांग्रेस को ही वास्तविक कांग्रेस मानता है।

(ii) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (फूट से पहले और फूट के बाद)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—आयु की दृष्टि से भारत के राजनीतिक दलों में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थान कांग्रेस के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। उसकी स्थापना 1922 में हुई थी, परन्तु ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का सबसे अधिक प्रबल विरोधी होने के कारण उसे उसके जन्म के समय ही अवैध घोषित कर दिया गया था। फलतः उसे अपने शैशव काल से ही छिपकर काम करना पड़ा। इसके संविधान का प्रारूप 1931 में बना था, जिसे 1933 में पार्टी के प्रथम अधिवेशन में स्वीकार किया गया।

राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति कम्युनिस्टों का दृष्टिकोण उनके अन्तर्राष्ट्रवाद से हमेशा से प्रभावित रहा है। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को केवल भारतीय जनता का संघर्ष नहीं माना, अपितु उन्होंने कहा कि वह विश्व साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का एक अभिन्न अंग है। अतः उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से देखा। यह खेद की बात है कि 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रति जो स्वीकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था, उसे अपनाने में कम्युनिस्ट पार्टी असमर्थ रही। कारण स्पष्ट था। द्वितीय महायुद्ध में इस समय रूस और ब्रिटेन मिलकर कार्य कर रहे थे। अपने देश के हितों के विरुद्ध होते हुए भी रूस के मित्र ब्रिटेन का विरोध करना कम्युनिस्टों के बूते से बाहर था। फलतः कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से उसका फिर अलग हो गया।

इस पृष्ठभूमि में अगस्त 1947 में देश स्वतन्त्र हुआ। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते थे। पार्टी के महामन्त्री पी० सी० जोशी का मत था कि स्वतन्त्रता और सत्ता का हस्तान्तरण वास्तविक था तथा कम्युनिस्टों को नेहरू सरकार का समर्थन करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरा दृष्टिकोण बी० टी० रणदिवे का था जिनका यह मत था कि वास्तविक स्वतन्त्रता केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही प्राप्त की जा सकती थी। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार कम्युनिस्टों को कांग्रेस के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता थी।

1948 में कम्युनिस्ट पार्टी की कलकत्ता में दूसरी कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस में पी० सी० जोशी के ध्यान पर बी० टी० रणदिवे को पार्टी का महामन्त्री चुना गया। कम्युनिस्ट पार्टी की इस कांग्रेस ने स्टालिन के इस मत को मान्यता प्रदान की कि विश्व दो पक्षों में बँटा हुआ है एक

पक्ष मोसाम्बिकवादी का है तथा दूसरा पक्ष समाजवादी गति का है। इस कार्यक्रम में यह नियत किया गया कि कम्युनिस्टों को साम्राज्यवादी सामंतवाद एवं पंजीवाद सभी के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता है।

मोसाम्बिकी चलन के साथ रणनीति में कुछ बारीकियों एवं तत्मात्मवादी नीतियों का अनुसरण किया। फलस्वरूप विभिन्न भागों में हस्तान्तरण सगति की गति जहाँ-तहाँ पुनर्निर्माण और पंजीयन के दस्तावेज पर हमला भी किया गया जिसमें कुछ भाग मात्र भी गये और कई घायल हुए। यहाँ के माघ में आज़ादी के तत्पश्चात् क्षत्र में विमानों का छापामार युद्ध भी सगति किया गया। किंतु अपरिचित सहायता की शक्ति नहीं हो सकी। विभिन्न राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने कम्युनिस्टों के इस आन्दोलन का कुचलन का भरमंड प्रयत्न किया। जनक राजा में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया जिसमें माघ के दौरान जनक कम्युनिस्ट गिरफ्तार हुए जिसमें मारे भी गये। यह स्पष्ट था कि इस दमन से कम्युनिस्ट आन्दोलन कुचला गया था सत्ता का परतुलन नहीं था। यह स्पष्ट था कि इस दमन से कम्युनिस्ट आन्दोलन कुचला गया था सत्ता का परतुलन नहीं था। इस पृष्ठभूमि में कम्युनिस्ट पार्टी का अपना नातियाँ पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप रणनीति का पार्टी के महामंत्री के पास महसूस किया गया। 1951 में पार्टी ने एक विचार अधिवेशन के तत्पश्चात् हुआ जिसमें उद्देश्य पार्टी को बारीकियों में मुक्त करना था।

1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। इस समय तक देश के जनक राजा में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा था उसके बहुत से कार्यकर्ता या तो जेल में बंद थे और या के भूमिगत होकर काम कर रहे थे। परंतु इन मोसाम्बिकी के बावजूद चुनाव के परिणाम कम्युनिस्टों के लिए अत्यंत सुखद और गरव कम्युनिस्टों के लिए अत्यंत जागरूकता सिद्ध हुए। जहाँ नोकसभा के लिए बचत 70 स्थानों पर चुनाव लड़े थे और इनमें उन्हें 27 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। जहाँ तक सभा में कम्युनिस्ट पार्टी कायदे के बाद दूसरे नम्बर की पार्टी थी। इसी प्रकार राजा की विधान सभा में के लिए उसने बचत 587 सीटों पर अपने प्रयाशी लड़े जिसमें और इनमें 181 का सफलता मिली थी। कम्युनिस्टों की इस सफलता के सफलता के ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने फरवरी 1953 में कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय स्तर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस समय तक यह मान्यता बचत 4 दलों का प्राप्त था कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त अन्य तीन थे—कांग्रेस प्रजा समाजवादी पार्टी और जनमध।

दूसरे आम चुनाव के परिणामों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया। लोक सभा में उसे 29 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। 1952 में उसे कुल 47 12 009 मत प्राप्त हुए थे 1957 में उसके पास में पड़े मतों की संख्या 1 20 68 452 हो गई थी। स प्रकार अब वह सोदा की दृष्टि से ही नए बर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से भी देश की दूसरी बड़ी पार्टी थी। जब पहली बार देश के दशभाग सभी विधानमण्डलों में उसके प्रतिनिधि मौजूद थे। यही नहीं आधुनिक प्रणाली और पश्चिमी प्रणाली में वह मुख्य विरोधी पार्टी की तथा केरल में उसे शासक दल की भूमिका की जगह करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तैहास में यह पहला अवसर था जब सभा के किसी भाग में बचत बचत के माध्यम से कम्युनिस्टों का अपना शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई थी।

जैसा कहा जा चुका है कम्युनिस्ट पार्टी में राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति हमला से विरोधी दृष्टिकोण पाये जाते रहे थे। 1959 में इसी प्रकार की एक समस्या उस समय प्रस्तुत हुई जबकि भारत और चीन के बीच एक सामान्य विवाद उत्पन्न हुआ। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मकमाइन रेखा को भारत की पूर्वी सीमा बताया गया तथा चीन के इस कार्य पर आपत्ति प्रकट की गई कि वह इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सिस्त्रिम और भूतान से

बातचीन कर रहा है। प्रस्ताव में कहा गया कि चीन को केवल भारत से ही बात नहीं करनी चाहिए, 1961 में इस स्थिति को फिर से दुहराया गया। लोक सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एस० ए० डांगे ने सीमा विवाद पर भारत सरकार के दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से समर्थन किया। पार्टी के अन्दर कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हें यह स्थिति मान्य नहीं थी, इन लोगों का कहना था कि सीमा विवाद में भारत का दृष्टिकोण गलत था और चीन का सही। इस प्रकार के कम्युनिस्ट पश्चिमी वंगाल में एक बड़ी सख्या में पाये जाते थे। फलतः पार्टी के अन्दर पाये जाने वाले यह मतभेद पार्टी के बाहर भी व्यक्त किये जाने लगे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विवादग्रस्त एक तीसरा प्रश्न भी था और वह यह था कि शासक दल के प्रति पार्टी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अप्रैल 1961 में पार्टी सम्मेलन में अजय घोष और डांगे ने यह मत प्रतिपादित किया था कि समाजवादी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को एक 'राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा' को गठित करने का प्रयास करना चाहिए और इस मोर्चे में कांग्रेस के अन्दर पाये जाने वाले वामपथी तत्त्वों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। पार्टी सम्मेलन ने डांगे-घोष दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया, परन्तु जब राष्ट्रीय परिषद् के निर्वाचन का प्रश्न आया तो उसने पार्टी में एकता कायम रखने की दृष्टि से सकीर्णतावादी तत्त्वों को भी चुन लिया। इस प्रकार 110 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद् में जहाँ 60 सदस्य अपने सही दृष्टिकोण के कारण चुने गये थे, वहाँ 50 सकीर्णतावादी भी उनके साथ निर्वाचित कर लिये गये।

तीसरे आम चुनाव के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने जो घोषणा-पत्र जारी किया उसमें यह कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को 'प्रतिक्रियावादी' सस्था नहीं मानती। इसलिए यदि आगामी चुनाव में कांग्रेस की समाजवादी नीतियों की कार्यान्विति को सम्भव बनाने के लिए कम्युनिस्ट तथा अन्य लोकतान्त्रिक प्रत्याशी एक बड़ी सख्या में निर्वाचित हो जाते हैं तो पार्टी को उसी से सन्तोष हो जायगा। 1962 की जनवरी में महामन्त्री अजय घोष का देहान्त हो गया। उनके निधन के उपरान्त दल में एकता कायम रखने के लिए पार्टी सविधान में संशोधन किया गया जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय कार्यकारिणी की सदस्य-संख्या 25 से 30 हो गई और सेक्रेटेरियट की 5 से 9। अभी तक पार्टी का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी महामन्त्री होता था, अब दो पदाधिकारी हो गये—अध्यक्ष और महामन्त्री। इन दो पदों पर डांगे और नम्बूदिरिपाद को निर्वाचित किया गया। परन्तु पार्टी की यह एकता स्थायी सिद्ध नहीं हो सकी। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। देश के अन्य राजनीतिक दलों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् ने भी चीनी आक्रमणकारियों की भर्त्सना की, परन्तु राष्ट्रीय परिषद् में कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो चीनियों की इस आलोचना को गलत मानते थे। इनमें से तीन पार्टी के सेक्रेटेरियट के भी सदस्य थे। अतः उक्त प्रस्ताव के पारित होने के बाद इन तीनों—ज्योति बसु, सुन्दरैया और हरीकिशन सिंह सुरजीत ने सेक्रेटेरियट से त्याग-पत्र दे दिया। नम्बूदिरिपाद ने महामन्त्री के पद से त्याग-पत्र देने की इच्छा व्यक्त की, किन्तु उन्होंने इस पर आग्रह नहीं किया। इसके बाद अनेक वामपथी कम्युनिस्ट गिरफ्तार कर लिये गये—इनमें नम्बूदिरिपाद, ज्योति बसु, सुन्दरैया और सुरजीत सभी शामिल थे।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पार्टी के अन्दर आन्तरिक विवाद अब उस स्थिति पर पहुँच गया था जहाँ से किसी भी सम्बद्ध पक्ष के लिए यह सम्भव नहीं रह गया था कि वह दूसरे के साथ समझौता कर सके। इस पृष्ठभूमि में अप्रैल 1964 में राष्ट्रीय परिषद् की एक बैठक हुई। इस बैठक में से 32 सदस्य उठकर चले आये, बाहर आने वालों में गोपालन और नम्बूदिरिपाद भी शामिल थे।

जुलाई 1964 में इन्ही के नेतृत्व में तेनाली में विरोधी कम्युनिस्टों का एक सम्मेलन हुआ

और इस प्रकार कम्युनिस्ट आन्दोलन में एक पहना दार पड़ी। अपने तनाना अधिवेशन में इन कम्युनिस्टों ने अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान भारतीय राज्य के साथ उनका कोई समझौता नहीं हो सकता तथा नहरे की जानिया के साथ उह पूण विराध है क्वाकि उनम सयुक्त राष्ट्र अमरीका की नव उपनिवगवानी और आक्रमणकारी योजनाओं के बाया-वयन के लिए माग प्रशस्त होना है।

8 सितम्बर 1964 का नाग सभा के 32 कम्युनिस्ट सदस्यों में 11 ने गणपत के नवृत्त में अपना एक जनगुट बना लिया फलतः सदन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति दूसरे बने दन की नहा रही।

14 सितम्बर का राष्ट्रीय परिषद् ने उन सब नागों को पार्टी सदस्यता से निकाल दिया जिन्होंने तनानी सम्मेलन में भाग लिया था।

नयी पार्टी ने अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) रखा। अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के गणभण एक तिहाई सदस्यता ने नयी पार्टी की मन्म्यता स्वीकार करना।

उन पार्टी की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए इनके 1971 के घोषणा पत्र की विवेचना आवश्यक है।

कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र—कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा था कि उसका चुनाव नम्य दक्षिणपथी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ को पराजित करना तथा उनके इस प्रयास को विफल बनाना है कि वे के में अपनी सत्ता स्थापित कर सकें तथा एक एनी लोकसभा की रचना कर सकें जिसका रहान पिछड़ी लोकसभा की अपेक्षा अधिक वामपथी और अधिक नाकतात्रिक हो तथा जो सविधान में मूलभूत परिवर्तनों को नान और सदन की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हो।

घोषणा पत्र की प्रस्तावना में पार्टी ने सिन्धुकेट जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के गठबंधन की कट गाना में जांचोचना की थी तथा यह कहा था कि हमारे वाममार्गी जादानन का हमना के लिए नजित करने के लिए सयुक्त समाजवादी पार्टी के नतत्व ने लोकतंत्र और समाजवाद के इन गानों के साथ खुले रूप से गठबंधन करना स्वीकार किया है। पार्टी ने सत्तारक्त काग्रस की भी वसलिए जांचोचना की कि बका के राष्ट्रीयकरण के दान जनता में जा आगाय जागृत हुइ थी उह पूरा करने में वह असमर्थ रहा है।

कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में माक्सवादी पार्टी की भी जांचोचना की। उसने माक्सवादी के इस दृष्टिकोण को गनत बताया कि सत्तारक्त काग्रस और महा गठबंधन की पार्टी में कोई अंतर नहीं है। उसने कहा कि न दोना से अपनी दूरी को समान रखने का ओर में माक्सवादी पार्टी यथाथ में कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य लोकतांत्रिक पार्टियों का अपने आक्रमण का नम्य बना रही है। पार्टी ने माक्सवादी पर वामपथी एकता जन संगठनों एवं जन-आन्दोलन में फूट डालने का आरोप लगाया। अपने तथाकथित उग्रवाद की आन में माक्सवादियों को सिन्धुकेट के साथ समझौता करने में और दक्षिणपथी प्रतिक्रियावाद के चुनाव को तान मल करने में कोई सकोच नहीं हुआ है। इस प्रकार माक्सवादी पार्टी सिन्धुकेट जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का खन खन रही है।

घोषणा पत्र में यह माग नहीं की गई थी कि सम्पत्ति के अधिकार का सविधान में स्थान न दिया जाय परन्तु उसमें यह अवश्य कहा गया है कि एकाधिकारी पजीपतियाँ भूतपूर्व नरेगा जमींदारों तथा अन्य सम्पन्न शक्तियों के अधिकार को सीमित किया जाय। उसने माग की कि सर्वोच्च न्यायलय के गठन में आवश्यक सुधार किये जायें एकाधिकारी पजी द्वारा नियंत्रित संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय प्रगतिशील भूमि-सुधार किये जायें राया के विधानमण्डल के द्वितीय सत्र समाप्त किये जायें तथा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी जाय।

घोषणा-पत्र में कुछ सांविधानिक सुधारों की भी माँग की गयी। इस सम्बन्ध में पहली माँग यह थी कि प्रिवी पर्सों तथा भूतपूर्व नरेशों के विज्ञेयाधिकारों के सम्बन्ध में जो प्राविधान सविधान में पाये जाते हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाय। दूसरी माँग यह थी कि इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारी जो अभी भी सेवारत हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाय तथा सविधान के 314वें अनुच्छेद को भी सविधान से निकाला जाय ताकि 'ब्रिटिश शासन के इन मामलों' को दिये जाने वाले सरक्षण का अन्त किया जा सके।

कम्युनिस्ट पार्टी ने यह भी माँग की कि सांविधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए दोनों मन्तों के मिले-जुले अधिवेशन को करने की व्यवस्था की जाय, देश की मौलिक एकता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जायें तथा गवर्नरों के पद खत्म किये जायें। उसने यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करने के लिए भी सविधान में संशोधन किये जायें। इसके हेतु पार्टी का यह सुझाव था कि सदन द्वारा व्यक्त जनता की इच्छा न्यायपालिका की चुनौती से परे होनी चाहिए। उसका यह भी सुझाव था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पर कोई भी सांविधानिक प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल ज्येष्ठता के आधार पर नहीं होनी चाहिए तथा सदन को साधारण बहुमत में किसी भी न्यायाधीश को पदच्युत करने का अधिकार होना चाहिए।

कृषि के क्षेत्र में पार्टी की माँग थी कि भूमि की हदबन्दी नीची की जाए, हदबन्दी के लिए परिवार को इकाई माना जायें तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अपवादों को मान्यता न दी जायें। उसने अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का वचन दिया।

औद्योगिक क्षेत्र में पार्टी का कहना था कि एकाधिकारी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा विदेशी पूँजी पर राज्य का अधिकार स्थापित किया जाय। उसने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए ताकि वह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका अदा कर सके।

मूल्यों के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र में यह माँग की गई थी कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए, अग्रिम व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए तथा मटे के ऊपर बैंकों को उधार नहीं देना चाहिए। पार्टी ने इस बात का भी सुझाव दिया कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का वितरण सस्ते मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

पार्टी ने देश में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली को भी बदलने की माँग की ताकि देश के धर्म-निरपेक्ष एवं तकनीकी आधार को शक्तिशाली बनाया जा सके। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया कि छात्रों को शिक्षा समस्याओं के प्रबन्ध में भाग दिया जाना चाहिए तथा वैज्ञानिक समस्याओं को अधिक स्वायत्त बनाना चाहिए।

कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्प्रदायिक शक्तियों को खत्म करने के लिए प्रभावी प्रशासकीय कदम उठाने की माँग की तथा यह कहा कि अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ी हुई जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

विदेश नीति के क्षेत्र में पार्टी ने कहा कि 'उपनिवेश-विरोध, साम्राज्य विरोध तथा सोवियत मध्य और अन्य समाजवादी देशों के साथ मैत्री कायम रखने के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करना चाहिए।' पार्टी ने जातिवाद की नीति की आलोचना की तथा उसने कहा कि ब्रिटिश कॉमनवैलथ में भारत को अलग हो जाना चाहिए। उसने वियतनाम के लोकतान्त्रिक गणराज्य, दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार, जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य तथा कोरिया के लोकतान्त्रिक जन-गणराज्य को पूर्ण मान्यता प्रदान करने पर आग्रह किया। उसने हिन्द-पाक सम्बन्धों को ताश्कन्द समझौते की भावना के अधीन सुधार करने की माँग की तथा यह भी कहा कि चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(iii) समाजवादी पार्टियों

भारत में समाजवादी पार्टियों का इतिहास विलयनों एवं विघटनों का इतिहास रहा है। अनेक बार समाजवादी आन्दोलन को एकता के सूत्र में पिरोने के प्रयास किये जा चुके हैं, इन प्रयत्नों को तात्कालिक सफलता भी मिली है परन्तु अल्प समय में ही इनमें फिर से फूट पड़ गई है। यह क्रम निरन्तर चलता रहा है।

1933-34 में कांग्रेस के अन्दर एक वामपंथी संगठन के रूप में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, उस समय इसका नाम कांग्रेस समाजवादी पार्टी था। 1948 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त यह कांग्रेस से अलग हो गई और इसने अपने आप को भारतीय समाजवादी पार्टी का नाम दिया। प्रथम आम चुनाव के थोड़े दिन पूर्व आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कुछ गांधीवादी कहलाने वाले व्यक्ति भी कांग्रेस से जलग हो गये थे और उन्होंने अपने आपको किसान-मजदूर प्रजा पार्टी का नाम दिया था। इन दोनों पार्टियों को आशा थी कि चुनाव में इन्हें काफी सफलता मिलेगी। समाजवादी पार्टी तो यह आशा सजोए बैठी थी कि चुनाव के उपरान्त वह कांग्रेस की मुख्य विकल्प होकर सामने आयेगी। परन्तु चुनाव के परिणाम इन दोनों दलों के लिए अत्यन्त निराशाजनक सिद्ध हुए। अतः यह आवश्यक समझा गया कि समान विचारधारा वाले दलों को आपस में मिल जाना चाहिए। इसलिए 12 सितम्बर 1952 को इन दोनों पार्टियों का विलयन हो गया और इस प्रकार प्रजा समाजवादी पार्टी (प्रसोपा) का गठन हुआ। इस विलयन के परिणामस्वरूप दल का नियन्त्रण समाजवादियों के हाथों में चला गया क्योंकि इस नये दल के सभी मन्त्री पुराने समाजवादी ही थे, परन्तु दल के सम्मानित स्थान किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्यों को दिये गये। आचार्य कृपलानी नये दल के अध्यक्ष बने और अशोक मेहता उसके महामन्त्री।

उक्त दलों के विलयन में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह कार्य सुगमतापूर्वक इसलिए सम्पन्न हो गया क्योंकि बातचीत के दौरान विचारधारा से सम्बद्ध प्रश्नों को नहीं उठाया गया, केवल आम सिद्धान्तों की चर्चा की गई। परन्तु थोड़े दिनों साथ रहने के अनुभव ने यह प्रमाणित कर दिया कि दोनों के कार्यक्रम, काम करने का तरीका, प्रचार, भाषा आदि सभी में बहुत अन्तर थे। वस्तुतः पुरानी समाजवादी पार्टी में ही विचारधारा की समानता का अभाव था, किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के साथ विलयन करके उसमें एक नये असमान तत्त्व को स्थान दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि दल के आन्तरिक संघर्ष खुलकर सामने आते।

प्रसोपा के अधिकांश नेताओं का यह मत था कि उन्हें उन राज्यों में जिनमें कम्युनिस्ट और साम्प्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हैं कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। 1953 में इस सम्बन्ध में जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी में बातचीत भी हुई थी। परन्तु यह दृष्टिकोण डा० राम मनोहर लोहिया और उनके युवा साथियों की समझ में नहीं आया। इनका कहना था कि हमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को समान दूरी पर रखना चाहिए। इसी बीच 1954 में ट्रावनकोर-कोचीन (अब केरल) में ट्रावनकोर-तमिलनाडु कांग्रेस ने राज्य के तमिल भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य में मिलाने के लिये सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। इस समय इस राज्य में यानू पिल्ले के नेतृत्व में प्रसोपा का मन्त्रिमण्डल कायम था, जो अल्पमत में होते हुए भी कांग्रेस के समर्थन से वहाँ टिका हुआ था। इस मन्त्रिमण्डल के समय में तमिल सत्याग्रहियों के ऊपर गोली चला दी गई। डा० लोहिया ने माँग की कि इस गोलीकाण्ड के बाद यानू पिल्ले मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। मुख्य मन्त्री ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि में दल में एक आन्तरिक मकट उत्पन्न हो गया। इसका निराकरण करने के लिए नागपुर में नवम्बर 1954 में दल का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार गोलीकाण्ड पर खेद तो व्यक्त किया गया, परन्तु मन्त्रिमण्डल में त्याग-पत्र देने को नहीं कहा गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद डा० लोहिया ने दल से त्याग-पत्र दे दिया और उन्होंने दिसम्बर 1955 में समाज-

राष्ट्रीय समिति को नियुक्त किया। प्रेम भसीन इस समिति के महामन्त्री चुने गये। फरवरी 1965 में एन० जी० गोरे को दल का अध्यक्ष चुना गया।

चौथे आम चुनाव को इन दोनों दलों ने अलग-अलग लड़ा तथा उसके लिए उन्होंने अलग-अलग घोषणा-पत्र जारी किये। प्रसोपा ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय, वज्र भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सेना संगठित की जाय, क्षेत्रीय प्रणाली का अन्त किया जाय, 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में राशनिंग आरम्भ किया जाय तथा किसानों को कृषि वस्तुओं का उचित मूल्य दिया जाय। पार्टी ने यह भी माँग की कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेष अदालतें गठित की जायें, प्रशासन के विरुद्ध लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्वतन्त्र अधिकारी की नियुक्ति की जाय, मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार दिया जाय, चुनावों के तीन महीने पूर्व मन्त्रिमण्डलों के त्याग-पत्र ले लिये जायें तथा अन्तरराज्यीय विवादों का निराकरण करने के लिए एक आयोग गठित किया जाय।

ससोपा ने अपने घोषणा-पत्र में केन्द्र और राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना के लिए आह्वान किया। उसने कहा कि सघ और राज्यों के सम्बन्धों को फिर से इस प्रकार परिभाषित किया जाय ताकि केन्द्र राज्यों में स्थापित 'जनता की सरकारों' का गला न घोट सके। आर्थिक मामलों में ससोपा का सुझाव था कि व्यक्तिगत व्यय 1500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इससे अतिरिक्त आय राज्य के पास जमा हो जानी चाहिए जो उसके स्वामी को या उसके उत्तराधिकारियों को 25-30 वर्ष के बाद लौटा दी जाय। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया कि सिचाई की एक सप्तावर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिए तथा वह भूमि, जो न्यूनतम उत्पादन देने में असमर्थ रहे उस पर राज्य का अधिकार हो जाना चाहिए।

लोकसभा के चुनाव में ससोपा को 23 स्थान प्राप्त हुए और प्रसोपा को 13। इसी प्रकार राज्यों की विधान मण्डलों में ससोपा को 175 सीटों पर सफलता मिली और प्रसोपा को 106 सीटों पर। यदि इन आँकड़ों की तुलना 1962 के चुनाव-परिणामों से की जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि चौथे चुनाव में प्रसोपा की शक्ति क्षीण हुई थी तथा उनके मुकाबले में ससोपा की शक्ति में वृद्धि हुई थी। चुनावों के बाद जब 8 राज्यों में मिली-जुली सरकारें बनीं तो दोनों पार्टियों ने उनमें हिस्सा बँटाया।

1969 में जब कांग्रेस में फूट पड़ जाने के परिणामस्वरूप इन्दिरा गांधी के मन्त्रिमण्डल का सदस्य बहुमत समाप्त हो गया तो उस समय इन दोनों दलों ने उसके प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाये। वस्तुतः इस प्रश्न पर ससोपा में आन्तरिक एकता का अभाव था। एस० एम० जोशी के नेतृत्व में कुछ सदस्यों का यह विश्वास था कि श्रीमती गांधी को अपनी समाजवादी प्रतिज्ञाओं को कार्यान्वित करने का समय दिया जाना चाहिए। दूसरे गुट में नेता राजनारायण थे जिनका कहना था कि श्रीमती गांधी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए कांग्रेस (संगठन) के साथ सॉठ-गाँठ की जानी चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा गुट कर्पूरी ठाकुर का था। उनका कहना था कि गैर-कांग्रेसवाद का तकाजा है कि कांग्रेस के दोनों गुटों का विरोध किया जाय। इन मतभेदों का निराकरण करने के लिए ससोपा का एक विशेष अन्वेषण जनवरी 1970 में सोनपुर में हुआ। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि पार्टी सरकार का तरता पलटने के लिए किसी भी दल के साथ समझौता करने को तैयार है तथा वह ऐसे दलों के साथ गठबन्धन करने को उद्यत है जो एक निश्चित समय में पूरे होने वाले समाजवादी कार्यक्रम में विश्वास करते हों। इसके बाद राज्यों में संयुक्त मोर्चे गठित किये गये जिनमें जनसघ और स्वतन्त्र पार्टी को भी स्थान दिया गया। पार्टी-सदस्यों में इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। लोकसभा के 9 ससोपा सदस्यों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व की यह नीति दल में फूट के लिए मार्ग-प्रशस्त कर रही है। इस स्थिति को टालने के लिए

[illegible]

1 THE 12TH 21ST

[illegible]

— 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 114

॥ ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ॥

[illegible]

1. 11. 11. 11. 11

[illegible]

1. 11.15.11

[illegible]

अच्छी नहीं थी। इस बार उसे केवल दो सीटों पर सफलता मिली, पिछली बार उसे 13 सीटें मिली थी। लोकसभा के चुनावों के साथ उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु की विधान सभाओं के भी चुनाव हुए थे। यहाँ भी दोनों दलों की स्थिति बहुत खराब थी। 1967 में प्रसोपा को उड़ीसा में 21 सीटों पर सफलता मिली थी, अबकी बार उसे केवल 4 सीटें मिली। इसी प्रकार ससोपा की इस राज्य में पहले दो सीटें थी, अबकी बार उसे किसी सीट पर सफलता नहीं मिल सकी। इन दोनों दलों की ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में थी। इस सदर्भ में इन दोनों दलों ने एकता के लिए फिर से प्रयत्न किया। फलतः 8 अगस्त 1971 को दोनों दलों ने मिलकर एक नये दल की रचना की जिसे उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी ने 61 सदस्यों की एक तदर्थ समिति को नियुक्त किया जिसका अध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर (ससोपा के अध्यक्ष) को तथा मन्त्री मधु दंडवते (प्रसोपा के उपमन्त्री) को निर्वाचित किया गया। परन्तु इस नये दल के अस्तित्व में आने के थोड़े दिन ही बाद उसमें फूट के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। राजनारायण तथा उनके ससोपा के पुराने सात सहयोगियों ने यह माँग की कि उन्हें चौबीसवें संशोधन विधेयक का विरोध करना चाहिये। 27 अगस्त 1971 को एस० एन० द्विवेदी ने दल से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने घोषणा की कि वे उड़ीसा में कांग्रेस और प्रसोपा के गठबन्धन के लिए काम करेंगे। इस प्रकार देश में समाजवादी पार्टियों की पारस्परिक फूट अभी भी ज्यों की त्यों कायम है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में ससोपा, भारतीय क्रान्ति दल के काफी निकट आ गई है और 1974 में जिन 7 पार्टियों ने आपस में अखिल भारतीय स्तर पर विलय का प्रस्ताव किया है उसमें ये दोनों भी शामिल हैं।

भारतीय जनसंघ

इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। वस्तुतः इसके पूर्व 1925 में विजयादशमी के अवसर पर के० बी० हेडगेवार ने 'हिन्दू जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तथा प्राचीन हिन्दू राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति' के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर० एस० एस०) की स्थापना की थी। कांग्रेस नेताओं के कारावास के काल में इसने देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएँ स्थापित कर ली थी। इस काल में देश में मुस्लिम सम्प्रदायवाद के उदय ने भी हिन्दुओं में साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित किया। आर० एस० एस० को इस परिस्थिति से बढ़ावा मिला। 1947 में देश के विभाजन की पृष्ठभूमि में देश में सम्प्रदायवादी प्रवृत्तियाँ ऊपर उठकर आयीं। अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय राजनीति का कोई भी विद्यार्थी साम्प्रदायिक शक्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। जनवरी 1948 में ऐसे ही एक साम्प्रदायिक पागल नाथूराम गोडसे ने महात्मा गान्धी की हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप समूचे देश में आर० एस० एस० तथा अन्य हिन्दू साम्प्रदायिक संगठनों के विरुद्ध रोष की लहर दौड़ गई। इस सन्दर्भ में सरकार ने आर० एस० एस० पर प्रतिबन्ध लगा दिया। बाद में यह प्रतिबन्ध तब हटाया गया जबकि इसके नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि उनका संगठन केवल सांस्कृतिक कार्य करेगा तथा वह अपने आपको राजनीति से दूर रखेगा। इसलिए आर० एस० एस० के कार्यकर्त्ताओं को राजनीतिक कार्यों के सम्पादन के लिये एक नये दल की आवश्यकता थी। जनसंघ की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई थी।

जनसंघ के नेताओं ने इस बात का हमेशा प्रतिवाद किया है कि उनका दल कोई साम्प्रदायिक संगठन है। उसके सबसे पहले अध्यक्ष डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनेक बार इस बात का खण्डन किया कि उनके दल का हिन्दू सम्प्रदायवाद के साथ कोई सम्बन्ध है। इस स्थिति को संघ के सभी नेताओं ने अनेक बार दुहराया है।

जनसंघ के सम्बन्ध में एक पहेली हमेशा से रही है, वह पहेली यह है कि आर० एस० एस०

या। दक्षिण में अपने प्रभाव को कायम करने का यह प्रयत्न आज भी जारी है, परन्तु इस प्रयत्न में उसे कोई विशेष सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। सम्भवतः इसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि दक्षिण के लोग उत्तर के 'हिन्दी साम्राज्यवाद' के विस्तार के विरुद्ध हैं। सभ के राजनीतिक और आर्थिक विचारों की जानकारी हम उसके 1971 के चुनाव घोषणा-पत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अतः यहाँ उसका संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है।

जनसभ ने अपने घोषणा-पत्र में असाम्प्रदायिक राज्य के प्राचीन आदर्श में आस्था व्यक्त की, परन्तु साथ ही में उसने उस 'छद्म धर्मनिरपेक्षता' को अस्वीकार किया जो अधर्म एवं तुष्टिकरण का सम्मिश्रण है। दल न केवल सहिष्णुता का समर्थक है, अपितु वह यह भी चाहता है कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर होना चाहिये। सभ ने जिस समतावादी समाज की परिकल्पना की है उसमें किसी के भी साथ जन्म, आनुवंशिकता, विरादरी अथवा धर्म के आधार पर कोई भी पक्षपात नहीं किया जायगा।

सभ ने मतदाताओं के समक्ष जो आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें निम्नलिखित बातें कही गई थी—

(i) मूल्यों को स्थिर रखने के लिये एक आयोग की स्थापना, जो मुनाफे की दर को नियन्त्रित करे तथा मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी करने वालों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था, (ii) उचित दामों की दुकानों की स्थापना, (iii) 10 प्रतिशत विकास दर को सम्भव बनाने के लिये एक स्वदेशी योजना तैयार करना, (iv) विदेशों से मिलने वाली समूची सहायता को बन्द करना, (v) कम्युनिस्ट देशों से साथ होने वाले व्यापार का राष्ट्रीयकरण, (vi) सम्पत्ति के अधिकार की सुरक्षा, (vii) तीन साल के भीतर सभी कुशल व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाना तथा शेष लोगों के लिये पाँच वर्ष के भीतर रोजगार की व्यवस्था करना, (viii) 14 वर्ष तक के बालकों के लिये मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना, (ix) प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, (x) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को मुआवजा दिलवाना, (xi) जम्मू और कश्मीर के संविधान को रद्द करना तथा उसका भारतीय सभ में पूर्ण विलयन करवाना, (xii) स्त्रियों के लिये समान अवसरों की व्यवस्था करना, (xiii) आकाशवाणी को एक स्वायत्तता प्राप्त निगम के रूप में संगठित करना, (xiv) अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना, (xv) विदेशी वंकों का राष्ट्रीयकरण, (xvi) समस्त विदेशी उपभोक्ता उद्योगों का भारतीयकरण, (xvii) छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन, (xviii) मजदूरों का प्रबन्ध में भाग, (xix) एक-सा सिविल कोड, (xx) आणविक शस्त्रास्त्र को तैयार करना।

1971 के चुनाव को लड़ने के लिए जनसभ ने कांग्रेस (संगठन), स्वतन्त्र पार्टी और ससोपा के साथ गठबन्धन किया। परन्तु इसके बावजूद चुनाव में उसे कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। 1967 में लोकसभा में उसे 35 सीटें मिली थीं। अब उसकी सीटें घटकर 22 रह गयीं।

सभ को इससे भी बुरे दिन उस समय देखने पड़े जब उसने मार्च 1972 में राज्य विधान-सभाओं का चुनाव लड़ा। 1967 के चुनाव में इन राज्यों में उसकी कुल सीटें 176 थीं और वह दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में शासक दल था, परन्तु इस बार उसकी सीटों की संख्या घटकर 105 रह गई तथा दिल्ली के ऊपर से उसका नियन्त्रण हट गया।

6 मई 1972 को सभ की जनरल कौन्सिल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया कि निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र चुनावों को कराने के लिये आवश्यक सुधार किये जायें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसने यह प्रस्तावित किया कि चुनाव के पहले मन्त्रियों को त्याग-पत्र दे देना चाहिये, तथा उनके द्वारा सरकारी वाहनों के प्रयोग पर पाबन्दी लगा देनी चाहिये, यदि यह सुविधा शासक दल को दी जाती है तो यह स्वीकृति विरोधी दलों को भी मिलनी चाहिये। उसने यह भी माँग की कि मतों की गणना मतदान-केन्द्रों के अनुसार होनी चाहिये तथा चुनाव आयोग का पुनर्गठन इन प्रकार होना चाहिये जिससे कि वह बहु-मदस्थीय समस्या बन सके।

साथ पूर्णतः अरुचि है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी की घोर विरोधी हो। स्वतन्त्र पार्टी के राजनीतिक दर्शन को मोटे तौर पर व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में वह राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का विरोध करती है उसका कहना है कि देश की अविकाश राजनीतिक बुराईयाँ 'परमिट-लाइसेंस कोटा' राज के कारण पैदा हुई हैं। यह ठीक है कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता इस बात से इनकार करते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण अहस्तक्षेप की नीति (laissez faire) का है, इस के बावजूद भी इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि उनके अनुसार राज्य को केवल 'रात्रिकालीन चौकीदार' की भूमिका अदा करनी चाहिये। 1962 के चुनाव घोषणा-पत्र में स्वतन्त्र पार्टी ने कहा था कि 'सरकार का काम शासन करना है, व्यापार करना नहीं।' फलतः स्वतन्त्र पार्टी नियोजित अर्थव्यवस्था को देश के लिये अहितकर मानती है। तीसरे चुनाव के पूर्व जारी किये गये घोषणा-पत्र में उसने योजना आयोग को खत्म करने की बात कही थी। उसने औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की सांभेदारी को गलत बताया है। उसके अनुसार इस सम्बन्ध में सरकार की भूमिका 'सहायक और नियन्त्रक की होनी चाहिए। सांभेदार की नहीं।' यद्यपि पार्टी ने अपनी नीतियों की घोषणा करते हुए जहाँ-तहाँ 'सामाजिक न्याय' का भी उल्लेख किया है, परन्तु इससे निजी औद्योगिक क्षेत्र के प्रति उसके पूर्वाग्रहों को छिपाया नहीं जा सकता। इसलिये यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पार्टी उद्योगों पर अधिक करो को आरोपित करने, घाटे की वित्तीय व्यवस्था तथा विदेशी ऋणों आदि का विरोध करती है। कृषि के क्षेत्र में पार्टी भूमि की हदबन्दी तथा सहकारी खेती का विरोध करती है। पार्टी सम्पत्ति के अधिकार की सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से सजग है, यही कारण है कि उसने 17वें, 24वें और 25वें सशोधनों की कटु आलोचना की है।

भारत की विदेश नीति की यदि किसी पार्टी ने सबसे अधिक आलोचना की है तो वह पार्टी स्वतन्त्र पार्टी है। उसके अनुसार गुट-निरपेक्षता, पञ्चशील और सह-अस्तित्व निरर्थक शब्द हैं। चीनी आक्रमण के उपरान्त से वह निरन्तर इस बात की माँग करती आयी है कि भारत को पश्चिम की गुट-बन्धियों में शामिल हो जाना चाहिये। वह पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सुधारने के पक्ष में है। इस सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व यह एक आम चर्चा का विषय था कि वह पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए उसे काश्मीर देने के पक्ष में है। परन्तु स्वतन्त्र पार्टी के नेताओं ने इस बात का खण्डन किया है।

1967 के आम चुनावों तक स्वतन्त्र पार्टी की उपलब्धियाँ कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं थी। 1962 के चुनावों में उसने लोकसभा में 22 सीटें जीती थी तथा राज्य विधान सभाओं में उसे 166 स्थान प्राप्त हुये थे। 1967 के चुनावों में उसे लोकसभा में 44 स्थान प्राप्त हुये थे। इस प्रकार वह देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी, राज्यों की विधान सभाओं में उसे 255 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी।

1969 में जब कांग्रेस में फूट उत्पन्न हुई तो स्वतन्त्र पार्टी ने उस फूट का स्वागत किया। रंगा और मसानी ने इसे 'अवश्यम्भावी' बताया और कहा कि यह फूट वास्तव में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी (मार्क्सवादी) के बीच फूट है। 15 नवम्बर 1969 को एक वयान में रंगा ने कहा कि यदि श्रीमती गांधी की सरकार को पराजित कर दिया जाता है तो यह सम्भव हो सकेगा कि वे आपस में मिलकर श्रीमती गांधी के गुट का विकल्प प्रस्तुत कर सकें। दिसम्बर 1969 में दल के अध्यक्ष मसानी ने कांग्रेस (संगठन), जनसंघ, प्रसोपा आर ससोपा के साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बातचीत भी चलाई। परन्तु यह बातचीत इसलिए सफल नहीं हो सकी, क्योंकि गुजरात में कुछ घटनाएँ ऐसी घटी जिनके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र पार्टी और कांग्रेस (संगठन) के बीच तनाव पैदा हो गया। कांग्रेस में फूट पड़ जाने के बाद गुजरात के मुख्य मन्त्री हितेन्द्र देसाई ने कांग्रेस (संगठन) का साथ दिया, परन्तु उनके काफी समर्थकों ने श्रीमती गांधी का समर्थन किया। गुजरात विधान सभा में स्वतन्त्र पार्टी विरोध की सबसे बड़ी पार्टी थी। गुजरात

। ॐ कृष्णाय नमः ।

12 14

न्यायान्न पश्यन्ति तं नार न जा रीक्ष ।

बुद्धिमान् ।

181

हुआ था। इस बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्य मन्त्री महामाया प्रसाद सिन्हा को दल का अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के डी० के० कुन्ते को महामन्त्री चुना गया था। दल ने गांधीवादी विचारधारा में अपना विश्वास घोषित किया। परन्तु भाक्रान्द की गांधीवाद में आस्था में हमें आधुनिकता दिखाई पड़ती है। गांधी जी की भाँति वह चर्खे पर बल नहीं देता, परन्तु वह कृषि के आधुनिकीकरण तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है। वह औद्योगीकरण का भी समर्थन करता है, किन्तु इसका सुभाव है कि विकास का क्रम नीचे से शुरू होना चाहिये, ऊपर से नहीं।

भारतीय क्रान्ति दल में आन्तरिक दृढ़ता का अभाव है तथा सर्वसाधारण के समर्थन का दावा नहीं कर सकता। इसका समर्थन करने वाले मुख्यतः सम्पन्न किसान हैं और चूँकि इस प्रकार के किसानों में कुछ विशिष्ट जातियों का ही वाहुल्य है, इसलिये सामान्यतः इस दल को इन्हीं जातियों का दल माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 1969 के मध्यावधि चुनावों में इसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी। इसका मुख्य श्रेय इसके संस्थापक नेता चौधरी चरणसिंह को है जिन्हें राज्य की राजनीति में उच्च जातियों के प्रभुत्व के विरुद्ध पिछड़ी और कृषक जातियों, विशेषतः जाटों, जहीरों और कुमियों को संगठित करने में कामयाबी प्राप्त हो गयी थी। इस दल की जड़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक इलाकों में विशेष रूप से पक्की हैं। 1967-68 में जब चरणसिंह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की सरकार गठित हुई थी और चीनी के दाम बहुत बढ़ गये थे, उस समय गन्ना-उत्पादकों ने 200 करोड़ रुपये कमा लिया था। फलतः 1969 के मध्यावधि चुनाव में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में उसे जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। इसे पिछड़ी और अनुसूचित जातियों का भी समर्थन प्राप्त था। परन्तु उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। इस चुनाव में उसने उत्तर प्रदेश विधान सभा में 98 स्थानों पर सफलता प्राप्त की तथा कुल मतों के 21.29 प्रतिशत मत उसके पक्ष में पड़े।

परन्तु 1971 के लोकसभा के चुनाव में इसे मुह की खानी पड़ी। ऐसा सम्भवतः इसलिये हुआ क्योंकि दल के नेता चौधरी चरणसिंह ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाकर आँका था। फलतः उन्होंने चुनाव को अकेले लड़ने का निर्णय किया, इसलिये उन्होंने न तो तय्यकथित 'महा गठबन्धन' (Grand Alliance) के साथ हाथ बँटाया और न सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ ही। इसका परिणाम यह हुआ कि दल के उम्मीदवारों को सभी जगह करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के फलस्वरूप लोकसभा में उसे केवल एक स्थान पर सफलता मिली, जबकि चुनाव के पहले पुरानी लोकसभा में उसके दस सदस्य थे। पराजित होने वाले उम्मीदवारों में चौधरी चरणसिंह भी शामिल थे। इससे भाक्रान्द की प्रतिष्ठा पर जबरदस्त चोट पहुँची। परन्तु 1974 के उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनाव में यह दल मुख्य विरोधी दल के रूप में उभर कर आया है।

अकाली दल—दूसरा क्षेत्रीय दल अकाली दल है जिसने पंजाब के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जमा की है। इसकी स्थापना प्रथम महायुद्ध के उपरान्त गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन के रूप में हुई थी। इस संगठन के माध्यम से सिक्खों ने गुरुद्वारों पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये आन्दोलन किया था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त इस दल ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिये आन्दोलन किया। दल के नेता के रूप में सन्त फतहसिंह के अभ्युदय के पूर्व मास्टर तारामिह दल के सबसे प्रमुख नेता थे। स्पष्टतः दल का प्रभाव केवल पंजाब तक सीमित है और पंजाब में भी वह केवल सिक्खों की अपने प्रति निष्ठा का दावा कर सकता है। इस आधार पर अकाली दल को एक साम्प्रदायिक संगठन घोषित किया जा सकता है। वस्तुतः दल के उग्रवादियों ने पंजाबी सूबा के स्थान पर 'सिक्ख-ग्रह-राज्य' (Sikh-Homeland) की माँग की है, जिसमें उसका साम्प्रदायिक स्वरूप भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है।

अकाली दल सदैव में गुटबन्दी से ग्रसित रहा है। जब तक मास्टर तारामिह जीवित थे तब तक एक गुट का नेतृत्व उनके हाथ में था और दूसरे का सन्त फतहसिंह के हाथ में।

सकी थी। लोकतान्त्रिक दल ने इस चुनाव में 200 से अधिक प्रत्याशी खड़े किये थे और उसे एक भी स्थान पर कामयाबी नहीं मिली थी। यही बात स्वतन्त्र पार्टी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। उसने लगभग 300 स्थानों पर चुनाव लड़ा था और उसे केवल एक स्थान पर सफलता प्राप्त हुई थी। सच बात यह है कि भारतीय लोकदल में शामिल सभी घटक निराशा की भावना से ग्रसित थे और इस निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने जो तरीका सोचा वह यह था कि वे सब अपना विलयन एक नये दल में कर दें।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकदल की रचना कांग्रेस के मुकाबले में एक विकल्प प्रस्तुत करने की दृष्टि से की गई थी, कम से कम लोकदल के संस्थापकों ने इस आशय का दावा अवश्य किया था। परन्तु यहाँ प्रश्न है कि क्या परम्पर-विरोधी विचारधाराओं को लेकर सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध विकल्प का निर्माण किया जा सकता है? लोकदल में जो घटक शामिल हुए थे उनमें सबसे प्रमुख भाक्रान्द और उत्कल कांग्रेस थी। ये दोनों क्षेत्रीय दल थे और इनका उद्गम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से ही हुआ था। भाक्रान्द सम्पन्न किसानों की पार्टी थी और उसका उद्देश्य सत्ता में सम्पन्न किसानों को साझादारी दिलाना था। उत्कल कांग्रेस उड़ीसा के नवोदित पूँजीपति वर्ग की पार्टी थी। ससोपा अपने को समाजवाद के आदर्श के प्रति प्रतिबद्ध बताती थी। स्वतन्त्र पार्टी देश में उन्नीसवीं शताब्दी में पायी जाने वाली लेसेज फेयर (laissez faire) व्यवस्था कायम करवाना चाहती थी। मुस्लिम मजलिस मुसलमानों की एक साम्प्रदायिक पार्टी थी। लोकतान्त्रिक दल का उद्गम भारतीय जनमध से था और उसके नेता बलराज मधोके ने 'इस्लाम के भारतीयकरण' का नारा देकर अपने दृष्टिकोण को भली भाँति व्यक्त कर दिया था। भारतीय खेतीहर सघ इस पूरे जमघट में एक नगण्य घटक था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय लोकदल में जो दल शामिल हुए उनकी कोई सुस्पष्ट विचारधारा नहीं थी। हाँ, एक बात पर उनके बीच कोई मतभेद नहीं था और वह बात यह थी कि सारा विपक्ष एक साथ रहे ताकि सरकार का विकल्प देश में पैदा हो।

अगस्त 1974 में दल की नीतियों की घोषणा करते हुए कहा गया कि वह कृषि, कुटीर और लघु-उद्योग-धन्धों के विकास को बड़े और भारी उद्योग-धन्धों के विकास की अपेक्षा प्राथमिकता देगा। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दल, किसानों को ऋण, सम्मुन्नत बीज, खाद तथा सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। दल बड़े किसानों से उत्पादन का एक भाग 'लेवो' के तौर पर वसूलने की नीति का भी समर्थन करता है, परन्तु उसका विश्वास है कि शेष अनाज का व्यापार अनाज के व्यापारियों के द्वारा स्वतन्त्र रूप से चलना चाहिए।

अगस्त 1974 में अपने जन्म के बाद भारतीय लोकदल ने हरियाणा के एक उप-चुनाव में सफलता प्राप्त की तथा गुजरात विधान सभा के 1975 के चुनावों में उसने गैर-कम्युनिस्ट दलों द्वारा निर्मित 'जनता मोर्चा' के घटक के रूप में हिस्सा लिया और उसे दो स्थानों पर सफलता मिली। वस्तुतः भारतीय लोक दल की रचना के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक दल है। केवल दो ही राज्य ऐसे हैं जहाँ उसका जन-आधार है और वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। उसका थोड़ा प्रभाव हरियाणा और राजस्थान में भी पाया जाता है।

प्रश्न

- 1 भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताएँ बताइये।
- 2 कांग्रेस में पाई जाने वाली गुटबन्दी ने देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है।
- 3 भारतीय लोकदल पर टिप्पणी लिखिए।

दबाव समूह (PRESSURE GROUPS)

पिछले वर्षों में दबाव समूहों का महत्त्व में अत्यधिक वृद्धि आई है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि औद्योगिक अथवा परम्परागत समाज में हिंसापूर्ण समुदायों में गठन असंगठित रहते हैं तथा उनका प्रभाव में समाज के औद्योगीकरण के बाद ही वृद्धि होगी। भारत के संदर्भ में भी यह बात पूर्ण रूप से सही है।

परम्परागत समाजों में 'गोत्र' का मुख्य उद्यम कृषि होता है तथा इसमें मुख्य सामाजिक ऋद्धि परिवार और परिवार के प्रकार के समुदाय (जहाँ सदस्यों के पारम्परिक सम्बन्धों में समानता होती है) होता है। आधुनिक समाज की रचना तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप हुई है। उसके विकास के साथ-साथ और अव्यक्त सगठनों का भी उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार के सगठनों में ट्रेड यूनियन व्यापारिक और औद्योगिक सगठन शामिल शामिल हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परम्परागत समाज में किसी भी प्रकार के दबाव समूह नहीं होते हैं किन्तु उनका क्षेत्र कबन परिवारों की पारम्परिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित रहता है। आधुनिक समाजों में वे उस प्रक्रिया का एक अंग हैं जिसके द्वारा सगठित समुदाय प्रतियोगी दबाव का प्रस्तुत करते हैं और देश के राजनीतिक ढाँचे के अंतर्गत उनका सामान्य खोजने का प्रयास करते हैं।

भारतीय समाज में परम्परावाद एवं आधुनिकता का अद्भुत सम्बन्ध हुआ है। जहाँ जहाँ यह एक तरफ पश्चिम जैसे दबाव समूह पाये जाते हैं तो एक समूहों की भी कमी नहीं है जिनका मुख्य उद्देश्य परम्परावादी है। इस प्रकार के समूहों में साम्प्रदायिक सगठनों तथा जाति विरादरी पर आधारित समुदायों का समावेश होता है। जहाँ यह स्पष्ट है कि भारत के दबाव समूहों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे दबाव समूह आते हैं जिन्हें धर्म, जाति, कुलीनता अथवा भाषा के परम्परागत ढाँचे के आधार पर संगठित किया गया है। दूसरी श्रेणी में उन समूहों का समावेश होता है जिनकी उत्पत्ति समाज के आधुनिक कला के उदय के कारण हुई है जहाँ उद्योग अथवा विश्वविद्यालय।

1. परम्परावादी दबाव समूह

अपना विभिन्नता तथा आंतरिक सगठन के अभाव के बावजूद हिन्दू धर्म में सारा दबाव समूहों में सबसे अधिक गतिशीलता—कुछ लोग उस अनुभव की कह सकते हैं—दबाव समूह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जन्म दिया है जो अपनी सन्देश सत्या 10 गाँव बताता है। यह बात किसी को छिपी नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिन्दू समाज तथा हिन्दू संस्कृति के हितों का रक्षा तथा हिंदी को उचित स्थान प्रदान के लिए काम करता है। जनसंघ के साथ उनके सम्बन्ध भी निम्नांकित छिपे नहीं हैं। वह उसके माध्यम से अपने राजनीतिक उद्देश्यों का प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यथायथ में जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई विरोध अन्तर नहीं है यदि अन्तर है तो कबन इतना ही है जो एक स्वामी का देखरेख में चलने वाली दाँतों का दुकानों के बीच होता है जिन पर भिन्न भिन्न वस्तुओं को बचा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कथनानुसार जनसंघ की दुकान पर राजनीति बचत है और अपनी पुरानी दुकान पर संस्कृति। फलतः एक की गणना राजनीतिक दाना में होती है और दूसरे की दबाव समूहों में।

इसी श्रेणी में ऐसे सगठनों को भी गिनाया जा सकता है जो विशिष्ट धार्मिक समूहों के हितों के लिए काम करते हैं। भारतीय ईसाइयों के अखिल भारतीय सम्मेलन, पारसी सेन्ट्रल एसोसियेशन एण्ड पोलिटिकल लीग, एंग्लो-इण्डियन एसोसियेशन, आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म रक्षिणी सभा आदि को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। जाति समूह भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, जैसे हरिजन सेवक सघ, मारवाड़ी एसोसियेशन, वैश्य महासभा, जाट सभा, त्यागी सभा आदि। ये सभी समुदाय भारत की साम्प्रदायिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों के समूह सरकार पर अपने हितों की रक्षा के लिए बराबर दबाव डालते आये हैं। उसी के फलस्वरूप संविधान में 23वाँ संशोधन हुआ है जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आरक्षित स्थानों की व्यवस्था फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इस समूह ने समय-समय पर यह भी प्रयत्न किया है कि उनके प्रमुख नेता, जैसे जगजीवन राम को (केन्द्र में) और गिरधारी लाल को (उत्तर प्रदेश में) प्रधानमंत्री अथवा मुख्य मंत्री बनाया जाय।

तमिलनाडु के सन्दर्भ में नाडार कास्ट एसोसियेशन (Nadar Caste Association) का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। 1965 में उसकी सदस्य-संख्या 20 हजार से अधिक थी और उसके वार्षिक अधिवेशन में 5000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1952 के प्रथम चुनाव के बाद से ही नाडार एसोसियेशन कांग्रेस का समर्थन करता आया है। वस्तुतः 1968 के नागरिकों के उपचुनाव में कामराज की जीत को नाडार जाति के समर्थन सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। भारत में, जहाँ राजनीति जाति-विरादरी से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित होनी है, इन विरादरियों के समूहों की मतदान के समय निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म और जाति-विरादरी का राजनीति में इस प्रकार का हस्तक्षेप भारतीय लोकतन्त्र के लिए निस्सन्देह अशुभ है। परन्तु यह हमारे देश के राजनीतिक जीवन का एक कटु यथार्थ है, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता।

2 आधुनिक दबाव समूह

आधुनिक दबाव समूहों के अन्तर्गत व्यापारिक एवं औद्योगिक हित समूहों, कृषि-सम्बन्धी हित समूहों, विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध समुदायों तथा प्रशासकीय कर्मचारी समूहों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ इनकी संक्षिप्त विवेचना आवश्यक है।

(1) व्यापारिक एवं औद्योगिक हित समूह—भारत में व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में हित समूहों का इतिहास 19वीं शताब्दी में उस समय से आरम्भ किया जा सकता है जबकि 1830 में ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए चेम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की। भारतीय व्यापारियों ने इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स की रचना 1885 में की। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही इस दबाव समूह का जन्म हुआ। भारतीय व्यापार के अधिकृत इतिहास में इस सम्बन्ध में लिखा है—‘यह कोई पूर्णतः आकस्मिक बात नहीं है क्योंकि आने वाले वर्षों में स्वशासन के लिए राजनीतिक आन्दोलन का प्रतिभाग (counterpart) उस आर्थिक आन्दोलन में हुआ जो भारतीय उद्योग-वन्धों को प्रोत्साहन देना चाहता था।’

1926 में फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज (F I C C I) की स्थापना हुई। 1931 में स्वयं गांधी जी ने फेडरेशन की वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया तथा फेडरेशन ने जनेक अवसरों पर ऐसे प्रस्ताव पारित किये जिनके द्वारा उसने राजनीतिक मामलों में गांधी जी के नेतृत्व का समर्थन किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फेडरेशन की स्थापना औपनिवेशिक काल में इसलिए हुई थी ताकि भारतीय उद्योगपतियों की ब्रिटिश शासकों द्वारा बोये गये अपमानों और भेदभाव की नीति के विरुद्ध रक्षा की जा सके। फेडरेशन ने मोटे तौर पर राष्ट्रीय आन्दोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। वस्तुतः ऐसा करना उसके अपने हित में था

वशाकि देश की स्वतंत्रता भारतीय उद्योगपतियां व निर्यात उद्योगों का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी।

स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरान्त फेडरेशन का प्रभाव और शक्ति तथा म वृद्धि हुई है। 1961 में फेडरेशन के सदस्य निकाया की संख्या 137 या और 286 एमामिपेट सदस्य व जिनमें सभी बड़ी फर्मों के संगठन भी शामिल थे जिनमें हिंदुस्तान माटम स्वच्छी मिंस तथा टाटा आयरन एंड स्टील।

फेडरेशन के मुख्य निम्नलिखित हैं—आंतरिक और विदेशी व्यापार परिवहन उद्योग कारखाना में प्रती प्रस्तुता वित्त एवं अन्य आर्थिक विषया में भारतीय व्यवसायों को प्रोत्साहन देना व सभी विषयों के बारे में संगठित कार्य करना तथा पूर्वांक आर्थिक हितों को प्रभावित करना वान विधायन अथवा अन्य कार्य को प्रोत्साहन देना उमका समयन अथवा विचार करने के लिए सभी आवश्यक उदम वव उपाया के अंतर्गत उठाना।

फेडरेशन के अतिरिक्त देश में दो अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन पाये जाते हैं जिनके नाम हैं—आन इंडिया मनुफ़क्चरर्स एसोसिएशन तथा एमामिपेट चम्बरस आफ़ कामर्स आफ़ इंडिया। परंतु इन दोनों में से कोई भी फेडरेशन जैसा प्रभावी नहीं है हालांकि वे फेडरेशन की गतिविधियों के पूरक अंग हैं। आन इंडिया मनुफ़क्चरर्स एसोसिएशन देश के छान उद्योगपतियों का संगठन है तथा एमामिपेट चम्बरस आफ़ कामर्स विदेशी पूंजीपतियों का।

उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय व्यापारिक संगठनों के कार्यक्रम के साथ राज्याय आर्थिक व समय में ही अच्छे सम्बन्ध थे। स्वतंत्रता के बाद कार्यक्रम ही सत्ताह्वित हुए जिनमें फेडरेशन और कार्यक्रम के बीच पुराने सम्बन्ध बने रहे। फेडरेशन के संस्था में चुनाव न करने के लिए कांग्रेस का काफी चर्चा दिया और इस प्रकार उन्होंने सरकार की नीतियों का अपन पक्ष में प्रभावित किया। वस्तुतः एक नये समय तक कार्यक्रम कायमकारी साथ और समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के लिए व वास्तविक देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पनपाती रही। इसके मूल में मुख्य बात यही रही कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ नए बड़े घनिष्ठ सम्बन्ध थे। कांग्रेस के नेताओं ने नए माध्यमों से नए समय का उचित भी ठहराया। उदाहरण के लिए जिन सम्पत्तियों और व्यापारिक संस्थानों द्वारा राजनीतिक पार्टियों का चढ़ा देने पर पाबंदी लगाने का विधेयक प्रस्तुत करते हुए भूषण गुप्त ने राज्य सभा में यह कहा कि कांग्रेस पार्टी आज कच्छर में खड़ी है। यदि वह हम प्रस्ताव का स्वीकार नहीं करती तो बात समूह ममारों का वित्त हो जायेगी कि वे अपना राजनीतिक स्थिरता के लिए टांग के करों की सम्पत्ति पर निर्भर करते हैं तो उसका उत्तर नते हुए नागवहानुर शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस ने नगमा चार हजार उम्मीदवार खड़े किये थे और उनमें से कुछ को छोड़कर जिनके पर्याप्त साधन थे उनमें से सभी उम्मीदवारों के लिए धन सौजना था और यदि उस धन की खोज करनी है तो उस चर्चा भी करना है। जब किसी ने यह पूछा कि समाजवादी ढांचे के समाज का क्या हुआ तो शास्त्री जी ने क्या उद्योगपतियों में राजनीतिक समझ है और यदि वे अपने हिस्सेदारों तथा साधारण सम्पत्तियों की बैठक के परामर्श से कुछ राजनीतिक दलों को चर्चा देने का निश्चय करते हैं तो मैं नहीं जानता कि हमसे हम अपनी अधिक परगानी क्या होती है? जो भी हो इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि व्यापारिक संगठनों ने एक नये समय तक सरकार की नीतियों को प्रभावित किया है और आज भी यह बात नगमा बहरी जा सकती कि सरकार अब उनके प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है।

1972 में देश के पूंजीपतियों की ओर से जिनमें टाटा प्रमुख है एक स्मृतिपत्र सरकार को दिया गया था जिसमें यह मुझाव दिया गया था कि सरकार और निजी पूंजीपतियों को मिलकर संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector) में उद्योग वव स्थापित करने चाहिये। इस स्मृतिपत्र का सरकार ने नेताओं पर प्रभाव न पड़ा तो ऐसा बात नहीं है। उदाहरण के लिए कार्यक्रम के अहमतागत अधिवक्ता में वन्तीय में श्री मुद्राहण्यम ने इस मुझाव का समर्थन किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यापारिक और औद्योगिक दलों के समूहों की भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में एक

महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

(2) ट्रेड यूनियन—भारत में ट्रेड यूनियनों का संगठन प्रथम महायुद्ध के बाद से शुरू हुआ। आरम्भ में कांग्रेस के अनेक नेताओं का ट्रेड यूनियन आन्दोलन के साथ सम्बन्ध था। उदाहरण के लिए 1920 में जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बाद के वर्षों में इस पद को सुशोभित करने वाले अन्य कांग्रेसी नेता थे—चित्ररंजन दास, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस।

अपने आरम्भिक वर्षों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने जो मांगें प्रस्तुत कीं, वे यद्यपि मूलतः आर्थिक थीं तथापि उनके राजनीतिक स्वरूप की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहुधा लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन राजनीति में हस्तक्षेप करता है जो अव्याजनीय है। इस प्रकार के लोगों की मान्यता है कि इस गलत प्रवृत्ति के लिए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट उत्तरदायी हैं। जब से ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर इन लोगों का नियन्त्रण कायम हुआ है तभी से इस प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। परन्तु यह बात सत्य के विलकुल विपरीत है। सत्य यह है कि भारत में ट्रेड यूनियन आन्दोलन का सूत्रपात ही राजनीतिक नेताओं ने किया था। उसका उद्देश्य भी राजनीतिक था, ट्रेड यूनियन नेता उस राजनीतिक आन्दोलन को व्यापक आधार प्रदान करना चाहते थे, जिसमें वे स्वयं शामिल थे, ताकि राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण के समय सत्ता गोरे साहबों के हाथ से निकलकर काले साहबों के हाथों में न चली जाये। राजनीतिक नेताओं में गाँधी जी का दृष्टिकोण इससे भिन्न था। उनका कहना था कि जब तक मजदूरों में अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता पैदा न हो जाये, उन्हें राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। अतः उनके निर्देश के अनुसार अहमदाबाद में एक आन्दोलन संगठित हुआ जिसे मजूर महाजन का नाम दिया गया। इसने अपने आपको राजनीति से एक लम्बे समय तक दूर रखा, किन्तु जब 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ हुआ तब यह संगठन अपने आपको उस आन्दोलन से अलग नहीं रख सका। उस समय आन्दोलन के समर्थन में इसने अहमदाबाद में हड़तालों को संगठित किया। स्वतन्त्रता के उपरान्त इस संगठन ने अपने राजनीतिक स्वरूप को कायम रखा। आज मजूर महाजन के कार्यकर्त्ता इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं और उन्हें राजनीति में भाग लेने से लेशमात्र भी सकोच नहीं है।

राजनीतिक नेताओं का ट्रेड यूनियनों में भाग लेने का एक परिणाम यह हुआ कि आज ट्रेड यूनियन आन्दोलन पूर्णतः विभक्त है तथा उसकी एकता नष्ट हो चुकी है। इस प्रकार भारत में लगभग सभी राष्ट्रीय पार्टियों की अपनी-अपनी ट्रेड यूनियन हैं और इन ट्रेड यूनियनों में आपस में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। कम्युनिस्टों का आल-इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर नियन्त्रण है, कांग्रेस के प्रभाव में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, हिन्दू मजदूर सभा को सोशलिस्ट नियन्त्रित करते हैं, मार्क्सवादी पार्टियों का प्रभाव सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन पर है तथा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टियों आदि छोटे वामपंथी दलों ने भी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन की रचना कर ली है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस दौड़ से जनसंघ भी अलग नहीं है, उसका भी एक ट्रेड यूनियन संगठन है जिसे उन्होंने भारतीय मजदूर संघ का नाम दिया है।

ट्रेड यूनियनों का देश की राजनीति पर काफी प्रभाव रहा है, विशेषकर ऐसे नगरों और क्षेत्रों में जहाँ संगठित मजदूरों की बड़ी संख्या रहती है। देश की औद्योगिक एवं श्रमनीतियों के निर्माण में उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है परन्तु उनका यह प्रभाव उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसका मुख्य कारण उनकी पारस्परिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। उनके आपस में सम्बन्ध अत्यधिक कटू रहे हैं और उन्होंने किसी ऐसी आचरण संहिता को भी विकसित नहीं किया है जिससे समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकें। अनेक बार उनमें एकता कायम करने के प्रयास भी किये गये हैं, किन्तु यह एकता केवल उस समय तक कायम रही है जब तक उनमें सम्बद्ध राजनीतिक दलों के लिए एकता कायम रखना उपयोगी था।

निस्सन्देह इस स्थिति का वांछनीय नहीं कहा जा सकता। अतः सका निराकरण करने के लिए यह जाव यह है कि टड यूनियन आन्दोलन को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी से मुक्त करने का प्रयास किया जाय।

(3) किसान संगठन—भारत अपि प्रधान रूप से और देश की जनसंख्या में मजदूरों की अपेक्षा किसानों की संख्या बहुत अधिक है। परन्तु टड यूनियनों की स्थापना पहले से किसान संगठन प्राप्त लाभ में स्थापित हो सक। 1920 के बाद गांधी जी ने किसानों के स्थानीय आन्दोलनों को संगठित किया और आन्दोलनों में बिहार में चम्पारन और गुजरात में धारवाड़ों के सत्याग्रहों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आन्दोलनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय किसान आन्दोलन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो गया।

1930 के वाणिक्य कायम की राजनीति अधिक उग्र हो गई। 1931 में कायम ने मूल अधिकारों का एक चार्टर तैयार किया जिसमें स्वस्थ की हस्तक्षेप प्रस्तुत की गयी। इसमें किसानों की स्थिति को सुधारने पर ध्यान दिया गया था। अतः इस सन्दर्भ में यह आवश्यक था कि कायम के कार्यकर्ताओं का ध्यान किसान आन्दोलनों को संगठित करने की ओर जाता। फलस्वरूप 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जन्म हुआ। किसान सभा में काम करने वाले कायसी सामान्यतः समाजवादी और कम्युनिस्ट जैसी वामपंथी विचारधारा के ही लोग थे। इसलिए आरम्भ में ही किसान सभा वामपंथी संगठन रहा। आन्तरिक मतभेदों के कारण कम्युनिस्टों का पूर्ण नियंत्रण स्थायमान हो गया। अखिल भारतीय किसान सभा की राष्ट्रीय संगठनात्मक संरचना के रूप में संगठित किया गया है।

किसान सभा पर कम्युनिस्टों का प्रभाव स्थापित होने के कारण समाजवादियों ने अपना अलग किसान संगठन कायम कर लिया। उन्होंने उस हिंदू किसान पंचायत का नाम दिया। कुछ दिनों बाद छोट्ट वामपंथी दलों ने भी एक अखिल भारतीय किसान संगठन को जन्म दिया जिसका नाम युनाइटेड किसान सभा का नाम दिया। हरित क्रांति के सन्दर्भ में जब जाति विरोधों के नाम पर बड़े सम्पन्न किसानों ने अखिल मूल मजदूरों का मतान्तर आरम्भ कर लिया तो कम्युनिस्टों ने खेत मजदूरों का 1968 में एक अलग संगठन कायम कर लिया जिसका नाम अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का नाम दिया। इस प्रकार कम्युनिस्टों का प्रभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में दो संगठन काम कर रहे हैं—किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन। इन ग्रामीण संगठनों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि मजदूर संगठनों में सबका भिन्न-भिन्न प्रभाव देश की राजनीति पर अनेक व्यापक नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। इसका कारण यह है कि दलालों में जाति विरोधों की भावना गुटबाजी तथा आर्थिक असमानता की चेतना अनेकों अधिक है कि वाणिज्यिक संगठन उचित रूप में काम नहीं कर पा रहा।

(4) विद्यार्थी संगठन—भारत में संगठित विद्यार्थी आन्दोलन का सुरुवात भी औपनिवेशिक शासन में ही हुआ गया था। प्रस्तुत 1936 में अखिल भारतीय विद्यार्थी फोरम की स्थापना के पूर्व से के अनेक प्रांतों में नौजवानों की संगठनात्मक और उच्च राष्ट्रीय आन्दोलन के सर्वाधिक सक्रिय नेता महर्षि जी का पथ प्रदर्शन प्राप्त था।

1939 में जब तृतीय महायुद्ध का आरम्भ हुआ तो उस समय विद्यार्थी फोरम पर कम्युनिस्टों का प्रभाव स्थापित हो गया। यद्यपि उस समय देश के नौजवानों का गांधी जी की युद्ध में सम्बन्ध में अनेक नीति समझ में नहीं आ रही थी। 1945 में कायम के प्रभाव में अखिल भारतीय स्टूडेंट काँग्रेस की स्थापना हुई। आन्तरिक मतभेदों के कारण समाजवादियों ने भा. समाजवादी युवजन सभा की रचना कर ली। यद्यपि समय के परिवर्तन कायम के प्रभाव में एक नये अखिल भारतीय संगठन की स्थापना हुई जिसमें नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स का नाम दिया गया। जनसंख्या के प्रभाव में विद्यार्थी परिषद् संगठन का उदय हुआ है।

विद्यार्थी संगठनों ने जहाँ विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं पर आन्दोलन किया है वहाँ से ही अन्य समस्याओं के प्रति भी उन्होंने उदासीनता नहीं लियी है। उदाहरण के लिए उन्होंने

वेरोजगारी, विश्वशान्ति, वियतनाम मे युद्ध-वन्दी आदि अनेक मसलो पर छात्रो को आन्दोलित किया है। इससे स्पष्ट है कि भारत का विद्यार्थी वर्ग राजनीतिक चेतना मे किसी से कम नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के सभी विद्यार्थी सगठन राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा के केन्द्र बने हुए हैं। फलतः विद्यार्थी राजनीतिक दलबन्धियों मे आवश्यकता से अधिक भाग लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों मे बड़े पैमाने पर अव्यवस्था पाई जाने लगी है।

(5) महिला सगठन—देश मे स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लम्बे समय से महिलाओं के सगठन सक्रिय रहे हैं। उनमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (All India Women's Conference) है। कुछ समय तक उस पर कम्युनिस्टों का प्रभाव रहा, परन्तु बाद मे वह गैर-कम्युनिस्टों के प्रभाव मे आ गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्त्री-समाज के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना तथा उनकी कानूनी व सामाजिक स्थिति को सुधारना है। जब ससद के समक्ष हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत था तो उस समय इस सगठन ने दवाव समूह के रूप मे सक्रिय भूमिका अदा की थी।

(6) प्रशासकीय कर्मचारी समूह—अपने हितों की रक्षा के लिए तथा अपने कार्यों मे सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मचारियों ने भी अपने-अपने सगठनों की स्थापना की है। इस प्रकार के सगठनों मे आल इण्डिया रेलवेमैन फेडरेशन, आल इण्डिया पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ वर्कर्स यूनियन, आल इण्डिया बैंक एम्प्लॉयीज एसोसियेशन, आल इण्डिया यूनिवर्सिटी कालेज टीचर्स एसोसियेशन आदि महत्वपूर्ण हैं। इन सगठनों ने सरकार को अनेक बार अपनी नीतियों को कर्मचारियों के पक्ष मे निर्मित करने के लिए बाध्य किया है।

• दवाव समूहों की कार्यविधि

जैसा कहा जा चुका है कि इन दवाव समूहों का प्रमुख कार्य अपने हितों का संरक्षण और उनकी वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे अनेक उपाय काम मे लाते हैं—कभी-कभी इन उपायों से कानून की सीमाओं का भी अतिक्रमण हो जाता है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय मे देश ने गांधी जी से विदेशी नौकरशाही के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सत्याग्रह की तकनीक सीखी थी। भारत के आधुनिक दवाव समूहों ने न केवल सत्याग्रह की परम्परा को कायम रखा है, अपितु उन्होंने उसे विकसित भी किया है। वस्तुतः उनकी कार्य-प्रणाली मे जहाँ देश के राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत के तत्त्व मौजूद हैं वहाँ उनमे वे तत्त्व भी पाये जाते हैं जिन्हें पश्चिम के दवाव समूह काम मे लाते हैं। उनके द्वारा अपनाये जाने वाले उपायों को निम्न प्रकार गिनाया जा सकता है

(1) लोबीइंग (Lobbying)—इस तरीके का प्रयोग सबसे पहले अमरीकी दवाव समूहों ने किया था। इसके माध्यम से दवाव समूह प्रशासकीय अधिकारियों, विशेषतः विधानमण्डल के सदस्यों पर प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न करते हैं। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इनका कार्य विधानसभाओं के सत्तावसान के बाद समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत ये समूह अपना कार्य निरन्तर करते रहते हैं। उनका काम प्रशासकीय अधिकारियों तथा सामान्य जनता को भी प्रभावित करता है—प्रशासकीय अधिकारियों को इसलिए क्योंकि कानून और अधिनियमों की व्याख्या उन्हीं के द्वारा होती है और सामान्य जनता को इसलिए क्योंकि जनता द्वारा उनके दृष्टिकोण का समर्थन उन्हें सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करा सकता है।

(2) व्यापक प्रचार—दवाव समूह प्रचार के सभी साधनों को काम मे लाते हैं। लेखन, प्रकाशन, भाषण, सभाओं का आयोजन आदि उसके समान माध्यम हैं। पत्र-पत्रिकाओं एवं लेखों के माध्यम से ये जनता को अपने दृष्टिकोण से ज्वलंत कराते हैं। जनमत को प्रभावित करने मे उनका लक्ष्य निर्वाचन मे ऐसे दलों जयवा उम्मीदवारों की सफलता होती है जो उनके विशिष्ट

हिता के संरक्षण का ज़ाबामन है। यह स्पष्ट है कि ये चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते। ये कब-कब समय-समय पर दत्ते हैं और प्रचार हेतु ये कार्यकर्ता और आर्थिक सहायता भी दत्त है।

(3) हड़ताल धिरेव बंद और प्रदर्शन—प्रशासन को अपने दृष्टिकोण के पक्ष में नियंत्रण कराने के लिये ये प्रदर्शन हड़ताल बन्द और धिरेव का भी सहारा लेते हैं। हड़ताल और प्रदर्शन का प्रयोग तो राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में ही शुरू हो गया था। धिरेव और बन्द मध्य की नई तकनीक है जिनका प्रयोग माट तौर पर 1967 के बाद से शुरू हुआ है। इन माध्यमों से दबाव समूहों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने है। प्रथम अमृतोष की अभिव्यक्ति और द्वितीय अपने पक्ष में लोकमत का निर्माण। यदि अपने पक्ष में लोकमत को निर्मित करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो यह जागा की जा सकती है कि लोकमत के दबाव से अपनी मांगों को पूरा कराने में भी उन्हें सफलता मिल सकती है।

(4) 'वायपालिका' की शरण—कभी-कभी दबाव समूह विधानमण्डल द्वारा पारित किये गए विधेयकों को रद्द करवाने के लिए अथवा वायपालिका द्वारा निर्मित किसी ऐसी नीति को अवरोध घोषित करवाने के लिए जिनसे उनके किसी हित पर आघात पड़ सकता है 'वायपालिका' की भी शरण लेते हैं। पिछले वर्षों में वक्ता के राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पक्ष और विनापाधिकार विधेयक राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध ऐसे ही समूहों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गयी थी।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि दबाव समूहों और राजनीतिक दलों में अन्तर है। यह सत्य है कि भारत में ये दबाव अभी उस प्रकार विकसित नहीं हुए हैं जिस प्रकार वे पश्चिम के देशों में विकसित हैं। यहाँ नहीं भारत में इनके सम्बन्ध में इस समय तक कोई आचार संहिता (rule of the game) भी नहीं बन सकी है। फलतः ये समूह किसी भी प्रशासकीय नीति अथवा वाय को प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए आम तौर पर प्रत्यक्ष कार्यवाही का सहारा लेते हैं। फलस्वरूप समूह दश में जायदैन दंग और उपन्व होन रहते हैं। कुछ लोगो का कहना है कि ये उपन्व राष्ट्रीय आन्दोलन की विरामत है। एक सीमा तक यह बात सही भी हो सकती है परन्तु अधिक सही बात यह है कि देश में जनसमस्या तो बहुत है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन बहुत कम। ऐसी स्थिति में अमृतोष का अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। यहाँ नहीं याचिका अधिकारी जनता की मांगों की उपस्था करते हैं तो उस स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि अमृतोष की अभिव्यक्ति उग्र रूप से हो।

प्रश्न

1. भारत में दबाव समूहों का वर्गीकरण कीजिए।
2. भारतीय दबाव समूहों ने राजनीति को प्रभावित करने के लिए कौन-कौन सी कार्यविधि को अपनाया है ?

भारतीय लोकतन्त्र की समस्याएँ (PROBLEMS OF INDIAN DEMOCRACY)

1 जातिवाद (Casteism)

‘भारतीय समाज एक परम्परावादी समाज है, परन्तु लोकतन्त्र एक आधुनिक अवधारणा है जो अपने सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ ऐसी बातों की अपेक्षा करती है जिनका परम्परावादी समाज की मान्यताओं के साथ कोई मेल नहीं हो सकता। जातिवाद उन्हीं बातों में से एक है। यहाँ उसकी संक्षिप्त विवेचना आवश्यक है।

(यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत की सामाजिक पद्धति का संगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है। परन्तु जब हम जाति और राजनीति के अन्तर्सम्बन्धों की विवेचना करते हैं तो सामान्यतः हम गलत प्रश्न से अपने अध्ययन का आरम्भ करते हैं—‘क्या जाति-प्रणाली का लोप हो रहा है?’ वस्तुतः इसके स्थान पर जो प्रश्न होना चाहिये वह यह है कि राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति किस प्रकार का रूप धारण कर रही है तथा जाति-ग्रस्त समाज में राजनीति का क्या रूप है? जो भारतीय राजनीति में जातिवाद की उपस्थिति की शिकायत करते हैं, वे वास्तव में इस प्रकार की राजनीति की कल्पना करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। इन लोगों को न तो राजनीति के सम्बन्ध में सही समझ है और न जाति-प्रणाली के। वास्तव में लोकतान्त्रिक राजनीति के अन्तर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है जिससे उससे सम्बद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन प्राप्त कर सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। जिस समाज में जाति को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण संगठन माना जाता है, उसमें यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि राजनीति इस संगठन के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं, वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। जब राजनीति में जाति की अभिव्यक्ति होती है तो उसके माध्यम से जाति और रक्त सम्बन्धों पर आधारित समुदाय अपने लिए राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होते हैं। राजनीतिक नेता जाति समुदायों को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन से उन्हें सत्ता तक पहुँचने में सहायता मिल सके। यदि राजनीतिक नेताओं को अपने लिये समर्थन प्राप्त करने के लिए जाति समुदायों के अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार के समुदाय उपलब्ध हैं तो उन्हें उनको भी प्रयोग में लाने में सकोच नहीं होता।)

(यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जाति-प्रणाली भारतीय समाज का एक परम्परागत पहलू है। यह सही है कि पिछले वर्षों में पश्चिम के प्रभाव के परिणामस्वरूप भारतीय समाज का आधुनिकीकरण हुआ है, परन्तु यह आधुनिकीकरण समाज के पारम्परिक रूप का पूर्णतः उन्मूलन करने में जमफत रहा है। फलतः देश में दो भिन्न प्रकार की संस्कृतियों की अलग-अलग धाराएँ प्रवाहित होनी रही हैं एक पारम्परिक संस्कृति है और दूसरी है प्रयुद्ध लोगों की संस्कृति। पारम्परिक संस्कृति धर्म-प्रधान है, उसमें जाति की प्रधानता है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए कोई स्थान नहीं है, अपितु उसमें अन्ध-विश्वासों को स्थान दिया जाता है। संक्षेप में वह जिन समाज की रचना करती है, वह मूलतः तंग समाज (closed society) है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति

का समाज में स्थान उसका जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है। उसमें विपरीत प्रबुद्ध संस्कृति (elite culture) हम निरपेक्ष रूप से उसका आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा उसमें जानि विराट् की जैसे पारम्परिक संगठनात्मक नियमों का स्थान नहीं है। स्पष्ट रूप से प्रकाश की संस्कृति के माध्यम में जिस समाज की रचना होती है उसे आवश्यक रूप से एक खुला समाज (open society) होना चाहिए। भारत में औपनिवेशिक काल से ही उक्त दोनों प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व अवलोकित किया जा सकता था। वस्तुतः उस समय ये दोनों संस्कृतियाँ एक-दूसरे के समानान्तर चल रही थीं। पारम्परिक संस्कृति जनसाधारण की संस्कृति थी और प्रबुद्ध संस्कृति अग्रजों पर नियंत्रण की। उस समय इन दोनों संस्कृतियों के बिनायक का अर्थ एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति का किसी प्रकार में प्रभावित करने की किसी न कल्पना भी नहीं की थी। यद्यपि उस समय इसकी वास्तविक आवश्यकता नहीं थी। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन भी मुख्यतः अग्रजों पर नियंत्रण के माध्यम से वर्गीय शासन का अन्त करना था। परन्तु जब देश स्वाधीन हुआ और उसके साथ वैज्ञानिक विचारों के आधार पर चुनाव शुरू हुए तो उसके फलस्वरूप आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे-धीरे प्रवेश करना आरम्भ कर दिया। जनसाधारण या पारम्परिक संस्कृति से अनुप्राणित ये वैचारिक अभिप्राय हमारे सामने पेश हुए कि उनका पक्ष लेना और उनके अन्तर्गत समाज में परिवर्तन की आवश्यकता थी। अतः जिन्होंने समाज की जानाकारी थी उन्हें दोनों का प्राप्त करने के लिए इन दोनों का मेल था। अतः जिन्होंने समाज की जानाकारी थी उन्हें दोनों का प्राप्त करने के लिए जनसाधारण के पास पक्षधर की आवश्यकता थी। यह स्पष्ट है कि जनसाधारण का अपने पक्ष में मिलान के लिए यह भी जरूरी था कि उनसे उस भाषा में बात की जाय जो उनके लिए बुद्धिग्राह्य हो। जानि प्रणाली के प्रकार की भाषा को प्रस्तुत करनी थी। ऐसी स्थिति में यदि राजनीति में जानि का भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती गई तो हमें आवश्यकता का बोध नहीं होता था।

यदि हमें इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि राजनीतिक सामाजिक संगठन के विभिन्न चरण विभिन्न प्रकार के नतीजे तथा विभिन्न प्रकार की संगठनात्मक क्षमता का अन्तर्गत करत हैं। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि राजनीतिक प्रक्रिया एक चरण से निरन्तर दूसरे चरण में प्रवृत्त रहती है। प्रत्येक प्रकार की योग्यता से सम्पन्न नतीजों का स्थान दूसरे प्रकार की समताओं से सम्पन्न नहीं रहता है। अतः आरम्भ में नतीजों के अन्तर्गत उन लोगों के हाथों में था जिन्होंने पाश्चात्य विचारों को ग्रहण किया था तथा जिन्होंने वह प्रवृत्ति के राजनीतिक संगठनों के परिचालन का अनुभव था। इस समय आवश्यकता हमें समताओं की है जो ऐसे प्रशासकों के साथ काम कर सकें जिनका दृष्टिकोण और रहन-सहन पाश्चात्य था जिन्होंने वाद विवाद तथा सद्धान्तिक बहस में भाग लेने की रुचि थी जिनके पास कानून का ज्ञान था तथा जो छोट-मोट जानी-पूनी में भाग लेने के लिए सामाजिक मामलों में रुचि लेने वाले व्यक्तियों का आश्रय करने की समता रखते थे। भारतीय सामाजिक प्रयोगों में सबसे उच्च स्थान पर इनके कारण से प्रकाश के व्यक्ति सामाजिक ग्राहणों में ही मिल सकते थे। उनके पास उच्च विद्या था उच्च अग्रजों की शिक्षा का प्राप्त होना था तथा साथ ही नीतियों से उन्होंने भारत के पारम्परिक ज्ञान का भी प्राप्त किया था। सके अनिश्चित प्रशासन के साथ ही उनके सम्बन्ध में उनकी पानियाँ संचालित हो रही थी। इस प्रकार हमें चरण के राजनीतिक नतीजों की आवश्यकता हमें जानि के सदस्या के द्वारा पूरी होती थी। अतः यह वास्तविकता का बोध नहीं कि हमें काल में नतीजों के सामाजिक ग्राहणों के ही हाथों में रहा। अतः अन्त में जब राजनीति जनसाधारण का और अधिक उन्मुख हुई तो उसका आधार भी प्राप्त हो गया। इस नयी परिस्थिति में राजनीतिक परिचालन के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिनके पास प्रवृत्तियों और संगठनात्मक समता थी। वस्तुतः ही आवश्यकता नहीं कि हमें क्षमता के साथ मोनोपॉल बनने की और निरन्तर करने की योग्यता भी जुड़ी हो।

स्पष्ट रूप से प्रकाश की क्षमताओं के विचारों में ही के माध्यम में पायी जानी थी जिनका सम्बन्ध व्यापार और कृषि के साथ था। अन्त में राजनीति में जब जिन लोगों का बोध

बाला कायम हुआ वे या तो व्यापारी और उद्योगपति थे और या वे कुलक थे। ये लोग उन प्रबुद्ध लोगों की अपेक्षा कम आधुनिक थे, जिन्हें उन्होंने अपदस्थ किया था। उनका रुझान भी ग्रामोन्मुख था, उनकी भाषा भी ऐसी थी जिसे आधुनिक नहीं कहा जा सकता। सच बात यह है कि राजनीति में जातिवाद की समस्या की अभिव्यक्ति अपने गम्भीर रूप में इसी चरण के साथ शुरू होती है।

कालान्तर में पुरानी मान्यताओं का लोप होने लगा और उनके स्थान पर नये राजनीतिक मूल्यों का उदय होने लगा। इस स्थिति को जन्म देने में जो कारण सहायक हुए उनमें शिक्षा और तकनीक का प्रसार, ग्रामों का नगरीकरण तथा स्थिति के प्रतीकों में परिवर्तन को मुख्य रूप से गिनाया जा सकता है। इस स्थिति के उदय होने के साथ राजनीतिक प्रक्रिया के विकास का तीव्र चरण आरम्भ होता है। इस चरण में नये और व्यापक सम्बन्धों की रचना हुई, आत्म-परितुष्टि की नई कसौटी विकसित की गई, भौतिक लाभों की प्राप्ति के लिए लोगों की आकांक्षा बढ़ी तथा परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थानों को स्थानान्तरण एक आम बात बन गई। इस प्रकार स्थानीय अथवा विशिष्ट जाति अथवा सम्प्रदाय की भक्ति के स्थान पर जो नई भक्ति विकसित हुई वह अधिक आधुनिक थी। जो एक प्रकार से अपनी जीविका कमाते थे, जो एक ही प्रकार के काम की परिस्थितियों में अपना गुजारा करते थे, उनके बीच निश्चय ही एक प्रकार से समान हित पाये जाते थे, चाहे उनकी जाति-बिरादरी कुछ भी क्यों न हो। इस प्रकार का दृष्टिकोण सामान्यतः नगरों में कारखानों और मिलों में काम करने वाले श्रमिकों तथा मध्यम-वर्गीय नौकरी-पेशा लोगों में देखता जा सकता है। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इस तीसरे चरण में जाति के प्रभाव का लोप होने लगा है। वस्तुतः भारत एक ऐसा देश है जिसमें शताब्दियों का सह-अस्तित्व अवलोकित किया जा सकता है। परन्तु इसके साथ ही इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उस प्रक्रिया का समारम्भ हो चुका है जिसकी अन्तिम परिणति धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना में होने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब भारत के पारस्परिक समाज का लोकतान्त्रिक राजनीति के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ तो उसके परिणामस्वरूप नये सामाजिक मूल्य भी विकसित हुए और इस प्रकार समाज के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हुई है। पिछले वर्षों का अनुभव साक्ष्य है कि जहाँ विरादरी बहुत बड़ी है, वहाँ उसमें एकरूपता नहीं है और जहाँ वह बहुत छोटी है तो वह सख्या की दृष्टि से किसी शक्ति की रचना नहीं करती। दूसरे, यदि कोई राजनीतिक दल अथवा नेता किसी एक विरादरी के साथ अपनी आत्मीयता स्थापित कर लेता है तो उसके फलस्वरूप अन्य विरादरियों उससे विमुख हो जाती हैं और यह तथ्य उस दल अथवा नेता के पराभव का कारण सिद्ध होता है। अतः चुनाव की राजनीति के परिचालन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बहु-जातीय समर्थन को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये। इस प्रकार इस राजनीति के द्वारा जहाँ जाति के टुकड़े हुए हैं वहाँ उसने उसके अन्य विरादरियों के साथ सम्बन्ध भी स्थापित किये हैं। जिन राजनीतिक दलों अथवा नेताओं ने इस तथ्य की अवहेलना की है उन्हें अन्ततोगत्वा असफलता का मुंह देखना पड़ा है।

(इतना होते हुए भी भारतीय राजनीति अभी भी एक बड़ी सीमा तक जातिवाद से प्रभावित है। इस स्थिति को जन्म देने में सबसे बड़ी भूमिका देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस की रही है। परन्तु 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो जाने के बाद जातिगत राजनीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस विभाजन के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें जातिवादी राजनीति को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब जनता के सन्मुख प्रश्न यह था कि कांग्रेस का कोनसा भाग जनतन्त्र एवं समाजवाद के लक्ष्यों की सिद्धि की ओर अग्रसर होने पर कटिबद्ध है। राज्यों की राजनीति भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं बची। कांग्रेस के नेताओं के दो भागों में बँट जाने के कारण जातियों के निश्चयों में भी विभाजन हो गया। फलतः जिस प्रकार कांग्रेस दल के दो भाग हो गये, उसी के साथ जानिगत राजनीति में भी दरार पड़ गयी।

इस उद्योग प्रयत्न का एक स्पष्ट रूप यह स्वरूप में आया कि 1971 के आम चुनावों के मध्यावधि चुनावों में जातिवाद पर आधारित राजनीति उद्योग रूप धारण नहीं कर सकी। यह ठीक है कि प्रत्यागियों के चयन में राजनीति में सामाजिक जातिवाद के विचारों में प्रभावित हुए परन्तु चुनावों में जातिवाद की वास्तविक भूमिका नहीं रही। यद्यपि यह चुनाव अपने रूप का अद्भुत था जिसमें मुख्य विरोध गरीबी हटाओ बनाम गरीबी हटाओ बनाम गरीबी हटाओ मतदाताओं ने अपना निर्णय व्यक्त हुए जाति के स्वरूप तत्त्व का वह प्रधानता नहीं दी जिसका रूप पिछले चुनावों में स्वरूप में आता था।

यदि 1969 के बाद की भारतीय राजनीति की विश्लेषणा की जाय तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि जिस अनुपात में राजनीति उद्योग है उस अनुपात में उस जातिवाद के दुप्रभावा से मुक्ति प्राप्त हुई है। यद्यपि यह जनता यथास्थिति में जातीय परिवर्तन चाहता है वह उस जातीयपूर्ण व्यवस्था का अन्त और समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है जो उसने ऊपर जनाग्रहण से प्राप्त की है। जाति प्रथा यथास्थिति की धारणा है वह सामंती समाज का अवशेष है। अतः उसका नाश करने और समाजवाद के उच्च आदर्शों के साथ कार्य करना ही है। अतः जब भी जनता के समक्ष उद्योग विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है तो उसमें यथास्थिति के मुकाबले में उद्योग का चयन किया है। अतः यदि जातिवाद का सही अर्थ में मुकाबला करना अपेक्षित है तो यह आवश्यक है कि राजनीति और समाजवाद के आदर्शों का प्राप्त करने के लिए इमानदारी से काम करना जायें।

2 सम्प्रदायवाद (Communalism)

जातिवाद की भाँति सम्प्रदायवाद भी भारतीय राजनीति के समक्ष एक जटिल समस्या है। यद्यपि यह वास्तव में समस्या नहीं है। यह समस्या उस समय भी प्रस्तुत थी जबकि देश राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। इस समस्या के वास्तविक भी यदि 1947 में देश परतंत्रता की बड़िया को काटने में सफल हुआ तो ऐसा समझा जाता है कि हमने अपना काम कर लिया अपनी इस समस्या को भुलाकर देश के विरुद्ध कोई संयुक्त माँचा बना लिया था परन्तु हम देश का स्वतंत्र कराने में समझौते सफलता मिली थी क्योंकि देश तीसरे महायुद्ध के उपरान्त इस घाव नहीं रह गया था कि वह भारत जैसा विभाजन देश पर अपने नियंत्रण को लागू करना चाहता।

स्वतंत्रता के बाद भी इस समस्या का निराकरण करने में हम असफल रहे हैं। आज भी देश में सम्प्रदायवाद का प्रभाव है और यदि देश भी हाथ तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि देश के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच पूर्ण सद्भावना पाई जाती है। यदि ऐसा होता तो यहाँ साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का संगठन ही सम्भव नहीं हो पाता। प्रश्न है कि इस सम्प्रदायवाद का कारण क्या है तथा इसमें भारतीय राजनीति का किस प्रकार प्रभावित किया है? यहाँ हमकी विस्तृत समीक्षा की जाय सकती है।

जवाहरलाल नेहरू ने भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए उस जनता में एकता कहकर पुकारा था। उनके इस चयन के आगे एक प्रश्न विद्यमान है कि भाग्य में एकता पाई जाती है परन्तु उसकी जनता उसका राजनीतिक जीवन का एक कर्म यथायथ है। भारत एक बहुधर्मात्मक देश है इसमें जनता को मानने का रहस्य है जिसमें हिन्दू मुसलमान सिक्खों और पारसी और बौद्ध प्रमुख हैं। हिन्दू भारत में बहुसंख्यक है जबकि अन्य सम्प्रदाय अल्पसंख्यक हैं। इन अल्पसंख्यकों में मुसलमान सबसे अधिक मुख्य हैं क्योंकि संख्या की दृष्टि से उनका नम्बर हिन्दुओं के बाद आता है। औपनिवेशिक शासन के दिनों में अल्पसंख्यकों के सम्प्रदायों का पारस्परिक मतभेदों को उभार फूट डाने के लिए प्रयत्न किया और इसी जटिल परिणति देश को विभाजन में हुई। परन्तु विभाजन के बाद भी देश में मुसलमान बौद्ध सिक्खों और पारसी के

राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हें जीवन, धर्म और सम्पत्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। सविधान के द्वारा भी उन्हें उनके अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था। परन्तु ऐसा पाकिस्तान में नहीं किया गया। फलतः वहाँ से हिन्दू बड़ी संख्या में भारत शरणार्थी बनकर आये। इस सन्दर्भ में सम्प्रदायवाद की समस्या का कोई समाधान सम्भव नहीं हो सकता था।

स्वतन्त्रता के फौरन बाद देश में विशाल पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों का कोई विशेष कारण नहीं था। कभी दंगा इसलिए हो गया क्योंकि श्रीनगर में एक ब्राह्मण लड़की को मुसलमान बनाकर उसकी एक मुसलमान के साथ शादी कर दी गई थी, तो कभी दंगा इसलिए हो गया क्योंकि मेरठ में एक मुसलमानों की मीटिंग पर हिन्दुओं ने विरोध प्रदर्शित किया था। कभी दंगा इसलिए हो गया क्योंकि होली के त्यौहार पर हिन्दुओं ने मुसलमानों के ऊपर रंग फेंक दिया तो कभी दोनों सम्प्रदायों के लोग आपस में इसलिए लड़ मरे क्योंकि जब एक आवारा गाय ने एक मुसलमान डबल रोटी बनाने वाले की कुछ रोटियाँ खा ली तो उस मुसलमान ने उस गाय को मारा जिससे उस गाय की मृत्यु हो गई। निस्सन्देह, इन छोटी-छोटी बातों पर देश में काफी खून खराबी हो चुकी है। प्रश्न है कि देश के स्वाधीन होने के बाद भी ये दंगे क्यों होते हैं? इस प्रश्न के ऊपर में मुख्यतः तीन कारण गिनाये जा सकते हैं—मुस्लिम पृथक्तावाद, हिन्दू सम्प्रदायवाद तथा सरकार की उदासीनता। यहाँ इन तीनों कारणों की समीक्षा अपेक्षित है।

स्वतन्त्रता के बाद कुछ मुसलमान नेताओं ने विभाजन की भूल को स्वीकार किया था। उन्होंने इस गलती को सुधारने के लिए अपने सह-धर्मावलम्बियों को यह परामर्श भी दिया था कि उन्हें देश में ऐसी पार्टियों और व्यक्तियों को समर्थन देना चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और आर्थिक न्याय में आस्था रखते हैं तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य-धारा में अपने आपको विलीन कर देना चाहिए ताकि उनके माथे से यह कलक हट जाये कि वे देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार का परामर्श देने वाले नेताओं में मद्रास के मौहम्मद इस्माइल तथा नवाब इस्माइल खॉं मुख्य थे। परन्तु ये विचार कार्यक्रम में परिणत नहीं किये जा सके क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठन मुसलमानों को इस बात का उपदेश दे रहे थे कि उन्हें अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा और अन्य हितों की रक्षा के लिए अपने आपको पृथक् संगठनों में संगठित करना चाहिए। जमायते-इस्लामी ने मुसलमानों को यह परामर्श दिया कि 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इन चुनावों के द्वारा इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। 1948 में वकी-खुवी मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन की मांग की। वस्तुतः वे मुसलमान नेता जो इस प्रकार की बात करते थे, वे लोग थे जिनके पास आधुनिकता छू तक नहीं गई थी, जिन्होंने दृष्टिकोण धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण था और जो हमेशा यह वेसुरा राग अलापते थे कि हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति में कोई साम्य नहीं है तथा उनके बीच कभी कोई एकता स्थापित नहीं की जा सकती। इस प्रकार के मुसलमान नेताओं ने मार्च 1971 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के पूर्व समूचे भारत के मुसलमानों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें मुसलमानों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में आठ दर्जन प्रस्ताव पारित किये गये थे। इनमें अल्पसंख्यकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, उर्दू की रक्षा, नौकरियों में मुसलमानों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति को कायम रखना तथा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को देश में चालू करना शामिल थे। इस सम्मेलन ने एक जखिन भारतीय राजनीतिक परामर्श समिति की भी स्थापना की जो समूचे देश के स्तर पर मुसलमानों की गतिविधियों में ताल-मेल बैठा सके। निस्सन्देह मुस्लिम धर्मांधता तथा पिछड़ेपन ने उनके बीच में सम्प्रदायवाद का कभी पूर्ण उन्मूलन नहीं होने दिया। सामाजिक पिछड़ेपन के साथ-साथ मुसलमान आर्थिक रूप में भी पिछड़े हुए रहे। स्वतन्त्रता के बाद भी उन्होंने शिक्षा के प्रसार का वाछिन लाभ नहीं उठाया, फलतः सरकारी नौकरियों में भी उन्हें उस अनुपात

म जगह नहा मिन सका जिन व चाहत थ। उसक परिणामस्वरूप मुमनमाना म निगना न नाव का उत्पन्न हुआ है मुस्लिम सम्प्रदायवाद का नाम तन म इस कारण का एक विगप यादगन रहा है। इनक अतिरिक्त भारतीय राजनानि म मुस्लिम सम्प्रदायवाद का उत्पत्ति क निग पाकिस्तान का भी एक भीमा तक उत्तरदायी बताया जा सकता है। जब भी भारत म काइ साम्प्रदायिक युद्ध हुआ पाकिस्तान न उस समय जिन म थी गानन का काम किया। उदाहरण के लिए जय हजरत गन की सम्मिलित म पवित्र वात की चारी तता उस समय तत्कालीन पाकिस्ताना विग मत्री जुफरार अता भुग न अपन एक वयान म कहा था कि यह चारी भारत सरकार का माजिग म है। पाकिस्तान न भारत की मुस्लिम जनता का राष्ट्रीय जीवन स जयग रखन का त्मना स प्रयत्न किया है और उस जयन म प्रयत्न म पूर्णतः असफलता मिनी था एसी बात नहा है। नम परिस्थिति म यदि स्वतन्त्रता के वात भी भारत म मुस्लिम सम्प्रदाय वात फायम रहा ता तमम कार्य आश्चर्य का बात नहा थी।

जहा सम्प्रदायवाद के लिए मुमनमान सम्प्रदायवादी उत्तरदायी है वहा तमक लिए हिन्दू सम्प्रदायवाद कम उत्तरदायी नहा है। स्वतन्त्रता के पहल भी भारत म हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन न जिनम हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम मुख्य रूप म निग जा सकने ह। नम संगठन न तम वात के ऊपर हमेशा गन लिया कि भारत हिन्दुता का देश है तथा जय अमावस्यी विगपत मुमनमान तस देश म विजातीय उत्त्व की रचना करत ह।

ऊपर 1970 म तम मुस्लिम सम्मेलन का उत्पन्न किया जा चुका है। तस सम्मेलन के वात हिन्दू मतानभा न अपन एक प्रस्ताव म यह माग की कि मुसलमानों का सरकारी स्तर पर पाकिस्तान भज नना चाहिए। 1965 के युद्ध म पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध के अन्तिम तम अन्तिम के सम्मेलन म निगत हुए गानवनकर न कहा कि वह ता कम हा है जस कि भाग न खन म तुमना का पौधा। गिव मना के वात आकर न इस्लाम के तर खतर म हिन्दुता को आगात करत तम कहा— हिन्दुता का न खन हिन्दू रचना चाहिए वनि कट्टर हिन्दू हाना चाहिए तथा उ न जनन धर्म के लिए जहात करन वाता हाना चाहिए। मुझे यह कहन म का न नजा नहा है कि मैं एक कट्टर हिन्दू ह। स्पष्ट है कि तम प्रकार के प्रचार का उत्पत्ति म दग म सम्प्रदाय वाद का उभूतन नहा किया जा सकता था।

सम्प्रदायवाद का पनपान म सरकार का उदासीनता की भी एक निश्चित भूमिका रखी है। सब बात यह है कि तम और राध्या की सरकार न तम समस्या का निराकरण करन के लिए का न मजबूरन काम नहा उठाये। उहान तम समस्या के कारणों की भी का न समा गन नहा की। जत सम्प्रदायवाद के राग का का न निगन नहा हा सका। एसी स्थिति म उपचार का को न प्रश्न ही नहा उठ सकता था।

सरकार का प्रगामकीय यत्न भी तम समस्या का सुनभान के लिए अनुपयुक्त मिद्ध नहा है। साम्प्रदायिक उत्पत्ता के समय सरकारी अधिकारिया न न कवन सामयिक कायवाही करन म मकीच किया है अपितु गिकायत तो यह भी है कि उत्पन्न उत्पत्ता का मन्वान का भी काम किया है। उदाहरण के लिए 1972 म जब उत्तर प्रदेश के एक नगर फिरोजाबाद म साम्प्रदायिक उत्पत्त नहा ता उस समय कुछ समय मन्स्या न प्रधानमंत्री का एक नापन लिया था जिनम त्मान स्थानीय पुनिम अधिकारिया पर यह आरोप लगाया था कि उहान दग का उत्पत्ता तन का काम किया था। तम प्रकार के जनक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकत है जिनम यह प्रमाणित गता है कि साम्प्रदायिक तत्त्वा की सरकारी शिभाषा म गहरी ज है। निश्चय था तस प्रकार के अधिकारिया के माध्यम से साम्प्रदायिक समस्या के समाधान का प्रयत्न नहा जा सकत।

पिछल वर्षा म अनक शर साम्प्रदायिक दग पर प्रतिगव गगन की मांग की ग है। परंतु इस माग की सरकार न हमेशा यह कहकर जम्बाकार कर लिया कि मजिधान न जलगत यह सम्भव नहा है। यदि तन तक का स्वाकार कर भी लिया जाय तो भी सरकार के पास

साम्प्रदायिकता का दमन करने के लिए अनेक साधन मौजूद हैं। जब निवारक नजरबन्दी कानून को पारित किया गया था उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इसका प्रयोग साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध किया जायगा। परन्तु ऐसा शायद ही कभी हुआ हो।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि देश में साम्प्रदायिक समस्या के समाधान के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार के नेता ईमानदारी के साथ धर्मनिरपेक्ष हों। यदि उनकी धर्म-निरपेक्षता बाह्य आडम्बर से अधिक कुछ नहीं है तो ऐसी स्थिति में संविधान में निहित उच्च आदर्श केवल पवित्र सकल्प मात्र रह जायेंगे, उनका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं होगा।

3 क्षेत्रीयता (Regionalism)

भारत की अनेकता को व्यक्त करने वाली दूसरी समस्या क्षेत्रीयता की है। सम्प्रदायवाद के अन्तर्गत व्यक्ति राष्ट्र की अपेक्षा अपने सम्प्रदाय को अधिक प्यार करते हैं, क्षेत्रीयता के प्रभाव के अधीन व्यक्ति राष्ट्र के मुकाबले में उस क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं जिसमें उनका निवास है। सम्प्रदायवाद मुख्यतः देश के दो बड़े सम्प्रदायों के सन्दर्भ में देखा जा सकता है, जबकि क्षेत्रीयता की बीमारी ऐसी है जो समूचे देश में व्याप्त है। कभी-कभी उसकी अभिव्यक्ति संगठित एवं सुनियोजित आन्दोलनों के माध्यम से भी हुई है। इन आन्दोलनों को मुख्यतः चार प्रकार की माँगों के आधार पर संगठित किया गया है—(i) भारतीय सघ से पृथक् होने की माँग, (ii) पृथक् राज्यत्व को प्राप्त करने की माँग, (iii) पूर्ण राज्यत्व को प्राप्त करने की माँग, तथा (iv) अन्तर-राज्यीय विवाद।

प्रश्न है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में क्षेत्रीयतावाद का उदय क्यों हुआ? इस सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य पहली बात यह है कि भारत जैसे विशाल बहुभाषा-भाषी एवं बहु-संस्कृतियों वाले देश में क्षेत्रीयता का उदय कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यथार्थ में इसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में भी होती थी। परन्तु स्वाधीन होने के बाद यह समस्या उग्र रूप में देश के सामने प्रस्तुत हुई। इसके अनेक कारण थे

(1) आर्थिक कारण—क्षेत्रीयता को जन्म देने वाले कारणों में सबसे पहले आर्थिक कारणों को रखा जा सकता है। स्वाधीन होने के बाद जब देश में आर्थिक विकास का कार्यक्रम आरम्भ किया गया, तो उसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्र तो बहुत अधिक विकसित हो गये, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र अत्यधिक रूप से पिछड़े गये। इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में असन्तोष का उदित होना स्वाभाविक बात थी। मिजो और नागा विद्रोहों को वास्तव में इसी पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है।

(2) भाषा और सांस्कृतिक कारण—भारत में क्षेत्रीयता का सम्बन्ध भाषा के साथ अनिवार्य रूप से है। इसी भाषा को आधार मानकर अनेक क्षेत्रों के लोगों ने अपने लिए पूर्ण राज्यत्व की माँग की है और जब यह माँग स्वीकार नहीं की गई तो उसके फलस्वरूप क्षेत्रीयता के अधीन उग्र आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ है। इस प्रकार भाषावाद को क्षेत्रीयता का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। वस्तुतः भारत में भाषा द्वारा अनुप्राणित क्षेत्रीयता के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। सबसे पहले तेलगू-भाषी लोगों ने आन्ध्र राज्य की स्थापना के लिये आन्दोलन किया। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों की स्थापना के लिए जो आन्दोलन चला, वह भी भाषावाद से ही अनुप्राणित था। इसी प्रकार पंजाबी सूबा के आन्दोलन के मूल में भी भाषा-सिद्धान्त की एक प्रमुख भूमिका रही थी।

भाषा के साथ संस्कृति अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु के लोगों को अपनी तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के ऊपर बहुत अधिक गर्व है तथा वे अपनी संस्कृति की अपेक्षा शेष भारत की संस्कृति को तुच्छ मानते हैं। यदि उन्होंने आरम्भ में अपने राज्य को भारतीय सघ से

अलग करने की बात कही तो उसे हम वही सदन में सम्मिलित चाहिए।

इस सम्बन्ध में पहला कदम यह है कि देश के राजनीतिक वातावरण को सुधारा जाय। आज देश में विभिन्न सम्प्रदाय जाति और क्षेत्र के लोगों में एक दूसरे के प्रति वाद्विचार का अभाव है। इस अविश्वास की स्थिति में राष्ट्रीय एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

भाषा सम्बन्धी विवाद भी राष्ट्रीय एकीकरण के माग में बहुत बड़ी बाधा है। भाषा के प्रश्न को लेकर आज देश में अतनी अधिक गुटबन्दी हो चुकी है कि लोग खुद मस्तिष्क से इस समस्या पर विचार करने के लिए भी बहुधा तैयार नहीं मिलते। अतः इस विवाद का प्रौद्योगिकीय समाधान अत्यन्त आवश्यक है। इस तथ्य की प्राप्ति के लिए यह अपेक्षित है कि विभिन्न भाषायी समुदायों के बीच अधिकारिक मात्रा में सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। वस्तुतः ऐसा करके ही उनके बीच पायी जाने वाली अविश्वास की दीवार को गिराया जा सकता है।

राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं से अनुकूल हो। इसलिए विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम ऐसे हों जो विद्यार्थियों में यह चेतना पैदा कर सकें कि वे पहले भारतीय हैं और बाद में कुछ और। वही प्रकार पाठ्यक्रम में होने चाहिए जो छात्रों में समानिष्ठता की दृष्टिकोण से विकसित करने में सहायक हो सकें। इस तथ्य की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि इतिहास के अध्ययन और अध्यापन में मूलभूत परिवर्तन किये जायें।

शिक्षा संस्थाओं के ग्रामिक सम्प्रदाय अथवा जातियों के ऊपर नाम रखने की परम्परा का भी अंत किया जाना परमावश्यक है। इस अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि लोगों में एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता विकसित की जाय। यदि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किसी धर्म विषय के अनुयायियों के प्रति पक्षपात करते पाये जायें तो उनके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

राष्ट्रीय एकीकरण को सम्भव बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि यहाँ आर्थिक विकास की योजनाओं को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाये जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पायी जाने वाली आर्थिक असमानताओं का अन्त हो सकें। पिछड़े हुए क्षेत्रों में केवल राजनीतिक असन्तोष की रचना करते हैं अपितु वे उन सम्भावनाओं का भी जन्म देते हैं जो राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त है। अतः राष्ट्रीय एकता के लिए यह भी आवश्यक है कि आर्थिक गति का वास्तविक रूप से वितरित किया जाय।

अन्त में इस तथ्य की प्राप्ति के लिए नागरिकतात्मक एकता की स्थापना करना आवश्यक समझा जाना चाहिए। हमें दो बार राष्ट्रीय एकीकरण सम्मिलित हो चुका है परन्तु इन सम्मिलनों में जो कुछ भी निर्दिष्ट किया गया उस पर अभी भी व्यवहारिक रूप में ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रीय एकता का कानून के द्वारा बनाना किन्हीं लोगों पर बाधा नहीं डाल सकता और न इसकी उपरान्त राजनीति में सम्मिलन के द्वारा ही सम्भव है। सबके विकास के लिए यह ध्येय और अध्यवसाय की जरूरत है।

प्रश्न

- 1 भारतीय राजनीति में जातिवाद के उत्पन्न के कारणों की समीक्षा कीजिए।
- 2 स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राजनीति सम्प्रदायवाद से क्या प्रभावित है ?
- 3 पिछले वर्षों में भारतीय राजनीति में धर्मोपेक्षा की भावना की किस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है ?
- 4 भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर एक निबंध लिखिए।

भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्त्व (NATURE AND DETERMINANTS OF INDIAN POLITICS)

परम्परागत एवं अर्वाचीन मूल्यों का संघर्ष

अनेक देशी और विदेशी विद्वानों ने भारतीय समाज को गतिहीन समाज की संज्ञा प्रदान की है। वस्तुतः इस गतिहीनता का प्रभाव हम अपने समाज में आज भी—गणतन्त्र की स्थापना के पच्चीस वर्ष बाद भी अवलोकित कर सकते हैं। यह ठीक है कि भारतीय समाज पूर्णतः गतिहीन नहीं है, उसमें गतिशीलता के तत्त्व भी विद्यमान हैं। सच बात यह है कि भारतीय सामाजिक जीवन में सन्निहित गतिहीनता का अध्ययन केवल सापेक्ष रूप से हो सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् भारत के गतिहीन समाज में गतिशीलता की अभिव्यक्ति हुई है अथवा नहीं और यदि हुई है तो उसका भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

यहाँ आरम्भ में ही यह बात उल्लेखनीय है कि भारत में सामाजिक अन्तर्विरोधों ने विस्फोटक स्थिति को कभी जन्म नहीं दिया। फलतः भारतीय समाज का विकास अन्य देशों की भाँति नहीं हो सका। इसके विपरीत भारत इस अर्थ में एक अद्भुत देश है क्योंकि उसमें अभी तक इतिहास में जितनी भी सामाजिक पद्धतियाँ रही हैं, उन सबका एक आश्चर्यजनक समन्वय पाया जाता है। इस प्रकार हमारे देश में आज भी कबायली लोग पाये जाते हैं जिनकी सभ्यता हमें आज भी आदिम समाज की सभ्यता की याद दिलाती है। हमारे देश में आज भी बंधे हुए मजदूरों (bonded labour) के रूप में दास-प्रथा के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। जमींदारी पंथा और प्रिवी पर्सों (privy purses) के ख़ात्मे के बाद भी हमारे समाज का सामन्ती स्वरूप किसी से छिपा हुआ नहीं है और यह बात भी सर्वविदित है कि इस शताब्दी के आरम्भिक चरण में ही देश में पूँजीवादी अर्थतन्त्र का उदय हो चुका था। (टाटा के स्टील कारखाने की स्थापना 1910 में हुई थी)। इसके साथ देश के नगरीकरण (urbanization) तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का भी समारम्भ हुआ था। इस प्रकार देश में परम्पर विरोधी सामाजिक शक्तियों का अस्तित्व बना रहा। इस सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरू का यह कथन उल्लेखनीय है कि 'भारत में शताब्दियाँ एक साथ रहती हैं' (In India, centuries live together)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज के विकास के इतिहास में किसी भी समय कोई कान्तिकारी उथल-पुथल नहीं हुई, यहाँ तक कि नवीन स्वतन्त्र भारत के अभ्युदय के उपरान्त भी यह नहीं जा सकता कि हमारा समाज अथवा हमारी राजनीति लोकतान्त्रिक क्रान्ति के दौर में से होकर गुजर रही है।

1947 में सत्ता उन भारतीयों को हस्तान्तरित की गई जो उस समय के भारत के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण माने जाते थे। भारतीय नेताओं ने सत्ता प्राप्त करने के लिए न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से वानचीत और एक प्रकार की सौदेबाजी की थी, बल्कि उन्होंने यह सौदेबाजी यहाँ के सामन्ती नरेशों के साथ भी की थी। इस सबका परिणाम यह हुआ कि देश में पाये जाने वाले सामन्ती तत्त्वों ने यहाँ की नव-नियोजित जनव्यवस्था के मुचारूप में संचालित होने के मार्ग में अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भूमि की हद-बन्दी (land ceilings) और 'हरित क्रान्ति' के हल्ला-गुल्ला के बाद भी ग्रामीण भारत सामन्ती

शोषण से अपने आप को अभी तक मुक्त नहीं कर सका है। यही नहीं भारतीय राजतंत्र और समाज का सामंती स्वरूप आज जाति विरादरी साम्प्रदायिक एवं कबायली तनावों में व्यक्त हो रहा है। इनके फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता का धक्का पहुंचा है तथा राज्य व्यवस्था को बाध होकर गतिशीलता की स्थिति को बीकार करना पड़ा है।

आधुनिक भारतीय समाज पिछले मंजो से कम, स कम दो जर्जों में भिन्न है। पहला जर्ज चीन युग में समाज में जन समूह की राजनीति (mass politics) का उदय और विकास हुआ है। यह दत्तान की आवश्यकता नहीं कि प्राचीन भारत इस प्रकार की राजनीति से सबका अनभिज्ञ था। दूसरे, सामंती सामाजिक शक्तियों के अस्तित्व के कारण जन समूह की राजनीति समाज में लोकतान्त्रिक आन्दोलनों को बन पहुंचाने में असफल रही है। इसके सबका प्रतिकूल सामन्ती पुराणियों के कारण जन समूह की राजनीति की अभिव्यक्ति बहुधा गंभीर आन्दोलनों में हुई है जिनमें देश में उच्छ्वसन एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिला है।

स्वतंत्रता के पश्चात् जनमांगण का राजनीति में सक्रिय हस्त के अवसर को वाता के कारण प्राप्त हुए पहला पापक मतान्तरिक तथा दूसरा आर्थिक नियोजन। परन्तु जहाँ उनके कारण जनसाधारण राजनीति में सक्रिय हुए जहाँ समाज में सामन्ती तत्त्वा का भी सक्रिय हस्त के लिए विवश किया। वस्तुतः सामन्ती अवस्था के लिए यह सक्रियता अनिष्ट आवश्यक थी क्योंकि समाज के अपने प्रत्यक्षतावादी अस्तित्व को नाश नहीं रख सकते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आरम्भ में ही भारत में जन समूह की राजनीति का उदय जल्द ही वातावरण में हुआ। 1947 से पूर्व इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। इसका मुख्य रूप से दो कारण थे। प्रथम साधारणतः लोग अपनी विरादरी से निराकर राजनीति और सरकार के साथ कोई सीधा सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करते थे और दूसरे जो लोग राष्ट्रीय आन्दोलन के माध्यम से राजनीति में सक्रिय होते थे उनकी समूची गतिविधियाँ केवल एक उद्देश्य से उत्प्रेरित थी—देश से विदेशी साम्राज्यवादी को निर्यात। इस सम्बन्ध में मार्लिस जोस का यह कथन उल्लेखनीय है—ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का कर्तव्य एक शक्तिशाली मित्र या और वर या ब्रिटिश शासन, उस संगठित करने वाला समान गुरु। आज जब वह मात्र गौरीरूप से अनुपस्थित है यह स्वाभाविक है कि भारतीय समाज के अन्तर्विरोध और विभिन्नताय जा आपनिवेशित दासता के विरुद्ध संघर्ष के क्षेत्र में बहुत अधिक मुखर नहीं हो सके। सामान्य उम्र करके प्रायः जन समूह की राजनीति ने इन अन्तर्विरोधों की अभिव्यक्ति का और अधिक सुस्पष्ट बना दिया है, वस्तुतः यह सुस्पष्टता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यद्यपि ये अन्तर्विरोधों ने एक बड़ी सामाजिक भारतीय राजनीति को निर्धारित किया है।

प्रश्न है कि ये अन्तर्विरोध क्या हैं जो भारतीय राजनीति में विघटनकारी तत्त्वा के रूप में काम कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। वस्तुतः ये अन्तर्विरोधों के अन्तर्गत हुए उन सभी तत्त्वाओं को शामिल कर सकते हैं जो एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में भारत के विकास का अभी तक अवरोधित कर रहे हैं। जातिवाद सम्प्रदायवाद धर्मवाद भाषावादी जाति का गणना एक तत्त्वा की श्रेणी में की जानी चाहिए।

परन्तु यह तमबोर का एकमात्र पहलू नहीं है एक दूसरा पहलू भी है जो भारतीय राजनीति के उदय में एक प्रतिनिधित्व करता है। धर्म निरपेक्षता वाकतः समाजवाद और गुट निरपेक्षता हमारे देश की राजनीति के उदय पक्ष की अभिव्यक्ति हैं। सब बात यह है कि ये दोनों पहलुओं का सम्बन्ध किन्हीं मूल्यों और आस्थाओं के साथ है। पहलू पक्ष के मूल्य और आस्थाएँ इन्होंने और परम्पराओं के साथ बंध हुए हैं। जातिवाद सम्प्रदायवाद धर्मोपेक्षावाद जाति बुगदियों की जड़ हमारे देश की सामान्य सस्कृति में निहित हैं जबकि धर्म निरपेक्षता वाकतः न और समाजवाद अर्थात् जनसाधारणतः हैं। भारत की राजनीति आधुनिकता और परम्परागत के बीच चल रहे इस संघर्ष में प्रभावित हो रहा है। जहाँ यहाँ उनकी विवेचना समीचीन है।

भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले आधुनिक तत्त्व

पिछले अध्याय में परम्परावादी मूल्य-व्यवस्था का प्रनिनिधित्व करने वाले तत्त्वों—जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता आदि की विवेचना की जा चुकी है। परन्तु जैसा कहा जा चुका है कि भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले केवल वे ही तत्त्व नहीं हैं। परम्परावादी मूल्य-व्यवस्था से सर्वथा भिन्न एक दूसरा पक्ष भी है जिसने हमारे देश की राजनीति के स्वरूप को निर्धारित करने में एक निर्णायक भूमिका अदा की है। इस पक्ष का सम्बन्ध आधुनिक मूल्यों एवं आस्थाओं के साथ है। धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवाद की अवधारणाओं का सम्बन्ध आधुनिक मूल्यों के साथ है। यहाँ भारतीय सन्दर्भ में इन तत्त्वों के व्यावहारिक पक्ष की विवेचना अपेक्षित है।

(1) धर्म-निरपेक्षता—सविधानकारों ने देश में जिस राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की, उसका स्वरूप धर्म-निरपेक्षता था, यह वान असन्दिग्ध है। सविधान में सन्निहित धर्म-निरपेक्षता की अपनी कुछ विशिष्टताएँ हैं। सर्वप्रथम, यह धर्म-निरपेक्षता उदार है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि भारत हिन्दू-बहुसंख्यक राज्य है तथापि यहाँ सविधान के द्वारा सभी अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के सदस्यों के मूल अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए सविधान के 25वें अनुच्छेद के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। दूसरे, भारत में धर्म-निरपेक्षता अमर्यादित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता अथवा जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतन्त्रता के ऊपर प्रतिबन्ध आरोपित कर सकता है। तीसरे हमारे यहाँ धर्म-निरपेक्षता को एक गतिशील विचार के रूप में मान्यता दी गयी है। इसका आशय यह है कि यद्यपि हमारे देश में धर्म की राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्राप्त नहीं है, तथापि राजनीति को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की छूट है। उदाहरण के लिए राज्य को किसी भी सम्प्रदाय के निजी कानून (personal law) को परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रश्न है कि धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त ने भारतीय राजनीति को किस सीमा तक प्रभावित किया है? ऊपर कहा जा चुका है कि देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक तत्त्व साम्प्रदायिकता है, परन्तु इस साम्प्रदायिकता के बावजूद भारत की जनता ने प्रत्येक मौके पर अपनी असाम्प्रदायिक राजनीतिक समझ का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए डा० जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हमारी धर्म-निरपेक्षता का भी परिचायक है। इस सम्बन्ध में हमारे देश में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत चेस्टर वाउल्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि 'नेहरू की महानतम उपलब्धि एक ऐसे राज्य की रचना है जिसमें साढ़े चार करोड़ मुसलमानों को जिन्होंने पाकिस्तान न जाने का निर्णय किया था, शान्तिपूर्ण तरीके से रहने तथा अपनी इच्छा के अनुसार पूजा करने की स्वतन्त्रता है।'

प्रश्न है कि देश के राजनीतिक दलों ने धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को किम सीमा तक व्यावहारिक रूप प्रदान किया है? वैसे तो देश में असाम्प्रदायिक एवं धर्म-निरपेक्ष दलों की कमी नहीं है, परन्तु सत्य यह है कि धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त का अनुसरण सामान्यतः केवल वामपंथी दलों ने और विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टियों ने ही किया है। फलतः उन राज्यों की राजनीति जहाँ वामपंथी दलों विशेषतः कम्युनिस्ट आन्दोलन का प्रभाव है, धर्म-निरपेक्ष है तथा वहाँ प्रयत्नों के बावजूद भी साम्प्रदायिक दलों का प्रभाव नगण्य रहा। इस सम्बन्ध में केरल और पश्चिमी बंगाल के उदाहरण दिये जा सकते हैं। केरल में ई०एम०एस० नम्बूद्रीपाद एक हिन्दू ब्राह्मण को पताम्बी के एक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से अपने आप को निर्वाचित करवाने में कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में भी वामपंथी राजनीति असाम्प्रदायिक एवं धर्म-निरपेक्ष है। एक अर्थ में वह केरल की अपेक्षा अधिक असाम्प्रदायिक है। आज तक पश्चिमी बंगाल में किसी भी वामपंथी दल ने किसी भी साम्प्रदायिक पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का ताल-मेल नहीं किया

है। यहाँ यह उत्तरनीय है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सामायन चुनाव जितने के लिए पर्याप्त नहीं खाती है। फलतः उनकी राजनीति में अजय दत्त की अपेक्षा धर्म निरूपता के सिद्धान्त के प्रति अधिक निष्ठा पाई जाती है।

(2) लोकतंत्र और समाजवाद—संविधानकारों ने जान-बूझकर एक नैतिकतात्मिक पद्धति की स्थापना की है। 1964 में एक प्रबल मतारूपण का प्रयास ने नैतिकतात्मिक समाजवाद का तथ्य स्वीकार किया। वास्तव में समाजवाद धर्म है जिस नैतिकतात्मिक तराई से प्राप्त करना है और उच्च नियोजन का स्थान प्रमुख है। सामायन लोग अभी तक यह मानते जाते हैं कि लोकतंत्र और समाजवाद एक परस्पर विरोधी विचारधारा है और इसलिए उन दोनों में कोई भेद नहीं हो सकता। परंतु आज के युग में यह विचार अप्रासंगिक है क्योंकि लोकतंत्र केवल राजनीतिक अधिकारों और शासन में जनता की भागीदारी का ही प्रश्न नहीं है बल्कि उसका अर्थ अधिकारिक मान्यता में सामाजिक एवं आर्थिक धर्म समान अवसर और औद्योगिक क्षेत्र में नैतिकतात्मिक व्यवस्था की स्थापना करना है। अतः यह स्पष्ट है कि राजनीतिक लोकतंत्र और लोकतंत्र के बिना असम्भव है। कम्युनिस्ट समाजवाद आर्थिक लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है।

भारत के प्रधान गणराज्य के संस्थापक एक नैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे यह बात संविधान की अनेक व्यवस्थाओं से स्पष्ट है। सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना के माध्यम में संविधानकारों ने देश में एक एक राय का रचना का आश्वासन दिया है जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक धर्म की उपलब्धि हो सकेगी। अतः अतिरिक्त संविधान के चौथे अध्याय में भी संविधानकारों ने अपने इस आश्वासन को दुहराया है। यहाँ यह उत्तरनीय है कि भारतीय संविधान का अपना एक दान है और वह दान है सामाजिक परिवर्तन। यह परिवर्तन नैतिकतात्मिक समाजवाद की दिशा में होना चाहिए यह बात भी स्पष्ट है।

संविधान के नाश होने के बाद यथास्थिति और सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियाँ के बीच निरन्तर संघर्ष की स्थिति पायी जाती रही है। यथास्थिति की शक्तियों ने अपने हितों की प्राप्ति के लिए बहुधा धार्मिकता की शरण ली है और सामाजिक परिवर्तन की शक्तियाँ ने समर्थ की। भारतीय गणतंत्र के पिछले 25 वर्षों में सत्ता के भाँटों में कि कुछ अत्यन्त पराजय के राज्यों में भी सत्ता संघर्ष में उन शक्तियों की विजय है जो लोकतंत्र और समाजवाद में आस्था रखते हैं। फलस्वरूप पिछले वर्षों में देश में सावजनिक क्षेत्र का विकास हुआ है आज हम क्षेत्र में 2 हजार व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। सावजनिक क्षेत्र आज युग में भारतीय समाजवाद की एक शक्तियों की आवार गिरा मित्र होगा ऐसी आशा की जा सकती है।

पिछले वर्षों में संविधान के कुछ प्रावधानों को भी अमान्य मशोर्धित कर दिया गया है ताकि समाजवाद की शरण देश के अभियान को किसी भी प्रकार बाधित न किया जा सके। चौबीसवें और पचासवें संविधान के इसी दिशा में एक कर्म समझा जाना चाहिए।

नैतिकतात्मिक समाजवाद ने देश के जनमानस को अपनी ओर आकर्षित किया है यह बात भी असंदिग्ध है। इसका सर्वप्रथम प्रमाण यह है कि प्रत्येक चुनाव में देश के मतदाताओं ने उन दलों का विजयी बनाया है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़-मनस्क हैं। 1971 का लोकसभा का चुनाव यथाथ में समाजवादी दल गरीबी हटाओ की विजय की।

गत अध्याय में भारतीय संविधान द्वारा संस्थापित ढाँचे की विवेचना की जा चुकी है। परंतु संस्थापित ढाँचे का वातावरण में काम नहीं करना। उनकी कार्यावधि एक निश्चित सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि में होती है। पिछले अध्याय में हमने अमान्य उन समस्याओं का उल्लेख किया था जो आज भारतीय लोकतंत्र के समर्थ प्रस्तुत हैं। सामाजिक संस्थाओं में अपने आप का सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाँचे की प्रवृत्ति पाई जाती है। फलतः सामाजिक ढाँचे का वह उच्च स्वरूप कसा ही क्या न हो कि भी स्थायी नहीं रहता यद्यपि

मे वह हमेशा गतिशीलता की स्थिति में रहता है। भारत भी इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं हो सकता। इसलिए पिछले वर्षों में भारतीय राजनीति में नये मोड़ उपस्थित हुए हैं। यहाँ उनकी विवेचना आवश्यक है।

भारतीय समाज का बदलता हुआ स्वरूप तथा उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव

स्वतन्त्रता के पूर्व भारतीय समाज परम्पराओं पर आधारित एक 'बन्द समाज' (closed society) था। स्वाधीन भारत ने अपनी जीवन यात्रा का आरम्भ ऐसी स्थिति से किया था जहाँ जीवन के समूचे मूल्य जातिवाद, सम्प्रदायवाद एवं अन्धविश्वासों के द्वारा निर्धारित होते थे। यहाँ से आरम्भ करके आज वह उम मजिल पर आ पहुँचा है जिसे हम 'खुले समाज' (open society) की सज्ञा प्रदान कर सकते हैं। वस्तुतः यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम भारतवासी उचित रूप से गर्व कर सकते हैं, परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि परम्परावादी समाज की सम्पूर्ण बुराइयों का अन्त हो चुका है तथा भारतीय समाज अब पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक सस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए समीचीन पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। यथार्थ में यदि इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो हम निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मजिल अभी भी बहुत दूर है। सच बात तो यह है कि भारतीय समाज की पुरानी बीमारियाँ अब नये रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, जाति-प्रथा और उस पर आधारित ऊँच-नीच की भावना पहले एक सामाजिक बुराई थी। उस रूप में उसका निस्सन्देह अन्त हो चुका है, परन्तु अब इस बुराई ने एक राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। फलतः एक बड़ी सीमा तक जनसाधारण का राजनीतिक आचरण विरादरी, जाति अथवा सम्प्रदाय की भावना से अनुप्राणित होता है। क्षेत्रीयता की भावना का भी इस समस्या को जटिल बनाने में एक योगदान रहा है। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि पिछले वर्षों में सकीर्ण आवारों पर राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। इस प्रकार के दलों का स्वरूप जहाँ क्षेत्रीय है वहाँ उनका सगठनात्मक आधार जाति अथवा सम्प्रदाय है। उदाहरणार्थ द्रमुक, अकाली दल तथा भारतीय क्रान्ति दल को लिया जा सकता है। द्रमुक तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, परन्तु उसकी सदस्यता की संरचना ब्राह्मण-विरोधवाद के आधार पर हुई है। इसी प्रकार अकाली दल के भी केवल पंजाब तक सीमित होने के कारण, क्षेत्रीय दलों में ही गिनती हो सकती है। परन्तु उसकी रचना भी केवल क्षेत्रीयता के आधार पर हुई हो, ऐसी बात नहीं है। उसके निर्माण में सिख सम्प्रदायवाद की निर्णायक भूमिका रही है। भारतीय क्रान्ति दल भी अखिल भारतीय दल होने का दावा नहीं कर सकता, वह केवल एक उत्तर प्रदेशीय सगठन है तथा साथ ही में वह केवल उन विरादरियों का सगठन है जो कृषि के साथ सम्बद्ध हैं। ऐसी विरादरियों में मुख्य रूप से जाट, अहीर और कुर्मी आते हैं। हरित क्रान्ति के फलस्वरूप इन विरादरियों की आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनकी आकांक्षा राजनीतिक शक्ति पर आधिपत्य स्थापित करने की है। स्वतन्त्र भारत के आरम्भिक वर्षों में भी इस प्रकार के दल पाये जाते थे, परन्तु देश के राजनीतिक जीवन पर उनका प्रभाव नगण्य था। किन्तु आज इस प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु में द्रमुक सत्तारूढ़ दल है तथा अकाली दल और भाक्राद पंजाब और उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों की भूमिका अदा करते हैं। कुछ समय तक ये दल भी शासक दल रह चुके हैं।

भारतीय राजनीति जातिवाद की भावना से किस सीमा तक ग्रसित है, इसका अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि यदि आज राजनीतिक नेताओं को उनकी अपनी विरादरी का समर्थन प्राप्त नहीं है तो वे राजनीति में सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। इस तथ्य के प्रमाण में दो उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। राजनीतिक नेता के रूप में चरणसिंह तथा कामराज की सफलता की उनकी अपनी-अपनी विरादरियों में गहरी जड़ों के आधार पर ही व्याख्या की जा सकती है। चरणसिंह जाट विरादरी के सम्मानित नेता हैं, दूसरी विरादरी वाले

उद्भूतता मानने का भी तथा नहीं है। उसी प्रकार कामगज अपना विराट्गो नाम पर विराट्गो में उत्तराधिकार प्रारम्भ है। स्वायत्तता प्राप्त करने के पूर्व भारतीय राजनीति जातिवाद के प्रकार के कुप्रभाव में मुक्त था। फलतः मूल्य राष्त्रीय जातिवाद का एक बर्तमान गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करने में तैयार नहीं था। परन्तु आज जाति के राजनीतिकरण के सम्बन्ध में हम बात की जा रही है। आज तो प्रत्येक विराट्गो के अपने अपने नेता हैं और यह हमारी बर्तमान स्थिति पर पहुँच चुकी है कि सत्ता का प्रसारण में पाय जान जाने आन्तरिक गुणा की रचना भी एक बर्तमान सीमा तक जाति के आधार पर होने लगी है। फलतः जब चुनाव के समय प्रत्यागियों का मन का टिकट दिया जाता है तो उस समय मुख्य ध्यान हम बात पर दिया जाता है कि उनकी विराट्गो क्या है तथा विराट्गो में कौन-सी विराट्गो बहुसंख्यक है।

स्वतन्त्रता के आरम्भ के बाद में कांग्रेस बहुधा अपना टिकट हम प्रत्यागियों को देती थी जिनका अपने विराट्गो क्षेत्र में कोई सम्बन्ध नहीं होता था। उदाहरण के लिए भीराना जजान का घर बनकत में था परन्तु उद्भूत चुनाव मामागत उत्तर प्रदेश में उठा। ठीक वैसेकर महाराष्ट्र में परन्तु उद्भूत भी दादर उत्तर प्रदेश में चुनाव उठा। उसी प्रकार कृष्ण मेहनत करने के विराट्गो हान हान भी दम्भ में दादर कांग्रेस के सफल प्रत्यागि रह चुके थे। परन्तु आज के राजनीतिक सम्बन्ध में हम प्रकार के उदाहरणों का क्वचिदपवाद के रूप में ही लक्षा जा सकता है। यदि किसी बाह्य बान (outsider) का टिकट मिल भी गया तो चुनाव में उसके विराट्गो हान की सम्भावना न के बराबर रहती है। 1971 के लोकसभा के चुनाव में जबकि कुछ गांधी के अनुयायी दल में अन्धविश्वास गांधी की आधी चतुर रनी की युनुस सलीम एक बाह्य बान का अनीगत स कांग्रेस का टिकट दिया गया था परन्तु उस बाधी के बावजूद भी युनुस सलीम चुनाव में विजयी नहीं हो सके थे।

नेत्रीयता और जातिवाद की बीमारियाँ की अभिव्यक्ति जहाँ नेत्रीय दल में आई है वहाँ कुछ जतिन भारतीय दल का भी इन भावनाओं का उभारने में कम योगदान नहीं रहा है। उदाहरणार्थ जनमध एक जतिन भारतीय दल है और उसका मुख्य आधार राष्त्रीय स्वयंसेवक दल के कार्यकर्ता हैं। आरम्भ में यह दल विराट्गोवाद और शत्रुवाद की बीमारियाँ से मुक्त था। पिछले वर्षों में उस भी नेत्रीयता और विराट्गो की भावनाओं को उत्तजित करने में सक्षम नहीं हुआ है। यह बान सक्षम है कि जाति के नेत्रीय आधार पर बर्तमान का माणव का जनमध का समयन प्राप्त था।

निम्नलिखित यह एक नए प्रवृत्ति है जिसका उदय पिछले वर्षों में भारतीय राजनीति में हुआ है और जिसकी जड़ भारतीय समाज के वर्तमान स्वरूप में अवस्थिति का जा सकता है।

भारतीय राष्त्रीय आन्दोलन के धर्म निरपेक्ष एवं असांख्यिक स्वरूप का सामाजिक सभी गांधी न मानना प्रचलन की है। फलस्वरूप वर्तमान शक्ति के उपराल दल के नवीन सविधान में हम निरपेक्षता के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार में है। परन्तु स्वाधीनता तथा स्वायत्तता के पूर्व के भारत के विभाजन के कुप्रभाव में अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जहाँ दल में साम्प्रदायिक आधार पर राजनीतिक दल संगठित हो रहे हैं वहाँ साम्प्रदायिकता का प्रगति करण साम्प्रदायिक दल के माध्यम में भी हुआ है। यह बात सविनिन्दित है कि दल में कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका आधार गुट साम्प्रदायिक है और हम प्रकार के दल में हिन्दू मतवादी और गिन सभी के साम्प्रदायिक दल शामिल हैं। उदाहरणार्थ यदि जनमध और निम्न मतवादी हिन्दू साम्प्रदायिक दल हैं तो मुस्लिम दल और मुस्लिम मजलिस मुस्लिम साम्प्रदायिक के साथ सम्बद्ध है। हमें प्रकार के दल मिल साम्प्रदायिकता में प्रयत्न रूप जुटा हुआ है। साम्प्रदायिक दल तो अभी भी जान बान दल चुनाव के समय अपने अपने साम्प्रदायिक समस्या की साम्प्रदायिक भावनाओं का उभारने का प्रयत्न करते हैं और अपने प्रकार के प्रयत्न में उद्भूत आगि रूप में सत्ता भागिना है। फलतः किसी हिन्दू सम्प्रदायिक विराट्गो क्षेत्र में मुस्लिम

प्रत्याशी की विजय को साधारणतः अपवाद के ही रूप में देखा जाता है। इसी तरह मुस्लिम-बहु-संख्यक निर्वाचन क्षेत्र में हिन्दू प्रत्याशी की विजय को भी सामान्यतः अनहोनी बात ही माना जाता है। मतदाता की इस प्रकार की मन स्थिति को सत्तारूढ़ दल के रवैये से भी बल पहुँचा है। अभी तक प्रत्येक निर्वाचन के समय कांग्रेस ने जिन आधारों को ध्यान में रखकर टिकटार्थियों के बीच टिकट बाँटे हैं उनमें उनका तथा निर्वाचन क्षेत्र का साम्प्रदायिक आधार मुख्य रहे हैं।

ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि साम्प्रदायिकता देश की राजनीति पर एक सीमा तक आच्छादित रहती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिक राजनीति के लिए जहाँ साम्प्रदायिक दल उत्तरदायी है, वहाँ उसके लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस का उत्तरदायित्व भी कुछ कम नहीं है। कांग्रेस येन-केन-प्रकारेण सत्ता में रहना चाहती है। इसलिए प्रत्येक चुनाव के समय सत्ता में बने रहने के लिए उसे किसी भी प्रकार के हथकड़े को अपनाने में सकोच नहीं होता। यदि एक तरफ कांग्रेसी नेता मसजिदों और दरगाहों में जाकर मुस्लिम जनता को सम्बोधित कर सकते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें तिरुपति के मन्दिर में जाकर तथा वहाँ के पुजारी से अपनी विजय के लिए आशीर्वाद लेने में भी सकोच नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि सम्प्रदायवाद हमारे राजनीतिक आचरण को निर्धारित करने में एक निर्णायक भूमिका अदा करने लगे तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ?

1967 के चुनावों के बाद राजनीतिक नेताओं के समक्ष कुछ ऐसी राजनीतिक विवशताएँ भी पैदा हुई हैं जिनका सामना करने के लिए उन्होंने साम्प्रदायिक दलों के साथ सॉट-गॉट को एक छोटी बुराई के रूप में अनिवार्य समझकर स्वीकार कर लिया। उदाहरण के लिए केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मुस्लिम लीग के साथ गठ-बन्धन किया है, भारतीय क्रान्ति दल ने मुस्लिम मजलिस को 1974 के चुनाव में अपना साझीदार बनाया था तथा 1967 के बाद देश के विभिन्न राज्यों में असाम्प्रदायिक दलों ने जनसंघ के साथ मन्त्रिमण्डलों की रचना की थी। इसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति में सम्प्रदायवाद को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो गया।

स्वतन्त्रता के आरम्भिक दिनों में असाम्प्रदायिक दलों से साम्प्रदायिक दलों के साथ किसी भी प्रकार का गठ-बन्धन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, परन्तु आज इस प्रकार के गठ-बन्धन हमारी राजनीति के लिए सामान्य बात बन चुके हैं, यह प्रवृत्ति शुभ नहीं है।

अन्त में यह कहना होगा कि भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष आज अनेक समस्याएँ हैं और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन समस्याओं का सन्तोषप्रद ढंग से हल किया जाय। भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वांछित परिवर्तनों को लाने में लोकतान्त्रिक राजनीति ने रचनात्मक योगदान दिया है। हमें आशा है कि हमारा लोकतन्त्र इन समस्याओं के हल करने में समर्थ हो सकेगा।

प्रश्न

- 1 भारतीय राजनीति के किन्हीं दो प्रमुख निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए।

भारत की विदेश नीति

(INDIA'S FOREIGN POLICY)

का भी राष्ट्र रक्षा व वातावरण में नहीं रहता वस्तुतः वह एक छोटी प्रणाली के अंतर्गत रहता है जिसमें अनेक राज्य हैं। इन राज्यों के ऊपर बाह्य के राज्यों की प्रणाली का अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः किसी भी देश की राजनीति का अध्ययन उसकी विदेश नीति के अध्ययन के बिना पूरा नहीं माना जा सकता।

आधुनिक और सैनिक दृष्टि से भारत को एक महाशक्ति नहीं है। उसके समक्ष अनेक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएँ हैं जो उसकी राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ी समस्या प्रस्तुत करती हैं। परन्तु उसके प्राबल्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रभाव बहुत अधिक रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया है। परिणामतः वह आरम्भ से ही अप्रतिरुद्ध विचार का नेता रहा है। इस स्थिति ने भारत को विश्व राजनीति में वह स्थान दिया है जिसकी वजह किसी भूत में शामिल होने के बाद कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह सही है कि पिछले वर्षों में विनाशजनक चीन के विरुद्ध युद्ध में पराजय पाने के बाद भारत की अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बर्बाद लगा था किंतु दशकों के स्वाधीन होने के उपरान्त भारत दक्षिण एशिया के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर आया है।

साठे दौर पर भारत की विदेश नीति को दो युगों में बांटा जा सकता है नहरू युग और उत्तरनहरू युग। जब तक नहरू जी जीवित थे वही भारत की विदेश नीति के निर्माता थे तथा वही उसका संचालक प्रकृत थे। एक समय तक वह भारत की ही नहीं अपितु समूचे नीमरे विश्व के सुपरिचिन्तक थे। यद्यपि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उनके सम्मान और प्रभाव में कुछ कमी आई थी तथापि इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके प्राबल्य उनकी प्रतिष्ठा अखिर तक सर्वाधिक रही। उनके निधन के पश्चात् भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान को एक धक्का लगा था।

भारत की विदेश नीति के आधार

भारत की विदेश नीति के सार में तीन तत्त्वों के ऊपर विशेष रूप से उनकी आवश्यकता है। ये तत्त्व हैं—भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति ऐतिहासिक अनुभव जिसमें परम्परागत जीवन पद्धति और उस पर विदेशी प्रभाव दोनों शामिल हैं तथा आन्तरिक शक्तियाँ और स्वायत्तता।

यदि भारत के मानचित्र पर दृष्टिपात किया जाय तो हम सहज में ही भारत के भौगोलिक एवं सामरिक महत्त्व का अनुमान लगा सकते हैं। 1903 में भारत के एक भूतपूर्व गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने यह भविष्यवाणी की थी कि भारत की भौगोलिक स्थिति उसे अधिकाधिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख स्थान की ओर खिंचेगा और भूमिका अत्यन्त बड़ी होगी। 1948 में नहरू जी ने कहा था कि भारत की स्थिति दक्षिणी दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी एशिया में एक सुरीली कड़ी की है।

भारत अपने उत्तर में विश्व के सबसे ऊँचे पर्वतों से घिरा हुआ है उसके दक्षिण में हिन्द

महासागर स्थित है, उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। भारत के पश्चिमी सीमान्त पश्चिम पाकिस्तान की सीमाओं से मिलते हैं तथा पूर्वी सीमान्त बंगला देश की सीमाओं से टकराते हैं। भारत का समुद्री तट 3500 मील लम्बा है तथा यदि पाकिस्तान और बंगला देश के साथ मिलने वाले सीमाओं को शामिल कर लिया जाय तो उसके भूमि पर स्थित सीमान्तों की लम्बाई 8200 मील है। भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे राज्य पाकिस्तान के साथ कटुतापूर्ण सम्बन्ध उसे औपनिवेशिक दासता से विरासत के रूप में मिले हैं। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध आरम्भ हो गया तो उस समय देश में पहली बार यह अनुभूति हुई कि पाकिस्तान से मिलने वाले सीमान्तों के अतिरिक्त भी उसके ऐसे अन्य सीमान्त भी हैं जिनकी सुरक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती। चीन के साथ उसकी सीमाये 1500 मील लम्बी हैं। सोवियत सीमाये भारत के काश्मीर प्रदेश से कुछ मील के फासले पर स्थित हैं। नेपाल और भूटान की सुरक्षा में भारत की स्वयं की सुरक्षा निहित है। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम का एक छोटा सा राज्य था जो भारत का एक संरक्षित क्षेत्र था परन्तु जिसका अब भारत में विलय हो चुका है।

हिन्द महासागर में भारत की स्वाभाविक अभिरुचि है। एक दीर्घ समय तक भारत का हिन्द महासागर से होकर विदेशी व्यापार हुआ है। अतः अपने व्यापार की ही अभिवृद्धि के लिए भारत के लिए यह परमावश्यक है कि वह हिन्द महासागर को एक शान्ति के क्षेत्र के रूप में विकसित करे। हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने में भारत की रुचि इसलिये भी है क्योंकि इसके साथ उसकी सुरक्षा की समस्या भी अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। पिछले वर्षों में हिन्द महासागर महाशक्तियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना है। यदि इसके परिणाम-स्वरूप भारत में चिन्ता की लहर दौड़ी है तो यह स्वाभाविक ही है।

भारत की विदेश नीति के निर्धारण में उसके ऐतिहासिक अनुभव का योगदान कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भारत ने एक लम्बे समय तक साम्राज्यवादी शोषण एवं उत्पीड़न का अनुभव किया था। अतः 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ जाने के बाद भी भारत के जनमानस में वे सब कड़वी यादें अंकित थीं जिनका सम्बन्ध औपनिवेशिक शासन के साथ था। अतः यह आवश्यक था कि भारत की विदेश नीति का स्वरूप साम्राज्य-विरोधी होता।

भारत की विदेश नीति के निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका आन्तरिक शक्तियों और दवावों की रही है। आन्तरिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राज्य नहीं है। उसमें आन्तरिक दुर्बलताये हैं, उसमें राष्ट्रीय एकता का अभाव है तथा आर्थिक दृष्टि से वह एक पिछड़ा हुआ देश है। राजनीतिक दृष्टि से भी नेहरू जी के निधन के पश्चात् स्थिति 1971 के चुनावों तक डावाडोल रही। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि देश की आन्तरिक समस्याये भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती। उत्तर-नेहरू काल में आन्तरिक एवं विदेश नीति के बीच की कड़ी स्पष्ट रूप से अवलोकित की जा सकती थी। 1964 के बाद 1971 तक भारत की विदेश नीति सक्रिय नहीं थी। इस काल में भारत ने विश्व की विवादग्रस्त समस्याओं पर ध्यान न देकर केवल इस बात पर ध्यान दिया कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ उसके सम्बन्ध किस प्रकार सुधारे जाने चाहिए। फलतः इस काल में देश के नीति-निर्माताओं का ध्यान केवल चीन और पाकिस्तान पर केन्द्रित रहा। इस काल में विरोधी दलों और दवाव समूहों ने भी विदेश नीति को प्रभावित करने में विजिप्त योगदान दिया। इस प्रकार के समूहों में व्यापारिक हित समूह तथा साम्प्रदायिक हित समूहों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। व्यापारिक समूह जिनमें फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रमुख हैं पड़ोसी देशों के साथ अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए अच्छे सम्बन्ध चाहते थे, फलतः उनके दवाव पर भारत ने नेपाल, श्रीलंका और बर्मा के साथ अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाये।

गुट निरपभता (Non alignment)

सामान्यतः भारत का विदेश नीति गुट निरपभता की नीति के नाम से जानी जाती है। कुछ समय के बाद विदेश नीति को प्रमुख है गुट निरपभता का तत्त्व का ही परिभाषा की जाती है। वस्तुतः यह विचार आन्तिमिक है। यह तत्त्व में कृष्ण मेहनत का मनुष्य राष्ट्र में की जनता में समानता में ही यह भाषा का यह ही उद्देश्य है— हम तत्त्व में नहीं है। हम गुट और पालिका सम्बन्ध में तत्त्व नहीं है। हम साम्राज्यवादी या अथवा अन्य का द्वारा आधिकार स्थापन करने के सम्बन्ध में ही तत्त्व नहीं है। हम नैतिक मूल्यों के सम्बन्ध में तत्त्व नहीं है। हम नैतिक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में तत्त्व नहीं है। वित्त का भी यह ही मकत है। हमारा स्थिति यह है कि हम शीत-युद्ध के सम्बन्ध में गुट निरपभता अप्रतिरुद्ध है। स्वयं नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में एक बार कहा था— जहाँ स्वतंत्रता का चुनावों का जानी है वहाँ पालिका स्तर में है हम ने तत्त्व में और तत्त्व रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुट निरपभता और तत्त्वता समान अर्थ रखने वाले नहीं हैं। वास्तव में तत्त्वता एक निरपभता (negative) विचार है जबकि गुट निरपभता का एक स्वाकारात्मक (positive) विचार समझा जाना चाहिए। एक अन्तर्गत राज्य अन्तर्गत ममस्याओं के ऊपर अपना नियंत्रण किता पूरापूरा के आधार पर नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप में उनमें निहित सहायता और सुरक्षा के आधार पर है। स्वाधीन हान के बाद भारत ने विदेश नीति के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने का प्रयास किया है। यहाँ गुट निरपभता के सिद्धान्त में सन्निहित मायताओं की विवेचना करना समीचीन होगा।

यह सम्बन्ध में सर्वप्रथम ध्यान में रखने की बात यह है कि गुट निरपभता को अपरिबर्तनीय विचार अथवा सिद्धान्त नहीं है वास्तव में यह एक गतिशील विचार है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नये नये प्रयत्न करता है। प्रश्न है कि गुट निरपभता क्या अभिप्राय है? माटे तौर पर गुट निरपभता वह सिद्धान्त है जिसका मानना जाता है कि अन्तराष्ट्रीय संघटन के उद्देश्य हान के सिद्धि में यह प्रश्न का उत्तर नहीं देना कि कौन सहा है बल्कि यह प्रश्न का उत्तर यह का प्रयत्न करता है कि क्या सहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुट निरपभता अपने आप को किता गुट में नहीं बाँधता बल्कि वह स्वतंत्र विदेश नीति अनुमान करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुट निरपभता एक स्वाकारात्मक विचार है वास्तवता का नीति निरपभतात्मक विचार नहीं है।

गुट निरपभता के सम्बन्ध में ध्यान में रखने की बात यह है कि आधुनिक सम्बन्ध में वह सामान्यतः विरोध की मूक है। यह बात की समझने के लिए यह बात रखना उपयोगी होगा कि आज अधिकांश गुट निरपभता यह है जो कुछ समय पूर्व तक औपनिवेशिक दासता के अधीन में थी। आज स्वतंत्र हान के उपरान्त यहाँ अपने स्वतंत्र अर्थ प्रवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। वास्तव में ऐसा करके ही वे अपने आप को दासता के अधीन से मुक्त कर सकते हैं क्योंकि आज भी इन देशों का अर्थतन्त्र एक बड़ी सीमा तक पुराने सामान्यवादी शासन के द्वारा नियंत्रित हाना है। यदि इन देशों को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की रचना में सफलता मिल जाती है तो उस स्थिति में इन सामान्यवादी देशों के बाजार की सीमायें निकुं जायगी। स्पष्ट यह वह स्थिति है जिसे कोई भी सामान्यवादी नहीं महसूस कर सकता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह स्थिति की प्राप्ति करने के लिए नये शासन के लिए यह परमावश्यक है कि वे नैतिक विभिन्न गुणों से जलते रहकर अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें। गुटबाजी में फँस जाने के बाद उनमें इस बात की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वे अपने आर्थिक पुनर्निर्माण पर समुचित ध्यान दे सकें।

यदि गुट निरपभता सामान्य विचार की अभिव्यक्ति है तो उस स्थिति में उस मायका

रूप से समाजवादी देश का समर्थक होना चाहिए। वास्तव में समाजवादी देशों ने इन राज्यों के अर्थतन्त्र को अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता प्रदान करने में भारी योगदान दिया है। यह एक जानी-पहचानी बात है कि जहाँ पश्चिम के साम्राज्यवादी राज्यों ने हमें उपभोक्ता वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में दी, वहाँ सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों ने हमारी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि गुट-निरपेक्षता कभी भी समाजवादी देशों के विरुद्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार समाजवादी राज्यों के साथ मैत्री-सम्बन्धों को गुट-निरपेक्षता की दूसरी मूलभूत मान्यता घोषित किया जा सकता है।

गुट-निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं करती। यथार्थ में जैसा कहा जा चुका है कि उसका प्रतिपादन भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, उसके आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया और सच बात यह है कि इस नीति के अनुसरण से देश को लाभ भी पहुँचा है। अपने आर्थिक विकास के लिए हमें शक्ति के दोनों गुटों से सहायता प्राप्त हुई है। यदि एक गुट ने हमें उपभोक्ता वस्तुओं की सहायता दी है, तो दूसरे ने हमें भारी उद्योग दिये हैं जिनकी सहायता से देश आज अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ है। स्पष्टतः इस प्रकार की सहायता की उस समय अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता। राजनीतिक दृष्टि से भी गुट-निरपेक्षता की नीति देश के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। देश 1947 में स्वाधीन हुआ था, परन्तु अपनी स्वाधीनता के थोड़े ही दिनों में वह तीसरे विश्व का जाना-पहचाना अधिकृत प्रवक्ता था। 1952 से आरम्भ होने वाले दशक में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इतनी अधिक प्रतिष्ठा बढ़ी थी कि सोवियत प्रधानमन्त्री क्रेम्लिन ने यह सुझाव दिया था कि भारत को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि को गुट-निरपेक्षता की तीसरी बुनियादी मान्यता बताया जा सकता है।

उपर्युक्त मान्यताओं की कसौटी पर नेहरू जी के जीवन काल के अन्तिम दिनों की भारतीय विदेश नीति की समीक्षा की जा सकती है। उस समय देश भयंकर आर्थिक संकट में होकर गुजर रहा था, तीसरी योजना के लक्ष्य खतरे में पड़ गये थे, चीन की लड़ाई ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्णरूप से झुकाने दिया था। यही नहीं चीन के विरुद्ध युद्ध में उसे जो असफलता मिली थी उसने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसके सम्मान को बड़ा आघात पहुँचाया था। इस पृष्ठभूमि में स्वयं देश में भारत की विदेश नीति के औचित्य में सन्देह व्यक्त किया जाने लगा था। संसद में भी इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। स्वयं नेहरू जी ने इस आलोचना के औचित्य को स्वीकार किया था, उन्होंने कहा था कि हम अभी तक अवास्तविकता के ससार में रह रहे थे। परन्तु इसके साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि 'हम अपनी वर्तमान कठिनाई के कारण अपने मूल सिद्धान्तों को छोड़ने नहीं जा रहे।'।

पिछले वर्षों में चीन और पाकिस्तान ने भारत की गुट-निरपेक्षता को 'दुहरा गठबन्धन' (Double alignment) की सजा प्रदान की थी। इन देशों का कहना था कि भारत ने गुट-निरपेक्षता के नाम पर संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ दोनों से सहायता प्राप्त की है। पहले तो उसे दोनों खेमों से सहायता मिलती थी, परन्तु पिछले दिनों में उसे केवल सोवियत संघ से सहायता मिली है। इस प्रकार उनका यह निष्कर्ष है कि भारत की गुट-निरपेक्षता या तो 'दुहरा गठबन्धन' का छद्म नाम था जथवा पिछले वर्षों में उसने सोवियत संघ के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध कायम करके गुट-निरपेक्षता को तिलाजलि दे दी है। वस्तुतः ये दोनों आलोचनाएँ गलत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में ऐसे गुट-निरपेक्ष देशों के उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने विश्व की दोनों महाशक्तियों से सैनिक और आर्थिक सहायता प्राप्त की थी और जिनकी गुट-निरपेक्षता में कभी भी किसी ने सन्देह व्यक्त नहीं किया था। यूगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य (मिन) तथा इण्डोनेशिया इसी प्रकार के देश हैं। दूसरे, यदि पिछले वर्षों में भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों में जबकि प्रगाढ़ता आई है तो ऐसा होना स्वाभाविक ही था। उस समय जबकि

गीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था पश्चिमी गुट निगपन अमरीकी विदेश मन्त्रि मन्त्र गुट निरपेक्षा का जननिक मानत थे यथा उनकी दृष्टि में वह कम्युनिस्ट देशों के साथ गठबंधन करने के लिए बंधन आवश्यक मानता था। उसके विपरीत सोवियत संघ ने भारत को गुट निरपेक्षा का मन्त्र में साम्राज्य विरोध की अभिव्यक्ति माना है यद्यपि भारत की राष्ट्रमण्डल की सम्मति उसकी समझ में नहीं आई। परन्तु जब कान्फ्रेंस में उसके समक्ष यह प्रमाणित होने लगा कि राष्ट्रमण्डल की सम्मति के बावजूद भी भारत स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की क्षमता रखता है तो उस भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में कार्यरत नहीं आया।

महाशक्तियों के साथ सम्बन्ध

गीत-युद्ध में उग्रता जान के पूर्व भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के पारस्परिक सम्बन्धों के ऊपर कभी काँट बिचार नहीं करता था। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारत के अमरीका के साथ काँट मतभेद नहीं थे। उदाहरण के लिए भारत ने कांग्रीस के प्रश्न पर अमरीकी दृष्टिकोण की हमारा आलोचना की। उसके प्रतिरूप भारत ने अमरीका की औपनिवेशिक नीतियों का कभी समर्थन नहीं किया। 1949 में जब चीन के गृह युद्ध में पराजित होने के बाद व्यापक दार्शनिकों के फारमूला भाग जान के लिए बाध्य होना पड़ा और वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार स्थापित हुई तो भारत और अमरीका के बीच एक गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया क्योंकि भारत ने न केवल चीन के नये राज्य को मान्यता प्रदान करनी बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उस स्थान निश्चय का प्रयत्न किया। उसके उपरान्त जब कोरिया का युद्ध आरम्भ हुआ उस समय भी भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के पारस्परिक मतभेद सुनकर सामने आये। अमरीका युद्ध में भारत का सक्रिय संयोग चाहता था परन्तु इसके विपरीत उसने उस युद्ध में मध्यस्थता के लिए प्रयास किया और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने 38वीं समानांतर रेखा को पार किया तो भारत ने उसका डटकर विरोध किया। जान में जब अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना आरम्भ किया तो यह स्वाभाविक ही था कि दोनों देशों के बीच कन्वाहट पैदा होती। 1957 में प्रधानमंत्री नेहरू ने संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की थी। उस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और अमरीका के सम्बन्धों में कुछ सशान हुआ था। परन्तु उस यात्रा के पश्चात् अमरीकी सरकार ने आन्जनहाउस मिशन का प्रतिपादन किया और जेनरल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सैन्य भेजी। भारत ने अमरीका के दोनो कार्यों का विरोध किया। 1959 में राष्ट्रपति आन्जनहाउस की भारत यात्रा के बाद दोनो देशों के बीच फिर से जटिल सम्बन्धों का शीर्षक हुआ। परन्तु इसके पश्चात् कुछ एसी घटनाएँ फिर घटी जिन्होंने दोनों देशों के सम्बन्धों में बिगाड़ पैदा कर दिया। दिसम्बर 1961 में जब भारत ने गांधी का पुतला दासता से मुक्त किया तो संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत के इस कार्य की कटु आलोचना की। उस समय अमरीकी प्रतिनिधि स्टीवसन ने नाटकीय रूप में यह घोषणा की थी आज राष्ट्र का हम उस नाटक के प्रथम अंक को देख रहे हैं जिसका अन्त संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के साथ हो सकता है। पुतला की उपनिवेशवाद के मन्त्रिज समर्थन के उपरान्त यह स्वाभाविक ही था कि भारत में अमरीका विरोधी भावनाएँ मजबूत होनी।

नवम्बर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय अमरीका ने भारत का सैनिक सहायता दी। परन्तु इस सहायता के देने में भी अमरीका ने उस उदारता का परिचय नहीं दिया जिससे उसमें अपेक्षा की जाती थी। भग्न उस समय एम. दान के विरुद्ध युद्ध चल रहा था जिसमें अमरीकी शासकों की नाट्यपूर्ण कर रहीं थी। अब उस युद्ध में अमरीका का उन्मुख हृदय में मर्यादा करने की चाहिए थी। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अमरीकी शासकों का तर्क में क्या गया कि वे आधुनिक शास्त्रज्ञ हमसे उसी समय के संकट में जबकि पाकिस्तान के साथ वे मोर के प्रश्न पर हमारे विवाद का अन्त हो जाय। चूँकि पाकिस्तान से हमारा कोई

समझौता न हो सका, इसलिये जिन शस्त्रास्त्रों की हमें आवश्यकता थी, वे हमको अमरीका से प्राप्त नहीं हो सके। परन्तु इसके बावजूद भी भारत में चीनी आक्रमण के उपरान्त अमरीका के लिए सद्भावना मौजूद थी और बहुत सम्भव था कि यह सद्भावना कालान्तर में स्थायी भी हो जाती। परन्तु ऐसा इसलिये नहीं हो सका क्योंकि फरवरी 1963 में जब पाकिस्तान ने काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् में फिर से प्रस्तुत किया तो उस समय अमरीकी प्रतिनिधि ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इससे फिर भारत में अमरीका के विरुद्ध कटुता की भावनाएँ पैदा हुई हैं। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय भी अमरीका ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। यह वह समय था जब भारत में अन्न का उत्पादन बहुत कम हुआ था और इस कमी को पूरा करने के लिए अमरीका ने हमें गेहूँ भेजने का वायदा किया था। परन्तु इस युद्ध के पश्चात् अमरीका ने हमें गेहूँ भेजने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार 1971 में बंगला देश के मुक्ति-संघर्ष के समय भी अमरीका की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी। अतः इस पृष्ठभूमि में यदि भारत में अमरीकी विरोधी भावनाएँ बलवती हुई हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1975 में अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देना फिर से आरम्भ कर दिया। यही नहीं, हिन्द महासागर में स्थित डिआगो गार्शिया नामक टापू में उसने अपना सैनिक अड्डा भी इसी काल में बनाया। इसमें दोनों पक्षों के बीच विरोध बढ़ा है। यथार्थ में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के पारस्परिक सम्बन्धों का जितना विगाड़ आज पाया जातो है उतना पहले कभी नहीं था।

दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ के साथ भारत के सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। 1946 और 1947 में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भारत और सोवियत संघ के दृष्टिकोण एक से ही थे। उदाहरण के लिए, भारत और सोवियत संघ के बीच मूलवश के आधार पर भेदभाव, उपनिवेशवाद, निःशस्त्रीकरण, एटम बम तथा वीटो के प्रश्नों पर एक में ही दृष्टिकोण था। वस्तुतः इन दोनों देशों के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर मतभेद को देखकर डलेस ने कहा था कि 'भारत में सोवियत कम्युनिज्म अन्तरिम हिन्दू सरकार के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।' परन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चली, थोड़े ही समय में यूनान और कोरिया के प्रश्नों पर इन दोनों में मनमुटाव पैदा हो गया। इसी समय भारत ने ब्रूसेल्स की सन्धि को मान्यता दे दी। निश्चय ही, भारत का यह काम सोवियत संघ को रुचिकर नहीं हो सकता था। इसी पृष्ठभूमि में अप्रैल 1949 में सोवियत प्रेस ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ साँठ-गाँठ कर रही है। परन्तु 1949 के अन्त तक दोनों देशों के सम्बन्धों ने एक दूसरा मोड़ लिया। इस काल में चीन में कम्युनिस्टों की सरकार स्थापित हो गई थी और भारत उसे मान्यता प्रदान करने वाला पहला गैर-कम्युनिस्ट देश था। इसके फलस्वरूप भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों में भी सुधार होने लगा। परन्तु जून 1950 में जब कोरिया में युद्ध आरम्भ हुआ तो भारत ने पश्चिमी देशों के स्वर में स्वर मिलाकर उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। भारत का यह काम सोवियत संघ में रोप पैदा करता, यह स्वाभाविक था। भारत को भी अपनी गलती का अनुभव हुआ और उसने अपनी भूल को सुधारने के लिए जुलाई 1950 में कोरिया में युद्ध-विराम की अपील की। इस अपील का सोवियत संघ में समुचित स्वागत किया गया। फलतः दोनों देशों के सम्बन्धों में एक बड़ी सीमा तक प्रगति आई। 1951 में भारत ने अमरीका के उस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया जिसमें कोरिया में चीन को आक्रान्ता कहा गया था। भारत-सोवियत सम्बन्धों के ऊपर इसका भी अनुज्ञ प्रभाव पड़ा। परन्तु दिसम्बर 1952 में कोरिया के युद्धवन्दियों के प्रश्न पर सोवियत संघ और भारत के बीच पुनः मतभेद पैदा हो गये। विशिस्की ने संयुक्त राष्ट्र संघ की असेम्बली में भाग लेने की जासूसी करने हुए यह कहा कि भारत की नीति में तनाव के बढ़ने की आशंका है।

1954 में अमरीका की प्रेरणा ने नीटो और बगदाद पैक्टों की रचना हुई। भारत ने इन नैतिक गुटवन्दियों का कड़ा विरोध किया। अतः इस पृष्ठभूमि में यह स्वाभाविक ही था कि

सोवियत मध के साथ उसके सम्बन्धों में सुधार होता। इसी काल में नहरू जी ने सोवियत संघ की तथा युगान्ति और स्त्राचव न भारत की यात्रा की। इन यात्राओं ने दोनों देशों को एक-दूसरे के समीप लाने में बड़ा योगदान दिया। सोवियत संघ ने काश्मीर और गोवा के प्रश्नों पर भारत का समर्थन पूर्ण प्रयत्न भारतवासी के हित में अपने लिए सद्भावना को पदा करने में सफलता प्राप्त की। इस अनिच्छित उस काल में सोवियत संघ ने भारत को तकनीकी और आर्थिक सहायता भी प्रचुर मात्रा में प्रदान की। भिलाई के स्थापना कारखाने भारत सोवियत मंत्री का एक गतिशील आधार प्रदान किया है। वात में वाहनों के स्थापना कारखाने के निर्माण में भी सोवियत संघ की सहायता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राजनीतिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच एक दूसरे के प्रति सद्भावना ही पायी जाती रही है। उदाहरण के लिए निस्त्रीकरण के प्रश्न पर भारत ने सोवियत एशिया के आम तौर पर समर्थन किया है।

1966 के बाद सोवियत संघ भी विश्व व्यापार में अस्वास्त्र बेचने लगा और पाकिस्तान भी उसके पास ग्राहक के रूप में पकड़ गया। स्पष्टतः संघ के लिए पाकिस्तान को अस्वास्त्र बेचने से इनकार करना सम्भव नहीं हो सकता था। परन्तु भारत में उसकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं हुई। भारत सरकार ने सोवियत संघ का एक पत्र त्रिवेणर उस सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की। उस में निम्नलिखित राजनीतिक क्षेत्रों पर इसका ऊपर जना गुल्ता भी बहुत मचाया और उन्होंने अपनी उस मति का दुबारा दोहराया कि भारत को पश्चिमी गुट में शामिल हो जाना चाहिए। परन्तु उस समय सोवियत संघ ने भारत को यह पक्का आश्वासन दिया कि पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ के सम्बन्ध भारत के प्रति मनी की कोमत पर निर्मित नहीं किए जायेंगे। सोवियत संघ का यह आश्वासन कितना पक्का था उसका प्रमाण हम उस समय मिला जबकि यंगना देश के मुक्ति-संघ की पृष्ठभूमि में भारतीय पक्ष का समर्थन करने का उत्तरदायित्व बचन समाजवादी देशों ने ही निभाया था। उस समय 9 अगस्त 1971 को दोनों देशों ने मित्रता और सहायता की एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उस संधि पर स्ताक्षर करने के लिए सोवियत विदेश मंत्री गोमिका स्वयं नहीं दिखी आये थे। इस संधि ने भारत-सोवियत सम्बन्धों को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया। यह संधि हमारे देश के लिए कितनी उपयोगी थी उसका प्रमाण हम उस समय मिला जब किम्बर 1971 में हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के लिए राष्ट्रीय हाना पना। जना बना जा चुका है उस समय अमरीका गुप्तकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। जब यंगना देश में पाकिस्तान का पराभव सन्निकट था उस समय उसका मतवा उड़ा गगान की लानी में प्रवा भी कर चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रसम्भनी और सुरक्षा परिषद में उसने भारत के विरुद्ध मतदान को संगठित कराने में एक प्रमुख भूमिका अदा की थी। परन्तु उस समय सोवियत संघ के साथ मनी ही हमारे काम आई।

उस प्रकार निष्पक्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्धों में उतार चढ़ाव जा रहे हैं तथापि दोनों देशों के बीच सद्भावना का कभी काइ अभाव नहीं रहा।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध

1947 में देश का विभाजन काग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति में हुआ था फिर भी उसमें इन उज्जात रायों के बीच पाय जान बान सम्बन्धों में कां मुधार नहीं हुआ। एक विपरीत न निरन्तर गिड़गिड़ने लगे। वस्तुतः जिस दो राष्ट्यों के सिद्धान्त के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था उस सिद्धान्त में ही हिंसा और भारत के प्रति घृणा बीज रूप में है निहित था। अतएव एसी स्थिति में उस बात की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी कि उस घृणा करने वाले राज्य के साथ सम्बन्धों काधारण हो सकें। यही यह उल्लेखनीय है कि भारत ने अनेक

अवसरो पर पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले 1949 में इस प्रकार के समझौते का प्रस्ताव उसके सामने रखा गया, 1956 में नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को दोबारा प्रस्तुत किया, नवम्बर 1962 में पाकिस्तान से एक बार फिर इस आशय की अपील की गई, परन्तु पाकिस्तान इसके लिए कभी तैयार न हुआ। नेहरू जी के निधन के उपरान्त 15 अगस्त 1964 को लालबहादुर शास्त्री ने इस प्रस्ताव को फिर दोहराया। परन्तु भारतीय नेताओं के इन वक्तव्यों का पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। वस्तुतः दोनों देशों के समक्ष कुछ समस्याएँ भी ऐसी थीं जिनका समाधान आसान नहीं था।

भारत और पाकिस्तान के बीच पाये जाने वाले विवादों में सबसे अधिक गम्भीर विवाद का सम्बन्ध काश्मीर की समस्या के साथ है।

नवम्बर 1947 में दोनों देशों की सेनाओं में खुली लड़ाई आरम्भ हो गई। भारत ने यह समस्या सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत की। परिषद् ने समस्या का निराकरण करने के लिए अनेक जाँच एवं मध्यस्थता आयोग नियुक्त किये। इनसे युद्ध तो रुक गया, परन्तु दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। फलतः दोनों देशों के बीच सीमा-सम्बन्धी विवाद उठते रहे, यात्रा सम्बन्धी नियन्त्रण जारी रहे तथा दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना बन्द नहीं किया। इस बीच पाकिस्तान ने अमरीका की सैनिक गुट-बन्धियों की सदस्यता स्वीकार कर ली जिसके परिणामस्वरूप उसे अमरीकी सैनिक सहायता प्रचुर मात्रा में मिलने लगी। ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों से यदि और अधिक तनाव उत्पन्न हो गया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी।

1958 में पाकिस्तान में एक सैनिक क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप जनरल अयूब ख़ाँ वहाँ के सर्वेसर्वा बन गये। इस नये शासन की स्थापना के उपरान्त भारत-पाक सम्बन्धों में एक नये युग का समारम्भ हुआ। सद्भावना बढ़ी, कुछ समझौते भी हुए। परन्तु इतना होते हुए भी काश्मीर के प्रश्न पर दोनों देशों में कोई समझौता नहीं हो सका। नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा था कि वर्तमान युद्ध-विराम रेखा के आधार पर दोनों पक्षों में कोई समझौता हो जाना चाहिए। परन्तु पाकिस्तान को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था।

कुछ दिन बाद अयूब ख़ाँ ने भारत के समक्ष एक 'संयुक्त-सुरक्षा समझौता' करने का सुझाव रखा। परन्तु भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में इसलिए असमर्थ था क्योंकि उससे भारत की गुट-निरपेक्षता पर आघात पहुँचता था।

इसी समय दोनों देशों के बीच एक नवीन समस्या पैदा हो गई। यह समस्या कच्छ-सिन्ध सीमान्तों से सम्बद्ध थी। जनवरी 1960 में इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह निश्चित हुआ कि दोनों पक्ष इस समस्या का निराकरण करने के लिए आपस में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान सरकार ने पाँच वर्ष तक खामोश रहने के बाद यकायक जून 1965 में बल-प्रयोग के द्वारा अपने दावों को मनवाने का प्रयत्न किया। कच्छ के रन में भारतीय सीमाओं के भीतर कुछ भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने अधिकार स्थापित कर लिया। निस्सन्देह पाकिस्तान का यह काम अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। ऐसा लगता था कि दोनों देशों में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाएगा परन्तु ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अपील पर 30 जून 1965 को दोनों पक्ष युद्ध-विराम के लिए तैयार हो गये।

मामला अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के 90 प्रतिशत दावों को अस्वीकार कर दिया।

भारत-पाक संघर्ष—कच्छ के रन पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उसकी स्याही भी सूखने नहीं पाई थी, तब तक पाकिस्तान ने भारत के लिए एक दूसरी समस्या खड़ी कर दी। 5 अगस्त 1965 को हजारों की संख्या में पाकिस्तानी घुमपैठिये सादा कपड़ों में आधुनिक शस्त्रास्त्र से लैस होकर काश्मीर में घुस आये। निस्सन्देह पाकिस्तान का यह

नाम भारत की प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखण्डता का एक चुनौती था। अतः इसका जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा सना न पाकिस्तान से आये हुए इन घुसपट्टियों का सफाया करना आरम्भ कर दिया। युद्ध विराम रेखा को नाश कर वे सारे प्रवेश द्वार बंद कर दिये जहाँ से होकर पाकिस्तानी हमलावर काश्मीर में आ रहे थे। जवाब में पाकिस्तान ने 1 सितम्बर 1965 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जम्मू के छम्ब क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने न केवल आधुनिकतम अमरीकी पटन टैंकों तथा सार्वर जेट विमानों का प्रयोग किया अपितु हवाई हमला में राकेटों तथा मिसाइलों का भी प्रयोग किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने न केवल युद्ध छेड़ने में पहल की बल्कि सघष को व्यापक रूप देने में भी उसी ने पहनकदमी की। विना हाकर भारत ने भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने तथा पाकिस्तानी क्षेत्र में अपनी सेनाओं का प्रवेश कराने का फैसला किया।

लगभग तीन सप्ताह के घमासान युद्ध के पश्चात् 23-24 सितम्बर 1965 की रात्रि को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। इस युद्ध के फलस्वरूप कारगिल से सिंध-बान्धेर तक के मोर्चों पर युद्ध विराम के समय तक लगभग 700 वर्गमीन पाकिस्तानी भूमि भारत के अधिकार में आ चुकी थी। कारगिल की चौकियों के अतिरिक्त टिथवान (20 वर्ग मील) और उडी-मुछ (200 वर्ग मील) क्षेत्र में भारत उस प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हुआ जिसे काश्मीर की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान में म्यानकोट (180 वर्ग मील) गहौर कसूर (140 वर्ग मील) जीर सिंध (150 वर्ग मील) क्षेत्र पर भी भारतीय सेनाओं का अधिकार हो गया।

कुछ भारतीय भूमि पर पाकिस्तान का भी अधिकार स्थापित करने में सफलता मिली। जम्मू के छम्ब जोरिया क्षेत्र में 190 वर्ग मील तथा खमकरण क्षेत्र में 20 वर्ग मील भारतीय इलाका पाकिस्तान के अधिकार में पहुँच गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने कुछ भूमि राजस्थान में भी अपने अधिकार में कर ली।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युद्ध में पतड़ा भारत का ही भारी रहा। यह बात इस तथ्य से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 50 टैंकों पर कब्जा कर लिया और लगभग 500 टैंकों को नष्ट कर लिया। सैनिक पयवशका के अनुसार पाकिस्तान की दो तिहाई बख्तरबंद सेना नाकाम हो गई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के 75 विमान जो पाकिस्तानी मार करने वाले विमानों के आगे से अधिक हैं भी नष्ट कर लिये।

इस सघष के समय सोवियत संघ एक ऐसा देश था जिसने भारत के न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन किया। सोवियत संघ जानता था कि भारत और पाकिस्तान का सघष जीपनिवशिक युग की एक विस्तार है उपनिवेशवादिक नैज्जन वणित स्वायत्तों की प्रति के निरन्तर प्रदायवा को प्रोत्साहन दिया था जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में पारस्परिक शत्रुता एवं सघष के लिए भूमिका प्रस्तुत हुई थी। अतः सोवियत संघ ने इस शत्रुता का निराकरण करने के लिए भारत और पाकिस्तान के शासनाध्यक्षाओं को तात्काल में एक दूसरे से इस सम्बन्ध में बात करने के लिए आमन्त्रित किया। पहल तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति अय्यूब ने इस निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया परन्तु बाद में वे इसे स्वीकार करने के लिए राजी हो गये। इस प्रकार जनवरी 1966 के पहले सप्ताह में सोवियत संघ के एक नगर ताशकन्द में दोनों देशों के शासनाध्यक्षाओं का एक सम्मेलन सोवियत प्रधानमंत्री कोसीगिन की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की समाप्ति पर 10 जनवरी 1966 को दोनों शासनाध्यक्षाओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता ताशकन्द घोषणा के नाम से प्रख्यात है।

ताशकन्द घोषणा—इस घोषणा में केवल 9 अनुच्छेद हैं जो निम्नलिखित हैं—

(1) दोनों राज्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि उन्हें अर्च्छ पक्षियों के सम्बन्ध कायम करने के लिए समुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार पूरे प्रयत्न करने चाहिए। उन्होंने अपने

इस उत्तरदायित्व को भी स्वीकार किया कि वे अपने विवादों को सुलझाने के लिए ताकत से काम नहीं लेगे।

(ii) दोनों राज्यों के शासनाव्यक्ष इस पर राजी हुए कि दोनों देशों के सव सशस्त्र आदमी 25 फरवरी 1966 तक उन ठिकानों पर वापस लौट जायेंगे, जहाँ वे 5 अगस्त 1965 के पहले थे और दोनों देश युद्ध-विराम रेखा पर, युद्ध-विराम की शर्तों का पालन करेंगे।

(iii) दोनों राज्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार को रोकना चाहिए तथा ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देना चाहिए जो उनके बीच मैत्री की सम्भावनाओं को विकसित करे।

(iv) उन्होंने एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर सहमति व्यक्त की।

(v) दोनों राज्यों के शासनाव्यक्षों ने एक-दूसरे के साथ सामान्य राजनयिक सम्बन्धों को स्थापित करने पर भी सहमति प्रकट की।

(vi) भारत के प्रधानमन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस पर भी सहमत थे कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, संचार और सांस्कृतिक सम्पर्क को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पर विचार करेंगे।

(vii) उन्होंने एक-दूसरे के युद्ध-बन्दियों को रिहा करने को भी स्वीकार किया।

(viii) उन्होंने शरणार्थियों, निष्कासितों तथा गैर-कानूनी बसने वालों की समस्याओं से सम्बद्ध प्रश्नों पर एक-दूसरे से बातचीत जारी रखने की घोषणा की।

(ix) दोनों शासनाव्यक्ष इस बात पर सहमत हुए कि जिन मामलों का दोनों देशों से सीधा सम्बन्ध है उन पर विचार के लिए दोनों पक्षों की सर्वोच्च एवं अन्य स्तरों पर बैठकें होती रहेंगी।

भारत-पाक सम्बन्धों के इतिहास में ताश्कन्द घोषणा के द्वारा एक नया मोड़ देने का प्रयास किया गया था। इसके द्वारा दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था कि वे भविष्य में किसी भी झगड़े को हल करने के लिए हथियार नहीं उठावेंगे और दोनों देशों के बीच सामान्य, शान्तिपूर्ण एवं पारस्परिक सहयोग के सम्बन्धों से जो वातावरण बनेगा, उससे ही वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे।

1969 में पाकिस्तान में दूसरी सैनिक क्रांति हुई। याह्या ख़ाँ इस बार सत्तारूढ़ हुए। परन्तु पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में झगड़ा निरन्तर बढ़ता गया। पाकिस्तान बंगला देश की जनता को अपने अमानुषिक अत्याचारों का शिकार बना रहा था। अतः उससे बचने के लिए लगभग 1 करोड़ आदमी शरणार्थी के रूप में भारत आ गये। निस्सन्देह भारत की अर्थव्यवस्था पर यह बहुत बड़ा बोझ था। परन्तु भारत इस बोझ को बर्दाश्त करता रहा। उसे आशा थी कि विश्व लोकमत पाकिस्तान को नर संहार करने से रोकेंगा। इस सन्दर्भ में यह स्वाभाविक था कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध और भी अधिक बिगड़ते। फलतः 3 दिसम्बर 1971 को दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध आरम्भ हो गया। दो सप्ताह के युद्ध के पश्चात् बंगला देश में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को न केवल पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा, उसे पश्चिम में भी भारी पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध में भारत ने 97000 पाकिस्तानी सैनिकों को बन्दी बनाया तथा सिन्ध, पंजाब और अविभक्त काश्मीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में कर लिया। जैसा स्वाभाविक था, युद्ध में इस करारी पराजय के बाद पाकिस्तान में याह्या ख़ाँ की सरकार का पतन होता। उनके बाद जुट्फिकार अली भुट्टो वहाँ के राष्ट्रपति बने।

शिमला सम्मेलन के समक्ष समस्याएँ—सत्ता में आने के बाद भुट्टो के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह युद्ध में हारे हुए प्रदेशों को वापस पा जाने की तथा युद्ध-बन्दियों की रिहाई की थी। इसके लिए यह परमावश्यक था कि वह भारत से बात करते। फलतः जुलाई 1972 में

भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच गिमना में एक गिलर सम्मेलन आयोजित हुआ।

1971 के युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में बगला दंगे के रूप में एक नये प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य का उदय हुआ। जनमर्या की दृष्टि से वह इस क्षेत्र का दूसरा बड़ा राज्य था। अतः उसकी स्थापना के पश्चात् पाकिस्तान का दर्जा तीसरा हो गया। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान द्वारा भारत की बराबरी के दर्जे की खोज हाम्यास्पद हो हो सकती थी। यही नहीं इस बीच में भारत और बंगला देश के बीच अत्यधिक प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे तथा पाकिस्तान के पास अब वह क्षमता नहीं थी कि वह नयी दिल्ली और ढाका के सम्बन्धों में विगाड़ पदा कर सके।

उपयुक्त परिवर्तना से भी अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि बंगला देश के अभ्युदय के उपरान्त स्वयं भारत का गति के एक केन्द्र के रूप में उदय हुआ है। यह ठीक है कि महाशक्तियों की तुलना में भारत की शक्ति बहुत कम है परन्तु जहाँ तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है कोई भी महाशक्ति उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान और भारत के बीच गिलर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के समुल्लेख जो समस्याएँ प्रस्तुत था उन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है सबसे पहला वे समस्याएँ थी जिनका जन्म दिसम्बर 1971 के युद्ध के कारण हुआ था दूसरे वे समस्याएँ थी जिनका सम्बन्ध दोनों राज्यों के बीच साधारण सम्बन्धों की स्थापना के साथ था। जहाँ तक पहली श्रेणी की समस्याओं का सम्बन्ध है उनके बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि दोनों देश एक-दूसरे के उन क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापिस बुलाये जिन पर उन्होंने युद्ध के समय अधिकार स्थापित कर लिया था। काश्मीर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इस समस्या का समाधान कठिन नहीं था क्योंकि दोनों राज्यों के सीमान्त सामान्यतः सुपरिभाषित हैं। परन्तु यह बात काश्मीर के सम्बन्ध में इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जो पहली युद्ध विराम रेखा थी उस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का स्तर प्राप्त नहीं था। वस्तुतः उसके लिए भी पाकिस्तान के नेताओं को उत्तरदायी माना जाना चाहिए क्योंकि जब नेहरू जी ने यह प्रस्तावित किया था कि युद्ध विराम रेखा को धोरे स्थापना के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मान लना चाहिए तो उस समय पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का ठुकरा दिया था। इस स्थिति में भारत सरकार के लिए दंगे की जनता को इस बात पर सहमत करना कठिन था कि अधिकृत काश्मीर के उस क्षेत्र से हमारी सैनिक हटा जा जाय जिस पर दिसम्बर के युद्ध के फलस्वरूप भारत का अधिकार हो गया था। कानूनी दृष्टि से पाकिस्तान का अधिकृत काश्मीर भारत का अंग है इसलिए भारत कानूनी अथवा नैतिक दृष्टि से काश्मीर के उस भाग को पाकिस्तान कोौटाने के लिए बाध्य नहीं है जिस उसने पाकिस्तान के गैर-कानूनी अधिकार से मुक्त कराया है। यही नहीं इस क्षेत्र के जिन भागों को हमने अपने अधिकार में लिया है वह सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यथावत् में पिछले समय में पाकिस्तान ने इसी क्षेत्र में अपने अण्ड बसाकर भारत पर आक्रमण किया है। अतः इन ठिकानों को पाकिस्तान को वापिस करने की बात उन लोगों को समझ में कभी भी नहीं आ सकती जिनके ऊपर दंगे की प्रतिस्था का उत्तरदायित्व है। युद्ध द्वारा उत्पन्न दूसरी समस्या का समाधान भी वास्तव में कोई आसान बात नहीं है क्योंकि अधिकृत युद्ध-वर्तियों को बगला देश में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भारत और बंगला देश के उच्च सैनिक कमान के समक्ष हथियार डाले थे। जहाँ तक पश्चिमी माच पर गिरफ्तार किए गये बर्तियों का प्रश्न था उनकी रिहाई की समस्या का समाधान कर्त्त कठिन प्रश्न नहीं था। परन्तु पूर्वी माच पर गिरफ्तार बर्तियों को बंगला देश की सरकार को छोड़ कर दिया गया था। किया जा सकता था। बंगला देश में भी इन बर्तियों की समस्या इस आन्तरिक स्तर पर साथ जुड़ी हुई है कि इन बर्तियों में से उन लोगों पर मुकद्दमा चलाया जाय जिन्होंने माच 1971 में तत्काल दिसम्बर 1973 तक बंगला देश की जनता के विरुद्ध जबरन अपराध किए थे। अतः इस समस्या का समाधान के लिए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान वास्तव में बंगला देश के

प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए राजी हो। परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि पाकिस्तान वगला देश को मान्यता प्रदान करे।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार लाने की समस्या वास्तव में पाकिस्तान-वगला देश के पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारने की समस्या के साथ जुड़ी हुई है। भारत के नेता समस्या के इस पहलू से अवगत थे, इसकी अनुभूति पाकिस्तान के नेताओं को भी थी। परन्तु उनमें यथार्थ को स्वीकार करने के लिए उस साहस का अभाव था जिसकी आवश्यकता थी। वस्तुतः शिमला समझौता इस दुर्बलता से ग्रसित था। फिर भी शिमला समझौता सही दिशा में उठाया गया सही कदम था। इस समझौते के द्वारा दोनों पक्षों ने अपनी इस आकांक्षा को व्यक्त किया था कि वे एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसी की भाँति रहना चाहते हैं। 25 वर्ष तक संघर्ष एवं तनाव के वातावरण में रहने के उपरान्त दोनों पक्षों द्वारा शिमला समझौते को स्वीकार करना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण घटना थी।

शिमला समझौते की व्यवस्थायें—शिमला समझौते के अन्तर्गत भारत-पाक सम्बन्धों में जुड़े हुए अनेक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया था। सर्वप्रथम उसमें यह कहा गया था कि दोनों पक्ष अपने बीच पाये जाने वाले संघर्षों का अन्त करना चाहते हैं तथा वे अपने बीच ऐसे मैत्री एवं सद्भावना के सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं ताकि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान तथा एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के आधार पर उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना हो सके। इस समझौते के द्वारा दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर की व्यवस्थाओं के अनुरूप यह प्रतिज्ञा की कि वे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए न तो बल-प्रयोग की धमकी देंगे और न कभी बल-प्रयोग करेंगे। अपने सम्बन्धों का साधारणीकरण करने के लिए उन्होंने यह निश्चित किया कि दोनों देशों के बीच डाक, तार व भूमि और वायु के संचार की सुविधायें फिर से आरम्भ की जायेंगी। समझौते में यह भी कहा गया कि दोनों देश आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।

दोनों पक्षों ने अपने बीच में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे अपनी सशस्त्र सेनाओं को अपने-अपने सीमान्तों तक वापिस बुला लेंगे। जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि दोनों पक्ष 17 दिसम्बर को हुए युद्ध-विराम के अवसर पर स्थापित नियन्त्रण रेखा का सम्मान करेंगे।

समझौते में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि दोनों देशों के नेता दुबारा फिर मिलेंगे, परन्तु इससे पूर्व उनके प्रतिनिधि ऐसे उपायों पर विचार करने के लिए तथा एक दूसरे से बात करने के लिए मिलते रहेंगे जिनसे उनके बीच सम्बन्धों को सुधारा जा सके।

शिमला समझौते का महत्त्व और उसकी कार्यान्विति—शिमला समझौते का विश्व की समूची शान्तिप्रिय एवं प्रगतिशील जनता ने स्वागत किया था। जब समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उस समय यह आशा की जाती थी कि अब भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में एक नया मोड़ आयेगा और अब उस स्थिति का भी अन्त हो सकेगा जिसमें यद्यपि युद्ध तो नहीं होता, परन्तु जिसे शान्ति की सज़ा भी प्रदान नहीं की जा सकती। यह आशा निराधार भी नहीं थी क्योंकि यह पहला अवसर था जबकि दोनों देशों के नेता स्वतः इस इरादे से एक दूसरे से मिले थे ताकि वे द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकें। वस्तुतः समझौते में जो बातें कही गई थी, वे भी इसी बात का इशारा कर रही थी कि सम्भवतः उसके द्वारा तनाव एवं संघर्षों के दिनों का अन्त हो सकेगा तथा दोनों देश अच्छे पड़ोसी की भाँति रह सकेंगे। परन्तु समझौते के बाद अभी तक जो कुछ भी हुआ है उससे बहुत अधिक आशा नहीं बँधती।

भारत और चीन

भारत और चीन के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आधुनिक समय में

भी जब 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चीन को प्रति न वचन मौखिक सहानुभूति प्रदर्शित की बल्कि अपनी सहानुभूति के प्रतीक के रूप में उसने एक डाक्टररी जूता भी चीन भेजा। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हुई तो भारत ने नये चीन को तत्काल मायता दे दी और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उसे विश्व के अन्य राष्ट्रों से भी मायता मिल जाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की उस सदस्यता प्राप्त हो जाय।

1950 के जून में दोनों देशों के बीच एक छोटा सा मतभेद उस समय पड़ा हो गया जबकि चीन ने तिब्बत को स्वतंत्र किया और वहाँ अपनी सत्ता को बलपूर्वक स्थापित किया। यद्यपि भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुता को कोई चुनौती नहीं दी तथापि उसका कहना था कि इस प्रश्न का गतिपूण हल खोजने का प्रयत्न किया जाना चाहिए था। 1954 में तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। इस समझौते में उभयपक्षों ने यह घोषणा की कि वे इन सिद्धान्तों के आधार पर अपने पारस्परिक सम्बन्धों का परिचालन करेंगे। परन्तु यों ही दिनों के बाद दोनों देशों के बीच फिर से मतभेद पड़ा होने लगा। 1956 से लेकर 1959 तक तिब्बत के खम्पा लोमों ने चीनी आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। चीनी सना ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। फलतः हजारों तिब्बतवासियों तथा दलाईलामा को तिब्बत छोड़ने और भारत में आकर शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत सरकार ने उन्हें शरण और सहायता दी। चीन ने भारत सरकार के इस काम को पसन्द नहीं किया।

1956 में चीन ने नद्दाख के एक भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। भारत ने जब इसका विरोध में चीन को पत्र लिखा तो चीन ने इसका उत्तर में यह लिखा कि उसने जिस क्षेत्र पर अधिकार किया है वह चीन का भाग है भारत का नहीं। इसी काल में नद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र में चीन ने एक सड़क भी बना ली। उही दिनांक सूचनायें भी प्राप्त हुई कि चीनी सना टुकड़ियाँ ने नेपा प्रवेश में भी घुसने के प्रयत्न किये परन्तु चीन ने भारत पर उक्त यह आरोप लगाया कि भारतीय सना के दस्ता ने भारत-तिब्बत सीमा पर तिब्बतियों के सहयोग से चीन के किसी प्रदेश पर अधिकार स्थापित कर दिया है। इसी समय चीन ने कुछ नवीन प्रकाशित किये जिसमें भारत की सीमान्तों पर स्थित भागों का चीनी सीमा के भीतर दिखाया गया था। इस स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि दोनों देशों के बीच मतभेदों में उग्रता आ जाती। जब भारत ने चीन से इन बातों की गिरावट की तो चीन ने कहा कि भारत और चीन की सीमाओं का ठीक से निर्धारण नहीं हुआ है। भारत सरकार का इसका उत्तर में यह कहना है कि दोनों देशों के बीच की सीमा बहुत पुराने समय से निर्धारित है। मकमूल में रखा एक ऐतिहासिक सीमा है। चूँकि चीन को भारत का यह दृष्टिकोण माय नहीं था और सीमा पर उसके अनियंत्रण जारी था अतः भारत को अपनी उत्तरी सीमा पर सुरक्षात्मक कदमों को उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

दिसम्बर 1959 में भारत सरकार ने सीमा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से कुछ प्रस्ताव चीन के समुख रखे परन्तु चीन की सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। भारत इस समय इस बात पर बल दे रहा था कि सीमा विवाद को वार्ता द्वारा हल किया जाय और वार्ता की सफलता के लिए चीन भारतीय सीमा से अपनी सैनिक टुकड़ियों को हटा ले। समस्या का समाधान पाने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने सरकारी अधिकारियों का एक-एक अध्ययन दल नियुक्त किया। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार चीन अपने दावों को न्यायोचित सिद्ध करने में असफल रहा है। इस बीच में चीन ने नेपाल और बर्मा के साथ अपने सीमा विवादों का हल करने के लिए समझौते किये तथा उसने पाकिस्तान से भी कहा कि अधिकृत काश्मीर के गिरगिट प्रदेश में पाक-चीन सीमा को ठीक से निर्धारित कर लिया जाए। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि भारत ने काश्मीर के किसी भी भाग पर पाकिस्तान के अधिकार को मायता नहीं दी है। अतः चीन का यह काम निश्चय ही भारत विरोधी था। इस पृष्ठभूमि में भारत के लिए अपनी सीमा-सुरक्षा

की व्यवस्था को हट करना आवश्यक हो गया।

20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने लद्दाख व नेफा दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय प्रदेश पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। भारत सरकार इस आक्रमण के लिए तैयार न थी। इसके अनिरीक्त भूगोल भी चीन की सहायता कर रहा था। अतः युद्ध में चीन का पलड़ा ही भारी रहा।

चीन के इस आक्रमण से एशिया और अफ्रीका के देशों को विशेष रूप से कष्ट पहुँचा था। अतः एशिया के इन दोनों महत्त्वपूर्ण देशों के बीच पाई जाने वाली इस स्थिति का अन्त करने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री की पहल पर कोलम्बो में बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इण्डोनेशिया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों का 10 से 12 दिसम्बर तक एक सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत-चीन संघर्ष पर विचार किया गया। 19 जनवरी 1963 को कोलम्बो प्रस्ताव प्रकाशित किये गये जिनमें निम्न बातें कही गई थी—

(1) पश्चिमी क्षेत्र में चीनी अपनी सैनिक चौकियों को 20 किलोमीटर पीछे हटा ले और भारतीय सरकार अपनी सेना को वर्तमान स्थिति में रखे।

(2) जब तक सीमा-विवाद का अन्तिम हल न निकले चीनी सेनाओं द्वारा खाली किये गये प्रदेश में दोनों ओर एक-दूसरे की सहमति पर नागरिक चौकियाँ स्थापित की जायें।

(3) पूर्वी क्षेत्र में दोनों सरकारों द्वारा मान्यता-प्राप्त यथार्थ नियन्त्रण की रेखा युद्ध-विराम रेखा के रूप में मानी जाय।

(4) मध्य क्षेत्र के विषय में यथास्थिति को कायम रखा जाय।

भारत सरकार ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, परन्तु चीन सरकार ने ऐसा नहीं किया। चूँकि दोनों ही पक्ष इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी स्थिति को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे, अतः समस्या जहाँ थी वही बनी रही।

1962 के बाद भारत के समक्ष शत्रुतापूर्ण आचरण करने वाले दो पड़ोसियों की समस्या हमेशा से रही है। इन दोनों पड़ोसियों में भारत की सुरक्षा के लिए चीन का खतरा पाकिस्तान के खतरे की अपेक्षा कहीं अधिक है। आखिर चीन भारत की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, जबकि पाकिस्तान भारत की अपेक्षा एक दुर्बल राष्ट्र है। पिछले वर्षों में भारतीय विदेश-नीति की एक प्रमुख समस्या भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान का गठ-बन्धन रही है। इस गठ-बन्धन के अनेक उदाहरण हैं। 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार पाकिस्तान ने अधिकृत काश्मीर का एक भाग चीन को दे दिया। 1965 में भारत-पाक संघर्ष के समय चीन ने भारत को एक अल्टीमेटम दिया तथा 1971 में चीन ने बंगला देश में पाकिस्तान की नृशंस कार्यवाहियों का समर्थन किया तथा भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान को अपना राजनीतिक समर्थन दिया। उसने पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश के प्रवेश का विरोध किया है। यथार्थ में चीन भारत को एक शक्तिशाली पड़ोसी के रूप में नहीं देखना चाहता।

1971 के युद्ध के पूर्व यह लगता था कि भारत और चीन के बीच शायद पारस्परिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई बातचीत हो। परन्तु इस युद्ध के समय चीन ने जो दृष्टिकोण अपनाया उसके बाद इस आशा पर ठुसारापात हुआ है। फलतः जो गतिरोध 1962 में पैदा हुआ वह आज भी पूर्ववत् कायम है।

एशिया के अन्य राज्यों के साथ भारत के सम्बन्ध

पाकिस्तान और चीन के अतिरिक्त भारत के अन्य पड़ोसी राज्यों में मुख्य नेपाल, बर्मा, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान हैं। भारत के समीप ही दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। अतः स्वाभाविक रूप से इन राज्यों के साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रखने में भारत की रुचि है।

पश्चिमी एशिया और सुदूर पूर्व के देशों के साथ भी भारत के अच्छे सम्बन्ध हैं। 1958

म भारत क राष्ट्रपति ने जापान की यात्रा की थी उस समय स एशिया के य दाना देन एक दूसरे क समीप आय हैं। 1969 म प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी भी जापान गई थी। वस यात्रा क फलस्वरूप दाना देना के बीच जायिक सहयोग म वृद्धि हुई है।

टर्की और ईरान को ट्रोडकर पश्चिमी एशिया क अय सभी राायो के साथ भारत क सम्बन्ध श्रत्यधिक मजबूत रह है। नहरू जी क अरब राष्ट्रवाद के सुपरिचित नेता नासिर के साथ घनिष्ठ मत्री थी। दाना नताजा का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण मूलतः उपनिवेशवाद विरोधी था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि उनक नृत्व म उनके राायो के बीच भी सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हा। 1967 क अरब इजराइल संघर्ष म भी भारत की सहानुभूति अरब देशो क साथ थी। परन्तु 1969 मे रवात म जब इस्लामिक शिखर सम्मेलन हुआ ता पाकिस्तानी प्रभाव म आकर अरब देशो ने भारत को उस सम्मेलन म भाग नही लेन दिया। वसमे भारत को निश्चय ही एक धक्का लगा। वसके उपरांत 1971 के भारत पाक संघर्ष म अरब देशो ने पूर्ण रूप स चुप्पी साध ली। बगना देन म पाकिस्तान द्वारा बरते गये अत्याचारा के विरोध म भी उहाने कुछ नही कहा। भारत के लिए अरब राज्या का यह आचरण अप्रत्याशित था। स्वतंत्र बगना देश की स्थापना तथा युद्ध म पाकिस्तान की पराजय के उपरांत प्रगतिशील अरब राायो ने अपने इस आचरण की सफाई लेने की भी कोशिश की थी। किंतु स्पष्टतः यह सफाई नतोपजन्तक नही थी।

भारत और ब्रिटेन

स्वतंत्रता के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच सम्बन्धो म महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन क फलस्वरूप दोनों राायो के बीच सद्भावना और मत्री क सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। स्वतंत्र होने क बाद भारत ने राष्ट्रमण्डल के साथ अपने सम्बन्धो को कायम रखा उसने ब्रिटेन के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्धो को भी पहन जसे ही बनाय रखा। भारत स्ट्रिंग क्षत्र का सदस्य है तथा उसको मुद्रा ब्रिटिश पौण्ड के साथ सम्बद्ध है। जपन जायिक विकास की योजनाआ मे भी भारत को ब्रिटेन से पर्याप्त मात्रा म सहायता प्राप्त हुई है।

परन्तु वसका अभिप्राय यह कदापि नही है कि भारत ने ब्रिटेन के सभी कामा का समर्थन किया है। सच बात यह है कि प्रावश्यकता पडन पर भारत न ब्रिटेन को अपनी आलोचना का शिमार बनाया है। उदाहरण के लिए 1956 म स्वेज नहर के संकट के दौरान भारत सरकार ने ब्रिटिश कायवाही की कट गन्धो म आलोचना की थी। काश्मीर के प्रश्न पर ब्रिटेन न सन्ध से पाकिस्तान क पक्ष का ही समर्थन किया है वसस भी भारत और ब्रिटेन के बीच मन मुटाव पदा हुआ है। इसी प्रकार गोघ्रा को पुतगाली दासता स मुक्त कराने के लिए जब भारत ने सैनिक कायवाही की तो उस समय भी उसे ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त नही हो सका। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि भारत और ब्रिटेन के बीच सामान्यतः अच्छे सम्बन्ध पाय जाते हैं तथापि एस अनक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न हैं जिन पर दोनों राायो के बीच गम्भीर मतभेद पाय जात है।

उपसंहार

गत 25 वर्षों म अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षत्रीय वातावरण म स्वस्थ परिवर्तन हुए हैं। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश अपनी अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके हैं। आज समाजवादी विश्व पहले की अपेक्षा बड़ी अधिक गतिमान है तथा आज पश्चिम के देश उस स्थिति म नहीं हैं जिससे व ससार की गति को कोई खतरा पहुँचा सक। आज के ससार के सामुख जो सबसे बड़ी समस्या है वह सम्पन्न और विपन्न राष्ट्रों के बीच की खाई को पाटन की है। आज विश्व क छोटे और गरीब राष्ट्र भी अपनी राष्ट्रीय प्रभमत्ता की रक्षा क प्रति बहुत अधिक सजग हैं अतः वसे राष्ट्र उह दरा धमका कर उनसे जा चाह बह नही करा सकते। पिछन वर्षों म गति क गय वगा का उदय हुआ है फलतः विश्व राजनीति क ढाँच म अपक्षित परिवर्तना क अभ्युदय की प्रक्रिया

आरम्भ हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय वातवरण में हुए इन परिवर्तनों के साथ दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पाकिस्तान का उसके स्वयं के अपने बोझ से पतन हो चुका है प्रभुसत्ता-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य के रूप में वगला देश के अभ्युदय से भारतीय उप-महाद्वीप की राज्य-प्रणाली में एक मौलिक अन्तर आया है। आज भारत इस क्षेत्र के दूसरे बड़े राज्य के साथ मैत्री सम्बन्धों के बारे में आश्वस्त है।

1971 के युद्ध ने दक्षिण एशिया में उस कृत्रिम शक्ति-सन्तुलन का भी अन्त कर दिया है जिसे पहले तो पश्चिमी देशों ने, विशेषतः अमरीका ने स्थापित किया था। बाद में उसकी स्थापना में चीन से भी सहयोग किया था। अब उस प्रकार के शक्ति-सन्तुलन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज भारत अधिक सुरक्षित वातावरण में रह रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली में पिछले वर्षों में परिवर्तन हुए हैं उनको जन्म देने में भारत की निस्सन्देह भूमिका रही है। जिस प्रक्रिया के द्वारा भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई उसने उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया को तेज करने में एक बड़ा योगदान दिया। उसकी गुट-निरपेक्षता की नीति विश्व के नये राष्ट्रों को आकर्षक प्रतीत हुई। इसके फलस्वरूप पश्चिमी शक्तियों के तत्वावधान में वह साम्राज्यवादी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी जो द्वितीय महायुद्ध के पहले पायी जाती थी। उसने विश्व शान्ति उस समय कायम रखने में सहायता दी जबकि विश्व युद्ध को आरम्भ करने की क्षमता केवल महाशक्तियों तक ही सीमित थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने समाजवादी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये। यह बात निःसन्देह है कि यह मैत्री विश्व राजनीति में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है।

अन्त में, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देकर तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठन एवं अभिकरणों में भाग लेने की आवश्यकता को स्वीकार करके भारत ने विश्व शान्ति की सम्भावनाओं को मजबूत बनाया है। यद्यपि भारत की विदेश नीति शान्ति को अपना लक्ष्य मानकर चलती है तथापि पिछले वर्षों में उसे अनेक बार युद्ध लड़ने के लिए बाध्य होता पड़ा है। यदि गोआ पर पुर्तगाली शासन न होता, यदि पाकिस्तान एक ऊल-जलूल राज्य न होता, यदि चीन भारत का पड़ोसी राज्य न होकर वहाँ स्थित होता जहाँ ब्राजिल है, तो सम्भवतः भारत उन युद्धों से बच जाता जो उसे पिछले वर्षों में लड़ने पड़े हैं। भारत को पाकिस्तान के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। यथार्थ में पाकिस्तान का विघटन तो स्वयं पाकिस्तान के जन्म में ही सन्निहित था। भारतीय विदेश नीति चीन विरोधी भी नहीं है। वस्तुतः पिछले वर्षों में चीन ने ही भारत विरोधी दृष्टिकोण को अपनाया है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विदेश नीति के क्षेत्र में पिछले वर्षों में भारत की जो उपलब्धियाँ रही हैं उनके ऊपर भारतवासियों को गर्व करने का उचित अधिकार है। आज का अन्तर्राष्ट्रीय समाज 1946 के अन्तर्राष्ट्रीय समाज की अपेक्षा अधिक न्यायपूर्ण है और जैसा कहा चुका है इस स्थिति को लाने में भारत की भूमिका निस्सन्देह महत्वपूर्ण रही है।

प्रश्न

- 1 भारत की विदेश नीति के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए।
- 2 क्या 'तटस्थता' और 'गुट निरपेक्षता' एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं ? भारत की विदेश नीति के सदम में समावेश है।

GOVERNMENT COLLEGE LIBRARY

K O T A . (Raj.)
